



आज का भारत



वि. मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास  
समस्त विश्व मे सहयोगी कंपनिया

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

‘इंडिया टुडे’ का अनुवाद  
प्रथम हिंदी संस्करण 1977

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित

मूल्य 57 00

एस० जी० बसानी द्वारा वि. मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
के लिए प्रकाशित तथा माडन प्रिंटर्स, दिल्ली 110032 में मुद्रित ।

RAJANI PALME DUTT AAJ KA BHARAT

मेरे पिता

उपेंद्र कृष्ण दत्त की स्मृति में

(जन्म कलकत्ता, भारत 17 अक्टूबर 1857

मृत्यु लेदरहेड, इंग्लैंड, 12 मई 1939)

जिन्होंने मुझे राजनीतिक समझ का

पहला पाठ पढ़ाया, भारतीय जनता

और आजादी के लिए सघन

सारी जनता का प्यार

करमा सिखाया



# अनुसंधान परिषद् की ओर से ४०६

इतिहास

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अनेक उद्देश्यों में एक है शोध की उपलब्धियों को उस पाठकवर्ग तक पहुँचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं में इतिहास सबंधी रचनाएँ तैयार तथा प्रकाशित करें। अंगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुँच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठकवर्ग का यह छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रकृति बल पवड रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भा० इ० अ० प० ने कुछ गौरवग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आदृत और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

प्रस्तुत पुस्तक 'आज का भारत' मार्क्सवादी इतिहास लेखन का एक मागदशक उदाहरण है। इसमें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की कायप्रणाली की प्रकृति का विश्लेषण किया गया है तथा यह दिखाया गया है कि इससे भारत किस तरह ब्रिटिश पूँजीवाद का कृपि-पिछलतग्नू बनकर रह गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितनी बुरी तरह पिछड़ेपन का शिकार हुआ। इसके साथ ही पुस्तक में स्वाधीनतासंग्राम में सवहारावर्ग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि 'आज का भारत' प्रकाशित होने के बाद दत्त का अनुसरण करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं फिर भी वे किसी भी रूप में इस पुस्तक से आगे नहीं बढ़ पाई हैं और यह आज भी अपनी तरह का गौरवग्रंथ है।

इस पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए हम अनुवादक श्री आनंदस्वरूप वर्मा, नगेंद्रप्रसाद वर्मा तथा अन्य सभी सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

26 जनवरी 1977

नई दिल्ली

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्

इस पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए हम अनुवादक श्री आनंदस्वरूप वर्मा, नगेंद्रप्रसाद वर्मा तथा अन्य सभी सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

रामशरण शर्मा

अध्यक्ष



## अनुक्रम

1970 के संस्करण की भूमिका/1

आधुनिक विश्व में भारत/23

स्वाधीनता की पूर्व संध्या में भारत/24

साम्राज्यवाद और भारत/29

भारत में साम्राज्यवाद का दिवालियापन/32

भारत का जागरण/35

खण्ड एक

भारत जैसा है और जैसा होना चाहिए

भारत का बभ्रव और उसकी गरीबी/43

भारत का वैभव/43

भारत की गरीबी/50

अत्यधिक आबादी होने की आतिया/65

दो सप्ताहों की विषमता/82

समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीस वर्ष/83

मध्य एशियाई गणराज्यों का अनुभव/91

खण्ड दो

भारत में ब्रिटिश राज

भारत की गरीबी का रहस्य/103

भारत पर मार्क्स के विचार/107

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छिन्नभिन्न होना/109  
 भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका/112  
 भारत में ब्रिटिश शासन की 'पुनरुज्जीवनकारी' भूमिका/117

भारत में ब्रिटिश शासन का पुराना आधार/122

भारत की लूट/123

भारत और औद्योगिक क्रांति/132

उद्योग के क्षेत्र में तबाही/140

भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद/150

महाजनी पूजा में सम्मेलन/152

महाजनी पूजा और भारत/160

उद्योगीकरण की समस्या/167

उद्योगीकरण के माग में बाधाएँ/173

युद्ध से पहले के बीस वर्षों का लेखा जोखा/180

महाजनी पूजा की दमघोड़ पकड़/185

महाजनी पूजा और द्वितीय विश्वयुद्ध/192

महाजनी पूजा और नई साविधानिक योजना/204

भारत में साम्राज्यवाद का परिणाम/211

खण्ड तीन

भारत की मूल समस्या कृषि समस्या

कृषि के क्षेत्र में संकट/216

खेती पर जरूरत से ज्यादा दबाव/218

कृषि पर अत्यधिक दबाव के नतीजे/223

खेती में ठहराव और गिरावट/226

किसानों पर बोझ/239

जमीन की इजारेदारी/239

भूमि व्यवस्था का रूपांतरण/244

जमींदारी प्रथा की शुरुआत/246

किसानों की दरिद्रता/253

कज का बोझ/262

तीन तरह का बोझ/269

किसान क्रांति की ओर/274

श्रृषि क्षेत्र में सनट का विकास/274

विज्ञान क्रांति की आवश्यकता/282

सरकारी सुधारों की असफलता/285

किसान आंदोलन का विकास/290

## खण्ड चार

### भारतीय जनता का आंदोलन

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय/296

एकता और अनेकता/297

जाति, धर्म और भाषा के प्रश्न/304

भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत/311

राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म/320

राष्ट्रीय संग्राम की तीन मजिलें/330

समय की पहली बड़ी लहर (1905-1910)/331

समय की दूसरी बड़ी लहर (1919-1922)/342

समय की तीसरी बड़ी लहर (1930-1934)/362

मजदूरवर्ग का उदय और समाजवाद/390

औद्योगिक मजदूरवर्ग का विकास/391

मजदूरवर्ग की हालत/395

मजदूर आंदोलन की स्थापना/410

राजनीतिक जागरण/417

मेरठ का मुकदमा/423

मेरठ के बाद मजदूर आंदोलन का पुनर्गठन/430

विश्वयुद्ध से पहले की लहर/433

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में मजदूरवर्ग/436

भारतीय जनतंत्र की समस्याएँ/443

राजा महाराजा/445

साम्प्रदायिक भेदभाव/460

बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान/469





## 1970 के संस्करण की भूमिका

'आज का भारत' पुस्तक को लिखे लगभग तीस वर्ष और भारत में इसे पहली बार प्रकाशित हुए लगभग पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं। बीच के इन वर्षों में भारत को आजादी मिलने के साथ साथ नए घटनाक्रम का एक पूरा युग गुजर चुका है और नई नई खोजों से ऐसे तमाम मसलों पर और भी रोशनी पड़ी है जिनपर इस पुस्तक में विचार करने का काफी हद तक पहली बार प्रयास किया गया था। इसलिए आज का भारत' को महज अपने काल की एक ऐतिहासिक वृत्ति के रूप में मायता दी जानी चाहिए जिसमें मार्क्सवादी दृष्टि से भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का और आजादी मिलने के समय तक भारतीय जनता के संघर्ष का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन और मेहनतकश वर्ग का आंदोलन शामिल है, फिर भी ऐसा लगता है कि इस पुस्तक की मांग आज भी है और इसीलिए 1947 के मूल भारतीय संस्करण का पुनः प्रकाशन किया गया है।

पुस्तक का मूल पाठ वही है जो 1947 के संस्करण में था। इसमें जानबूझकर कोई सुधार या परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, उन कुछ अंशों को इस पुस्तक में जरूर शामिल कर लिया गया है जिसे ब्रिटेन में प्रकाशक के संस्करण की वजह से निकाल देना पड़ा था। उन अंशों का यहाँ पहली बार प्रकाशित किया गया है। इन निकाले गए अंशों के पार में दो शब्द कहना काफी उपयोगी होगा क्योंकि यहाँ ब्रिटेन में आज भी जारी राजनीतिक संस्करणों की एक अद्भुत मिसाल पेश करने हैं।

'आज का भारत' की पाठ्यलिपि मूलतः 1936-39 ई० में लेफ्ट बुक क्लब के लिए लिखी गई थी। इस सन्ध्या की पुस्तकों विक्टर गोलाज प्रकाशित करते थे। पुस्तक लिखने का

अनुवध 1936 में ही हुआ था पर अंतिम तौर से पांडुलिपि नवंबर 1939 यानी विश्व युद्ध छिड़ने के बाद तक नहीं दी जा सकी। कारण यह था कि इस पुस्तक के सिलसिले में मुझे बहुत काम करना पड़ा और इसके लिए अपनी व्यस्तताओं के बीच बड़ी मुश्किल से किसी तरह रुक रुक कर समय निकालना पड़ता था। इन वर्षों में मेरे ऊपर अनेक जिम्मेदारियां थी, मैं उन दिनों 'डेली वर्कर' और 'लेबर मथली' का संपादन करता था, कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो का सदस्य था, 1937 के प्रारंभ में गठित क्रिप्स, वेबन, मैक्सटन, ब्राकवे, और पालिट के साथ संयुक्त मार्चा समिति में मैं शामिल था और विभिन्न चरणों में इसकी नियमित बैठक चला करती थी। साथ ही मैं कुछ अन्य गति विधियां में भी लगा था। चैवरलेन डेलेडियर के कृत्रिम युद्ध का हमने विश्लेषण किया और उसके साम्राज्यवादी चरित्र का उद्घाटन किया जिसके कारण मोराज ने अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना संबंध तोड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि वे इस पुस्तक को प्रकाशित करने से कतराने लगे पर मैंने उन्हें अनुवध की याद दिलाई। इसपर उन्होंने कहा कि इसे प्रकाशित करना कानूनी तौर से वेहद खतरनाक है। मैंने उन्हें बतलाया कि यह किताब कानूनी तौर पर प्रसारित हान के लिए लिखी गई है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे आपत्तिजनक अंश पर निशान लगा दें ताकि वैधानिक दृष्टि से जहां सुधार करना जरूरी हो मैं कर दूँ। फिर उन्होंने मेरी पांडुलिपि अपने वकील के पास भेज दी। उनके वकील ने पूरी पुस्तक देखने के बाद बताया कि पुस्तक का एक भी अंश ऐसा नहीं है जो कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक हो, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पुस्तक का संपूर्ण प्रभाव वेहद उत्तेजना पैदा करने वाला है ('इसका सीधा उद्देश्य जनमत को इस सीमा तक भटकाना है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता पलटने का प्रयास करे')। अपने वकील द्वारा पुस्तक के एक भी अंश को या एक भी वाक्य को कानूनी तौर से आपत्तिजनक न बताने पर मोराज ने यह काम स्वयं करने का निश्चय किया और जिन अंशों को वह प्रकाशन के लिए खतरनाक समझते थे उनपर उन्होंने लाल पसिल से निशान लगा दिया। जितनी धार 'क्रांति' शब्द का इस्तेमाल हुआ था उनकी पसिल इस शब्द को घेर कर निशान बनाती रही यहां तक कि एक जगह इंग्लैंड के संसद में 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति की बात जहां लिखी थी वहां भी क्रांति शब्द पर उन्होंने निशान लगा दिया। हम दोनों पांडुलिपि सामने रखकर दिन भर विचार विमर्श करते रहे, हर चिह्नित अंश का ज्या का ह्यो रखने के लिए मुझे कठिन संघर्ष करना पड़ा लेकिन तकरीबन एक सौ ऐसे स्थल थे जिन्हें चमलने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा ताकि मैं पुस्तक का प्रकाशन कर सकूँ। इसलिए अब तक प्रकाशित पाठ में बार बार 'रूप परिवर्तन' और 'निर्णायक तपदीलिया' करनी पड़ी है।

1947 में इस पुस्तक का दूसरा संशोधित संस्करण भारत में प्रकाशित हुआ। (इस प्रकाशन में पूर्व भारत में इस कानूनी तौर से प्रकाशित करना संभव नहीं हो सका था हालांकि गैरकानूनी रूप में हमने कुछ हिस्से या कुछ अंशों में अनुवाद छापकर वितरित किए जा चुके थे) तब 1946 तक की घटनाओं को शामिल कर लिया गया और इस

प्रकार पुस्तक को विस्तार दिया गया। 1946 में मैंने भारत की यात्रा की (भारत में मेरे प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद पहली बार) और इस यात्रा के अनुभवों को भी अतिरिक्त सामग्री के रूप में इस संस्करण में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन तमाम चीजों को जोड़ने के बावजूद सामान्य तौर से मूल पाठ वही रहने दिया गया जो 1940 के संस्करण किए गए अंग्रेजी संस्करण का था।

अब जबकि 1947 के भारतीय संस्करण का पुनर्मुद्रण किया जा रहा है इसकी तैयारी के दौरान गोलाज को संस्करण के लिए दी जाने से पहले की मूल पांडुलिपि पर और गोलाज द्वारा थोपे गए परिवर्तनों और आपत्तिजनक अंशों पर हाथ लगा सका हूँ। तदनुसार, यद्यपि मुद्रण का काम आगे बढ़ रहा था फिर भी यह पता चलते ही मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और कुछ जरूरी अंश पुस्तक में शामिल किए। पुस्तक में ऐसे परिवर्तनों परिवर्धनों की संख्या लगभग पचास है। इस प्रकार वर्तमान संस्करण में पहली बार वे सारे अंश शामिल किए गए हैं जिन्हें अंग्रेज प्रकाशक ने संस्करण लागू करके निकाल दिया था।

यहां एक सवाल पूछा जा सकता है कि 1970 में जब यह नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है तो मैंने 1946 में 1970 के दौरान की घटनाओं के बारे में लिखने के अवसर का फायदा क्यों नहीं उठाया।

इसका जवाब यह है कि आजादी के बाद से आज के युग के घटनावृत्तों का विकास इतना गंभीर और व्यापक रहा और इस दौरान उत्पन्न समस्याएँ इतनी दूरगामी रही कि इनपर उचित ढंग से विचार करने के लिए एक सच्चा नई पुस्तक की जरूरत है, पुरानी विचारों को ही जोड़ घटाकर काम नहीं चला सकता। 1946 से 1969 तक की घटनाओं का व्योरा प्रस्तुत करने के लिए अंत में जोड़े गए कुछ अध्यायों से साफ पता चल जाता है कि पैरद लगाया गया है क्योंकि इस पुस्तक में विवेचित अधिकांश मामले अब पश्च-दृष्टि से प्रभावित होंगे। यह चाहे पूर्ण ज्ञान के जरिए हो अथवा अंश अनुभवों के जरिए या पुराने प्रश्नों का नए रूपों में स्फूर्ति करके किया जाए। परिणामतः 1947 के पाठ को अपनी खासियत और अपूर्णताओं के साथ ज्यों का त्यों रखने में जानबूझकर एक आत्मनिर्पेक्षात्मक अध्यादेश का पालन किया गया है।

कुल मिलाकर इस पुस्तक में साम्राज्यवाद के इतिहास और जन आंदोलन के विकास का सामान्य तौर पर जो निरूपण और विश्लेषण किया गया है वह अब तक समय की कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन अनेक विशिष्ट मामले जिनका यहाँ जिक्र किया गया है, बाद के अनुभवों से प्रभावित हुए हैं या उन्होंने नए रूप धारण किए हैं और उनपर यदि आज निगाह जाए तो उसके लिए एवढा भिन्न ढंग से बताना होगा। इस सिलसिले में उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

पहले गांधी की भूमिका को ही ले। गांधी की भूमिका का समान रूप से सकारात्मक और नकारात्मक चरित्र कुल मिलाकर बाद के ऐतिहासिक शोध और विवेचन के परीक्षण पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के समूचे स्तर को पहले के मकीन दायरे से उठाकर राष्ट्रव्यापी जन आन्दोलन के स्तर तक पहुँचा देन और अत्यंत पिछड़ी निष्क्रिय जनता के ज़रूरत राष्ट्रिय चेतना का मंचार करने एवं मधुप के लिए उद्देश्य प्रेरित करने में गांधी की रचनात्मक भूमिका पर बल दिया जाना ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण था जब कुछ वामपंथी आलोचक कठमुल्लेपन के साथ गांधी का एकपक्षीय मूल्यांकन करते उद्देश्य जन आंदोलन का दुश्मन और कभी कभी तो ब्रिटिश एजेंट यानी अंगरेजों का दलाल कहने लगे थे। लेकिन इसी के समानांतर गांधी की नकारात्मक भूमिका पर भी ऐसे समय प्रकाश डालना ज़रूरी था जब उनके समय के उद्देश्य निरपराध्य मत और पैगवर के रूप में पेश कर रहे थे (यह प्रवृत्ति आज भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है)। गांधी की नकारात्मक भूमिका के सदर्भ में देखें तो गांधी न अहिंसा के नाम पर हमेशा जमींदारों और संपत्तिवान वर्ग के हितों की रक्षा की। सामाजिक तौर में वह घोर रूढ़िवादी थे। जिस किसी जनसंघर्ष की शुरुआत उन्होंने की, उसे उस समय तत्काल रोक दिया जब संघर्ष न संपत्तिवान वर्ग और साम्राज्यवाद के हितों के विरुद्ध प्रातिकारी रूप लेना शुरू किया। ऐसे समय गांधी को हमेशा यह भय रहता था कि आंदोलन वही जनप्रिय प्राति का रूप न ले ले। लेकिन चौथे दशक के उत्तरार्ध में, जिस समय यह पुस्तक मूल रूप में लिखी गई गांधी की भूमिका और नीतियों के मूल्यांकन से संबंधित मतों पर काफी बहस चल रही थी। इसीलिए गांधी के चरित्र के बारे में इस पुस्तक में जो विश्लेषण किया गया है वह तथ्य के रूप में सच होने के बावजूद वादविवाद की संभावनाओं से भरपूर है।

आज इस महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत संतुलित मूल्यांकन करना ज्यादा उचित होगा हालांकि आज भी हमारा विश्लेषण अनिवार्य रूप से उसी पुरानी पद्धति पर ही होगा। इस मूल्यांकन के लिए उनके अंतिम दिनों के कार्यों के उच्च स्तर और श्रेष्ठता को भी ध्यान में रखना होगा जब उन्होंने सांख्यिक रूप से माउंटबेटन समझौते की भूमिका को और कहा कि यह उनके सपनों के स्वराज्य का मजाक है अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को सांप्रदायिक दंगों और नरसंहार की आग बुझाने में लगा दिया, इस आधार पर खुद को कम्युनिस्टों के ज्यादा करीब पाया और जतन में दक्षिणपंथी दुराग्रहियों की गाली के शिकार हुए।

भाषा के प्रश्न पर (पृ० 295-98) 222 पंक्तियों में भाषाओं के साम्राज्यवादी मित्य के खंडन का औचित्य तो बना रहता है लेकिन कांग्रेस सिद्धांत की इस अंतर्निहित स्वीकृति पर कि हिंदी भारत के लिए एक आम भाषा का समाधान प्रस्तुत करेगी उन कठिनाइयों ने प्रश्नचिह्न लगा दिया है जो इस नीति को लागू करने के दौरान पैदा हुई। और इस अनुच्छेद में प्रस्तुत निष्कर्ष कि 'भारत में भाषाओं की समस्या तकरीबन 12 या 13 विभिन्न भाषाओं की समस्या है', मजबूत सही आकलन के काफी करीब है।

‘बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान’ (पृ० 464-81) के प्रश्न पर यह अनुच्छेद, बेशक, ऐसे समय लिखा गया था जब पाकिस्तान अभी एक राजनीतिक योजना का अंग था और एक राष्ट्र के रूप में उसकी स्थापना नहीं हुई थी। उस समय विश्लेषण के जो सामान्य सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए थे उनकी दिशा इस प्रकार थी—राजनीतिक क्षेत्र में सांप्रदायिक विभाजन को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन को विफल करने एवं उसमें फूट डालने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहन देने में साम्राज्यवाद की जिम्मेदारी, व्यवहार में हिंदूवाद को साथ लेकर राष्ट्रीय प्रचार करने और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम सहयोग पर आधारित करने में कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी, यह मान लिया जाना कि बाद के दौर में मुस्लिम लीग को उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त हुआ और भारत के विभाजन की मांग तथा अलग राज्य की स्थापना, विकृत रूप में ही सही, वास्तविक राष्ट्रीय मांग थी जो भारत के बहुराष्ट्रवादी स्वरूप के अनुरूप थी, राष्ट्रीयता को घम पर आधारित करने के किसी भी प्रयास की भूलना क्योंकि यह प्रतिक्रियावादी और विभाजनकारी प्रवृत्ति है तथा इससे अनेक नुकसानदेह विनाशकारी दुष्परिणामों की आशंका है।

तब से पाकिस्तान नामक राज्य की स्थापना हो चुकी है, 1956 में उसने ‘इस्लामिक गणराज्य’ की घोषणा की और आज दो दशकों से भी अधिक समय से उसका अस्तित्व बना हुआ है। तदनुसार नई राज्य सीमाओं के अंदर लोकप्रिय सघन विकसित हुआ है। विश्लेषण के सामान्य सिद्धांतों की वैधता बनी रहती है। पाकिस्तान की स्थापना की दुनियाद कितनी अस्थिर थी और इसका शासन सभालने वाला बग कितना सकीर्ण विचारधारा वाला था, इसका जायजा इन तूफानी वर्षों की घटनाओं तथा निरंतर अशांति एवं दमन, 1958 से लागू माशरूफ़ और अयूब खान की सैनिक तानाशाही से मिल जाता है। इस पुस्तक के लिखने के समय तक अयूब खान के पतन और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व की समाप्ति की मांग को लेकर पूर्वी पाकिस्तान में तेज हो रहे लोकप्रिय आंदोलन के साथ वर्तमान संकट पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है।

अंतिम अध्याय ‘भविष्य’ को मूल के अनुसार ही पुनर्मुद्रित किया गया है। इस अध्याय में स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या 1946 में, आजादी की प्राप्ति की भावी स्थितियों का आकलन करने का प्रयास किया गया है और इसलिए यह अध्याय कुछ हद तक अब भी महत्वपूर्ण है। बाद की घटनाओं की रोशनी में देखें तो मुख्य विषयवस्तु का आज भी कुछ महत्व है। प्रथम साम्राज्यवाद द्वारा नपथ्य से जहां तक हो सके अपना नियंत्रण बनाए रखने की निरंतर कोशिशों का आभास मिलता है। सबसे पहले तो आजादी देने जैसी प्रारम्भिक प्रतिवधक शर्तों के जरिए करने की कोशिश और फिर इन तरीकों के विफल हो जाने पर ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के संचालन की रक्षा करने और यहां तक कि उसके क्षेत्र का इस आशा के साथ विस्तार करने की कोशिश कि भले ही अब भारतीय ध्वज फहराता हो पर इस नए युग में वास्तविक सारांश और शोषण से पैदा मुनाफे का सर्वोत्तम

भाग तथा निर्णायक शक्ति जहाँ तक हो सके, ब्रिटिश पूँजीवाद के हाथों में बनी रह। दूसरे साम्राज्यवाद की इस निरंतर जकड़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता के सघर्ष की प्रत्याशित प्रगति और सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यों, कृषि के क्षेत्र में दिन ब दिन गभीर होते सकट और वर्गों के संघर्ष के साथ इस सघर्ष का एक अविच्छिन्न सघर्ष। तीसरे आजादी मिलने के बाद भारत के सामने बुर्जुआ के विभिन्न हिस्सों की भावी भूमिका और वैकल्पिक रास्ते (अ) दक्षिणानूसी शक्तियों का रास्ता (ब) आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे पूँजीवादी भारत के विकास और संभवतः 'भारतीय समाजवाद' का नाममात्र का लेबल लगाकर नियंत्रित पूँजीवाद के लिए राष्ट्रीय बुर्जुआ का रास्ता और अंततः (स) जनताविक क्रांति का काम पूरा करने, साम्राज्यवाद का सफाया करने, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण करने पिछड़ेपन और सामूहिक गरीबी की स्थितियों को समाप्त करने और इस प्रकार समाजवाद की दिशा में वास्तविक प्रगति की आधारशिला रखने के लिए मजदूरों, किसानों और लोकप्रिय शक्तियों के बढ़ते दस्तों का रास्ता।

आज उस परिदृश्य को लिखे जाने के बाद से 22 वर्षों के अनुभव ने तपसील, पेचीदगी, उतार-चढ़ाव तथा व्यक्तित्व के कौतुक की कहीं अधिक विपुलता के साथ उन महान विषयों को आगे बढ़ाया है जिन्हें उस समय महज सामान्य सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया जा सका था।

15 अगस्त 1947 को भारत का आजाद होना, जो शुरू में तो ब्रिटिश डोमिनियन रहा पर बाद में 26 जून 1950 को जिसने भारतीय गणराज्य की घोषणा की, विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और भारतीय जनता के कई पीढ़ियों के सघर्ष का फल था। यह विजय फासीवाद के विरुद्ध सोवियत संघ की अगुवाई में विश्व की जनता के मुक्ति मोर्चों की 1945 की जीत के बाद, विश्व भर में राष्ट्रीय मुक्ति, समाजवाद और जनता की प्रगति की सबसे पहली विजय थी। इसके बाद ही 1949 में चीनी जनता की क्रांति की सफलता ने पुराने उपनिवेशवाद पर मरणातक प्रहार किया और विश्वमनुलन में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ।

चिंतु भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद साम्राज्यवाद द्वारा अपन प्रभाव का झुंटेमाल करने और आजाद भारत में शोषण के अपने हितों की रक्षा करने की कोशिशें समाप्त नहीं हुईं। इसकी वजह 1947 के समझौते की तत्कालीन विशिष्टताओं में आ गई थी जिसे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के मागदर्शन में तैयार किया गया था। इसमें उम्र जबदस्त सांप्रदायिक फूट का पायदा उठाया गया जिससे ब्रिटिश साम्राज्य पाश्चात्त्य हमेशा प्रोत्साहित किया और स्वाधीनता की मांगों का दो स्वतंत्र दशा, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत के विभाजन के साथ जोड़ दिया गया।

1947 का माउंटबेटन समझौता, जिसने भारतीय स्वाधीनता की मांगता को वैधानिक स्वरूप दिया, दरअसल साम्राज्यवाद तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उच्च नेतृत्व वगैरे बीच हुआ एक सुलह समझौता था जिसके लिए लोकप्रिय जनक्रांति की आशंका के बारे में मतभेदों के बावजूद दोनों पक्षों ने कुछ सवमाय आधार ढूँढ लिए थे। परंपरागत सरकारी मिय के विपरीत भारत और पाकिस्तान को प्राप्त आजादी न तो गांधीवादी तरीके की जीत थी और न ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा दिया गया यह कोई स्वायत्त 'उपहार' ही था।

यह अहिंसा की विजय नहीं थी। 1946 के जनविद्रोह ने जिसमें रायल इंडियन नैवी के लोगो ने विद्रोह करके यूनिन जैक के स्थान पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लाल झंडा तीनों की संयुक्त पताका फहराई और इस विद्रोह की गंभीरता से लोगों को अवगत कराया, तथा सेना की अय इकाइयों में इसी तरह की घटनाओं तथा जबरदस्त हड़तालों और सड़कों पर चल रहे युद्ध ने साम्राज्यवादियों को तेजी से पीछे हटने को मजबूर किया। 19 फरवरी 1946 का लाड एटली का घोषणापत्र, जिसमें भारत के मबंध में एक नए दृष्टिकोण का एलान किया गया था और जिसमें भारतीय स्वशासन के सिलसिले में बातचीत शुरू करने के फैसले की घोषणा की गई थी, 18 फरवरी के नौसैनिक विद्रोह के ठीक एक दिन के भीतर आया। लेकिन इस विख्यात विजय का नेतृत्व कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस के पहले के 'अहिंसात्मक' अभियानों में, जो सारे के सारे घुरी तरह विफल हो गए थे, और इस विद्रोह में वही कोई समानता नहीं थी। उल्टे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतागण इस जनविद्रोह से घुरी तरह भयभीत थे। वे इस विद्रोह पर काबू पाने के लिए रोजाना ब्रिटिश कमांडर इन चीफ और ब्रिटिश अधिकारियों से सलाह मशविरा करते थे। उन्होंने सावजनिक रूप से इसे अहिंसा के विरुद्ध पाप कह कर और एक अपवित्र किस्म की हिंदू मुस्लिम एकता का नाम देकर इस विद्रोह की भत्सना की तथा सैनिकों को आत्म-समर्पण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। इस प्रकार वह लंबी बातचीत शुरू हुई जिसके फलस्वरूप अगस्त 1947 का सुलह समझौता हुआ। लोकप्रिय क्रांतिकारी लहर की विफलता, नेतृत्व द्वारा इकार करने से और यहां तक कि राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के विरोधी रवैये से पैदा हुई थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का दौर होने के बावजूद वही कोई पर्याप्त विवसित वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व काम करने की स्थिति में नहीं था। इन कमियों के कारण जनता की क्रांतिकारी शक्तियां घृणित सांप्रदायिक नरसंहार में लग गई। इसे उस लंबी बातचीत द्वारा काफी तीव्रता मिल गई थी जिसमें घोषित रूप से सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे की तैयारी हो रही थी और इस बातचीत का समूचा स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक था। इस प्रकार 1946-47 के क्रांतिकारी विप्लव का लाभ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उच्च बुर्जुआ नेतृत्व को मिला हालांकि इस नेतृत्व न व्यवहार रूप में क्रांतिकारी लहर का विरोध किया था और साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठ सहयोग किया था। स्वतंत्रता के प्रारंभ के इस परस्पर विरोधी स्वरूप की तह में अनेक कठिनाइयां दबी पड़ी थीं जो बाद के वर्षों में उभर कर सामने आईं।



स्वतंत्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा दी गई भेंट भी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने तर्कों को बड़े साफ शब्दों में फ्रिप्स ने 5 मार्च 1947 को पार्लियामेंट में पेश किया था

हमारे सामने कौन से विकल्प थे ? बुनियादी तौर पर हमारे सामने दो विकल्प थे। पहला यह था कि हम विदेश मंत्रालय की सेवा में और अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करके तथा ब्रिटिश सेना को उल्लेखनीय ढंग से मजबूत बनाकर भारत में ब्रिटिश शासन को दृढ़ बनाने की कोशिश करते।

इस नीति के साथ यह निणय लेना आवश्यक हो जाता है कि हम कम से कम 15 से 20 वर्षों तक भारत में बने रहना चाहिए। दूसरा विकल्प यह था कि हम इस सच्चाई को मान लें कि पहला विकल्प संभव नहीं था।

इस प्रकार 'दोनों विकल्प' यथार्थ रूप में केवल एक थे क्योंकि 'ब्रिटिश सेना को उल्लेखनीय ढंग से मजबूत' बनाना संभव नहीं था जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बने रहने के लिए आवश्यक था। यह वही ब्रिटिश सरकार थी जिसने 60 लाख मृत्युएं लागा के दमन के लिए ब्रिटिश सैनिकों का भेजने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जनता के मुक्ति आंदोलनों को विफल करने के लिए वर्षों तक अत्यंत बुरा युद्ध का संचालन किया। लेकिन जहां तक भारत की 40 करोड़ की आबादी का प्रश्न था, सेना तक लोकप्रिय विद्रोह के फैल जाने के बाद ब्रिटिश सरकार के सामने इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वह भारत से अपना शासन समाप्त कर ले और राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च ढंग के साथ जहां तक संभव हो अच्छे से अच्छा समझौता कर ले। इसी प्रकार भारत में लाड माउंटबेटन के सेनापति लाड इस्मैन अनिवार्य रूप से भारत से चले जाने का अपना फैसला दिया। (इसका उल्लेख एलेन कैंपबेल जासन की पुस्तक 'मिशन विद माउंटबेटन' में मिलता है।)

मार्च 1947 में भारत, समुद्र के बीच में खड़े एक ऐसे जहाज की तरह था जिसमें आग लग गई हो और जिसके खाव पर हथियार लदे पड़े हों, उस समय तात्कालिक मसला हथियारों तक आग को पहुंचने से पहले ही बुझा देना था। दरअसल, हमने जो कुछ किया उसके अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं था।

साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय बुजुर्गों दोनों का हित इसी में था कि लोकप्रिय जनक्रांति को रोका जाए और इन दोनों के बीच एक सौदे के रूप में माउंटबेटन समझौते के सुलहवादी चरित्र ने अनिवार्य रूप से उपलब्ध स्वाधीनता के स्वरूप और शर्तों का प्रारंभ में ही गंभीर रूप से परीक्षण कर दिया। इस बात में संदेह की गुंजाइश नहीं है कि गांधी ने इस समझौते का यह कहकर नामजूर कर दिया कि वह (समझौता) स्वराज्य की उनकी धारणा के अनुकूल नहीं है। उनके जीवनी लेखक ने अगस्त 1947 के हॉपिंग्सपूर्ण

समारोहों में उनके भाग लेने से इन्कार करने का जिन्न किया है

देश भर में समारोह मनाए जा रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसकी भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में किसी से भी ज्यादा भूमिका थी, इन समारोहों में हिस्सा नहीं लिया। जब भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग का एक अधिकारी गांधी के पास उनके सदेश के लिए आया तो गांधी ने जवाब दिया कि 'मैंने मैदान छोड़ दिया है।' जब उनसे फिर कहा गया कि उनका कोई सदेश नहीं देना अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने जवाब दिया 'मुझे कुछ भी सदेश नहीं देना है। यदि ऐसा करना बुरा है तो होता रह।' (डी० जी० तेंदुलकर 'महात्मा लाइफ आफ मोहनदास करमचंद गांधी', खंड 8, पृष्ठ 95-96)।

अपनी हत्या के चार दिन पूर्व, 1948 के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने इन शब्दों में अपनी मोहभंग की स्थिति का वर्णन किया

'26 जनवरी का यह दिन स्वाधीनता दिवस है। इस दिवस को मनाना उस समय काफी उपयुक्त था जब हम उस स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसे न हमने देखा था और न जिसका संचालन किया था। अब हमने इसका संचालन कर लिया और हमारा मोह भंग हो गया। कम से कम मेरी तो यही स्थिति है, आपकी चाहे हा या न हो।' (वही, खंड 8, पृष्ठ 333)

इस मुलह समझौते के लिए चुकाई गई कीमतों में सबसे बड़ी कीमत भारत के विभाजन के रूप में अदा करनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान ने नाम से दो प्रभुसत्तासंपन्न राज्यों की स्थापना करके भारत का बंटवारा कर दिया गया। यह बंटवारा राष्ट्रीयता पर नहीं बल्कि धर्म पर आधारित था जिसे राष्ट्रीयता के समतुल्य माना गया था। चूंकि इससे सबद्वे दोना धर्मों के लोग यानी हिंदू और मुसलमान व्यवहार रूप में भारत के प्रत्येक हिस्से में घुले मिले थे, इसलिए इस बंटवारे का काम बहद कृत्रिम सीमाएं खींचकर ही करना पड़ा (पाकिस्तान का निर्माण दो पृथक हिस्सों में करना पड़ा जिसके बीच भारत का हजारों मील का क्षेत्र पड़ता था)। इसके परिणामस्वरूप भारी सट्टा में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना पड़ा, खून खराबा हुआ, सांप्रदायिक हत्याएं हुई और बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना पड़ा। दोनों देशों के बीच चिरकालिक संघर्ष ने समूचे अनुवर्ती वर्षों के दौरान दोनों का कमजोर बनाया, उनके बजट को सैनिक खर्च पर लगाया और साम्राज्यवादी घुसपैठ को आसान बनाया। शुरू के दिनों में ही, जब अभी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का नियंत्रण ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कर रहे थे, काश्मीर के प्रश्न पर दोनों देशों के बीच इस संघर्ष ने वाकामेदा युद्ध का रूप धारण कर लिया। लगभग दो दशक बाद 1965 में फिर दोनों देशों

के बीच वाक्यादा युद्ध हुआ और सोवियत सघ की मध्यस्थता के जरिए ही एक अस्थायी युद्ध विराम कायम हान में सफलता मिल सकी। जैसाकि आयरलैंड तथा ब्रिटिश उप-निवेशवादी शासन से निकले अनेक देशों के साथ हुआ, यहाँ भी विदा होते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने दश के बदवारे का अपना सुपरिचित उपहार दिया जिसके भयंकर परिणामों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की पूर्ति को एक जनता की प्रगति को कमजोर बनाया तथा दो नए राष्ट्रा के बीच परस्पर वैमनस्म और फूट का फायदा उठाने के लिए साम्राज्यवाद को सुविधाजनक अवसर दिया।

माउण्टबेटन समझौते के सुलहवादी चरित्र का एक और नकारात्मक परिणाम यह था कि नए राज्या को राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व के अधीन प्रभुसत्तासंपन्न और स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता तो दी गई फिर भी प्रारंभ में ही इन दोनों देशों को काफी हद तक पुराने साम्राज्यवादी शासन के सिलसिले के रूप में चित्रित किया गया। साम्राज्यवाद के समूचे प्रशासन तंत्र को ही लेकर आगे बढ़ाया गया, वही नौकरशाही और याय-पालिका तथा पुराने साम्राज्यवादी एजेंटों और चापलूसों की पुलिस, दमन के वही पुराने तरीके, पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली बर्षा, लाठी चार्ज, सभा करने पर प्रतिबंध, समाचारपत्रों पर प्रतिबंध या बिना आरोप लगाए अथवा मुकदमा चलाए लोगों को हिरासत में रखना। भारत में साम्राज्यवाद की विशाल संपत्ति—लागत पूँजी और वित्तीय हितों की उत्साहपूर्वक रक्षा की गई और साम्राज्यवादी शोषण का अविकल प्रवाह जारी रहा। प्रारंभ में सैनिक नियंत्रण व्यवहार रूप में साम्राज्यवादी हाई कमान के हाथों में ही रहा और दोनों देशों की सेनाओं के सेनाध्यक्ष, सैनिक सलाहकार तथा सैनिकों की सख्या में अफसरों के पदों पर अग्रज बने रहें। सैनिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण ब्रिटेन में दिया जाना जारी रहा। यहाँ तक कि शुरू में तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी सघ के प्रधान के रूप में अपने पुराने पद पर ही बना रहा और दोनों देशों के महत्वपूर्ण प्रांतों में भी ब्रिटिश गवर्नर अपना पद गभान रहे।

इस प्रारंभिक दौर में जुलाहा महंतकश वर्ग के और किसानों के असंतोष का जमन करने के लिए जबरदस्त हमला किया गया। 1949 तक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बताया कि मजदूरों और किसानों में 25,000 नेता जेलों में पड़े हैं और इनमें से अधिकांश बिना किसी आरोप या मुकदमे के गिरफ्तार किए गए हैं। भारत की नई सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारों आँकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 1947 में 1 अगस्त 1950 तक यात्रा अपने गंतव्य में तीन वर्षों के अंदर उमकी पुलिस या सना न कम से कम 1982 यात्रा जनता के प्रत्याग पर गांधी चलाते 3 784 व्यक्तियों का भूत डाना और लगभग 10 000 व्यक्तियों का घायल किया 50 000 लोगों का जन के अंदर डाना और 82 कैदियों का जन के जेल गांधी मार दी गई।

फिर भी 1947 के गमगीत और पुनर्गठन साम्राज्यवादी सामन से काफी कुछ विरामन में

प्राप्त शासनतंत्र और शासन पद्धति वाली इस नई सरकार के नकारात्मक पहलुओं की वजह से हमें अनुकूल महती उपलब्धियाँ की अनदेखी नहीं कर देनी चाहिए। ये उपलब्धियाँ थी—जनतांत्रिक शक्ति के कुछ नियत कार्यों की पूर्ति, आंतरिक सुधार और आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का स्पातरण जिसका निष्पादन आजादी के बाद के 15 वर्षों में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के नतुत्व और खासतौर से प्रधानमंत्री नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत हुआ।

भारत की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राज्य और 1950 से एक गणराज्य के रूप में हुई। इसमें जुड़ी बातें थी, सावभौम मताधिकार, काय नपादन करने वाली एक ससद, नियमित चुनाव जिसमें तमाम पार्टियाँ भाग लेती हैं, और (विशेष अधिकारों तथा खासतौर से पुलिस कायवाहियों के पूर्व उल्लिखित नकारात्मक पहलुओं के बावजूद) वाक् स्वातंत्र्य, समाचारपत्रों, सभाओं और संगठन बनाने के अधिकारों का अपेक्षाकृत उच्च स्तर। कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी थे, केरल में जब एक कम्युनिस्ट सरकार निर्वाचित हुई तो 1959 में उसे केंद्र सरकार ने अपदस्थ कर दिया। लेकिन 40 करोड़ (अब 56 करोड़) की विशाल और विविध आबादी वाले किसी नवस्वाधीन एशियाई देश में, जहाँ का बहुमत अभी भी निरक्षर है, बुर्जुआ (पूँजीवादी) ससदीय जनतंत्र के काय का सामान्य तौर पर जो स्तर था, वह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पाकिस्तान का यह उपलब्धि नहीं मिली। वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के मुट्ठी भर समृद्ध बड़े जमींदार परिवारों और सरकारी और सैनिक उच्च अधिकारियों ने सभी जनतांत्रिक आकांक्षाओं को विफल कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को गुलाम दश की तरह रखा और उसका जमकर शोषण किया तथा कमजोर ससदीय संस्थाओं को समाप्त कर उनके स्थान पर शीघ्र ही निबद्ध सैनिक तानाशाही स्थापित कर दी।

शाही रियासतें, जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह के खिलाफ साम्राज्यवाद को मुख्य सहारा दिया था, तत्काल ही भारत और पाकिस्तान दोनों जगह प्रभुसत्तासपन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भग कर दी गई और राज्य के सामान्य ढाँचे में शामिल कर ली गई हालाँकि राजा महाराजों को अपनी पदवी धारण किए रहने की अनुमति दे दी गई, उन्हें भारी मात्रा में राजस्व प्रदान किया गया, और इस आधार पर वे बाद में प्रतिक्रियावादी राजनीतिक भूमिका निभाने में समर्थ हो सके, इसका उदाहरण भारत की स्वतंत्र पार्टी की भूमिका है।

भारत में नागरिक अधिकारों के दायरे में जाति के आधार पर भेदभाव का कानूनी तौर से उन्मूलन शामिल किया गया जो खासतौर से उन लाखों करोड़ों 'अछूतों' के प्रति भेदभाव बरत जान के बारे में था जिनपर दकियानूस हिंदू व्यवस्था ने यह थोप दिया था। हालाँकि भारत के अनेक हिस्सों में अधिकारों की इस कानूनी मान्यता का पालन नहीं हुआ।

कृषि संबंधी सुधार के उपाय अपनाए गए जिनसे भूमि संबंधी संकट का समाधान या

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो नहीं हुआ और न जोतने वाले को जमीन ही मिली पर ब्रिटन द्वारा स्थापित बड़े जमींदारों और जागीरदारों की व्यापक जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। फिर भी कानून में भरपूर बचाव का रास्ता होने की वजह से जिन जमींदारों और उनके परिवारों की मर्ति ले ली गई थी, वे उल्लेखनीय सीमा तक अपनी जागीर बचाए रखने में समर्थ हो सके। इसके अलावा मुआवजे की राशि बहुत अधिक योप दिए जाने से केवल धनी या मध्यम दर्जे के किसानों को ही भूमि के व्यापक वितरण का लाभ मिल सका और गांव की उस गरीब जनता को जिनके पास केवल अपने गुजारे भर की जमीन थी और जो मुस्तकिल रूप से कृषि में दबी थी तथा लाखों-करोड़ों भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कोई राहत न मिल सकी। सातवें दशक के पूर्वार्ध के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गांवों में 36 प्रतिशत परिवारों के पास कुल खेती योग्य जमीन का 36 प्रतिशत और शेष एक चौथाई परिवार के पास कुल 84 प्रतिशत हिस्सा था। गुनार मिरडल ने अपनी कृति 'एशियन ड्रामा' (3 खंडों में, एलेन लेन 1968) में 1965 में भारत के बारे में लिख रहे एक अमरीकी विशेषज्ञ का उद्धरण दिया है 'हालांकि अमर उपादान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक जमीन पर काम करने वाले उस जमीन के मालिक नहीं बनते या कम से कम उन्हें वास्तविक रूप में सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक सारी बातें व्यर्थ ही साबित होगी।

अपने विस्तृत विश्लेषण में मिरडल ने दिखाया है कि किस प्रकार महंगे आधुनिक रासायनिक और वैज्ञानिक उपकरणों की शुरुआत से, जिसे केवल अच्छे खाते-पीते किसान ही खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और की गई है, तथा किस प्रकार सुधार सबंधी तमाम उपायों ने सरकार और वर्तमान वगैरह सबंधों को सहारा देने के लिए समृद्ध किसानों का एक स्तर तैयार कर राजनीतिक मकसद तो पूरा किया है लेकिन इन उपायों ने कृषि सबंधी संकट की वास्तविक समस्याएँ हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इन उपायों की तुलना जार के शासनकाल में स्तालिनपिन द्वारा किए गए कृषि सबंधी सुधारों से करना प्रासंगिक होगा। स्तालिनपिन के सुधारों का भी उद्देश्य वर्तमान शासन को एक सामाजिक आधार देने के लिए समृद्ध किसानों का एक ठोस वर्ग तैयार करना था लेकिन इन सुधारों से दिनोदिन गंभीर होता कृषि संकट रूढ़ न सका और अंततः इसका विस्फोट 1917 की क्रांति के रूप में हुआ।

आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग ने भारत में मौजूदा साम्राज्यवादी आर्थिक हिता की रक्षा करने तथा प्रारंभ में दम बर्षों तक राष्ट्रीयकरण न करने की गारंटी देकर विदेशी पूँजी का अपने देश में लगान के लिए आकर्षित करने की कोशिश के जरिए पुनर्निर्माण और उद्योगीकरण के व्यापक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का प्रयास किया। इसमें उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कोरिया युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए और इसमें मध्यस्थता करने के मयुक्त प्रयास के लिए 1950 में नहरू और स्तालिन के बीच पत्राचार हुआ। सावियत संघ के साथ इस सहयोग के आधार पर पंचवर्षीय योजना की पद्धति

अपनाई गई। बताया जाता है कि 1951 से 1966 के बीच की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल उत्पादन में 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक विकास के कार्य में मदद देने में सोवियत संध, साम्राज्यवाद से स्वतंत्र एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। 1955 में सोवियत संध ने पूरी तरह नया विशाल इस्पात कारखाना बनाकर उद्योगीकरण के काम में प्रत्यक्ष सहायता देने का सूत्रपात किया। साम्राज्यवाद ने ऐसा कोई विकास कार्य कभी नहीं किया था। सोवियत संध, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड ने विकासशील देशों में आधुनिक भारी इंजीनियरिंग कारखानों के विशालतम समूह के निर्माण में सहायता पहुंचाई। बाद के वर्षों में इस उदाहरण ने पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों को भी नए इस्पात कारखानों के निर्माण के लिए बाध्य किया और पश्चिमी जर्मनी तथा ब्रिटेन ने एक-एक कारखाना बनाया। इस्पात का उत्पादन 1950 में 15 लाख टन से बढ़कर 1964 में 65 लाख टन हो गया। इस अवधि में विद्युत शक्ति का उत्पादन भी दुगुना हो गया।

फिर भी पूंजीवाद के मूल आधार पर ध्यान दें तो इस आर्थिक प्रगति का एक नकारात्मक पहलू था। यह सही है कि दिसंबर 1954 के मसदीय प्रस्ताव और 1955 के अवाडी कांग्रेस प्रस्ताव में निधारित उद्देश्यों के अनुसार सरकार और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 'समाजवाद' या 'समाजवादी ढांचे का समाज' की स्थापना का सिद्धांत घोषित किया। लेकिन जैसा कि अत्यंत समृद्ध इजारेदार और कांग्रेस के मुख्य समर्थक घनश्यामदास विडला ने, 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस को अपना समर्थन दिए जाने के बारे में लिखा है उनके अनुसार

हमारा नारा जनतांत्रिक समाजवाद है। कोई भी नहीं जानता कि इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो प्रसारण में कहा है कि निजी क्षेत्र को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह काफी उत्साहवर्द्धक बात है।' (जी०डी० विडला, प्राब्लम्स आफ इंडिया टुडे—लंदन स्थित उच्चायोग के मुखपत्र 'इंडिया वीक्ली' के 10 मार्च 1966 के एक में प्रकाशित लेख)

दरअसल पूंजी का केंद्रीकरण तेजी से होता गया और बड़े इजारेदारों की 'यून सव्या' ने भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इसके साथ ही विदेशी पूंजी ने अपनी घुसपैठ और अनेक क्षेत्रों में पहले से ही अपनी प्रबल स्थिति का और मजबूत कर लिया और भारतीय इजारेदारों के साथ अपना मक भी विस्तार कर लिया। 1963 के प्रारंभिक दिनों में 'सैटरडे इवनिंग पोस्ट' को दी गई एक भेंट में नेहरू ने दावा किया ब्रिटेन की कपनिया ब्रिटिश के शासन के दिनों में कमाए गए मुनाफों की तुलना में आज ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। यहां तक कि सर बिमटन चर्चिल ने भी इस पर काफी मतोप प्रकट किया है।

अप्रैल 1968 में कांग्रेस 'फारेम फार सोशलिस्ट ऐक्शन' में अपने भाषण में नेहरू ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि समाज को शिक्षा के बावजूद भारत में धनी और गरीब वर्ग के बीच की खाई बढ़ती जा रही है

ऐसा लगता है कि विकास की प्रक्रिया का फायदा मुख्यतः उन्हें मिल रहा है जो इसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास अपेक्षाकृत अधिक साधन हैं। इसका नतीजा कुछ हद तक यह हो रहा है कि धनी व्यक्ति और समृद्ध होता जा रहा है जबकि गरीब लोग की स्थिति में कोई तबदीली नहीं आ रही है।

विदेशी सहायता पर निर्भरता काफी बढ़ गई और विदेशी सहायता का वर्तमान अंश पहले मिली सहायता के शुल्क को अदा करने में ही चुक गया। बेरोजगारी की संख्या पहली योजना की समाप्ति तक 53 लाख थी जो दूसरी योजना के अंत तक बढ़कर 71 लाख और तीसरी योजना के अंत तक बढ़कर 96 लाख हो गई। अनुमान है कि चौथी योजना की समाप्ति तक यह संख्या 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के बीच पहुंच जाएगी। 1962 तक भारतीय योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 'भारत की दो तिहाई जनता भुखमरी के विदु पर गुजारा कर रही है।' (स्टेटसमेंट, 29 जनवरी 1963)

प्रगति के उपायों को सामाजिक क्षेत्र, खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लागू करने के प्रयास किए गए। 1931 में कुल आबादी के 92 प्रतिशत लोग निरक्षर थे (जैसा कि इस पुस्तक में उल्लिखित है) लेकिन 1961 की जनगणना में बताया गया कि इस संख्या में कमी हुई है और अब केवल 76 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि हुई। मृत्यु दर में कमी हुई। यह 1931-41 में 31.2 व्यक्ति प्रति हजार से घट कर 1960 में अनुमानित 16.2 व्यक्ति प्रति हजार हो गई।

सबसे बढ़कर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विश्व के सदस्य में भारत की भूमिका का अत्यंत विशिष्ट रूपांतरण हुआ और इस काम का निष्पादन छठे दशक में नेहरू सरकार द्वारा किया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत का आविर्भाव एक अधिराज्य (डोमिनियन) के रूप में हुआ लेकिन प्रारंभ से ही उसने 'गुटनिरपेक्षता' की नीति को व्यक्त किया अर्थात् 'सैंटो' (प्रारंभ में वगदाद संधि) या सीटो (1954 में गठित) जिसमें पाकिस्तान शामिल हो गया जैसे वर्गीय साम्राज्यवादी गठबंधनों में वह नहीं शामिल होगा। 1950 में, जब भारत ने ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को तिरोहित करके गणराज्य की स्थापना की और ब्रिटिश सम्राज्ञी को केवल राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में भाव्यता दी, विश्वशांति के मद्देन में नई रचनात्मक भूमिका में भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। तथापि 1950 की गर्मियों में भारत सरकार ने मधुबन राष्ट्र में अमरीका के अवधानिक प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर कोरिया के विरुद्ध अमरीकी सैनिक आक्रमण का औचित्य ठहराया था। लेकिन इस स्थल से

पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के आक्रमण तथा एशियाई देशों के विनाश से जुड़ने के विरुद्ध भारत में लोकप्रिय होती भावना तथा 1949 में चीन जनवादी गणराज्य विजय के बाद एशिया में नए शक्ति संतुलन से भारतीय विदेश नीति के स्थिति निर्धारण में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

विश्वशांति के लिए भारत की सक्रिय भूमिका की शुरुआत जुलाई 1950 में नेहरू और स्टालिन के बीच हुए पत्राचार तथा कोरिया युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के साथ हुई। 1954 के दक्षिण पूर्व एशिया मक्दम, भारत ने हस्तक्षेप न करने और वियतनाम की जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनता के आधार पर शांति स्थापित करने के पक्ष में पांच बड़े राष्ट्रों का कोलंबो सम्मेलन आयोजित किया। जून 1954 में भारत और चीन की सरकारों ने 'पंचशील' या शांति के पांच सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के बारे में एक संयुक्त घोषणापत्र तैयार किया। अप्रैल 1955 में भारत सरकार और चीन सरकार ने मिलकर बाङ्गु में प्रथम अफ्रीका एशियाई सम्मेलन आयोजित किया जिसमें अफ्रीका और एशिया के 29 देशों ने भाग लिया। इसमें कुल डेढ़ अरब की संयुक्त आबादी वाली विश्व की आबादी के बहुमत का प्रतिनिधित्व हुआ और विश्वशांति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता के लक्ष्यों की घोषणा की गई। निश्चित रूप से यह विश्व के नए संतुलन का एक रहस्योद्घाटन था। 1955 की समाप्ति तक सोवियत नेताओं की भारत यात्रा से अभूतपूर्व जनउत्साह की चलक मिलती है। 1956 में भारत ने स्वयं युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति का सामाजिक रूप से विरोध किया। यह युद्ध अरब देशों की मुक्ति के खिलाफ इसराइल के साथ साठगांठ करके आगल फ्रांसीसी साम्राज्यवाद द्वारा संचालित था।

बाङ्गु सम्मेलन से उदघाटित नए विश्व संतुलन से पश्चिमी साम्राज्यवाद, खासतौर से ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद, चौंक पड़ा। उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और समाजवाद के पक्ष में तथा साम्राज्यवाद के विरोध में नवस्वाधीन देशों के उभरते समूह को नेतृत्व देने के लिए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले दो देशों, भारत और चीन के बीच मैत्री और सहयोग साम्राज्यवाद के भविष्य के लिए कितना घातक हो सकता है, इस मैत्री और सहयोग में उन्हें विश्व समाजवाद की अनिवार्य विजय का माग दिखाई पड़ा। इसलिए उनका समूचा प्रयास, भारत में प्रतिन्यायावादी इजारेदार शक्तियों के साथ मिलकर भारत और चीन सरकार की मैत्री को तोड़ने पर केंद्रित हो गया। इस उद्देश्य के लिए भारत-चीन सीमा समस्या का अनुचित लाभ उठाया गया तथा मैत्री और सहयोग के स्थान पर संघर्ष और युद्ध की स्थापित करने के लिए समूचे मामले को भड़काया गया।

1962 का भारत-चीन सीमा युद्ध एक अप्रिय घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यमों में तथा भारत में इसके हानिप्रद नतीजे हुए। व्यवहार रूप में यह युद्धविराम के साथ समाप्त



हुआ पर कोई समझौता न हो सका। फिर भी, पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों और भारत में बड़े व्यापारी वर्ग के बीच उनके प्रतिस्पर्धावादी सहयोगिता का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया, उन्होंने अपने निजी हितों के लिए इस मसले का अनुचित लाभ उठाया। भारत सरकार और चीन सरकार के बीच मैत्री और सहयोग समाप्त हो गया और उसका स्थान मघप ने ले लिया। अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। भारत के अंदर वामपंथी प्रगति को रूकावट का सामना करना पड़ा और अराष्ट्रवाद के उन्माद की लहर चल पड़ी। वामपंथी आंदोलन छिन मिलन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया, अनेक लोग जेलों में डाल दिए गए और बाद के वर्षों में इस विभाजन ने फूट का रूप ले लिया। मतिमंडल में नेहरू के प्रमुख वामपंथी सहयोगी रक्षामंत्री कृष्ण मेनन के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया और उन्हें मतिमंडल से निकाल दिया गया। दरअसल उन्हें सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने में भी वंचित कर दिया गया। 1969 में पश्चिम बंगाल में वे संयुक्त मोर्चे की मदद से निदलीय सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर सदन में आ सके। यह दक्षिणपंथी अभियान नेहरू के भी विरुद्ध दिशा लेने लगा था पर इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार नेहरू के अंतिम दिना पर अग्रिय अनुभवों के बादल छाए थे ब्राडुग के उत्साह का स्थान चीन के साथ हुए मघप ने ले लिया, गुटनिरपक्ष राष्ट्रीय के बीच भारत की प्रतिष्ठा और नेतृत्व कमजोर पड़ गया और सीमा के प्रश्न पर इनसे से अधिकांश ने भारत को अपना समर्थन नहीं दिया, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में साम्राज्यवादी घुसपैठ बढ़ती गई। साथ ही विदेशी ऋणदाताओं ने 'सहायता संधि' (कसाटिसम) बनाकर खुलेआम सरकार की नीति को प्रभावित करने का दावा किया, आर्थिक ह्रास होता गया बेराज गारा की समस्या में तेजी से वृद्धि हुई और आम जनता की हालत बदतर होती गई, स्वयं कांग्रेस संगठन के अंदर गुटबाजी और भ्रष्टाचार पनपने लगा तथा दक्षिणपंथी प्रतिस्पर्धावादी शक्तियों की चुनौती बढ़ती गई। राष्ट्रीय पंजीपति वर्ग के नेतृत्व के अंतर्गत अनुकूल उपनिवेश की संभावनाएं भरपूर ढंग से नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के सफल वर्षों में महसूस कर ली गई थी। उनकी सीमाओं और उनके नकारात्मक पहलुओं का अर्थ तेजी में अनुभव किया जा रहा था। स्थितियाँ एक नए युग के लिए तैयार हो रही थी और इसके लिए भारतीय जनता के एक नए प्रयास की आवश्यकता थी।

1964 में नेहरू के निधन के बाद आर्थिक स्थिति में तथा कांग्रेस से संबद्ध पुरानी सत्ता रूढ़ मस्वाभा में और भी तेजी से गिरावट आई। विदेशी सहायता पर बढ़ती निर्भरता, घाट का बजट, मुद्रास्फीति, खाद्यान्न का भारी मात्रा में आयात, उत्पादन की गति में धीमापन तेजी में बढ़ती बेरोजगारी, सामाजिक भ्रष्टाचार में गिरावट और आम जनता के उपभोक्ता स्तर का गिरावट जाना इन सारी बातों में संकेत मिलना था कि भारत अत्यंत गंभीर स्थिति में प्रवेश कर रहा है और ये स्थितियाँ जनता की व्यापक हस्तक्षेप का नेतृत्व करेंगी तथा इनके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव होंगे।

सरकारी तालिका में दज औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 1960 में 11 प्रतिशत से घटकर 1964 में 7 प्रतिशत, 1965 में 5.4 प्रतिशत और 1966 में 2.5 प्रतिशत हो गई। नेहरू ने अपने अंतिम दिना में इसपर खेद प्रकट ही किया था कि धनी और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। 1953-57 और 1960-61 के बीच आय के वितरण के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक सर्वेक्षण से पता चला कि इस अवधि के दौरान आबादी के सर्वोच्च 10 प्रतिशत लोगों की राष्ट्रीय आय में 28 से 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि निम्न आयवर्ग के 40 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी में 20 से 13 प्रतिशत की कमी हुई है। इंडियन लेबर जनल द्वारा अंकित वास्तविक आय तालिका (1951 को 100 मानकर) देखने में पता चलता है कि 1956 में यह 115.4 थी जो 1960 में 113.8 और 1964 में 104.1 हो गई। खाद्यान्नों की वार्षिक खपत 1961-62 में 375 पौंड प्रति व्यक्ति से घटकर 1966-67 में 233 पौंड प्रति व्यक्ति हो गई। 1961-62 में प्रति व्यक्ति 16.2 गज सूती कपड़ा इस्तेमाल हुआ, 1966-67 में यह घटकर 15.1 गज हो गया।

जून 1966 में रुपये का अवमूल्यन हुआ जिसने पहले से ही चली जा रही ह्रासोन्मुख स्थिति पर जबरदस्त प्रहार किया। यह अवमूल्यन आवश्यक रूप से  $36\frac{1}{2}$  प्रतिशत की ऊंची दर से हुआ। इसके फलस्वरूप पौंड की विनिमय दर 13 रुपये से बढ़कर 21 रुपये हो गई। यह जबरदस्त अवमूल्यन अमरीकी साहूकार (बैंकरो) के दबाव से किया गया था जिन्हें विश्वबैंक द्वारा खुलेआम स्वर दिया गया था। इसके नतीजे विध्वंसकारी थे। चूंकि अब भी भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चीजों में मुख्यतया प्राथमिक वस्तुएं (प्राइमरी कमाडिटी) थीं जिनसे विश्व बाजार पहले से ही भरा पड़ा था इसलिए भारतीय निर्यात को कोई उल्लेखनीय प्रतिसतुलनकारी लाभ नहीं मिला। लेकिन निर्यात की बढ़ती हुई लागत काफी थी और इसकी अभिव्यक्ति कीमतों में बेतहाशा वृद्धि तथा मुद्रास्फीति में हुई जिससे फलस्वरूप पहले से ही भुखमरी की स्थिति में गुजर कर रही आम जनता पर और भी भार पड़ा। अवमूल्यन के जरिए विदेशी ऋण पर व्याज और चुकोती की दर बढ़कर 13 अरब 69 करोड़ रुपये या 65 करोड़ पौंड हो गई।

भारतीय स्थिति की इन कठिनाइयों का फायदा उठाने के लिए पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों और खासकर अमरीकी सरकार तथा अमरीकी साहूकार (बैंक्स) ने अपना फंदा और बस दिया। 'सहायता' के नाम पर अधिक से अधिक खगोलीय आकृतियों को थोड़ा थोड़ा करके बांटा गया जो व्यवहार में दानवर्ता के पास ही वापस पहुंच गया और उसे पहले की सहायता की दर पर भुगतान कहा गया। दरअसल हिसाब लगाने से पता चला कि कुछ ही वर्षों के अंदर व्याज और चुकोती की राशि कुल सहायता से अधिक हो जाएगी।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर, जो 1980-81 तक जाएगी, भारत को समूचे 15 वर्षों में लगभग 18 अरब डालर की विदेशी महायता की जरूरत पड़ेगी। इसी अवधि के दौरान भुगतान की जाने वाली व्याज राशि और चुकोती

राशि 14 अरब डालर हो जाएगी। वस्तुतः 1975 के बाद सभावित चुकोती राशि पूँजी के सभावित अतर्वाह को पोछे छोड़ देगी।' (इकनोमिस्ट, 8 अप्रैल 1967)

जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया शर्तें और कठोर हो गईं अमरीकी उत्पादन के मानदंडों (भारत जिसे दबाव कहता है), जो भविष्य में सहायता सवधी वायदों को संचालित करेंगे भारतीय और विदेशी निजी उद्योगों की और बड़ी भूमिका, अपेक्षाकृत कम नियंत्रण, अमरीकी (और विश्ववैक) निर्धारणों के अनुरूप आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने की इच्छा की बात खुलकर करता रहा है। ('दि टाइम्स' के वाशिंगटन सवाददाता की टिप्पणी, 3 मई 1966)

इसी प्रकार 'टाइम्स' के वाशिंगटन स्थित सवाददाता ने लिखा कि 'अमरीका को अब इस बात की चिंता नहीं है कि वह जबरदस्त दबाव के होने की बात का खडन करे।' उक्त सवाददाता ने अपने लेख में भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निजी पूँजी के स्थान पर और वतमान कानून एवं नियंत्रणों में परवर्ती सशोधन की बात पर विशेष बल दिया। अमरीकी कांग्रेस ने कुख्यात फूड ऐक्ट पी० एल०-480 को भारत में अमरीकी उद्देश्यों के लिए उपलब्ध पूरक राशि की सुविधा के साथ स्वीकार करके कानून में निश्चित रूप से यह बात शामिल कर दी कि इसका लक्ष्य भारत में 'निजी उद्योग और पूँजीनिवेश के लिए अनुकूल वातावरण' तैयार करना होना चाहिए।

यह वह स्थिति थी जिसने वतमान शासन और कांग्रेस सरकार के विरुद्ध तेज होते जन विद्रोह को जन्म दिया जो 1967 के आम चुनाव के समय बहुत स्पष्ट रूप में सामने आ गया। जनता के अंदर काफी दिनों से गुस्सा दबा पड़ा था और विगत 12 महीना में लगातार हो रही आम हड़तालों सामूहिक रूप से काम बंद करने, ससद तक जुलूस ले जाने और विशाल प्रदर्शनों तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ों में इस गुस्से की अभिव्यक्ति हो चुकी थी। इसी अभिव्यक्ति को 1967 के आम चुनाव में और भी प्रकट होने का अवसर मिला और जनता ने अनेक कांग्रेस मंत्रियों और नेताओं का चुनाव में सफाया कर दिया तथा कई स्थानों पर कांग्रेस के बहुमत को समाप्त कर दिया। लोगों के गुस्से की यह अभिव्यक्ति चुनाव सवधी ससदीय प्रतिनिधित्व के मसले पर आशिक रूप से भटकाव में पड़ गई क्योंकि इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई और उसके टुकड़े हो गए। इससे पहले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा दूसरा स्थान मिलता रहा था और उसे लोग इन रूप में मानने लगे थे कि वह कांग्रेस को चुनौती दे सकती है और भविष्य में कांग्रेस का विवल्प प्रस्तुत कर सकती है। पार्टी में फूट पड़ जाने में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी गण्युक्त वामपंथी शक्ति नहीं बच रही जा एक साथ मिलकर जनता की मांगा की और उनके विद्रोह का आग बढ़ाने में शक्तिशाली भूमिका अदा कर सके। फलस्वरूप इस

फूट से विभिन्न दलों ने लाभ उठाया हालांकि कांग्रेस की भूतपूर्व एकाधिकारी स्थिति से वामपथ की तरफ झुकाव देखा गया हाताकि यह झुकाव भी एकजुटता के साथ नहीं था। लेकिन कुछ अर्थ राज्यों में अपेक्षाकृत नई दक्षिणपथी पार्टियों के पक्ष में झुकाव की घटनाएं मुख्य रूप से सामने आईं। इन विविध नतीजों से कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला कि किसी एक संयुक्त वामपथी दल के अभाव में मतदाताओं ने उस पार्टी को समर्थन देना शुरू किया जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वह कांग्रेस के एकाधिकारपूर्ण प्रभुत्व को समाप्त करने में प्रभावशाली होगी। पहले के चुनाव समझौता के आधार पर जहां संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, जैसे कि केरल में, वहां उच्च पूरी तरह सफलता मिली। 1969 के मध्यावधि चुनाव में यह बात पश्चिमी बंगाल में बहुत खुलकर सामने आई। इस अनुभव ने प्रगति के भावी पथ का संकेत दिया और लोगों ने यह महसूस किया कि यदि वामपथी एकता हो तो यह प्रगति उपलब्ध की जा सकती है।

कम्युनिस्ट पार्टी का दो दलों में (बाद में तीन दलों में) अस्थाई विघटन वामपथी एकता की प्रगति के माग में सबसे गंभीर बाधा बना। इसकी वजह यह थी कि कम्युनिस्टों की सट्टा अर्थ वामपथी दलों के सदस्यों की संख्या की तुलना में सबसे ज्यादा थी और वे सबसे अधिक शक्तिशाली थे। 1967 के आम चुनाव में दोनों दलों के मिलेजुले कम्युनिस्ट सदस्यों की कुल संख्या 44 थी जबकि 1962 के चुनाव में इनकी संख्या 30 ही थी। इससे यह पता चलता है कि यदि पार्टी में फूट नहीं पड़ी होती तो कम्युनिस्टों का स्थान अब भी कांग्रेस के बाद पहले नंबर पर होता। लेकिन बटवारा होने के परिणामस्वरूप दक्षिणपथी दल स्वतंत्र पार्टी को दूसरा स्थान मिला। इसके सदस्यों की संख्या 18 से बढ़कर 42 हो गई और इस प्रकार इसे आधिकारिक तौर पर विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। इसके बाद दूसरी मुख्य प्रतिक्रियावादी पार्टी जनसंघ का स्थान रहा और इसके सदस्यों की संख्या 14 से बढ़कर 35 हो गई। ऐसे समय में, जबकि, अब तक की प्रबल कांग्रेस नीतियों के विरुद्ध व्यापक अनंतोष से एक नई दिशा की मांग जोर पकड़ती जा रही थी, दक्षिणपथी प्रतिक्रियावाद की यह प्रगति सभावित खतरे का सूचक थी। दो प्रमुख दक्षिणपथी पार्टियों, स्वतंत्र और जनसंघ को कुल 3 करोड़ वोट मिले जबकि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को प्राप्त मतों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख थी।

ये दक्षिणपथी पार्टियां, पुरानी दक्षिणानुस प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करती थी और ये अपेक्षाकृत नई पार्टियां थी जिनका उद्देश्य कांग्रेस के विघटन से फायदा उठाना था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई और इसकी स्थापना कांग्रेस के उन अत्यंत दक्षिणानुस तत्वों ने की थी जो कांग्रेस द्वारा घोषित 'समाजवाद' के कार्यक्रम और मावजिक क्षेत्र पर बल दिए जाने से असंतुष्ट थे। इस पार्टी को इजारेदारों का समर्थन प्राप्त था जिनकी साठगाठ पुराने सामंती राजाओं के साथ थी। इन महाराजाओं और महारानियों ने पिछड़े क्षेत्रों की अपनी भूतपूर्व शासित जनता में चुनाव में खुद वोट लेने के लिए फिर अपना सर उठाना शुरू कर दिया। यह पार्टी अत्याधुनिक अमरीका प्रशासन बड़े व्यापारियों

और अति पुरातन फैशनेबुल राजकुमारों का सहो अर्थों में एक रुढ़िवादी संगठन थी। जनसंघ ने पुराने प्रतिप्रियावादी हिंदू सांप्रदायिकता के ताजा नतीजा का प्रतिनिधित्व किया। जनता में फूट डालने के लिए साम्राज्यवादियों ने इस प्रवृत्ति का काफी बढ़ावा दिया था। सांप्रदायिक आतंकवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर, जिसके सदस्य गोडसे ने गांधी की हत्या की, जब 1948 में प्रतिबंध लगाया गया तो इसके राजनीतिक बाजू हिंदू महासभा की काफी बढ़नामी हुई। 1951 में जनसंघ की स्थापना उन्हीं लोगों ने की जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। इसके कार्यक्रम में जो बातें शामिल थी वे थी अंध देशभक्ति (हारे हुए क्षेत्रों को वापस लेना)', सेना का विस्तार, परमाणु हथियारों का शस्त्रीकरण। साधुओं के सांप्रदायिकतावादी जनोत्तेजक प्रदर्शनों का आयोजन और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए (इस नारे की गांधी ने काफी पहले भ्रमना की थी) संघीय कानून की मांग। साथ में सावजनिक क्षेत्र को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक मांग भी शामिल थी 'राज्य द्वारा अनावश्यक दखलदाजी किए बगैर निजी उद्योग को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।'।

दक्षिणपथ के आक्रामक खतरे को देखते हुए हाल के वर्षों में वामपंथी एकता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और लोकप्रिय जनतांत्रिक शक्तियों में एकजुटता आई है। राज्यों के महत्वपूर्ण चुनावों में संयुक्त मोर्चे की सफलताएं मिली और संयुक्त मोर्चा सरकारों की स्थापना हुई जिनमें दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों तथा कांग्रेस के अंदर के जनतांत्रिक तत्वों ने भाग लिया। इसके बाद 1969 के ग्रीष्म में कांग्रेस सरकार की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'सिंडीकेट' या पुरानी कांग्रेस के मस्थापित प्रतिक्रियावादी नेताओं की खुलेआम अवहेलना करके 14 बकों का राष्ट्रीयकरण किया और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के सावजनिक समर्थन तथा वामपंथ के जन आंदोलन के जरिए राष्ट्रपति गिरि का चुनाव कराया।

नई राजनीतिक मजिल की दिशा में व्यापक जनतांत्रिक प्रगति की ये शुरुआतें अब भी अनिश्चितता से भरी हैं और संक्रमण के इस अस्थिर दौर के खतरे स्पष्ट हैं। प्रतिप्रियावाद विभिन्न रूपों में जवाबी हमल की तैयारी कर रहा है। इन रूपों में प्रतिप्रियावादी पार्टियां और कांग्रेस के दक्षिणपंथी खेमे के एक वैकल्पिक गठजोड़ की योजना और यहाँ तक की जनतंत्र के मूल आधार के लिए खतरे का संकेत भी शामिल है।

भारत की जनता अब उठ चुकी है। भारत आज महान संघर्षों और दूरगामी रूपांतरणों के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। उस तूफानी अग्नि पराक्षाओं और चुनौतियों से होकर गुजरना है। अभी तक अपूर्ण भारतीय न्नाति तथा भारतीय जनता की आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति के सभी महान कार्य मजबूती के साथ जमत जा रहे हैं और व मौजूदा अस्थिर तथा तजी में बदलते संक्रमण काल और गंभीर राजनीतिक अंतर्विरोधों का रूपांकित कर रहे हैं। जनता की इस प्रगति के समानांतर ही दक्षिणपंथ का खतरा

भी चल रहा है। आर्थिक स्थिति, कृषि के क्षेत्र में संकट, व्यापक भूख और बेरोजगारी, समृद्धि और निधनता के बीच की बढ़ती खाई, ये सारी तात्कालिक समस्याएँ आज समाधान के लिए फरियाद कर रही हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन एवं सभी जनतांत्रिक तथा प्रगतिशील तत्वों की मिलीजुली ताकत से ही आम जनता को एकजुट किया जा सकता है ताकि वह अपने सामने खड़े खतरों को शिकस्त दे सके, अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता अख्तियार कर सके और आगामी कल के भारत का, मेहनतकों के भारत का निर्माण कर सके।

2 अक्टूबर 1969

रजनी पाम दत्त

4

## आधुनिक विश्व में भारत

मानवीय घटनाओं के क्रम में जब किसी एक जन समुदाय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन राजनीतिक बंधनों को रद्द कर दे जिसने उन्हें दूसरे से जोड़ा है और पृथ्वी की शक्तियों में से पृथक् और समान स्थान ग्रहण कर ले जिसके लिए प्रकृति के नियमों और प्रगति के नियमों ने उन्हें अधिकार दिया है तो मानव जाति के अभिमत को मर्यादित सम्मान देने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे उन कारणों की घोषणा करें जिन्होंने उन्हें पृथक् रहने के लिए प्रेरित किया है (अमरीकी स्वाधीनता की घोषणा)।

भारत का भविष्य आज विश्व राजनीति के समक्ष अनेक ज्वलंत प्रश्नों में से एक है। भारत की 40 करोड़ जनसंख्या, समूची मानव जाति का लगभग पाचवा हिस्सा है। पिछले दो सौ वर्षों से भारत की जनता विदेशी शासन के अधीन है। आज उस विदेशी शासन की समाप्ति की घड़ी नजदीक आ गई है।

विश्व स्तर पर देखें तो आधुनिक जगत में साम्राज्यवादी प्रभुत्व बने रहने का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है, भारत की गुलामी। सदियों से इस विशाल भूभाग की संपत्ति और स्रोत, यहां की जनता का जीवन और उसका धर्म, पश्चिमी पूंजीवाद की घुसपैठ, आक्रमण और विस्तार तथा अतंतु पूर्ण प्रभुत्व और जबरदस्त शोषण का लक्ष्य रहा है। इस व्यवस्था की समाप्ति संपूर्ण मानवजाति के पांचवें हिस्से के लिए मात्र एक नए भविष्य का सूत्रपात ही नहीं करेगी बल्कि वह विश्व सबंधों के सन्तुलन में निर्णायक परिवर्तन लाएगी। साथ ही वह साम्राज्यवाद की व्यवस्था को और कमजोर तथा समूचे



विश्व में जनता के स्वातंत्र्य सगम को और अधिक मजबूत भी करेगी। भारत की मुक्ति के साथ स्वतंत्र चीन का उदय, एशिया की जनता तथा अन्य सभी उपनिवेशों की जनता की मुक्ति का मांग प्रशस्त होगा।

आधुनिक विश्व की सभी समस्याओं और संघर्षों को भारत में अपना केंद्रबिंदु मिलता है। यहाँ आधुनिक विजेताओं के दुर्दम्य भार के नीचे पिस गई और निष्क्रिय हो गई प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेषों के बीच आदिम अथर्व्यवस्था, गरीबी और गुलामी के निकृष्ट-तम रूप के साथ साथ महाजनी पूँजी के शोषण का अत्याधुनिक स्वरूप भी मिलता है। यहाँ वृषि के क्षेत्र में गंभीर संकट तथा अकाल की स्थिति है, लोग वज्र का पैसा चुकता न कर पाने के कारण गुलामी करने पर मजबूर होते हैं, जाति और कुजाति की बेड़ियों में लोग जकड़े हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में असीम शोषण है तथा अमीर और गरीब के बीच इतनी चौड़ी खाई है जितनी विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी, सामाजिक एवं धार्मिक संघर्ष, वगैरह तथा भारत के अंदर उभरते राष्ट्रीय मसले, ये सारी समस्याएँ अपने अनेक पहलुओं में किसी गुलाम देश के पिछड़ेपन और अवरुद्ध विकास को प्रतिबिंबित करती हैं तथा विदेशी प्रभुत्व के दबाव के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति की मुख्य समस्या के साथ स्वयं को सामने लाती हैं और मुक्ति के लिए संघर्ष की स्थितियों को जटिल बनाती हैं।

भारत आज जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक शक्ति के युग में प्रवेश कर रहा है। इस शक्ति का पहला चरण होगा, विदेशी शासन से मुक्ति और पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति। लेकिन यह निवृत्त आती जा रही मुक्ति उन भीषण आंतरिक समस्याओं, सामाजिक तनावों और संघर्षों को सामने ला देगी जो सदियों के विदेशी प्रभुत्व के कारण इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है और जो आज समाधान के लिए फिर माद कर रहे हैं। भारत की जनता का आज राष्ट्रीय और सामाजिक पुनरुद्धार का महत्वपूर्ण पाप पूरा करना है।

## 1 स्वाधीनता की पूर्व संध्या में भारत

फासिस्ट शक्तियों पर मयुक्त राष्ट्र की विजय के फलस्वरूप नई विश्व परिस्थिति में भारतीय स्वातंत्रता के प्रश्न को विश्व राजनीति की अग्रिम पंक्ति में ला दिया है।

1914-18 के प्रथम विश्वयुद्ध ने और उसी अनुक्रम में विश्व भर में फैली जातिवादी तहलकें नये उपनिवेशों की तरह भारत में भी महान परिवर्तन के युग का सूत्रपात किया। 1919-22 में जबरदस्त जनसंघर्षों ने भारत का क्षयशील किया और 1930-34 में (विश्व आर्थिक संकट के बाद) जिसका मुख्य अधिक अंग भारत पर पड़ा) पहल से भी ज्यादा तेजी से राष्ट्र की गति रुकने लगी। ब्रिटिश शासन ने इस उपनत राष्ट्रीय आन्दोलन का मुकाबला सभी मुद्दों और सभी दमन के द्वारा करना चाहा। भावी स्वातंत्र्य के मायने

के साथ साविधानिय रियायते पेश की गई जिनसे वास्तविक मता सबधो में कोई तबदीली नहीं आई। इन साविधानिय रियायतो के फलस्वरूप 1937 में ग्यारह में से आठ प्रांता में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मन्त्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन इससे दिनोदिन बढ़ता असंतोष कम नहीं हुआ, उल्टे उसे और प्रोत्साहन मिला। 1939 में युद्ध छिड़ने के समय, जनता पर थोपने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे संघीय संविधान के विरुद्ध आजादी के लिए एक जबरदस्त संघर्ष का वातावरण बन चुका था। किसी सलाह मशविरे या जनता के अनुमोदन का दिखावा किए बिना युद्ध में भारत को घसीट लाने तथा आपात-कालीन युद्ध तानाशाही से शासकों और जनता के बीच की खाई और बढ़ी।

द्वितीय विश्व युद्ध से भारतीय मुक्ति के प्रश्न को नया महत्व मिला। संयुक्त राष्ट्र ने आधि-कारिक तौर पर अपने इस लक्ष्य की घोषणा की कि, 'प्रत्येक देश की जनता को अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार है।' प्रथम विश्वयुद्ध के विपरीत, संयुक्त राष्ट्र के संगठन ने चार बड़ी शक्तियों के नेतृत्व में एक संयुक्त निकाय का गठन किया जिसमें दो साम्राज्यवादी राष्ट्र ब्रिटेन और अमरीका के अलावा दो गैर साम्राज्यवादी शक्तियों, राष्ट्रवादी चीन और समाजवादी सोवियत संघ को शामिल किया गया। ममूची दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन फासीवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी विश्व परिस्थिति में भारतीय जनता भी पूरी शिद्दत के साथ उसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग करती जिसके लिए तमाम लोग संघर्ष कर रहे थे और जिसमें प्राणों की आहुति देने के लिए भारतीय सैनिकों को बुलाया जा रहा था।

एशिया में युद्ध की विशेष परिस्थितियों ने इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया। एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुत्व ने जब तक अपनी आत्मघाती मूलता के कारण जापानी आक्रमण और विस्तार का बढ़ावा दिया था, लेकिन वही आक्रमण जब पल हावर के बाद सीधे आगे बढ़ने लगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिल गई। प्राचीन उपनिवेशवादी व्यवस्था के दिवालियपन और भीतरी खोखलेपन की उस समय सबके सामने पोल खुल गई जब दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े बड़े इलाके लगभग बिना किसी प्रतिरोध के आक्रामकों के हाथ में आ गए। हा, कुछ स्थानों पर विदेशों से बुलाए गए सैनिकों ने उन इलाकों को बचाने का प्रयास किया पर उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि विदेशी शासक उस जनता को, जिसपर वे शासन करते थे, आदोक्षित करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुए।

इस रहस्योद्घाटन का भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन को अप-राजेय शक्ति मानने का भ्रम टूट ही गया। जापानी सैनिक आगे बढ़ते गए और उन्होंने भारत की सीमा का रोद डाला। धुरी शक्तियां ने भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बोस, जिन्होंने खुद का उनके हाथों में सौंप दिया था, और 'इंडियन नेशनल आर्मी' का बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया और अपने आक्रमण तथा विजय के इरादों पर इस ढोंग का

नकाब चढ़ा लिया कि वह भारत के लिए चिंतित है। स्वाधीन भारत के विरुद्ध इस तरह के प्रचार का कोई असर नहीं होता, लेकिन गुलाम भारत के मदभ में देखने से पता चलता है कि इस प्रकार के प्रचार का अनिवाय रूप से एक हृद तक असर पड़ा।

इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें केवल जनतंत्र के सिद्धांतों के लिए ही नहीं बल्कि भारत और संयुक्त राष्ट्र के समूचे युद्धस्थल की रक्षा के लिए भारतीय मुक्ति का बाय तेजी से हाना आवश्यक हो गया। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने दुनिया भर में फासिस्ट गठबंधन के खिलाफ जनतांत्रिक संघर्षों में शामिल लोगों के हित और भारत के हित को समान हित मान लिया था। उन्होंने उस समान हित को मायता दी, और ऐसे समय में भी जब ब्रिटेन के शासक फासिस्ट आक्रमण को मदद दे रहे थे और उसे सह दे रहे थे, उन्होंने फासीवाद का समर्थन करने वाली प्रतिक्रियावादी नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध किया। उन्होंने इस बात को मायता दी कि धुंगी राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के युद्ध में भारत का हित फासीवाद की पराजय और उस खेमे की विजय के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें राष्ट्रवादी चीन, समाजवादी सोवियत संघ तथा यूरोप के जनतांत्रिक मुक्ति आंदोलन शामिल हैं। लेकिन उन्होंने यह मांग की, जो बिल्कुल ठीक थी, कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और यह स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय सरकार के अधीन हो, साथ ही उसके पास पूर्ण और कारगर अधिकार होने चाहिए ताकि वह संयुक्त राष्ट्र के गठबंधन में स्वच्छा से बने भागीदार के रूप में भारतीय जनता की शक्ति को एकजुट कर सके। यह मांग संयुक्त राष्ट्र के हितों के अनुकूल थी। इसको संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के जनतांत्रिक मित्रधारियों वाली ने ही समर्थन नहीं दिया बल्कि ब्रिटेन के मित्रों, घास तौर में राष्ट्रपति रूजवेल्ट और माशेल च्यांग काई शेक, ने अपने अपने आधिकारिक श्रेणियों से इसका समर्थन किया।

बिना द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति भी भारत में आजादी नहीं ला पाई। ब्रिटेन में टोरीवाद (अनुदार दलीय सरकार) के दिन थे और टोरी शासकों ने भारत को आजादी देने के हर प्रस्ताव का दुराग्रहपूर्ण ढंग से विरोध किया। यहां तक कि युद्धकालीन स्थिति का देखत हुए किसी ऐसे अस्थायी समझौते के प्रस्ताव का भी उन्होंने विरोध किया जिसमें भारत के लोकप्रिय नेताओं के हाथ में प्रभावकारी सत्ता पहुंच सकती थी। चर्चिल का मूल वाक्य कि वे 'ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे' धनुरी और कठिनाइयों से भरे अत्यंत संघट्टपूर्ण दिनों में भी ब्रिटिश नीति को मंचानित करता रहा। 1942 का त्रिप्स समझौता भग्न हुआ। तत्कालीन परिस्थिति में उत्पन्न दुविधा में हताश और बिचरा हुआ राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के बाद पैदा हुए गतिराध के दण्डन में पम गया। भारत के राष्ट्रीय नेता जला में डाल दिए गए और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अनधिकारिक तौर पर जो छिटपुट आंदोलन हुए और उनमें जो अव्यवस्था पड़ी उस सामान्यी से दबा दिया गया। युद्ध के बाद भी भारत को हैमिंग गुलाम दण की ही रहा और राजनीतिक गतिराध की स्थिति बनी रही।

लेकिन फासीवाद पर संयुक्त राष्ट्र की विजय ने एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। समूची दुनिया में फासिस्ट शक्तियों की सैनिक पराजय और उनका पूरी तरह धराशायी होना 1917 के दिनों के बाद प्रतिक्रियावाद पर हुआ सर्वाधिक जबरदस्त प्रहार था। सभी देशों में जन आंदोलनों की लहर उमड़ पड़ी। साम्राज्यवाद बेहद कमजोर हो गया। जर्मन, इतालवी और जापानी साम्राज्यवाद का दुनिया के नक्शे से सफाया हो गया। बस केवल दो बड़े साम्राज्यवादी देश, ब्रिटेन और अमेरिका, बायम रह सके और इनके साथ फ्रांस, बेल्जियम, हालैंड और पुर्तगाल जैसे अधीनस्थ उपनिवेशवादी साम्राज्यों का अस्तित्व बना रह सका। यूरोप में नई जनतांत्रिक सरकारों ने उन पुरानी दक्खिनीय सरकारों का स्थान ले लिया जिन्होंने फासीवाद के समक्ष या तो आत्मसमर्पण कर दिया था या फासीवाद के साथ गठबंधन कर लिया था। ब्रिटेन में टोरीवाद को चुनाव में करारी हार मिली और उसके स्थान पर पहली बार लेबर पार्टी के बहुमत की सरकार ने सत्ता सभाली। समूचे एशिया में उपनिवेशवाद विरोधी मुक्ति आंदोलन तेज होते गए, और इंडोनेशियाई गणराज्य आंग-डच साम्राज्यवाद तथा उसकी जापानी सेना के सैनिक प्रहार के विरुद्ध डटा रहा। भारत में आजादी की व्यापक मांग तथा राष्ट्रीय विद्रोह का आंदोलन 1945-46 की सदियों में पराकाष्ठा पर पहुंच गया और इसकी अभिव्यक्ति हिंदू-मुस्लिम एकता संबंधी जनप्रदर्शनों में तथा सेना तक राष्ट्रीय विद्रोह के विस्तार में हुई।

इस परिस्थिति ने नई लेबर सरकार के निर्देशन में ब्रिटिश नीति को तेजी से एक मोड़ लेने के लिए मजबूर किया। 19 फरवरी 1946 को लेबर सरकार के प्रधानमंत्री श्री एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के निर्णय की घोषणा की। 15 मार्च को इस मिशन की रवानगी के अवसर पर श्री एटली ने एलान किया

अतीत के फार्मूले को वर्तमान स्थिति पर लागू करना हितकर नहीं है।

1946 का तापमान वही तापमान नहीं है जो 1920 में, 1930 में या यहां तक कि 1942 में था

जनमत की गति और वेग को महायुद्ध से ज्यादा कोई भी चीज तेज नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका युद्ध के प्रारंभिक दिनों में इस प्रश्न से कुछ भी सरोकार रहा होगा उसे यह पता है कि 1914-18 के युद्ध का भारतीय आकांक्षाओं और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो लहर शांतिकाल में अपेक्षाकृत मंद गति से उठती है वह युद्धकाल में प्रचंड हो जाती है और ऐसा घासतौर से युद्ध के तत्काल बाद होता है क्योंकि युद्ध के दौरान वह लहर कुछ हद तक कगारों से बंधी रहती है। मुझे पक्का यकीन है कि इस समय राष्ट्रीयता की लहर भारत में और सच नहे तो समूचे एशिया में बड़े वेग से बह रही है

भारत को खुद यह तय करना चाहिए कि उसकी भावी स्थिति क्या होगी और

विश्व में उसका क्या स्थान होगा। मुमकिन है कि समुन्नत राष्ट्र के जरिए या राष्ट्रमंडल के जरिए एकता स्थापित हो जाए लेकिन कोई भी महान राष्ट्र विश्व की घटनाओं में हिस्सा बटाए वगैर अकेले टिका नहीं रह सकता।

मुझे आशा है कि भारत शायद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत रहना चाहे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में उसे काफी फायदा होगा लेकिन यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपनी ही मर्जी से करना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और ब्रिटिश साम्राज्य एक दूसरे के साथ किसी बाहरी बाध्यता से नहीं बंधे हैं। यह स्वतंत्र लोग का स्वतंत्र संगठन है।

दूसरी तरफ, यदि वह स्वतंत्रता चाहता है, और मेरे विचार से यह चाहने का उसे पूरा हक है, तो हमें चाहिए कि हम इस हस्तांतरण को यथासंभव आसान और बाधरहित बनाएं।

यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी में आई कि ब्रिटेन की सरकारी अभिव्यक्ति में, भारत के सम्भावित लक्ष्य के संदर्भ में 'स्वतंत्रता' शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया।

फिर भी भारत के अंदर और भारत के बाहर अनेक क्षेत्रों में की जान वाली सहज आशाएँ कि कैबिनेट मिशन की खानगी और इससे पहले ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों का अर्थ भारत की स्वतंत्रता देना है, बिल्कुल अधूरी आशाएँ थीं। कैबिनेट मिशन और तदनंतर नए सांविधानिक प्रस्तावों के इतिहास की जांच हम अगले पृष्ठों में करेंगे। इन समझौतों और उपायों का अंतिम नतीजा व्यावहारिक अनुभव में प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन यह संभाव्य है कि ऐतिहासिक निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकलेगा कि वास्तव में ये प्रस्ताव भारतीय स्वाधीनता की शुरुआत के बजाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा सांविधानिक रूपांतर और समझौते के प्रयत्नों की लंबी श्रृंखला की अंतिम कड़ी थीं।

1946 में अब भी भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है। भविष्य में स्वतंत्रता का चुनाव करने के अधिकार के संदर्भ में औपचारिक रियायतें संविधान बनाने वाले निकाय के केवल उसी को अधिकार हैं इस्तेमाल करना है—पूवनिर्धारित और अप्रातिनिधिक चरित्र, संरचना तथा कार्यविधि के कारण अधिकांशतः निष्प्रभाव कर दी गई है।

इस प्रकार आने वाले दिनों में साम्राज्यवाद को कुछ दिन और टिके रहने तथा नए रूपों में भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व कारणरहित से बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की सदाई अभी जीतनी है।

लेकिन आज किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को यह संदेह नहीं है कि ऐतिहासिक घटनाक्रम की समूची धारा अब भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में है और यह कि निकट भविष्य में भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी।

यही वह संदर्भ है जिसके द्वारा हम आज के भारत, साम्राज्यवादी शासन के अंतिम दिन, साम्राज्यवादी प्रभुत्व की ख़ासी कहानी तथा भारतीय जनता की उफनती अग्रगति की जांच कर सकते हैं।

## 2 साम्राज्यवाद और भारत

सदियों से भारत आधुनिक साम्राज्यवादी विस्तार और प्रभुत्व का मुख्य आधार रहा है। भारत का क्षेत्रफल 1,808,679 वर्गमील है जो ब्रिटिश द्वीप समूह के क्षेत्रफल का पंद्रह गुना और ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का बीस गुना है। भारत की जनसंख्या 1941 की जनगणना के अनुसार 38 करोड़ 90 लाख है और अनुमानित अब लगभग 56 करोड़ होगी जो संपूर्ण मानव जाति का लगभग पांचवा हिस्सा है।

भारत की 56 करोड़ आबादी ब्रिटिश साम्राज्य की कुल आबादी का तीन चौथाई हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के समुद्रपारिय आबादी का 4/5 हिस्सा तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक आबादी का लगभग 9/10 हिस्सा है।

वर्तमान युद्ध से पहले के आठ प्रमुख उपनिवेशवादी साम्राज्यों के विस्तार की तुलना करें ता पता चलेगा कि 1938 में ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय जनता, विश्व के अन्य उपनिवेशों में रहने वाले लोगों के आधे से अधिक हिस्से का तथा शेष अन्य उपनिवेशवादी साम्राज्यों, फ्रांस, जापान, हालैंड, अमेरिका, बेल्जियम, इटली और पुर्तगाल की कुल औपनिवेशिक आबादी के डेढ़ गुने हिस्से से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करती थी।

साम्राज्यवाद द्वारा प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाए गए देशों में भारत सबसे बड़ा ही नहीं है। यह सबसे पुराना और सबसे ज्यादा समय तक अनेक पीढ़ियों से शासित और शोषित है इसलिए यह औपनिवेशिक व्यवस्था की कायपद्धति और उसके परिणाम का मुखमूल रूप बन करता है।

यूरोप की सभी उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपनी पहली कोशिश भारत और भारत की संपदा को हथियाने की की, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश में वे अमेरिका और वेस्टइंडीज के आरपार ठोकते खाते रहे, बाद में वहीं जाकर वे अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, चीन तथा एशिया के अन्य हिस्सों तक अपना विस्तार कर पाए।

यदि हम नक्शे पर निगाह डालें तो आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार भारत साम्राज्य-

वादी प्रभुत्व का केंद्र बिंदु रहा है। यह साम्राज्यवाद भारत को प्रभावशाली केंद्र बनाकर हिंद महासागर के चारों ओर तथा फारस की खाड़ी तक, पश्चिम में नए मध्यपूर्वी साम्राज्य और अरब तक, फिर लाल सागर और मिस्र तक, तथा दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के समस्त भूभाग तक, पू्व में बर्मा, मलय राज्य और ईस्टइंडीज तक, दक्षिण पू्व में आस्ट्रेलिया तक और सिंगापुर के प्रवेश द्वार के साथ साथ हाल ही में नए बर्मा यूनान मार्ग होते हुए चीन के रास्ते तक फैला हुआ है।

उत्तर में अभेद्य पर्वत के अवरोध (जो केवल उत्तर पश्चिम में आक्रमण के लिए खुला है) और समुद्र पर नियंत्रण के कारण भारत इस समूचे क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए एक दुर्ग का काम करता है साथ ही वह स्वयं में संपत्ति और शोषण का समृद्धतम स्रोत है।

भारत में यूरोपीय पूँजी की धुसपैठ आज से चार सौ वर्ष से भी पहले उस समय शुरू हुई जब 1500 ई० में पुर्तगाल ने कानीकट में अपना कारखाना लगाया और 1506 में गोवा पर विजय हासिल की। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में फ्रेंच कंपनी द इंडीज की स्थापना हुई। व्यापार समझौते से अलग हटकर जो विजय के प्रारम्भिक छार थे, भारत में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासक शासन 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। 1757 में प्लासी के युद्ध को परंपरागत प्रस्थान बिंदु मानें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दो सौ वर्षों का निर्यात से परिचय मिलता है।

पश्चिमी सभ्यता द्वारा भारत की विजय में यूरोप में पूँजीवादी विकास के प्रमुख स्तंभों में से एक की मज्जि में, विश्व में ब्रिटन की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया तथा आधुनिक साम्राज्यवाद की मूलची गरचना का निर्माण किया। दो शताब्दियों तक यूरोप का इतिहास जितना स्वीकार किया जाता है उसमें वही अधिक सीमा तक भारत पर प्रभुत्व के आधार पर निर्मित होता रहा। ब्रिटन का स्पन और पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, रूस और जर्मनी के साथ एक एक का संघर्ष होता रहा उसके पीछे भारत तक पहुंचने का रास्ता और भारत के प्रभुत्व का प्रश्न ही मुख्य था इसका पता लगाया जा सकता है। इंग्लैंड में आंतरिक राजनीति के दौर के पीछे तथा समूचे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरे भग्न तथा अनिश्चितता के साथ महाराज के पीछे भी इसी प्रभुत्व की भूमिका की यात्रा की जा सकती है।

भारत का बाहरी पक्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी मान लिया गया है। जगति उस समय भी भारत में फैल रहा, साम्राज्यवाद के अंतिम महत्वपूर्ण वायव्य साइड बज्जिन ने 1894 में निम्न का (वायव्य साइड बना में पक्ष)

विश्व प्रसार की भारत में बना या नि भारत की गरबाज और भारत पर विचार ही बर्तन व निर्यात है विचार विचार के अभाव में इंग्लैंड का

उसका उचित स्थान दिलाया है, उसी प्रकार एशिया में उसकी स्थिति से उत्पन्न वैभव और सम्मान ही ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला है। प्राचीन एशियाई महाद्वीप के केंद्रस्थल पर वह उस सिंहासन पर आरुढ़ हैं जिसने हमेशा पूर्व पर शासन किया। उसका राजदंड पृथ्वी और समुद्र पर दूर दूर तक फैला हुआ है। 'ईश्वर की तरह उसके हाथ में त्रिशूल है और सम्राट की तरह उसके मस्तक पर ताज सुशोभित है।' (माननीय एच० एन० क्जन प्रावलम्स आफ दि फार ईस्ट' 1894, पृ० 419)

चार वर्ष बाद 1898 में साम्राज्यवाद के इस मदहोश प्रशस्तिगायक ने एक नया राग छेड़ा भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है—यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिराज्य का कोई दूसरा हिस्सा गवा देता है तो भी हम जीवित रह सकते हैं पर यदि हमने भारत को खो दिया तो हमारे साम्राज्य का सूरज अस्त हो जाएगा।

शब्दाडंबरपूर्ण बहुधा उद्धृत किए जाने वाले इस वाक्य से आभास मिलता है कि उन्हें अपने अंतिम दिनों का एहसास होने लगा था।

ऐतिहासिक तथ्यों को देखने से पता चलता है कि ब्रिटेन के लिए तथा ब्रिटिश पूँजीवाद की समूची संरचना और उसके विकास के लिए भारत का आर्थिक और वित्तीय महत्व बहुत अधिक रहा है। यह महत्व अब कम हो रहा है तथापि अब भी उल्लेखनीय है। भारतीय बाजार पर चला आ रहा पुराना एकाधिकार, जो 19वीं सदी में 4/5 हिस्से से भी ज्यादा तक पहुंच गया था और 1914-18 के युद्ध की पूर्वसंध्या तक भी दाँत तिहाई था, अब समाप्त हो गया है फिर कभी वापस न आने के लिए। 1929 के बाद से भारत ब्रिटिश सामानों का एकमात्र सबसे बड़ा बाजार नहीं है और 1938 तक उसका स्थान तीसरा हो गया था। फिर भी भारतीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ब्रिटेन के हाथ में है। 1933 में भारत कुल अनुमानित ब्रिटिश पूँजी 1 अरब पौंड थी। (इंडियन चैंबर आफ कामर्स अनुमान)। यह राशि ब्रिटेन द्वारा समुद्रपारीय देशों में लगाई गई कुल पूँजी का एक चौथाई थी। इस समूची राशि में अब कमी आ गई है हालाँकि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद से जो परिवर्तन हुए हैं उनके प्रभावों के बारे में कोई आधिकारिक आकलन अभी तक नहीं किया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि युद्ध के दबाव के कारण जबकि दूसरे देशों में ब्रिटेन का समुद्रपारीय पूँजीनिवेश स्वतंत्र रूप से बेचा गया, भारत में लगी पूँजी को दृढ़ता के साथ बनाए रखा गया। कागज-पत्रा पर कुल संपत्ति का वर्तमान योग उस क्षतिपूर्ति से अधिक है जो युद्ध के दौरान भारत से, बिना भुगतान किए सामानों की प्राप्ति से जमा स्टॉलिंग सतुलना के रूप में थी। लेकिन उनके भविष्य का निबटारा होना अब भी बाकी है। भारत से, किसी न किसी रूप में, ब्रिटेन जाने वाले वार्षिक कर की राशि अनुमानतः 15 करोड़ पौंड (यह गणना वर्ष 1921-22 पर आधारित है जो शाह और सबाटा की पुस्तक 'वैल्यू ऐंड टैक्सबल कंपैसिटी इन इंडिया' के पृष्ठ



234 पर उल्लिखित है।) या उसी तिथि में समूचे भारतीय वजेट के योग से अधिक और ब्रिटेन की जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति 3 पौंड प्रतिवर्ष की राशि से अधिक के बराबर या आकलन के समय सुपर टैक्स देन वाले प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक के लिए लगभग 1700 पौंड प्रतिवर्ष के बराबर है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारत का सामरिक महत्व भी कम नहीं है। इसका महत्व दो तरह से है एक तो इससे ब्रिटेन को अन्य हिस्सों में अपने साम्राज्य के विस्तार का आधार मिलता है, नवदी संपत्ति मिलती है और अनख्य समुद्रपारीय युद्धों और अभियानों के लिए सैनिक मिलते हैं दूसरे उसे एक ऐसा केंद्रीय स्थल मिलता है जहाँ से लगातार सामरिक जोड़ तोड़ (भूमध्य सागर, स्वेज नहर और लान सागर, फारम की खाड़ी और मध्य पूर्व साम्राज्य तथा सिंगापुर का नियंत्रण) संचालित होते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के सामरिक महत्व का और भी ज्यादा प्रमाण मिला।

### 3 भारत में साम्राज्यवाद का दिवानियापन

भारत में साम्राज्यवादी शासन का नतीजा क्या निकला है? प्रेक्षकों के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण कितने भी भिन्न क्यों न रहें हों, लेकिन एक मुद्दे पर दक्षिणपंथी और वामपंथी, सभी सहमत हैं। साम्राज्यवादी शासन के दो सौ वर्षों के बाद, भारत यहाँ की जनता की भीषण गरीबी और वृष्टि की जो तस्वीर पेश करता है वह दुनिया में बेमिसाल है।

यह देश के प्रकृतिया गरीब होना या समाधानों की कमी का मसला नहीं है। जित विशाल क्षेत्रों में लोग रहते हैं वे प्राकृतिक संपदा और साधना की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। यह समृद्धि केवल भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादन की संभाव्यता के ही मामले में नहीं है बल्कि वन्य वन्य माल के मामले में भी है जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से कायला, लोहा और जलशक्ति जैसे बेहद विकसित औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ जनता की प्रतिभा और तकनीकी अभिरुचि तथा दक्षता (जो तब से जब भारत साम्राज्यवादी शासन से पूर्व तकनीकी दृष्टि से अर्ध दशों की तुलना में आगे था, अब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ) के लिए किया जा सकता है। वैसे यदि कृषि उत्पादन की संभाव्यता और जमीन की उर्वरता की जाँच की जाए तो पता चलेगा कि यदि इसका पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए तो मौजूदा आबादी से कहीं अधिक आबादी के लिए भरण पदार्थ पदा हो सकता है।

फिर भी ये साधन और संभावनाएँ मुख्यतया अविकसित हैं। पूँजीवाद के वार में मजदूर सामान्य तौर पर हमें यह मानत है कि उसमें उत्पादन की बरबानी होती है और उत्पादन की गणना श्रमनाश का इस्तेमाल करने में पूँजीवाद विफल होता है तो भारत में यह

विफलता अपनी चरम सीमा तक पहुँची है और यह स्थिति उसे अपने स्वरूप में किसी अन्य साम्राज्यवादी देश से बुनियादी तौर पर भिन्न बनाती है।

हाल ही में एक अमरीकी पर्यवेक्षक प्रोफेसर बुशनान ने 1934 तक के भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया और उन्होंने बहुत ही निराशाजनक नतीजे निकाले

यह ऐसा देश है जहाँ वह सारा कच्चा माल मौजूद है जिसपर उत्पादन निर्भर करता है फिर भी पिछले सौ वर्षों से भी अधिक समय में इसने कारखानों में बने सामानों का भारी मात्रा में आयात किया है और महज कुछ अति साधारण उद्योगों का जिनके लिए अन्य देशों में बेहद उन्नत मशीनें और सगठन हैं, विकास किया है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास, पटसन, आसानी से निकाला जा सकने लायक कोयला, आसानी से प्राप्य और उच्चकोटि का कच्चा लोहा है, यहाँ तमाम साँग ऐसे हैं जो लाभदायक रोजगार न पाने के कारण प्रायः भुखमरी की स्थिति में रहते हैं, यहाँ सोना और चांदी का जितना जखीरा है उतना शायद ही किसी दूसरे देश में हो। देश की सीमाओं के अंदर उत्कृष्ट बाजार है जिसमें दूसरे लोग बड़े पैमाने पर अपने बनाए सामान बेच रहे हैं, इन सारे लाभों के बावजूद भारत एक सौ वर्ष बाद भी कारखाना उद्योग से अपनी आबादी के केवल दो प्रतिशत हिस्से को सहारा दे रहा था।

(डी० एच० बुशनान 'दि डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट एंटर्प्राइज इन इंडिया', 1934, पृष्ठ 450)।

भारतीय अर्थशास्त्र के प्रमुख ब्रिटिश विशेषज्ञ और लंदन विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्राध्यापता डाक्टर वेरा एसटे ने भारत में अवरोद्ध आर्थिक विकास की तस्वीर खींची। उन्होंने इसे अलत 'विचित्र' माना।

क्योंकि 18वीं सदी तक भारत में आर्थिक विकास की गति अप्रत्याशित काफी तेज थी और उत्पादन तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक सगठन की भारतीय पद्धति इतनी सुदृढ़ थी कि वह विश्व के किसी भी हिस्से में प्रचलित पद्धति का मुकाबला कर सकती थी

वस्तुतः यह दावा नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोई आर्थिक प्रगति नहीं हुई। ब्रिटिश मयोजन के परिणामस्वरूप भारत को सस्ते विदेशी सामान मिले, अनेक तरह के भारतीय उत्पादनों के लिए तांगों की मांग बढ़ी और जनता का उस कायपद्धति और प्रशासन प्रणाली से परिचय हुआ जिससे वह काफी बड़ी हुई मात्रा में अनाज

का उत्पादन करने (खास तौर से विस्तृत सिचाई साधनों द्वारा) तथा अय सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजन (रेल और पानी के जहाज द्वारा) योग्य हो सकी। खास तौर से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत का कुल उत्पादन और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ा।

लेकिन इन परिवर्तनों ने भारत और पश्चिमी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ा दी जिससे भारत की प्रवृत्ति प्रमुख वच्चे मालों और घाघ पदार्थों का उत्पादन करने एवं उनका निर्यात करने तथा कपड़ा, लोह और इस्पात के बने सामानों, मशीनों और अनेक तरह के सामानों का आयात करने की प्रवृत्ति और बढ़ी। इसके अलावा जनसंख्या में मगामी वृद्धि ने कुल उत्पादन में हुई वृद्धि को इस सीमा तक बंध कर दिया कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का पता नहीं लगाया जा सका। इन तथ्यों से निश्चय ही यह दृष्टिकोण बना कि भारत में आर्थिक विकास 'अवरुद्ध' हो गया है।

19वीं सदी के अंत तक जनता की समृद्धि पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव असंदिग्ध रूप से निराशाजनक था। (वी० एस० दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया तीसरा संस्करण, 1936, प्रस्तावना, पृष्ठ 5)

इधर हाल के वर्षों की क्या स्थिति है जिनमें कभी कभी यह कहा गया है कि यह स्थिति अब बदल गई है और उद्योगीकरण का काम ठीक ढंग में आगे बढ़ रहा है? वी० एस० ने ही 1931 की जनगणना के आंकड़ों की जांच पड़ताल की और इस नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे

इन आंकड़ों का तजी के साथ विकसित हो रहे उद्योगीकरण के साथ सामंजस्य बैठाना कठिन है। कृषीय विकास की तुलना में औद्योगिक विकास न केवल नगण्य है बल्कि भारत अब भी उन तमाम सामानों और सेवाओं की व्यवस्था के लिए, जो भौतिक दृष्टि से विकसित किसी भी देश के लिए अनिवार्य हैं विदेशियों पर बेहद निर्भर है। सुव्यवस्थित आर्थिक जीवन की उपलब्धि अब भी नहीं हो पाई है और जनसामान्य का जीवनस्तर अत्यंत निम्न है। (वही, पृष्ठ 8)

इस विरोधामास का क्या जवाब है जो सभाव्य प्रचुरता के बीच अवर्णनीय गरीबी में (जो किसी सामान्य पूँजीवादी देश में पाए जाने वाले इस तरह के विरोधामास से काफी अधिक है), तथा तकनीक के क्षेत्र में सर्वाधिक संपन्न और अत्यधिक विकसित राष्ट्र के दो सौ वर्षों के शासन के बावजूद अवरुद्ध आर्थिक विकास में दिखाई देती है?

इस विरोधाभास को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम भारतीय जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सदर्भ में साम्राज्यवाद की वास्तविक कायप्रणाली का निवृत्ता से अध्ययन करें।

भारत के उत्पादक साधनों को विकसित करने में विफल होने के कारण ही भारत में आज साम्राज्यवाद के आतंन वाले अंतिम दिनांक का मकेन मिलने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे सामंती राजाओं की शासन प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश पूंजीवादी आनामका की अपेक्षा-कृत आर्थिक श्रेष्ठता ने ही (उस आक्रमण के दौरान बड़े पैमाने पर विनाश और लूटमार के बावजूद) उन्हें दो सौ वर्ष पूर्व भारत पर विजय दिलाई।

भारत में पुरानी व्यवस्था के दिवालियापन और नई व्यवस्था के जन्म की सामाजिक-राजनीतिक अभिव्यक्ति ही साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध जिसने बीसवीं सदी में भारतीय परिदृश्य पर अधिक से अधिक आधिपत्य कायम किया, भारत की जनता का सक्रिय विद्रोह है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि स्थितियाँ उस रूपांतरण के लिए परिपक्व हो चुकी हैं जो भारत में साम्राज्यवादी अपकरण से उत्पन्न निश्चलता को समाप्त कर देगा और इसके स्थान पर जनता के आधुनिक गतिशील भारत का निर्माण करेगा।

## भारत का जागरण

साम्राज्यवादी शासन की इस पतनशील और दिवालिया प्रणाली के विरुद्ध ही भारत की जनता इतने व्यापक और सख्तमुखी विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुई है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन<sup>1</sup> पिछली शताब्दी के दौरान अनेक चरणा से गुजरकर और 19वीं सदी के अंतिम पच्चीस वर्षों से आधुनिक स्वरूप में विकसित हुआ है। इसका विकास कानूनी और गैरकानूनी, सांविधानिक और क्रांतिकारी, कई रूपों में हुआ है। इसने अपने भीतर रूढ़िवादी और जातीय तथा आधुनिक युग में समाजवादी और साम्यवादी, अनेक धाराओं को समाविष्ट किया। आज में 50 वर्ष पहले तक वैधानिक आंदोलन की मार्गें साम्राज्यवादी ढाँचे के अंतर्गत महज सामान्य सुधारों के लिए थीं। संगठित आंदोलन मुद्रों भर शिक्षित मध्यमवर्ग तक ही सीमित था। लेकिन बीसवीं सदी में आंदोलन का क्षेत्र और लक्ष्य लगातार व्यापक होता गया है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने पूरी तरह व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लिया, अब पूर्ण स्वशासन की मांग की जाने लगी जिसकी व्याख्या अंततः 1929 ई० और बाद के वर्षों में की गई और इस मांग का पूर्ण स्वाधीनता तथा ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने की मांग कहा गया।

भारत जग रहा है। भारत, जो हजारों वर्षों से एक के बाद एक विजेताओं की जीत का

शिक्कार रहा है, अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना का उद्बोधन कर रहा है जिसमें स्वतंत्र जनसमुदाय विश्व रंगमंच पर अपनी खुद की भूमिका अदा करे। इस जागरण ने हमारे जीवनकाल में ही लंबी छलांगें लगाई हैं। पिछले 25 वर्षों में एक नए भारत का उदय हुआ है। चाहे कितने भी अवरोधों पर अभी विजय क्यों न प्राप्त करनी हो पर स्वतंत्रता के माग पर भारत की प्रगति को आज समूचे विश्व के लोग निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाली विजय के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने का अथ गुलाम कौमा पर आधुनिक साम्राज्यवादी प्रभुत्व के मुख्य आधार का समाप्त हो जाना है।

विगत संपूर्ण अवधि के दौरान ब्रिटिश नीति ने राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने, उसे रोकने, उसमें फूट डालने, उसे भ्रष्ट करने या उसका विरोध करने तथा आंदोलन की प्रगति का डटकर सामना करने का भरपूर प्रयास किया। इसके लिए उसने अपने शस्त्रागार के सारे हथियारों का इस्तेमाल किया, वह हथियार चाहे जबरदस्त दमन का रहा हो या सांविधानिक रियायतों का, चाहे फूट डालने के कुशल संचालन का रहा हो या आंदोलन के नेतृत्व बग तक पहुंच का। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति ने, जो साम्राज्यवादी नीति की वेहद कुशल, लचीली और अनुभवी अभिव्यक्ति थी, सुधारों के साथ बल प्रयोग को जोड़कर और ऊपरी तौर पर दूरगामी रियायतें देकर हर तरह से अपने को नई स्थिति के अनुकूल ढालने और अपनी सत्ता तथा शोषण की असंख्यता को बरकरार रखने की कोशिश की। साम्राज्यवाद के ढांचे के अंतर्गत स्वशासन और स्वतंत्रता की दिशा में उपनिवेशों की जनता की नैतिक और शांतिपूर्ण प्रगति की संभावना की बात करने वाले उदार साम्राज्यवादी और सुधारवादी सिद्धांतों को यहाँ व्यवहार की कसौटी पर उतरना पड़ा। इतिहास इस सघट्ट के अंतिम परिणाम का निर्धारण करेगा जो मात्र भारतीय जनता के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगा।

पिछले 25 वर्षों की घटनाओं ने दिखा दिया है कि नई स्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने के साम्राज्यवाद के सभी प्रयास तथा इस अवधि की खास बात यानी बल प्रयोग और रियायत की प्रत्यावर्ती लहरें न ता राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रवाह को रोक सकी और न भारत की समस्या का कोई समाधान दे सकी।

साम्राज्यवादी शासन व अधीन भारत की राजनीतिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ में बढ़मूल उदीयमान अंतर्विरोधों का बार बार एकता के प्रयासों का विफल कर दिया है। ऊपर अत्यधिक विकसित एवं विस्तृत महाजनी पूँजी का शासन और प्रभुत्व तथा नीचे निम्नतम स्तर की सामाजिक दुःशा और पिछड़ापन का जोना स्तर कारण और प्रभाव का जान में एक दूगर में गुंथे हुए है। इनका विरोधी स्तरों का बीच अर्थात् ऊपरी स्तर पर साम्राज्यवादी शोषकों तथा निचले सिरे पर असहायों की संख्या

वढान वाली जनता की दो परस्पर विरोधी पराकाष्ठाओं के बीच सन्नमणकारी रूप विधानों, विचवई परापजीविता, शोषण के अधीनस्थ रचनातत्त्व, पुरानी अपघटित होती हुई शक्तियों और नई प्रगामी शक्तियों का जमघट है। इनका प्रतिवर्ष विस्तार हो रहा है और इन सबके माध्यम से भारतीय जनता की उदीयमान राष्ट्रीय चेतना का तथा भारत की क्षुधित आम जनता की उदीयमान आर्थिक मांगों का विकास हो रहा है। यह ऐसी स्थिति है जिसके हर मोड़ पर सामाजिक विस्फोट का बारूद दबा पड़ा है।

भारत की बुनियादी समस्या केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि सामाजिक है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता की चुनौती का सीधा अर्थ समूची मानवता के पाचवें हिस्से द्वारा विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाने का दावा है। लेकिन राजनीतिक स्वाधीनता के दावे की तुलना में, जिसमें उसे राजनीतिक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, स्वतंत्रता की यह मांग ज्यादा गहराई तक प्रहार करती है। यह अपने मूल में, दूर तक संस्थापित उस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध चुनौती है जिसका आश्रयस्थल तो लंदन शहर है लेकिन जो भारत के अंदर स्थापित विशेषाधिकार और शोषण की अधीनस्थ प्रणाली के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दूसरे को परे रखकर पहले को क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती, इसके लिए दोनों पर एक साथ प्रहार करना होगा।

इस अर्थ में भारत की समस्या अंतिम विश्लेषण में एक सामाजिक समस्या है। भारत की मूल समस्या 40 करोड़ मनुष्यों की समस्या है। यह उनकी समस्या है जो बेहद गरीबी की स्थिति में जीवन बिता रहे हैं और जिनकी आवादी का एक विशाल बहुमत अंध भुखमरी की स्थिति में है। इसके साथ ही वे एक ऐसे विदेशी शासन के अधीन हैं जिसका उनके जीवन पर पूरा नियंत्रण है और जो इस तरह की भयावह स्थितियाँ पैदा करने वाली समान व्यवस्था को ताकत के बल पर बरकरार रखे है। ये करोड़ों लोग जीवन के लिए, जीवन के साधनों के लिए और प्रारम्भिक स्वतंत्रता के लिए सघप कर रहे हैं। उनके सघप की समस्या और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके की समस्या ही भारत की समस्या है।

भारतीय जनता के सघप का तात्कालिक उद्देश्य है राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति और स्वशासन का जनतांत्रिक अधिकार। लेकिन यह उद्देश्य भारत के अंदर एक गंभीरतम सामाजिक सघप और एक गतिवान सामाजिक नाति के पहले चरण को चिन्तित करता है। राष्ट्रीय और सामाजिक मसलें एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और इस अंत सबंध की समझदारी ही भारतीय स्थिति के समझने की कुंजी है।

सामाजिक रूढ़िवादिता आज भी भारत में जड़ जमाए हुए है और यह राष्ट्रीय आंदोलन की समस्याओं और उसके चरित्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इस तरह की सामाजिक रूढ़िवादिता और प्रतिस्त्रियावादी प्रवृत्तियों के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन का

विकास कमजोर पड़ता है तथा उसमें विघटन पैदा होता है। साम्राज्यवाद ने तूटमार के अपने असली कारनामों पर परदा डालने के लिए युद्ध को 'सभ्यता का प्रसार करने वाले' के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए हमें अब दूसरी दिशा में प्रचारित की जाने वाली सद्गति प्रवर्धनाओं तथा कृत्रिम मिथकों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

क्योंकि साम्राज्यवाद की कृत्रिम मिथक कथाओं के विरोध में, भारत में कुछ ऐसे लोगों के बगैरे, जिसकी दृष्टि हमेशा पीछे की तरफ लगी रहती है, जवाबी मिथक कथाएँ गढ़ने का प्रयास किया है। साम्राज्यवादी प्रभुत्व की बुराईयाँ की प्रतिक्रिया में इन लोगों ने भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व के काल की स्वर्ण युग के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने उस सड़ी गली समाज व्यवस्था की बुराईयाँ को कम आकने का प्रयास किया है जो ब्रिटिश शासन से पूर्व पतन के गत में जा चुकी थी। उन्होंने भारत के अतीत के उन प्रतिक्रियावादी अवशेषों को, जिन्होंने प्रगति को रोका, जनता की चेतना को दबाया और एकात्मता में बाधा पहुँचाई, इतिहास के दृष्टांत से महज सही ठहराने का ही नहीं बल्कि उन्हें गौरवाचित और आदर्श स्थिति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। वे इन प्रतिक्रियावादी अवशेषों के आधार पर राष्ट्रीय चेतना के निर्माण की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को सामान्यतया 'पश्चिमी सभ्यता' के विरुद्ध संघर्ष में तब्दील करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दृष्टि हमेशा आगे के बजाय पीछे रखी।

इससे राष्ट्रीय मोर्चा मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो जाता है। भारतीय समाज की बुराईयाँ केवल साम्राज्यवादी शासन से नहीं व्युत्पन्न हुई हैं बल्कि वे भारत के इतिहास प्रसिद्ध अतीत से भी विरासत में मिली हैं। उल्टे यदि उन बुराईयों के विरुद्ध लड़ने में राष्ट्रीय मोर्चा साम्राज्यवाद के मुकाबले खुद को ज्यादा समय दिखा सके तो वह मजबूत होता जाएगा। जहाँ तक साम्राज्यवाद की बात है वह अपनी भूमिका और अपने सामाजिक आधार की मूल प्रकृति के अनुसार इन बुराईयों को जारी रखने और यहाँ तक कि उन्हें और बढ़ावा देने के लिए विवश होता है।

जब तक साम्राज्यवाद अपेक्षाकृत अधिक विकसित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सका, तब तक अपनी तमाम आनुपमिक कुरताओं और धर्वादी के बावजूद वह अपना प्रभुत्व कायम रख सका। आज राष्ट्रीय मोर्चे की शक्तियों और भारतीय जनता की उत्ततिशील सामाजिक शक्तियों के बीच जितनी ही स्पष्टता के साथ तादात्म्य स्थापित होता जा रहा है—और वे साम्राज्यवाद के मुकाबले एक स्पष्ट सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट दीख सकती हैं—उतनी ही स्पष्टता के साथ उनकी भावी विजय भी निश्चित हो रही है।

भारत में बढ़ रहे संकट के कारण तमाम आंतरिक सामाजिक संघर्ष और समस्याएँ सामने

आ रही है। भारतीय जनता के सामने आज जा बुनियादी श्रातिकारी काय है वे मानवता के और किमी हिस्से के सामने नहीं है। भारत के पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न गभीर समस्याएँ, सदियों की दासता से उत्पन्न गदगी को साफ करने का काम, अवरुद्ध विकास और दकियानूस सामाजिक रीति रिवाज, इन सबका समाधान राष्ट्रीय मुक्ति के साथ ही नहीं हो जाएगा। उस समय ये सारी समस्याएँ अपने पूरे आयाम में सामने आएंगी और उनके समाधान के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ की तैयारी का पहला चरण पूरा होगा।

भारत की मेहनतकश जनता की चेतना के विकसित होने तथा अपने भाग्य की वागडोर उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ में लेने के साथ ही इन सघर्षों और समस्याओं का समाधान हाता जाएगा तथा भारत अपने वर्तमान आर्थिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन से उबरकर विश्व के सर्वाधिक उन्नत देशों के स्तर तक पहुँच जाएगा। भारत की जनता को आज आने वाले दिनों में विश्व समाजवाद की स्थापना करने में और पूर्व तथा पश्चिम के बीच और उन्नत एवं पिछड़े राष्ट्रों के बीच भेदभाव का अंतिम रूप से समाप्त करने के महान काम में अत्यंत प्रमुख भूमिका निभानी है।

वर्ग समाज की सीमा में, सर्वाधिक आदिम से सर्वाधिक उन्नत तक, सभ्यता और संस्कृति की प्रत्येक अवस्था भारत में विद्यमान है। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की व्यापक और विविध समस्याओं को भारतीय परिस्थितियों में अत्यंत स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। असमान जातियों और धर्मों के बीच सबधों और सह अस्तित्व की समस्याएँ, पुराने अधविश्वासपूर्ण और पतनशील सामाजिक रूपों और परंपराओं के विरुद्ध सघर्ष, शिक्षा के लिए सघर्ष, महिलाओं की मुक्ति के लिए सघर्ष, कृषि के पुनर्गठन और उद्योग के विकास तथा गाँव और शहर के बीच सबध का मसला, अत्यंत विविध और प्रखर रूपों में वर्ग सघर्ष के मसले, राष्ट्रवाद और समाजवाद के सबध की समस्याएँ, आधुनिक विश्व के ये विविध मसले भारत में विशेष सुस्पष्टता और आप्रहृ के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

इन विविध समस्याओं को अलग करके नहीं हल किया जा सकता। इन्हें निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण के लिए भौतिक और मानवीय शक्तियों को मुक्त करके, राष्ट्रीय मुक्ति की प्रमुख समस्या के साथ जोड़ना होगा। भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ अपने जटिलतम रूप में उन अत्यंत विचित्र और गभीर समस्याओं का समाधान है जिसका सामना समान रूप से विश्व की जनता को करना पड़ रहा है।

भारत की जनता ने पहले भी विश्व के इतिहास में एक महान भूमिका अदा की है, विजेताओं के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति, चिंतन, कला और उद्योग के क्षेत्र में। भारतीय जनता की राष्ट्रीय और सामाजिक मुक्ति से मानवता को महान और नए सौभाग्य की प्राप्ति होगी।



## टिप्पणी

- 1 'भारतीय राष्ट्र और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' शीर्षक का इस्तेमाल यही और बाद के पलों में, भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण स्वयं करने के पक्ष में चलाए जा रहे संघर्ष की एकराती को दर्शाते करने के लिए किया गया है। इस शब्दावली के इस्तेमाल में स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाए जाने वाले संभावित भावी राजनीतिक रूपा के प्रश्न पर या भावी स्वतंत्र भारत के बहुराष्ट्रवादी चरित्र (जो राजनीतिक समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है) के अन्त्युद्भव के संकेतों पर निम्न देना नहीं निहित है। इस विशेष मामले पर अलग से विचार किया जाएगा।

खण्ड एक

भारत जैसा है और जैसा होना चाहिए



## भारत का वैभव और उसकी गरीबी

‘भारत के बारे में सर्वाधिक दिलचस्प तथ्य यह है कि उसकी धरती समृद्ध है और लोग गरीब।’ (एम० एल० डालिंग ‘दि पंजाब पीजेट इन प्रोस्पेक्टिविटी ऐंड डेब्ट’, 1925, पृष्ठ 73) भारत की वर्तमान स्थिति के सदर्भ में दो तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला तथ्य है भारत का वैभव, उसकी प्राकृतिक संपदा, उसके प्रचुर साधन, उसकी अतर्निहित समृद्धि जिसमें उसकी संपूर्ण वर्तमान आबादी को और उससे भी बड़ी आबादी को सुखी बनाने की क्षमता है।

दूसरा तथ्य है भारत की गरीबी, उसकी आबादी के बहुत बड़े हिस्से की निधनता, ऐसी निधनता जिसकी वे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जो पश्चिमी जगत की परिस्थितियों को देखने के अभ्यस्त है। इन दो वास्तविकताओं के बीच है भारत की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की समस्या।

### भारत का वैभव

भारत गरीब लोगों का देश है लेकिन वह गरीब देश नहीं है। भारत के प्राकृतिक साधन इतने ज्यादा अनुकूल हैं कि यदि खेतीबाड़ी और उद्योग का मिलाजुला विकास किया जाए तो यहां के लोग समृद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हैं। साथ ही यह भी सच है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत विश्वस्तर पर जायिक विकास के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में था।

यह सभी लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में, दूसरे देशों के लोगों की दृष्टि में, भारत

विशाल धन संपदा वाला देश माना जाता था। इस तरह के विवरणों का उचित संदेह के साथ देखा जाना चाहिए क्योंकि जिन प्रेक्षकों ने उन दिनों ये विवरण प्रस्तुत किए थे उन्होंने संपत्ति के वितरण पर ध्यान देने के बजाय धनी और शक्तिशाली लोगों के पास जमा संपत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया था। इस तरह के प्रेक्षकों का विशिष्ट उदाहरण क्लाइव है जिसने 1757 में बंगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद को देखने के बाद लिखा था

‘यह शहर उतना ही विस्तृत, उतनी ही अधिक आबादी वाला और उतना ही समृद्ध है जितना लंदन। पक्का इतना है कि यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास लंदन की तुलना में असीम संपत्ति है।’ (इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट के पृष्ठ 249 पर उद्धृत)

इस तरह के उपलब्ध वर्णनों में काफी भिन्नता और अतिशयोक्ति है और इनकी जांच के लिए हमारे पास कोई सभावित वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि 17वीं सदी और 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने प्रायः इस बात का उल्लेख किया है कि उन दिनों गांवों में भी लोग आमतौर पर समृद्ध थे जबकि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है।<sup>1</sup> इस प्रकार 17वीं सदी में भारत की यात्रा का विवरण लिखते समय तैवर्नियर ने टिप्पणी की कि

‘छोटे से छोटे गांव में भी चावल, आटा, मक्खन, दूध, सेम तथा अन्य सब्जियां, चीनी तथा सूखी और शीरेवाली अन्य मिठाइयां प्रचुर मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं।’ (तैवर्नियर ट्रवल्स इन इंडिया आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस संस्करण, 1925 खंड 1, पृष्ठ 238)

वेनिस निवासी मनुची ने, जो 17वीं सदी में औरंगजेब का मुख्य चिकित्सक बना, अपने स्मरणों में अत्यंत भाव-विभोर होकर अलग-अलग प्रांतों के हिसाब से भारत के वैभव का वर्णन किया है। इसका ठेठ उदाहरण उसका बंगाल का वर्णन है। बाद के वर्षों में क्लाइव और उसने उत्तराधिकारियों के शासनकाल में हुई इसकी बरबादी और वर्तमान भयंकर गरीबी को ध्यान में रखते हुए मनुची का यह वर्णन देखने योग्य है

मुगल शासकों के सभी राज्यों में से बंगाल फ्रांस में सबसे अधिक महंगी है। बंगाल की बेहद उबरता का सबूत उसकी अपूर्व संपदा है जो वहां से यूरोप भेजी जाती थी। हम वक्षिज्ञ कह सकते हैं कि वह किसी भी मामले में मिस्र से कम नहीं है बल्कि सिल्क, कपास, चीनी और नील के उत्पादन के मामले में तो वह मिस्र से भी आगे है। यहां फल, दाल, अनाज, मलमल और जरी तथा रेशम के कपड़े, सभी चीजें भरी पड़ी हैं। (एफ० एफ० कावू

‘दि जनरल हिस्ट्री आफ दि मुगल एपायर’, वेनिस वासी मनूची के ‘मेमायस’ से उद्धृत। मनूची लगभग 40 वर्षों तक औरंगजेब का मुख्य चिकित्सक रहा, जान घायर, लदन द्वारा 1709 में प्रकाशित)

इसी तरह फ्रांसीसी यात्री वॉनियर ने, 17वीं सदी के मध्य में, 1660 के आसपास दो बार बंगाल की यात्रा की और उसने मुगल साम्राज्य की समाप्ति से पूर्व जो कुछ देखा उसका वर्णन किया

अपनी दो बार की यात्रा में बंगाल के बारे में मैं जो कुछ जान सका हूँ उससे मुझे विश्वास होने लगा है कि यह मिस्र की तुलना में अधिक धनी है। यह भारी मात्रा में सिल्व और कपास, चावल, चीनी और मक्खन का निर्यात करता है। यह अपने उपभोग के लिए प्रचुर मात्रा में गेहूँ, राग सन्निधि, अनाज, मुरगे मुरगिया, बतखें और बलहस पैदा करता है। इसके पास धेरें सारे सूअर, भेड़ें और बकरे हैं। हर तरह की मछलियों का इसमें पाया जाता है। राजमहल से लेकर समुद्र तक असंख्य नहरें हैं जिन्हें बहुत गेहूँ से काटकर बनाया गया है ताकि नौमचालन और सिंचाई का काम किया जा सके। (सर विलियम विलकाक्स की पुस्तक ‘लेक्चर्स आन दि एशिएट सिस्टम आफ इरिगेशन इन बंगाल’ में वॉनियर का उद्धरण, बलकत्ता विश्वविद्यालय, 1930, पृष्ठ 18-19)

ब्रिटिश शासन से पहले के भारत में आम जनता के जीविक स्तर से संबंधित सामाजिक मसलों पर अनिवार्य रूप से विवाद पैदा होते हैं हालांकि साक्ष्यों और जागृतिगो से निस्संदेह रूप से यह सचेत मिलता है कि काफी लोग खुशहाल थे।

फिर भी यह तथ्य विवाद से परे और सवमान्य है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का औद्योगिक विकास समकालीन विश्व स्तर के सदम में काफी अधीन था। 1916-18 के भारतीय औद्योगिक जायोग ने इस वक्तव्य के साथ अपनी रिपोर्ट शुरू की

ऐसे समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में अमर्भ्य जनजातियाँ बसी हुई थी, भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यंत कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था। और काफी समय बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुँचे इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपमानास्पद अधिन विवर्धित यूरोपीय देशों से कम नहीं था (इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ 6)

आयोग के अध्यक्ष और भारत की यनिज सपदा के अधिकारी विद्वान सर थोमस हालैंड ने 1908 में अपनी रिपोर्ट में कहा

देश में तैयार लाहे की थ्रेण्ट किस्म, उच्च स्तर का इस्पात तैयार करने के लिए आज यूरोप में अपनाए जा रहे तरीके का पूवज्ञान, और तावे तथा पीतल के बने कलात्मक सामानों ने एक समय में भारत की धातुवर्मीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। ('दि मिनरल रिमोर्सेज आफ इंडिया', टो० एच० हालैंड की रिपोर्ट 1908)

यह ध्यान देने की बात है कि भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के लिए भौतिक परिस्थितियाँ इस हद तक तैयार थी कि लोह और इस्पात का उत्पादन काफी ऊँचे स्तर तक विकसित हो चुका था। हम आगे के अध्यायों में उन कारणों की खोजबीन करेंगे जिनकी वजह से ब्रिटिश शासनकाल में भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति का विनाश हुआ और उसका अपेक्षित पिछड़ी आर्थिक स्थिति में हुआ।

इस तथ्य को भी सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भारत में वे सभी प्राकृतिक साधन मौजूद हैं जो सर्वोच्च आधुनिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। कृषि के सदर्भ में, भारत सरकार की आर्थिक उत्पादना के बारे में रिपोर्ट देने वाले सर जॉन वाट के निष्कर्ष का उद्धृत करना प्रासंगिक होगा

मह स्वीकार कर लेना ज्यादा निरापद लगता है कि सिंचाई के विस्तार, परिवहन की सम्यक् और पूर्ण सुविधाएँ, कृषि के सामान और तरीकों में विकास तथा कृषियोग्य क्षेत्र का विस्तार करके—भारत की उत्पादकता को कम से कम 50 प्रतिशत तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। निश्चय ही यदि केवल अविकसित साधनों के अतर्भूत मूल्य और उनकी सीमा को देखा जाए तो विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनमें कृषि का इतना शानदार ढंग से विकास करने की संभावना है जितनी भारत में है।  
(सर जॉन वाट 'मेमोरेण्डम ऑन दि रिमोर्सेज आफ ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता, 1894 पृष्ठ 5)

इसमें भी ज्यादा बड़ी मात्रा में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक साधन मौजूद हैं। भारत के पास कीमती लाहा तेल, मगनीज, सोना, चांदी और तांबा प्रचुर मात्रा में हैं। (तेल के मामले में, नए विधान के अंतर्गत वर्मा के राजनीतिक पृथक्करण ने वर्तमान मुख्य मन्त्री का वाट दिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पृथक्करण के मुख्य कारणों में एक कारण यह भी था कि वर्मा के तेल पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभुत्व बना





मात्रा इतनी ज्यादा है कि यदि उनका इस समय इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसे उनकी बरबादी ही कहा जाएगा क्योंकि उनके इस्तेमाल से भारत में भी लोहे का उत्पादन उतना ही होता जितना अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और रूस जैसे देशों में औसतन होता है। इन देशों में औसत उत्पादन 1 करोड़ 62 लाख टन है जबकि भारत में मात्रा 18 लाख टन। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत में लोहे का उत्पादन कुल उत्पादन जितना होना चाहिए था उससे 11 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था और 89 प्रतिशत का अपव्यय माना जाना चाहिए। (आर० के० दास 'दि इंडस्ट्रियल एफिसिएसी इन इंडिया, 1930, पृष्ठ 17)

भारत के खनिज लोह भंडार के बारे में ताजा अनुमान अमरीकी तकनीकी मिशन ने पेश किया है। मिशन की रिपोर्ट से पता चलता है

भारत में कच्चे लोहे के भंडार संभवतः दुनिया में सबसे बड़े हैं और इसकी किस्म अत्यंत किसी देश के लोहे की तुलना में श्रेष्ठ है। अकेले सिंहभूम जिले में, 60 प्रतिशत अधिक लोहे के अशवाले कच्चे लोहे के भंडार अनुमानतः 3 अरब टन से कम नहीं और मुमकिन है कि यह 20 अरब टन तक हो। अनुमान लगाया गया है कि बस्तर राज्य में इन भंडारों में उत्तम किस्म का 72 करोड़ 40 लाख टन कच्चा लोहा है। मध्य प्रांत के पड़ोसी जिला में भी महत्वपूर्ण भंडार हैं। इनमें से एक राजहाना पहाड़ियों में है जिसमें अनुमानतः 25 लाख टन खनिज लोहा है और उसमें लोहे की मात्रा 67½ प्रतिशत है। (रिपोर्ट आफ दि अमेरिकन टेक्निकल मिशन टु इंडिया, अगस्त 1942 पृष्ठ 24)

1918 की औद्योगिक आयोग रिपोर्ट के अनुसार

'भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने भारत की खनिज संपदा की प्रकृति और मात्रा की व्यवस्थित ढंग से जाच-पड़ताल की है हालांकि पूर्वोक्त उपकरणों तथा व्यवस्था पर व्यय हटु सीमित धनराशि के कारण उस सिरे तक छानबीन के लिए काम करना असंभव ही रहा है जहां और जांच किए वगैर व्यापारिक कार्यों के लिए उम्मा उचित ठहराया जा सके, बहुत खास मामला की बात और है।

दंग व खनिज भंडार तमाम तथाकथित 'महत्वपूर्ण' उद्योगों का बनाए रखन के लिए पर्याप्त हैं। वे उद्योग काम चालू नहीं हो सकते जिनके लिए अनिवार्य निचला और संभवतः भारीवहन की जरूरत पड़ती है।

भारतीय महाद्वीप में कई हिस्से में कच्चा लोहा पाया जाता है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं हैं जिनमें अच्छे किस्म के खनिज और कोयले की सतोषजनक आपूर्ति के बीच पर्याप्त निकटता है हानाकि सभी सभावनाओं के साथ वर्तमान लोहा और इस्पात के काम का व्यापक विस्तार उचित ठहराया जा सकता है। (इंडियन इंडस्ट्रियल कमिशन रिपोर्ट, पृष्ठ 36)

भारत के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के स्थानापन्न सुपरिंटेंडेंट डाक्टर सी० एस० फ्रांस ने अमेरिकी खान इंजीनियर सी० पी० पेरिन के अनुमान को उद्धृत किया है। सी० पी० पेरिन पिछले लगभग 25 वर्षों से इंडियन आयरन ऐंड स्टील इंडस्ट्री के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यदि एक चतुर्भुज बनाए जिसका उत्तर-पूर्व कोण कलकत्ता हो तो इस शहर से 400 मील पश्चिम और 200 मील दक्षिण में उत्तम कोटि का 20 अरब टन खनिज लोहा है जो बंगाल के कायला क्षेत्र से औसतन 125 मील की दूरी पर है। (इस्पात उद्योग को सुरक्षा देने के संवध में इंडियन टरिफ बोर्ड की रिपोर्ट, 1924)

यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'प्रवध के खर्च चलाने और पूर्वेक्षण उपकरणों के लिए सीमित धनराशि' इसीलिए दी गई है वह खोजबीन का काम इतना न बढ़ा ले जिससे हम अपार प्राकृतिक संपदा का उपयोग भारत की समृद्धि बढ़ाने के लिए होने लगे। इस प्रकार इसका व्यौरा केवल कागजों पर ही रज है—ठीक वैसे जैसे कोई खगोल वैज्ञानिक अपने कागजों में तारों, नक्षत्रों का नक्शा खींच रखा हो। 1933-34 में संपूर्ण 'वैज्ञानिक विभागों' पर कुल व्यय समूचे सरकारी खर्चों के 1 प्रतिशत का एक तिहाई हिस्सा तथा सैनिक व्यय के 1/5 वें हिस्से से भी कम था। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह रिपोर्ट बड़े अनिश्चित ढंग में मात्र इतना मनेत देती है कि कायला और लाहा अपनी सारी सभाव्यता में इतने पर्याप्त हैं कि वर्तमान लोहा और इस्पात के काम का व्यापक विस्तार उचित ठहराया जा सकता है।'

#### जलशक्ति साधन

| देश          | संभावित | (दस लाख हास पावर में) |                |
|--------------|---------|-----------------------|----------------|
|              |         | विकसित                | प्रतिशत विकसित |
| अमेरिका      | 350     | 117                   | 33             |
| कनाडा        | 182     | 45                    | 25             |
| फ्रांस       | 54      | 21                    | 37             |
| जापान        | 45      | 17                    | 37             |
| इटली         | 38      | 18                    | 47             |
| स्विट्जरलैंड | 25      | 18                    | 72             |
| जर्मनी       | 20      | 11                    | 55             |
| भारत         | 270     | 08                    | 3              |

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज भारत की जलशक्ति है। भारत के विजलीकरण के लिए इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इन क्षमताओं की अवहलना की जा रही है। पृष्ठ 49 पर दी हुई तालिका में भारत के साथ तुलना करते हुए दुनिया के प्रमुख दश के जलशक्ति साधनों और उनके इस्तेमाल के अनुपात को (वर्ल्ड अलमनाक 1932) में दिखाया गया है।

जलशक्ति के मामले में अमरीका के बाद भारत का ही स्थान है फिर भी वह अपने इन साधनों के केवल 3 प्रतिशत का ही उपयोग करता है जबकि उसकी तुलना में स्विट्जरलैंड 72 प्रतिशत जमनी 55 प्रतिशत, इटली 47 प्रतिशत, फ्रांस और जापान 33 प्रतिशत और अमरीका 33 प्रतिशत भाग इस्तेमाल कर रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था का चाह जो भी पहलू लें, यही तस्वीर सामने उभरती है कि यहाँ अभी भी मभावनाओं से युक्त मपदा है लेकिन वर्तमान शासन व्यवस्था में उसकी वस्तुतः अवहलना की गई है और विकास का काम नहीं हुआ है। इस स्थिति के खतरे को स्वयं महााज्यवादियों ने महसूस किया है हालांकि उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। वस्तुतः से प्रकाशित भारत के प्रमुख अगरेजी अखबार 'स्टेट्समैन' के मपदाव और 'दि टाइम्स' के वक्तव्य में वर्णित महााददाता सर अल्फ्रेड ने 1933 में रायल इंपायर गोसायटी की एक बैठक में आगाह किया था

सर अल्फ्रेड वाटसन ने कहा कि भारत खाए हुए अवसरों का देश है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर है। यद्यपि भारत के पाग के मारी देशों प्रचुर मात्रा में हैं जिनमें कोई देश महान औद्योगिक देश बनता है लेकिन वह आज अधिकांश दुष्ट दुनिया के पिछड़े देशों में से एक है और उद्योग के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है हमने उद्योग के मामले में भारत की अग्रगण्य क्षमता का विवेकित करने की समस्या पर कभी गंभीरता से काम नहीं किया

यदि आप वाद करेंगे कि भारत अपनी विशाल आबादी की बढ़ी हुई मांग के आधार पर विनियुक्त ही अभूतपूर्व दम में अपना औद्योगिक विकास नहीं करता तो आप का जीवननिर्वाण मल जा अभी ही भयानक रूप में नीचा है भूमण्डलीय स्तर पर भी नीचे गिर जाएगा। (सर अल्फ्रेड वाटसन, रायल इंपायर गोसायटी में भारत में 'दि टाइम्स' 4 जनवरी 1933)

**भारत की मगीची**

भारत की महााददातों की अग्रगण्य क्षमता और उस विवेकित करने में विफलता की

पृष्ठभूमि में भारतीय जनता की भयानक गरीबी अपने अनिष्टकारी महत्व के साथ स्पष्ट दिखाई दे रही है।

भारतीय आकड़े प्रशासन तंत्र को संचालित करने की दृष्टि से तो बेहद भारी भरकम हैं लेकिन जब उन आकड़ा से जनता की हालत की स्थिति का पता लगाने का प्रश्न उठता है तो वे बिल्कुल व्यर्थ और अनुपयोगी साबित होते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा औसत आय के बारे में कोई आधिकारिक आकलन नहीं है। (विभिन्न सरकारी जाच-पड़ताली के नतीजों को निजी और गोपनीय रखा गया है।) यह ठीक वैसे ही है जैसे भारत या समूचे ब्रिटिश भारत के लिए कोई नियमित आकड़े नहीं हैं जो कुल उत्पादन, वेतन दरों या मजदूरी के औसत स्तर, काम के घंटों या मजदूरी की शर्तों की जानकारी दें। स्वास्थ्य के धारे में कोई पर्याप्त आकड़े नहीं हैं और न ही आवास के धारे में आकड़े उपलब्ध हैं।

प्रतिव्यक्ति औसत आय के आकलनों का एक अनुक्रम तैयार किया गया है और उसपर तीव्र विवाद पैदा हुआ है। इनमें 1868 से युद्ध के बाद तक के आकलन शामिल हैं

#### प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन

| आकलनकर्ता   | सरकारी या<br>गैरसरकारी | जिस वर्ष<br>किया गया | वर्ष से<br>संबंधित | प्रति व्यक्ति<br>वार्षिक आय<br>रु०    शि० |     |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|---|-----|
| डी० नोरोजी <sup>3</sup>                                       | गैरसरकारी              | 1876                 | 1968               | 20  | 40  |
| वेरिंग एंड वारनर  | सरकारी                 | 1882                 | 1881               | 27  | 45  |
| लाड वजन   | सरकारी                 | 1901                 | 1997-98            | 30  | 40  |
| डब्ल्यू० डिग्वी <sup>4</sup>                                  | गैरसरकारी              | 1902                 | 1899               | 18  | 24  |
| फिडले सिराज   | सरकारी                 | 1924                 | 1911               | 49  | 65  |
| वाडिया एंड जोशी <sup>5</sup>                                  | गैरसरकारी              | 1925                 | 1913-14            | 44½                                       | 59  |
| शाह एंड खन्ना <sup>7</sup>                                    | गैरसरकारी              | 1924                 | 1921-22            | 74  | 95  |
| साइमन रिपोर्ट   | सरकारी                 | 1930                 | 1921-22            | 116                                       | 155 |
| बी० के० आर० बी० राव <sup>8</sup>                              | गैरसरकारी              | 1939                 | 1925-29            | 78  | 117 |
| सेंटल बैंकिंग इक्वायरी<br>कमेटी (बैंक कृषीय-<br>आवादी के लिए) | सरकारी                 | 1931                 | 1928               | 42  | 63  |
| फिडले मिराज <sup>9</sup>                                      | सरकारी                 | 1932                 | 1931               | 63  | 94½ |
| सर जेम्स ग्रिग <sup>10</sup>                                  | सरकारी                 | 1938                 | 1937-38            | 56  | 84  |
| बी० के० आर० बी० राव <sup>11</sup>                             | गैरसरकारी              | 1940                 | 1931-32            | 62  | 93  |

गणना के आधार में भिन्नताओं तथा साथ ही मूल्यों के स्तर में दूरगामी परिवर्तनों के कारण इन अंकों का मिलान नहीं किया जा सकता। भारतीय कीमती का सूचक अंक, जो 1873 में 100 था (39 सामान अभारित लेकिन इसमें 1897 तक व्यापार नहीं शामिल थे), 1900 तक बढ़कर 116, 1913 तक 143 और 1920 तक 281 हो गया। इसके बाद इसमें गिरावट आई और 1931 में यह 236, 1925 में 227, 1930 में 171 और 1936 में 125 हो गया।

गणना के आधार से काफी व्यापक उतार-चढ़ाव का भी पता चलता है और विभिन्न आकलनों को मात्र प्रारंभिक संकेतों के रूप में लिया जा सकता है। इससे पुराने सरकारी आकलन खेतीबाड़ी से हुई आमदनी के कुल मूल्य (प्रायः निश्चित रूप से वास्तविकता से अधिक मूल्यांकन) पर आधारित थे। डिग्री के आयु में से आय की राशि को सेवा के लिए निकाल दिया गया है। सबसे अधिक मशहूर और प्रायः सामान्य रूप से स्वीकृत आंकड़े नौरोजी तथा मेजर वेरिंग (बाद में लार्ड नोमर) के थे। नौरोजी का आकलन 1868 के लिए था जिसमें प्रति व्यक्ति आय 2 पाँड बताई गई थी। मेजर वेरिंग ने अपने आकलन की घोषणा 1882 में की थी और इसमें प्रति व्यक्ति आय 2 पाँड 5 शिलिंग थी। ये आंकड़े खुद ही बताते हैं कि एक सौ से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किए जाने के बाद भी भारत की स्थिति स्वयं सरकारी आंकड़ों के अनुसार क्या थी।

बाद के आंकड़ों से ज्यादा उतार-चढ़ाव का पता चलता है। आंशिक रूप से यह कीमतों की बेहद अस्थिरता की झलक देता है। 1912 से 1920 के दौरान कीमती में दुगुने से भी ज्यादा वृद्धि हो गई और फिर एक दशक बाद, 1931 से उसमें गिरावट आई जो युद्धपूर्व के स्तर तक पहुँच गई। प्रोफेसर फिडल गिराज के युद्धोत्तर आकलनों में भी यह माना गया है कि युद्ध के बाद गैर-कृषीय आय के अनुपात में वृद्धि हुई है। प्रोफेसर गिराज 1914 से 1921 तक भारत सरकार के सांख्यिकी निदेशक के पद पर रह चुके हैं।

1930 में साइमन कमिशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका पहला भाग, भारत में साम्राज्यवादी शासन की सफाई के लिए बड़ी संख्या में वितरित करने के उद्देश्य से लिखा गया था। इसमें जोसल भारतीय आय को काफी बढ़ा-चढ़ाकर लगभग 8 पाँड प्रतिव्यक्ति बताया गया। इस अनुमान का बाद में खूब प्रचार किया गया। चूंकि इस अनुमान में बताया गई राशि इससे पहले पेश किए गए किसी भी अनुमान की तुलना में अधिक थी, इस लिए उसके आधार की जांच करने की आवश्यकता थी।

साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में तैयार की थी। प्रथम विश्व युद्ध हुए उस समय लगभग दस वर्ष बीत चुके थे लेकिन उसमें अपनी गणना का आधार विश्व युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों को बनाया जब चीजों की कीमतें काफी बढ़ गई थी।

इसने 1919-20 1920-21 और 1921-22 के दौरान औसत आय के, जो 74 रुपये से 116 रुपये के बीच था। तमाम आवलनों का हवाला दिया। इसके बाद कमीशन ने इन वर्षों की सबसे ऊँची मूल्य को चुनकर उस 'उपयुक्त आवलन' में सर्वाधिक आशावादी' मूल्य (खंड 1, पृष्ठ 314) का नाम दिया। फिर उसने बाद की गणनाओं में इस असाधारण मूल्य का इस्तेमाल किया और इसे पूरी अवधि की प्रतिनिधि मूल्य मान लिया हालाँकि हमने उस मूल्य का प्रतिनिधित्व किया था जो युद्ध के बाद हुई सहसा वृद्धि के काफी निकट थी (यह मानकर कि इस बीच मूल्यों में गिरावट आ गई है, इन्हें आज उच्च अंश में नहीं पेश किया जा सकता', खंड 2 पृष्ठ 207—दरअसल मूल्य सूचक अब 1920 में 281 से घटकर 1930 में 171 और 1934 तक 119 हो गया था) और इस अति-शयोक्तिपूर्ण मूल्य को उसने अंगरेजी मुद्रा में लगभग 8 पौंड (8 पौंड से कम) प्रतिवर्ष के बराबर रखकर इसे औसत भारतीय की वार्षिक आय कहा जबकि औसत अंगरेजी की आय 95 पौंड प्रतिवर्ष थी।

इस सबके बावजूद साइमन कमीशन ने 1921-22 में भारतीयों की औसत आय का जो सबसे अधिक आशावादी अनुमान लगाया वह प्रतिदिन 5 पैसे के बराबर था। फिर भी वास्तविक तथ्यों के ज्यादा करीब पहुँचने के लिए यह जरूरी है कि गणना के समय जिन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया उनपर हम ध्यान दें और आवश्यक सुधार करें।

भारतीय कीमती का भारत सरकार द्वारा निधारित सूचक अब 1921 में 236 से घटकर 1936 में 125 हो गया अर्थात् लगभग आधा हो गया। इस मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कृषि-उत्पादन जो भारतीयों की आय का मुख्य आधार है। 1921 और 1936 के बीच अनाज की फुटकर कीमती का सूचक अब सामान्य तौर पर आधे से भी ज्यादा कम रह गया। यह अब चावल के लिए 355 से 178, गेहूँ के लिए 360 से 152, चना के लिए 406 से 105 और जौ के लिए 325 से 134 हो गया।

इस प्रकार यदि अनाज की कीमती में हुई गिरावट को भी ध्यान में रखा जाए तो 1921-22 में साइमन कमीशन ने 5 पैसे प्रतिदिन की औसत आय का जो अनुमान लगाया था, वह युद्ध से पूर्व की अवधि में ढाई पैसे प्रतिदिन ही रह गया।

चिंतु यह भी विशाल बहुमत की वास्तविक आय नहीं बल्कि कुल औसत आय है। इसमें से वह राशि घटानी होगी जो साम्राज्यवाद द्वारा घरेलू खर्च के नाम पर और नजराने के नाम पर वसूल की जाती थी (इनमें ऋण पर व्याज, ब्रिटिश पूँजी निवेश पर लाभांश, बकाया तथा महाजनो का कमीशन शामिल है) और भारत से बाहर भेज दी जाती थी तथा बदले में ब्रिटन से भारत में कोई माल नहीं आता था। शाह और खवाता का अनुमान है

कि इस तरह कुल राष्ट्रीय आय का दसवें से कुछ अधिक भाग देश के बाहर चला जाता है। इस प्रकार जो आय प्रतिदिन ढाई पैसे की वह केवल सवा दो पैसे प्रतिदिन रह जाती है।

इसके बाद हमें इस औसत आय में शामिल आय की वृद्धि अममानता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि साइमन कमीशन के इस आकड़े को सही माने कि ब्रिटन में औसत आय प्रति व्यक्ति 95 पाउंड है तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक पत्नी और तीन बच्चों वाले औसत मजदूर को साल भर में 475 पाउंड मिलता है। वस्तुतः जो मजदूर इसका आधा प्राप्त करता है वह बेहद लाभप्रद स्थिति में है और औसत मजदूर को अधिक से अधिक एक तिहाई, आमतौर से एक तिहाई से कम ही प्राप्त होता है। वितरण की यही अममानता भारत पर भी लागू होती है। प्रोफेसर के० टी० शाह और के० जे० खन्ना ने अपनी पुस्तक 'वैल्यू ऐड टैक्सेशन कैंपेनिटी आफ इंडिया' (1924) में बताया है कि आबादी के 1 प्रतिशत हिस्से को राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग मिलता है जबकि कुल आबादी के 60 प्रतिशत को राष्ट्रीय आय का सिर्फ 30 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। इसका अर्थ यह है कि आबादी के 60 प्रतिशत भाग या आबादी के बहुमत की वास्तविक औसत आय का पता लगाने के लिए प्रति व्यक्ति कुल औसत राष्ट्रीय आय को आधा करना पड़ेगा।<sup>1</sup>

इस प्रकार यदि हम साइमन कमीशन के सबसे अधिक आशावादी अनुमान पर आय के वितरण के आकड़ा को लागू करें तथा बाद में आने वाली मंदी तथा साम्राज्यवाद द्वारा वसूले गए घरेलू खर्च और नजराने के रूप में देश से बाहर जाने वाली राशि पर ध्यान दें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में भारत की आबादी के अधिकांश के औसत व्यक्ति की दैनिक आय एक पैसे से सवा पैसे तक है।

यह हिसाब लगाने में हम उस बात पर ध्यान दिया गया है जो साम्राज्यवाद के अनुकूल है और इसका आधार खुद साम्राज्यवाद के आकलन है।

सामान्य तौर पर जो अनुमान लगाया गया है (ठीक ठीक आकड़ा के अभाव में इतना ही लिया जा सकता है) उसकी पुष्टि हाल ही में सरकारी सूत्रों से प्राप्त दो और आकलनों से होती है। 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था

प्रांतीय समितियों की रिपोर्टों तथा अन्य प्रकाशित सांख्यिकीय सूचनाओं से पता चलता है कि 1928 के मूल्य स्तरों के आधार पर वार्षिक कृषि उत्पादन का कुल मूल्य 12 अरब रुपये है। कुछ महायुद्ध व्यवसायों में हुई सम्पत्ति आय का जो अनुमानित कृषि आय की 20 प्रतिशत है ध्यान में रखकर और

आधार बनाकर तथा पिछले दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि एवं 1929 से कीमती म आई गिरावट की उपक्षा करके दखे तो ब्रिटिश भारत में किसी खेतिहर की औसत आय लगभग 42 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं आती जो 3 पौंड प्रतिवर्ष से थोड़ा ही अधिक है। (रिपोर्ट आफ दि इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी, 1931 पृष्ठ 1, पृष्ठ 39)

इससे पता चलता है कि कृषि काम में लग लागो की कुल आय प्रतिव्यक्ति 2 पैसे है। यह आंकड़ा 1928 के मूल्य स्तर पर आधारित है। 1928 और 1936 के बीच कीमतों का सूचक अंक 201 से घटकर 125 हो गया। इससे 2 पैसे प्रतिदिन की आय घटकर सप्ताह में 14 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी।

अप्रैल 1936 में भारत सरकार के वित्तमन्त्री सर जेम्स प्रिंस ने अनुमान लगाया कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय 16 अरब रुपये या 1 अरब 20 करोड़ पौंड है। ये आंकड़े कुल राष्ट्रीय आय तथा करारपण के बीच अनुपात दिखाने के उद्देश्य से पेश किए गए थे। यदि यह मानकर चलें कि ये आंकड़े केवल ब्रिटिश भारत पर लागू होते हैं (यदि ये आंकड़े समूचे भारत के लिए हैं तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय यथानुपात और भी कम होगी) और इस राशि को ब्रिटिश भारत की जनसंख्या से विभाजित कर दें, जो 1938 में अनुमानित 28 करोड़ 50 लाख थी, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रतिव्यक्ति कुल औसत आय 56 रुपये या 84 शिलिंग थी। आमदनी के इस वितरण के आंकड़ों को इस कुल राशि पर लागू करें (अर्थात् 60 प्रतिशत आबादी जो 30 प्रतिशत की आमदनी की हिस्सेदार है) तो हम फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश भारत में आबादी के विशाल हिस्से के औसत भारतीय की आय 138 पैसे प्रतिदिन या 125 पैसे प्रतिदिन से थोड़ी अधिक थी। डाक्टर वी० के० आर० वी० राव ने कुल आय 62 रुपये या 93 शिलिंग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष का अनुमान लगाया है।<sup>13</sup> प्रोफेसर शाह और खन्ना द्वारा सिद्ध किए गए अनुपात को फिर लागू करने पर हमें पता चलता है कि भारतीय जनता की अधिकांश आबादी की औसत आय लगभग डेढ़ पैसे प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति है।

ये आंकड़े महज इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि इनसे हम भारत की गरीबी की भयंकरता का एक प्रारम्भिक आभास मिल जाता है। रहन-सहन की परिस्थितियों के रूप में इन आंकड़ों का क्या महत्व है? प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री शाह और खन्ना ने इसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया है

औसत भारतीय की आय महज इतनी है कि जिसमें या तो हर तीन व्यक्तियों में से दो को खाना मिल सके या उन सबको आवश्यक तीन वस्तुओं के भोजन के स्थान पर दो वस्तुओं का भोजन दिया जा सके वगैरह वे सब इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें बिना कोई कपड़ा पहन रहना है पूरा वर्ष घर के



बाहर आसमान के नीचे बिताना है, किसी प्रकार का आमोद प्रमोद या मनोरंजन नहीं करना है और सबसे घटिया, सबसे रद्दी और सबसे कम पोष्टिक भोजन के अलावा और किसी चीज की मांग नहीं करनी है। (शाह और खन्ना दि बल्क एंड टैक्सबल कैपेसिटी आफ इंडिया, 1924, पृष्ठ 253)

जेल सहिता (जेल कोड) और अकाल सहिता (फैमिन कोड) के खर्चों की तुलना स अभिप्राय का कुछ पता लगाया जा सकता है। 1939 में भारत में एक कैदी की देखरेख पर प्रतिवर्ष 116 67 रुपये खर्च होता था जो बैंकिंग जाच समिति द्वारा अनुमानित भारतीय खेतियार की औसत आमदनी का लगभग तीन गुना है। 1923 में बंबई में मजदूर वर्ग के आय-व्यय की सरकारी जाच से मजदूरों के जीवनस्तर और जेलसहिता तथा अकाल सहिता के जीवनस्तर का अग्रवर्ति साम्य का पता चलता है

### प्रतिवर्षिक पुरुष द्वारा दैनिक उपभोग

| बंबई के<br>मजदूरों का बजट | बंबई की जेलें |            | बंबई<br>अकाल सहिता<br>(बलदार) |
|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------|
|                           | कठोर श्रम     | हल्का श्रम |                               |
| अनाज 1 29 पौंड            | 1 05 पौंड     | 1 38 पौंड  | 1 29 पौंड                     |
| दाल 0 09 "                | 0 27 "        | 0 21 "     | —                             |
| मांस 0 03 "               | 0 04 "        | 0 04 "     | आकड़े                         |
| नमक 0 04 "                | 0 03 "        | 0 03 "     | उपलब्ध                        |
| तल 0 02 "                 | 0 03 "        | 0 03 "     | नहीं है                       |
| अन्य 0 07 "               | —             | —          |                               |
| चीजें                     |               |            |                               |
| 1 54 पौंड                 | 1 42 पौंड     | 1 69 पौंड  |                               |

(रिपोर्ट ऑन एन इक्वायरी इंटु बंकिंग क्लास बजट्स इन बांब, बांब लेबर आफिस, 1923)

बंबई में मजदूर, जो गांवों में रहने वाली आम जनता से बहुत स्थिति में है, अकाल के मिलने वाले राशन के स्तर पर और कदिया में मिलने वाले जल राशन से भी नीचे स्तर पर अपनी राटी चला पाता पाता है।<sup>11</sup>

जहां तक साल दर साल आम जनता की स्थिति का प्रश्न है सरकारी रिपोर्टों से एसी ही तस्वीर सामना आती है

‘भारत में अत्यंत कुशल कामगरो को छोड़कर अन्य कामगरो को जो मजदूरी मिलती है वह उनके राटी-कपडे व छत्र को चला पाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। चारो तरफ बेहद भीड़ गंदगी, फटेहाली तथा कगाली देखी जा सकती है।’ (‘इंडिया इन 1927-28’)

‘भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी इस तरह की निधनता से ग्रस्त है जिसकी तुलना समूचे पश्चिमी जगत के किसी भी देश से नहीं की जा सकती। यहां की अधिकांश जनता किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए है।’ (‘इंडिया इन 1929-30’)

‘आज भी 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत लोग किमी तरह जी रहे हैं।’  
(सर अल्फ्रेड चैटटन जनरल आफ दि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जुलाई 1930)

1933 में भारतीय चिकित्सा सेवा के निदेशक मेजर जनरल सर जान मेगा ने जन स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि कुल आबादी के 39 प्रतिशत लोगों का अच्छी तरह पोषण होता है, 41 प्रतिशत लोगों का बुरी तरह पोषण होता है और 20 प्रतिशत लोगों का अत्यंत बुरी तरह पोषण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 61 प्रतिशत लोग या दो तिहाई हिस्सा अल्पपोषण का शिकार हैं। बंगाल के लिए यह संख्या क्रमशः 22 प्रतिशत, 47 प्रतिशत और 31 प्रतिशत है अर्थात् बंगाल में 78 प्रतिशत लोग या पांच में से लगभग चार लोग अल्पपोषण के शिकार हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि ‘भारत भर में बीमारी फैली है और यह लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है।’

पोषक आहार विशेषज्ञ डा० ऐंकायड का कहना है कि भारत में कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा लगातार अल्पपोषण का शिकार रहा है।’ (फूड ग्रेस पालिसी कमेटी की रिपोर्ट में उद्धृत, 1943, पृष्ठ 33)

1926 में सरकार ने भारत में कृषि के लिए एक राज आयोग नियुक्त किया था। हालांकि विषयो की सीमा के कारण उसने जमीन की मिल्कियत एवं वास्तविकी, लगान और भू राजस्व की वसूली की असल समस्याओं पर, जिनके कारण गरीबी व्याप्त है, विचार ही नहीं किया लेकिन स्वयं सरकारी अधिकारियों ने आयोग के कार्यालय में किसानों की भयानक हालत के प्रमाणों का अबार लगा दिया। भारत सरकार के कृषि सलाहकार और आयोग के समक्ष प्रथम गवाह डाक्टर डी० क्लाउस्टन ने बताया कि गांवों की जनता शारीरिक रूप से कमजोर है और आसानी से महामारियों का शिकार हो जाती है।’ वनल ग्राह्य ने आयोग को बताया कि ‘कृषि के क्षेत्र में सुधार के रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई किसानों की पोष्टिक आहार का न मिलना है।’ कूतूर के पस्चर इस्टीमेट

में अभावजन्य बीमारियों की जाच-पड़ताल के सचालक लेफ्टिनेंट कर्नल आर० मैक हैरिसन न तो और भी ज़रदार शर्दा में कहा

भारत में जनता जिन अनेक अममथताओं से ग्रस्त है उनमें शायद सबसे बड़ी चीज है पोष्टिक आहार का अभाव । भारत में बीमारियों के जितने भी कारण हैं उनमें सबसे व्यापक कारण कुपोषण है । (लेफ्टिनेंट कर्नल आर० मैक हैरिसन 'मेमोरैंडम आन माल-यूट्रिशन ऐज ए काज आफ फिजिकल इनएफिसिएंसी ऐंड दल हेल्थ एमग दि मासेज इन इंडिया, वृषि मन्त्री राज आयोग के समक्ष साक्ष्य' । (पृष्ठ 95) ।

1929 में सरकार ने भारत के मजदूरों की हालत की जाच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग ने पता लगाया कि 'अधिकांश औद्योगिक केंद्रों में कज के बोम से दवे व्यक्तियों और परिवारों की मख्या, कुल आबादी की दो तिहाई से कम नहीं है अधिकांश व्यक्तियां पर जितना कज है वह उनकी तीन महीनों की तनम्वाह से ज्यादा है और प्रायः काफी ज्यादा है । (पृष्ठ 224)

इसने पाया कि विभिन्न उद्योगों में लगे मजदूरों के वेतन में काफी अंतर है । बंबई की सूती कमंडा मिल का पुरुष मजदूर 56 शिलिंग प्रतिमाह और महिला मजदूर 26 शिलिंग प्रतिमाह पाती है, बंबई के अकुशल मजदूरों का वेतन 30 शिलिंग प्रतिमाह, मुख्य शरिया कोयला खान में खदान मजदूरों का वेतन औसतन 15 शिलिंग से 22 शिलिंग प्रतिमाह है, मौसमी कारखानों में पुरुषों की मजदूरी 6 पैसे से 1 शिलिंग प्रतिदिन और महिलाओं की 4 पैसे से 9 पैसे प्रतिदिन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अकुशल मजदूरों को 9 पैसे प्रतिदिन और महिलाओं को 6 पैसे प्रतिदिन तथा बच्चों को 4 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है, मद्रास और समुक्त प्रांत में पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी 5 पैसे प्रतिदिन तक है । उसने देखा कि 'अनियमित' कारखाना और उद्योगों में, जहां भारत के औद्योगिक मजदूरों की काफी बड़ी संख्या नौकरी में है, कुछ स्थानों में 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे मजदूरी करते हैं । उन सर्वाधिक मुकुमार वर्गों में उह 1 तो खाने के लिए पर्याप्त छुट्टी मिलती है और न हफ्त में एक दिन के लिए अवकाश मिलता है, महज दो आने (2 25 पैसे) के लिए उह प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है । (पृष्ठ 96)

जहां तक लोग रहने के लिए मकान का संबंध है औसत मजदूर परिवार के पास एक काठरी भी नहीं है । प्रायः एक ही कोठरी में कई परिवार अपनी गुजर करते हैं । 1911 में बंबई की समूची आबादी 69 प्रतिशत हिंसा एक कमरे में रहता था (जबकि उसी वर्ष लंदन में इस तरह रहने वाला की संख्या 6 प्रतिशत थी) और प्रत्येक कमरे में औसतन 4.5 व्यक्ति रहते थे । 1931 की जनगणना के अनुसार बंबई की कुल आबादी का 74 प्रतिशत

हिस्सा एक कमरे की चाल में रहता था, इससे पता चलता है कि बीस वर्षों के बाद अति-मजदूरी में वृद्धि हो गई। आबादी का एक तिहाई भाग एक कोठरी में पांच आदमियों के हिसाब से रहता था, 2,56,379 व्यक्ति एक कोठरी में 6 से लेकर 9 आदमियों तक के हिसाब से रहते थे, 8,133 व्यक्ति एक कोठरी में 10 से लेकर 19 आदमियों तक के हिसाब से रहते थे, 15,490 व्यक्ति एक कोठरी में 20 या इससे अधिक आदमियों के हिसाब से रहते थे। यह भयानक जनमजदूरी उस समय और स्पष्ट दिखाई देती है जब सवहारा की दशाएँ औसत में शामिल करके नहीं अपितु अलग से देखी जाती हैं।

1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सूती कपड़ा मजदूरी की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जिसने 1940 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया

बंबई में जांच का काम ई, एफ और जी बांड तक सीमित था क्योंकि यही मुख्य रूप से मजदूरी की वस्तु थी। एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि जांच के दौरान जिन परिवारों से संपर्क किया गया उनमें से 91.24 प्रतिशत एक कोठरी की चाल में रहते हैं और इस तरह की प्रत्येक चाल में औसतन 3.84 व्यक्ति रहते हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्ध फण और चाल का क्षेत्रफल क्रमशः 26.86 और 103.23 वर्ग फीट है। (टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट, खंड-2, 1940, पृष्ठ 273)

ब्रिटिश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कराची में समूची आबादी का एक तिहाई भाग एक कमरे में 6 से 9 व्यक्तियों के हिसाब से है। अहमदाबाद में 73 प्रतिशत मजदूर वर्ग एक कमरे के मकान में रहता था।

रहन सहन की स्थिति 1931 के बाद और खासतौर से युद्ध के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई। बंबई की आबादी 1945 में बढ़कर 23 लाख हो गई जबकि 1931 में यह 11 लाख और 1941 में 14 लाख 81 हजार थी। लेकिन इसके साथ ही 1931 के बाद से मकानों की संख्या में केवल 83,828 की ही वृद्धि हुई। प्रति मकान कुल औसत 7.01 है, जबकि 1931 में यह 4.01 था। बेशक एक कोठरी की चाल की तुलना में बड़ी चाल में भीड़भाड़ काफी अधिक है।

आवास समिति (बंबई नगरपालिका द्वारा नियुक्त समिति) ने बंबई में प्रतिव्यक्ति औसत उपलब्ध धरातल 12 वर्गफीट निर्धारित किया जबकि बंबई कारागार मैनुअल के अनुसार मैदिया तक का प्रतिव्यक्ति 40 वर्गफीट की जगह देने की व्यवस्था है। (रिपोर्ट आफ दि हाउसिंग पैनल, जनवरी 1946)

इसके अलावा बंबई की आबादी का 13 प्रतिशत भाग आज सबको पर सो रहा है। जब

कि युद्ध से पूर्व सड़को पर सोने वालों की सट्या 5 प्रतिशत थी। जहाँ तक सफाई का संबंध है विहटले कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया

सफाई की तरफ बरती जा रही लापरवाही का सन्नत प्रायः सड़ते हुए कूड़े के ढेरा और गंदे पानी के गड्ढों से मिल जाती है जबकि शौचालयों के अभाव में सामान्यतः हवा और मिटटी का दूषण बढ़ जाता है। मकानों में भी अविवाश एमें ह जिनकी न तो कोई नींव है और जिनमें न तो कोई छिड़की है, केवल उसी ओर कमरा खुला होता है जिस ओर दरवाजा होता है और वह भी इतना नीचा होता है कि बिना थुके उसमें से होकर अंदर नहीं जाया जा सकता। पर्दा करने के लिए मिटटी के तेल के पुराने कनस्तरा और पुरानी बोरिया का इस्तमाल किया जाता है जिनसे रोशनी और हवा आने में और भी रुकावट पैदा होती है। इस तरह की कोठरियों में लोग पैदा होते हैं, सोते हैं, खाते-पीते हैं जिंदगी बिताते हैं और मर जाते हैं। (पृष्ठ 271)

बंबई के श्रम कार्यालय ने 1932-33 में मजदूरों के बजट की जाच की और पाया कि इनके घरों में से 26 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें आठ या उससे कम घरों के लिए पानी का एक नल है 44 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें 9 से 15 घरों के लिए एक नल है और 29 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें 16 या इससे अधिक घरों के लिए एक नल है (रिपोर्ट जाफ इक्वायरी इटु वर्किंग क्लास बजटम इन बावे 1935)। इनमें 85 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें 8 या इससे कम घरों के लिए एक शौचालय है, 12 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें 9 से 15 घरों के लिए एक शौचालय है और 24 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें 16 या इससे अधिक घरों के लिए एक शौचालय है। 1935 में अहमदाबाद सूती मिल मजदूर संघ ने औद्योगिक आवास के बारे में एक जाच की और पाया कि जिन 23,706 मकानों की जाच की गई उनमें से 5,669 के पास किसी भी पानी की किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी जबकि वे लोग जिन्हें पानी की सप्लाई की जाती थी, उनमें से 200 या इससे अधिक परिवारों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में एक दो नल थे, 5,000 मकानों में पाखानों की कोई व्यवस्था नहीं थी, सफाई या जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। औद्योगिक आयोग के समक्ष एक गवाह ने अपने बयान में कहा

हालांकि मैं अपनी जिंदगी में और अनेक देशों में पर्याप्त गरीबी देखी है और हालांकि मैं गरीबी के बारे में काफी कुछ पढ़ा भी है तथापि बंबई में इन बहुत गरीब जागों के तथाकथित घरों की दृष्टि से पहले मैंने इसकी दृष्ट्यविदारकता और चरम बदनसौबी का अनुभव नहीं किया था (मजदूरों के) उसने परिवार के साथ उस घर में देखते ही खुद अपने में अनापाम ही गवान पड़ना पड़ता है क्या यह भी मनुष्य है या मैं ही पातान नाम के किसी बाल्यनिक निर्जीव प्राणी का जादू से बुला रहा हूँ ?

एक 10 फीट लंब और 10 फीट चौड़े कमरे में, जहाँ हिमलट्टुने की जगह भी

मुश्किल से ही हो, पूरा परिवार सोता है, पलता है, गोबर की तीखी गंधवाले उपलो की मदद से घाना बनाता है, अपने पारिवारिक जीवन क सभी समारोह मनाता है, बस केवल उनका सामूहिक शौचानय उनसे अलग रहता है। पुराने मकान की तथाकथित ऊपरी मजिन पर के कुछ कमरे जिनमे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा सकता, एक ढलवा छत के नीचे बने मुराब से ज्यादा कुछ नहीं है। पीछे के कमरे आमतौर से अंधेरे और उदास है और काफी गौर से देखन पर तथा उस अधवार से आखा के अभ्यस्त हा जान पर ही उन कमरा म रहने वाले लागो को दखा जा सकता है। (प० ई० माइरम्स एविडेंस बिफार दि इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, 4, पृष्ठ 354)

इन स्थितिया की जाच के लिए बंबई सरकार द्वारा नियुक्त एक भारतीय महिला डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट मे बताया

एक चाल की दूसरी मजिल पर 15 फीट लव और 12 फीट चौड़े कमरे म मैं छ परिवारो को रहते देखा। कमरे म इन छ परिवारो के अलग अलग चूल्ह बने हुए थे। जाच करने पर मुझे पता चला कि इस कमरे मे रहने वाल बयस्को और बच्चो की अनती मर्या तीस ह। इसमे रहन वाली छ महिलाआ म स तीन का कुछ ही दिन। मे बच्चा पैदा होन वाला था रात मे पूरा कमरा छ चूल्हो के धुए से भर उठता था और इसके साथ ही तमाम गदगिया भी कमर मे मौजूद दिखाई देती थी जो निश्चित रूप स प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद किसी भी मा और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए घातक थी। इस तरह के तमाम कमरे मैं देखे। एक मकान के तहखाने के कमरो की हानत और भी वन्तर थी। यहा दिन की रोशनी मुश्किल से ही पहुच पाती थी मूज की रोशनी ता इन कमरा म कभी पहुची ही नहीं। (बाव लेबर गजट, दिमबर 1922, पृष्ठ 31)

21 अप्रैल 1946 का मैं ज्वर के निपिद्ध इलाके परेल के केंद्र म स्थित सूती मिल मजदूरो की चाल को देखने गया। यहा 12 फीट लवी और 10 फीट चौडी एक दूसरे से सटी झोपडियो की तमाम कतारें थी। इनम कोई खिडकी नहीं थी। जब मैं इस तरह की चाल के जदर गए तो हमन देखा कि चारा तरफ जधेरा फैला हुआ है और एक डिवरी की कापती ली स अवेरा कुछ कम हो रहा था जबकि कमरे म जल रह स्नोव के कारण काफी गरमी महसूस हा रही थी। जिस पहली झोपडी म हमने प्रवेश किया उसम 10 लोग रह रह थे। इसका किराया सात रुपये प्रतिमाह था। एक दूसरी झोपडी मे मैं 13 छोटे छोटे स्टीव और बनर देखे जिनसे पता चला कि यहा 13 परिवार रहत ह। मेरा गाइड भी उसी इलाक का था और उसने बताया कि यहा कम से कम 20 लोग या इससे अधिक लोग रहत ह। लकिन उस कमर म रहन वाले लागो ने इस डर से मुझे सही सही मर्या नहीं बताई कि

कही किराया बढ़ा न दिया जाए। इन मकानों की पहली तीन कतारों में 30 कमर थे जिनमें तकरीबन 300 लोग रहते थे लेकिन उनके लिए केवल तीन नल लगे हुए थे और इन नला में सुबह और शाम के वक्त रक रककर पानी आता था। एक नाली के ऊपर सूराख बनाकर तीन शौचालय तैयार किए गए थे। इनमें से एक पूरी तरह भर गया था और इस्तमाल करने लायक नहीं था। अगली कतार में 160 मकान थे और इनके इस्तमाल के लिए केवल छ नल थे। पानी की कमी के कारण सुबह एकदम तड़के और शाम को दो दो घंटे तक नल चलता था जबकि बंबई के समृद्ध इलाकों में इन मकानों में पानी दिन भर उपलब्ध था।

इस अधभुखमरी, वेहद भीडभाड और सफाई की व्यवस्था न होने का लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। इन स्थितियों की वजह उस समय की मृत्यु दर में देखी जा सकती है। 1937 में मृत्यु दर 22.4 व्यक्ति प्रति हजार पाई गई जबकि इसी अवधि में इंग्लैंड और वेल्स में यह दर 12.4 व्यक्ति प्रति हजार थी। इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाला व्यक्ति औसतन जितनी आयु की आशा करता है भारत में रहने वाला व्यक्ति उसके केवल आधे समय तक जीवित रहता है।

भारत में औसत आयु अधिकांश पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। 1921 की जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए यह औसत क्रमशः 24.8 और 24.7 वर्ष था। इसका अर्थ यह हुआ यह इंग्लैंड और वेल्स की औसत आयु 55.6 की तुलना में भारत में 24.75 थी। 1931 में इसमें और कमी आई और यह पुरुषों तथा महिलाओं के लिए क्रमशः 23.2 और 22.8 हो गई। ('इंस्टिट्यूट लेबर इन इंडिया', इंटरनेशनल लेबर आफिस 1938 पृष्ठ 8 1931 में की गई भारत की जनगणना पर आधारित, पृष्ठ 98)<sup>15</sup>

इन स्थितियों की वजह इस बात से मिल जाती है कि भारत में पैदा होने वाले प्रति एक हजार बच्चा पर, प्रसव के दौरान मरने वाली माताओं की संख्या 24.5 है जबकि उसके मुकाबले में इंग्लैंड और वेल्स में माताओं की मृत्यु का अनुपात 4.1 प्रति हजार है। इनकी वजह इस विषमतापूर्ण वास्तविकता से भी मिल जाती है कि अहमदाबाद शहर में, जहां लोग ऊपर वर्णित स्थितियों में रहते हैं मृत्यु दर 41.05 प्रति हजार थी जबकि अहमदाबाद छावनी में स्वास्थ्य और आराम की सभी सुविधाओं में लस यूरोपियनों की मृत्यु दर 12.84 प्रति हजार थी। इस स्थिति की वजह इस तथ्य से भी मिल जाती है कि भारत में एक साल के अंदर पैदा हुए प्रति हजार बच्चा में से 163 बच्चे शशवत्साल में ही मर जाते हैं जबकि इंग्लैंड और वेल्स में यह संख्या 46 थी। वल्लभता में यह संख्या 239 बंबई में 248 और मद्रास में 227 थी (एक कमर के मकान में रहने वाला में मृत्यु दर और भी ज्यादा देखी गई।) इस प्रकार 1926 में बंबई में एक कमर के मकान में प्रति

हजार पर मरने वाले नवजात बच्चों की संख्या 577 थी, दो कमरेवाले मकान में 254 थी और अस्पतालों में प्रति हजार पर यह संख्या 107 थी) ।

भारत में, मरकारों कागजों में मौत का कारण प्रायः 'बुखार' बताया जाता है (ब्रिटिश भारत में 1932 में प्रतिवर्ष 62 लाख मौतों में से 36 लाख मौतों का कारण बुखार ही बताया गया है) । अधभुखमरी की अवस्था में रहने और निधनता का जीवन बिताने के घुरे स्वास्थ्य के रूप में जो नतीजे होते हैं उनपर परदा डालने के लिए बुखार जैसे गालमोल शब्द का इस्तमाल किया जाता रहा है । भारत की आर्थिक परिस्थितियों के आधिकारिक विद्वान और साम्राज्यवाद के हमदर्द डॉ॰ एनस्ट न कहा है कि भारत में जितने लोग मरते हैं उनमें चार में तीन व्यक्ति गरीबी की बीमारियों से मरते हैं

1926 में कुल मृत्यु दर 26.7 व्यक्ति प्रति हजार में से 20.5 व्यक्तियों की मृत्यु हैजा, चेचक, प्लेग, 'बुखार', पचिश और दस्त में हुई । इनमें से लगभग सभी बीमारियाँ गरीबी की बीमारियाँ हैं जिनमें जल की कमी होती है और इन सभी बीमारियों को रोका जा सकता था । पर्याप्त चिकित्सा और चिकित्सा सवधी सलाह तथा मर्यादित उपचार के साथ साथ सफाई की बेहतर व्यवस्था (जिसमें शुद्ध जल की सप्लाई, भोजन की दूषित होने से रोकना, गंद पानी और मल मूत्र के निष्कासन की पर्याप्त व्यवस्था और रहने के लिए आवास की बेहतर मकान की सुविधा शामिल है) के जरिए निश्चित रूप से शहरी में मरने वालों की इतनी बड़ी संख्या को और तपेदिक तथा श्वास संबंधी रोगों से होने वाली मृत्यु को काफी बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है । भारत में बीमारी के कारण मृत्यु (और घुरे स्वास्थ्य) को बड़े पैमाने पर उन साधनों के द्वारा रोका जा सकता है जो अधिकांश पश्चिमी देशों में अपनाए जा चुके हैं और सफर साबित हुए हैं । (डॉ॰ एनस्ट 'दि इकॉनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया', पृष्ठ 69)

अक्टूबर, 1943 में भारत सरकार ने सर जोसेफ ब्लोम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति का गठन किया जिसने 1946 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बड़े सफर शब्दों में कहा

'जन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है । इसमें स्वस्थ जीवन के लिए सहायक परिवेश की सुविधा, पर्याप्त पोषिक आहार की सुविधा तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए<sup>16</sup> रोगों के निदान और चिकित्सा में संबंधित सुविधाएँ शामिल हैं । ये सुविधाएँ समुदाय के सभी सदस्यों को मिलनी चाहिए चाहे वे इसके बदले में कुछ देने के लिए तैयार हों । इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के काम



मे जनता का भी सश्रिय सहयोग प्राप्त होना चाहिए। बड़ी सख्या मे निदानयोग्य बीमारियो और मृत्यु दर का जिसका उल्लेख अभी किया गया है, मुख्य कारण यह है कि इन बुनियादी शर्तों के सिलमिले मे व्यवस्था अपर्याप्त है। देश के अधिकतर हिस्सो मे परिवेश सबधी सफाई का स्तर बहुत निम्न है, अपोषण और अल्पपोषण से आवादी के एक उल्लेखनीय हिस्से की जीवनशक्ति मे और प्रतिरोध क्षमता मे कमी आती है। इसके अलावा मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएँ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकदम अपर्याप्त है जबकि सामान्य शिक्षा और स्वास्थ्य सबधी शिक्षा का अभाव हाने से जनता की उस उदासीनता को दूर करने मे कठिनाई काफी बढ जाती है जिसकी वजह से लोग अपने आसपास की गदगी भरी स्थिति को वर्दाश्ट करत है बडे पैमाने पर मौजूद बीमारियो को थेलते रहते है। (रिपोट आफ दि हेल्थ सर्वे ऐंड डेवलपमेन्ट कमेटी, 1946 खंड 1 पृष्ठ 11)

विश्व मे निम्नतम स्तर की गरीबी और दुदशा का यह चित्र सभी गैरसरकारी प्रेक्षका ने प्रस्तुत किया ह। यहा एक अमरीकी के विचार पेश किए जा रह ह जिसन भारत के एक गाव मे कुछ दिन बिताए थे। उसने महसूस किया कि ग्रामीणो को चिकित्सा सबधी सहायता या दूसरी तरह की सहायता देने की सभी कोशिशें गरीबी की बुनियादी समस्या के सामने व्यथ हो गइ

आवादी के तीन करोड से चार करोड लोगो को दिन भर मे एक बकत से अधिक खाना नही मिलता है और वे निरतर भुखमरी की स्थिति मे जिंदगी गुजारत ह। जो मरीज मर पास आते थे उनके लिए अच्छी खुराक का निर्देश दना एक निराशाजनक स्थिति थी।

यदि उनसे यह कहा जाता था कि हैजे के मरीज के मैले कपडा का जला दो तो उनका जवाब हाता था कि अगर वह नही मरा ता बाद मे क्या पहनगा। गरीबी के कारण वे इस तरह की 'फिजूलखर्ची' का नही थेल सकत थे।

भारत के गावों की जनता का दवा की गोलियों की नही बल्कि भोजन और शिक्षा की जम्बरत ह। (जी० इमरसन वायसलेस इंडिया '1931)

दि टाइम्स' समाचारपत्र के कलकत्ता स्थित दफ्तियानूस साम्राज्यवादी सवाददाता का भी कुछ इसी तरह की बात कहनी पडी। उम यह कहना पडा कि नज्दीक से देखन पर भारत जयभुखमरी की एगो तम्बीर प्रस्तुत करता ह जा जवरन निगाहा मे कौध जानी है।

भारत के विभिन्न भागों से गुजरते समय कोई भी व्यक्ति अपोषण और अध्रमुखमरी के ददनाक दृश्या को देखने से अपने को नहीं बचा सकता । ये दृश्य आखों में चुभने लगते हैं । किसी भी व्यक्ति को इस बात में भी कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत के तमाम लोग यह बिलकुल नहीं जानते कि उनके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे वे भरपट खा सकें ।

जिस प्रांत से मैं सबसे ज्यादा परिचित हूँ उसका उदाहरण देना चाहूंगा । बंगाल के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि भारतवासियों का पोषण आज उतने अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है जितने अच्छे ढंग से एक पीढ़ी पूर्व हाता था । (दि टाइम्स के कलकत्ता सवाददाता, 1 फरवरी 1927)

साम्राज्यवादी शासन के 180 वर्षों बाद भारत की जनता की यह स्थिति है ।

यह ध्यान देने की बात है कि गरीबी की यह स्थिति स्थिर नहीं है । यह एक गतिशील स्थिति है और इसका विकास होता जाता है । 'दि टाइम्स' के सवाददाता की इस टिप्पणी से कि आधुनिक भारत की स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं अनेक समर्थ प्रेक्षक सहमत हैं । बंगाल के स्वास्थ्य सचालक ने 1927-28 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 'काफी बड़ी संख्या में बंगाल के मौजूदा किसान ऐसा भोजन खाने लगे हैं जिसे खाकर चूहे भी पाच सप्ताह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते ।' और यह कि 'अपर्याप्त भोजन के कारण उनके शरीर में जीवनशक्ति इतनी कम हो गई है कि वे गंभीर रोगों के संपर्क में आते ही उनके शिकार हो जाते हैं । इसी प्रकार 1933 में भारतीय चिकित्सा सेवा (इंडियन मेडिकल सर्विस) के निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जैसा पहले ही देखा गया है 'समूचे भारत में बीमारियाँ लगातार बल्कि बहुत तेजी से प्रगट रही हैं ।' स्थिति के इस तरह बिगड़ते जाने का संबंध साम्राज्यवादी शासन की परिस्थितियों में कृषि का मकट तेजी से बढ़ने जाने से है जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक जबरदस्त प्रेरक शक्ति है ।

## अत्यधिक आबादी होने की भ्रांतियाँ

भारतीय जनता की इस भयंकर गरीबी का क्या कारण है ?

इसके वास्तविक कारणों की खोज शुरू करने से पूर्व हमें उन वर्तमान सतही दलीलों को अपने रास्ते से हटा देना होगा जिसके कारण प्रायः समस्या का गंभीरता के साथ विश्लेषण नहीं हो पाता ।

इसकी एक आम मिसाल यह दलील है कि भारतीय जनता की गरीबी का कारण सामाजिक पिछड़ापन, आम जनता की अज्ञानता और उसका अधविश्वास (सामाजिक में ९८

वादिता, जातपात के बंधन, गो पूजा, स्वास्थ्य विज्ञान की उपेक्षा, महिलाओं की स्थिति इत्यादि) है। इसमें कोई सदेह नहीं कि भारत की गरीबी में इन बातों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस तरह की प्रतिगामी चीजों पर विजय पाना भारतीय जनता के सामान पुनर्निर्माण के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब इन कारणों को भारत की गरीबी का मूल कारण घोषित किया जाता है तब वस्तुतः गाड़ी को धोड़े के आगे रख दिया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन जनता की निम्न आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक दासता का परिणाम और उसकी अभिव्यक्ति है न कि जनता की निम्न आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक दासता उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का परिणाम तथा अभिव्यक्ति है। निरक्षरता के लिए उस सरकार की भूमना की जा सकती है जो जनता को अज्ञान में रखती है और उन्हें शिक्षा देने से इकार करती है लेकिन हम उस जनता की भूमना नहीं करेंगे जिसे सीखने का अवसर दिया ही नहीं गया। मूल समस्या आर्थिक-राजनीतिक है और सांस्कृतिक समस्या इस मूल समस्या पर टिकी है। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को ऐसे समय जबकि भयंकर गरीबी बनी हुई, अपनी उन्नति करने का उपदेश देकर और स्वास्थ्य पर भाषण पिलाकर नहीं दूर किया जा सकता। इस पिछड़ेपन का सगठन के भौतिक आधार में परिवर्तन के जरिए ही दूर किया जा सकता है और यही अथवा सभी रास्तों की कुंजी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरत है वगैरह सबंध में परिवर्तन की, जिसका अर्थ है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। साम्राज्यवादी और सामंती सबंधों के जुए को उतार फेंक एक शक्तिशाली जन आंदोलन ही भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक साथ मांग प्रशस्त कर सकता है।

इस विश्लेषण की सत्यता का पता सावियत मंच के उदाहरण से चल जाता है। जारशाही व अतगंत जनता की गरीबी और निम्न जीवन स्तर की व्याख्या करते समय आमतौर पर विद्वान लोग इसे रूसी कृषक समुदाय के तथाकथित सहज पिछड़ेपन का अनिवार्य परिणाम बताते हैं। लेकिन जय बहा के मजदूरों और किसानों ने एक बार मिलकर अपने शोषकों का उखाड़ फेंका तो उन्होंने अपने आपका तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में इतना समय दिखाया कि दुनिया का सर्वाधिक विकसित देश भी पीछे छूट गए। भारत में भी ऐसी ही स्थिति आएगी भल ही इस प्रक्रिया का किन्हीं दूसरे रूपों और मजिला से गुजरना पड़े। भारतीय किसानों का वास्तविक पिछड़ापन महज तकनीक और मजदूरी के क्षेत्र में ऊपर से दिखाई देने वाला निम्न स्तर तक (जो दासता और अवरुद्ध विकास के प्रत्यक्ष चिह्न हैं) ही नहीं है बल्कि सबसे बड़का यह साम्राज्यवादी और जमींदारों के सामने जातमसमपण करने तक है। इन साम्राज्यवादियों और जमींदारों का प्रभुत्व विकास का रास्ता है। लेकिन यह एक ऐसा पिछड़ापन है जो निवर्त भविष्य में समाप्त होने जा रहा है और यही हम जान वाले दिनांक प्रति आशा पैदा होती है।

भारत की गरीबी का कारण में प्रायः दोहराए जाने वाले एक कारण का प्रचार वम रहा है यह कारण है अत्यधिक आबादी के तथाकथित परिणाम। यह दृष्टिकोण इतना ज्यादा

प्रचलित है और बार बार इसे दोहराने में यह पश्चिमी देशों के 10 पाठकों में से, जिन्हें वास्तविकताओं से परिचित होना आवश्यक नहीं मिला, 1 के दिसाग में इतनी तेजी से बँट जाता है कि हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम इसपर और भी विस्तार से विचार करें और यह दिखाएँ कि ज्ञात तथ्यों के आधार पर कैसे इसका पूरी तरह खंडन हो जाता है।

फूर लोगो की मदद के लिए जितने धूँट गये हैं उनमें सबसे बड़ा झूठ यह है कि आबादी के अत्यधिक बढ़ जाने से पूँजीवाद के अंतर्गत जनता की गरीबी बढ़ जाती है। आधुनिक युग में यह धूँट माल्थस नामक उस प्रतिस्पर्धावादी पादरी के समय से प्रचारित हुआ है जिन्होंने वस्तुतः कोई नई बात तो नहीं कही लेकिन जिसने 1798 में फ्रांस की क्रांति और उदारतावादी सिद्धांतों के खिलाफ प्रचार करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में (जैसा उसकी पुस्तक के टाइटिल में घोषित है) अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और जिसको इसके पुरस्कारस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के कालेज में प्रोफेसर-शिप मिली। उसके सिद्धांत का इंग्लैंड के कुलीनतंत्र ने आनंदविभोर होकर स्वागत किया और मानवजाति के विकास के विषय में सभी उत्कंठाओं को समाप्त कर देने वाली एक महान शक्ति कहा। (मार्क्स 'पूँजी', खंड I, 25वाँ अध्याय) माल्थस का सिद्धांत आज भी प्रतिस्पर्धावादियों का बहुत प्रिय दशन है हालाँकि सभी मतों के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने इसका मजाक उड़ाया है। यह सिद्धांत उत्पादन के विकास की संभावनाओं पर मनमाने तौर पर कुछ जबरदस्त सीमाएँ लगा देता है और यह भी ऐसे समय जब उत्पादन का विकास सर्वाधिक तीव्र विस्तार के युग में प्रवेश कर रहा हो। 19वीं सदी के अनुभव ने माल्थस के सिद्धांत की उस समय ध्वजिया उड़ा दी जब आबादी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ संपत्ति का विस्तार हुआ और यह बात बहुत साफ़तौर पर उदघाटित हो गई कि गरीबी की वजह जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि कुछ और है। 20वीं सदी में खासतौर से प्रथम महायुद्ध के बाद और विश्वव्यापी आर्थिक संकट के आने पर इस सिद्धांत का फिर से जीवित करने की कोशिश की गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आकड़ों की मौजूदगी ने उसे फिर समाप्त कर दिया। लोगों ने इस तथ्य को देखा कि युद्ध के दौरान हुए मरण और व्यापक विनाश के बावजूद दुनिया में विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और औद्योगिक सामानों के उत्पादन में लगातार इतनी वृद्धि हुई कि वह विश्व की जनसंख्या से आगे निकल गई। इस तथ्य ने लोगों का यह सोचने पर विवश किया कि उनके दुखों का कारण समाज व्यवस्था में ही नहीं निहित है। शासक वर्ग के सामने यह समस्या पैदा होने लगी कि संपत्ति की वृद्धि को कैसे रोका जाए और इसके लिए उसने कई उम्दा तरीके निकाले। साथ ही आबादी के मदभ में उसे यह शिकायत होने लगी कि यूरोप और अमरीका के लोग युद्धबलि की पूर्ति के लिए काफी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। आधुनिक शासक वर्ग ने माल्थस के सिद्धांत का उलट दिया और यह नारा अपनाया कि संपत्ति कम और बच्चे ज्यादा पैदा करो।

पुराने ढंग के प्रतिक्रियावाद का यह बदनाम सिद्धांत यूरोप और अमरीका से खदेड़े जाने के बाद अब एशिया में अपना अंतिम आश्रय स्थल ढूँढ रहा है। भारत और चीन की गरीबी के बारे में एकमात्र कारण यह बताया जाता है कि यह गरीबी वहाँ की समाज व्यवस्था की नहीं बल्कि 'जरूरत से ज्यादा आबादी' की वजह से है। यह कहा जाता है कि साम्राज्यवादी शासन के जनहितकारी प्रभावों ने भारतीय महाद्वीप से युद्ध को समाप्त कर दिया है और महामारी तथा अकाल की सीमा में तथाकथित कमी करने उसने दुर्भाग्यवश आबादी की वृद्धि को रोकने के 'प्राकृतिक उपायों' को खत्म कर दिया और इस प्रकार भारत की अदूरदर्शी और बहुप्रज जनता को पेट भरने तक की रोटी भी दुर्लभ हो गई है। (1770 से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भयंकर ज्वाल पड़े। 1918 में इंग्लैंड से एक करोड़ चालीस लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बंगाल के हाल के अकाल के दौरान 35 लाख व्यक्ति मारे गए और आज आबादी का बहुमत 'चूड़े के खाने लायक आहार' की स्थितियों पर निर्भर है) इसलिए भूमि पर बढ़ता हुआ दबाव और अधभुखमरी की स्थितियाँ ब्रिटिश शासन की परोपकारिता के अनियाय स्वाभाविक परिणाम हैं। इन स्थितियों में तबदीली तभी लाई जा सकती है जब भारत की जनता जासूसी वृद्धि की दर को यूरोप की बुद्धिमान जनता की वृद्धि दर के अनुपात से भी कम करे।

जैसे जैसे भारत की समस्या अधिक भीषण होती जा रही है साम्राज्यवादी क्षेत्रों में इस तरह के तर्क देने का फलन अक्सर अधिक बढ़ता जा रहा है। साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ न बड़े नाटकीय ढंग से चीख कर कहा कि 'वह भारतीय माल्यस कहा है जो भारत के वृक्षों की विनाशकारी बाढ़ को रोक सके?' (एस्ट 'इकनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' पृष्ठ 475)। साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र के ही एक दूसरे प्रवक्ता ने घोषित किया कि 'ऐसा लगता है कि भारत माल्यस के इस सिद्धांत का कार्यान्वित कर रहा है कि जन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए युद्ध, महामारी अथवा अकाल नहीं होते तब वह इस सीमा तक बढ़ जाती है कि लोगो को जिंदा रहने लायक भी खाना नहीं मिलता।' (एन०सी० नावेल्स 'दि इकनामिक डेवलपमेंट आफ दि ब्रिटिश ओवरसीज इंपायर, पृष्ठ 351) यह दृष्टिकोण उन वामपंथी, प्रगतिशील' क्षेत्रों में भी फैला जो साम्राज्यवादी चान की गिरफ्त में आ चुके हैं। 1933 में जम निरोध अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सत्वावधान में लंदन में हुए आर्गनाइज्ड एंड ट्रापिकन मेटीसिंग में एशिया में जम निरोध विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि कचन विविधता विज्ञान के एक समन्वय के रूप में ही नहीं बल्कि एशिया की गरीबी की समस्याओं के समाधान के एक जायिक उपाय के रूप में जम निरोध का समर्थन किया जाए। ('कचन कंट्रोल आफ एशिया' की रिपोर्ट देखें, इसे बय बट्टोल इंटरनैशनल इनफार्मेशन सेंटर ने 1935 में प्रकाशित किया था।) इसका प्रसार सरकारी रिपोर्टों में भी हुआ

अनाज का बड़ा हुआ उत्पाद लोगो के जीवनस्तर मे कोई सुधार या उपलब्ध खाद्य पदार्थों की मात्रा मे वृद्धि नहीं कर सका। क्योंकि इन अनुपूण स्थितियों मे आबादी तेजी से बढ़ जाती है। पहले युद्ध, अकाल और महामारी ये तीना जनसंख्या म कमी करने के लिए सक्रिय थी। युद्ध और अकाल का सक्रिय प्रभावकारी के रूप मे प्रायः नकार दिया गया है जबकि महामारी से होने वाली मौत म उल्लेखनीय कमी आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दश पर दबाव बढ़ता चला गया। हमारे अलावा और लोगो की भी यह राय है कि जनसंख्या का मसला मामा य जीवनस्तर का निम्न बनान म एक भूमिका अदा करता है' (ब्रिटिश कमिशन रिपोर्ट आन लेबर इन इंडिया 1931, पृष्ठ 249)

सरकारी राज आयोग की अध्यक्षता करते हुए और हाउस आफ काम्स के भूतपूर्व स्पीकर के मुख से बोलते हुए संपूर्ण प्रभामंडल से परिपूर्ण माल्यस को देखिए। तथ्य क्या है ?

पहली बात तो यह है कि ऊपर दी गई तमाम दलीलों से कुछ ऐसी धारणा बनती है गोया ब्रिटिश शासनकाल म भारत की जनसंख्या दूसरे दशो की तुलना म बेहद तेजी से बढ़ती गई है और इसीलिए ऐसी हालत आ गई है कि यह देश हृद से ज्यादा गरीब हो गया है। लेकिन कितने लोग यह जानते है कि ब्रिटिश शासनकाल के अंतगत भारत के इतिहास की वास्तविक सचाइया देखने से दिलकुल उलटी तस्वीर सामने आती है।

ब्रिटिश शासनकाल के अंतगत जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर यूरोप के किसी भी देश की तुलना म उल्लेखनीय रूप से कम रही है और विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के सामान्य पैमाने पर देखें तो यह सबसे निम्न स्तर पर रही है। यह बात समान रूप से अंगरेजो के संपूर्ण शासनकाल या पिछले पचास वर्षों की अवधि पर लागू होती है।

समृद्धी अवधि के लिए केवल अटकला का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि भारत म 1872 तक कोई जनगणना नहीं हुई थी। मोरलड न अनुमान लगाया था कि 16वीं सदी के अंत म भारत की आबादी 10 करोड थी ('इंडिया ऐट दि डेय आफ अक्बर' पृष्ठ 22) आज यह संख्या 35 करोड है। इससे पता चलता है कि 300 से अधिक वर्षों मे जनसंख्या म साठे तीन गुना की वृद्धि हुई है। सावधानीपूर्वक किए गए पहले अनुमान (सेंसस रिटर्न्स आफ 1931 की भूमिका मे सरकार के बीमा विशेषज्ञ फिनलाइजेन) के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स की जनसंख्या 1700 मे 51 लाख थी। आज यह संख्या 4 करोड 4 लाख हो गई है। इसका अर्थ लगभग दो सौ तैंतीस वर्षों की अल्प अवधि मे आठ गुना वृद्धि हुई है। इंग्लैंड मे जनसंख्या वृद्धि भारत की तुलना मे दुगने से भी ज्यादा दर से हुई।<sup>17</sup>

शताब्दी का उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, जब औद्योगिक क्रांति के साथ जोड़े जाने वाले, यूरोप के विशेष विस्तार में कमी आनी प्रारम्भ हुई थी। हम सबसे पहले 1914 के पूर्व के भारत और यूरोप की तुलना करें ताकि हमारे विवरण में वे जटिलताएँ न आए जो यूरोपीय देशों में सीमागत परिवर्तन के कारण पैदा हुई हैं। भारत में और प्रमुख यूरोपीय देशों में 1870 और 1910 के बीच जनसंख्या में वृद्धि की दर के निम्नांकित आंकड़े देखने से बात साफ होती है।

#### जनसंख्या में वृद्धि, 1870-1910

| देश               | प्रतिशत वृद्धि |
|-------------------|----------------|
| भारत              | 18.9           |
| इंग्लैंड और वेल्स | 58.0           |
| जर्मनी            | 59.0           |
| बेल्जियम          | 47.8           |
| हालैंड            | 62.0           |
| रूस               | 73.9           |
| यूरोप (औसत)       | 45.4           |

(वी० नारायण 'पापुलेशन आफ इंडिया,' 1925, पृ० 11)

मास को छोड़कर जब सभी यूरोपीय देशों की में भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम रही है।

1872 में 1931 तक की अवधि की जाँच करने से हमें तथ्यों का पता चलता है इस अवधि के दौरान भारत में यह दर 30 प्रतिशत थी जबकि इंग्लैंड और वेल्स में यह 77 प्रतिशत पाई गई। पिछले 60 वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स में जनसंख्या वृद्धि की दर भारत की तुलना में दुगुनी से भी ज्यादा रही।<sup>18</sup>

मार्च 1921 से 1940 की अवधि में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में अधिक रही (यह दर 21 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में अमेरिका में यह दर 24 प्रतिशत थी)। लेकिन भारत में गरीबी की समस्या की शुरुआत 1921 के बाद से ही नहीं हुई है।<sup>19</sup>

1931 में केंद्रीय बजट जांच समिति ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें काफी व्यापक दायरे में भारत की आर्थिक स्थितियों का आधिकारिक और अत्यंत विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। दस समिति ने विशेष हाकर भारतीयों की परंपरागत व्याख्या 'अल्पवर्ध' आयातों की भूमिका का वर्णन कर दिया

जमीन से होने वाला प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति एकड़ उत्पादन अथवा तमाम देशों की तुलना में कम है। औसत किसान आज भी अनाज और आहार की अपर्याप्त मात्रा पर निर्भर है जो उसके काम करने की शारीरिक क्षमता पर असर डालती है—साथ ही देश की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। इन स्थितियों की जिम्मेदारी हम पूरी तरह जनसंख्या में अनुचित वृद्धि तथा उसके कारण जमीन पर पड़ने वाले भार पर नहीं डाल सकते। हमें भारत में जनसंख्या के विकास की तुलना इंग्लैंड की जनसंख्या के विकास के साथ करनी चाहिए। हमारे पास दोनों देशों के 30 वर्षों के आंकड़े मौजूद हैं जिन्हें देखने से पता चलता है कि इंग्लैंड और वेल्स की आबादी में 1891 और 1901 के बीच 12.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 1901 और 1911 के बीच 10.91 प्रतिशत और 1911 तथा 1921 के बीच 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में इन्हीं वर्षों में ब्रिटिश भारत की आबादी में क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।<sup>1</sup> (रिपोर्ट आफ दि सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमिटी, 1921, पृष्ठ 40-41)

अब आबादी के घनत्व पर विचार करें। 1941 में पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व 246 व्यक्ति प्रति वर्ग मील था जबकि इंग्लैंड और वेल्स में यह घनत्व 703, बेल्जियम में 702, हॉलैंड में 639 और जर्मनी में 348 व्यक्ति वर्गमील था। विभिन्न जिलों में जनसंख्या के असमान घनत्व को ध्यान में रखते हुए इन आंकड़ों का महत्व सीमित है। लेकिन फिर भी यदि हम सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले प्रांत बंगाल का लें तो हम पाएंगे कि वहां यह संख्या 779 व्यक्ति प्रति वर्गमील है जो इंग्लैंड या वेल्स या बेल्जियम के स्तर से थोड़ा ही ऊंचा है। यह सही है कि बंगाल के कुछ खाम जिलों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है जैसे ढाका में यह 1,542 व्यक्ति प्रति वर्गमील, टिपरा में 1,525 या फरीदपुर में 1,024 व्यक्ति प्रति वर्गमील आबादी का घनत्व है। लेकिन अत्यधिक घनी आबादीवाले इन जिलों से सबूत विशेष सवाल पर, और इस प्रश्न पर कि उपलब्ध तथ्य यह मानने कि कोई गारंटी देते हैं कि अत्यधिक घनी आबादीवाले बंगाल में भी जनसंख्या ने जीवन के साधनों को पीछे छोड़ दिया है (शेष भारत का उल्लेख किए बिना), 1931 के 'बंगाल सेंसर रिपोर्ट' के फ़ैमले का उल्लेख किया जा सकता है।

क्या जनसंख्या वृद्धि ने खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है? कृषि के विकास में निरदनीय उपेक्षा के बावजूद और खेती योग्य जमीन के केवल आंशिक हिस्से के इस्तेमाल के बावजूद आधुनिक काल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि आबादी की वृद्धि खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि से आगे निकल गई हो। देश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा अब भी बहुत अपर्याप्त है और इसपर भी इस अपर्याप्त मात्रा का हिस्सा निर्मात कर दिया जाता है लेकिन इस अपर्याप्तता का कारण यह नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि ने खाद्यानों की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है बल्कि



इसका कारण यह है कि भारत में अब भी उत्पादन की पिछड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ जमीन की मिलकियत की पुरानी प्रणाली अब भी कायम है और अनक तरह के भारी बोझों ने कृषि की कमर तोड़ रखी है।

1891 और 1921 के बीच जनसंख्या में 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में अनाज का उत्पादन करने योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में दुगुनी रफ्तार से वृद्धि हुई।

1921 से 1931 के दौरान हमारे पास प्रोफेसर पी० जे० थामस के आंकड़े उपलब्ध हैं जो उन्होंने 1935 में जारी 'पापुलेशन ऐंड प्रोडक्शन' में शामिल किए थे। वर्ष 1920-21 और 1921-22 के औसत को 100 मानकर उन्होंने 1930-31 और 1931-32 के औसत के लिए सूचक अथवा जनसंख्या के लिए अनुमानित 110.4, कृषि उत्पादन के लिए 116 और औद्योगिक उत्पादन के लिए 151 निर्धारित किया। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस दशक में जनसंख्या की वृद्धि का सबसे उच्च आंकड़ा रिकार्ड किया गया उस दशक के दौरान आबादी में जहाँ 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं कृषि उत्पादन में 16 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

माल्थस के पक्के चेलों और दुर्भाग्य के पैगवर प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी को भी अपनी हाल की पुस्तक 'फूड प्लेनिंग फार फोर हड्रेड मिलियन्स' (1938) में यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा कि कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है' (पृष्ठ 18) और अपने इस कथन की पुष्टि के लिए उन्हें आंकड़े प्रस्तुत करने पड़े हैं।

### भारत में आबादी और उत्पादन की प्रवृत्ति (1910-1933)

| (1910-11 से 1914-15 के औसत के आधार पर सूचक अथवा) |            |           |             |              |                  |     |
|--|------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-----|
| आबादी  |            | सभी फसलों | खाद्य फसलों | अखाद्य फसलों | औद्योगिक उत्पादन |     |
| 1910-11 में औसत                                  | 1914-15 का | 100       | 100         | 100          | 100              | 100 |
| 1932-33  |            | 117       | 127         | 134          | 121              | 156 |

(राधाकमल मुखर्जी 'फूड प्लेनिंग फार फोर हड्रेड मिलियन्स', 1938, पृष्ठ 17 और 27)

खाद्य और औद्योगिक उत्पादन की तुलना में दुगुनी रफ्तार से बढ़ा है और औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में निगुनी रफ्तार से वृद्धि हुई है। 1900 से 1930 तक के पूरे तीन दशकों का मालाश प्रमाण करने हुए प्राफेसर थामस ने निष्कर्ष

1900 और 1930 के बीच भारत की आबादी में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन खाद्य पदार्थों और अच्छे माल के उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन में 189 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1921-30 के दशक में जनसंख्या में वेशव आकस्मिक वृद्धि हुई लेकिन उत्पादन की भी प्रगति बनी रही। व्यापार में मंदी की स्थिति के बावजूद बाद के वर्षों में भी यह प्रगति बनी रही, औद्योगिक उत्पादन का सूचक (1928 में 100) 1934-35 में 144 रहा और चालू वर्ष में इससे भी ज्यादा हो सकता है।

इन सारी बातों से पता चलता है कि जनसंख्या में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम रही। आकड़ों ने इस खतरे का समयन नहीं किया कि जनसंख्या वृद्धि उत्पादन वृद्धि को पीछे छोड़ देगी। जा लोग भारत में 'बच्चों की विनाशकारी बाढ़' से खतरा महसूस करते हैं वे यदि राष्ट्रीय आय के वितरण, उपभोग की विस्म और जनसंख्या के भौगोलिक वितरण एवं अर्थ संबंध मसला की स्थिति में सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो इससे देश का काफी भला होगा। (प्रोफेसर पी० जे० थामस का 'दि टाइम्स', 24 अक्टूबर 1935 में लेख)

इस प्रकार तथ्यों को देखने से पता चलता है कि इस बात को भारत की गरीबी का कारण नहीं कहा जा सकता कि यहाँ जीवन निर्वाह के साधनों के उत्पादन में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में बड़ी तज़ी से वृद्धि हुई है। आकड़ों का देखने से हमें जीवन निर्वाह के साधनों के उत्पादन में ही वृद्धि का पता चलता है, इसलिए गरीबी के कारणों की तलाश वही और की जानी चाहिए।<sup>20</sup>

कहने का मतलब यह नहीं कि स्वामित्व, पट्टा, तकनीक, परजीविता, और उपलब्ध श्रम शक्ति की बरबादी की वर्तमान स्थितियाँ के अंतर्गत जीवन निर्वाह साधनों का वर्तमान उत्पादन लागों की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। यह बेहद अपर्याप्त है। चाहे पुरुष हो या महिला, यदि कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए साधारण जीवन बिता रहा हो तो उस भोजन के रूप में प्रतिदिन 2400 कैलरी शक्ति मिलनी चाहिए। जो लगभग थोड़ा बहुत काम करते हैं उन्हें 2500 से 2600 कैलरी की ज़रूरत है और जो लोग ऐसे कामों में लगे हैं जिसमें अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है उन्हें 2800 से 3000 कैलरी जीवन शक्ति चाहिए। कुन्नूर के पोष्टिक आहार अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक डाक्टर एन्नायड ने 'दि न्यूट्रिटिव बैल्यू आफ इंडियन फूड्स एंड दि प्लानिंग आफ सैंटिसिफिकेटरी डाइट्स' नामक स्वास्थ्य बुलेटिन नंबर 23 (1941) में लिखा है कि भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अपर्याप्त और सतुलित आहार के जरिए दिन भर में केवल 1750 कैलरी शक्ति मिलती है।<sup>21</sup> (रिपोर्ट आफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, खंड 1, पृष्ठ 69-70) इसके अतिरिक्त बसा (चरबी), प्रादीन और सामान्य तौर पर जीवन रक्षक

खाद्य पदार्थों की खासतौर से गंभीर कमी है। दूध का कुल उत्पादन अनुमानतः 113 अरब पीड है जो मनुष्य के लिए आवश्यक मात्रा में आधे से भी ज्यादा कम है।

इन तथ्यों से वतमान सामाजिक और आर्थिक संगठन के दिवालियेपन का पता चलता है जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भारत के अपार प्राकृतिक साधनों के इस्तमाल और विकास में असफल रहा है। लेकिन इस बात के प्रमाण नहीं हैं कि भारत में ज़रूरत से ज्यादा लोग हैं। इसके विपरीत दुनिया भर के विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया है कि यदि भारत के साधनों का ठीक ढंग से इस्तमाल किया जाए तो समूचे देश की आज जितनी आबादी है, या निश्चित भविष्य में जितनी हो सकती है उसमें कहीं अधिक आबादी इन साधनों के सहारे बड़े आराम की जिंदगी बिता सकती है। भारत में कृषि योग्य जितनी जमीन है उसका लगभग एक तिहाई भाग अभी तक इस्तमाल में नहीं आया है। जिस भाग पर खेती होती भी है वहां खेती करने का तरीका इतना अधिक आदिम है कि उसमें प्रति एकड़ जितनी पैदावार होती है उससे तीन गुना अधिक पैदावार उतनी ही जमीन और कम थम शक्ति लगाकर ब्रिटेन में की जा सकती है (पैदावार के लिए गहू की उपज से तुलना की गई है)। भारत की गरीबी की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम भारतीय साधनों के पूरे पूर इस्तमाल के माग में आने वाली स्कावटों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

इस स्थल पर आकर साम्राज्यवादी अर्थशास्त्री और उसके प्रचारक वास्तविक समस्या से घटका जाते हैं। उनका कहना है कि 'वतमान परिस्थितियों में अर्थात् वतमान साम्राज्यवादी और सामंती दबावों, सूदखारा द्वारा की जान वाली वसूली, विकास के माग में बाधा पहुंचाने और ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक आवश्यकताओं के रूप में आर्थिक विघटन की स्थिति में मौजूदा उत्पादन अपर्याप्त है और इसीलिए भारत की आबादी ज़रूरत से ज्यादा है। इस प्रकार उन्हीं डाक्टर एस्टे ने, जिन्होंने 'बच्चों की विनाशकारी बाढ़' को रोकने के लिए 'भारतीय माल्यस' की चीख मचाई थी और जिनका हमने पहले उल्लेख भी किया है, बड़े शांत ढंग से निम्न शब्दों में अपनी दलील पेश की है

'यह दलील दी जाती है कि भारत की आबादी ज़रूरत से ज्यादा नहीं है बल्कि यदि उत्पादन वितरण और उपभोग के नात साधनों का उत्कृष्टतम ढंग से इस्तमाल किया जाए तो मौजूदा आबादी से भी बड़ी आबादी का काम चल सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा रहा है कि इस तरह की परिस्थितियों में इससे भी बड़ी आबादी का काम चल सकता है लेकिन इससे यह प्रश्न बचानी नहीं रह जाता कि कम में कम आबादी कितनी हो। मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत यह निश्चित है कि यदि आबादी कम होती तो प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता। (वी० एम्टे 'इकनॉमिक डेवलपमेंट आफ इंडिया,' 1936 पृष्ठ 40 रेखांकन मेरा है)

‘मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत’ शब्द का इस्तेमाल ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह ऊपर से दखने पर ऐसा लगता है जैसे तथ्या का एक व्यावहारिक और वस्तुगत दृष्टि से लिया गया हो लेकिन सच्चाई यह है कि इसके जरिए साम्राज्यवाद और जमींदार द्वारा किए जा रहे शोषण के समूचे ढांचे और उनके नतीजे की आवश्यकता को मान लिया गया है।

इसी प्रकार भारत में कृषि की जांच करने के लिए जो भारी भ्रष्टाचार राज आयोग नियुक्त किया गया था और जिमन रिपाट ऐंड एबीडेंस’ के माट मोट ग्रथ निवाले उसे जमीन के स्वामित्व, किसानों के अधिकारों तथा लगानों और मालगुजारी की व्यवस्था जैसे बुनियादी सवाल को जांच करने को मनाही कर दी गई थी। इस छोटी सी अवधारणा के आधार पर इस समस्या को बहुत जटिल मान लिया गया और भारत को अत्यधिक आबादी वाला देश घोषित कर दिया गया।

यदि उत्पादन का वर्तमान संगठन जो साम्राज्यवाद के अंतर्गत है जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया जाता है—जिस निश्चित रूप से संगठन में सुधार करके ठीक किया जा सकता है—ताजा निष्कर्ष निकलता है वह यह नहीं है कि संगठन में सुधार की आवश्यकता है बल्कि यह है कि आबादी को कम किया जाना चाहिए। उसके पैर काट दो क्योंकि उसकी लंबाई चारपाई से ज्यादा है।’

1933 में लंदन स्कूल आफ हाइजिन ऐंड ट्रापिकल मेडीसिन में ‘एशिया में जम निरोध’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में डा० कुविजस्की ने भारत संबंधी इस गलत धारणा का निमज्जा से खंडन किया था। डा० कुविजस्की को सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सांख्यिकीय अधशास्त्रियों के अग्रणी न कहा था कि वह आबादी की समस्याओं के जीवित विद्वानों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और अधिकारी व्यक्ति है।’ अपने भाषण में डा० कुविजस्की ने कहा

‘इन चीजों की तरफ हम अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमें यह बताया गया है कि भारत में इस समय बीस करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है और समूची आबादी को भोजन देने के लिए 353 करोड़ एकड़ जमीन पर खेती करने की जरूरत है। लेकिन हम इतनी ज्यादा जमीन की क्या जरूरत है और किन परिस्थितियों में इतनी सारी जमीन पर खेती आवश्यक है? यह तभी आवश्यक है जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल न कर और जब हम खेती में सुधार न करें। जिस किसी व्यक्ति को आधुनिक खेती का थोड़ा भी ज्ञान है वह इस बात में इकार नहीं कर सकता कि भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा शिक्षा दिए बिना भी बीस करोड़ एकड़ जमीन पर सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त मात्रा में

खाने की चीज पैदा की जा सकती है। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के उपायों के जरिए भारत में बढ़ी हुई मृत्यु दर को नीचे लाया जा सकता है उसी प्रकार कृषि में सुधार करके खाने-पीने की चीजों के अभाव को दूर किया जा सकता है।

इसी प्रकार हम सर जाज वाटस के फंडले को स्मरण कर सकते हैं जो उन्होंने 1894 में 'मेमोरैंडम ऑन दि रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया' में (पृष्ठ 24 पर उद्धृत) किया था। उन्होंने कहा था कि कृषि के क्षेत्र में 'भारत की उत्पादन क्षमता को आसानी के साथ कम से कम पचास प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है' और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था 'कि यदि अतृप्त मूल्यों और अव्यक्त साधनों की मात्रा पर ही ध्यान दें तो कह सकते हैं कि दुनिया में कम ही ऐसे देश हैं जिनमें कृषि की इतनी जबरदस्त संभावना है जितनी भारत में है।'

यहां तक कि साम्राज्यवाद समूह कुछ ब्रिटिश विशेषज्ञों ने हाल ही में जो योजना तैयार की है उसमें माल्थस के जनसंख्या संबंधी समूचे सिद्धांत को ध्वजिया उड़ा दी है। जसा प्रोफेसर ए० बी० हिल ने अपनी प्रस्तावना में कहा है इस योजना का उद्देश्य ऐसी सभा वित्त व्यवस्था का संगठन करना है जिसके द्वारा साधारण, व्यावहारिक तथा ठोस परिणामों के देने योग्य अनुभव पर आधारित उपाय निकाले जा सकें और उन्हें इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके कि भारत में कुल अनाज उत्पादन अगले सात वर्षों में सवा गुना से लेकर डेढ़ गुना तक बढ़ाया जा सके।' (ए फूड प्लान फॉर इंडिया, 1945)

इस सिलसिले में 1931 में हुई बंगाल की जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्ष भी काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसकी परिचयात्मक टिप्पणी में खाद्यान्न की सप्लाई और जासब्या की समस्या पर विचार किया गया है

'पहले से ही दुनिया की सबसे घनी आबादीवाले इस प्रांत बंगाल में इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या वृद्धि की संभावना से यह धारणा बनती है कि बंगाल की आबादी तर्जों के साथ उस सीमा तक पहुंच जाएगी जब जीवन निर्वाह के साधन किसी भी कीमत पर जनता की मांग पूरी नहीं कर सकेंगे। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन निर्वाह के निम्नतम स्तर पर गुजर कर रहा है। इस प्रांत की क्षमताओं का यदि विकास नहीं किया गया तो जनसंख्या में किसी प्रकार की वृद्धि से निराशा और घुटन की स्थितियां बढ़ेंगी। बहने का मतलब यह है कि ये क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं कि आबादी की भावी स्थिति के बारे में निराशा का रख अपना उचित नहीं है। भारत के शेष भाग की तरह बंगाल भी अपने अल्पव्यक्त साधनों और इन साधनों के इस्तमाल की अक्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इस बात

की मभावना नहीं है कि यहाँ की धरती अब पहले से ज्यादा खराब होगी और बगाल जैसे इलाकों के बारे में जहाँ छोटी से छोटी फसल के लिए भी खाद की जरूरत है आम राय यह है कि उपज का न्यूनतम स्तर बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और उसका इस दर से अनुकूलन हो चुका है जिससे पौधे मौसम से अपना आहार प्राप्त करते हैं। बगाल का किसान व्यवहार रूप में अपने खेत में कभी खाद नहीं डालता और यदि वह खाद का इस्तेमाल करे, साथ ही कृषि के विवसित औजार काम में लाए तो उसके खेत की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। अनुमान लगाया गया है कि (जी० क्लाक 17वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन की कायवाही) यदि विवसित साधनों का इस्तेमाल किया जाए तो समूचे भारतवर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग तीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि और सघन किस्म की खेती के अतगत आवश्यक किसी भी श्रम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है क्योंकि बगाल के खेतिहर कुल मिलाकर मभवत दुनिया के किसी भी हिस्से के खेतिहर से कम काम करते हैं। पूरक तालिका 1 में यह भी दिखाया गया है कि कृषि योग्य कुल भूमि में से इस समय वस्तुतः केवल 67 प्रतिशत भूमि में ही खेती होती है। यदि कुल कृषि योग्य भूमि पर खेती की जा सके और यदि खेती के उन्नत तरीके अपनाए जाएँ जिससे वर्तमान उपज में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि बगाल में मौजूदा जीवनस्तर पर 1931 की जनसंख्या की लगभग दुगुनी जावादी का काम चल सकता है।' (बगाल सेंसस रिपोर्ट, 1931 खंड 1, पृष्ठ 63)

भारत और यूरोप के देशों के बीच निर्णायक अंतर आवादी के बढ़ने की दर नहीं है। जनसंख्या वृद्धि की दर यूरोपीय देशों में ज्यादा रही है। भारत और यूरोपीय देशों की स्थितियों के बीच फरक यह है कि यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास और उत्पादन का जो विस्तार हुआ है और जिसमें आवादी की और तजी से बढ़ने में सहायता पहुँचाई है, आर्थिक विकास और उत्पादन का वह विस्तार भारत में नहीं हुआ। जैसा हम आगे देखेंगे उसे ब्रिटिश पूँजीवाद की काय प्रणाली और उसकी ज़रूरतों ने कृत्रिम ढंग से रोक दिया जिसके फलस्वरूप आवादी के एक बड़े हिस्से को आदिम ढंग की और अनेक तरह के बोझों से दबी खेती पर निर्भर रहना पड़ा। एक ओर तो देश की धन-दीनत का शोषण करके बाहर भेज दिया गया है और औद्योगिक तथा अन्य विकास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ अधिकांश जनता के जीवन निर्वाह के एकमात्र साधन खेती का भी अपाहिज बना दिया गया है और उसे उपेक्षा तथा पतन के लिए अभिशप्त बना दिया गया है।

भारत की अत्यंत गरीबी का रहस्य कोई ऐसा प्राकृतिक कारण नहीं है जो मनुष्य की पहुँच

या उसके नियंत्रण से पर की चीज हो, अत्यधिक जनसंख्या की काल्पनिक कहानी स भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि इसका कारण साम्राज्यवादी शासन से पैदा सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं। इसका प्रमाण बाद के अध्यायों में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रमाण से जो राजनीतिक निष्कर्ष निकलते हैं उनसे पता चलता है कि भारतीय जनता को जीवन निर्वाह के साधन देने के लिए यहाँ सामाजिक, राजनीतिक रूपांतरण जरूरी हैं और इस विश्लेषण से पता चलता है कि यह अवश्यभावी है।

## टिप्पणियाँ

- 1 डब्ल्यू० एच० मूरलुड ने अपनी पुस्तक इंडिया ऐट दि डेय आफ अक्बर (1920) और फ्राम अक्बर टु औरगजेव (1923) में उन तमाम नकारात्मक प्रमाणों को इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि वह यह दिखा सकें कि 17वीं सदी में भी भारत की जनता काफी गरीब थी। फिर भी जब वह इंडिया ऐट दि डेय आफ अक्बर के वेल्थ आफ इंडिया नामक अपने अध्याय में निष्कर्ष निकालते हैं तो वह इसी नतीजे पर पहुँचने को मजबूर होते हैं

यह असंभव है कि यदि संपूर्ण भारत के सद्यः में प्रति व्यक्ति कुल आय देखें तो इस अनुपात में कोई ज्यादाता-दीली मिले यह संभव है कि यह तथ्यहीन अपेक्षाकृत कम ही हो और 'यान् सभावना इस बात की है जिससे कि यह पटले की तुलना में अधिक हो लेकिन किसी भी स्थिति में यह अंतर इतना बड़ा नहीं होगा कि आर्थिक स्थिति में किसी निश्चित फर-बदल का संकेत मिले (पृष्ठ 286)

जहाँ तक बुनियादी सामानों के उत्पादन का संबंध है कृषि से औसत आय लगभग उतनी ही होती थी जितनी आज है जंगलों से भी यह आय लगभग उतनी ही थी मछली पालन से चाय<sup>१</sup> कुछ आय होती थी और खनिज पदार्थों से निश्चित रूप से आज की अपेक्षा कम आय होता था। जहाँ तक उद्योगों का संबंध है कृषि उद्योगों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं दिखाई देता जहाँ जहाँ निर्माण के अभाव में हस्तशिल्प के विविध सामानों उन सारे सामानों और घातायत उत्पादन से हुई औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन देश में की बनावट से हुई आय में गिरावट आई है। खनिज और परिवहन उत्पादन तथा हस्तशिल्प के विविध सामानों से हुआ लाभ इतना अधिक नहीं था जो इन घाटों को काफी हद तक प्रतिसंतुलित कर सकें। लेकिन ये फायदे ठोस होने के बावजूद उस समय बहुत छोटे हो जाते हैं जब हम उन्हें कृषि से हुई आय के समक्ष देखते हैं (पृष्ठ 287)

आम के तीन आय स्रोतों जहाँ जहाँ निर्माण विदेश वाणिज्य और वस्त्र निर्माण (सूती और पटमन) को विस्तृत जाँच करने से इस निष्कर्ष का औचित्य महसूस होता है कि इन उद्योगों ने देश की औसत आय का स्तर वर्तमान स्तर से ऊँचा उठाने में आज की तुलना में उस समय ज्यादा योगदान नही किया होगा' (पृष्ठ 293)

निश्चित रूप से भारत आज की तुलना में उस समय (अक्बर के शासनकाल में) ज्यादा समृद्ध नहीं था और संभवतः आज की तुलना में वह गरीब था (पृष्ठ 294)

जब दूसरे पक्ष के अत्यंत श्रम साध्य तक 300 वर्षों के बाद भी आर्थिक प्रगति में ठहराव का दावा कर सकते हैं (दृष्टा 300 वर्षों में यूरोपियन देशों में हुए परिवर्तनों को देखें) तो जाहिर है कि विश्व के पमानों पर जितना सापेक्षिक ह्रास हुआ होगा

- 2 पाठकों को यह जानकारी आवश्यक होगा कि इस कमीशन के नतीजों और रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अत्यंत गोपनीय ठहराया और उन्हें न तो प्रकाशित किया न उनपर अमल किया

- 3 डॉ० नोरोजी 'पावर्टी ऐंड इन ब्रिटिश इंड इन इंडिया 1876
- 4 डब्ल्यू० डिगबो 'प्रास्परिटी ब्रिटिश इंडिया', 1902
- 5 जी० फिडले सिराज 'दि साइम आफ पब्लिक फिनांस 1924
- 6 वाडिया और जोशी 'दि बल्क आफ इंडिया' 1925
- 7 शाह और धबाता 'वल्क ऐंड टक्सेबल कपेसिटी आफ इंडिया 1924
- 8 वी० व० आर० वी० राव 'इंडियाज नेशनल इन्कम 1939
- 9 जी० फिडले सिराज 'पावर्टी ऐंड किडन इकोनोमिक प्रालिम्स इन इंडिया 1932
- 10 भारत सरकार के वित्त सदस्य सर जम्स ग्रिग का अप्रैल 1938 में केंद्रीय विधानसभा में बजट भाषण
- 11 वी० के० आर० वी० राव 'दि नेशनल इन्कम आफ ब्रिटिश इंडिया 1940
- 12 'दि टाइम्स ट्रुथ ऐंड इजीनियरिंग इंडियन सप्लीमेंट के अप्रैल 1939 में 'दि इंडियन मार्केट के व्यापारिक अनुमान के मतगत भारत में आमदनी' के बटवारे और आमदनी की 'यूनता पर कुछ रोशनी डाली गई है। यह सरकारी आंकड़े ब्रिटिश पूँजीपतियों ने अपने इस्तेमाल के लिए तैयार किए थे और इसमें साम्राज्यवादी शोषण के परिणामों की कोई खूबसूरत तस्वीर प्रचार के उद्देश्य से पेश करने की कोशिश नहीं की गई है बल्कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए वास्तविक तथ्यों को रखा गया है ताकि उपमास्ताशा की श्रणियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। इसके परिणाम साइमन कमिशन के परिणामों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। भारतीय परिवारों की आय की अनुमानित श्रेणियाँ निम्न हैं

| आय स्तरों में   | ब्रिटिश मद्रा | परिवारों की संख्या |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 100 000 से अधिक | 7,500 पौंड    | 6 000              |
| औसत 5 000       | 375 पौंड      | 270 000            |
| औसत 1 000       | 75 पौंड       | 250 000            |
| औसत 200         | 15 पौंड       | 35 000 000         |
| औसत 50          | 3 पौंड 10 शि० | शेष बचे लोग        |

ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा अपने निजी इस्तेमाल के लिए तैयार की गईं तालिका खुद ही सारी कहानी कह देती है।

- 13 डा० राव के अनुसार शहरी आय प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है। गांवों में प्रति व्यक्ति आय 51 रुपये या 77 शिलिंग है जबकि शहरों में यह 166 रुपये या 249 शिलिंग है। गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क जनता के विभिन्न वर्गों की स्थितियों के बीच है।  
बेशक जैसाकि हम आगे चलकर देखेंगे गांवों में लगभग समूची फसल जमींदार और सूदखोर महाजन से लेते हैं।  
शहरी इलाकों में भी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा कुल जागहड़ी के दसवें हिस्से से भी कम के पास रहता है। यहाँ तक कि जो लोग अपेक्षाकृत संपन्न हैं और जिनकी आय प्रतिवर्ष दो हजार रुपये से अधिक है उनमें भी 18 प्रतिशत लोगों के पास कुल आय का केवल 17 प्रतिशत हिस्सा आता है जबकि 1 प्रतिशत से कुछ अधिक लोग कुल आय का 10 प्रतिशत हिस्सा पाते हैं।  
(वी० के० आर० वी० राव 'दि नेशनल इन्कम आफ ब्रिटिश इंडिया, 1931 32 पृष्ठ 189)
- 14 उपरोक्त आश्चर्यजनक परिणामों के बाद में जालोचना हुई और कहा गया कि इसमें उन अतिरिक्त पदार्थों का हिसाब नहीं लगाया गया है जिन्हें मजदूर इस्तेमाल करते हैं मसलन सस्ती मिठाईयाँ मसाले, मछली सजिया या पत्त ज़ादि। इसी कारणों से 1925 में सरकारी तौर पर फिर हिसाब लगाया गया। इससे पता चला कि उपरोक्त तालिका में छाछ पदार्थों की सूची में जो उल्लेख किया गया है उसका यह मात्र 406 प्रतिशत ही है। जहाँ तक बर्तन के वस्तु मजदूर द्वारा प्रतिदिन



उपभोग की जाने वाली कुल 2 450 कलोरी में 113 कलोरी की ओर बढ़ि हुई और इस प्रकार कुल योग 2 563 कलोरी हो गया (वापे सेक्टर गजट अप्रैल 1925 पृ० 841 42)। पोष्टिक साहज के बारे में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की उपसमिति ने 'यूनितेड राशि 3 390 कलोरी और प्रो० आर० मुखर्जी ने भारतीय परिस्थितियों में 2 800 कलोरी निर्धारित की थी। (फंड प्लानिंग फार फोर हइड मिलियंस, 1938)। इन अनुमानों को देखने से पता चलता है कि बर्बाद का एक वयस्क मजदूर वितनी कम कलोरी प्रतिदिन ग्रहण करता है।

- 15 भारत में जन्म मरण के आकड़े अत्यंत अशुद्ध हैं। 1931 की जनगणना रिपोर्ट में मलती की गुंजाइश 20 प्रतिशत रखी है। प्रत्याशित आयु के बारे में सरकारी विवरण से 1881 से 1911 तक के निम्न आकड़े मिलते हैं

|         | 1881  | 1891  | 1901  | 1911  |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| पुरुष   | 23 67 | 24 59 | 23 63 | 22 59 |
| महिलाएँ | 25 58 | 25 54 | 23 96 | 23 31 |

1921 के जनगणना कमिशनरी द्वारा प्रस्तुत इन विवरणों के अनुसार 1881 से 1911 के बीच प्रत्याशित आयु में गिरावट आई 1921 के लिए कोई आकड़ा नहा तयार किया गया। पिछले 50 वर्षों में भारत की यह स्थिति इंग्लैंड और वेल्स की स्थिति से काफी विपरीत है जहाँ 1881 90 से 1933 के बीच प्रत्याशित आयु क्रमशः 45 4 से बढ़कर 60 8 हो गई।

1931 के लिए की गई एक वस्तुस्थिति गणना में पुरुषों के लिए 26 9 वर्ष और महिलाओं के लिए 26 6 वर्ष की प्रत्याशित आयु कराई गई है। इससे मामूली बढ़ि का संकेत मिलता है परंतु इन आकड़ों की अशुद्धि का उस समय पता चल जाता है जब हम प्रत्याशित आयु और दर की गई मृत्यु दर के विवरणों की तुलना करते हैं। अब हम 1931 के आकड़ों में उल्लिखित प्रत्याशित आयु के अपेक्षाकृत अनकूल अंक की भी ध्यान में रखकर मृत्यु दर की गणना करते हैं तो पता चलता है कि पुरुषों के लिए यह प्रति हजार 37 और महिलाओं के लिए प्रति हजार 38 है जबकि दरों की गई मृत्यु दर महज २३ है। प्रत्याशित आयु के आकड़ों अपने आप में गलत हैं लेकिन वे जो भी हैं उनसे इसी निष्कर्ष की समझ मिलती है कि भारत में सामान्य मृत्यु दर को कम से कम प्रति हजार पर 33 मानना ही सही है। (जी० चंद इंडियाज टोमिंग मिलियंस पृष्ठ 113)

- 16 ब्रिटिश भारत में सामान्य और विशेष रोगों की चिकित्सा सहित अस्पतालों में रागियों के लिए कुल उल्लेख शब्दों की तुलना जय देश से की जा सकती है

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| अमेरिका           | 1000 जनसंख्या पर 10 48 शब्दों |
| इंग्लैंड और वेल्स | 1000 जनसंख्या पर 7 14 शब्दों  |
| ब्रिटिश भारत      | 1000 जनसंख्या पर 0 24 शब्दों  |

- 17 यह जानकारी काफी दिलचस्प है। कि विश्व जनसंख्या के बारे में प्रो० कार-सांडर्स नहाल की अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक (वर्ल्ड पापुलेशन पास्ट प्रीेंट ऐंड फ्यूचर—ए०एम० कार-सांडर्स 1936) में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि 1650 से 1933 के बीच विश्व की कुल जनसंख्या में जो बढ़ि हुई उसमें यूरोप का योगदान 18 3 प्रतिशत से बढ़कर 25 2 प्रतिशत हो गया जबकि एशिया का योगदान 60 6 से घटकर 54 5 प्रतिशत हुआ। जाज भी बहुप्रचारित वास्तविक कथाओं के विपरीत प्रचुरता की ओर बढ़ता यूरोप विश्व इतिहास में बुजुर्गों की वृद्धि के दौरान एशिया की अपेक्षाकृत कम होती आबादी का स्थान लिया है।

- 18 फर्गिन इन्वायरी कमिशन समापक रिपोर्ट 1945 पृ० 75

- 19 प्रमुख सांख्यिकी डा० आर० आर० मुक्तिस्वी ने 1921 से 1931 के बीच भारत में प्रजनन जनसंख्या में हुई अचानक भारी बढ़ि का कारण ज़ायतौर से रिक्तते जाने वाले निष्कर्षों के महत्व

पर कुछ सदेह प्रकट किया है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अत्यधिक आबादी की भविष्य वाणिया की गई हैं। उनका कथन है कि

अनेक देशों के बारे में जहाँ जनगणना की जाती है हम वहाँ की वर्तमान आबादी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं पर जन्म और मृत्यु के पारस्परिक आकड़े न मिलने के कारण हम जनसंख्या की प्रवृत्ति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार भारत की जनगणना के आकड़ों से पता चलता है कि 1921 से 1931 के बीच जनसंख्या में वृद्धि 3 करोड़ 40 लाख अर्थात् 10.6 प्रतिशत हुई। लेकिन 1931 की जनमरण संबंधी तालिका के अनुसार मृत्युदर काफी अधिक लगती है जबकि विवाह के पश्चात् उत्पन्न बच्चों की संख्या और माँ बनने में असमय विधवा महिलाओं की संख्या देखने से पता चलता है कि जनन क्षमता अपेक्षाकृत कम हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 1921 से 1931 के बीच भारत में जनसंख्या में जो प्रवृत्ति रूप में वृद्धि हुई है वह वास्तविक वृद्धि नहीं है। इस वृद्धि के आभास का कारण 1931 में की गई अपेक्षाकृत ज्यादा ठीक-ठीक गणना और आयु की स्थाई संरचना के कारण है जिससे जन्म संख्या बढ़ी और मृत्यु संख्या में कमी देखी गई। (डा० आर० आर० कुन्जिस्की, पापुलेशन ट्रेंड्स इन दि वर्ल्ड, — 25 दिसंबर 1937 के स्टेटिस्ट में प्रकाशित) यह ध्यान देने की बात है कि भारत में जन्म दर में प्रत्यक्ष गिरावट आ रही है। 1901-10 के दशक में जन्म दर प्रति हजार पर 38 दर्ज की गई थी जो 1931-40 के दशक में 34 हो गई और 1943 में 26 हो गई।

- 20 भारत में साम्राज्यवाद द्वारा घोषी गई सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण ही किसान जनता वृद्धि से गरीब होती जा रही है और अनाज के उत्पादन में गिरावट आ रही है। इस तथ्य को भारत सरकार के एक अधिकारी डब्ल्यू० बंस ने ब्रिटिश भारत के लिए तैयार किए गए निम्न लिखित आकड़ों में और भी ज्यादा स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है :

| वर्ष    | प्रमुख खाद्यान्नों<br>वास्तु इलाके<br>(करोड़ एकड़) | प्रमुख खाद्यान्नों<br>का उत्पादन<br>(करोड़ टन) | जनसंख्या<br>(करोड़ व्यक्ति) |
|---------|--|--|-----------------------------|
| 1921-22 | 15.86  | 5.43   | 23.36                       |
| 1931-32 | 15.69  | 5.01   | 25.68                       |
| 1941-42 | 15.65  | 4.57   | 29.58                       |

(डब्ल्यू० बंस टक्कासाजिकल पोपुलेशनल आफ एग्नीक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया 1944) 1921-22 से 1941-42 के दौरान ब्रिटिश भारत में जहाँ जनसंख्या में 6 करोड़ 22 लाख की वृद्धि हुई वहीं प्रमुख खाद्यान्नोंवाली कृषि भूमि के क्षेत्रफल में 20 लाख एकड़ से ज्यादा की कमी आई। उत्पादन के आकड़ों और भी ज्यादा चौकाने वाले हैं। उत्पादन में 86 लाख टन की कमी आई।

- 21 राशन में जबरदस्त कटौती के फलस्वरूप फिलहाल औसतन एक भारतीय महज 960 किलोमीटर का उपयोग करता है जबकि एक अमेरिकी 3150 किलोमीटर और एक ब्रिटिश 3000 किलोमीटर का शक्ति प्राप्त करता है।

## दो ससारो की विषमता

मैंने स्वयं देखा है कि सी वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भी भारत के गावा में भोजन और पानी की गंभीर कमी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा का अभाव संचार माधन की उपक्षा शिक्षा मरधी सुविधाओं की दरिद्रता, और हर तरफ निराशा की भावना है। इन स्थितियों में मुझे यह नहीं लगता कि ब्रिटिश शासन किसी के लिए उपकारी सिद्ध होगा। इस देश में सोवियत रूस के बार में बात करना लगभग अपराध है फिर भी मैं सोवियत तथा भारत के बीच के अंतर का उल्लेख करने से खुद का राक नहीं पाता हूँ। मुझे यह माफ़ शब्दों में स्वीकार करना पड़ता है कि सोवियत मध्य में अनाज उत्पादन शिक्षा प्रदान करने तथा बीमारी के विरुद्ध मध्य करने की दिशा में जो उत्साहपूर्ण तथा अमाधारण उपाय अपनाए गए हैं उन्हें देखकर मुझे दुःखी होती है। सोवियत-यूरोप और सोवियत एशिया के बीच अविषमता अथवा अपमानजनक भेदभाव की कोई भी विभाजन रखा नहीं है। मैं केवल यहाँ और यहाँ घटित हो रही स्थितियों की तुलना कर रहा हूँ जिन में मैं स्वयं पड़ा हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तथानयित ब्रिटिश साम्राज्य में हमारी रंग स्थिति की जिम्मेदारी शासक और शासित वर्ग के बीच की बढ़ती खाई पर है। (स्वीडनाय टगार 1936)

भारत वनमा और भावी की मून तस्वीर का पूरा करने के लिए व्यावहारिक निरूपण की आवश्यकता है।

अभी पिछले बीस वष पहले तक यह तक देना सभव था कि भारतीय साधनों के विकसित करने में या जनता का जीवनस्तर ऊचा उठाने में साम्राज्यवाद की असफरता की किसी भी सैद्धांतिक भ्रमना का अथ एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद की आलोचना करना और एशिया के एक देश की स्थितिया में व्याप्त उन तमाम अवरोधों को देखने में विफल रहना है जो अत्यंत निम्न तकनीक तथा पिछड़ेपन और मुख्यतः निरक्षरता से ग्रस्त आबादी के कारण पैदा होते हैं। वर्तमान स्थितिया अथाह हैं और इस तथ्य को साम्राज्यवाद के समयको ने भी स्वीकार किया है फिर भी साम्राज्यवाद के पक्ष में बहुधा यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरा शासन इससे अधिक उपलब्धिया प्राप्त नहीं सकता था या नहीं कर सकता।

आज इस तरह के तर्क मगत नहीं प्रतीत होते। आधुनिक युग के अनुभव ने अत्यंत पिछड़ी स्थितियों के अतगत भी तेजी के साथ रूपांतरण की सम्भावनाओं को काफी विस्तृत बना दिया है। इस सदर्भ में युद्ध के बाद टर्की के पुनरुत्थान और आत्मानर्ति का उदाहरण काफी शिक्षाप्रद है और भारत के लिए इससे अच्छा सबक मिल सकता है। किंतु खास तौर से सोवियत मध्य में समाजवादी क्रांति ने पिछले बीस वर्षों के दौरान जो सफलताएं प्राप्त की हैं और एक ऐसे विशाल देश में जहां उत्पादन की तकनीक बहुत पिछड़ी हुई थी, लोग काफी असंगठित थे और अधिकांशतः निरक्षर थे और जहां यूरोपीय तथा एशियाई दोनों तरह के लोग रहते थे, उसने जैसे महान परिवर्तन कर दिखाए हैं उनसे सभी देशों की जनता की आंखें खुल गई हैं। साथ ही इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आया है कि ऐसे देशों में भी क्या किया जा सकता है। सोवियत मध्य का अनुभव भारत की जनता के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि इस तुलना का हम कुछ और विस्तार के साथ सामन रखें तो काफी लाभप्रद होगा। इससे भारत की वर्तमान जड़ स्थिति पर रोशनी तो पड़ेगी ही, साथ ही इस बात का आशाजनक संकेत भी मिलेगा कि यदि उचित सामाजिक और राजनीतिक स्थितिया पैदा की जाएं तो बहुत कुछ उपलब्ध किया जा सकता है।

## 1 समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीस वर्ष

संयोग की बात है कि 1917 में सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे हुए और उसी वर्ष भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के एक सौ अस्सी वर्ष पूरे हुए (वर्तमान ब्रिटिश शासन की स्थापना हम प्लामी के युद्ध से मानें)। इस प्रकार समाजवाद ने रूस में जो कुछ कर दिखाया और जितने समय में कर दिखाया उसमें 9 गुना अधिक समय साम्राज्यवाद को भारत में कुछ कर दिखाने के लिए मिला।

इन दोनों विशाल देशों की पूर्ववर्ती स्थितिया में जो अंतर है वह काफी महत्वपूर्ण है (खास तौर से एक स्वतंत्र साम्राज्यवादी देश और एक उपनिवेश के बीच का अंतर) फिर भी दोनों देशों का विरासत में जो स्थिति मिली है उसमें कुछ समानता भी है मसलन

समूची आवादी के एक बड़े हिस्से का निरक्षर होना तथा अधिकांश किसानों का पिछड़ा होना सभ्यता के भिन्न भिन्न चरणों में एक के बाद एक अलग अलग जातियों तथा राष्ट्रीयता के लोगों द्वारा वैसे भूभाग की विशालता, अपक्षायित अविकसित प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता ग्रामीण व्यवस्था के घटक को छोड़कर और किसी भी तरह के जनतांत्रिक रूप के अनुभव से शून्य निरक्षर शासन की परिपाटी। इन समानताओं को मद्देनजर रखते हुए यह तुलना करने की जरूरत पड़ती है कि एक सौ अस्सी वर्षों में साम्राज्यवाद ने भारत को क्या दिया और बीस वर्षों में समाजवाद ने रूस को क्या दिया।

शोषण की पूर्ववर्ती प्रणालियों के स्थान पर समाजवाद या उत्पादन के सामूहिक संगठन की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है जो आधुनिक परिस्थितियों से उपजी है। इस धारणा को कल्पनालोक के क्षेत्र से गुजर कर विज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने में सौ वर्ष से भी कम समय लगा और नई सामाजिक व्यवस्था की व्यावहारिक सिद्धि के अनुभव का जरिए यह विज्ञान हमारे ही युग में अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर सका है। आज व्यवहार रूप में समाजवाद की प्राप्ति हो गई है। इसलिए केवल सिद्धांत के स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी साम्राज्यवाद और समाजवाद की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम जारशाही रूस को ले सकते हैं। लेकिन हम 1917 के उस रूस को नहीं लेंगे जिसकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी हालांकि समाजवादी शासन को रूस इसी हालत में मिला था। अपने अध्ययन के लिए हम जार के ही शासन काल के 1913-14 के रूस को लेंगे जब उसकी उपलब्धियां सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसकी तुलना हम 1937 के रूस से करके देखेंगे कि 20 वर्षों में समाजवाद ने उस देश को क्या बना दिया है। इसी प्रकार हम 1914 के अत्यंत प्रथम विश्वयुद्ध से पहले के भारत को लेंगे और देखेंगे कि 20 वर्षों में यानी 1934 तक इस देश में साम्राज्यवाद की क्या उपलब्धियां रही। अतः हम इसी अवधि में सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में हुए विकास की ओर भी उपयोगी तुलना करेंगे। इन गणराज्यों में वे तमाम विशेष कठिनाइयां और समस्याएँ मौजूद थीं जो भारत में पाई जाती हैं और वहां की जनता के विकास का सामान्य स्तर शुरू में भारत से कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ था।

उत्पादन शक्तियों के विकास की जो बुनियादी वसोटी है, उसी से हम अपना बात शुरू करें।

सोवियत संघ में औद्योगिक उत्पादन (बड़े उद्योगों का) का सूचक अब 1913 में 100 से बत्तर 1937 में 816.4 हो गया। यह 8 गुनी वृद्धि थी। यह वृद्धि एक ऐसी प्रगति की द्योतक है जिसकी तुलना किसी भी देश के आर्थिक इतिहास से नहीं की जा सकती। इसका रूस में निम्नोक्त उद्योगीकरण, भारी उद्योग और मशीन निर्माण की स्थापना, विदेशी

पूजी से स्वतन्त्र स्थिति और साथ ही हल्के उद्योग की स्थापना का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया बल्कि एक पिछड़े देश से स्थापत्य करने, उस रूप का जिस पहले 'ग्रामीण महा-द्वीप' और विदेशी पूजी के आधिपत्य में उद्योग की दृष्टि से अल्पविकसित देश के रूप में जाना जाता था यूरोप के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र और विश्व के दूसरे सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक देश का दर्जा दिया। देश की कुल पैदावार की तुलना में औद्योगिक उत्पादन का अनुपात 1913 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 1937 में 77 प्रतिशत हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस जो पहले मुख्य रूप से कृषिप्रधान देश था अब प्रमुख रूप से उद्योगप्रधान देश बन गया। देश में कुल जितने काम करने वाले लोग थे, 1913 में उनके सोलह प्रतिशत लोग औद्योगिक कामगार थे और 1937 में इनकी संख्या बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई। 1913 में राष्ट्रीय आय (1926-27 के मूल्यों को आधार मानकर) 21 अरब रुबल थी जो 1937 तक बढ़कर 96 अरब रुबल अर्थात् पहले से साढ़े चार गुनी अधिक हो गई।

प्रारम्भ में ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का या कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय का सामान्य सूचक एक निकातन का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। मुख्य उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन का सूचक एक निकातन का एक गैरसरकारी प्रयास डी०वी० मीक ने किया था। उन्होंने यह प्रयास अपने एक लेख 'इंडियन एक्मटनल ट्रेड' में किया था जिसे अप्रैल, 1936 में 'रायल सोसायटी आफ आर्ट्स के भारतीय अनुभाग' के समक्ष पढ़ा गया था। अपने लेख में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में 1910-11 से लेकर 1914-15 तक के पांच वर्षों के सूचक अंक को 100 मानकर यह आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि 1932-33 का सूचक अंक 156 था, अर्थात् कुल वृद्धि 56 प्रतिशत हुई थी जोकि अपेक्षाकृत निम्न जब से हुई सोवियत संघ की वृद्धि की दर का 16वां हिस्सा है। 1911 और 1921 में एक औद्योगिक जनगणना हुई थी हालांकि 1931 में वह नहीं हुई। उससे पता चला था कि 'संगठित उद्योगों' में अथवा उन कारखानों में जहाँ 20 से अधिक मजदूर काम कर रहे हों, 1911 में 21 लाख आदमी काम करते थे। 1921 तक यह संख्या बढ़कर 26 लाख हो गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति वर्ष 2.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती थी। यह वृद्धि यदि 20 वर्ष तक बराबर इसी दर से होती रहती तो कुल 48 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर होती (दरअसल युद्ध और उसके तुरंत बाद के वर्षों में वृद्धि की यह दर बनी नहीं रह सकी)। सोवियत संघ की वृद्धि की दर का यह 19वां भाग होती है। 1911 में उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 175 लाख बताई गई थी और 1931 में 153 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में 12.6 प्रतिशत की पूरी पूरी कमी हो गई। यह इस बात का प्रतीक था कि छोटे मोटे हाथ के उद्योग लगातार नष्ट होते जा रहे थे और उनके अनुरूप प्राधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि जहाँ कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या 1911 में 72 प्रतिशत से बढ़कर 1921 में 73 प्रतिशत हो गई और 1931 में भी इसी स्तर पर बनी

रही, वहाँ औद्योगिक मजदूरा की संख्या 1911 के 11.7 प्रतिशत से घटकर 1931 में 10 प्रतिशत पर आ गई। साम्राज्यवाद द्वारा 20 वर्षों में टूट-उपलब्धि की ऐसा ही 'प्रगति' थी।

इस सामान्य तस्वीर का और महत्वपूर्ण बनाने के लिए दोनो देशों के सर्वाधिक उल्लेखनीय भौतिक उत्पादन के आंकड़ों की ओर भी ज्यादा ठीक ठीक तुलना करना जरूर है। भारत में कोयले का उत्पादन 1914 में 1 करोड़ 64 लाख टन से बढ़कर 1934 में 2 करोड़ 20 लाख टन हो गया। अर्थात् 20 वर्षों में 55 लाख टन की वृद्धि हुई जो 34 प्रतिशत वृद्धि थी। रूस में कोयले का उत्पादन 1913 में 2 करोड़ 90 लाख टन से बढ़कर 1937 में 12 करोड़ 80 लाख टन हो गया अर्थात् 9 करोड़ 90 लाख टन की वृद्धि हुई जो 340 प्रतिशत वृद्धि थी। यह भारत में हुई वृद्धि की तुलना में पूरे दस गुना अधिक थी। इस्पात का उत्पादन जो भारत में युद्ध से पहले अभी शुरू ही हुआ था 1914 में 10 लाख टन नहीं पहुँचा था (यह 8 लाख 34 हजार टन था)। सोवियत संघ में इस्पात का उत्पादन 1937 तक 1 करोड़ 75 लाख टन तक पहुँच गया था जो युद्ध से पहले की तुलना में 1 करोड़ 30 लाख टन से अधिक की वृद्धि का द्योतक है। सोवियत संघ में 1913 में 1 अरब 90 करोड़ किलोवाट घंटे बिजली तैयार होती थी जो 1937 में बढ़कर 36 अरब 50 करोड़ किलोवाट घंटे हो गई अर्थात् कुल 18 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि में भारत में विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति थी इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है हालाँकि 1935 में अनुमानतः भारत में ढाई अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होती थी। यह संख्या सोवियत संघ के विद्युत उत्पादन के 14वें हिस्से से भी कम और सोवियत संघ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के स्तर के 30वें हिस्से से भी कम है।

कृषि के क्षेत्र में यह विपत्ति और भी गहरी हो जाती है क्योंकि सोवियत संघ में विशाल बहुमत के लिए जो रूपांतरण हुआ उसका बुनियादी दृष्टि से काफी महत्त्व है। जार शासित रूस में जमींदारों, सूदखोर महाजनों और कुलकों (धनी किसानों) की दबाव पर चलने वाली निधन और भूखी किसान जनता ने आज सामूहिक खेती करने वाले स्वतंत्र और समृद्ध किसान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अब वे अपने बड़े बड़े सामूहिक कृषि फार्मों में दुनिया की आधुनिकतम मशीन और तकनीक की मदद से खेती कर रहे हैं। जबसे खेती के सामूहिकीकरण का काम पूरा हुआ है तबसे 5 वर्षों के अंदर वे किसान अपनी नकद आय तिगुनी कर रहे हैं। 1913 में फसल के क्षेत्र में एक तिहाई की वृद्धि हुई और इसके साथ अनाज की पैदावार डेढ़ गुनी हो गई। यह 1913 में 80 करोड़ 10 लाख सेंटनस से बढ़कर 1937 में 1 अरब 20 करोड़ 20 लाख सेंटनस हो गई। वपस की पैदावार 1913 में 74 लाख सेंटनस से बढ़कर 1937 में 2 करोड़ 58 लाख सेंटनस हो गई जो साढ़े तीन गुनी वृद्धि है। भारत में कृषि के क्षेत्र में जो संकट है उसका हम अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे लेकिन यह संकट हर वर्ष और अधिक गंभीर रूप ले रहा है। जमींदारों, सूदखोर महाजनों और सरकार के मिलेजुले दबाव ने किसानों को

कंगाल बना दिया है और उनकी जमीनो से उह लगातार बढखल किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों मे फसल बोने के क्षेत्र म और फसल की मात्रा म जो वृद्धि हुई है वह जनमख्या की वृद्धि से मुश्किल से ही बढ पाई है। पूण मदी के बहुत ही स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।

यदि हम उत्पादन और साधनो के विकास के बुनियादी उपायो से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की खुशहाली को बढावा देने के लिए राज्य द्वारा किए गए सामाजिक उपायो पर नजर डालें तो साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच की विपमता किसी भी मामले मे कम नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र म सोवियत संघ मे काफी प्रगति हुई है। जारशाही रूस म 78 प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर थे और उह जानबूझ कर निरक्षर बनाए रखा गया था लेकिन यह सख्या अब घटकर 8 प्रतिशत हो गई है। 1930 मे सोवियत सरकार द्वारा एक आदेश के अतगत सावजनिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की स्थापना की गई और 1934 के एक आदेश के जरिये सभी लोगो के लिए 7 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य बना दी गई। इस शिक्षा का प्रसार बडे औद्योगिक केंद्रो से शुरू होकर सावजनिक 10 वर्षीय शिक्षा प्रणाली तक ले जाया गया है।

भारत मे 1911 म कुल आबादी के 94 प्रतिशत लोग निरक्षर थे और 1931 मे यह सख्या 92 प्रतिशत ही रही। 20 वर्षों मे साम्राज्यवाद ने कुल आबादी के 50वें हिस्से की निरक्षरता दूर की।

1937 मे सोवियत संघ मे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो मे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चो की सख्या 2 करोड 94 लाख (जारवादी रूस मे यह सख्या 78 लाख थी) या कुल आबादी का 17.2 प्रतिशत थी।

भारत मे 1934-35 के आकडो का देखने से पता चलता है कि ब्रिटिश भारत के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो मे किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चो की सख्या 1 करोड 35 लाख या कुल आबादी का 4.9 प्रतिशत थी। लेकिन इन आकडो की जाच करने से पता चलता है कि जिनके बारे मे यह समझा जाता था कि वे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वे भी पहले वर्ष से आगे नहीं बढ सके। और जो लोग चौथे वर्ष तक पहुच गए उनमे से पाचवा हिस्सा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका (देखें 'एजुकेशन इन इंडिया 1928-29,' 1931, पृष्ठ 28)। इस प्रकार जो लोग चार वर्ष की सीमित प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनकी सख्या सरकारी आकडे, 1 करोड 11 लाख या 22 लाख के पाचवें हिस्से के बराबर है जो कुल आबादी का 0.8 प्रतिशत है।



1937 में सोवियत मध्य में विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या 5 लाख 51 हजार थी जो कुल आबादी के तीन दशमलव का व्यक्ति प्रति हजार के बराबर थी (जाराशाही रूस में यह संख्या मात्र 1 लाख 20 हजार थी)।

1934-35 में ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या 1 लाख 9 हजार 8 सौ थी जो कुल आबादी की 0.4 व्यक्ति प्रति हजार के बराबर थी। यह संख्या सोवियत मध्य की तुलना में आठ गुनी कम है।

तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में, जो किसी अवििकमित देश के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबसे ज्यादा गंभीर विपत्ति पाते हैं। सोवियत मध्य में प्राविधिक माध्यमिक स्कूलों और फैक्टरी स्कूलों का जो व्यापक जाल बिछा हुआ है उसकी तुलना भारत से किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। अकेले वर्ष 1937 में सोवियत मध्य में स्नातक स्तर तक शिक्षा पाने वाले प्राविधिक विशेषज्ञों (औद्योगिक और भवन इंजीनियरों, परिवहन एवं मंचार इंजीनियरों, कृषि का मशीनीकरण करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों और कृषि विशेषज्ञों) की संख्या 45,900 थी। भारत में 1934-35 में इंजीनियरिंग, कृषि या वाणिज्य में स्नातक स्तर तक की शिक्षा पाने वालों की कुल संख्या महज 960 थी जो सोवियत मध्य की संख्या से 1 और 48 के अनुपात में है। आबादी के अनुपात से यह 1 और 78 का संबंध है।

अखबारों और प्रकाशनों के संबंध में सांस्कृतिक विकास का अर्थ उपाया पर विचार करें तो पता चलेगा कि सोवियत मध्य में 1913 में दैनिक समाचार पत्रों की संख्या जहां 859 थी वहां संख्या 1937 में बढ़कर 8521 हो गई अर्थात् उनके प्रकाशन में 10 गुनी वृद्धि हुई। उनका दैनिक वितरण 27 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 62 लाख हो गया अर्थात् उसमें 14 गुना वृद्धि हुई। भारत में 1913-14 में 827 समाचार पत्र निकलते थे जो 1933-34 में बढ़कर 1748 हो गए। उनके दैनिक वितरण का कोई आंकड़ा नहीं उपलब्ध है लेकिन यह वितरण बहुत कम रहा होगा। सोवियत मध्य में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 1913 में 8 करोड़ 67 लाख से बढ़कर 1937 में 67 करोड़ 30 लाख हो गई। यह वृद्धि लगभग आठ गुनी थी। भारत में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या (आंकड़े उपलब्ध नहीं) 1913-14 में 12189 से बढ़कर 1933-34 में 16763 हो गई जो 20 वर्षों में केवल एक तिहाई की वृद्धि थी।

यदि हम सोवियत मध्य में विद्यमान जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधा के उपायों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि लोगों की भ्रष्टाचार और सुविधा के लिए जितना मुहम्मद और मुख्यस्थित इंतजाम यहां है उतना किसी भी दूसरे देश में नहीं है। इनके साथ ही

हम भारत में इन सेवाओं के प्रति जो गहरी उम्मीदें देखते हैं उसमें दोनों देशों की व्यवस्था की विपमता का पता चलता है। सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक के पैदा होने से लेकर मरने तक उससे स्वास्थ्य और खुशहाली की देखरेख की जाती है जिनमें हर तरह की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा तथा अन्य तरह की सुविधाएँ शामिल हैं, माताओं और शिशुओं की देखरेख की व्यवस्था है, सवतन अवकाश की सुविधा है, मजदूरों के लिए विश्रामगृह है और वृद्धावस्था के लिए उचित इंतजाम है। दूसरी तरफ भारत में सामाजिक बीमा की अत्यंत सीमित प्रणाली भी, जो पूँजीवादी देशों में आम तौर पर पाई जाती है, नहीं है। यहाँ सावजनिक स्वास्थ्य मंत्री कोई कानून नहीं है और कस्बा या गाँव में मेहनतकश जनता के लिए सावजनिक स्वास्थ्य और सफाई की सर्वाधिक बुनियादी आवश्यकताएँ इतने निम्न स्तर पर पूरी की जाती हैं जिन्हें नहीं के बराबर ही समझना चाहिए।

सोवियत संघ में जन स्वास्थ्य पर 1913 में 12 करोड़ 80 लाख रूबल खर्च किया गया जो 1928 में 69 करोड़ 90 लाख रूबल, 1933 में 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख रूबल और 1937 में 9 अरब 5 करोड़ रूबल हो गया। यह वृद्धि 70 गुना अधिक थी। 1937 में 9 अरब 5 करोड़ रूबल का अर्थ यह हुआ कि प्रति व्यक्ति 53 रूबल खर्च किए गए। भारत में जन स्वास्थ्य के खर्च के मुख्य बोझ को प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण प्रांतों पर डाले जाने से 1913 के आंकड़ों से प्रभावकारी तुलना नहीं हो पाती। लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से जन स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि 1921-22 में 4 करोड़ 73 लाख रुपये थी जो 1935-36 में बढ़कर 5 करोड़ 72 लाख रुपये हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि 1921-22 में कुल केंद्रीय और प्रांतीय खर्च 2। प्रतिशत में बढ़कर 1935-36 में 2.6 प्रतिशत हो गया। 1935-36 में 5 करोड़ 72 लाख रुपये का अर्थ यह हुआ कि प्रति व्यक्ति 2.75 पैसे हो गया।

दोनों देशों की स्थितियों की तुलना के लिए यदि हम वहाँ के अस्पतालों में मरीजों के रहने के इंतजाम पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि सोवियत संघ में 1913 में अस्पतालों में 138 000 मरीजों के रहने की व्यवस्था थी जो 1937 में बढ़कर 543 000 तक पहुँच गई। इसका अर्थ यह हुआ कि समूची आबादी में प्रति 313 व्यक्ति पर एक व्यक्ति के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी। ब्रिटिशकालीन भारत में यह मर्यादा 1914 में 48 435 थी जो 1934 में बढ़कर 72 271 हो गई (इनमें सभी सरकारी और निजी संस्थाएँ शामिल हैं जिनमें से अनेक संस्थाएँ केवल यूरोपीयों के लिए या सेना के कर्मचारियों के लिए थीं)। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल आबादी के प्रति 3810 व्यक्ति पर एक व्यक्ति के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी। सोवियत संघ में इस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधा की तुलना में यह 12 गुना कम है।

जारशाही रूस में 1913 में मृत्यु दर 28.3 प्रति हजार थी जो भारत में 1914 में मृत्यु

दर 30 प्रति हजार के काफी करीब है। लेकिन सोवियत संघ में 1926 तक यह दर कम होकर 20.9 प्रति हजार पर आ गई जबकि उसी वर्ष भारत में यह दर 26.7 प्रति हजार थी। 1913 में मास्को में मृत्यु दर 23.1 प्रति हजार और 1926 में 13.4 प्रति हजार थी। बर्लिन में 1914 में मृत्यु दर 32.7 प्रति हजार और 1926 में 27.6 प्रति हजार थी। मास्को में 1913 में शिशुओं के मरने की दर 270 प्रति हजार थी जो 1928-29 तक घट कर 120 प्रति हजार हो गई। उस वर्ष बर्लिन में यह दर 255 प्रति हजार थी।

सांख्यिक सफाई और छूत की बीमारियों पर पड़ने वाले उससे प्रभाव पर विचार करें। सोवियत संघ में 1913 में प्रति दस हजार पर 7.3 लोग टाइफस से पीड़ित थे लेकिन 1929 में यह संख्या 2.0 प्रति 10 हजार हो गई अर्थात् 72 प्रतिशत की कमी हुई। इसी प्रकार डिप्थीरिया के मामले में यह संख्या 31.4 से घटकर 5.9 प्रति हजार हो गई अर्थात् 80 प्रतिशत की कमी हुई। चेचक के मामले में यह संख्या 4.7 से घटकर 0.37 प्रति हजार हो गई अर्थात् 90 प्रतिशत की कमी हुई (एच० ई० सिगरिस्ट, साशलाइज्ड मैडिसिन इन दि सोवियत यूनियन', पृष्ठ 357)। टाइफस और डिप्थीरिया के बारे में भारत में कोई आकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन चेचक से हुई मौतों के आकड़े से एक उप योगी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। भारत में 1914 में चेचक से मरने वालों की संख्या 76590 थी अर्थात् इसकी दर 3.2 व्यक्ति प्रति दस हजार थी। 1934 में यह संख्या 83925 अर्थात् 3.0 प्रति दस हजार हो गई। 1935 में इस संख्या में मामूली वृद्धि हुई। भारत में चेचक से मरने वालों की संख्या में 20 वर्षों के अंतराल के बाद भी कोई फर्क न पड़ना (3.2 और 3.0 प्रति 10 हजार) और सोवियत संघ में इसी अवधि में चेचक से मरने वालों की संख्या में 4.7 से घटकर 0.37 का हो जाना दोनों की विषमता को प्रकट करता है।

1913 में सोवियत संघ में डाक्टरों की संख्या 19800 थी जो 1937 तक बढ़कर 97000 हो गई। भारत में 1934-35 में विश्वविद्यालयों से निकल चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या 630 थी। इसमें उन डाक्टरों की भी मामूली संख्या जोड़ी जा सकती है जो इंटर से प्रशिक्षण लेकर लौटें थे।

अतः हमें हम मजदूरों की हालत पर विचार करें और सोवियत संघ में उनके काम में निर्धारित घंटे पर ध्यान दें ता पता चलेगा कि सोवियत संघ से 1922 में सभी उद्योगों में 8 घंटे की अवधि काम करने के लिए निर्धारित की गई जो 1927 में सभी उद्योगों में 7 घंटे के दिन के रूप में तय हो गई। इसमें छुट्टियां पेश की गईं जमीन के नीचे काम करने वाले मजदूरों के लिए निर्माणाधीन काम करने वालों के लिए और 16 तथा 18 वर्ष के बच्चों के कारखानों के लिए 1927 में ही काम का 6 घंटे का दिन निर्धारित किया गया। 14 वर्ष की उम्र में काम करने से बच्चे को भी म्युनिस्टर में काम की इजाजत नहीं थी और 14

वष से 16 वष की आयु वग के जो लड़के असा गरण परिस्थितियो म काम करत थे उनके लिए दिन भर मे काम की अधिकतम अवधि 4 घट तय की गई।

भारत मे 1922 के फँक्टरी ऐक्ट द्वारा 11 घटे का दिन निर्धारित किया गया और 1934 के फँक्टरी ऐक्ट ने काम के लिए 10 घट का दिन तय किया तथा 12 वष से कम उम्र के बच्चो को रोजगार देने की मनाही की गई। लेकिन कारखाना की स्थिति की जाच करने वाले इसफँक्टरी की सख्या इतनी कम रखी गई (व्हिटले कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1929 मे भारत भर मे उनकी सख्या केवल 39 थी) कि किसी भी इस्पेक्टर के लिए प्रत्येक कारखाने मे साल मे एक बार भी पहुचना असभव था। इसका नतीजा यह हुआ कि मालिका ने फँक्टरी ऐक्ट की अवहेलना की और खामतौर से कम उम्र के बच्चो को नौकर रखने म इस कानून की काफी अवहेलना की गई। इसने अलावा फँक्टरी ऐक्ट औद्योगिक मजदूरो के महज एक छोटे से भाग पर लागू है (1931 की जनगणना से पता चलता है कि 1 करोड 77 लाख व्यक्ति उद्योगो तथा परिवहन सेवाओ मे काम करते थे और इनमे से 1936 मे सिफ 16 लाख व्यक्तिया पर फँक्टरी ऐक्ट लागू था)। भारत के अधिकांश मजदूरो के लिए काम के घटो की कोई सीमा नहीं है उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है या छोट से छोटे बच्चो के शोषण की कोई सीमा नहीं है। जैसाकि व्हिटले कमीशन की रिपोर्ट म बताया गया था 5 5 वष के बच्चो को दिन भर मे 12 घटे तक काम करना पडता था।

विभिन्न क्षेत्रो मे दोनो देशो की स्थितिया मे जिस विरोध का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह ठोम तथ्यो पर आधारित है। इन तथ्यो के आधार पर, राजनीतिक दृष्टिकोण चाह जो भी हो, यह फैसला दिया जाना चाहिए कि सोवियत मध और भारत के बीच जो वैषम्य दिखाई पडता है वह सभ्यता और बबरता के बीच का वैषम्य है।

फिर भी बीस वष पहले जारशाही रूस और ब्रिटिशशासित भारत के लोगो की हालत मे इतना बडा अंतर नहीं था। यह रूप परिवर्तन 20 वर्षो के समाजवादी शासन के कारण हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि आवश्यक राजनीतिक परिस्थितिया पैदा कर दी जाए और वग शक्तियो के सबध मे परिवर्तन हो जाए तो भारत म भी इस तरह का रूपांतरण हो सकता है।

## 2 मध्य एशियाई गणराज्यो का अनुभव

सोवियत मध के मध्य एशियाई गणराज्यो के अनुभव से इस तुलनात्मक अध्ययन की ओर भी पुष्टि हो जाती है।

यदि हम 1913 के जारशाही रूस की तुलना आज के भारत से करें तो निस्संदेह रूप से यह बात मही लगती है और इस ध्यान मे रखना चाहिए कि भारत म रूपांतरण के लिए

प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु 1913 के जारशाही रूस की विकास अवस्था की तुलना में सामान्य तौर पर निम्न है हालांकि इससे विकास की आनुपंगिक दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (वस्तुतः 1913 के पहले के दशक में उत्पादक स्तरों के विश्व स्तर पर जारशाही रूस पिछड़ा रहा था)। लेकिन यह विशेषता सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों के उदाहरण को और भी महत्व दे देती है क्योंकि 20 वर्ष पहले ये गणराज्य आज के भारत की तुलना में वही ज्यादा पिछड़े हुए थे। इसके साथ ही प्रगति की उनकी वर्तमान उच्च अवस्था भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है।

सोवियत संघ और ब्रिटिश शासित भारत के बीच सामान्य तौर पर विद्यमान विपत्तिता का आश्चर्यजनक है ही, यह विपत्तिता उस समय और अधिक दिखाई पड़ती है जब हम मध्य एशियाई सोवियत गणराज्यों को देखते हैं। यहां हम यह देख सकते हैं कि प्रारंभ में इन गणराज्यों की स्थितियां भी काफी हद तक भारत की स्थितियां जैसी थीं और दोनों की विकास प्रक्रिया में भी काफी समानता थी। भारत की स्थिति को जिन विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका सामना उन्हें भी करना पड़ता था। इन गणराज्यों की जनता भारत की तुलना में अधिक पिछड़ी, आदिम, पंडित और निधनता से ग्रस्त थी। एशियाई जलव्यवस्था और एशियाई सामाजिक परिस्थितियों तथा महिलाओं की स्थिति, और धर्म आदि से संबंधित विशेष प्रकार की सभी समस्याएं इन गणराज्यों में बहुरूप में मौजूद थीं। इसलिए साम्राज्यवाद की उपनिवेशवादी नीति और पिछड़ी हुई जनता के संदर्भ में समाजवाद की नीति में जो अंतर है, वह इन गणराज्यों में जितनी स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है उतना और वही संभव नहीं है।

सात सोवियत समाजवादी गणराज्यों को मिलाकर स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्य मध्य के अंतर्गत तीन मध्य एशियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य समान रूप से स्वशासी गणराज्यों के रूप में शामिल हैं। इनके नाम हैं तुर्कमेनिस्तान जिसकी आबादी 12.5 लाख और क्षेत्रफल 171,000 वर्गमील है, उजबेकिस्तान जिसकी आबादी 50 लाख और क्षेत्रफल 66,000 वर्गमील है और ताजिकिस्तान जिसकी आबादी 15 लाख और क्षेत्रफल 55,000 वर्गमील है। इनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं बारा-काल्पक स्वायत्त गणराज्य और किरगीज स्वायत्त गणराज्य। ये पांच गणराज्य कजाकिस्तान से दक्षिण में हैं और भारत की सीमा के काफी करीब हैं।

कजाकिस्तान में दक्षिण में मध्य एशिया के पांच समाजवादी गणराज्य स्थित हैं जिनके नाम यहां हमें लागू की राष्ट्रियता पर आधारित हैं, उजबेक तुर्कमेन, ताजिक, किरगीज और बारा-काल्पक गणराज्य।

यह सोवियत समाजवादी गणराज्य मध्य का घूर्णन दक्षिण प्रदेश है। इसकी सीमा पारस, अफगानिस्तान और पश्चिमी चीन से लगी हुई है। मध्य एशिया

की सीमा से भारत 15 किलोमीटर की दूरी पर है।

क्रांति से पूर्व मध्य एशिया अधिगुलाम और औपनिवेशिक मजदूरों की भूमि थी। अब यह समान अधिकारवाली जातियों, समाजवादी कृषि और नवनिर्मित उद्योगों की धरती बन गई है। (मिखाइलोव सावियत ज्योग्राफी, 1937, पृष्ठ 6-7)

हम अपना अध्ययन ताजिकिस्तान से शुरू करें जो भारत से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है। अतीत में ताजिक लोगों का जीवन खुशहाल नहीं था। क्रांति होने के पूर्व तक वे जार-शाही रूस के जुए के अंतर्गत थे और बुखारा के अमीर की सामंती-मजहबों तानाशाही से ग्रस्त थे। जारशाही साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो गृहयुद्ध शुरू हुए वे 1925 तक अंतिम रूप से समाप्त नहीं हुए। 1925 में ताजिकिस्तान एक स्वायत्त गणराज्य बन गया और 1929 में वह एक स्वतंत्र सघीय गणराज्य के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में शामिल हो गया।

ताजिक लोगों का जीवन जारशाही के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ेपन की स्थिति में था। इनका जीवन कितना पिछड़ा था इसका पता हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि क्रांति से पहले वहां केवल 0.5 प्रतिशत लोग ही पढ़ लिख सकते थे (जबकि भारत में 1911 में 6 प्रतिशत लोग साक्षर थे)। 1933 तक वहां के 60 प्रतिशत लोग साक्षर हो गए थे (जबकि 1931 में भारत में केवल 8 प्रतिशत लोग ही साक्षर हो पाए थे)। 1936 तक ताजिक गणराज्य में 3 हजार स्कूल (अर्थात् आबादी के हर पांच सौ लोगों के लिए एक स्कूल), पांच उच्च शैक्षणिक संस्थाएँ और तीस से ज्यादा प्राविधिक विद्यालय हो गए थे। 1939 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3,28,000 तक पहुँच गई थी (जबकि 1914 में यह संख्या महज सौ थी), और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या 21 हो गई थी।

1924 में ताजिकिस्तान में कृषि के काम में जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल 1,00,50,000 एकड़ था। 1936 तक यह 1,62,60,000 एकड़ हो गया और मुख्य फसल के रूप में कपास की खेती की गई। अधिकतर किसान परिवारों ने कृषि का मामूहिक तरीका अपना लिया है। कपास की खेती का काम अधिवाशतया मशीनों से किया जाने लगा है। जुताई, बटाई आदि का काम अधिवाशतया ट्रैक्टरों से लिया जाता है। इन सारी चीजों में सिंचाई का विकास काफी महत्व रखता है।

कपास की उपज काफी हद तक सिंचाई पर निर्भर करती है। 1929 में ताजिकिस्तान ने सिंचाई पर तीन लाख रूबल खर्च किए। 1930 में एक करोड़ बीस लाख रूबल और 1931 में बजट में छह करोड़ दस लाख रूबल अर्थात् 50 रूबल प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया था और इनके लिए

अधिकांश धन जनता पर कर लगाकर नहीं वसूला गया बल्कि यह धन सोवियत मध्य की केंद्रीय सरकार से मिला था। (जे० कुनित्ज़ 'डान ओवर ममरक'द,' 1935 पृष्ठ 235)

ताजिकिस्तान के इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सिंचाई के विकास का काम कितना धीमा था। इतना ही नहीं पहले के सिंचाई कार्यों की उपस्था पर भी इससे रेशनी पड़ती है। इसके साथ ही जहाँ अत्यंत सीमित पैमाने पर नए सिंचाई कार्य शुरू किए गए हैं (1913-14 में कुल सिंचित क्षेत्र 4 करोड़ 68 लाख एकड़ से बढ़कर 1933-34 में 5 करोड़ 50 लाख एकड़ हो जाना) व केवल पूंजीनिवेश के आधार पर शुरू किए गए जिसके लिए औसतन 7 प्रतिशत से अधिक वाली ऊंची दर के प्रतिफलन की मांग की गई। इन प्रकार किसानों पर अतिरिक्त भारी बोच पड़ा और इस कार्य के फायदे गरीब किसान तक नहीं पहुंच सके।

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन स्थानों का तर्ज से औद्योगिक विकास किया जाना है जहाँ पहले कोई उद्योग नहीं था। समाजवाद के अंतर्गत इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि भूतपूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रों को ग्रामीण भीतरी प्रदेशों के रूप में रखा जाए जबकि आधुनिक उद्योग को पहले की तरह विशेषाधिकार प्राप्त 'महानगरीय' क्षेत्रों की वस्तु बना दिया जाए। उल्टे पुराने पिछड़े इलाकों के विशेष औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज्यादा सन्नियता से कदम उठाए जाते हैं।

श्रांति से पहले तक ताजिकिस्तान में कोई भी उद्योग नहीं था। आज इस प्रदेश में कई कारखाने और सिल्क कारखाने हैं जिनका निर्माण पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुआ है। वारजोव्स्क विजलीघर के निर्माण का काम पूरा हो गया है और इससे शहर के औद्योगिक क्षेत्रों का विजली दी जाएगी। स्तालिनावाद में कपड़े का कारखाना पूरे जोर शोर से चल रहा है और यही स्थिति लेनिनावाद के बड़े सिल्क कारखाने की है। इस वर्ष एक विशाल कपड़ा मिल, मांस तैयार करने का कारखाना शराब बनाने की फैक्टरी और एक सीमेंट फैक्टरी के निर्माण का काम शुरू हुआ है। इतना ही नहीं दो कारखानों में काम शुरू हो गया है और इसके साथ ही तेल बनाने के दो कारखानों को पास साफ करने के दो कारखानों, छपाई के दो कारखानों इत्यादि में भी काम शुरू हो गया है। (यू० एस० एस० आर० ट्रेड डेलीगेशन इन ब्रिटन 'मथली रिव्यू,' अक्टूबर 1936 पृष्ठ 552)

श्रांति से पूर्व ताजिकिस्तान में आधुनिक सड़कें नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ताजिकिस्तान में 181 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई और 12 हजार किलोमीटर

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

Handwritten musical notation on staves.

१५ वि० १५  
 १५ वि० १५  
 १५ वि० १५  
 १५ वि० १५  
 १५ वि० १५

दा। जय  
 निर्मलिन  
 का कान  
 ग। जय  
 रहा है  
 इस व  
 मराव बन  
 जा है।  
 वर साव  
 ३

सड़कें बनाई गई। इनमें से 6 हजार किलोमीटर की मड़कें मोटर चल सक्ती है।

सावजनिक स्वास्थ्य की ही वान लीजिए। 1914 में ताजि  
1939 तक इनकी संख्या 440 हो गई। 1914 में वहां समू  
म केवल सौ मरीजों के रहने की व्यवस्था थी लेकिन 1939  
प्रबन्ध हो गया। 1914 में वहां के जच्चाखानों में एक भी  
था लेकिन 1937 में 240 मरीजों के रहने की व्यवस्था हो  
भी सहायता के लिए एक भी बेड नहीं था लेकिन 1937  
हो गई।

ममाजवाद के अतगत ताजिक जनता के अदर नए जीवन का  
की अभिव्यक्ति निम्न गीत म की गई है। यह गीत ताजिब स  
का है जिसे जोगाबा कनित्ज ने 'डान ओवर समरकंद' म उर

मेरी सास मुक्त और गम है

जब मैं देखता हूँ जुतती हमारी सूखी धरती,  
जब मैं देखता हूँ बनकर पूरा हुआ कोई बाध  
और जब मैं देखता हूँ उन्हें अपने साथ जा एक नई जग  
की काशिश में है,

मैं उल्लसित होता हू उस तरह जैसे एक पिता अपन बेटे  
 मैं रोक नहीं पाता खद को प्यार उठन से जियो !

सारे नए इसान',

जब मैं देखता हूँ अपने बट को खेत में चलता हुआ  
जब मैं देखता हूँ एक हल फाड़ता है माटी और गहरी  
में रोम नहीं पाता खद को प्रकार उठने में

‘विजय उनकी जा श्रमरत’

जब मुझे आशका दहलाती है 'पुराना सत्तार लौटगा'  
 मैं भूलुठित हो जाता हूँ, भय से वफ हो जाता हूँ।  
 मुझे बहक दो, वामरइ, मुझे कुछ गालियाँ दो  
 मैं युद्ध को जानूँगा, मैं अपनी भूमि बचाऊँगा



1927-28 में सोवियत गणराज्यों का प्रति व्यक्ति खर्च का वजट  
(रुबल में)

| मद                                    | रूसी<br>गणराज्य | यूक्रेन | श्वेत रूस | ट्रांस<br>कार्पेशिया | उजबेकिस्तान | तुर्कमेनिस्तान | औसत   |
|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------|
| गानन प्रबन्ध                          | 0.69            | 0.86    | 1.06      | 2.23                 | 1.60        | 2.45           | 1.02  |
| आर्थिक प्रशासनिक<br>विभाग             | 1.08            | 0.88    | 1.57      | 1.13                 | 1.04        | 1.46           | 1.06  |
| सामाजिक-सांस्कृतिक<br>आवश्यकताएँ      | 2.16            | 1.92    | 2.57      | 3.59                 | 2.48        | 3.84           | 2.20  |
| वित्त प्रबन्ध राष्ट्रीय<br>उपब्यवस्था | 1.65            | 1.62    | 2.37      | 4.95                 | 3.39        | 8.90           | 1.91  |
| स्थानीय वजट की स्थानांतरित            | 5.87            | 5.56    | 5.57      | 6.70                 | 5.77        | 5.58           | 5.83  |
| अन्य पैसे                             | 0.04            | —       | —         | 0.53                 | 0.20        | —              | 0.06  |
| कुल योग                               | 11.49           | 10.84   | 13.14     | 19.13                | 14.48       | 22.23          | 12.08 |

531000, माध्यमिक विद्यालयों में 130000 और आय सस्यानों में 710000 छात्र अध्य-  
यन कर रहे थे। सामूहिक कृषि फार्मों के तेजी से विकास के अतिरिक्त उद्योग के मामले  
में उत्पादन 1913 में 26 करोड़ 90 लाख रुबल से बढ़कर 1936 में 1 अरब 17 करोड़  
50 लाख रुबल हो गया और बिजली का उत्पादन 1928 में 3 करोड़ 40 लाख यूनिट से  
बढ़कर 1936 में 23 करोड़ यूनिट तक पहुँच गया। उद्योग के दायरे में 51 सूती धागे  
बनान की फैक्टरियाँ, कागज का खान, कृषि के काम में आने वाली मशीन बनाने का एक  
बड़ा कारखाना (ताशकंद में), एक सीमेंट फैक्टरी, गंधक की खान, एक आक्सीजन  
फैक्टरी, कागज का एक कारखाना, चमड़े का एक कारखाना और कपड़े सिलने के कई  
कारखाने शामिल हैं। 1914 और 1937 के बीच डाक्टरों की संख्या 128 से बढ़कर  
2185 हो गई। क्रांति से पहले इस देश के पास अपनी कोई वणमाला तक नहीं थी। लैंडिंग  
के दंग की एक नई वणमाला के द्वारा इस कठिनाई को हल कर लिया गया। 1935 तक  
इस गणराज्य में पाँच भाषाओं में 118 समाचारपत्र निचलते थे जिनकी वष भर में दस  
करोड़ से भी ज्यादा प्रतियाँ बिकती थी।

इस अत्यंत विशाल रूपांतरण के लिए आर्थिक साधन कैसे जुटाए गए? इस प्रश्न के जवाब  
से यह साफ पता चल जाता है कि पिछड़े लोगों के औपनिवेशिक शोषण की साम्राज्यवादी  
प्रणाली और समाजवाद के अतगत् समानता के आधार पर विभिन्न जातियों के बीच  
सहयोग की प्रणाली में कितना बड़ा फर्क है। साम्राज्यवादी शासन के अतगत् औपनिवे-  
शिक देशों की पिछड़ी हुई और गरीब जनता से हर साल बेशुमार नजराना वसूल किया  
जाता है जो साम्राज्यवादी देशों के शोषक वर्ग की जेब में जाता है। समाजवाद के अतगत्  
पिछड़ी हुई जातियों के तेजी से विकास में जो अतिरिक्त राशि खर्च होती है उसे सोवियत  
संघ के बजट में उनके लिए अनुपात से अधिक रकम रखकर पूरा किया जाता है। ताकि  
इस सत्रमण काल में इन पिछड़ी जातियों को प्रति वष जितना धन वे राज्य को देती हैं  
उससे अधिक धन मिले। (अपने ऊपर बज का कोई बोझ इकट्ठा किए बगैर वे यह राशि  
आराम से पाती हैं)। पृष्ठ 96 की तालिका से पता चलेगा कि 1927-28 में सोवियत संघ  
के अलग-अलग गणराज्यों में प्रति व्यक्ति अलग-अलग मदों में कितने रुबल खर्च करने की  
व्यवस्था है

इसमें यह दिखाई पड़ेगा कि सभी बुनियादी मदों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य, रूस और  
यूक्रेन, आय गणराज्यों के बाद के स्थान पर हैं। संघ पिछड़ी जातियों वाले राज्यों की  
सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का काम तेज करने की देखरेख अपने जिम्मे लेता है।

सोवियत संघ का 1939 का बजट भी यही तस्वीर सामने प्रस्तुत करता है। जहाँ समूचे  
सोवियत संघ तथा गणराज्यों के कुल बजट में पिछड़े वर्ग के मुकाबले में 12.4 प्रतिशत  
की वृद्धि हुई थी, वहाँ कजाकिस्तान के बजट में 20.1 प्रतिशत और तुर्कमेनिस्तान के बजट  
में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रूसी सोवियत गणराज्य का बजट जहाँ अपने क्षेत्रों

से प्राप्त राजस्व का 18.8 प्रतिशत था वहीं ताजिकिस्तान के बजट में यह राशि पूरी की पूरी 100 प्रतिशत निर्धारित की गई। 1928-29 से लेकर 1939 के पूरे दशक के दौरान समूचे सोवियत संघ का सामाजिक तथा सांस्कृतिक खर्चा 25 गुना हो गया था जबकि तुर्कमेनिस्तान का खर्च 29 गुना और कजाखिस्तान का 31 गुना हो गया। इसी तरह नए औद्योगिक निर्माण कार्यों के मामले में भी पिछड़े हुए इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस तरह कजाखिस्तान का कुल बजट 1 अरब 51 करोड़ 30 लाख रूबल था लेकिन कम से कम 50 करोड़ 90 लाख रूबल की राशि मध्य के क्षेत्रों से निर्धारित की गई ताकि इस क्षेत्र में तापे की ढलाई का विशाल बालघूम कारखाना बनाया जा सक। बरगंडा इस समय सोवियत संघ का तीसरा कोयला बेसिन है और तश्चिक्कंद और रिद्स्क का सीसे का कारखाना सोवियत संघ के सीसे के कुल उत्पादन के तीन चौथाई हिस्से की पूर्ति करता है।

इस प्रकार समाजवाद ने अतन्त्र बहुत जागरूक ढंग से उद्योग का नया वितरण संचालित किया जाता है। जैसाकि मिखाइलोव ने अपनी पुस्तक 'सोवियत ज्योग्राफी' में बताया है, पुराने जारशाही रूस में उद्योग-धंधे समूचे साम्राज्य के विशाल क्षेत्र में असमान ढंग से वितरित थे। रूस के उद्योग का आधा हिस्सा वर्तमान मास्का, लेनिनग्राद, इवानोव प्रान्त आदि में केंद्रित था। आर्थिक नक्शे पर यह क्षेत्र एक टापू की तरह दिखाई देता था। यही वह जगह थी जहां से औद्योगिक पूंजी का जन्म हुआ और उसका विकास हुआ। यही स जारशाही की विजय की किरणें फूटी और औद्योगिक केंद्र के काम आने वाले कृषि उत्पादन और कच्चे माल का भारी भंडार इकट्ठा किया गया। उत्पादन और कच्चे माल के बीच लंबी दूरी बनाकर दोनों को पृथक् कर दिया गया। सामाजिक धर्म की बरवादी हुई लेकिन उपनिवेशों ने इस खर्च को बर्दाश्त किया। 'कपास के उत्पादन' उजबेक को उचित मूल्य नहीं दिया जाता था और तैयार कपड़े के लिए भी बड़ी मामूली रकम दी जाती थी बरवाद हो गए दस्तकारों और शिल्पियों के हाथ बिजली से भी ज्यादा सस्ते थे।'

योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन ने सहकारी विकास और राष्ट्रीय समानता के आधार पर उद्योग के वितरण के नए सिद्धांत शुरू किए

योजनाबद्ध समाजवादी उत्पादन और वितरण ने केंद्र से प्रतिस्पर्धा को दूर रखा। पुराने निपेधात्मक कानूनों के स्थान पर राष्ट्रीय दूरस्थ जिला के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास की नीति विकसित हुई।

सोवियत संघ में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार हैं। कानूनी तौर पर सभी जातियों के बीच समानता की बात रूसी क्रांति के बिल्कुल प्रारम्भिक दिनों में दी गई थी लेकिन असमानता को वास्तविक रूप से समाप्त करने में तब यह जरूरी है कि रूस का पुराना उपनिवेशों की जनता के

वार्पिक निष्ठेन नो दूर ग्नि जाए। (एन० निवाहोव सोवियत  
ज्योब्राची' 1925 पृष्ठ 51)

इसलिए 1923 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की 12वीं कांग्रेस में स्तालिन ने रूस लिबरल की  
शोषण की थी

रूस के सर्वहारा वर्गों को मूलों और भाषा का विकास करने के अन्तर्गत सीमावर्ती  
जिलों में, साम्यविक दृष्टि से पिछड़े गणराज्यों में उद्योग के केंद्र स्थापित  
करने के हर उपाय जनमानस चाहिए। पिछड़े गणराज्य अपनी वित्तीय दायी की  
बचह में नहीं पिछड़े हुए हैं बल्कि उनकी हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि ५२  
से पहले उन्हें कच्चे मान का लोत मान समझा जाता था। (स्तालिन रिपोर्ट  
आन दि नेमान कवेसचन दू दि द्वेल्व्य कांग्रेस थाक दि रसियन कम्युनिस्ट  
पार्टी, अप्रैल 1923)

हम यहाँ साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शोषण और समाजवादी व्यवस्था के अतर्गत अलग  
अलग जानियों के बीच समानता की उपलब्धि के फल को देखा है। समाजवादी व्यवस्था  
में सर्वाधिक पिछड़े लोग कितनी तेजी के साथ सर्वाधिक उन्नत लोगों के स्तर तक पहुँचे  
हैं, यह गौर करने की बात है।

मध्य एशियाई सोवियत गणराज्या के समाज अधिकारों और तेज विकास का यह पित  
देखकर भारतीय जनता उद्विग्न हो उठती है। यह ऐसा पित है जिसे देखकर अधिकारों  
रूप से साम्राज्यवादी शासन के अधीन भारत के विनाश में आए उद्धार तथा शोषण के  
साथ समाजवादी देश की स्थिति की तुलना करने की दृष्टि हो उठती है। लेकिन साथ  
ही यह ऐसी भी तस्वीर है जो हमारे मन में आशा का उल्लास भरती है और दुर्ग विश्वास  
पैदा करती है कि भविष्य में साम्राज्यवाद के जुए को उतार फेंकने के लिए भारत की  
मेहनतकश जनता जब खुद अपने देश की माँगें मन जाएगी, तब भारत में भी इसी ही  
तेजी से प्रगति हो सकेगी।



खण्ड दो  
भारत मे ब्रिटिश राज







बाकी है। इस काम में इतना परिश्रम और लगभग इतने पैसे लगेंगे जो किसी एक व्यक्ति और साधारण निजी संपत्ति की पहुँच से बाहर है।

आयरलैंड की समस्या के बारे में लाड रोजवेरी का यह कथन कि 'इस समस्या ने क्या इतिहास के दायरे में प्रवेश नहीं किया क्योंकि यह सभी राजनीति के दायरे से बाहर जा ही नहीं सकी' भारत पर लागू होता है। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त किए जान के बाद ही, गंभीरतापूर्वक भारतीय इतिहास के अध्ययन का काम शुरू किए जान की गंभावना है। और यह अध्ययन विजेताओं के दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा।

अपने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व में, 19वीं सदी के इंग्लैंड के रूढ़िवाद के नेता ने इंग्लैंड के इतिहास के बारे में लिखा है।

यदि इंग्लैंड का इतिहास कभी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया जिसके पास जानकारी और साहस दोनों हों, और ऐसे काम के लिए य दोनों बातें समान रूप से जरूरी हैं, तो दुनिया के लोग नीबुर् (Niebuhr) का इतिवृत्त पढ़ते समय जितना विस्मित होते हैं उतने वही ज्यादा विस्मित इस इतिहास का पढ़कर होंगे। सामान्य तौर पर यह तो सभी महान घटनाएँ तोड़मरोड़ कर पेश की गई हैं अधिकांश महत्वपूर्ण कारणों को छिपाया गया है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ या कभी उल्लेख ही नहीं किया गया और जिनका उल्लेख किया भी गया उत इतना गलत समझा गया और इतने गलत रूप में पेश किया गया कि इसमें निश्चय। यात्रा तालिका पूरी तरह रहस्यमय रहा। (डिजरायली, 'सोबिल' (Sybil) अध्याय 3)

पूत्रीया के मुग म और घामगीर पर 'आनन्द ज्ञानि' के बाप से इन्स्ट के इतिहास का यह रहस्यमयकरण इस समय की महज एक शक्ति प्रस्तुत करता है कि मनीषिमीय धर्मिक तथ व 'गंगा की अमनियता का पौराणिक ज्ञान की आद म धर्मना मना है ।

महाराष्ट्र सरकार  
मुंबई

१३

[illegible]

ॐ नमो

३। १०३

५५ + ५५

समय तक उसकी रणनीति की बुनियादी बातों के करीब आत है।

इस क्षेत्र में आधिकारिक मनगढ़त कहानियों तथा पक्षमंडन की प्रवृत्ति खासतौर से स्पष्ट है। बुजुआ सभ्यता के असली रूप को उसकी पूरी नग्नता के साथ प्रकट करने वाले अत्यंत प्रारंभिक तथ्यों को इंग्लैंड की जनता की सामान्य चेतना तक पहुंचाने से पूरी ताकत के साथ रोका गया है और उसे छिपाया गया है, ये तथ्य महज आयरलैंड या भारत के लोग की ज्वलंत स्मृतियों में भर पड़े हैं। समाचारपत्रों या मंचों पर सामान्यतः गंभीर ऐतिहासिक विश्लेषण का स्थान स्कूली लड़के किपलिंग टाइप प्रेमकथाओं ने ले लिया है। यहाँ तक कि साम्राज्य के अधिग्रहण को, जो किसी राकफेलर के जीवन भर किए गए बाप जितनी ही कठोर अध्यवसायी संचयन प्रक्रिया थी, परंपरागत इतिहास में 'दिमाग की खल्ल हालत में घटित' एक 'दुष्टटना' कहा गया है। 'ब्रिटेन के शाही ताज में सबसे चमकीले रत्न' विषयक शब्दाडंबर भारतीय जनता की भयंकर और शर्मनाक स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने में रुकावट पैदा होती है। यह उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार किसी भी सरकार के लिए अभियोगपत्र है।

इंग्लैंड और भारत के संबंधों के इतिहास में यह मिथक शास्त्र जितना सुस्पष्ट है उतना और कहीं नहीं।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक युग में मिथक शास्त्र की यह प्रवृत्ति बढ़ी है। जहाँ वर्लिंगटन, बक, क्लाइव, हेस्टिंग्स या ऐडम स्मिथ जैसे लोगों ने नजराने की उगाही, उत्पीड़न और लूटपाट की सच्चाइयों के बारे में साफ साफ और बिना किसी लागलपट के बताया, जहाँ सालसवरी तक ने भारत के 'रक्तसाव' की बात कही, वही आज, जबकि सत्ता का आधार अब निरापद नहीं रह गया है, आधुनिक सरकारी उद्गार बमनकारी मधुरता से भरे मानवप्रेम का राग अलाप रहे हैं जिसके पीछे शोषण और मुव्य-वस्तित दमनकारी संगठन का वास्तविक आधार छिपा है।

बिलकुल हाल के, भारत के इतिहासकारों ने एक दिलचस्प मदभ टिप्पणी में, पिछले पचास वर्षों के दौरान स्पष्टवादिता में 'मौन सेंसरशिप' (जैसा उनका कथन है) में रूपांतरण पर उल्लेखनीय बात कही है

ब्रिटिश भारत के बारे में लिखे गए सामान्य इतिहासों में से एक सौ वर्ष या इससे पूर्व लिखे गए इतिहास पिछले पचास वर्षों में लिखे गए इतिहास की तुलना में, समभवतः बिना किसी अपवाद के, ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा सज्जादा बिना किसी लागलपट के और ज्यादा दिलचस्प है। उन दिनों में किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसा भी राजद्रोही हो सकता है जो सही अर्थों में मौनिक समस्याओं (मसलन भारत में आपके रहने का अधिकार क्या अधिकार है?)



सं हमारा सरोकार बस इतना ही है कि हम उन गतिशील शक्तियों को सामने लाए जा आज भी जिंदा है।

आधुनिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस गतिशील दृष्टिकोण के साथ भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने ही सबसे पहले समाज को मंचालित करने वाली उन शक्तियों पर वैज्ञानिक प्रणाली की तंत्र रोज़नी डानी जिनके कारण ब्रिटिश शासनवाले से पहले और बाद में भारत का विकास हुआ, उन्होंने ही सबसे पहले साफ साफ शब्दों में भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका और भविष्य के लिए इसके पुनरुद्धार के कारिगरी महत्व को समान रूप से समझाया। उन्होंने इस कार्य को, जो मानवता के भविष्य के लिए किए गए उनके कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है 19वीं सदी के मध्य में पूरा किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक उनका यह काम दबा पड़ा रहा और लगभग अज्ञात रहा हालांकि तब तक उनके कार्य का मुख्य क्षेत्रों के बारे में समूचे विश्व की जानकारी हो चुकी थी। अभी महज पिछले 25 वर्षों से उनके कथ्य की लोक-प्रियता व्यापक रूप से छात्रों में बढ़ने लगी है और भारत की समस्याओं से संबंधित वर्तमान चिंतन को तेजी से प्रभावित करने लगी है। आज इतिहास में भी आधुनिक अनुसंधान उनके दृष्टिकोण की मुख्य रूपरेखा की काफी पुष्टि कर रहा है।

## 1 भारत पर मार्क्स के विचार

तब वह वर्ष पूर्व इंग्लैंड के एक प्रमुख समाजवादी लेखक ने, तथापि यह विचार व्यक्त किया कि 'भारत की समस्या का मार्क्सवाद की घिसीपिटी स्थापनाओं के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास समाजवाद के विकास में गंभीर बौद्धिक योगदान नहीं है बल्कि एक दिमागी कसरत है।' (हराल्ड लास्की कम्युनिज्म, 1927, पृष्ठ 194)

मार्क्स ने अपने चिंतन तथा कार्य का एक उल्लेखनीय अंश निरंतर भारत का अध्ययन करने में लगाया था, इस बात की जानकारी का अभाव पश्चिमी यूरोप के समाजवादी चिंतन की सीमाओं का एक विशिष्ट उदाहरण है। दरअसल भारत के बारे में 1853 में धारावाहिक रूप से लिखे गए मार्क्स के प्रसिद्ध लेखों की गिनती उनके उन लेखों में की जाती है जो हर दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं और उनमें जिन मसलों को उठाया गया है उनके संबंध में आधुनिक चिंतन की शुरुआत ही इन लेखों से होती है। मार्क्स के लेखों का यदि पूरी तरह अध्ययन करें तो पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने एशियाई अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से भारत तथा चीन के नदों में) की घाम घाम बातों पर लगातार बहद ध्यान दिया है। किस तरह उन्होंने इनपर यूरोपीय पूँजीवाद के सघात के प्रभावों का अध्ययन किया और इस बात पर ध्यान दिया कि विश्व के भावी विकास के लिए तथा साथ ही भारतीय एवं चीनी जनता के उद्धार के लिए उसमें क्या नतीजे निकाले जा सकते हैं। उन्होंने भारत की समस्याओं के अध्ययन पर चितना ध्यान दिया या इसका उदाहरण 'पूँजी' में तब तक 50 बार भारत के उल्लेख से पता चल जाता है। मार्क्स और एंगल्स के बीच

को उठाए और जब जनता का मतलब ब्रिटिश जनता था, उस समय आलाचना जीवत और पूरा जानकारी पर आधारित होती थी और राजनीतिक अपेक्षाओं को ध्यान में लाए बिना फैसला दिया जाता था। अगर वे वर्षों में, सभी भारतीय मसलों पर काफी हद तक और निस्संदेह स्वाभाविक तौर पर प्रशासन के दृष्टिकोण से विचार करने की प्रवृत्ति पाई गई है 'क्या इससे सरकार का काम ज्यादा आसान और ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से होगा?' आज के लेखक का अनिवार्य रूप से अपने तालाब से बाहर भी एक सप्ताह है जहां लोग एकाग्रता से देख चुके हैं और जो उनके अपने लोगों के समान ही सवेदनशील हैं और आनंद ले रहे हैं म भी उतने ही फुर्तीले हैं। 'जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है।' किसी की बातें सुन लेने, यहां तक कि छिपकर सुनने वाली जनता, विश्वासभाजन न होने को यह ज्ञान निरंतर मौन सेंसरशिप का काम करता है जिससे ब्रिटिश भारतीय इतिहास वर्तमान विद्वता में निरुद्धतम ध्वजा बन गया है।' (ई० थामसन और जी० टी० गैरार्ड राज एंड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1934, पृष्ठ 665)

अपने वर्तमान उद्देश्यों के लिए हम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिवृत्त के किसी व्यक्ति को और उन रुढ़ तथ्यों का जिसका अध्ययन किसी भी वर्तमान स्तरीय पुस्तक में किया जा सकता है अनुसरण करने नहीं जा रहे हैं। इसके लाभप्रद विवेचन के लिए अलग से एक पुस्तक लिखने की जरूरत होगी। हमारा मतलब यहां महज विकास की कुछ निर्णायक शक्तियों को, जो वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याओं के मूल में हैं, प्रदर्शित करना है।

अतीत तो अतीत ही है। यदि ईमानदारी से कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास नानवधक इतिहास नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लैंड के लोगों को उस इतिहास के कुछ तथ्यों से अवगत होना चाहिए (जिन्हें विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों से प्राप्त अलग रखा गया है) ताकि वे अपने आपको साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से मुक्त कर सकें और साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीयों को उनसे अवगत होना चाहिए ताकि वे भारतीय आजादी के लिए अपने को दृढ़ प्रतिज्ञा सैनिक के रूप में लस कर सकें। लेकिन अतीत में जीने से या राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार काय का विगत दिनों के अभ्यास और शिकायतों तक केंद्रित रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अतीत के अत्याचारी और अत्याचार से पीड़ित लोग काफी पहले ही मर चुके हैं एक गवर्नर जनरल की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार यदि भारतीय बुनकरों की हड्डियां से 1834 में भारत के मैदान सफे हो गए थे तो आज गवर्नर जनरल की हड्डियां भी अपने खानदानी मकबरे में किसी बेहतर स्थिति में नहीं हैं। आज का ज्वलंत प्रश्न है मौजूदा उत्पीड़न और मुक्ति का मार्ग। अतीत

सँ हमारा सरोकार बस इतना ही है कि हम उन गतिशील शक्तियाँ का सामन लाए जा आज भी जिंदा है।

बाधुनिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस गतिशील दृष्टिकोण के साथ भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने ही सबसे पहले समाज की संचालित करने वाली उन शक्तियों पर वैज्ञानिक प्रणाली की तज राशनी डाली, जिनके कारण ब्रिटिश शासनकाल में पहले और बाद में भाग्य का विकास हुआ, उन्होंने ही सबसे पहले साफ साफ शब्दों में भाग्य में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका और भविष्य के लिए इसके पुनर्धारक प्रातिकारी महत्व को समान रूप से समझाया। उन्होंने इस बात का, जो मानवता के भविष्य के लिए किए गए उनमें कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, 19वीं सदी के मध्य में पूरा किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक उनका यह काम दबा पड़ा रहा और लगभग अज्ञात रहा हालाँकि तब तक उनके बातों के मुख्य क्षेत्रों का वार में ममूँचे विश्व का जानकारी हो चुकी थी। अभी महज पिछले 25 वर्षों से उनके कथ्य की नौक-प्रियता व्यापक रूप से छात्रों में बढ़ने लगी है और भारत की समस्याओं से संबंधित बात मान चिंतन को तजी से प्रभावित करने लगी है। आज इतिहास सन्धी आधुनिक अनु-संधान उनके दृष्टिकोण की मुख्य रूपरेखा की काफी पुष्टि कर रहा है।

## 1 भारत पर मार्क्स के विचार

तरह वष पूर्व इंग्लैंड के एक प्रमुख समाजवादी लेखक ने तथापि, यह विचार व्यक्त किया कि 'भारत की समस्या का मार्क्सवाद की फिसीपिटी स्थापनाओं के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास समाजवाद के विकास में गभीर बौद्धिक योगदान नहीं है बल्कि एक दिमागी कसरत है।' (हराल्ड लास्की कम्युनिज्म, 1927, पृष्ठ 194)

मार्क्स ने अपने चिंतन तथा बातों का एक उल्लेखनीय अंश निरंतर भारत का अध्ययन करने में लगाया था, इस बात की जानकारी का अभाव पश्चिमी यूरोप के समाजवादी चिंतन की सीमाओं का एक विशिष्ट उदाहरण है। दरअसल भारत के बारे में 1853 में धारावाहिक रूप से लिखे गए मार्क्स के प्रसिद्ध लेखों की गिनती उनके उन लेखों में की जाती है जो हर दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं और उनमें जिन मसलों को उठाया गया है उनके संबंध में आधुनिक चिंतन की गुरुआत ही इन लेखों से होती है। मार्क्स के लेखों का यदि पूरी तरह अध्ययन करें तो पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने एशियाई अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से भारत तथा चीन के मदभ में) की धाम धाम बाता पर लगातार बेहद ध्यान दिया है। किन्तु तरह उन्होंने इनपर यूरोपीय पूँजीवाद के सघात के प्रभावों का अध्ययन किया और इस बात पर ध्यान दिया कि विश्व के भावी विकास के लिए तथा साथ ही भारतीय एक चीनी जनता के उद्धार के लिए उसमें क्या नतीजे निकाल जा सकते हैं। उन्होंने भारत की समस्याओं के अध्ययन पर कितना ध्यान दिया था इसका उदाहरण 'पूँजी' में तमरीबन 50 बार भारत के उल्लेख से पता चल जाता है। मार्क्स और एंगेल्स के बीच

पत्र व्यवहार में ता दास भी अधिक् बार भारत की चर्चा हुई है।

कम्युनिस्ट घापणापत्र (जिम्मे मानग और एगल्स) इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि पूँजीवादी उत्पादन व वित्तन के लिए भारतीय और चीनी बाजारों के खुल जाने का वित्तन महत्व है) जारी करने का तथा 1848 की नातिकारी लहर व दब जान के फौरन बाद माक्स ने अपना सारा ध्यान दावी हार के बुनियादी कारणों की तलाश में लगा दिया। उन्होंने पाया कि इसका सबसे बड़ा कारण पूँजीवाद का यूरोप से बाहर एशिया, आस्ट्रेलिया और कैलीफोर्निया में फैल जाना था। इस चिन्तन धारा की ओर भी तीव्र अभिव्यक्ति 1858 का एक पत्र में हुई है जिसका उल्लेख 1852 में ही एंगेल्स का नाम लिखे गए एक पत्र में किया गया है

हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि बुर्जुआ समाज एक बार फिर सोलहवीं सदी में रह रहा है। मुझे आशा है कि जिस प्रकार पहली सोलहवीं सदी में पूँजीवाद का जन्म दिया, उसी प्रकार यह दूसरी सोलहवीं शताब्दी उसकी वजह खोदेगी। बुर्जुआ समाज का विशेष काम अपनी मुख्य रूपरेखा में किसी भी कीमत पर विश्व बाजार की स्थापना करना और इस आधार पर उत्पादन को संगठित करना है। चूंकि दुनिया गोल है इसलिए कैलीफोर्निया और आस्ट्रेलिया के उपनिवेश बन जान तथा चीन और जापान में बाजार कायम हो जाने से यह प्रक्रिया पूरी हो गई लगती है। अब हमारे सामने गंभीर सवाल यह है यूरॉप में नाति हान हो वाली है और शुरू से ही उसका स्वरूप समाजवादी होगा। लेकिन चूंकि दुनिया के बड़ी बड़े भाग में अब भी बुर्जुआ समाज की गतिविधियों का प्रभुत्व है इसलिए क्या इस छोटे से हिस्से में अनिवार्य रूप से नाति कुचल नहीं दी जाएगी? (माक्स का पत्र एंगेल्स के नाम, 8 अक्टूबर 1858)

माक्स ने 19वीं सदी के छठे दशक में ही यह समझ लिया था कि पूँजीवाद के विकास के लिए तथा यूरोप में समाजवादी नाति के लिए यूरोप के बाहर पूँजीवाद के प्रसार का क्या महत्व है लेकिन यूरोपीय समाजवाद के प्रमुख लोग ने अभी हान के वर्षों में इसे धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया है।

1852 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारपत्र अंतिम बार नवीनीकरण के लिए संसद में पेश किया गया, माक्स ने 'यूनाक डेली ट्रिब्यून' के लिए भारत के बारे में लगातार आठ लेख लिखे। इन लेखों को, पूँजी में उल्लिखित प्रसंगा का और एंगेल्स के साथ पत्राचार में आए सदस्यों को देखने से भारत के बारे में माक्स के चिन्तन के सार तत्व का पता चलता है।

## 2 भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना

माकम का विश्लेषण 'एशियाई अर्थव्यवस्था' की विशेषताओं से शुरू होता है जिसको सबसे पहले पूंजीवाद के सघात ने मरामत किया था। जून 1853 में एंगेल्स ने माकम को लिखा कि, 'समस्त पूरव की समझने की कुंजी यह है कि वहाँ जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है।' लेकिन जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का न होना यूरोपीय अर्थव्यवस्था के आदिम प्रारम्भिक स्वरूप से मूलतः भिन्न नहीं है, यह भिन्नता बाद के विकास से पैदा हुई।

इधर लोगों के बीच एक बेतुकी धारणा फैली है कि अपने आदिम स्वरूप में सामूहिक संपत्ति स्लाव लोगों या वहाँ तक कि केवल रूसिया की ही विशिष्टता है। यह आदिम स्वरूप रोमन, ट्यूटन और कैल्ट लोगों में था जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं और इसके अनेक उदाहरण भारत में आज भी मिल सकते हैं हालाँकि अब वे अशत वरवाद हो चुके हैं।

सामूहिक स्वामित्व के एशियाई और खासतौर से भारतीय स्वरूपों का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि किस प्रकार आदिम साम्यवाद के विभिन्न रूपों से इसके विघटन के विभिन्न रूप विकसित हुए। इस प्रकार मिसाल के तौर पर हम पाएँगे कि रोमन और ट्यूटन में निजी संपत्ति के जो विविध बुनियादी स्वरूप थे, उनका सबंध भारतीय साम्यवाद के विभिन्न रूपों से है। (माकम दि क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनामी, अध्याय 1)

फिर क्यों नहीं पूरव में भी, पश्चिम की ही तरह आदिम साम्यवाद से भूमिसंपत्ति और सामत-वाद का विकास हुआ? एंगेल्स का कहना है कि इसका उत्तर हमें वहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में मिलता है

यह कैसे हुआ कि पूरव के लोग भूमिसंपत्ति और सामतवाद की अवस्था तक नहीं पहुँचे? मेरे विचार से इसका मुख्य कारण वहाँ की जलवायु है जिसके साथ वहाँ की खास तरह की मिट्टी की स्थितियाँ जुड़ी हैं। इस सिलसिले में विशेष रूप से, वे बड़े रेगिस्तानी इलाके भी काफी महत्वपूर्ण हैं जो सहारा से लेकर अरब, ईरान, भारत और तातार प्रदेश से होते हुए एशिया के सबसे ऊँचे पठारों तक फैले हुए हैं। यहाँ खेती की पहली शत सिंचाई के प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम साधनों का होना है और यह काम या तो कम्यूनो के जिम्मे या प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकार के जिम्मे होता है। (एंगेल्स का पत्र माकम के नाम 6 जून 1853)

खेती की परिस्थितियाँ, भूमि पर निजी स्वामित्व कायम करने के अनुकूल नहीं थी। इसी





से पानी बांटता है, ब्राह्मण धार्मिक कृत्यों का संचालन कराता है, अध्यापक बच्चों को बालू में लिपना-पढ़ना सिखाता है ज्योतिषी गांव के लोगों को बुवाई और बटाई के लिए तथा कृषि मजदूरी के कार्यों के लिए शुभ दिन की जानकारी देता है लोहार खेतों के औजार बनाता है और उनकी मरम्मत करते हैं, कुम्हार गांव के सभी लोगों के लिए बरतन बनाता है। इसके अलावा गांव में एक नाई, कपड़े साफ करने के लिए धोबी, एक सुनार भी होता है। वही वही किसी किसी समुदाय में कुम्हार सुनार का भी काम करता है और वही पाठशाला के अध्यापक का भी। इन दजन भर लोगों का घब गांव के लोग चलाते हैं। यदि आबादी बनी तो पुराने ढाँचे के आधार पर, खाली जमीन पर एक नया समुदाय स्थापित हो जाता है।

इन आत्मनिर्भर समूहों में उत्पादन का बहुत सरल संगठन है। इन समुदायों से निरंतर एक ही तरह के समुदायों का निर्माण होता रहता है और यदि कोई समुदाय दुर्घटनावश नष्ट हो जाता है तो उसी स्थान पर उसी नाम से वंश ही दूसरा समुदाय जन्म ले लेता है। इन समुदायों में उत्पादन की सरलता ही वह मुख्य बात है जिसके कारण एशियाई समाजों में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता। इस अपरिवर्तनशीलता के एकदम विपरीत एशियाई राज्यों का लगातार विघटन और निर्माण होता रहता है तथा राजवंशों में परिवर्तन का सिलसिला जारी रहता है। राजनीतिक स्थिति पर घुमडते तूफानी वादों से समाज के आर्थिक तत्वों का ढाँचा अछूता रह जाता है। (माक्स 'पूजी', खंड 1, अध्याय 15, अनुभाग 4)

यही वह परंपरागत भारतीय अवस्था थी जिसकी बुनियाद को विदेशी पूँजीवाद के प्रतिनिधि ब्रिटिश शासन ने छिन भिन्न कर दिया। अंगरेजों से पहले जिन शक्तियों ने भारत पर विजय हासिल की थी उनमें और अंगरेजों में यही फर्क था कि पहले के विदेशी विजेताओं ने जहाँ भारत के आर्थिक आधार को ज्यों का त्यों रहने दिया और अंत में उसमें घुलमिल गए वहाँ ब्रिटिश विजेताओं ने उस आधार को छिन भिन्न कर दिया और वे ऐसी विदेशी शक्ति के रूप में बने रहे जिसमें सत्ता का संचालन बाहर से होता था और भारत से नजराने की वसूली करके बाहर भेजा जाता था। भारत में विदेशी पूँजीवाद की विजय और यूरोप में पूँजीवाद की विजय के बीच भी यह अंतर है कि यहाँ ध्वस्त-त्मक प्रक्रिया के साथ-साथ उसी के अनुरूप नई शक्तियों का विकास नहीं हुआ। भारत की जनता ने महसूस किया है कि 'उसकी पुरानी दुनिया तो उजड़ चुकी थी पर नई दुनिया का कहीं पता नहीं था और इसलिए ब्रिटिश शासन के अजीब भारतीय जनता के दुख-दद के साथ एक 'खास तरह का विवाद' जुड़ गया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हिंदुस्तान पर जब तक पड़ी तमाम विपत्तियों का

कारण यहाँ खास तरह की 'एशियाई अव्यवस्था' का जन्म हुआ जो नीचे गाँव के स्तर पर तो आदिम साम्यवाद के अवशेषों को अपन साथ लिए हुए थी और ऊपर केंद्रीय शासन की निरकुशता थी जिसका काम युद्ध और लूटपाट के साथ साथ सिंचाई और सावजनिक निर्माण के कार्यों का प्रबंध करना था।

इसलिए भारत को समझने के लिए वहाँ की ग्राम व्यवस्था को समझना जरूरी है। ग्राम व्यवस्था का उत्कृष्ट वर्णन माक्स ने 'पूजी' में किया है

वे छोटे और अत्यंत प्राचीन भारतीय समुदाय, जिनमें से कुछ तो आज तक चले आ रहे हैं जमीन की सामूहिक मिलवियत कृषि और दस्तकारी के मेल, और एक अपरिवर्तनीय श्रम विभाजन पर आधारित है जो किसी नए समूह की शुरुआत होने पर बनी-बनाई योजना के रूप में काम आता है। सौ से लेकर कई हजार एकड़ तक में फैले ये समूह अपने आप में ठोस और पूर्ण होते हैं तथा अपनी ज़रूरत की सभी चीजों का उत्पादन कर लेते हैं। इन्हें द्वारा तैयार किए गए सामानों का मुख्य भाग समुदाय के सीधे इस्तमाल के काम आता है और बाजार में बेचे जाने वाले माल का रूप नहीं लेता। इसलिए भारतीय समाज में, कुल मिलाकर, यहाँ उत्पादन माल के विनिमय से पैदा श्रम विभाजन से स्वतंत्र है। उत्पादन का केवल वह हिस्सा जो उपभोग से बच रहता है, बाजार में बिकने के लिए जाता है और वह अतिरिक्त हिस्सा भी तब तक बाजार में बिकने नहीं जाता जब तक कि उसका एक अंश राज्य के हाथों में नहीं पहुँच जाता। सदियों से उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा लगान के रूप में, जो जिनस की शक्ल में होता है, राज्य को दे दिया जाता है।

भारत के अलग अलग हिस्सा में इन प्राचीन समुदायों के विधान भी अलग अलग हैं। इनमें से जो सबसे भरल विधान है उसके अंतर्गत सभी लोग मिलकर खेत जोतते हैं और उसमें पैदा फसल को आपस में बाँट लेते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार में कताई और बुनाई का काम सहायक उद्योग के रूप में होता है। इस प्रकार एक तरफ एक ही तरह के काम में लगे लोग होते हैं और दूसरी तरफ गाँव का 'मुखिया' होता है जो जज, पुलिस और टैक्स बसूल करने वाले का काम एक साथ करता है एक पटवारी होता है जो खेती-बाड़ी का हिसाब रक्खा है और इसमें मगधित सभी बातें अपने पास दर्ज करता रहता है एक और अधिकारी हाता है जो अपराधियों का दंड देता है, गाँव से गुजरने वाले अजनबियों की रक्षा करता है तथा उन्हें दूसरे गाँव तक सुरक्षित ढंग में छोड़ आता है। पटरंगार पटोम के गाँवों में गाँव की रक्षा करता है। एक दूसरा अधिकारी सिंचाई के लिए सावजनिक तालाबों

इन आत्मनिभर समूहों में उत्पादन का बहुत सरल संगठन है। इन समुदायों से निरंतर एक ही तरह के समुदायों का निर्माण होता रहता है और यदि कोई समुदाय दुष्टनावश नष्ट हो जाता है तो उसी स्थान पर उसी नाम से वैसा ही दूसरा समुदाय जन्म ले लेता है। इन समुदायों में उत्पादन की सरलता ही वह मुख्य बात है जिसके कारण एशियाई समाजों में सभी कोई परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता। इस अपरिवर्तनशीलता के एकदम विपरीत एशियाई राज्यों को लगातार विघटन और निर्माण होता रहता है तथा राजवंशों में परिवर्तन का सिलसिला जारी रहता है। राजनीतिक क्षितिज पर घुमड़ते तुफानी वादों से समाज के आर्थिक तत्त्वों का ढाँचा अछूता रह जाता है। (माक्स पूजा, पृष्ठ 1 अध्याय 15, अनुभाग 4)

यही वह परंपरागत भारतीय अव्यवस्था थी जिसकी बुनियाद को विदेशी पूजावाद के प्रतिनिधि ब्रिटिश शासन ने छिन भिन कर दिया। अगर जो स पहल जिन शक्तिया ने भारत पर विजय हासिल की थी, उनमें और अगर जो स पहल जिन शक्तिया ने विजेताओं ने जहां भारत के आर्थिक आधार को ज्यादा बर्बाद कर दिया और अतः उसमें घुलमिल गए वहां ब्रिटिश विजेताओं ने उस आधार का छिन-भिन्न कर दिया और व ऐसी विदेशी शक्ति के रूप में बने रहें जिसमें सत्ता का संचालन बाहर से होता था और भारत से नजराने की बसूली करके बाहर भेजा जाता था। भारत में विदेशी पूजावाद की विजय और यूरोप में पूजावाद की विजय के बीच भी यह अंतर है कि यहां ध्वस्त-तमक प्रक्रिया के साथ-साथ उन्नी के अनुरूप नई शक्तिया का विकास नहीं हुआ। भारत की जनता ने महसूस किया है कि उसकी पुरानी दुनिया तो उजड़ चुकी थी पर नई दुनिया का वही पता नहीं था और इसलिए ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय जनता के दुख-दुःख के साथ एक 'घास तरह का विषाद' जुड़ गया।

इसम बाई गन्ध ही मि यह हिंदुस्तान पर अब तक पड़ी तमाम विपत्तियां स

दुनियादी तौर पर यह भिन्न और ज्यादा गंभीर है। मेरा इशारा यूरोप की उस तानाशाही की तरफ नहीं है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एशियाई तानाशाही पर डाल दी गई और दोनों के मेल से ऐसा विकराल रूप निर्मित हुआ जो सालसेट के मदिरों की भयावह दैवी पिशाच मूर्तियों से भी ज्यादा विस्मित करने वाला था।

हिंदुस्तान में कितनी ही बार गृहयुद्ध छिड़े, विदेशी आक्रमण हुए, क्रांतियां हुई, विदेशियों ने बार बार देश को जीता-अकाल पड़े लेकिन ये घटनाएँ भले ही सतही तौर पर आश्चर्यजनक रूप से जटिल लगें और बड़ी तेजी से घटित होने वाली तथा विनाशकारी लगें लेकिन वे सतह से ज्यादा नीचे तक प्रभावित नहीं कर पाती थीं। इंग्लैंड ने भारतीय समाज के समूचे ढाँचे को तोड़ दिया है और उसके पुनर्निर्माण के अभी तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का इस तरह उजड़ जाना और नई दुनिया का वही पता न चलना, हिंदुस्तानियों के वर्तमान दुःख-दद के साथ एक खास तरह का विपाद जोड़ देता है और ब्रिटिश शासित हिंदुस्तान को उसकी समस्त प्राचीन परंपराओं तथा उसके संपूर्ण विगत इतिहास से काट देता है। (माकम दि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 'यूयाक डेली' ट्रिब्यून, 25 जून 1853)

### 3 भारत में ब्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका

माकम ने बड़ी सावधानी और मनोयोग के साथ इस बात का अध्ययन किया था कि ब्रिटिश शासन की यह विनाशकारी भूमिका किस प्रकार पूरी हुई। इसके लिए उन्होंने 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के प्रारंभिक काल तथा 1813 के बाद की अवधि के बीच के अंतर को जिसमें यह इजारेदारी समाप्त हो गई और औद्योगिक पूंजीवादी माल ने भारत पर धावा बोलकर अपना काम पूरा कर लिया, बड़े साफ तौर पर स्पष्ट किया है।

शुरू की अवधि में विनाश के प्रारंभिक कदम इस प्रकार उठाए गए—महले तो कंपनी ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को लूटा। ('18वीं सदी के दौरान जो धन-दौलत भारत से इंग्लैंड भेजी गई वह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यापार वाणिज्य के जरिए नहीं भेजी गई थी। वह भारत के सीधे शोषण के जरिए और बेतहाशा लूट-खसोट के जरिए इंग्लैंड भेजी गई थी।') दूसरे, कंपनी ने सिंचाई और सावजनिक निर्माण कार्यों की उपेक्षा शुरू की। पहल की सरकारें इन बातों की ओर पूरा ध्यान देती थी और उन्हें उपेक्षित नहीं रहने देती थीं तीसरे, कंपनी ने जमींदारी की अगरेजी प्रथा, जमीन पर निजी मिलकियत, तथा जमीन को बेचने और हस्तांतरित करने की प्रणाली शुरू कर दी और इंग्लैंड का समूचा फीजदारी मानून यहाँ लागू कर दिया, चौथे, भारतीय माल पर गोलियों लगाकर या उससे

आयात पर भारी चुगो लगाकर पहले इंग्लैंड में और फिर यूरोप में उन्हें जाने से रोक दिया गया।

फिर भी इन बातों से 'भरणातक चोट' नहीं पहुँची। यह चोट 19वीं सदी के पूँजीवाद के युग में पड़ी।

ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारेदारी का घनिष्ठ संबंध इंग्लैंड के कुलीन तंत्र (धनिक वर्ग) के साथ था जिसने ब्रिह्म क्रांति के साथ अंतिम तौर पर अपनी सत्ता कायम कर ली

सही अर्थों में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत अधिक से अधिक 1702 ई० से मानी जानी चाहिए। इसी वर्ष विभिन्न समितियाँ, जो ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार के एकाधिकार का दावा करती थीं, एक साथ मिल गईं और उन्होंने एक कंपनी का गठन किया। उस समय तक असली ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही कई बार खतरे में पड़ चुका था—एक बार क्रामवेल के सरक्षित राज्य में उसे कई वर्षों के लिए काय करने से वंचित कर दिया गया था और एक बार विलियम-3 के शासनकाल में संसद के हस्तक्षेप से उसके विलकुल समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया था।

संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को उस डच राजा के आधिपत्य के समय स्वीकार किया जब ब्रिह्म दलवाले ब्रिटिश साम्राज्य को राजस्व देने वाले किसान बन चुके थे, बैंक आफ इंग्लैंड का जन्म हो चुका था इंग्लैंड में देशी उद्योगों की रक्षा की प्रणाली बाकायदा शुरू हो चुकी थी और यूरोप में निश्चित रूप से शक्ति संतुलन स्थापित हो चुका था। ऊपरी तौर से दिखाई पड़ने वाली स्वतंत्रता का वह युग ही, दरअसल उन एकाधिकारों का युग था जिसकी स्थापना एलिजाबेथ और चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में शाही अधिकारपत्रों द्वारा नहीं होती थी, बल्कि जिनको संसद की स्वीकृति से अधिकार दिया गया था और जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

(माकम 'दि ईस्ट इंडिया कंपनी, इट्स हिस्ट्री ऐंड आउटवर्म' न्यूयाक डेली ट्रिब्यून 11 जुलाई 1853)

इस इजारेदारी के खिलाफ इंग्लैंड के औद्योगिक माल निर्माताओं ने लगातार आंदोलन किया। उन्होंने भारतीय माल को भारत में न आने देने की माँग की और उन्हें अपने इस प्रयास में सफलता भी मिल गई। इसके अलावा इंग्लैंड के उन व्यापारियों ने भी विरोध किया जो भारतीय माल के लाभप्रद व्यापार से बहिष्कृत हो गए थे। इसी संघर्ष का परिणाम था कि इंडिया बिल के संवाल पर 1783 में फाक्स की सरकार का पतन हुआ। इस बिल का उद्देश्य कंपनी के निदेशकों और मानिकों के अधिकारों (बाद में आफ

डायरेक्टिंग ऐंड प्रोप्राइटींग) को ममान्त कर देना था। इसी मस्ये के फलस्वरूप 1786 से लेकर 1795 तक हॉस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग के मामले का नेवर लयी लड़ाई चली। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पूरी हान और उमरे द्वारा इंग्लैंड के कारखानेदार पूँजीवाद को सामने लाने के बाद ही 1813 में कंपनी की इजारेदारी टूट गयी और टूटने की यह प्रक्रिया 1833 तक पूरी हो गई।

भारत का आर्थिक ढांचा भी 1813 के बाद ही निश्चित तौर पर उस समय टूटा जब इंग्लैंड के औद्योगिक सामानों ने भारतीय बाजार पर धावा बोल दिया। भारत के आर्थिक ढांचे के टूटने का प्रभाव 19वीं सदी के पूर्वार्ध पर क्या पड़ा इसका विवरण माफ़ न ठोस तथ्यों के साथ पेश किया है। 1780 से 1850 के बीच भारत में ब्रिटन से जो माल आया उसकी कीमत 386 152 पौंड में बढ़कर 8,024 000 पौंड हो गई अर्थात् ब्रिटन द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए गए कुल माल का 32वां भाग पहले भारत आता था, पर अब कुल निर्यात का आठवां हिस्सा भारत पहुँचने लगा। 1850 में ब्रिटन के सूती कपड़ा उद्योग का जो माल विदेशों को निर्यात किया जाता था, उसका चौथाई हिस्सा अबले भारत पहुँचता था। उस समय ब्रिटेन की आबादी का आठवां हिस्सा इस उद्योग में लगा हुआ था और इस उद्योग से ब्रिटेन की कुल राष्ट्रीय आय को बारहवां हिस्सा मिलता था

1818 से 1836 के बीच ग्रेट ब्रिटेन से भारत को धागे का जो निर्यात किया गया उसकी वृद्धि का अनुपात 1 और 5,200 का था। 1824 में ब्रिटन ने भारत को मुश्किल से 6,000,000 गज मलमल भेजा था पर 1837 में इसने 64 000,000 गज से भी अधिक मलमल का निर्यात किया। लेकिन इसके साथ ही ढाँचा की आबादी 150 000 से घटकर 20 000 हो गई। इसका सबसे बुरा परिणाम उन नगरों का पतन था जो अपने कपड़ों के लिए सुविख्यात थे। ब्रिटिश भाषा और विज्ञान में समूचे हिंदुस्तान में कृषि उद्योग और कारखाना उद्योग की एकता को जड़ से उखाड़ फेंका।  
(माक्स 'दि ब्रिटिश रूल इन इंडिया,' 'यूयाक' डेली ट्रिब्यून 10 जून 1853)

सूती कपड़ों के निर्माण के लिए ब्रिटेन ने जो प्रणाली संगठित की उसका भारत पर बहुत गंभीर असर पड़ा। 1834-35 में गवर्नर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 'इनका दुख-दद व्यापार के समूचे इतिहास में अनुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की अस्थियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है।' (माक्स 'पूँजी,' खंड 1, अध्याय 15, अनुभाग 5)

ग्राम व्यवस्था का निर्माण 'कृषि और उद्योग संबंधी व्यवसाय की घरेलू एकता' पर आधारित था। 'करघा और चर्खा पुराने भारतीय समाज की धुरी थे' लेकिन 'अंगरेज घुसपैठियों ने भारत के करघे का ताड़ डाला और चर्खे को नष्ट कर दिया।' इस प्रकार ब्रिटेन ने एक

महानतम और यदि सच सच कहे तो ऐसी सामाजिक क्रांति कर डाली जैसी एशिया में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इस क्रांति ने न केवल पुराने औद्योगिक नगरों को नष्ट कर डाला और उन नगरों में रहने वाले लोगों को गावों में खदेड़ दिया बल्कि गावों के आर्थिक जीवन का मतुलन भी बिगाड़ दिया। यही से खेती पर भीषण दबाव शुरू हुआ जो आज तक निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अत्यंत बेरहमी के साथ किसानों से अधिक से अधिक कर वसूला गया और बढ़ते में उनकी खेती में आवश्यक विस्तार के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास रुक गया। (1850-51 में लगान के रूप में वसूले गए 19,300,000 पौंड में से 166,390 पौंड या कुल राशि का मात्र 0.8 प्रतिशत किसी तरह के सावर्जनिक निमाण पर व्यय किया गया।)

इस लगान के थम की स्थितियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले आयाम हो सकते हैं। यह उत्पादन के विस्तार को कमोवेश असंभव बना सकती है और प्रत्यक्षतः उत्पादन में लगे लोगों को रोटो कपडा चलाने के यूनतम भौतिक साधना तक घसीट कर ला सकती है। यह खासतौर से उस स्थिति में होता है जब इस रूप का परिचय तथा शोषण किसी विजयी औद्योगिक देश द्वारा होता है, जैसा भारत के साथ इंग्लैंड कर रहा है। (माक्स 'पूजी', खंड 3, अध्याय XIVII, अनुभाग 3)

भारत से ब्रिटेन द्वारा जबरन वसूले गए 'नजराने' का अनुमान माक्स ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है

भारत को अच्छी सरकार' के लिए नजराने के रूप में, तथा ब्रिटिश पूँजी पर ब्याज और लाभांश आदि के रूप में 50 लाख पौंड देना है। इसमें वह राशि नहीं जोड़ी गई है जो ब्रिटिश अधिकारी प्रतिवर्ष अपने वेतन में से बचाकर घर भेजते हैं या अंगरेज सौदागर मुनाफे के नाम पर घर भेजते हैं ताकि उसे इंग्लैंड में व्यवसाय में लगाया जा सके। (माक्स 'पूजी', खंड 3, अध्याय 35, अनुभाग 4)

क्या माक्स भारत की ग्रामीण व्यवस्था के पतन और भारतीय समाज के पुराने आधार के ध्वंस पर आसू बहाते हैं? माक्स ने हर देश की तरह यहाँ भी हुई बुर्जुआ सामाजिक क्रांति के फलस्वरूप जनता की असीम यत्नशक्ति को देखा। जनता का कष्ट भारत में और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला क्योंकि यहाँ जो बुर्जुआ सामाजिक क्रांति हुई वह ऊपर बताई गई परिस्थितियों के तहत हुई। लेकिन उन्होंने उस ग्राम व्यवस्था के वेहद प्रतिक्रियावादी चरित्र को भी देखा और मानव जाति की प्रगति के लिए उस व्यवस्था के ध्वंस की अपरिहार्य आवश्यकता को भी महसूस किया। माक्स ने उन 'रमणीय ग्राम समुदायों' में मानवीयता के अन्वेषण का उडे जोरदार शब्दों में वर्णन किया है। माक्स के शब्द आज भी



उन लोगों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो लोग यूरोप की तरह भारत में भी आगे की वजाय पीछे की ओर निगाह धुमाए रहते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सघष का तरीका यह मानते हैं कि चर्खा और करघावाले उस भारत को फिर जीवित किया जाए जो अंगरेजों के आने से पहले था।

उन लाखों करोड़ों उद्यमी, पितृसत्तात्मक एवं निरीह सामाजिक सगठनों की इकाइयों का बिखरना और नष्ट हो जाना, दुख के सागर में उनका फँक दिया जाना तथा उनके अलग अलग सदस्यों का अपनी प्राचीन सम्यता और जीवन निर्वाह के अपने पशतानी साधनों से हाथ धो बैठना किसी भी मनुष्य की भावनाओं को खण बना सकता है जो लाजिमी भी है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर से निरीह दिखाई देने वाले इन रमणीक ग्राम समुदायों ने, सदा से ही पूव की गिरकुश तानाशाही के लिए ठोस आधार का काम किया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मानव मस्तिष्क को उसकी संपूर्ण गरिमा और ऐतिहासिक शक्तियों से वंचित करके अत्यंत सकीण दायरों में कैद रखा, उसे अधविश्वास का आसान साधन और पुरानी रीति रिवाजों का गुलाम बना रखा।

हमें उस बबर स्वाथपरता को नहीं भूलना चाहिए जो जमीन के एक मामूली से टुकड़े पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए अनेक साम्राज्यों के विनाश को और अव्यवस्थित अत्याचारों के अपराध कम को चुपचाप देखती रही, जिसने बड़े बड़े नगरों में लोगों का कत्लेआम देखा और इसे एक स्वाभाविक घटना से ज्यादा महत्व नहीं दिया और जो स्वयं भी हर उस आक्रमणकारी का निरीह शिकार बनती रही जिसने उसकी ओर तनिक ध्यान भी नहीं दिया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस अशोभनीय, निश्चल और निष्क्रिय जीवन ने इस अव्यवस्थित अस्तित्व ने अपने से भिन्न, विनाश की जगली, निरुद्देश्य और उच्छृंखल शक्तियों को उत्पन्न कर दिया था और नरहत्या तक को हिंदुस्तान की एक धार्मिक प्रथा बना दिया था।

हम यह नहीं भूलना चाहिए कि ये छोटे छोटे समुदाय जातपात के भेदभाव तथा दासप्रथा से विपाकित हो चुके थे। उन्होंने परिस्थितियों के स्वामी के रूप में मनुष्य का विकास करने के बजाय उसे परिस्थितियों का दास बना दिया था, उन्होंने स्वयं विकास करने वाली सामाजिक व्यवस्था को अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियति का रूप दे दिया था और इस प्रकार उन्होंने प्रकृति की ऐसी उपासना का जन्म दे दिया था जो अपने आप में नृशस थी। इसकी

अधोगति का पता इस तथ्य से ही चल जाता है कि मनुष्य, जो प्रकृति का शासक है, बानर हनुमान और शबला गाय के सामने श्रद्धा से घुटने टेकने लगा।  
(माक्स 'दि ब्रिटिश रूल इन इंडिया')

इसलिए, यद्यपि माक्स ने भारत में अंगरेजों की आर्थिक नीति को 'सुअरपन' कहा है (14 जून 1853 को एग्रेल्स के नाम लिखे पत्र में) लेकिन साथ ही वह अंगरेजों की नीति को 'इतिहास का अनभिप्रेत साधन' मानते हैं

यह सच है कि हिंदुस्तान में एक सामाजिक क्रांति लाने में इंग्लैंड अपने निवृष्टतम स्वार्थों से ही प्रेरित होकर काम कर रहा था और अपने इन घटिया हितों की पूर्ति का उसका तरीका मूर्खतापूर्ण था, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या मानवजाति एशिया की सामाजिक अवस्था में कोई बुनियादी क्रांति लाए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है? यदि नहीं, तो इंग्लैंड ने चाह कितने भी अपराध क्यों न किए हों, इस क्रांति को सपन्न करने में उसने इतिहास के अनभिप्रेत साधन का काम किया है।

(वही)

#### 4 भारत में ब्रिटिश शासन की 'पुनरुज्जीवनकारी' भूमिका

माक्स का कहना है कि इंग्लैंड को 'भारत में दो भूमिकाएँ निभानी थी, एक ध्वसात्मक और दूसरी पुनर्निर्माणात्मक, जिसके अंतर्गत प्राचीन एशियाई समाज को नष्ट करना था और एशिया में पश्चिमी समाज के भौतिकवादी आधार तैयार करने थे।' जहाँ तक, उसके ध्वसात्मक पक्ष की बात है उसे मुख्य रूप से देखा जा सकता था, तो भी पुनर्जीवन देने वाला उसका काम शुरू हो गया था।

अंगरेज ही ऐसे थे जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ थे और इसलिए हिंदू सभ्यता के लिए अगम्य थे। उन्होंने देशज समुदायों में फूट डालकर, देशज उद्योगों को नष्ट कर और देशज समाज की सभी उन्नत और महान चीजों को गिरा कर इस सभ्यता का विध्वंस किया। भारत में उनके शासन के बारे में इतिहास के पन्ने जो कुछ बताते हैं उनसे इस विध्वंसकारी भूमिका का ही पता चलता है। उनके निर्माणात्मक कार्यों की झलक इन ध्वसावशेषों के अबार से मुश्किल से ही मिलती है। फिर भी अब यह काम शुरू हो गया है। (माक्स 'दि फ्यूचर रिजल्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया', न्यूयाक डेली ट्रिब्यून, 8 अगस्त 1853)

माक्स न पुनर्जीवित देने वाली इस भूमिका की शुरुआत किन चीजों में देखी ? इस सदर्भ में उन्होंने कई संकेत प्रस्तुत किए हैं

- 1 राजनीतिक एकता मुगल बादशाहों के शासनकाल में स्थापित एकता से कहीं अधिक दृढ़ और व्यापक एकता' जो निश्चित रूप से 'इलक़िद्वे टेलीग्राफ' द्वारा और मजबूत तथा स्थाई बनेगी',
- 2 'देशी सेना' (यह बात 1857 के विद्रोह के पहले कही गई थी। विद्रोह के बाद यह सेना भंग कर दी गई। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में जानवृद्धि वृद्धि कर दी गई और उनकी संख्या समूची सेना की एक तिहाई हो गई। इसके साथ ही ब्रिटिश सैनिक नियंत्रण और मजबूत हो गया),
- 3 'एशियाई समाज में पहली बार समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की शुरुआत' (माक्स का यह कथन 1835 से 1873 के बीच की अवधि का है। 1835 में भारत में समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी पर 1873 में ब्रिटिश सरकार ने इस स्वतंत्रता के विरुद्ध एक के बाद एक 'प्रेस ऐक्ट' बनाए और इस पत्रों मुख साम्राज्यवादी शासन के आधुनिक युग में तो उसने इस स्वतंत्रता के विरुद्ध अपने को निरंतर मजबूत किया है),
- 4 'एशियाई समाज की एक बड़ी कमी अर्थात् जमीन पर निजी मिल्कियत' की स्थापना,
- 5 अंगरेजों द्वारा बेमन से और बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, भारतीयों के एक शिक्षित वर्ग का तैयार होना, जिसे शासन का संचालन करने की आवश्यक जानकारी थी और जो यूरोपीय विज्ञान से अनुप्राणित था',
- 6 भाषा से चलने वाले जहाजों के जरिए यूरोप के साथ नियमित और शीघ्रगामी संचार संबंध की स्थापना।

इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी भारत के औद्योगिक पूंजीवादी शोषण का अवश्य भावी परिणाम। भारत के बाजार को विकसित करने के लिए यह जरूरी था कि 'भारत का रूपांतरण एक उत्पादक देश के रूप में' किया जाए, अर्थात् उसे बाहर से बनाए जान वाले तैयार सामान के बदले में निर्यात करने के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए उन्हें भारत में रेलों, सड़कों और सिंचाई के साधनों का विकास करना जरूरी हो गया। जिस समय माक्स ने ये बातें लिखी थी, अभी यह दौर शुरू ही हुआ था। उस नए विकास के नतीजों को ध्यान में रखकर ही माक्स ने भारत के

सबध में अपनी सर्वाधिक चर्चित और सुविख्यात भविष्यवाणी की थी

मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश उद्योगपति महज इसी उद्देश्य से रेलें बनवा रहे हैं ताकि वे कम खर्च में अधिक कपास और दूसरे कच्चे माल अपने उद्योग धंधा के लिए निकाल सकें। लेकिन एक बार यदि आप किसी देश के संचार साधनों में मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो फिर आप उस देश को मशीनों का निर्माण करने से नहीं रोक सकते। यह संभव नहीं है कि आप किसी विशाल देश में रेलों का जाल बिछाएँ और उन औद्योगिक प्रक्रियाओं को वहाँ न शुरू होने दें जो रेल यातायात की तात्कालिक और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं, इसका नतीजा यह निश्चित रूप से होगा कि उद्योग की जिन शाखाओं का रेल से कोई सीधा संबंध नहीं है उनमें भी मशीनों का इस्तेमाल होने लगे। इसलिए रेल व्यवस्था से हिंदुस्तान में आधुनिक उद्योगधंधों की शुरुआत हो गई है। रेल व्यवस्था से उत्पन्न ये उद्योगधंधे कई पुरुषों से चले आ रहे उस श्रम विभाजन को भंग कर देंगे जिस पर भारत की वणव्यवस्था टिकी हुई है जो भारत की प्रगति और उसकी ताकत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। (माक्स 'दि फ्यूचर रिजल्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया')

क्या इसका अर्थ यह है कि माक्स ने साम्राज्यवाद का भारत में एक प्रगतिशील शक्ति का दर्जा दिया जिसमें भारतीय जनता को आजाद करने और उसे सामाजिक प्रगति के रास्ते पर ले जाने की क्षमता थी? नहीं, माक्स की धारणा इसके एकदम विपरीत थी। जब माक्स ने भारत में अंगरेजों के पूँजीवादी शासन की 'पुनर्जीवन देने वाली' भूमिका की चर्चा की थी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी बता दिया था कि वह साम्राज्यवाद की महज इस भूमिका का उल्लेख कर रहे हैं कि उसने नई प्रगति के लिए भौतिक परिस्थितियाँ तैयार कर दी हैं लेकिन यह नई प्रगति स्वयं भारतीय जनता ही कर सकती थी और वह भी इस शतक पर कि या तो वह स्वयं मुक्ति प्राप्त करे या ब्रिटन में औद्योगिक मजदूर वर्ग की विजय के फलस्वरूप, जो भारतीय जनता को भी आजाद करेगी, वह साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हो। जब तक ऐसा नहीं होता भारत में साम्राज्यवाद द्वारा लाई गई सभी भौतिक उपलब्धियाँ भारतीय जनता की स्थितियों के लिए न तो कोई फायदा पहुँचाएंगी और न उनमें कोई विकास होगा।

संभव है कि इंग्लैंड का संपूर्ण पूँजीपति वर्ग, यह करने पर मजबूर हो जाए लेकिन वह आम जनता की सामाजिक स्थिति में भौतिक दृष्टि से न तो कोई सुधार करेगा और न आम जनता को मुक्ति ही दिलाएगा। यह बात केवल उत्पादक शक्ति के विकास पर ही नहीं बल्कि जनता द्वारा उनके विनियोग पर

भी निभर है। यह पूजीपति वग दोनों के लिए भौतिक परिसर निर्धारित करने में विफल नहीं होगा, यह मानी हुई बात है। क्या पूजीपति वग न इससे ज्यादा कभी कुछ किया है? क्या उसने अलग अलग व्यक्तियों और जनता को रक्तपात और गंदगी, दुख और अपमान के बीच घसीटे बगैर कभी किसी प्रगति को प्रभावित किया है?

अगरेज पूजीपति वग ने हिंदुस्तानियों के बीच समाज के जिन नए तत्वों के बीज बिखारे हैं हिंदुस्तान की जनता उनके फल तब तक नहीं चख सकेगी जब तक या तो स्वयं ब्रिटेन में वर्तमान शासक वग को हटाकर औद्योगिक मजदूर वग (सबहारा) सत्ता में सभाल ले या हिंदुस्तानी खुद इतने शक्तिशाली न हो जाए कि अगरेजों की गुलामी के जुए को एकदम उतार फेंके।

(वही)

इसके साथ भारतीय क्रांति की संभावना के सदर्भ में और उपनिवेशों की गुलाम जनता की मुक्ति की आवश्यकता के सदर्भ में 1882 में एंगेल्स के वक्तव्य की तुलना की जा सकती है

भारत शायद, और जिसकी वस्तुतः काफी संभावना है, क्रांति संपन्न करेगा और चूँकि अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील सबहारा किसी औपनिवेशिक युद्ध का संचालन नहीं कर सकता इसलिए इसकी पूरी संभावना रखने की आवश्यकता है। वेश्वर इसे बेशुमार विध्वंसों के बीच से गुजरना होगा लेकिन सभी क्रांतियों के साथ इस तरह की बातें अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं। क्रांति की घटना अंग्रेजों के मसलन अल्जीरिया और मिस्र में भी हो सकती है। और हमारे लिए निश्चित रूप से यह सर्वोत्तम चीज होगी।  
(काउत्सकी के नाम एंगेल्स का पत्र, 12 सितंबर 1882)

यह ध्यान देने की बात है कि 19वीं सदी के मध्य तक भारतीय स्थिति का मानन द्वारा किया गया विश्लेषण तीन मुख्य बातों पर आधारित है। इनमें पहली बात है भारत में अगरेजों की विनाशकारी भूमिका, पुराने समाज को नेस्तनाबूद करना, दूसरे, पूँजीवाद के मुक्त व्यापारवाले युग में भारत में ब्रिटिश शासनकाल की पुनर्जीवन देने वाली भूमिका, भविष्य के नए समाज के लिए भौतिक परिसरों का निर्धारण किया जाना, तीसरे, राजनीतिक रूपांतरण की आवश्यकता को व्यावहारिक निष्कर्ष के रूप में मान लिया जाना जिससे एक नए समाज की स्थापना के लिए भारतीय जनता साम्राज्यवादी शासन से अपने को मुक्त कर ले।

समूचे विश्व में पूँजीवाद की ही तरह आज भारत में साम्राज्यवाद अपनी वस्तुगत प्रगति

शील या पुनर्जीवन देने वाली भूमिका को, जो पूँजीवाद ने स्वतंत्र व्यापार वाले युग के अनुरूप था, काफी पहले निभा चुका है और अब ज़रूरतस्तः प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में भारत में इसका स्थान है। यह भारतीय प्रतिक्रियावाद के अन्य रूपों को सहारा दे रहा है। इस प्रकार वह दिन अब आ गया है जब मार्क्स द्वारा निर्देशित राजनीतिक रूपांतरण के कार्य को ही अपना प्रमुख कार्य बना लिया जाए।

## भारत में ब्रिटिश शासन का पुराना आधार

‘उस हिंसा और लूट की कोई सीमा नहीं है जिसे भारत में ब्रिटिश शासन के नाम से जाना जाता है।—लेनिन इन्फ्लेमेबल मैटीरियल इन वर्ल्ड पालिटिक्स’ 1908

भारत के बारे में मार्क्स को लिखे 90 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है। इस दौरान काफी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका बावजूद मार्क्स के ऐतिहासिक विश्लेषण का मुख्य सारांश आज की स्थितियाँ पर भी लागू होता है और तबसे आज तक की घटनाओं के अनुभव न भारत के भविष्य के बारे में मार्क्स के दृष्टिकोण की (19वीं सदी में भारत के बारे में जितने लोगों ने लिखा उनमें मार्क्स का विश्लेषण अतुलनीय है) पुष्टि तो की ही है साथ ही उनके द्वारा निर्धारित राजनीतिक निष्कर्षों की पुष्टि की प्रक्रिया भी आज देखी जा सकती है।

आज हम मार्क्स के विश्लेषण को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा भारतीय जनता की शक्तियों, दानों के विकास के समूचे युग पर लागू कर सकते हैं।

भारत में साम्राज्यवादी शासन के इस इतिहास में तीन मुख्य युग सामने आते हैं। पहला युग व्यापारिक पूँजी का युग है जिसका प्रतिनिधित्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इस व्यवस्था का साधारण स्वरूप 18वीं सदी के अंत तक चला। दूसरा युग औद्योगिक पूँजी का युग है जिसमें 19वीं सदी में भारत के शोषण का एक नया आधार कायम किया। तीसरा युग महाजनी पूँजी का आधुनिक युग है जिसने पुराने अवशेषों पर भारत के शोषण

की अपने ढंग की खास प्रणाली विकसित की और जो सबसे पहले 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में शुरू हुई और इधर हाल के वर्षों में पूरी तरह विकसित हुई।

मार्कम ने भारत के सदम में शुरू के दो युगों, व्यापारिक पूँजी और औद्योगिक पूँजी के युग, का विश्लेषण किया। हमें अब इस विश्लेषण को महाजनी पूँजी के आधुनिक युग और भारत में इसकी नीति तक ले जाना है।

इसलिए हम शुरू की दो अवस्थाओं पर सरमरी तौर पर विचार कर सकते हैं, ये दोनों अवस्थाएँ वर्तमान प्रणाली के लिए आधार कायम करने तथा वर्तमान अवस्था तक के घटनाक्रमों को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद ही हम आज के युग की घटनाओं पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

## 1 भारत की लूट

आमतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी का युग 1600 ई० से, जब उसे पहला चार्टर (सरकारी अधिकारपत्र) मिला था, 1858 ई० तक, जब यह अंतिम रूप से सम्राट के अधीन चला गया, माना जाता है। दरअसल, भारत पर इसके प्रभुत्व का मुख्य काल 18वीं सदी का उत्तरार्ध था।

हालांकि प्रारंभिक तिजारती गोदामों की स्थापना 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी (1612 में सूरत में, 1639 में फोर्ट सेंट जॉज, मद्रास में, बंबई ने 1669 से और फोर्ट विलियम, कलकत्ता ने 1696 में कंपनी को पट्टा दिया) फिर भी नई ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसने बाद में भारत पर विजय हासिल की, पहला अधिकारपत्र 1698 ई० में मिला और वह 1708 तक अपना मंगठित रूप नहीं बना सकी। इस प्रकार भारत पर विजय हासिल करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी उस कुलीनतंत्र की एक अद्भुत रचना थी जिसने ब्रिह्म ऋाति के जरिए इंग्लैंड पर अपनी जकड़ मजबूत कर ली थी।

18वीं सदी के मध्य से इस कंपनी ने भारत में अपनी प्रादेशिक सत्ता कायम करनी शुरू की। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं सदी में आंतरिक संघर्षों से भारत तबाह हो गया था और वहाँ आंतरिक विभ्रम का दौर चल रहा था (कुछ मामलों में इसकी तुलना इंग्लैंड में वॉम आफ राजेज (गुलाबों के युद्धों) या जमनी के 20 वर्षीय युद्ध से की जा सकती है) यह स्थिति पुरानी व्यवस्था के विघटन और विकास की सामान्य प्रक्रिया में प्रगामी व्यापार, जहाजरानी तथा भारतीय समाज में उत्पादन हितों के आधार पर पूँजीपति वर्ग की सत्ता के उदय के लिए आवश्यक थी। फिर भी इस नाजुक अवधि के दौरान, अपने उत्तम तकनीकी और सैनिक उपकरणों तथा सामाजिक आर्थिक सबद्धता के साथ यूरोप के और भी अधिक विकसित पूँजीपति वर्ग ने जो धावा बोला उससे विकास की यह सामान्य प्रक्रिया विफल हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी व्यवस्था के



विघटन के समय भारत में आधिकारिक रूप से पूजापति वग का जो शासन कायम हुआ, वह पुरानी व्यवस्था की खोल के अंदर तैयार हो रहे भारतीय पूजापति वग का नहीं बल्कि विदेशी पूजापति वग का शासन था। इसने पुराने समाज पर खुद को जबरदस्ती आरोपित कर दिया और भारत के उभरते पूजापति वग को भ्रूणावस्था में ही नष्ट कर दिया। भारत के विकास के खासदी यही है जिसने बाद में विदेशी पूजापति वग के लाभ के लिए निष्फल या विकृत सामाजिक विकास का रूप ले लिया।

18वीं सदी के भारत की खास बात विभ्रम और सत्रमण के इस नाजुक युग में ही विदेशी हमलावरों को अपने प्रभुत्व क्षेत्र कायम करने के लिए सघम और पड़यत्न का अवसर दिया। एक दूसरे के घिनाफ छिड़े इस युद्ध में, पूजापतियों की सर्वाधिक विकसित शक्ति के प्रतिनिधि ब्रिटिश पूजापति वग को, सफलता मिली। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल की विजय के साथ भारत में प्रादेशिक सत्ता स्थापित की गई हालांकि यह शुरू शुरू में नाममात्र के लिए पुराने रूपों के तहत थी। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते भारत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में इसका मजबूती से प्रसार हो गया।

1858 तक कंपनी विधिवत कायम सभालती रही। फिर भी, नए विजित क्षेत्रों का शासन के रूप में ब्रिटिश राज्य की प्रभुसत्ता लाड नाथ के 1773 के रेगुलेशन ऐक्ट और 1784 के पिट्स ऐक्ट के बाद से ही स्थापित हो चुकी थी। इन दोनों अधिनियमों ने क्रमशः गवर्नर जनरल, उनकी कोसिल एवं एक सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय मामलों के विदेश मंत्री और लंदन में बांड आफ कंट्रोल की स्थापना की। 1813 में कंपनी की इजारेदारी की समाप्ति के साथ ही (सिवाय चीन व्यापार के जो 1833 में समाप्त हुआ) इसकी ब्रिटिश आर्थिक भूमिका भी समाप्त हो गई। इसकी दोहरी प्रणाली का आडंबर 19वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान तब तक चलता रहा जब तक 1857 के विद्रोह ने इसके दिवालिया और अविकसित स्वरूप का भड़ाफोड़ नहीं कर दिया। इसके बाद के वर्षों में कंपनी को अंतिम रूप से भंग कर दिया गया।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व और भारत में इसके विशेष शोषण का निर्णायक दौर आधुनिक पूजावाद की भ्रूणावस्था अर्थात् 18वीं सदी का उत्तरार्ध था। उस शोषण का चरित्र औद्योगिक पूजा द्वारा किए गए बाद के 19वीं सदी के शोषण के चरित्र से भिन्न है और इसके लिए अलग से विश्लेषण की जरूरत है।

भारत में साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का मूल उद्देश्य ठीक वही था जो व्यापारिक पूजा की इजारेदारी कंपनियों का होता है अर्थात् समुद्रपार के किसी देश के मान और उत्पादनों के व्यापार पर एकाधिकार कायम करके मुनाफा कमाना। इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश माल के लिए बाजार तलाश करना नहीं था बल्कि उसका प्रयत्न भारत और पूर्वी द्वीप समूह (ईस्ट इंडीज) के सामान (खासतौर से मसाले और सूती तथा रेशमी सामान)

को सप्लाई पर कब्जा करना था क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप में इन चीजों की बड़ी मांग थी और हर बार पूरब के देशों की सफल यात्रा के बाद काफी लाभ कमाया जा सकता था।

फिर भी, बपनी के सामने शुरू से ही एक समस्या थी। इन सामानों को व्यापार के जरिए भारत से प्राप्त करने के लिए यह जरूरी था कि बदले में भारत को कुछ दिया जाए। 17वीं सदी के प्रारंभ में विकास की जिस अवस्था तक इंग्लैंड पहुंच सका था उसमें भारत का देने के लिए कोई भी ऐसी चीज उसके पास नहीं थी जिसकी उत्तमता और तकनीकी स्तर के मामले में भारतीय सामान से तुलना की जा सके। उसके पास एक उद्योग विकसित अवस्था में था, ऊन उद्योग, लेकिन ऊनी सामान भारत के किसी काम का न था। इसलिए भारत में माल खरीदने के लिए अंगरेजों को बहुमूल्य धातुएं बाहर लानी पड़ती थीं

पूरब के साथ व्यापार करने में असली यह कठिनाई थी कि यूरोप के पास वे चीजें बहुत कम थी जिसकी पूरब को जरूरत थी मसलन, दरवारी के लिए विलासिता का कुछ सामान, सीसा, तांबा, पारा और टिन मूंगा और हाथी दात। चादी ही एक ऐसी चीज थी जो भारत ले सकता था। इसलिए माल खरीदने के लिए मुख्यतया चादी ही निवालनी पड़ी। (एल० सी० ए० नावेल्स 'इकोनामिक डेवलपमेंट ऑफ दि ओवरसीज इंपायर,' पृष्ठ 73)

इसलिए शुरू के दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी को बप में 30 000 पौंड तक मूल्य के चादी, सोना और विदेशी सिक्कों के निर्यात का विशेष अधिकार दिया गया। लेकिन व्यापारिक पूंजीवाद की समूची प्रणाली के लिए यह बहुत दुखद और असंगत बात थी क्योंकि उन दिनों इन बहुमूल्य धातुओं को ही देश की एकमात्र वास्तविक संपत्ति समझा जाता था और व्यापार का अनिवार्य उद्देश्य यह माना जाता था कि देश में बाहर से बहुमूल्य धातुएं आए अर्थात् वास्तविक संपत्ति में वृद्धि हो।

शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के, 'साहसिक' सौदागर इस समस्या को हल करने का जोर शोर से प्रयास कर रहे थे और इस बात की कोशिश में लगे थे कि बिना कुछ पैसा दिए या बहुत कम राशि देकर भारत का माल ले लिया जाए। शुरू में उन्होंने जो तरीके निकाले उनमें से एक तरीका था घुमा फिराकर व्यापार करना। इसके अंतर्गत वे खासतौर से अफ्रीका और अमरीका के अपने उपनिवेशों से लूट खसोट के जरिए जो माल इकट्ठा करते थे उससे भारत में अपने रहने का खर्चा निकाल लेते थे क्योंकि अभी भारत में सीधे सीधे लूट खसोट करने की उनमें ताकत नहीं थी

भारत के साथ इंग्लैंड का व्यापार दरअसल यह खोज निवालने की दीड थी कि भारत को कौन सी चीज चाहिए और इस सिलसिले में वेस्ट इंडीज और स्पानी



सारा छल कपट फीका पड़ जाता है। कंपनी के गुमाश्तों और उनकी साजिश का साथ देने वाले जाचनदारों (कपड़ों की जाच करने वाले) द्वारा जो दाम तय किया जाता है वह बाजारों या खुली दर पर बिकने वाले इसी तरह के कपड़ों की तुलना में 15 प्रतिशत और वही कहीं तो 40 प्रतिशत कम होता है। (विलियम वोल्ट्स 'कंसिडरेशंस ऑन इंडियन अफेयर्स' 1772 पृष्ठ 191-94)

इस प्रकार 'व्यापार' के नाम पर व्यापार कम और लूट जगमगाती थी।

लेकिन जब 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या नागरिक प्रशासन मिलने के साथ ही मालगुजारी वसूलने का काम मिल गया तब व्यापार के मुनाफे का अलावा सीधी लूट का एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसका कोई और छोर नहीं था। इसके बाद व्यापक पैमाने पर पूरी वेशमी के साथ जो लूटपाट शुरू हुई उसने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी प्रशासन को इतिहास का एक अग्रणी शब्द बना दिया। हाउस ऑफ बॉमन्स के 1784 के प्रस्ताव के अनुसार

संसदीय जाच के नतीजों से पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्देश्यों में चाहे वे राजनीतिक हों या व्यापारिक, पूरी तरह भ्रष्ट और विकृत पाई गई, उसने हर क्षेत्र में तीव्रतर विरोध बढ़ाते हुए लूटमार के मकसद की पूर्ति के लिए राजकीय अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त युद्ध और शांति के अधिकारों का दुरुपयोग किया है। शांति संधी लगभग सभी संधियों के जरिए उन्होंने जनता के विश्वास को अनेक बार आघात ही पहुंचाया है। जो देश एक समय अपार समृद्ध थे उन्हें इस कंपनी ने असमर्थता, अपेक्षा और जनशून्यता की स्थिति में पहुंचा दिया।

इसके साथ ही अपनी भूमिका के बारे में कंपनी की खुद की राय भी देखी जा सकती है जो उसने 1858 में संसद में प्रस्तुत याचिका में व्यक्त की थी (इसे जान स्टुअर्ट मिल नामक पाठ्यपुस्तक 'परोपदेश' ने लिखा था)

जिस सरकार ने वे एक हिस्सा हैं वह अपने इरादों में परिवर्तन ही नहीं है बल्कि उसने परोपकारिता के जो काम किए हैं वह मानव जाति के लिए अब तक किए गए कार्यों में कमिनाल हैं।

इस दावे के विपरीत सर जॉन कानवेल लीविस ने 1858 में संसद में एतान किया

मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस धरती पर आज तक कोई भी सम्यक सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वामघाती और इतनी लुटरी नहीं पाई

अमरीका में गुलामों की बिक्री से प्राप्त चांदी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी।  
(नावेल्स पूर्वोद्धृत पुस्तक, पृष्ठ 74)

लेकिन जल्दी ही, 18वीं सदी के मध्य तक, जैसे जैसे, भारत पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने लगा, विनिमय में अपना पताड़ा भारी रखने के लिए तथा कम से कम पैसे देकर अधिक से अधिक माल हड़पने के लिए कंपनी द्वारा बल प्रयोग के तरीके भी अधिक से अधिक इस्तमाल किए जाने लगे। व्यापार और लूट के बीच की विभाजन रेखा, जो शुरू से ही बहुत साफ साफ कभी नहीं खींची गई थी (शुरू के इन 'साहसिक' सौदागरों ने बहुधा व्यापार और डकैती के बीच कोई भेद नहीं रखा), अब धुंधली पड़न लगी थी। व्यक्तिगत उत्पादनकर्ताओं—चाहे वे बुनकर हो या किसान, की तुलना में कंपनी का सौदागर हमेशा ऐसी अनुकूल स्थिति में होता था कि वह अपनी शर्तों पर उनपर थोप सके। वह अब इस लायक हो गया था कि विनिमय की समानता के सभी ढोंग छोड़कर ताकत के बल पर अपने पक्ष में सौदेबाजी कर सके। 1762 तक ऐसी हालत हो गई कि बंगाल के नवाब को बहुत निरीह बनकर कंपनी के एजेंटों की शिकायत कंपनी के सामने करनी पड़ी

वे रयाता (किसानों), व्यापारियों आदि से जबरदस्ती एक चौथाई कीमत देकर उनके माल और उनके उत्पादन हड़प रहे हैं और किसानों आदि को मारपीट कर तथा उनका दमन करके वे अपनी एक रुपये की चीज 5 रुपये में बच रह रहे हैं। (अंगरेज गवर्नर के नाम बंगाल के नवाब का ज्ञापनपत्र, मई 1762)

इसी प्रकार एक अंगरेज सौदागर विनियम बाल्टिम ने 1772 में प्रकाशित कंसिडरेशंस ऑन इंडियन अफेयर्स में इस प्रक्रिया का निम्नलिखित वर्णन किया था

अंगरेज अपने बनिया और वाले गुमास्ता के जरिए मनमाने ढंग से यह तय कर देते हैं कि माल तैयार करने वाला हर निर्माता उन्हें कितना माल देगा और बदले में उसे कितनी कीमत मिलेगी। गरीब बुनकर की मजदूरी का आमतौर पर जरूरी नहीं समझा जाता है, जहां तक गुमास्तों की बात है, कंपनी की लागत पर काम देते समय उनमें कंपनी की मर्जीवाली शर्तों पर दस्तखत करा लिया जाता है। यदि कोई बुनकर वह दाम लेन से इन्कार कर देता या जा कंपनी देती थी तो उनके दानों हाथ बाध दिए जाते थे और कोई लगाकर उन्हें भगा दिया जाता था। आमतौर में इन तरह के अनक बुनकरों का नाम कंपनी के रजिस्टर में गुमास्ता के रूप में दर्ज है। उन्हें गुलामों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है और उन्हें किसी दूसरे के लिए काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस विभाग में जितना छन बचता होता था वह बल्गाम में परा है, लेकिन गरीब बुनकरों के साथ जितनी ठगी की जाती है उसमें सामने में

सारा छल कपट फीका पड़ जाता है। कंपनी ने गुमाश्ती और उनकी साजिश का साथ देने वाले जाचनदारों (कपड़ों की जाच करने वाले) द्वारा जो दाम तय किया जाता है वह बाजारों या खुली दर पर बिकने वाले इसी तरह के कपड़ों की तुलना में 15 प्रतिशत और वही कहें तो 40 प्रतिशत कम होता है। (विलियम वोल्डस 'कंसिडरेशंस ऑन इंडियन अफेयर्स' 1772 पृष्ठ 191-94)

इस प्रकार 'व्यापार' के नाम पर व्यापार कम और लूट ज्यादा थी।

लेकिन जब 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या नागरिक प्रशासन मिलने के साथ ही मालगुजारी वसूलने का काम मिल गया तब व्यापार के मुनाफे के अलावा सीधी लूट का एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसका कोई ओर छोर नहीं था। इसके बाद व्यापक पैमाने पर पूरी देशीयों के साथ जो लूटपाट शुरू हुई उसने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी प्रशासन को इतिहास का एक अथहीन शब्द बना दिया। हाउस ऑफ कामन्स के 1784 के प्रस्ताव के अनुसार

सप्तदीय जाच के नतीजा से पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्देश्यों में चाहे वे राजनीतिक हों या व्यापारिक, पूरी तरह भ्रष्ट और विकृत पाई गई, उसने हर क्षेत्र में तीव्रतर विरोध बढ़ाते हुए, लूटमार के मक्सद की पूर्ति के लिए राजकीय अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त युद्ध और शांति के अधिकारों का, दुरुपयोग किया है। शांति संधी लगभग सभी संधियों के जरिए उन्होंने जनता के विश्वास को अनेक बार आघात ही पहुंचाया है। जो देश एक समय अपार समृद्ध थे उन्हें इस कंपनी ने असमर्थता, अपक्व और जनशून्यता की स्थिति में पहुंचा दिया।

इसके साथ ही अपनी भूमिका के बारे में कंपनी की खुद की राय भी देखी जा सकती है जो उसने 1858 में ससद में प्रस्तुत याचिका में व्यक्त की थी (इसे जान स्टुअर्ट मिल नामक पाखंडी परोपदेशक ने लिखा था)

जिस सरकार के वे एक हिस्सा हैं, वह अपने इरादों में पवित्रतम ही नहीं है बल्कि उसने परोपकारिता के जो काम किए हैं वह मानव जाति के लिए अब तक किए गए कार्यों में वेमिसाल है।

इस दावे के विपरीत सर जान कानवल लीविस ने 1858 में ससद में एलान किया

मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस घरेलू पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटरी नहीं पाई

गई जितनी 1765 से 1784 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी।

(हाउस आफ कामंस में सर जाज कनिंगल लीविस का वयान, 12 फरवरी 1858)

क्लाइव ने 1772 में ससद में अपने भाषण के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में (उसके कर्मचारियों के बारे में ही नहीं जिन्होंने कंपनी की लूट के अलावा खुद भी निजी तौर पर लूटपाट में हिस्सा लिया था) अपने विचार व्यक्त किए जिसमें उन्होंने कहा था

कंपनी ने एक ऐसा साम्राज्य कायम कर लिया है जो फ्रांस और रूस का छोड़कर यूरोप के किसी भी साम्राज्य से ज्यादा विस्तृत है। उसने 40 लाख स्टर्लिंग की मालगुजारी अर्जित की है और इसी के अनुपात में व्यापार किया है। यह मानना स्वाभाविक है कि इस तरह का उद्देश्य, प्रशासन का सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट करने का योग्य है क्या उन्होंने इसपर विचार किया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे कोई ठोस और वास्तविक समझने के बजाय दक्षिणी सागर के बुलबुले की तरह समझा। उन्होंने भविष्य की कोई चिंता न कर वर्तमान के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा आज जो मिल रहा है वह ले लें—कल की देखी जाएगी। उन्होंने रोटियों और मछलियों के तात्कालिक बटवारे के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। (हाउस आफ कामंस में क्लाइव का भाषण, 30 मार्च, 1772)

वगाल तथा अन्य विजित क्षेत्रों में नागरिक सत्ता स्थापित करने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यवस्था कायम की उसका क्या स्वरूप था? 1765 में क्लाइव ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक खत लिखकर बड़े सहज और स्पष्ट रूप में बताया है कि प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए कंपनी के पास एकमात्र योग्यता यह होना चाहिए कि वह मुद्रा के रूप में एक निश्चित राशि इंग्लैंड भेजे। क्लाइव ने हिसाब करके यह राशि बता भी दी थी। इन बातों से साफ पता चलता है कि बाद के वर्षों में लोकोपकार का जो घाटा खड़ा किया गया था वह कितना परस्पर विरोधी था

जहां तक मैं समझता हूँ इस अधिग्रहण और बदवान आदि पर पहले से चल आ रहे आपके बज्जे के द्वारा आगामी वर्षों में मिलने वाला राजस्व 250 लाख मिक्का रुपये से कम नहीं होगा। भविष्य में इस राशि में कम से कम 20 से 30 लाख की वृद्धि होगी। शांति के दिनों में मनिक और अनैतिक व्यय 60 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता, नवाब के भत्ते पहले ही कम करके 42 लाख रुपये और राजा (मुगल सम्राट) के नजराने 26 लाख रुपये कर दिए गए हैं। इस प्रकार कंपनी को 122 लाख सिक्का रुपये या 1,650,900 पौंड स्टर्लिंग का विगुड लाभ बच रहेगा। (ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के नाम क्लाइव का पत्र 30 गितंबर 1765)

बलाइव का यह पक्ष इतना सीधा सीधा और व्यापारिक विस्मय का है मानो किसी व्यापारी का बहीखाता हो। जनता से कर के रूप में जितना धन वसूला जाता है, उसका एक चौथाई हिस्सा सरकार के कामकाज के लिए पर्याप्त समझा जाता है, एक चौथाई हिस्सा स्थानीय राजाओं (नवाब और भुगल शासक) के दावों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, राजस्व का शेष आधा हिस्सा, जो अनुमानतः 15 लाख पौंड है, विशुद्ध लाभ है। वाटमले का व्यवसायी की सरकार का सपना जितनी पूर्णता के साथ यहाँ साकार हुआ वह अभूतपूर्व है।

1773 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कंपनी के प्रशासन के प्रथम छ वर्षों के दौरान बंगाल के सदस्य में आय और व्यय का विवरण दिया गया है जिससे पता चलता है कि ये नतीज निर्वर्णित उद्देश्यों के बितने अनुरूप थे। इसमें प्राप्त कुल राजस्व 13,066,761 पौंड और कुल व्यय 9,027,609 पौंड दिखाया गया है जिससे 4,037,152 पौंड के विशुद्ध लाभ का पता है। इस प्रकार बंगाल में राजस्व से हुई आय लगभग एक तिहाई भाग 'शुद्ध लाभ' के रूप में देश से बाहर भेजा गया।

लेकिन कुछ मजदूराना इतना ही नहीं था। कंपनी के अफसरों ने व्यक्तिगत तौर पर वेशुमार दोलत कमाई। स्वयं बलाइव जब भारत आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन यहाँ से लौटने के समय तक उसके पास तबरीवन ढाई लाख पौंड तो यही साथ ही वह एक जागीर भी बना गया था जिससे उसे 27,000 पौंड प्रति वर्ष की आमदनी होती थी। उसने स्वयं यह बताया था कि 'दो वर्षों में 100,000 पौंड कमाए गए हैं।' कुल मुनाफे का काफी हद तक सही अनुमान निर्यात और आयात के आकड़ों से लगाया जा सकता है। गवर्नर वेरल्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार 1766 से 1768 यानी तीन वर्षों के दौरान 6,311,250 पौंड का निर्यात किया गया जबकि आयात केवल 624,375 पौंड का किया गया। इस प्रकार देश का शासन सभालने वाली, नई तरह की इस व्यापारिक कंपनी ने जितना माल देश के अंदर मगाया उसका दस गुना देश से बाहर भेजा।

इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के मीदागरों का सबसे प्यारा सपना पूर्ण हो गया। यह सपना था भारत का कुछ दिए वगैरे यहाँ की संपत्ति लूट ले जाना। बलाइव की मौसिल का एक सदस्य एल० स्नैपटन 1763 में ही यह देखकर फूला नहीं समाया था कि प्लासी के युद्ध के बाद लूटपाट की प्रारम्भिक अवस्थाओं के बाद, तीन वर्षों तक एक भी औसत सोना चांदी भेजे वगैरे समूचे भारत का व्यापार चलाया जा सका होगा।

इन शानदार सफलताओं ने देश को लगभग 30 लाख की धनराशि मिली है, क्योंकि यदि ठीक ढंग से कहा जाए तो सूबा से प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण राशि अतः इंग्लैंड ही पहुँचती है। अपने दोषों के जरिए या कलकत्ता के अपने राजाने में हुड्डिया और रसीदों के भुगतान के जरिए कंपनी के हाथों में इतनी बड़ी



सपत्ति आ गई कि वह एक औंस भी सोना चादी बाहर भेजे वगैर लगातार तीन वर्षों तक संपूर्ण भारत का (चीनो को छोड़कर) व्यापार चलाती रही। विदेशी कपनियों के जरिए भी काफी बड़ी राशि बाहर भेजी गई। वे इस तरह के बाहरी देशों के साथ व्यापार मनुलन में हमारा पलड़ा भारी कर देती हैं। (एल० स्ट्रैपटन 'रिफ्लेक्शंस आन दि गवर्नमेंट आफ इंडोस्तान,' 1763)

बंगाल से हुई आमदनी के जिस हिस्से को इंग्लैंड भेजा गया उसके लिए जिस विकृत शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वह बहुत सोच विचार के बाद तय की गई थी, उस कपनी की 'लागत पूंजी' कहा गया। इस प्रणाली के बारे में हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति ने 1783 में कहा

बंगाल से हुई आय के एक निश्चित भाग को कई वर्षों से इंग्लैंड निर्यात किए जाने वाले सामानों की खरीद से अलग रखा जाता है और इसे लागत पूंजी कहा जाता है। बहुधा इस राशि की विपुलता के आधार पर ही कपनी के मुख्य कमचारियों की योग्यता का अनुमान लगाया जाता है, और भारत की इस असहायता के मुख्य कारण को सामान्यतौर पर उसकी संपदा और समृद्धि का पैमाना माना जाता है—लेकिन उस देश के साथ लाभप्रद व्यापार के कारण नहीं बल्कि नजराने के भुगतान के कारण ही उसका ऊपर से दिखाई देने वाला रमणीय और मोहक रूप बना रहा है—

बंगाल और इंग्लैंड के बीच परस्पर व्यवहार (क्योंकि यह व्यापार नहीं है) का लेखा जोखा करने पर राजस्व से प्राप्त आय से पूंजी निवेश की प्रणाली के घातक प्रभाव वेहद स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। उस दृष्टि में देखें तो, जहां तक कपनी का सवाल है देश से जितना भी सामान बाहर भेजा जाता था वह किसी ऐसी प्रणाली पर आधारित नहीं था जिसके जतगत निर्यातित सामान के बदले कोई सामान भारत भी पहुंचाया जाए। इन सामानों के बदले में कोई भुगतान भी नहीं किया जाता था। ('हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति की नवी रिपोर्ट,' 1783, पृष्ठ 54-55)

बंगाल के लोग पर इस व्यवस्था का क्या असर हुआ इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। लूट स होन वाली आम को दिनादिन तजी के साथ बढ़ाने की मांग की जाता थी जिसने परिणामस्वरूप भूमि से प्राप्त हान वाल राजस्व या मालगुजारी में भीषण वृद्धि की गई और दमकी वगुली के रूप में विमाना के पास में बीज के लिए रखे गए अनाज तथा उनके बीज छीन लिए जान थे। 1764-65 में बंगाल के अंतिम भारतीय शासन के शासनकाल के अंतिम वर्ष में 817,000 पौंड की मालगुजारी वसूल की गई। कपनी प्रशासन के प्रथम वर्ष 1765-66 में बंगाल में प्राप्त मालगुजारी 1,470,000 थी। 1771-72

तब यह राशि वरबरा 2,341,000 पौंड और 1775-76 तक 2,818,000 पौंड हो गई। 1793 में जब लाड बान्नालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया तो उन्होंने यह राशि 3,400,000 पौंड निर्धारित कर दी।

उस समय के सभी प्रेक्षकों का यही कहना है कि इस प्रक्रिया से कुछ ही वर्षों के अंदर देश तबाह और बरबाद हो गया, इसके परिणामस्वरूप जो अकाल पड़ा उसमें आबादी का एक तिहाई हिस्सा खत्म हो गया और देश का एक तिहाई भाग 'केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल' के रूप में बदल गया।

1769 में मुर्शिदाबाद में कंपनी के रेजिडेंट वंचेर ने कंपनी को यह रिपोर्ट दी थी

किसी भी अंगरेज के लिए यह सोच पाना बड़ा कठिन होगा कि कंपनी को दीवानी मिलने के बाद से इस देश की जनता की हालत बदतर हो गई और इस सच्चाई में सदेह नहीं किया जा सकता—यह खूबसूरत देश जो अत्यंत निरक्षर और नानाशाह शासन व्यवस्था के अधीन भी फलता फूलता रहा था, अब विनाश के कगार पर खड़ा है जबकि आज प्रशासन में अंगरेजों का सचमुच काफी बड़ा हिस्सा है—

मुझे व दिन अच्छी तरह याद है जब इस देश में व्यापार पर कोई रोक-टोक नहीं थी और यह देश निरंतर फल फूल रहा था लेकिन आज मैं इसकी वर्तमान तबाह हालत का चिंता के साथ दया रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि इस तबाही का कारण मुख्यतया वह इज्जतदारी है जो कंपनी के नाम पर देश के लगभग सभी उत्पादकों के बाद के वर्षों में बायम कर ली।

इस तबाह हालत के बाद 1770 में बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा जिसे कंपनी की सरकारी रिपोर्ट में 'वर्षनातीत' कहा गया। किसी जमाने पूर्णिया का सूबा धन धान्य से परिपूर्ण था पर 'उसकी एक तिहाई से अधिक आबादी इस अकाल में समाप्त हो गई है। अब हिस्से में भी बरबादी का यही आलम है। इस अकाल में अनुमानित एक करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। फिर भी अकाल के दौरान मालगुजारी न केवल कड़ाई और निंद्यता के साथ वसूली गई बल्कि वह और बढ़ा दी गई। 12 फरवरी 1771 को कंपनी की कलकत्ता कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा 'इस अकाल की भयकरता और अकाल के फल-स्वरूप लागा की सख्या में भारी कमी के बावजूद मौजूदा माल के लिए बंगाल और बिहार सूबों के भुगतान में कुछ वृद्धि की गई है।' यह वित्त प्रचार सपन किया गया इसने बारे में वॉरन हस्टिंग्स की 1772 की कड़ी टिप्पणी दी जा सकती है

इस सूबे की कम से कम एक तिहाई आबादी के खर्ग हा जान तब इमने

फलस्वरूप खेती में बमी आ जाने के बावजूद 1771 में जितनी मालगुजारी वसूली गई वह 1768 से भी ज्यादा थी। स्वभावतया यह आशा की जाती थी कि इस महाविपत्ति के जैसे दुष्परिणाम हुए ह। उसे देखते हुए मालगुजारी भी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योकि मालगुजारी का पुराना स्तर बड़ाई के साथ कायम रखा गया। (यारन हिस्ट्रिज रिपोर्ट टु दि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स 3 नवंबर 1772)

पंद्रह वर्षों बाद संसद सदस्य विलियम फुल्लटन ने अपने विवरण में कंपनी प्रशासन के 20 वर्षों बाद बंगाल के हफातरण का चित्र प्रस्तुत किया

बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे-पूरे थे और पूव में वाणिज्य, धन मपदा तथा उद्योग के भंडार थे

लेकिन हमारे कुशासन में 20 वर्षों की अल्पावधि में ही इन गांवों के अनर्क हिस्सों को बजर का रूप दे दिया। खेता में अब खेती नहीं की जाती, बड़े बड़े इलाकों में झाड़िया उगी पड़ी हैं, किसान लुट चुके हैं, औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है, बार बार अकाल पड़े हैं, और फलस्वरूप जनसंख्या का ह्रास हुआ है। (विलियम फुल्लटन, संसद सदस्य ए ब्यू आफ दि इंगलिश इस्टरेस्ट्स इन इंडिया, 1787)

वक ने अपनी अलंकारपूर्ण भाषा में भत्सना करते हुए कहा कि 'यदि आज हम भारत छोड़कर भागना पड़े तो हमारे शासनकाल के शमनाक वर्षों की कहानी कहने के लिए जा चीजें बच रहेगी उनसे यही पता चलेगा कि यहाँ का शासन किसी भी अर्थ में औसत उठाया या चीते के शासन से बेहतर नहीं था।'

1789 में इस कथन की गूज उस समय फिर सुनाई पड़ी जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉड कानवालिस ने यह रिपोर्ट दी

मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कंपनी शासित क्षेत्र का एक तिहाई इलाका अब जंगल बन गया है जहाँ केवल जंगली जानवर बसते हैं। (लॉड कानवालिस, 18 सितंबर 1789 का कायवृत्त)

## 2 भारत और औद्योगिक क्रांति

18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की लूट से जो कुछ हासिल हुआ उसी के आधार पर आधुनिक इंग्लैंड का निर्माण हुआ।

18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड अभी मुख्यतया कृषिप्रधान देश ही था। 1750 ई० तक म उत्तरी क्षेत्रों में कुल आबादी का एक तिहाई हिस्सा रहता था, ग्लास्टरशायर की आबादी लक्जम्बर्ग की तुलना में ज्यादा घनी थी (ए० टायनबी, 'दि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन', पृष्ठ 9-10)। उन दिनों ऊनी उद्योग मुख्य उद्योग था, वेन के हिस्ट्री आफ दि काउन्ट मैयुफैक्चर' (पृष्ठ 112), के अनुसार ऊनी माल का निर्यात कुल निर्यात का एक तिहाई या एक चौथाई था। अपनी पुस्तक में वेन ने लिखा है कि '1760 ई० तक सूती यपड़े बनाने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती थी, वे लगभग उतनी ही साधारण थी जितनी भारत में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें।' (पृष्ठ 115)

सामाजिक दृष्टि से, जहाँ तब वर्गों के विभाजन, सबहारा वर्ग की उत्पत्ति और पूँजी पति वर्ग के सुदृढ़ शासन का सबब है, औद्योगिक पूँजीवाद की दिशा में प्रगति के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। उसका व्यापारिक आधार तैयार हो गया था। लेकिन औद्योगिक पूँजीवाद की अवस्था तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक था कि 18वीं सदी के मध्य तक के इंग्लैंड में सचित पूँजी की तुलना में और भी बड़े पैमाने पर पूँजी इकट्ठी हो जाए।

फिर 1757 में पलासी का युद्ध छिड़ गया और भारत की संपदा अविकल रूप से इंग्लैंड पहुँचने लगी।

इसके तत्काल बाद, एक के बाद एक अनेक बड़े आविष्कार हुए जिनमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 1764 में हाररीज्ज ने कताई की मशीन (स्पिनिंग-जेनी) का आविष्कार किया, 1765 में जेम्स वाट ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया और 1769 में इस इंजन को पेटेंट कराया, 1769 में आकराइट ने वाटर फ्रेम तैयार किया और 1775 में उसने रई की धुनाई, बिचाई और कताई की मशीनों को पेटेंट कराया, 1779 में फ्रापटन का मूल तैयार हुआ और 1785 में काराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। 1788 में लोहा गलाने की भट्टियों में भाप के इंजन का इस्तेमाल किया गया।

इन वर्षों में हुए तमाम आविष्कारों से पता चलता है कि इन मशीनों के इस्तेमाल के लिए सामाजिक परिस्थितियाँ तैयार हो चुकी थीं। पहले के आविष्कारों का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ था। 1733 में के ने अपनी 'फ्लाई शटल' मशीन को पेटेंट कराया और 1738 में ब्याट ने जल शक्ति से चलने वाली रोलर स्पिनिंग मशीन को पेटेंट कराया, लेकिन ऐसा लगता है कि इन आविष्कारों में से कोई भी काम में नहीं लाया गया।' (जो० एच० पैरीज 'दि इंडस्ट्रियल हिस्ट्री आफ माडर्न इंग्लैंड', पृष्ठ 16)

इंग्लैंड में औद्योगिक इतिहास के आधिकारिक विद्वान डा० कनिंघम ने अपनी पुस्तक 'ग्रोव आफ इंग्लिश इंडस्ट्री ऐंड बामस इन माडर्न टाइम्स' में बताया है कि आविष्कारों

के इस युग का विकास महज 'आविष्कारशील प्रतिभा के कुछ खास और रहस्यपूर्ण प्रस्फुटन' पर ही नहीं निभर करता था बल्कि इससे सबद्ध तथ्य यह था कि इंग्लैंड में उस समय तक इतनी पूजा जमा हो चुकी थी कि इन आविष्कारों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना संभव हो गया था।

आविष्कारों और नई खोजों को देखने से बहुधा ऐसा लगता है जैसे ये आकस्मिक हों, 18वीं सदी में लोग नए यंत्र समूहों को मौलिक प्रतिभा के एक विशेष और रहस्यपूर्ण प्रस्फुटन का परिणाम मानते हैं। लेकिन यदि यह कहा जाए कि आकराइड और वाट इस मामले में भाग्यशाली थे कि उनके लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी, तो इसका मतलब उनकी योग्यता को घटाकर देखना नहीं है। विलियम ली और डोरो डगले के समय से ही अनेक प्रवीण लोग रहे हैं लेकिन उनके जमाने की परिस्थितियाँ उनकी सफलता के लिए प्रतिकूल थीं।

महंगे साधनों या काफी खर्चीली प्रक्रियाओं की शुरुआत ने काफी तागत बढ़ा दिया है। कितना भी कर्मठ व्यक्ति क्यों न हो, जब तक उसके पास काफी पूजा न हो और उसकी पहुँच के अंदर व्यापक बाजार न हो, वह इस दिशा में प्रयास नहीं कर सकता। 18वीं सदी में ये परिस्थितियाँ ज्यादा से ज्यादा सुलभ हो रही थीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य बैंकों की स्थापना ने पूजा के निमाण को काफी बल दिया और किसी समय व्यक्ति के लिए अब यह काफी हद तक संभव हो गया था कि अपने व्यवसाय के प्रबंध को विकसित करने में महंगे साधनों का इस्तेमाल करे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।  
(डब्ल्यू० कनिंघम 'ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री ऐंड कामर्स इन माइन टाइम्स', पृष्ठ 610)

फिर भी, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना मात्र से पूजा का प्रारम्भिक सचय नहीं हो सका। 18वीं सदी के मध्य तक बैंकिंग पूजा और चल पूजा बम थी। फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अचानक पूजा का सचय कैसे हाने लगा? माकम न बताता है कि किस प्रकार पूजावाद के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं तथा उसके बाद के विकास की तरह ही आधुनिक विश्व में पूजा का सचय, और सब बातों से ज्यादा उपनिवेशों की लूट, मैक्सिको और दक्षिण अमरीका की चादी, गुलामों की तिजारात और भारत की लूटपाट से हुआ है। (आग्येर का कहना है कि यदि विश्व में मुद्रा का प्रवेश एक गाल पर जम जात धून के धब्बे से हुआ है तो पूजा का जन्म सर से परे तक एक एक रोम छिद्र धून और गदगो से तरबतर हुआ है। पूजा, पृष्ठ 1, अध्याय 31)। और 18वीं सदी में इंग्लैंड में अचानक बड़े पैमाने पर जो पूजा इकट्ठी हुई वह, अधिकांशतः, भारत की लूट से झट्टा पूजा थी।

बैंक आफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद 60 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसके पास सबसे छोटा नोट बीस पौंड का था। यह नोट इतना बड़ा था कि इसका प्रसारण आसानी से नहीं हो पाता था और तवाड़ स्ट्रीट से आगे तक शायद ही वह कभी गया हो। 1790 ई० में लिखते समय वह ने बताया था कि 1750 में जब वह इंग्लैंड पहुँचे थे तो विभिन्न प्रांतों में 'बारह बैकरा की दुकानें' 'ट्वल्व बैकस शाप्स' नहीं थीं हालाँकि उस समय (1790 में) ये दुकानें हर उस कस्बे में थीं जहाँ बाजार थे। इस प्रकार बंगाल से जो चांदी इंग्लैंड पहुँची उसमें मुद्रा की मात्रा ही नहीं बढ़ाई बल्कि इसकी गति भी तेज की क्योंकि तत्काल 1759 ई० में बैंक ने दस और पंद्रह पौंड के नोट जारी किए और प्राइवेट फर्मों ने देश में बाजार की बाढ़ ला दी। (शुक्लडम्स 'दि ला आफ सिविलाइजेशन ऐंड डिंक', पृष्ठ 263 64)

भारत की सचित्र निधि की बाढ़ ने, देश की नवद पूँजी में उल्लेखनीय वृद्धि करने में केवल उसकी ऊर्जा को बढ़ाया बल्कि उसकी गति को तत्तीला बनाया और उसमें तेजी ला दी। प्लासी के युद्ध के शीघ्र ही बाद बंगाल से लूटी गई संपत्ति लंदन पहुँचने लगी और इससे प्रभाव भी उसी समय दिखाई देने लगे। सभी आधिकारिक विद्वान इस बात पर एकरात हैं कि 19वीं सदी को सभी पूर्ववर्ती सदियों से अलग करने वाली महान घटना, अर्थात् 'औद्योगिक क्रांति', की शुरुआत 1760 ई० से हुई। वेस के अनुसार 1760 से पहले लक्काशायर में सूती कपड़ा बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती थी वह लगभग उतनी ही साधारण थी जितनी भारत में इस्तेमाल की जान वाली मशीन, जबकि 1750 के आसपास के वर्षों में ईंधन के काम के लिए जंगलों का नष्ट कर दिए जाने से इंग्लैंड का लोहा उद्योग पूरी तरह पतन की स्थिति में पहुँच गया था। उस समय देश में इस्तेमाल होने वाला पाँच में से चार हिस्सा कोयला स्वीडन से आता था।

प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई और इसके बाद जितनी तेजी से परिवर्तन हुए उसकी कोई मिसाल नहीं है। 1760 में प्लाइम गेटल का निर्माण हुआ और प्रगति के काम में लकड़ी की जगह पर कोयले का इस्तेमाल होने लगा। 1764 में हारबीज से स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, 1776 में फ्रायट ने मूल बनाया, 1785 में वाटराइट ने पावरलूम का पेटेंट कराया और इन सबमें महत्वपूर्ण काम 1768 में जेम्स वाट द्वारा भाप से चलता वाला इंजन (स्टीम इंजन) का आविष्कार था। ऊँचा के केंद्रीकरण के लिए जितनी भी योजनाएँ हुई थी उनमें यह सबसे पक्की योजना थी। लेकिन हालाँकि इन मशीनों का समय की गति का तेजी प्रदान करने में माध्यम का काम किया लेकिन ये वांछित तेजी नहीं प्रदान कर पायी। आविष्कार अपना आप में निष्क्रिय

विस्मय होते हैं। इनमें म अनेक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार सचानन के लिए आवश्यक पर्याप्त शक्ति एकत्र होने के इंतजार में शताब्दियां तक बेकार पड़े रहे। यह शक्ति हमेशा मुद्रा के रूप में और ऐसी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए जो वही जमाना हो बल्कि गति में हो। भारत की सचिंत निधि के इस देश में आने से पहले और इसका परिणामस्वरूप उत्पन्न भ्रष्टाचार के विस्तार से पहले किसी ऐसी शक्ति का अस्तित्व नहीं था जिसे पर्याप्त कहा जा सक और यदि जेम्स वाट अपने समय से 50 वर्ष पहले हुए होते तो अपने आविष्कार के साथ न जाने क्या खतम हो गए होते। संभवतः जबसे दुनिया की शुरुआत हुई है किसी पूजा निवेश में इतना जबरदस्त भुनाफा कभी नहीं हुआ जितना भुनाफा भारत की लूट में इंग्लैंड को हुआ क्योंकि लगभग 50 वर्षों तक ग्रेट ब्रिटेन को किसी भी प्रतियोगी का सामना नहीं करना पड़ा। 1694 से प्लासी के युद्ध (1757) तक विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। 1760 और 1815 के बीच विकास की रफ्तार काफी तेज और आश्चर्यजनक थी। (वही, पृष्ठ 259-60)

इस प्रकार भारत की लूट सचय का गुप्त स्रोत थी जिसने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

लेकिन जब एक बार भारत की लूट की मदद से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पूरी हो गई तो कारखाना में बने हुए ढेरों माल के लिए उपयुक्त बाजार ढूँढने का नया काम शुरू हुआ। इससे आर्थिक प्रणाली में एक क्रांति जरूरी हो गई जो व्यापारिक पूंजीवाद के सिद्धांतों से लेकर स्वतंत्र व्यापार वाले पूंजीवाद के सिद्धांतों तक सीमित थी। और इसने बदले में औपनिवेशिक व्यवस्था की पूरी पद्धति में तब्दीली ला दी।

नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि भारत में पुरानी इजारेदारी की जगह एक स्वतंत्र बाजार का निर्माण किया जाए। यह जरूरी हो गया कि भारत को सूती कपड़े का निर्यात करने वाले देश की स्थिति से हटाकर सूती वस्त्रों के आयात करने वाला देश के रूप में बदल दिया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक क्रांति हो। साथ ही इसका मतलब यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाए। भारत के शोषण के तरीकों में रूपांतरण की जरूरत महसूस की गई और इस रूपांतरण का स्वरूप ऐसा माना गया जिसकी रचना कंपनी के इजारेदारों के निहित स्वार्थों के जबरदस्त प्रतिरोध के बावजूद की गई।

इस परिवर्तन के लिए रास्ता तैयार करने की दिशा में शुरू के कदम 18वीं सदी के अंतिम पंद्रह वर्षों में पहले ही उठा लिए गए थे।

यह बात बहुत स्पष्ट थी कि कारगर ढंग से शोषण जारी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कमचारियों द्वारा लूटपाट का जो अराजक और विनाशकारी तरीका अपनाया जाता था वह परिवर्तन किए बिना जारी नहीं रह सकता था। कंपनी की बहूदा और भूखतापूर्ण लालची प्रवृत्ति शोषण के आधार को नष्ट कर रही थी। यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार इंग्लैंड में कुछ वर्षों बाद लकाशायर के निर्माताओं की असौम्य लालची प्रवृत्ति ने जनता की नौ पीढ़ियों को एक ही बार में नष्ट कर दिया। जिस प्रकार भविष्य में होने वाले शोषण के हित में पूंजीपति वर्ग की ओर से राज्य द्वारा की गई काय-वाही के जरिए निर्माताओं की लालची प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई, उसी प्रकार 18वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में राज्य के केंद्रीय अवयवों से अनुरोध किया गया कि वे भारत में कंपनी के कार्य संचालन को व्यवस्थित करें। यहाँ भी इस आक्रमण का खिलाफ अलग अलग द्वंद्वी हितों ने ही किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ अलग अलग जितने भी हित थे वे सब एकजुट हो गए थे और उन्होंने कंपनी के खिलाफ धावा बोल दिया था। इस आक्रमण के फलस्वरूप इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन के विरोध में व्यापक स्तर पर जो साहित्य आया वह संपूर्णता, प्रामाणिकता और विवेचन की दृष्टि से किसी भी युग में साम्राज्यवाद का भडाफोड करने वाले साहित्य में बेमिसाल था।

अंगरेज निर्माता पहले ही 18वीं सदी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान छेड़ चुके थे क्योंकि उन्हें भारत में बने अच्छे किस्म के कपड़ों के आयात के कारण बाजार में एक खतरनाक ढंग की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। 1720 ई० तक उन्हें एक काम में सफलता मिल गई, उन्होंने भारतीय सिल्क के कपड़ा और सूती कपड़ों के इंग्लैंड आने पर पूरी रोक लगवा दी और सूती कपड़े से बने प्रत्येक भारतीय सामान पर भारी सीमा शुल्क लगवा दी। कंपनी द्वारा भारतीय माल का व्यापार एक गोदाम व्यापार की तरह था। यह माल इंग्लैंड के बंदरगाहों से यूरोप को भेजा जाता था।

लेकिन 18वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों से जो नया आक्रमण शुरू हुआ वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समूचे भ्रष्ट एकाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध था। इस प्रहार को न केवल इंग्लैंड के उद्योगमान औद्योगिक निर्माताओं का समर्थन प्राप्त था बल्कि वे शक्तिशाली व्यापारी भी उसका समर्थन कर रहे थे जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारेदारी में कोई हिस्सा नहीं था। यह प्रहार नए विवासशील औद्योगिक पूंजीवाद के आने की पूर्व सूचना थी। उसकी मांग थी कि भारत के बाजार में सबको अपना माल बेचने की छूट होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार और लूट मार के कारण वहाँ के बाजार का शोषण करने के रास्ते में उत्पन्न रुकावटें दूर की जानी चाहिए।

यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के खिलाफ इस आक्रमण की शुरुआत 1776 में ऐडम स्मिथ ने की थी जो स्वतंत्र व्यापार के बलासिक्की अधशास्त्र के जनक और नए युग के अप्रदूत माने जाते हैं। 1776 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'वैल्यू ऑफ नेशनस' का राज-



नेताओं की नई पीढ़ी ने जिसका नतुत्व पिछ 7 किया था, अपना धमप्रय बना लिया था। इस पुस्तक में ऐडम स्मिथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समूचे आधार पर निममता से आक्रमण किया था और पुस्तक का एक छंड (सेक्शन 1) इसके लिए दिया। अपनी पक्की शास्त्रीय शैली में उन्होंने लिखा

ऐसी खास किस्म की कंपनी हर मामले में गड़बड़ी पैदा करती है। जिन देशों में यह काम कर रही होती है उनके लिए यह हमेशा ही कमो-कम असुविधा पैदा करती है और जिन देशों की इन कंपनियों के शासन के अंतर्गत रहने का दुभाग्य मित्र है उनका तो विनाश ही हो जाता है।

ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि प्रभुसत्ता सपन मानें तो उसका हित इसी में है कि उनके भारतीय प्रदेशों में यूरोप से जो सामान जाते हैं वे यथामूल्य सस्ती दर पर बेचे जाएं और वहां से जो भारतीय सामान मंगाए जाएं उनकी कीमत काफी अच्छी रखी जाए या यथासंभव महंगी दर पर बेचे जाएं। लेकिन इसकी उलटी स्थिति का अर्थ व्यापारी के रूप में उनके हितों की रक्षा करना होगा। जहां तक प्रभुसत्ता सपन होने की बात है उनके हित ठीक वही है जो उस देश के है जिस पर उनका शासन है। लेकिन यदि व्यापारी के हित के रूप में देखें तो यह हित पहली स्थिति के एकदम विपरीत मालूम होंगे।

यह एक खास तरह की सरकार है जिसमें प्रशासन का प्रत्येक सदस्य देश से बाहर जाना चाहता है और फलस्वरूप जितनी जल्दी संभव हो पाता है वह सरकार के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर लेता है। वह जैसे ही अपनी सारी संपत्ति के साथ देश छोड़कर जाता है, उसका उस देश के साथ सारा लगाव खत्म हो जाता है भले ही वह देश भूकंप से कभी न तहस नहस हो रहा हो। (ऐडम स्मिथ 'वैलथ आफ नेशंस', चौथा भाग, अध्याय 7)

प्रायः कोई धनी व्यक्ति, और कभी कभी साधारण व्यक्ति भी, महज इसलिए भारत के स्टाफ में हजार पौंड का दोयरे खरीदना चाहता है ताकि पोट आफ प्रोप्राइटीस में वोट देने का अधिकार उसे मिल जाए और इसी के आधार पर वह अपने को प्रभावशाली बना ले। हालांकि इससे वह भारत की लूट में कोई हिस्सा नहीं लेता लेकिन लुटेरों की नियुक्ति में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। वस्तुतः वह अपने इस प्रभाव का उपभोग कुछ वर्षों तक और अपने कुछ मित्रों के लिए कर सके। ऐसा करने में वह लाभार्थी की परवाह शायद ही करती है या शायद ही कभी यह सोचता है कि जिस स्टाफ पर उसका वोट आधारित है उसका मूल्य क्या है। महान साम्राज्य की समृद्धि के बारे में, जिसके प्रशासन में वोट का अधिकार मिलने से उसकी हिस्सेदारी पैदा होती

है, वह शायद ही कभी सोचता हो। आज तक कोई एमी प्रभुसत्ता देखने में नहीं आई अथवा देखने में नहीं आएगी जो अपनी जनता के सुख दुःख के प्रति इतनी ज्यादा उदासीन हो, अपने शासित प्रदेश के विकास या बरबादी के प्रति इतनी लापरवाह, अपने प्रशासन के गौरव या अपमान के प्रति इतनी निश्चित हो। (वही, पाचवा भाग, अध्याय 1)

यहां हम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक आधार के प्रति उभरते हुए निर्माताओं के विरोध की आवाज तथा पुरानी प्रणाली के ऊपर औद्योगिक पूंजीवाद की विजय के पूर्वाभास से परिचित होते हैं।

1782-83 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने आधार का विरोध और उस आधार में परिवर्तन की मांग का जायजा हमें हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति की बैठक की वाचवाही से मिलता है। 1783 में फॉक्स ने इंडिया बिल पेश किया जिसका उद्देश्य डायरेक्टरो और प्रोपराइटरो के कोटो को समाप्त करके सदन द्वारा उनकी जगह पर कुछ कमिश्नरो की नियुक्ति करना था। कंपनी ने इस बिल का विरोध किया और यह बिल पारित नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि फॉक्स की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और उसकी जगह पर पिट ने अपनी सरकार बनाई जो अगले बीस वर्षों तक सत्ता में रही। यह इतिहास का एक नाजुक मोड़ था और इस स्थल पर पता चला कि भारत इंग्लैंड की राजनीति का महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। 1784 में पिट ने इंडिया एक्ट पेश किया जिसमें हालांकि जटिल दाहरी व्यवस्था का विकल्प पेश करके फॉक्स के प्रस्ताव के साथ समझौता किया गया था, फिर भी उसमें राज्य द्वारा सीधे नियंत्रण के उसी बुनियादी सिद्धांत को स्थापित किया गया था। यह बिल हेस्टिंग्स तथा कंपनी के विरोध के बावजूद पारित हो गया। 1786 में लॉड बानबालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया ताकि वह प्रशासन में जबरदस्त परिवर्तनों को लागू कर सकें। 1778 में वारेन हेस्टिंग्स पर, जो 1772 से 1785 तक गवर्नर और गवर्नर जनरल के रूप में काम कर चुके थे, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा वस्तुतः एक सरकारी कदम था जिसकी सीधे तौर पर पिट के फौमले से ऐसा करने का अधिकार मिला था और इस काम के लिए पिट को फॉक्स, बक और शेरीडान जैसे प्रमुख सांसदों का समयन प्राप्त था। यह मुकदमा व्यक्ति के खिलाफ इतना नहीं, जितना कि एक व्यवस्था के खिलाफ था।

इस आक्रमण के तेज होने के काम में फॉक्स की क्रांति जैसी महत्वपूर्ण विश्वव्यापी समस्याओं से बाधा पड़ती। इसने पिट के प्रशासन के सुधारवादी दौर को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड के पूंजीपति वर्ग को विश्व की प्रतिस्पर्धाकारी शक्तियों के नेता के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। बक ने भारत में अत्याचार और कुप्रशासन की जबरदस्त भर्तना का रास्ता छोड़ दिया हालांकि अपनी इन्हीं भर्तनाओं के कारण वे उदारवादी सत्ता की

प्रशमा हासिल कर सके थे। अब वे और भी तीव्रता के साथ फ्रांस में मुक्ति के लिए लड़ रही जनता की भूमना करने लगे और ऐसा करते-उह यूरोप के सम्राट और महा राजाओं की प्रशमा प्राप्त हुई। यह एक दिलचस्प बात है कि भारत में गवर्नर की कौंसिल के सदस्य फिलिप फ्रांसिस ने जिहान कौंसिल में हर्स्टिग के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी और हर्स्टिग पर मुकदमा चलाने के लिए बक को आवश्यक सामग्री प्रदान की थी, फ्रांस की क्रांति के सदर्भ में प्रतिक्रियावादी भूमिका निभाने के लिए बक का एक बहुत ही कठोर पत्र लिखा। हर्स्टिग पर मुकदमा सात वर्षों तक चला और 1795 में हर्स्टिग का सभी आरोपों से बरी करते हुए यह मुकदमा समाप्त हो गया। पिट स्वतंत्र व्यापार की दिशा में अपनी प्रारम्भिक योजनाओं से हटकर फ्रांस के युद्ध को सुरक्षा देने की प्रणाली में विश्वास करने लगे। 1813 में फ्रांस के युद्ध के समाप्त होने और औद्योगिक पूँजी के मजबूती से स्थापित होने के साथ ही भारत का मसला नए सिरे से उठाया गया और नई अवस्था की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया।

लाड वानवालिस ने गवर्नर जनरल की हैसियत से प्रशासन में नए सिरे से सुधार किए ताकि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मनमानी लूट और भ्रष्टाचार के तरीके की जगह पर अच्छे वेतन पान वाले सरकारी अफसरों की नियुक्ति की जा सके। उन्होंने मनमाने ढंग से लगातार बढ़ती जा रही मालगुजारी को समाप्त करने की कोशिश की ताकि देश को वीरान बनने से बचाया जा सके और शोषण के आधार को समाप्त किया जा सके। इस कोशिश में उन्होंने बंगाल के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया जिससे ब्रिटिश राज के सामाजिक आधार के रूप में जमींदारों के नए वर्ग का जन्म हुआ और इस वर्ग से सरकार को स्थाई तौर पर एक निश्चित रकम मिलने लगी।

इन सारे उपायों का उद्देश्य सुधार करना था। दरअसल इन उपायों के जरिए समूचे पूँजीपति वर्ग के हित में भारत का अधिक वैज्ञानिक ढंग से शोषण करने के लिए आधार तैयार किया गया था। इन परिवर्तनों में औद्योगिक पूँजी द्वारा शोषण के नए चरण का मांग प्रशस्त किया ताकि भारत की समूची अर्थव्यवस्था के शोषण को जो पहले बहुत अव्यवस्थित ढंग से लूटपाट के जरिए किया जाता था अब एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया जा सके।

### 3 उद्योग के क्षेत्र में तबाही

1813 में उद्योगपतियों तथा अन्य व्यापारियों का हमला अंततः सफल हो गया और भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में औद्योगिक पूँजीवादी शोषण का नया दौर 1813 से शुरू हो गया।

1813 से पहले भारत के साथ अप्रशासित व्यापार होता

1883 में

प्रकाशित अपनी पुस्तक 'एक्स्पेंशन आफ इंग्लैंड' में, 19वीं सदी में हुए रूपांतरण को रेखांकित किया है

मक कुलाच ने एडम स्मिथ के अपने संस्करण में भारत के बारे में टिप्पणी करते हुए बताया है कि 1811 के आसपास, अर्थात् कंपनी के एकाधिकार के समय भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार नगण्य था जो इंग्लैंड और जर्सी या आइल आफ मैन के बीच हो रहे व्यापार से थोड़ा ही अधिक महत्वपूर्ण था

लेकिन आज जर्सी या आइल आफ मैन के बजाय भारत के साथ अपने व्यापार की तुलना में हम अमरीका या फ्रांस के साथ अपने व्यापार से करते हैं— इंग्लैंड का माल आयात करने में अमरीका के बाद अब भारत का स्थान है और फ्रांस तथा अन्य देशों का स्थान भारत के बाद जाता है। (जे० आर० सीले 'एक्स्पेंशन आफ इंग्लैंड,' 1883, पृ० 299)

इसी प्रकार 1812 में कंपनी की आधिकारिक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि उन दिनों भारत का महत्व इंग्लैंड के माल की मंडी के रूप में नहीं बल्कि लूटपाट या बर नजराने आदि के साधन के रूप में था

इस देश के लिए उस विशाल साम्राज्य के महत्व का आकलन इस बात से नहीं किया जाना चाहिए कि इस देश के निर्माता भारतवासियों द्वारा अपने माल के उपभोग से कितना फायदा उठाते हैं बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि उससे राज्य की धन संपत्ति में प्रतिवर्ष कितनी बड़ी वृद्धि होती है। (1812 के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट जिस प्रसाद में अपनी पुस्तक 'सम एसपैक्ट्स आफ इंडियाज फार्च्युन ट्रेड' में पृष्ठ 49 पर उद्धृत किया है।)

सरकारी आदेशपत्र के उद्घोषण और एकाधिकार की समाप्ति से पूर्व 1813 की नवसदीय जाच की कानूनी प्रक्रिया से पता चलता है कि उस समय की चिंतन धारा किस तरह बदल गई थी और उसकी दिशा ब्रिटेन के नए उभरते हुए मशीन उद्योग के लिए बाजार के रूप में भारत का विकास करने पर केंद्रित थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किस प्रकार पुरातन विचारधारा के बारे में हस्तिगर्ज जैसे प्रतिनिधियों ने इस सम्भावना में इशारा किया था कि भारत का एक मंडी के रूप में विकास हो सकता है।

जिस समय यह जाच काय संपन्न किया गया, ब्रिटेन जाने वाले भारतीय सूती वस्त्र पर 78 प्रतिशत 'गुल्फ' लगता था। यदि ये निषेधात्मक 'गुल्फ' नहीं होते तो अपने प्रारम्भिक दौर में ब्रिटिश कंपनी उद्योग का विकास नहीं हो पाता।

प्रमाणों में यह बताया गया था (1813 में) कि इस अवधि तक भारत में बने सूती और रेशमी कपड़ों को इंग्लैंड में बने कपड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कम कीमत पर ब्रिटिश बाजार में बचकर मुनाफा कमाया जा सकता था। फलस्वरूप यह जरूरी हो गया था कि इंग्लैंड में बने कपड़ों को उनके मूल्य पर 70 प्रतिशत और ६० प्रतिशत शुल्क या मुनिश्चित निषेध लगाकर बचाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसे निषेधात्मक गुल्को और सरकारी आदेशों का अस्तित्व नहीं होता तो पैस्ले और मानचेस्टर के कारखाने शुरू में ही ठप हो जाते और भाप की शक्ति से भी शायद ही दुबारा चालू हो पाते। इनका निर्माण भारतीय निर्माताओं के बलिदान से हुआ। (एच० एच० विल्सन 'हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया,' खंड 1, पृष्ठ 385)

ब्रिटिश सूती कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं पर लगाए गए सीमा शुल्क में भेदभाव का सिलसिला 19वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ। 1840 को सस दीय जाच में यह बताया गया कि भारत जाने वाले ब्रिटिश सूती और रेशमी सामानों पर जहां 3.5 प्रतिशत और ऊनी सामानों पर 2 प्रतिशत कर देना पड़ता है वहीं ब्रिटेन आने वाले सूती कपड़ा पर 10 प्रतिशत, रेशमी कपड़ा पर 20 प्रतिशत और ऊनी कपड़ों पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है।

इस प्रकार भारतीय मंडी में ब्रिटिश निर्माताओं का प्रभुत्व कायम करने और भारतीय कारखाना उद्योग को नष्ट करने में मशीन उद्योग की तकनीकी श्रेष्ठता का ही हाथ नहीं था बल्कि एकतरफा स्वतंत्र व्यापार (ब्रिटिश सामानों का भारत में एकदम निशुल्क प्रवेश या लगभग निशुल्क प्रवेश, लेकिन ब्रिटेन के बाजार में भारतीय माल जाने पर सीमा शुल्क लगाया जाना तथा नौ संचालन कानूना यानी रेवीगेशन ऐक्ट्स के जरिए यूरोपीय देशों या अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार पर रोक लगाना) के लिए सरकार की जोर से दी गई प्रत्यक्ष सहायता का भी हाथ था।

19वीं सदी के पूर्वार्ध में यह प्रणिया निर्णायक रूप से जारी रही हालांकि इसके प्रभाव समूची 19वीं शताब्दी यहां तक कि 20वीं शताब्दी में भी देखे गए। ब्रिटिश निर्माताओं की इस प्रगति के साथ साथ निर्माताओं की अवनति चलती रही।

1814 और 1835 के बीच इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों की भारत में खपत 10 लाख गज से कुछ कम से कम 5 करोड़ 10 लाख गज से भी अधिक हो गई। इसी अवधि में ब्रिटेन के बाजार में जाने वाले भारतीय सूती कपड़ों के कटपीसा की मध्या साइड बारह लाख से घट कर 3 लाख 6 हजार हो गई और 1844 तक तो यह गणना महज 61,000 ही रह गई।

मूल्य में व्याप्त विषमता भी कम चौकान वाली नहीं है। 1815 और 1932 के बीच

निर्यात किए गए भारतीय सूती कपड़े का मूल्य 13 लाख पौंड से घटकर 1 लाख पौंड हो गया अर्थात् सत्रह वर्षों में व्यापार में 12/13 का नुकसान हुआ। इसी अवधि में ब्रिटन से भारत में आए सूती कपड़े का मूल्य 26,000 पांड से बढ़कर 400,000 पौंड हो गया अर्थात् 17 गुनी वृद्धि हुई। 1850 तक स्थिति ऐसी हो गई कि भारत जो कई सौ वर्षों से समूची दुनिया को अपना कपड़ा भेजता आ रहा था वह निर्यात किए जाने वाली कुल ब्रिटिश सूती कपड़े का एक चौथाई हिस्सा अपने यहां मगाने लगा।

इंग्लैंड के मशीन से बने कपड़ों में जहां भारत के बुनकरों को बरबाद किया वहीं दूसरी तरफ मशीन के बने सूत ने भारत के सूत कातने वालों को उजाड़ दिया। 1818 से 1836 के बीच भारत में इंग्लैंड के बने सूत का निर्यात 5200 गुना हो गया।

यही हालत रेशमी कपड़ों, ऊनी कपड़ों, लोहे बतन, काच और कागज के मामले में भी देखी जा सकती है।

भारत के उद्योग वर्गों के इस व्यापक विनाश का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों की तबाही के साथ साथ नए मशीन उद्योग का विकास भी हुआ था। लेकिन भारत में, लाखों शिल्पियों और कारीगरों की तबाही के साथ विकल्प के रूप में किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। पुराने और घनी आबादीवाले औद्योगिक नगर ढाका, मुर्शिदाबाद (जिसे क्लाइव ने 1757 में 'लंदन जितना ही विस्तृत, उतनी ही अधिक आबादीवाला और उतना ही समृद्ध' कहा था), सूरत आदि 'ब्रिटन की कृपा' से देखते ही देखते ऐसे उजाड़ हो गए कि भीषणतम युद्ध होने पर या विदेशी विजेताओं के शिकार हान पर भी उनकी वंसी दशा नहीं होती। सर चार्ल्स ट्रेवेलन ने 1840 में मसदीय जाच का बताया कि ढाका शहर की आबादी 150 000 से घटकर 30 000 या 40 000 हो गई और एक जमाने में भारत का मैनचेस्टर समझा जाने वाला यह शहर अब तेजी से जंगल बनता जा रहा है और मलेरिया का शिकार हो रहा है। अत्यंत समृद्ध नगर से घटकर इसकी स्थिति अब अत्यंत गरीब और छोटे नगर की हो गई है। निम्सनेह उनकी भयंकर दुर्गति हुई है।' ब्रिटिश साम्राज्य से प्रारंभिक इतिहासकार माटगोमरी मार्टिन ने इसी जाच के दौरान बताया कि 'सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानों की बरबादी, जहां दशों निर्माता उत्पादन में लगे थे, अत्यंत दुःखद यथार्थ है जिसपर विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि व्यापार का कोई उचित तौर तरीका है। मेरे विचार में यह बमजोर के विपरीत गजबूत की शक्ति का प्रयोग है।' 1890 में सर जेम्स स्काटन ने लिखा 'आज से भी से भी कम वर्ष पहले ढाका का कुल व्यापार अनुमानतः 1 करोड़ रुपये का था और यहाँ की आबादी 200 000 थी। 1787 में 30 लाख रुपये मूल्य की ढाका की मलमल इंग्लैंड भेजी गयी 1917 में यह विलुप्त हो गया। अगम्य जोर औद्योगिक आबादी की रोजगार दन वाली कलाई और बुनाई की कला अब लुप्त हो गई। जो परिवार पहले

काफी समृद्ध थे उन्हें अन्न मजदूर होकर शहरों को छोड़ना पड़ा है और गावों में जाकर अपनी जीविका का काई प्रबंध करना पड़ा है। पत्तन की यह स्थिति ढाका में ही नहीं बल्कि सभी जिलों में है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मिलता जब कमिश्नर और जिला के अधिकारी इस बात की ओर सरकार का ध्यान न आकर्षित करते हों कि देश के सभी हिस्सों में उद्योगधंधों से रोजी रोटी चलाने वाला वर्ग कमाल होता जा रहा है।'

1911 की जनगणना रिपोर्ट से पता चलता है कि यह प्रक्रिया उस समय भी जारी थी। उदाहरण के लिए 1911 की रिपोर्ट से पता चलता है कि सूती वस्त्र में लगभग चारियों की संख्या में पूर्ववर्ती 10 वर्षों में 6 प्रतिशत की कमी आई है, यह कमी उस समय तक सूती वस्त्र निर्माण के क्रमशः विस्तार के बावजूद आई है। इस कमी का श्रेय 'हाथ से सूत की बुनाई का काम लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाने' को है।

1911 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार खाल, चमड़ा और धातु के काम में लगने वाले लोगों की संख्या में 6 प्रतिशत की कमी आई हालांकि इसके साथ धातु व्यापारियों की संख्या में 6 गुनी वृद्धि हुई। इसका कारण साफतौर पर बताया गया कि

धातुकर्मियों की संख्या में कमी और इसके साथ ही धातु व्यापारियों की संख्या में वृद्धि का कारण मुख्यतः यह था कि देश में बने पीतल और तांबे के बर्तनों की जगह पर यूरोप से आयात किए गए कलईदार बर्तन और अल्युमिनियम के सामान का इस्तेमाल होने लगा। (सेसस आफ इंडिया रिपोर्ट, 1911)

सादा और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने का मिली

जिन जिन क्षेत्रों में रेलें पहुंच सकती थी वहां वहां सस्ता विदेशी लोहा और इस्पात पहुंच गया जिससे लोहा चलाने वाला देशी उद्योग व्यवहार में समाप्त हो गया। फिर भी इस प्रायद्वीप के दूरवर्ती इलाकों में इसका आज भी चलन है। ('इपीरिमल गजेटियर आफ इंडिया,' 1907, पृष्ठ 3 पृष्ठ 145)

भारत में इस्पात का इस्तेमाल हथियार बनाने, मजबूत के सामान तैयार करने और जोड़ार बनाने में किया जाता था तथा इससे अत्यंत उच्च बोर्डिंग के सामान तैयार किए जाते थे। पुराने हथियारों का काई मुकाबला नहीं है और कहा जाता है कि दक्षिण की मशहूर तलवारें जिस इस्पात से डालकर बनाई गई थी वह हैरामाद (भारत) से बेजा गया था। जिल्सी का मशहूर लोहा मशहूर मुत्तु म्मत्तु म्मत्तु का वजन 6 टन से अधिक है और उस पर अति मृत्ति के बीच की रचना 415 ई० पू० की है। काई भी आज तक यह नहीं समझा पाया कि उस समय इतनी बड़ी तलवारें कैसे संभव हो सकीं। लोहा चलाने वाली

भट्टिया के भारत भर में जो अवशेष मिलते हैं वे मूलतः वैसे ही हैं जैसे आधुनिक काल से पूर्व के यूरोप में थे

अगडिया या लोहा गलाने वाली जाति दूर दूर तक फैली थी और अनेक जिलों में कच्चा लोहा बनाने वालों के लिए लोहार शब्द इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मस्ते ढग से तैयार किए गए यूरोपीय लोह ने उनका लगभग सारा व्यापार छीन लिया है और अधिकांश अगडिया अब अकुशल मजदूर बनकर रह गए हैं। आज से सवा सौ वर्ष पहले डा० फ्रांसिस बुकानन को इस तरह के अनेक लोहा गलाने वाले मिले थे। (डी० एच० बुकानन डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट एटरप्राइज इन इंडिया, 1934, पृष्ठ 274)

केवल पुराने औद्योगिक नगर और केंद्र ही विनष्ट नहीं हुए और उनकी आबादी उजड़कर गांवों में भर गई और गांवों में ज्यादा भीड़भाड़ हो गई बल्कि सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांवों की पुरानी अव्यवस्था तथा कृषि एवं घरेलू उद्योग की एकता के आधार पर मरणांतक प्रहार हुआ। शहरों और गांवों दोनों स्थानों में रहने वाले लाखों शिल्पियों और कारीगरों, कातनेवालों, बुनकरों, कुम्हारों और लोहा गलाने वालों, लोहारों के मामले खेती करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बच रहा। इस प्रकार भारत, जो कृषि और उद्योग की मिलीजुली पद्धतिवाला देश था अब जबरन ब्रिटन के कारखानेवाले पूंजीवाद का कृषीय उपनिवेश बना दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल के इन्हीं दिनों से और ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप भारत में खेती पर वह घातक दबाव शुरू होता है जिसे सरकारी दस्तावेजों में बड़ी सहजता के साथ पुराने भारतीय समाज की एक स्वाभाविक घटना का नाम दिया जाता है और जिसे अनान और सतही लोगों द्वारा 'अत्यधिक आबादी' के लक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल, कृषि पर भारी सख्तायों में लोगों की निभरता ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही बढ़ी जो केवल 19वीं सदी में ही नहीं बल्कि 20वीं सदी में भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसकी पुष्टि जनगणना के आंकड़ों को देखने से हो जाती है (1891 से 1921 के बीच कृषि पर निभर आबादी 61 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई, इन आंकड़ों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए अध्याय 7 देखें)।

1840 में ही माटगोमरी मार्टिन ने पूर्वोद्धृत संसदीय जांच समिति के सामने इस खतरे के प्रति चेतावनी दी थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को 'इंग्लैंड के कृषि फाम के रूप में' तब्दील करने की कोशिश कर रही है

मैं यह नहीं मानता कि भारत एक कृषिप्रधान देश है, भारत जितना कृषिप्रधान देश है उतना उद्योगप्रधान भी है और जो उसे कृषिप्रधान देश की स्थिति तक लाना चाहता है वे संभ्रमता के पैमाने पर उसका ध्यान नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि भारत इंग्लैंड का कृषि फाम बनगा, भारत एक शिल्पप्रधान



देश है, विभिन्न कोटि के उसके उत्पादनों का युगों से अस्तित्व रहा है और कोई भी देश ईमानदारी से चलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है—अब उसे कृषिप्रधान देश के दर्जे पर ला देना भारत के साथ अयाय करना होगा।

1829 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो व्यापार के एकाधिकार से वंचित हो गई थी और इसलिए जिसकी दित्तचस्पी व्यापार के दयाय अब मालगुजारी में ज्यादा हो गई थी, भारत में चल रही 'व्यापारिक क्रांति' का अत्यंत निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया। गवर्नर जनरल लॉड विलियम कैवेंडिश 'पेंटिक' के 30 मई 1929 के काय विवरण से इसका पता चलता है जिसमें कोट आफ डायरेक्ट्स का दृष्टिकोण दिया गया है

कोट की सहानुभूति व्यापार परिपद (बोर्ड आफ ट्रेड) की उस रिपोर्ट से काफी बढ़ गई है जिसमें व्यापारिक क्रांति के प्रभावों की निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है। इसकी वजह से भारत में विभिन्न वर्गों के लोगों को इस समय इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है जिसकी व्यापार के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है।

लेकिन कारखानेदारों के हित आगे बढ़ते जाने के लिए कृतमकल्प थे। 1840 में ससदीय जाच में मैकलेसफील्ड के एक निर्माता श्री कोप ने कहा 'मैं निश्चित रूप से भारतीय मजदूरों की स्थिति पर रहम खाता हूँ लेकिन साथ ही मुझे भारतीय मजदूर के परिवार से ज्यादा चिंता अपने परिवार की है। चूंकि भारतीय मजदूर के परिवार की स्थिति मुक्त बदतर है इसलिए उनके लिए मैं अपने परिवार की सुख सुविधाओं की बलि चढ़ा दूँ, मेरे स्थाल में यह चलत है।'।

भारत के लिए औद्योगिक पूँजीपतियों की नीति बड़ी साफ थी भारत को ब्रिटिश पूँजीवाद का कृषिप्रधान उपनिवेश बनाना कच्चे माल की यहाँ से सप्लाई करना और तयार माल को भारत में बेचना। इस नीति का 1840 में मैनचेस्टर चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष थामस बैजले ने अपन लक्ष्य के रूप में काफी स्पष्ट कर दिया था

भारत एक विशाल देश है और यहाँ की आबादी इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश माल खरीदा करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। भारतीय व्यापार के सबध में हमारे सामने समूची समस्या यह है कि हम जो माल वहाँ भेजने को तैयार हैं उसकी कीमत क्या भारत के लोग अपने धरती के उत्पादना में अदा कर सकते हैं ?

यहाँ भारत के नए युग के शापण का जो हिसाब लगाया गया है वह उतना ही स्पष्ट और बिना लाग-लपट का है जितना 75 वर्ष पहले क्लाइव ने भारत के पुराने युग के शोषण का हिसाब लगाया था, जिस पढ़ने ही उद्धृत किया जा चुका है।

भारत के बाजार को विवसित करने के लिए यह आवश्यक था कि उत्पादन को बढ़ाया जाए और भारत से होने वाले कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि की जाए। ब्रिटिश नीति ने अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पैतरा बदला

शुरू के 50 वर्षों में इंग्लैंड के लिए भारत के महत्व का कारण यह था कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक कच्चे माल, चमड़ा, तेल, रंग, पटसन और कपास की सप्लाई करता था और साथ ही इंग्लैंड के उत्पादनकर्ताओं के लिए लोहे और कपास का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भी प्रदान करता था। (एल० सी० ए० नावेल्स 'इकनामिक डेवलपमेंट आफ दि आवरसीज एषायर,' पृष्ठ 305)

अंगरेजों की नीति के एक नए चरण में प्रवेश करने का संकेत 1833 में उसी समय मिल गया जब अंगरेजों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे भारत में जमीन खरीद सकते हैं और बागान लगा सकते हैं। उसी वर्ष वेस्ट इंडीज में गुलामी की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। उसके तत्काल बाद भारत में बागानों की यह नई प्रणाली जारी करना एक क्षीने पदों के आवरण में गुलामी व अलावा और कुछ नहीं था। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में शुरू शुरू में जिन लोगों ने बागानों का काम शुरू किया उनमें से अधिकांश वेस्ट इंडीज के गुलामी के मालिक थे (वेस्ट इंडीज से अनुभवी बागान मालिक यहां लाए गए इस क्षेत्र में उजड़ू किस्म के बागान मालिकों ने प्रवेश किया जिनमें से कुछ अमरीका में गुलामी के मालिक थे और वे अपने साथ दुर्भाग्यपूर्ण आदतें और तौर तरीके लाए।' बुकानन 'डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट एटरप्राइज इन इंडिया,' पृष्ठ 36-37)। इनके भयंकर परिणाम 1860 में नील आयोग (इंडीगो कमीशन) के सामने उद्घाटित हुए। आज दस लाख से भी अधिक मजदूर चाय, रबड़ और काफी के बागाना मजदूर हैं अर्थात् कपड़ा मिला कोयला खानों, इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात उद्योगों में मजदूरों की लगभग दो तिहाई संख्या बागानों में काम करती है।

अर्थात् तीस गुना वृद्धि हुई। 1849 में 68 हजार पौंड के पटसन का निर्यात किया गया था जो 1914 में बढ़कर 86 लाख पौंड हो गया अर्थात् 126 गुना वृद्धि हुई।

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस भारत से अधिक से अधिक माल बाहर भेजा जाने लगा जहाँ लोग खुद भूख से ग्रस्त थे। 1849 में 8 लाख 58 हजार पौंड की कीमत का अनाज बाहर भेजा गया, इसमें मुख्यतया चावल और गेहूँ बाहर भेजा गया था। 1858 तक 38 लाख पौंड की कीमत का अनाज बाहर गया जो 1877 में बढ़कर 79 लाख पौंड, 1901 में 93 लाख पौंड और 1914 में 1 करोड़ 93 लाख पौंड हो गया अर्थात् इसमें 22 गुना वृद्धि हुई।

इसके साथ साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अकालों की संख्या और भयावहता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सात बार अकाल पड़े थे जिनमें अनुमानतः 15 लाख लोग मौत के शिकार हुए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 24 बार अकाल पड़ा (1851 से 1875 के बीच 6 बार और 1876 से 1900 के बीच 18 बार) जिनमें सरकारों आकड़ों के अनुसार अनुमानतः 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। मोट तौर पर कहा जाए तो 19वीं सदी के अंतिम तीस वर्षों में अकाल और खाद्यान्नों की जितनी कमी हुई वह एक सौ वर्ष पहले की तुलना में चार गुना अधिक और चार गुना ज्यादा व्यापक थी।' (डब्ल्यू. डिग्वी. फ्रांसपेरस ब्रिटिश इंडिया, 1901) डब्ल्यू. एस. लितीन अपनी पुस्तक 'इंडिया ऐंड इट्स प्राब्लम्स' में सरकारी अनुमानों के आधार पर अनाज से होने वाली मृत्यु के निम्न आकड़े दिए हैं

| वर्ष      | अकाल से होने वाली मौतों की संख्या |
|-----------|-----------------------------------|
| 1800-25   | 1,000,000                         |
| 1825-50   | 400,000                           |
| 1850-75   | 5,000,000                         |
| 1875-1900 | 15,000,000                        |

1878 में एक अनाज आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए अनाज की समस्या पर विचार करना था। आयोग की रिपोर्ट 1880 में प्रकाशित हुई और इसमें बताया गया कि भारत में अनाजों के विनाशकारी परिणामों का एक मुख्य कारण और राहत पहुँचाने का काम सरकारें नहीं करती हैं यह है कि यहाँ की किसान जनता प्रत्यक्ष रूप से श्रम पर निर्भर है और यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसके सहारा आबादी का उन्नयन नौवें हिस्से अपना काम चला सके।

भारत में नागा की गरीबी और खाद्यान्नों के मजदू के समय उत्पन्न घटते की जड़ में

महत्वपूर्ण बात वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें आबादी का अधिकांश भाग महज खेती पर निर्भर है। साथ ही वर्तमान घुराइयो को दूर करने के लिए ऐसा कोई भी उपाय पूरी तरह प्रभावकारी नहीं हो सकता जिसमें लोगो के लिए विभिन्न किस्म के धंधे जारी करना शामिल न हो। इसका कारण यह है कि आबादी का अतिरिक्त हिस्सा जो आज खेती में लगा हुआ है उसे वहां से हटाने के लिए उद्योग धंधो में या इसी तरह के किसी रोजगार में लगाने की जरूरत है। (इंडियन फेमिन कमीशन रिपोर्ट, 1880)

इन शब्दों के साथ औद्योगिक पूंजी ने भारत में अपने कारनामों पर खुद ही फैसला दे दिया।

### पाद टिप्पणी

- 1 इस अध्याय की अधिकांश सामग्री के लिए जार० सी० दत्त की पुस्तक 'इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अन्डर जर्नी ब्रिटिश रूल' (1901) और 'इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन दिक्टोरियन एज' (1903) के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। ये पुस्तकें 19वां सदी के अंत तक के विकास के बारे में सर्वाधिक आधिकारिक अध्ययन प्रस्तुत करती हैं।

## भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद

प्रशासन और शोषण यहाँ साथ साथ चलते हैं  
1905 में लाड कजन का वक्तव्य ।

1914-18 के युद्ध के बाद से आमतौर पर यह धारणा बन गई कि भारत में साम्राज्यवाद एक ऐसी नई अवस्था में पहुँच चुका है जो अपने पूर्ववर्ती काल से लगभग एकदम भिन्न है।

राजनीतिक क्षेत्र में, यह समझा जाता है कि पुरानी निरक्षुब्धता की समाप्ति 1917 की घोषणा के साथ हो गई जिसने 'साम्राज्यवाद के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना' के नए लक्ष्य का वादा किया था, और बाद के इतिहास को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की 16 मई 1946 की घोषणा के जरिए इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति की दिशा में एक के बाद एक साविधानिक सुधारों के द्वारा क्रमिक विकास (जनता के विरोध और असहयोग के दौर से विकृत) के इतिहास के रूप में देखा गया।

यह समझा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में भारत के औद्योगिक विकास के लिए पुराने अहस्तक्षेपपूर्ण विरोध ने एक नए दृष्टिकोण को स्थान दिया जो ब्रिटिश शासन की प्रोत्साहनकारी देखरेख के अंतर्गत तथा ब्रिटिश पूँजी के साथ भारत को एक आधुनिक औद्योगिक देश के रूप में बदल रहा है। 1918 के बाद के वर्षों के तथ्यों की बारीकी से जाँच करने से पता चलेगा कि ये तथ्य साम्राज्यवाद के ह्रास-मुख दिनों में उसकी प्रगतिशील तस्वीर खोजने में असमर्थ है।

निस्संदेह, भारत के पुराने मुक्त व्यापारवाले औद्योगिक पूँजीवादी शोषण से एक नया रूपांतरण हुआ है। लेकिन परिवर्तन की निर्णायक शुरुआत दरअसल, 1914 के युद्ध के

द्वारा नहीं हुई, सरसरी तौर पर देखने से यह लग सकता है कि उसने पुराने आर नए के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध और उसके दूरगामी प्रभाव परिवर्तन की उस प्रक्रिया के बीच में आ टपटे जो 20वीं सदी के शुरू के 15 वर्षों में जारी थी। यह परिवर्तन मुक्त व्यापारवादी औद्योगिक पूँजीवादी अवस्था की महाजनी पूँजी और भारत में इसके शासन के सक्रमण द्वारा हुआ। इस मनमन की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी थी।

1914 के युद्ध ने समूचे घटनाक्रम को तेज कर दिया और उन्हें आगे बढ़ा दिया, साथ ही पूँजीवाद के आम सकट को खोलकर उसने एक के बाद एक ऐसे राजनीतिक जन आदोलनों की शुरुआत की जिनसे भारत इसके पहले अपरिचित था। इस दोहरी प्रक्रिया से आधुनिक काल के भारत का विशिष्ट चरित्र उभरता है। इसी के साथ इस काल के भारत में महाजनी पूँजी के शासन के सभी लक्षणा को देखा जो इसके प्रारम्भिक दौर में अधूरे रूप में विद्यमान थे। इसके सबके साथ ही, जनप्रहार की एक लहर चल पड़ी जिसने साम्राज्यवादी प्रभुत्व की नींव को हिला दिया। इन दो संचालक शक्तियों ने आज नए भारत की रचना की है।

भारत में जो साविधानिक सुधार हो रहे हैं वे कोई आज की खोज नहीं है। य 1861 के कौन्सिल ऐक्ट (ई० ए० हान ने अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया' में बताया है कि इस ऐक्ट ने 'ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधि सत्त्वात्मा के आरम्भिक बीज बोए थे) 1865 और 1882 में म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्गों के विकास, 1892 के कौन्सिल ऐक्ट और 1909 के मोरले मिंटो सुधारों के समय से निरंतर विवसित हुए हैं। आधुनिक युग की शुरुआत आमतौर से 1917 की घोषणा से मानी जाती है पर इसकी वास्तविक शुरुआत 1914 के एकदम पहले के वर्षों में मोरले मिंटो सुधारों के साथ ही हो गई थी। इसने सत्ता की वास्तविकता को बनाए रखने के साथ साथ बहुप्रचारित उदार सुधारों और रियायतों (बल प्रयोग के साथ साथ) की प्रक्रिया का श्रोगर्णेश किया। यह सही है कि मोटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने अपनी खुद की प्रगति का महत्व जतलाने के लिए मोरले मिंटो सुधारों की निंदा करने और उनका महत्व कम आकन की कोशिश की (उस क्षण के उत्साह में उनके लिए बड़े बड़े दावे किए गए), लेकिन द्वितत्त्व की उसकी खुद की पद्धतियों की भी उसके उत्तराधिकारियों द्वारा कम निंदा नहीं की गई। यह सभी मानते हैं कि प्रारम्भिक योजना ने स्वशासन नहीं प्रदान किया, लेकिन यह आलाचना बाद की योजनाओं पर भी लागू होती है। 1918 के बाद के वर्षों को ब्रिटिश जनता के सामने भले ही इस रूप में पेश किया गया हो जिसमें सत्ता द्वारा रियायतें दी जाने की बात शामिल हो लेकिन भारतीय जनता के सामने एक दूसरी ही तस्वीर थी। इस दौर के बारे में बताया गया है कि रियायतों के साथ साथ व्यापक और घोर दमन का सिलसिला जारी रहा, अभूतपूर्व पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, व्यापक स्तर पर हिंसा हुई और जगह जगह गोлия चली तथा निपेघात्मक कानून लागू किए गए।

इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में नए दौर के प्रारम्भिक संकेतों की तलाश 20वीं सदी के शुरु के वर्षों में की जा सकती है। 1905 में ही लाड वंजन ने उद्योग और वाणिज्य के नए विभाग की स्थापना की और 1907 में पहला औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय कपड़ा मिल उद्योग का विकास 1914 के बाद के बीस वर्षों की तुलना में 1914 के पहले के बीस वर्षों में अपेक्षाकृत ही नहीं बल्कि पूरी तरह तेज रहा। उद्योगीकरण के लक्ष्यों के संदर्भ में नीति में परिवर्तन की घोषणाएं पहले की अपेक्षा उस समय से ज्यादा महत्वपूर्ण रही और सीमाशुल्क संबंधी नई नीति का निर्माण भी 1918 के बाद के वर्षों में हुआ। लेकिन यह सभी मानते हैं कि आवश्यकताओं और संभावनाओं की तुलना में इनके परिणाम बहद अपर्याप्त थे और उत्पादन संबंधी विकास में बाधा पहुंचाने वाले विरोध जारी ही नहीं रहे बल्कि नए रूपों में ये और तेज हुए।

आधुनिक काल का मुख्य रूपांतरण वह राजनीतिक रूपांतरण है जो स्वतंत्रता के संघर्ष में भारतीय जनता द्वारा नए चरण तक प्रगति के द्वारा हुआ है। जो भी हो, इस प्रगति की उपलब्धि साम्राज्यवाद के विरोध में हुई है।

भारत में साम्राज्यवादी शासन के आधुनिक काल का संचालन करने वाली शक्तियों के विश्लेषण के लिए औद्योगिक पूँजी के युग से महाजनी पूँजी के युग में संक्रमण को अच्छी तरह समझना होगा। इस काल को समझने के लिए इस प्रक्रिया और इसके परिणामों को समझना सबसे जरूरी है।

## 1 महाजनी पूँजी में संक्रमण

19वीं सदी में औद्योगिक पूँजी जिन खास खास तरीकों से भारत का शोषण करती थी उनमें सीधी लूट के तरीके समाप्त नहीं हो गए थे। वे भी जारी थे लेकिन उनका रूप बदल गया था।

नजराना, 19वीं सदी के मध्य तक सरकारी प्रवक्ता इसे खुलेआम नजराना ही कहते थे, अथवा ताखो पॉड की जो संपत्ति प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजी जाती थी, उसका सिलसिला जारी रहा, उसे गृह शुल्क के अंतर्गत तथा ब्यवित्तगत तौर पर भेजा जाता रहा। व्यापार के विकास के साथ-साथ घन भेजे जाने की क्रिया में भी 19वीं सदी के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। भेजी जाने वाली इस राशि के बदले में भारत को कोई माल नहीं मिलता था (सिवाय यथा नुपात उस मामूली राशि के जो सरकारी भंडारा के लिए इंग्लैंड से आती थी।) 20वां सदी में इसमें और भी वृद्धि हुई हाताकि व्यापार में अपेक्षाकृत गिरावट आई।

1848 में वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज में चीनी और काफी की खेती के बारे में हाउस आफ कामंस की प्रवर समिति के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डायरेक्टर वनत साइमन ने अनुमान लगाया था कि नजराने (यह शब्द उन्होंने स्वयं इस्तमाल किया था)

की राशि के रूप में प्रतिवर्ष 35 लाख पौंड दिया जाता है। भारत इस नजराना का बोझ तभी बर्दाश्त कर सकता है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो।' इसी प्रकार भारत के एक व्यापारी एन० एलेक्जेंडर ने इसी समिति के सामने बताया कि '1847 तक भारत लगभग 60 लाख पौंड का आयात और लगभग 90 लाख पौंड का निर्यात करता था। आयात और निर्यात के बीच का यह अंतर ही वह नजराना है जो कंपनी को मिलता था और जो लगभग चालीस लाख पौंड होता था।'

1851 से 1901 के बीच शासन करने वाले अधिकारियों द्वारा 'गृह शुल्क' के नाम पर इंग्लैंड भेजी गई कुल राशि में सात गुना वृद्धि हुई और यह 25 लाख पौंड से बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख पौंड हो गई जिसमें से केवल 20 लाख पौंड से सामान आदि खरीदे गए थे। इस आंकड़े में वह राशि नहीं शामिल की गई है जो सरकारी अफसरों ने व्यक्तिगत तौर से भेजी थी। 1913-14 तक यह राशि बढ़कर 1 करोड़ 94 लाख पौंड हो गई जिसमें से केवल 15 लाख पौंड का सामान आदि खरीदा गया था। 1933-34 तक सरकारी खाते के अनुसार इंग्लैंड में खर्च की गई कुल राशि 2 करोड़ 75 लाख पौंड थी जिसमें से केवल 15 लाख पौंड सामान वगैरह की खरीद में खर्च हुआ था (1914 में रुपये की विनिमय दर एक शिलिंग चार पैसे थी जिसे 1933 में बदलकर एक शिलिंग 7 पैसे कर दिया गया जिससे इसका भुगतान करने के लिए आवश्यक रूपय की संख्या भारत में कम हो गई लेकिन भारत के मूल्य स्तर में गिरावट आने से इसका काफी प्रति समतुलन हो गया। 1914 में मूल्य स्तर 147 था जो 1933 में कम होकर 121 हो गया। इससे 1914 के मूल्य के अनुसार भारत पर 3 करोड़ पौंड का बोझ पड़ गया।)

1851 से 1901 के बीच भारत से हाने वाले निर्यात (पष्य और खजानों का) में तीन गुना वृद्धि हुई और यह 33 लाख पौंड से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख पौंड हो गया (पष्यों में 72 लाख पौंड से 2 करोड़ 74 लाख पौंड तक की वृद्धि हुई)। लेकिन 20वीं सदी में निर्यात में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 1901 से 1913-14 के बीच यह 1 करोड़ 10 लाख पौंड से बढ़कर 1 करोड़ 42 लाख पौंड हो गई। फिर भी 1913-14 का वर्ष औसत से नीचे ही था। युद्ध में पहले के 5 वर्षों अर्थात् 1909-10 से लेकर 1913-14 का औसत देखा जाए तो निर्यात में कुल वार्षिक आधिक्य 2 करोड़ 25 लाख पौंड था। इस 1901 के स्तर का दुगुना मान सकते हैं (देखें 'रिपोर्ट ऑफ दि इंडियन फिन्सल कमिशन', 1922, पृष्ठ 20)।

1933-34 तक भारत से बिया गया कुल निर्यात 6 करोड़ 97 लाख पौंड तक पहुँच गया जिसमें से 2 करोड़ 68 लाख पौंड के पष्य और 4 करोड़ 29 लाख पौंड के खजाने भेजे गए। यह अंतिम राशि जो अमाधारण रूप से अधिक है इस बात का संकेत देती है कि मकद के समय स्टिलिंग की सहायता के लिए भारत से सोना भेजा गया। यदि बेहतर ढंग से तुलना करने के लिए 1931-32 से 1935-36 के पांच वर्षों की अवधि का औसत लें तो



यह राशि 5 टराल 92 लाख पौंड आएगी जो मुद्र पूव व पाच वर्षों की अवधि (1910-14) की लगभग तीन गुना अधिक और 1901 के स्तर को पाच गुना से भी अधिक होगी।

यदि 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुए नजराने की राशि में वृद्धि का, जो भारत से इंग्लैंड भेजी गई (जिगम भारतीय निर्यात और आयात के बीच मूल्य स्तर में अंतर के लिए होने वाले शोषण का कोई उल्लेख नहीं है) कोई चाट तैयार करें ता पहली ही क्षण में यह साफ साफ पता चल जाएगा कि आधुनिक युग में इंग्लैंड ने भारत के शोषण में कितना प्रगति की है, हालांकि यह आज भी अपनी भारी वारगुजारिया के एक अंश से ज्ञान की जानकारी नहीं देता है।

#### भारत से इंग्लैंड जाने वाले नजराने में वृद्धि (लाख पौंड में)

|                           | 1851 | 1901 | 1913-14 | 1933-34 |
|---------------------------|------|------|---------|---------|
| गृह शुल्क                 | 25   | 1 73 | 1 94    | 2 75    |
| भारतीय निर्यात में अधिकता | 33   | 1 10 | 1 42    | 6 97    |

अथवा व्यापार सवधा का और सतुलित चित्र पेश करने के लिए पाच वर्ष की अवधि का खाका देख सकते हैं

#### पाच वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत (लाख पौंड में)

|                           | 1851-55 | 1897-1901 | 1909-10 से 1913-14 तक | 1931-32 से 1935-36 तक |
|---------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| भारतीय निर्यात में अधिकता | 43      | 1 53      | 2 25                  | 5 92                  |

इस तालिका से पता चलता है कि भारत से इंग्लैंड जाने वाली धन सपत्ति में तजी से वृद्धि हुई। इससे शोषण के रूप और तरीके में परिवर्तन की झलक मिलती है।

19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत से इंग्लैंड जाने वाले नजराने की राशि में जबरदस्त वृद्धि और बीसवीं सदी में इस वृद्धि के जारी रहने के पीछे, दरअसल, जो बात छिपी है वह यह है कि शोषण के एक नए रूप का जन्म हो चुका था जिसकी 19वीं सदी के स्वतंत्र व्यापारवाले औद्योगिक पूँजीवाद से शुरुआत हुई थी लेकिन जो महाजनी पूँजी द्वारा भारत के शोषण के 20वीं सदी की नई अवस्था में विकसित हो रहा था।

19वीं सदी के स्वतंत्र व्यापार पर आधारित औद्योगिक पूँजीवाद की आवश्यकताओं ने अंगरेजों को इस बात पर मजबूर किया कि वे भारत में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करें। एक तो इस बात की आवश्यकता थी कि अब अपनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रशासन लागू किया जाए जो

ब्रिटन के संपूर्ण पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति कुछ अंशों में 1833 के नरनारी आदेशपत्र से हुई और 1858 में यह काम पूरी तरह मगन हो गया।

दूसरे, भारत की व्यापारिक घुसपैठ के लिए पूरी तरह छोल देना आवश्यक था। इसके लिए जरूरी था कि रेल लाइनों का जाल देश भर में बिछा दिया जाए, सड़कों का विकास किया जाए, सिंचाई की ओर ध्यान दिया जाए जिसकी ब्रिटिश राज में पूरी तरह उपेक्षा की गई थी, विद्युत संचालित टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की जाए और देश भर में एक जैसी डाक व्यवस्था कायम हो, बलकों और मातहत कमचारियों की भरती के लिए सीमित अंश में अंगरेजी ढंग की शिक्षा शुरू की जाए और यूरोप के ढंग की बैंक व्यवस्था शुरू की जाए।

इस सबका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक निर्माण कार्यों के सदर्भ में एशिया में किसी सरकार द्वारा अत्यंत प्रारंभिक कार्यों की सी वर्यों तक उपेक्षा करने के बाद अब शोषण की आवश्यकताओं में, बेहद एकतरफा और असंतुलित ढंग से ही सही एक ऐसी शुरुआत के लिए सरकार को मजबूर किया (औद्योगिक विकास का गला घोट कर और उसे निष्फल बना कर) जिसका उद्देश्य जनता के लिए अत्यंत दुःसह आर्थिक शर्तों पर विदेशी घुसपैठ के लिए महज व्यापारिक और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

रेल व्यवस्था के बारे में, 1853 में लाड डलहौजी की मशहूर रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर रेल व्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। इस रिपोर्ट में बड़े साफ शब्दों में व्यापारिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और बताया गया था कि ब्रिटिश माल के लिए भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत का इस्तेमाल करने के लिए रेल व्यवस्था मजबूत करना बहुत जरूरी है

मुझे पूरा यकीन है कि इसकी स्थापना से भारत को जो व्यापारिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इंग्लैंड को कपास की अत्यधिक जरूरत है जिसे भारत कुछ अंश में पैदा करता है और यदि उसके दूरदराज क्षेत्रों से जहाजों में लाद कर भेजने के लिए बदरगाहों तक पहुंचान की उचित व्यवस्था कर दी जाए तो वह अच्छे किस्म की कपास पर्याप्त मात्रा में पैदा कर सकता है। जैसा हमने देखा है व्यापार की जितनी ही सुविधा दी गई है उतनी ही बड़ी मात्रा में भारत के तमाम बाजारों में इंग्लैंड के सामानों की मांग बढ़ी है। दुनिया के इस हिस्से में हमारे लिए नए नए बाजार तैयार हो रहे हैं और हमारे माल की जो कीमत इन बाजारों में निर्धारित हो रही है उनका अनुमान चतुर से चतुर दूरदर्शी व्यक्ति भी नहीं लगा सकता। (लाड डलहौजी, गवर्नर जनरल, 1848-56, रेल व्यवस्था पर रिपोर्ट, 1853)

तन्निन मन्त्रिय विभाग और खासतौर से रत्न निमाण की इस प्रिया ने, जो भारत में व्यापारिक घुमपैठ के लिए औद्योगिक पूँजी की आवश्यकताओं से पैदा हुई थी (साथ ही लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग सामानों के बाजार के लिए उत्पन्न जरूरत), कुछ अवश्यमावी परिणाम हुए। इन्होंने एक ठो दोरकी नींव रखी, और वह था भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश का दोर। अब यहाँ अंगरेजों ने अपनी पूँजी लगानो शुरू कर दी।

साम्राज्यवादी विस्तार के मामलात नियम व अंतगत इस प्रिया को पूँजी का नियात कहा जायगा। तन्निन जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ जो कुछ हुआ उसे यदि पूँजी का निर्यात कहें तो यह वास्तविकता से आखें मूंदना होगा। जिसे पूँजी का वास्तविक निर्यात कहा जाता है वह यहाँ बहुत कम हुआ। 1914 तक की पूरी अवधि में केवल 1856 से लेकर 1862 तक के सात वर्ष ही ऐसे हैं जब निर्यात से आयात अधिक रहा करना सामान्यतः निर्यात ही अधिक रहता था। इन सात वर्षों में जितनी कीमत का माल भारत से इंग्लैंड गया उससे 2 करोड़ 25 लाख पौंड ज्यादा कीमत का माल इंग्लैंड से भारत आया। यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी क्योंकि अतत भारत में लगी हुई ब्रिटिश पूँजी 1914 तक 50 करोड़ पौंड के लगभग हो गई थी। समूची अवधि में ब्रिटेन से भारत को पूँजी का जो निर्यात हुआ वह भारत से इंग्लैंड का भेजे गए नजरानों की तुलना में इतना अधिक था कि वह उसका प्रति सतुलन बनाए रख सकता था। और यह भी ऐसा समय जब पूँजी का व्यापार में लगाया जा रहा हो। इस प्रकार भारत में लगाई गई ब्रिटिश पूँजी का प्रवर्ध वस्तुतः भारतीय जनता की लूट से भारत में एकत्र करके किया गया था और फिर उसे ब्रिटेन की ओर से भारत की जनता पर वज के रूप में दज कर लिया गया था। इसपर तभी से भारत को ब्याज और लाभांश देना पड़ रहा है।

भारत में ब्रिटिश पूँजीनिवेश का केंद्र सावजनिक ऋण था। यही वह प्रिय तरीका था जिसे ब्रिटेन के अल्पतत्त्व ने अपनी जकड़ मजबूत करने के लिए अपनाया था। 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सत्ता ली तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सात करोड़ पौंड का कज भी उत्तराधिकार में मिला। दरअसल, जैसा कि भारतीय लेखकों ने हिसाब लगाया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से नजरानों के रूप में 15 करोड़ पौंड से भी अधिक की राशि निकाली थी जो भारत से बाहर, अफगानिस्तान, चीन और अन्य देशों में ब्रिटेन द्वारा छेड़े गए युद्ध के खर्चों के अतिरिक्त है। यदि सही ढंग से हिसाब किया जाता तो इंग्लैंड पर भारत का ही कज निकलता। लेकिन ब्रिटिश सरकार के हिसाब में भारत ही कजदार रहा और उसपर यह कज तेजी से बढ़ता गया।

रपये हा गई जिसे दो भागों में बांट दिया गया 7 अरब 9 करोड़ 90 लाख रुपये (53 करोड़ 24 लाख पौंड) भारतीय ऋण और 4 अरब 69 करोड़ 10 लाख रुपये (35 करोड़ 18 लाख पौंड) स्टनिंग ऋण या ब्रिटिश ऋण। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासनकाल के लगभग 75 वर्षों में ऋण की राशि में 12 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई।

विशेष महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंग्लैंड का स्टनिंग ऋण नेजी में बढ़ रहा था। 1856 तक यानी कंपनी के शासनकाल की समाप्ति तक वह ऋण 40 लाख पौंड से कम ही था। 1860 तक इसमें तब्दी से वृद्धि हुई और यह 3 करोड़ पौंड हो गया, 1880 तक 7 करोड़ 10 लाख, 1900 तक 13 करोड़ 30 लाख 1913 तक 17 करोड़ 70 लाख और 1939 तक 35 करोड़ 58 लाख पौंड हो गया।

इस ऋण का कारण एक तो युद्ध आदि के वे खर्च थे जो भारत से वसूल किए जाते थे और दूसरा, सरकार द्वारा शुरू की गई रेल और सावजनिक निर्माण योजनाओं की लागत। शुरू के 7 करोड़ पौंड का वज्र मुख्यतः लाड वेनजली के युद्धों, प्रथम अफगान युद्धों, सिख युद्धों और 1857 के विद्रोह को कुचलने में हुए खर्च के कारण था। बाद के 7 करोड़ पौंड का, जिसके द्वारा 18 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने ऋण की राशि दुगुनी कर दी, एक हिस्से 2 करोड़ 40 लाख पौंड को रेल निर्माण और सिंचाई कार्यों पर खर्च किया गया। वज्र का शेष भाग इस कारण बढ़ा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन प्रत्येक कल्पनीय खर्चों के लिए भारत के मद से पैसा लेती थी जिसका भारत से या भारत में ब्रिटिश शासन से संबंध हो या न हो। यहाँ तक लंदन में टर्कों के सुल्तान को दावत देने, चीन और फारस के साथ ब्रिटन के राजनयिक एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने, अबीसीनिया में युद्ध छेड़ने या भूमध्य सागर के जहाजों के डेके का खर्च उठाने में भारत पर ही वज्र का बोझ लादा जाता था।

भारत के मध्ये आसानी से भुट दिए जाने वाले खर्चें बड़े हास्यास्पद लगते थे।

विद्रोह के फलस्वरूप हुए खर्चें हो या ब्रिटिश राज्य के नाम कंपनी के अधिकारों के हस्तांतरण की कीमत, चीन और अबीसीनिया में एक साथ जारी युद्धों के खर्च हा या लंदन में सरकारी कामकाज के लिए ऐसी कोई भी चीज खरीदी गई हो जिसका भारत से दूर दूर तक कोई संबंध न हो, इंडिया आफिस में सफाई का काम करने वाली महिला की तनख्वाह हो या उन जहाजों का खर्च हा जो पानी में उतार तो दिए गए हा लेकिन जिहान युद्ध में हिस्सा न लिया हा जयवा भारतीय सैनिक टुकड़ियों के छ महीने के प्रशिक्षण का खर्च हा, इन सभी कामों का खर्च उम रैयत के खाते से वसूला जाता था जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। टर्कों के सुल्तान ने 1868 में लंदन की राजकीय यात्रा की और उनके लिए राजकीय नृत्य की व्यवस्था इंडिया आफिस में की गई तथा इसपर

जितना पैसा खर्च हुआ वह पैसा भारत से वसूला गया। 1870 से पहले तक भारतीय खजाने से जिन कामों के लिए पैसा निवाला गया उनमें ईलिंग में पागलखाना खोलने, जजीबार के दल के सदस्यों को उपहार देने, चीन और फारस में ग्रेट ब्रिटेन के राजनयिक और वाणिज्य सबंध स्थापित करने, भूमध्य सागर में स्थित जंगी वेड़े के स्थाई खर्च का एक अंश वसूलने और इंग्लैंड से भारत तक तार सेवा स्थापित करने का समूचा खर्च शामिल है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शाही प्रशासन के शुरू के 13 वर्षों के दौरान भारतीय राजस्व में 3 करोड़ 30 लाख पौंड से 5 करोड़ 20 लाख पौंड प्रति वर्ष की वृद्धि हुई और 1866 से 1870 तक घाटे के रूप में 1 करोड़ 15 लाख पौंड की राशि दर्ज की गई। 1857 से 1860 के बीच घरेलू ऋण के रूप में 3 करोड़ पौंड की राशि अंकित की गई और इसमें तेजी से वृद्धि हुई जबकि ब्रिटिश राजनेताओं को मितव्ययता के लिए भारतीय हिसाब-किताब में विवेकपूर्ण जोड़ तोड़ के जरिए वित्तीय मामलों में कुशल होने के लिए ख्याति मिली। (एल० एच० जेक्स 'दि माइग्रेशन आफ ब्रिटिश कैपिटल,' पृष्ठ 223-24)

राज्य की मदद से रेल पथ निर्माण का विकास और यह कार्य करने के लिए निजी कंपनियों को दी गई गारंटी तथा साथ ही सीधे राज्य द्वारा रेलवे निर्माण से इस ऋण में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जो प्रणाली अपनाई गई थी उसके अंतर्गत रेल निर्माण के लिए ब्रिटेन का पूंजीपति जितनी भी पूंजी लगाता था उसपर सरकार से पांच प्रतिशत ब्याज की गारंटी मिलती थी। जाहिर है इस प्रणाली ने वेहद फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया। 1872 तक शुरू के छ हजार मील में जो रेल लाइन बिछाई गई उसपर 10 करोड़ पौंड का खर्च आया। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मील में रेल लाइन बिछाने में 16 हजार पौंड से अधिक की राशि खर्च हुई। 1872 में रेलवे के आय व्यय के भूतपूर्व सरकारी ऑडिटर ने भारतीय वित्त के बारे में मसदीय समिति को बताया कि 'आपस में एक तरह की ऐसी समझदारी थी कि उनके काम को बड़ी धारिकी से नियंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक सारा हिसाब किताब सौंप नहीं दिया गया खर्च किए गए पैसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मालूम थी।' इसी समिति के सामने भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री डब्ल्यू० एन० भैस ने बताया कि 'बड़े पैमाने पर पैस की फिजूलखर्ची हुई और ठेकेदारों का मितव्ययता का कोई इरादा नहीं था। सारा पैसा अंगरेज पूंजीपतियों द्वारा लगाया जाता था और जब तक उन पूंजीपतियों का भारत के राजस्व पर पांच प्रतिशत की गारंटी थी उनके लिए यह सोचना बेकार था कि जो पैसा वे लगा रहे हैं वह हुगली नदी में फेंका जा रहा है या उसका इस्तमाल ईंट और गारे में किया जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फिजूलखर्ची यहां हो रही है उतनी पहले कहीं भी देखने में नहीं आई थी।' ,

19वीं नदी के अंत तक रेल निर्माण पर 22 करोड़ 60 लाख पौंड खर्च किया गया था

ब्रिटीश राज के भी बात था। दूर 4 कराट पौंड का तुलना में हुआ था। यह मात्र नुस्-मान भारतीय बजट पर जाना गया। 20वीं शती में रत्ना में मुद्रा का बर्माण जाओ और 1943-44 तक जब रत्ना निर्माण काय में रत्ना स्मॉलिंग कृष्ण जा नाभग। कराट पौंड प्रति वष था (1913-34 में 9 कराट 70 साय पौंड) भारत में इम्पैड नज दिया गया।

रत्ना निर्माण और काय काफी गया रत्ना बागा। एष कृष्ण छोट माटे उद्योगों के विभाग क माय माय 19वीं शती क उद्योग में ब्रिटन के पूँजीपति कती गती में अपनी निजी पूँजी भारत में लगान लगे।

दती प्रबधि में रत्ना इन्डिया कंटीनी क एकाधिकार के प्रतिस्था ने समाप्त हा। पर भगवत्ता न भारत में अपा निजी बैंक भी गया। 1876 के प्रेमीटिंगी बैंक ऐक्ट न तीन प्रेमीटिंगी बैंकों का गरागी गरमण क अधीन ला गिया जिन् बाद में 1921 में उद्भूत बडे बैंक इन्डियन बैंक आर इन्डिया में मिता दिया गया। विनिमय बैंका न जिनक मुख्यालय भारत से बाहर थे भारत में अपना काय प्रेमीटिंगी बैंक क साथ मिलकर करना शुरू किया। प्रेमीटिंगी बैंक ब्रिटिश नियता के अधीन पित बाणिज्य और उद्योग पर अपना प्रभुत्व ग्राहण हुए थे। विनिमय बैंका (इनके मुख कार्यालय भारत में बाहर थे) में ग्रामतीर में बाट्ट बक आर इन्डिया आस्ट्रेलिया में बाट्टा जिगे 1853 में बाट्ट (गरागी आर) मिता था गोटोइन बैंक आर इन्डिया जो उसी वष प्राप्त जादेवान एष बक में निरना था, 1861 में शुरू नगनत रत्ना आर इन्डिया और 1867 में शुरू हायकाग एष गपार्ड बैंकिंग कारपारेशन (विनिमय बैंको में चार बडे बैंक) प्रमुख थ। भारत के उद्योग स्टाय बैंका न द्वा विनिमय बैंका क प्रभुत्व के पिताप आगे बढ़ने की कामिनी की लेनि चूकि विदेशी बैंका का कई तरह के लाभ प्राप्त थे इसलिए उह गपनता नहीं मित्र गकी। 1913 तक विदेशी बैंका के पास (प्रेमीटिंगी बैंका और विनिमय बैंका) बैंका की कुल जमा राशि का तीन चौथाई हिस्सा था जबकि भारतीय उद्योग स्टाय बैंको क पास में एष चौथाई से भी कम हिस्सा आ सता था।

1909-10 में सर जाज पैज ने अनुमान लगाया था कि भारत और लका में कुल 36 करोड 50 लाख पौंड की ब्रिटिश पूँजी लगी हुई है (इसमें कपनिया की पूँजी का छोडकर निजी पूँजी का शामिल नहीं किया गया है। कपनिया की पूँजी का तत्काल कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है)। सर जाज पैज ने 1911 में रायन स्टेटिस्टिकन सोसायटी के सामन एष तथ्य पडा था जिसे उहने यह बात कही थी और एष आकडा प्रस्तुत किया था (जनरल आफ दि रायल स्टेटिस्टिकल सोसायटी, खड 74, भाग 1, 2 जनवरी 1911, पृष्ठ 186)

पृष्ठ 160 की तालिका से यह दया जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश की प्रक्रिया या तथ्याकथित पूँजी के निर्यात का यह मतलब नहीं था कि भारत में आधुनिक

उद्योग का विकास हो गया था। 1914 के युद्ध के पहले भारत में जितनी ब्रिटिश पूँजी लगी थी उसका 97 प्रतिशत भाग सरकारी कामों, भातायात, वापस आने और बैंकों में लगा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि पूँजी का अधिकांश ऐसा कामों में लगा था जिनसे अगरजो

|                            | सात पौड़ों में |
|----------------------------|----------------|
| सरकारी और म्यूनिसिपल       | 1825           |
| रेल                        | 1365           |
| वापस आने (चाय, काफी, रबड़) | 242            |
| ट्राम वे                   | 41             |
| खाने                       | 35             |
| बैंक                       | 34             |
| तेल                        | 32             |
| व्यापारिक और औद्योगिक      | 25             |
| वित्त भूमि और पूँजीनिवेश   | 18             |
| विविध                      | 33             |

को भारत में अपना व्यापार फैलाने और कच्चे मालों के स्रोत तथा ब्रिटिश मान के बाजार के रूप में उसका शोषण करने में मदद मिलती थी। इन कामों का औद्योगिक विकास से किसी भी तरह का संबंध नहीं था।

सर जॉर्ज पैश ने जो अनुमान लगाया था वह निम्नलिखित एक रूढ़ अनुमान था जिसमें उन बातों को पर रख दिया गया था जिनको जानकारी संभव नहीं थी। 1914 से पहले भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश के बारे में जो अन्य अनुमान लगाए गए थे उनके अनुसार ऐसी कुल पूँजी 45 करोड़ पौंड (एच० ई० हावर्ड ने 1911 में 'इंडिया ऐंड दि गोल्ड स्टैंडर्ड', में उल्लेख किया है), और 47.5 करोड़ पौंड (20 फरवरी 1909 में इकोनामिस्ट में प्रकाशित एक लेख 'अवर इन्वेस्टमेंट्स एब्राड' के अनुसार) थी।

## 2 महाजनी पूँजी और भारत

इस प्रकार सामान्यतः भारत के महाजनी पूँजीवादी शोषण के लिए प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ही जमीन तैयार हो गई थी पर यह अपने पूरे स्वरूप में बाद के वर्षों में ही आ सका।

1909-10 में भारत में लगाई गई पूँजी की संरचना का सर जॉर्ज पैश ने विवरण दिया जिससे पता चलता है कि पहले से ही मौजूद औद्योगिक पूँजीवाद और व्यापार के जरिए भारत के शोषण की परिस्थितियों से उत्पन्न ब्रिटिश महाजनी पूँजी द्वारा भारत के शोषण का नया आधार गुरु से ही व्यापार की प्रक्रिया का सहायक था। उमन इस प्रक्रिया का

स्थान कभी नहीं ग्रहण किया। फिर भी इसकी माता में जो परिवर्तन हुआ वह आधुनिक युग के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

19वीं सदी में उद्योग के क्षेत्र में जंगरेजों का जो एकाधिकार कायम हो गया था और विश्व बाजार में उनका जो दबदबा बन गया था वह 1875 के बाद कमजोर पड़ने लगा। विश्व के अन्य हिस्सों में भी नए अमरीकी और यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों के सामने उनका पतन दिखाई पड़ने लगा। भारत में इस अवनति की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही क्योंकि यहाँ राजनीतिक प्रभुसत्ता के ज़रिए जंगरेजों ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी। यहाँ तक कि 1914 के युद्ध तक ब्रिटेन का लगभग दो तिहाई भारतीय बाजार पर अधिकार बना था जबकि शेष एक तिहाई हिस्सा विश्व के अन्य देशों का मिला था। इसके बावजूद 1875 के बाद से उनका व्यापार भारत में भी धीरे-धीरे किन्तु निरंतर कमजोर पड़ने लगा।

1874 से 1879 तक के पाँच वर्षों में भारत में जो कुल माल विदेशों से आया था उसका 82 प्रतिशत हिस्सा ब्रिटेन से आया था। इसके अलावा कुल माल का 11 प्रतिशत हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों से आया था। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों के लिए भारतीय बाजार का 1/14 से भी कम हिस्सा बच रहा था। 1884-89 तक ब्रिटन का हिस्सा 82 प्रतिशत से घटकर 79 प्रतिशत हो गया। 1899-1904 तक यह 66 प्रतिशत और 1909-14 तक 63 प्रतिशत हो गया।

लेकिन साथ ही लगाई गई पूँजी पर मुनाफ़े में और घरेलू खर्च की राशि में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। 1913-14 में भारत और ब्रिटेन के बीच 11 करोड़ 70 लाख का व्यापार हुआ। जिन सामानों का व्यापार किया गया, चाहे वे ब्रिटन से आयात किए गए हों या भारत से, उन सब पर 10 प्रतिशत व्यापारिक लाभ की दर से 1 करोड़ 20 लाख पौंड का मुनाफ़ा हुआ। यदि इसमें भारत को भेजे गए सभी ब्रिटिश सामानों पर निर्माताओं के मुनाफ़े के रूप में और 10 प्रतिशत जोड़े (7 करोड़ 80 लाख पौंड पर 80 लाख पौंड) तथा जहाज़ कर्पनिया के मालिकों की आय के रूप में 80 लाख पौंड जोड़ें (1913 के व्यापार बोज़ की एक जाँच में अनुमान लगाया गया था कि 1913 में जहाज़रानी से ब्रिटन को जा कुल 9 करोड़ 40 लाख पौंड की आय हुई थी उसमें भारत का हिस्सा केवल 9 प्रतिशत था), तो पता चलेगा कि जंगरेज व्यापारियों, निमाताओं और जहाज़ कर्पनिया को 1913 में भारत से अधिक से अधिक कुल 2 करोड़ 80 लाख पौंड का मुनाफ़ा हुआ था।

लेकिन एच०ई० हावर्ड के 'इंडिया ऐंड दि ग्रेट स्टैंडर्ड' के अनुसार 1911 तक भारत में कुल ब्रिटिश पूँजी 45 करोड़ पौंड थी जो 1914 के युद्ध के अवसर पर 50 करोड़ पौंड में भी अधिक हो गई थी। यदि इस पूँजी पर औसत व्याज की दर महज़ 5 प्रतिशत हो



रखी जाए तो भी उससे ढाई करोड़ पौंड की आमदनी होगी। इसमें पूँजी के उन सभी वर्गों से होने वाली आय और मुनाफा जोड़ना होगा जिसका प्रतिनिधित्व भारत में काम करने वाली गैर-व्यापारिक कंपनियाँ करती थी (वागानो, कोयला खाना, पटसन आदि उद्योग प्रायः 50 प्रतिशत तक लाभांश के रूप में भुगतान करते थे)। इसके अलावा उसमें बैंकों के वसीयतों विनिमय के सौदों और बैंकों एवं बीमा कंपनियों से होने वाली आमदनियों को जोड़ना होगा, इसे यदि कम से कम डेढ़ करोड़ पौंड माना जाए और आय में जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 4 करोड़ पौंड की आय होती थी। इसके साथ साथ नष्ट पर व्याज की राशि के अतिरिक्त घरेलू खर्च 1913-14 तक 90 लाख पौंड हो गया था। इस प्रकार पूँजी निवेश पर मुनाफे और प्रत्यक्ष नजराने के रूप में जाने वाली कुल राशि लगभग 5 करोड़ पौंड हो गई थी।

तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस तरह के किसी भी अनुमान का बहुत सीमित महत्व है। लेकिन यह स्पष्ट है कि 1914 तक भारत के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों, निर्माताओं और जहाज कंपनियों को कुल मिलाकर जितना लाभ होता था उससे कहीं ज्यादा बड़ी राशि यहाँ लगी हुई ब्रिटिश पूँजी के मुनाफे तथा सीधे नजराने के रूप में इंग्लैंड चली जाती थी। इससे यह पता चलता है कि बीसवीं सदी में महाजनी पूँजी द्वारा भारत का शोषण ही इस देश की लूट का मुख्य स्वरूप बन गया था।

1914-18 के युद्ध ने और उसके बाद के वर्षों ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज किया। भारत के बाजार में ब्रिटेन का हिस्सा दो तिहाई से घटकर एक तिहाई से थोड़ा ही अधिक रह गया। सीमा शुल्कों और ब्रिटेन के सामानों के प्रति अभिरुचि के बावजूद जापान, अमेरिका और अतत्त नवीकृत जर्मन सामानों की प्रतियोगिता तेजी से सामने आई। भारतीय औद्योगिक उत्पादन ने खासतौर से हल्के उद्योग के क्षेत्र में काफी प्रगति की है हालाँकि उसे महत्वपूर्ण अवरोधों और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सरकार की तरफ से भी उसे सदा निरुत्साहित किया गया। औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत 1914 के पहले ही हो गई थी जो युद्ध के बाद के वर्षों में और भी अप्रत्यक्ष रूप में जारी रहा।

1913 में 1931-32 के बीच ब्रिटन द्वारा भारतीय सामानों का आयात 64 प्रतिशत तक घटकर 35 प्रतिशत हो गया। बाद के वर्षों में ओटावा के अधिमाय उपायों ने 1934-35 तक आयात की मात्रा 40.6 प्रतिशत कर दी लेकिन 1935-36 तक यह फिर 38.8 प्रतिशत और 1936-37 तक 38.5 प्रतिशत हो गयी। जापान का अंश 1913-14 में 2.6 प्रतिशत था जो 1935-36 में बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गया, दूसरी अवधि में जर्मनी का अंश 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया और अमेरिका का अंश 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया ('इकोनामिस्ट' 13 फरवरी 1937)।

अभी हाल के वर्षों में प्रशासन की दृष्टि से 1937 से बर्मा को अलग किए जाने से सरकारी आकड़े प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी 'रिव्यू आफ दि ट्रेड आफ इंडिया' के अनुसार भारतीय बाजार (बर्मा को छोड़कर) का अंश निम्न रहा

भारतीय सामान के आयात का अनुपात  
(प्रतिशत)

|         | 1935-36 | 1937-38 | 1939 40 |
|---------|---------|---------|---------|
| ब्रिटेन |         |         |         |
| बर्मा   | 31.7    | 29.9    | 25.2    |
| जापान   | 17.5    | 14.9    | 19.0    |
| जर्मनी  | 13.0    | 12.8    | 11.7    |
| अमरीका  | 7.9     | 8.8     | 4.0     |
|         | 5.6     | 7.4     | 9.0     |

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के व्यापार में अनेक परिवर्तन हुए। शत्रु देशों के साथ व्यापार ठप हो जाने से अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और ईरान, अरब, ईराक, टर्की, मिस्र आदि जैसे मध्य पूर्वी देशों के साथ भारत के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 'रिव्यू आफ दि ट्रेड आफ इंडिया इन 1942-43' ने निम्न आकड़े प्रस्तुत किए 1942-43 में भारतीय सामानों के आयात में ब्रिटेन का अंश 26.8 प्रतिशत था (1939-40 में 25.2 प्रतिशत) अमरीका का अंश 17.3 प्रतिशत (1939-40 में 9.0 प्रतिशत) कनाडा का अंश 5.0 प्रतिशत (1939 40 में 0.8 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया का अंश 2.9 प्रतिशत (1939-40 में 1.4 प्रतिशत), और मध्यपूर्व के देशों (मिस्र को छोड़कर) का अंश 20.2 प्रतिशत (1939-40 में 2.9 प्रतिशत) था, मिस्र का अंश 1942-43 में 7.4 प्रतिशत था।

ब्रिटेन का अंश अब भी सबसे ज्यादा था। यह अपने सभी मुख्य प्रतियोगियों के मिले जुले अंश से भी ज्यादा था। लेकिन इस सबसे बड़े अंश में तजी से एकावट पैना होने लगी थी और अपना बड़ा हिस्सा बनाए रखने के लिए ब्रिटेन भारतीय और विदेशी प्रतियोगियों के विरुद्ध हताशा में जबरदस्त कदम उठाने लगा था। 1936 से भारत (यहां तक कि बर्मा सहित) ब्रिटेन के सामानों का मुख्य ग्राहक नहीं बना रहा जबकि पिछले सौ वर्षों से वह ब्रिटेन का प्रमुख ग्राहक था। 1937 में ब्रिटेन का सामान खरीदने वालों में भारत का दूसरा स्थान और 1938 में तीसरा स्थान हो गया।

भारत के बाजारों में ब्रिटेन के सामानों की मौजूदगी में जबरदस्त कमी आई जा 1818 के बाद तजी से शुरू हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि सूती कपड़ा के निर्यात के जगह 19वीं सदी में ब्रिटेन भारत का जा औद्योगिक पूंजीवादी शोषण करता था वह त्रिनाश-कारी प्रभावा के साथ लड़खड़ाकर बह पड़ा। उद्योग और व्यापार के कारण भारत में अपनी रिपेट में बताया कि 1913 से 1923 तक भारत द्वारा ब्रिटिश सूती

कपडों के निर्यात में 57 प्रतिशत की कमी आई। 1913 में भारत ब्रिटन से 3 अरब 5 करोड़ 70 लाख गज कपड़ा मंगाता था जो लकाशायर द्वारा कुल 7 अरब, 7 करोड़, 50 लाख गज कपड़े के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा था। 1928 तक यह कम होकर 1 अरब, 45 करोड़, 20 लाख गज और 1939-40 तक 14 करोड़, 40 लाख गज हो गया। 1942-43 के दौरान ब्रिटन से कुल 1 करोड़ 10 लाख गज कपड़े का आयात किया गया।

लेकिन जहाँ एक तरफ शोषण का पुराना आधार नष्ट हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर महाजनी पूँजी के शोषण से होने वाले मुनाफों का नया आधार लगातार तयार होता जा रहा था और व्यापक होता जा रहा था। ववई के चैंबर आफ कामर्स के भूतपूर्व सचिव श्री सायर ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' में अपना अनुमान पेश किया कि यदि बड़े फिसेपिटेड्स से देखा जाए तो 1929 तक भारत में कुल ब्रिटिश पूँजी 57 करोड़, 30 लाख पौंड थी और ज्यादा संभावना है कि यह राशि 70 करोड़ पौंड थी। उनके हिसाब से वितरण के आँकड़े निम्न थे

|   |                       |
|---|-----------------------|
| सरकारी स्टॉलिंग ऋण                          | 26 करोड़, 10 लाख पौंड |
| गारंटीशुदा रेलवे ऋण                         | 12 करोड़ पौंड         |
| 5 प्रतिशत युद्ध ऋण                          | 1 करोड़, 70 लाख पौंड  |
| भारत में पंजीकृत कंपनियों में लगी पूँजी     | 7 करोड़, 50 लाख पौंड  |
| भारत से बाहर पंजीकृत कंपनियों में लगी पूँजी | 10 करोड़ पौंड         |

भारत में काम करने वाली कंपनियाँ के लिए 17 करोड़ 50 लाख पौंड की राशि का लगभग निश्चित रूप से कम आँकी गई राशि बताया गया और कहा गया कि कितनी पूँजी लगाई गई थी उस कुल पूँजी का यदि 70 करोड़ पौंड कहें तो 'वह संभवतः बहुत अधिक नहीं होगी।' उन्होंने आगे कहा

भारत में दाव पर लगी हमारी पूँजी के महत्व का संभवतः विशेषज्ञों की एक सीमित संख्या द्वारा पूरी तरह समझा गया है। अधिकांश लोगों को इसकी अधिकता या विविधता की सही जानकारी नहीं है। कितनी पूँजी लगाई गई है और कितनी सवा दी जा रही है इसके बारे में वास्तविक रूप से व्यापार में लगे अनेक सौदागरों, बैंकरों और निर्माताओं तक का भी संभवतः अनुमान लगाना कठिन होगा। विदेशी पूँजी भारत में इतने रूपों में प्रवेश करती है कि इस सिलसिले में कोई भी हिमायत लगाना एक अटपटलवाजी ही होगी। ('फाइनेंशियल टाइम्स,' 9 जनवरी 1930)

ब्रिटिश एग्रीकल्चरल चैंबर आफ कामर्स इन इंडिया द्वारा 1933 के लिए अभी एन्वयमेंट में लगाया गया अनुमान 1 अरब पौंड का है इसमें 37 करोड़, 90 लाख पौंड सरकार

स्टर्लिंग ऋण है 50 करोड़ पौंड उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका पजी करण तो भारत से बाहर हुआ है पर जो भारत में काम करती हैं और शेष राशि भारत में पजीकृत कंपनियों में लगी पूँजी तथा विविध कार्यों में लगी है।<sup>1</sup>

विश्व भर में ब्रिटन की अनुमानित 4 अरब पौंड की पूँजी लगी हुई है और यह 1 अरब पौंड समूची ब्रिटिश पूँजी निवेश के एक चौथाई हिस्से का निरूपित करता है। 1911 में जब सर जॉर्ज पैश ने अपना अनुमान पेश किया था तब उन्होंने बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश पूँजी लगी हुई है वह समूचे विश्व में लगी ब्रिटिश पूँजी के 11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। इस राशि के 1/9 से 1/4 होते, 11 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत होने से हम आज भारत के लिए ब्रिटिश महाजनी पूँजी के बढ़त महत्व को नाप सकते हैं और इससे भारत में ब्रिटिश वित्तीय हिता की रक्षा के विशेष उपायों से लैस आधुनिक साम्राज्यवादी नीति के रहस्य को समझ सकते हैं।

शोषण के आधुनिक साम्राज्यवादी तरीकों द्वारा प्रति वर्ष भारत से नजराने के रूप में इंग्लैंड जाने वाली राशि का मूल्य क्या है? भारतीय अर्थशास्त्रियों शाह और खन्ना ने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'वेल्थ ऐंड टैक्सबुल कैपेसिटी आफ इंडिया' में इसका अनुमान लगाने का प्रयास किया था। वर्ष 1921-22 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उन्होंने हिसाब लगाया और निम्न नतीजे निकाले (1921-22 में 1 शिलिंग 4 पैसे के वर्तमान औसत विनिमय पर स्टर्लिंग के बराबर की राशि को उनके रुपये के अनुमान में जोड़ दिया गया है)

भारत से ब्रिटिश तथा अन्य देशों को जाने वाला वार्षिक नजराना  
(1921-22)

|                                 | लाख रुपये में | लाख पौंडों में |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| राजनीतिक कामों के लिए कटौती     |               |                |
| या गृह शुल्क                    | 5000          | 333            |
| भारत में पजीकृत विदेशी          |               |                |
| पूँजी पर व्याज                  | 6000          | 400            |
| विदेशी कंपनियों को दिया गया     |               |                |
| माल और यात्री भाड़ा             | 4163          | 277            |
| बैंकिंग कमीशनो पर भुगतान        | 1500          | 100            |
| भारत में विदेशी व्यापारियों और  |               |                |
| व्यवसाय में लगे लोगों का मुनाफा |               |                |
| आदि                             | 5325          | 355            |
|                                 | 21988         | 1465           |

दो अरब 20 करोड़ रुपये या लगभग 15 करोड़ पाँड की मोटे तौर पर जोड़ी गई यह राशि अनुमान लगाने के समय ब्रिटेन की आबादी के प्रति व्यक्ति 3 पाँड से भी अधिक के बराबर या ब्रिटेन में सुपर टैंक्स देने वाले प्रत्येक के लिए लगभग 1700 पाँड प्रतिव्यप के बराबर है।

1921-22 के अत्यंत उच्च स्तर से कीमतों में गिरावट के बाद कुल नजराने की राशि का अभी हाल ही में अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास श्री एम० विश्वेश्वरया ने 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्लैंड इकोनामी फार इंडिया' में किया है। अपने विश्लेषण के जरिये उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले (1 शिल्लिंग 6 पैसे के वर्तमान विनिमय दर पर स्टर्लिंग के बराबर की राशि को रुपये में दिए गए उनके अनुमान में जोड़ दिया गया है)

|   | लाख रुपये में | लाख पाँडों में |
|---|---------------|----------------|
| ब्रिटिश और विदेशी जहाजरानी सेवा   | 3500          | 260            |
| विदेशी बैंकों को भुगतान करने योग्य मुद्रा विनिमय तथा अन्य कमीशन                         | 2100          | 160            |
| भारतीय उद्योगों में लगे ब्रिटन की नागरिकता वाले व्यक्तियों के व्यापारिक लाभ और वेतन आदि | 4000          | 300            |
| भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी पर ब्याज   | 6500          | 490            |
|   | 16100         | 1210           |

यह अनुमान पेंशन तथा अन्य घरेलू खर्चों के लिए सरकारी तौर पर इंग्लैंड भेजी गई राशि और भारत के साथ व्यापार संबंध रखने वाले गैरब्रिटिश नागरिकों की देय राशि के अतिरिक्त है। 1913-34 में ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त घरेलू खर्च की राशि से इसमें 1 करोड़ 40 लाख पाँड की और वृद्धि हो गई और इस प्रकार कुल योग 13 करोड़ 50 लाख पाँड हो गया। चूंकि भारत में मूल्यों का सूचक वर्ष 1921 में 236 से घटकर 1933 में 121 हो गया, इसलिए ऐसा लगता है कि यदि सही सही अनुमान लगाया जाए तो यह योग दस वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को निरूपित करेगा। फिर भी तमाम सामानों के बारे में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इन अनुमानों से एक स्पष्ट सन्देश ही मिलता है।

भारत द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले वार्षिक नजराने के बारे में ताजा अनुमान लार्ड्स ऑफ रोजींगर ने अपनी रिपोर्ट 'इडेपेंडेंस फार कॉलोनिअल एशिया—दि वास्ट टु डिवैन्ट वल्ड' में प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट 1945 में अमरीका की फारेन पालिसी एसोसिएशन द्वारा जारी की गई थी। इसमें अनुसार इंग्लैंड भारत से प्रतिव्यप 13 करोड़, 50 लाख पाँड

नजराने के रूप में पाता है जिसमें अतगत् निम्न चीज शामिल हैं

|   | लाख पाँडों में |
|---|----------------|
| 67 करोड़ की लगाई गई पूजा पर व्याज की ब्रिटिश दर 6-7-8 प्रतिशत के हिसाब से व्याज | 460            |
| घरेलू खर्च के मद में व्यापार  | 330            |
| जहाजगानी  | 300            |
| भारत में नौकरी पर रह ब्रिटिश जनो द्वारा भेजी गई राशि                            | 60             |
| कुल योग   | 1150           |

( 'हिंदुस्तान स्टैंडर्ड', कलकत्ता, 5 जुलाई 1945 )

जिन कारणों का एकदम सही सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता उनके कारण इस हिसाब में घटती बढ़ती की पूरी पूरी गुंजाइश रखने हुए अनिवाय रूप से यही नतीजा निकलता है कि आधुनिक युग में भारत का बीते युग की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता के साथ शोषण हुआ है। अनुमान लगाया गया था कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत की सत्ता महाजन से पहले के 75 वर्षों में, भारत से कुल 15 करोड़ पाँड नजराने के रूप में इंग्लैंड गया। आधुनिक युग में, युद्ध से पूर्व 20 वर्षों के दौरान इंग्लैंड ने भारत से प्रतिवर्ष अनुमानित 13 करोड़, 50 लाख पाँड से लेकर 15 करोड़ पाँड तक नजराने के रूप में वसूला। महाजनी पूजावाद की स्थितियों के अंतर्गत भारत के इस तीव्र होत गए शोषण की वजह से ही आज भारत में इतना गंभीर राजनीतिक संकट और साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह पैदा हो गया है।

### 3 उद्योगीकरण की समस्या

कभी कभी यह विचार व्यक्त किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आधुनिक महाजनी पूजा वाले युग ने, खासतौर से 1914-18 के युद्ध के बाद से जबरदस्त शोषण के बावजूद स्वतंत्र व्यापारवाले, औद्योगिक पूजावादी प्रभुत्ववाले पूर्ववर्ती पतन के स्थान पर किसी न किसी तरह उद्योगीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। आधुनिक साम्राज्यवादी प्रचार ने, जो भारत को विश्व के 'प्रमुख औद्योगिक देश' के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है (1922 में ब्रिटिश सरकार ने जेनेवा में इसका जबरदस्त दावा किया। यह दावा बेहद सदिग्ध आकड़ों पर आधारित था और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की संचालन समिति में ब्रिटेन के लिए अतिरिक्त स्थान बनाना था), इस विचार को बढ़ावा दिया है और भारत में औद्योगिक विकास के प्रति सिद्धांत रूप में एक शुभचिंतक दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की है।

तथ्यों की छानबीन से पता चलता है कि इस विचार का दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं

है। आधुनिक युग में 1911 के युद्ध से पहले और स्यासतौर से युद्ध के बाद भारत में एक सीमा तक औद्योगिक विकास हुआ है लेकिन इस विकास की तुलना किसी भी तरह बड़े गैरसुराणीय देशों में इसी काल में हुए विकास के साथ नहीं की जा सकती। भारत में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है वह, दरअसल आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में ब्रिटिश महाननीपूजी व जबरदस्त विरोध का सामना करने और जगसे सघप करव हुआ है। यह विकास अमनुजित और एततरफा विकास है जो मुख्यतया हल्के उद्योग क्षेत्र में हुआ, निष्पायक भूमिका अदा करने वाले भारी उद्योग में बहुत मामूली विकास हुआ। जैसा कि पहले अध्याय में की गई प्रारम्भिक जाच से स्पष्ट मिलता है, यह कहना आज भी असंभव है कि भारत में सामान्यतः उद्योगीकरण की कोई प्रक्रिया घटित हुई है।

1914 तक साम्राज्यवाद, भारत में औद्योगिक विकास का घुले तौर पर और साफ साफ विरोध करता था। 1914 तक भारत के बारे में ब्रिटिश नीति उसी प्रवृत्ति से संचालित हो रही थी जिस प्रवृत्ति 1 स्वतंत्रता के युद्ध से पूर्व अमरीका के प्रति ब्रिटिश सवधा को संचालित किया था और जिम्मे अमरीकी उपनिवेशों में इस्पात भट्टियाँ स्थापित करने पर पूरी तरह प्रतिवध लगा दिया था (ऐडम स्मिथ 'वेलथ आफ नेशंस', खंड 47,2)। सर वेलेटाइन किरोल ने सरकारी तौर पर विशुद्ध भारतीय उद्यम के प्रति ईर्ष्या के बारे में 1922 में लिखा

भारतीय औद्योगिक विकास के बारे में अतीत के हमारे काम हमेशा कोई बहुत सहायनीय नहीं रहे हैं और युद्ध के कारण पड़ने वाला दबाव था जिसने विशुद्ध भारतीय उद्योग के प्रति यदि ईर्ष्या नहीं तो अलगाव की पुरानी प्रवृत्ति को त्यागने के लिए मजबूर किया। (सर वेलेटाइन किरोल का 2 अप्रैल, 1922 के आब्जर्वर' में प्रकाशित लेख)

इसी प्रकार सरकार की 1921 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया

युद्ध से कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण कारखानों और सरकारी आर्थिक सहायता के जरिए भारतीय उद्योगों को बढावा देने के लिए किए गए कुछ प्रयासों को ब्लाइटहाल की ओर से बड़े कारगर ढंग से निरुत्साहित किया गया। (मार्गल ऐंड मैटीरियल प्रोग्रेस आफ इंडिया, 1921 पृष्ठ 144)

सर जान हीवेट ने 1937 में कहा

तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का मसला सरकार और जनता के सामने पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय में है। शायद ही कोई और विषय हो जिस पर इतना कुछ लिखा या कहा गया हो लेकिन काम बहुत कम किया गया हो।

(यूनाइटेड प्राविसेज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जान होवेट का भारतीय औद्योगिक सम्मेलन में भाषण, 1907)

1921 की सरकारी रिपोर्ट में, भारतीय औद्योगिक विकास को 'व्हाइटहाल की ओर से कारगर ढंग' से निरुत्साहित 'किए जाने के उल्लेख के फलस्वरूप 1905 में लाड कंजन की पहल पर वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुई और 1908 में मद्रास सरकार द्वारा उद्योगों के लिए एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। मद्रास के उद्योग विभाग के कार्यों का 'स्थानीय यूरोपीय व्यापारिक समुदाय ने विरोध शुरू किया। इनका कहना था कि यह निजी उद्योगों के लिए गंभीर खतरा है और राज्य द्वारा सरकार के दायरे से बाहर के क्षेत्र में किया गया अनुचित हस्तक्षेप है' (इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ 70)। 1910 में सेनैटरी आफ स्टेट लाड मारले ने एक अभिगृहीत विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करके व्हाइटहाल के प्रतिग्रह को प्रयोगात्मक रूप दे दिया

सूचे में नए उद्योगों की स्थापना के प्रयासों का जो व्यौरा मद्रास सरकार ने भेजा है, उसकी मैंने जांच की है। इनके नतीजा से काफी श्रम और पटुता का पता चलता है फिर भी इनका स्वरूप ऐसा नहीं है जिसे देखते हुए इस दिशा में राज्य द्वारा किए प्रयास की उपयोगिता के बारे में सदेह न किया जा सके बल्कि ये औद्योगिक निर्देशों तक स्वयं को बड़ाई से सीमित रखें और व्यापारिक जाग्रत से बचे रहें। मुझे आपत्ति औद्योगिक सूचना का ब्यूरो स्थापित करने से या सूचना के ऐसे केंद्र से नए उद्योगों, तरीकों या उपकरणों के बारे में सलाह प्रचारित करने से नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि निजी उद्योग में दखलदाजी के इरादे से कुछ न किया जाए।  
(लाड मारले, 29 जुलाई 1910 की विज्ञप्ति)

इस विज्ञप्ति के 'घातक प्रभाव' को इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट (पृष्ठ 4) ने दर्ज किया।

भारतीय औद्योगिक विकास को हतोत्साहित करने का काम महज प्रशासनिक सक्रियता तक या निष्क्रियता तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसने अपने माफिक सीमाशुल्क नीति भी तैयार की। 19वीं सदी के सातवें और आठवें दशक में जब भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी कमजोर स्थिति से तरक्की करने लगा तो तत्काल ही इंग्लैंड में इस बात के लिए आंदोलन शुरू हो गया कि आयात किए जाने वाले सामानों पर चुगी समाप्त की जाए, यह चुगी सूती कपड़े के सामान पर भी लगती थी। 1874 में मैनचेस्टर में चैंबर आफ कामर्स ने इस आशय का एक पत्र पेश किया और 1877 में हाउस आफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजते हुए लाड साल्सबरी ने इसके मकसद को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भेजते समय इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि पांच और



मिले अब काम शुरू ही करने वाली है, और यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च 1877 के अंत तक भारत में 1, 231, 284 तकले चलन लगेंगे' (लाइ साल्सवरी का पत्र—गवर्नर जनरल के नाम, 30 अगस्त 1877)। तदनुसार 1879 में माट सूती कपड़ों पर जहां प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था, आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया और 1882 में नमक और शराब को छाड़कर सभी सामानों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया। 1894 में जब वित्तीय जरूरतों ने सूती कपड़ा सहित अन्य सामानों पर आयात शुल्क फिर से लगाने को बाध्य किया तो मिल के बने सभी भारतीय कपड़ों पर उत्पादन शुल्क थोपने का तरीका ढूँढ निकाला गया। यह ऐसा कर था जो किसी भी देश के आर्थिक इतिहास में बमिसाल है। 1896 में यह उत्पादन शुल्क 35 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया जो 1917 तक पूरी तरह लागू रहा। 1917 में आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने पर इसका प्रभाव आर्थिक रूप से कम हुआ और 1925 में जाकर यह पूरी तरह समाप्त किया गया (दरअसल यह मिल मजदूरों की हड़ताल के दबाव से हुआ)।

इन परिस्थितियों में 1914 तक औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा। 1914 तक फ्रेंच रोज ऐक्ट के अंतर्गत औद्योगिक मजदूरों की संख्या महज 9,51,000 थी। जो विकास हुआ वह मुख्यतः कपास और जूट उद्योग तक ही सीमित रहा। कपास उद्योग में भारतीय पूँजी अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी और पटसन उद्योग में ब्रिटिश पूँजी की कोशिश यह थी कि ब्रिटेन के पटसन मजदूरों की मांगों के विरोध में एक फायदेमंद हथियार के रूप में वह भारत में उपलब्ध मजदूरों का इस्तेमाल कर सकें जो सस्ते दर पर काम कर देंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केवल मरम्मत करने के लिए स्थापित कारखानों का और वह भी मुख्यतया रेलवे के लिए काम करने वाले कारखानों का अस्तित्व था। लोहा और इस्पात की शुरूआत 1914 के युद्ध के अवसर पर ही हो सकी, लेकिन मशीनों का उत्पादन अब भी शुरू नहीं हुआ था।

प्रथम विश्वयुद्ध के साथ ही सरकार ने अपनी नीति में पूरी तरह परिवर्तन की घोषणा की। सरकारी स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में उद्योगीकरण की नीति का लक्ष्य बनाने की घोषणा की गई, ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया था। नई नीति की घोषणा पहली बार भारत के वाइसराय लार्ड हाउडिंग ने 1915 में की।

यह दिनोदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि युद्ध के बाद भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक निश्चित और आत्मचेतन नीति की ज़रूरत रखना होगा नहीं तो भारत विदेशों के निर्माताओं के उत्पादनों का अंधार झुंझा करने की एक जगह बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे यह बात साफ होती जा रही है कि बड़े देशों का राजनीतिक भविष्य उनकी आर्थिक स्थिति पर

टिका हुआ है वैसे वैसे बाहरी दश अपन लिए बाजार की तलाश की होड म तजी स लगे हुए है। इस समस्या क प्रति भारतीय जनता एकमत है और इसको नजरअदाज नहीं किया जा सकता

युद्ध के बाद भारत अपने को इस बात का अधिकारी पाएगा कि वह अधिक से अधिक सहायता की माग कर सके ताकि जहा तक परिस्यतिया अनुमति दें उसे एक औद्योगिक देश के रूप म उचित स्थान प्राप्त हो सकेगा। (भारत के सचिव के नाम लाड हाडिंग का पत्र 26 नवंबर 1915)

इसके बाद 1916 म इस्टीमेट्यूट आफ मार्किंग इंजीनियर्स के अध्यक्ष सर थामस हालैंड के सभापतित्व म भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ जिसने 1918 म अपनी रिपोर्ट दी। भारतीय साविधानिक सुधारों के बारे में 1918 की मोटागू—चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में भी यही लक्ष्य निर्धारित किया गया था

सभी तरह से औद्योगिक विकास के लिए एक अग्रगामी नीति की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए ही नहीं बल्कि भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी जरूरी है

आर्थिक और सैनिक दोनों आधारों पर शाही हितों की भी यह माग है कि भारत की प्राकृतिक संपदा का अब से बहतर इस्तेमाल किया जाए। हम शक्ति के उस आवेग का अदाजा नहीं लगा सकते जो एक औद्योगिक भारत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को प्रदान करेगा। (मोटागू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, पृष्ठ 267)

नीति में इस घोषित परिवर्तन के कारणों की उत्पत्ति युद्ध की परिस्यतिया से हुई थी और इने सरकारी वयानों के जरिए बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन कारणों को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है।

सबसे पहले सैनिक और सामरिक कारण थे। युद्ध की परिस्यतियों ने, संचार और आपूर्ति व्यवस्था के नष्ट हो जान तथा मैसोपोटामिया की अपनीतियों ने भारतीय साम्राज्य की पुरानी पद्धति और पूव में ब्रिटेन की समूची सामरिक स्थिति की कमजोरी को एकदम नंगा करके सामने रख दिया। इसके कारण भारत में आधुनिक उद्योग के सर्वाधिक प्रारम्भिक आधार को विकसित करने में विफलता मिली जिसका नतीजा यह हुआ कि लंबी दूरी की समुद्रपारीय सप्लाई पर महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए निर्भर होना पडा। ब्रिटिश शासकों पर इस स्थिति का कितना जबरदस्त प्रभाव पडा इसका जायजा हमें मोटागू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट म मिल जाता है जिसमें भारत के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया गया है कि भारत 'युद्ध के पूर्वो रगमच का आधार बन सकता है।

समुद्री संचार व्यवस्था के अन्ध-धौंसी तौर पर भंग होने की सम्भावना के कारण हमें युद्ध के पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षात्मक वायवाहिया करने के लिए गोला ब्राह्म के आधार के रूप में भारत पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज के युग में औद्योगिक दृष्टि से किसी विकसित समुदाय के उत्पादन मात्रा में नहीं किन्तु अपने स्वरूप में इस सीमा तक युद्ध के हथियारों से भेल खाते हैं कि भारत के प्राकृतिक साधनों का विकास करना नगभग एक मैनिक आवश्यकता बन गया है।

दूसरे कारण वे थे जो आर्थिक होड़ से पैदा हुए थे। भारतीय बाजार पर अंगरेजों द्वारा स्थापित एकाधिकार को विदेशी प्रतियोगियों ने छ्वस्त करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही युद्ध की आवश्यकताओं से उत्पन्न ब्रिटिश औद्योगिक स्थिति के कमजोर होने से इस बात का खतरा पैदा हो गया था कि युद्ध के बाद अन्य देशों का भारत में तजी से प्रवेश होने लगेगा और ब्रिटेन के हाथ से भारत का बाजार निकल जाएगा। जैसा लाड हाडिंग ने बताया था, खतरा इस बात का है कि भारत 'विदेशी निर्माताओं के सामानों का अवसर लगाने की जगह' बन जाएगा। इसे रोकने के लिए सीमा शुल्क की प्रणाली से दो मकसद हल हगि। एक तो उससे जिस हद तक विदेशी उद्योगप्रतियों के देश में घुसने के बजाय खुद भारत के जदर उद्योग धंधों का विकास हाता था, उस हद तक अंगरेजों के लिए इस बात की सम्भावना थी कि अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण व अतन ब्रिटिश पूँजी के लिए मुनाफा निकाल सके। लेकिन यदि भारत के बाजार पर किसी स्वतन्त्र विदेशी पूँजीवादी शक्ति का कब्जा हो जाता तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहनी। दूसरे, सीमा शुल्क की व्यवस्था यदि एक बार हो जाती है तो इस बात के लिए भी रास्ता तैयार हो जाएगा कि ब्रिटेन से आने वाले माल पर शुल्क कम कराके अंगरेज भारत के बाजार पर फिर से कब्जा कर लें।

तीसरे, अदरुनी राजनीतिक कारण थे। युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद के अशांत वयों में भारत पर अपना नियन्त्रण बनाए रखने के लिए अंगरेजों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे भारत के पूँजीपति वर्ग का सहयाग प्राप्त करे और इसके लिए यह आवश्यक था कि वे यहां के पूँजीपति वर्ग को कुछ आर्थिक तथा राजनीतिक सुविधाएं दें तथा सुविधाएं देने का वायदा करे। जैसाकि लाड हाडिंग ने बड़ी ईमानदारी के साथ संकेत दिया था कि 'भारतीय जनता के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'

नीति में परिवर्तन के लिए रक्षात्मक शुल्क व्यवस्था के विकास का तरीका अपनाया गया। इस दिशा में पहले कदम के रूप में सूती कपड़े के सामान पर सीमा शुल्क बरग दिया गया और 1917 में यह 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1921 में 11 प्रतिशत कर दिया गया जबकि उत्पादों पर केवल 3.5 प्रतिशत रहत दिया गया और उसे भी 1925 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। विदेशों से आयात किए गए सामानों पर लगन बाने

कर का भी बढ़ा दिया गया और इस 1921 में 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 1922 में 15 प्रतिशत कर दिया गया। 1921 में एक वित्तीय आयोग गठित किया गया जिसने प्रत्येक मामले में पूरी छानबीन करने के बाद 'भेदभावपूर्ण मरक्षण' के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी जबकि पांच भारतीय सदस्यों की असहमति टिप्पणी ने पूरा पूरा मरक्षण दिए जाने का समयन किया। आयोग ने यह रिपोर्ट 1922 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क बोट की स्थापना की सिफारिश की गई थी 1923 में वाड की स्थापना हो गई। बोट के मामले जो पहला महत्वपूर्ण मसला विचारार्थ आया वह था लाहा और इस्पात उद्योग का मसला। 1924 में लाहा और इस्पात उद्योग को 33 1/3 प्रतिशत की दर से सुरक्षण मिला और साथ ही ग्रैन्वूटी की प्रणाली भी शुरू की गई।

इस समय भारतीय औद्योगिक पूँजीपतियों को इस बात की बहुत आशा हो गई थी कि सरकार अब उद्योगों के विकास में मदद करने की नीति का पालन करेगी। यह स्वराज पार्टी अथवा भारतीय प्रगतिशील पूँजीवाद की पार्टी का गुण था जिसने 1923 में राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधीवादी नतूदन में चलने वाली 'असहयोग' की नीतियों को विफल किया था, और 1923-26 के वर्षों में उस पार्टी की अपनी नीतियों का दबदबा बना था। इस नीति के अंतर्गत पहले तो कामिना में घुसने की बात शामिल थी ताकि अंदर से लड़ाई चलाई जाए और फिर सम्मानीय महयोग पर अमल किया जाए। लेकिन आने वाले वर्षों में इन आशयों पर जबरदस्त कुठाराघात होना था।

#### 4 उद्योगीकरण के मार्ग में बाधाएँ

1914-18 के युद्ध के बाद औद्योगिक विकास का सरकार से जो मदद मिली उसकी चरम सीमा यह थी कि 1924 में उसने लोहा और इस्पात उद्योग का मरक्षण और आर्थिक सहायता दी। इसका बाद यह देखा जा सकता है कि सरकारी मदद कम होती गई।

भारतीय औद्योगिक आयोग ने उद्योगों से संबंधित एक शाही विभाग खोलने की व्यापक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में काम करने वाले प्रांतीय विभागों का जाल बिछा दिया जाए। लेकिन इस योजना का कोई फल सामने नहीं आया। केंद्रीय संगठन को कभी स्थापना नहीं हो पाई जबकि प्रांतीय विभागों को शिक्षा विभाग की तरह 'हस्तांतरित' विषयों की सूची में शामिल कर लिया गया। इसका अर्थ यह था कि उनका अपना खर्च चलाने के लिए पैसा का अभाव रहे और इनके फलस्वरूप जो जड़ना पैदा हो उसकी समूची जिम्मेदारी भारतीय मलियों के सर पर थोप दी जाए। 1934 तक जो उपलब्धियाँ हुई थी उनका विवरण किसी गहरी निदान प्रेक्षक ने बड़ी कुशलता में पत्र किया है

उद्योगिक केंद्रीय संगठन की स्थापना आज तक नहीं हो पाई और 1919 के मानविक सुधारों के साथ प्रांतीय संगठन को शिक्षा के माध्यम से हस्तांतरित

विषय वनावर रख दिया और इस प्रकार इसे स्थानीय सरकार के हाथों में सौंप दिया जो चुने गए विधानसभा सदस्यों के प्रति जिम्मेदार है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि उपलब्ध धनराशि एकदम अपर्याप्त है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नीतियां नहीं शुरू की जा सकती। इसके अलावा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि सरकार की दूरगामी एकीकृत नीति हो जिसका सबंध केवल कच्चे माल और उत्पादन के तरीकों से नहीं बल्कि बाजार की व्यवस्था से भी हो। दरअसल इसे शिक्षा संबंधी नीति और राष्ट्रीय महत्व की लगभग सभी बातों से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें संदेह है कि भारत में स्थापित केवल प्रांतीय कार्यालयों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव हो पाएगा।  
(डी० एच० बुकानन दि डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, 1934, पृष्ठ 463-64)

अभी हाल में औद्योगिक सूचना और अनुसंधान संबंधी केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई है जिसे तीन वर्षों के लिए 37,500 पौंड की राशि निर्धारित की गई है। यह एलान किया गया कि यह ब्यूरो मुख्यतया रेशम के कपड़े तैयार करने और हथकरघा के वस्त्र बनाने पर ध्यान देगा।

अब तक घोषित व्यावहारिक परिणामों के अनुसार औद्योगिक सूचना और अनुसंधान संबंधी एक केंद्रीय ब्यूरो जल्दी ही काम शुरू करने वाला है जिसपर अगले तीन वर्षों में पांच लाख रुपये (37 500 पौंड) खर्च किए जाएंगे। यह ब्यूरो रेशम के कपड़ों और हथकरघा वस्तुओं की बुनाई पर ध्यान देगा। भारी उद्योगों को जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, एकदम अछूता छोड़ दिया गया है और देश के आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए व्यापक प्रस्तावों को यदि उनका कहीं अस्तित्व है तो, अपरिभाषित रखा गया है और वह रहस्य के आवरण में लिपटा पड़ा है। (मर एम० विश्वेश्वरैया प्लाट इकोनोमी फार इंडिया 1936, पृष्ठ 247)

1924 में लोहा और इस्पात की संरक्षात्मक गुल्को की सुविधा मिल जाने पर शुल्क बांड के पास इस तरह के संरक्षण के लिए अन्य कई उद्योगों ने भी अपने प्रायनापन्न भ्रज। अधिकांश मामलों में इन आवेदनों को मंजूर नहीं किया गया। इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मामले सीमेंट और कागज उद्योग से संबंधित थे। केवल एक प्रायनापन्न मंजूर किया गया जो माचिस उद्योग का था। इसका कारण यह था कि भारत के माचिस उद्योग में विदेशी पूंजी लगी थी।

इसने भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी लोहा और इस्पात की संरक्षात्मक प्रणाली के प्रति उस समय किया गया संतुलक जब 1927 में उस नवीकरण के लिए पण किया गया।

बुनियादी शुल्को में कमी की गई और आर्थिक सहायता समाप्त कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि एक नया सिद्धांत स्थापित कर दिया गया यह ब्रिटेन से आने वाले माल पर कम शुल्क लगाने या साम्राज्य के माल पर शुल्क लगाने में रियायत वरतने का सिद्धांत था।

यह बात अब शुल्क प्रणाली का मूल सिद्धांत बन गई थी। 1930 तक शाही सामानों के साथ रियायत वरतने के दायरे में सूती कपड़ से बने सामान आ गए थे। 1932 में आटावा समझौते हुए और व्यापक तौर पर भारतीयों के विरोध तथा भारतीय विधानसभा में असंतोष की भावना व्यक्त करने वाले मता के बावजूद साम्राज्य से आने वाले सामानों पर रियायत वरतने वाली प्रणाली को भारत पर थोप दिया गया। ब्रिटेन द्वारा भारतीय सामानों के आयात की मात्रा में वृद्धि हुई और 1931-32 में यह 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 1934-35 में 40.6 प्रतिशत हो गई। जापान तथा ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों के सूती सामान पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया (1933 में जबरदस्त व्यापारिक होड़ के दौरान एक समय इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया) जबकि ब्रिटेन के बने सूती सामानों पर शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। 1933 में शुल्क बोर्ड की रिपोर्ट ने शाही सामानों का प्रति वरती जाने वाली रियायत के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया लेकिन इसकी अवहेलना कर दी गई।

ब्रिटिश उद्योग की प्रतियोगात्मक क्षमता का प्रत्यक्ष रूप में मदद देने के अलावा शुल्क प्रणाली ने भारत में उद्योग के विकास पर अपना प्रभाव डालने के साथ मुख्यतया विदेशी हितों को फायदा पहुंचाया और इन विदेशी हितों में सबसे ज्यादा ब्रिटिश हित थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि इस संरक्षणात्मक प्रणाली का खुलकर लाभ उठाते हुए बड़े विदेशी इजारेदारों ने भारत में अपने-अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं और भारत के औद्योगिक विकास के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं।

20वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभिक दिनों में लागू शुल्क प्रणाली जिसे मूलतः भारतीय उद्योग को सहायता पहुंचाने का एक साधन घोषित किया गया था, बाद में वर्षों में ब्रिटिश उद्योग को सहायता पहुंचाने के लिए काम आने लगी। (साथ ही उसने भारत से कच्चे माल और अधनिर्मित सामानों का निर्यात के लिए अपन अनुकूल दर निर्धारित किए अर्थात् 1914 से पूर्व की स्थिति की ओर लौटने की पेशीश की)। इससे जाहिर होता है कि शुल्क प्रणाली के महत्व में उल्लंघनीय रूपांतरण हो गया। यहाँ तक कि प्रतिक्रियावादी वंजन सरकार ने 1914 में युद्ध से पूर्व भारत का लिए ब्रिटिश साम्राज्य का सामानों के प्रति वरती जाने वाली रियायत का विरोध किया था और कहा था कि इससे भारत को विमुक्त घाट का सामना करना पड़ेगा। भारत का बाजार में ब्रिटिश निर्माताओं की ही सबसे बड़ी इजारेदारी कायम थी और किसी अन्य विदेशी निर्माता के विरुद्ध नहीं बल्कि इन ब्रिटिश निर्माताओं के ही विरुद्ध भारतीय उद्योगपतियों ने मरक्षण की इच्छा जाहिर

की थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश पूँजीवाद ने भारत में सीमा शुल्कों की इच्छा मूलतः इसलि जाहिर की थी ताकि वे भारत के बाजारों को नैरब्रिटिश प्रतियोगियों के आक्रमण से बचाए रख सकें। इस प्रकार यहाँ हितों की टकराहट थी। इस संघर्ष की अभिव्यक्ति उस समय भारतीय विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से हुई जब साम्राज्यिक तरजीह की प्रणाली को और भी व्यापक बनाने वाला ओटावा समझौता और जनवरी 1935 का व्यापक समझौता 58 वें विरुद्ध 66 मतों से अमल में लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस मतदान को रद्द कर दिया और समझौते को लागू कर दिया। अब यह विरोध खुलकर सामने आ गया और 1916-18 का 'परोपकारिता' वाला वातावरण काफी पीछे छूट गया।<sup>3</sup>

इस प्रक्रिया को व्यापक आर्थिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। 1914-18 के युद्ध के तत्काल बाद विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यापार में जो तेजी आई थी उसका स्वरूप भारत में और जगहों से कहीं अधिक उग्र था। सूती कपड़े और पटसन की मिलों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। बंबई की प्रमुख कपड़ा मिलों ने औसतन जितने लाभार्जन का भुगतान किया वह 1920 में 120 प्रतिशत था और कुछ मामलों में तो यह 200-250 और यहाँ तक कि 365 प्रतिशत भी देखने में आया (आर्नॉल्डिस 'दि काटन इंडस्ट्री आफ इंडिया')। प्रमुख पटसन मिलों द्वारा दिया गया औसत लाभार्जन 140 प्रतिशत था और कहीं तो वोनस मिलाकर यह 400 प्रतिशत तक हो गया था। 1918 से 1921 तक के चार वर्षों के लिए 41 पटसन मिलों की रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि इन्हें कम से कम 2 करोड़ 29 लाख पौंड का मुनाफा हुआ। ये सभी मिलें ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन हैं और इनकी कुल पूँजी 61 लाख पौंड है। मुनाफों की जो राशि बँटाई गई है उसके अतिरिक्त इन मिलों ने 1 करोड़ 90 लाख पौंड सुरक्षित कोष में डाल दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 60 लाख पौंड की पूँजी पर चार वर्षों में इन्हें कुल 4 करोड़ 20 लाख पौंड की आय हुई।

युद्ध के बाद के वर्षों में भारत में ब्रिटिश पूँजी दस आशा के साथ तजी से आई कि वह इस जबरदस्त मुनाफे में हिस्सा बँटाएगी। पहले ही सर जाज पेश ने वर्ष 1908-10 के लिए अनुमान लगाया था कि भारत और लंका में औसतन 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 90 लाख पौंड तक ब्रिटिश पूँजी का निर्यात हुआ है, अर्थात् ब्रिटेन की विदेशों में लगी कुल पूँजी का 9 प्रतिशत भारत और लंका में है। 1921 में यह राशि बढ़कर 2 करोड़ 90 लाख पौंड अर्थात् कुल पूँजी निर्यात के एक चौथाई से अधिक भाग, 1922 में 3 करोड़ 60 लाख पौंड अर्थात् फिर एक चौथाई से अधिक भाग और 1923 में 2 करोड़ 50 लाख पौंड अर्थात् कुल पूँजी निर्यात का पाँचवा हिस्सा हो गई। 1920-21 और 1921-22 के दो वर्षों के दौरान निर्यात में नाममात्र की वृद्धि पाई गई। 1856-62 में अर्थात् रेल निर्माण में लगाई गई पूँजीवाले वर्षों के बाद पहली बार यह स्थिति पैदा हुई, लेकिन इसने वस्तुतः वृत्तिमय रूप से रूढ़िवादी की दर 2 शिफ्ट तक बढ़ा देने के सरकारी प्रयास के फलस्वरूप परिणामों का आशिक तौर पर प्रतिबिम्बित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में

आने वाले मामला पर अधिशुल्क लगा, भारतीय निर्यातकों को तबाह होना पड़ा और इस मुद्रा विनिमय को बनाए रखने के निष्फल प्रयास में सरकार के कम से कम 5 करोड़ 50 लाख पौंड खच हुए।

लेकिन 1920 और 1921 के समाप्त होते होते यह तेजी अचानक मंदी में बदल गई। सरकार की मुद्रा विनिमय नीति ने उस समय इस स्थिति को और गंभीर बना दिया जब रुपये की दर को 2 शिलिंग से घटाकर अचानक 1 शिलिंग 4 पैसे पर ला दिया गया। इसमें निर्यातकों का भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा और उन्हें 3 करोड़ पौंड से भी अधिक का नुकसान भुगतना पड़ा। कई भारतीय फर्मों जिनकी स्थापना युद्ध के बाद की तेजी के दिनों में हुई थी बाद के वर्षों में दीवालिया बन गईं। यह पता चलते ही कि युद्ध के बाद की तेजी के दिनों में होने वाला असामान्य मुनाफा अब आगे जारी नहीं रह सकता, ब्रिटिश पूँजी में कमी आने लगी। 1924 में कुल 26 लाख पौंड की ब्रिटिश पूँजी भारत आई जो उस वर्ष ब्रिटेन द्वारा निर्यात की गई कुल पूँजी के 50वें हिस्से से भी कम राशि है। 1925 में भारत आने वाली पूँजी 34 लाख पौंड, 1926 में 20 लाख पौंड और 1927 में 10 लाख पौंड से भी कम थी अर्थात् ब्रिटिश पूँजी निर्यात के प्रतिशत के आधे से भी कम अंश भारत आया।

युद्ध से पूर्व और युद्ध के बाद के दिनों में भारत और लका में आई ब्रिटिश पूँजी में सबधित निम्न आकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं (युद्धपूर्व वर्षों के आकड़े सर जात्र पैश के और युद्धोत्तर वर्षों के आकड़े मिडलैंड बैंक के हैं)

**ब्रिटिश पूँजी का भारत और लका को निर्यात  
(लाख पौंडों में)**

| वार्षिक औसत | भारत और लका को | विदेशों में निर्यात की गई कुल पूँजी | भारत और लका का प्रतिशत |
|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1908-10     | 147            | 1723                                | 8.5                    |
| 1921-23     | 302            | 1290                                | 23.7                   |
| 1925-27     | 21             | 1209                                | 1.7                    |
| 1932-34     | 42             | 1351                                | 3.1                    |
| 1934-36     | 10             | 302                                 | 3.3                    |

युद्ध के पश्चात् छोटे समय के लिए आई तेजी के बाद यह अनुपात नीचे आ गया और युद्ध से पहले के स्तर तक पहुँच गया। सरकारी लेखा जोखा देखें तो भारत में पूँजीकृत कंपनियों की कुल पूँजी का ब्योरा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है

**ब्रिटिश भारत में पूँजीकृत कंपनियों की प्रदत्त पूँजी  
(बर्मा को छोड़कर)**

|            | 1914-15 | 1924-25 | 1934-35 | 1939-40 |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| पौंडों में | 74.4    | 239.8   | 266.6   | 288.5   |



1914 से 1924 के दशक में यह वृद्धि 222 प्रतिशत थी या वार्षिक औसत 22 प्रतिशत था। लेकिन 1924 से 1934 तक के बाद के दशक में यह वृद्धि महज 11 प्रतिशत थी या वार्षिक औसत 1 प्रतिशत था। 1934 से 1939 के पांच वर्षों में भी वार्षिक औसत केवल 1.5 प्रतिशत था। यदि मूल्य स्तर में परिवर्तन की गुंजाइश छोड़ भी दें, जिससे ये आंकड़े प्रभावित होते हैं तो भी यह विषमता महत्वपूर्ण है और युद्ध के बाद के वर्षों में कुछ समय के लिए आई तेजी के बाद फिर आई गिरावट अपरिहार्य है।

1927 में 'स्टेटिस्ट' ने 1914 के आधार को 100 मानकर भारत में पंजीकृत नई कंपनियों की पूँजी का एक सूचकांक जारी किया।

ब्रिटिश भारत की दो गई नई पूँजी

| प्रतिवष                              | 1914 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| पंजीकृत कंपनियों की पूँजी का सूचकांक | 100  | 221  | 121  | 51   | 40   | 31   | 45   | 29   |

1914 के स्तर से नीचे आई जबरदस्त गिरावट पर लंदन के आर्थिक पत्र ने टिप्पणी की

जैसाकि इन अंकों से स्पष्ट है इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से बाधा पड़ी है। इसके लिए भारत सरकार की मुद्रा और विनिमय नीति को दोष दिए जाने से नहीं बचा जा सकता। ('स्टेटिस्ट,' 6 अगस्त 1927)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वव्यापी अर्थसंकट की शुरुआत से पहले ही भारत के औद्योगिक विकास में बाधाएं पड़ने लगी थी। तीसरे दशक के मध्य में भारतीय फर्मों को बड़े कठिन समय से गुजरना पड़ा। कपड़ा उद्योग से अलग औद्योगिक उत्पादन में भारतीय पूँजीपतियों का नतुत्व करने वाली कंपनी 'टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी' का 100 रुपये के शेयर 1926 में घटकर 10 रुपये के शेयर हो गए और उसे मजबूर होकर 20 लाख पाँड के ऋण पत्र के लिए लंदन के बाजार तक जाना पड़ा। ब्रिटिश महाजनी पूँजी ने युद्ध के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय उद्योग पर अपनी पकड़ अस्थायी तौर पर ढीली कर दी थी पर इन वर्षों के दौरान उसने पकड़ फिर मजबूत कर दी।

भारतीय उद्योग की एक और जबरदस्त धक्का तब लगा जब 1927 में सरकार ने भारतीय रुपये का मूल्य जो युद्ध के पहले 1 शिलिंग 4 पैसे था, स्थाई तौर पर 1 शिलिंग 6 पैसे कर दिया। सरकार ने यह कदम भारतीय वित्त और मुद्रा पर 1926 की हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद उठाया था। संयुक्त की इस नीति को भारतीय पूँजीपतियों ने

व्यापक विरोध के बावजूद जारी रखा गया। भारतीय पूँजीवाद के नेता सर पुष्पोत्तमदाम ठाकुरदास ने मुद्रा आयोग की रिपोर्ट पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि, 'इससे भारतीय उद्योगपतियों को ऐसी चोट पड़ेगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका प्रहार, और वह भी जबरदस्त प्रहार उन लोगों पर होगा जो कृषि पर निर्भर करत हैं अर्थात् आबादी का 4/5 भाग इसका शिकार होगा।' ठीक इसी समय वित्तीय नियंत्रण, जिसपर भारतीय प्रभाव की तनिका भी सभावना नहीं थी वापस लेने की दिशा में कदम उठाए गए और 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एक नया भारतीय रिजर्व बैंक खोलने का फैसला किया गया जिसकी सिफारिश हिन्टन यंग कमीशन ने की थी। अतः 1934 में भारतीय विराध के खिलाफ लव सघष के बाद इसकी स्थापना कर ही दी गई।

पहले से ही चली आ रही इन कठिन परिस्थितियों के दौरान ही विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव भारत पर आ पड़ा और इसकी चोट भारत पर किसी अन्य महत्वपूर्ण देश की तुलना में ज्यादा गहरी लगी क्योंकि भारत प्राथमिक उत्पादन पर बहद निर्भर करता था। भारत के प्राथमिक उत्पादनों का मूल्य जिसपर व्यवहारत आबादी का 4/5 हिस्सा निर्भर रहता था (इस मूल्य से कमजोर आर्थिक विकास के लिए बाजार का भी परिचालन होता था) घटकर आधा हो गया। 1928-29 से 1932-33 के बीच भारत से निर्यात किए गए सामानों का मूल्य 3 अरब 19 करोड़ रुपये से घटकर 1 अरब 35 करोड़ रुपये हो गया, भारत आए सामानों का मूल्य 2 अरब 60 करोड़ रुपये से घटकर 1 अरब 35 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी भारत में इंग्लैंड भेजे जाने वाले नजराने की राशि, ऋण पर ध्यान और घरेलू खर्च की राशि कम होने के वजह से कीमतों के गिर जाने से दुगुनी हो गई और इसे भारत से बड़ी निर्यात के साथ बसूला गया। भारत के पास न तो यूरोप की तरह हूबर ऋण स्थगन व्यवस्था थी, न जर्मनी की तरह ऋण पर रोक लगाने की योजना थी और न ही ऋण अदायगी के प्रतिपाद की ही कोई सुविधा थी जैसी सुविधा अमरीकी ऋण के मदद से ब्रिटेन को मिली थी। भारत का नजराने के रूप में अपना खजाना इंग्लैंड भेजना पड़ा। 1931 से 1935 के बीच इंग्लैंड ने भारत से कम में कम 3 करोड़ 20 लाख औंस सोना ऐंठ लिया जिसका मूल्य 20 करोड़ 30 लाख पाँड आया गया ('इकोनामिस्ट,' 12 दिसंबर 1936) अथवा वही से पहले ब्रिटेन के सुगश्ति कोप में कुल जितना सोना था यह मात्रा उससे भी अधिक थी। 1936 से 1937 के बीच भारत से 3 करोड़ 80 लाख पाँड मृत्यु का और मोना इंग्लैंड भेजा गया ('इकोनामिस्ट' 2 अप्रैल 1938)। इस प्रकार 1931-37 के सात वर्षों के दौरान कुल 24 करोड़ 10 लाख पाँड के मूल्य का सोना इंग्लैंड गया। भारत की आम जनता के आदि वचन के साधनों से अनभिज्ञ होने के कारण अपनी वचन के पैसों से मोना खरीद लेती थी। यह सोना देश की गरीब और किमांग जनता की वचन के परंपरागत तरीके का नतीजा था। वही मोना, जो भारत की निधन जनता की मामूली वचन थी, इंग्लैंड पहुँच गया। ब्रिटिश महाजनी पूँजी ने अपना स्वर्ण भंडार भरने के लिए भारतीय सोने की बड़े सुनियोजित ढंग से लूट की। बैंक ऑफ

इंटरनेशनल सैटसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश खजाने में 1932 में 3 अरब 2 करोड़ 10 लाख स्विस फ्रांक सोना था जो 1936 के अंत तक बढ़कर 7 अरब 91 करोड़ 10 लाख हो गया अर्थात् चार वर्षों में 162 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसाकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुआ था, एक बार फिर 1933-37 में ब्रिटिश पूँजीवाद ने अपना घाटा पूरा करने का जो नया तरीका ढूँढा वह भी भारत की लूट-खसोट पर ही आधारित था।

1936 के अंत तक 'इकोनामिस्ट इंडिया सप्लीमेंट' ने 'उद्योगीकरण' की प्रगति के बारे में एक निराशाजनक चित्र पेश किया

उद्योग पर निम्न तोगों की मख्या में अब कमी आने लगी है और इन कुछ वर्षों में कुछ उद्योगों में तो खामतीर से पटमन और सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाली की मख्या में बहुत कमी आई है

हालांकि भारत ने अपने उद्योगों को आधुनिक बनाना शुरू कर दिया है फिर भी यह कह सकना मुश्किल है कि भारत का 'उद्योगीकरण' हो चुका है।

(‘इकोनामिस्ट, इंडिया सप्लीमेंट, ए सर्वे आफ इंडिया टुडे,’ 12 दिसंबर 1936)

## 5 युद्ध से पहले के बीस वर्षों का लेखा जोखा

अब हम उद्योगीकरण के लिए जोश भरे वायदों की रोशनी में प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच के बीस वर्षों अर्थात् भारतीय औद्योगिक आयोग के गठन के बाद बीस वर्षों में हुए भारतीय आर्थिक विकास के परिणामों का जायजा लें।

इन बीस वर्षों की अवधि में, जिसमें मावियत सघ में समाजवादी उद्योगीकरण की ऐसी विजय देखने की मिली जिसने यूरोप और एशिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया, निस्संदेह भारत में भी कुछ औद्योगिक विकास हुआ। इसने इस विकास का आगे बढ़ावा जो ब्रिटिश सरकार के विरोध के बावजूद 1914 से पहले ही गति ले चुका था। एक के बाद एक उद्योगों ने भारत के घरेलू बाजार की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारतीय सूती कपड़ा मिलों ने जिन्होंने 1914 में भारत में इम्पेरीयल विए गए मिल निर्मित सूती कपड़ों का एक चौथाई हिस्सा नैयार किया था 1934-35 तक अपना उत्पादन बढ़ाकर तीन चौथाई कर दिया। भारतीय इस्पात उद्योग जिसकी युद्ध से पहले बस न्यापना ही हो पाई थी, 1932-33 तक भारतीय बाजार में इस्पात की जरूरतों का लगभग तीन चौथाई हिस्सा पूरा करने लगी थी (1934 में गुल्क बांड की रिपोर्ट के अनुसार)। फिर भी यह, धीमे औद्योगिक विकास का कारण इस्पात के मामले में भारतीय बाजार के अपेक्षा सीमित होने की माप का ही मुख्यतया परिचय देता है। 1935-36 में 879,000 टन इस्पात का उत्पादन हुआ जो कि एक रिकार्ड है फिर भी यह उत्पादन उसी वर्ष पोर्लैंड में हुए इस्पात के उत्पादन से कम है (जबकि पोर्लैंड की आवादी भारत की आबादी के दसवें

हिस्से से भी कम है), और 1936 में जापान में हुए इस्पात के उत्पादन के छठे भाग से भी कम है और सोवियत संघ व इस्पात उत्पादन के 19वें हिस्से व बराबर है।

लेकिन किसी देश के उद्योगीकरण के लिए निर्णायक महत्व बपड़ा उद्योग का नहीं है, जिसने 1914 से पहले हर मामले में भारत में अपना आधार मजबूत बना लिया था। किसी देश के उद्योगीकरण के लिए निर्णायक भूमिका भारी उद्योगों के विकास की लोहे और इस्पात के उत्पादन की तथा मशीनों के उत्पादन की होती है। और इसी क्षेत्र में युद्ध से पूर्व भारत की कमजोरी बिलकुल साफ थी। उस समय भी भारत मशीनों के मामले में अथ देशों पर पूरी तरह निर्भर था

हालांकि लोग बिजली से चलने वाले कारखानों में एकत्र हैं फिर भी इजीनियरिंग और टैक्सटाइल उद्योगों का रूप घरेलू उद्योगों का रूप ले रहा है। किसी बपड़ा मिल में एक के बाद एक तबले लगाने या करघे लगाने की समस्या होती है। भ्रमरमत करने के कारखानों का काम मूलतः व्यक्तिगत स्तर का है। किसी देश में सही अर्थों में तब तब्दीली आती है जब लोहा और इस्पात उद्योग सफल होने लगते हैं। धातु सबंधी उद्योगों के विकास का अर्थ सही अर्थों में औद्योगिक क्रांति है। इंग्लैंड, जर्मनी और अमरीका इन सभी देशों ने अपने यहां बपड़ा उद्योग शुरू करने से पहले आधुनिक पैमाने पर लोहा और इस्पात उद्योग शुरू किया। (एल० सी० ए० नावेल्स 'इकोनामिक डेवलपमेंट आफ दि ओवरसीज इंपायर,' पृष्ठ 443)

वास्तविक उद्योगीकरण के लिए इस आवश्यक क्रम को और भी जोरदार ढंग से सोवियत संघ की महान समाजवादी औद्योगिक क्रांति में देखा गया है। सोवियत संघ ने प्रथम पंच वर्षीय योजना में अपना सारा ध्यान भारी उद्योग पर लगाया फिर परिणामस्वरूप, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसने अपने यहां के हल्के उद्योग की प्रगति को आगे बढ़ाया। भारत इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि किसी पराधीन और औपनिवेशिक देश का आर्थिक विकास किस प्रकार एकदम उलटते क्रम से होता है।

यदि हम इस अवधि के दौरान उद्योग और कृषि में लग लोगों की संख्या की तुलना 1914 से पूर्व की संख्या से करें तो औद्योगिक विकास का निम्न स्तर और भी खुलकर सामने आ जाता है। जनगणना के आंकड़े देखने से पता चलता है कि 1911 से 1931 के बीच उद्योग पर निर्भर रहने वालों की संख्या घटी है जबकि कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उद्योग पर निर्भर लोगों की संख्या 1911 में 11.2 प्रतिशत थी जो 1921 में घटकर 10.49 प्रतिशत और 1931 में 10.38 प्रतिशत हो गई।

यहां तक कि सरकारी कागजों में भी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की जो संख्या

दज की गई है वह उल्लेखनीय है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इनकी संख्या में बहुत गिरावट आई और उद्योगों में लगे कुल मजदूरों के अनुपात में देखें तो इस संख्या में जबरदस्त रूप से सापेक्षिक गिरावट आई।

### उद्योग घरों में लगे मजदूरों का अनुपात (1911-31)

|   | 1911 | 1921 | 1931 | रूपांतरण<br>का प्रतिशत<br>1911-31 |
|---|------|------|------|-----------------------------------|
| जनसंख्या (करोड़ में)  | 31.5 | 31.9 | 35.3 | 12.1                              |
| कायरेत आबादी (करोड़ में)  | 14.9 | 14.6 | 15.4 | 4.0                               |
| उद्योग घरों में लगे व्यक्ति<br>(करोड़ में)                                | 1.75 | 1.57 | 1.53 | 12.6                              |
| कायरेत आबादी की तुलना<br>में उद्योग घरों में लगे<br>व्यक्तियों का प्रतिशत | 11.7 | 11.0 | 10.0 | 9.1                               |
| कुल आबादी में औद्योगिक<br>मजदूरों का प्रतिशत                              | 5.5  | 4.9  | 4.3  | 21.8                              |

इस प्रकार 20 वर्षों में औद्योगिक मजदूरों की संख्या में 20 लाख से भी ज्यादा की कमी आ गई। जनसंख्या में जहाँ 12 प्रतिशत से भी अधिक की कमी आई कुल आबादी में औद्योगिक मजदूरों का प्रतिशत पाँचवें हिस्से से भी ज्यादा कम हुआ। प्रमुख उद्योगों के बारे में 1911 के बाद के विवरण से भी कमी की यही तस्वीर सामने आती है।

### प्रमुख उद्योग घरों में मजदूरों की संख्या में कमी

|  | 1911      | 1921      | 1931      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| कपड़ा उद्योग   | 4,449,449 | 4,030,674 | 4,102,136 |
| सिलेसिलाएँ कपड़े और<br>प्रसाधन सामग्री तैयार करने<br>वाले उद्योग | 3,747,755 | 3,403,842 | 3,380,824 |
| लकड़ी उद्योग   | 1,730,920 | 1,581,006 | 1,631,723 |
| खाद्य सामग्री तैयार करने<br>वाले उद्योग                          | 2,134,045 | 1,653,464 | 1,476,995 |
| मिट्टी के बरतन बनाने<br>वाले उद्योग                              | 1,159,168 | 1,085,335 | 1,024,830 |

इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के पहले, भारत की जो वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आती है उसके लिए 'अनुधामीकरण' शब्द का ठीक ही इस्तेमाल किया गया है।

इसका अर्थ यह हुआ कि पुराने हस्तशिल्प उद्योग का ताश हुआ है और उसके स्थान पर आधुनिक उद्योग का विकास भी नहीं हुआ। कारखाना उद्योग की प्रगति ने हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की कमी पूरी नहीं की। विनाश की यह प्रक्रिया ही 19वीं सदी की घात बात थी और यह प्रक्रिया 20वीं सदी में तथा 1918 के बाद के वर्षों में जारी रही।

इसके नतीजे भी अपरिहार्य हैं। साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत भारत के उद्योगीकरण की तत्वीर एक धोखा है। साम्राज्यवादी शासन के बाद के वर्षों में कृषि के काम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमाव हुआ

कुछ औद्योगिक केंद्र इतने बड़े हैं कि कारखाना की स्थापना से पूर्व हस्तशिल्प उद्योग द्वारा उह जो सहारा मिलता था उसकी तुलना में अपेक्षाकृत छोटे समूह को कारखानों से प्रत्यक्ष सहारा मिलता है। आज भी यह देश निर्यात की तुलना में प्रतिवर्ष काफी अधिक मात्रा में कारखाना में बने सामानों का आयात करता है। इन अनुपातों में जहां क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी यह खासियत है कि यहाँ से कच्चे माल का काफी निर्यात और तैयार माल का आयात हो रहा है। अपने कारखानों और अपने निम्न जीवन स्तर के बावजूद भारत आज से सौ वर्ष पहले की तुलना में तैयार सामानों के मामले में अब भी कम आत्मनिर्भर है (डी० एच० बुकानन डेवलपमेंट आफ कॅपिटलिस्ट इंडस्ट्राइज इन इंडिया, 1934, पृष्ठ 451)

1931 में फैक्टरीज ऐक्ट के अंतर्गत कुछ मजदूरों की संख्या 15 लाख अर्थात् कायरत आबादी का 1 प्रतिशत से भी कम थी। यदि इसमें हम खदानों में काम करने वाले 2,60,000 लोगो और 8,20,000 रेल कर्मचारियों की संख्या जोड़ दें तो भी आधुनिक उद्योग में लगे 26 लाख लोगो की संख्या कुल कायरत आबादी का महज 1.5 प्रतिशत होती है।

इतना ही नहीं, 1914 के बाद की विकास की दर भी, जो तीव्र उद्योगीकरण की छाप से दूर हो रही, कुछ मामलों में 1914 के पहले की अवधि की तुलना में घटी रही। पृष्ठ 184 की तालिका से फैक्टरीज ऐक्ट के अंतर्गत मजदूरों की संख्या वृद्धि का पता चलता है (1922 तक यह ऐक्ट उन संस्थानों पर लागू होता था जिनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या 50 या इससे अधिक हो लेकिन 1922 से यह 20 या इससे अधिक और कहीं कहीं 10 या इससे अधिक मजदूरों वाले संस्थानों पर लागू होने लगा। जहां तक संख्या को प्रभावित करने का सवाल है यह परिवर्तन युद्धोत्तर काल के आकड़ों के लिए अधिक अनुकूल है और इसलिए हमारे तर्कों को बल प्रदान करता है)

1897 से 1914 के 17 वर्षों में कारखाना मजदूरों की संख्या में 5,30,000 की वृद्धि हुई। 1914 से 1931 के 17 वर्षों में कारखाना मजदूरों की संख्या में 4,80,000 की वृद्धि हुई।



अल्पधिन अतर्विरोध के बीच पलते रह। साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था जनता के आर्थिक विवास का अपन शिकजे म बसकर विफन और धोमा कर दती है।

ये अतर्विरोध न केवल इस रूप म मौजूद है जिनका भारत के औद्योगिक विकास म अपने विराधी हिता से सीधा वैर है और जो प्रमश क्षीण होती ब्रिटिश पूजी का हर तरीके से भारतीय बाजार में हिस्सा बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कृत सक्त्व है बल्कि वे इस रूप में भी मौजूद हैं कि वे साम्राज्यवादी शापण की स्थितियों के अतगत भारतीय उद्योग के लिए घरेलू बाजार की असाध्य समस्याएँ पैदा करते हैं और सेतिहर जनता को कगाल बना देते हैं। सीमा शुल्क प्रणाली इस अतर्विरोध को हल नहीं करती है बल्कि बामगर किसान समुदाय पर अतिरिक्त बोझ डालकर वह इस अतर्विरोध को और तज कर देती है। भारत में उद्योग धंधों की समस्या को सेती की समस्या से अलग करके हल नहीं किया जा सक्ता और सेती की समस्या का सबध साम्राज्यवादी शापण के मूल आधार से है। इस अत में ये अतर्विरोध ब्रिटिश महाजनी पूजी की सामरिक जकड म प्रकट होते हैं। इस महाजनी पूजी ने सामरिक महत्व के सभी निर्णायक स्थलों पर अपना नियन्त्रण स्थापित करके भारतीय उद्योग को अपनी दया पर आश्रित कर दिया है।

6 महाजनी पूजी की दमघोटू पकड

भारत के बारे में, भारत स बाहर जो बातचीत होती है उसमें उद्योगीकरण, सीमाशुल्क म रियायती और भारत के बाजार पर दिनोदिन कमजोर होते ब्रिटिश नियन्त्रण पर खूब बढचढकर चर्चा की जाती है, लोगों को इस बात की कम ही जानकारी है कि भारतीय अव्यवस्था पर ब्रिटिश महाजनी पूजी की जकड बढती जा रही है और भारतीयों की प्रगति के विरुद्ध इस जकड का बनाए रखने के लिए ब्रिटेन हर तरह के हथकड़े अपना रहा है।

भारतीय पूजी के विकास के बावजूद ब्रिटिश पूजी का बैंकिंग, वाणिज्य, मुद्रा विनिमय और बीमा, जहाजरानी, रेल व्यवस्था, चाय, कॉफी और खर बागाना तथा पटसन उद्योग में (जहा परिमाण के हिसाब से अपेक्षाकृत विशाल भारतीय पूजी पर ब्रिटिश नियन्त्रण है) एकाधिकारपूर्ण प्रभुत्व कारगर ढंग से बना हुआ है। समूची राजनीतिक प्रणाली इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। लोहा और इस्पात उद्योग में भारतीय पूजी को ब्रिटिश पूजी से समसौता करने का मजबूर होना पडा है। यहा तक कि भारतीय पूजी के स्रोत सूती कपडा उद्योग में, 'प्रबधम एजेंसी' (मनजिंग एजेंसी) के जरिए ब्रिटिश पूजी का नियन्त्रण जितना दिखाई देता है उससे काफी अधिक है।

मनेजिंग एजेंसी प्रणाली, भारत तथा एशिया के अन्य देशा म साम्राज्यवादी उद्योग के लिए एक खास तरह की प्रणाली है और इसका इस्तेमाल भारत के औद्योगिक विकास पर अंगरेजों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक प्रधान अस्त्र के रूप म हुआ है। इस प्रणाली



**कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की  
औसत दैनिक सख्या**

| वर्ष | सख्या     |
|------|-----------|
| 1897 | 421,000   |
| 1907 | 729,000   |
| 1914 | 951,000   |
| 1922 | 1,361,000 |
| 1931 | 1 431,000 |

इस प्रकार पहले की तुलना में 1914 के विकास की गति न सिर्फ धीमी रही बल्कि कुल वृद्धि भी पहले से कम हुई।

महा तक कि सूती कपड़ा उद्योग में, जहाँ यह वृद्धि काफी उल्लेखनीय थी, भारत में इस बढ़ती की रफ्तार जापान या चीन की तुलना में काफी कम थी। निम्न तालिका से 1914 से 1930 के बीच भारत, जापान और चीन में तखला की सख्या में मापक्षिक वृद्धि का पता चलता है (बुकानन, वही, पृष्ठ 220)

**बुनाई के तखलों की सख्या**

|       | 1914      | 1930      | वृद्धि    |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| भारत  | 6,397,000 | 8,807 000 | 2 410,000 |
| जापान | 2,414,000 | 6 837,000 | 4,423 000 |
| चीन   | 300,000   | 3 699,000 | 3,399 000 |

भारत में यह वृद्धि 37 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में जापान और चीन में यह वृद्धि 188 प्रतिशत रही। 1914 में जापान और चीन में जितने तखले काम करते थे उनको मिला दिया जाए तो भी भारत के तखला की सख्या दुगुनी से अधिक थी। 1930 तक जापान और चीन ने (और चीन की काफी कुछ प्रगति जापानी नियंत्रण के अधीन हुई) भारत को एकदम पीछे छोड़ दिया।

भारत में उद्योगीकरण की इस धीमी गति के क्या कारण हैं? इस अवरूढ़ आर्थिक विकास के लिए भारत के 'गमूचे सामाजिक' ढांचे की कई बातें जिम्मेदार हैं लेकिन इसका मुख्य कारण साम्राज्यवादी प्रणाली में ही निहित है। साम्राज्यवादी व्यवस्था की बाय प्रणाली का उच्च अनिवार्य रूप से स्वतंत्र औद्योगिक विकास के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है और इसी कारण उद्योग भारतीय जनता की उन शक्तिशाली को हर तरह से नष्ट किया है जो अल्प अवसरों पर काबू पाने में सक्षम हो सकती थीं। इसलिए उद्योगीकरण के सभी गपने और बाय

अत्यधिक अतविरोधों के बीच चलते रह। साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था जनता के आर्थिक विकास को अपन शिकजे में बसकर विफल और धोमा कर देती है।

ये अतविरोध न केवल इस रूप में मौजूद हैं जिनका भारत के औद्योगिक विकास में अपने विराधी हिता से सीधा वैर है और जो क्रमशः क्षीण होती ब्रिटिश पूँजी का हर तरीके से भारतीय बाजार में हिस्सा बनाए रखने और बढ़ाने के लिए कृत सकल्प है बल्कि वे इस रूप में भी मौजूद हैं कि वे साम्राज्यवादी शोषण की स्थितियों के अंतगत भारतीय उद्योग के लिए घरेलू बाजार की असाध्य समस्याएँ पैदा करते हैं और खेतिहर जनता को कगाल बना देते हैं। सीमा शुल्क प्रणाली इस अतविरोध की हल नहीं करती है बल्कि नामगर किसान समुदाय पर अतिरिक्त बोझ डालकर वह इस अतविरोध को और तेज कर देती है। भारत में उद्योग घटो की समस्या का खेती की समस्या से अलग करके हल नहीं किया जा सकता और खेती की समस्या का सबंध साम्राज्यवादी शोषण के मूल आधार से है। अतः ये अतविरोध ब्रिटिश महाजनी पूँजी की सामरिक जकड़ में प्रकट होते हैं। इस महाजनी पूँजी ने सामरिक महत्व के सभी निर्णायक स्थलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके भारतीय उद्योग को अपनी दया पर आश्रित कर दिया है।

## 6 महाजनी पूँजी की दमघोटू पकड़

भारत के बारे में, भारत से बाहर जा बातचीत होती है उसमें उद्योगीकरण, सीमाशुल्क म रियायतों और भारत के बाजार पर दिनोदिन कमजार होत ब्रिटिश नियंत्रण पर खूब बढ़चढ़कर चर्चा की जाती है, लोगों को इस बात की कम ही जानकारी है कि भारतीय अव्यवस्था पर ब्रिटिश महाजनी पूँजी की जकड़ बढ़ती जा रही है और भारतीयों की प्रगति के विरुद्ध इस जकड़ को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन हर तरह के हथकड़े अपना रहा है।

भारतीय पूँजी के विकास के बावजूद ब्रिटिश पूँजी का बैंकिंग, वाणिज्य, मुद्रा विनिमय और बीमा, जहाजरानी, रेल व्यवस्था, चाय, काफ़ी और खर बागाना तथा पटसन उद्योग में (जहाँ परिमाण के हिसाब से अपेक्षाकृत विशाल भारतीय पूँजी पर ब्रिटिश नियंत्रण है) एकाधिकारपूर्ण प्रभुत्व कारगर ढंग से बना हुआ है। समूची राजनीतिक प्रणाली इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। लोहा और इस्पात उद्योग में भारतीय पूँजी को ब्रिटिश पूँजी से समझौता करने को मजबूर होना पड़ा है। यहाँ तक कि भारतीय पूँजी के खेत सूती कपड़ा उद्योग में, प्रबंधक एजेंसी' (मनर्जिंग एजेंसी) के जरिए ब्रिटिश पूँजी का नियंत्रण जितना दिखाई देता है उससे काफ़ी अधिक है।

मनर्जिंग एजेंसी प्रणाली, भारत तथा एशिया के अन्य देशों में साम्राज्यवादी उद्योग के लिए एक खास तरह की प्रणाली है और इसका इस्तमाल भारत के औद्योगिक विकास पर अंगरेजों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक प्रधान अस्त्र के रूप में हुआ है। इस प्रणाली

के जरिए अपधातुत बहुत थोड़ी मैनेजिंग एजेंसी कपनिया विभिन्न औद्योगिक कपनिया और कलकारखाना का बढावा देती हैं, उनपर नियन्त्रण रखती हैं और काफी हद तक उनके लिए पूँजी इकट्ठा करती हैं, उनके संचालन और उत्पादन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखती हैं तथा उनमें निर्मित सामान का बाजार में भेजती हैं। इन कपनिया के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स एक मातहत की भूमिका निभाते हैं, उनकी नाममात्र की भूमिका होती है। मुनाफे की राशि कपनियों के हिस्सेदारा का नहीं मिलती, उसे मैनेजिंग एजेंसिया ही हजम कर जाती है। 1927 में सीमा शुल्क बोर्ड सूती वस्त्र उद्योग जाच समिति के सामने लिए गए साक्ष्य के अनुसार, 1905 से 1925 के 20 वर्षों के दौरान बंबई की कपडा मिलों ने मैनेजिंग एजेंटों को जो कमीशन दिया वह कुल प्रदत्त पूँजी का औसतन 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष था। यह राशि मैनेजिंग एजेंसी के शेयरों पर दिए गए किसी लाभांश और खरीद तथा बिक्री के जरिए मिले कमीशन के अतिरिक्त है। ऐसे भी मामले देखने में आए हैं जिसमें कपडा मिला को घाटा हुआ है पर साथ ही मैनेजिंग एजेंसी को उस मिल के कुल घाटे से ज्यादा कमीशन मिला है जिसकी वह देखरेख करती थी। उदाहरण के लिए 1927 में बंबई की 75 कपडा मिलों को कुल 7,36,309 रुपये का घाटा हुआ लेकिन मैनेजिंग एजेंटों ने भत्ता और कमीशन के रूप में 30,87,477 रुपये प्राप्त किए (पी० एस० लोकनाथन 'इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन इन इंडिया', 1935, पृष्ठ 168)।

मैनेजिंग एजेंसी कपनिया भारतीय और अंगरेजी दोनों तरह की हैं, लेकिन सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कपनिया अंगरेजी की हैं। स्वाभाविक है कि इनका सरकार और तन्त्र के साथ घनिष्ठतम संबंध है। एंड्रयू एंड कंपनी तथा जाडन एंड स्कनर जैसी फर्म भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास का एक अध्याय हैं। बंबई कपडा उद्योग के मामले में, 1927 में 'टैरिफ बोर्ड काटन टेक्सटाइल इक्वायरी' ने बंबई की कपडा मिलों से संबंधित 99 प्रतिशत आंकड़े देकर उसके आधार पर इन शक्तियों के संबंध की उल्लेखनीय तस्वीर पेश की (खंड I पृष्ठ 258 परिशिष्ट XII, वर्तमान तालिका इस परिशिष्ट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और जून 1928 के 'लेबर रिसर्च' में प्रकाशित हुई)

बंबई की कपडा मिलें

|  | मिलें | तकले      | करघे   | पूँजी<br>(करोड़ रुपये में) |
|--|-------|-----------|--------|----------------------------|
| अंगरेज मैनेजिंग एजेंटों वाली कपनिया 9  | 27    | 1,112,114 | 22,121 | 9.89                       |
| भारतीय मैनेजिंग एजेंटों वाली कपनिया 32 | 56    | 2,360,528 | 51,580 | 9.77                       |

इससे यह देखा जा सकता है कि अंगरेज मैनेजिंग एजेंटों का जहाँ केवल 22 प्रतिशत कपनिया पर नियन्त्रण था वहीं उनकी मिलों पर 33 प्रतिशत, तकलों पर 32 प्रतिशत, करघों

पर 30 प्रतिशत और पूँजी के एक बड़े हिस्से अर्थात् 50.3 प्रतिशत पर नियंत्रण था। यह ऐसे उद्योग की स्थिति है जो भारतीय पूँजी के विकास का प्रमुख क्षेत्र है।

वाद के वर्षों में उत्पन्न आर्थिक संकट ने मैनेजिंग एजेंसियों को मिला पर अपना पंजा जमाने और कुछ मामलों में तो भारतीय शेयर होल्डरों का स्वामित्व छीन लेने का मौका दिया। इस नव्य को 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है

हानाकि यह सही है कि जैसे मकट में बचई का गुजरना पड़ा, उसमें मैनेजिंग एजेंटों को काफी घाटा सहना पड़ा है क्योंकि वे अपने अधीन मिलों में प्रत्यक्ष तौर पर पूँजी लगाए हुए थे लेकिन कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें एजेंटों ने अपने कर्ज को मिलों के नाम ऋण पत्र के रूप में तबदील कर दिया, इसका नतीजा यह हुआ कि वे मिलों पूरी तरह इनके हाथ में आ गईं और शेयरहोल्डरों ने जो पूँजी इन मिलों में लगाई थी, उनसे वे हाथ धो बैठे।  
(रिपोर्ट ऑफ दि सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी, 1931, खंड I, पृष्ठ 279)

भारतीय उद्योग पर ब्रिटिश पूँजी की परकूट अब भी बनी हुई है हालांकि भारत में ब्रिटिश संपत्ति की समानि के मही सही आकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन, जैसाकि श्री ह्यू डाल्टन ने जुलाई 1946 में हाउस ऑफ कामंस में कहा था भारतीयों के हाथ में इसका स्थानांतरण ज्यादा नहीं हुआ। दूसरी तरफ एकदम उल्टी प्रक्रिया अर्थात् भारत में पूँजी की पुसपठ देखी जा सकती है। विदेशी कंपनियां ने भारत में अपनी उप कंपनियां खोल दीं और भारत में इन्हें पंजीकृत भी कराया। सीवर ब्रदर्स, डनलप, इपीरियल कैमिकल्स जैसी विशाल कंपनियां की भारत में अपनी सहायक कंपनियां हैं। और 'इंडिया लिमिटेड्स' की यह सध्या प्रतिदिन बढ़ रही है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने 1945 में केन्द्रीय विधान मंडल के वजट अधिवेशन में कहा कि 1942-43 तक के चार वर्षों के दौरान, ब्रिटिश भारत से बाहर पंजीकृत पांच कंपनियां ने अपने नाम के अंत में 'इंडिया लिमिटेड' जोड़कर भारत में व्यापार स्थापित किया। इनके अलावा, 1943-44 की समानि तक के पांच वर्षों में 108 'इंडिया लिमिटेड्स' ने भारत में अपना पंजीकरण कराया, इन कंपनियों के अंतर्गत हर तरह के उद्योग आते हैं। जैसा प्रोफेसर वाडिया और मर्चेंट ने लिखा है, 'भारी पूँजी से लग गैरभारतीय कारखानों ने माचिस, सिगरेट, साबुन, जूता, स्वर, रमायन आदि का जबरदस्त उत्पादन शुरू किया और भारतीय कारखानों को नष्ट कर दिया है। इन्होंने न केवल बड़े उद्योगों का मुकाबला किया बल्कि हमारे (भारत के) लघु उद्योगों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया' (वाडिया और मर्चेंट 'अवर इकोनामिज्म प्राब्लम', 1945 पृष्ठ 466)

भारतीय उद्योग के लिए इन 'इंडिया लिमिटेड्स' के बढ़ते खतरों के कारण बचई की

औद्योगिक और आर्थिक जाय समिति ने 1940 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा

यदि हमारी औद्योगिक नीति का लक्ष्य छोटी कंपनियों की स्थापना का प्रावधान देना है तो यदि इन बड़ी विदेशी कंपनियों को बिना उचित और कारगर वंशिक के खुद को स्थापित करने की अनुमति दी गई तो हम अपने लक्ष्य में विफल हो जाएंगे। (रिपोर्ट, 1940, पृष्ठ 168)

तो भी, ब्रिटिश महाजनी पूँजी की नियंत्रण शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विदेशी बैंकिंग व्यवस्था की है जो सरकार की वित्तीय और विनियमनी नीति के साथ मिलकर काम कर रही है। जब तक वित्तीय शक्ति पर ब्रिटिश एकाधिकार बना रहता है, भारत के सिवा स्वतंत्र पूँजीवादी विकास की बात करना एक खोखली बात के सिवा और कुछ नहीं है। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का गठन चार तरह की संस्थाओं या संस्थाओं के समूहों के द्वारा हुआ है।

1 रिजर्व बैंक आफ इंडिया, जिसकी स्थापना एक ऐक्ट के जरिए 1934 में हुई और जो 1935 से काम कर रहा है, इस व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है। बैंक आफ इंग्लैंड की तरह इस बैंक का स्वामित्व और इसपर नियंत्रण गैरसरकारी है लेकिन इसके पास मुद्रा जारी करने, मुद्रा विनियम और सरकार की बैंकिंग तथा सरकार द्वारा भेजी गई रकम का नियमन करने और इस प्रकार बैंक आफ इंग्लैंड की ही तरह वज की व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सरकार द्वारा इसके गवर्नर, दो उपगवर्नरों और पांच डायरेक्टरों को नामजद किया जाता है लेकिन इन आठ पदाधिकारियों में से छः को ही मतदान का अधिकार प्राप्त है, सरकार के नामजद लोगों में से इन छः लोगों के वोट के मुकाबले, गैरसरकारी रूप से चुने गए आठ डायरेक्टरों में से सभी का मतदान का अधिकार है। इस प्रकार बचाने के लिए इसे राजनीतिक नियंत्रण से सुरक्षा प्राप्त है। 1935 में इस नए सेंट्रल बैंक की स्थापना तथा साथ ही गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के बनाने का उद्देश्य यह था कि यदि वैधानिक सुधारों के फलस्वरूप कुछ भारतीय प्रतिनिधिकभी केंद्रीय सरकार में आ भी जाए तो आर्थिक सत्ता का यह दुगुना उनकी पहुंच से परे बना रहे, या यदि 'लंदन टाइम्स' (11 फरवरी 1928) के शब्दों में कहे तो वह 'उस राजनीतिक दबाव से, जिससे ऋण और मुद्रा की व्यवस्था को पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए, बचा रहे।' युद्ध के दौरान जिस तरीके से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने साम्राज्यवादी नीति की इच्छा के सामने घुटा टेक दिए और महज एक सरकारी विभाग के रूप में काम किया उससे साफ पता चल जाता है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के निर्वाचित सदस्यों का बहुमत मात्र एक दिखावा है और वास्तविक नियंत्रण सरकार के हाथों में निहित है। रिजर्व बैंक की प्रथम दस वर्षों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए 'इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिस्ट्स' लिखता है

इस प्रकार रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा इसके लिए तैयार किए गए फंड्स को

तकनीकी निष्पादक का काम प्रशसनीय ढंग से किया। इसमें कार्यों के सभी उपलब्ध प्रमाणों और विवेकपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर हम यह टिप्पणी करने के लिए विवश हैं कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय बांड को अपने उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं मिले। दरअसल सच्चाई यह है कि सरकार का इरादा बैंक का राजनीतिक नियंत्रण से नहीं बल्कि जनता के नियंत्रण से मुक्त रखना था। (ईस्टन इकोनामिस्ट, 25 मई 1945)

2 इंपीरियल बैंक आफ इंडिया की स्थापना 1920 के ऐक्ट के द्वारा तीन भूतपूर्व प्रेमीडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी और यह 1921 से काम कर रहा है। इसका भी स्वामित्व और नियंत्रण निजी है हानानि। इसकी स्थापना कानूनी तौर पर हुई है और इसकी अधिकृत पूंजी 90 लाख पौंड है। मूलतः इसका गठन एक केंद्रीय बैंक की तरह किया गया था जो मुद्रा जारी करने और व्यापारिक कार्यों में सरकारी बैंक की भूमिका निभा सके। 1934 के संशोधक ऐक्ट के जरिए यह अब व्यापारिक कार्यों को जारी रखने के साथ साथ रिजर्व बैंक के सहयोग से कार्य करता है। इसकी लगभग 400 शाखाएं और उपशाखाएं हैं। भारत के सभी बैंकों की कुल जमा राशि का एक तिहाई हिस्सा इस बैंक में है। 1936 में इसके 11 डायरेक्टर अंगरेज थे और चार डायरेक्टर भारतीय।<sup>4</sup>

3 एक्सचेंज बैंक अथवा भारत में काम करने वाले ब्रिटिश या विदेशी निजी बैंक। इन बैंकों के मुख्यालय भारत से बाहर हैं और इनका स्वरूप पूरी तरह अभारतीय है।<sup>5</sup> ये निर्यात और आयात व्यापार में लगी पूंजी का नियंत्रण करते हैं। 1943 में इनकी मध्या 16 थी जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे चाटर्ड बैंक आफ इंडिया, आस्ट्रेलिया एंड चाइना, दि मरकैंटाइल बैंक आफ इंडिया, दि नेशनल बैंक आफ इंडिया, दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन और लायड बैंक। भारत के बैंकों में कुछ जमा राशि का पाचवा हिस्सा इन बैंकों में जमा है।

4 दि इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स या भारत में पंजीकृत निजी बैंकों का स्थान इस व्यवस्था में सबसे नीचे है। भारतीय पूंजी केवल यही कोई भूमिका निभा पाती है लेकिन इनमें से भी कुछ बैंकों पर, मसलन इलाहाबाद बैंक पर जो सबसे बड़े बैंकों में से एक है और अब चाटर्ड बैंक आफ इंडिया, आस्ट्रेलिया एंड चाइना से संबद्ध है, विदेशी नियंत्रण कायम हो गया। इसलिए इनकी कुल शक्ति को भारतीय बैंक व्यवस्था की शक्ति नहीं माना जा सकता। इन बैंकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कई को असफलता मिली। इनमें पोपुलर बैंक आफ इंडिया, इंडियन स्पेंसी बैंक और एलायंस बैंक आफ शिमला शामिल हैं। 1922 से 1928 के बीच कम से कम 100 भारतीय बैंक बंद हो गए (इकोनामिस्ट, 12 अप्रैल 1930)।

बैंकों के इन तीन समूहों अर्थात् इंपीरियल बैंक आफ इंडिया (1921 से पहले तीन

प्रेसीडेंसी बैंको), एक्सचेंज बैंको और इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंको के पास 1913, 1920 और 1934 में वितनी जमा राशि थी, यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है

**बैंक की जमा राशि<sup>a</sup>**  
(करोड़ रुपये में)

|      | इंपीरियल बैंक आफ इंडिया<br>(या प्रेसीडेंसी बैंक) |         | एक्सचेंज बैंक |         | इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक |         |
|------|--|---------|---------------|---------|---------------------------|---------|
|      | राशि   | प्रतिशत | राशि          | प्रतिशत | राशि                      | प्रतिशत |
| 1913 | 42.4   | 43.5    | 31.0          | 31.8    | 24.1                      | 24.7    |
| 1920 | 87.0   | 36.9    | 74.8          | 31.6    | 73.5                      | 31.6    |
| 1934 | 74.9   | 33.6    | 71.4          | 32.0    | 76.8                      | 34.4    |

यह देखा जा सकता है कि अंगरेजी और विदेशी बैंक, इंपीरियल बैंक आफ इंडिया और एक्सचेंज बैंक का दबदबा कायम था। इसके अलावा इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक का मुख्य रूप से जा विकास हुआ वह 1913 से 1920 के बीच की अवधि में हुआ, इस अवधि में उनकी जमा राशि कुल बैंक में जमा राशि के एक चौथाई हिस्से से बढ़कर एक तिहाई हो गई। इसके बाद से इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक की प्रगति बढ़ी धीमी रही और यदि इनमें से कुछ के विदेशी नियंत्रण के अधीन आ जाने की बात की अनदेखी कर दी जाए तो पता चलेगा कि भारतीय पूँजी के दृष्टिकोण से इस अवधि में संभवतः ह्रास की ही स्थिति रही।

|                                       | जमा राशि<br>1938 | (करोड़ रुपये में) |        | 1943   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
|                                       |                  | 1941              | 1942   |        |
| 1 इंपीरियल बैंक आफ इंडिया             | 81.51            | 108.92            | 163.46 | 214.53 |
| 2 एक्सचेंज बैंक                       | 67.20            | 106.73            | 116.85 | 140.19 |
| कुल विदेशी बैंक में जमा राशि          | 148.71           | 215.65            | 280.31 | 354.72 |
| 3 अनुसूचित बैंक                       | 91.87            | 129.04            | 189.34 | 319.65 |
| 4 गैर अनुसूचित बैंक                   | 14.94            | 20.05             | 29.01  | 40.23  |
| इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक की कुल राशि | 106.81           | 149.09            | 218.35 | 359.99 |

युद्ध के वर्षों के दौरान भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके लिए 1938 के बाद इन तीनों बैंकों के समूह में जमा राशि की तुलना की जानी चाहिए।

पृष्ठ 190 की तालिका देखने से पता चलता है कि सम्मिलित पूँजी के सभी भारतीय बैंक (इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक) पर इंपीरियल बैंक और एक्सचेंज बैंक का दबदबा था जो 1943 तक बना रहा। केवल 1943 में जहाँ वही भारतीय बैंक ने अपनी स्थिति मजबूत की और उनकी जमा राशि इंपीरियल और एक्सचेंज बैंक की जमा राशि से लगभग 1.5 प्रतिशत अधिक हुई।

भारतीय उद्योगपतियों की सबसे जबरदस्त शिकायत यह रही है कि भारत की बैंक व्यवस्था पर ब्रिटेन के नियंत्रण का इस्तेमाल भारत के औद्योगिक और स्वतंत्र आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचाने के लिए और ब्रिटिश हितों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है। इस सिलसिले में टी० सी० गोस्वामी के उस वयान को देखा जा सकता है जो 'एक्सटर्नल कैपिटल कमेटी' की रिपोर्ट के साथ सलग्न है

मैं इस आम धारणा को व्यक्त करना चाहूँगा, जो मेरी जानकारी में पर्याप्त तथ्या पर आधारित है, कि ऋण देने के मामले में नस्लवादी और राजनीतिक भेदभाव बरता जाता है। भारतीयों के साथ प्रायः ऋण प्राप्त करने के मामले में वह सलूक नहीं किया जाता जो उनकी संपत्ति के आधार पर उनके साथ किया जाना चाहिए जबकि ब्रिटिश व्यापारियों को बहुधा इतना अधिक ऋण मिल जाता है जो व्यापार के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत उन्हें नहीं मिलना चाहिए। (टी० सी० गोस्वामी 'एक्सटर्नल कैपिटल कमेटी' की रिपोर्ट में सलग्न बक्तव्य, पृष्ठ 24)

इंडियन सेंट्रल बैंकिंग की अल्पमत (माइनारिटी) रिपोर्ट ने इस शिकायत का समर्थन किया। बहुमत (मेजोरिटी) रिपोर्ट इस शिकायत पर उत्प्रेक्षणीय रूप से मौन रही और उसने 'पूरी पूरी जानकारी के अभाव में' फैसले को स्थगित करने का एलान किया

इस तरह की कुछ शिकायतें आई हैं कि कज के लिए आई दरखास्तों पर विचार करते समय इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के अफसर नस्लवादी भेदभाव बरतते हैं। यह भी कहा गया है कि बैंक के गोरे मैनेजर्स के रहन सहन का जो ढंग है और उनका जो सामाजिक और तरीका है उससे इसी बात की ज्यादा गुंजाइश रहती है कि उनका भारतीयों की बजाय यूरोपीयों से ज्यादा प्रगाढ़ संबंध होगा और इस व्यक्तिगत जानकारी तथा संबंध के कारण कज चाहने वाली यूरोपीय कंपनियों को भारतीय कंपनियों के मुकाबले ज्यादा तरजीह मिल जाती है।

आम धारणा यह भी है कि भारतीय फर्मों के मुनाफ़े यूरोपीय फर्मों को बैंक



ज्यादा चुल्हार बज देता है और जिन भारतीय फर्मों ने बैंक से मदद ली है उनके बड़े तल्प तजुबे रहें। यह भी कहा जाता है कि गैरभारतीय फर्मों ने जहाँ बैंक से पूरी पूरी मदद ली है वहीं भारतीय फर्मों को दी गई मदद काफी कम है और फर्म की आवश्यक जरूरतों को काफी हद तक पूरा नहीं करती। इंपीरियल बैंक आफ इंडिया ने भारतीय और गैरभारतीय फर्मों को दिए गए ऋण का ध्यौरा हमारे सामने पेश किया है पर जब तक अलग अलग फर्मों के बारे में हम पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, हम इस शिकायत की जाच कर पाने में असमर्थ हैं। (मेजारिटी रिपोर्ट आफ दि इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी, 1931, खंड 1, पृष्ठ 271-72)

इसी प्रकार 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जाच समिति के अध्यक्ष स एम० विश्वेश्वरैया ने लिखा

भारत में उद्योग धंधे शुरू करने के माग में जो कठिनाइयाँ हैं उनमें प्रमुख कठिनाई वित्त की है। इसका वास्तविक कारण यह है कि देश की मुद्रा शक्ति सरकार के नियंत्रण में है और, जैसाकि हमने देखा है, औद्योगिक नीतियों के मामले में सरकार भारतीय नेताओं से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। ऐसे बैंक बहुत कम हैं जिनपर भारतीय व्यापारियों का अधिकार है और बड़े बैंक में से अनेक बैंक या तो सरकारी प्रभाव के अंतर्गत हैं या वे ब्रिटिश और विदेशी बकों की शाखाएँ हैं। (सर एम० विश्वेश्वरैया 'प्लांड इकोनामी फार इंडिया,' 1934, पृष्ठ 95)

## 7 महाजनी पूँजी और द्वितीय विश्वयुद्ध

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में स्वतंत्र भारतीय आर्थिक विकास की कीमत पर ही ब्रिटिश महाजनी पूँजी का वास्तविक प्रभुत्व मजबूती के साथ बनाए रखा गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध और इसके फलस्वरूप पूर्व में लड़ाई के सामानों की सप्लाई के लिए भारत को आधार बनाने की आवश्यकता और सभावना भी साम्राज्यवादी रणनीति में कोई तब्दीली नहीं लाई। युद्ध की संपूर्ण अवधि के दौरान ब्रिटिश नीति का हमेशा यही उद्देश्य रहा कि भारत का किसी भी तरह से उद्योगीकरण न होने दिया जाए। 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' ने 31 अगस्त 1945 को लिखा

हम सारी चीजें बना सकते थे फिर भी हमने कुछ नहीं बनाया। हम किसी भी चीज की और हर चीज की महज सप्लाई करते रहे दुनिया भर की चीजों की गरम्मत करत रहे पर हमने बनाया कुछ भी नहीं। हमारे सामने न तो कोई योजना थी और न कोई प्रणाली। बल्कि यूँ कहें कि हमारे सामने जो

योजना बड़े साफ़तौर पर थी वह थी युद्ध के बाद के वर्षों में इस देश को उद्योगीकरण से बचाने की।

फिर भी, अनिवार्यतः युद्ध के दौरान औद्योगिक गतिविधियाँ कुछ हद तक बढ़ी। भारतीय कारखानों में (इसमें हथियार बनाने के सभी सरकारी कारखाने आदि शामिल हैं) कायरत मजदूरों की संख्या 1939 में 1,751,136 से बढ़कर 1944 में 2,520,000 हो गई। ब्रिटिश भारत में सम्मिलित पूँजी की कंपनियों की प्रदत्त पूँजी 1939-40 में 2 अरब 88 करोड़ 50 लाख रुपये थी जो 1943-44 में बढ़कर 3 अरब 29 करोड़ 20 लाख रुपये हो गई। औद्योगिक कार्यों का सूचकांक (भारत में ब्रिटिश वित्तीय हितों के साप्ताहिक मुख-पत्र 'कैपिटल' द्वारा प्रतिमाह की गई गणना के अनुसार) 1939-40 में 114.0 था, जो मई 1945 में अर्थात् यूरोपीय युद्ध की समाप्ति पर बढ़कर 120.5 हो गया। जनवरी 1945 में यह अब 132.1 हो गया और यही अधिकतम अब रहा। कुछ तरह के सामानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कागज का उत्पादन बढ़ा, युद्ध से पूर्व के वर्षों में 59,000 टन कागज का उत्पादन हुआ था जो 1943-44 में बढ़कर 90,000 टन हो गया। (बाद में 1944-45 में इसमें गिरावट आई और यह 75,000 टन हो गया)। युद्ध के दौरान मिल में बने कपड़े का उत्पादन 3 अरब 80 करोड़ गज से बढ़कर 4 अरब 70 करोड़ गज हो गया ('ईस्टन इकोनोमिस्ट', 4 जनवरी 1946)। युद्ध से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप रसायनों आदि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इस्पात का वार्षिक उत्पादन 1939 में लग-भग 750,000 टन था जो 1943-44 में बढ़कर लगभग 1,125,000 टन हो गया। विशेष विस्म के एलाय और एसिड स्टील जैसे नए तरह के इस्पात का पहली बार उत्पादन हुआ। विमानों, पानी के जहाजों आदि की मरम्मत भी कुछ हद तक की गई।

लेकिन, जैसा कि भारतीय व्यापार एवं उद्योग महासंघ (इंडियन चाम्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) के अध्यक्ष सर बद्रीदास गोयनका ने कहा है, युद्ध के दिनों में भारत में उत्पादन में जो भी वृद्धि हुई वह 'मौजूदा कारखानों और मशीनों का बतहाशा चलाकर तथा मजदूरों से कई कई शिफ्टों में काम कराकर हुई है। युद्ध में लग अल्प देशों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के साधन स्थापित किए गए पर भारत में, बहुत थोड़े मामलों को छोड़कर, सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ।' ('ईस्टन इकोनोमिस्ट', 5 मार्च 1946)।

युद्ध से पहले भारतीय उद्योग अप्रयुक्त क्षमता के आधिक्य से तन्त था। उदाहरण के लिए पटसन उद्योग में तीन चौथाई से लेकर दो तिहाई अतिरिक्त क्षमता थी। बंबई मिल मालिक संघ के एन अनुमान के अनुसार उत्पादन साधना से लैंस देश की 389 बपड़ा मिलों में से 22 मिलें ऐसी थी जिनमें वर्ष 1939 में थोड़ा बहुत उत्पादन होता था या जो बिलकुल बंद पड़ी थी (पी० सी० जैन 'इंडिया विल्डम हर वार इकोनामी', 1943 पृष्ठ 4)। युद्ध के दौरान पहले तो इस अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल किया गया और बाद में बतमात्र साधना पर ज्यादा में ज्यादा बोल उठता गया। दरअसल नए

उद्योगों को शुरू करने के लिए ही नहीं बल्कि मौजूदा उद्योगों को फिर से साधन संपन्न बनाने के लिए भी आवश्यक पूंजीगत माल (कैपिटल गुड) के आयात की अनुमति नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप जो बीज पड़ा वह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए रेल यातायात को ले। युद्ध पूर्व के वर्षों की तुलना में एक यात्री गाड़ी ने 32 प्रतिशत ज्यादा और एक मालगाड़ी ने 85 प्रतिशत ज्यादा भार वहन किया, युद्ध पूर्व के दिनों में एक इंजन अपने शेड में जाने से पहले जितनी दूरी तय करता था उससे दुगुनी से भी ज्यादा दूरी उसे तय करनी पड़ी। ऐसे 29 प्रतिशत इंजनों और भारी सव्वा म रेल डिब्बों को बिना बदले इस्तेमाल में लाया गया जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका था ('स्ट्रन इकोनामिस्ट' 15 फरवरी 1946)। सूती कपड़ा उद्योग का ही उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि आज बुनाई करने वाली 50 प्रतिशत मशीनें ऐसी हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। ब्लो रूम मशीनों का उदाहरण ले तो पता चलेगा कि उद्योग में आज इस्तेमाल होने वाली इन कुल मशीनों में से 115 प्रतिशत मशीनें 1890 से पहले, 111 प्रतिशत मशीनें 1906 से 1910 के बीच, 186 प्रतिशत मशीनें 1921 से 1925 के बीच और 114 प्रतिशत मशीनें 1936 से 1940 के बीच लगाई गई थी। सूत खींचने और चलाने वाले फ्रेमों में से 355 प्रतिशत फ्रेम 1910 से पहले लगाए गए थे (वही, 7 जुलाई 1944) और इन्हीं पुराने उपकरणों को युद्ध की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ता था। जहाजों के लिए बदरगाह की उचित व्यवस्था न होने की झूठी दत्तिल देकर सरकार ने इस बात की सख्त ताकीद रखी कि युद्ध के दौरान भारत में पूंजीगत सामानों को नहीं ही भेजा जाए।

इस बात की भी कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई कि भारत के विशाल साधनों का इस्तेमाल किया जाए वरना युद्ध की स्थिति से निबटने के प्रयास खतर में पड़ जायेंगे। मोटरकार और जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना नहीं करा दी गई—इसके लिए मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी गई और मेना के लिए इन्हें खरीद जाने की भी गारंटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं अमरीकी तकनीकी मिशन की सिफारिशों का भी (जितना जल विद्युत परियोजना, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, बड़ी लाइन के इंजन बनाने आदि जैसे किसी भी दुनियादी उद्योग की स्थापना के खिलाफ साफ साफ शब्दों में और खुलकर अपना मत व्यक्त किया था) भारत सरकार ने नामजूर कर दिया।

अमरीकी तकनीकी मिशन ने देखा कि 'बवई में जहाजों की मरम्मत कराने वाले एक कारखाने में मैनिफेस्ट के जूतों में लगने के लिए द्रुमात की कीटाणुनाशक तैयार की जा रही हैं और रेल राइ के लिए स्विच मीटर बन रहे हैं जबकि बदरगाह में 100 से भी अधिक जहाज छाटी-बटी मरम्मत के इंतजार में पड़े हैं (रिपोर्ट, पृष्ठ 3)। मिशन ने, लगभग अन्य सभी उद्योगों में सुधार की सिफारिशें क अलावा, जहाजों और विमानों की भारत में उचित मरम्मत और छोटी नावों पर चढ़ाने के इंजनों माल गाड़ियां तथा अन्य निम्न की गाड़ियों के निर्माण की सिफारिशें की थी। मिशन ने वायदा किया था कि यह सब

तरह की आवश्यक मशीनें और तकनीकी सहायता अमरीका से दिलाएगा। उसके अनुसार

भारत में औद्योगिक उत्पादन के विस्तार को कम से कम आंशिक तौर पर अमरीका से पट्टे पर उधार मिले सामानों पर और इस देश के तकनीशियनों की सलाह पर आधारित करना होगा। (रिपोर्ट आफ दि अमेरिकन टेक्निकल मिशन, पृष्ठ 6)

फिर भी सरकार ने अमरीकी तकनीशियनों और तत्त्व की मदद के बावजूद उन बुनियादी सिफारिशों को मानने से इकार किया। इतना ही नहीं उसने रिपोर्ट को एकदम गुप्त रखा और प्रकाशित नहीं होने दिया।

कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे अधिराज्यों को बुनियादी उद्योग घड़े स्थापित करने और अपने आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा उठाने के लिए मदद दी गई, लेकिन भारतीय अर्थ-व्यवस्था का वही रूप बना रहने दिया गया जो पहले से चला आ रहा था, भारी उद्योग अविकसित ही रहे।

भारत के विकास को रोकने की इस नीति के लिए मुख्यतया पूर्वी क्षेत्र की सप्लाय कौंसिल (ईस्टर्न ग्रुप सप्लाय कौंसिल) की सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। इसका कार्यालय भारत में था और इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न देशों से लड़ाई के बाम आने वाले सामानों को एक जगह इकट्ठा करके फिर वितरित करना था। इस सस्या के जरिए ही सरकार ने ऐसी व्यवस्था की ताकि भारत का औद्योगिक विकास न हो सके। सरकार की दलील यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के मातहत देशों को एव ही चीज के उत्पादन में नहीं बल्कि अलग अलग चीजों के उत्पादन में लगना चाहिए। कौंसिल में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में एव सरकारी अधिकारी था और कौंसिल ने विभिन्न देशों को युद्ध सामग्रियों का आडर प्रेषित करने में बहुत सोच समझवर भेदभाव करता। बारखाना मालिका के संगठन आल इंडिया मैनुफैक्चरिंग आर्गनाइजेशन' के अध्यक्ष सर एम० विश्वेश्वरैया के अनुसार

ऐसा लगता है कि वर्तमान युद्ध के लिए आवश्यक सामानों का आडर ईस्टर्न ग्रुप सप्लाय कामें में और रोजर मिशन की सलाह पर युद्ध में लगे उन विभिन्न देशों के बीच बांट दिया गया है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हैं। जो इतना काम किए गए हैं उनके अनुसार ऐसा लगता है कि भारत के बारखानों में और उद्योगपतियों के जिम्मे वही गिना चुना सामान बनाने का काम सौंपा गया है जिगम १ तो किसी उत्तम तकनीकी बुशकता की जरूरत है और न तकनीकी व्यवहार की। जिना सामानों के निर्माण में भारी उद्योग या थ्रेण्ड तकनीकी

पुशलता की जरूरत है उन्हें अमरीका या कनाडा और आस्ट्रेलिया से वनाने को कहा गया है। (एम० विश्वेश्वरैया 'प्रास्पेक्टिवी ग्रू इंडस्ट्री,' 1943, पृष्ठ 15)

ईस्टन ग्रुप सप्लाई कौंसिल के प्रतिगामी लक्ष्य और कार्यप्रणाली को देखकर ब्रिटिश निहित स्वार्थ को दिमबर 1940 में ही काफी तसल्ली हुई थी। अक्टूबर 1940 में ईस्टन ग्रुप सप्लाई कौंसिल का अधिवेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के प्रतिनिधि श्री गार्ड लाकाक ने भी हिस्सा लिया। इसपर लंदन के 'रेलवे गजट' ने निम्न टिप्पणी का

मिशन में व्यापार वाड के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें (गार्ड लाकाक) यह काम सौंपा गया था कि युद्ध की महत्वपूर्ण जरूरतों को बरीयता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह इस बात का जायजा ले कि इस समय युद्ध के लिए किए जा रहे उत्पादनो के विस्तार का भविष्य में ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा—साथ ही श्री लाकाक का विचार है कि मिशन की यात्रा के फलस्वरूप ऐसी चीजों के उत्पादन को विस्तार देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है जो युद्ध के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जैसी कि पहले आशका थी, भारत में ब्रिटिश उद्योग के युद्धोत्तर हित ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। (सर एम० विश्वेश्वरैया 'रीकस्ट्रक्शन इन पोस्ट वार इंडिया,' में उद्धृत, 1944 पृष्ठ 15)

अमरीकी तकनीकी मिशन ने यह भी सोचा कि अब सैनिक स्थिति में चूक परिवर्तन हो गया है 'इसलिए विदेशी कमानों की ओर से भारत सरकार द्वारा की गई खरीदक लिए कौंसिल के जरिए निवासी से अब कोई खास मकसद नहीं हल होगा।' तदनुसार, मिशन ने सिफारिश की कि 'सामानों के लिए विदेशों से भारत पहुंचे आदशा पर सीधे भारत के सप्लाई डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। इसने लिए ईस्टन ग्रुप सप्लाई कौंसिल के जरिए पहले से कोई अनुमति लेना जरूरी नहीं है' और कहा कि इस कौंसिल को अब महज 'ऐसी एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए जो उत्पादन और सप्लाई के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करे और उनमें तालमेल बैठाए।' (रिपोर्ट, पृष्ठ 7)

लेकिन उपरोक्त कारणों से, भारत सरकार का जवाब, नकारात्मक था, यह सारी स्वाभाविक भी था। मिशन की रिपोर्ट पर भेजे गए अपने ज्ञापन में भारत सरकार ने कहा कि ईस्टन ग्रुप सप्लाई कौंसिल के सविधान के अंतर्गत कौंसिल से मांगा जा निर्धारित करने की अपक्षा की जाती है और कौंसिल अपने को इस अधिकार से वंचित नहा कर सकता।'।

भारत सरकार ने न केवल भारत में बुनियादी उद्योगों के विकास को रोकना बल्कि उन

विदेशी फर्मों को सीधी मदद भी पहुँचाई। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम काम-शियल कारपोरेशन ने युद्ध के दौरान 50 लाख पीड की प्रदत्त पूँजी से अपना काम शुरू किया और उसे विभिन्न देशों के साथ व्यापार का पूरा एकाधिकार दे दिया गया। इसके अलावा भारत में मोटर गाड़ियों के संयोजन तक के काम के लिए दो अमरीकी कंपनियों, जनरल मोटर्स और फोर्ड, के साथ लगभग पूरा पूरा अनुबंध कर लिया गया।

इन संपूर्ण वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास होने के बजाय भारत का जितना भयंकर शोषण हुआ वैसा ब्रिटिश शासन के संपूर्ण इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस वार में भारतीय जनता के ऊपर पिछले युद्धों से भी ज्यादा बोझ डाल दिया गया। नवंबर 1939 में ब्रिटेन की सरकार ने अपना एजेंडा, भारत सरकार के साथ एक आर्थिक समझौता किया जिसमें रक्षा व्यय को आपस में बांटने का विधान था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार भारत में प्रतिरक्षा व्यवस्था पर कुल जितनी राशि खर्च हुई, उसमें से भारत पर कितना बोझ पड़ा इसे स्पष्ट देखा जा सकता है

- 1 शांति काल की सामान्य अवस्था में भारत का रक्षा व्यय 36 करोड़ 77 लाख रुपये प्रतिवर्ष निश्चित किया गया, साथ ही,
- 2 कीमतों में वृद्धि के कारण इस मूल राशि में भी वृद्धि की गई, साथ ही
- 3 इस तरह के युद्ध संबंधी उपायों का खर्च, जो भारत ने अपने हित की रक्षा के लिए उठाए हों, उसे वहन करना पड़ा, और
- 4 ब्रिटेन की रक्षा के लिए विदेशों में लगे सैनिकों के खर्च के लिए भारत को अपने हिस्से की राशि के रूप में 10 लाख रुपये की एकमुश्त रकम अदा करनी पड़ी।

भारत को सभी स्थल सैनिकों को रखने, प्रशिक्षित करने, हथियारों से लैस करने और उनकी देखरेख करने का खर्च तब तक उठाना पड़ा जब तक वे भारत में जमे रहे और भारतीय इलाके की रक्षा के लिए उपलब्ध रहे। जब वे विदेश रवाना हो जाते थे तो वे खर्च ब्रिटेन की शाही सरकार से वसूल जा सकते थे और ब्रिटेन की शाही सरकार आगे के उनके सारे खर्चों की जिम्मेदारी ले लेती थी।

इसके अलावा, भारत में तैनात विदेशी सैनिकों को सप्लाई किए गए सभी सामान और सेवाओं का खर्च देते पर भी ब्रिटेन सहमत हो गया। इस कारण युद्ध में जापान के शामिल होने के बाद खर्चों में तब्दी से वृद्धि हुई।

यह समझौता ऊपर से देखने पर बहुत निष्पक्ष और व्यापारिक लगता था और इस बात

का आभास देता था कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षा व्यय को भारत व सिर मडना नहीं है लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह कम खुले रूप में भारत पर सारा बोझ डालने का साधन मात्र था।

एक ही परिवार के तीन सदस्य अर्थात् ब्रिटेन की शाही सरकार, भारत सरकार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया, इस बात पर सहमत थे कि रिजर्व बैंक को ब्रिटेन की शाही सरकार की ओर से किए गए इस तरह के तथा अन्य खर्चों के बदले में भारत में अधिक से अधिक कागजी मुद्रा जारी करनी चाहिए। वे इसपर भी एकमत थे कि शाही सरकार उन जारी किए गए नोटों के बराबर की स्टर्लिंग मुद्रा को बैंक आफ इंग्लैंड के खाते में जमा करती जाए। इस प्रकार पूरा समझौता भुगतान के महज बायदा तक सीमित रह गया और भारत को जबरदस्त खर्च का बोझ सहना पड़ा। भारत की अव्यवस्था पर इससे कितना बोझ पड़ा इसका पता हम भारत के रक्षा व्यय और ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय को जोड़कर लगा सकते हैं। समझौते के अंतर्गत जिन मदों में खर्च को भारत का रक्षा व्यय माना गया था वह बहद बढ़ गया और कुछ वर्षों में तो वह युद्ध की कुल राष्ट्रीय आय का एक तिहाई तक हो गया।

#### भारत का रक्षा खर्च (करोड़ रुपया में)

| वर्ष     | पूँजी लेखा पर | राजस्व लेखा पर | कुल योग |
|----------|---------------|----------------|---------|
| 1939-40  | —             | 49 54          | 49 54   |
| 1940-41  | —             | 73 61          | 73 61   |
| 1941-42  | —             | 103 93         | 103 93  |
| 1942-43  | 52 51         | 214 62         | 267 13  |
| 1943-44  | 37 46         | 358 40         | 395 86  |
| 1944-45  | 62 83         | 395 49         | 458 32  |
| 1945-46* | 14 93         | 376 42         | 391 35  |
| कुल योग  | 167 73        | 1572 01        | 1739 74 |

(रिजर्व बैंक आफ इंडिया 'रिपोर्ट आन वरेंसी ऐंड फाइनेंस, 1945-46') \*समोझित अनुमान

ब्रिटेन की शाही सरकार से वसूली योग्य माना गया युद्ध १९४५-४६ में था।

जून 1946 तक बैंक आफ इंडिया भारत पर दो करोड़ 1 अरब

59 करोड़ 69 लाख पौंड या 21 अरब 29 करोड़ 25 लाख रुपये थी। यह बकाया राशि में अब भी बढ़ती जा रही है।

### वसूली योग्य युद्ध व्यय<sup>3</sup>

| वर्ष     | करोड़ रुपये में |
|----------|-----------------|
| 1939-40  | 4 00            |
| 1940-41  | 53 00           |
| 1941-42  | 194 00          |
| 1942-43  | 325 40          |
| 1943-44  | 377 87          |
| 1944-45  | 410 84          |
| 1945-46* | 347 07          |
| कुल योग  | 1712 18         |

(वही, पृ० 48)

\*संशोधित अनुमान

संपूर्ण युद्ध काल में इस कुल राशि को भारतीय जनता की पहुँच से दूर रखा गया। स्वर्ण या सामान किसी भी रूप में भारत इस राशि को अपने काम नहीं ला सकता था। बकाया राशि में निरंतर वृद्धि होती गई पर भारत को एक भी पैसा नहीं मिला जिससे वह आवश्यक मशीनें आदि विदेशों से खरीद सकता।

भारत के मानविकी अपनी हैसियत का ब्रिटन ने भरपूर फायदा उठाया। दूसरे देशों में इन स्टैलिग बकाया के बदले में ब्रिटेन द्वारा लगाई गई पूँजी के साथ जैसा व्यवहार रहा उससे विपरीत भारत को इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई कि वह ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी पूँजी को समाप्त कर दे। केवल भारत के सावजनिक ऋण (स्टैलिग) को, जो 32 करोड़ 34 लाख पौंड था, स्वदेश लौटाने की अनुमति दी गई, शेष। अरब 27 करोड़ 35 लाख पौंड राशि अथवा वस्तुतः सदियों पुराने इस ऋण की चार गुनी राशि आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ी है। युद्ध के बाद इस आशय के प्रस्ताव आए कि कोई वहाना बनाकर उस ऋण को उधार दिया जाए या इसे कम कर दिया जाए। 1946 में गणपत आगल अमरीकी वित्तीय समझौते में जो शर्तें निर्धारित की गई थी उनमें से एक शर्त इस बारे में भी थी जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई।

इसके अतिरिक्त साम्राज्यवादी शासकों ने भारत के ऋण को भी हज़म कर लिया। युद्ध के दौरान 'डालर पूल अर्रेंजमेंट' नामक व्यवस्था की गई थी जिसके अधीन 'स्टैलिग' शेष व सभी देशों को इसके लिए मजबूर किया गया कि वे अपनी ऋण निधि को जो उन्हें



अपना सामान अमरीका को बेचकर प्राप्त हो सकती थी, एक जगह जमा करें। इस डालर कोप से भारत तथा अन्य देश अमरीका से सीधे कुछ नहीं खरीद सकते थे। इन डालर का इस्तेमाल केवल ब्रिटिश सरकार लड़ाई का सामान खरीदने के लिए करती थी। यहां तक कि डालर कोप में जमा डालर का सही आकड़ा भी नहीं प्रकट किया गया और इस राशि के बारे में विभिन्न लोगो द्वारा जो अटकलें लगाई गईं उनके बीच काफी अंतर है।

अमरीका के वाणिज्य विभाग ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि 1942 से 45 के चार वर्षों के दौरान अमरीका के साथ भारत का व्यापार सतुलन उल्लेखनीय रूप से अनुकूल रहा है और यह 42 करोड़ 10 लाख डालर के बराबर है। श्री मनु सूयंदार के अनुसार 1 अरब 14 करोड़ रुपये के मूल्य का डालर अब भी भारत के खाते में पड़ा है। 8 मार्च 1946 व 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' ने अनुमान लगाया कि अक्टूबर 1945 तक भारत ने ब्रिटेन व 'डालर पूल' को कम से कम 90 करोड़ डालर तो दिया ही होगा। लेकिन भारत सरकार के वित्तमन्त्री ने भारत द्वारा महज मार्च 1945 तक ब्रिटिश सरकार के डालर पूल में दी गई कुल राशि को 49 करोड़ 20 लाख रुपये बताया।

इस प्रकार मार्च 1945 तक यह राशि 1 अरब से 2 अरब रुपये के बीच कुछ भी हो सकती है और इस राशि में तब से ही वृद्धि हो रही है। लेकिन इस डालर कोप को बड़ी सफलता पूर्वक उन पूंजीगत सामानों के आयात में लगाने से बचाया गया जिनका इस्तेमाल भारत के उद्योगीकरण के लिए किया जाता। आज भी इस कोप को भारत के इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा रहा है। 1946 में अपने बजट भाषण में वित्तमन्त्री ने उस समय तब भी भारतीय जनता को यह बताना चाहा कि डालर पूल को बनाए रखने में उनका (भारतीयों का) हित है।

अधिक से अधिक करेंसी नोट जारी करके, युद्ध का खर्च चलाने की इस साम्राज्यवादी प्रणाली का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारत जब युद्ध की चपट से बाहर आया तब तब यह बेगल हो चुका था और आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर। युद्ध का असली भार तो उस जनता पर पड़ा जो पहले से ही भुजमरी की स्थिति में थी।

सबसे पहल हम यह देखें कि मुद्रास्फीति का किस सीमा तक सहारा लिया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्टों से ली गई इस तालिका में पता चलता है कि युद्ध मालीन वर्षों के दौरान नोट जारी करने में वस्तुतः 600 प्रतिशत वृद्धि हुई (और यह प्रतिशत आज भी जारी है), जबकि औद्योगिक वास्तवताप का सूचक अर्थ, जो 1939-40 में 114.0 था युद्ध के दौरान (जनवरी 1945 में) 132.5 व अधिकतम अर्थ तब पहुंच गया। इस मुद्रास्फीति में अनस्वरूप उद्योगपतियां और युद्ध मामलियों में टेन्शन ने बहुत भूतपाव किया।

विद्युत वितरण

(करोड़ रुपये में)

|             |        |
|-------------|--------|
| वर्ष १९३९   | १७२.११ |
| १९४०-४१     | २०२.२२ |
| १९४१-४२     | २३१.४  |
| १९४२-४३     | २४०.०० |
| १९४३-४४     | २६६.४३ |
| १९४४-४५     | २७७.११ |
| १९४५-४६     | २८८.०४ |
| २८ जून १९४६ | २९७.१३ |

कपड़ा उद्योग में हुए मुनाफों पर विचार करें। हाताकि समूचे भारत में कपड़ा उद्योग में जो मुनाफा हुआ, उसके आकरे हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिर भी सामान्य तौर पर बवाई की निचों के आकरों से इस मुनाफे का पर्याप्त आभास मिल जाता है। बवाई की कपड़ा निचों ने १९४१ में ६ करोड़ ०५ लाख रुपये का मुनाफा कमाया जो १९४० के मुनाफे की तुलना में २२५० प्रतिशत अधिक था (वाणिज्य और मर्चेंट अवर इन्डोस्ट्रियल प्रावजन, १९४५ पृष्ठ २७०)। बवाई की १५ प्रमुख कपड़ा मिलों ने १९४० में कुल ९० लाख, १९४१ में २ करोड़ ९५ लाख १९४२ में ८ करोड़ ९ लाख १९४३ में १७ करोड़ ५२ लाख और १९४४ में १३ करोड़ ६ लाख रुपये का मुनाफा कमाया (एच० टी० पारीष कामन, ७ जुलाई १९४५)

औसत विभिन्न मुनाफों का सूचक अंक

(आधार १९३९ को १०० मानकर)

(प्रति उद्योग)

|             | १९३० | १९४० | १९४१ | १९४२ | १९४३ |
|-------------|------|------|------|------|------|
| पटसन        | १००  | ५९०  | ६१७  | ८९६  | ९२६  |
| कपास        | १००  | ७३   | २०५  | ३१३  | ६१५  |
| चाय         | १००  | ११८  | २१३  | २९३  | ३०२  |
| चीनी        | १००  | १४३  | १२२  | १६०  | २१८  |
| कोयला       | १००  | ८८   | १०७  | ९५   | १२१  |
| इंजीनियरिंग | १००  | ११५  | ११०  | ३६   | २२५  |
| विविध       | १००  | १०१  | ३२६  | ३०१  | १०१  |
| हर तरह के   | १००  | १३७  | २६३  | २५०  | ३२७  |

(एम० एच० गोपाल दशरथिमान प्राविण्डम मिला १९३९, १९४१, १९४३, १९४४ पृष्ठ ७५०)



फुटकर कीमतों में और वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, बरई में दूध का दाम 2 आना प्रति पौंड से बढ़कर 1 रुपये से 2 रुपये प्रति पौंड तक हो गया। टमाटर की कीमत 2 आना प्रति पौंड से बढ़कर 10 आना प्रति पौंड हो गई, आलू की कीमत 1 आना प्रति पौंड से बढ़कर 4 आना प्रति पौंड हो गई। उत्तर प्रदेश में, जहाँ गेहूँ काफी पैदा होता है, युद्ध से पहले गेहूँ का मूल्य लगभग 4 रुपये प्रति मन था जो जुलाई 1946 में बढ़कर 18 रुपये प्रति मन हो गया। डबलरोटी की कीमत में भी वृद्धि हुई और युद्ध से पहले 8 औंस की रोटी की कीमत जहाँ 1 आना थी, 6 औंस की रोटी की कीमत ढाई आना हो गई। ड्रिल की कीमत युद्ध से पहले 7 आना प्रति पौंड थी पर जून 1943 में यह 42 आना प्रति पौंड हो गई। खाद्यान्नों के मूल्य का सूचक अकसितगर 1939 में 93 था जो सितंबर 1943 में बढ़कर 530 हो गया।<sup>10</sup>

मजदूर वर्ग के जीवन निर्वाह स्तर का सूचक अंक (अधिकांशतः कंट्रोल दरों पर की गई गणना) घटता बढ़ता रहा। मिसाल के तौर पर बरई ने मजदूरों के लिए यह सूचक अंक अगस्त 1939 में 100 से बढ़कर अगस्त 1944 में 238 हो गया और फिर मार्च 1945 में घटकर 214 तथा फिर जुलाई 1946 में बढ़कर 255 हो गया। अहमदाबाद के मजदूरों के लिए यह सूचक अंक अक्टूबर 1939 में तो 329 तक पहुँच गया था, जून 1946 में यह 297 ही रह गया।

दूसरी तरफ, मजदूरों की आय में बड़ी मामूली सी वृद्धि हुई। सभी उद्योगों में मालिकों ने जीवन निर्वाह व्यय की वृद्धि के अनुपात में महंगाई भत्ता देना से इन्कार किया। भारत सरकार के मासिक प्रकाशन 'इंडियन लेबर गजट' में जो आंकड़े दिए हैं उन पर विश्वास तो पूरा पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार कपड़ा उद्योग में 1944 में मजदूरों की कुल वार्षिक आय 100 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी, इजीनियरिंग उद्योग में 100 प्रतिशत से कम, सरकारी आड़ने-स कारखानों में केवल 50 प्रतिशत और खान उद्योग में बहुत कम 24 प्रतिशत तक रही।

सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह थी कि मजदूरों का वेतन पहले से ही इतना था जिसमें उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता था, अब उस वास्तविक वेतन में भी कटौती हुई। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे ग्रामीण जनता की भी स्थिति बेहतर नहीं थी।

इस प्रकार अत्यंत मित्त राष्ट्रों और अधिराज्यों ने विपरीत युद्ध के बाद भारत पहले से भी ज्यादा गरीब हुआ है और इसका मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति साम्राज्यवाद का दृष्टिकोण था जिसने भारत को हमेशा एक पिछड़ा उपनिवेश बनाये रखना चाहा। युद्ध के कारण पड़ने वाले बोझ के कारण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का अवसर हाथ से निकल गया बल्कि भारत को आज अत्यंत गंभीर औद्योगिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

प्रेमसागर गुप्त द्वारा की गई गणना के अनुसार प्रवाई शहर की 69 कपडा मिला ने, जिनमे कुल प्रदत्त पूजी 13 करोड 93 लाख रुपये की थी, युद्ध के पांच वर्षों के दौरान इस पूजी का भाडे छ गुना विमुद्ध मुनाफा कमाया। इन वर्षों का वार्षिक औसत 1939 के मुनाफा की तुलना मे 26 गुना से भी अधिक है।<sup>19</sup> विभिन्न उद्योगों मे हुए मुनाफों के पृष्ठ 201 पर दिये गये सूचकांक देखने से भी यही तस्वीर उभरती है।

यहा तक कि मुनाफों का सरकारी सूचक अंक (भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तुत), जो स्पष्टतः कम करके बताया गया है और जिसमे अधिकतम मुद्रास्फीति वाले वर्ष अर्थात् 1942 तक की अवधि और इसनिष्ठ 1943 तक के मुनाफों को रखा गया है, वास्तविक प्रवृत्ति को नहीं छिपा सका।

मुनाफों का सूचक अंक  
(आधार 1928 को 100 मानकर)

|                        | 1939  | 1942  |
|------------------------|-------|-------|
| कपास                   | 154 6 | 760 7 |
| पटसन                   | 13 6  | 49 2  |
| चाय                    | 96 2  | 219 5 |
| कोयला                  | 139 1 | 110 3 |
| चीनी                   | 179 4 | 219 8 |
| लोहा और इस्पात         | 289 3 | 403 3 |
| कागज                   | 151 8 | 488 4 |
| सभी उद्योगों<br>का योग | 72 4  | 169 4 |

इस समूची प्रक्रिया ने किसान मजदूर जनता पर अकथनीय कष्ट और जुल्म टाण। पूरे 6 वर्षों तक भारत की जनता को वेतन मे तरह तरह की कटौतियां, भोजन और वस्त्र के अभाव तथा देशव्यापी अकालों और गरीबी का सामना करना पडा।

भारत सरकार के आकड़ों के अनुसार खाद्यान्नों की थोक कीमतों का सूचक अंक अगस्त 1939 मे 100 था पर अगस्त 1941 मे 122 9, अगस्त 1942 मे 163 2 और जुलाई 1943 मे 300 2 हो गया। जनवरी 1944 मे इसमे गिरावट आई और यह 233 0 हो गया लेकिन इस गिरावट का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने जो कंट्रोल कीमतें निर्धारित की थी वे बाजार की दरसे कम थी। इसके बाद इस सूचक अंक मे थोड़ी सी तत्काली हुई और दिसंबर 1945 मे यह 238 8 हो गया। दरअसल, कीमतों मे पहले से बड़ी अधिक वृद्धि हुई क्योंकि कंट्रोल दर पर चीजें मुश्किल से ही उपलब्ध होती थी। देश भर में काना बाजारी एक सामान्य बात हो गई।

फुटकर कीमतों में और बढ़ि हुई। उदाहरण के लिए, चन्ई में दूध का दाम 2 आना प्रति पौंड से बढ़कर 1 रुपये से 2 रुपये प्रति पौंड तक हो गया। टमाटर की कीमत 2 आना प्रति पौंड से बढ़कर 10 आना प्रति पौंड हो गई, आलू की कीमत 1 आना प्रति पौंड से बढ़कर 4 आना प्रति पौंड हो गई। उत्तर प्रदेश में, जहाँ गेहूँ काफी पैदा होता है, युद्ध से पहले गेहूँ का मूल्य लगभग 4 रुपये प्रति मन था जो जुलाई 1946 में बढ़कर 18 रुपये प्रति मन हो गया। उवलरोटी की कीमत में भी वृद्धि हुई और युद्ध से पहले 8 आँस की रोटी की कीमत जहाँ 1 आना थी, 6 आँस की रोटी की कीमत ढाई आना हो गई। ड्रिल की कीमत युद्ध से पहले 7 आना प्रति पौंड थी पर जून 1943 में यह 42 आना प्रति पौंड हो गई। खाद्यान्नों के मूल्य का सूचक अक सितंबर 1939 में 93 था जो सितंबर 1943 में बढ़कर 530 हो गया।<sup>10</sup>

मजदूर वर्ग के जीवन निर्वाह स्तर का सूचक अक (अधिकांशतः कटोल दरों पर की गई गणना) घटता बढ़ता रहा। मिसाल के तौर पर बर्बई ने मजदूरों के लिए यह सूचक अक अगस्त 1939 में 100 से बढ़कर अगस्त 1944 में 238 हो गया और फिर मार्च 1945 में घटकर 214 तथा फिर जुलाई 1946 में बढ़कर 255 हो गया। अहमदाबाद के मजदूरों के लिए यह सूचक अक अक्टूबर 1939 में तो 329 तक पहुँच गया था, जून 1946 में यह 297 ही रह गया।

दूसरी तरफ मजदूरों की आय में बड़ी मामूली सी वृद्धि हुई। सभी उद्योगों में मालिकों ने जीवन निर्वाह व्यय की वृद्धि के अनुपात में महंगाई भत्ता देने से इकार किया। भारत सरकार के मासिक प्रकाशन 'इंडियन लेबर गजट' ने जो आंकड़े दिए हैं उन पर विश्वास तो पूरा पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार कपड़ा उद्योग में 1944 में मजदूरों की कुल वार्षिक आय 100 प्रतिशत में थोड़ी अधिक थी, इजीनियरिंग उद्योग में 100 प्रतिशत से कम, सरकारी आड़ने-स कारखाना में केवल 50 प्रतिशत और खान उद्योग में बहुत कम, 24 प्रतिशत तक रही।

सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह थी कि मजदूरों का वेतन पहले से ही इतना था जिसमें उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता था, अब उस वास्तविक वेतन में भी कटौती हुई। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, ग्रामीण जनता की भी स्थिति बेहतर नहीं थी।

इस प्रकार अन्य मित्र राष्ट्रों और अधिराज्यों के विपरीत युद्ध के बाद भारत पहले से भी ज्यादा गरीब हुआ है और इसका मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति साम्राज्यवाद का दृष्टिकोण था जिसने भारत को हमेशा एक पिछड़ा उपनिवेश बनाये रखना चाहा। युद्ध के कारण पड़ने वाले बोझ के कारण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण का अवसर हाथ से निकल गया बल्कि भारत को आज अत्यंत गंभीर औद्योगिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

## 8 महाजनी पूजी और नई साविधानिक योजना

ब्रिटिश शासक द्वारा जितने भी साविधानिक सुधार किए गए उनका उद्देश्य यही था कि भारत में ब्रिटेन के निहित स्वार्थों को किसी तरह वन रहने दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए तथा उनको और मजबूत बनाया जाए। 1946 में ब्रिटिश पैरियेंट मिशन के साथ जो सबसे ताजा समझौता हुआ है, उसकी यदि जांच पड़ताता हो तो पता चलेगा कि भारत को औपचारिक आजादी देने का दिखावा करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद अब भी अपने आर्थिक प्रभुत्व को कायम रखने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटिश पूजी के हितों का ज्यादा से ज्यादा पूर्ति के लिए भारत के औद्योगिक विकास का रोकने की नीति, युद्ध के बाद के वर्षों में भी जारी है लेकिन अब उसने नया रूप ग्रहण कर लिया है। इसकी अभिव्यक्ति उन व्यापार समझौता में होती है जो ब्रिटिश भारत में और राजा महाराजाओं की भारतीय रियासतों में संयुक्त रूप से व्यापार स्थापित करने के लिए भारतीय और ब्रिटिश उद्योगपतियों के बीच हुए हैं।

1935 के इंडिया ऐक्ट की धारा 3 से लेकर CXXI तक का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन के निहित स्वार्थों को निश्चित रूप से कुछ आर्थिक और वित्तीय 'सुरक्षण' प्रदान करना है। आर्थिक या वाणिज्यिक 'भेदभाव' को रोकने के नाम पर इन धाराओं के जरिए ब्रिटिश गवर्नरों को इस बात का असंमित अधिकार दिया गया कि यदि कोई भारतीय मतालय ब्रिटिश हितों की कीमत पर भारतीय वाणिज्य या उद्योग का पक्ष ले रहा हो तो उस रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए।

लेकिन ब्रिटिश पूजी के प्रति यह खुली तरफदारी अब ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। इन 'सुरक्षा उपायों' का समाप्त करने की मांग अब काफी जबरदस्त हो गई है। 4 अप्रैल 1945 को केंद्रीय विधानसभा ने, श्री मातु सुवेदार के प्रस्ताव को बिना मतभेद के पारित कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि 'इंडिया ऐक्ट' से इन धाराओं का निकाल दिया जाए। 12 मार्च 1945 को अपना प्रस्ताव पेश करते हुए श्री सुवेदार ने कहा था

यूरोपीय फर्मों ने अपनी क्षेत्रीय सीमा से बाहर के जिन अधिकारों को भारत में चाहा है उसकी मिसाल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के किसी भी देश की सविधि में नहीं मिलती।

इसके अलावा युद्ध ने अब एकदम नई परिस्थिति पैदा कर दी है। युद्ध का खर्च चलाने की प्रक्रिया में, जिसका बुनियादी उद्देश्य युद्ध के समूचे भार को भारत पर ढाल देना था, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब साम्राज्यवाद भारत के औद्योगिक विकास की पहली की तरह अर्थात् उद्योगोत्थरण की मांग को सीधे सीधे और एकदम नामजूर करके, नहीं रख सकता।

भारतीय उद्योगपति आज पहले के किसी समय की तुलना में ज्यादा ही शक्तिशाली हो चुके हैं। युद्ध के फलस्वरूप उन्हें इतना जबरदस्त मुनाफा हुआ है कि उनके पास अब उद्योगों में लगाने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी है। परिणामस्वरूप उद्योगीकरण की मांग अब काफी बड़ी है।

इस पूंजी के अपने पास होने के कारण ही भारतीय उद्योगपतियों को यह विश्वास है कि उनका आधार काफी सुरक्षित है। उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्र आर्थिक योजना की भी बात सांचनी शुरू कर दी है। युद्ध के बाद के वर्षों के लिए पेश की गई अनेक गैरसरकारी योजनाओं के अलावा, बड़े बड़े भारतीय उद्योगपतियों ने स्वयं एक योजना तैयार की है जिसे अमल में लाकर वे 15 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय दुगुनी करना चाहते हैं। इस योजना का नाम 'भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना' था। इसका आमतौर से प्रचलित नाम 'ववई योजना' है। यह योजना कितनी भी प्रतिनियमावादी क्या न हो लेकिन इसने देश भर का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें उद्योगीकरण की उत्कट इच्छा की शलक मिलती थी। इसके अलावा, अब चूंकि भारतीय उद्योगपतियों के पास अपने मुताबिक खच करने के लिए आवश्यक पूंजी है इसलिए वे सहायता के लिए आज अमरीका तथा अन्य देशों की ओर देख रहे हैं और यह काम वे ब्रिटन से स्वतंत्र हाकर अपने आप कर रहे हैं।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद इन परिवर्तनों को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं है। हाउस आफ कामंस में एक बहस के दौरान 'रायल सोसायटी के सेक्रेटरी और ससद सदस्य (कंजरवेटिव) श्री ए० बी० हिल ने कहा

यदि हम साहस, उदारता और दूरदर्शिता का परिचय दें तो भारतीय उद्योग के साथ सहयोग करने का हमारे पास मौका है लेकिन यदि हम ऐसा नहीं किया तो जमका अर्थ यह नहीं कि भारतीय उद्योग का विकास नहीं होगा बल्कि इसका अर्थ यह कि भारत के लोग सहायता के लिए हमारे पास आने के बजाय अमरीका के पास चले जायेंगे। (इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1944, खंड 2, पृष्ठ 302)

इसलिए इन नई बातों का ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अब भारतीय उद्योगधंधों के विचारों के विरोध का स्वरूप बदलना पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र की ही तरह आर्थिक क्षेत्र में भी साम्राज्यवाद अब अपने का नए युग के अनुरूप ढालने लगा है। ब्रिटन जब भारत में अपने निहित स्वार्थों को भारतीय पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करके ही बनाए रख सकता था, भारत के उद्योगीकरण पर आक्रमण की योजना अब बाहर से नहीं बल्कि भीतर घुसकर तैयार की जा सकती थी। भारतीय इजारादारा की मजदूरी से ही भारत का ब्रिटन का कारखाना में बने सामान का निर्यात बाजार बनाए रखा जा



मकता था। इस प्रकार भारत को तकनीकी मदद देने के बहाने जिसकी बहुत जरूरत थी, साम्राज्यवाद ने अपने आर्थिक हिता को बनाए रखने की एक नई चाल अपनाई, और यह चाल थी भारतीय उद्योगपतियों के साथ व्यापार में साझेदारी (पाटनरशिप)। साम्राज्यवाद ने एक दूसरे पर निर्भरता और हिंसा की एकता का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, हाल की इन सभी घटनाओं और घोषणाओं ने हमारे सामने इस सच्चाई को एकदम खोलकर रख दिया कि सयुक्त हिस्सेदारी के जरिये साम्राज्यवाद भारत को छोड़ने के बजाय इसपर अपनी वित्तीय और आर्थिक जकड़ मजबूत करता जा रहा है, इन समझौतों के जरिये भारत में स्वतंत्र आर्थिक विकास की छूट देने की बजाय, भारत के औद्योगिक विकास का अदर से तहस-नहस करने की योजना बन रही है और कोई रूप ग्रहण कर रही है।

नई साम्राज्यवादी नीति की व्यवस्था करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त सदस्य सर आर्किवालड रोलैंडस ने भारत से विदाई के अवसर पर कहा कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध भविष्य में चाहे कैसे भी क्यों न रहे, यह दोनों के हित में है कि 'उद्योग, धन, व्यापार और मस्जुति के क्षेत्र में उनके संबंध पहले की अपक्षा अधिक घनिष्ठ बनाए जाएं। वामन बयर्ड, 8 जून 1946)

लाड वेवेल का वयान और भी साफ था। वह ब्रिटेन के पजीपतियों को यह आश्वासन देने में लगे थे कि '1935 के इंडिया ऐक्ट में 'व्यापारिक हिता की सुरक्षा' की जो धारणा है वह हटाई नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि यदि भारत और ब्रिटेन के पूजीपति साझे में व्यापार करे तो यह भविष्य में अंगरेजों के आर्थिक हिता की पूर्ण सुरक्षा का एक उपाय हो सकता है। कलकत्ता के एगोमिण्टेड कैबिनेट आफ बामा में चोलेते हुए लाड वेवेल ने '10 दिसंबर 1945 को कहा

में 'तही मोत्तता कि जब तक वास्टीटयूशन ऐक्ट और भारत एक्ट ब्रिटेन के बीच दुई व्यापारिक संबंधों में एक सामान्य मशाघन तही किया जाता तब तक इंडिया ऐक्ट की व्यापारिक हिता की सुरक्षा मजबूती धाराओं का पूरी तरह समाप्त किए जाने की कोई सम्भावना है। लेकिन भारत सरकार भारतीयों की इस गलत आशाना में पूरी तरह अवगत है कि वे क्यागभव अपनी गुप्त की पत्नी में और अपनी देशेष्ट्य में बुनियाती उद्योग धंधों का विभाग करना और उनपर नियंत्रण रखना चाहता है, और उनकी इस आशाना का अवरोधन नहीं की जाएगी। फिर भी मैं समझता हूँ कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए सम्भाव्य और मौजूदा संबंधों का पूर्ण विकास की सुरक्षा में सम्भाव्य सम्पूर्ण है। और इस तरह के संबंध स्थापित करके हमें एक सम्पूर्ण और भविष्य में सम्भाव्य हिता के लिए मजबूती अर्थात् सुरक्षा मिल सकती है। मगर हमें यह विचार है कि सम्भाव्यता वास्तविकता में अलग है और भारत

उद्योगों के बीच सहयोग से ही भारत का औद्योगिक विकास अत्यंत तेजी से और लाभदायक ढंग से संभव है। (टाइम्स आफ इंडिया, 11 दिसंबर 1945)

इसे आपसी सहयोग के लिए दी गई परोपकारितापूर्ण दलील न समझा जाए इसलिए कुछ अन्य प्रवक्ताओं ने ब्रिटिश पूंजीवाद की ओर अधिक सुनिश्चित मार्गों की। भारत में ब्रिटिश वित्त व्यवस्था के मुखपत्र 'कैपिटल' ने 15 नवंबर 1945 को लिखा

ब्रिटिश व्यापार का ऐसा कोई इरादा नहीं कि वह इस समय या बाद में बस देश के बाहर निकल जाए भले ही कुछ लोगों की निगाहों में इसकी भूमिका भविष्य में एक मातहत की भूमिका हो पर वह उस देश से खदेड़े जाने को तैयार नहीं होगा जिसकी समृद्धि में इसका जबरदस्त योगदान रहा हो।

एसोसिएट्स चैम्बर्स आफ कामर्स के अध्यक्ष सर रेनविक हैडो ने 10 दिसंबर 1945 को कहा

ब्रिटेन में ऐसे कई उद्योगपति हैं जिन्हें यदि उचित व्यवहार का आश्वासन मिले तो वे भारत में कारखाना स्थापित करने के लिए तैयार होंगे जिससे भारत का स्याई फायदा होगा। लेकिन यह स्वाभाविक है कि वे किसी दूसरे के लगाने और खर्च करने के लिए पैसा देने को तैयार नहीं होंगे। कोई ऐसी एकतरफा व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें ब्रिटेन तो पूंजीगत सामान और विशेषज्ञों की सुविधाएं प्रदान करे और जंगरेजों को भारत आकर नए उद्योग धंधे शुरू करने तथा जो पहले से मौजूद हैं उनकी देख रेख करने के लिए हतोत्साहित किया जाए। (टाइम्स आफ इंडिया, 11 दिसंबर 1945)

रायल सोसायटी के सेक्रेटरी प्रो० ए० बी० हिल ने ब्रिटेन की मांगों को और भी स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी

चाहे जो हो, उन्हें (भारतीयों को) यह महसूस करना होगा कि ब्रिटिश उद्योगों में सारी चीजें महज निस्स्वाय भाव से नहीं करने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उन्हें यह आशा होगी कि ब्रिटेन अपनी दक्षता और साधनों से कोई ऐसा उद्योग स्थापित करेगा जिसपर उसका मामूली सा नियंत्रण होगा। यदि वे विकास करना चाहते हैं तो उनकी यहाँ के लोगों के साथ बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आधे आधे की हिस्सेदारी ही उचित मालूम देती है। ('भारत ज्योति', 1 अप्रैल 1946)

और ब्रिटिश साम्राज्यवादी भारतीय उद्योगपतियों को अपने साथ साझेदारी के लिए

मजदूर करने में अपने शासकों होने का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हालांकि भारतीय उद्योग पतियों ने युद्ध के दौरान भारी मुनाफा कमाया और अपनी स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत कर ली फिर भी अभी ब्रिटिश पूँजीपतियों का ही पलड़ा भारी रहता है। राज्य व्यवस्था का उनका नियंत्रण है और इसलिए वे पूँजीगत सामानों के आयात पर भी नियंत्रण रखते हैं, उनका भारत के समूचे स्टैलिंग सतुलन पर नियंत्रण है। वे भारत के सभी बाजारों को हर तरह की उपभोगता सामग्रियों से पाट सकते हैं और ऐसा करने की वे काशिश भी कर रहे हैं।<sup>11</sup> भारतीय उद्योगपतियों का अपनी शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर करने में वे अपनी इसी विशेष सुविधायुक्त स्थिति का इस्तेमाल करते हैं।

भारत, बर्मा और लवा के लिए भूतपूर्व ब्रिटिश ट्रेड कमिशनर सर टी० सैंसवफ ने ब्रिटिश पूँजीपतियों की एक बैठक में बोलते हुए बड़े साफ शब्दों में उन अनुकूल स्थितियों का वर्णन किया जो भारतीय व्यापारियों की तुलना में ब्रिटिश के बड़े व्यापारियों को प्राप्त है

भारतीय व्यापार और देश की विशिष्ट जरूरतों के बारे में हमारे अनुभव, बाजार में हमारे निहित स्वार्थ, हमारे बेजोड़ व्यापारिक संपर्क और हमारी ख्याति जिसमें हमारी कजदार की स्थिति से मिला लाभ जुड़ जाना चाहिए की यदि पूरा पूरा महत्व दिया जाए तो निश्चय ही यह आशा की जा सकती है कि भारत एक बार फिर हमारे सामान के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार हो सकता है। ( 'वावे क्रानिकल', 5 मार्च 1945 रेखांकन जोड़ा गया है)

भारतीय और ब्रिटिश पूँजीपतियों के बीच कई समझौते भी संपन्न हुए। जून 1945 में भारत की सबसे बड़ी इजारदार फर्मों में से एक फर्म बिडला ब्रदर्स लिमिटेड और इंग्लैंड के नफील्ड संगठन के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत भारत में मोटरकारों का निर्माण होना था। बिडला नफील्ड समझौते का उद्देश्य, समाचारपत्रों में छपी खबरों के अनुसार (समझौते की वास्तविक शर्तें प्रकाशित नहीं की गईं), भारत में समुक्त रूप से एक कंपनी स्थापित करना था। इससे नफील्ड का 25 से 30 प्रतिशत तक शेयर होना और मुनाफे तथा पेटेंट की रायल्टी आदि में अच्छा खासा हिस्सा उसे मिलना। नफील्ड संगठन को ऐसे 'तकनीकी हिस्से पुरजे सप्लाय' करने और बनाने थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत में नहीं बनाया जा सकता था और नफील्ड के तकनीशियनों को ही इस बात का भी फैसला करना था कि कौन से उपकरण भारत में और कौन से ब्रिटेन में बनाए जाएं। (नैपिटल, 3 जनवरी 1946)।

इसी तरह का एक समझौता दिसंबर 1945 में भारत की एक बड़ी इजारदार फर्म टाटा ग्रुप और इपीरियन कैमिकल इंडस्ट्रीज के बीच हुआ। आई०सी०आई० ग्रिप्स की सबसे बड़ी इजारदार मस्था है और इस समझौते का उद्देश्य भारत में भारी रसायन उद्योग स्थापित

करना था। समाचारपत्रों में प्रकाशित चरित्रों के अनुसार इस उद्योग में 24 प्रतिशत पूँजी आई०सी०आई० की होगी और शेष हिस्सा टाटा ग्रुप का होगा। इसके अलावा 'जब तक धरेलू इस्तेमाल में आने वाले सामानों का इतना उत्पादन नहीं होने लगता कि उससे सारी जरूरतें पूरी हो जाएँ, तब तक देशी तथा आई० सी० आई० द्वारा आयातित रंग सामग्रियाँ को मयुक्त रूप से बाजार में बेचा जाएगा।' (ए०पी०आई० की खबर, 22 दिसंबर 1945)। और यह अवधि 15 से 20 वर्ष की बताई गई। भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों के बीच इसी तरह के और अनेक समझौते हो रहे हैं।

भारत के बड़े और मधोले व्यापारियों के साथ इन समझौतों के अलावा ब्रिटिश साम्राज्य-वादियों की योजना है कि वे भारत के तानाशाही राज्यों का विकास अपने भावी मुख्य विशेष रूप से आर्थिक आधार क्षेत्र के रूप में करेंगे। वे इन भारतीय राज्यों को अधिक से अधिक ब्रिटिश पूँजी भेजना चाहते हैं, चाहे इसमें उन रियासतों के प्रशासन हिस्सा ले या न लें। अप्रैल 1945 में अपनी औद्योगिक नीति के बारे में जारी किए गए वक्तव्य में भारत सरकार ने इन राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए एक विशेष व्यवस्था की घोषणा की थी

यह समान रूप से स्पष्ट है कि लाइसेंस प्रणाली का संचालन ऐसा होना चाहिए जिससे भारतीय राज्यों को इस बात का आश्वासन मिले कि औद्योगिक विकास की उनकी मायसंगत आकांक्षा की उपेक्षा नहीं की जाएगी। ('हिंदुस्तान टाइम्स,' 23 अप्रैल, 1945)

औद्योगिक विकास पर रोक लगाने के लिए तैयार की गई 'लाइसेंस' प्रणाली का उद्देश्य यह भी है कि इस विकास के माध्यमों पर नियंत्रण रखा जाए और संभवतः भारतीय राज्यों को लाइसेंसों और पूँजीगत सामानों के निर्धारण में अधिक से अधिक तरजीह दी जाए। इन राज्यों में ही राजाओं, महाराजाओं के प्रतिनिध्यावादी शासन के अधीन ब्रिटिश पूँजी को भरपूर सुरक्षा मिलनी थी।

भारत में ब्रिटिश तृतीय हितों के मुखपत्र 'कैपिटल' ने 24 जनवरी 1946 को ब्रिटिश उद्देश्यों को बड़े साफ शब्दों में अभिव्यक्ति दी

सभी (राज्य) अपनी सीमा के अंदर औद्योगिक उपक्रम शुरू करने के लिए बेचैन हैं और ब्रिटिश भारत में ये संभावनाएँ कभी कभी इतनी क्षीण लगती हैं कि ऐसे कई अवसर आते हैं जब नई औद्योगिक परियोजनाओं के प्रचलित राजनीतिक उथल-पुथल से दूर भाग निकलने के लिए जोरदार ढंग से प्रेरित होते हैं। इसके साथ ही पार्टी और सभ का दिन व दिन तेज होता जाता है। भारतीय राज्य संस्थापक शांत वातावरण की अपेक्षा रखता है। यहाँ सत्तारूढ़

वग से उसकी परंपरा और पृष्ठभूमि के कारण यह भाषा की जा सकती है कि वह उद्योगपतियों की इस इच्छा के प्रति हमदर्द होगा कि उसे बाहर के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपना कारोबार खुद चलाने दिया जाए।

और यह आश्वासन भारत की रियासतों ने पहले ही दे रखा है। पटियाला राज्य के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के लिए भारतीय राज्यों के औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल के नेतृ श्री एच०एस० मलिक ने साझेदारी के आधार पर विदेशों के विकसित उद्योगपतियों साथ उद्योग शुरू करने की खुलेआम हिमायत की थी। श्री मलिक ने कहा

हम यह महसूस करते हैं कि जब आप अमरीका या इंग्लैंड के किसी उद्योगपति को अपने यहां स्थान देते हैं और उद्योग में उसे पूजी लगाने देते हैं तो उसकी पूजी 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत जो भी हो, निश्चित रूप से उद्योग की सफलता में दिलचस्पी लेगा। मैं नहीं समझता कि आप जब तक उनपर पूरा पूरा विश्वास करने को तैयार नहीं होते, आप कुशल, अनुभवी और उन्नत उद्योगपतियों से भरपूर सहयोग की आशा किस तरह करते हैं। (टाइम्स आफ इंडिया, 17 जनवरी 1946)

इंडियन चेंबर आफ प्रिंसज के सेक्रेटरी श्री मकसूल अहमद ने भी 'एशियाटिक रिव्यू' में एक लेख में लिखा 'रियासतों के औद्योगिक विकास में भारत और ब्रिटेन की साझेदारी की भी काफी गुंजाइश है।'

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत की धरती में अधिक से अधिक गहराई तक पैठकर भारत में ब्रिटिश महाजनी पूजी के भविष्य को सुरक्षा दिलाने में ही लगा है। भारतीय उद्योगपतियों के साथ समझौते के जरिए इस बात की निगरानी रखी जाती है कि भारत में लगी ब्रिटिश पूजी सुरक्षित रहे। इसकी वांछित प्रतिक्रियाएँ भी स्पष्ट हैं। भारत में ब्रिटिश पूजी के बारे में बोलत हुए भारत के सर्वोच्च इजारेदार और नफील्ड समझौते के एक हिस्सेदार श्री जी०डी० बिडला ने कहा

मैं नहीं समझता कि इसका कभी स्वामित्वहरण होगा। ब्रिटिश फर्म अपना काम जारी रखेंगी। ('हिंदुस्तान टाइम्स', 11 अप्रैल 1946)

भारतीय रियासतों में राजाओं के निरंकुश शासन को बनाए रखकर वर्तमान पूजीनिवेश को सुरक्षित रखने की न केवल कोशिश की जा रही है बल्कि नए सिरे से ब्रिटिश पूजी की घुसपैठ की योजना बनाई जा रही है।

इन समझौतों से भारत का उद्योगीकरण किसी भी रूप में संभव नहीं है। जमा बिडला

नफील्ड आर टाटा—आई०सी०आई० जैसे दो महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की शर्तों से स्पष्ट है, इन साझेदारियों के फलस्वरूप भारत में बुनियादी भारी उद्योगों की स्थापना कभी नहीं होगी। एक अनिश्चित अवधि तक रसायनों का उत्पादन इंग्लैंड में होगा और भारतीय ट्रेडमाक के तहत भारतीयों को बेचे जाएंगे। इसी प्रकार ब्रिटेन में बने उपकरणों और पुर्जों को जोड़ने के लिए एक वकशाप से अधिक भारत की हैसियत नहीं होगी। ब्रिडला-नफील्ड समझौते के अंतर्गत प्रस्तावित कारों के 'भारतीय उत्पादन' का स्वरूप हम 'हिंदुस्तान-टैन' के उत्पादन में देख ही चुके हैं। इसके बारे में खूब प्रचार किया गया कि यह 'भारत में बनी' कार है लेकिन सचार्ई यह है कि इसके सारे हिस्से मोरिस के हैं और उन्हें भारत में केवल जोड़ दिया गया है।

इस प्रकार ये समझौते भारी उद्योग, भारी इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग की स्थापना को यथामभव रोकने और सीमित करने तथा ब्रिटेन में बने सामान के लिए भारत को एक निर्यात बाजार बनाने के लिए महज एक आवरण का काम करते हैं। जैसा 'बावे फ्रान्क्ल' ने 27 दिसंबर 1945 के अपने संपादकीय में कहा था, इन समझौतों के फल-स्वरूप नए तरह के निहित स्वार्थों का उदय होगा जो इस देश के तीव्र उद्योगीकरण के माग में जबरदस्त अवरोध बनेंगे—और अंततोगत्वा जब राष्ट्रीय सरकार बनेगी तो उसे इन स्वार्थों से निवटने में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

भारत और ब्रिटेन के इजारेदारों के बीच इस तरह का आर्थिक समझौता, जो 1945 में बड़े पमाने पर सपन होन लगे थे, उस साविधानिक बातचीत की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिसके फलस्वरूप 1946 का राजनीतिक समझौता सपन हुआ।

## 9 भारत में साम्राज्यवाद का परिणाम

माकम ने जब ब्रिटिश शासन के बारे में कहा था कि यह भारत में 'एक सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा' और इंग्लैंड को 'क्रांति सपन कराने में इतिहास के हाथों अनजाने आ गया ओजार' कहा था तब उनका आशय एक दोहरी प्रक्रिया से था जैसा कि उनकी व्याख्या से स्पष्ट होता है। एक तो पुरानी समाज व्यवस्था के विनाश की प्रक्रिया। दूसरी, नई समाज व्यवस्था के लिए भौतिक आधार तैयार करने की प्रक्रिया। यह दोनों प्रक्रियाएँ आज भी जारी हैं, हालांकि बाद की प्रक्रिया से विवसित आधुनिक साम्राज्यवाद की नई मजिलों की विशेषताओं ने उनके महत्व को घुघला कर दिया है।

पुराने हस्त उद्योग के नष्ट हो जाने के परिणामों की एक श्रृंखला इस तथ्य से मिल जाती है कि औद्योगिक मजदूरों की संख्या बराबर कम होती जा रही है (युद्ध के कारण इसमें अस्थाई तौर पर व्यवधान पड़ा था), और आधुनिक उद्योग के धीमे विकास के कारण इस संख्या में आज तक वृद्धि नहीं हुई। पुरानी ग्रामीण अव्यवस्था का विनाश आज

अतर्विरोधों के ऐसे दौर में पहुँच चुका है जो कृषि के क्षेत्र में सामान्य मकड़ पैदा कर रहा है।

इसके साथ ही जैसी माकम ने भविष्यवाणी की थी, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भौतिक आधार पर आधुनिक उद्योग की प्रारम्भिक शुरुआत हो चुकी है, यद्यपि इसकी स्तर अत्यंत धीमी है मगर यह शुरुआत हो चुकी है। और इसके फलस्वरूप भारतीय समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ है। यह नया वर्ग आधुनिक मशीन उद्योग में वेतनभागी औद्योगिक मजदूरों का वर्ग है जो भावी भारत में नई समाज व्यवस्था स्थापित करने वाली स्वतन्त्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

लेकिन इस प्रक्रिया के आगे जारी रहने के फलस्वरूप आज एक नई परिस्थिति पैदा हुई है जिसने उन शक्तियों को जन्म दिया है जो उस समय मौजूद नहीं थी जब माकम ने यह लिखा था। आज भारत में उत्पादक शक्तियों के बड़े पैमाने पर विकसित होने और आधुनिक स्तर तक पहुँचने के लिए स्थितियाँ परिपक्व हो गई हैं और प्रति उप इसकी आवश्यकता तेज और अनिवार्य होती जा रही है। दूसरी तरफ, आधुनिक साम्राज्यवाद अब भारत के प्रारम्भिक पूँजीवादी प्रभुत्व के उन दिनों की तरह वस्तुगत दृष्टि से शक्ति उत्पन्न करने वाली भूमिका नहीं अदा कर पा रहा है जब वह अपने विनाशकारी प्रभावों से नई प्रगति का भाग प्रशस्त कर रहा था और इसकी प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक भौतिक स्थिति में पैदा कर रहा था। इसके विपरीत भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद उत्पादन शक्तियों के विकास में प्रमुख रुकावट बनकर उठा हुआ है और अपने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व के सभी हथियारों से उत्पादक शक्तियों के विकास को निष्फल और धीमा कर रहा है। भारत में पूँजीवादी शासन की श्रांतिकारी भूमिका की बात करना अब सम्भव नहीं है। भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद की भूमिका पूरी तरह से प्रतिक्रियावाणी भूमिका है।

पुराने प्रगामी पूँजीवाद ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्राचीन भारतीय समाज के तान काट को छिन भिन कर दिया। यहाँ तक कि उसने कुछ प्रतिक्रियावाणी धार्मिक आर सामाजिक अवशेषों पर प्रहार का सजग नेतृत्व किया, एवं वे बाएँ एवं राजाओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने टोमीनियनों को उनके समान प्रभुत्व में मिला लें, पवित्र मूरापीय शिक्षा और अवधारणाओं के प्रचार की पहली बार शुरुआत की और कुछ समय के लिए समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। इस अवधि के दौरान भारतीय समाज के प्रगामी तत्वों ने अवगत उभरते हुए मध्यवर्गों, जिन्होंने निधि राममाहन राय के ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और उनके प्रयोगों का सहयोग प्रदान किया, पतनशील प्रतिक्रियावाणी तत्वों, क्षमगुण राजाओं महाराजाओं और मामलों के विरोध का नतूतन दिया जा 1857 के विद्रोह में अपनी पराजय पर गुरु और फिर दूब गया। उस समय कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो शासन और सदन के

शिवार किसान बग या नेतृत्व दे और उनकी आवाज को मुखरित कर। 1857 के विद्रोह को असफलता ही हाथ लगी।

1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन ने अपनी नीति में परिवर्तन शुरू किया। भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद अपनी षटपुतली के रूप में राजाओं महाराजाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है और पूरी ताकत के साथ उनकी राजनीतिक भूमिका का बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करता है जिसकी सबसे ताजा अभिव्यक्ति कैम्बेनेट मिशन के फैसले में होती है। वह प्रतिभियावादी सामाजिक और धार्मिक अवशेषों को दबाए रखना चाहता है और उनमें सुधार के लिए प्रगतिशील भारतीय जनमत द्वारा की जाने वाली भागों के विरुद्ध वह उनकी उत्साहपूर्वक रक्षा करता है (जैसा विवाह की उम्र निर्धारित करने तथा अछूतों पर लगे प्रतिबंध हटाने के प्रश्न पर हुआ)। वह दमन का व्यापक ढांचा तैयार करके धोलने और विचार व्यक्त करने पर रोक लगाता है और भारतीय जनता की सामाजिक शैक्षणिक तथा औद्योगिक प्रगति की मांग में राड़े अटवाता है। अपने इन्हीं लक्षणा में आज भारत में साम्राज्यवाद सामाजिक तथा राजनीतिक और उसी सीमा तक आर्थिक क्षेत्र में प्रतिभियावाद का मुख्य गढ़ बन गया है।

इसलिए आधुनिक युग में भारतीय समाज की सभी प्रगतिशील शक्तियाँ साम्राज्यवाद को मुख्य दुश्मन और प्रतिभियावाद का पोषक मानकर उसके विरुद्ध अभूतपूर्व शक्ति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एकजुट हो गई हैं और दूसरी तरफ पतनशील प्रतिभियावादी शक्तियाँ ही आज साम्राज्यवादी शासन की सबसे बफादार समर्थक बन गई हैं।

भारत की उभरती उत्पादक शक्तियाँ आज साम्राज्यवाद की वेड्डियों और उस अविकसित आर्थिक ढांचे के विरुद्ध जी जान से लगी हैं जिसका पोषण साम्राज्यवाद करता है और जिसे वह बनाए रखे है। इस मध्य की अभिव्यक्ति कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न सबट में होती है। यह सबट ही साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के दिवालियेपन का सूचक है और निर्णायक परिवर्तनों की मुख्य प्रेरक शक्ति है। भारत में तभी से आगे बढ़ती कृषि क्रांति के संकेतों को पहचानना बस ही संभव है जैसे जारशाही रूस में या 18वीं सदी के फ्रांस में संभव था। भारत में विकसित हो रही कृषि क्रांति, साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध विकसित हो रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक मुक्ति आंदोलन के साथ मिला हुआ है, और इन दोनों की एकता ही भारतीय इतिहास के नए अध्याय की कुंजी है।

इसलिए, भारत की आधुनिक राजनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय संघर्ष की समस्याओं के अध्ययन की शुरुआत कृषि समस्या के अध्ययन के साथ ही की जा सकती है।



## टिप्पणियाँ

- 1 भारत में सगी विदेशी पूँजी का कोई सही आँकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। 'स्टैटिस्टिकल अम्ब्रुइट फार ब्रिटिश इंडिया' ने उन आइटम स्टॉक कंपनियों का प्रगत पूँजी 1938-39 में 74 करोड़ 11 लाख पौंड बताया है जो भारत में बाहर पंजीकृत हैं लेकिन ब्रिटिश भारत में अपना काम कर रही हैं। इस राशि में भारत सरकार का स्टॉकिंग ऋण और भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों की स्वयं पूँजी को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी 1912 के वर्ष से तुलना करने पर पता चलता है कि 26 वर्षों की अवधि के दौरान भारत में स्टॉकिंग पूँजी निवेश में 66 करोड़ 76 लाख पौंड का वृद्धि हुई है। 1918-19 के वर्ष से 26 करोड़ 80 लाख पौंड की वृद्धि हुई है। 1918-19 से स्टॉकिंग और ऋण कंपनियों की राशि 2 करोड़ 85 लाख पौंड थी जो 1938-39 में बढ़कर 9 करोड़ 62 लाख पौंड हो गई और व्यापारिक एवं उत्पादन कंपनियों की राशि वही अवधि में 20 करोड़ 54 लाख पौंड से बढ़कर 34 करोड़ 49 लाख पौंड हो गई।
- 2 अक्टूबर 1922 में लीग आफ नेशंस की कौंसिल के अधिवेशन में भारत सरकार की ओर से लार्ड चेम्सफोर्ड ने कहा 'भारत के इस दावे का औचित्य अभी निर्धारित करना है कि उसे प्रमुख औद्योगिक महत्व के आठ राज्यों में शामिल कर लिया जाए। उसके दावे के आधार व्यापक और सामान्य हैं और अपना औचित्य ठहराने के लिए उन्हें आँकड़ों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। भारत के पास औद्योगिक बेतनभोगी लोगों की सख्या लगभग 2 करोड़ है। उन्होंने इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी कि 'औद्योगिक बेतनभोगी मजदूरों की 2 करोड़ की सख्या से मुख्यतया हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग में लगे मजदूर हैं कि इस व्यक्तियों का इससे अधिक लोगों को अपने महा नौजरी देने वाली समस्याओं में काम करने वाले लोगों की सख्या, 1921 की औद्योगिक जनगणना के अनुसार 26 लाख थी। इनमें से लगभग 10 लाख मजदूर बागानों में काम करने वाले थे कि औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूर। उन्होंने यह भी बताने की जरूरत नहीं समझी कि फक्करीज ऐक्ट के अंतर्गत जो मजदूर आते हैं उनका कुल सख्या महज 13 लाख थी।
- 3 इस संधि का और भी ज्यादा पता उन नए व्यापार समझौतों से चलता है जो भारत और ब्रिटन के बीच मार्च 1939 में हुए थे। इस समझौते को भारतीय विधानसभा ने मार्च 1939 में 47 के मुकाबले 59 वोटों से नामजूर कर दिया था और इंडियन चैंस आफ कामर्स के महासचिव की समिति ने भी इस समझौते के विरोध की घोषणा की थी। एक बार फिर विधानसभा ने मत की बब हलना का गई और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद यह व्यापार समझौता थाप दिया।
- 4 इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमिटी को 1930 में जो सूचना प्रेषित की थी उसके अनुसार इंपीरियल बैंक की कुल 5 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये की प्रगत पूँजी में से 2 करोड़ 84 लाख रुपये अमरातीया के और 2 करोड़ 78 लाख रुपये भारतीयों के थे (रिपोर्ट, खंड 11 पृष्ठ 264)। इससे 'अमरातीया' की पूँजी बहुत कम मिल जाता है। दरअसल प्रभावशाली पदों पर स्थित कुछ अंगरेज शेयरहोल्डरों की पूँजी की अपेक्षा में कम भाग होने के बावजूद अंगरेजों का पूरा पूरा नियंत्रण था।
- 5 1936 में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सेंट्रल एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया की स्थापना की। भारतीय बैंक व्यवस्था द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश करने का यह पहला प्रयास था।
- 6 इस सलाहका में प्रस्तुत आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्टैटिस्टिकल ट्रेन्ड्स रिजर्विंग टु बस इन इंडिया एंड बर्मा फार दि इयर्स 1942-43 से लिए गए हैं।

- 7 इस सिलसिले में अमरीकी तकनीकी मिशन की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। मिशन ने अपनी रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में 'विशाल प्राकृतिक और मानव साधनों के कारण औद्योगिक उत्पादन के लिए भारत की महान क्षमताओं की तरफ ध्यान दिलाया है। मिशन यह महसूस करता है कि प्राकृतिक साधनों के दस्तकाल को काफी विकसित किया जा सकता है और इसका विस्तार किया जा सकता है यहाँ तक कि काम के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। मिशन ने भारतीय कामगारों की यांत्रिक अभिरुचि को प्रमाण सहित देखा है। इसे यदि उचित प्रोत्साहन दिया जाए और इनके काम की स्थितियाँ यदि बेहतर बना दी जाएँ तो कुछ ही समय के प्रशिक्षण के बाद ये कुशल कारीगर हो सकते हैं।
- 8 मुद्र पत्र में ब्रिटिश साम्राज्य नीति की विफलता के कारण युद्ध सबधी व्यय का बिल बहुत ज्यादा आया। यह नीति थी उपनिवेशों की जनता को राजनीतिक सत्ता देने से इकार करने वहाँ की जनता का सक्रिय समर्थन और विश्वास प्राप्त करके उन देशों के समूचे साधनों को अपने अनुकूल बनाने से इकार की करने नीति।
- 9 यह कुल मुनाफा एजेंटों के फीशन, वायकारी घघ और कमचारियों के वेतन की राशि को अलग करने और अवमूल्यन की गुजाइश छोड़कर निर्धारित किया गया है।
- 10 पी०एस० लोवनाथन 'इंडियाज पोस्टवार रिकान्स्ट्रक्शन ऐंड इट्स इटरनेशनल आस्पेक्ट्स', 1946 पृष्ठ 31
- 11 युद्ध जिस समय समाप्त होने जा रहा था उसके आसपास सरकार ने जो सबसे पहले कदम उठाए उनमें एक यह था कि भारतीय फौजों के साथ युद्ध सबधी अनुबंधों को तेजी से समाप्त कर दिया जाए और युद्ध के सामानों की सप्लाई के लिए ब्रिटेन में आडर दिए जाए। मार्च 1945 में इंग्लैंड की यात्रा पर गए हैदरी मिशन ने 1945 में 20 करोड़ 60 लाख रुपये और 1946 में 48 करोड़ रुपये मूल्य के ब्रिटिश सामानों के आयात की व्यवस्था की और मुख्यतया उपभोक्ता सामग्रियों के लिए आर्डर दिए गए।



खण्ड तीन

भारत की मूल समस्या    कृषि समस्या

## कृषि के क्षेत्र में सकट

किसानों की स्थिति की वर्तमान अधोगति से कृषि क्रांति की पूर्वसूचना मिलती है।—प्रोफेसर आर० मुकर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया', 1933

भारतीय किसानों की गरीबी और दुदशा विश्व की भयानकतम सच्चाइयों में से एक है। भारत की कृषि सबंधी समस्या पर हाल की सुविख्यात पुस्तक 'लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया', में प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी ने इस स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में किया है

कृषि पर निर्भर भारतीय जनता आज बेहद अपर्याप्त साधनों से काम चलाती है। यदि हम किसानों की ही खुशहाली की दृष्टि से देखें तो इन साधनों का वितरण बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से हुआ है। पिछले 50 वर्षों में भूमि के स्वामित्व और काश्तकारी में हुए परिवर्तनों की यदि हम छानबीन करें तो पता चलेगा कि यह अव्यवस्थित वितरण दिनोदिन और भी बुरा होता जा रहा है। छोटी जोतवालों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है जबकि जमींदारों और जमीन से वंचित किए गए किसानों लगान बसूली करने वाले वग और खूब पसीना एक करने वाले कृषि दासों के बीच जो विषमता व्याप्त है वह कृषि सबंधी हमारे इतिहास के एक नाजुक दौर की सूचना देता है। किसानों में वगचेतना एक अस्पष्ट आवाज उठने लगी है जो भारत के कुछ हिस्सों में जहाँ तक सबंधी है यह कृषि के क्षेत्र में व्याप्त दुःखों को चुनौती देती है। (पृष्ठ 4)

वह इस निसर्क पर

विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक अभिरूचियों के लोग अब तभी में यह मान लगे हैं कि भारत की भूमि प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है। यह विचार अब समाज के सभी वर्गों में फैल चुका है। भारी जनगणना के दबाव के कारण इन जोता की सध्या इतनी कम हो गई है और इनमें इतना विघटन आ गया है कि अब कोई न तो अपने परिवार के सभी सदस्यों के भ्रम से लाभ उठा सकता है और न ही जीवन निर्वाह स्तर कम होने के कारण अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। साथ ही जमींदार की भूमिका अब लगान प्राप्त करने वाले की हो गई है जबकि पहले उसकी भूमिका संपत्ति पैदा करने वाले की थी। कृषि के बाय में उसने अब अपनी पुरानी और सम्माननीय भूमिका निभाना छोड़ दिया है। आज वह न तो कृषीय पूँजी की सप्लाई करता है और न ही खेती के कार्यों का ही संचालन करता है। जमींदार से नीचे विचौलिया का एक वर्ग तैयार हो गया है। इन विचौलियों ने मौजूदा भूमि प्रणाली की जटिलताओं से भरपूर लाभ उठाया है और इन्होंने वास्तविक खेतिहरों की कष्टकर स्थिति को और भी गंभीर बनाया है। यह आलोचना नहीं बल्कि तथ्यों का सारांश है। पुरानी व्यवस्था टूट चुकी है और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था का जन्म अनिवार्य है जो कृषि संबंधी जीवन और सामाजिक जीवन की वर्तमान स्थितियों के अनुकूल हो। (पृष्ठ 361-62)

भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति के सभी प्रेक्षक इस सामान्य निष्कर्ष को मानते हैं। लेकिन यह प्रश्न कि कौन से परिवर्तन किए जाएं और किस प्रकार किए जाएं, एक साथ ही उन तमाम प्रश्नों को उभार देते हैं जो साम्राज्यवादियों द्वारा शासित भारत की वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कृषीय संबंधों के क्षेत्र में ही उस मौजूदा समाज व्यवस्था की नींव का पता लगाया जा सकता है जो साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत बनी हुई है और जनजीवन का गला घाट रही है। यही परिवर्तन की अत्यंत शक्तिशाली प्रेरक शक्तियां भी जन्म ले रही हैं और अपने को मजबूत बना रही हैं ताकि वे वर्तमान समाज व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था का मांग प्रशस्त कर सकें।

भारत की कृषि समस्या को साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत देश की सामान्य अर्थव्यवस्था तथा साम्राज्यवादी शासन द्वारा सपोषित मौजूदा सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

1926 में कृषि संबंधी शाही आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने 1928 में 800 पृष्ठों की अपनी भारी भरकम रिपोर्ट पेश की। इसमें 800 पृष्ठों के अतिरिक्त साक्ष्यों के 16 खंड भी शामिल थे। इसके विचाराधीन विषयों में 'कृषि को विकसित करने तथा ग्रामीण जनता की खुशहाली और संपन्नता में वृद्धि के लिए सुझाव प्रस्तुत करने थे'। लेकिन साथ ही



और इस कारण यह जरूरी हो जाता है कि इस स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन प्रस्तावित करते समय बहुत सतर्कता बरती जाए। इसका अद्भुत उदाहरण 1918 की माटेग्यू चेम्तफोड रिपोर्ट है जिसके 'कडीवास इन इंडिया' नामक पहले भाग में कहा गया है

जनता का एक प्रमुख व्यवसाय खेती है। सामान्य स्थितियों में इंग्लैंड जैसे अत्यधिक उद्योगीकृत देश में 100 में से 58 व्यक्ति उद्योग में और महज 8 कृषि में लगे थे। लेकिन भारत में प्रत्येक सौ व्यक्तियों में से 71 व्यक्ति कृषि या चरागाह में लगे हैं—समूचे भारत में 31 करोड़ 50 लाख लोगों में से 22 करोड़ 60 लाख आदमी धरती के सहारे जीते हैं और 20 करोड़ 80 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी या दूसरों की जमीन जोतकर या प्रत्यक्ष रूप से इनपर निर्भर रहकर अपना गुजर बसर करते हैं।

इसी प्रकार इंग्लैंड में सावजनिक तौर पर वितरित करने के लिए तैयार की गई 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट ने, 'दि प्रीडामिनेन्स आफ ऐग्रिकल्चर' नामक अपने पहले भाग में उपयुक्त अंश को उद्धृत किया और इस आशाजनक निष्कर्ष से अपने को खुश कर लिया कि इन कारणों से यहाँ परिवर्तन निश्चय ही बहुत धीमी गति से होना चाहिए

भारत के गांवों में रहने वाले एक औसत व्यक्ति अतिप्राचीन काल से तीज त्योहारों, मेलों और घरेलू समारोहों तथा अकाल और बाढ़ को भयावहता के सिलसिले से ग्रस्त है और इन परिस्थितियों में सामान्य राजनीतिक मूल्यांकन में किसी भी तरह की जल्दबाजी का काम या मौसम, पानी, फसलों और मवेशियों के परंपरागत और मनोरंजक अंश से परे हटकर ग्रामीण क्षितिज के विस्तार का काम निश्चय ही बड़ी धीमी रफ्तार से होगा।

कृषि पर भारतीय जनता की जबरदस्त निर्भरता और औद्योगिक देशों में मौजूद द्रास्यी विपरीत स्थिति का यहाँ जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है वह एकदम सही है। लेकिन इस तथ्य का प्रस्तुत करते समय उन शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो साम्राज्यवाद को उपनिवेशवादी व्यवस्था को मंचालित करती हैं और जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसी कारण जो तत्वीर सामने आती है वह गलत और गुमराह बन वाली तत्वीर होती है। इससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे भी गलत ही होते हैं क्योंकि भारत में तेजी से परिवर्तन लाने वाली शक्तियों का विकास ही तब होगा जब कृषि के क्षेत्र में सफ़ट तेज होगा।

साम्राज्यवादियों द्वारा पक्ष की गई इस भौंडी तत्वीर में हमेशा उस तथ्य को गजरअदाज किया गया है जो बताता है कि आबादी के तीन चौथाई भाग का, एकमात्र व्यवसाय के रूप में कृषि पर अत्यधिक, असंतुलित और पर्विला दबाव आधुनिक युग में सारा से रहे



उही विचाराय विषयो के अतगत उसे चेतावनी भी दी गई थी

भूमि के स्वामित्व तथा वास्तविकारी की वर्तमान व्यवस्था के संघर्ष में अथवा मालगुजारी और सिंचाई शुल्क के निर्धारण के विषय में कोई सिफारिश करना आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर होगा।

यह बात तो बिलकुल सही ही है जैसे हैम्लेट नाटक में से-डैनमार्क के राजकुमार को निकाल दिया जाए। भारत में भूमि प्रणाली की समस्या पर विचार किए बिना कृषि की समस्या पर विचार करना असंभव है। कृषि संबंधी वर्तमान संकट के पीछे प्रारम्भिक बुनियादी मामले इस प्रकार हैं

- 1 अल्प आर्थिक साधनों को बढ़ाकर कृषि पर आबादी का जरूरत से ज्यादा दबाव,
- 2 भूमि के एकाधिकार और किसानों के ऊपर पड़ने वाले बोख का प्रभाव,
- 3 खेती की तकनीक का निम्न स्तर और तकनीक के विकास में उत्पन्न बाधाएँ,
- 4 ब्रिटिश शासनकाल के अधीन खेती में ठहराव आ जाना और उसका नष्ट होना,
- 5 किसानों की तेजी से बढ़ती हुई निधनता, जोतों का टुकड़ा में बंटते जाना और उनमें बिसराव आना तथा बड़ी संख्या में किसानों का अपने खेतों से वंचित होना,
- 6 इनके फलस्वरूप किसानों में वर्गभेदों का बढ़ना और इसके कारण किसानों की एक बड़ी संख्या का भूमिहीन सवहारा की स्थिति में पहुँच जाना। यह संख्या एक तिहाई से आधी तक है।

इन सारे कारणों का सर्वेक्षण करके ही समस्या के समाधान पर विचार किया जा सकता है।

### 1 खेती पर जरूरत से ज्यादा दबाव

जैसाकि हमें बार बार याद दिलाया जाता है, भारत एक 'ग्रामीण महादेश' है। इस तथ्य की ओर खासतौर से उन लोगों ने ध्यान दिलाया है जो सम्भवतः इस वास्तविकता को भारत के तेज जनतांत्रिक या सामाजिक विकास के माग में तथाकथित अवरोध मानकर खुश होते हैं।

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी की कृषि पर निर्भरता तथा पश्चिमी यूरोप के अल्पसंख्यक उद्योगीकृत समुदायों के बीच की विषमता को सामान्य तौर पर एक सहज घटना के रूप में चित्रित किया जाता है। इससे भारतीय समाज के पिछड़े स्वरूप का पता चलता है

और इससे कारण यह जरूरी हो जाता है कि इस स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन प्रस्तावित करते समय बहुत सतर्कता बरती जाए। इसका अद्भुत उदाहरण 1918 की माटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है जिसके 'फंडीशन इन इंडिया' नामक पहले भाग में कहा गया है

जनता का एक प्रमुख व्यवसाय खेती है। सामान्य स्थितियों में इंग्लैंड जैसे अत्यधिक उद्योगीकृत देश में 100 में से 58 व्यक्ति उद्योग में और महज 8 कृषि में लगे थे। लेकिन भारत में प्रत्येक सौ व्यक्तियों में से 71 व्यक्ति कृषि या चरागाह में लगे हैं—मसूचे भारत में 31 करोड़ 50 लाख लोगों में से 22 करोड़ 60 लाख आदमी घरों के सहारे जीते हैं और 20 करोड़ 80 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी या दूसरों की जमीन जोतकर या प्रत्यक्ष रूप से इनपर निर्भर रहकर अपना गुजर बसर करते हैं।

इसी प्रकार इंग्लैंड में सांख्यिकीय तौर पर वितरित करने के लिए तैयार की गई 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट ने, 'दि प्रोडामिनेन्स आफ ऐग्रिकल्चर' नामक अपने पहले भाग में उपर्युक्त अंश को उद्धृत किया और इस आशाजनक निष्कर्ष से अपने को खुश कर लिया कि इन कारणों से यहां परिवर्तन 'निश्चय ही बहुत धीमी गति से' होना चाहिए

भारत के गांवों में रहने वाले एक औसत व्यक्ति अतिप्राचीन काल से तीज त्यौहारों, मेलों और घरेलू समारोहों तथा अकाल और बाढ़ की भयावहता के सिलसिले से ग्रस्त है और इन परिस्थितियों में सामान्य राजनीतिक मूल्यांकन में किसी भी तरह की जल्दबाजी का काम या मौसम, पानी, फसलों और मवेशियों के परंपरागत और मनोरंजक अंश से परे हटकर ग्रामीण क्षितिज के विस्तार का काम निश्चय ही बड़ी धीमी रफ्तार से होगा।

कृषि पर भारतीय जनता की जबरदस्त निर्भरता और औद्योगिक देशों में मौजूद इसकी विपरीत स्थिति का यहां जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है वह एकदम सही है। लेकिन इन तथ्यों को प्रस्तुत करते समय उन शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो साम्राज्यवाद की उपनिवेशवादी व्यवस्था को संचालित करती हैं और जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इसी कारण जो तस्वीर सामने आती है वह गलत और गुमराह करने वाली तस्वीर होती है। इससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे भी गलत ही होते हैं क्योंकि भारत में तेजी से परिवर्तन लाने वाली शक्तियों का विकास ही तब होगा जब कृषि के क्षेत्र में संकट तेज होगा।

साम्राज्यवादियों द्वारा पक्ष की गई इस भ्रष्ट तस्वीर में हमेशा उस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है जो बताता है कि आबादी के तीन चौथाई भाग का, एकमात्र व्यवसाय के रूप में कृषि पर अत्यधिक, असंतुलित और खर्चीला दबाव आधुनिक युग में सास ले रहा

प्राचीन आदिम भारतीय समाज की कोई वंशगत विशेषता नहीं है बल्कि वह जिस पैमाने पर आज सामने है वह सीधे सीधे साम्राज्यवादी शासन का ही दुष्परिणाम है और आधुनिक युग की वास्तविकता है। कृषि पर इस अमंगल निम्बरता में ब्रिटिश शासनकाल में 'तेजी से वृद्धि' हुई है। यह उद्योग और कृषि के बीच चले आ रहे मतुलन के नष्ट होने का सूचक है और इससे यह पता चलता है कि भारत, साम्राज्यवाद का खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया है।

पिछले 50 वर्षों की जनगणना की यदि सरकारी रिपोर्ट देखें तो असली तस्वीर का पता चल जाता है। यह तस्वीर और भी ज्यादा साफ दिखाई दे सकती है वंशतः इससे पहले के वर्षों के जनगणना सबंधी आकड़े मिल जाए। 19वीं सदी के शुरू के 75 वर्षों में ही भारत के उद्योग धंधों की मुख्य रूप से वरवादी हुई, पुराने आबाद औद्योगिक केंद्र उजड़ गए इन केंद्रों के लोगों को गांवों में खदेड़ दिया गया और इनकी वरवादी के साथ साथ गांवों में रहने वाले ताखो दस्तकारों की जीविका भी छिन गई। इस अवधि का कोई आकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल के कुछ दशकों के जनगणना आकड़ों को देखने से पता चलता है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हमारे युग में यह और भी तेज हुई है।

पहली जनगणना 1881 में हुई थी। लेकिन यह बेहद अधूरी थी और इससे किसी तरह की तुलना नहीं की जा सकती। व्यवसायरत लोगों की सूची में दज 11 करोड़ 50 लाख पुरुष कामगरी में से 5 करोड़ 10 लाख व्यक्ति खेतिहर मजदूर थे। आधे से भी कम का यह अनुपात निश्चित रूप से काफी कम है। 1891 से 1921 तक के जो आकड़ उपलब्ध हैं उनसे काफी हद तक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इनसे निम्न तस्वीर उभरती है

#### कृषि पर निम्न व्यक्तियों का प्रतिशत

|      |      |
|------|------|
| 1891 | 61.1 |
| 1901 | 66.5 |
| 1911 | 72.2 |
| 1921 | 73.0 |

1931 में वर्गीकरण के आधार में कुछ इस तरह की तबदीली कर दी गई थी जिससे ऐसा लगता था कि कृषि पर निम्न लोगों की संख्या कम होकर 65.6 प्रतिशत हो गई है। लेकिन यह परिवर्तन वागज पर ही था। '1921 से 1931 के बीच खेती और चरागाह पर निम्न लोगों की संख्या में ऊपरी तौर पर जो गिरावट आई है वह एक भ्रम है जो वर्गीकरण में, न कि पन्ने में परिवर्तन के कारण है। 1921 से 1931 के बीच खेतीबारा में लग लोगों की संख्या में मुश्किल से ही कमी आई है।' (एस्टे 'इरानामिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पृष्ठ 61)। यह ध्यान देने की बात है कि इंडियन मॉडल बैंकिंग इक्वापरी कमिटी ने 1931 में अपनी रिपोर्ट में कहा (पृष्ठ 39)

भारत में खेती पर गुजर बसर करने वालों का अनुपात काफी अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1891 में यह अनुपात 61 प्रतिशत था। 1901 में बढ़कर यह 66 प्रतिशत और 1921 में 73 प्रतिशत हो गया। 1931 में हुई जनगणना के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 1931 में इस मध्या में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

प्रोफेसर वाडिया और मर्चेंट ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि यदि पुरानी जनगणना के दौरान अपनाई गई वर्गीकरण पद्धति का पालन किया गया होता तो, जहां तक कृषि का संबंध है, 1931 में खेती में लग लोग ही नहीं बल्कि इसपर निर्भर लोगों की संख्या सहित यह अनुपात कुल आबादी का 75 प्रतिशत तो निश्चित रूप से होता।' (अर्थ इकानोमिक प्रॉब्लम', पृष्ठ 86)। वर्गीकरण के संशोधित आधार पर गणना करने पर भी 1931 में यह अनुपात 66.6 प्रतिशत है जो 1891 के अंक 61 प्रतिशत से अधिक है।

ब्रिटिश पूंजीवादी नीति की कायप्रणालियों के जर्गिए कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता के कारणों पर पाँचवें अध्याय के उपशीर्षक-3 के अंतर्गत पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। 1911 के लिए निष्पन्न जनगणना कमिशनर ने, इन कारणों को स्पष्टतः उस समय मायता दे दी, जब उन्होंने लिखा

सस्त यूरोपीय सामानों और वस्तुओं के आयात ने तथा स्वयं भारत में पश्चिमी ढंग की अनेक फैक्ट्रियाँ की स्थापना ने समावेश अनेक ग्रामीण उद्योग धंधों को विनष्ट किया है। खेती से हुई पैदावार की ऊँची कीमतों को देखकर गाँवों के कई दस्तकारों ने भी अपनी खानदानी कारीगरी छोड़कर खेती का काम शुरू किया है—पुरानी ग्रामीण संरचना का जिस मात्रा में विघटन हो रहा है, वह अलग अलग हिस्सों में उल्लेखनीय रूप से कम या अधिक है। अपेक्षाकृत विकसित सूतों में यह परिवर्तन सर्वाधिक उल्लेखनीय है। (मेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 1911, खंड 1, पृष्ठ 408)

1911 के बाद से उद्योग धंधों के क्षेत्र में आई यह गिरावट और इसके कारण कृषि पर आज भी एकतरफा निर्भरता चरम सीमा पर पहुँच गई है। 1911 से 1931 के बीच उद्योग धंधों में लगे लोगों की संख्या में 20 लाख से भी ज्यादा की कमी आई जबकि आबादी में 3 करोड़ 80 लाख की वृद्धि हुई।

उद्योग धंधों पर निर्भर आबादी का प्रतिशत

|      |    |
|------|----|
| 1911 | 55 |
| 1921 | 49 |
| 1931 | 43 |

इन बीस वर्षों में जहाँ आवादी में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं उद्योग धंधों में तगें लागों की संख्या में 12 प्रतिशत की कमी भी आई। इसके साथ ही कुल आवादी के अनुपात में औद्योगिक मजदूरों के प्रतिशत में पाचवें हिस्से में भी ज्यादा की कमी आई और 1941 में इसमें 4.2 प्रतिशत की और गिरावट आई। इससे पता चलता है कि 'अनुद्योगीकरण' की विनाशकारी प्रक्रिया लगातार जारी थी अर्थात् पुराने हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो रहा था और उसके स्थान पर आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था जिसके फल स्वरूप खेती पर आवादी का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था।

इसके साथ ही भोजन के काम आने वाली फसलों की तुलना में उन खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि हुई। 1892-93 से 1919-20 के बीच खाद्य पदार्थवाली फसलों के क्षेत्रफल में 18 करोड़ 70 लाख से लेकर 21 करोड़ एकड़ की अर्थात् कुल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उन खाद्य फसलों का क्षेत्रफल 3 करोड़ एकड़ से बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख एकड़ हो गया अर्थात् कुल 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (वाडिया और जोशी, 'वैल्यू ऑफ इंडिया') हात के वर्षों में यह प्रक्रिया और भी तेजी से जारी रही। 1910-11 से 1914-15 और 1934-35 के पांच वर्षों का औसत यदि लें तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थवाली फसलों के क्षेत्रफल में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उन खाद्य फसलों में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई (आर० मुखर्जी की पुस्तक 'फूड प्लानिंग फार फोर हंड्रेड मिलियंस' पृष्ठ 16 पर बनी तालिका देखें)। 1934-35 से 1939-40 के दौरान उन खाद्य फसलों के क्षेत्रफल में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ की वृद्धि की तुलना में खाद्य फसलों के क्षेत्रफल में वस्तुतः गिरावट आई और यह 15 लाख एकड़ दर्ज की गई। कपास का निर्यात 1900-1 में 178,000 टन किया गया जो 1936-37 में बढ़कर 762,133 टन हो गया। इससे पता चलता है कि 328 प्रतिशत की वृद्धि हुई (1939-40 में यह राशि 526,411 टन थी), 1900-1 में कुल 19 करोड़ पौंड चाय का निर्यात किया गया जो 1939-40 में बढ़कर 35 करोड़ 90 लाख पौंड हो गया 1900-1 में 549,000 टन तिलहन का निर्यात किया गया जो 1938-39 में बढ़कर 1,172,802 टन हो गया।

इस प्रकार ब्रिटिश पूँजीवादी नीति का प्रत्यक्ष दुष्परिणाम यह है कि कृषि पर दिन ब दिन अधिक से अधिक दबाव बढ़ता गया, निर्यात के लिए उन खाद्य फसलों का उत्पादन पर निरंतर जोर दिया जान लगा (साथ में भारत की जनता की भुखमरी भी बढ़ती गई) और इस नीति ने भारत को कच्चे माल के स्रोत तथा अपने माल की मंडी बनाकर रख दिया।

लेकिन कृषि पर यह जबरदस्त दबाव और किसानों के शोषण की सामाजिक स्थिति ही भारतीय जनता की गरीबी की बुनियाद है। भारत में ब्रिटिश पूँजीवादी नीति का सीधा परिणाम यह है कि पुरानी पद्धति में की जा रही खेती पर लगातार जबरन में ज्यादा दबाव डाला गया और यही भारतीय जनता की निधनता की बुनियादी स्थिति है। 1940

के अवाल आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था, उसने लिखा

भारत की जनता की गरीबी और अभाव के दिनों में आसन घटरो की जड़ में जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है वह यह है कि यहाँ की जनता का एकमात्र व्यवसाय खेती है।

आज से एक सौ वर्ष पूर्व 1840 में, चार्ल्स ट्रेवेल्यन ने हाउस आफ कॉमंस की प्रवर समिति को बताया था

हमने उनके उत्पादन का सफाया कर दिया, उनके पास अपनी जमीन से हुई उपज के अलावा और कुछ नहीं है जिस पर वे निर्भर कर सकें।

एक शताब्दी बाद 1928 में कृषि के बारे में शाही आयोग ने वही पुरानी दुखभरी कहानी दुहराई (रिपोर्ट, पृष्ठ 433)

जमीन पर लोगों का बढ़ता दबाव, जीवनयापन के लिए किसी वैकल्पिक साधन का न होना, बचाव का कोई रास्ता पाने में कठिनाई, और वह प्रारंभिक युग जिसमें एक कमाने वाला और दस खाने वाले होते थे, इन सारी बातों ने किसान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि जहाँ भी और जिस भी शत पर संभव हो वह अनाज पैदा करे।

## 2 कृषि पर अत्यधिक दबाव के नतीजे

कृषि पर अत्यधिक मध्या में लोगों की निर्भरता का अब यह है कि भारत की वर्तमान पिछड़ी हुई खेती का, एक बढ़ती हुई आबादी के दिनोंदिन ज्यादा हाते भाग को जीविका के साधन देने पड़ते हैं।

दूसरी तरफ, जमीन के एकाधिकार तथा किसानों को अपाहिज बनाने वाले शोषण के कारण खेती का विकास मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सीमाओं में कैद हो गया है कि वर्तमान खेती आबादी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अत्यधिक असमर्थ हो गई है।

यही वह दुर्दम्य स्थिति है जिसने भारत की खेती को अपने शिकजे में कस लिया है। कृषि के क्षेत्र में संकट की जड़ में यही कारण है। इसका नतीजा हम खेती के विकास में आए ठहराव में देख सकते हैं। यहाँ तक कि कृषि पर तब असहनीय दबाव के कारण उत्पादन के वर्तमान स्तर में गिरावट के और कृषि में जुटे लोगों की तबाह हालत के भी संकेत देखे जा सकते हैं।

सेती पर घटते हुए अत्यधिक दवान का अर्थ यह है कि कृषि के कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध जमीन में कमी आती जा रही है। 1911 में सर थामस होल्डरनेस ने लिखा था

संरक्षित देशी राज्या सहित भारत की कुल आबादी साठे इक्कीस करोड़ है। इन विशाल आबादी का तीन चौथाई हिस्सा कृषि पर निर्भर है। देशी राज्या के बारे में प्राप्त विवरण चूँकि अपूर्ण है इसलिए इस बात की सही सही जानकारी नहीं है कि कुल कितनी जमीन में सेती होती है। लेकिन यदि हम यह मानकर चलें कि जो हिस्सा कृषि पर सीधे सीधे निर्भर है, उसमें प्रति व्यक्ति के हिस्से में सवा एकड़ जमीन आती है, तो ज्यादा गलत नहीं होगा

भारत की जमीन न सिर्फ इस बड़ी आबादी को भोजन देती है बल्कि उसके काफी बड़े हिस्से को उन चीजों की पैदावार के लिए अलग कर दिया गया है जो देश से बाहर निर्यात के लिए बाई जाती है। दरअसल यह मुख्यतया सेती से हुई उपज को बेचकर आयात के लिए अपने बिलों का भुगतान करती है और अन्य अंतराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करती है। इस प्रकार विदेशी बाजार का माल सप्लाई करने के लिए इस्तमाल होने वाली जमीन को कृषि के काम में लगी कुल जमीन में से घटाने से जो जमीन बचती है वह भारत की कुल आबादी के बीच 2/3 एकड़ प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं पड़ती। इसलिए 2/3 एकड़ प्रति व्यक्ति से जितनी पैदावार हा पाती है उसी से भारत की आबादी को भोजन और कुछ हद तक कपड़ा मिलता है। विश्व में शायद ही कोई देश हो जहाँ जमीन से इतना काम लिया जाता हो। (सर थामस होल्डरनेस, 'पोपुल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया', 1911 पृष्ठ 139)

1917 में बंबई के कृषि निदेशक, डा० हार्ल्ड एच० मान ने पूना के एक घास गांव की जाच के परिणाम प्रकाशित किए। जाच के दौरान उन्होंने देखा कि 1771 में औसत जोत 10 एकड़ थी। 1818 में यह 17½ एकड़ थी। 1820-40 में यह घटकर 14 एकड़ हो गई और 1914-15 में महज 7 एकड़ रह गई। उन्होंने जाच के दौरान पाया कि 81 प्रतिशत जोतें अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी अपनी मिलिक्यत नहीं बनाए रख सकीं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला

इससे यह जाहिर है कि पिछले 60 या 70 वर्षों में जमीन की जोतो का स्वरूप बदल गया है। ब्रिटिश शासन से पहले के दिनों में और ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में जोतो का आकार आमतौर से ठीक ठाक था। अधिकांश मामलों में यह 9 या 10 एकड़ से अधिक था और 2 एकड़ से कम की व्यतिरिक्त जातें शायद ही बची थीं। अब जातो की मट्या दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है और इन

जोता में से 81 प्रतिशत जोतो का आकार 10 एकड़ से कम है जबकि कम से कम 60 प्रतिशत जोतें 5 एकड़ से भी कम की हैं। (डाक्टर एच० एच० मान 'लैंड एंड लेबर इन ए डवन विलेज,' पृष्ठ 1, 1917, पृष्ठ 46)

अप्य सूबो के लिए भी इसी तरह के नतीजे मिले हैं। श्री कीटिंग ने विचार व्यक्त किया है कि बबई प्रेसीडेंसी की कृषीय जोतें काफी बड़े पैमाने पर ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जिसमें उनकी कारगर ढंग से खेती असंभव है, और डा० स्लेटर की खोज के अनुसार 'मद्रास के कुछ हिस्सों में इसी तरह की स्थितियां मौजूद हैं। अप्य सूबा में स्थितियां काफी हद तक ऐसी ही हैं।' (एग्जीक्यूटिव कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ 132)

1921 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की संख्या एकड़ में इस प्रकार है

|                 |     |                     |      |
|-----------------|-----|---------------------|------|
| मद्रास          | 4 9 | बर्मा               | 5 6  |
| संयुक्त प्रांत  | 2 5 | पंजाब               | 9 2  |
| आसाम            | 3 0 | मध्य प्रांत और बरार | 8 5  |
| बिहार और उड़ीसा | 3 1 | बंबई                | 12 2 |
| बंगाल           | 3 1 |                     |      |

ये औसत संख्याएं हैं जिनमें बहुसंख्यक की अत्यधिक कमी की अल्पसंख्यक की बड़ी बड़ी जोतों से अंश छिपाया गया है।

'सोशल एंड इकानामिक सर्वे आफ ए कोकण विलेज', (प्रांतीय सहायिता संस्थान, बंबई द्वारा प्रकाशित, रूरल इकानामिक सीरीज, संख्या-3) के नतीजों से पता चलता है कि 192 एकड़ की कृषियोग्य भूमिवाले एक गांव में ऐसे 24 व्यक्तियों के पास 113 एकड़ जमीन या औसतन प्रति व्यक्ति 4 71 एकड़ जमीन थी जो खेती नहीं करते थे जबकि 28 खेतिहरो के पास कुल 78 एकड़ या प्रति व्यक्ति 2 85 एकड़ जमीन थी।

मलाबार के एक गांव के आर्थिक जीवन, 'इकानामिक लाइफ इन ए मलाबार विलेज' (मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र सीरीज नं० 2 द्वारा प्रकाशित) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उक्त गांव में 34 प्रतिशत जोते 1 एकड़ से कम की थी।

स्थाई अधिकारविहीन कृषकों के संबंध में अर्थात् कृषकों की बहुसंख्या के संबंध में कृषि संबंधी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार (पृ० 133)

सूबे के आकड़ा में केवल पंजाब के आकड़े उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि 22 5 प्रतिशत किसान एक एकड़ या इससे कम में खेती करते हैं, 15 4 प्रतिशत किसान एक से ढाई एकड़ जमीन में, 17 9 प्रतिशत किसान ढाई से पांच एकड़ जमीन में और 20 5 प्रतिशत किसान 5 से 10 एकड़ जमीन में



लेती करते हैं। बरई को छोड़कर जिसके नतीजे संभवतः काफी हद तक पंजाब जैसे होंगे और वर्मा को छोड़कर जहाँ यह औसत अपेक्षाकृत काफी अधिक होगा, अन्य सभी सूबों में प्रति कृषक औसत जमीन काफी कम है।

इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक 'समृद्ध' पंजाब में भी (जो अन्य सूबों की अपेक्षा कम समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है), आबादी का एक तिहाई से अधिक भाग ढाई एकड़ से कम में और आधे से अधिक भाग 5 एकड़ से कम में लेती करता है।

बंगाल में, 1921 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति कार्यरत किसान द्वारा जोनी गई जमीन 22 एकड़ थी। 1921 की बंगाल जनगणना रिपोर्ट ने लिखा कि 'य आकड़े खुद ही कृषकों की गरीबी के बारे में बताते हैं।'

ये ऐसे तथ्य हैं जिनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इनसे जमीन के लिए एक पुरानी और निरंतर बढ़ने वाली भयंकर भूख का पता चलता है। ये सारे तथ्य केवल एक दिशा की ओर संकेत करते हैं और यह संकेत ठीक वैसा ही है जैसा रूस के कृषीय इतिहास ने इस तरह के तथ्यों से संकेत दिया था।

### 3 खेती में ठहराव और गिरावट

क्या जमीन के लिए इस पुरानी और बढ़ती हुई भूख का अर्थ यह है कि हमारे सामने आबादी की तुलना में, प्रकृति द्वारा अनिवार्य रूप से घोषी गई भूमि की कमी की समस्या है? स्थिति इसमें एकदम विपरीत है। आजकल व्यापक रूप से फैली हुई इस धारणा के बावजूद यदि तथ्यों की जांच करें तो पता चलेगा कि स्थिति कुछ और ही है (प्रमाण के लिए देखें अध्याय 2, उपशोधक 3)।

समस्या यह नहीं है कि भारत में भूमि की वेहद कमी है। जो कमी महसूस होती है उसका कारण प्रत्यक्ष यह है कि प्रतिबन्धों और विकास की उपेक्षा की वजह से उपलब्ध कृषियोग्य जमीन का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जाता। दूसरे, यह कमी इस कारण पैदा हुई है कि जिन जमीन में खेती होती है उसमें उत्पादन का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इसकी वजह है वर्तमान समाज व्यवस्था का दुर्दम्य बोझ जिसने कृषि का अपाहिज बना दिया है और तकनीकी विकास तथा व्यापक मशीन के माग में आन बानी बाधपूर्ण।

अनुमान लगाया गया है कि तकनीक के छोट पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद, भारत में उपलब्ध समूची कृषियोग्य भूमि में यन्त्र भूमि सुधार और सिंचाई के आवश्यक उपाय काम में लाए जाएं तो 44 करोड़ 70 लाख लोगों की जीविका चल सकती है। यह मर्यादा वर्तमान आबादी में 7 करोड़ अर्ध की मर्यादा है। (जार्ज मुगर्जी 'फूड प्लानिंग फॉर इंडिया' मिनिंग' पृष्ठ 26)।

भारतीय अथशास्त्री आर० के० दास का अनुमान है कि कृषियोग्य उपनब्ध भूमि का 70 प्रतिशत भाग बेकार जाता है और उत्पादन सब्धी कार्यों के लिए केवल 30 प्रतिशत भाग का इस्तेमाल होता है

वस्तुतः जितनी जमीन में फसल बोई जाती है वह कुल मिलाकर 22 करोड़ 80 लाख एकड़ है जो कृषियोग्य समूची भूमि का 53 प्रतिशत है। लेकिन जिन खेतों में एक बार से अधिक फसल बोई गई है, उन्हें यदि प्रत्येक फसल के लिए अलग खेत मानें तो कुल जमीन, जिसमें खेती की जाती है 26 करोड़ 20 लाख एकड़ होती है। यहाँ की जलवायु का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसमें कृषियोग्य भूमि के उल्लेखनीय हिस्से में साल में दो से अधिक फसल बोई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुल जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें एक बार से अधिक फसल नहीं बोई जा सकती और कुछ खेत तो ऐसे भी हैं जिनमें आने वाले कुछ वर्षों में एक भी फसल नहीं बोई जा सकती। इसलिए यह माना जा सकता है कि औसतन कुल कृषियोग्य भूमि में साल में दो फसलें बोई जा सकती हैं। इस प्रकार क्षमतायुक्त कृषियोग्य भूमि लगभग 86 करोड़ 40 लाख एकड़ है जिसमें से केवल 26 करोड़ 20 लाख एकड़ या 30 प्रतिशत भूमि का उत्पादन कार्य के लिए इस्तेमाल होता है और 60 करोड़ 20 लाख एकड़ या 70 प्रतिशत बेकार पड़ी रहती है। (आर० के० दास 'दि इंडस्ट्रियल एफिसिएसी आफ इंडिया', 1930, पृष्ठ 13)

वस्तुतः वर्तमान मंदी के प्रभाव के कारण लगी राक से पहले तक, पिछले 25 वर्षों में, खेती की जाने वाली मौजूदा भूमि का क्षेत्रफल आबादी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा। निम्न तालिका से इसका संकेत मिलता है

#### खेती की गई जमीन और जनसंख्या का सूचक अंक

|   | जनसंख्या | बोई गई<br>कुल जमीन | छाया नवाली<br>जमीन |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| युद्धपूर्व का औसत<br>(1910-11 से 1914-15) | 100      | 100                | 100                |
| 1930-31                                   | 107      | 118.6              | 113.9              |
| 1934-35                                   | 120      | 117.2              | 112.4              |

(आर० मुखर्जी 'फूड प्लानिंग फार फोर हंड्रेड मिलियंस', पृष्ठ 16-17)

इस प्रकार 1910-14 में 1930-31 के बीच जनसंख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन खेती करने वाली जमीन में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इधर हाल के वर्षों में युद्ध के

फलस्वरूप आई मदी के कारण कृषियोग्य भूमि के क्षेत्र में वेहद कमी के अशुभ संकेत मिले हैं और खाद्यान्नोवाले क्षेत्र में ता और भी ज्यादा कमी हुई है। किंतु इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषियोग्य भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसपर अभी खेती नहीं की जा रही है। मौजूदा आकड़ा से यह तस्वीर और साफ होती है

**ब्रिटिश भारत का कृषीय क्षेत्र, 1939-40**  
(बर्मा को छोड़कर)

|  | एकड़ करोड़ में |
|--|----------------|
| सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त कुल भूमि का क्षेत्रफल | 51 27          |
| जंगलवाली भूमि                                  | 6 81           |
| खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि                      | 8 93           |
| बजर के अलावा कृषियोग्य बेकार पड़ी भूमि         | 9 72           |
| बजर भूमि                                       | 4 73           |
| फसल बोई गई कुल जमीन                            | 20 99          |

(‘स्टैटिस्टिकल ऐब्स्ट्रेक्ट फार ब्रिटिश इंडिया’)

इस प्रकार कृषियोग्य कुल 35 करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन के महज 59 प्रतिशत हिस्से में फसल बोई गई है जबकि 13 2 प्रतिशत जमीन बजर पड़ी है और खेती लायक कम से कम 27 3 प्रतिशत जमीन बेकार पड़ी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि सरकारी तौर पर कुल जमीन के छठे हिस्से से भी अधिक भाग के बारे में कहा गया है कि यह जमीन ‘कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है’ लेकिन कृषि सवधी आयोग की रिपोर्ट में यह कहना पड़ा (पृष्ठ 605) कि ‘यह विश्वास करना कठिन है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध खान में जिस जमीन को डाला गया है वह या तो उपलब्ध नहीं है या खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।’ इसीलिए यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि कृषियोग्य वह जमीन जिसपर खेती नहीं की गई है, सरकारों आकड़े से 27 3 प्रतिशत से भी ज्यादा है और एक तिहाई के करीब भी हो सकती है।

इस विशाल जमीन का, जो ‘बजर नहीं थी और कृषियोग्य होने के बावजूद बेकार पड़ी थी’ क्या स्वरूप है और क्या कारण है कि उसपर खेती नहीं की गई? यह जानना जरूरी है कि विभिन्न प्रांतों में इस जमीन की मात्रा अलग अलग थी। यहा तक कि सबसे ज्यादा आबादीवाले और सबसे अधिक विवसित प्रांतों बंगाल, मद्रास या संयुक्त प्रांत में बजर का छोड़कर कृषियोग्य बेकार भूमि की मात्रा काफी अधिक थी। बंगाल में यह 18 प्रतिशत मद्रास में 21 प्रतिशत और संयुक्त प्रांत में 20 3 प्रतिशत थी। इस सवाल का जवाब सर

जेम्स वेड की रिपोर्ट में 1879 में ही दे दिया गया था। यह रिपोर्ट अकाल आयाग के बारे में थी और इसे भारत के मामलों के मंत्री को सौंपा गया था।

भारत में उपलब्ध अच्छी जमीन के लगभग पूरे हिस्से पर दखल किया जा चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी बहुत सी अच्छी जमीन बेकार पड़ी है जिसपर जंगल लगे हुए हैं और जिसे साफ करके तथा सुधार करके खेती के योग्य बनाया जा सकता है लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए पूंजी की जरूरत है और जनता के पास ऐसे कामों में लगाने के लिए पूंजी नहीं है। (सर जेम्स वेड की रिपोर्ट भारतीय मामलों के मंत्री के नाम, 31 अक्टूबर 1879)

ऐसी बात नहीं है कि इस जमीन में खेती नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहां के किसान बेहद गरीब हैं उनके पास यदि एक औसत भी अतिरिक्त राशि आती है तो उससे ज्यादा जबरन वसूल ली जाती है जिसकी वजह से किसानों का एक विशाल जनसंख्या जीवनयापन के स्तर से भी निम्न स्तर पर अपनी गुजर कर रहा है। यही कारण है कि इस काम को पूरा करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। यह काम महज सरकार की सहायता से सामूहिक संगठन के जरिए और समुदाय के अतिरिक्त साधनों की उत्पादन के इस महत्वपूर्ण विस्तार काम में लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। सरकार ने अपनी इस जिम्मेदारी को कभी महसूस नहीं किया और इसी स्थल पर आकर वर्तमान सरकारी और सामाजिक व्यवस्था की असाधारण विफलता की अभिव्यक्ति होती है। इस व्यवस्था ने ब्रिटिश शासनकाल से पहले की सरकारों द्वारा सावजनिक निर्माण और सिंचाई के कार्यों की देखरेख करने में पूरी तरह उपेक्षा की और किसानों से जबरदस्ती उनकी संपत्ति वसूल कर उनके हाथ से खेती का काम छीन लिया। इसके साथ ही अभी हान के वर्षों में भूमिसुधार और सिंचाई कार्यों की जो शुरुआत की गई है वह इसकी संभावनाओं और आवश्यकताओं की तुलना में नगण्य है।

शुरू में सरकार ने सिंचाई तथा सावजनिक निर्माण कार्यों के प्रति उपेक्षा का जो रवैया अपनाया उसके लिए उसे काफी कुख्याति प्राप्त हो चुकी है और माक्स ने तो इसका बहुत पहले ही उल्लेख किया था

एशिया में अति प्राचीन काल से सामान्यतया सरकार के तीन विभाग काम करते हैं पहला वित्त विभाग अर्थात् घरेलू स्तर पर लूटपाट करने वाला विभाग, दूसरा युद्ध विभाग अर्थात् विदेशों के स्तर पर लूटपाट करने वाला विभाग और अंतिम सावजनिक निर्माण विभाग भारत में अंगरेजों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों से वित्त और युद्ध विभाग तो ले लिया लेकिन उन्होंने सावजनिक निर्माण विभाग की पूरी तरह उपेक्षा की। इसलिए कृषि के क्षेत्र में काफी गिरावट आई

क्याकि ब्रिटिश शासका के मुक्त प्रतिस्पर्धा, अहस्तक्षेप और स्वच्छदना के सिद्धांत के आधार पर कृषि का काम नहीं चल सकता था। (काल माक्स 'दि ब्रिटिश रूल इन इंडिया,' यूयाक डेली ट्रिब्यून, 25 जून 1853)

1838 में एक प्रेक्षक (जी० थाम्सन 'इंडिया ऐंड दि कालोनीज,' 1838) ने लिखा था कि देश की सेवा के लिए और जनता की भलाई के लिए हिंदू या मुसलमान सरकारा न जिन सबको तालाबों और नहरों का निर्माण किया था उनकी हालत आज जीण शीण हो गई है आज स्थिति यह है कि सिंचाई के माधनों के अभाव में जनता को अकाल का सामना करना पड़ रहा है।' भारत में आधुनिक सिंचाई काय के पथप्रदर्शक सर आर्थर काटन ने 1854 में अपनी पुस्तक 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया' में जो कुछ लिखा वह माक्स से भी ज्यादा तीखा है

समूचे भारत में सावजनिक निर्माण कार्य की लगभग पूरी तरह उपेक्षा की गई है यहाँ का नारा बस यही रहा है कि कुछ मत करो, कुछ मत करने दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर तरह का घाटा उठाओ, जनता को अकाल से मरने दो, लाखों लोगों को पानी और सड़क के लिए पैसा वसूल कर कगाल बना दो (लेफ्टिनेंट कर्नल काटन 'पब्लिक वर्क्स इन इंडिया,' 1854, पृष्ठ 272)

माटथुमरी मार्टिन ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'दि इंडियन इंपायर' (1858) में लिखा है कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 'विकास काय शुरू तो नहीं ही किए, उसने उन पुराने निर्माण कार्यों की मरम्मत की भी उपेक्षा की जिससे उस राजस्व प्राप्त होता था।' निश्चय ही यह उपेक्षा ब्रिटेन के अंदर समकालीन ब्रिटिश अप्रवर्धित व्यापार की तुलना में उल्लेखनीय रूप से और भी ज्यादा तेज हुई। जैसा जान ब्राइट ने 24 जून 1858 को हाउस ऑफ कॉमंस में कहा 'अकेले मानचेस्टर शहर ने अपने निवासियों को केवल पानी की सप्लाई पर जो राशि खर्च की है वह राशि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने विशाल डोमीनियन में 1834 से 1848 के 14 वर्षों के दौरान सावजनिक निर्माण के प्रत्येक काम पर खर्च की गई राशि से कहीं ज्यादा है।'

यह तब कि 1900 तक सरकार ने रेल व्यवस्था के निर्माण पर अपने कोष से 22 करोड़ 50 लाख पौंड खर्च किए ताकि भारत में ब्रिटिश व्यापार की घुसपैठ हो सके लेकिन इस अवधि तक कृषि जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण काय के लिए आवश्यक नहरों के निर्माण पर केवल दस करोड़ पौंड खर्च किए गए। यह राशि रेल व्यवस्था पर खर्च की गई राशि का नया हिस्सा है।

इससे पहले कि हम यह मानें कि यह उपेक्षा अतीत में ही बरती गई और वर्तमान युग में

अब इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ 1930 में बंगाल सिंचाई विभाग समिति की हाल की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना काफी प्रासंगिक होगा

प्रत्येक जिले में नाव के जरिए सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए जो नहरें बनाई गई हैं उनमें समय बीतने के साथ ही पानी सूखता जा रहा है और वह दलदल का रूप ले रहा है। पूर्वी बंगाल में नहरें और नदियाँ ही वहाँ की सबकें और राजमाग हैं। इस प्रांत के लोगों के आर्थिक जीवन के लिए इनका कितना महत्व है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। (पृष्ठ 6)

मध्य बंगाल आज एक पतनशील भूभाग बन गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर मलेरिया का खतरा है जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है और जमीन की उत्पादन क्षमता नष्ट हो रही है। वेशक यह कहा जा सकता है कि गिरावट की यह स्थिति अब इतनी आग बढ चुकी है कि इसपर रोक नहीं लगाई जा सकती और अब यह क्षेत्र लाजमी तौर पर धीरे धीरे दलदल और जंगल में बदल जाएगा। (पृष्ठ 11)

जहाँ तक छोटे मोटे रास्ता के रखरखाव और उनको फिर से शुरू करने की बात है व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस सूबे के कुछ हिस्सों में नहरें सूख गई हैं, नावों का चलना वष में कुछ ही महीनों तक हो पाता है और फसल को बाजार में तभी भेजा जा सकता है जब बरसात के पानी से नहरें इस लायक हो जाएँ कि नावों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सके। (पृष्ठ 11) (बंगाल की सिंचाई विभाग समिति की रिपोर्ट, 1930)

जल विज्ञान (हाइड्रोलिक्स) के प्रमुख इंजीनियर सर विलियम बिलकाक्स ने बंगाल की सिंचाई व्यवस्था के पतन पर अपना जो निणय दिया था वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है

विख्यात हाइड्रोलिक इंजीनियर सर विलियम बिलकाक्स का नाम मिस्र और मेसोपोटामिया में किए गए विशाल सिंचाई कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने हाल ही में बंगाल की स्थिति की छानबीन की। अपनी खोज के द्वारा उन्होंने पता लगाया कि डेल्टा क्षेत्र की असह्य विनाशकारी छाटी नदियाँ निरंतर अपना मार्ग बदल रही हैं और यह मूलतः नहरें थी जिन्हें अंगरेजी शासनकाल ने खतरनाक नदियों का रूप दे दिया। पहले इन नहरों से गंगा की बाढ़ का पानी इधर उधर बंट जाता था और इससे सेतों की उचित ढंग से सिंचाई हो जाती थी। इन्हीं नहरों के कारण बंगाल की समृद्धि इस सीमा तक बढ़ गई थी कि 18वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागरों की लालच भरी निगाहें

इसकी तरफ आकर्षित हुई इस बुनियादी नहर व्यवस्था को विकसित करने और इसका इस्तेमाल करने की कोई कोशिश कभी नहीं की गई उल्टे रेलवे के तटबंधों को नमश ताड़ दिया गया जिससे नहरों का पूरी तरह विनाश हो गया। गंगा के पानी के साथ दोमट मिट्टी तमाम इलाकों में पहुंचती थी जिससे जमीन की उत्पादन क्षमता बढ़ती थी लेकिन इन इलाकों को गंगा के जल से अलग बलम कर दिया गया और वे धीरे धीरे बजर तथा अनुवर होते गए। कुछ अग्र इलाकों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने से काफी बड़े पैमाने पर पानी एक ही जगह इकट्ठा होने लगा जिससे अनिवाय रूप से मलरिया फैल गया। इसके अलावा गंगा के ढालू बहाव के लिए उचित तटबंधों के निर्माण की कोई कोशिश नहीं की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव से अनेक गांव, पेड़ पौधे और खड़ी फसलवाले खेत गंगा की गोद में समाने लगे।

सर विलियम विलकाक्स ने आधुनिक प्रशासकों और अधिकारियों की बटु आलोचना की है। उनका आरोप है कि ये लोग तकनीकी सहायता के लिए विसी भी विशेषज्ञ को कभी भी बुला सकते थे और सलाह ले सकते थे लेकिन उन्होंने इस विनाशकारी स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हर दशक में स्थिति बदतर होती गई। (जी० इमरसन 'वायसलेंस मिलियस' 1931, पृष्ठ 240-41)

सर विलियम विलकाक्स का समूचा बयान उनकी पुस्तक 'लेक्चर्स आन दि एनसिऑट सिस्टम आफ इरिगेशन इन बंगाल एंड इट्स ऐप्लीकेशन टू माडन प्रान्क्लम्स' (बलवता यूनिवर्सिटी रीडरशिप लेक्चर्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1930) में मिल सकता है। इस साथ ही उस विवाद का अंश भी मिल जाएगा जो बंगाल में सिंचाई के बारे में सर विलियम विलकाक्स के लेक्चर पर बंगाल के सिंचाई विभाग के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर सी० ऐडम्स विलियम्स सी० आई० ई० ने उठाए थे। साथ में श्री विलियम्स द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सर विलियम विलकाक्स का जवाब भी उपलब्ध हो जाएगा। (बंगाल सफ्टवेयर बुक डिपार्टमेंट, 1931)

इस प्रकार जो लापरवाही और उदासीनता बरती गई है वह किसी भी अर्थ में ब्रिटिश शासनकाल के पिछले डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास की बात नहीं है बल्कि वह आज के युग में भी जारी है। 1930 की एक सरकारी रिपोर्ट की शर्णावली में यह तो मौजूदा कृषिभूमि भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़न और भूमि की बेहद कमी की स्थिति में 'जमीन पगल पैग' करने की अपनी दमता छोटी जा रही है।' 1789 में लार्ड कानयालिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित प्रदेश का अधिवास 'जंगली जानवरों से भर हुआ जंगल के रूप में' तबदील होता जा रहा है। 1930 में मध्य बंगाल के बारे में सरकारी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 'निश्चय ही यह स्थिति हो सकती है कि मनुष्य

स्थिति में इस सीमा तक गिरावट आ गई है कि अब इसमें सुधार नहीं किया जा सकता और यह भूभाग धीरे-धीरे दनदल और जंगल का रूप लेने के लिए अभिशप्त है।

लेकिन भारत के किसानों की अत्यधिक संख्या को अपनी फसलें महज कृषियोग्य भूमि के 59 प्रतिशत हिस्से तक ही सीमित नहीं करना होगा। कृषियोग्य भूमि के इस सीमित क्षेत्र के अंदर भी यहां की सामाजिक स्थितियां, किसानों को अपाहिज बना देने वाला बोझ, उनकी भयंकर गरीबी और आदिकालीन तकनीक जिसे विकसित करने का कोई साधन उनके पास नहीं छोड़ा गया, का अर्थ यह है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में खेती करने वालों की अधिक जरूरत है। उत्पादन का स्तर किसी भी देश की तुलना में बहुत कम है।

यदि हम भारत में हुई चावल और गेहूं की उपज की तुलना चीन, जापान या अमरीका की पैदावार से करें तो हमें महत्वपूर्ण विषमता दिखाई देगी

प्रति एकड़ में हुई उपज (क्विंटल में)

|       | भारत | चीन  | जापान | अमरीका |
|-------|------|------|-------|--------|
| चावल  | 16.5 | 25.6 | 30.7  | 16.8   |
| गेहूं | 8.1  | 9.7  | 13.5  | 9.9    |

(‘प्रॉब्लम्स आफ दि पैसिफिक’ 1931, पृष्ठ 70)

राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशंस) के आकड़ा के आधार पर की गई तुलना भी उपलब्ध है

प्रति एकड़ में हुई उपज (पौंड में)

|         | चावल  | गेहूं |
|---------|-------|-------|
| भारत    | 1,357 | 652   |
| जापान   | 2,767 | 1,508 |
| मिस्र   | 2,356 | 1,688 |
| अमरीका  | 2,112 | 973   |
| इटली    | 4,601 | 1,241 |
| जर्मनी  |       | 1,740 |
| ब्रिटेन |       | 1,812 |

(‘स्टैटिस्टिकल इयर बुक आफ दि लीग आफ नेशंस’, 1932 33)

क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखें तो यह विषमता और भी



उल्लेखनीय है। भारत में प्रत्येक 2.6 एकड़ भूमि पर खेती के काम में एक व्यक्ति लगा है जबकि ब्रिटेन में 17.3 एकड़ और जर्मनी में 5.4 एकड़ भूमि पर एक व्यक्ति खेती करता है। श्रम की इस भयंकर वरबादी से पता चलता है कि कृषि पर आबादी का वितना जबरदस्त दबाव है और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह कितनी पिछड़ी हुई है। पैदावार में अन्य देशों की तुलना में जो कमी है वह प्राकृतिक रूप से यहाँ की मिट्टी की कम उत्पादकता के कारण नहीं है।

कहा यह जाता है कि भारत की मिट्टी अपनी प्रकृति से ही कम उपजाऊ है। यह बात सही नहीं है। यहाँ की मिट्टी को कम उपजाऊ बनाया गया है। यहाँ की विशाल नदी उपत्यकाएँ एक जमाने में दुनिया के सबसे उर्वर प्रदेश रह चुकी हैं। डेनमार्क और जर्मनी में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी तौर पर रेतीला बजर हिस्सा है जहाँ केवल घासपात और कटीली झाड़ियाँ पैदा होती हैं। (इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, एनक्लोजर XIII, पृष्ठ 700। ए० पी० मैकडोगल का ज्ञापन, 19 मार्च 1931)

इसी ज्ञापन में निम्न बात कही गई है

यदि प्रति एकड़ उत्पादन को फ्रांस के उत्पादन के बराबर बढ़ा दिया जाए तो देश की संपदा में 669,000,000 पौंड की वृद्धि हो जाएगी। यदि इस उत्पादन को ब्रिटेन के बराबर बढ़ा दिया जाए तो इसमें प्रति वर्ष 1,000,000,000 पौंड की वृद्धि हो जाएगी। फिर भी इंग्लैंड किसी भी मापने में अत्यधिक खेतिहर देश नहीं है। इस राशि में भारत की जमीन के उस हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया है जिसमें साल में दो फसलें तैयार होती हैं। भारत को जो यह लाभ प्राप्त है उससे सूखे से होने वाली किसी क्षति की पूर्ति मान ली जानी चाहिए। डेनमार्क में गेहूँ की उपज के सदर्भ में देखें तो यहाँ हुई संपदा प्रतिवर्ष 1,500,000,000 पौंड होनी चाहिए। इसलिए यह कहना गलत है कि भारत की ग्रामीण जनता की गरीबी के लिए यहाँ की मिट्टी जिम्मेदार है।

खेती का मौजूदा उत्पादन न सिर्फ आज बहुत निम्न स्तर पर है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि खेती की उत्पादन क्षमता में बराबर गिरावट आई है। उपर्युक्त उद्धृत मकडोगल ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ की मिट्टी की उत्पादकता इसलिए कम होनी गई क्योंकि 'जिना घाट डाल लगातार खेती की गई और ध्वन को जगह पर छाद या इस्तेमाल करना छोड़ दी वरबादी की गई' (जंगल मयघी पट्टे बानूना का दुष्परिणामों की श्रृंखला का मिलती है)। ज्ञापन में यह भी रेखांकित किया गया है कि पश्चिमी जंगल में घनों के हटाने और भूगर्भ का इस्तेमाल घाट के रूप में किया जाता है जबकि भारत में मारा का मारा भूगर्भ जानबूझकर खोना दिया जाता है' (इसमें चरगागाहों की सुविधा का हानि का

जल मिलती है)। भारत का किसान गाय का गोबर जलाने का काम में लाता है और उसकी इस क्रिया को प्रायः एक विचित्र तथा बरबादी करने वाली आदत मान लिया जाता है। इस संबंध में कृषि संवर्धन आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है। इसमें कहा गया है कि जंगली लकड़ी या कोयले के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा रेल द्वारा परिवहन के लिए ऊँची दरों के कारण भारतीय किसान फिलहाल ईंधन के रूप में गोबर का ही इस्तेमाल करता है क्योंकि यही उसे आसानी से सुलभ हो पाता है (पृष्ठ 264)। इस स्थिति का कोई समाधान नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे अनिवाय रूप से मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट आती जा रही है। बंगाल के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है

खाद के अभाव में तेतिहर भूमि की उर्वरता में तेजी से गिरावट आ रही है। विभिन्न फसलों की पैदावार दिनादिन कम होती जा रही है। (बंगाल प्राविंसियल बैकिंग इक्वायरी कमेटी रिपोर्ट, 1930, पृष्ठ 21)

इस कथन के समर्थन में कुछ आंकड़े दिए गए हैं

बंगाल में प्रति एकड़ में औसत उपज (पौंड में)

| निम्न स्तर में समाप्त होने वाले 5 वर्ष | जाड़ा |       |     |               |
|--|-------|-------|-----|---------------|
|  | गेहूँ | चावल  | चना | सरसो और तिलहन |
| 1906-07                                | 801   | 1,234 | 881 | 492           |
| 1911-12                                | 861   | 983   | 881 | 492           |
| 1916-17                                | 698   | 1,036 | 867 | 460           |
| 1921-22                                | 688   | 1,029 | 826 | 485           |
| 1926-27                                | 721   | 1,022 | 811 | 483           |
| 20 वर्षों में आई कमी                   | 80    | 212   | 70  | 9             |

भारत सरकार के एक विशिष्ट अधिकारी डब्ल्यू० वनस सी० आई० ई० ने भी समूचे भारत के लिए कुछ इसी तरह के आंकड़े पेश किए थे तालिका पृष्ठ 236 पर)

गेहूँ की उपज के बारे में भी बिगड़ती हुई स्थिति का पता चलता है। 1909-13 में गेहूँ की पैदावार औसतन प्रति एकड़ 724 पौंड थी जो 1924-33 में घटकर 636 पौंड हो गई। (वही, पृ० 57)

**चावल की औसत उपज  
(प्रति एकड़ पौंड में)**

|         |    |         |    |     |     |
|---------|----|---------|----|-----|-----|
| 1914-15 | से | 1918-19 | का | औसत | 982 |
| 1926-27 | से | 1930-31 | का | औसत | 851 |
| 1931-32 | से | 1935-36 | का | औसत | 829 |
| 1938-39 |    |         |    |     | 728 |

(‘टेक्नोलाजीकल पासिविलिटीज आफ ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, 1944 पृष्ठ 55)

इस प्रकार यदि हम केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखें और समूची अव्यवस्था के सदर्भ में भारत में कृषि की पैदावार की प्रवृत्तियों पर ही विचार करें तथा बढ़त हुए सामाजिक अंतर्विरोधों को फिलहाल दरकिनार कर दें तो भी हरदृष्टिकोण से यह जाहिर हो जाता है कि भारत की खेती का सकट दिनोदिन बढ़ता जा रहा है।

इस बढ़त हुए सकट के कारणों की तलाश हम प्राकृतिक दशाओं में नहीं बल्कि सामाजिक सबंधों के क्षेत्र में करनी चाहिए। विलकुल हाल के अनुभवों से पता चलता है कि दमरूप और अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से हमेशा किसानों को यही उपदेश देने की काशिश की गई है कि वे पिछड़े हुए हैं और इस बात की कोशिश नहीं की गई कि उनके शोषण को रोकने के लिए कुछ किया जाए या खेती के उनके तरीके विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएं। इन किसानों के पास न तो कोई साधन है जिससे वे उन्नत तकनीकी पद्धतियाँ अपना सकें और न तो भूमि की पट्टेदारी की मौजूदा स्थितियों में इन बातों की कोई सम्भावना ही है।

निश्चय ही वर्तमान स्थितियों और सीमाओं के भीतर भारतीय किसानों की बुझना और साधनसंपन्नता की परख विशेषज्ञों ने की है। 1889 में सरकार ने रायल एग्रीकल्चरल सोसायटी के कंसल्टिंग कमिस्ट जे० ए० वोल्बर को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वह भारतीय कृषि की तकनीक की जांच करें और उसमें विकास के सुझाव दें। उनका जांच की रिपोर्ट दो वष बाद प्रकाशित हुई। यह भारतीय कृषि के बारे में एक असाधारण श्रुति है। इसमें उन्होंने लिखा

एवं मुझे पर कोई असहमति नहीं हो सकती, और वह यह है कि इंग्लैंड में और कभी कभी भारत में भी यह जो धारणा व्यक्त की जाती है कि भारतीय कृषि कुल मिलाकर आदिवासी और पिछड़ी हुई है तथा इसमें सुधार करने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं पूरी तरह भ्रांतिपूर्ण है। यदि उसकी कान अंशु रही तो भारतीय रैयत या किसान उतना ही अच्छा है जितना ग्रेन

का औसत किसान और कुछ मामलों में तो वह ब्रिटिश किसान से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। लेकिन यदि फसल खराब हो गई तो केवल यही कहा जा सकता है कि इस स्थिति के लिए सुधार की सुविधाओं का न होना काफी हद तक जिम्मेदार है। सुधार की सुविधाओं का यहाँ जितना अभाव है उतना शायद ही किसी और देश में हो। इसके अलावा कठिनाइयों के मुकाबले में यहाँ का किसान जितने धैर्य और बिना शिकायत के सधन करता है उतना कोई दूसरा नहीं।

हमारे ब्रिटिश किसानों को मेरे इस कथन पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत के रहने वाले गेहूँ की खेती इंग्लैंड द्वारा गेहूँ की खेती किए जाने से सैकड़ों वर्ष पहले से करते आ रहे हैं। इसलिए इस बात की संभावना नहीं है कि उनके तौर तरीक़ों में अधिक विकास की क्षमता है तो भी अधिक फसल पैदा करने में जो चीज़ उन्हें बाधा पहुँचा रही है वह है वे सीमित साधन जो उनकी पहुँच में हैं उदाहरण के लिए पानी या खाद की सप्लाई।

लेकिन कृषि के साधारण कार्यों को यदि देखें तो हमें इस तरह के दृष्टांत इतने बेहतर ढंग से और कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ लोग इतने कायदे से अपने खेतों को छोटे छोटे घासपात से साफ रखते हों, सिंचाई के इतने अच्छे उपकरण इस्तेमाल में लाते हों, मिट्टी और उसकी क्षमता की इतनी अच्छी जानकारी रखते हों, बोन और बाटने के ठीक ठीक समय के बारे में जानते हों। ये सारे गुण भारतीय कृषि में ही मिलेंगे। यह विशेषताएँ किसी सर्वोत्तम स्थिति की भारतीय कृषि की विशेषताएँ नहीं हैं बल्कि साधारण स्तर पर यह चीज़ें मिल जाएँगी। यह भी अद्भुत है कि फसल को हेरफेर कर बोन की उह काफी जानकारी है और दो फसलें का मिलाकर बोन का तरीका उह बखूबी मालूम है। निश्चय ही कम से कम मैं तो इतनी सावधान खेती किसी और देश में नहीं देखी थी जहाँ खेती में पूरी मुस्तैदी बरतने के साथ साथ कठोर परिश्रम, फसल का संरक्षण और साधन की खर्चता पर इतना जोर दिया जाता हो। भारत की अपनी यात्रा के दौरान मैं कई स्थानों पर रहा और ये सारी खूबियाँ मैंने वहाँ देखी। (डाक्टर जे० ए० वोल्कर 'रिपोर्ट ऑन दि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन ऐग्रीकल्चर' 1891)

भारतीय कृषि के घटते हुए संकट का कारण न तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं और न ही किसानों की मुश्किलता अथवा साधनगणनता का अभाव है। जिन सीमाओं के अंतर्गत उह काम करता पड़ता है उह यदि देखें तो यह कहना गलत होगा कि भारतीय किसान की गरीबी का कारण उनका तथाकथित पिछापन है जिसकी वजह से उनका विकास

नहीं हो पा रहा है। वस्तुतः इस संकट का कारण साम्राज्यवाद है और साथ ही साम्राज्यवाद द्वारा पोषित वे सामाजिक संघर्ष हैं जिनकी वजह से कृषि पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। कृषि के विकास में गतिरोध पैदा हो गया है, उसमें गिरावट आने लगी है अधिकांश किसानों को दिनोदिन परेशान रहना पड़ता है और आधा पेट खाकर किसी तरह गुजर बसर करना पड़ता है। साम्राज्यवादी शासन और इससे उत्पन्न सामाजिक संघर्षों के कारण ही आज ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं जिनका एकमात्र परिणाम और समाधान दूरगामी प्रभावयुक्त क्रांति ही हो सकती है। कृषि के क्षेत्र में इस सामाजिक संघर्ष पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनसे ही हमें कृषीय संकट दूर करने की प्रेरक शक्तियों का पता चलेगा।



४०६  
इतिहास

8

## किसानों पर बोझ

‘कृषीय प्रणाली अब ध्वस्त हो चुकी है और समाज का नया संगठन अवश्यभावी है।’—  
1933 में जवाहरलाल नेहरू का वचन ।

मोजूदा शासन के अतगत कृषि पर आबादी के अत्यधिक दबाव, कृषि का निम्न स्तर, कृषि के क्षेत्र में ठहराव और गिरावट के रूप में खेती की पैदावार में जो सकट दिखाई पड़ता है वह खेती के सामाजिक व्यवस्था के आंतरिक संकट की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है। साम्राज्यवादी परिस्थितियों में किसानों के शोषण की ऐसी जबरदस्त प्रणाली विकसित हुई है जिसकी मिसाल किसी और देश में नहीं मिल सकती। साम्राज्यवादी प्रभुत्व और शोषण के रक्षात्मक बचच के भीतर कई तरह का पूरक परोपजीवितावाद विकसित हुआ है जो मजूरी व्यवस्था पर निर्भर है और व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसके परिणाम-स्वरूप जो प्रक्रिया सामन आती है उससे न केवल किसानों पर बढ़ते हुए बोझ, उनकी गरीबी और कृषि के बोझ से उनके दबे होने का ही पता चलता है बल्कि वर्गों के बीच बढ़ते हुए भेदभाव और बड़े पैमाने पर किसानों का उनके खेती से बेदखल किए जाने का भी पता चलता है। जमीन से बेदखल किसान एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जो कृषि दास प्रथा के काफी करीब है या वे दिन ब दिन बढ़ती हुई भूमिहीन सबहारा की एक सेना की शक्ल अस्तित्व पर रह रहे हैं। यही वह प्रक्रिया है जो आने वाले तूफान की सूचना दे रही है।

### 1. जमीन की इजारेदारी

ब्रिटिश शासनकाल में पहले भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था पायी थी उसमें जमीन पर किसानों का हक था और सरकार को फसल का एक हिस्सा मिल जाता था। भारत

की धरती पर जनजाति का या उसके उपविभागों का स्वामित्व था। इसमें ग्रामीण समाज कबीला या गांव में बसे विरादरी के अन्य लोगों की मिल्कियत थी, जमीन कभी राजा की संपत्ति नहीं समझी गई' (आर० मुखर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया', 1933, पृष्ठ 16)। 'चाहे सामंती व्यवस्था हो या शाही योजना, जमीन पर किसानों को छोड़कर कभी किसी अन्य का स्वामित्व नहीं रहा' (वही, पृष्ठ 36)।

'राजा का हिस्सा' अथवा राजा को दी जाने वाली मात्ता हिंदू राजाओं के शासनकाल में छोटे भाग से लेकर बारहवें भाग तक हुआ करती थी। युद्ध के काल में उपज की यह राशि एक चौथाई तक की जा सकती थी। मनु ने अपनी संहिता में कहा था

जिस प्रकार जोक, बछड़ा और मधुमक्खी अपना आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार राजा को अपने राज्य से मामूली कर ग्रहण करना चाहिए। राजा को भवेशियों और स्वर्ण की बढ़ी हुई राशि का पांचवा हिस्सा तथा फसल का आठवा, छठवा या बारहवा अंश प्राप्त करना चाहिए। फिर भी एक क्षत्रिय राजा जो युद्ध के दिनों में फसल का एक चौथाई अंश तक ग्रहण करता है वह यदि अपनी सामर्थ्य भर अपनी प्रजा की रक्षा करता है तो किसी प्रकार के दोषारोपण से मुक्त है।

मुगल बादशाहों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद इस राशि को बढ़ाकर एक तिहाई कर दिया था। अकबर ने इस प्रकार का कानून बनाया था

पुराने बीते दिनों में हिंदुस्तान के सम्राट भूमि की पैदावार का छठा हिस्सा नजराना और कर के रूप में वसूलते थे। शहशाह ने तय किया है कि सामान्य तौर पर बोए गए खेत की उपज का एक तिहाई हिस्सा राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाए।

मुगल साम्राज्य के विघटन के दिनों में वे लोग, जिनके जिम्मे कर की वसूली का काम सौंपा गया था और जिन्होंने अपने को खुद ही अधिसामंती सरदारों या स्वतंत्र सरदारों का दर्जा दे दिया था, नजराने की इस राशि को क्रमशः बढ़ाने लगे और इस राशि को एक तिहाई से बढ़ाकर आधा तक कर दिया।

नव मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अंगरेजों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने जमीन की आय से सरकारी कोष को समृद्ध करने की पुरानी पद्धति भी अपना ली लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दम प्रणाली का स्वरूप बदल दिया और ऐसा करके उन्होंने भारत की भूमि व्यवस्था का रूपांतरण कर दिया। जिस समय उन्होंने शासन सभाता उस समय तक भारत का पुराना शासन प्रबंध अस्तित्व में ही चुका था और पतन की निशा में बह रहा था। उन दिनों किसानों से जबरन बहुत अधिक धन वसूलता जाता था और उन्हें एक तरह

से लूट लिया जाता था। फिर भी गांव की सामुदायिक व्यवस्था और जमीन के साथ उसका परंपरागत संबंध उस समय तक भी टूटा नहीं था और नजराना के रूप में किसानों को राज्य को जो कुछ देना पड़ता था वह सालाना पैदावार का एक हिस्सा ही होता था। (नजराने की राशि सामान्य तौर पर पैदावार के रूप में और कभी कभी नकदी के रूप में दी जाती थी।) उस समय तक पैदावार चाहे कम हो या ज्यादा प्रतिवर्ष एक निश्चित जोत के आधार पर निश्चित मानगुजारी देने की प्रणाली अभी नहीं शुरू हुई थी।

अराजकता के दिनों में किसानों से जितनी निंद्यता के साथ नजराना वसूला जाता था उसे नए विजेताओं ने कर वसूलने का सामान्य ढंग समझा। समकालीन लेखकों की रचनाओं से पता चलता है कि शुरू में नए शासकों में पहले से ज्यादा संपत्ति वसूलने की प्रवृत्ति काम कर रही थी अथवा यह हो सकता है कि कर वसूलने की अपेक्षाकृत अधिक मुश्किल व्यवस्था के कारण किसानों का पहले में ज्यादा शोषण होने लगा था। डा० बुकानन ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में कंपनी की ओर से एक सर्वेक्षण किया था जो सरकारी तौर पर इतनी सावधानी के साथ की गई पहली जांच थी। उन्होंने अपनी पुस्तक 'स्टैटिस्टिकल सर्वे' में लिखा कि वसूली की यह नई प्रणाली अत्यंत दुस्सह है। उन्होंने 1800 ई० में दक्षिण भारत का और 1807-14 ई० में उत्तर भारत का सर्वेक्षण पूरा किया। फिर उन्होंने बंगाल के दिनाजपुर जिले के सदर में लिखा

ग्रामवासियों ने अपने आरोपों में बताया कि हालांकि मुगल शासकों के अधिकारियों द्वारा उनसे प्रायः जबरदस्ती संपत्ति वसूल ली जाती है और सभी अवसरों पर उन्हें बर्बर अपमानित किया जाता है फिर भी जम उनके ऊपर काफी राशि वसूला रूप में जमा हो जाती है और उनकी जमीन बेच दी जाती है उस समय वे इन तबलीफों को बरदाश्त कर लेते हैं। यह एक ऐसा चलन है जिसमें वे बच नहीं सकते। इससे अलावा अधिकांश अवसरों पर घूसखोरी का काफी बोलबाला है और उनका आरोप है कि आज वे घूस के रूप में जितना कुछ देते हैं वस्तुतः उसका आधा हिस्सा भी वे पहले नहीं देते थे। (डा० फ्रान्सिस बुकानन 'स्टैटिस्टिकल सर्वे' खंड IV, हाउस आफ वामस की प्रवर समिति की पांचवी रिपोर्ट में उद्धृत, 1872)

1826 में विशेष हेबर ने लिखा

मरा विचार है कि करारोपण की वर्तमान दर से मूल देशवासी अथवा अंगरेज कोई भी संपन्न नहीं हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ पैदा करता है उससे आधे हिस्से की सरकार मांग करती है हिंदुस्तान (उत्तर भारत) में मैंने राजा के अधिकारियों से सामान्य तौर से यह भावना देखी और कुछ परिस्थितियों के कारण मैं स्वयं भी उनकी इस भावना से सहमत हूँ कि कंपनी ने सूबा में रहने वाली



किसान जनता कुल मिलाकर देशी राजाओं की रियासतों में रहने वाली जनता की तुलना में अधिक गरीब अधिक परेशान और अधिक बुरी हालत में है। माय ही यहाँ मद्रास में, जहाँ की मिट्टी सामान्य तौर पर उबर नहीं है यह अंतर और भी साफ दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी देशी रियासत का शासन उतनी मालगुजारी की भाँति नहीं करता है जितनी कि हम करते हैं। (विशेष हेबर मेमोयर्स ऐंड कोरस्पोंडेंस', 1830, खंड II, पृष्ठ 413)

थापन और गैरट नामक इतिहासकारों ने लिखा

विद्रोह से पूर्व कर निर्धारण का इतिहास 'आर्थिक लगान' की वसूली के लिए किए गए असफल प्रयासों की शृंखला का इतिहास है। इस आर्थिक लगान को बहुधा 'कुल उत्पादन' माना जाता था। जिन खेतों से बंगाल को राजस्व की प्राप्ति होती थी उनकी नीलामी का उद्देश्य 'कुल उत्पादन' का अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करना था। इस प्रणाली की विफलता के कारण ही स्याई उदोबस्त लागू किया गया। मद्रास और बंबई में शुरू में जो राशि निर्धारित की गई थी वह आमतौर पर अनुमानित 'कुल उत्पादन' का 4/5 भाग थी। यह राशि बहुत अधिक थी। इसी तरह उत्तर पश्चिम सूबों के लिए कर निर्धारण का पहला प्रयास विफल हो गया और इस प्रयास को 1842 में तिलाजलि दे दी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि 19वीं सदी के शुरू के 25 वर्षों के दौरान जो जबरदस्त कर निर्धारण थोपा गया, उससे मद्रास और बंबई सूबा को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। यहाँ तक कि पंजाब में जहाँ ब्रिटिश निर्धारण ने सिखों की पुरानी माँगों में कमी कर दी, ऐसा लगता है कि नकद भुगतान और वसूली में कठोरता से किसानों के हित का सामान्य तौर पर ठेस पहुँची। (एच० फ्लेचर वेल्थ ऐंड वेलफेयर आफ दि पंजाब', पृष्ठ 122), (थापन ऐंड गैरट 'राइज ऐंड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' पृष्ठ 427)

1921 में डा० हेराट मान ने दक्कन के एक गाँव का दूसरी बार सर्वेक्षण किया। उन्होंने अंगरेजों के शासन से पहले और अंगरेजों के शासन के बाद के दिनों में ली जाने वाली मालगुजारी में जबरदस्त अंतर पाया

अंगरेजों की विजय के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। 1823 में 2 121 रुपये की मालगुजारी वसूल की गई और गाँव का खर्च 1817 के खर्च का आधा रह गया। (मान और कानिटवर 'लंड ऐंड लेबर इन ए दक्कन विलेज', खंड II, 1921 पृष्ठ 38)

1844 से 1874 तक 3 तीस वर्षों में भी राजस्व निर्धारण की राशि पूरे गाँव के लिए

1,161 रुपया या 9 आना 8 पाई प्रति एकड़ थी। 1874 से 1904 के तीस वर्षों के दौरान यह राशि 1,467 रुपया या 11 आना 4 पाई प्रति एकड़ थी। 1915 में नए सिरे से यह राशि निर्धारित की गई और इसे बढ़ाकर 1,581 रुपया या 12 आना 2 पाई प्रति एकड़ कर दिया गया।<sup>1</sup> 1917 में डाक्टर मान ने दकन के एक गांव के अपने पहले सर्वेक्षण में देखा कि कुल राजस्व की राशि समय-समय पर बढ़ाई गई है, यह राशि 1829-30 में 889 रुपये थी जो 1849-50 में बढ़ाकर 1,115 रुपये और 1914-15 में बढ़ाकर 1,660 रुपये कर दी गई।

वंगाल में मुगल शासकों के प्रतिनिधियों के शासन के अंतिम वर्ष अर्थात् 1764-65 में बड़ा मालगुजारी के रूप में 818,000 पौंड की राशि वसूल की गई। 1765-66 में अर्थात् ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वंगाल का वित्तीय प्रशासन अपने हाथ में लिए जाने के पहले वर्ष में यह राशि बढ़ाकर 1,470,000 पौंड कर दी गई। 1793 में जब बंगाल में स्थाई (इस्तमरारी) बंदोबस्त लागू किया गया तो यह राशि 3,091,000 पौंड हो चुकी थी।

कंपनी अपने पूरे राज्य से जो मालगुजारी वसूलती थी वह 1800-01 में 42 लाख पौंड थी (यह वृद्धि मुख्यतया इलाका बढ़ने से हुई थी लेकिन साथ ही मालगुजारी की बढ़ी हुई दर भी इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी) और 1857-58 तक जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले लिया तो यह राशि बढ़कर 1 करोड़ 53 लाख पौंड हो गई। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के दौरान मालगुजारी की राशि 1900-01 में 1 करोड़ 75 लाख पौंड और 1911-12 में 2 करोड़ पौंड हो गई। 1936-37 में यह राशि 2 करोड़ 39 लाख पौंड हो गई थी।

आधुनिक काल में भी राजस्व निर्धारण के आकड़ों को देखने से पता चलता है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में मुकाबले बाद में उपज का पहले से कम भाग किसान से लिया जाने लगा था (इस गणना का सामान्य आधार लगान पर कुल उत्पादन का आधा हिस्सा माना जाता था, मुखर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया', पृष्ठ 202)। लेकिन उस समय तक शोषण के दूसरे तरीकों में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई और उन्होंने पहले से ज्यादा उल्लेखनीय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उन्होंने सरकार द्वारा मालगुजारी प्रत्यक्ष वसूलने की भूमिका त्याग दी और इसके लिए जो रास्ते अपनाए गए वे थे जमींदारों प्रथा का विकास, लगान की बढ़ी हुई राशि, व्यापार के क्षेत्र में घुसपैठ, उन्मोक्त सामानों पर बड़े हुए अतिरिक्त कर तथा दिनोदिन बढ़ता बज। मुख्य रूप से मालगुजारी पर टिके साधारण नजराने ने भारतीय अर्थव्यवस्था में घुसे हुए अनेक परीपत्रीवियों सहित आधुनिक महाजनो पूँजी द्वारा किए जा रहे शोषण के स्वरूप को स्थापित दिया।

इसके अलावा भी राजस्व के निर्धारण का स्तर आज के युग में भी प्रत्येक मशाघन के बाद

निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रत्येक मशोधन के बाद किसानों पर जबरदस्त बोझ पड़ जाता है जिससे विद्रोह आंदोलन जन्म लेते हैं। 1928 में बारडोली में कांग्रेस के नेतृत्व में 87 हजार किसानों का आंदोलन हुआ जिसमें बड़ी हुई मालगुजारी का सफल विरोध किया और सरकार को यह मानन पर मजबूर किया कि यह मशोधन अयायपूर्ण है और मालगुजारी की निर्धारित राशि कम की जानी चाहिए।<sup>12</sup> आर० मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'लैंड प्रावाम्स आफ इंडिया' (पृष्ठ 206) में लिखा है कि 'मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत में खासतौर से मालगुजारी की राशि दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ी है।' उनका कहना है कि 1890-91 से 1918-19 के बीच भू-राजस्व 24 करोड़ रुपये से बढ़कर 33 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। उन्होंने आगे लिखा है

इन 30 वर्षों के दौरान खेती से होने वाली आय में जहाँ मोटे तौर पर 30, 60 और 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई वहीं संयुक्त प्रांत, मद्रास और बंबई के लिए भू-राजस्व की राशि में क्रमशः 57, 22.6 और 15.5 प्रतिशत की बढ़ावती हुई। इन सूचों में गैरआर्थिक जोतोंवाले किसानों का बहुमत है और भू-राजस्व में हुई इस वृद्धि से तथा नकद रूप में इसके विनिमय और फसल काटने के समय इसकी वसूली से इन किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत धक्का लगा। (पृष्ठ 345)

## 2 भूमि व्यवस्था का रूपांतरण

शुरू के वर्षों में मालगुजारी की दर में जो वास्तविक वृद्धि हुई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत पर अंगरेजों के शासन के बाद यहाँ की भूमि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। इस क्रांति की दिशा में पहला कदम मालगुजारी निर्धारण की प्रणाली और भूमि के स्वामित्व का पंजीकरण या जियम रिटर्न की आर्थिक और कानूनी धारणाओं में भारत की परंपरागत आर्थिक संस्थाओं और धारणाओं का हटाकर उनका स्थान ले लिया अथवा उन पर अपने को थोप दिया। ये दोनों धारणाएँ एक-दूसरे से काफी भिन्न थीं। पहले परंपरा थी कि सालभर की उपज का एक अंश 'राजा का हिस्सा' होता था जो संयुक्त मिल्कियत वाले किसानों या गांव का स्वयं प्रबंध करने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा नजराने या कर के रूप में शासक को दिया जाता था। 'राजा का हिस्सा' भी वार्षिक पैदावार के घटने बढ़ने के साथ घटता बढ़ता रहता था। अंगरेजों ने इस परंपरा का समाप्त कर, मालगुजारी के रूप में एक निश्चित रकम लेना शुरू किया। यह राशि जमीन के हिमाय से तय कर दी जाती थी और साल में फसल कम हुई हो या ज्यादा, यह निर्धारित राशि देनी ही पड़ती थी। जयकाश मामला में, यह मालगुजारी जंग अलग व्यक्तियों पर लगाई गई थी। ये लोग या तो खुद खेती करते थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। शुरू के दिनों में सरकारी प्रशासकों द्वारा और शुरू में सरकारी दस्तावेजों में यह राशि को जागतोर से 'गंगा' कहा जाता था। इसमें पना चलता है कि वस्तुतः किसान अब सीधे राज्य का या राज्य द्वारा नियुक्त जमींदार का

काश्तकार बन गया हाताकि इस सबके बावजूद उमरे कुछ मालिकाना तथा परंपरागत अधिपार भी होते थे। इस सारी प्रक्रिया को भारत में इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा (भारत में इस तरह की व्यवस्था की अतीत में कोई मिसाल नहीं है। कर देने वाले पुराने किसानों के आधार पर नए बग की रचना की जा रही है), व्यक्तिगत जोतों की प्रणाली, जमीन को बंधव रखन तथा बेचने की प्रणाली और वहा की पूजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरा कर दिया गया। भारत की अव्यवस्था के लिए यह नई व्यवस्था विलकुल अजनबी थी और इस व्यवस्था का प्रशासन एक ऐसी विदेशी नौकरशाही करती थी जो कानून बनाने (विधानांग) उसे लागू करने (कार्यांग) और न्याय करने (न्यायांग) का काम स्वयं करती थी। इस रूपांतरण से अंगरेज विजेताओं ने व्यवहारतः भूमि पर पूरा पूरा अधिकार कर लिया और किसानों को ऐसे काश्तकार का दर्जा दे दिया जिन्हें लगान का भुगतान न करने पर जमीन से बेदखल किया जा सके या उस जमीन को स्वयं द्वारा नामजद किए गए जमींदार के नाम लिखा जा सके। ये जमींदार भी सरकार की इच्छा से ही जमीन के मालिक थे और लगान न देने पर उन्हें भी जमीन से बेदखल किया जा सकता था। पुराने जमाने में अपना प्रबंध संचालन स्वयं करने वाले ग्रामीण समुदाय को उसके आर्थिक कार्यों और प्रशासनिक भूमिका से वंचित कर दिया गया। जो जमीन पहले गांव में साबे की जमीन समझी जाती थी उसे अलग अलग लोगों में बांट दिया गया।

इस प्रकार औपनिवेशिक प्रणाली की विशिष्ट प्रक्रिया वस्तुतः बहुत बेरहमी के साथ भारत में पूरी की गई—भारत की जनता को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया हाताकि इस प्रक्रिया को और भी जटिल कानूनी रूपों की भूलभुलैया द्वारा अशत ढका गया जो आज डेढ़ सौ वर्षों के बाद एक दूसरे में उलझी प्रणालियों, काश्तकारियों, परिपाटियों और अधिपारों का अमेध जगल बन गई है। किसान पहले जमीन के मालिक थे, अब उनकी मिल्कियत छीन ली गई और वे लगान देकर दूसरे की जमीन पर सेती करने वाले काश्तकार बन गए। इसके साथ ही बंधक रखन और कजदार होने की तकलीफें जिनका उनकी अधिकांश जोतों को सामना करना पड़ता है, वे भुगत रहे हैं। यह प्रक्रिया जब और आगे बढ़ी तो किसानों का एक बड़ता हुआ हिस्सा पिछले सौ वर्षों में और घासतीर से पिछने पचास वर्षों में भूमिहीन भजदूर बन गया अर्थात् सेतीहर सब-हारा का एक नया बग तैयार हो गया जो आज सेती पर निर्भर एक तिहाई आबादी से बटकर आधी आबादी तक पहुंच गया है।

दरअस्त मामक ने इसी रूपांतरण के प्रारम्भिक चरण का उल्लेख किया था जब उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया था कि प्राचीन ग्रामीण समुदायों का विघटन बुजुआ व्यापारिक पुसपंठ की अप्रत्यक्ष कायवाहियों और मशीन निमित्त सामानों का भारत में प्रवेश के कारण ही नहीं बल्कि इसलिए भी हुआ क्योंकि अंगरेज विजेताओं ने 'शासकों और जमींदारों के रूप में प्रत्यक्षतः राजनीतिक और आर्थिक सत्ता' का प्रयोग किया। यह

स्थिति चीन में इस तरह के समाज के विघटन की प्रक्रिया की तुलना में ज्यादा तीव्र है क्योंकि वहाँ 'अंगरेजों की ओर से किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता का समर्थन नहीं था'

भारत और चीन के साथ अंगरेजी के संबंधों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि वाणिज्य व्यापार के क्षयकारी प्रभाव के विरोध में पूर्व पूँजीवादी राष्ट्रीय उत्पादन प्रणाली की आंतरिक मजबूती और सधियोजन ने काफी अवरोध प्रस्तुत किए। सामान्य तौर पर यहाँ की उत्पादन प्रणाली का आधार छोटे पैमाने की कृषि और घरेलू उद्योगों की एकता से निर्मित है। भारत में इन चीजों के साथ साथ कम्यून जैसे कुछ संगठन हैं जिनका जमीन पर सार्विक का स्वामित्व है। भारत में अंगरेजों ने इन छोटे छोटे आर्थिक संगठनों को ध्वस्त करने के लिए शासकों और जमींदारों के रूप में अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक और आर्थिक दोनों ताकतों का एक साथ इस्तेमाल किया।

इसके आगे उन्होंने अपनी पादटिप्पणी में लिखा

यदि किसी देश के इतिहास को लें तो यह भारत में अंगरेजों के प्रबल संचालन का इतिहास है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में असफल और सही अर्थों में बेतुके (और व्यवहार में कुर्यात) प्रयोगों का एक सिलसिला है। अंगरेजों ने बंगाल में बड़े पैमाने पर इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा की भौंडी नकल की, दक्षिण पूर्व भारत में उन्होंने छोटे छोटे खेती का आवंटन की नकल की और उत्तर पश्चिम में उन्होंने भारतीय गांव के कम्यून (पंचायती समाज) को, जिसमें जमीन सबकी साझे की संपत्ति हुआ करती थी अपनी सामर्थ्य पर उन्होंने इस तरह बदल डालने का प्रयास किया कि वह खुद ही भजाक बनकर रह जाए। (कालमाक्स 'कपिटल', खंड III XX, पृष्ठ 392-93)

### 3 जमींदारी प्रथा की शुरुआत

पश्चिमी विजेताओं ने भारत में जमीन का बदोबस्त सबसे पहले इस तरह करने की कोशिश की कि इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा थोड़े परिष्कृत रूप में वहाँ लागू कर दी गई। 1793 में लॉर्ड कानवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा बाद में उत्तरी मद्रास के कुछ इलाकों के लिए जो बिख्यात इस्तमरारी बदावस्त (स्पाई भूमि बदोबस्त) लागू किया उसका असली स्वरूप यही था। इन प्रांतों में पहले से मौजूद जमींदार वस्तुतः जमीन के मालिक नहीं थे बल्कि कर या मालगुजारी वसूलने वाले सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें इन प्रांतों के पुराने शासकों ने कमीशन पर मालगुजारी वसूलन के लिए नियुक्त किया था (अधिकृत रूप से उन्हें ढाई प्रतिशत कमीशन मिलता था हालांकि व्यवहार में वे लूट खमोट कर कुछ अधिक पैसा पा जाते थे)। अंगरेज सरकार ने इन जमींदारों का हमेशा के लिए जमीन का मालिक बना दिया और स्पाई तौर पर एक ऐसी राशि तय

कर दी जो व सरकार को दे सके। यह राशि किसानों की कुल मौजूदा भुगतान राशि के 10/11 की दर से जोड़ी गई और 11वें हिस्से को जमींदार द्वारा भुगतान करने के लिए छोड़ दिया गया।

उस जमाने में समझौते की ये शर्तें जमींदारों और किसानों के लिए बहुत कष्टकर और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद थी। सरकार ने यह निर्धारित किया कि बंगाल के जमींदार प्रतिवर्ष 30 लाख पौंड किसानों से वसूल करके सरकारी कोष को दिया करेंगे। पुराने राजाओं के शासनकाल में सरकार के लिए जमींदार जा वसूली करते थे उससे यह राशि बहुत ज्यादा थी। बहुत से जमींदार लगान की वसूली में अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसानों पर कुछ रहम दिखाते थे और कड़ाई के साथ नहीं पेश आते थे। वे मातंगुजारी की इस निर्धारित राशि के बोझ का नहीं उठा सके और उनकी जमींदारी बड़ी बरहमी के साथ सरकार द्वारा नीलाम कर दी गई। पुराने जमींदारों में कुछ भले किसानों के प्रति उनका कुछ दायित्व है ऐसे जमींदारों की बरखादी की अनेक दटना बहानिया सुनने को मिलती है। चूंकि वे जमींदार अपने नाम निर्धारित राशि को सरकारी कोष में जमा करने में सफल नहीं हो सके इसलिए उन्हें बरहमी के साथ निवाल बाहर किया गया। धूल और धनलोभ व्यापारियों का एक ऐसा बग सामन आया जिसने इन जमींदारियों को खरीद लिया। ये किसानों से एक एक पाई वसूलने के लिए हर तरह का हथकड़ा अपनाते थे। 'भद्र मालिका के तण बग' का यही स्वरूप था और इन्तमरारी बदोबस्त का उद्देश्य भी ऐसे ही बग तैयार करना था। 1802 में मिदनापुर के कलक्टर द्वारा पक्ष की गई रिपोर्ट में कहा गया था

जमीन की चिन्नी और जन्ती की प्रणाली ने बंगाल के अधिवाश बड़े बड़े जमींदारों को बहुत बड़े वर्गों के अंदर एकदम गरीब और भिखारी बना दिया।

इसने बंगाल की भू संपत्ति में संभवतः इतना बड़ा परिवर्तन किया जितना किसी भी युग में या किसी भी देश में इतने कम समय में महज आंतरिक कानून के जरिए नहीं किया गया होगा।

लेकिन साथ ही इस प्रणाली ने एक और दिशा ली जिसके बारे में सरकार ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुद्रा का मूल्य गिर जाने और जमींदारों द्वारा किसानों से लगान में वसूल की जाने वाली राशि के बढ़ने के साथ साथ इस लूट में सरकार का हिस्सा, जो म्याई तोर पर 30 लाख पौंड तय हो चुका था बराबर कम होता गया जबकि जमींदारों का हिस्सा दिनोदिन बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि बंगाल में म्याई बदोबस्त के अंतगत वसूली जाने वाली कुछ मातंगुजारी अनुमानतः 1 करोड़ 20 लाख पौंड है जिसका एक चौथाई हिस्सा सरकार के पास और तीन चौथाई हिस्सा जमींदारों के पास जाता है।<sup>2</sup>

इस स्थिति व साफ हो जाने के बाद से स्थाई बदोबस्त पर आज हर तरफ से प्रहार किया जाने लगा है और इसकी भत्सना हो रही है। यह भत्सना जमींदारों को छोड़कर किसानों और समूची भारतीय जनता द्वारा ही नहीं की जा रही है, बल्कि साम्राज्यवादियों ने भी इसकी निंदा की है। इस बदोबस्त में संशोधन करने के लिए एक मजबूत आंदोलन छिड़ा हुआ है (स्वाई बदोबस्त पर साम्राज्यवादियों द्वारा किए जा रहे समकालीन प्रहार की तीव्रता का उदाहरण 'आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया' के पृष्ठ 561-70 पर की गई जबर दस्त भत्सना में देखा जा सकता है)। साम्राज्यवाद के आधुनिक समर्थक यह सफाई देने की कोशिश करते हैं कि यह समूचा बदोबस्त अनजान में और गलती से हो गया था और यह गलती इसलिए हुई क्योंकि इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि यहाँ के जमींदार लोग जमीन के मालिक नहीं थे। एस्टे ने अपनी मशहूर पुस्तक 'इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' (पृष्ठ 98) में ऐसा ही लिखा है

शुरू में भारत की जटिल प्रणाली कंपनी के कमचारियों के लिए एक बंद किताब की तरह थी। उन्होंने जमींदारों की खोज शुरू की। बाद में यह पता चला कि अधिकांश मामलों में ये जमींदार जमीन के मालिक नहीं थे। उस समय कंपनी के कमचारियों को 'जमींदार' शब्द का यही अर्थ समझ में आया जिस अर्थ में यह शब्द इंग्लैंड में जमीन के मालिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

लेकिन यह परीक्षा मूखताप्रण है। उन दिनों के दस्तावेजों को देखते ही यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि लांड कानवालिंस और तत्कालीन राजनताओं के दिमाग में यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी कि वे जमींदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं और उन्हें यह भी पता था कि ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है।

स्वाई जमींदारों बदोबस्त का उद्देश्य इंग्लैंड के ढंग पर जमींदारों का एक ऐसा नया वर्ग तैयार करना था जो अंगरेजी राज के लिए सामाजिक आधार का काम करे। अंगरेजों ने यह महसूस किया कि उनकी सत्ता काफी कम है और उन्हें एक विशाल आबादी पर अपना आधिपत्य कायम रखना है इसलिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा नया वर्ग पैदा किया जो लूट खसोट का एक हिस्सा पाकर अपने निहित स्वार्थ को अंगरेजी राज के बने रहने के साथ जोड़ ले। उस ज्ञापन में जिसमें लांड कानवालिंस ने अपनी नीति की वकालत की थी यह साफ साफ कहा था कि वह इस बात के प्रति पूरी तरह सजग है कि वह एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं और ऐसे अधिकारों की स्थापना कर रहे हैं जिनका जमींदारों व पुराने अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि 'मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जमींदारों के अधिकारों का दावा पुराने होने पर जनता के हित के लिए उन्हें या अन्य लोगों का संपत्ति का अधिकार देना जरूरी होगा।' सर रिचार्ड टेंपल ने अपनी पुस्तक 'मैन ऐंड इवेंट्स आफ माई टाइम इन इंडिया' (पृष्ठ 30) में लिखा है कि

लाड वानवालिस का स्थाई बदोबस्त 'एक ऐसा उपाय था जो बंगाल की जाता के बीच इंग्लैंड की जमींदारी से संबंधित सस्थाओं को स्वाभाविक बनाने में कारगर साबित हुआ।' लाड विलियम वैटिक ने, जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, अपने कार्यकाल के दौरान एक भाषण में स्थाई बदोबस्त के बारे में बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि यह नाति को रोकने के लिए बचाव का काम करेगा

यदि जबरदस्त जनविद्रोह या नाति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की जरूरत है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कई मामला में और कई महत्वपूर्ण बाता में असफल होने के बावजूद स्थाई बदोबस्त का कम से कम यह एक बहुत बड़ा फायदा है कि उसने धनी भूस्वामियों का एक विशाल संगठन खड़ा किया जा तहेदिल से यह चाहत है कि अगरजी राज बना रहें और जिनका जनता पर पूरी तरह दबदबा बायम है। (8 नवंबर 1829 को दिया गया लाड विलियम वैटिक के भाषण का अंश। यह ए० बी० कीथ की पुस्तक 'स्पीचेज ऐंड डाक्यूमेंट्स आन इंडियन पालिसी 1750-1921', खंड 1, पृष्ठ 215 पर पुन प्रकाशित किया गया है।)

भारत में जमींदारी प्रथा के साथ ब्रिटिश शासन का गठबंधन आज भी जारी है। यह मुख्य-तया अंगरेजों द्वारा अपना सामाजिक आधार तैयार करने के लिए किया गया था और यह आज ब्रिटिश शासनकाल को ऐसे विकट अंतर्विरोधों में उलझा रहा है जो जमींदारी प्रथा के पतन के साथ साथ ब्रिटिश राज के पतन की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत की जनता की आजादी की लड़ाई तेज होती जा रही है प्रत्येक सूवे में जमींदारों की लैंड होल्डस फंडेशन, लैंड ओनर एसोसिएशन जैसी विभिन्न संस्थाएँ ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की घोषणा करने में लगी हुई हैं। 1925 में बंगाल लैंड ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वाइसराय को जो अभिनंदनपत्र दिया वह इस सदर्भ में एक अच्छा उदाहरण है। इसमें कहा गया था

महामहिम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि जमींदार लोग सरकार का पूरा पूरा समर्थन करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ सरकार की सहायता करेंगे।

1938 में पहला आल इंडिया लैंड होल्डस कांफ्रेंस (जमींदारों का सम्मेलन) आयोजित की गई जो सभी जमींदारों का मिलाजुला संगठन स्थापित करने की तैयारी के लिए आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन की खास बात मेमनसिंह के महाराजा का अध्यक्षीय भाषण था जिसमें उन्होंने घोषित किया था कि 'यदि हमें एक वग के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ मजबूत करें।' 1935 के संविधान में इस बात का विशेष प्रावधान किया गया कि प्रांतीय विधानसभाओं और राष्ट्रीय विधानसभाओं में जमींदारों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।



लेकिन स्थाई बदोबस्त के सिलसिले में हुई भूला का दोहराया नहीं गया। इसके बाद जमींदारी से संबंधित जो बदोबस्त किए गए उन सबको 'अस्थायी' रखा गया अर्थात् समय समय पर जमीन का नए सिरे से बदोबस्त होता था ताकि सरकार की अपनी जरूरत के मुताबिक मालगुजारी बढ़ाते रहने का अवसर मिले।

स्थायी बदोबस्त के बाद जो वष शुरू होते हैं उनमें अनेक जिलों में विकल्प के रूप में एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की गई और इसकी शुरुआत मद्रास से की गई। इस बदोबस्त की खास बात यह थी कि सरकार को किसानों के साथ सीधे सीधे कोई बदोबस्त करना चाहिए जो स्थाई नहीं, अस्थायी हो अर्थात् जिनमें हमेशा कुछ वर्षों के अंतर पर सशोधन किया जा सके और इस प्रकार लूट के धन को किसी बिचौलिये में वाटन की बजाय पूरा का पूरा स्वयं हड़प लिया जाए और स्थाई बदोबस्त की बुराइयों से बचा जाए। इस प्रणाली का रयतवारी बदोबस्त नाम दिया गया और इसे सबसे पहले मद्रास में शुरू किया गया। रयतवारी बदोबस्त के साथ सर यामस मुनरो का नाम खासतौर से जुड़ा हुआ है क्योंकि 1807 की जमींदारी प्रणाली के विरोध में उन्होंने सबसे पहले मद्रास के गवर्नर की हसिमत से 1820 में मद्रास के अधिकतर हिस्सों के लिए सामान्य बदोबस्त के रूप में यह व्यवस्था जारी की थी। यह व्यवस्था बाद में अनेक सूबों में लागू की गई और आज यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के आधे से अधिक हिस्से में लागू है।

हालांकि रयतवारी बदोबस्त के बारे में यह दलील दी गई थी कि यह भूमि व्यवस्था भारतीय सस्याओं के काफी समान है परंतु वास्तविकता यह थी कि यह बदोबस्त जमींदारी प्रथा से किसी भी मामले में कम घातक नहीं था। इसका कारण यह था कि इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था और मालगुजारी का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा के आधार पर न करके जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। अमल में, मद्रास के बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इस नई प्रथा का काफी गिन तक डटकर विरोध किया और उसने चाहा कि हर गांव की आबादी के साथ सामूहिक बदोबस्त किया जाए जिसे मौजावारी बदोबस्त कहा जाता था। लेकिन बोर्ड का अपने इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। 1818 में रयतवारी व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने जा जापन दिया वह देखने योग्य है

हम देखते हैं कि विदेशी विजेताओं का एक छोटा सा गिरोह एक ऐसे विशाल भूभाग पर अधिकार जमा लेता है जिसमें रहने वाले लोग विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं और जिनकी भाषा, रीति रिवाज तथा आदतें विजेताओं की आन्तता से एकदम भिन्न हैं। इन लोगों का नए विजित क्षेत्रों के सही साधना का और मरा के बाशिन्दों की जमीन की वास्तविक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने विजय हासिल करने के साथ ही एक ऐसी छद्मालो योजना चलायी शुरू कर दी जैसी यूरोप के अत्यंत सभ्य देशों में भी भिन्न नहीं मिलती है।

इहान जमीन का लगान निर्धारित किया और यह लगान प्रत्येक प्रांत, जिले या गांव के लिए नहीं बल्कि उनके आधिपत्य वाले प्रदश में पडने वाले हर अलग अलग खेतों पर लगाया गया।

हम देखते हैं कि इस तथ्याकथित विकास के नाम पर अनजाने में ही उन्होंने पुराने बंधनों का समाप्त कर दिया और उन प्रथाओं को खत्म कर दिया जिन्होंने प्रत्येक हिंदू गांव की जनता को एक सूत्र में बांध रखा था। इसके साथ ही कृषि संबंधी कानून के जरिए उस जमीन पर से ग्रामीणा का अधिकार समाप्त कर दिया जिसपर सदियों से ग्रामीण समाज का सामूहिक स्वामित्व था। उन्होंने घोषणा की कि वे प्रत्येक खेत के लिए उनकी मांगें सीमित कर देंगे लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस तरह की सीमा निर्धारित करके और एक ऐसी अधिकतम सीमा की घोषणा करके जिसे प्राप्त करना संभव नहीं था तथा अपने से पूर्ववर्ती मुस्लिम सरकार की तरह जनता पर मनमाने ढंग का निर्धारण करके उन्होंने किसानों को जबरदस्ती खेत जोतने के लिए मजबूर किया। यदि किसानों ने खेत जोतने से इकार किया और गांव छोड़ने की कोशिश की तो वे उन्हें जबरन वापस घसीट लाए, उनकी मांगों को तब तक टालते रहे जब तक फसलें पककर तैयार नहीं हो गईं। इसके बाद जितना भी वे वसूल सकते थे, उतना उन्होंने वसूल लिया और बैलों तथा अनाज के दानों (बीज के लिए) के अलावा किसानों के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। यह कहना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने किसानों की उनके बैल और बीज के लिए थोड़ा अनाज देने का अनुग्रह किया। इस प्रकार उन्होंने इन किसानों को खेतीबारी के ऐसे काम में लगा दिया जिसमें वे सारी मेहनत इन विजेताओं के लिए करते रहे न कि अपने लिए। (मद्रास बांड आफ रेव्यू की 5 जनवरी 1918 की रिपोर्ट का विवरण)

वहां के अधिकारियों ने सामूहिक समझौते के पक्ष में तर्क दिए और इस तथ्य को मायता देने की बात कही कि 'ये जमीनें युगों युगों से ग्रामीण समुदाय के सामूहिक स्वामित्व के अधीन हैं,' लेकिन उनके तर्कों को अनसुना कर दिया गया। लंदन के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने रयतवारी प्रथा के पक्ष में फैसला लिया था उस समय के दस्तावेज की शब्दावली में कहे तो किसानों को निजी मिलियन का वरदान देने का फैसला किया और उनके निर्देशों में लैंस हीवर थामस मुनरो लंदन से वापस आए ताकि वे इस प्रथा को सामान्य समझौते के रूप में लागू करें।

इस प्रकार ब्रिटिश भारत में जमीन की काश्तकारी को परंपरागत रूप में तीन मुख्य वर्गों में रखा गया। तीनों वर्गों की व्यवस्था में लोगों को जमीन पर अधिकार की प्राप्ति ब्रिटिश सरकार से होती थी क्योंकि उसका दावा था कि देश की समूची जमीन का सर्वोच्च स्वामित्व उसके पास है।

एक तो, बंगाल, बिहार और उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्से में स्थाई जमींदारी बंदोबस्त था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कुल 19 प्रतिशत जमीन पड़ती थी। दूसरा, अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त जिसमें संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत का अधिकांश तथा बंगाल, बंबई और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे (यह या तो अलग अलग लोगों के साथ किया गया था या समूह के मालिकों के साथ था जैसा कि पंजाब में आजमाए गए तथाकथित साया बंदोबस्त के मामले में था)। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30 प्रतिशत क्षेत्र आता था। तीसरा, रयतवारी बंदोबस्त जिसके अंतर्गत 51 प्रतिशत क्षेत्र था। यह बंदोबस्त बंबई, मद्रास व अधिकांश इलाकों, बरार, सिंध, असम तथा अन्य हिस्सा में लागू था।

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रिटिश भारत के केवल 49 प्रतिशत इलाका में ही जमींदारी प्रथा थी। व्यवहार में, जमीन को बटाई पर उठाकर तथा सूदखोर महाजनो एवं अन्य लोगों द्वारा असली किसानों को उसकी जमीन से बेदखल करके और छुद उस हथिया कर रयतवारी इलाकों में भी जमींदारी प्रथा बड़े व्यापक रूप में और बढ़ी तबों से फैल गई थी। मुमकिन है कि इस प्रथा को शुरू करते समय असली किसानों के साथ सीधे बंदोबस्त करने का इरादा रहा हो पर अब तक इन सबधों में काफी परिवर्तन हो चुका है। अनुमान लगाया गया है कि 'मद्रास और बंबई में 30 प्रतिशत से अधिक जमीन ऐसी है जिसे वास्तविक खद नहीं जोतते हैं' (मुखर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया', पृष्ठ 329), 1901 से 1921 के बीच मद्रास में, गैरखेतिहर भूस्वामियों की संख्या, प्रति हजार 19 से बढ़कर 49 हो गई, जबकि खेतिहर भूस्वामियों की संख्या प्रति हजार 484 से घटकर 381 हो गई, खेतिहर वास्तविकों की संख्या प्रति हजार 151 से बढ़कर 225 हो गई। 1921 वगैरे की गई पंजाब की जनगणना रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि कृषीय भूमि से मिलने वाले लगान पर जीविका चलाने वालों की संख्या 1911 में 626 000 थी, जो 1921 में बढ़ कर 1,008,000 हो गई। 1891 से 1921 के बीच संयुक्त प्रांत में ऐसे लोगों की संख्या 46 प्रतिशत तक बढ़ गई जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषीय लगान था। मध्य प्रांत और बरार में इसी अवधि में लगान प्राप्त करने वालों की संख्या में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत भर में जमींदारी प्रथा का इस तरह फैलना और आधुनिक युग में इसका अधिकतम तबों से बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि किसानों को तबों से उनकी जमीन से बंधन किया जा रहा है और छोटे बड़े धनवान लोग उद्योग धंधों में पूँजी लगान का कोई कारण उपाय न देखकर गेती में पूँजी लगाने की कोशिश में लगे हैं। काफी बड़े बड़े इलाकों में शिवमी दर शिवमी एक श्रृंखला तैयार हो गई है ('कुछ इलाकों में तो छोटे तबों व जमींदारों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वहीं वहीं ता जमीन जोतने या न वास्तविक वास्तविक तथा जमींदारों के बीच पचास या दससे भी अधिक मध्यम वर्गीय उत्पन्न किए गए हैं। सामान रिपोर्ट ग्रह 1, पृष्ठ 340)

इसका परिणाम यह आता है कि सरकार न किसानों की रक्षा के लिए वास्तविकों को

संवर्धित जो वानून बनाए हैं, वे केवल छोटे दर्जे के जमींदारों तक ही पहुंचे हैं और वास्तविक किसानों की ज्यादातर सख्या यदि भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में नहीं तो ऐसी अधिकांश स्थिति में तो पहुंच ही गई है जिनका सरकार और बड़े मुफ्तखोरों के अतिरिक्त ऐसे तमाम चिन्तिलियों द्वारा पैरहमी के साथ शोषण किया जा रहा है जो काम कुछ नहीं करते और किसानों की मेहनत पर ऐश करते हैं। यह प्रक्रिया जिसने जमींदारी प्रथा की असंगतियों को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, इस बात की अभिव्यक्ति है कि भारत में खेती का सबूट दिनोदिन गंभीर होता जा रहा है।

#### 4 किसानों की दरिद्रता

इन स्थितियों के नतीजे के रूप में, भारत में कृषि संवर्धन की जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है वह बहुत उग्र और निरंतर बढ़ते हुए वर्गभेदों की तस्वीर है। 1931 की जनगणना के आंकड़े देखने से भारत की खेती में वर्ग विभाजन के निम्न स्वरूप का पता चलता है

|  |            |
|--|------------|
| लगान वसूलने वाले ऐसे भूस्वामी जो खेती नहीं करते            | 4,150,000  |
| खेती करने वाले भूस्वामी और दूसरों की जमीन जोतने वाले किसान | 65 495,000 |
| सेत मजदूर  | 33,523,000 |

इस वर्गीकरण का बहुत सीमित महत्व है क्योंकि 'खेती करने वाले भूस्वामी और दूसरों की जमीन जोतने वाले किसान' के नाम से जो सामान्य वर्गीकरण किया गया है उससे जोतों के क्षेत्र पर कोई रोशनी नहीं पड़ती और फलस्वरूप बड़े किसान मजदूर किसान और गरीब किसान के बीच भेद नहीं हो पाता। खासतौर से इस वर्गीकरण से यह नहीं मालूम हो पाता कि उन किसानों की कितनी बड़ी संख्या है जिनके पास गैरआर्थिक जोतें हैं, जिनकी हालत मजदूरों जैसी हो गई है और जिन्हें मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी रोटियाँ चलानी पड़ती हैं। व्यवहार में छोटे शिकमी किसान और मजदूर में बड़ा मामूली फर्क रह जाता है। इसलिए किसानों की हालत की सही तस्वीर की जानकारी के लिए हमें जनगणना के आंकड़ों के साथ-साथ सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर की गई क्षेत्रीय तथा स्थानीय जांच पड़ताल के नतीजों को भी देखना चाहिए।

वर्गीकरण की प्रणाली में परिवर्तनों के कारण जनगणना के पुराने आंकड़ों के साथ तुलना भी नहीं हो पाती। 1921 की जनगणना से पता चलता है कि खेती से जीविका चलाने वालों की संख्या 22 करोड़ 10 लाख थी जो 1931 में 10 करोड़ 30 लाख हो गई। इनमें परिवार के आश्रितों की संख्या भी शामिल है। इसलिए यह जल्द ही है कि पुरानी जनगणना में 'वास्तविक कामगारों' की संख्या अर्थात् 10 करोड़ को 1931 की संख्या अर्थात् 10 करोड़ 30 लाख के साथ ध्यान में रखें ताकि मोटे तौर पर ही सही तुलना तो की

जा सके। वर्गीकरण की प्रणाली में और परिवर्तन करके इस तुलना को भी निष्पन्न बना दिया गया है। बाद के वर्गीकरण में उन सब लोगों को अलग कर दिया गया जिनके खेती के पक्ष को अथ पशा का पूरक माना जाता था। इसके अलावा खेती के काम में मदद देने वाली महिलाओं को, जो किसानों की सहाय्य थी और जिनकी संख्या 70 लाख होती थी 'घरेलू काम' के वर्ग में डाल दिया गया। इस प्रकार खेती के काम में लग लाग की संख्या में गिरावट आने का भ्रामक चित्र पेश किया गया (जैसाकि पृष्ठ 188-89 में पहले ही बताया जा चुका है)। फिर भी, बाद का परिवर्तन जो निष्पन्न निकाले जाने हैं उनके सामान्य प्रभाव को मजबूत ही करता है। इस आधार पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन से निम्न नतीजे निकलते हैं

|                              | 1921<br>लाख में | 1931<br>लाख में |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| खेती न करने वाले जमींदार     | 37              | 41              |
| किसान (भूस्वामी या काश्तकार) | 746             | 655             |
| खेत मजदूर                    | 217             | 335             |

इन आंकड़ों के जरिए खासतौर से दूसरे वर्ग के संबंध में कोई विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों नहीं संभव है, इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ, निम्नदेह एक सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है, जिस में हम खेती न करने वाले जमींदारों की संख्या में हुई वृद्धि (1911 के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 28 लाख थी) तथा भूमिहीन खेत मजदूरों की संख्या में हुई जबरदस्त वृद्धि में देख सकते हैं। मद्रास के बारे में और विस्तृत आंकड़े लिए जा सकते हैं

**मद्रास में कृषि के क्षेत्र में वर्ग विभाजन  
(कृषीय आबादी का प्रति हजार)**

|                          | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| काम न करने वाले भूस्वामी | 19   | 23   | 49   | 34   |
| काम न करने वाले काश्तकार | 1    | 4    | 28   | 16   |
| काम करने वाले भूस्वामी   | 481  | 426  | 381  | 390  |
| काम करने वाले काश्तकार   | 151  | 207  | 225  | 120  |
| खेत मजदूर                | 345  | 340  | 317  | 429  |

(1901-21 के आंकड़े जनगणना रिपोर्टों पर आधारित हैं और पी० पी० पिल्ल की पुस्तक 'इकानामिक कंडीशंस इन इंडिया' के पृष्ठ 114 पर इनका उल्लेख है, 1931 के आंकड़े, मद्रास की 1931 की जनगणना रिपोर्ट से लिए गए हैं।)

1901 से 1931 के तीस वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर ढाई गुनी हो गई है जो काम नहीं करते और लगान वसूलते हैं (प्रति हजार 20 से बढ़कर 50), खेती करने वाले भूस्वामिया या वास्तवकारों की संख्या में एक चौथाई तक की कमी हुई है (प्रति हजार 625 से घटकर 510), भूमिहीन मजदूरों की संख्या जो पहले कुल आबादी का एक तिहाई थी, अब आबादी की लगभग आधी हो गई (प्रति हजार 345 से बढ़कर 429)।

बंगाल में हमें निम्न स्थिति का पता चलता है (जनगणना परिणामों पर आधारित)

|                          | 1921      | 1931      | परिवर्तन |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| खेती न करने वाले जमींदार |           |           |          |
| या लगान वसूलने वाले      | 390,662   | 633,834   | +61%     |
| खेती करने वाले भूस्वामी  |           |           |          |
| और वास्तवकार             | 9,274,924 | 6,079,717 | -50%     |
| मजदूर                    | 1,805,502 | 2,718,939 | +34%     |

यहां भी इन आंकड़ों से कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कुल कृषीय आबादी में 20 लाख तक की गिरावट का एक भ्रम पैदा होता है। लेकिन इससे खेती न करने वाले पर लगान वसूलने वाले लोगों और भूमिहीन खेत मजदूरों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि की वास्तविकता सिद्ध होती है।

ऐसे लोगों की संख्या में जो लगान तो वसूलते हैं पर खेती नहीं करते, आवश्यकतानुसार वृद्धि हुई है। दश के विभिन्न हिस्सों से मिले साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है। पिछले अध्याय में इसका उल्लेख हुआ चुका है। इससे पता चलता है कि किसानों को कितने बड़े पैमाने पर जमीन से बेदखल किया गया था।

भूमिहीन खेत मजदूरों की संख्या बढ़ने की बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। 1842 में सर थॉमस मुनरो ने जनगणना कमिश्नर की हैसियत से कहा कि भारत में एक भी भूमिहीन किसान नहीं है (यह निश्चित रूप से एक गलत बयान था लेकिन इससे संकेत मिलता है कि भूमिहीन किसानों की संख्या ऐसी नहीं मानी गई थी जिसका हिसाब रखने की जरूरत हो)। 1882 की जनगणना में अनुमान लगाया गया कि खेती के काम में 75 लाख 'भूमिहीन दिन मजदूर' लगे हैं। 1921 की जनगणना के समय खेत मजदूरों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख थी जो खेती में लगे लोगों की आबादी का पांचवा हिस्सा थी। 1931 की जनगणना से पता चला कि यह संख्या 3 करोड़ 30 लाख हो गई जो खेती में लगे लोगों की आबादी का एक तिहाई है। तब से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान वास्तविक अनुपात लगभग आधा है (जैसा कि 1938 में बंगाल विधानसभा में वास्तवकारी

कानून में संशोधन संबंधी वहसों में देखा गया, मद्रास के बारे में ऊपर उद्धृत आवेदों भी इसी बात का संकेत देते हैं)।

इन खेत मजदूरों की मजदूरी के सदर्भ में निम्नांकित तालिका काफी महत्वपूर्ण है

|   | 1842 | 1852 | 1862 | 1872 | 1911 | 1922  |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| खेत मजदूर की<br>दैनिक मजदूरी,<br>बिना भोजन के<br>(आना में)<br>चावल का मूल्य<br>(सेर प्रति<br>रुपया) | 1    | 1½   | 2    | 3    | 4    | 4 स 6 |
|   | 40   | 30   | 27   | 23   | 15   | 5     |

(आर० मुखर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया', पृष्ठ 222)

इस प्रकार, इस दौरान खेत मजदूरों की नकद मजदूरी में जहां चार से तब ७ गुनी वृद्धि हुई, वहीं चावल का मूल्य आठ गुना बढ़ गया। कहने का अर्थ यह है कि 'प्रगति' के इन 80 वर्षों के दौरान, वास्तविक मजदूरी में एक चौथाई से आधे तब की गिरावट आई है। 1934 के पंचवार्षिक मजदूरी सर्वेक्षण (क्विंगवैनियल वेज सर्वे) की रिपोर्ट के अनुसार 1934 में औसत दैनिक मजदूरी 3 आना या 3 पैसे थी। 326 गांवों में दैनिक मजदूरी 8 आना या डेढ़ पैस थी।

इस मापदंड के और नीचे उतरने पर, यदि और नीचे आना संभव होता हम कृषि श्रमता के लिए साहूकारों की गुलामी, मजदूरी से वंचित भूमिहीन मजदूरों के एस ज़खारतू शैल में पहुँच जाते जो भारत के सभी हिस्सों में मौजूद हैं, जिससे वे मृत्यु के मोर्चे पर होंगे।

भारत में आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से में वे स्थाई गेतिहर मजदूर हैं जिन्हें शायद ही कभी नकद मजदूरी मिलती हो जिससे स्थिति पूरा दाम या आर्थिक दाम की है। भारत के अनेक भागों में यह प्रथा प्रचलित है कि श्रमिकों को मानगुजार या साधारण त्रयक लगभग हमेशा ही अपने नौकरों का कर्म जान में पगान में संपन्न हो जाता है और इस प्रकार नौकर पर उनकी ज़ात मजदूरी हो जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।

यदि प्रजापति मजदूरों की श्रमिकों का भी लागू हो जाय तो वे श्रमिकों का गुलाम मजदूर

है। इनमें से अधिकांश के परिवार के सदस्य, पिछली कई पीढ़ियों से अपने मालिकों के परिवार की सेवा एकदम गुलाम की तरह कर रहे हैं।

मद्रास के दक्षिण पश्चिम में इज्जवा, चेन्ना, पुलेया और होलिया लोग हैं। ये सब वस्तुतः गुलाम हैं। पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में जमीन पर सबसे मजबूत पकड़ ब्राह्मणों की है और खेतिहर मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा पारिया लोग है जो जा प्रायः पांडियाल होते हैं। पांडियाल खेतिहर गुलामों की एक जाति है जो वज के कारण किसी जमींदार की पुश्तैनी गुलामी की जकड़ में फँस गए—यह वज कभी चुकता नहीं हो सका बल्कि एक पुश्त से दूसरे पुश्त पर चढ़ता चला गया और देनदार जब अपनी जमीन किसी के हाथ बेचता था या मरता था तो पांडियाल लोग का भी जमीन के साथ ही नए मालिक के पास स्थानांतरण हो जाता था।

खेतिहर मजदूरों का सबसे निकृष्ट रूप बिहार के कामिया लोगों में दिखाई देता है। ये लोग बहुधा मजदूर हैं जो लिए गए वज पर चढ़ रहे सूद के बदले में अपने मालिक के लिए नीच से नीच काम करने के लिए मजबूर हैं। (आर० मुखर्जी 'लैंड प्रॉब्लम्स आफ इंडिया', पृष्ठ 225-29)

अनेक इलाकों में ये खेतिहर गुलाम और साहूकारों के दास आदिवासी जातियों के लोग हैं। लेकिन जिसकी जमीन छिन गई है और जो वज के कारण साहूकारों की गुलामी में जकड़ा गया है या जो बटारी पर खेती करने के लिए मजबूर है उस किसान की हालत भी कानूनी खेतिहर गुलाम से कोई बहुत अच्छी नहीं है।

इनसे काफी हद तक मिलती जुलती स्थिति बागान मजदूरों की है। चाय, काफी और रबर के बड़े बड़े बागानों में 10 लाख से भी अधिक मजदूर काम करते हैं और इन बागानी में से 90 प्रतिशत से अधिक पर यूरोपीय कंपनियों का स्वामित्व है। इन मजदूरों की मेहनत से बागान मालिक काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इन बागानों में देश भर से मजदूर भरती किए गए हैं। मजदूर इन बागानों में अपने परिवार के साथ रहते हैं जिनपर बागान मालिकों का पूरा पूरा नियंत्रण है। मजदूरों के परिवार के सदस्यों को अत्यंत बुनियादी नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के श्रम का अत्यंत कम मूल्य पर शोषण किया जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में बठोर श्रम वाले अनुबंध विधिवत समाप्त कर दिए गए हैं और 1930 की ह्विटले रिपोर्ट के बाद कई कानून लागू किए गए हैं लेकिन अब भी यहाँ काम करने वाले मजदूर बड़े कारगर ढंग से अपने मालिकों की मरजी से बंधे हैं। इन मजदूरों का काफी लंबी अवधि के लिए यहाँ तक कि जीवन भर के लिए मालिकों की गुलामी करनी पड़ती है।



किसानों को कगाल बनाए जाने का पता भूमिहीन मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि से चलता है। इनकी संख्या कृषि में लगी कुल आबादी का एक तिहाई या कहीं कहीं तक है। दरअसल गैरआर्थिक जोतों के मालिक किसानों, शिकमी देने वाले काश्तकारों और आरक्षित काश्तकारों के बहुमत की स्थिति में भी खेतिहर मजदूरों से बहुत फर्क नहीं है और दोनों के बीच का भेद बहुत अस्पष्ट है। 1930 में मद्रास बैकिंग इक्वायरी रिपोर्ट में लिखा

खेता में काम करने वाले नौकरों और शिकमी किसानों के बीच कोई स्पष्ट रेखा खींचना हमारे लिए काफी कठिन है। शिकमी की प्रथा में ऐसा कम ही होता है कि किराए का भुगतान मुद्रा में किया जाता हो। यह प्रथा आमतौर से बटाई के आधार पर चलती है। जमींदार को फसल का 40 से 60 प्रतिशत और कहीं कहीं 80 प्रतिशत हिस्सा मिलता है तथा शेष अर्ध काश्तकार प्राप्त करता है। आमतौर से काश्तकार साल दर साल इन्हीं शर्तों पर कठोर परिश्रम करता रहता है, जमींदार से कर्ज लेता रहता है और जमींदार ही उसे बीज तथा हल बैल देता है। दूसरी तरफ, खेत पर काम करने वाला नौकर जमींदार से बीज और हल बैल प्राप्त करता है, छोटी मोटी जरूरतों के लिए समय समय पर उस जमींदार से अग्रिम धनराशि मिल जाती है और फसल तैयार होने पर उसे फसल का कुछ हिस्सा मिल जाता है। कुछ मामलों में इन नौकरों को अनाज की एक निश्चित मात्रा के साथ साथ थोड़ी नकद राशि भी मिल सकती है। मुमकिन है कि कोई काश्तकार अपने बीज और हल बैल से खेती करे लेकिन व्यवहार में इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, और ऐसी हात में जब जमींदार अनुपस्थित हो तो यह हमेशा स्पष्ट नहीं रहता है कि वास्तविक किसान शिकमी काश्तकार है या खेती पर काम करने वाला नौकर।

1927 में एन० एम० जोशी ने जखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के समक्ष अपना यह अनुमान प्रस्तुत किया था कि दश भर में खेतिहर मजदूरों की संख्या ढाई कराड़ है और 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आशिक तौर पर खेत मजदूर हैं। इस प्रकार बहुमूल्य भारतीय किसानों की स्थिति छोटे किसान की बजाय ग्रामीण सवहारा के जगह परीय है।

साम्राज्यवादियों के आत्मसंतोष का मन्त्रवृत्त दस्तावेज 1930 की राइमन कमिशन रिपोर्ट में दावप पूर्व की कृषि आयोग रिपोर्ट की दुहरात हुए एतान किया था

आज भी यही अर्थों में खेतिहर वही व्यक्ति है जिसने पाग एंड जोंग बंद है और जो अपने परिवार को मदद में तथा कभी कभी किराए पर मजदूर तलाश कर कुछ पैसे कमाता है। (राइमन रिपोर्ट, पृष्ठ 18)

मौजूदा सच्चाइयों के सदृश में यह तस्वीर कितनी काल्पनिक है, यह यहाँ प्रस्तुत तथ्यों से देखा जा सकता है। 1927 में कृषि आयोग के समक्ष दिए गए साक्ष्य में, बर्बई के एक जिले का विश्लेषण दिया गया था। इस जिले का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ था और इसे 'अत्यंत अनेक जिलों की तुलना में अत्यधिक खुशहाल' घोषित किया गया था। 1917 से 1922 के महज पांच वर्षों के जोतों के अनुपात में जो परिवर्तन आया वह इस प्रकार था (खंड II, साक्ष्य का प्रथम भाग, पृष्ठ 292)

### जोतों की सख्या

| जोत एकड़ में | 1917   | 1922   | कमी या वृद्धि<br>(प्रतिशत) |
|--------------|--------|--------|----------------------------|
| 5 से कम      | 6,272  | 6 446  | +2 6                       |
| 5 से 15      | 17,909 | 19,130 | +6 8                       |
| 15 से 25     | 11,908 | 12,018 | +0 9                       |
| 25 से 100    | 15,532 | 15,020 | -3 3                       |
| 100 से 500   | 1,234  | 1,117  | -9 5                       |
| 500 से अधिक  | 20     | 19     | -5 0                       |

गवाह ने, जो सरकारी अधिकारी था, टिप्पणी की

इन आंकड़ों को, जो केवल पांच वर्षों की अवधि के हैं देखने से मुझे ऐसा लगता है कि 15 एकड़ तक की जोता में खेती करने वाले किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन 15 एकड़ का यह क्षेत्र कुछ जमीनों को छोड़कर ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दो बैलें से खेती करने पर कोई फायदा हो 25-100 एकड़ की जोतों में भी गिरावट आई है जिसका अर्थ यह है कि अपेक्षाकृत समृद्ध खेतिहर वर्ग की जो थोड़ी पूँजी के साथ अपने को स्थापित करने में भाग्यशाली साबित हो, संख्या में कमी आई है।

इस प्रकार 1922 तक कुल खेतिहर जोतदारों का आधा हिस्सा (भूमिहीन मजदूरों की विशाल संख्या को छोड़कर) ऐसा था जिसके पास इस तरह की जोतें नहीं थी जिसमें वह दो बैलों से खेती करके लाभ कमा सके। इनकी संख्या तजी से बढ़ रही थी।

किसानों की वास्तविक स्थिति के किसी भी सर्वेक्षण से जोता के आकार के महत्वपूर्ण मसले के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस मद्दे में इस अध्याय के दूसरे भाग में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं। पुरानी जनगणना की शब्दावली में 'साधारण किसानों' (चाह के खेत के मालिक हो या काश्तकार) और भूमिहीन मजदूरों के बीच जो भेद रिया गया है उससे वास्तविक स्थिति का बहुत कम संकेत मिलता है। सही स्थिति का पता उस भेद भाव से चल सकता है जो भूमिहीन मजदूरों की विनाशकारी समस्या और गैरआधिक जोतों वाले

किसानों तथा आर्थिक जोतो वाले किसानों की भी छोटी सख्या के बीच किया जाता है। इस छोटी सख्या को भले ही 'अपेक्षाकृत समृद्ध खेतिहर' और लगान वसूलने वाले खेतिहर किसानों के वर्ग में क्यों न रखा जाए।

बंगाल मालगुजारी आयोग (बंगाल लैंड रेवेयू कमीशन, फ्लाउड कमीशन) के सामने जो गवाहिया पेश हुई थी उनमें आमतौर पर यह विचार प्रकट किया गया था कि एक औसत परिवार के लिए अपना पूरा खर्च चलाने के लिए कम से कम पाच एकड़ जमीन की जरूरत है। लेकिन आयोग को जाच के दौरान पता चला कि बंगाल के लगभग तीन चौथाई किसान परिवारों के पास पाच एकड़ से कम जमीन है और 57.2 प्रतिशत जोतों का क्षेत्र तीन एकड़ से भी कम है।

डा० हेराल्ड एच० मान द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण 'लाइफ एंड लेबर इन ए दकन विजेज' से इस स्थिति पर और अधिक रोशनी पड़ती है। डा० मान वयव म कृषि निदेशक थे और 1914-15 में उन्होंने दक्कन के एक गांव की स्थितियों की व्यापक तौर पर जाच पड़ताल की। यह जाच पड़ताल वास्तविक स्थितियों, खेती, फसल जमीन की जाच और परिवार के आय व्यय के बारे में की गई विशुद्ध वैज्ञानिक जाच थी जो दक्कन के एक 'गैर उपजाऊ' गांव को सामने रखकर की गई थी। यह पहला मौका था जब इस व्यापक और सर्वांगीण रूप से कोई जाच की गई हो। इसके परिणाम बेहद चौंका देने वाले थे (खुद लेखक के शब्दों में ये परिणाम अप्रत्याशित अत्यधिक निराशाजनक थे)। ये परिणाम इतने आश्चर्यजनक थे कि इनकी आलोचना की गई और कहा गया कि जिस गांव का सर्वेक्षण किया गया है उसके नतीजों को सर्वमाय नहीं माना जा सकता। इस दाव की वैज्ञानिकता की आलोचना मभव नहीं थी। इसके बाद डा० मान ने अपनी जाच का निष्कर्ष एक दूसरे गांव लिया और 1921 में उन्होंने इस गांव का जो अध्ययन प्रकाशित किया उसमें भी लगभग वही निष्कर्ष निकले और इस बार के निष्कर्ष पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे तब से देश के अनेक हिस्सों में इस तरह के सर्वेक्षण किए गए हैं जिनमें आमतौर पर इन निष्कर्षों की सत्यता की पुष्टि हुई है।

जिस पहले गांव का उन्होंने सर्वेक्षण किया था उसमें देखा गया कि 81 प्रतिशत जाँटें ऐसी थी जिनके द्वारा अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी उनमें मालिकों का खर्च नहीं बन सकता था। 156 जोतों के विभाजन में निम्न तस्वीर उभर कर सामने आई

|                 |    |
|-----------------|----|
| 30 एकड़ से अधिक | 2  |
| 20-30 एकड़      | 9  |
| 10-20 एकड़      | 16 |
| 5-10 एकड़       | 14 |
| 1-5 एकड़        | 71 |
| 1 एकड़ से कम    | 22 |

भागीय रकम के जीवन्मूर्त के अनुमान तथा परिणामी दरमामा 7 इस गांव में अधिकांशतः उपनग्न अच्छी मृदा जमीन की आधिक्य जात लगभग 10 से 15 एकड़ होगी, कीटिंग व इस अनुमान का अनुसरण करते हुए वह इस निष्पत्ति पर पहुंचे कि 'यदि प्रत्येक जात की एक ही घट में रखा जाए तो भी यह जाहिर है कि एक बड़े हिस्से (81 प्रतिशत) का क्षेत्र इसमें कम है।' रकम के जीवन्मूर्त का 'यूनितम आर्थिक' राशि के अनुमान के आधार पर यह निष्पत्ति निष्पत्ति गयी। इस जीवन्मूर्त के अंतर्गत शामिल छात्र और पहनन की चीजें घटिया से घटिया हैं और कृत्रिम प्रकाश जैंग आराम की भी गुंजाइश नहीं है। कुल 103 परिवारों की जाच से वह इस नतीजा पर पहुंचे कि 103 में से बस 8 परिवार ऐसे थे जो अपनी जमीन के आधार पर 'सुदृढ़ आर्थिक स्थिति' में थे, उन परिवारों की संख्या 28 थी जो अपनी जमीन हानि के बावजूद बाहर काम करने अपनी स्थिति ठीक बनाए रख सके थे, लेकिन अपनी जात से पूरी पूरी आय करने व माय माय बाहर भी काम करने के बावजूद 'डावाडोल' आर्थिक स्थितिवाले परिवारों की संख्या 67 थी अर्थात् ऐसे परिवारों की संख्या 65 प्रतिशत थी। फिर भी जहां तक इस पहलू काय की बात है, इसमें पड़ोस में हथियार बनाने का एक बड़ा कारखाना था जिसमें कुल आबादी के 30 प्रतिशत हिस्से को रोजगार मिल जाता था और इस गीमा तक स्थितियां कोई प्रातिनिधिक स्थितियां नहीं थी।

दूसरे गांव में, जिनमें आगपाम कोई कारखाना या औद्योगिक केंद्र नहीं था, 85 प्रतिशत परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी 'डावाडोल' पाई गई। इस गांव में जहां 'यूनितम आर्थिक' जात लगभग 20 एकड़ थी, 77 प्रतिशत जोते इस स्तर से नीचे थी। यहां के 147 परिवारों में, पहले वग में 10 परिवार आते थे जो अपनी जातों के आधार पर अपनी 'सुदृढ़ आर्थिक स्थिति' बनाए रख सकते थे, दूसरे वग में 12 व्यक्ति थे जो अपनी जमीन व माय माय बाहर काम करने अपनी स्थिति ठीक रख सकते थे और 125 व्यक्ति अथवा 85 प्रतिशत 'नाम' ऐसे थे जो अपनी जमीन से पूरी पूरी आय करने के अलावा बाहर भी काम करते थे और फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति 'डावाडोल' थी। इस अंतिम वग में कुल 732 'नामा' की आबादी में से 664 व्यक्ति आते थे, अर्थात् आबादी के 91 प्रतिशत लोग इस 'डावाडोल' आर्थिक स्थिति में थे।

सर्वाधिक 'यूनितम म्तर' से भी नीचे रहने वाली यह विशाल संख्या किस पर अपना जीवन निर्वाह कर पाती है? वे अपना काम नहीं चला सकते। नतीजा यह होता है कि वे अनिवाय रूप से बज में गड़बड़ में दिनादिन डूबते जाते हैं, अपनी जमीन से हाथ धो बैठते हैं और भूमिहीन शेत मजदूरों की फौज का एक हिस्सा बन जाते हैं। जाच से पता चला कि गांवों पर बज की जबरदस्त पकड़ है जो दिनोदिन सक्त होती जा रही है। सर्वेक्षण किए गए पहले गांव की कुल वार्षिक आय 8,338 रुपये थी जबकि बज की राशि 2,515 रुपये थी। इस समय गांवों पर बज का असह्य बोझ है जो गांव के कुल पूजोगत मूल्य का 12 प्रतिशत है और जमीन से जितनी आय होती है उसका 24.5 प्रतिशत ऋण के भुगतान

मे जाता है' (पृष्ठ 152)। दम्भ सर्वेक्षण में पता चला कि जमीन से कुल आय 15,807 रुपए की हुई जबकि कृषि भुगतान 1 रुपए में 6755 रुपए जमा किए गए। अर्थात् जमीन से हुई आय का 2 भाग सूदखोर महाजा के पास गया।

अपने सर्वेक्षण के अंत में डा० मान ने सामान्य निष्कर्ष के रूप में लिखा

एसा लगता है कि यदि हमारी खोजबीन और गणनाएँ गांव के जीवन की कोई सही तस्वीर पेश करती है तो औसतन भोजन मिलता है, बज के बोझ से वहन से ज्यादा दब जाते हैं और वतमान आबादी तथा सेती के वतमान साधनों से व वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में प्रत्यक्षत पहल से भी कम समर्थ है।

### 5 कर्ज का बोझ

जैसे जैसे किसान की कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर कर्ज का बोझ भी ज्यादा बढ़ता जाता है और उसकी कठिनाइयों में वृद्धि होती जाती है। इस तरह वह एक दुश्चक्र में फँस जाता है जिसकी अंतिम परिणति यह होती है कि वह अपनी जमीन से वेदखत कर दिया जाता है। इस प्रकार कर्ज के बोझ का बढ़ते जाना, और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं यानी गैरखेतिहरों के हाथों जमीन का गिरवी रखने, बेचने या हस्तांतरण करने का सिलसिला ही वह प्रमुख मापदंड है जिससे इस कृषि के क्षेत्र में व्याप्त सकट को नाप सकते हैं। साइमन कमिशन रिपोर्ट (खंड 1, पृष्ठ 16) के अनुसार 'किसानों की विशाल संख्या सूदखोर से मिले ऋण पर गुजारा करती है।'

ब्रिटिश राज के साथ-साथ किसानों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता गया है और यह प्रश्न एक बहुत आवश्यक और व्यापक बन गया है यह बात सभी लोग स्वीकार करते हैं। 1911 में सर एडवर्ड मैकलागन ने लिखा

बहुत पहले से यह माना जाता है कि कर्ज के बोझ से दबा होना भारत के लिए कोई नई स्थिति नहीं है। मुनरो, एल्फिंस्टन और अन्य लोगों ने अपनी पुस्तकों में स्पष्ट कर दिया है कि हमारे शासन की शुरुआत से पहले भी काफी लोग कर्ज से दबे थे। लेकिन यह भी माना गया है कि हमारे शासनकाल में और खासतौर से पिछले 50 वर्षों में लोगों के कर्जदार होने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समय-समय पर मिली रिपोर्टों से वार्षिक बिक्री तथा गिरवी रखने से संबंधित आंकड़ों को देखने से साफ पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों में कर्ज की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। (1911 में सर एडवर्ड मैकलागन का बयान जो सेट्रल बैंकिंग इन्वेंचरी कमेटी की 1931 की रिपोर्ट में पृष्ठ 55 पर उद्धृत है।)

1880 में ही अवाल अयाग न कहा था

जिन लोग के पास जमीन है उनका एक तिहाई हिस्सा गभीर और विकट रूप से बज में डूबा हुआ है और कम से कम इतनी ही सख्या में अन्य लोग बज में बोझ में लद हैं हालांकि उनमें इस बज से उबरने की क्षमता भी है।

तब से बज का यह बोझ तजी से बढ़ा है। 1928 में कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा

इसकी काफी अधिक संभावना है कि कुल ग्रामीण ऋण में वर्तमान शताब्दी में ही वृद्धि हुई है। क्या जनता की बढ़ती हुई परिस्पर्ति और ऋण का अनुपात एक ही स्तर पर बना हुआ है? और पुराने किसानों की तुलना में समृद्ध किसानों पर यह बोझ भारी है या हल्का? इन सवालों का, उपलब्ध प्रमाणों से कोई जवाब नहीं मिलता। (रिपोर्ट आफ दि ऐग्रीकल्चरल कमिशन, 1928, पृष्ठ 441)

बज में वृद्धि के इस तथ्य की पुष्टि 1931 में सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी से होती है

कृषीय ऋणग्रस्तता के परिमाण में वृद्धि हुई है या नहीं, इस प्रश्न पर आम धारणा यही है कि पिछली सदी के दौरान इसने परिमाण में वृद्धि हुई है। (रिपोर्ट आफ दि सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी, 1931, पृष्ठ 55)

उस समय (1931) ग्रामीण ऋण के बारे में समिति ने अनुमान लगाया था कि यह 900 करोड़ रुपये या 67 करोड़ 50 लाख पौंड था। लेकिन उसके बाद से, आर्थिक सबट पैदा होने और कृषीय दाम गिरने से ऋण की मात्रा में तजी से वृद्धि हुई और हाल के अनुमानों से पता चलता है कि यह राशि बढ़कर दुगुनी हो गई। (पृष्ठ 262 देखें)

ब्रिटिश शासन के दौरान और खासतौर से आधुनिक काल में ऋणग्रस्तता के इतनी तजी से बढ़ने के क्या कारण हैं? समस्या को गभीरता से न लेने वाले लेखकों तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थक लेखकों आज भी इस ऋणग्रस्तता को किसानों की 'अदूरदर्शिता' और 'फिजूलखर्ची' की नतीजा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि शादी व्याह, मृत्यु के बाद का क्रिया कम इस तरह के दकियानूस सामाजिक समारोहों या मुफ्तमेवाजी पर पैसा खर्च करने की आदत ही उनकी ऋणग्रस्तता की जड़ है। लेकिन ठोस ग्यार्यों से इस विश्लेषण की पुष्टि नहीं होती। पहले ही 1875 में दक्कन रायल्स कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था

शादी विवाह तथा अन्य समारोहों पर होने वाले खर्च को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। इन अवसरों पर किया जाना वाला खर्च उसके (रखत के) कुल खर्च में कुछ महत्वपूर्ण जरूर होता है लेकिन उसकी कजदारी का यही कारण है, ऐसा मुझे बहुत कम लगता है।

बंगाल की प्रांतीय रैफिंग जाच समिति का कहना है कि 'गावों की हालत की गहरी जाच पड़ताल' के फलस्वरूप, यह नतीजा निकलता है कि उपर्युक्त आरोप गलत है। उदाहरण के लिए बोगरा जिले के करीमपुर गांव में, जहाँ 52 परिवार ऋण के बोध से दबे थे, 1928-29 के एक वर्ष के दौरान, जिन कामों के लिए कज दिया गया वे इस प्रकार थे

|  | रुपयों में   |
|--|--------------|
| पुराने कर्जों की अदायगी                              | 389          |
| भवेशियों की खरीद सहित पूँजी के और म्याई विकास के लिए | 1,087        |
| जमीन की मालगुजारी और लगान के लिए                     | 573          |
| खेती के लिए  | 435          |
| सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए                    | 150          |
| मुकदमेवाजी के लिए                                    | 15           |
| अन्य कार्यों के लिए                                  | 66           |
| <b>कुल योग</b>                                       | <b>2,715</b> |

सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए या मुकदमेवाजी के लिए कज की जो राशि ली गई वह कुल राशि का केवल 16वां भाग थी। केवल दूसरे मद की राशि ऐसी है जिसे किसी अर्थ में उत्पादक ऋण कहा जा सकता है। यह कुल राशि का 2/5 है और इससे पता चलता है कि किसानों के पास पूँजी की कमी है। शेष राशि जो कुल राशि की आधी से अधिक है इसलिए ली गई ताकि जमीन की मालगुजारी, लगान, कर्जों की अदायगी और मौजूदा खेती की अत्यावश्यक जरूरतों का पूरा किया जा सके।

1933-34 में बंगाल में, दक्षिण पश्चिम बीरभूम में एक जाच की गई और उसमें भी इसी तरह के नतीजे सामने आए। यहाँ 6 गांवों के 426 परिवारों में से 234 परिवार अर्थात् 55 प्रतिशत परिवार कज से ग्रस्त पाए गए, इनपर 53,799 रुपये का कज था अर्थात् औसतन प्रति परिवार 230 रुपये (17 पौंड 5 शिलिंग) का कज था। कज लेने के निम्न कारण ज्ञात हुए

कज की मुख्य मद, जो मोटे तौर पर एक चौथाई है, लगान के भुगतान के लिए ली गई, पुराने कज और लगान की मिलीजुली राशि कुल राशि की एक तिहाई है, पूँजी व विवाह के लिए कुल राशि का एक चौथाई से भी कम अंश खर्च किया गया, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए निर्धारित राशि दूसरे उदाहरण की तुलना में 1/10 फिर भी

|                                   | रुपया  | प्रतिशत |
|-----------------------------------|--------|---------|
| लगान देने के लिए                  | 13,007 | 24 2    |
| पूजी के विकास के लिए              | 12,736 | 23 7    |
| सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए | 12,021 | 22 3    |
| पुराने बजों की अदायगी के लिए      | 4,503  | 8 4     |
| खेती में होने वाले खर्च के लिए    | 2,423  | 4 5     |
| मुकदमेबाजी के लिए                 | 708    | 1 3     |
| अन्य कार्यों के लिए               | 8,401  | 15 6    |

(एस० बोस ए सर्वे आफ हरल इनडेडनेस इन साउथ वेस्ट वीरभूम, बंगाल, इन 1933-34, इंडियन जनल आफ स्टैटिस्टिक्स, सितंबर 1937)

यह पाचवें हिस्से में थोड़ी ही अधिक रही। बज का मुख्य अंश आर्थिक जरूरतों के लिए लगाया गया, इसका महज एक मामूली हिस्सा उत्पादक ऋण है।

इस प्रकार भारतीय किसानों के ऋण लेने के आर्थिक कारण हैं और जमीन की मालगुजारी तथा लगान के बोझ के जरिए होने वाले उनके शोषण से इनका गहरा संबंध है। उपर्युक्त समिति के शब्दों में 'ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण सामान्य तौर पर कृषक वर्ग की गरीबी है।' बंबई के राजस्व विभाग के एक अधिकारी सर टी० हाप ने 1879 में दक्कन के खेतिहरों के लिए राहत बिल (दक्कन ऐग्रीकल्चरलिस्ट्स रिलीफ बिल) पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था 'किसानों पर पड़े हुए कर्ज के बोझ का एक कारण हमारी मालगुजारी व्यवस्था भी है।' दक्कन खेतिहर राहत ऐक्ट की वायप्रणाली के बारे में 1892 के आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 'यह निर्विवाद है कि दक्कन के किसानों के नए नए बजों से लड़ने में वर्तमान प्रणाली की सहायता एक मुख्य कारण है।' एक ऐसी प्रणाली जो फसल के अच्छी या बुरी होने अथवा आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना 30 वर्षों के लिए एक जैसी मालगुजारी की रकम निर्धारित कर रही हो, उससे भले ही मालगुजारी वसूलने वाले अधिकारी को या अपना बजट तैयार करने वाले सरकारी राजनेता को सहूलियत हो पर जहां तक देश की जनता का सवाल है, जिसे अपनी बेहद अनिश्चित आय में से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित रकम दे देनी है, वह फसल न होने वाले वर्षों में बर्बाद हो जाती है और उसे अनिवार्यतः सूखे और महाजन की गिरफ्त में आना पड़ता है। अत्यंत बुरी स्थितियों में मालगुजारी में माफी दे देने या अनिच्छापूर्वक वसूली को स्थगित कर देने से यह प्रक्रिया नहीं रुक सकती। उपर्युक्त आयोग ने पूना जिले के अनेक गांवों से इस बात के प्रमाण इकट्ठे किए कि जमीन की मालगुजारी का किस प्रकार भुगतान होता है। गांवों से मिले जवाबों का यहां सार प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।



शादी विवाह तथा अन्य समारोहों पर होने का महत्व दिया गया है इन अवसरों पर किये (रयत के) कुन खच में कुछ महत्वपूर्ण जहूँ का यही कारण है ऐसा मुझे बहुत कम लगता

बंगाल की प्रांतीय बैंकिंग जाच समिति का कहना पड़ताल' के फलस्वरूप, यह नतीजा निकलता है के लिए बोगरा जिले के फरीमपुर गांव में, जहाँ 1928-29 के एक वर्ष के दौरान, जिन कामों के

पुराने कर्जों की अदायगी  
मवेशियों की खरीद सहित पूँजी के और स्थानों  
जमीन की मालगुजारी और लगान के लिए  
खेती के लिए  
सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए  
मुकदमेबाजी के लिए  
अन्य कार्यों के लिए

#### कुल योग

सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए या मुकदमों वह कुल राशि का केवल 16वा भाग थी। केवल अर्थ में उत्पादक ऋण कहा जा सकता है। यह यह है कि किसानों के पास पूँजी की कमी है। शेष राशि इसलिए ली गई ताकि जमीन की मालगुजारी, लगे की अत्यावश्यक जरूरतों का पूरा किया जा सके। 1933-34 में बंगाल में, दक्षिण पश्चिम वीरभूमि तरह के नतीजे सामने आए। यहाँ 6 गावों के 426 प्रतिशत परिवार वज से ग्रस्त पाए गए, इनपर 53 प्रति परिवार 230 रुपये (17 पौंड 5 शिलिंग) का ज्ञात हुए

कज की मुख्य मद जो माट तोर पर एक चौथाई है पुराने कर्जों और लगान की मिलीजुली राशि कुल र के लिए कुल राशि का एक चौथाई से भी कम अन्य धार्मिक कार्यों के लिए निधारित राशि दूसरे उदाहर

इसका कारण यह है कि महाजन की मदद बिना न केवल मालगुजारी ही नहीं जमा हो सकती बल्कि बहुधा महाजन सूद पर रुपया देा क अलावा अनाज की खरीद और बिक्री भी करता है। फसल बढ़ने के समय किसानों की उपज पर उसका एक तरह से एकाधिकार रहता है, प्रायः वह किसानों को बुआई के समय किसानों की बीज और हल बल आदि देता है। किसानों के पास इतनी योग्यता ता होती नहीं कि वे महाजन का बहीखाता देख कर इस बात की जांच करे कि उन्होंने कितना पैसा दिया या लिया और कितना लिखा गया है इसलिए वे दिन ब दिन महाजन के चंगुल में फसते जाते हैं। इस प्रकार सूदखोर महाजन गांव का तानाशाह बन जाता है। जैसे जस किसानों की जमीन उसके हाथ में आती जाती है वैसे वैसे वह यह प्रक्रिया और आगे बढ़ाता जाता है। फिर किसान खेत मजदूर बन जाते हैं या उस महाजन के खेतों को बटाई पर जोतने लगते हैं और जो कुछ वे पैदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वे लगान और सूद के रूप में महाजन को देते जाते हैं। फिर सूदखोर महाजन गांव की अव्यवस्था में छोटे किसानों को अपना मजदूर बना लेता है। संभव है कि शुरू शुरू में किसानों का गुस्सा महाजन पर हो क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वही सारे अत्याचार और दुखद का कारण मालूम देता है। शांतिपूर्ण और सदियों से तकलीफ उठाने वाले भारतीय किसानों के द्वारा भी महाजनों की हत्याओं की जो छुटपुट खबरें आती हैं उनसे इस प्रक्रिया का पता चलता है लेकिन जल्दी ही उन किसानों का यह पता चल जाता है कि इन महाजनों के पीछे ब्रिटिश राज की समूची शक्ति काम कर रही है। सूद खोर महाजन, महाजनों पूजा द्वारा किए जा रहे शोषण के समूचे रचनात्मक का एक ऐसा पुर्जा है जो एकदम उस जगह काम करता है जहां उत्पादन होता है।

जैसे जैसे साहूवार की ज्यादातिया बढ़ती जाती है, सरकार सामान्य तौर पर शोषण के हिता को ध्यान में रखकर ही, कुछ ऐसे उपाय करने की कोशिशें कर रही है जिससे महाजन इस साने के अडे देने वाली मुर्गी यानी किसान वग को खत्म ही न कर दे। सूद की दर को कम करने के लिए और किसानों के हाथ में जमीन का निक्कलना रोकने के लिए सरकार ने विशेष कानूनों का अवार लगा दिया है। लेकिन उसे स्वयं यह मानना पड़ा है कि ये कानून असफल साबित हुए हैं (ग्रामीण श्रृंखलाग्रस्तता को रोकने के इरादे से बनाए गए कानूनों का जो अनुभव है उसके सदभ में कृषि आयोग की रिपोर्ट का 'कानून की विफलता' पृष्ठ 436-37 अध्याय देखें)। इसका प्रमाण यह है कि किसानों पर ऋण का बोझ दिनोदिन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ोतरी पर कोई अकुश नहीं है।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऋणदारी और इसकी वृद्धि की समूची समस्या की काफी विस्तार से एम० एल० डालिंग ने अपनी पुस्तक 'दि पंजाब पीजेंट इन प्रास्पेक्टिवी एंड डेट' में छानबीन की है। यह पुस्तक सबसे पहले 1925 में प्रकाशित हुई थी। अपनी बाद की पुस्तक 'रिस्टिकस लोकिटर' (1930) और 'विजडम एंड वेस्ट इन ए पंजाब विलेज' (1934) में भी उन्होंने इस समस्या का काफी विवेचन किया है। इसमें हालांकि अमतीर पर लेखक का दृष्टिकोण पक्षसमर्थक है फिर भी इससे तथ्यों की जानकारी तो हो ही जाती

|           |   |
|-----------|---|
| पिपत्तगाव | अच्छी फसल व दिना म भी थापा वज लेना पड़ता है।  |
| देउलगाव   | कुछ मामलो मे वज लेना पड़ता है।  |
| वनगाव     | मालगुजारी की वसूली का समय शायद ही कभी फसल पककर तयार होती हो इसलिए उसे वज लेना पड़ता है।   |
| नदगाव     | यदि बारिश ठीक से नहीं हुई तो खड़ी ज्वार की जमानत पर उस ऋण लेना पड़ता है।  |
| ढोड       | खड़ी फसलो की जमानत पर वजें लेते है।   |
| गिरिम     | पात पर उधार लिया जाता है या साख न होने की अवस्था म खड़ी फसले वच दी जाती ह।  |
| सोनवाडी   | यदि वचत से और मवशिया की वचने से जा पैसे मिलते है उनस मात गुजारी न दी जा पाए तो वज लेना पड़ता है।                                |
| बघाना     | खड़ी फसलो पर ऋण लेकर मालगुजारी की पहली किस्त अदा की जाती है। यदि फसल न हो तो जमीन को गिरवी रख दिया जाता है या वेच दिया जाता है। |
| भोरगोना   | इसी प्रकार।   |
| अबी       | इसी प्रकार।   |
| तारदोली   | खड़ी फसलो पर वज लेकर पहली किस्त चुकाई जाती है। यदि फसल नहीं हो तो मूद पर वज लिया जाता है।                                       |
| कुसीगाव   | इसी प्रकार।   |

1900 मे प्रकाशित 'दि ग्रेट फेमिन' मे वागान नैश ने आयोग की रिपोर्ट से ऊपर निखी तालिका का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा था 'अपनी बर्बई यात्रा के दौरान इस बात से पूरी तरह सहमत हो गया हू कि सरकारी अधिकारी, सूदखार महाजनो को मातगुजारी के भुगतान के लिए एक मुख्य सहारा मानते है।'

भारतीय समाज में सूदखोर महाजन और कज कोई नई चीज नहीं है। लेकिन पूँजीवादी शोषण और खासतौर से साम्राज्यवाद के युग मे सूदखोर महाजन की भूमिका न नए नए आयाम ग्रहण किए है और उसका महत्व बढा है। पहले के जमान मे कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जमानत पर ही महाजन से पैसा ले सकता था और इसलिए महाजन का कारोबार काफी अनिश्चित और जोखिम भरा होता था, व्यवहार म उसका लतदन गाव के फसले के अधीन होता था। पुराने कानून के अनुसार वज देन वाला व्यक्ति वज लेन वाले व्यक्ति की जमीन पर बच्चा नहीं कर सकता था। ब्रिटिश शासनकाल म य सारी स्थिति बदल गई। ब्रिटिश कानूनी प्रणाली ने महाजन को वजदार की तुर्की करन और जमीन का हस्तांतरण करन का अधिकार दकर सूदखार महाजनो को स्वण अवसर प्रदान किया और इनकी मदद के लिए पुलिस और कानून की पूरी ताकत उनके पीछे लगा दी। इस प्रकार सूदखोर महाजन पूँजीवादी शोषण की समूची व्यवस्था की धुरी बन गया।

इसका कारण यह है कि महाजन की मदद के बिना न केवल मालगुजारी ही नहीं जमा हो सकती बल्कि बहुतों महाजन सूद पर रूपाया देने का आवाज आवाज की खरीद और बिक्री भी करता है। फसल कटने के समय किसानों की उपज पर उसका एक तरह से एकाधिकार रहता है, प्रायः वह किसानों का बुआई के समय किसानों को बीज और हल बैल आदि देता है। किसानों के पास इतनी योग्यता तो होती नहीं कि वह महाजन का बहीखाता देखकर इस बात की जांच करे कि उन्होंने कितना पसा दिया या लिया और कितना लिखा गया है इसलिए वे दिन के दिन महाजन के चंगुल में फसत जाते हैं। इस प्रकार सूदखोर महाजन गांव का तानाशाह बन जाता है। जैसे जैसे किसानों की जमीन उसका हाथ में आती जाती है वैसे वैसे वह यह प्रक्रिया और आगे बढ़ाता जाता है। फिर किसान खेत मजदूर बन जाते हैं या उस महाजन के खेतों को बटाई पर जोतने लगते हैं और जो कुछ वे पैदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वे लगान और सूद के रूप में महाजन को देते जाते हैं। फिर सूदखोर महाजन गांव की अव्यवस्था में छोटे किसानों को अपना मजदूर बना लेता है। नभय है कि शुरू शुरू में किसानों का गुस्ता महाजन पर हो क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वही सारे अत्याचार और दुखद का कारण मालूम होता है। शांतिपूर्ण और सदियों से तकलीफ उठाने वाले भारतीय किसानों के द्वारा भी महाजनों की हत्याओं की जो छुटपुट खबरें आती हैं उनसे हम प्रक्रिया का पता चलता है लेकिन जल्दी ही उन किसानों को यह पता चल जाता है कि इन महाजनों के पीछे ब्रिटिश राज की समूची शक्ति काम कर रही है। सूदखोर महाजन, महाजनों पूजा द्वारा किए जा रहे शोषण के समूचे रचनात्मक का एक ऐसा पुर्जा है जो एकदम उस जगह काम करता है जहां उत्पादन होता है।

जैसे जैसे साह्यार की ज्यादातिया बढ़ती जाती है, सरकार सामान्यतौर पर शोषण के हितों को ध्यान में रखकर ही, कुछ ऐसे उपाय करने की कोशिशें कर रही है जिससे महाजन इस साने के अडे देने वाली मुर्गी यानी किसान बग का खत्म ही न करे। सूद की दर को कम करने के लिए और किसानों के हाथ में जमीन का निकलना रोकने के लिए सरकार ने विशेष कानूनों का अवार लगा दिया है। लेकिन उसे स्वयं यह मानना पडा है कि ये कानून असफल साबित हुए हैं (ग्रामीण श्रृणग्रस्तता को रोकने के इरादे में बनाए गए कानूनों का जो अनुभव है उसके सदर्भ में वृषि आयोग की रिपोर्ट का 'कानून की विफलता' पृष्ठ 436-37 अध्याय देखें)। इसका प्रमाण यह है कि किसानों पर वज का बोझ दिनादिन बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ती पर कोई अक्रुश नहीं है।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वजदारी और इसकी वृद्धि की समूची समस्या की काफी विस्तार से एम० एल० डालिंग ने अपनी पुस्तक 'दि पजाब पीजेंट इन प्रास्मरिटि ऐंड डेट' में छानबीन की है। यह पुस्तक सबसे पहले 1925 में प्रकाशित हुई थी। अपनी बाध की पुस्तकों 'रस्टिकस लाकिटर' (1930) और 'विजडम ऐंड बैस्ट इन ए पजाब विलेज' (1934) में भी उन्होंने इस समस्या का काफी विवेचन किया है। इसमें हालांकि अमतीर पर लेख का दृष्टिकोण पश्चिममय है फिर भी इससे तथ्या की जानकारी तो हा ही जाती

है। अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार अंगरेजों द्वारा भारत पर शासन स्थापित करने के बाद से पंजाब में लोगों पर कड़ि निरंतर लदता गया है

सिखों के शासनकाल में खेती का रेहन रखा जाना मुश्किल था लेकिन अंगरेजों के आने के बाद प्रत्येक गांव में लोगों के खेत रेहन रखे जाने लगे और 1878 तक इस सूचे का सात प्रतिशत रेहन हो चुका था

1880 तक किसान भूस्वामी और महाजन के बीच का असमान सघर्ष सूदखोर महाजन की विजय के साथ समाप्त हो गया इसके बाद 30 वर्षों तक महाजन अपनी पराकाष्ठा पर रहा और इस दौरान इन महाजनों की समृद्धि बढ़ती रही और इनकी सख्या में यहाँ तक वृद्धि हुई कि बैकरो और महाजनों की सख्या जहाँ (उनके आश्रितों सहित) 1868 में 53,263 थी, 1911 में बढ़कर 193,890 हो गई। (एम० एल० डालिंग 'दि पंजाब पीजेंट इन प्रास्पेक्टिवी ऐंड डेट', पृष्ठ 208)

डालिंग महोदय की धारणा थी कि 1911 तक सूदखोर महाजन अपनी 'पराकाष्ठा' पर पहुँच गया था और 1927 में कृषि आयोग के समक्ष अपने माध्य में उन्होंने बड़ी आशा के साथ यह सकेत किया था कि, 'पंजाब में दो जिला को छोड़कर हर कहीं सूदखोर महाजन श्रमण अपने व्यापार में कमी कर रहा है और इस कमी का मुख्य कारण है सहकारिता आंदोलन का विकास, किसान कर्जदारों की कानूनी संरक्षण दिया जाना और कृषक सूदखोरा का जन्म।' (रिपोर्ट, पृष्ठ 442)। लेकिन 1930 में अपनी दूसरी पुस्तक 'रेस्ट्रिक्स् लोकटर' के प्रकाशित होने तक एक आशावादी लहजे के बावजूद, उन्हें एक बार फिर आगाह करना पड़ा था

भूमि हस्तांतरण कानून (लैंड एलिमिनेशन ऐक्ट) के बावजूद इस बात का खतरा है कि किसानों को एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन से बेदखल किया जाए। पश्चिमी पंजाब में, जहाँ बड़े जमींदार इस कानून का फायदा उठाकर किसानों की कीमत पर अपनी जमीनें बढ़ाने में लगे हैं इस आशका के सबन पहले ही मिल चुके हैं। (पृष्ठ 326)

1935 तक पंजाब के भूराजस्व अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था

ग्रामीण इलाका में कृषक सूदखोर प्रत्यक्ष रूप से अपने को मजबूत बना रहे हैं। (पंजाब भूराजस्व प्रशासन की रिपोर्ट, 1935, पृष्ठ 6)

1919 में की गई जाँच में डालिंग महोदय इस नतीजे पर पहुँचे थे कि केवल 17 प्रतिशत

भूस्वामी ऋणमुक्त थे और औसत ऋण की राशि कम से कम 463 रुपये अर्थात् जमीन की मालगुजारी की रकम की 12 गुना थी।

बंगाल में फरीदपुर जिले के आकड़ा से कजदारी की वृद्धि का जबरदस्त उदाहरण मिलता है। 1906 में, जे० सी० जैक ने जो बाद में कतकता के हाईकोर्ट के जज हो गए थे, इस जिले की जाच की थी और इस जाच के परिणामस्वरूप बाद में 'इवानामिक लाइफ इन ए बंगाल डिस्ट्रिक्ट' (1916) में प्रकाशित हुए थे। इन परिणामों से पता चला था कि उस समय फरीदपुर में 55 प्रतिशत परिवार बज से मुक्त थे। 1933-34 में यानी 25 वर्षों बाद बंगाल के बोर्ड ऑफ इक्वायरी ने उसी जिले में फिर जाच की और यह नतीजा निवाला कि उस समय फरीदपुर के केवल 16.9 प्रतिशत परिवार बज से मुक्त थे।

## 6 तीन तरह का बोझ

इस प्रकार किसान खेतों पर यदि वह भूमिहीन सवहारा की श्रेणी में अब तक भी नहीं तो, आज तीन तरह के बोझ के नीचे दबा है। अतिरिक्त राशि का उपभोग करने वाले तीन तत्व हैं। वे उस अल्प राशि में से अपना हिस्सा वसूलन के लिए दबाव डालते हैं जो उस किसान ने अपनी थोड़ी सी जमीन और अत्यंत सीमित साधनों के द्वारा पैदा की है और जिसके लिए उपज की यह अल्प राशि खुद ही इतनी कम है कि वह अपनी और अपने परिवार की छाटी में छाटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता।

जमीन की मालगुजारी के लिए सरकार के दावे सब पर समान रूप से अपना असर डालते हैं और इसी प्रकार अप्रत्यक्ष करों का बोझ इन किसानों की छोटी से छोटी खरीद को भी प्रभावित करता है (साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर आसू बहाए थे कि 'भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता नमक, मिट्टी का तेल और शराब जैसी छोटी मोटी चीजों पर लगन वाले गृह आगकारी कर के दायर का सीमित कर दिया है। इन चीजों के लिए ग्रामीण इलाके बाहरी सप्लाय पर निर्भर करते हैं।' यहां तक कि नमक पर, जो गरीबों की सबसे बुनियादी जरूरत है लगाया गया कर 1939-40 में कम से कम 81 लाख पौंड अर्थात् मालगुजारी के 2/5वें हिस्से तक पहुंच गया।

सरकार की मालगुजारी के अतिरिक्त जमींदार द्वारा लगाए गए जमाने का बोझ किसानों के बहुमत पर पड़ता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत है और इसके अतिरिक्त रयतदारी प्रणाली के अंतर्गत पटन वाले क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई हिस्सा काश्तकारों के अधीन है।

सूद के लिए महाजन के दावे काफी बड़ी सख्या को प्रभावित करते हैं। डार्लिंग महोदय के आकड़ों और फरीदपुर के उदाहरण को देखें तो यह राशि 4/5 तक पहुंचती है।

इस प्रकार कुल पैदावार का कितना हिस्सा किसान से छीन लिया गया ? उसकी रोजी रोटी बनाने के लिए कितना हिस्सा उसके पास छाड़ दिया गया ? भारतीय कृषि व इस बुनियादी प्रश्न के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तक कि इस बात की भी कोई कोशिश नहीं की गई कि किसानों द्वारा जमीन की मालगुजारी के अलावा लगान के रूप में कितनी राशि दी जाती है इसका पता लगाया जाए। वज्र पर किसानों को कितना सूद देना पड़ता है, यह जानने की कोशिश नहीं की गई। ठीक ठीक सूचना के अभाव में केंद्रीय बैंकिंग इक्वायरी बमेटी के अल्पमत की रिपोर्ट में सामान्य अनुमान लगाने की कोशिश की गई है (पृष्ठ 36-37)। अपने अनुमान में समिति ने मालगुजारी की राशि को 35 करोड़ रुपये मानकर गणना शुरू की। इसने संभवतः बहुत घिसेपिटे तरीके से वज्र पर लगने वाली सूद की राशि को मालगुजारी को 35 करोड़ रुपये की राशि का तीन गुना अर्थात् 1 अरब रुपये निर्धारित किया। इसी प्रकार मालगुजारी के अलावा लगान की कुल राशि को मालगुजारी की राशि का डेढ़ गुना मान लिया। इस प्रकार किसानों पर जो कुल बोझ पड़ता है वह मालगुजारी की राशि का लगभग पाँच गुना है। फिर भी जैसा कि रिपोर्ट से संकेत मिलता है यह निश्चित रूप से कुल राशि को घटाकर देखा हुआ। विचौलियों द्वारा लिए गए लगान की राशि को मालगुजारी का डेढ़ गुना अधिक मानना उस बिल पर आधारित है जो मद्रास में जारी किया गया लेकिन किसानों की स्थितियों को सुधारने के लिए जिसे लागू नहीं किया गया। निश्चित तौर पर बंगाल में यह वास्तविक राशि (जहाँ लगान की कुल राशि मालगुजारी की राशि की कम से कम चार गुना और संभवतः छ गुना है) और संभवतः अत्यन्त स्थानों पर और भी ज्यादा होने की आशंका है। इस रिपोर्ट में यह धारणा व्यक्त की गई है कि जहाँ कहीं भी विचौलिये मौजूद हैं वहाँ किसानों पर पड़ने वाला बोझ एक और डेढ़ के अनुपात से वही ज्यादा है हालाँकि जमीन और उत्पादकता के लिहाज से स्थान स्थान पर और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थितियाँ होंगी ही। वज्र पर दी जाने वाली सूद की दर कुल 9 अरब रुपये पर एक अरब रुपये अर्थात् 11 प्रतिशत जोड़ी गई है जो निश्चित रूप से बहुत कम है। आमतौर से गाँव का सूदखार महाजन प्रतिमाह एक रुपये पर एक आना (कभी कभी डेढ़ आना) सूद लेता है अर्थात् सालाना सूद की दर 75 प्रतिशत हुई। इसलिए वास्तविक बोझ उस राशि से निश्चित रूप से काफी अधिक होगा जो इस अनुमान में शामिल की गई है। यदि नमक पर लगने वाले कर का बोझ जोड़ दिया जाए तो भी यह अनुमान 2 अरब रुपये सालाना अथवा 20 रुपये प्रति किसान के नजदीक पहुँच जाता है। इसका मुकाबले हमारे सामने केंद्रीय बैंकिंग इक्वायरी बमेटी की बहुमत रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत अनुमान ही है जिसमें कहा गया है कि 'ब्रिटिश भारत में एक किसान की औसत आमदनी लगभग 42 रुपये सालाना या 3 पौंड सालाना से ज्यादा नहीं है।' (पृष्ठ 39)

शोषण की एक सही श्रृंखला एन० एम० सुब्रह्मण्यम की वृत्ति स्टडी आफ ए साउथ इंडियन विलेज' (कापेस पोलिटिकल गेड इकोनॉमिक स्टडीज नम्बर 2 1936) में मिलती है। विचनापल्ली जिंने में नरुर नाम का एक गाँव है। इसी आबादी 620 है। इस गाँव की

अव्यवस्था का अध्ययन किया गया और यहाँ के निवासियों की सभी स्रोतों से हानि वाली कुल आय, कुल खर्च और उपभोग के लिए बची राशि का सही सही विवरण प्रस्तुत किया गया। शापण की सीमा की झलक यहाँ बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ जमीन पर जिनका स्वामित्व है वे गांव से बाहर रहते हैं और यहाँ के लोगों को जिनसे पज पर रपया मिला है व भी गांव से बाहर है। इस प्रकार लगान और सूद के रूप में काफी बड़ी राशि गांव से बाहर चली जाती है जो गांव की कुल आय में से निकली हुई रकम का बहुत साफ साफ चित्र प्रस्तुत करती है।

इस जाच से कौन से नतीजे सामने आए? बाजार भाव पर यदि सारे उत्पादन का भूल्याकन करे तो कृषि से हुई कुल आय 344,000 रुपये होती है। खेती के काम में खर्च राशि को यदि घटा दें (इसमें मजदूरी की राशि शामिल नहीं है और गांव के अंदर मजदूरी के रूप में जा पैसे दिए गए हैं उसे अलग करके देखें) तो कृषि से हुई कुल आय 212,000 रुपये निकलती है। अग्रणीय स्रोतों से हुई कुल आय (बाहर कमाई गई मजदूरी, सरकारी कमचारियों के वेतन और पशु, पूजा पर लगा सूद आदि छोड़कर) 24,000 रुपये होती है और इस प्रकार सभी स्रोतों से हुई कुल आय की राशि 2,36,000 है।

इसके मुकाबले गांव से बाहर जाने वाली निम्न राशियाँ पर ध्यान दिया गया जमीन की मालगुजारी, सिंचाई तथा अन्य खर्च 30,000 रुपये, गांव से बाहर रहने वाले भूस्वामियों को दिया गया लगान 70,000 रुपये, वज पर दिया गया सूद (8 प्रतिशत की कम से कम दर पर जोड़ी गई राशि) 40,000 रुपये, ताड़ी आदि की दुकानों के लिए सरकार को दिया जाने वाला किराया, पड़ का कर और पड़ के मातृक को दिया जाने वाला किराया 12,000 रुपये। इस प्रकार सरकारी राजस्व, टैक्स, किराया और सूद के रूप में दी जाने वाली कुल राशि 1,52,000 रुपये हुई। 4 हजार रुपये की राशि को छोटे माट कामों के लिए बाहर जाने वाली राशि मान लें तो गांव से कुल 1,56,000 रुपये का भुगतान हुआ है उसमें से गांव के लिए केवल 80,000 रुपये बच रहते हैं अर्थात् प्रति व्यक्ति मात्र 13 रुपये बचते हैं।

यह देखा जा सकता है कि इस गांव का प्रत्येक निवासी औसतन 38 रुपये या 2 पौंड 17 शिलिंग प्रति वर्ष कमाता है। कर वसूलने वाले अधिकारी, जमींदार और सूदखोर महाजन द्वारा अपना हिस्सा वसूल लेने के बाद उनके पास 13 रुपये या 19 शिलिंग से भी कम की राशि बचती है जिसमें उसे सालभर का अपना खर्च चलाना होता है। इस प्रकार कुल बर्गाई का दो तिहाई हिस्सा उससे ले लिया जाता है और एक तिहाई हिस्सा उसके पास बचा रहता है।

कुल आय में से दो तिहाई में भी अधिक भाग जमीन की मालगुजारी और उत्पादन कर सूद के भुगतान और गांव से बाहर रहने वाले भूस्वामियों के लगान के रूप में गांव से



बाहर चला जाता है।' इस विस्तृत अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकला या निष्कर्ष महज सारांश प्रस्तुत किया गया है। महान फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस के किसानों की स्थिति का वर्णन करते हुए कार्लोस ने लिखा था

विधवा मा अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए जेबें इकट्ठा कर रही है और अपने शानदार होटल के बरामदे में नजामत के साथ आराम करत हुए इन लगाए हुए भद्र पुरुष के पास एक ऐसी कोमियागोरी है जिससे वह विधवा मा से हर तीसरी जड़ छीन लेगा और अपनी इस हरकत को नाम देगा लगान और कानून।

आज के ब्रिटिश भारत में इससे भी ज्यादा रहस्यमय कीमियागिरी दखी गई है। यहाँ किसान के पास तीन म से केवल एक जड़ छोड़ी जाती है और शेष दा जड़ें भद्र पुराण के पास पहुँच जाती है।

पाद टिप्पणिया

- 1 जमीन की मालसुझारी निपटारण की सनकी तालिका जो 17वीं शती से शुरू होती है, राष्ट्रीय चरम है

एक भारतीय गाय मे मुराजस्य मे वृद्धि

| वर्ष                      | भूराजस्व<br>(रुपये) | निर्धारीत राशि<br>(एकड़) |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1698                      | 301                 | 1943                     |
| 1727                      | 620                 | 2000                     |
| 1730                      | 1173                | 2000                     |
| 1770                      | 1632                | 2003                     |
| 1785                      | 552                 | 1944                     |
| 1790                      | 66                  | 1944                     |
| 1803                      | 1009                | 1931                     |
| 1808                      | 818                 | 1944                     |
| 1817                      | 792                 | 1944                     |
| 1823 (ब्रिटिश राज के बाद) | 2121                | 2089                     |
| 1844-74                   | 1161                | 2089                     |
| 1874-1904                 | 1467                | 2271                     |
| 1915                      | 1581                | 2271                     |

2. बारोनी में बर के बारे में हुई हड़ताल का महत्ता पर अवगणना हो जा गिल्ली को भी बर वाली महत्त्वपूर्ण है। सागा का गिरावला व ओबिय पर प्रभावित नहीं माना गया है बर पर गिरावला का र्क है कि सभी तरह के बर निषारण का ओबिय को पुनो 44 के लिए बर एक अभूतपूर्व उपाहरण प्रस्तुत किया गया है।  
इस भूभाग (बारोनी) का निषारण पर निषारण का सामान्य प्रक्रिया का दोहन महत्त्व दिया गया था। मानवप्रतापी को र्क भाग के विरुद्ध राजाभिज्ञता न आचार उपाध का ओर इतर वतावरण बर्क सरकार का मूर्खता का माना तब तब महत्ता का प्रभाव र्कित विचार का र्क था। इस मामले में र्क नाराजी को देखते हुए का 44 उचित

- या लखित इसका वास्तविक महत्व यह है कि इसने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया : भविष्य में अब जो निर्धारण किए जाएंगे उनपर राजनीतिक बहस की काफी संभावना है। (डब्ल्यू० एच० मूरलध सी० एस० आई० सी० आई० ई० 'पीजेंटम सैटहाल्डस एंड दि स्टेट इन माडन इंडिया', 1932 पृष्ठ 166)
- 3 लगान की कुल राशि में अनुचित और ग़रकानूनी वसूली द्वारा वृद्धि की गई। 1937 में बंगाल विधान सभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान, जब कारनकारी कानून पर बहस चल रही थी तीन अलग अलग वक्ताओं ने बंगाल के लिए लगान की कुल राशि 29 करोड़ रुपये (17 करोड़ वैधानिक और 12 करोड़ अवधानिक) 30 करोड़ रुपये (20 करोड़ वैधानिक और 10 करोड़ अवधानिक), और 26 करोड़ रुपये (20 करोड़ वैधानिक और 6 करोड़ अवधानिक) निर्धारित किया था। ये वाक्ताव्य पूरायोग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें लगभग 2 करोड़ पौंड की अवधानिक वसूली भी शामिल है।
- 4 1939 में उत्तर बिहार में खिरहार नामक गांव की दशा की जांच की गई जिससे यह निष्कर्ष निकला कि 'सबसे बड़ी मद्दिया यहाँ भूमिहीन मजदूरों का है। ऐसे लोगों का 760 परिवार हैं जिनमें 5023 लोग रहते हैं और जो गांव की कुल आयदादी का 72 प्रतिशत है। (एस० सरकार इकानामिक कमीशन आफ ए विलेज इन नार्थ बिहार, इंडियन जनल आफ इकानामिक्स, जुलाई 1939)

## किसान क्रांति की ओर

अब जागो, वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो,  
अब चोर लुटरे अपने घर में घुस आये हैं, मत सोओ  
अब जागो, वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो,  
जब जब बैसाख महीने में अपनी फसलें काटें किमान  
तब जन्तु करें चौहरे जमीन और फसलें सूट जमींदार  
एक दिन को भी है चैन नहीं

मिट्टनत तरी जो फस लाती सब आग सामन सुट जाते,  
वे नहीं छोड़त एक दाना जो का पाय तरा आहार ।

अब जागो वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो

—गताकी शर्मा, मयुरा जिला के भूमिहीन किसान अध्‍यक्ष ग्रामीण कृषि गन्तव्य  
फरीदाबाद, मार्च 1938

जब विस्मय के आधार पर अब हमें पता चल रहा है कि कृषि विकास में  
किसानों के विचारों का क्या स्थिति है । कृषि विकास के कारणों और प्रभावों की स्थिति  
का विकास समूह ब्रिटिश शासन के नीचे आता है और आज के सारी स्थितियों का  
परिणाम पर प्रभाव डाले हैं ।

### 1. कृषि क्षेत्र में मतलब का विकास

किसानों की स्थिति है । कृषि क्षेत्र में विकास का मतलब है कि किसानों का जीवन  
जाता, शर्मा पर आता है । कृषि क्षेत्र में विकास का मतलब है कि किसानों का जीवन

इसके साथ ही भारत की औपनिवेशिक स्थिति के कारण 'अनुद्योगीकरण' की प्रक्रिया भी जारी रहती है। यह स्थिति अन्य बातों को प्रभावित करती है और उन्हें गंभीर भी बनाती है। दूसरी विशेषता है खेती के विकास में ठहराव और गिरावट आ जाना जमीन की उपज कम होना, श्रम की बरबादी होना कृषि योग्य जमीन को खेती के काम में लाने में निष्फल होना वर्तमान कृषि योग्य जमीन का विकास न करना। इसके फलस्वरूप कुछ समय बाद खेती की उपज में गिरावट आने लगती है और खेती के लिए कुल उपलब्ध जमीन में कमी आने लगती है। तीसरी विशेषता है जमीन के लिए किसानों की भूख का बढ़ते जाना, जोतों का आकार निरंतर कम हात जाना जोतों का छोटे छोटे टुकड़ा में बंटते जाना और ऐसी जोतों का अनुपात बढ़त जाना जिनके बल पर किसान के लिए अपनी आजीविका चलाना मुश्किल होता है। आज ज्यादातर जाते इसी तरह की हैं।

चौथी विशेषता है जमींदारी प्रथा का विस्तार होना, तरह तरह के शिकमी दर शिकमी का बढ़ते जाना, ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होना जो खेती नहीं करते लेकिन लगान वसूलते हैं। इस प्रकार अधिकांश किसानों की जमीनें इन भूस्वामियों के हाथों में जाने लगती हैं। पांचवी विशेषता यह है कि उन किसानों पर बज का दबाव बढ़ता जाता है जिनके पास अब भी कुछ जमीन है। अभी एकदम हाल के वर्षों में किसानों पर बहद बज चढ़ गया है। छठी विशेषता है बज के बदले में किसानों की जमीनों का सूदखोर महाजनों और मट्टेबाजों के हाथ में पहुँचते जाना। इनका परिणाम हम जमींदारी प्रथा के विकास में और भूमिहीन सबहारा की संख्या में वृद्धि में देखते हैं। सातवी विशेषता यह है कि उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप खेतिहर सबहारा की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जाती है। 1921 से 1931 के दस वर्षों के अंदर इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती जाती है। 1921 से 1931 के दस वर्षों के अंदर इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती जाती है। 1921 से 1931 के दस वर्षों के अंदर इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती जाती है।

यह सभी लोग मानते हैं कि 'अधन्यता' के कारण ही जमीन की बदचाली की यह प्रक्रिया पूरी हुई। 1892 में ही खेतिहरों के लिए बनाए गए राहत कानून की कामप्रणाली की जांच के लिए गठित दक्कन आयोग ने बड़ी बड़वाहट के साथ लिखा था कि 'भारत जैसे कृषिप्रधान देश में जमीन का हस्तांतरण कठोरता में लगान वसूलन वाले ऐसे बाहरी लोगों को दिया जा रहा है जो जमीन के विकास के लिए कुछ भी नहीं करते हैं।' आयोग ने भूस्वामियों के नए बज के बारे में अपना मत प्रकट किया कि 'जिन गैरजिम्मेदार जमींदारों की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए ये दुनिया में शायद सबसे कम उपयुक्त हैं। एक जमींदार के रूप में उनकी भूमि प्रवृत्ति एक सूदखार की है जो अपने शान्तिकार पर, जो उनका बजदार भी है बड़ी में बड़ी शर्तें प्राप्त है और प्रायः उनमें लगभग गुप्तानों जैसा व्यवहार करते हैं।' 1928 में एग्री आयोग ने स्वीकार किया कि 'किसानों को उगता है कि बज के बिना उनका काम नहीं चल सकता और इस धारणा में भूस्वामियों की अमीय व्यवहार मिल जाता है। शान्त किसान लोग अपनी जमीन का भूस्वामियों के हाथों में नेत्रों

## किसान क्रांति

अब जागो, वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो,  
अब चार लुटरे अपने घर में घुस आये हैं, मत सोओ  
अब जागो, वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो,  
जब जब बैसाच महीन में अपनी फसलें काटें किसान  
तब जल करे चौदरे जमीन और फसलें लूट जमीनार  
एक दिन को भी है चैन नहीं  
मिहनत तरी जो फल लाती सब आग सामने लूट जात,  
वे नहीं छोड़ते एक दाना जो बन पाये तैरा आहार ।  
अब जागो वीर किसानो जागो, कृष्ण का ही तुम पथ गहो  
—गतोकी शर्मा, मथुरा जिला व भूमिहीन किसान अध्मन ग्रामी  
परिपत्रिका, मार्च 1938

इस विश्लेषण के आधार पर अब मक्षोप में यह बताया जा सकता है कि  
मकट का विप्लववादों के साथ बढ़ रहा है । कृषि मकट के कारण और  
का विकास मजूरों के विद्रोह नाम के नीचे आता है और आज के मार्ग  
परगनाछा पर चल रही है ।

### 1. कृषि क्षेत्र में मकट का विप्लव

पत्नी के पता है राष्ट्रीय अध्यापकता में गंतों की स्थिति का उल्लेख  
जाता है । पर जागो का उद्देश्य में जागो उद्देश्य पत्नी और विद्रो

रुपये थी, 1931-32 में वस्तुतः 33 करोड़ रुपये निर्धारित की गईं जा 1933-34 में 30 करोड़ रुपये हो गईं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस राशि में 9 प्रतिशत से अधिक की कमी आई जो अधिवाश मामला में मालगुजारी का भुगतान करने की अक्षमता और जमीन छोड़ देने के कारण थी।

1934 की बंगाल जूट जाच समिति की रिपोर्ट में दिए गए अनुमान को 1920-21 और 1932-33 के बीच त्रयशक्ति में हुई कमी और वृद्धि के सदृश में देखें तो बंगाल के किसानों की असहाय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के अनुसार बंगाल में विनियोग्य फसलों के कुल मूल्य में 1920-21 से 1929-30 के बीच में काफी गिरावट आई। इन वस्तुओं का औसत वार्षिक मूल्य 1920-21 से 1929-30 के दशक में 72 करोड़ 40 लाख रुपये था जो 1932-33 में 32 करोड़ 70 लाख रुपये हो गया। इसके साथ ही मौद्रिक देयता में 27 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख रुपये हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि किसानों की 'स्वतंत्र क्रय शक्ति' 44 करोड़ 50 लाख रुपये से घटकर 4 करोड़ 40 लाख रुपये हो गई। इसी अवधि में कलकत्ता में मूल्यों का सूचकांक औसतन 223 से घटकर 129 हो गया अर्थात् 44 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि 'स्वतंत्र क्रयशक्ति' में 90 प्रतिशत की कमी आई।

यही वह दौर था जब भारतीयों की परंपरागत वचन अर्थात् सोने के आभूषणों को किसानों से छीन लिया गया ताकि दीवालियेपन का निवारण किया जाए और भारत से जाने वाले वार्षिक नजराने को बनाए रखा जाए। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि माल के निर्यात से यह घाटा पूरा नहीं हो रहा था। 1931 से 1937 के बीच कम से कम 24 करोड़ 10 लाख पौंड का सोना भारत से वसूल कर बाहर भेजा गया। लेकिन इस 'जन्त किए गए' सोने से केवल एक बग लाभ उठा सका और आने वाली मुसीबतों एक सीमित अवधि तक ही टाली जा सकी।

संयुक्त प्रांत में उन शासकगणों द्वारा जो लगान नहीं दे सके काफी बड़ी संख्या में भूमि का परित्याग किया गया। यह संख्या 1931 में 71,430 थी। 2,56,284 लोगों से जबरन मालगुजारी वसूलने का आदेश जारी किया गया। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार 1930 में बंगाल में सिंचाई संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 'कृषि के क्षेत्र से जमीन निकलती जा रही है।'

1934-35 तक स्थिति यह हो गई कि कृषि संबंधी आंकड़ों से यह पता चलने लगा कि कृषि क्षेत्र में 50 लाख एकड़ से भी ज्यादा की कमी आई। 1933-34 में कुल 23 करोड़ 32 लाख एकड़ जमीन में फसलें बोई गई थीं। 1934-35 में यह संख्या 22 करोड़ 69 लाख एकड़ हो गई अर्थात् 5,266,000 एकड़ की कमी आई। घाटानोवाली भूमि के क्षेत्र में 5,589,000 एकड़ की कमी आई।

से जाना भाग्यवादी ढंग से स्वीकार कर लेते हैं और उसकी सर्वोच्च स्थिति निर्विरोध बनी रहती है' (पृ० 435)। प्रसंगवश, जमीन हड़पने वाले इन सूदखोरों के प्रति सरकारी आयोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो रोष प्रकट किया है उसमें इन आयोगों ने यह कहीं नहीं कहा है कि सूदखोरों की शक्ति के पीछे सरकार द्वारा मिल रहा कानूनी समर्थन है। सरकार द्वारा मालगुजारी की जबरन वसूली के कारण ही किसानों ने सबसे पहले अपनी जमीन किसी सूदखोर महाजन को दी। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इस सामान्य धारणा को स्थापित दिया

कृणग्रस्तता का परिणाम अतंतोगत्वा यह होता है कि खेतिहर वग अपनी जमीन को हस्तांतरण गैरखेतिहर सूदखोर के नाम कर देता है जिससे एक ऐसे भूमिहीन सवहारा (भजद्वार) का वग पैदा होता है जिसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है। कहा जाता है कि इससे खेती की क्षमता में कमी आती है क्योंकि सूदखोर महाजन इस जमीन को ऐसी दर पर शिकमी बढ़ा देता है कि किसान को अच्छी फसल पैदा करने का कोई लाभ नहीं दिखाई देता। (केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 59)

1931 की जनगणना रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि, 'गैरखेतिहर भूस्वामियों के पास जमीन इकट्ठी होते जाने की आशंका है।' (सेसस आफ इंडिया, 1931, खंड I, भाग I पृष्ठ 288)

लेकिन खेती में गिरावट आने, किसानों की जमीन छिनने और उनमें वग विभेद के बढ़ने की यह समूची प्रक्रिया विश्वव्यापी अथसकट के कारण, कृषीय उत्पादन की क्षमता में गिरावट आने के कारण और तत्पश्चात् दूसरे महायुद्ध तथा देशव्यापी अकाल के कारण काफी आगे बढ़ गई है और बहुत तेजी से बढ़ रही है।

व्यापारिक आसूचना और माहि्यती (कॉमर्शियल इंटेलिजेंस ऐंड स्टैटिस्टिक्स) के महा निदेशक द्वारा प्रकाशित आकड़ों से इस गिरावट की सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। 1928-29 में मंदी का दौर शुरू होने में पहले के वष में, फसल कटने के समय में औसत दामों की आधार मानने पर खेती से लगभग 10 अरब 34 करोड़ रुपये मूल्य की पैदावार हुई थी। 1933-34 में केवल 4 अरब 73 करोड़ की पैदावार हुई। इससे पता चलता है कि पैदावार में 55 प्रतिशत की गिरावट आई।

अचानक आय आधी हो जाने से उन किसानों को, जो पहले से अगहाम स्थिति में थे, बिनगी दुदशा का सामना करना पड़ा होगा इसकी उल्लेख आमतौर से की जा सकता है। रुपये के रूप में उठ जा भुगतान करना पड़ता था उसपर रियायत उठ नहीं मिल पाती थी। इनके विपरीत जमीन की मालगुजारी, जो 1928-29 में 33 करोड़ 10 लाख

रुपये थी, 1931-32 में वस्तुतः 33 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो 1933-34 में 30 करोड़ रुपये हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस राशि में 9 प्रतिशत से अधिक की कमी आई जो अधिकांश मामला में मालगुजारी का भुगतान करने की क्षमता और जमीन छोड़ देने के कारण थी।

1934 की बंगाल जूट जाच समिति की रिपोर्ट में दिए गए अनुमान को 1920-21 और 1932-33 के बीच फ़ायदा में हुई कमी और वृद्धि के संदर्भ में देखें तो बंगाल के किसानों की असहाय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के अनुसार बंगाल में विनीयोज्य फसलों के कुल मूल्य में 1920-21 से 1929-30 के बीच में काफी गिरावट आई। इन वस्तुओं का औसत वार्षिक मूल्य 1920-21 से 1929-30 के दशक में 72 करोड़ 40 लाख रुपये था जो 1932-33 में 32 करोड़ 70 लाख रुपये हो गया। इसके साथ ही मौद्रिक देयता में 27 करोड़ 90 लाख से बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख रुपये हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि किसानों की 'स्वतंत्र फ़ायदा' 44 करोड़ 50 लाख रुपये से घटकर 4 करोड़ 40 लाख रुपये हो गई। इसी अवधि में कलकत्ता में मूल्यों का सूचकांक औसतन 223 से घटकर 129 हो गया अर्थात् 44 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि 'स्वतंत्र फ़ायदा' में 90 प्रतिशत की कमी आई।

यही वह दौर था जब भारतीयों की परंपरागत वस्त्र अर्थात् सोने के आभूषणों को किसानों से छीन लिया गया ताकि दीवालियपन का निवारण किया जाए और भारत से जाने वाले वार्षिक नजराने का बनाए रखा जाए। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि माल के निर्यात से यह घाटा पूरा नहीं हो रहा था। 1931 से 1937 के बीच कम से कम 24 करोड़ 10 लाख पाँड का सोना भारत से वसूल कर बाहर भेजा गया। लेकिन इस 'जब्त किए गए' सोने से केवल एक बग़ लाभ उठा सका और आने वाली मुसीबतों एक सीमित अवधि तक ही टाली जा सकी।

संयुक्त प्रांत में उन कारगरों द्वारा जो लगान नहीं दे सके काफी बड़ी संख्या में भूमि का परित्याग किया गया। यह संख्या 1931 में 71,430 थी। 2,56,284 लोगों से जबरन मालगुजारी वसूलने का आदेश जारी किया गया। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार 1930 में बंगाल में सिंचाई संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 'कृषि के क्षेत्र से जमीन निकलती जा रही है।'

1934-35 तक स्थिति यह हो गई कि कृषि संबंधी आंकड़ों से यह पता चलने लगा कि कृषि क्षेत्र में 50 लाख एकड़ से भी ज्यादा की कमी आई। 1933-34 में कुल 23 करोड़ 32 लाख एकड़ जमीन में फसल बोई गई थी। 1934-35 में यह संख्या 22 करोड़ 69 लाख एकड़ हो गई अर्थात् 5,266,000 एकड़ की कमी आई। यादगारवाली भूमि के क्षेत्र में 5,589,000 एकड़ की कमी आई।



1934 के बाद मूल्य वृद्धि की स्थिति में मामूली सा सुधार हुआ लेकिन इससे आर्थिक मंदी की स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई और विध्वंस के प्रभावों पर भी काबू नहीं पाया जा सका। एस्टे ने अपनी पुस्तक 'इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' में लिखा कि '1934 के बाद से जनता का कष्ट और भी गंभीर हुआ होगा'।

किसानों की आय आधी होने से कज का भार दुगुना हो गया। अनिवार्य रूप से इसका यह अर्थ हुआ कि कज में वृद्धि हुई जो अब अनुमानतः 1931 के स्तर से दुगुनी हो गई। 1921 में अनुमान लगाया गया कि कुल कृषीय ऋण 40 करोड़ पौंड था (देखें एम० एन० डालिंग की पुस्तक 'दि पंजाब पीजेंट इन प्रास्पेक्टिव ऑफ डेट')। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि यह राशि 9 अरब रुपये या 67 करोड़ 50 लाख पौंड थी। 1937 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कृषीय ऋण विभाग (ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट) ने अनुमान लगाया कि यह राशि 18 अरब रुपये या 1 अरब 35 करोड़ पौंड थी।

यह राशि 1921-31 के दस वर्षों में 40 करोड़ पौंड से बढ़कर 67 करोड़ 50 लाख पौंड और 1931-37 के 6 वर्षों में 67 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ पौंड हो गई। इस अवधि के दौरान किसानों पर ऋण की इस राशि की यदि आधार मानें तो इससे पता चलता है कि ऋण के क्षेत्र में सकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था।

भारतीय कृषीय अर्थव्यवस्था का दीवालियापन उस समय अपने नग्न रूप में सामने आ गया जब द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के शामिल होने के साथ ही बर्मा से चावल का आयात बंद कर दिया गया। इससे तत्काल ही अनाज की कमी की स्थिति पैदा हो गई और भारत में कीमते तेजी से बढ़ने लगी। इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता था। इसके लिए सबसे पहले काश्तकारों पर बोझ कम करके और उन्हें सिंचाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देकर अनाज का उत्पादन बढ़ाने का जबरदस्त अभियान छेड़ना चाहिए था। दूसरे, कीमता पर काबू पाया जा सकता था और सभी खाद्यान्नों की राशनिंग की जा सकती थी। तीसरे, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा की जा रही जमाखोरी और बालाबाजारी को कारगर ढंग से रोका जा सकता था लेकिन ये सारे कदम उठाने के बजाय साम्राज्यवादी सरकार ने जो आम जनता का शोषण करके युद्ध को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कृत संकल्प थी, मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि पर भरोसा किया तथा स्वयं सेना के लिए अनाज की सप्लाई के लिए जमाखोरों का सहारा लिया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि जनता के बीच खाद्यान्नों का समान वितरण करने की व्यवस्था की जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि हालांकि 1943 में महज 14 लाख टन अनाज की ही कमी थी (जो भारत की कुल जरूरत का बहुत मामूली अंश है) लेकिन देश में अनेक हिस्सों में जबरदस्त अकाल पड़ा जिससे भारी सख्या में मौतें हुईं।

प्रोफेसर के० पी० चट्टोपाध्याय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल बंगाल में अकाल में मरने वालों की संख्या 35 लाख थी। यहाँ तक कि अकाल की जाच के लिए गठित सरकारी आयोग ने भी मरने वालों की संख्या 15 लाख बताई थी।

अकाल के बाद भयंकर महामारी फैली और सितंबर 1944 तक विभिन्न बीमारियों से 12 लाख व्यक्तियों की बंगाल में मृत्यु हुई (भवानी सेन 'हरल बंगाल इन रूइंस' पृष्ठ 18)।

यह अकाल 'मानवनिर्मित' अकाल था। बंगाल में दरअसल, केवल 6 हफ्ते के राशन की कमी थी और बाहर से अनाज मंगाकर तथा छायाजनों का लोभों के बीच समान वितरण करके इस कमी को आसानी से दूर किया जा सकता था। लेकिन बंगाल की एक तिहाई से भी अधिक जनता अकाल की चपेट में आ गई। अनाज का समूचा भंडार जमींदारों और व्यापारियों द्वारा दबा लिया गया और भ्रष्ट नौकरशाही ने इन भंडारों को जमाखोरों के हाथों से बाहर निकालने की कोशिश के बजाय इनकी कीमतें बढ़ाने में मदद पहुँचाई और करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। जनवरी 1942 में बलकत्ता में चावल का मूल्य 6 रुपये प्रति मन था जो नवंबर 1942 में 11 रुपये, फरवरी अप्रैल 1943 में 24 रुपये, मई में 30 रुपये, जुलाई में 35 रुपये, अगस्त में 38 रुपये, और अक्टूबर 1943 में 40 रुपये तक पहुँच गया। मुफ़त्सिल जिले में चावल की कीमत 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति मन तक हो गई। अकाल के दौरान चावल हमेशा उपलब्ध था और असीमित मात्रा में उपलब्ध था लेकिन उसका मूल्य 100 रुपये प्रति मन था। इसके फल-स्वरूप बड़े व्यापारियों ने इस अकाल के दौरान काला बाजार के जरिये 1 अरब 50 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाया (वही पृष्ठ 1)।

अकाल की मार सबसे पहले बंगाल के 75 प्रतिशत किसान परिवारों पर पड़ी जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन थी और जो अनाज की अपनी जरूरतों इस जमीन से पूरी नहीं कर सकते थे। मई 1943 तक इन 75 प्रतिशत परिवारों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और सारा अनाज 'जातदारों और व्यापारियों तथा सरकारी एजेंटों और कारखाना मालिकों के पास जमा हो गया' (वही, पृष्ठ 4)। अकाल ने सबसे पहले सबसे गरीब तबके को अपना निशाना बनाया और फिर धीरे धीरे इसका असर मझोले किसानों पर भी पड़ने लगा। जो किसान जितना ही गरीब था उसे उतनी ही जल्दी अपना सारा मामान बेच देना पड़ा, वह असहाय हो गया और मौत की गोद में जा पहुँचा। जैसा कि प्रोफेसर पी० सी० महलनबीस तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अम लोभों ने एक सर्वेक्षण के बाद बताया

वस्तुतः अकाल के पहने प्रत्येक परिवार के हिसाब से धान के खेतों का सब डिवीजना में जो वर्गीकरण किया गया था वह मोटे तौर पर अकाल की स्थितियों के प्रभाव की मात्रा के समानांतर पाया गया। ('ए सैपुल सर्वे आफ आफ्टर

इफैक्ट्स आफ दि बगाल फेमिन आफ 1943', पृष्ठ 3, साध्य, खंड 7, भाग 4, 1946)

इस अकाल के फलस्वरूप किसान जनता की गरीबी और बढ़ी और जमीन का अधिक से अधिक हिस्सा धनी जमींदारों और सूदखोर महाजनों के पास इकट्ठा होता गया।

इस सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 1943 से अप्रैल 1944 के एक वर्ष के अकाल के दौरान लगभग 15 लाख 90 हजार परिवारों ने (अकाल से पहले जिनके पास धान के खेत थे उनकी एक चौथाई सख्या) या तो अपने धान के खेत बिल्कुल ही बेच दिए या रेहन रख दिए। इनमें से 2 लाख 60 हजार परिवारों को पूरी तरह अपनी जोतों से हाथ धोना पड़ा और इस प्रकार वे भूमिहीन मजदूर की स्थिति में पहुँच गए। 6 लाख 60 हजार परिवारों ने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेचा और 6 लाख 70 हजार परिवारों ने अपने धान के खेत रेहन रखे। इनमें से अधिक से अधिक एक प्रतिशत किसानों को अपनी जमीन वापस मिल सकी। अन्य किसानों को कानूनी उपायों से भी जमीन वापस नहीं मिली ('रूरल बगाल इन रूइंस', पृष्ठ 6)। अकाल के दौरान 7 लाख 10 हजार एकड़ धान के खेत बेचे गए थे जिनमें से गांव द्वारा केवल 20 हजार एकड़ वापस धरीदे गए। मोटे तौर पर वहाँ तो 4 लाख 20 हजार एकड़ खेत पर बाहरी लोगों का बज्जा हो गया जो संभवतः शहर में रहने वाले गैरखेतिहार व्यक्ति थे ('संपुल सर्वे', पृष्ठ 14)।

बिक्री की प्रक्रिया इस बार जमीन तक ही सीमित न रही। जनता का संपूर्ण जीवन छिन भिन्न हो गया। माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को इस आशा में सड़क के किनारे फेंकने की मजबूर हो गए कि कोई उन्हें उठाकर ले जाएगा और उन्हें खाना खिला देगा। पतियों ने मजबूरी में अपनी पत्नियाँ को छोड़ दिया और सारे परिवार को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। महिलाएँ अपना शरीर बेचने पर मजबूर हुईं और वे चकलाघरा में पहुँच गईं। अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता में आए 1 लाख 25 हजार निराश्रितों में से लगभग 30 हजार जवान औरतों ने वेश्यावृत्ति अपना ली ताकि वे किसी तरह सास लेती रह सकें।

हजारों लाखों की सख्या में लोग अनाथ हो गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार मई 1944 में बंगाल में कुल निराश्रितों की सख्या 10 लाख 80 हजार थी जिनमें से 4 लाख 80 हजार व्यक्ति महज युद्ध और अकाल के कारण इस हालत में पहुँचे थे वहीं (पृष्ठ 5)। उन लोगों की सख्या 60 लाख थी जो पूरी तरह निराश्रय तो नहीं हुए थे लेकिन अत्यधिक निधन थे ('रूरल बगाल इन रूइंस', पृष्ठ 16)।

गांव की समूची अव्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। अकाल के दौरान जिन लोगों पर सबसे जबरदस्त भार पड़ा वे गांव के दस्तकार और कारीगर थे जिनमें मछुआरे, मोची, सुतार,

कुम्हार और जुलाहे आदि थे। वस्तुतः सबसे पहले इन्हीं पर अकाल की मार पड़ी और ये पूरी तरह कगल हो गए। यहाँ तक कि जो लोग पहली चोट को बर्दाश्त कर गए वे भी कगाली की हालत की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव के दस्तकारों के लिए पुनर्वसन का काम बहुत कठिन हो गया है। उनकी जरूरत की सभी चीजें मसलन घागा, लोहा, जाल चमड़ा इत्यादि कालाबाजार में पहुँच गया है। किसानों के पास खेत जोतने के लिए बैल नहीं है। बगान के गावों में रहने वाले 3 लाख अर्थात् 85 प्रतिशत परिवारों के पास अब कोई भवेशी नहीं है जबकि अकाल पड़ने से पहले इनके पास काफी सख्या में भवेशी थे। इस एक वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत बैल या तो मर गए या गैरखेतिहर नौगा के हाथों में पहुँच गए।

कजदार परिवारों की सख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित आँकड़े एकत्र किए थे जिनसे अकाल से अर्वाधिक बुरी तरह ग्रस्त इलाकों में रहने वाले परिवारों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि का पता चलता है

| कज में डूबे परिवारों का प्रतिशत |      |      |
|---------------------------------|------|------|
|                                 | 1943 | 1944 |
| किसान परिवार                    | 43   | 66   |
| विभिन्न दस्तकार                 | 27   | 56   |
| विविध                           | 17   | 46   |

(वही, पृष्ठ 12)

आज स्थिति यह है कि किसानों की एक बहुत बड़ी मख्या का पान न तो जमीन है, न बीज है, न भवेशी हैं और न ही अपनी जरूरत की चीजें खरीदन के लिए पैसा है। इसके साथ ही बार बार रोग के आक्रमण के कारण अनेक स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरह असम हो गए हैं। वस्तुतः 'संपत्तिवान' किसान आज गांव के समृद्ध किसान अथवा जोतदार पर निर्भर कर रहा है ताकि उसे जमीन, भवेशी, खली और बीज मिल सके। जमीन पान के लिए और भवेशियों तथा बीज की व्यवस्था के लिए उसे अपन को किसी भी शत पर बेचना पड़ता है। यदि वह ऐसा न करे तो वह एक मजदूर की हैसियत में पहुँच जाएगा। (वही, पृष्ठ 10)

बगाल में जो कुछ हुआ वह उस सकट का उग्रतम रूप था जो समूचे देश पर छा रहा था। युद्ध के समय में हुई मूल्यवृद्धि से किसान जनता वही भी लाभ न उठा सकी। वेबन मन्त्रीने किसानों का एक बहुत मामूली तबका अपना कुछ कज उतार सका। नविन ग्राम जनता कज के बोझ के नीचे दिनोदिन दबती गई और इस प्रकार जमीन उसके हाथ से निकल गई। हाज ही में मद्रास सरकार ने डॉक्टर वी० वी० नायडू की देखरेख में युद्ध के दौरान गावों में कज की स्थिति का एक सर्वेक्षण कराया। इस जांच के बाद जो विभिन्न आँकड़े सामने आए उनमें कोई सही तस्वीर नहीं मिल पाती है। वे जो तस्वीर पग करते हैं वह

पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है और इसमें जमींदारों के पक्ष को काफी महत्व दिया गया है। लेकिन इस जाच के जरिये भी वास्तविक प्रवृत्ति का छिपाया नहीं जा सका अर्थात् यह बात सामने आ गई कि युद्ध के फलस्वरूप छोटे भूस्वामियों, काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों के कज में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

जितने दिना तक युद्ध चलता रहा किसानों से जमीन की बेदखली की प्रक्रिया भी भयंकर रूप से जारी रही। इसकी वजह से भारत अभाव, भुखमरी और अकाल की स्थिति में पहुँच गया। अकाल के तीन वर्षों के अंदर, 1946 में भारत के सामने एक बार फिर वह स्थिति आ गई है जब खाद्यान्न की कमी के बारे में अनुमान लगाया गया है कि 60 लाख टन अनाज कम है और जावादी का एक चौथाई हिस्सा विनाश की आशंका से ग्रस्त है।

## 2 किसान क्रांति की आवश्यकता

इस प्रकार भारतीय किसान के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या पैदा हो गई है वह उनके अस्तित्व की है और इस समस्या का समाधान अनिवार्य रूप से उन्हें दूढ़ना है। क्या मौजूदा शासन व्यवस्था के तहत, मौजूदा भूमि व्यवस्था और इसपर आधारित साम्राज्यवादी शासन के तहत कोई हल ढूँढा जा सकता है? जाहिर है और इसे सभी लोग मानते हैं कि कुछ बहुत बुनियादी परिवर्तन आवश्यक हैं जो जमीन की वास्तविकता के समूचे आधार को और जमीन के वितरण की मौजूदा प्रणाली को बदल डालें। छेती की तकनीक में तब्दीली करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। फ्लाइड कमिशन को दिए गए एक ज्ञापन में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने कहा था

स्थायी बदोबस्त ने जमींदारों को असीमित अधिकार दे दिए हैं और इसने बदले में इस प्रणाली को अपने जबरदस्त दबाव के तहत एकाधिकार और मातना का रूप दे दिया है। हमारा अनुभव हम बताता है कि स्थायी बदोबस्त एक ऐसा कठोर ढाँचा तैयार करता है जिसमें कोई भी व्यावहारिक सुधार काम नहीं कर सकता। वैधानिक सुधार की बात को भले ही विधान की पुस्तिका में स्थान दे दिया जाए पर जमींदार बग के पास जो अधिकार हैं उनसे वह निरर्थक किया जा सकता है। यही वह प्रणाली है जो अपने विभिन्न प्रतिनिधियों, जमींदारों, सूदखोर महाजनों और पुलिस के जरिए उत्पीड़ित किसानों के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश करती रहती है कि वे अपनी जमीन छोड़कर चले जाएँ। इन परिस्थितियों में यदि स्थायी बदोबस्त व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की जाती है तो यह किसी गड़बड़ मोच का नतीजा नहीं है बल्कि इस मांग के पीछे एक गहरी समझदारी है और वह यह है कि जमीन की वास्तविकता प्रणाली में कोई सुधार करना असंभव है। (ज्ञापन, पृष्ठ 4-5)

जमींदारी प्रथा समाप्त होनी ही चाहिए। जैसा हमने भारत में देखा है जमींदारी प्रथा

उस विदेशी सरकार की एक कृत्रिम दान है जो पश्चिमी मस्वाजा को यहाँ आरोपित करना चाहती है और जिसकी यहाँ की जनता की परंपराओं में कोई जड़ नहीं है। इसका नतीजा यह है कि यहाँ की जमींदारी प्रथा किसी भी देश के मुकाबले विलकुल ही वतव्यहीन है, यहाँ तक कि वह दिखाने के लिए भी भूमि के विकास या संरक्षण के काम में अपनी आवश्यक भूमिका नहीं निभाती। उल्टे, वह अपनी अहूरदर्शितापूर्ण बहुत अधिक मांग से भूमि का गतत इन्फ्लेमेशन और इसकी वरवादी करती है। यह किसानों पर विपुल रूप से परोपजीविता का दावा है और जहाँ बड़ी जमींदारियाँ हैं वहाँ जमींदार प्रायः अपना एक नुमाइदा नियुक्त कर देता है जो छोटे जमींदार की भूमिका निभाता है और फिर विचोतिये जमींदार के कारण परोपजीविता में और वृद्धि होती है। किसानों की पहले से ही अपर्याप्त उपज पर इन परोपजीवियों के दावों के लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी पदा किया जाता है उससे पहले, जीवन यापन की आवश्यकताएँ फिर सामाजिक आवश्यकताएँ और अंत में कृषि के विकास की आवश्यकताएँ पूरी की जानी चाहिए।

यही बात महाजनी प्रथा और कज के पहाड़ के बारे में भी सच है। कज की राशि में जवरदस्त कमी और फिर इसे रद्द कर देना एकदम जरूरी है। लेकिन केवल इतना कर देने से कोई फायदा नहीं होगा या अस्थायी तौर पर ही थोड़ी राहत मिल सकेगी यदि इसके साथ साथ कजदारी को रोकने के लिए या महाजनों की भूमिका के विकल्प में कोई अन्य संगठन न तैयार किया गया। इसका अर्थ सबसे पहले तो यह हुआ कि किसानों पर किए जाने वाले अत्यधिक दावों समाप्त किए जाएँ और आर्थिक जोता को संगठित किया जाए और दूसरे, जब तक कोई मामूहिक संगठन न तैयार हो जाए जो अंततः कज की जरूरतों का स्थान ले ले तब तक सस्ती दर पर ऋण की सुविधा होनी चाहिए।

यह मानना पड़ेगा कि लगान की माफी और लगान की राशि में कमी तथा ऋण में कमी और ऋण पर लगान वाले ब्याज की दर में कमी के अस्थायी और जागिक उपाय तत्काल संभव हैं और कांग्रेस सरकारों द्वारा विभिन्न प्रातों में कहीं कम और कहीं अधिक उपाय किए जा रहे हैं पर समस्या के बुनियादी हल के लिए पूरी भूमि व्यवस्था का पुनर्संगठन जरूरी है। लगभग 30 लाख छोटे और अधीनस्थ जमींदारों के एक बड़े वर्ग का अस्तित्व है, जो स्वयं बहुत गरीब हैं और जिनकी जातें लगभग उतनी ही हैं जिनकी कि शहर में रहने वाले किसी अल्प वेतनभोगी व्यक्ति की वृद्धावस्था की पेशान होती है। जमींदारी प्रथा की समूची प्रणाली को जटिल बना दिया है। इसके फलस्वरूप लगान में कमी करने का कोई भी उपाय ऐसा होना चाहिए जिससे इस बात की निश्चितता रहे कि मुख्य भार बड़े जमींदारों पर पड़ेगा। यह सुझाव दिया गया है कि श्रेणीगत कृषीय आय कर (वर्तमान आय कर व्यवस्था में कृषीय आय पर कर नहीं लगता और इस प्रकार एक तरफ तो जमींदार आय कर देने से मुक्त हो जाता है और दूसरी तरफ उद्योग धंधों पर अधिप्राधिक बोझ पड़ जाता है) की व्यवस्था की जाए जिसमें बड़े जमींदारों पर कर की ऊँची म ऊँची दर लगाई जाए और छोटे जमींदारों को कर से मुक्त रखा जाए तो इस लक्ष्य का

प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी, राज्य की आय बढ़ाकर या लोकशासन अथवा कांग्रेस सरकार के जरिए खेती के विकास के लिए काफी पैसा जारी कराकर भी किसानों पर बोझ कम करने की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक इस तरह प्राप्त की गई राशि का इस्तेमाल जमीन की मालगुजारी कम करने और इसके साथ ही अनिवार्य रूप से लगान की राशि में कमी करने के लिए न की जाए। तदनुसार जमींदारी प्रथा की बुराईया से और व्यवस्थित ढंग से निवटने का काम व्यापक आर्थिक पुनर्गठन के कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए जो छोटी जोतावाले विस्थापित किसानों और उन लाखों लोगों के लिए जो निश्चय ही खेती के क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ होने से अपने व्यवसाय से अलग हो चुके हैं, जीवनयापन का कोई वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करें। इसलिए खेती के विकास और उद्योग धंधों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों में एकता जरूरी है।

बुनियादी समस्या महज जमींदारी प्रथा की समस्या नहीं है बल्कि वर्तमान भूमि व्यवस्था और जातों के वितरण का पुनर्गठित करने की व्यवस्था है। गैरआर्थिक जोतों तथा खेती के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होने की खामियों को दूर करने के लिए जोता का पुनर्वितरण बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए जब यह स्मरण किया जाता है कि बर्बई प्रेसीडेंसी में 48 प्रतिशत खेत 5 एकड़ से भी कम क्षेत्र के हैं और फिर भी उनका कुल योग समूचे क्षेत्रफल के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है उसी समय यह महसूस किया गया था कि पुनर्वितरण का काम कितना जरूरी है (कृषि आयोग का साक्ष्य, खंड II, भाग 1, पृष्ठ 76)। फिर भी इस तरह के पुनर्वितरण का काम जिसमें निश्चित रूप से सरप्राय के दावों की तरफ से व्यक्तिगत निहित स्वार्थों को नुकसान पहुंचाना है, किसी विदेशी सरकार की नौकरशाही नहीं पूरा कर सकती है चाहे वह इसने किए बिना भी इच्छुक क्यों न हो। यह काम केवल किसानों के पहल और उनकी कायदाही के जरिए हो सकता है और यह काम ऐसी सरकार के नेतृत्व के अंतर्गत हो सकता है जो उन किसानों का प्रतिनिधित्व करे और उनके हितों के लिए सघन करे।

फिर भी कृषि संबंधी विकास की समूची समस्या से निपटने के लिए भूमि का पुनर्वितरण केवल पहला कदम है। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि कृषि में तकनीक का आधुनिक स्तर तक लाया जाए, खेती के काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और खेती के लायक जमीन के जो इलाके वज्र पड़े हैं उन्हें खेती योग्य बनाया जाए। इस सद्म में वैदेशीय बैंकिंग जाच समिति (इनक्वैजोर 13, पृष्ठ 700) के उस अनुमान को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा जिसमें कहा गया था कि यदि प्रति एकड़ उपज को उस स्तर तक उठा दिया जाए जिस स्तर पर इंग्लैंड में उपज होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति बरष संपत्ति में एक अरब पाँच की तत्काल वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार यदि उपज का स्तर डैनमार्क में गहू के उत्पादन के स्तर तक पहुंचा दिया जाए तो प्रति बरष संपत्ति में कुल वृद्धि 1 अरब 50 करोड़ पाँच की होगी (अर्थात् 1933-34 में हुई पसलों के कुल मूल्य





हित महाजनी पूजी द्वारा भारतीय जनता के शोषण के साथ जुड़े हुए हैं ताकि भारत एक पिछड़ा हुआ, कृषीय उपनिवेश बना रहे। इन बातों में साम्राज्यवाद के लिए छेती की समस्या को हल करने का प्रयत्न करना असंभव है।

स्वयं साम्राज्यवादियों ने भी यह स्वीकार किया है कि अत्यंत आवश्यक कृषीय समस्या को हल करने में साम्राज्यवाद असफल साबित हुआ है। इस सदन में 1927 में भारतीय कृषि की जांच के लिए गठित शाही आयोग के विचाराय विषयों का प्रतीकात्मक महत्व है। इस आयोग का गठन अंगरेजों द्वारा शासन स्थापित करने के 170 वर्षों बाद किया गया। आयोग की स्थापना का उद्देश्य 'ब्रिटिश भारत में कृषीय और ग्रामीण अव्यवस्था की समस्याओं पर विचार करना था लेकिन आयोग को भूमि व्यवस्था पर हाथ भी नहीं लगाने दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी छोटी मोटी सिफारिशें अनिवार्य रूप से सीमित महत्व की सिफारिशें बनकर रह गईं जो व्यवहार में पूरी तरह ब्रह्मर साबित हुई। इन्हें रिपोर्ट और साक्ष्य के 17 खंडों में दफना दिया गया। कृषि के क्षेत्र में बढ़ते हुए सकट को किसी सीमा तक रोकने के लिए इसमें कृषि संबंधी स्थितियों के प्रमाण का भंडार था लेकिन इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद से छेती की समस्या बड़ी तर्जों से उग्र रूप लेती गई है।

छेती की समस्या के सदन में साम्राज्यवाद की नपुंसकता का प्रमाण उसके दिवालियेपन का व्यवहारिक लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। अभी हाल के वर्षों में बहुत सीमित क्षेत्र में कृषि संबंधी शोध समस्याओं और केंद्रों की व्यवस्था की गई है (इंपीरियल ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना तभी संभव हो सकी जब शिकागो के एक लघुपति व्यक्ति ने भारी धनराशि दान में दी, 1936-37 में कृषि संबंधी विभागों पर केंद्रीय और प्रांतिय सरकारों द्वारा कुल 22 लाख 50 हजार पौंड खर्च किया गया जो कुल बजट का 1/4 प्रतिशत था। लेकिन इस तरह के संस्थान और केंद्र किसान जनता की व्यवहार रूप में तब तक सहायता नहीं पहुंचा सकते जब तक उनके पास तकनीकी विकास के लिए साधन नहीं उपलब्ध होते और जब तक वह शापण नहीं बढ़ जाता जो उन्हें अधमुखभरी, गुलामी और अज्ञानता की सर्वाधिक पिछड़ी स्थितियों में बंद किए हुए हैं।

कृषि संबंधी आयोग की रिपोर्ट में (पृष्ठ 436-37) इन बातों का पहने ही उल्लेख किया गया है कि बजटदारी के विकास पर रोक लगाने के लिए छेतिहरो की सहायता के लिए कानून संबंधी जो विभिन्न उपाय किए गए वे अमफन साबित हुए। इनो प्रकार काय कारों की सुरक्षा के लिए कायकारी संबंधी कानून बनाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का जमींदारी व्यवस्था के तेजी में विस्तार का कारण में तथा शिक्षा की प्रगति और जबरन लगान वसूली का तरीका गहन में गहनता नहीं मिली। मुद्रिया प्राण मर्यादित कायकारों के साथ ही छोट जमींदारों की भूमि का विभागों नग्न और उा कायकारों का शापण करना लगा है जिससे कोई संरक्षण नहीं प्राप्त है।

जैसा पहले ही बताया गया है (देखें पृष्ठ 176-78) पुरानी सिचाई व्यवस्था की भरपूर अपेक्षा और अतत वरवादी के बाद 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश सरकार ने सिचाई की व्यवस्था के संबंध में जो थोड़ा बहुत काम किया है उसे बहुधा कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि का नाम दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश भारत में कुल बीए गए क्षेत्र का 23 प्रतिशत हिस्सा ही आज भी सिचाई की सुविधा पा सका है (1939 40 में 24 करोड़ 50 लाख एकड़ में से केवल 5 करोड़ 50 लाख एकड़ ही सिंचित क्षेत्र था)। सरकार की सिचाई व्यवस्था से केवल 10 प्रतिशत जमीन को ही लाभ मिलता है (1939 40 में ढाई लाख एकड़ जमीन)। इसके अलावा भारतीय रियासतों में लगभग 15 लाख एकड़ में सिचाई होती थी और इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र 6 करोड़ 55 लाख एकड़ हुआ। सिचाई के लिए काफी पैसा लिया जाता है और यही कारण है कि यह सुविधा गरीब किसानों के लिए नहीं है। इससे किसानों पर और भी बोझ बढ़ जाता है। सरकार की सिचाई व्यवस्था ने 1918-21 में कुल 78 प्रतिशत का मुनाफा कमाया और यहाँ तक कि 1935-36 में भी उसने 57 प्रतिशत का विशुद्ध मुनाफा कमाया।

खेती के क्षेत्र में जो दुर्व्यवस्था है उसको अंतिम तौर से समाप्त करने के लिए सरकार ने रामबाण के रूप में सरकारी विभाग के अंतर्गत सहकारी ऋण समितियों के आधार पर कृषी सहयोगों को विकसित और पापित किया। सहयोगों में सरकार ने जो यह विशेष दिलचस्पी दिखाई उसके मूल में कौन से उद्देश्य काम कर रहे थे और कौन सी आशाएँ थी इन्से डालिंग महोदय ने अपनी ताजा पुस्तक 'मैं वड़ी कुशलता के साथ समझाया है। लगान और जमींदारी न देने के लिए कांग्रेस ने जो आंदोलन किया था उसका उल्लेख करते हुए श्री डालिंग ने लिखा है कि पंजाब का एक जिला सूखतापूरा प्रचार सं ग्रस्त हो गया है।' और उन्होंने टिप्पणी की कि 'यह महत्वपूर्ण बात है कि इन गाँवों में म केवन एन में मद्द-कारी समिति थी।' उन्होंने आगे कहा

इस तरह के आंदोलनों का सबसे अच्छा प्रतिपारक है—सहायक और ट्राम बोर्डों सहित नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्ष मून में जा 20 हजार गमिनिया काम कर रही थी उनका गाँव पर एक उपशामन अगर था और डन्नि वानू भग वरने की घटनाओं को आमतौर से फेलन स राका। इस तरह का घटनाश्री से अनेक नगर परेशान हो चुके हैं। (एम० एन० शनिंग 'वन एन वेट इन दि पंजाब विलेज' 1934 पृष्ठ 83 84)

दुर्भाग्यवश गेतिहरो को ऋण देने के लिए जा मद्दगमि वानम की गई उगम गरीब किसान लाभान्वित हो सकें क्योकि उनका पान इनकी मद्दगमि के लिए आवश्यक साधन नहीं हैं। इसका लाभ मुख्यतः मजदूर किसानों का मिलता है जो पढ़ने की उम्र में न्यति में हैं और जिन्हें जादाना में निगुद करने की प्रवृत्ति है।

हम जो पैमाना इस्तेमाल करेंगे उसके एक सिरे पर ऐसे लोग हैं जो अच्छे खाते पीते हैं और जो स्वयं की सदस्य बनाकर असीमित देयता का खतरा अपने ऊपर मोल लेना नहीं चाहते। दूसरे सिरे पर ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने गरीब हैं कि उन्हें सदस्यता नहीं मिल सकती। इसलिए यह मानना उचित नहीं होगा कि सहकारिता आंदोलन में लगी आवादी औसत कृषि आवादी का प्रतिनिधित्व करती है।' (बंगाल प्रांतीय वॉकिंग जांच समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 69)

एक और बड़ी कठिनाई यह है कि निम्नतम जिलों में, जहां किसानों की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ऋण समितियों का कोई इस्तेमाल नहीं है। इन समितियों के बेकार पड़े रहने से बेहतर यह है कि वे उन किसानों की कज दें जो जमीन के टुकड़े टुकड़े होने या अन्य कठिनाइयों की वजह से अपनी जोतों का भुगतान करने में ब्याईं तौर पर अक्षम हैं। इस प्रकार मुख्यतया अत्यंत समृद्ध इलाकों में ही ऋण समितियां कामयाब हुई हैं। (एस्टे इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया, पृष्ठ 202)

यह मौजूदा स्थितियां में कृषि संबंधी सहयोग का क्षेत्र अत्यंत सीमित होने के कारण है। 1939-40 में ब्रिटिश भारत में कृषीय सहकारी समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 4,098,426 थी जो गांवों में रहने वाली कुल आबादी का 1/6 प्रतिशत थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के अनुपात के बारे में कृषि आयोग की रिपोर्ट में निम्न तालिका दी गई थी (पृष्ठ 447)

कृषीय सहकारी समितियों के सदस्यों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों का अनुपात

| प्रतिशत        |      |
|----------------|------|
| बंगाल          | 3.8  |
| बंबई           | 8.7  |
| मध्य प्रांत    | 2.3  |
| मद्रास         | 7.9  |
| पंजाब          | 10.2 |
| संयुक्त प्रांत | 1.8  |

रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के अनुसार, यह देखा गया कि पंजाब, बंबई और मद्रास को छोड़कर, प्रमुख सूबों में यह आंदोलन गांवों में रहने वाली आबादी के एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच सका है। इन अनुपातों से प्राप्त स्तर का पता चलता है (यह ध्यान देने की बात है कि बंगाल और संयुक्त प्रांत जैसे सर्वाधिक अभावग्रस्त सूबों में, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, यह अनुपात काफी कम है) और यह जानकारी मिलती है कि जब तक वर्तमान अल्प मयता और बांध बंधे रहेंगे, तब तक कृषीय सहकारिता से यह आशा नहीं की जा सकती कि इसमें बिमानों की समस्याएं हल होंगी।

साम्राज्यवाद के समयको के लेखों में भी अब यह काफी खुलकर आने लगी है कि भारतीय कृषि की समस्या को अर्थात् भारतीय जनता की अत्यावश्यक जीवन समस्या को हल करने के लिए, एक बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है जो भूमि प्रणाली की जड़ तक पहुंचे। वे अब यह भी मानने लगे हैं कि इस तरह के पुनर्गठन की कोशिश साम्राज्यवादियों द्वारा नहीं की जा सकती बल्कि यह काम केवल भारतीय जनता ही एक जिम्मेदार सरकार के तहत पूरा कर सकती है।

राजनैतिज्ञा और अधिकांशिया न भी ग्रामीण जीवन के सुधार की अत्यावश्यक जरूरत को स्वीकार किया है लेकिन इस दिशा में किए गए खाम खाम उपाय बहुधा या तो अपर्याप्त साबित हुए हैं या इनके लिए श्रान्तिकारी परिवर्तनों की जरूरत है जिसके लिए भारत के स्वायत्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।  
(थाम्पसन और गैरट 'राइज ऐंड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया' 1934, पृष्ठ 648)

यह सुझाव दिया गया है कि इसका सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि एक एक करके घास खास इलाका को लिया जाए और हर तरह के पारिवारिक तथा कानूनी अधिकारों सहित वहां की समूची व्यवस्था को 'दुरुस्त' किया जाए।  
(इनाहावाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ट्रेनिंग संख्या 9, 1918 में एच० स्टैनले जेबोम का लेख 'दि कमालिडेशन आफ ऐग्रीकल्चरल होलिडिंग्स इन दि यूनाइटेड प्रोविसेज')। फिर भी यह तब तक पूरी तरह अव्यावहारिक लगता है जब तक एक जिम्मेदार सरकार न काम में लगे। (एस्टे 'दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' 1936, पृष्ठ 101)

हालांकि यह सच है कि यदि ज्ञात विकसित साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए तो कृषि की पैदावार में श्रान्ति लाने के लिए यह पर्याप्त होगा लेकिन इसमें सन्देह है कि उन बुनियादी बंठनाइयों को निकट भविष्य में समाप्त किया जा सकेगा जो अतीत में विकास की प्रक्रिया तेज करने में बाधा पहुंचाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी आवश्यक सुधार के दौरान धार्मिक तथा सामाजिक समस्याओं और रीति रिवाजों में एक अंश तक हस्तक्षेप करना पड़ेगा और यह काम ऐसी सरकार नहीं कर सकती जिसे जनता का भरपूर विश्वास और समर्थन न प्राप्त हो। (वही, पृष्ठ 177)

इन दृष्टिकोण का आधार जिस सिद्धांत पर टिका है वह निम्नदेह ठीक है भले ही इन धार्मिकों द्वारा जो तर्क पेश किया जाता है वह मौजूदा स्थिति में किसी बुनियादी सुधार के काम को बिजबित करने और अस्वीकार करने के लिए पेश किया जाता है। (निरिचित

तौर पर इतजार करना होगा,' 'पूरी तरह अव्यावहारिक है वशतः', 'निकट भविष्य में संदिग्ध है')।

भारतीय कृषि में अर्थात् भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के जीवन में जिन महान परिवर्तनों की आवश्यकता है और जिनकी जरूरतों को प्रत्येक पक्ष स्वीकार करता है, ऐसे वे परिवर्तन केवल भारतीय जनता ही एक ऐसी सरकार के नेतृत्व में ला सकती है जिसका चुनाव स्वयं उसने किया हो, जिसमें उसका विश्वास हो, जो खुद जनता की स्वतंत्र क्रियाशीलता और सहयोग प्राप्त कर सकती हो।<sup>1</sup> इसीलिए कृषि के क्षेत्र में पुनर्गठन का काम, जो अब बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय मुक्ति और जनतांत्रिक स्वतंत्रता के काम से जुड़ा है। किसान क्रांति का संघ जनतांत्रिक क्रांति से है।

#### 4 किसान आंदोलन का विकास

हाल के कुछ वर्षों में किसान आंदोलन का जो विकास हुआ है, वह इस परिस्थिति में भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जब से भारत में अंगरेजों का शासन स्थापित हुआ तब से समय समय पर किसान असंतोष और किसान विद्रोह की घटनाएँ सामने आईं और इनकी संख्या में बराबर वृद्धि होती गई। प्रारंभ में किसानों का यह असंतोष और गुस्ता आदिम और स्वतः स्फूर्त रूप में अलग अलग सूदखोर महाजनों और जमींदारों से बदला लेने तथा हिंसा का प्रयोग करने की छुटपुट कायवाहियों का रूप लेता रहा। 1852 में बर्मा सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में सर जॉन बिगनट ने लिखा था

हमारी प्रेसीडेसी के दो विरोधी छोरों पर गांव के सूदखोर महाजनों की उनके बजदारी द्वारा हत्या की गई है जिनके बारे में मेरी आशा यह है कि इन घटनाओं को बजदारी पर दमन के फलस्वरूप की गई कायवाही मात्र न समझा जाए। यह एक ऐसा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि हमारी खेतिहर आबादी और सूदखोर महाजनों के बीच आमतौर पर जो संघर्ष चल रहा है वह कितना गंभीर है। और यदि ऐसा है ही तो इन घटनाओं में एक तरफ जबरदस्त दमन और दूसरी तरफ घोर पीड़ा का किस सीमा तक पता चलता है? व कौन सी स्थिति है जिनमें किसानों का, जो बड़े सहनशील और मरिदा से चले आ रहे दुर्व्यवहार तथा जयाय की चुपचाप झेलन वाले मान जाते हैं, महाजनों की गलतियाँ सुधारने के लिए और अपनी धूमिल भृत्य राखने के लिए हत्या तक का सहारा लेना पड़ता है? किस तरह जयाय की उनकी धारणा का नाश किया जाना चाहिए? कानून या सरकार ग उन्होंने कैसे यह आशा छोड़ दी कि उनकी शिकायतों पर गुनवाई की जाएगी और वह कौन सी सीमा थी जहां आकर उन्होंने धैर्यपूर्ण और शांत स्वभाव न इतना गंभीर बदम आठ लिया? (सर जॉन बिगनट रिपोर्ट दु सिमान गवर्नमेंट द 1852)



समय समय पर विशाल प्रदर्शन हुए जिनमें 30 हजार से लेकर 40 हजार किसानों ने भाग लिया, इनके साप्ताहिक समाचारपत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, इनके लिए गाने लिखे गए और पत्र तैयार किए गए। किसानों की शिक्षा के लिए स्कूलों की शुरुआत हुई। इससे साबित होता है कि किसानों का आंदोलन काफी मजबूत और ठोस होता जा रहा था। कांग्रेस मंत्रिमंडल पर इस बात के लिए जबरदस्त दबाव डाले जा रहे थे कि वे सुधार के उपाय अमल में लाएं। इन सरकारों पर जमींदारों के प्रभाव को कम करने की भी कोशिशें जारी रही।

अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा अधिवेशन अप्रैल 1939 में हुआ। इस समय तक संगठन के सदस्यों की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई थी। इस अधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में घोषणा की गई

पिछले वर्ष भारत के किसानों में चमत्कारी जागृति और उनकी संगठनात्मक शक्ति के विकास का प्रमाण मिला है। देश के सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन में किसानों ने पहले से यही अधिक बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने चेतना के स्तर को भी प्राप्त कर लिया है जो उन्हें उनके वर्ग से परिचित करानी है और यह वर्ग सामंतों और साम्राज्यवादियों के निम्न शोषण के खिलाफ अपना अस्तित्व बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश में लगा है। इसलिए उनके वर्ग संगठनों में निरंतर वृद्धि हुई है और इस शोषण के खिलाफ उनका संगठन इतने ऊंचे स्तर तक उठा है कि विभिन्न आर्थिक संघर्षों में उन्हें हिस्सा लेना पड़ा है और इस प्रकार उनमें एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है। उन्होंने उन शक्तियों का स्वरूप को समझ लिया है जिसके विरुद्ध वे संघर्ष कर रहे हैं और अब वे यह जान चुके हैं कि उनकी गरीबी और शोषण की समाप्ति के लिए सही तरीका कौन सा है। देश की अन्य साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर की गई कामवाहियां अब उनकी दृष्टि को सीमित नहीं रखा है। वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राज के रोज के संघर्ष की तकमगत परिणति साम्राज्यवाद पर जबरदस्त आक्रमण और साम्राज्यवाद की समाप्ति में ही हानी चाहिए। इसके साथ ही एक किसान क्रांति आवश्यक है जो उन्हें जमीन दगी, राज्य और उनके बीच द्विचालियों द्वारा किए जा रहे हर तरह के शोषण को समाप्त करेगी, राज के बोझ से उन्हें मुक्त करेगी और उनके परिश्रम का पूरा पूरा फल उन्हें प्राप्त हो सकेगा।

दूसरे, पिछला वर्ष प्रांतीय सरकारों द्वारा किसानों को दी गई छाटी मोटी गहना का वर्ष रहा। ये राहें वेहद अपर्याप्त थीं और निहित स्वार्थों ने इनके माग में बड़ी बड़ी र्कावर्टें डाली जिनका मुकाबला करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बुनियादी किसान समस्याओं को हल करने में प्रांतीय स्वायत्तता बिलकुल ही असमर्थ है। इन बातों ने प्रांतीय स्वायत्तता के पापवेष

की पूरी तरह सामने ला दिया। सगठन की आज यह घोषित करते हुए गव हो रहा है कि भाग्य के विमान अपन को सामंती साम्राज्यवादी शापण स मुक्ति दिलाने के लिए और इस काम को पहले के मुकाबले और तजी से करने के लिए वृत्तसकल्प है।

किसान सगठन यह घोषणा करता है कि समय आ गया है जब देश की सयुक्त शक्तिया काग्रेम राज्या की जनता, किसानो, मजदूरो और सामान्य जनो तथा सगठनो के साथ मिलकर साम्राज्यवादी प्रभुत्व के गुलाम सविधान पर आक्रमण करने पूरा राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त करने और भारतीय जनता के जनतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए आगे आएं जिममे अतल किसान मजदूर राज कायम किया जा सके।

गमा के इस अधिवेशन के कुछ ही महीना के अंदर विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसके बाद 'भारत रक्षा अधिनियम' के अंतर्गत भारतीय जनता पर दमन का एक जबरदस्त दौर चला। मजदूरों और किसानों आंदोलनों के नेताओं की देश भर में व्यापक गिरफ्तारियां हुईं और बिना मुकदमा चलाए उन्हें जलाम डांट दिया गया। लेकिन तमाम दमन के बावजूद किसानों ने देश भर में साम्राज्यवादी सामंती व्यवस्था के विरुद्ध अपना जबरदस्त सघप जारी रखा। पंजाब में ताहोर और अमृतसर के किसानों ने जमीन की मालगुजारी कम करने की मांग को लेकर बड़े बड़े जुलूस निकाले और प्रदर्शन किए। 5 हजार से भी अधिक किसानों को, जिममें सैंकड़ों महिलाएं भी शामिल थी, जेलों में ठूस दिया गया। उनकी कुछ मांगें छ महीने बाद जाशिक तौर पर मान ली गई और तब आंदोलन समाप्त हुआ लेकिन इससे पहले इन बंदी किसानों में से चार की मृत्यु जेल के अंदर हो गई। बिहार, आंध्रप्रदेश, बंगाल, मध्य प्रांत, सयुक्त प्रांत, मालाबार, सिंध और सुरमा घाटी में किसानों ने मनमानी कर वसूली तथा जबरन घेदखली आदि के खिलाफ जबरदस्त सघप चलाया। मार्च 1940 में पलास में अखिल भारतीय किसान सभा का पांचवा अधिवेशन हुआ जिममें पारित प्रस्ताव में घोषणा की गई

सभा का यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि भारत के किसान, जिनकी शांति में सबसे बड़ी बाजी लगी हुई है, देश के मजदूरों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के सघप में हरावल दस्त का काम करेंगे, विदेशी सरकार की सत्ता को चुनौती देंगे तथा देश के मसाधनों को देश से बाहर भेजे जान का विरोध करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसानों को चाहिए कि वे अपने राज के रोज के सघप को अपनी किसान सभाओं के नेतृत्व के तहत चलाएं और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सघप के साथ साथ भारतीय राजाओं और महाराजाओं, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध भी जोरदार सघप चलाएं क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ये ही आधार स्तंभ हैं। दिनोदिन तेज होत और व्यापक क्षेत्रों में फैलते इन सघपों को शीघ्र ही देशव्यापी



कर और लगान न देने के आंदोलन का रूप ले लेना चाहिए ताकि साम्राज्यवाद के इन परोपजीवियों की आर्थिक सत्ता समाप्त हो जाए और भारत में ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक सत्ता को नीव हिल उठे ।

1942-45 की अवधि पूरे किसान आंदोलन के लिए बड़ी परीक्षा की थी । अगस्त 1942 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन पर निमग्न आक्रमण किया गया, काग्रस नताशा की गिरफ्तारियां हुईं और इसके बाद दमन का एक जबरदस्त दौर चला । इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई । जमींदारा, व्यापारियों, जमाखोरो और कालाबाजारियों ने भ्रष्ट नौकरशाही के साथ साठ गांठ करके बरोड़ों लोगों के जीवन के साथ भयंकर खिलवाड़ किया । बड़े पैमाने पर गांवों की किसान जनता अनाज और विनाश की चपेट में आ गई, बंगाल में गरीब निधन किसान भविष्यवा की तरह मारे गए ।

इस प्रकार संगठित किसान आंदोलन के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी । इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा और उसकी प्रांतीय शाखाओं ने राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई के लिए तथा एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए दबतापूवक आंदोलन चलाया, सरकारी दमनचक्र का बहादुरी से सामना किया, युद्ध के लिए जवरन की जा रही धन की बसूली के खिलाफ सघन किया और अधिक अन्न पैदा करने के लिए तथा प्रत्येक गांव में नौकरशाहों, जमाखोरो और कालाबाजारियों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए आत्मसहायता आंदोलन को संगठित किया ।

यह समूचा दौर भारतीय किसानों की शानदार उपलब्धियों से भरा है । आंध्र प्रदेश में हजारों एकड़ बजर जमीन को खेती के योग्य बनाया गया । किसानों ने आपस में एक जुटता कायम की बड़े बड़े बांध बनाए और विशाल भूभागों को बाढ़ की बरबादी में बचाया । बंगाल में भयंकर अकाल के दिनों में भी अधिकांश गांवों में किसानों ने घूम घूम कर अनाज इकट्ठा किया और गांव की अतिरिक्त खाद्य सामग्रियों को उन अभावग्रस्त इलाकों में भेजा जहां उनके किसान भाई भूख से मर रहे थे । अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में एक देशव्यापी अभियान छेड़ा गया जिसका उद्देश्य भयंकर अकाल से बंगाल की जनता को राहत पहुंचाना था । इस अवसर पर देश भर के किसान उठ खड़े हुए और उन्होंने बंगाल की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर अनाज और धन इकट्ठा किया । स्वयं अपने सूबा के अंदर किसानों ने अनाज समितियां कायम की, चोरबाजारियों का भंडाफोड़ किया और अनाज के छिपे हुए गोदामों का पता लगाया तथा जबरन सत्ता में बीच अनाज का वितरण किया । सरकार के स्थानीय अधिकारियों की तरफ से सत्ता आदि की हर कायबाही का अपूर साहस और विश्वास के साथ मुकाबला किया गया ।

देश की आजादी के लिए और सामान्य आदमियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने

के कारण तथा जाता की अनाज सुलभ कराने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा अधिकाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय संगठन बन गई। 1942 में उनके सदस्यों की संख्या 225,781 थी जो 1944 में 553,427 हो गई और 1945 में 829,686 तक पहुंच गई। युद्ध समाप्त होने पर भारत की गरीब किसान जनता में जागरण की नई लहर आई। लगातार गहराते अन्न संकट ने, आवश्यक उपभोगिता सामग्रियों की कमी और मूल्यवृद्धि ने तथा सरकारी जुल्म और गांवों में जमींदारों के दमन ने किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक जुझाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। एक तरफ किसान यह भाग कर रहे हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्काल कानून बनाए जाए और दूसरी तरफ वे खुद भी किसान सभा के नेतृत्व में जमींदारों की बंजर जमीन पर वज्जा करने के काम में पहल कर रहे हैं। इससे साथ ही वे बेदखली तथा लगान वृद्धि की जमींदारों की कोशिशों का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं।

### पाद टिप्पणी

1. कृषि संघी आयोग की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बयान शामिल है जिसका महत्व निम्नलिखित है इसके सेचनों द्वारा सोचे गए महत्व से कहीं ज्यादा है

जहां पर पांच साख गांवों की समस्या का मामला है, यह बात बहुत साफ है कि सरकारी संगठन उन गांवों में प्रत्येक व्यक्ति से मिलने की वांछा नहीं कर सकता। ऐसा समय बनाने के लिए जनता को खुद अपनी सहायता करने के लिए संगठित होना चाहिए और उनके स्थानीय संगठनों को बड़े संघों के रूप में उस समय तक बने रहना चाहिए जब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था न तैयार कर ली जाए जो प्रत्येक गांव में उन सदस्यों को पहुंचा सके जो विभिन्न विशेष विभाग पहुंचाना चाहते हैं। (पृष्ठ 468)

यह टिप्पणी काफी सही है यद्यपि इसमें लेखकों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उनका मकसद वास्तविक तथ्यों को केवल पेश कर देना था लेकिन इसमें भावी ग्राम सोवियतों के सिद्धांत का एक बुनियादी तत्व भी निहित है।



खण्ड चार

भारतीय जनता का आदीलन

## भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

ज्योंही गदर का खतरा सामने आता है भले ही यह गदर का रूप ले, राष्ट्रीयता की साथ भौमिक भावना की अभिव्यक्ति का ही रूप ले, उस क्षण अपने साम्राज्य का बनाए रखन की समस्त आशाओं पर पानी फिर जाता है यो उसे सुरक्षित रखने की हमारी इच्छा भी समाप्त हो जानी चाहिए।—जे० आर० सीले दि एक्सपेंशन आफ इंग्लड 1883

इससे पहले के अध्याया में हमने मुख्यतः इतिहास के विषय के रूप में भारतीय जनता की दुखद स्थिति का वर्णन किया है। अब हमारे सामने अपेक्षाकृत एक अधिब मुद्यत दृश्य है और वह है इतिहास के वर्तमान के रूप में भारतीय जनता की भूमिका। पूर्ववर्ती विशेषण ने उस स्थिति को और उन शक्तियों को हमारे सामने अनावृत करके रखन का प्रयास किया है जो भारतीय जनता के मुक्ति आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रही है और उसे अनिवाय बना रही हैं। अपनी पहली अवस्थाओं में यह आंदोलन अनिवायत विरोध शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक सघन का स्वरूप ग्रहण करता है और इसमें साथ ही यह सघन जमींदारों और सुदखारों के शोषण से मुक्ति के लिए किसानों द्वारा चलाए जा रहे सघन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की प्रगामी चेतना और जन आधार का इतिहास है जिसकी घुर्जात उदीयमान बुर्जुआ और ध्वंसार्थक के थोड़े से लोग न अपन अत्यधिक सीमित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की थी और इतिहास की प्रक्रिया के दौरान, जो अब बही जाकर अपने पूर्णस्वरूप और अपनी उपलब्धियाँ सब पट्टन रहा है तथा और भी दूरगामी सामाजिक मुक्ति के लिए रास्ता तयार कर रहा है।

## 1 एकता और अनेकता

साम्राज्यवाद के समयक शुरू शुरू के दिनों में एक विशेष प्रश्न किया करते थे जिस व आज भी बहुधा दुहराते हैं हालांकि अलग अलग अवस्थाओं में इस प्रश्न का स्वरूप बदला हुआ होता है। उनका प्रश्न है कि क्या भारत की जनता जैसी कोई चीज है? क्या उप-महाद्वीप जैसे विस्तारवादी विशाल भारतभूमि पर जातपात की दीवारों तथा भाषा एवं अन्य दूसरे कारणों से अनेक टुकड़ा में बंट विभिन्न नस्ल और धर्मों के लोगों के विविधतापूर्ण जमघट को, जिसके सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर भी व्यापक तौर पर भिन्न हैं एक 'राष्ट्र' माना जा सकता है या कभी वह एक 'राष्ट्र' बन सकता है? क्या यह बिलकुल ही बदली हुई परिस्थितियों में पश्चिमी अवधारणाओं का स्थानांतरण नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि भारत में जो एकमात्र एकता है वह ब्रिटिश शासन के जरिए थोपी गई एकता है?

इस बुनियादी प्रश्न के प्रति जो दृष्टिकोण है वह कई अवस्थाओं से गुजरा है। पुराने मत के साम्राज्यवादियों ने भारतीय राष्ट्र की प्रत्येक धारणा को तिरस्कारपूर्ण ढंग से ठुकरा दिया और इसे कल्पनामय कहा। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व को कम से कम साम्राज्यवादियों के उदार मतों तत्वों द्वारा व्यापक मायता मिली। फिर यह दलील दी जान लगी कि भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व का मायता दिए जान जैसी स्थितियों का विकास ब्रिटिश शासन की देन है और लोगों ने मन में अंगरेजों के उदारतावादी आदर्शों के घर कर जाने का नतीजा है। अभी बिलकुल हाल के वर्षों में भारत की अधिकाधिक जनता में राजनीतिक जागरूकता के पैदा न होने और उनके बहुराष्ट्रीय चरित्र के बटन हुए मकेत ने इस प्रश्न को एक नया आयाम दिया है। इस पहलू का, जिसे ठीक ही समझा जाता है कि यह किसी भी अर्थ में भारत की एकता के प्रतिकूल नहीं है 'पाकिस्तान' व इस विरोध प्रचार अभियान द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को 'दो राष्ट्र' के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। वेशक, साम्राज्यवाद के समयको ने इस वाद की दलील का पूरा पूरा लाभ उठाया है।

राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती शक्ति के सामने पुराने मत के साम्राज्यवादियों द्वारा दिए गए जवाब ने उनके सशक्ति सहज आत्मविश्वास को फीका कर दिया था। 1888 में सर जान स्ट्रेचो ने बड़े दृढ़ शब्दों में घोषणा की थी 'भारत जैसी कोई चीज नहीं है और न कभी होगी।' यह घोषणा करते समय उनकी मुद्रा कुछ बंनी ही थी जैसी किसी जिराफ का बहादुरी के साथ मुकाबला करते समय चिड़ियाघर के किसान की होती है

भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहली और अत्यावश्यक बात है यह जानना कि भारत जैसी कोई चीज या कोई देश नहीं है और न कभी होगा

जिगमे यूरोपीय विचारों के अनुसार भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक एकता जैसी कोई एकता हो। जिसके बारे में हम इतना कुछ सुनते हैं वैसे न तो कोई भारतीय राष्ट्र है और न कहीं 'भारत की जनता' है। (सर जान स्ट्रेची इंडिया, इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड प्रोग्रेस, 1888, पृष्ठ 5)

सर जान सीले की भी धारणा यही थी

भारत को एक राष्ट्र मानने की धारणा उस भट्टी भूल पर आधारित है जिसमें राजनीतिशास्त्र मुख्यतया दूर करना चाहता है। भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है बल्कि यह यूरोप या अफ्रीका की तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह किसी एक राष्ट्र या एक भाषा को सीमा रेखा को नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों और अनेक भाषाओं की सीमा का अवन करता है। (सर जान सीले दि एक्सपेंशन आफ इंग्लैंड, 1883, पृष्ठ 254-7)

'सम्मान क्या है?' सर जान फ्लस्टाफ ने सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, 'एक शब्द।' उस शब्द 'सम्मान' में क्या है, वह सम्मान क्या है? एक दिखावा। उसी महान यथार्थवाद की भावना में हमारे आधुनिक सर जान महाशयो ने विदेशी शासन से भुक्ति के लिए करोड़ों भारतीयों के सपनों को एक 'भट्टी भूल' साबित किया है। इसी प्रकार आस्ट्रियाई साम्राज्य के सिद्धांतकारों ने अपने सतोंप के लिए यह साबित कर दिया था कि इटली एक 'भौगोलिक अभिव्यक्ति' है।

उन प्रारंभिक दिनों में इन देशों के अस्तित्व को बड़े साफ शब्दों में नकारने की प्रवृत्तियों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र धारा में कोई रुकावट नहीं आई और तब बादशाह कानुनों के दरबारियों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब यह दलील दी जाने लगी है कि साम्राज्यवाद द्वारा पहले तो नकारने और बाद में उसे समाप्त करने की असफल कोशिश के बावजूद यदि आज भारतीय राष्ट्र जैसी कोई चीज है तो यह जाहिर है कि इसका थप ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियाँ को दिया जाना चाहिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्र अस्तित्व में आया है। इस दावे का किस अर्थ तक ऐतिहासिक औचित्य था, इस पर हम अगले अनुच्छेद में विचार करेंगे।

समस्याओं पर आम जनता की जानकारी के लिए तथाकथित सूचनाप्रद दस्तावेज के रूप में इसका बड़े पैमाने पर वितरण किया गया था। इस अविस्मरणीय दस्तावेज के प्रारम्भ में ही बड़े इत्मीनान के साथ घोषणा की गई थी कि जिस 'भारत का राष्ट्रवादी आन्दोलन' कहा जाता है, वह वस्तुतः 'भारत की विशाल आबादी के केवल एक भागूली हिस्से की लकाधाओं को सीधे सीधे प्रभावित करता है।' इस फैसले के पीछे कितनी कुशाग्र अत दृष्टि काम कर रही थी इसका पता इस घोषणा के फौरन बाद ही उस समय चल गया जब 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप और 1937 के चुनाव के परिणाम सामने आए। इस घोषणा के बाद रिपाट में भारत की जो रुढ़िगत तस्वीर पेश की गई थी उसके बारे में हालांकि लेखकों ने हमेशा यह दावा किया कि उनका विवेचन विशुद्ध वैज्ञानिक निष्पक्ष और वस्तुगत है पर अपने विवेचन के जरिए वे पाठक को आतंकित करना चाहते थे। अपने विवेचन में वे कभी 'भारत की समस्या' की 'विशालता और कठिनाई' का वर्णन करते हैं तो कभी 'भारत की विशाल जनसंख्या और भारत के विशाल क्षेत्रफल' का हवाला देकर पाठकों को आतंकित करते हैं, कभी '222 बोलियों' का उल्लेख करके यहाँ की 'भाषा की समस्या' का वर्णन करते हैं तो कभी 'असंख्य जातियों के कारण उत्पन्न जटिलता' की चर्चा करते हैं, कभी 'धार्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली लगभग असीम विविधता' का और हिंदुआ तथा मुसलमानों के 'बुनियादी विरोध' का जिक्र करते हैं तो कभी 'विभिन्न जातियाँ और धर्मों के रंग बिरंग जमघट' का चित्र पेश करते हैं। कभी 'विभिन्न नस्ल और धर्मों के जमाव' के बारे में बताते हैं तो कभी 'तर्ह-तर्ह के लोगों के जनसमूहों के समुदाय' की चर्चा करते रहते हैं। इसी तरह के नम्रता और शिष्टता से भरे तमाम वाक्य इस खंड में भर पड़े हैं।

इस रवैये का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। दरअसल इसके जरिए उन पाठकों को मन में जो किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं है, यह धारणा बैठाना है कि 'भारत में तेजी से स्वशासन स्थापित करने की योजना असंभव है और साथ ही पाठकों को इसी मुख्य नतीजे पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया जाता है ('एच० डब्ल्यू० नेविमन ने एक' समाजवादी पत्रिका में इस रिपोर्ट की समीक्षा की थी और पूरी सदभावना के साथ यह समीक्षा की गई थी। उनके शब्दों में इसे देखें)

एक ऐसे छोट महाद्वीप के अनुकूल सविधान या सरकार के स्वरूप की रचना (न कि आलोचना) के काम में अत्यंत दुस्तर कठिनाईयाँ हैं, जिसमें 560 देशी रिमासमें (नाममात्र के लिए स्वतंत्र) हैं 222 विभिन्न भाषाओंवाली जातियाँ हैं दो प्रमुख और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण धर्म हैं (अकेले ब्रिटिश भारत में 16 करोड़ 80 लाख हिंदू और 6 करोड़ मुसलमान) 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जाति से निकाले गए हैं या 'उत्पीड़ित' हैं और जिन्हें 'अछूत' कहा जाता है भारत के बारे में जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है उस अपना अध्ययन शुरू करने के लिए इन दोस तथ्यों को जानना होगा। यदि उस इनकी जानकारी



जिसमें यूरोपीय निचारा के अनुसार भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक एकता जैसी कोई एयता हा । जिसके बारे म हम इतना कुछ सुनते आए हैं वैसे न तो कोई भारतीय राष्ट्र है और न वही 'भारत की जनता' है ।  
(सर जान स्ट्रेची इडिया, इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड प्रोग्रेस, 1888, पृष्ठ 5)

सर जान सीले की भी धारणा यही थी

भारत को एक राष्ट्र मानने की धारणा उस भद्दी भूल पर आधारित है जिसको राजनीतिशास्त्र मुख्यतया दूर करना चाहता है । भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है बल्कि यह यूरोप या अफ्रीका की तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है । यह किसी एक राष्ट्र या एक भाषा की सीमारेखा को नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों और अनेक भाषाओं की सीमा का अवन करता है । (सर जान सीले दि एक्सपेंशन आफ इंग्लैंड, 1883, पृष्ठ 254-7)

'सम्मान क्या है ?' सर जान फलस्टाफ ने सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, 'एक शब्द ।' उस शब्द 'सम्मान' में क्या है, वह सम्मान क्या है ? एक दिखावा । उसी गहन यथार्थवाद की भावना में हमारे आधुनिक 'सर जान' 'महाशयो ने विदेशी शासन में मुक्ति के लिए करोड़ों भारतीयों के सघन को एक' 'भद्दी भूल' साबित किया है । इसी प्रकार आस्ट्रियाई साम्राज्य के सिद्धांतकारी ने अपने सतोंप के लिए यह साबित कर दिया था कि इटली एक 'भौगोलिक अभिव्यक्ति' है ।

उन प्रारंभिक दिना में इन देशों के अस्तित्व को बड़े साफ शब्दों में नकारने की हरकतों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र धारा में कोई रूकावट नहीं आई और तब वांशाह कानुन के दरबारियों ने अपनी रणनीति बदल दी । अब यह दलील दी जाने लगी है कि साम्राज्यवाद द्वारा पहले तो नकारने और बाद में उसे समाप्त करने की असफल कोशिशों के बावजूद यदि आज भारतीय राष्ट्र जैसी कोई चीज है तो यह जाहिर है कि इसका घेय ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों को दिया जाना चाहिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्र अस्तित्व में आया है । इस दावे का किस अंश तक ऐतिहासिक औचित्य था, इस पर हम अगले अनुच्छेद में विचार करेंगे ।

भारत की विविधता को अपना आधार बनाने वाली दलील आज भी बहुत प्रचलित है । इसका आशय था तो भारत राष्ट्र को नकारना होता है या इसे मायता देने में वरती गई अत्यधिक धीमी रफ्तार का औचित्य ठहराना होता है । साइमन कमिशन की रिपोर्ट 'सर्वेक्षण खंड' में वह आज भी अपनी पूरी तहक भडक के साथ देखी जा सकती है । साइमन कमिशन की रिपोर्ट का यह खंड भारत के बारे में आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य के दुष्प्रचार का मुख्य हिस्सा है । इसे 1930 में प्रकाशित किया गया था और भारतीय

समस्याओं पर आम जनता की जानकारी के लिए तथाकथित सूचनाप्रद दस्तावेज के रूप में इसका बड़े पैमाने पर वितरण किया गया था। इस अविस्मरणीय दस्तावेज के प्रारम्भ में ही बड़े इत्मीनान के साथ घोषणा की गई थी कि जिसे 'भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन' कहा जाता है, वह वस्तुतः 'भारत की विशाल आबादी के केवल एक मामूली हिस्से की अकाशाओं को सीधे सीधे प्रभावित करता है।' इस फैसले के पीछे कितनी कुशाग्र अन्तर्दृष्टि काम कर रही थी इसका पता इस घोषणा के फौरन बाद ही उस समय चल गया जब 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप और 1937 के चुनावों के परिणाम सामने आए। इस घोषणा के बाद रिपोट में भारत की जा रूढ़िगत तस्वीर पेश की गई थी उसके बारे में हालांकि लेखकों ने हमें यह दावा किया कि उनका विवेचन विशुद्ध वैज्ञानिक निष्पक्ष और वस्तुगत है पर अपने विवेचन के जरिए वे पाठक को आतंकित करना चाहते थे। अपने विवेचन में वे कभी भारत की समस्या की 'विशालता और कठिनाई' का वर्णन करते हैं तो कभी भारत की 'विशाल जनसंख्या और भारत के विशाल क्षेत्रफल' का हवाला देकर पाठक को आतंकित करते हैं, कभी '222 बोलियों' का उल्लेख करके यहाँ की 'भाषा की समस्या' का वर्णन करते हैं तो कभी 'असंख्य जातियों के कारण उत्पन्न जटिलता' की चर्चा करते हैं, कभी 'धार्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली लगभग असीम विविधता' का और हिंदुओं तथा मुसलमानों के 'बुनियादी विरोध' का जिक्र करते हैं तो कभी 'विभिन्न जातियों और धर्मों के रंग बिरंग जमघट' का चित्र पेश करते हैं। कभी 'विभिन्न नस्लों और धर्मों के जमाव' के बारे में बताते हैं तो कभी तरह-तरह के लोगों के जनसमूहों के समुदायों की चर्चा करते रहते हैं इसी तरह के नम्रता और शिष्टता से भरे तमाम वाक्य इस खंड में भरे पड़े हैं।

इस रवैये का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। दरअसल इसके जरिए उन पाठकों के मन में जो किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, यह धारणा बैठाना है कि भारत में तभी से स्वशासन स्थापित करने की योजना असंभव है और साथ ही पाठकों को इसी मुख्य नतीजे पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया जाता है (एच० डब्ल्यू० नेविसन ने एक समाजवादी पत्रिका में इस रिपोट की समीक्षा की थी और पूरी सद्भावना के साथ यह समीक्षा की गई थी। उनके शब्दों में इसे देखें)

एक ऐसे छोटे महाद्वीप के अनुकूल सविधान या सरकार के स्वरूप की रचना (न कि आलोचना) के काम में अत्यंत दुस्तर कठिनाइयाँ हैं, जिसमें 560 देशी रिपब्लिक्स (नाममात्र के लिए स्वतंत्र) हैं, 222 विभिन्न भाषाओंवाली जातियाँ हैं, दो प्रमुख और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण धर्म हैं (अबने ब्रिटिश भारत में 16 करोड़ 80 लाख हिंदू और 6 करोड़ मुसलमान), 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जाति से निकाले गए हैं या 'उत्पीड़ित' हैं और जिन्हें 'अछूत' कहा जाता है भारत के बारे में जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है उसे अपना अध्ययन शुरू करने के लिए इन ठोस तथ्यों को जानना होगा। यदि उसे इनकी जानकारी

जिनम यूरोपीय विचारों के अनुसार भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक एकता जैसी कोई एतता हो। जिसके बारे में हम इतना कुछ सुनते आए हैं वैसे न तो कोई भारतीय राष्ट्र है और न वही 'भारत की जनता' है। (सर जान स्ट्रेची इंडिया, इट्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड प्रोग्रेस 1888, पृष्ठ 5)

सर जान सीले की भी धारणा यही थी

भारत को एक राष्ट्र मानने की धारणा उस भू-भूल पर आधारित है जिसको राजनीतिशास्त्र मुख्यतया दूर करना चाहता है। भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है बल्कि यह यूरोप या अफ्रीका की तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह किसी एक राष्ट्र या एक भाषा की सीमा रेखा को नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों और अनेक भाषाओं की सीमा का अंकन करता है। (सर जान सीले दि एक्सपैशन आफ इंग्लैंड 1883, पृष्ठ 254 7)

'सम्मान क्या है?' सर जान फलस्टाफ ने सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, एक शब्द। 'उस शब्द सम्मान' में क्या है, वह सम्मान क्या है? एक दिखावा। उसी गहन यथार्थवाद की भावना में हमारे आधुनिक 'सर जान' महाशयों ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए करोड़ों भारतीयों के सघन को एक 'भू-भूल' साबित किया है। इसी प्रकार आस्ट्रियाई साम्राज्य के सिद्धांतकारों ने अपने सत्ताप के लिए यह साबित कर दिया था कि इटली एक 'भौगोलिक अभिव्यक्ति' है।

उन प्रारंभिक दिनों में इन देशों के अस्तित्व की बड़े साफ शक्यों में नकारन की हरकतों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र धारा में कोई रूकावट नहीं आई और तब बादशाह वानुते के दरबारियों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब यह दलील दी जाने लगी है कि साम्राज्यवाद द्वारा पहले तो नकारन और बाद में उसे समाप्त करने की असफल काशिशों के बावजूद यदि आज भारतीय राष्ट्र जैसी कोई चीज है तो यह जाहिर है कि इसका श्रेय ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों को दिया जाना चाहिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्र अस्तित्व में आया है। इस दावे का किस अंश तक ऐतिहासिक औचित्य था, इस पर हम अगले अनुच्छेद में विचार करेंगे।

भारत की विविधता को अपना आधार बनाने वाली दलील आज भी बहुत प्रचलित है। इसका आशय था तो भारत राष्ट्र को नकारना होता है या इस मायता देने में बरती गई अत्यधिक धीमी रफ्तार का औचित्य ठहराना होता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट सर्वेक्षण खंड में वह आज भी अपनी पूरी तटक भडक के साथ देखी जा सकती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का यह खंड भारत के बारे में आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य के दुष्प्रचार का मुख्य हिस्सा है। इसे 1930 में प्रकाशित किया गया था और भारतीय

समस्याओं पर आम जनता की जानकारी के लिए तथाकथित सूचनाप्रद दस्तावेज के रूप में इसका बड़े पैमाने पर वितरण किया गया था। इस अविस्मरणीय दस्तावेज के प्रारंभ में ही बड़े इत्मीनान के साथ घोषणा की गई थी कि जिसे 'भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन' कहा जाता है वह वस्तुतः भारत की विशाल आबादी के केवल एक मामूली हिस्स की अकांक्षाओं को सीधे सीधे प्रभावित करता है।' इस फैसले के पीछे कितनी कुशाग्र अंतर्दृष्टि काम कर रही थी इसका पता इस घोषणा के फौरन बाद ही उम समय चल गया जब 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप और 1937 के चुनावों के परिणाम सामने आए। इस घोषणा के बाद गिफ्ट में भारत की जो हठिगत तत्त्वीय पेश की गई थी उसके बारे में हाताकि लखना न हमेशा यह दावा किया कि उनका विवेचन विशुद्ध वैज्ञानिक निष्पक्ष और बन्धुगत है पर अपने विवेचन के जरिए वे पाठकों को आतंकित करना चाहते थे। अपने विवेचन में वे कभी भारत की 'समस्या' की विशालता और 'ठिनई' का वर्णन करते हैं तो कभी भारत की 'विशाल जनसंख्या और भारत के विशाल क्षेत्रफल' का हवाला देकर पाठकों को आतंकित करते हैं, कभी '222 धोलियों' का उल्लेख करके यहाँ की 'भाषा की समस्या' का वर्णन करते हैं तो कभी 'असंख्य जातियों के कारण उत्पन्न जटिलता' की चर्चा करते हैं, कभी 'धार्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जगभग असीम विविधता' का और हिंदुओं तथा मुसलमानों के 'धुनियादी विराध' का जिक्र करते हैं तो कभी 'विभिन्न जातियों और धर्मों के रंग विरंग जमघट' का चित्र पेश करते हैं। कभी 'विभिन्न नस्ल और धर्मों के जमाव' के बारे में बताते हैं तो कभी तरह-तरह के लोगों के जनसमूहों के समुदायों की चर्चा करते रहते हैं, इसी तरह के नम्रता और शिष्टता से भरे तमाम वाक्य इस खंड में भर पड़े हैं।

इस रवैये का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। दरअसल इसके जरिए उन पाठकों के मन में जो किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, यह धारणा बैठाना है कि भारत में तेजी से स्वशासन स्थापित करने की योजना असंभव है और साथ ही पाठकों को इसी मुख्य नतीजे पर पहुँचाने के लिए प्रेरित किया जाता है (एच० डब्ल्यू० नर्विसन न एक् समाजवादी पत्रिका में इस रिपोर्ट की समीक्षा की थी और पूरी सद्भावना के साथ यह समीक्षा की गई थी। उनके शब्दों में इसे देखें)

एक ऐसे छोट महाद्वीप के अनुकूल संविधान या सरकार के स्वरूप की रचना (न कि आलोचना) के काम में अत्यंत दुस्तर 'ठिनई' है, जिनमें 560 दशौं रियासतों (नाममात के लिए स्वतंत्र) हैं, 222 विभिन्न भाषाभाषी जातियाँ हैं, दो प्रमुख और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण धर्म हैं (अकेले ब्रिटिश भारत में 16 करोड़ 80 लाख हिंदू और 6 करोड़ मुसलमान), 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जाति से निवाले गए हैं या 'उत्पीड़ित' हैं और जिन्हें 'अछूत' कहा जाता है भारत के बारे में जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है उसे अपना अध्ययन शुरू करने के लिए इन ठोस तथ्यों का जानना होगा। यदि उसे इनकी जानकारी

जिसमें यूरोपीय विचारा के अनुसार भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक एकता जैसी कोई एक्ता हो। जिसके बारे में हम इतना कुछ सुनते आए हैं वैसे न तो कोई भारतीय राष्ट्र है और न वही 'भारत की जनता' है। (सर जान स्ट्रेची इंडिया, दटस ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐंड प्रोग्रेस, 1888, पृष्ठ 5)

सर जान सीले की भी धारणा यही थी

भारत को एक राष्ट्र मानने की धारणा उस भद्दी भूल पर आधारित है जिसको राजनीतिशास्त्र मुप्यतया दूर करना चाहता है। भारत कोई राजनीतिक नाम नहीं है बल्कि यह यूरोप या अफ्रीका की तरह मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। यह किसी एक राष्ट्र या एक भाषा की सीमा रेखा को नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रों और अनेक भाषाओं की सीमा का अंकन करता है। (सर जान सीले दि एक्सपेंशन आफ इंग्लंड, 1883 पृष्ठ 254 7)

'सम्मान क्या है?' सर जान फलस्टाफ ने सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, 'एक शब्द।' उम शान 'सम्मान' में क्या है, वह सम्मान क्या है? एक दिखावा। उसी गहन यथार्थवाद की भावना में हमारे आधुनिक 'सर जान' 'महाशया ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए करोड़ों भारतीयों के सघन को एक' भद्दी भूल' साबित किया है। इसी प्रकार आस्ट्रियाई साम्राज्य के मित्रतावादी न अपने सतोप के लिए यह साबित कर दिया था कि इटली एक 'भौगोलिक अभिव्यक्ति' है।

उन प्रारंभिक दिनों में इन देशों के अस्तित्व की बड़े साफ शब्दों में नकारने की हरकतों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्र धारा में कोई रुकावट नहीं आई और तब बादशाह फानुते के दरबारिया ने अपनी रणनीति बदल दी। जब यह दलील दी जाने लगी है कि साम्राज्यवाद द्वारा पहले तो नकारने और बाद में उसे समाप्त करने की असफल कोशिशों के बावजूद यदि आज भारतीय राष्ट्र जैसी कोई चीज है तो यह जाहिर है कि इसका श्रेय ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियाँ को दिया जाना चाहिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्र अस्तित्व में आया है। इस दावे का किस अंश तक ऐतिहासिक औचित्य था, इस पर हम अगले अनुच्छेद में विचार करेंगे।

भारत की विविधता का अपना आधार बनाने वाली दलील आज भी बहुत प्रचलित है। इसका आशय था तो भारत राष्ट्र को नकारना होता है या इसे मायता देने में बरती गई अत्यधिक धीमी रफ्तार का औचित्य ठहराना होता है। साइमन कमिशन की रिपोर्ट 'सर्वेक्षण खंड' में वह आज भी अपनी पूरी तड़क भड़क के साथ देयी जा सकती है। साइमन कमिशन की रिपोर्ट का यह खंड भारत के बारे में आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य के दुष्प्रचार का मुख्य हिस्सा है। इसे 1930 में प्रकाशित किया गया था और भारतीय

समस्याओं पर आम जनता की जानकारी के लिए तथावधित सूचनाप्रद दस्तावेज के रूप में इसका उड़े पैमाने पर वितरण किया गया था। इस अविस्मरणीय दस्तावेज के प्रारम्भ में ही बड़े इत्मीनान के साथ घोषणा की गई थी कि जिसे 'भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन' कहा जाता है, वह वस्तुतः 'भारत की विशाल आबादी के केवल एक मामूली हिस्से की अकांक्षाओं को सीधे सीधे प्रभावित करता है।' इस फैसले के पीछे कितनी कुशाग्र अत-दृष्टि काम कर रही थी इसका पता इस घोषणा के फौरन बाद ही उस समय चल गया जब 1930-34 के संविनाय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप और 1937 के चुनावों के परिणाम सामने आए। इस घोषणा के बाद रिपोर्ट में भारत की जो रुढ़िगत तस्वीर पेश की गई थी उसके बारे में हानावि लखनो ने हमेशा यह दावा किया कि उनका विवेचन विशुद्ध वैज्ञानिक निष्पक्ष और वस्तुगत है पर अपने विवेचन के जरिए वे पाठक का आतंकित करना चाहते थे। अपने विवेचन में वे कभी 'भारत की समस्या' की विशालता और 'कठिनाई' का वर्णन करते हैं तो कभी भारत की 'विशाल जनसंख्या और भारत के विशाल क्षेत्रफल' का हवाला देकर पाठकों को आतंकित करने हैं, कभी '222 बोलियों' का उल्लेख करके यहां की 'भाषा की समस्या' का वर्णन करते हैं तो कभी असंख्य जातियों के कारण उत्पन्न जटिलता की चर्चा करते हैं, कभी 'धार्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली लगभग असीम विविधता' का और हिंदू आस्था तथा मुसलमानों के बुनियादी विरोध का जिक्र करते हैं तो कभी विभिन्न जातियों और धर्मों के रंग विरंग जमघट का चित्र पेश करते हैं। कभी विभिन्न नस्ला और धर्मों के जमाव के बारे में बताते हैं तो कभी 'तरह तरह के लोगों के जनसमूहों के समुदाय' की चर्चा करते रहते हैं, उसी तरह के नग्नता और शिष्टता में भरे तमाम वाक्य इस खंड में भरे पड़े हैं।

इस रवैये का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। दरअसल इसके जरिए उन पाठकों के मन में जो विभीषण प्रभाव में ग्रस्त नहीं है, यह धारणा बँढाना है कि भारत में तेजी से स्वशासन स्थापित करने की योजना असंभव है और साथ ही पाठक को इसी मुख्य नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है (एच० डब्ल्यू० नेबिसन ने एक समाजवादी पत्रिका में इस रिपोर्ट की समीक्षा की थी और पूरी सद्भावना के साथ यह समीक्षा की गई थी। उनके मन्दा में इसे देखें)

एक ऐसे छोटे महाद्वीप के अनुकूल संविधान या सरकार के स्वरूप की रचना (न कि आलाचना) के काम में अत्यंत दुस्तर कठिनाइयाँ हैं, जिसमें 560 देशी रियासतें (नाममात्र के लिए स्वतंत्र) हैं, 222 विभिन्न भाषाओंवाली जातियाँ हैं, दो प्रमुख और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण धर्म हैं (अकेले ब्रिटिश भारत में 16 करोड़ 80 लाख हिंदू और 6 करोड़ मुसलमान), 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जाति से निकले गए हैं या उत्पीड़ित हैं और जिन्हें 'अछूत' कहा जाता है। भारत के बारे में जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है उसे अपना अध्ययन 'गुरु' करने के लिए इन ठीम तथ्यों को जानना होगा। यदि उसे इनकी जानकारी

नहीं है ता उसे रिपोर्ट का पड 1 पडना चाहिए । यदि वह इह न तो जानता है जीर न पडता है तो वह वेशक चीन से पडा रहे । (एच० डब्ल्यू नैविसन, 'यू लीडर' के 27 जून 1930 के अक मे साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा)

भारत के बारे मे जो खूबिया अस्तित्वार किया गया और जिस तरीके से इसे प्रचारित किया गया उस तरीके की सफलता का प्रमाण इसी से मिलता है कि एच० डब्ल्यू० नैविसन जैसे वामपथी हमदद भी एक 'समाजवादी' पत्रिका मे इसी तरह के नतीजे पर पहुंचते हैं । साइमन कमीशन के इस प्रचार का सरकारी समाचारपत्रों मे ही नहीं बल्कि उस समय के उदारवादी श्रमिक या 'समाजवादी' सभी वामपथी समाचारपत्रों ने स्वीकार कर लिया । सभी ने इस सरकारी प्रचार को प्रत्यक्षत दिखाई पडने वाले आधार पर स्वीकार कर लिया । सचाई तो यह है कि निष्पक्षता और राजनीतिनो की तरह अवाछनीय तथ्या को मायता देने के ढांग के बावजूद ये बातें दुष्प्रचार और नग्न प्रचार थी । ये किसी भी हालत मे ऐसे बुनियादी 'ठोस तथ्य' नहीं थे जो भारत के बारे मे जानकारी हासिल करने के इच्छु व्यक्ति को जरूर जानने चाहिए ।' इन तथ्यों का चयन करने मे पूरी सतकता बरती गई थी और यह सब जानबूझकर इस मकसद से किया गया था ताकि इन तथ्यों के मूल मे जो बातें है उह भी तोड मरोड कर प्रस्तुत किया जाए । आज के भारत की कल्पित 'समस्याओं' के बारे मे सरकारी स्तर पर जो तस्वीर पेश की गई है उसमे उन सभी तथ्यों को छिपाया गया है जो भारत की मौजूदा हालत को वास्तविक तौर पर समझने के लिए जरूरी है, इसमे साम्राज्यवादिया द्वारा भारत के शोषण की सभी सचाइयों पर भारत मे ब्रिटिश महाजनी पूजी की भूमिका पर, ब्रिटिश सत्तारूढ वग द्वारा कमाण गए मुनाफे पर शोषण के उन तरीका पर जो जनता के दुख दद के कारण हैं, जनता के उभरते सघर्षों पर (जातिगत या धार्मिक भेदभाव से निरपेक्ष रहकर) और साम्राज्यवाद द्वारा उस सघर्ष के दमन के तरीको पर परदा डाला गया है । बुनियादी 'ठोस तथ्य' तो ये हैं जिनके बारे मे किसी ईमानदार समाजवादी पत्रिका या जनवादी पत्रिका को घोषणा करनी चाहिए थी कि ये हैं वे तथ्य जिहें भारत के बारे मे जानकारी हासिल करने के इच्छु लोगो को अवश्य जानना चाहिए ।' इसके बजाय इस रिपोर्ट ने ('साइमन कमीशन ने अपना काम साहस के साथ और पूरी तरह किया जहा तक इस पहली रिपोर्ट का प्रश्न है सर जान साइमन और उनके सहयोगियों ने अपना नाम जितनी समझदारी के साथ किया उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए । मुझे इसमे सदेह है कि वहद उग्र राष्ट्रवादी भी बड़े बड़े तथ्यों के बारे मे कोई गभीर भूल निकाल पाएंगे', (फेनरब्राक्के 'यू लीडर', 13 जून 1930 मे) उन सभी तथ्या की बड़े प्रेम और विस्तार के साथ चर्चा की जा भारत की जनता के प्रतिकूल थे और जिनसे 'फूट डालो और राज करो' की सरकारी नीति को बल मिलता था ।

अमरीका के किसी नागरिक को यदि उसने देश की स्थिति के बारे मे किए गए निष्पक्ष

सर्वेक्षण से सबधित ब्रिटेन की निम्न अधिकृत रिपोर्ट पढ़ने को मिले तो वह हैरान रह जाएगा

अमरीकी उपमहाद्वीप की खास बात यह है कि उसकी जलवायु और भौगोलिक विशेषताएँ अत्यंत विविधता लिए हुए हैं और इसी प्रकार वहाँ की जनता की जातियों और धर्मों में बड़ी विविधताएँ हैं। अमरीका को एक इकाई मानने की प्रचलित धारणा से कोई साधारण ब्रिटिश प्रेक्षक इस जोखे में आ सकता है कि यहाँ उन विभिन्न नस्लों और धर्मों का जमाव है जिनसे मिलकर अमरीका का अस्तित्व है। अबेले 'यूयाक' शहर में लगभग 100 विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ की संख्या तो इतनी अधिक है कि यूयाक एक साथ ही इतालवियों, यहूदियों और नीग्रो लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा जा सकता है। इस तरह के विविध तत्वों के पास पास रहने के कारण अत्यंत भयंकर सांप्रदायिक संघर्ष भी हुए हैं। खामतीर से दक्षिणी राज्यों में इसकी वजह से नस्लवादी दंगे और हत्याएँ हुई हैं जिनकी पुनरावृत्ति तभी रोकी जा सकती है जब कोई ऐसी बाहरी निष्पक्ष शक्ति तैनात की गई जो कानून और व्यवस्था लागू कर सके। 'यूयाक' में शिकागो के हथियारबंद डाकूओं और चीनी कोठियों के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों की कुत्साति ने लोगों का ध्यान जिन मामलों से हटाया वे कम महत्वपूर्ण नहीं थे मसलन ऊटा में मोरमोस के, मिनेसोटा में फिनलैंडवासियों के, मिसिसिपी तक मैक्सिकी जाप्रवाम तथा पश्चिमी तट पर जापानियों के पृथक् अस्तित्व की समस्या। आदिम निवासियों की उल्लेखनीय संख्या के अस्तित्व की तो बात अलग रही।<sup>1</sup>

फिर भी, यही वह भावना थी जिसके अंतर्गत साइमन बमीशन ने भारत की स्थिति के सर्वेक्षण का काम पूरा किया।

निश्चय ही अमरीकी क्रांति की पूर्वसंध्या तक अंगरेजों को लागू अमरीकी जनता के बारे में भी ऐसे ही विश्लेषण किया करते थे और इस बात के 'प्रमाण' दिया करते थे कि अमरीकी जनता को एकजुटता असंभव है। लेकिन अपने इतिहास में इसका उल्लेख किया है

अंगरेजों के वंशजों के साथ भारी सत्या में डच, जर्मन, फ्रांसीसी, स्वीडिश, स्कॉच और आयरिश लोगों ने उपनिवेशों का एक ऐसा पंचमेल चरित्र बनाया और उन्होंने सरकार, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक हित और सामाजिक रूप की इतनी किस्मों की रचना की कि क्रांति से पहले तमाम लोगों को इस बात में संदेह था कि उनके बीच कोई एकता हो सकती है। (डब्ल्यू० ई० एच० लेवी 'हिन्ट्री आफ इंग्लैंड इन दि एंटीय सेचुरी' पृष्ठ 14, पृष्ठ 12)



और पुनः ,

एक ऐसा देश जहाँ बगन वाले लागे का इतना बड़ा अनुपात अनग अनग इसी और अलग अलग धर्मों का हा और जा हाल में आए आप्रवासी हैं, जहाँ अत्यंत विशाल प्रदेश और अविकसित मत्तार गाधना के कारण उनमें बीच एक दूसरे से बड़ा मामूली सा संपर्क बाधित हो रहा है और जहाँ पैसा बर्मान की प्रवृत्ति आश्चर्यजनक रूप से बहुत तीव्र है। वहाँ इस बात की बहुत कम सम्भावना थी कि देशभक्ति या समुदाय की भावना उत्पन्न हो गये। (यही, पृष्ठ 34)

यन्त्रों ने 1759 और 1760 में उत्तरी अमरीकी उपनिवेशों की यात्रा की थी और लिखा था

आग और पानी में भी उतनी निपमता नहीं है जितनी उत्तरी अमरीका के विभिन्न उपनिवेशों में है—यदि मानव मस्तिष्क के बारे में मैं पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हूँ तो मरा दयालु है कि विभिन्न उपनिवेशों के स्वरूपों और तरीकों में, स्वायत्त में इतना फर्क है कि यदि उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो शीघ्र ही उपमहाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, जबकि रैंड इंडियन और नीग्रो लोग बड़ी आतुरता से उस अवसर के इंतजार में रहेंगे जब वे उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दें।

विषयात् अमरीकी देशभक्त ओटिस ने 1765 में लिखा

ईश्वर न कर कि ये लोग कभी अपनी मातृभूमि के प्रति वक्तव्यच्युत साजित हों। यदि कभी ऐसा दिन आया तो यह एक भयंकर दृश्य की शुरुआत होगी। यदि आने वाले कल में इन उपनिवेशों को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने का कह दिया जाए तो अमरीका रक्तपातमय वधस्थल बनकर रह जाएगा जहाँ सब कुछ अस्तव्यस्त होगा।

इस प्रकार आधुनिक कट्टरपंथियों की ये भविष्यवाणियाँ कि, यदि अंगरेजों ने भारत छोड़ दिया तो 'हयाबाड और गढ़बडी की उबाऊ चीख और बालाहल से वातावरण भर जाएगा' (चर्चित), उसी जानी पहचानी राग की पुनरावृत्ति है। इसलिए एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की विजय की पूर्वसंध्या में किसी साम्राज्य के शासकों की ओर से की जा रही इन स्वायत्त भविष्यवाणियों और तथ्यों की प्रस्तुति के प्रति जनताविक्रम चेतना के लोगों को मजबूत रहना होगा।

बीते हुए कल के भारत में किस सीमा तक एकता थी और किस सीमा तक विघटन था

यह प्रश्न इतिहासकारों के लिए छोड़ा जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि आधुनिक युग के इतिहासविषयक अनुसंधानकर्ता, यहाँ तक कि साम्राज्यवाद का समर्थन करने वाले इतिहासकार भी उनमें शामिल हैं, अब उन बातों का समर्थन नहीं करते जो 50 वर्ष पूर्व सीले और स्ट्रेचे जैसे लोगों ने कही थी। उनके कथन वेहद अपर्याप्त जानकारी पर आधारित थे।

समस्त भारत की राजनीतिक एकता यद्यपि कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई लेकिन वह सदियों से जनता का आदर्श रही है। संस्कृत भाषा का साहित्य देखने से चक्रवर्ती राजाओं की सावभौम प्रभुसत्ता की धारणा का पता चलता है और इसपर अनेक अभिलेखों में जोर दिया गया है। महाभारत की कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में विभिन्न राष्ट्रों के एकत्र होने की कहानी से यह पता चलता है कि समस्त भारतीय जनता, जिनमें पुर दक्षिण के लोग भी शामिल थे वास्तविक बंधन द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए थे—और उनकी चिन्ताएँ समान रूप से सभी लोगों के लिए थीं। यूरोप के लेखकों ने एक तरह से यह नियम बना लिया है कि वे भारतीयों की एकता के बारे में बताने के बजाय उनकी अनेकता के बारे में ज्यादा बताएँगे। असाधारण रूप से स्वतंत्र भावनाओं के लेखक जोसेफ कर्निघम इस मामले में एक अपवाद हैं। 1845 में अंगरेजों के हमले के बारे में सिक्खों के भय का वर्णन करते हुए जोसेफ कर्निघम ने बहुत सही ढंग से स्थितियों का निरीक्षण किया और कहा कि काबुल से लेकर असम की घाटी तक और श्रीलंका द्वीप तक हिंदुस्तान एक देश माना जाता है और जनता के मस्तिष्क में इसमें अविराज्य के बारे में जो धारणा है वह किसी एक अधिपति या एक नस्ल के आधिपत्य से जुड़ी हुई है।<sup>1</sup> इसलिए भारत आज भी और दो हजार वर्षों से भी अधिक समय से एक आदर्श 'राजनीतिक' एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में एक गहरी बुनियादी एकता है जो भौगोलिक अलगाव या राजनीतिक अधिराज्य से उत्पन्न स्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली है। यह एकता खून, रंग, भाषा, पोशाक, तौर तरीके और संप्रदाय जैसी असंख्य विभिन्नताओं से परे है। (विनसेंट ए० म्मिथ दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, 1919, भूमिका पृष्ठ 9-10)

इस समय जो विचारणीय विषय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि फिलहाल भारत में कितनी एकरा है और कितनी विभिन्नता है और तब उन विभिन्नताओं के बारे में कुछ कहना जरूरी हो जाता है जिनका साम्राज्यवादी प्रचारका ने काफी प्रचार किया है और जिनके कारण वे यह दलील देते हैं कि भारत के लोगों को स्वराज्य देना अभी उचित नहीं है तथा अंगरेजी राज्य का कायम रहना यहाँ की जनता के लिए जरूरी है।

## 2 जाति, धर्म और भाषा के प्रश्न

इसमें कोई सदेह नहीं कि भारत की जनता को अतीत से विरासत के रूप में तमाम तरह की समस्याएँ भेद और असमानताएँ मिली हैं जिनपर उन्हें काबू पाना है और जो बीते हुए जमाने के अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। हर देश की जनता की कुछ अपनी विशिष्ट समस्याएँ होती हैं जो उसे अपने इतिहास से विरासत में मिलती हैं। स्वशासन स्थापित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसी के द्वारा भारतीय जनता के प्रगतिशील नेताओं को इन समस्याओं से निपटने और उन्हें हल करने का मौका मिलेगा और वे भारत की जनता को जनवादी एवं सामाजिक प्रगति के रास्ते पर ले जा सकेंगे। इसका कारण यह है कि पिछले 50 वर्षों में खासतौर से यह महसूस किया गया है कि साम्राज्यवादी पतन के आधुनिक युग में (19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में ब्रिटिश शासन की वस्तुगत रूप से प्रगतिशील भूमिका की समाप्ति के साथ) छुआछूत, जातपात के भेदभाव सांप्रदायिक भेदभाव निरक्षरता और इस तरह की बुराइयों का विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिनिधियों द्वारा अधिक सक्रियता से हमला किया जा रहा है जबकि साम्राज्यवाद सुधार सबधी तमाम योजनाओं के रास्ते में अड़चन डाल रहा है ताकि ये बुराईयाँ बनी रहें कभी न समाप्त हों और इनकी जड़ गहरी होती जाए।

ऐसी नीति स्वयं ही अपने को निंदनीय बना देती है जो एक तरफ तो गुलाम जनता की फूट और पिछड़ेपन का पोषण करती हो और उसको मजबूत बनाती हो तथा दूसरी तरफ सावजनिक रूप से यह छिडोरा पीटती हो कि इन बुराइयों से यह बात साबित हो जाती है कि वहाँ की जनता न तो कभी अपने अंदर एकता महसूस कर सकती है और न स्वराज्य के योग्य बन सकती है।

जहाँ तक सांप्रदायिक और धार्मिक भेदभाव का प्रश्न है जो भारत की जनता के सामने अत्यंत गंभीर और आवश्यक समस्या है, इस पर बाद के अध्याय में विस्तार से विवेचन की जरूरत है (देखें अध्याय 13 उपशीर्षक 2,3)। इस बात का प्रमाण मिल जाएंगे कि वस्तुतः सांप्रदायिक और धार्मिक भेदभाव को ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक सतक नीति के अंतर्गत काफी उठावा दिया है हालांकि मर्यादित तौर पर वे इससे इकार करते हैं। दरअसल साइमन कमिशन को स्वयं अपनी रिपोर्ट में यह मानना पड़ा कि जिन प्रदेशों में प्रत्यक्ष रूप से अंगरेजों का शासन है वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच बरभाव का बढ़ना एक खास विशेषता है ('आज की भारतीय रियासतों में सांप्रदायिक तनाव का अपभ्रान्त न हाना,' पृष्ठ 29) और अंगरेजों की गलती में इसमें बढ़ि हुई है ('ब्रिटिश भारत में एक पीढ़ी पहले तक सांप्रदायिक तनाव में जनजीवन की शांति भंग होने का घतरा बहुत कम था लेकिन सुधारों की गुरुआत और उन सुधारों के बाद की स्थिति के पूर्वानुमानों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक नया मोड़ दिया,' पृष्ठ 29)। निश्चय ही सांप्रदायिक समस्या तब तक पूरी तरह हल नहीं की जा सकती जब तक साम्राज्यवादी

शासकों को हटा नहीं दिया जाता। यही बात भारतीय रियासतों या रजवाड़ों के साथ लागू होती है। इनको पूरी तरह जंगरेजों का मरक्षण प्राप्त है। इस सरक्षण की वजह से ही इनका खच चलता है तथा इनका अस्तित्व बना रहता है।

जहां तक जातपात और छूत अछूत के भेदभाव का प्रश्न है इन भेदभावों के विरुद्ध काल्टल क्लब और रंगभेद [प्रसंगवश, मूलतः जाति (कास्ट) शब्द का अर्थ 'रंग' होता है और इससे आय हमलावरों की श्रेष्ठता और विशिष्टता का पता चलता है] के प्रतिनिधियों के उग्र रोष को ब्रिटेन के उन झाड़दारों द्वारा भी पूरे गुण दोष विवेचन के साथ पढ़ा जा सकता है जिनकी स्थिति एकदम गिन्न है और जिन्हें जैसाकि सभी जानते हैं, बड़े सहज ढंग से मेफयेर के भोजनवक्ष में निमज्जित किया जाता है। अछूतों तथा उत्पीड़ित वर्गों पर साम्राज्यवादियों की इतनी कृपा है कि वे मंदा उनकी सख्या बढ़ाते रहने का प्रयत्न करते आए हैं और हम इसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। एक पीढ़ी पहले तक, जब राजनीतिक स्थिति इतनी उग्र नहीं थी, झाड़ों सख्या आमतौर से 3 करोड़ बताई जाती थी। 1910 में वैंलेटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक 'इंडियन जनरेस्ट' में यह सख्या 5 करोड़ बताई। एस्टे की पुस्तक 'इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया' सत्रसे पहले 1929 में प्रकाशित हुई और उसमें बिना किसी प्रमाण के इस सख्या को 6 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। इस सख्या को आमतौर से सभामंचों और सदन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया। माइन इंडिया नाम से अधिसरकारी निबंध संग्रह 1931 में सर जान कर्मिंग के संपादन में प्रकाशित हुआ जिसमें यह सख्या 3 करोड़ से 6 करोड़ तक बताई गई। साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सख्या 4 करोड़ 20 लाख निर्धारित करने का प्रयास किया लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि बंगाल, रायकुत प्रांत और बिहार तथा उड़ीसा प्रांत में जहां 4 करोड़ 30 लाख में से 2 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं, 'शैक्षणिक रूप से अस्पृश्यता और वास्तविक अंगमयता के बीच कम घनिष्ठ संबंध है और यदि खासतौर से छानबीन की जाए तो शायद यह पता चल सके कि स्कूलों, कुएं से जल लेने और ऐसे ही मामलों में समान अधिकारों से जिन्हें वंचित रखा गया है उनकी सख्या उन इलाकों के लिए उत्पीड़ित वर्ग की प्रस्तुत कुल सख्या से कम है।' (पृष्ठ 41) दक्षिण वस्तुतः कुल सख्या विवादास्पद है।

छुआछूत के विरुद्ध सघन का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि प्रगतिशील राष्ट्रीय आंदोलन ने किया। वस्तुतः इस मिलजुल में उस घटना को याद किया जा सकता है जब सदियों से अछूतों के लिए वर्जित दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दरवाजे गांधी के आंदोलन की प्रेरणा से 'ओपन दिए गए और इसने बाद अछूतों को मंदिर में घुसने से रोकने के लिए जंगरेज सरकार ने इस दलील के साथ वहां अपनी पुलिस भेजी थी कि अछूतों के मंदिर में प्रवेश में जनता की धार्मिक भावनाओं का ठेस लगगी और सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह जाता ही भावनाओं को रखा करे।

निश्चय ही ब्रिटिश सरकार को इस बात की फ़िक्र थी कि अछूतों या उत्पीड़ित वर्गों के लोगों की मतदाता सूची अलग में बनाई जाए और उनको अलग से अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजन की गारंटी दी जाए ताकि लोगों में और अधिक फूट पड़े तथा राष्ट्रीय कांग्रेस कमजोर पड़ जाए। इस तरह पृथक मतदाताओं की लंबी सूची में हरिजनों को जोड़ दिया गया (हालांकि व्यवहार में जो नतीजा सामने आया उसमें अलग प्रतिनिधि भेजन की बात का उल्लेखनीय सीमा तक पूर्ण संधि की कायप्रणाली में निष्प्रभावित कर दिया)। लेकिन सरकार के इस स्नेह के विषय में स्वयं अछूत लोगों का क्या विचार था इसका प्रमाण हरिजनों के महासंघ के नेता डा० अबेडकर के उस वक्तव्य से मिल जाता है जो उन्होंने 1930 में जखित भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया था। डा० अबेडकर को ब्रिटिश सरकार अछूतों का नेता और उनका प्रवक्ता मानती थी। अपने भाषण में डा० अबेडकर ने कहा था

मुझे आश्चर्य है कि ब्रिटिश सरकार हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का विज्ञापन इसलिए नहीं करती कि वह इन्हें दूर करना चाहती है बल्कि इसलिए करती है ताकि इसको वह भारत की राजनीतिक प्रगति को पीछे खींच ले जाने का एक बहाना बना सके। (दलित वर्गों के अखिल भारतीय अधिवेशन में डा० अबेडकर का अध्यक्षीय भाषण, अगस्त 1930)

डा० अबेडकर ने आगे कहा

अगरजा के आने में पहले आप अछूत प्रथा के कारण घृणित स्थितियों में रह रहे थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने अछूत प्रथा समाप्त करने के लिए कुछ किया ? अगरजा के आने से पहले आप गांव से पानी नहीं ले सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने कुएं से पानी लेने का अधिकार आपको दिलाया ? अगरजा के आने में पहले आप मंदिरों में नहीं जा सकते थे। क्या अब आप मंदिरों में जा सकते हैं ? अगरजा के आने से पहले आप पुलिस में भरती नहीं हो सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार आपको पुलिस सेवा में भरती करती है ? अगरजा के आने में पहले आप मेना में भरती नहीं हो सकते थे। क्या अब आप मेना में भरती हो सकते हैं ? उपस्थित जन ! इन प्रश्नों में से किसी का जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते। जिन लोगों ने इन दिनों में दश का शासन सभाला है उन्हें आपने लिए कुछ करना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपनों हालत में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई है। जहाँ तक आपनों बात है ब्रिटिश सरकार ने उन प्रवर्धों को उम्मीद रूप में स्वीकार किया है जिस रूप में उन्हें प्राप्त हुए। उसने बड़ी ईमानदारी के साथ उन्हें जैसा था तैसा बना रहने दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी चीनी नर्जी का जब नमूना दिखाने के लिए एक पुराना बाट दिया गया था ड्रग पुराने कोट में 'गुग्गुलु' आदि की ही तरह नष्ट बाट में

भी पत्रद लगा दिए ताकि यह पता चले कि उगने दिए गए नमूने की ठीक ठीक नकल कर दी। आप पर किए गए अमाय एक घुने घाव की तरह से बने रहें और उन्हें ठीक नहीं किया गया।

आपके निवा दूसरा कोई आपके दुःख दूर नहीं कर सकता और आप भी इन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में न आ जाए। जब तक अंगरेज सरकार बनी रहेगी तब तक सत्ता का एक अंश भी आपके हाथों में नहीं आएगा। केवल स्वराज के संविधान में ही आपको अपने हाथ में राजसत्ता लेने का मौका मिल सकता है और इसके बिना आप अपनी जनता का उद्धार नहीं कर सकते।

उत्पीड़ित वर्गों के हित और उनकी मुक्ति अनिवार्य रूप से भारतीय जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जुड़ी है। जातपात को घिसटती हुई प्रथा उपदेश देने या कोसते रहने से नहीं दूर होगी, वह आधुनिक उद्योग और राजनीतिक जनतंत्र के विवास से ही दूर होगी। नए सामाजिक संबंध और समान हित पुराने बंधनों का स्थान लेते जाएंगे। जैसा मार्क्स ने कहा

आधुनिक उद्योग धंधे मजदूरी के उस पुष्टतंत्री विभाजन को समाप्त कर देंगे जिसपर भारत की वह जाति व्यवस्था आधारित है जो भारत की प्रगति में रुकावट डालती है और भारत को शक्तिशाली नहीं मान देती। (मार्क्स प्यूब्लिक रेजल्ट्स आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 'यूमाव' ट्रिव्यून 8 अगस्त 1853)

मार्क्स ने 70 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी की थी वह कितनी सच थी, इसका प्रमाण 1921 की जनगणना रिपोर्ट से मिलता है

जमशदपुर जैसी जगहों में जहाँ आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग काम होता है कारखानों में सभी जातियाँ और नस्ल के लोग साथ-साथ काम करते हैं और उन्हें अपने बगल में काम कर रहे व्यक्ति की जाति का लेकर कोई चिन्ता नहीं रहती। (बिहार और उड़ीसा की जनगणना रिपोर्ट, 1921)

निस्संदेह उन विशेष असमयताओं के कारण जो अछूतों, हरिजनों या सरकारी भाषा में कहें तो अनुसूचित जातियों को कमजोर बनाती हैं, बड़ी गंभीर समस्याएँ पैदा हो गई हैं। इन्हीं विशेष असमयताओं और शिकायतों ने अनुसूचित जातियों के महासभ के विकास का आधार तैयार किया है और इस सभ को कुछ इलाकों में एक सीमा तक संगठित रूप से समर्थन भी मिला है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान मजदूर आंदोलन तथा जनतंत्र के विवास के जरिए और इन असमयताओं के निवारण के लिए जनवादी

राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में संघर्ष चलाकर किया जा सकता है। वर्गीय आधार पर इन गुटों का आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन चनाने के लिए पृथक्तावादी संगठन बनाकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जहां तक भाषाओं के भेद का सवाल है और '222 अलग अलग भाषाओं' की प्रसिद्ध उक्ति की बात है, हम एक बार फिर देखते हैं कि साम्राज्यवादियों ने अपने कुप्रचार के जरिए इस कठिनाई को बेहद बढ़ाबढ़ाकर पेश किया। जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनका उद्देश्य भोलेभाले लोगों को गुमराह करना था। विभिन्न विशेषज्ञों ने, जो 16 से लेकर 300 तक हैं, विभिन्न अनुमान पेश किए। इस विभिन्नता से ही पता चलता है कि इन अनुमानों के पीछे कौन से राजनीतिक स्वार्थ थे। 1901 की जनगणना में भाषाओं की संख्या 147 बताई गई थी। यदि हम 1921 की जनगणना रिपोर्ट से इसकी तुलना करें जिसे साइमन कमिशन की रिपोर्ट ने इस्तेमाल किया है तो हम दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि 1901 से 1921 के बीच जहां जनसंख्या 29 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 31 करोड़ 60 लाख हो गई (जिसी नई विदेशी आबादी की वृद्धि के बिना) वहीं वाली जाने वाली भाषाएं 147 से बढ़कर 222 हो गईं (किसी नए या बहुभाषी प्रदेश के शामिल हुए बिना)। सचमुच एक ही पीढ़ी के दौरान नई नई भाषाएं पैदा करने की अदभुत क्षमता भारतीयों में है।

लेकिन यदि थोड़े और विस्तार से जांच की जाए तो '222 विभिन्न भाषाओं' की इस वीरोचित पुराण क्या पर, जिसमें गैरभारतीय जनमत का इतना अधिक प्रभावित किया, और भी रोशनी पड़ सकती है।<sup>1</sup> जांच से पता चलता है कि इन 222 अलग अलग भाषाओं में से कम से कम 134 भाषाएं तिब्बती बर्मी उपबर्ग की भाषाएं हैं। इन 'भाषाओं' का स्वरूप क्या है? 1902 में प्रकाशित 'इपीरियल गजटियर ऑफ इंडिया' (खंड 1 पृष्ठ 390-394) में 103 हिंदी चीनी भाषाओं की पूरी सूची दी गई है जिससे इसपर प्रकाश पड़ता है। 103 भाषाओं की इस सूची से हम इन 'विभिन्न भाषाओं' के बोलने वालों की संख्या का पता चलता है जो, उदाहरण के लिए निम्न है

| भाषा   | बोलने वालों की संख्या |
|--------|-----------------------|
| बुर्मी | 4                     |
| आद्रो  | 1                     |
| बुर्मी | 11                    |
| भानु   | 15                    |
| आबा    | 26                    |
| ताइरोग | 12                    |
| नीरा   | 2                     |

जाहिर है कि मजदुरीयता के साधन के रूप में भाषा की जो दार्शनिक अवधारणा है उसमें हमें संशोधन करना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि जादू भाषा को केवल 1 आदमी बोलता है और नौरा नामक भाषा बोलने वाली की भी संख्या महान है, उसे दो व्यक्ति बोलते हैं।

यदि विस्तार से जांच करे और इस जांच का महत्व केवल इस तरह के साम्राज्यवादी पुनर्जागरण का भंडाफोड़ करना ही है, तो पता चलता है कि 1. तथाकथित हिंदी चीनी परिवार की 'भाषाओं' की संख्या 1901 में 92 से बढ़कर 1921 में 145 हो गई, 2. ये 'भाषाएँ' भारत में बिलकुल ही नहीं बोली जाती। ये हिमालय और बर्मा चीनी सीमा के दूरस्थ प्रदेशों में बोली जाती हैं, 3. इनमें से अधिकांश भाषाएँ किसी भी रूप में 'भाषा' नहीं हैं, या तो ये थोड़े लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियाँ हैं या जनजातियाँ के नाम हैं, 4. इस समूह में शामिल 103 भाषाओं में से 17 को 100 से भी कम व्यक्ति, 39 को 1,000 से भी कम व्यक्ति, 65 को 10,000 से भी कम व्यक्ति, 83 को 50,000 से भी कम व्यक्ति, 97 को 200,000 से भी कम व्यक्ति बोलते हैं। इस समूह की एकमात्र भाषा बर्मा है। फिर भी इस तरह की चीजों को जोड़कर '222 अलग अलग भाषाओं' की संख्या थप दी गई और इसे साम्राज्यवादियों ने प्रत्येक मंच से, प्रत्येक समाचारपत्र के जरिए और संसद की प्रत्येक बैठक में प्रदर्शित किया।

इसके बाद 1931 की जनगणना में भाषाओं की संख्या 203 ही रह गई। जाहिर है कि जिन भाषाओं को केवल एक, दो या चार व्यक्ति बोलते थे वे बेचारे इस बीच दुर्भाग्यवश मर गए और इसपर अपनी मूर्खतापूर्ण कायवाही के द्वारा उन लोगों ने भारतीय जनता की स्वराज्य की मांग के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दलील को कमजोर कर दिया। 1937 में बर्मा के भारत से अलग हो जाने के बाद भाषाओं की मृत्युसंख्या और भी बढ़ गई क्योंकि भारतीय जनता का टुकड़े टुकड़े में बाँटा होना साबित करने के लिए जिन सैंकड़ों भाषाओं की सूची गिनाई जाती थी उनमें से अधिकांश भाषाएँ (128) बर्मा की भाषाएँ थीं। दिलचस्प बात यह है कि बर्मा को अलग करने के पक्ष में दलील देने के लिए भाषाओं की बहुलता का अवरोध, जिसकी रचना मुख्यतः बर्मा पर आधारित थी—अचानक गायब हो गया और उसके स्थान पर बर्मा में भाषाओं की अनिवार्य एकता पर जोर दिया जाने लगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने लिखा है कि (पृष्ठ 79), 'हालांकि इस प्रांत में 128 देशी जवान हैं, फिर भी समूची आबादी का 70 प्रतिशत भाग बर्मा या इससे घनिष्ठ रूप से मिलती जुलती भाषा बोलता है और इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।' अपनी नीति के हित में साम्राज्यवादियों के आंकड़े सबमूख वित्तों से लचीले होते हैं।

भारत के लिए एक आम भाषा की समस्या का समाधान अब ढूँढ़ा जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस की अधिकाधिक राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी (लिपि के अनुसार हिंदी या उर्दू) को आधार बनाया गया है। इसे भारत की अधिकांश जनता या तो बोलती है या समझ



लेती है। गांधी ने लिखा था कि समूचे भारत में हिंदू धर्मोपदेशक या मुसलमान मौलवा अपने धार्मिक प्रवचन हिंदी और उर्दू में करते हैं और उन प्रवचना को बिना पढ़ी लिखी जनता भी अच्छी तरह समझ लेती है (‘स्पीचिंग एंड राइटिंग’, पृष्ठ 398)। इसी प्रकार भारतीय सेना में जहाँ ‘222 अलग अलग भाषाओं’ जैसी अनगल बातों के लिए कोई स्थान नहीं है सभी आदेश हिंदुस्तानी में दिए जाते हैं। भारत के बारे में बहुधा यह प्रचारित किया जाता है कि अंगरेजी यहाँ की सामान्य भाषा है लेकिन यह एक कपोल कल्पना है। 100 वर्षों की अंगरेजी ‘शिक्षा’ के बावजूद केवल एक प्रतिशत जनता अंगरेजी पढ़ या लिख सकती है (35 करोड़ लोगों में से केवल साढ़े तीन लाख लोग अंगरेजी पढ़ या लिख सकते हैं—1931 की जनगणना रिपोर्ट)। इसके विपरीत ‘हिंदुस्तानी का विभिन्न बोलियों में 12 करोड़ से भी अधिक लोग समझते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है’ (जवाहरलाल नेहरू, ‘इंडिया ऐंड दि वर्ल्ड’, पृष्ठ 118)। भारत में भाषाओं की समस्या व्यवहारतः 12 या 13 भाषाओं की समस्या है (सर हरकोट बटलर ने अपनी पुस्तक ‘माइन इंडिया’ में पृष्ठ 8 पर लिखा है कि भारत में ‘कुल 12 प्रमुख भाषाएँ हैं।’ यह पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई थी)। इन 12 या 13 भाषाओं में से उत्तर भारत की 9 भाषाओं का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि 1921 की जनगणना रिपोर्ट को भी यह स्वीकार करना पड़ा था

इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर तथा मध्य भारत की मुख्य भाषाओं में एक सामूहिक तत्व है जिसके कारण उन भाषाओं को बोलने वाले अपनी बालबाल में कोई खास तब्दीली किए बिना एक दूसरे की बातचीत समझ लेते हैं। इस प्रकार भारत के बहुत बड़े हिस्से के लिए समान भाषा का आधार पहले से ही तैयार है।’ (मेसर्स आफ इंडिया, 1921, पृष्ठ 1, भाग 1, पृष्ठ 199)<sup>4</sup>

साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यदि इस अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया गया होता तो यह ज्यादा ईमानदारी की बात होती लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ दूसरी तरह की ही बातें बहो गईं।

ये विशेष मामले, जिन्हें प्रायः तथाकथित ऐसी कठिन समस्याओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें भारतीय जनता की एग्रेसिव स्थापित करने या स्वराज्य की दिशा में तभी से बढ़ने के काम में अवरोध बताया जाता है, ऐसे हैं जिन्हें देश के राजनेताओं द्वारा हल किया जा सकता है और हल किया जाना है। उन्हीं समस्याओं के कारण यहाँ इतने विस्तार से विवेचन करने की आवश्यकता पड़ी ताकि लोगों को वह आधार बताया जा सके जिसपर साम्राज्यवाजियों का निरर्थक कुप्रचार टिका हुआ है। इसने साथ ही इस विवेचन की जरूरत इसलिए भी है ताकि भारत से बाहर रहने वाले जनवादी विचारधारा के लोगों का साम्राज्यवादी प्रचार से गुमराह होने से रखा जा सके।

साम्राज्यवाद विरोधी सघष में भारतीय जनता की वास्तविक एकता अपनी स्वाधीनता और अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं निर्धारित करने के उनके अधिकार के मदर्भ में भारतीय राष्ट्र का वास्तविक अस्तित्व है या नहीं है, इसका प्रमाण आकडेवाजों के दफतरो में या ससदा के बहम कथों में नहीं मिल सकता। यह वास्तविक कायस्थेत् में ही साबित किया जाएगा, किया जा रहा है और पिछले 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि किया जा चुका है। कारण यह है कि भारतीय जनता की अनेकता या बहु-राष्ट्रीय स्वरूप से इस दुनियादी एकता का कोई विरोध नहीं है। ये ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें स्वयं भारतीय जनता ही हल कर सकती है और हल करेगी।

### 3 भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत

आधुनिक युग में भारतीय राष्ट्र की वास्तविकता से व्यवहार रूप में अब अधिक समय तक इकार नहीं किया जा सकता हालाँकि पुराने इकार की गूज आज भी मौजूद है। इसलिए साम्राज्यवादियों ने अपनी उन दलीलों के सदभ में जिसे वे एक पीढ़ी पहले तक दुहराते आ रहे थे, एक अजीब भुलकड़पन का परिचय दिया। अभी तक वे भारत को 'एक भौगोलिक अभिव्यक्ति' कहा करते थे और उसके राष्ट्रीय अस्तित्व को अत्यंत हठधर्मिता-पूर्ण ढंग से मानने से इकार करते थे लेकिन अब साम्राज्यवादियों ने अपक्षाकृत अधिक चालाक प्रवृत्ताओं ने एक दूसरी दलील देनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि यदि भारतीय राष्ट्र का वही अस्तित्व है और यदि इसका अस्तित्व मानने की मजबूरी है तो इसे साम्राज्यवाद की गौरवपूर्ण उपलब्धि कहा जाना चाहिए क्योंकि उसने ही भारतीय राष्ट्रीय चेतना का मूलपात किया और ब्रिटन के जनतांत्रिक आदर्शों के बीज भारत में बोने। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक तरह के उद्देश्यपूर्ण बालदोष के कारण इसे गुरु से ही अंगरेजी का वास्तविक लक्ष्य माना जाना चाहिए।

भारत के लोगों का वह हिस्सा जिसमें राजनीतिक चेतना है—बौद्धिक रूप से हमारी सतान है। उन्होंने उन आदर्शों को आत्मसात कर लिया है जो हमने उनके सामने रखे और इसके लिए हमें उन्हें श्रेय देना चाहिए। वर्तमान बौद्धिक और नैतिक खलबली का अर्थ यह नहीं कि भारतीय जनता हमारी भत्सना कर रही है बल्कि यह हमारे काय के प्रति उनकी सराहना है। (मोटागू—चैम्सफोर्ड रिपोट, 1918, पृष्ठ 115)

इस प्रकार भारतीय जनता का साम्राज्यवाद विरोधी अदम्य सघष नहीं बल्कि साम्राज्यवादी शासकों के परोपकारी वृत्त्य भारतीय जनता की राष्ट्रीय स्वाधीनता का पथ प्रदर्शन पर रहे हैं। जनता के बीच आधुनिक मुमसूत साम्राज्यवादी शासन अपने भाषणों से इनी तरह का चित्त प्रस्तुत करना चाहते हैं। बीने हुए त्तिना में इन शासकों द्वारा जनता के बीच जो बातें कही जाती थीं उन्हें अब ऊपर के गरवारी रोमा में पुनर्चिपूण कहा जाता है और पहल में ही पर्याप्त रूप से परेशानी पैदा करने वाली स्थिति में नीति के दिग्गव से अवाछ-

नीय कहा जाता है (उदाहरण के लिए जायसन हक्स की प्रमुख घोषणा कि 'हमने भारतीयों के हित के लिए भारत पर विजय नहीं हासिल की। मुझे पता है कि मिशनरी बैठका' म कहा जाता है कि हमने भारतीयों का स्तर उठाने के लिए भारत पर शासन किया। ऐसा नहीं हो सकता। हमने तलवार के जोर से भारत का जीता है और इसी के जोर से कायम इस पर शासन कायम रखेंगे। यह ब्रिटिश सामानों का सबसे अच्छा बाजार है इसलिए हम यहाँ बने हुए हैं।' अथवा ताड रदरमीर का यह कथन कि 'अनेक अधिकारियों का यह अनुमान है कि ब्रिटेन का प्रमुख व्यापार बैकिंग और जहाजरानी व्यापार सीधे तौर पर भारत पर 20 प्रतिशत भिन्न करता है। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रमुख आधार है। यदि हम भारत को छोटे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य पहले आर्थिक रूप से और फिर राजनीतिक रूप से ढह जाएगा।')।

सरकारी वक्तव्यों के लहजे में आज के युग में कोई तब्दीली आई हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। किंतु सशयवादी को इस जिज्ञासा के लिए क्षमा किया जा सकता है। लहजे में आया यह परिवर्तन उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का कारण नहीं अपितु उसका परिणाम है। इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात नहीं होगी कि सरकारी वक्तव्यों को इस नए लहजे से साम्राज्यवादी नीति और शक्ति की ठोस वास्तविकताओं के प्रति या इस शक्ति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादियों द्वारा प्रत्येक साधन इस्तेमाल करने के इरादे के प्रति भ्रम पैदा हो (हर साधन का मतलब मशीनगनों सहित दमन के सभी प्रचलित हथियार)। नवीनतम ब्रिटिश योजना के प्रश्न पर विचार करते समय इन वास्तविकताओं पर विचार करना जरूरी होगा।

इस तरह की दलील का व्यावहारिक महत्व स्पष्ट है। आधुनिक साम्राज्यवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी पोषित सतान मानने का कृपापूर्ण दावा किया है और उसका यह दावा एक पतनशील शक्ति की निरीह आत्मभ्रांति तथा आत्मपरितुष्टि कदापि नहीं है। पिछड़ी हुई जनता को राष्ट्रीय चेतना और सभाव्य स्वराज्य की भावना (जिसे मार्क्सवाद की शब्दावली में उपनिवेशवाद की समाप्ति का सिद्धांत कहा जाता है) का प्रशिक्षण देने और इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद पहुँचाने के लिए एक सभ्य बनाने वाली व्यवस्था के रूप में साम्राज्यवाद के सिद्धांत को सबसे पहले मैकडोनाल्ड जैसे साम्राज्यवाद के चाकरा और गद्दार समाजवादियों के एक गुट ने पेश किया। उन्होंने बाद में साम्राज्यवाद की सभ्य बनाने वाली इस भूमिका की व्यावहारिक समझदारी का परिचय भारत में अपना आतंकपूर्ण शासन कायम करके और जनतांत्रिक अधिकारों की मांग के अपराध में 60 000 भारतीयों को कैद करके दिया। साम्राज्यवाद के आधुनिक प्रवक्ताओं ने अत्यंत व्यावहारिक मकसद से इस सिद्धांत को ग्रहण किया है। इसने निकलने वाले व्यावहारिक निष्कर्ष इस प्रकार होंगे कि उस हानत में समझदार और रचनात्मक भारतीय राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद को अपना दुश्मन मानना छोड़ देगा, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन त्यागकर इसके स्थान पर साम्राज्यवाद के साथ तालमेल बैठाना और सहयोग करना शुरू

करेगा और साम्राज्यवाद को अपना ऐसा पथप्रदर्शक तथा शिक्षक मानगा ज्ञा भविष्य के एक बलिष्ठ समय में, और वह भी साम्राज्यवादियों द्वारा निर्धारित समय में, भारतीय जनता को बड़े आराम के साथ धीरे धीरे एक अनिश्चित और अपरिभाषित स्वराज्य की दिशा में ले जाएगा।

क्या यह मानना सही है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन को सतान है और इसका परिणाम है? निस्संदेह एक अर्थ में उनका दावा सही है हालांकि यह दावा करने वाले जिस अर्थ में इस तरह के दावे करते हैं वह एवदम भिन्न है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि जापानी हमलावर चाहें तो यह दावा कर सकते हैं कि अपने आक्रमण के जरिए उन्होंने चीन की जनता में राष्ट्रीय एकात्मता कायम कराने में मदद की और वस्तुपरक दृष्टि से देखें तो उनका यह दावा सही है। इसी तरह चूंकि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म और विकास साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के दौरान हुआ है इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी यह दावा कर सकता है कि उसने ही इसके लिए स्थितियां तैयार की। इसी तरह जारशाही भी रूस में मजदूर वर्ग की विजय का सुत्रपान करने का दावा कर सकती है और चाल्स प्रथम इस बात का दावा कर सकता है कि उसने कामरेन की विजय के लिए परिस्थितियां तैयार की।

फिर भी, आधुनिक युग के साम्राज्यवाद समयका का यह मतलब नहीं है। वे यह कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन की सकारात्मक उपलब्धियों ने भारत के राजनीतिक एकीकरण और आधुनिक केंद्रीकृत प्रशासन के लिए ही नहीं (यहां उनके पक्ष में ठोस तर्क हैं) बल्कि ब्रिटिश वैधानिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को आरोपित करके और शिक्षा प्राप्त करने वाले एक मातृली अल्पमत के लिए 'अंगरेजी ढंग की' शिक्षा लागू करके अन्वि-बाय रूप से भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोया और पढ़े लिखे लोग के बीच संसदीय सरकार तथा जनतान्त्रिक स्वतंत्रता के अंगरेजी आदर्शों का आरापित किया। इंग्लैंड के इतिहास में लोगों को धीरे धीरे नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का पाठ पढ़ाया। अंगरेजों के राजनीतिक विचारों ने, जिन्हें बक और मिल ने अभिव्यक्ति दी, इस पाठ को और मजबूती से उनके दिलों में स्थापित किया। बुनियादी तौर पर कुशाग्र बुद्धिवाले और तेजी से उत्साह में आने वाले शिक्षित भारतीयों का ज्ञान का एक नया भंडार मिला।' (एल० एफ० रणब्रुन विवियम 'क्लाट एवाउट इंडिया?', 1928, पृ० 105)

इस दाव में किम हद तक सचाई है? आधुनिक युग की जनतांत्रिक चेतना का विकास बहुत से देशों में हुआ है और इंग्लैंड में बहुत शुरुआत हुआ था। यह कोई इंग्लैंड की ही चीज नहीं है। यह भी पक्का सही नहीं है कि जनतान्त्रिक प्रगति के बीज बोने के लिए किसी देश पर विदेशी प्रभुत्व होगा जरूरी है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से और उससे भी ज्यादा स्वतंत्रता, समानता और सद्भाव के आदर्शों से आतप्रोत फ्रांस की महान शक्ति से 19वीं सदी के जनतांत्रिक आंदोलन में जितनी प्रेरणा प्राप्त की उसनी

उसने इंग्लैंड से नहीं की जहाँ सत्राट और मसद के बीच समझौता हो गया था। 20वीं सदी में 1905 और 1917 की रूसी क्रांति ने जनता की ओर खासतौर से एशिया तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग करने वाले सभी उपनिवेशों की गुलाम जनता के बीच जागृति की लहर पैदा करने में विशिष्ट भूमिका अदा की।

भारत में जनता की जागृति का विकास सत्तार की इन्हीं धाराओं के साथ साथ हुआ है और विकास के विभिन्न चरणों द्वारा इसे दिखाया जा सकता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राममोहन राय ने जब 1830 में इंग्लैंड की यात्रा की तो उन्होंने तमाम असुविधाओं के बावजूद फ्रांसीसी जहाज पर यात्रा करने के लिए इसलिए जोर दिया ताकि वह फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित कर सकें। यह घटना स्मरणीय है। राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन मूलतः जनता के उभरते आंदोलन को रोकने के लिए और ब्रिटिश शासन की रक्षा के लिए सरकारी प्रेरणा से हुआ था, 20 वर्षों तक सोती रही और 1905 की महान जन उत्तेजना और हलचल के बाद पहली बार अपनी नींद से जगी। इसके बाद जब क्रांतिकारी लहर शांत हो गई तो वे फिर शांतभाव से स्वामिभक्ति का माग अपनाने लगी। और जब 1917 के बाद विश्व भर में क्रांतिकारी आंदोलन की लहर उठी तब वह फिर एक बार अपनी नींद से उठकर पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ चली।

इंग्लैंड ने अगर मध्यस्थता नहीं होती तो राष्ट्रीय और जनतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की इन विश्वधाराओं में भारत कभी हिस्सा न ले पाता, यह धारणा मूलतः पूर्ण है और ऐसा केवल आत्मतुष्टि के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत चीन का उदाहरण हमें बतलाता है कि किस प्रकार एक ऐसे देश में जहाँ साम्राज्यवाद पूरी तरह पहले कभी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका था राष्ट्रीय जनतांत्रिक अंतःप्रेरणा कितनी ज्यादा शक्ति के साथ आगे बढ़ सकी और अपने लिए जमीन तैयार कर सकी। और इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक मुक्ति आंदोलन को लगातार साम्राज्यवादी हमला और घुसपैठ के द्वारा थोपे गए अवरोधों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा।

क्या भारत में राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने मानकों से बक, मिल और मैकले पढ़ने की शिक्षा ली थी तथा ग्लैंडस्टोन और ब्राइट जैसे यत्नाओं के ससदीय भाषण में आनंद लेना सीखा था? साम्राज्यवादियों द्वारा प्रचारित कहानी कुछ इसी तरह की है। यह कहानी बहुत साधारण है और इसके समानांतर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक फ्रांस की स्थापना नपोलियन की दृष्टि से हुई या बंधोलिव कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म लूथर की व्यक्तिगत विलक्षणताओं में पैदा हुआ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन महा की सामाजिक परिस्थितियों से, साम्राज्यवाद की परिस्थितियों और उनकी घोषण प्रणाली में पैदा हुआ है। वह उन सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ है जो इस घोषण के कारण भारतीय समाज में उत्पन्न हो

गई है। उसके पैदा होने का कारण यह है कि भारत में पूँजीपतिवर्ग का उदय हुआ चुका है और चाहे शिक्षा की कौसी भी व्यवस्था क्या न होती ब्रिटिश पूँजीपतिवर्ग व प्रभुत्व के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। यदि भारत के पूँजीपतिवर्ग न केवल संस्कृत में लिखे वेदों का अध्ययन किया होता अथवा सभी तरह की विचारधाराओं से अलग हटकर मठों में ज्ञान प्राप्त किया होता तो निश्चय ही उसे संस्कृत वेदा में भी अपनी आजादी के सघष की प्रेरणा से भरपूर सिद्धांत मिल जाते।

जब मैकाले ने साम्राज्यवाद की तरफ से अंगरेजों पद्धति की शिक्षा भारतीयों पर थोप दी और प्राच्यविदों को परास्त कर दिया तो उसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना नहीं था बल्कि उस चेतना का पैदा होने से रोकने के लिए उसकी जड़ तक छेद डालना था। इस काम के पीछे ठीक वही भावना काम कर रही थी जो पुराने रूसी साम्राज्य की विजित जातियों के लिए रूसीकरण की जारशाही पद्धति के पीछे थी। मैकाले का उद्देश्य ऐसे विनीत आज्ञाकारी लागा का एक वर्ग तैयार करना था जो अपनी जनता से पूरी तरह बंटकर अंगरेजों की इच्छा की पूर्ति कर सके। जनतंत्र के बीज बोने की भावना के लिए मैकाले काम कर रहा था। इस प्रश्न पर उसके विचार बहुत स्पष्ट हैं। मैकाले ने ही यह घोषित किया था कि 'हम पता है कि भारत के पास कभी एक स्वतंत्र सरकार नहीं हो सकती लेकिन उसके पास दूसरे दर्जे की सर्वोत्तम चीज अर्थात् एक दृढ़ और निष्पक्ष तानाशाही हो सकती है।' साम्राज्यवाद की समूची प्रणाली में निहित अंतर्विरोध का ही यह परिणाम था कि शिक्षा की जो पद्धति कुशल साम्राज्यवादी प्रशासन के लिए थोपी गई थी उसी ने भारत के लोगों के लिए इंग्लैंड के जनतांत्रिक और लोकप्रिय आंदोलनों तथा जनसंघर्षों से और भारत में चल रहे अत्याचारों की ही तरह वे अत्याचारों से लड़ रहे मिन्टन, शोली तथा वायरन जैसे कमियाँ से प्रेरणा प्राप्त करने का भी रास्ता खोल दिया। यही यही तो इनका मुवाबला शासकवर्ग के उन्हीं पुलीत तत्वाँ, पिटी, हेम्टिंग्स और वेनिंगटो से होता था जो भारत पर शासन कर रहे थे और भारत का शोषण कर रहे थे। लेकिन यह ऐसा विरोधामास था जिसका पूर्वानुमान उस समय नहीं लगाया गया और तब से आज तक साम्राज्यवादियों की बाद की पीढ़ी ने<sup>१६</sup> जिन्होंने इसके दुष्परिणामों को ठालने की पूरी कोशिश की और इसने लिए भारत में पुस्तक पर सेंसरशिप बढ़ा दी, कभी इन स्थितियों पर सेट नहीं प्रकट किया।

भारत में अंगरेजी राज की या जिन शक्तियों ने भारत के लागा की इच्छा या अनिच्छा पूर्य और राष्ट्र व साज में डाला है उनकी एतिहासिक भूमिका को कम करने गि्यान की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही मान्यता का एक उद्धरण प्रस्तुत किया है (अध्याय 4 उपशोषक 4) जिसमें उन्होंने उस उपनगि के दो प्रमुख तत्वाँ के बारे में बताया है जिनके कारण भारत में ब्रिटिश शासन ने 'अत्यंत घृणित स्वाधों में प्रेरित होकर अनजान भारत के विकास के लिए 'इतिहास के माधन' का काम किया।

भारत पर अंगरेजों की विजय और अंगरेजों द्वारा भारत के शोषण की मजदूरी और महत्वपूर्ण देने या उसकी ध्वसात्मक भूमिका यह थी कि उसने भारत में पुरानी समाज-व्यवस्था का आधार निमज्जातपूर्वक नष्ट कर दिया। किसी भी तरह की प्रगति के लिए इस आधार का नष्ट होना जरूरी था। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि अंगरेज यहां नहीं आते तो यह आधार नष्ट होता असंभव था। इसके विपरीत उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हम यह धारणा बना सकते हैं कि जिस समय अंगरेज भारत में आए उस समय यहां का परंपरागत भारतीय समाज, जो सड़न की स्थिति में था, समाजवादी क्रांति की पहली अवस्था के बगैर पर खड़ा नाप रहा था और इस अवस्था को वह केवल अपने साधनों के बल पर पार करने वाला था। लेकिन भारतीय समाज अभी सत्रमणकालीन अव्यवस्था के दौर में ही था कि ब्रिटेन की पूर्णतया परिपक्व पूंजीवादी क्रांति ने उसे जा पकड़ा और भारत पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। फिर भी वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेजों में यही लिखा गया कि पुरानी समाज-व्यवस्था का नष्ट होना ब्रिटिश शासन की देन थी।

ब्रिटिश शासन की दूसरी देन यह थी कि उसने देश की राजनीतिक एकता के जरिए भारत में नई समाज-व्यवस्था का भौतिक आधार तैयार किया। उसने भारत का संपूर्ण विश्व बाजार के साथ किया, आधुनिक संचार व्यवस्था खासतौर से रेल व्यवस्था और टेलीग्राफ प्रणाली की स्थापना की। इसके बाद आधुनिक उद्योगधंधों की शुरुआत की और इसके लिए प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक योग्यताओंवाले आवश्यक कमचारियों को प्रशिक्षित किया। हालांकि ये सारे काम उतने पूर्ण रूप में नहीं किए गए जितने पूर्ण रूप में अंगरेजी राज ने अपनी ध्वसात्मक भूमिका अदा की थी।

लेकिन इन दोनों कार्यों से न तो भारतीय जनता को स्वतंत्रता मिल सकती थी और न उसकी हालत में कुछ सुधार हो सकता था। उन्होंने इन दोनों चीजों के लिए महज एक भौतिक परिसर तैयार किया। लेकिन क्या पूंजीपतिवर्ग ने कभी इससे ज्यादा कुछ किया है? क्या उसने व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर लोगों को रक्तपात और गंदगी दुःख दद और अपमान के बीच घसीटे बिना कभी किसी प्रगति को प्रभावित किया है?

उसके लिए तीसरा कदम उठाना अभी शेष था। उसके लिए यह जरूरी था कि भारत की जनता उत्पादन की नई शक्तियों पर अधिकार कर ले और उन्हें अपने हित में संगठित करे। जैसा मार्क्स ने जोर देकर कहा था यह काम भारत की जनता साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चलाकर और अंगरेजों के जुए को पूरी तरह उतार फेंकने के लिए अपनी समूची शक्ति को विकसित करके ही पूरा कर सकेगी। भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का यह ऐतिहासिक दायित्व है। इस आंदोलन का राष्ट्रीय मुक्ति का लक्ष्य भारत की सामाजिक मुक्ति की ओर पहला कदम है।

19वीं सदी के पूर्वार्ध में अर्थात् ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में अंगरेज शासकों ने भारत में जो तबाही और बरबादी की और यहाँ के उद्योग धंधों को जित्त तरह नष्ट-भ्रष्ट किया उसके बावजूद उन्होंने कुछ बातों में अर्थात् भारतीय समाज के दक्षिणानुस और सामाजी शक्तियों के साथ सहजतापूर्वक लड़कर इतिहास की दृष्टि से एक प्रातिवारी भूमिका अदा की। देशी रजवाड़ों को जबरदस्ती हड़प लेने की उनकी नीति के कारण तमाम रियासतें खत्म होती जा रही थी और जो बची हुई रियासतें थीं उनके शासक चिन्तित हो उठे थे। यह साहसपूर्ण सुधारों का युग था। उदाहरण के लिए उस दौर में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई (इस काम में भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों ने पूरा पूरा सहयोग दिया), गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई (हालांकि यह एक रस्मी ढंग की कायवाही साबित हुई) शिशु हत्याओं और गुंडागर्दों के खिलाफ अभियान चलाया गया, पश्चिमी ढंग की शिक्षा शुरू की गई और समाचारपत्रों को स्वतंत्रता दी गई। प्रारम्भिक दिनों में इन अंगरेज शासकों का रवैया बहुत बठार था और भारत की परंपरागत प्रथाओं में जितनी भी पिछड़ी चीजें थीं उनके प्रति उनका रवैया बहुत असहानुभूतिपूर्ण था। उनकी यह दृष्टि धारणा थी कि 19वीं सदी की अंगरेजी की पूँजीवादी तथा ईसाई व्यवधारणाओं का समस्त मानवता की मान्यताएँ बन जाना चाहिए। फिर भी ये लोग उस दौर के उभर रहे पूँजीपतियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे और इस रूप में उन्होंने भारत में सीमित ढंग से काफी परिवर्तन किए। इनमें सर हेनरी सार्ल्स जैसे लोगों को काफी सम्मान और प्यार मिला। उस दौर की सभी परंपराएँ ब्रिटिश और भारतीयों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित हैं। अंगरेजों का सबसे बड़ा शत्रु थे पुराने प्रतिद्विष्टावादी शासक जिन्हें यह लगा कि अंगरेज लोग चालाकी से उनका स्थान ले लेंगे। उस समय भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों में राजा राममोहन राय का नाम और ब्रह्म समाज नामक उनके सुधारवादी आंदोलन का उल्लेख प्रमुख रूप से आता है। इन लोगों ने अंगरेजों की खुलेआम प्रशंसा की और उन्हें भारत की प्रगति का समर्थक माना इसलिए उनके सुधारवादी कायगमा को इन्होंने निस्संकोच रूप से पूरा समर्थन दिया और उन्हें एक नई मन्थना के हारावले के रूप में देखा।

1857 का विद्रोह बुनियादी तौर पर पुराने दक्षिणानुस और सामाजी शक्तियों तथा पदच्युत राजाओं द्वारा अपने अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग के लिए किया गया विद्रोह था। विद्रोह के इस प्रतिद्विष्टावादी स्वरूप के कारण जनता के व्यापक समर्थन का अभाव रहा और उसे विफल हो जाना पड़ा। फिर भी इस विद्रोह से यह बात स्पष्ट हो गई कि सतह के नीचे नीचे जनता में वैचैनी और असंतोष की वैसी भयानक आग गुनग रही है और इससे अंगरेज शासकों में अभूतपूर्व घबराहट पैदा हुई। ताउ मेटकाल्फ ने, जो 1835-36 में भारत के गवर्नर जनरल थे इस दौर के बारे में पहलू ही लिखा है ('पपम सैंड फोरेगोर्डेन', पृष्ठ 116 जे०एन० मारिंगन की सार्ल्स आप सचनरु', पृष्ठ 55 पर उद्धृत) समूची जनता हमारे विनाश पर जान-मनागर्भा अरुण मनागर्भा चान्गी थी उस लोगों की मर्त्यता कम नहीं है जो अपनी ताबत भर इस काम का बर्दाना देंगे।'।



1857 के बाद अंगरेजों की नीति और ब्रिटिश शासन के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब अंगरेजों की नीति अधिक से अधिक इस बात पर जोर देने लगी कि जनता के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत के प्रतिक्रियावादी तत्वों का समर्थन प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही भारत के उदीयमान पूँजीपतिवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली नई प्रगतिशील शक्तियाँ के साथ अंगरेज शासकों के संबंध जो पहले काफी मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ थे अब मदेह, शत्रुता और उदासीनता से भर गए। इस स्थिति में यदि कभी थोड़ी कभी आती भी थी तो केवल उस समय जब अंगरेज शासक परिस्थितियों से विवश होकर जनता के खिलाफ उनसे ज़्यादा तौर पर कोई गठबंधन कर लेते थे। भारतीय रियासतों को जबरदस्ती ब्रिटिश भारत में शामिल कर लेने की नीति अचानक समाप्त कर दी गई। इसके बाद से जो रियासतें शेष बची थीं उनके शासकों को अपनी कठपुतली बनाकर रखने की नीति का अनुसरण किया जाना लगा। उन्हें 'प्रभुसत्ता संपन्न' घोषित कर दिया गया और अपना सहयोगी बताया गया तथा उनके हर तरह के भ्रष्ट सामंती दमन तथा कुप्रशासन को संरक्षण ही नहीं दिया गया बल्कि उसे और मजबूत बनाया गया। अब रजवाड़ों के शासक एकदम परोपजीवी भूमिका निभाने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का राजनीतिक मानचित्र वेतुकी छोटी छोटी जागीरों के पदों से भर गया। बिल्कुल हाल के वर्षों में इन रियासतों और रजवाड़ों के शासकों को, जो अब पूरी तरह से साम्राज्यवादी मालिकों के हाथ के भ्रष्ट औजार बन चुके हैं फिर एक बार भारत के सांविधानिक विकास के मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की शक्तियाँ का विरोध करने के लिए सामने लाया गया। सामाजिक सुधार के रास्ते पर चलना भी अब बंद कर दिया गया और शासकवर्ग ने इसके स्थान पर हर प्रतिक्रियावादी धार्मिक प्रथा और रीति रिवाजों का जोरदार समर्थन करना शुरू किया (1891 का दि एज आफ वसेंट ऐक्ट इस बात की अवधि में लगभग एकमात्र अपवाद है)। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की उसमें एक तरफ़ तो भारत के लोगों को अंगरेजों की बराबरी का दर्जा देने का नाटक किया गया था (इस सदन में बाद के वायसरॉय लार्ड लिटन ने बड़े साफ़ शब्दों में घोषित किया कि 'ये दावे और ये उम्मीदें न तो कभी पूरी हो सकती हैं और न होगी।') और दूसरी तरफ़ उसमें सरकार के इस फैसले पर जोर दिया गया था कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार 'धार्मिक विश्वास और पूजापाठ के मामलों में कभी किसी तरह का हस्तक्षेप न करेगी।' इसके साथ ही भारतीय जनता की दबियानूस ताकतों को यह विश्वास दिलाया गया था कि 'भारत के प्राचीन अधिकार, रीतियाँ और तौर तरीक़ों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा।' 1876 में रॉयल टाइटिल्स एक्ट की घोषणा हुई जिसके अंतर्गत 1877 में महारानी विक्टोरिया का भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इस सदन में वायसरॉय लार्ड लिटन ने कहा कि यह कानून 'एक ऐसी नई नीति की सूचना देता है जिसके फलस्वरूप अब से इंग्लैंड के राजसिंहासन का भारत में एक शक्तिशाली दशो अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और हितों का प्रतिनिधि और रक्षक समझा जाना होगा।' इस अवधि में ही अंगरेज शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने और भारत के लोगों को ज़्यादा छोट मोट मतभेदों का अपन हित में

इम्नमाल करने के तरीका का अध्ययन शुरू किया और अतन् उन्होंने माप्रदायिक आधार पर मतदाना सूची तैयार करने की आधुनिक पद्धति के जरिए इस मसले को भारत की राजनीति का प्रमुख मसला बना दिया। इसके साथ ही 1857 के बाद से अंगरेज शासकों और भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों के बीच दूरी बढ़ती गई। दोनों पक्षा के लोग इन बात पर एकमत हैं कि 1857 के बाद से ही अंगरेज शासकों और प्रगतिशील भारतीयों के मध्य में बुनियादी रूप से तन्नीली आ गई।

इस प्रकार ब्रिटन में और समूचे विश्व में पूँजीवाद के सामान्य स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ था और पूँजीवाद के उदय की प्रारम्भिक काल की प्रगतिशील भूमिका के स्थान पर जिस प्रकार एक अधिन प्रतिस्पर्धावादी और पतनशील भूमिका का सूत्रपात हो गया था, उसी प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया था। आधुनिक साम्राज्यवाद या पतनोन्मुख पूँजीवाद की अन्तिम अवस्था के विकास के साथ ही उसकी यह प्रतिक्रियावादी भूमिका विशेष रूप में स्पष्ट हो गई।

दूसरी तरफ 19वीं सदी के अन्तिम दशकों में भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती दौर की वस्तुपरक ढंग से प्रगतिशील भूमिका की समाप्ति के साथ ही भारतीय समाज में नई शक्तियाँ तेजी से विकसित हो रही थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत का पूँजीपति वर्ग सामने आ रहा था। 1853 में बंबई में सूती कपड़ा बनाने का पहला कारखाना सफलतापूर्वक शुरू किया गया। 1880 तक इन कारखानों की संख्या 156 हो गई जिनमें 44,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1900 तक कारखानों की संख्या 193 और मजदूरों की संख्या 1,61,000 हो गई थी। प्रारम्भ से ही सूती वस्त्रों के इस नए उद्योग में मुख्यतया भारतीयों ने पूँजी लगाई और उन्होंने ही इसका संचालन किया। अनेक कठिनाइयों के बीच इसे अपने विकास के लिए मार्ग तैयार करना पड़ा। इसी के साथ साथ नया शिक्षित मध्यम वर्ग भारतीय रंगमंच पर सामने आ रहा था जो कबीली, डाक्टरों, अध्यापकों और प्रशासकों के रूप में पश्चिमी शिक्षा के सिद्धांतों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था। यह वर्ग नागरिकता की 19वीं सदी की जनतांत्रिक धारणाओं का आगे बढ़ा रहा था। पूँजीवादी उद्योग घरों तथा पश्चिमी ढंग की शिक्षा से लैस बुद्धिजीवियों के क्षेत्र में हुई यह शुरुआत अब भी अपेक्षाकृत काफी घीमी थी। लेकिन उस नए वर्ग ने जन्म ले लिया था जिसको आगे चलकर अनिवार्य रूप से अपने से ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी और अपने विकास के रास्ते में बाधक ब्रिटिश पूँजीपतिवर्ग का मुकाबला करना था और इसीलिए वह भारत की राष्ट्रीय मार्ग को सबसे पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति देने और देश का नेतृत्व करने के लिए बाध्य था।

भारत के इस नए पूँजीपतिवर्ग और ब्रिटिश पूँजीपतिवर्ग के बुनियादी आर्थिक मध्य की अभिव्यक्ति 1882 में ही उस समय हो गई जब लकाशायर के निर्माताओं की मांग पर सरकार ने भारत के विकसित हो रहे कपड़ा उद्योग के विरुद्ध भारत में आने वाले सूती

कपट पर से हर तरह का सीमा शुल्क हटा लिया। इसके तीन वर्षों बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई।

अंतिम बात यह है कि भारत में ब्रिटिश पूँजी के अनुप्रवेश के पत्रस्वरूप यहां के किसान वर्ग की गरीबी और परेशानी बढ़ रही थी और 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक और घातक और से इनमें अंतिम 30 वर्षों के दौरान स्थिति यह हो गई कि किसान हर तरफ से निराश हो गए और जन अमृतताप की घटाए मामने आने लगे। हम पहले ही यह बात बताने हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में जहां 7 अरब पैसे थे और उनमें 15 लाख आदमी मरे थे, वहां 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 24 अरब पैसे और उनमें 2 करोड़ 85 लाख आदमी मरे। इन 24 अरबों में से 18 अरब 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में पड़े थे (अध्याय 5, पृष्ठ 106)। 1875 का एक जनगणना विमान विद्रोह इस बातसे हुए असंतोष का एक घटनाक्रम माना जा सकता है। सरकार की उसमें कितनी हिंसा हुई इसका पता इसी बात में चलता है कि उसमें 1875 में दखन में दंगों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया किंगन गांधी की हत्या की पूरी जांच की और उपद्रवों के कारणों तथा दृष्टि की समूची स्थिति की छायांकित की। 1875 में सरकार ने एक अमान आयोग (कॉमिशन ऑन गवर्नमेंट) की नियुक्ति की। इस प्रकार 19वीं सदी के तीन चौथाई हिस्सा समाप्त होना होना भारत में उस सारी स्थितियों से निपटारा हो गई थी जो 19वीं सदी के 75 वर्षों में यहां मौजूद रह चुकी थी और जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के लिए आवश्यक थी।

#### 4 राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म

फिर भी अपनी सीमित मूलतः अमीरों-सोमाओं के बावजूद एक राष्ट्रीय संगठन के कानूनी तौर पर अस्तित्व में आने के साथ ही अनिवार्यतः ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगीं जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थीं। अपनी स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र ने इसके स्वामिभक्ति वाले चरित्र का धुंधला करना शुरू कर दिया हालाँकि शुरू के दिनों में यह काम बहुत सीमित रूप में हुआ। कुछ ही वर्षों के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इस मस्या पर सदेह करना शुरू कर दिया और इससे बचने में 'राजद्रोह' का केंद्र बनने का मदेह किया जाने लगा। घटनाक्रम के बाद के विवादात्मक रूप में राष्ट्रीय संघर्ष के जन आंदोलन जो 1914 के युद्ध से पहले प्रारम्भिक अवस्था में थे अब ज्यादा निर्णायक रूप से सामने आने लगे और इन्होंने अधिकांशतः जनसंघर्ष का रूप ले लिया। इन संघर्षों ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया जबकि सरकार ने इन संघर्षों का नेतृत्व करने वाली संस्था यानी कांग्रेस का गैरकानूनी घोषित कर दिया और इसका दमन करना चाहा। आज राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में लगे करोड़ों संगठित जनो का मुख्य केंद्रबिंदु है और व्यापक तौर पर लागू की यह धारणा है कि अंगरेजों के जाने के बाद भारत का शासन म्हाताने का दावा कर सकती है।

साम्राज्यवाद के सभी बुनियादी दावा को पराजित करके कांग्रेस की प्रगति का जा इतिहास रहा उसने यही प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तियाँ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थीं और साम्राज्यवाद ने उन शक्तियों को रोकने के लिए जो छोटे छोटे अवरोध तैयार किए थे उनसे इन शक्तियों का रोक सक्ता असंभव था।

बहुधा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारम्भ का 1855 में वायस की नींव पड़ने से साथ जोड़ा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हमसे पहले 75 वर्षों का अध्ययन करें तो आंदोलन के अग्रदूतों की तलाश की जा सकती है। उम मुधारवादी आंदोलन का पहले ही जन्म किया जा चुका है जिसकी अभिव्यक्ति 1828 में प्रह्लाद समाज की स्थापना में हुई। 1843 में बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसायटी की स्थापना हुई जिसने अपनी जाति के सभी वर्गों के हितों का बखाना, उन्हें 'यायाचिन अधिवासी' दिता और उन्हें 'युगहास रूपों' का लक्ष्य घोषित किया। 1851 में यह मस्या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में शामिल हो गई जिसने 1852 में ब्रिटन की संसद में एक याचिका भेजी जिसमें घोषणा की गई थी कि 'वे यह महसूस करते हैं कि ग्रेट ब्रिटन का साथ अपना संबंध से उच्छ्रित लाभ नहीं मिल सका है जितने की आशा करने का उचित है।' इस याचिका में मातृगुजारी व्यवस्था, कारखानेदारों को हतोत्साहित किए जाने, शिक्षा और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के प्रश्न पर अपनी शिकायत व्यक्त की गई थी और एक ऐसी सन्निधान पत्रिका की मांग की गई थी जिसका 'नोबल प्रिय स्वरूप हो और वह ऐसी हो कि कुछ मामलों में वह जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे।' इन प्रारम्भिक संगठनों का संबंध उस समय भी मुख्यतः म्हातानों के हितों से जुड़ा हुआ था और जिन मस्याओं का मरा से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई उनमें उद्योगों के जमींदारों की मस्या बंगाल में एक ही मस्या

भी शामिल थी। 1875 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह पहला संगठन था जिसमें मध्यवर्ग के शिक्षित लोग थे और जो बड़े भूस्वामियों के प्रभुत्व के खिलाफ थे। प्रतिनिध्यावादी संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और प्रगतिशील संस्था इंडियन एसोसिएशन, दोनों की शाखाएँ देश के विभिन्न हिस्सों में खोली गईं। 1833 में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बंगाल, मद्रास बंबई और संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 1883 के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता आनंदमोहन बोस ने की जो बाद में 1898 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने घोषणा की कि यह सम्मेलन एक राष्ट्रीय संसद का पहला चरण है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अवधारणा पहले ही रूप ले चुकी थी और भारतीय प्रतिनिधियों की पहल और सक्रियता में वह अभी परिपक्वता की स्थिति में पहुंच ही नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया। इसलिए सरकार ने ऐसे किसी आंदोलन की स्थापना नहीं की जिसका पहले से कोई अस्तित्व या आधार नहीं था। वस्तुतः सरकार एक ऐसे आंदोलन की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ी जो किसी भी स्थिति में अस्तित्व में आ रहा था और जिसका विकास सरकार की दृष्टि में भी अवश्यभावी था।

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का दृष्टिकोण यह था कि इससे आसन्न क्रांति की संभावना मिट जाएगी या उसका खतरा टल जाएगा। उपलब्ध दस्तावेजों और संस्मरणों की दृष्टि से यह बात साबित हो चुकी है हालांकि पूरा विवरण जानने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मगधालया से वे चीजें भी बाहर न आ जाएं जो अभी गुप्त रखी गई हैं और जिन्हें तब तक गुप्त रखे जाने की आशंका है जब तक दूसरी सरकार न आ जाए।

राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवृत्त संस्थापक एक अंगरेज प्रशासक श्री ए० ओ० ह्यूम थे जो 1882 तक सरकारी सेवा में रहे। सरकारी सेवा में अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का काम शुरू किया। सरकारी अधिकारी होने के कारण ह्यूम को पुलिस की काफी विशालकाय गुप्त रिपोर्टें पढ़नी पड़ीं जो मिली थीं जिनसे पता चलता था कि देश भर में जन असंतोष बढ़ रहा है और अनुरूप भूमिगत पड़ोसकारी संगठन तैयार हो रहे हैं। 19वीं सदी का आठवां दशक भयंकर अकाल और तंगी का दौर था और किसानों में कितना असंतोष बढ़ रहा था इसका परिचय दक्कन के किसान विद्रोह से मिल चुका था। 1877 में एक तरफ भयंकर अकाल पड़ रहा था और दूसरी तरफ पूरी शान शोकांत के माध्यम से राज दरबार लग रहा था जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। द्वितीय अफगान युद्ध भी इसी वर्ष हुआ था। असंतोष का मुनाबता दमन के जरिए किया गया था। 1878 के उत्तरांचल प्रेस एक्ट के जरिए समाचार-पत्रों की स्वाधीनता समाप्त कर दी गई। इसका बाद के वर्ष में आगमन एक्ट लागू किया गया जिसके जरिए प्रामाण्यता से अधिकार भी ल लिए गए जाते थे जंगली जानवरों से

अपनी रक्षा करत थे। सावजनिक सभाओं का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ह्यूम के जीवनी लेखक ने लिखा है

सरकार ने जिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रियावादी उपायों से काम लिया और जिन रूढ़ी तरीकों से पुलिस के जरिए दमन किया उन सबका यह परिणाम हुआ कि लाड लिटन के जमाने में भारत में कुछ ही दिनों के अंदर एक आतिशबाजी विस्फोट होने का खतरा पैदा हो गया। यही वह समय था जब श्री ह्यूम और उनके भारतीय सलाहकारों ने इसमें हस्तक्षेप की बात साजी। (सर विलियम वेडरबर्न एलेन आक्टविगन ह्यूम, फादर आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस (1913), पृष्ठ 101)

सर विलियम वेडरबर्न ने आगे बताया है कि इस हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या था

लगभग 1878 या 1879 में जब लाड लिटन की वायसराय की अवधि समाप्त होने वाली थी, श्री ह्यूम इस बात पर सहमत हो गए कि बहुत हुए अमत्तों का मुकाबला करने के लिए कोई निश्चित कदम उठाना जरूरी है। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले उनके शुभचिंतकों ने उनके पास यह लिखकर भेजा था कि सरकार और भारत की भावी खुशहाली को गंभीर खतरा है, जनता की आर्थिक सबटा का मामला करना पड़ेगा और बुद्धिजीवी वर्ग सरकार से अलग हो जाएगा। (वही, पृष्ठ 50)

कांग्रेस की स्थापना से पहले सरकारी आशीर्वाद के साथ जबरदस्त दमनचक्र चला। ये दोनों प्रक्रियाएँ एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक थीं। जब तक शक्तिशाली आतंककारी आंदोलन का दमन नहीं कर दिया गया, तब तक 'जनता के बढ़ते अमत्तों' को रोकने के लिए नरमदली नेताओं के नेतृत्व में कानूनी आंदोलन नहीं शुरू किया गया। दमन और समझौते का यह दोहरा या वैकल्पिक तरीका साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञों का पुराना हथियार था जिसका वे आने वाले दिनों में भी इस्तमाल करने के लिए अभिमत थे। इसके जरिए एक तरफ तो अडिमल जुआर शक्तियाँ काबू में आती या और दूसरी तरफ 'वफादार' मध्यमवर्गीय नेताओं के साथ गठबंधन किया जाता था।

वे किस तरह के प्रमाण थे जिनके आधार पर ह्यूम ने यह लिखा कि 'मुझे न तो तब तक भय हुआ था और न आज है कि उस समय हम सचमुच एक भयंकर आतंक के खतरे के बीच से गुजर रहे थे।' इन बातों का श्री ह्यूम के ही शब्दों में बताना लाभप्रद होगा। उनके कागजातों में जो आपन मिलता है उसमें इन बातों का उल्लेख है (आपन से लिए गए जिन अंशों का यहाँ दिया गया है उन्हीं श्री ह्यूम के जीवनी लेखक ने उद्धृत किया, अन्य उद्धृत अंश वे हैं जिनका सारांश उस जीवनीकार ने दिया है।)

मेरा ख्याल है कि लाड लिटन के भारत छोड़ने से तक्रीबन 15 महीनो पहले मैंने जो सबूत देखे उनसे मैं इस बात पर सहमत हो गया कि हम लोग भयंकर विस्फोट के आसन्न खतरे के बीच थे। मुझे सात बड़ी बड़ी जिल्लें दिखाई गईं (जो बमा, असम तथा कुछ छोटे भूखंडों को छोड़कर दश के कुछ भागों में विभाजन के मुताबिक थीं) इनमें तमाम बातें दर्ज थीं। उनमें देशी भाषाओं में लिखी गई किसी न किसी तरह की रिपोर्ट या समाचार का अंगरेजी में सारांश या संक्षिप्त अथवा विस्तृत अनुवाद था। यह सारी सामग्री अलग अलग जिला, उप जिला, सब डिवीजन, शहरों, कस्बों या गांवों के हिसाब से दी गई थी। इसमें प्रचुर मात्रा में रिपोर्ट दर्ज थी जिनके बार में बताया गया था कि इन जिल्लों में तीस हजार से अधिक सवादाताओं की रिपोर्टें दर्ज थीं। बहुत सी रिपोर्टों में सबसे निचले तबकों के लोगों की बातचीत का ब्यौता था जिनसे पता चलता था कि ये लोग अपनी मौजूदा हालत से एकदम निराश हो चुके थे, वे यह मान चुके थे उन्हें भूखा मर जाना है और इसलिए वे अब कुछ करना चाहते थे। वे कुछ करने जा रहे थे और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस 'कुछ' करने का अर्थ था हिंसा। अब तमाम रिपोर्टों में पुरानी तलवारों, बंदूकों और हथियारों का छिपाकर जमा करने की बात का उल्लेख था। हथियारों को जमा करने का उद्देश्य यह था कि मोका हाथ लगते ही उनका काम लिया जाए। यह नहीं समझा गया था कि इन सारी बातों के फलस्वरूप शुरू में ही सरकार के खिलाफ सही अर्थों में विद्रोह हो जाएगा। अनुमान यह लगाया गया था कि पहले छिटपुट अपराध होंगे, धिनीन व्यक्तियों की हत्या होंगी, बका में डाकें डाल जाएंगी और बाजार लूटे जाएंगे।' समूची स्थिति पर विचार करने से यह अनुमान लगाया गया कि अधभूखमरी की हालत में रहने वाले अत्यंत गरीब तबकों द्वारा शुरू में किए गए इन अपराधों के बाद इस तरह के अपराधों का सिलसिला चल पड़ेगा और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सामान्य तौर पर इतनी बिगड़ जाएगी कि अफ़िकारियों और भद्रजनों के बस में कुछ भी नहीं रह पाएगा। यह भी सोचा गया कि हर जगह घाट छोटे गिरोह धीरे धीरे बढ़े होत जाएंगे, ठीक वैसे जैसे पत्तियां पर पड़ी पानी की बूंदें जुड़ जुड़ कर बड़ी हो जाती हैं, दश के सभी अराजक तत्वों में एकरूपता आ जाएगी फिर जब इनके गिरोह काफी मजबूत हो जाएंगे तब पड़े निते बग के कुछ लोग भी इनके साथ हो जाएंगे। कारण चाह उचित हो या अनुचित लेकिन पड़े लिखे लोग पहले से ही सरकार से असंतुष्ट हैं और इस बात की आशंका थी कि ये लोग धीरे धीरे आंदोलनों का नेतृत्व करने लगेंगे तथा उपद्रवों की एक निश्चित श्रम देने के बाद वे उन्हें एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप दे देंगे और उसका नेतृत्व करने लगेंगे। (सर विलियम बडरबन दिस पृष्ठ 60-61)

सन् 1885 के प्रारम्भिक दिनों में अनुभवों राजनीतिज्ञ वायसराय नाइडफ़रिन ने मध्य मायम किया और सारी स्थिति उनका सामना रखी। यह बातचीत साम्राज्यवाद के मुद्रातन

शिमला में हुई और इस बातचीत में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की योजना तैयार की गई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन श्री टंक्यू० सी० बनर्जी ने कांग्रेस के जन्म का वर्णन इस प्रकार किया है

बहुत लंबा का शायद यह पता हो कि शुरू शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस रूप में स्थापना हुई और जिस प्रकार वह तब से काम करती आई है, वह वस्तुतः डफरिन और आवा के मारबिस की प्रेरणा हुई है। उस समय वह सम्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1884 में श्री ए० आ० ह्यूम के मन में यह विचार आया कि यदि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों का साल में एक बार एक जगह एकट्ठा किया जा सके जिसमें वे दोस्ताना नहजे में एक दूसरे के साथ सामाजिक मसलों पर विचारविमर्श कर तो देश का काफी हित हो सकता है। ह्यूम का विचार था कि इस बातचीत में राजनीतिक मसलों का शामिल किया जाए—

लाड डफरिन ने इस मामले में काफी दिलचस्पी ली और कुछ समय तक इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उन्होंने श्री ह्यूम से कहा कि उनके (लाड डफरिन के) विचार में यह योजना बहुत लाभप्रद रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसे लोग एकदम नहीं हैं जो ऐसे कार्य कर सकें जो इंग्लैंड में साम्राज्यों के प्रतिपक्ष में किए हैं—शासकों और शासिता के हित में यही ठीक है कि भारतीय राजनीति में प्रति वर्ष एक साथ मिल-बैठकर सरकार को बताएं कि प्रशासन में क्या दोष है और इसमें किस तरह सुधार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन तरह की बैठकों की अध्यक्षता स्थानीय गवर्नर न करें क्योंकि उनकी मौजूदगी के कारण हो सकता है कि लोग खुलकर अपनी बातें न कहें। श्री ह्यूम ने लाड डफरिन की दलीलों से इत्तफाक किया और जब उन्होंने बलकत्ता, बर्मा, मद्रास तथा देश के अन्य हिस्सों में प्रमुख राजनीतिज्ञों के सामने अपनी तथा लाड डफरिन की योजनाएं रखीं तो सर्वसम्मति से लाड डफरिन की योजना स्वीकार कर ली गई और इसको व्यावहारिक रूप देने का फैसला किया गया। लाड डफरिन ने श्री ह्यूम से यह बात मनवा ली थी कि जब तक वह भारत में रहे उनकी नाम गुप्त रखा जाए। (टंक्यू० सी० बनर्जी 'इंस्ट्रुक्शन टु इंडियन पालिटिक्स', 1898)

उदारवादी साम्राज्यवाद की परंपरागत नीति का यहां साफ तौर पर पता चलता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनांक का जिन लोगों ने अभी हाल में इतिहास लिखा है उन्होंने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है

कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले देश की जैसी स्थिति थी, वैसी स्थिति 1857 के बाद पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। अंगरेज अधिकारियों में श्री ह्यूम ही ऐसे थे

१००



जि 'होन दस आस'न खतरे को महसूस किया और उसे टालन की कोशिश की वह शिमला गए ताकि अधिकांशियों को बता सकें कि कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। दस बात की सभावना है कि ह्यूम की बातचीत से नए वायसराय को, जो काफी कुशल प्रशासक थे, स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के लिए ह्यूम को अनुमति दे दी। इस अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थितियाँ पूरी तरह परिपक्व थी। एक ऐसे किसान विद्रोह के स्थान पर, जिस शिक्षित वर्ग की सहानुभूति और समर्थन मिलता, इस सस्या के जरिए उभरते वर्गों को नए भारत का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल गया। कुल मिलाकर यह अच्छा ही हुआ कि हिंसा पर आधारित क्रांतिकारी परिस्थिति पैदा होने से एक बार फिर रोक दी गई। (एड्ज और मुर्कजी राइज ऐंड ग्रोथ आफ दि कांग्रेस इन इंडिया, पृष्ठ 128-29)

महत्वपूर्ण बात यह है कि 'हिंसा पर आधारित क्रांतिकारी परिस्थिति' को पैदा होने से रोकने की जिम्मे भूमिका का निर्वाह राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया उसकी शुरुआत गांधी के आने से पहले ही हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साम्राज्यवाद ने उसके अंदर यह बीज बाँ दिया था और इसकी सरकारी भूमिका निर्धारित कर दी थी।

कांग्रेस की भूमिका के बारे में ह्यूम की क्या धारणा थी, यह भी जानना जरूरी है

हमारी अपनी हरकतों से जो विशाल और बढ़ती हुई शक्तियाँ यहाँ पैदा हो गई थी, उनके समूचे जोश को बिना हमें कोई नुकसान पहुँचाए निकाल देने के लिए एक साधन की जरूरत थी और इस काम के लिए हमारे कांग्रेस आंदोलन से ज्यादा कारगर कोई साधन नहीं बनाया जा सकता था। (वेडरबन, देखें, पृष्ठ 77)

लाड डफरिन का मकसद यह था कि कांग्रेस के द्वारा 'बेफादार' लोगों को उग्रपंथियों से अलग करके सरकार की मदद के लिए एक आधार तैयार किया जाए और अपने इस उद्देश्य को उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के एक वर्ष बाद 1886 में, शिक्षित वर्गों की मागा के विषय में भाषण करते हुए बड़े ही साफ शब्दों में बताया था

भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें यूरोप के ढंग का जनतांत्रिक आंदोलन सुरक्षा के साथ लागू कर दिया जाए। मैं खुद ही उन मागा की सावधानीपूर्वक और गंभीरता के साथ जांच करना चाहूँगा जो विभिन्न आंदोलनों से पैदा हुई हैं, जहाँ तब संभव या वांछनीय हो पूरी रियायत के साथ उसे मेल बैठाना चाहूँगा, यह घोषित करना चाहूँगा कि इन रियायतों को अगले 10 या 15 वर्षों के लिए भारतीय प्रणाली का अंतिम समझौता मान लिया जाए और जन मताओं तथा उत्तेजना पैदा करने वाले भाषणों पर रोक लगा दूँगा।

उपप्राप्तियों की मांगों को यदि दरकिनार कर दिया जाए—तो अप्रत्याशित अधिक अप्रवर्तनीय बन के भी लक्ष्य न तो छतरनायक है और न फालतू—यहाँ के जिन देशी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है उनमें काफी लोग ऐसे हैं जो योग्य भी हैं और बुद्धिमान भी और जिनके निष्ठापूर्ण सहयोग पर कोई भी बिना संदेह भरोसा कर सकता है। यदि ये लोग सरकार का समयन करने लगेंगे तो सरकार के बहुत से ऐसे कामों का जनता में प्रचार हो जाएगा जो आज उसकी दृष्टि में विधान मंडल में वानून बनवाकर किए जाते हैं। और यदि इन लोगों के पीछे यहाँ के देशी लोगों की एक पार्टी पड़ी हो जाती है तो फिर भारत सरकार आज की तरह अकेली नहीं रह जाएगी। आज तो भारत सरकार तूफानी सागर के बीच अकेली जड़ान की तरह छड़ी है और चारों दिशाओं से भयंकर लहरें आकर उसपर टूट रही हैं। (सर अल्फ्रेड लायल लाइफ आफ दि मारक्विम आफ डफरिन ऐंट आवा', खंड 2 पृष्ठ 151-52)

लाइड डफरिन ने जो हिसाब लगाया था वह बहुत साफ था और शुरू के दिनों में जो नतीजे सामने आए उनसे लगा कि उन्हें अपने काम में पूरी सफलता मिल गई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन ने साम्राज्यवाद के प्रति अपनी पूरी भक्ति का परिचय दिया। अधिवेशन में पारित नौ प्रस्तावों में केवल प्रशासन में छोट मोट सुधारों की मांग थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मांगों से मिलती जुलती बस एक मांग थी और उसमें विधानपरिषद् में कुछ चुने हुए सदस्यों के लिए जाने की प्रार्थना की गई थी। श्री ह्यूम ने अपने शिष्यसमुदाय को किस सफलता से संचालित किया यह अधिवेशन समाप्त होने के समय की एक घटना से स्पष्ट हो जाता है। इस घटना का विवरण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की रिपोर्ट में दिया गया है

श्री ह्यूम ने अपने प्रति प्रकट किए गए सम्मान का जवाब देने के बाद कहा कि चूंकि जयकार का काम मुझे सौंपा गया है इसलिए मैं सोचता हूँ कि देर आयद दुस्त आयद के सिद्धांत का मानते हुए हम सभी तीन बार ही नहीं तीन गुना तीन अर्थात् नौ बार और यदि हाँ मंजूर हो तो तीन गुना तीन अर्थात् मनाइम बार उस महान विभूति की जय बोले जिसके जूते के फीते खालने के लायक भी मैं नहीं हूँ, जिसके लिए आप सब प्यारे हैं और जो आप सबका अपने बच्चों के समान समयती है अर्थात् सब मिलकर बोलिए महामहिम महारानी विक्टोरिया की जय।

श्री ह्यूम ने आगे कहा यह नहीं सुना जा सका क्योंकि उसी समय चारों तरफ से जयजयकार होने लगे और उस शोर में वक्ता की आवाज डूब गई। उनकी इच्छानुसार लोगों ने बार बार जयजयकार की।

इस तरह वाद्यम की सुरक्षा जी तुरही म हूँ (यहाँ भी त ११ पाठ १ वाली त्रिम कथा  
 पत्नी का स्वभाव दिया गया है) उमर की भी सुरक्षा मुख्य म माया १ ११ कवि अग्रज  
 १ ही को) किन्तु यही वाद्यम एक ही मरवा ११ पाठ ११ का ११ मरवा उमर  
 मरवा की धर्मक ११ ११ की भी ११ ११ कि इस मरवा म माया कराटा सोम  
 स्वाधीनता म मरवा म ११ तुरही ११ म माया म माया ११

[illegible]

## पाद टिप्पणिया

- 1 यह प्रणवनीय परीक्षा आर० पेज अनर्जित ने लेबर मणली के जसाई 1930 मक मे दि साहमन कमीशन रिपोर्ट नामक लेख म दी था ।
- 2 प्रस्तुत उद्धरण तथा इस तरह के अनेक उद्धरण मेजर बी०डी० बगु की पुस्तक 'रून आफ इंडियन टूट एंड इन्स्टीज' बलकत्ता, 1935 पृ० 254-67 पर 'क्टंपररी इंडिया ऐंड अमेरिका आन दि ईय आफ बिजमिंग मा' नामक दितचस्य परिशिष्ट म दिए गए हैं ।
- 3 सितंबर 1930 के 'लेजर मणली' म प्रकाशित लेख फबड इंडियन स्टडिस्ट्स एज इपीरियसिस्ट प्रोपगंडा म बिस्वस बिस्नेषण मिलेगा । उपयुक्त तथ्यों की पूरी व्याख्या के लिए इसका सडम दिया जाना चाहिए ।
- 4 यह एक दितचस्य बात है कि जब भी ब्रिटिश शीपको के सामने भारतीय बाजार पर कजा करने का मसला आया है भाषा सबकी समस्या जिस राजनीतिक मनसद के लिए इतना गभीर बताया जाता रहा है वही सहज ओर सरल हो जाती है तमाम भाषाओं की मौजूदगी से भाषा की समस्या जितनी विराट नगनी है वह दरअसल इतनी विराट नहीं है जो हल न की जा सके ।'

- (एच०जी० फल्टा दि इंडियन मार्केट टिटस टु दि ब्रिटिश एक्सपोर्ट दि टाइम्स टु डे ऐंड इजीनियरिंग इंडिया सप्तीमट, अप्रैल 1939)
- 5 भारत में पश्चिमी मिश्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए थे, उसका इस पुस्तक के लेखक ने अध्ययन किया है। यह राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत गंभीर अनुमान के आधार पर किया गया है। (सर अल्फ्रेड सायल जी० सी० आई० ई० वलेंट्वाइन चिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट 1910 की भूमिका पृष्ठ 13)
- 6 इन अप्रत्यूति और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक अवस्थाओं का पूर्ण विवरण सी० एफ० एड्रूज और जी० मुक्जी की पुस्तक दि राइस ऐंड ग्रेय आफ दि कांग्रेस इन इंडिया 1938 में देखा जा सकता है।

इस तरह कांग्रेस की पुनर्जात जी हजारी में हुई (महा भी तत्काल पाटी वाली जिस राजा वाली का इस्तमान किया गया है उसकी भी पुनर्जात पूरव व जागा है वही बल्कि अगर राजा ने ही की) लेकिन वही कांग्रेस एक ही गैरजातनी घोषित कर दी गई। सरकार उसका सदस्या की धरपकड़ बना लगी और जमान गया कि इस मस्या में जाया कराया लोग स्वाधीनता के मध्य में जिग पूरी निष्ठा व माय आ पुनः ।

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व समय में ही कांग्रेस का जो सहारा चरित्र सामने आया था कांग्रेस के बाद ने इतिहास व लिए भी उसका बहुत महत्व था । उसकी भूमिका का यह दोरगापन उसके समूचे इतिहास में बना रहा । एक तरफ तो वह 'जा आदोलन के पतर' से बचन व लिए साम्राज्यवाद व साथ सहयोग करती थी और दूसरी ओर वह 'राष्ट्रीय सपन में जनता का नतृत्व करती थी । कांग्रेस के चरित्र का यह दाहरापन पुराने युग के नता गोघले से लेकर नए युग के नता गोघले के शिष्य गांधी तक के नतृत्व के अतीवरोघा में मिलता है (हालांकि इन दोनों का अंतर मुख्यतः जन आदोलन की अलग अलग अवस्थाओं का अंतर है जिनके पत्रस्वरूप दोनों नताओं को अलग अलग माय नीति अपनाती पड़ी) । यह दोहरापन भारतीय पूजीपतिवग की दारोगी या दुलमुल भूमिका का परिचायक है । भारत के पूजीपति के हितों का टकराव ब्रिटिश पूजीपतिवग के हितों से होता है इसलिए वह भारतीय जनता का नतृत्व तो करना चाहता है पर उस सदा यह आशका भी रहती है कि जन आदालन की रफ्तार वही 'इतनी तज न हो जाए कि साम्राज्यवादियों के साथ साथ उनके भी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाए । जैसे जैसे राष्ट्रीय आदालन का विकास जनता का आधार बनाकर होगा और आदालन का हित उन हितों के विरुद्ध हागा जा साम्राज्यवादी हित हैं या साम्राज्यवादियों से सहयोग करने के इच्छुक विशेषाधिकार प्राप्त वग के हित है वैसे वैसे यह विसंगति अन्तिम तीर पर हन होती जाएगी ।

### पाद टिप्पणियाँ

- 1 यह प्रगतिशील परोडी आर० फेज अर्नाट ने 'लेबर मयली के जुलाई 1930 संक में 'दि साइमन कमीशन रिपोर्ट' नामक लेख में दी थी ।
- 2 प्रस्तुत उद्धरण तथा इस तरह के अनेक उद्धरण मेजर बी० डी० बसु की पुस्तक 'रुद्रन आफ इंडियन ट्रेड ऐंड इंडस्ट्रीज', कलकत्ता 1935 पृ० 254 67 पर 'कटवररी इंडिया ऐंड अमेरिका आन दि ईथर आफ विकिमिंग मा' नामक दिलचस्प परिशिष्ट में दिए गए हैं ।
- 3 मिनबर 1930 व 'लेबर मयली' में प्रकाशित लेख 'फेज इंडियन स्टैटिस्टिकस एंड इपीरियलिस्ट प्रोपेगंडा' में विस्तृत विश्लेषण मिलेगा । उपयुक्त तथ्यों की पूरी 'याख्या के लिए इसका संदर्भ दिया जाना चाहिए ।
- 4 यह एक दिलचस्प बात है कि जब भी ब्रिटिश शोषकों के सामने भारतीय बाजार पर कब्जा करने का मतलबा आया है भाषा सबधी समस्या जिसे राजनीतिक भ्रमसद के लिए इतना गंभीर बताया जाता रहा है वही सहज और सरल हो जाती है । तमाम भाषाओं की मौजूदगी से भाषा की समस्या जितनी विराट लगती है वह दरअसल इतनी विराट नहीं है जो हल न की जा सके ।

बड़े पैमाने पर असतोष की अभिव्यक्ति सामन आई। इसमें शहरों में रहने वाले निम्न पूँजीपतिवर्ग का अग्रतोष व्यक्त हुआ लेकिन वह आम जनता तक नहीं पहुँच सका। 1914-18 के युद्ध के बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और दल की नई शक्ति औद्योगिक मजदूरों अर्थात् आम जनता की क्या भूमिका है। इसके बाद जनसघर्षों की दो बड़ी लहरें आईं, पहली लहर युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में और दूसरी लहर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद आई। सघर्ष के इस इतिहास के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद आज अपनी शुरुआत के बाद से शक्ति के सर्वोच्च बिंदु पर पहुँच चुका है। राष्ट्रीय कांग्रेस, 1946 के चुनावों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने और अधिकांश प्रांतों में अपनी सरकारें बनाने के बाद प्रतिनिधित्व की निर्णायक स्थिति में पहुँच चुकी है और अब उसके सामने नेतृत्व की गंभीर जिम्मेदारियाँ हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन नाजुक मोड़ पर आ पहुँचा है। सभी प्रेक्षकों के सामने यह स्पष्ट है कि सघर्ष के एक ऐसे नए महान युग का सूत्रपात हो रहा है जो भारत में अंग्रेजी राज के लिए और भारतीय जनता के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस मौजूदा स्थिति की समस्याओं के सदर्भ में सघर्ष की इन पुरानी मजिलों और उनके सबक का तेजी से सर्वेक्षण किया जा सकता है।

## 1 सघर्ष की पहली बड़ी लहर 1905-1910

बीस वर्षों तक राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संस्थापकों द्वारा तैयार किए गए रास्ते पर चलती रही। इन बीस वर्षों में उसके प्रस्तावों में किसी भी रूप में स्वराज की बुनियादी मांग नहीं की गई अर्थात् किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय दावा नहीं किया गया, उसकी मांग केवल वही तक सीमित रही कि शासन की ब्रिटिश प्रणाली में ही भारतीयों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो। शुरू के नरमदली नेताओं का दृष्टिकोण जानने के लिए अत्यंत योग्य और सबसे ज्यादा नरमदली नेता श्री रमेशचंद्र दत्त का उदाहरण दिया जा सकता है। श्री दत्त 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1901 में 'भारत की जनता' की मांग को निम्न शब्दों में रखा

भारत की जनता अमान्य होतों के परिवर्तन और आतिथेयों को पसंद नहीं करती है। उसे नए सविधान की कोई दरकार नहीं। भारत के लोग पहले से ही निर्धारित कर दिए गए तरीकों पर काम करना पसंद करते हैं। वे मौजूदा सरकार को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और सरकार तथा जनता के बीच मध्यक और बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय मामलों के मंत्रालय में सबसे अधिक परिपक्व और वायसराय की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीय सदस्य शामिल किए जाएं जो भारतीय हितों तथा उद्योगों के प्रतिनिधित्व करें। वे चाहते हैं कि प्रत्येक सूबे के लिए वही कार्यकारी परिषद में भारतीय भी सदस्य की हैसियत से रहे। वे चाहते हैं कि प्रशासन संबंधी हर महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भारतीय

## राष्ट्रीय संग्राम की तीन मजिलें

भुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस देश की जनता को यदि राजनीतिक संकट के दौरान कोई निर्देश न दिए गए सिवाय इसके कि वे हिंसा से नफरत करें, व्यवस्था से प्यार करें और समय का परिचय दें, 'तो इस देश में नागरिक स्वतंत्रताएँ कभी अस्तित्व में नहीं आ सकेंगी।' (विलियम एवट ग्लेडस्टोन)

पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है उसका निरूपण करने के लिए अलग से अध्ययन की जरूरत है क्योंकि इसमें एक ऐसी जनता का समूचा राजनीतिक इतिहास शामिल है जो राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के अपने सघम की गंभीरतम मजिलों से गुजरी है। फिर भी वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर रोशनी डालने के तात्कालिक उद्देश्यों के लिए उस विवास और एक के बाद एक व्यक्त होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों की युगांतरकारी घटनाओं को बारीकी से देखना होगा जिन्होंने मौजूदा आंदोलन का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है और अपनी भूमिका निभाई है।

भारतीय राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विवास, सघम की तीन बड़ी लहरों से गुजरा है। इनमें से प्रत्येक लहर पहले की अपेक्षा अधिक ऊँची थी और प्रत्येक लहर न आंदोलन पर स्याई बिना छोड़े तथा एक नए दौर का सूत्रपात किया। जगह हमने देखा है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारम्भिक दौर ने केवल बड़े पूँजीपतियों का प्रतिनिधित्व किया जिसमें जमींदारों के प्रगतिशील तत्व, नए औद्योगिक पूँजीपति और युवाहाल बुद्धिजीवी शामिल थे। 1914 के पहले के वर्षों में पहली बार इस बात जल में उस समय हलचल पैदा हुई जब देश में

बड़े पैमाने पर असतोष की अभिव्यक्ति सामन आई। इसमें शहरों में रहने वाले निम्न पूँजीपतिवर्ग का असतोष व्यक्त हुआ लेकिन वह आम जनता तक नहीं पहुँच सका। 1914-18 के युद्ध के बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और देश की नई शक्ति औद्योगिक मजदूरों अर्थात् आम जनता की क्या भूमिका है। इसके बाद जनमधर्षों की दो मंजिलें लहरे आइ, पहली लहर युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में और दूसरी लहर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद आई। मधुप के इस इतिहास के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद आज अपनी शुरुआत के बाद से शक्ति के सर्वोच्च बिंदु पर पहुँच चुका है। राष्ट्रीय कांग्रेस, 1946 के चुनावों में जबर्दस्त सफलता प्राप्त करने और अधिकांश प्रांतों में अपनी सरकारें बनाने के बाद प्रतिनिधित्व की निर्णायक स्थिति में पहुँच चुकी है और अब उसने सामन नेतृत्व की गंभीर जिम्मेदारियाँ हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन नाजुक मोड़ पर आ पहुँचा है। सभी प्रेक्षकों के सामने यह स्पष्ट है कि मधुप के एक ऐसे नए महान युग का सूत्रपात हो रहा है जो भारत में अगरजी राज के लिए और भारतीय जनता के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इस मौजूदा स्थिति की समस्याओं के मद्देन में मधुप की इन पुरानी मजिलों और उनके सबक का तेजी से सर्वेक्षण किया जा सकता है।

## 1 मधुप की पहली बड़ी लहर 1905-1910

बीस वर्षों तक राष्ट्रीय कांग्रेस अपने संस्थापकों द्वारा तैयार किए गए रास्ते पर चलती रही। इन बीस वर्षों में उसके प्रस्तावों में किसी भी रूप में स्वराज की बुनियादी मांग नहीं की गई अर्थात् किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय दावा नहीं किया गया, उसकी मांग केवल वहीं तक सीमित रही कि शासन की ब्रिटिश प्रणाली में ही भारतीयों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो। शुरू के नरमदली नेताओं का दृष्टिकोण जानने के लिए अत्यंत योग्य और सबसे ज्यादा नरमदली नेता श्री रमेशचंद्र दत्त का उदाहरण दिया जा सकता है। श्री दत्त 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1901 में 'भारत की जनता की मांग' का निम्न शब्दों में रखा

भारत की जनता अचानक होने वाले परिवर्तनों और प्राप्ति की पसंद नहीं करती है। उसे नए संविधान की कोई दरकार नहीं। भारत के लोग पहले से ही निर्धारित कर दिए गए तरीके पर काम करना पसंद करते हैं। वे मौजूदा सरकार की बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं और सरकार तथा जनता के बीच मध्य और बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय मामलों के मंत्रालय से सबकुछ परिपद में और वायसराय की कार्यवाही की परिपद में कुछ भारतीय सदस्य शामिल किए जाए जो भारतीय श्रमिक तथा उद्योग धंधों का प्रतिनिधित्व करें। वे चाहते हैं कि प्रत्येक सूबे के लिए अपनी कार्यवाही की परिपद में भारतीय भी सदस्य की हैसियत से रहें। वे चाहते हैं कि प्रशासन तंत्र की हर महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भारतीय



जनता व हिता का भी प्रतिनिधित्व है। व चाहत है कि साम्राज्यवाद तथा उसके विशाल सूबों का प्रशासन जनता व सहयोग से चलाया जाए।

भारत के प्रत्येक बड़े सूबे में एक विधान परिषद है और इन परिषदों के कुछ सदस्यों का चुनाव 1892 के कानून व तहत होता है। यह प्रयाग सफल साबित हुआ है और इन विधान परिषदों का थोड़ा विस्तार कर देने से प्रशासन और मजबूत होगा तथा जाता के साथ इसका संबंध और घनिष्ठ होगा 30 जिलों और 3 करोड़ की आबादी वाले सूबों के लिए इन विधानपरिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 30 ता होनी ही चाहिए। प्रत्येक जिले को महसूस होना चाहिए कि सूबे व प्रशासन में उसकी भी कोई आवाज है। (रमेशचंद्र दत्त 1901, 'दि इकानामिन हिस्ट्री आफ इंडिया,' खंड I की भूमिका—'इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल', पृष्ठ xviii)

इन भागों की नरमी से इस बात की सही तोर पर अभिव्यक्ति होती है कि शुरू के दिनों के भारतीय पूजोपतिवर्ग की क्या स्थिति थी। उन दिनों कांग्रेस विलुप्त ही उच्च पूजोपतिवर्ग और खासतौर से उसके वैचारिक प्रतिनिधि अर्थात् शिक्षित मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। शुरू से ही इन क्षेत्रों से कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या काफी उत्साहवर्धक रही। यहां तक कि प्रतिनिधियों की संख्या सीमित रखने के उपाय करने पड़े। ब्रिटेन के एक सदस्य एडव्यू० एम्स० केन ने, जिन्होंने कांग्रेस के 1889 के अधिवेशन में भाग लिया था, लिखा कि, मेरे चारों तरफ जो चार हजार भद्र जन बैठे हुए हैं वे सभी भारत के वकीलों, डाक्टरों इजीनियरों और लेखकों में से चुने हुए लोग हैं।' शुरू के नरमदली नेताओं को अच्छी तरह पता था कि व जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं और व जनता के नाम पर भले ही उनकी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं पर वे इस बात का दावा नहीं कर सकते थे कि उनकी आवाज जनता की आवाज है। शुरू के दिनों में कांग्रेस के मुख्य पथप्रदर्शक सर फीरोजशाह मेहता ने कहा था कि, 'निश्चय ही कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है लेकिन पड़े लिखे भारतीयों का यह कतब्य है कि वे जनता की शिकायतों को सामने लाए और उनकी दूर करने का सुझाव प्रस्तुत करें।'।

उन दिनों के भारत का प्रारम्भिक पूजोपतिवर्ग भी अच्छी तरह जानता था कि वह अंगरेजी राज की चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसके विपरीत वह अंगरेजी राज को अपना सहयोगी समझता था। वह अंगरेजी राज को अपना मुख्य दुश्मन नहीं समझता था। उसके लिए मुख्य दुश्मन थे जनता का पिछड़ापन दश में आधुनिक विकास की कमी, अज्ञान और अंधविश्वास की शक्तियां और नीकरशाही शासन व्यवस्था की कमियां जिनके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इन बुराइयों के विरुद्ध अपने सघन में वे ब्रिटिश शासकों के सहयोग की आशा लगाए रहते थे। 1898 में कांग्रेस अधिवेशन के

अध्यक्ष श्री आनन्दमोहन बोस ने कहा था कि, 'शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का दुश्मन नहीं, दोस्त है। इंग्लैंड के सामने आन जो बाम पड़े हूँ उन्हें पूरा करने में भारत का शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का सहज और आवश्यक सहयोगी है।' 1890 में सर फीरोज़शाह मेहता ने कहा था कि, 'मुझे इसमें एकदम सन्देह नहीं कि ब्रिटिश के राज नेता समय की पुकार का समझेंगे।' कांग्रेस के जनक दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद से दिए गए अपने भाषण में ब्रिटिश से अपील की थी कि वह इस शक्ति को (भारतीयों व शिक्षित वर्ग को) अपने पक्ष में करने के बजाय अपना दुश्मन बनाए।' पुराने कांग्रेस नेताओं में सबसे मशहूर वक्ता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के आदर्शों की घोषणा करते हुए कहा था कि 'वह (कांग्रेस) सदा अंगरेजों के साथ अटूट निष्ठा के साथ काम करे क्योंकि इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना नहीं है बल्कि उसके आधार को और व्यापक बनाना है। उनकी आत्मा को और उदार बनाना है उसका स्वरूप को और परिष्कृत करना है और उसे राष्ट्र ने स्नह की अपरिवर्तनीय नींव पर पड़ा कर देना है।'।

इन घोषणाओं से जो ध्वनि निकलती है उससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि शुरू के दिनों के ये कांग्रेस नेता जंगरेज सरकार के प्रतिभ्रियावादी और राष्ट्रविराधी नौकर थे। इसके विपरीत, वे उस समय भारतीय समाज की सबसे प्रगतिशील शक्तियाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। जब तक नवोदित मजदूरवर्ग पूरी तरह संगठनविहीन था और उसकी कोई आवाज नहीं थी तथा किसानवर्ग भी अमगठित और छामोश था, भारत का पूँजीपतिवर्ग ही सबसे ज्यादा प्रगतिशील और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी शक्ति था। वह समाज सुधार का काम करता था, लोगो में जागृति फैलाता था तथा पिछड़ी और दकियानूस तमाम चीजों के खिलाफ 'योगो में शिक्षा का प्रसार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने का काम करता था। उन्होंने मांग की थी कि भारत का तकनीकी और औद्योगिक आर्थिक विकास बिना जाए।

तब किन उसने इस नाम में ब्रिटिश साम्राज्य उनकी मदद करेगा यह विश्वास और आशा जूठी साबित होनी लगी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इन 'योगो में ज्यादा बहल' इस रूप में प्रगतिशील कार्य के महत्व को समझा और महसूस किया कि साम्राज्यवादी हिता और शासन से अनिवार्यतः इसका आगे चलकर टकराव होगा। इसलिए शुरू के दिनों में कांग्रेस का जो मर्यादा मिला था वह मदहूँ और शत्रुता में बदल गया। कांग्रेस की स्थापना के तीन वर्षों के अंदर ही लाड उफरित हो जिनकी प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बड़े अपमानजनक ढंग में कांग्रेस के बारे में कहा कि यह 'बेबल मुँद्री भर लोगो का' 'गठन' है। श्रीमती बर्मेन्ट ने अपनी पुस्तक 'हाउ इंडिया राट फार फ्रीडम' में लिखा है कि '1887 में जब एक प्रतिनिधि ने अपने जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तो उससे 20,000 रुपये की जमानत मांगी गई कि वह शांति में भाग करे।' 1890 में मद्रास में एक सर्वूलर के जरिए सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उद्देश्य की हैमियत में

भी भाग लेन की मनाही की गई। 1900 में लाड कजन ने भारतीय मामला के मंत्री के पास एक पत्र में लिखा कि 'वाग्रेस अब लड़खड़ा कर मिरने ही वाली है और मेरी बड़ी महत्वानाशाही में से एक महत्वाकांक्षा यह भी है कि भारत में रहत हुए मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करूँ।' (रॉनैल्डो लाइफ आफ लाड कजन' खंड 2, पृष्ठ 151)

अतः भारतीय राष्ट्रवाद की पुरानी धारा के नेताओं के अंदर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जो आशा पैदा हो गई थी वह अब टूट गई। नरमपथियों के शीपस्थ नेता श्री गोखले ने अपने अंतिम वर्षों में बड़े क्षोभ के साथ कहा कि नौकरशाही बहुत शाफ़्तोर पर और तेजी से स्वार्थी होती जा रही है और राष्ट्र की आकांक्षा का धुनकर विरोध कर रही है। पहले यह ऐसी नहीं थी।' (हिस्ट्री ऑफ़ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस', 1935, पृष्ठ 151)

पुरानी नीति के असफल हान की बात जैसे जैसे साफ़ होती गई वैसे वैसे एक ऐसी नई धारा का जन्म होना अनिवार्य होता गया जो 'पुराने महारथियों की आलोचना करे और वास्तविक कार्यक्रम की मांग करे तथा ऐसी नीति अपनाए जिसका अर्थ साम्राज्यवाद से निश्चित रूप से संघर्ष तोड़ लेना हो। यह नई धारा जिसका संघर्ष खासतौर से बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व से था, 19वीं सदी के अंतिम दशक में ही देश के सामने आ गई थी लेकिन वह तब तक कोई निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर सकी जब तक कि 20 दशक में स्थिति पूरी तरह तैयार नहीं हो गई। तिलक का क्षेत्र बंबई प्रेसीडेंसी में महाराष्ट्र था जहाँ 19वीं सदी के आठवें दशक में महत्वपूर्ण किसान विद्रोह हुआ था। तिलक के साथ-साथ जिस नए नेतृत्व का उदय हुआ उनमें बंगाल में बिपिनचंद्र पाल और अरबिका घाव तथा पंजाब में लाला लाजपत राय प्रमुख थे।

'नई धारा' के नेता अपना अपना राष्ट्रवादी तथा अखंड राष्ट्रवादी और बटुए राष्ट्रवादी भी कहते थे। व्यापक तौर पर वे 'नरमपंथी' नेताओं के मुकाबले 'उग्रपंथी' के रूप में जाने जाते थे। इन शब्दों के अर्थ में यह समझ लेना गलत होगा कि उनमें मात्र इतना ही फर्क था कि एक या दो प्रगतिशील वास्तविकीय पक्षों का और दूसरा अक्रियानुगामी विचारों का लोका का दर्शनपथी भेदा। दरअसल उग्र स्थिति का एक परस्पर विरोधी चरित्र था जिसमें महत्वाकांक्षिता या कि राष्ट्रवादी आदर्शों का अभी भी अग्रचरित्र विचार हुआ था।

पुराने महारथियों के मुकाबले विरोध पक्ष की पुर्नजाति की दिशा में यह आशा थी कि साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने की नीति का निराकरण हो जाय और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक निर्णायक और दृढ़पंथी संघर्ष का सम्मान अर्जित हो जाय। जहाँ तक यह जातिवाद का प्रश्न है तो प्रगतिशील और राष्ट्रवादी स्थिति का प्रति-निधित्व करने वाले अग्रपंथी आदर्शों में भी जातिवाद का अभाव था। अब भी

किसी ऐमे जनआदोलन का आधार नही बना था जो निर्णायक सभ्य का सभ्य बना सकता। इन नेताओ का प्रभाव असतुष्ट निम्न मध्यवर्ग पर, पढे लिखे नौजवानो के दिलो पर और खासतौर स निधन छात्रो तथा बेरोजगारो की बढ़ती सख्या या अत्यंत निम्न वेतनभोगी बुद्धिजीवियो पर था। बीसवी सदी के प्रारम्भिक त्रयों मे इनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। इन्ह बराबर यह अहसास होता जा रहा था कि साम्राज्यवादी शासन व अधीन न तो इनकी प्रगति वा कोई माग प्रशस्त हो सक्ता है और न इनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति मे निम्न मध्यवर्ग व लोगो के अंदर दतना घैय नही था कि वे उच्चवर्ग के नेताओ की उन वाता को सुनत रह जिनमे धीरे धीरे विकास होने का आसामदायक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता था। सामाजिक सक्रमण और पुरानी समाज व्यवस्था के आसन विघटन के दौर मे ऐसे तत्व जनता व असतोष और उसकी दृढ आतिवारी शक्ति को बढ़ाने मे काफी सहायक सिद्ध हो सकते है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि जब तक ये लोग जन आदोलनो से अपना सबध नही जोडते तब तक ये लोग अपनी आकांक्षाए पूरी नही कर सकते और ऐसी स्थिति मे वे या तो जवानी विरोध व्यक्त करके अपना राप निकाल तेते है या अराजकतावादी और व्यक्तिवादी काम करते है जिनका अतंत राजनीतिक दृष्टि से कोई लाभ नही होता।

यदि नए नेताओ व पास कोई आधुनिक सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि होती तो वे यह जरूर समझते कि उनका और उनके समर्थको का मुद्दा काम है मजदूरों और किसानों के संगठन को उनके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति संग्राम के आधार पर विकसित करना। लेकिन 20वी सदी के पहल दशक मे भारत की जो स्थिति थी उसमे इस तरह की समझदारी की अपेक्षा करने का अय यह हाता कि सामाजिक विकास की मौजूदा अवस्था मे जैसी समझदारी हानी चाहिए उससे बढ़कर कोई अपेक्षा की जा रही है।

समाज तथा राजनीति के किसी वैज्ञानिक सिद्धांत स कट होने के कारण इन नए नेताओ ने नरमदली नेताओ की समझौतावादी और प्रभावहीन नीति का कारण यह समझा कि पुरान नेताओ के अंदर 'राष्ट्रीयता का अभाव' है और उनका अंदर पश्चिमी रंग ढंग की प्रवृत्तिया हैं। इसलिए नए नेताओ ने अपने प्रहार का निशाना इन प्रवृत्तियों को बनाया। इस प्रकार इन नेताओ ने नरमदली नेताओ की ठीक उही बातों की आलोचना की जो सचमुच प्रगतिशील वाते थी। इनने मुवात्रल मे उहान राष्ट्रीय आदोलन का सामाजिक रजिवाद की उन प्रवृत्तियों पर खडा करना चाहा जो भारत मे अब भी बहुत शक्तिशाली थी। उहान राष्ट्रीय आदोलन व निर्माण के लिए बटूर हिंदुत्व का महारा लिया और इस मायता का बन दिया कि आधुनिक पश्चिमी गम्भता की तुलना मे प्राचीन हिंदू या 'आप' सम्प्रदा आध्यात्मिक दृष्टि मे श्रेष्ठ है। उन्हने भारत व मध्याधिक प्रगतिशील आदोलन अर्थात राष्ट्रीय आन्दोलन को पुरानतपयी धर्म और धार्मिक अधविश्वाम की नींव पर खडा करना चाहा। इस युग मे ही भारत मे उभरानी राजनीति और सामाजिक

प्रतिक्रियावाद का घातक गठजोड़ हुआ जिसका राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बेहद विध्वंसकारी परिणाम हुआ जिसके प्रभाव को नष्ट करना अब भी बहुत कठिन है।

उग्र राष्ट्रवाद का कट्टर हिंदूवाद की जबरदस्त प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ के साथ गठबन्धन की अभिव्यक्ति 1890 में उस समय हुई जब तिलक ने 'एज आफ कमेंट बिल' के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। इस बिल में यह प्रावधान था कि लड़की की उम्र दस की बजाय बारह वर्ष हो जाने के बाद ही उसका पति उसके साथ सहवास कर सकता है। इस बिल का रानाडे तथा अन्य प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं ने ममथन किया था। तिलक ने उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन का नेतृत्व किया और हिंदूवाद की धोर प्रतिक्रियावादी शक्तियों की ओर से आवाज उठाई। बाद में उन्होंने 'गारक्षा समिति' का गठन किया। (हिंदुत्व के सिद्धांतों के अनुसार गाय की पवित्रता की जो बात की गई है वह उस युग विशेष की जब इस मत का प्रवर्तन किया गया—सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सभी धार्मिक रिवाजों की तरह मूलतः व्याख्येय है किंतु इससे अनुपयोगी भवेलिया को प्रोत्साहन देना आर्थिक दृष्टि से एक प्रतिक्रियावादी कदम है। इससे भवेलियों की स्थिति में गिरावट आती है और साथ ही यह मुसलमानों के साथ मधप का एक खतरनाक स्रोत भी है क्योंकि वे गाय का मांस खाना अनुचित नहीं समझते हैं)। मराठों के राष्ट्रीय नायक शिवाजी की स्मृति में ही नहीं बल्कि हाथी की सूँड वाले देवता गणेश की स्मृति में भी धार्मिक ढंग से राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाने लगे। बंगाल में कुछ विशेष उत्साही लोगों द्वारा सहार की देवी काली की पूजा भी बड़ी धूमधाम से शुरू की गई।

इन धार्मिक स्वरूपों के पीछे जो राष्ट्रीय और देशभक्ति पूरा उद्देश्य छिपे है उन्हें जान लेना आवश्यक है। धार्मिक कृत्यों की आड़ लेकर व्यापक तौर पर वार्षिक समारोह और सभाओं के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए। धार्मिक नामों से अनेक सम्मेलन बनाई गई और युवकों की जिमनास्टिक समितियों का गठन करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया। जब तक राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार नहीं प्राप्त था तब तक तो इन रूपों का सहारा लेने की बात समझ में आती है क्योंकि तब तक सभी प्रत्यक्ष राजनीतिक संगठनों और आंदोलनों का साम्राज्यवादियों द्वारा जबरदस्त दमन किया जाता था। फिर भी यहाँ महज यह प्रश्न नहीं है कि राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक उत्सवों का सहारा लिया जाता था। यहाँ यह भी प्रश्न नहीं है कि किसी राजनीतिक आंदोलन के विकास का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है। इस बात पर जोर दिए जाने से कि कट्टर धार्मिकता ही राष्ट्रीय आंदोलन की जान है और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले प्राचीन हिंदू सभ्यता की कल्पित जात्यात्मिक श्रेष्ठता (जिसे आधुनिक मानवैज्ञानिक निस्संदेह एक प्रतिवारी भ्रांति कहेंगे) की घोषणा करने से राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चेतना के वास्तविक विकास में अनिवार्य रुकावट आई और यह कमजोर हुआ है। मुस्लिम जनमत के एक बहुत बड़े हिस्से के राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहने का एक कारण यह भी है कि आंदोलन में हिंदुत्व पर चरानर जार दिया जाता रहा।

ये भयधारणाए भारतीय राष्ट्रवाद के बाद के विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक युग में गांधीवाद में भय अवधारणाए और भी परिष्कृत रूप में प्रकट हुई है, अतः इनका और भी सावधानी से विश्लेषण करना जरूरी है। इसका कारण यह है कि इन धारणाओं में इस विश्वास की अभिव्यक्ति की गई है कि भारत की आजादी का रास्ता सामाजिक विकास, तथा पुरानी कमजोरियाँ, आपसी फूटों और हानिप्रद परस्परालोचनों को दूर करने का रास्ता नहीं है बल्कि वह समाज को पीछे खींच लाना तथा अतीत के अवशेषों और तौर-तरीकों को फिर से जीवित करने का रास्ता है।

हमने यह देखा है कि यह दृष्टिकोण कैसे पैदा हुआ। बहुत राष्ट्रवादियों की दृष्टि में उच्च-यग के पुराने नरमदली नताआ की दृष्टि और कायपद्धति 'राष्ट्रीयताविहीन' हो चुकी थी और वे ब्रिटिश पूजोपनिषद् का सामाजिक जीवन और राजनीति सीख चुके थे। इस 'राष्ट्रीयता विहीनता' या ब्रिटिश संस्कृति के प्रति आत्मसमर्पण के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करना चाहा। लेकिन किस आधार पर वे इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके ?

वस्तुतः वे खुद ही पूजोवादी विचार के मनुचित दायरे में कैद थे (उस समय तब भारत के राजनीतिक जीवन का व्यवहार रूप में समाजवाद के साथ कोई संपर्क नहीं हो सका था), और इसीलिए वे पूजोवाद की कायपद्धति को उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को आलोचनात्मक समझ के साथ नहीं देख सके। फलस्वरूप वे यह नहीं समझ सके कि जिस तथाकथित 'ब्रिटिश' संस्कृति की वे निंदा कर रहे हैं वह वास्तव में पूजोवाद की संस्कृति है, वे यह नहीं समझ सके कि जहाँ तक पूजोपनिषद् के नेतृत्व का संबंध है, राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक उस आधार से परे नहीं जा सका है, और वे यह नहीं देख सके कि निर्णायक रूप से उस संस्कृति का प्रगतिशील विरोध मजदूरवर्ग ही कर सकता है। भारत में उस समय के अपने अनुभवों के आधार पर वे उदीयमान मजदूरवर्ग के दृष्टिकोण और उगरी संस्कृति की कोई धारणा नहीं बना सका जबकि यह संस्कृति ही बुनियादी संस्कृति का विकल्प थी और यह संस्कृति ही बुनियादी संस्कृति की अच्छाईयाँ का ग्रहण करे और बुराईयाँ का छाटकर उससे आगे बढ़ सकती थी। इसलिए जब उन्होंने विजनाआ की संस्कृति के विरोध के लिए किसी मजदूर आधार की तलाश शुरू की तो वह आधार रूप में विजेताओं से आने के पहले भारत में पूजोवाद से पूर्व की जो संस्कृति थी उस वही दिखाई पड़ सकी।

/

इसलिए पतनशील और भ्रष्ट तत्वमीमासा के वर्तमान दूषित घालमेल में छिन्न भिन्न हुई ग्रामीण अव्यवस्था के टूटे अवशेषों से, एक लुप्त सभ्यता की दरवारी भव्यता के शेषों से, उन्होंने हिंदू संस्कृति का, शाश्वत हिंदू संस्कृति का सुनहरा सपना फिर से तैयार करने की वांछना की और इसे ही आदर्श और मार्गदर्शक प्रकाश माना।

उन्होंने देखा कि ब्रिटिश पूजोवादी संस्कृति और विचारधारा की प्रचंड वात में भारतीय

पूजीपतिवग तथा बुद्धिजीवी पूरी तरह बहे जा रहे हैं इसलिए इस स्थिति पर पाबू पाने के लिए उन्होंने एक पुनर्निर्मित कमजोर हिंदू विचारधारा का महाराग लिया हाना कि वास्तविक जीवन में इस विचारधारा का अब कोई सहज आधार नहीं रह गया था। अपेक्षाकृत अधिक उग्रपथी नेताओं द्वारा हर तरह के सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास की भत्सना की जाने लगी और हर तरह की पुरानी बातों को सम्मान दिया जाने लगा। यहाँ तक कि बुरी प्रथाओं, स्वेच्छाचारिता और अधविश्वासों को भी श्रद्धा और सम्मान दिया जाने लगा।

यही वजह थी कि जनता के ये जुझारू राष्ट्रीय नेता, जिनमें से अनेक काफी निडर और निष्ठावान थे और जो अतीत के अवशेषों से लोगों को दूर खींचकर मुक्ति और समन दारी के रास्त पर आगे बढ़ा सकते थे, व्यवहार में सामाजिक कुरीतियों और अध विश्वासा के समर्थक बन गए, जातिपात के भेदभावा और विशेषाधिकार की हिमायत करने लग और काफी बत्ता-चढ़ाकर वणन करने वाली एक रहस्यवादी 'राष्ट्रीय' भावना के नाम पर उ होने उन सामाजिक और विचारधारात्मक पुरानी वेडियों को बनाए रखने की कोशिश की जो अगरेजों के आन से पूर्व यहाँ मौजूद थी।

कट्टर राष्ट्रवादियों की धारणा थी कि इसी तरीके से वे साम्राज्यवाद के विराध के लिए एक राष्ट्रीय जनआंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। केवल इसी बात से यह तथ्य समझ में आता है कि क्यों तिलक जसा बौद्धिक व्यक्ति भी बालविवाह तथा गारक्षा के समर्थन में आंदोलन चल रहा था।

लेकिन सच्चाई यह थी कि यह नीति सिद्धांत में ही नहीं व्यवहार में भी घातक थी। इससे न केवल लाजिमी तौर पर राजनीतिक चेतना के विकास और आंदोलन के प्रति स्पष्टता में बाधा पैदा हुई (लगभग सभी सुविख्यात उग्रवादी नेताओं में किसी ने कम किसी ने अधिक, बाद में या तो साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करना शुरू किया या राजनीति के प्रति सदिग्ध अयमनस्कता का परिचय दिया और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति में आत गए कि बाद के वर्षों में आंदोलन की प्रगति से उनकी हमदर्दी खत्म हो गई), बल्कि प्रगामी शक्तियाँ जापस में बंद भी गई। सामाजिक मामलों में उग्रपथी नेताओं के प्रतिनिध्यावादी 'नायक'ों के कारण ऐसे तमाम लोग आंदोलन से दूर हटते गए जो एक जुझारू राष्ट्रीय नीति का समर्थन करने का तो तैयार थे पर इतने विलक्षण नहीं थे कि वामपथी कार्यक्रम के स्थान पर प्रतिनिध्यावादी और अलौकिक कूड़ा बचरा स्वीकार करने लगे। यह विभाजन मोतीलाल नेहरू व मामल में बहुत साफ तौर पर दखा गया। मोतीलाल नेहरू, एक चरित्रवान व्यक्ति थे और उग्रपथियों के विरुद्ध नरमदली नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सघप के नेताओं में से एक थे। उनके बारे में उनके पुत्र ने लिखा है

दढ़ विचारों आजम्बी मनाभावा, जवरनस्त आत्माभिमान और महान् दृष्टाशक्ति

स युक्त होन के कारण वह (मोतीलाल नेहरू) नरमदली विचारो की प्रवृत्ति से काफी दूर थे। और फिर भी 1907 और 1908 में तथा बाद क वर्षों में निम्नदेह यह नरमदलिया में भी नरमदली थे और उग्रवादियों के काफी कटु आलोचक थे, हालांकि, मेरा ख्याल है कि वह तिलक की प्रशंसा करते थे।

ऐसा क्या था ?—अपने स्पष्ट सोच से वह इस नतीजे पर पहुँचे थे कि बड़ी जोशीलों और उग्र भाषा से तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उस भाषा के अनुबूल व्यवहार न किया जाए। उन्हें ऐसे किसी व्यवहार की संभावना नहीं दिखाई दी—और इसके अलावा इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि धार्मिक राष्ट्रवाद थी जो उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध थी। उन्होंने भारत के अतीत के पुनः प्रवर्तन की ओर कभी नहीं देखा। उन्हें उन चीजों से कोई हमदर्दी नहीं थी और वे तमाम पुराने रीति रिवाजों, जातपात के भेदभाव जैसी चीजों की प्रतिक्रियावादी समझते थे और इनमें बहद नफरत करते थे। उन्होंने पश्चिमी देशों की तरफ देखा और पश्चिम, देशों की प्रगति से काफी आकर्षण महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड के साथ साहचर्य के जरिए यह प्रगति भारत तक पहुँच सकती है। सामाजिक विकास की दृष्टि से बड़े तो 1907 में भारतीय राष्ट्रवाद का जो पुनः प्रवर्तन हुआ वह निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी था। (जवाहरलाल नेहरू 'आत्मकथा', पृष्ठ 23-24)

कट्टर राष्ट्रवादियों ने हालांकि अपने तर्कों के लिए यह धार्मिक आधार तैयार कर लिया था पर व्यावहारिक सघर्ष में वे कोई नया अस्त्र या कोई नई कार्ययोजना नहीं बना सके, सिवाय उस व्यक्तिवादी आनंदवाद के अस्त्र के जो हर देश में निराश किंतु नपुंसक और जनआंदोलन से कट निम्नपूजोपतिवर्ग का अस्त्र रहा है। यहाँ भी उस अस्पष्ट धार्मिक उत्प्रेरणा और उत्तेजना ने तथा गुप्त समितियों के गठन में बहुत कम असर दिखाया (हालांकि आतंकित साम्राज्यवादियों ने उनका काफी प्रचार किया और उनसे गठन पर काफी चिल्लियों की। जनता के विध्वंस के साम्राज्यवादियों को अपन तरीके के बेहद भयानक थे जिसकी जबरदस्त मिसाल बाद में अमृतसर में देखने में आई) और तब तक उसने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा की जब तक बाद में आंदोलन के एक नए युग की गुरुआत के लिए स्थितिमा परिपक्व नहीं हो गई और आतंकवादी आंदोलन ने सहयोगी की भूमिका नहीं निभाई।

1905 तक, जब आंदोलन के एक नए चरण के लिए स्थितिमा तैयार हो गई तब जो नया अस्त्र बूझ निकाला गया वह उनकी तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक अटकलवाजियों से बहुत दूर की चीज थी और मूलतः उसका एक आधुनिक और आर्थिक स्वरूप था—और यह अस्त्र आर्थिक बहिष्कार का अस्त्र था। आर्थिक बहिष्कार का यह अस्त्र उस युग का एकमात्र शक्ति प्रभावकारी अस्त्र था और इस तरीके के चुनाव में ही आंदोलन के युजुआ



चरित्र का पता चलता है। निम्सदह नरमदली नेताओं ने इस हथियार का समयन किया।

1905 में संधप के नए दौर की शुरुआत के लिए जो शक्तियाँ एकजुट हुईं वे वस्तुतः विकास की उस विश्वव्यापी लहर का ही प्रतिबिम्ब थी जो जापान के हाथा जारशाही की पराजय (आधुनिक युग में यूरोपीय शक्ति पर किसी एशियाई शक्ति की यह पहली विजय थी और भारत पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा) और पहली रूसी क्रांति की प्रारम्भिक विजय के बाद विश्व में आई थी। जिस तात्कालिक मसले पर भारत में संधप का सूत्रपात हुआ वह बंगाल के विभाजन (वर्गभंग) का मसला था। बंगाल उन दिनों भारत में राजनीतिक प्रगति का केंद्र था और उसके विभाजन की योजना लाड वर्जन ने तैयार की तथा उनके उत्तराधिकारी ने इसको असली रूप दिया। इस विभाजन के विरोध में देश भर में रोप की लहर फैल गई और 7 अगस्त 1905 को विदेशी सामानों के बहिष्कार की घोषणा की गई।

इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी तजी आई। फिर भी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन ने इस बहिष्कार को सशत समर्थन दिया। लेकिन 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन ने जो बुरी तरह उग्रपथिया के प्रभाव में था, एकदम नया कार्यक्रम स्वीकार किया। इस कार्यक्रम की स्वयं कांग्रेस के पुराने जन्मदाता दादाभाई नौरोजी ने पेश किया था। इस कार्यक्रम में पहली बार घोषणा की गई कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए भारत को स्वयं अपना शासन चलाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए (ऐसी राज्य व्यवस्था जैसी अंगरेजों के अपना शासन प्रबंध स्वयं चलाने वाले उपनिवेशों में कायम है)। इस कार्यक्रम में बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी या देशी उद्योग धंधों का प्रोत्साहन देने का समर्थन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा की हिमायत की गई। कांग्रेस कार्यक्रम की अब ये चार मूलभूत बातें हो गईं। स्वराज, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा।

एक वर्ष बाद अर्थात् 1907 में सूरत कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। नरमदली गुट का नतत्व मोक्षनेत्रों ने और उग्रपथियों का नतत्व तिलक ने किया। एक घटना के आधार पर जो काफी समय तक विवादोत्पन्न ममला रहा, यह बात बिना किसी सन्देह के कही जा सकती है कि उग्रपथियों के बन्ते प्रभाव से नरमदली नेताओं ने डरकर बहुत मनमाने ढंग से ऐसी हुरफतों की जिससे कांग्रेस का दो टुकड़ा हो गया। इनके बाद 1916 में दोनों गुटों में फिर एकता हो गई लेकिन 1918 में नरमदली लोगो ने अंततः कांग्रेस का छोड़ दिया और अलग से अपना लिबरल फेडरेशन बना लिया।

जागृता में नई जागृति के आत ही सरकारी दमन भी काफी तेज हो गया। 1907 में

राजद्रोही समाज पर राय लगाने वाला कानून, सजीव मीडियम एक्ट बनाया गया और 1910 में एक नया और सख्त प्रेस कानून बनाया गया (1878 का पुराना प्रेस कानून लाइसेंस के उदार शासनकाल में रद्द कर दिया गया था)। 1818 के एक कानून के आधार पर उग्रपथी नेताओं के विरुद्ध बिना मुकदमा चलाए दण्डनिकाला का तरीका अपनाया गया। यह सारा काम 'उदार' भारतमन्त्री लाइ मार्ले के शासनकाल में हुआ। 1908 में तिलक को, जिन्होंने सरकार से सबसे ज्यादा झगड़ी थी अपनी अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुम में 6 वर्ष की सजा दी गई और उन्हें माइले में तब तक कैद रखा गया जब तक 1914 का विश्वयुद्ध नहीं छिड़ गया। तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिलमजदूरों ने आम हड़ताल की। भारत के सर्वहारा वर्ग द्वारा की गई यह पहली राजनीतिक वायवाही थी और लेनिन ने इसे भविष्य का शुभ संकेत मानकर इसका स्वागत किया। अजय महत्वपूर्ण नेताओं को या तो सजा दी गई या देशनिवाला दे दिया गया। कुछ लोग सजा से बचने के लिए देश छोड़कर चले गए। 1906 से 1909 के बीच अकेले बंगाल में 550 राजनीतिक मुकदमों में अदालत में पड़े थे। पुलिस का दमनचक्र बड़ी तेजी से चला, अनेक सभाएं ताड़ी गईं, पंजाब में किसानों के विद्रोह का बड़ी निमंभता-पूर्वक दमन किया गया और राष्ट्रीय गीत गान पर स्कूलों बच्चों का गिरफ्तार किया गया।

पहले ही की तरह इस बार भी दमन के साथ साथ रियायतों का मिलमिना जारी रहा ताकि 'नरमदली नेताओं को साथ' लिया जा सके। 1909 में प्रस्तुत मार्ले मिटो सुधार का अत्यंत सीमित रूप था। 1892 के इंडियन कॉमिन्स एक्ट के जरिए विधानपरिषदों में भारतीय प्रतिनिधि लेने के कार्यक्रम को थोड़ा विस्तार दिया गया। अब केंद्रीय विधान-परिषद में अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदस्यों के एक अल्पमत को तथा प्रांतीय विधान-परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को शामिल किया गया। ये परिषदें केवल सलाहकार समस्याएं थी और इनके पास कोई ठोस अधिकार नहीं थे। कांग्रेस पर अब नरमदली नेताओं का एकछत्र अधिकार हो गया और उन्होंने अंगरेज सरकार के साथ अपनी एकता व्यक्त करने के लिए इन सुधारों का लाभ उठाया, 1910 में नए वाय-सराय के आने पर कांग्रेसी नेताओं ने अपनी वफादारी में भारी भावनाएं व्यक्त की और 1911 में जब एक शाही फरमान के जरिए बंगाल के विभाजन का संशोधन किया गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एलान किया कि 'ब्रिटिश सम्राट के प्रति हर एक व्यक्ति का हृदय श्रद्धा और आदर से भरा हुआ है, हम ब्रिटिश राजनताओं के प्रति कृतज्ञ हैं और हमारा विश्वास उनमें फिर से दृढ़ हो गया है।'

1911 में बंगभंग का संशोधन किया जाना, यहिप्पार आंदोलन की आंशिक सफलता की अभिव्यक्ति करता है। 1906 से 1911 के बीच गंधी जी जो लहर उठी थी वह तुरंत बार के वर्षों में अपनी शक्ति खोना नहीं रह सकी लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्थाई विकास हुआ था वह कभी नष्ट नहीं हुआ। 1914 के पहले के वर्षों में अपनी समाज

के बावजूद उग्रपथी नेताओं ने एक महान और स्थाई काम कर डाला था, इतिहास में पहली बार भारतीयों की आजादी की मांग विश्व राजनीति के मंच पर एक प्रमुख प्रश्न का रूप ले चुकी थी, भारत के राजनीतिक आंदोलन में पूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के बीज रोप जा चुके थे। यही बीज आगे चलकर आम जनता के बीच अंकुरित हुए।

## २ सघर्ष की दूसरी बड़ी लहर, १९१९-१९२२

प्रथम विश्वयुद्ध ने साम्राज्यवाद के समूचे ढाँचे पर स्थाई और जबरदस्त प्रहार किया तथा १९१७ और इसके बाद के वर्षों में विश्व भर में क्रांति की एक लहर चल पड़ी जिसके परिणामस्वरूप भारत में भी विद्रोह के रूप में जनआंदोलन का सूत्रपात हुआ।

जिस प्रकार १९०५ के जागरण के द्वारा विश्वव्यापी आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई उसी प्रकार बल्कि उससे भी ज्यादा उस महान जनआंदोलन द्वारा विश्वव्यापी आंदोलन का संकेत मिला जिसे १९१७ के बाद के वर्षों में अंगरेजी राज की नींव हिला दी। विश्व की जनता के सघर्ष के साथ भारतीय जनता के सघर्ष के विकास की एकता को समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की परंपरागत राजनीतिक धारा में कुछ ऐसे भी मनोगतवादी और अलगाववादी तत्व हैं जो बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में भी यह भ्रम पैदा करते हैं कि इन आंदोलनों को कोई व्यक्ति विशेष या दल विशेष चलाता है और इनकी सफलता या विफलता से ही आंदोलन चल पाता है या बंद हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि १९१७ के बाद के वर्षों से ही भारत में राजनीतिक आंदोलन का रूपान्तरण शुरू हुआ और जो आंदोलन समाज के इने गिन लोगों तक ही सीमित था वह आम जनता तक पहुंच गया। लेकिन यह रूपान्तरण भारत तक ही सीमित नहीं रहा।

एक दशक पूर्व जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय के बाद १९१४ के विश्वयुद्ध ने एशियावासियों के सामने इस मिथक को चकनाचूर कर दिया कि पश्चिमी साम्राज्यवाद अपराजेय है। साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच जापान में जो आत्मघाती सघर्ष छिड़ा उससे गुलाम देशों की करोड़ों जनता का हृदय इस उल्लास से भर उठा कि साम्राज्यों के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं।

शुरू से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने विशेष कानूना और अधिनियम—खास तौर से भारत रक्षा अधिनियम का निर्माण करके और क्रांतिकारी गुटों के अत्यंत ज़हूर सदस्यों को गिरफ्तार करके या नजरबंद करके स्थिति पर काबू पाने के लिए बड़ी सत्ती से काम लिया। साम्राज्यवादी युद्ध के शुरू के वर्षों में उसे इस काम में राजनीतिक आंदोलन के उच्चवर्ग ने स्वेच्छा से मदद दी। काग्रस ने, जिसपर नरमदली नेताओं का कब्जा था, युद्ध के दौरान हुए अपने चार अधिवेशनों में सप्रत्येक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके साम्राज्यवादी युद्ध के प्रति अपनी निष्ठा और हमदर्दी की घोषणा की। १९१८ में युद्ध की

समाप्ति पर दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में ता उमन अगरेज सम्राट के प्रति निष्ठा का एक प्रस्ताव पारित किया और सम्राट का इस बात के लिए बर्खास्त दी कि युद्ध सफलता-पूर्वक समाप्त हो गया। बदले में सरकार ने भी कांग्रेस पर कृपा की, 1914 के कांग्रेस अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर लार्ड पैटर्नलैंड ने भाग लिया। इसी प्रकार 1915 के अधिवेशन में बंबई के गवर्नर लार्ड बिलिंगटन ने और 1916 के अधिवेशन में संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने भाग लिया। इन अधिवेशनों में सरकारी प्रतिनिधियों का बड़ी गरमजोशी के साथ स्वागत किया गया। युद्ध शुरू होने के समय भारत के जो प्रमुख नेता लंदन में थे उन्होंने सरकार के प्रति अपना समयन घोषित करने में बड़ी उर्जा दिखाई। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उन दिना लंदन में था जिसमें लाजपत राय, जिन्ना, सिन्हा आदि थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय मामला के मंत्री का एक निष्ठापूर्ण पत्र लिखकर यह विश्वास प्रकट किया कि 'साम्राज्यवाद की शीघ्र विजय के लिए भारत के राजे रजवाड़े और भारत की जनता तत्काल और स्वच्छा से अपनी पूरी सामर्थ्य भर सहयोग करेंगी और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह देश के सभी साधन सम्राट को अर्पित कर देगी।' गांधी उसी समय दक्षिण अफ्रीका में लंदन पहुंचे थे। उन्होंने सेसिल होटल में अपने सम्मान में आयोजित एक समारोह में अपने नौजवान भारतीय दोस्तों से कहा कि 'उन्हें साम्राज्य के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और अपने वतन का पालन करना चाहिए।' उन्होंने अपने तथा अन्य लोगों के हस्ताक्षर सहित भारतीय मामला के मंत्री के नाम एक पत्र भेजा और अपनी सेवाएं अर्पित करने का वचन दिया।

हममें से तमाम लोग ने यह उचित समझा है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने उत्पन्न वर्तमान संकट की घड़ी में जो भारतीय ब्रिटेन में रह रहे हैं और जो इस योग्य हैं उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को बिना शर्त अपनी सेवाएं पेश करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से और सलग्न सूची में उल्लिखित नामों की तरफ से ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं।

बाद में उन्होंने लंदन में रहने वाले भारतीयों का एक स्वयंसेवी चिकित्सा दल संगठित करने के सिलसिले में जो काम किया वह किसी से छिपा नहीं है। भारत वापस लौटने पर उन्होंने वायसरॉय के समक्ष फिर अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया और कहा कि मेसोपोटामिया के युद्ध में होने वाले घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाने के लिए वह एक दल का गठन करना चाहते हैं। वायसरॉय ने गांधी के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा न करने की सलाह दी और कहा कि 'ऐसे संकट के समय भारत में उनकी मौजूदगी ही अपने आप में किसी भी सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।' वायसरॉय ने जब 1917 में दिल्ली में एक युद्ध सम्मेलन बुलाया तो उसमें गांधी भी शामिल हुए और जुलाई 1918 में तो उन्होंने गुजरात में किसानों के बीच यह कहना शुरू किया कि 'फौज में होकर ही स्वराज मिल सकता है और उन्होंने रणरूढ़ों की भरती का प्रचार किया।

अगर सरकार के अधिकारियों ने नरमदली नेताओं की 'वफादारी' के इन प्रदर्शनों और वक्तव्यों का यह अर्थ लगाया कि ब्रिटिश शासनाधिकारियों के उपकारों का दखकर भारतीय नेताओं में काफी उत्साह पैदा हुआ है और वे कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सचार्थ यह था कि भारतीय नेताओं ने यह सोचा था कि युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहायता करने से भारत में स्वराज की स्थापना तेजी से हो सकेगी। इसी आशय का वक्तव्य 1922 में गांधी ने अपने मुकदमे के दौरान दिया था।

ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करने के इन सारे प्रयत्नों के पीछे मेरा यह विश्वास था कि इस प्रकार की सवाबा के जरिए मैं अपने देश की जनता के लिए पूरा समानता का स्थान प्राप्त कर सकूंगा।

वाद में इन नेताओं का मोह भग हुआ और इसे उन्होंने स्वीकार भी किया। राजनीतिक नेतृत्व के उच्चवर्ग की इस नीति के बावजूद जनता का असंतोष, जो युद्ध के कारण काफी बढ़ गया था और भी बढ़ता गया। युद्ध का खर्च चलाने के लिए भारत की अत्यंत गरीब जनता में काफी कड़ाई के साथ पैसा वसूला गया चीजों की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई और मुनाफाखोरा ने अधाधुन कमाई की जिससे लोग तबाह और बरबाद हो गए। इन सारी बातों का नतीजा यह हुआ कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इनफ्लुएंजा फैला जिसमें एक करोड़ 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जनता के बढ़ते असंतोष की अभिव्यक्ति पंजाब के गदर आंदोलन और सेना में हुए विद्रोहों में हुई। इन आंदोलनों और विद्रोहों का बड़ी बरहमी में कुचल दिया गया और तमाम लोगों को फांसी और कैद की सजा दी गई। 1917 में इंग्लैंड के एफ जे की देखरेख में रोलट कमिशन नियुक्त किया गया जिसका काम 'भारत में चल रहे प्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित घटायों की जांच' के बाद यह सिफारिश करना था कि इन आंदोलनों का दमन करने के लिए कौन से नए दमनात्मक कानून बनाए जाए।

धीरे धीरे जनता का बढ़ता हुआ असंतोष राजनीतिक आन्दोलन के रूप में सामने आने लगा और 1916 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ नई प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी। 1916 में तिलक ने होम रूल फार इंडिया लीग अर्थात् भारत में स्वराज की स्थापना का सवर्धनसत्त्वा का गठन किया। उनके अभियान में एक अगरेज विमोतोफिस्ट महिता श्रीमती एनी बेसेंट शामिल हुई जो राष्ट्रीय आंदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति 'वफादारी' के रास्ते पर खींचने की वांछित करती थी। श्रीमती बेसेंट ने बाद के वर्षों में असहयोग आंदोलन का सक्रिय रूप से विरोध किया। 1916 में लघाऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उग्रप्रवियों और नरमदली नेताओं में फिर मत हा गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग (1905 में स्थापित) के बीच गठबंधन कराने की जा वांछित 1913 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन से 'गुप्त' हुई थी उन वांछितों को 1916 के अंत तक सम्पन्नता मिल गई। इस सम्पन्नता का पीछा एक

कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने टर्की के पिटाफ लड़ाई लड़े दी जिसकी वजह से मुस्लिम जनता में काफी रोष फैल गया था और 1915 में मुस्लिम लीग काफ़ेस में यह भावना व्यक्त भी की जा चुकी थी। 1916 में दोनों मस्त्वाआ के बीच लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ जिसका आधार ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहने हुए आशिक स्वराज था (इस सम्मेलन की खान वार्ते ये थी कि कौंसिल में चुने हुए सदस्यों का बहुमत हो कौंसिल के अधिकार बढ़ाए जाए और वायसराम की वायकारिणी के आधे सदस्य भारतीय हों)। इस सम्मेलन की कांग्रेस-लीग योजना नाम दिया गया। इसके साथ ही दोनों मस्त्वाआ द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का लक्ष्य यह है कि उस 'साम्राज्य के अंदर स्वशासी डोमीनियनों जैसा बराबरी का दर्जा मिले।'।

जब 1917 में हसी फ़ाति के बाद विश्व की न्यति में तेजी के साथ परिवर्तन आया तो समूचा घटनाचक्र इससे प्रभावित हुआ और इसकी अभिव्यक्ति ब्रिटेन और भारत के संबंधों में हुई। हसी फ़ाति ने राष्ट्रीय के आत्मनिर्णय के सवाल को और पुराने साम्राज्य के विघटन के मामले को इस तरह विश्व के सामने ला दिया कि दोनों पक्षों की साम्राज्यवादी शक्तियाँ काफी परेशानी में पड़ गईं। जारशाही के पतन के पाँच महीनों के अंदर ही ब्रिटिश सरकार ने जल्दी जल्दी एक एलान किया (इस घोषणा को मोटागू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मोटागू उस समय भारतीय मामलों के मंत्री थे लेकिन वस्तुतः इस घोषणा की योजना ब्रजन और चयरेलेन ने बनाई थी और उन्होंने ही इसे तैयार भी किया था)। इस घोषणा के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन के लक्ष्यों की व्याख्या करत हुए कहा गया था कि अंग्रेजी राज्य का उद्देश्य 'स्वायत्त शासन की सत्त्वाआ का धीरे धीरे विकास करना है जिसमें भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन रहने के बावजूद तमश जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में बढ़ सके।'। इसके साथ ही इस घोषणा में यह भी वायदा किया गया था कि 'इस दिया में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे।'। ब्रिटिश सरकार ने कितनी जल्दबाजी में यह घोषणा की थी इसका पता इस तथ्य से ही चल जाता है कि घोषणा कर देने के बाद इस बात की जांच शुरू की गई कि इस घोषणा का मनसब क्या था। इस जांच के परिणाम के आधार पर कही एक साल बाद जाकर मोटागू रेम्सफोर्ड रिपोर्ट तयार हुई। 1919 की समाप्ति तक सुधारों को (प्रान्तों में तथाकथित 'डार्डआर्की' प्रथा के अनुसार अर्थात् अंग्रेजी और भारतीय मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाना) लागू नहीं किया गया। उन सुधारों पर अमल करना 1920 में शुरू हुआ और तब तक भारत की समूची परिस्थिति में तब्दीली आ चुकी थी।

इससे दस वर्ष पहले मार्ले मिटल योजना के साथ इस तरह के सुधारों को आशिक सफ़लता मिल चुकी थी और इन सुधारों के जरिए उच्च वर्ग के राष्ट्रीय सेमे में फूट के बीज बोए जा चुके थे लेकिन इस प्रकार नरमदली नेताओं का जो समर्थन प्राप्त किया गया था उन वा बतमान घटनाक्रमों के दौर में वही राजनीतिक महत्व था। 1917 के अंत में बलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती वसेंट ने की। उन्होंने इस

अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कराया जिसमें कहा गया था कि 'एकता के सूत्र में बंधी हुई भारतीय जनता की ओर से कांग्रेस, महामहिम सम्राट को अत्यंत निष्ठापूर्वक और सम्मान के साथ अपने गहरे प्रेम का विश्वास दिलाती है तथा यह निवेदन करती है कि भारत की जनता हर कीमत पर और हर तरह की परेशानियाँ के बीच रहकर भी ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देगी।' लेकिन 1918 की गमियों में जब मोटामू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो बर्बर म. कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में इन प्रस्तावों की गई और इन्हें काफी निराशाजनक और असंतोषजनक कहा गया। कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन के बाद ही गांधी को छोड़कर अन्य सभी नरमदली नेता कांग्रेस से अलग हो गए और बाद में उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की जिसमें बुजुर्गों वगैरे के उन्हीं तत्वों का प्रतिनिधित्व था जो साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करना चाहते थे। दिसंबर, 1919 तक कांग्रेस ने फिर सुधारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया लेकिन इस बार इस मसले पर काफी मतभेद दिखाई दिया जिसमें गांधी ने श्रीमती बसेंट के समर्थन से सहयोग के लिए संधि का नेतृत्व किया और इसके विरोधी पक्ष का नेतृत्व सी० आर० दाम ने किया। अंतिम पारित प्रस्ताव में सुधारों की एक बार फिर आलोचना की गई और साथ ही यह मांग की गई कि 'आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार पूरी तौर पर उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार कायम करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए।' लेकिन इसके साथ ही प्रस्ताव में गांधी द्वारा पण किए गए इस मशौघन को भी जोड़ दिया गया जिसमें कहा गया था कि 'जब तक ऐसे कदम नहीं उठाए जाते तब तक कांग्रेस का यह विश्वास है कि जहाँ तक संभव होगा भारत की जनता इन सुधारों से इस तरह काम लेगी कि जल्द ही देश में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की जा सके।' 1919 की समाप्ति तक भी गांधी की धारणा सरकार के साथ सहयोग करने और सुधारों को मंजूर करने की थी। उन्होंने वष की समाप्ति पर अपने साप्ताहिक पत्र में एक लेख में लिखा था

सरकारी घोषणा के साथ सुधारों से संबंधित जो कानून पारित हुआ है उससे पता चलता है कि अंगरेजों को लग भारत के साथ न्याय करना चाहते हैं और इस बारे में अब हमारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि सुधारों की अवधारणा आलोचना न करके चुपचाप उनसे अनुसार काम करना शुरू करें ताकि इन सुधारों को सफलता मिल सके। (एम०के० गांधी 'यंग इंडिया', 31 दिसंबर 1919)

यह घोषणा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस घोषणा से पहले ही रोलट कानून बन चुके थे अमृतसर की घटना घट चुकी थी और पंजाब में मासल ला लागू हो चुका था। कहा जा सकता है कि यह घोषणा इन तीनों घटनाओं के बाद की घोषणा है जिनके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण बताया गया था। इस प्रकार यह पता चल जाता है कि जब इस घोषणा के अगले वर्ष राष्ट्रीय नेताओं ने असहयोग आंदोलन

छेड़ने का फैसला किया उस समय इन घटनाओं से अनग कुछ और जाने भी उनके ध्यान में थी।

दरअस्त काग्रेस वने तो अब भी सरकार के साथ सहयोग कर रही थी लेकिन 1919 में भारत की समूची स्थिति बिनाकुल बदल गई थी और कांग्रेस की सहयोग की नीति का समूचा आधार नष्ट होता जा रहा था। 1919 में समूचे देश में कानिकारी असतोप की व्यापक तहर देखने में आई। वर्ष 1918 के अंतिम और 1919 के शुरू के महीना में हड़ताल का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जैसा पहले भागत में कभी नहीं देखा गया था। दिसंबर 1918 में बंबई की मिलों से हड़ताल की शुरुआत हुई। जनवरी 1919 तक एक लाख 25 हजार मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया। 1919 के शुरू के दिनों में गैलट ऐक्ट पेश किया गया और माच के महीने में इसे लागू कर दिया गया। इस कानून का उद्देश्य यह था कि युद्ध के दौरान सरकार ने विशेष कानूनों को पारित करके दमन के जा असाधारण अधिकार अपन हाथ में ले लिए थे उन्हें युद्ध समाप्त हो जाने और विशेष कानूनों की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी सरकार के हाथों में बनाए रखा जा सके ताकि उसे अदालती कायवाही किए बिना मुकदमा चलाए बिना लोगों का जेल में बंद रखने का अधिकार मिल सके। रोलट ऐक्ट से जनता के बीच काफी असतोप फैला और जनता ने यह महसूस किया कि सुधारों की आड़ लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने जबरदस्त हुकूमत का इस्तमाल कर रहा है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने अनुभवों के आधार पर रोलट कानूनों के खिलाफ अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन चलाने की कोशिश की और इस उद्देश्य से उन्होंने फरवरी में सत्याग्रह लीग नामक एक संगठन की स्थापना भी कर दी। जनता से अनुरोध किया गया कि वह 6 अप्रैल की हड़ताल करे या मार कामकाज ठप कर दे। हड़ताल की इस अपील पर जनता ने जो उत्साह दिखाया उससे स्वयं के लाग आश्चर्य में पड़ गए जिन्होंने अपील की थी। माच और अप्रैल के महीनों में देश भर में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए हड़तालें हुईं, जनता के असतोप की अभिव्यक्ति हुई और वही कही पर जनता और पुनिम के बीच संधप हुआ तथा सरकार द्वारा किए गए हिंसात्मक दमन का जनता ने बहादुरी के साथ सामना किया। सरकारी दमन के फलस्वरूप अनेक लोग घायल भी हुए लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। इस वर्ष की सरकारी रिपोर्ट में इन बातों पर काफी आश्चर्य प्रकट किया गया है कि लोगों के बीच अचानक ऐसी एवता किस तरह बन गई और हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विरोध की सारी बातें कहा चली गई। रिपोर्ट में कहा गया था

इस आम उत्तेजना और उत्साह में एक खास बात यह दखी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे का अभूतपूर्व रिश्ता कायम हो गया। नेताओं ने बहुत दिना से हिंदू मुस्लिम एकरता को राष्ट्रवादी कार्यक्रम का एक निश्चित अंग बना रखा था। सावजनिक उत्साह के इस अवसर पर निचनी जातियाँ भी मतभेदों को भुला देने की शक्ति पैदा हो गई। भाईचारे के असाधारण दृश्य



गया। ता मित। हिंदुआ। मुगलमाना के हाथ से गुनआम जल ग्रहण किया और मुगलमाना न भी ऐसा किया। जुलूस में तारा जोर बडो में हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर गूज उठा। यह गताई है कि हिंदू नेताआ ता मस्जिद के गुंबदा से घने होकर भाषण दन का अवसर दिया गया। ('इंडिया इन 1919')

इसके बाद सन्तार न दमन के असाधारण तरीके इस्तमाल किए। अमृतसर में जलिया वाला बाग की घटना इसी समय हुई जहां जनरल डायर ने चारों तरफ दीवारों से घिरी एक्कित जनता पर 1600 गोलीया बरसाईं। जाता बिनकुल निहत्थी थी और उसका बाहर निकलन का कोई रास्ता नहीं था। इस हत्याकांड में (सरकारी आंकड़ा के अनुसार) 379 लोग मार गए और 1260 लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए भी नहीं ले जाया गया। बाद में दिए गए बयान के अनुसार इस निहत्थी जनता पर गोली चलाने का उद्देश्य 'वहां पर मौजूद लोग पर ही नहीं बल्कि खास तौर से पूर पंजाब के लोग पर सैनिक दृष्टि से नैतिक प्रभाव डालना था।' कहने का अर्थ यह है कि इस गोलीकांड का उद्देश्य समूची जनता को आतंकित करना था। भारत में उस समय दमन का कितना जबरदस्त सिलसिला चल रहा था इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कमेटी के नेताओं को भी इस हत्याकांड की जानकारी घटना के चार महीने के बाद हुई और लगभग आठ महीने तक इस हत्याकांड के किसी भी समाचार को सरकार ने न तो अखबारों में छपने दिया और न उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा ब्रिटिश जनता के सामने आने दिया। आंदोलन और कांग्रेस द्वारा घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन कर देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी कूटनीतिक कारणों से मजबूर होकर घटना की निंदा की और इसकी जांच की। लेकिन जनरल डायर का साम्राज्यवादियों से काफी प्रशंसा मिली (और उसे 20 हजार पौंड की रैंली भी भेंट की गई) तथा हाउस आफ लाड्स ने सरकारी तौर पर उसके काम की प्रशंसा की। पंजाब में मासल ला सगा दिया गया। आतंक के इस शासन के दौरान वहां कितने बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुए कितने लोगों का फासिया दी गई, हवाई जहाजों से कितनी जगह बम गिराए गए और अदालतों द्वारा कितनी भयानक सजाए दी गई इसका पूरा पूरा हिसाब अभी तक नहीं लगाया जा सका है। बाद के वर्षों में जो जांच पड़ताल हुई उससे भी केवल अधूरी जानकारी मिल सकी।

ब्रिटिश सरकार के मत के अनुसार इस अवधि में 'आंदोलन ने निस्संदेह ब्रिटिश राज के खिलाफ संगठित विद्रोह का रूप ले लिया था' (सर बेलेटाइन चिरोट 'इंडिया', 1926, पृष्ठ 207)। गांधी ने इस परिस्थिति से चिंता महसूस की। कलकत्ता बंबई, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर जनता ने अंगरेज शासकों के खिलाफ छुटपुट रूप से हिंसा का प्रयोग किया जिस पर गांधी जी ने घोषणा की कि मैं एक महान भूल की थी जिससे कुछ ऐसे तांगा को अव्यवस्था फैलाने का अवसर मिल गया जो सही अर्थों में सत्याग्रही नहीं थे और जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं था।' फलस्वरूप गांधी ने एक हफ्ता हड़ताल चलने के बाद ही

अप्रैल के मध्य में सत्याग्रह आदोलन रोक दिया और इस प्रकार आदोलन को ठीक ऐसे वकत पर, बंद कर दिया गया, जब वह अपने शिखर पर पहुंचन ही वाला था। बाद में जहां 21 जुलाई को अखबारों के नाम एक पत्र लिखकर यह बताया कि आदोलन वापस लेन का कारण यह था कि 'एक सत्याग्रही कभी सरकार को परेशान करना नहीं चाहता।' 'सत्याग्रह' का यह अनुभव आगे चलकर और भी व्यापक स्तर पर दोहराया जाना वाला था।

हम देख चुके हैं, दिसंबर 1919 में कांग्रेस मुधारा से काम लेने का फैसला कर रही थी और गांधी इस बात के प्रचार में लगे थे कि राष्ट्रीय आदोलन का कतव्य है कि वह चुपचाप काम करे ताकि मुधार सफल हो। लेकिन इस तरह के सपने सच होने की स्थितिया अब नहीं बच रही थी। 1919 में जनता में असंतोष की जो क्रांतिकारी लहर उठी थी वह 1920 और 1921 में भी बराबर आगे बढ़ती रही और 1920 के उत्तरार्ध में शुरू हुए आर्थिक संकट से तेजी में और बढ़ी हुई। 1920 के शुरू के छ महीने में हड़ताल का काफी जोर रहा। कम से कम 200 हड़तालें हुईं जिनमें 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया। 'मुधारा से चुपचाप काम लेने' की पड़िताऊ सलाह का इन क्रांतिकारी आदोलनों ने मखोल बना दिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष ने घोषणा की

इस तथ्य से आख मूद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर में गुजर रहे हैं हम अपने मूल स्वभाव और अपनी परंपरा से क्रांति के खिलाफ हैं। पारंपरिक रूप से हम आहिस्ता चलन वाले लोग हैं लेकिन जब हम आगे चलने की साज लेते हैं तो फिर बहुत तेजी से चलते हैं और लंबे वकत में रास्ता तय करते हैं। कोई भी जीवित पदार्थ अपने जीवनकाल में क्रांतियों से अपन को एकदम अलग नहीं रख सकता। (सितंबर 1920 में कतव्यता में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष पद से लाजपतराय का भाषण)

जहां तक बुनियादी मुद्दों की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष का विशयण सही था। कांग्रेस के प्रवक्ता की घोषणा का आशय यथायत यह था कि क्रांति के इस युग में अनृतत्व के सामने यह समस्या पैदा हो गई है कि वह उभरत आदोलन का नेतृत्व किस तरह करेगा कि वह स्वभाव और परंपरा से क्रांति के खिलाफ है। 'अनक देश में यह दृषन में आया कि युद्ध के बाद जो परिस्थितिया पैदा हुई थी और युद्ध ने जो अवसर दिए थे उनका नाम इसलिए नहीं उठाया जा सका क्योंकि उन दशा में राजनीतिक जानालन इतने परिपक्व नहीं थे जितने होने चाहिए थे। युद्ध के बाद की भारतीय परिस्थिति का अंतविरोध भी यही है।

यही वह परिस्थिति थी जब 1920 में गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के प्रमुख लोग ने (दूसरे समय तक गरम रोजी नेता कांग्रेस छोड़ चुके थे) अपना मोर्चा निष्पायक रूप से बदल दिया।

उन्होंने सुधारास सहयोग करन की बात ताब पर रख दी, उभरत जाआलना का नतत्व सभालने का सकल्प किया और इस उद्देश्य के लिए 'अहिंसात्मक असहयोग' की योजना तैयार की। इसके बाद से जनसघर्षों का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में आ गया लेकिन इस नेतृत्व के लिए यह कीमत चुकानी पड़ी कि सघर्ष सदा 'अहिंसात्मक' रहेगा।

सितंबर 1920 में कांग्रेस ने बलकत्ता के अपने विशेष अधिवेशन में अहिंसात्मक असहयोग की नई योजना को स्वीकार किया। इसका विरोध हुए बिना नहीं रहा पर इसकी अमल में लाने के लिए गांधी और मोतीलाल नेहरू तथा जुझारू मुस्लिम नेता अली वधुआ व बीच एक गठबंधन हुआ और कार्यावित्त किया गया। अली वधु उस समय के काफी मजबूत आंदोलन खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे (यह आंदोलन वैसे तो तुर्की व साथ सेब्रेज की संधि के द्वारा किए गए अत्याय का विरोध करने के लिए था लेकिन व्यवहार में इसने मुस्लिम जनता के अमतोष को एक सूत्र में बांधने का काम किया)। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि 'महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए प्रगतिशील अहिंसात्मक आंदोलन को तब तक चलाया जाएगा जब तक उपयुक्त घामिया का निराकरण नहीं कर लिया जाता और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती।' इस नीति का बड़ी चरणों से गुजरना था और इसकी शुरुआत सरकार द्वारा दी गई उपाधिया को त्यागन तथा तीन तरह के बहिष्कार (विधान सभाओं कानूनी अदालतों तथा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार) से हाने वाली थी। इसके साथ ही 'घर घर में चरखा और करघा फिर से चालू करने' की बात थी। आंदोलन के अंतिम चरण में भविष्य में किसी समय से कर न देने का अभियान शुरू करने की योजना थी। आगे चलकर यह दया गया कि तुरंत जो कदम उठाए गए वे मध्यवर्गीय लोगों, बकीलो और छात्रों द्वारा उठाए गए कदम थे जबकि आम जनता के जिम्मे केवल 'चरखा कातने और करघा चलाने' का काम सौंपा गया। कर न देने का अभियान (जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से लगान न देने का अभियान था) जिसमें जनता की सक्रिय भूमिका हो सकती थी बाद के लिए टाल दिया गया।

नवंबर में नई विधानसभाओं के चुनाव का बहिष्कार किया गया और इसमें काफी सफलता मिली। इस चुनाव में दाहिनाई मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार को भी काफी सफलता मिली, भारी सत्या में छात्रों ने जोश के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। बकीलो द्वारा किया गया बहिष्कार कम सफल रहा। मोतीलाल नेहरू और सी० आर० दास जैसे कुछ प्रमुख बकीलो ने अंगलता के बहिष्कार में भाग लिया।

नवंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का नया कार्यक्रम अंतिम तौर पर पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पर लगभग सवमममति थी। इस बार कांग्रेस के मित्रान में तन्नी नी आई। अब उमने साम्राज्य व अधीन रहन हण औपनिवेशिक स्वायत्त सरकार की स्थापना व अपन नक्ष्य का छाप्कर तथा नक्ष्य अपनाया जा शक्ति

पूर्ण और वैधानिक उपायो ने स्वराज प्राप्त करना' था। कांग्रेस के संगठन का भी स्वरूप बदला। पहले कांग्रेस का संगठन बड़ा ढीलाढाला था पर अब उसने अपने संगठन को काफी आधुनिक बना लिया, कांग्रेस की इकाइयां हर गांव और मुहल्ले में कायम की गईं और 15 सदस्यों की एक स्थाई कार्यकारिणी ('काय समिति') बनाई गई।

गांधी द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम और नीति से राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब कांग्रेस एक ऐसी राजनीति पार्टी बन गई थी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनसंघर्ष का नतृत्व करने को उठ खड़ी हुई थी। यहां से प्रगति करते करते कांग्रेस इस स्थिति (जिस देखकर प्रारंभिक दिनों के उग्र राष्ट्रवादी भी हैरान हो गए) तक पहुंच गई कि वह राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य केंद्रबिंदु बन गई।

लेकिन इस नए कार्यक्रम और इस नई नीति में एक और तत्व भी था जो जनसंघर्ष से अपरिचित था। यह तत्व था निम्न पूंजीवादी नैतिकतापूर्ण निगाधार चिंतन तथा सुधारवादी शांतिवाद का जिसकी अभिव्यक्ति बड़े मासूम लगने वाले शब्द 'अहिंसा' में हुई। गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल समूची धार्मिक एवं दार्शनिक अवधारणा को व्यक्त करने के लिए किया। उन्होंने इस विचारधारा का प्रचार-प्रसार बड़े कावपटुता और निष्ठा के साथ किया। गांधी की विचारधारा कुछ मामलों में भारत की पुरानी निराधार चिंतनधारा जैसा थी पर उसका घनिष्ठ संबंध तात्सनाय, थोरो और इममन जैसे पश्चिम के आधुनिक विचारकों के चिंतन के साथ था। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जब गांधी विदेश में थे तब इन दार्शनिकों के विचारों का काफी प्रभाव था और गांधी की विचारधारा के निर्माण में इन विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधी के उन अनेक सहयोगियों ने भी अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया जो गांधी की दार्शनिक अवधारणाओं से सहमत नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि दुश्मन के रूप में एक शक्तिशाली मशहूर शासक वर्ग से निहत्थी जनता की लड़ाई शुरू कराने के लिए अहिंसा के इस हथियार का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन बाद की घटनाओं के अनुभवों और अहिंसा शब्द की नित नई व्याख्याओं से यह स्पष्ट हो गया कि वस्तुतः ऊपर से यह शब्द बहुत निर्दोष, मानवीय और उपयोगी लगता है पर इसके पीछे न केवल अंतिम संघर्ष का नकारने की बात छिपी है बल्कि तात्कालिक संघर्ष का रोकने की भी बात छिपी है क्योंकि हमेशा आम जनता के हितों को बड़े बुजुर्गों और जमींदारवर्ग के हितों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। भारत का बड़ा पूंजीपतिवर्ग और जमींदारवर्ग निश्चय ही किसी भी निर्णायक जनसंघर्ष के खिलाफ था। यही वह अंतर्विरोध था जिसके कारण अपनी महान उपलब्धियों के बावजूद पहली बार और दस साल बाद दूसरी बार भी जब पहले से बड़े दमने पर संघर्ष छेड़ा गया, आंदोलन को मफलता नहीं मिली। इसी अंतर्विरोध के कारण स्वराज की प्राप्ति भी नहीं हो सकी जबकि नताशा ने जनता से वायदा किया था कि नई नीति अपनाने पर स्वराज की प्राप्ति शीघ्रतापूर्वक हो सकती है।

स्वराज प्राप्त का काम तब करने के लिए कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध मध्य चलान का जो नया जुझारु कार्यक्रम अपनाया, उससे जनजादोनों ने और जोर पकड़ा। गांधी ने बहुत दृढ़ और निश्चित शब्दों में एक भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने यह अविवक्षणीय वायदा किया कि स्वराज की प्राप्ति 12 महीना के अंदर हो जाएगी (यह वायदा, हालांकि, बड़ा मचकाना था फिर भी उन दिनों कुछ ऐसा उत्साहपूर्ण वातावरण था कि गांधी के अनुयायियों को इस वायदे के पूरा होने का पक्का यकीन था)। 12 महीनों की सीमा का अर्थ यह था कि 31 दिसंबर 1921 तक स्वराज मिल जाएगा। गांधी ने तो मिनबर 1921 में एक सम्मेलन में कहा तब यह डाला कि, यह वष छतम होने से पहले तक स्वराज प्राप्त करने के बारे में मैं इस हद तक निश्चित हूँ कि यदि स्वराज नहीं मिला तो 31 दिसंबर के बाद मैं जीवित रहने की कल्पना ही नहीं कर सकता।' (सुभाषचंद्र बोस दि इंडियन स्टूडेंट, पृष्ठ 84) लेकिन इस तिथि के बाद भी गांधी अनेक वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहें हानाकि उन्हें स्वराज रखन का सीमाय तक नहीं मिला।

गांधी ने अपनी विजय की तिथि तो स्पष्ट कर दी थी पर उनके अभियान का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था। हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिखा है

जनता का आग्रह जिस चीज में था वह था सामूहिक रूप से किया जाना वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह क्या आंदोलन था, इसका क्या रूप होगा? स्वयं गांधी ने न तो कभी इसे परिभाषित किया, न इसकी व्याख्या की और न वह खुद भी इसका कोई स्वरूप स्पष्ट कर सके। कोई कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति ही एक एक कदम चलने के बाद समझ सकता था कि इस आन्दोलन की निशा क्या है। यह ठीक वैसा ही था जैसे कोई राहगीर किसी घन जंगल में रास्ते की तलाश में तब तक भटकता रहे जब तक नहीं स कोई प्रकाश की किरण उसे न दिखाई दे। (हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 पृष्ठ 376)

सुभाष बोस ने अपनी पुस्तक 'दि इंडियन स्टूडेंट 1920-1934' में बताया है कि किम प्रनार 1921 के उन महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने एक मौखिक शिष्य के रूप में महात्मा गांधी ने पहली बार मुताबक की थी और घोर निराशा का अनुभव किया था। उन्होंने सारी बातों की स्पष्ट जानकारी चाही थी। उन्होंने जानना चाहा था कि उनकी (गांधी की) योजना कि किन कारणों से गुप्तगी और उस किस प्रकार कदम ब कदम बढ़ाया जाएगा जिससे अतृप्तता विदेशी नौकरशाही में सत्ता पर बढ़ा किया जा सकेगा।' लेकिन सुभाष बोस को गांधी कोई जवाब न द सके

कायनीति अपनाई जाए। (सुभाष बोस दि इंडियन स्ट्रगल 1920 1934', पृष्ठ 63)

जवाहरलाल नेहरू न गांधी की 'दिलचस्प अस्पष्टता' के बारे में निया है

यह बात जाहिर थी कि हमारा अधिकांश नेताओं की निगाह में स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता का कोई काफी छोटी चीज थी। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी खुद भी इस प्रश्न पर साफ नहीं थे और वह दूसरों को कोई स्पष्ट समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। (जवाहरलाल नेहरू 'आत्मकथा', पृष्ठ 76)

फिर भी, नेहरू के अनुसार

हम सब यह महसूस करते थे कि वह एक महान और अदभुत व्यक्ति है और एक तेजस्वी नेता है। हम उन पर पूरी तरह विश्वास करते थे और कम से कम उस समय सब कुछ करने का अधिकार हमें उह दे दिया था। (वही, पृष्ठ 73)

1921 में आंदोलन की प्रगति का पता केवल इसी तथ्य से नहीं चलता कि लोग जोश के साथ अमहयोग आंदोलन का साथ दे रहे थे वरिष्ठ दश के सभी भाग में दिनोदिन बढ़ रहे जनसंघ से भी आंदोलन का विकास की जानकारी मिलती है। असम बंगाल में रेल कमचारियों ने हड़ताल की, मेदिनीपुर में लोगो ने वन न बन का अभियान चलाया दक्षिण में मद्रास में मोपला विद्रोह हुआ और पंजाब में जुबारू अकालिया ने उन महतों के खिलाफ आंदोलन चलाया जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त था।

1921 के अंतिम दिना में संघ और भी तेज हो गया। इन सारी स्थितियों का देखकर सरकार काफी चिंतित हो गई और इस बार उसने काफी सोच समझ कर गांधी के विरुद्ध अपने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल किया। कनाडा के ड्यूक का वप ने शुरू में भाग्य यात्रा के लिए भेजा गया था, इस बार स्वयं प्रिंस आफ वेल्स को भारत यात्रा के लिए भेजा। सरकार का यह झूठी आशा तो नहीं थी कि इस तरह भारत की जनता खुश हो जाएगी लेकिन रहस्यमय रूप का हर अंग्रेज विशेषज्ञ यह मंजूर था कि भारत के लोग किस चीज का सबसे ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सरकार प्रिंस आफ वेल्स को भारत की यात्रा कराकर यह जांच करना चाहती थी कि जनता की भावनाएं इस समय क्या हैं। सरकार ने जो आशा की थी उससे यही अधिक ही उस इस यात्रा का परिणाम देखने को मिला, लेकिन विपरीत दिशा में। 17 नवंबर को जब प्रिंस आफ वेल्स भारत पधारे तो उनका स्वागत एक दशव्यापी हड़ताल से हुआ। जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और गहन प्रदर्शन भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। जनता के विरोध और सरकार के जबरदस्त दमन के बीच जम्बरू टय्बर हई जिम गांधी ने राकन की कोशिश की पर उन्हें

कामयात्री नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि गांधी ने यह एनान किया कि स्वराज शब्द से उन्हें बंदू आने लगी है।

इसी समय से राष्ट्रीय सेवा दल (नेशनल वालंटियर) का आंदोलन तज होन लगा। दल के स्वयंसेवक अब भी 'अहिंसात्मक सहयोग' के सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस या खिलाफत आंदोलन के ढांचे के अधीन संगठित थे। लेकिन अनेक स्वयंसेवक बढ़िया पहनत थे, कवायद करते थे और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए पिक्केटिंग करने तथा शांति पूर्ण ढंग से लोगों को समझाने के लिए एव हड़ताल कराने के लिए जुलूस बनाकर जाने थे।

सरकार ने राष्ट्रीय सेवा दल का दमन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 'स्टेट्समैन' और 'इंगलिशमैन' जैसे सरकारी अखबारों ने जोरशोर से यह प्रचार किया कि सेवा दल के स्वयंसेवकों ने बलवृत्ता पर बर्बाद कर लिया है और सरकार भग हा गई है। इन अखबारों ने तत्काल कायवाही करने की मांग की। सरकार ने सेवा दल को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। हजारों छात्रों और कारखाना मजदूरों ने स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी की वजह से रिक्त हुए स्थान को भर दिया। दिसंबर की समाप्ति तक गांधी को छोड़कर कांग्रेस के शेष सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बीस हजार राजनीतिक कदियों से जेलों को भर दिया गया। अगले वर्ष जब आंदोलन अपनी चरम स्थिति पर पहुंचा तो राजनीतिक कदियों की संख्या तीस हजार हो गई। लोगों में जोश का तूफान उमड़ पड़ा।

सरकार काफी चिंतित और परेशान हो गई और उसके हाथ पांव फूटने लगे। उसने सोचा कि यदि सावजनिक खिलाफत की यह बीमारी शहरों से हाकर गांवों की करांडों आवादी के बीच पहुंच गई तो ब्रिटिश शासन का बाई नहीं बचा सकता। उसके सार हवाई जहाज और वारुद गोलों भी 10 करोड़ लोगों की क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सकेंगे। इस आशंका से भयभीत होकर वायसराय ने जेल में राजनीतिक कदियों से सुलह समझौता करना शुरू किया। इसने लिए उसने पंडित मदनमोहन मालवीय की मध्यस्थता का सहारा लिया। वायसराय ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लें तो राष्ट्रीय सेवा दल को कानूनी संगठन के रूप में मान्यता दे दी जाएगी और राजनीतिक कदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बाई समझौता नहीं हो सका।

इन्हीं परिस्थितियों में, वर्ष के अंत में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस समय तक गांधी ही लगभग एकमात्र नेता बच रहे थे। बंगाल के बहादुर नेता सी० आर० दास, जिन्हें अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी जेल में थे इसलिए गांधी एक अजरज पारसी का अपन गाय ले आए जिन्हें अधिवेशन की कायवाही शुरू करने से पहले वापस

के नाम एक धार्मिक मदेश देना था। लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और विदेशी कपड़े की होली जलाए जाने के विरुद्ध एक प्रवचन दे डाला।

अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन ने एक जाशपूर्ण वातावरण में अनेक प्रस्ताव पारित किए जिनमें यह घोषणा की गई थी कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती और जनता के हाथों में शांति की वागडोर नहीं पहुंच जाती तब तक कांग्रेस अहिंसक असहयोग आंदोलन और भी शक्ति के साथ जारी रखने के लिए कृतमकल्प है।' अठारह वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों से अपील की गई कि वे राष्ट्रीय सेवा दल में भरती हों और इस लक्ष्य को पूरा करने का सकल्प किया गया कि सारा ध्यान सविनय अवज्ञा आंदोलन पर दिया जाएगा, भले ही यह आंदोलन सावजनिक हो या व्यक्तिगत, इसका स्वरूप सुरक्षात्मक हो या आक्रामक।' इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'महात्मा गांधी को कांग्रेस का एकमात्र अधिकारी' बनाकर सार अधिकार उनके हाथ में दिए गए। गांधी अब कांग्रेस के डिक्टटर या एकछत्र नरता हो गए। आंदोलन अपने शिखर पर था। विजय प्राप्ति के लिए उनके हाथों में समस्त अधिकार दे दिए गए। बड़े पैमाने पर सत्याग्रह छेड़ने के लिए अंतिम शक्ति परीक्षा की घड़ी आ गई थी। सार देश की निगाहें गांधी की ओर लगी थीं। लोग देख रहे थे कि वह अब क्या करते हैं ?

राष्ट्रीय उत्साह और आशा के इन जोशीले वातावरण में कांग्रेस का केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो तत्कालीन घटनाक्रम को देखकर चिंतित और अप्रसन्न था। वह व्यक्ति थे गांधी। उनका यह आंदोलन, जिस रास्ते की उन्होंने कल्पना की थी उस रास्ते पर नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो। यह तो वह रमणीय और दार्शनिक 'अहिंसात्मक' आंदोलन नहीं था जिसकी उनका दिमाग में तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी दैत्य के बंधन खाल दिए हों। आंदोलन में गतत किस्म के लोग घुसत जा रहे थे। उतावले किस्म के लोगों ने, जिनमें खास तौर पर गांधी के मुसलमान साथी थे, महात्मा का माग करनी शुरू कर दी थी कि 'अहिंसा' का रास्ता छोड़ दिया जाए। 1921 के अंतिम तिमाही में, जब हजारों लाखों देशभक्त सिपाही गांधी की जयजयकार करने हुए जेल जा रहे थे तब गांधी अपनी घबराहट और नफरत व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें स्वराज शब्द से बदबू आने लगी है।

अहमदाबाद में कांग्रेस ने पीछे हटना शुरू किया। लेकिन यह किया अभी खूनकर सामने नहीं आई क्योंकि देश में आसन्न लड़ाइयों की आशंका से तनाव था और हजारों लोग इस लड़ाई में शिरकत करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बात के छोटे मोटे संकेत बड़ा मौजूद थे कि कांग्रेस पीछे हटने लगी है। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर था जब देश भर में व्यापक और आम सत्याग्रह के सूत्रपात की घोषणा की जा सकती थी, जनता भी इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। यही वह क्षण था जब विजय के लिए अंतिम मध्य की रणमरी यजार्ई जा सकती थी। अहमदाबाद



कांग्रेस के नाम भारत की नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपन सदस्य में कहा

यदि कांग्रेस उस क्रांति का नतृत्व करना चाहती है जो भारत का उसकी नींव से हिला रही है तो उसे केवल प्रदर्शना और अस्थाई जोश पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे मजदूर सभा की तात्कालिक मांगों को अपनी मांगें बना लेना चाहिए, उसे किसान सभा के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम घोषित करना चाहिए और तब वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस सारी बाधाएँ दूर कर ले। तब अपने भौतिक हिता के लिए सचेतन ढंग से लड़ रही समस्त जनता की विपुल शक्ति कांग्रेस के पीछे होगी। (राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र, 1921)

संघर्ष शुरू करने का आवाहन अहमदाबाद अधिवेशन में नहीं किया गया। इतना ही नहीं सजग प्रेक्षकों ने गौर किया कि अहमदाबाद के प्रस्ताव में 'कर न देन' का कहीं भी जिक्र नहीं होना दिया गया है। आम सत्याग्रह का जहाँ जहाँ जिक्र आता था वहाँ वहाँ उसे 'वैशुमार अगर मगर की शर्तों से गोलमोल कर दिया गया था' वही उचित सुरक्षा उपायों के तहत तो वही आंदोलन के लिए जारी आवश्यक निर्देशों के अंतर्गत और वही 'जनता द्वारा अहिंसा का तरीका पर्याप्त रूप से सीख लिए जाने के बाद ही' आंदोलन छेड़ने की बात थी। इसके बाद रिपब्लिकन मुस्लिम नेता मौलाना हजरत मोहानी वाली घटना हुई। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया था कि स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है जिसमें संपूर्ण विदेशी नियंत्रण से मुक्ति मिल जाएगी। गांधी ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया (इस प्रस्ताव से मुझे तबलीफ हुई है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी की भावना का अभाव है।) और प्रस्ताव का नामजूर कर लिया।

भारत सरकार आखिरी फाड़कर अहमदाबाद की मांगवाहिया देख रही थी। उसने उन छाटे छाटे सचेतकों को पहचाना जो अहमदाबाद में अभिव्यक्त हुए थे और राहत की सांस ली। वायसराय ने तदनन्वित भारतीय मामलों के मंत्री वॉल्टर राय को तार भेजा

बड़े दिन की छुट्टियाँ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। गांधी पर बर्बरों के दंगा न गहरा असर डाला था। उन बातों का पता उनका उनका समय दिया गए भाषणों से चलता है। इन दंगा में उन्हें यह आश्चर्य पैदा हुई कि आम मत्वाण्ट गुरु पररा पर काफी उग्र स्थिति पैदा हो सकती है। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों का अध्ययन में भी इसी तथ्य का पता चलता है क्योंकि इन प्रस्तावों में न सिर्फ प्रिलाफ्ट पार्टी के सर्वोच्च उद्देश्यों का पता चलता है बल्कि यह सुझाव नहीं माना गया है कि कांग्रेस का नया नीति यह है कि वह मुसलमानों को भी शामिल करेगी। (वॉल्टर राय का पत्र, 1921)

गृह किया जाए कहीं पर भी कर न देने के अभियान का जिक्र नहीं है।  
(टेलीग्राफिक करेस्पॉण्डेंट रिगाडिंग दि सिच्यूएशन इन इंडिया, 1922)

गांधी के सामन अब कौन सा रास्ता है ? अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन कोई योजना निर्धारित किए बिना समाप्त हो गया। सारी योजनाएँ गांधी के ऊपर छोड़ दी गईं। जब परिसर चारों तरफ से घेर लिया गया था उस समय परिणाम निवासी यह कहकर अपने को आश्वस्त करते थे कि 'जनरल त्रौबू ने अवश्य ही कोई योजना तैयार की होगी।' भारतीय जनता की स्थिति भी इसी तरह की थी। एक तरफ तो वह साम्राज्यवादियों के जबरदस्त दमन का शिकार हो रही थी और दूसरी तरफ गांधी की ओर आशाभरी निगाह से देख रही थी कि वह जल्दी ही अपनी कोई योजना शुरू करेंगे।

लेकिन गांधी ने एक अजीब रवैया अपनाया। एक महीने तक वह चुपचाप इंतजार करते रहें। इस बीच विभिन्न जिलों के लोग ने गांधी को लिखा कि वे कर न देने का आंदोलन जल्दी शुरू करें लेकिन गांधी ने इन लोगों का किसी भी अनुरोध नहीं माना। गुटूर जिले के लोगों ने गांधी को अनुमति के बिना ही यह आंदोलन शुरू कर दिया। इसपर गांधी ने फौरन ही जिले के कांग्रेस अधिकारियों को लिखा कि निर्धारित तिथि तक सारे कर जमा कर दिए जाए। इसके बाद उन्होंने एक छोटे से जिले बारदोली में कर न देने का अपना अभियान शुरू करने का निश्चय किया। इस जिले की आबादी 87,000 अर्थात् भारत की कुल आबादी का चार हजारवा हिस्सा थी। यहाँ गांधी ने बड़ी सतकता के साथ 'अहिंसात्मक' स्थिति तैयार की थी। जिस समय पूरा देश गांधी के नेतृत्व की आशा लगाए बैठा था, उस समय उन्होंने बारदोली जैसे छोटे इलाके में अपने आपको सीमित कर लिया था। 1 फरवरी को उन्होंने वायसराय के पास अपना अल्टीमेटम भेजा जिसमें यह कहा गया था कि यदि राजनीतिक बदियों को रिहा नहीं किया जाता और दमनात्मक तरीके छोड़े नहीं जाते तो 'व्यापक स्तर पर सत्याग्रह' शुरू कर दिया जाएगा जो खास तौर से बारदोली से शुरू होगा। गांधी के इस अल्टीमेटम के कुछ ही दिनों बाद यह खबर आई कि सयुक्त प्रांत (उत्तरप्रदेश) में गुस्से से भरे किसानों ने वहाँ के थाने पर हमला करके उसे जला दिया है और समूचा थाना आग में जलकर स्वाहा हो गया है। किसानों में असंतोष बढ़ने की यह घटना भारत की आजादी के लिए निश्चय ही एक निर्णायक स्थिति का संकेत देती है लेकिन इस घटना से गांधी ने यह सोचा कि अब ज्यादा देर तक रुकने का समय नहीं है। उन्होंने जल्दी जल्दी 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई और इस बैठक में यह फैसला किया गया कि 'चोरीचोरा में जनता की अमानवीय हरकत' को देखते हुए न सिर्फ आम सविनय अवज्ञा आंदोलन को बल्कि उसके प्रचार सहित समूचे आंदोलन को ही बढ़ाकर दिया जाए। यह भी फैसला किया गया कि स्वयंसेवकों के जुनूस निकालने, सरकारी प्रतिबंध को तोड़कर सभाएँ करने आदि गतिविधियों को रोक दिया जाए और इसके बदले चरखा शराबबंदी और

शिक्षा से संबंधित 'रचनात्मक' ऋण किया जाए। इसका जवाब यह हुआ कि लड़ाई राक दी गई। पूरा आंदोलन समाप्त हो गया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

बारदोली के फैसले से कांग्रेस के सभी लोग हतप्रभ रह गए, यह कहने मात्र से उनकी सही सही भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर जे पाठकों का मनमाने के लिए यह कहा जा सकता है कि 1922 में भारत में बारदोली के फैसले का यही असर हुआ था जो 1926 में इंग्लैंड में आम हड़ताल कायम लेने का हुआ था।

जिस समय जनता में उत्साह और जोश उबला पड़ रहा था ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए महान दुःखटना थी। महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने, ये सब जेल में थे, आम जनता की ही तरह इस फैसले पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैं यह देख पा रहा था कि वह क्रोध और दुःख से व्याकुल हो रहे थे। (सुभाषचंद्र बोस 'नि इंडियन स्ट्रगल', पृष्ठ 90)

मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय तथा अन्य नेताओं ने गांधी के फैसले के विरोध में जेल से लंबे और बड़े रोपपूर्ण पत्र भेजे लेकिन गांधी ने बड़े निश्चल भाव से यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जेल में पड़े लोग 'नागरिकता की दृष्टि से मृत हो चुके हैं' और नीति के मामले में उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है।

समूचा आंदोलन जिसका संगठन ही इस आधार पर हुआ था कि जनता की किसी तरह की स्वतः स्फूर्त गतिविधियों को पूरी तरह हतोत्साहित किया जाए और एक व्यक्ति के आदेशों का यत्नवत पालन किया जाए बारदोली के फैसले से अनिवार्य रूप से एक तरह की लाचारी उलझन और पस्तहिम्मती का शिकार हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने बारदोली के फैसले का समर्थन करने हुए यह तर्क पेश किया था कि यदि आंदोलन को रोकना न जाता तो यह हाथ से निकल जाता और निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध हिंसा और रक्तपात का रास्ता अप्रतिहार कर लेता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि जिस ढंग से यह फैसला किया गया उसमें

कुछ पस्तहिम्मती आई। यह भी सत्य है कि इतने बड़े आंदोलन को अचानक रोक देने में देश में एक के बाद एक दुःखद घटनाओं का क्रम शुरू हुआ। राजनीतिक संघर्ष में छिटपुट और निरर्थक हिंसा की प्रवृत्ति तो रुक गई किन्तु इस दबी हुई हिंसा को कोई रास्ता तो ढूँढ़ना ही था और बाद के वर्षों में शायद इसने ही सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया। (जवाहरलाल नेहरू, 'आत्मकथा', पृष्ठ 86)

आंदोलन को इस तरह अगम बना दिया जाना बाद सरकार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ

हमला किया। 10 मार्च का गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हे छ वष बंद की सजा दी गई लेकिन इससे कही छोटा मोटा जनआंदोलन भी नहीं हुआ। सरकार ने दो वष के भीतर ही गांधी को रिहा कर दिया। इस समय तक मकद समाप्त हो चुका था।

बारदोली फैसले को लेकर और इस फैसले के बाद छ वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके गभीर परिणामों के प्रश्न पर काफी बहमें हुई। बारदोली के फैसले के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस फैसले की असली वजह केवल चोरीचोरा कांड न थी जैसा कि आधिकारिक तौर पर बताया जाता है बल्कि इस फैसले का कारण कुछ और ही था जो चोरीचोरा कांड से ज्यादा गभीर था। वस्तुतः वह समय आ गया था जब आंदोलन को रोकना जरूरी हो गया था क्योंकि 'ऊपर में हमारा आंदोलन बहुत मजबूत दिखाई देता था और लगता था कि इस आंदोलन को लेकर लोगों में काफी जोश है लेकिन यह अंदर से टुकड़े टुकड़े हो रहा था' (नेहरू, आत्मकथा, पृष्ठ 85)। प्रश्न किया जा सकता है कि आंदोलन किन अर्थों में 'टुकड़े टुकड़े' हो रहा था। यदि इसका अर्थ यह है कि आंदोलन पर सुधारवादियों और शांतिवादी विचारधारा के लोगों की पकड़ ढीली पड़ रही थी तो यह निस्संदेह रूप से सही है। लेकिन आंदोलन के विकास के फलस्वरूप यह होना ही था और यदि ऐसा न होता तो भविष्य में आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। (नेहरू ने यह मान लिया था कि सारे देश में जनविद्रोह होने पर ब्रिटिश सरकार की जीत होती जबकि सरकार को अपनी जीत का इतना विश्वास नहीं था)। दूसरी ओर यदि आंदोलन के टुकड़े टुकड़े होने का अर्थ यह है कि जनसंघ अपने उच्च स्तर से गुजर चुका था और अब वह कमजोर पड़ने लगा था तो यह बात निश्चय ही गलत है और बारदोली फैसले का समर्थन करने वाले भी इस बात का दावा नहीं करते थे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि स्वयं भारत सरकार ने बारदोली के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के तीन दिन पहले वास्तविक स्थितियों का बिल्कुल दूसरा ही मूल्यांकन किया था। 9 फरवरी 1922 को वायसराय ने एक तार लंदन भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था

शहरों के निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का गहरा असर पड़ा है कुछ क्षेत्रों में खास तौर पर असम घाटी, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा तथा बंगाल में किसानों पर भी प्रभाव पड़ा है। जहां तक पंजाब का सवाल है, अकाली आंदोलन देहात में रहने वाली सिख जनता तक पहुंच गया है। दश भर में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नाराज हो गया है और कुछ रहा है स्थिति काफी खतरनाक है भारत सरकार, अभी तक जैसी अव्यवस्था फैली है उससे भी गभीर अव्यवस्था का सामना करने के लिए तैयार बंधी है। सरकार इस बात को बिल्कुल ही छिपाना नहीं चाहती कि दश की मौजूदा हालत से वह काफी चिंतित है। (9 फरवरी 1922 को भारतीय मामलों के मंत्री के नाम वायसराय

का संदेश 'टेलीग्राफ़िक करसपाइंस रिगाडिंग दि मिन्पूअशन इन इंडिया'  
सी एम डी 1586 1922)

12 फरवरी को जब बारदोली के फैसले से समूचा आंदोलन रोक दिया गया, उससे तीन दिन पहले भारत सरकार ने देश की स्थिति की यह तस्वीर खींची थी।<sup>2</sup>

गुटूर व उदाहरण से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि जनता कितन अनुशासित ढंग से आंदोलन चला रही थी और निर्णायक उड़ाई व लिए किस सीमा तक तैयार थी। गुटूर में गांधी के आदेशों के बावजूद एक गलतफहमी के कारण कर न देने का आंदोलन शुरू कर दिया गया था। जब तक गांधी के पास से आंदोलन रोकने का आदेश नहीं आया तब तक गुटूर में सरकार पांच प्रतिशत भी कर वसूल नहीं पाई थी। कांग्रेस के केंद्र से आदेश मिलने की देर थी और देश भर में यह प्रक्रिया शुरू हो जाती तथा जनता भूमि कर और लगान देने से इकार कर देती। लेकिन इस प्रक्रिया के फलस्वरूप केवल साम्राज्यवाद का ही नहीं बल्कि जमींदारी प्रथा का भी नाश हो जाता।

बारदोली के फैसले के पीछे इही बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। इसका सबूत फैसले के मूल पाठ से ही मिल जाता है। 12 फरवरी को काय समिति द्वारा बारदोली में जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे यहां पूरा का पूरा उद्धृत कर देना उचित होगा। इस फसल का सावधानी के साथ अध्ययन करने से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तियां और अवरोधों को समझने में काफी मदद मिलेगी। बारदोली के प्रस्ताव की प्रमुख धाराएं निम्न हैं

परिच्छेद 1 कायसमिति चोरीचोरा में उपद्रवी भीड़ द्वारा किए गए अमानवीय आचरण की निंदा करती है जिसमें कास्टेबलों की निमग्न ढंग से हत्या की गई और बिना सच्चे समझे पुलिस थाने को जला दिया गया।

परिच्छेद 2 जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है हिंसात्मक उपद्रव होने लगते हैं जिससे पता चलता है कि देश अभी पर्याप्त रूप से अहिंसक नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस कायसमिति फैसला करती है कि व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और वह स्थानीय कांग्रेस समितियों को निर्देश देती है कि वे किसानों को लगान तथा दूसरे कर अदा करने और हर कायवाहिया बढ़ा कर दें।

परिच्छेद 3 सविनय अवज्ञा का जब तक देश का वातावरण दृढ़ता

समय  
कि

गारटी हो जाए कि अन्न गोरखपुर जैसी यन्नरता या बवई और मद्रास म कमश 17 नववर और 13 जनवरी को हुई गुडागदों की घटनाआ की पुनरावृत्ति नही हागी ।

परिच्छेद 5 सरकारी आदेशा का उल्लघन करके जुलूस निवातना और सभाए करना बंद कर देना चाहिए ।

परिच्छेद 6 कायसमिति काग्रेस के कायकर्ताआ और संगठनो को सलाह देती है कि वे रयत (किसाना) को यह सूचित कर दे कि जमीदारी को लगान न देना काग्रेस के प्रस्तावा और दश के हिनो के खिलाफ है ।

परिच्छेद 7 कायसमिति जमीदारी को इस बात का आश्वासन देती है कि काग्रेस के आदोलन का उद्देश्य किसी भी रूप म उनके कानूनी अधिकारो पर चाट पडुचाना नही है और जहा किमानो को किमी तरह की शिकायत है वहा कायसमिति यही चाहेगी कि आपसी सलाह मशविरे से और समझौता वार्ता से मामले का निपटा लिया जाए ।

प्रस्ताव से पता चलता है कि उमे पश करने वालो कं मन मे विशुद्ध रूप से अहिंसा के सिद्धांत की प्रेरणा नहीं काम कर रही थी । यह ध्यान देने की बात है कि प्रस्ताव को कम से कम तीन परिच्छेदो मे (परिच्छेद 2, 6 और 7) खास तौर पर बहुत जोर देकर और एक बहुत ही आवश्यक निर्देश के रूप म किसाना को यह सलाह दी गई है कि उह जमीदारी और सरकार का लगान अदा कर देना चाहिए । यहा हिंसा या अहिंसा का कोई मवान नही पैदा हाता । यहा प्रश्न केवल वगहिता का है, शापको और शोपितो का है । कोई यह नही कह सकता कि लगान न देना 'हिंमक' काय है । इसके विपरीत यह विरोध प्रकट करने का सबसे शातिपूर्ण (और सबसे प्रातिकारी भी) तरीका है । फिर क्यों उस प्रस्ताव मे जो हिंसा की भत्सना करने के लिए तैयार किया गया था, लगान न देने और जमीदारी के 'कानूनी अधिकारो' के सवाल पर इतना जोर दिया गया ? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है । दरअसल 'अहिंसा' की शब्दावली महज एक दिछावा है जिसकी आठ लेकर जान अनजाने वगहिता की रक्षा की जाती है और वग शोपण को बनाए रखा जाता है ।

गांधी के साथ जुड़े काग्रेस के प्रमुख नताआ ने आदोलन को इसलिए रोक् दिया था क्योंकि व जनता म फैल रही व्यापक जागृति से डर गए थे और उनके डर की वजह यह थी क्योंकि उससे उन सपत्तिवान बगों के हितो के लिए घतरा पैदा हा रहा था जिनके साथ काग्रेस के इन बरिष्ठ नताआ का घनिष्ठ मबध था । 1922 मे राष्ट्रीय आदोलन के टूटन का कारण 'हिंसा' या 'अहिंसा' का प्रश्न नहीं था बल्कि जनआदालतनो के विरुद्ध वगहितों

का प्रश्न था। यही वह चट्टान थी जिसपर आदालत टुकड़े टुकड़े हुआ था। अहिंसा का वास्तविक अर्थ भी यही था।

### 3 सघर्ष की तीसरी बड़ी लहर, 1930-34

बारदोली में राष्ट्रीय आंदोलन को जो आघात लगा उसके बाद पांच वर्षों तक आंदोलन एकदम पस्त पड़ा रहा। कांग्रेस में भी काफी पस्ती आ गई। 1924 में गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस एक करोड़ लोगों का सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चली थी किंतु वह दो लाख से ज्यादा सदस्य नहीं बना सकी है। हम राजनीतिक लोग सरकार का विरोध करने के अलावा और किसी मामले में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते।' उस वर्ष गांधी ने 'चरखा कातन की शत' विधान में रखवा दी थी (इसके अंतर्गत कांग्रेस के चुने हुए सगठनों के सदस्यों को प्रति माह दो हजार गज सूत स्वयं कात कर देना था) लेकिन इसके फलस्वरूप 1925 की सर्दियों तक सदस्यों की संख्या दस हजार ही हो सकी थी। 1925 में इस शत का समाप्त कर दिया गया और सूत कातकर देना सदस्या की इच्छा पर छोड़ दिया गया। 1925 में बाबू आनंदलाल ने लिखा कि देश में 'गतिरोध और जड़ता की स्थिति फैली हुई है।' उसी वर्ष लाला लाजपत राय ने 'अराजकता और उत्तसाह' की स्थिति की बात कही। उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक स्थिति में तनिक भी आशा और उत्साह के संकेत नहीं हैं। जनता में भयंकर रूप से निराशा फैली हुई है। सिद्धांतों, व्यवहार, राजनीतिक पार्टियों और समूची राजनीति हर चीज में एक बिछराव और विघटन की स्थिति व्याप्त है।' राष्ट्रीय आंदोलन की इस निराशाजनक स्थिति में सांप्रदायिक अव्यवस्था के लक्षण देश भर में फैल सके। मुस्लिम लीग ने फिर अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के जवाब में अत्यंत सकीण प्रतिक्रियावादी प्रचार करने लगी।

कांग्रेस के नेतृत्व के एक वर्ग ने जिसका प्रतिनिधित्व चित्तरंजन दास और मातीलाल नेहरू कर रहे थे बारदोली फैसले के बाद एक निर्णायक मोड़ लाने की कोशिश की क्योंकि वे गांधी की नीतियों को अव्यावहारिक समझते थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही चुनाव लड़ने और संसदीय स्तर पर नई विधानसभाओं में सघर्ष चलाने के लिए एक नई पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी रखा गया। जन आंदोलन की कमजोरी को देखते हुए चुनावों का और विधानसभाओं का बहिष्कार समाप्त करने का फैसला निःसंदेह एक प्रगतिशील कदम था। उन कांग्रेस के नेतृत्व और दक्षिणानुस नताओं ने इसका विरोध किया जो कांग्रेस के अंदर 'अपरिवर्तनवादी' माने जाते थे। और जो गांधी के चरखा शराववादी, अछूतोंद्वारा तथा सामाजिक सुधारों के इस तरह के अन्य रचनात्मक कार्यक्रम का ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता समझते थे। लेकिन इन लोगों में कांग्रेस के उस वर्ग को राबन की ताकत नहीं थी जो अपराधन अधिक प्रभावकारी नीति अपनाना चाहता था। 1925 तक कांग्रेस ने स्वराज पार्टी के सामने पूरी तरह और बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस में स्वराज पार्टी का बहुमत हो गया और इसका





का स्थान प्राप्त किया। निदल या लिबरल (पुराने नरमदली नेता) सदस्यों के साथ मिलकर यह किसी तरह अपना बहुमत भी बना सकती थी। चित्तरजन दाम न अमेंबली में प्रवेश करने के समय ही यह घोषणा कर दी थी कि 'मेरी पार्टी यहां सहयोग करने के लिए आई है। यदि सरकार उनका सहयोग स्वीकार करेगी तो वह देखेगी कि स्वराज पार्टी के सदस्य उसके अपन आदमी हैं। 1925 तक चित्तरजन दास यह कहने लगे थे कि (फरीदपुर के अपने बहुचर्चित वक्तव्य से) 'उह सरकार में हृदय परिवर्तन' के संकेत दिखे हैं (यह वक्तव्य कितना निरर्थक था इसे भारतीय मामलों के तत्कालीन मंत्री लाड बर्किनहेड के रख दिया जा सकता है जिन्होंने उन्हीं दिनों एक सावजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीयता के काल्पनिक प्रेत की खिल्ली उड़ाई थी)। चित्तरजन दास ने अपने इस वक्तव्य के साथ ही कुछ शर्तों के साथ सरकार से सहयोग करने का विधिवत प्रस्ताव भी रखा था। इनमें एक शर्त यह भी थी कि सरकार और स्वराज पार्टी दोनों मिलकर आतिकारी आंदोलन के खिलाफ सभ्य चलाएंगे। लिबरल पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसके बाद कहा कि उनके और स्वराज पार्टी के बीच अब कोई महत्वपूर्ण मतभेद नहीं रह गया है। 1926 के वसंत में सांख्यिकीय मसौदों के रूप में पदा को ग्रहण करने के बारे में फैसला होना जा रहा था लेकिन साधारण सदस्यों के विरोध के कारण यह नहीं हो सका। 1926 के पतझड़ में नए चुनाव हुए जिनमें मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर स्वराज पार्टी को जबरदस्त धक्का लगा।

लेबिन साम्राज्यवाद के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग के जो सपने पूजीपतिवर्ग ने देखे थे, वे टूटने लगे थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं और जनआंदोलन से कट जाने के कारण स्वराज पार्टी के लोगों के सामने समझौते के लिए मिनतें करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है साम्राज्यवादियों ने भी अपना रुख बदल दिया और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारत के पूजीपतिवर्ग को जो आर्थिक आर्थिक रियायतें दी थी उन्हें वापस लेना शुरू कर दिया। उसने अपना प्रभुत्व बरामद करने के लिए 1927 के मुद्रा कानून (मरेंसी बिल) के जरिए एक बड़ा आर्थिक हमला शुरू किया। इस कानून से रुपये की कीमत एक शिलिंग 6 पैसे निश्चित कर दी गई जिसका देश भर में विरोध हुआ लेकिन इस विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके साथ ही 1927 के अंत में नया इस्पात संरक्षण कानून (स्टील प्रोटेक्शन बिल) बनाकर 1924 के कानून से भारत के इस्पात उद्योग को जो संरक्षण मिला था, वह समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड आने वाले इस्पात पर चुगी कम कर दी गई। भारत के भावी संविधान का भाष्य निर्धारित करने के लिए 1927 के अंत में साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई। इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं शामिल किया गया।

इस प्रकार भारत का पूजीपतिवर्ग न चाहत हुए भी एक बार फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने की आशाएं पूरी नहीं हो सकती और यदि जबरन सफाईपूर्वक सोनियाजी बनाने का कार्यक्रम अपने को बनाना है तो एक बार फिर जनता की

शक्तियों को काम में लाना होगा और उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। लेकिन दस वर्ष पहले के मुकाबले में आज की स्थिति ज्यादा कठिन और पेचीदा हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि इन दस वर्षों में जनता की शक्तियां ने एक नए जीवन की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया था और वे स्वतंत्र रूप से तथा अपने स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्यों के साथ देश के रंगमंच पर उभरने लगी थी। अब उनका संघर्ष सक्रिय रूप से साम्राज्यवादियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि भाग्यीय शोषकों के खिलाफ भी तब होना लगा था। इस प्रकार अब संघर्ष का त्रिकोणात्मक स्वरूप पहला से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। अब साम्राज्यवाद और भारतीय जनता का अधिक गहरा संघर्ष और भारतीय बुजुर्गों की दुलभ भूमिका अधिक स्पष्ट हो गई थी। इसलिए इस बार संघर्ष की नई लहर एक नए रूप में सामने आई। इसके संकेत पहली बार 1927 के उत्तराखण्ड में दिखाई दिए थे और 1930-34 तक पूरी शक्ति के साथ उभर गए थे। यह लहर एक तरफ तो पहले से ज्यादा व्यापक जबरदस्त और टिकाऊ थी दूसरी तरफ इसका विकास स्व-रकबर और लक्ष्य के मामले में काफी दुलभ भूमिका दिखाते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलत हुआ। बीच-बीच में कई बार मुलह समझौते की बातें होती थी और बिना किसी समझौते के अचानक संधि हो जाती थी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक आंदोलन अंतिम रूप में ध्वस्त नहीं हो गया।

बीसवीं सदी के मध्यवर्ती वर्षों में जो नया तत्व सबसे पहले प्रकट हुआ और संघर्ष की इस नई लहर को जिस नए तत्व से प्रेरणा मिली थी वह था मजदूरवर्ग का एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में सामने आना। संघर्ष की नई लहर यद्यपि मजदूरवर्ग के नए तत्व में नहीं उठी थी मगर प्रेरणा उसी से मिली थी। इस बीच औद्योगिक मजदूरवर्ग ने अपने संघर्ष अत्यंत चोरतापूर्वक और शक्तिशाली ढंग में चलाए थे और अपने बीच से वह तत्त्व का भी जन्म देना लगा था। इसके साथ ही मजदूरवर्ग की नई विचारधारा अर्थात् समाजवाद का पहली बार एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में भारत में प्रचार होना लगा था। इस नई विचारधारा का नौजवानों और भारतीय राष्ट्रवाद के वामपंथी वर्गों के बीच काफी असर हुआ था और उससे उन्हें नया जीवन और शक्ति तथा व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था। 1924 के बानपुर पड़ोस के मामले से यह बात साफ हो गई थी कि साम्राज्यवाद भी काफी सतर्क होकर मजदूरवर्ग की शक्तिशाली राजनीति के पहलू से सतर्कता का ही कुछ देना चाहता है। 1926 और 1927 के दौरान मजदूर किसान पार्टियाँ (वर्कर्स पीजेंट्स पार्टियाँ) का गठन हुआ। 1928 के ट्रेड यूनियन आंदोलनों और हड़तालों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1929 में मजदूर हड़तालों का जबरदस्त सिलसिला चला जिसमें 31 647 000 काम के दिनों का नुकसान हुआ। पिछले पांच वर्षों में हुई हड़तालों में कुल मिलाकर भी इतने दिनों का नुकसान नहीं हुआ था। अब के मजदूर मजदूरों की नई संघर्षशील यूनियन गिरनी कामगार यूनियन या लाल गंडा यूनियन (रड फ्रेंड यूनियन) के सदस्यों की मजदूरों की आवाजों के अनुसार गान भर के अंदर 65 000 तक बढ़ गई। गान भर में मजदूर यूनियन के सदस्यों की संख्या में 70 प्रतिशत की बढ़ि हो गई। दोनों संघ सामान्य कमिशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुए उनमें मजदूरवर्ग की हिस्सेदारी

राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मजदूर सभा की जुलारू चेतना का नेजी में विकास हुआ और 1929 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर वामपंथी गुट की जीत हुई। यही व नई शक्तियाँ थी जो इस बार भारतीय जनता को सघन ने माग पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी।

घटनाक्रमों के इस विकास का प्रतिविम्ब कांग्रेस में भी दिखाई पड़ने लगा था और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक नए वामपंथी गुट का जन्म हो गया था। 1927 के अंत में जवाहरलाल नेहरू डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय तक यूरोप का दौरा करने के बाद भारत लौटे। नेहरू ने यूरोप में समाजवादी लागू और समाजवादी विचार धारा के साथ संपर्क किया था। 1927 के अंत में मद्रास कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें खाम तौर से युवकों के बीच वामपंथी प्रवृत्तियों की झलक मिली। मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें सर्वसम्मति से यह घोषित किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति है। (यह प्रस्ताव गांधी की अनुपस्थिति में पारित किया गया। गांधी ने बाद में इस प्रस्ताव की यह कटकर निंदा की कि 'यह बहुत जल्द बाजी में और बिना सोचे समझे किया गया है')। इससे पहले इस तरह की किसी भी प्रस्ताव का कांग्रेसी नेता विरोध करते आए थे। मद्रास अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में साइमन कमिशन के बहिष्कार का निश्चय किया गया और यह भी फैसला लिया गया कि वैकल्पिक सांविधानिक योजना तैयार करने के लिए सभी दलों का एक सम्मेलन हो और उसमें कांग्रेस भाग ले। कांग्रेस ने साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय लीग (इंटरनेशनल लीग ऑफ़ इपीरियलिज्म) से अपन को संबद्ध किया। नौजवानों और कांग्रेस के अंदर बढ़ती हुई वामपंथी प्रवृत्तियों के मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस का कांग्रेस का महामंत्री नियुक्त किया गया।

1927 के कांग्रेस अधिवेशन में वामपंथ की ऊपरी तौर पर जा विजय हुई वह एक सतही विजय थी और इस विजय का कारण यह था कि उसका विरोध किसी ने नहीं किया था। लेकिन 1928 में एक-के बाद एक घटना ने साइमन कमिशन के खिलाफ प्रदर्शनों की सफलता न, हड़तानों की वृद्धि न और नवगठित स्वतंत्रता लीग तथा छात्र युवक संगठनों के विकास न कांग्रेस के पुराने तत्त्व के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वामपंथी शक्तियाँ काफी तजी से बढ़ रही हैं और जल्दी ही व कांग्रेस का सफाया कर सकती हैं। सभी दलों के सम्मेलन में पुराने नेताओं ने कांग्रेस के बाहर के तत्त्वों या प्रतिक्रियावादी नेताओं के साथ मिल कर एक नैशनलिस्ट योजना बनाई (जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि योजना बनाने वाली समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे)। इस योजना में यह माग की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जल्द रहत हुए उत्प्रेरकपूर्ण सरकार का गठन किया जाए और इस प्रकार स्वतंत्रता की माग का अलग छोड़ दिया जाए। लेकिन जनता की बढ़ती हुई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बातों में मदद या निष्पत्ति योजना का कांग्रेस स्वीकार करनी।



सरकार को दो वष का समय दिया था लेकिन अधिवेशन न सिर्फ एक वष की मोहलत देना ही मजूर किया। यह प्रस्ताव भी अपेक्षाकृत कम वोटों से पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 1350 वोट पड़े जबकि सुभाषचन्द्र बास और जवाहरलाल नेहरू के उम वामपथी मण्डल के पक्ष में 903 वोट पड़े जिसमें नेहरू रिपार्ट के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता को तात्कालिक लक्ष्य घोषित किया गया था। 1928 की घटनाओं न यह बात साफ कर दी थी कि जनता का असतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है फिर भी आन्दोलन छेड़ने में 12 महीना की देर की गई। साम्राज्यवाद का 12 महीने का नोटिस दे दिया गया ताकि वह अपनी तैयारी पूरी कर ले। सुभाषचन्द्र बोस ने लिखा है कि 'कलकत्ता अधिवेशन के समझौतावादी प्रस्ताव का नतीजा यह हुआ कि 'वर्षायी मती समय बरबाद किया गया।' ('दि इंडियन स्ट्रगल', पृष्ठ 181) इस बीच घतर का एक सकेत भी मिल गया जब कलकत्ता के 20,000 मजदूरों ने (कांग्रेस का इतिहास में यह मध्या 50,000 बताई गई है) अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वतंत्र समाजवादी भारतीय गणराज्य के नारा के साथ प्रदर्शन किया। मजदूर दो घट तक अधिवेशन के पडाल पर कब्जा किए रहे। सुधारवादी नेताओं को उन्हे रास्ता देना पड़ा और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए अटूट संघर्ष छेड़ने की उनकी मांग सुनी पड़ी।

12 महीना की देर ने साम्राज्यवाद को भरपूर समय दे दिया और उसने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। मार्च 1929 में, उभरते हुए मजदूर आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मरठ जमे दूरवर्ती स्थान पर मुकदमा चलाया गया (जहाँ बिना जूरी के उन पर अदालती कायवाही की जा सके)। मुकदमा चार वर्षों तक चला और इन नेताओं को इन अवधि के दौरान जेल में रखा गया। इन वर्षों के दौरान एक के बाद एक संघों की लहरें उठती रही लेकिन इन राजनीतिक बदिया को सजाए भी नहीं सुनाई गई। मजदूर संगठनों और मजदूर किसान पार्टी के प्रमुख नेताओं के अलावा गिरफ्तार लोगों में तीन नत्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या राष्ट्रीय कांग्रेस की निर्वाचित कार्यवाहिनी के सदस्य थे। इस प्रकार कांग्रेस के नत्तत्व में संघर्ष शुरू होने से पहले ही मजदूरवर्ग का सिर बाट दिया गया और वामपथ के अत्यंत सुलझे तथा सकल्पशील नेताओं को जिनकी मही अर्थों में जनता के बीच पैठ थी, अलग कर दिया गया। इसके साथ वायसराय ने एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें मुम्ताज अली सेप्टी आर्डिनेंस जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया कि 'यदि मुम्ताज अली सेप्टी आर्डिनेंस जारी कर दिया जाय तो कुचलना था।

कांग्रेस के अत्यंत महत्वपूर्ण अ  
गांधी का कांग्रेस का  
तीन संघर्ष  
इंडेपेंडेंस  
न्या। ज

अवसर  
मान

11- पहल  
क तत्का  
तथा  
कर

चुके थे। अपने चयन के पक्ष में तक पेश करते हुए गांधी ने जवाहरलाल के गुणों का बयान किया और कहा

देशप्रेम के मामले में वह किसी से पीछे नहीं हैं, वह वीर और भावप्रवण हैं और आज के समय में इन गुणों की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन सधप में वीर और भावप्रवण होने के बावजूद उनमें एक राजनेता के विवेक का भी गुण है। उनके अदर अनुशासन की तीव्र भावना है और अपने कार्यों के ज़रिए उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके अदर उन निणयो को भी मानने की क्षमता है जिनसे उनकी सहमति नहीं है। स्वभाव से वह विनम्र हैं इतने व्यावहारिक हैं कि अकारण उगपथ का सहारा नहीं लेते। उनके हाथ में देश पूरी तरह सुरक्षित है।

नरमदली नेताओं ने साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने की एक बार अंतिम कोशिश की। 31 अक्टूबर 1929 को वायसरॉय ने एक बहुत ही अस्पष्ट वक्तव्य दिया जिसमें आगे चलकर कभी 'डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य तक' पहुँचने की बात कही गई थी। (यह एक ऐसा बयान था जिसके बारे में अगले ही दिन 'दि टाइम्स' समाचारपत्र ने लिखा कि 'इस वक्तव्य में न तो कोई वायदा था और न इससे नीति में किसी परिवर्तन का संकेत मिलता है।') भारतीय नेताओं ने इस वक्तव्य के बाद ही एक मयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे 'दिल्ली का घोषणापत्र' नाम से जाना जाता है। इस वक्तव्य में सरकार के साथ जी जान से सहयोग करने का प्रस्ताव किया। 'हम इस वक्तव्य से प्रकट होने वाली सरकार की हार्दिक भावनाओं की प्रशंसा करते हैं हम आशा करते हैं कि भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए जाने वाले डोमिनियन सविधान के लिए सम्राट के प्रयासों के साथ भरपूर सहयोग कर सकेंगे।' इस वक्तव्य पर गांधी श्रीमती वेसेंट, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस वक्तव्य से असहमति प्रकट की और बाद में उन्होंने इसे 'गलत और खतरनाक' बताया। उन्होंने कहा कि उनसे यू ही 'हस्ताक्षर करा लिया गया था' और उनसे कहा गया कि चूंकि वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं इसलिए यदि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया तो इससे कांग्रेस की एकता भंग हो जाएगी। बाद में गांधी ने उन्हें एक 'संतोष देने लायक पत्र' लिखा जिससे उनकी शिकाएँ दूर हो गईं। दिल्ली के घोषणापत्र से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को काफी खुशी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय नेता बमजार पड़ गए हैं ('कल रात के वक्तव्य का अर्थ यह है कि जिस वायव्य के लिए साहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है।'—'दि टाइम्स', 4 नवंबर 1929)। इस वक्तव्य से कोई लाभ नहीं हुआ, इससे कांग्रेस के सम्प्रदाय में और भटकाव ही आया। कांग्रेस अधिवेशन से कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेताओं की वायव्य से हुई भेंट का कोई नतीजा नहीं निकला।

1929 के अंतिम दिनों में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें आंदोलन छेड़न का फैसला किया गया। नहर् रीपोट में डोमीनियन कायम करने के घोषित लक्ष्य को पुराना घोषित कर दिया गया और ऐलान किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य 'पूर्ण स्वराज' रहेगा। अधिवेशन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह जब भी उचित समझे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दे जिसमें कर न देना भी शामिल हो। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, 1930 का वर्ष शुरू होते ही, भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा बड़ा पहराया गया (इस अंडे में पहले लाल, सफेद और हरा रंग था—बाद में लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग चुना गया)। 26 जनवरी 1930 का देश भर में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जगह जगह विशाल जुलूस निकले और प्रदर्शन किए गए जिनमें पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष का स्वल्प किया गया और ऐलान किया गया कि ब्रिटिश शासन को 'अब और स्वीकार करना मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति पाप करना है।' इसके साथ ही यह विश्वास प्रकट किया गया कि, 'यदि हमने स्वेच्छा-पूर्वक सरकार के साथ सहयोग करना और कर देना बंद कर दिया और उकसाए जाने पर भी हिंसा का सहारा नहीं लिया तो यह अमानवीय शासन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा।'।

जो संघर्ष अब शुरू हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था? इस अभियान की योजना क्या थी? वे कौन सी न्यूनतम शर्तें थी जिन पर सरकार के साथ समझौता करने का औचित्य था? वह कौन सा तरीका था जिससे ब्रिटिश सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव डाला जाता कि यह 'अमानवीय शासन' समाप्त हो जाता? शुरू में ही इन तमाम सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। ऊपरी तौर पर इस आंदोलन का घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति लगता था और कांग्रेस के सदस्य तथा कांग्रेस के आवाहन पर इस आंदोलन में शामिल जनता का भी समझत यही ख्याल था। वंशक, मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी मृत्यु के समय जो शब्द कहे थे (मोतीलाल नेहरू की मृत्यु गांधी इंदिरा समझौते की पूर्व संध्या पर हुई) उनमें भी आंदोलन के बारे में इसी धारणा का पता चलता है—यदि मुझे मरना ही है तो मेरी मौत स्वतंत्र भारत की गोद में हो। मेरी चिरनिद्रा की शुरुआत एक गुलाम देश में नहीं बल्कि आजाद देश में हो।'

फिर भी गांधी की धारणा यह नहीं थी। लाहौर अधिवेशन के तुरंत बाद 9 जनवरी के 'यूनायटेड वर्ल्ड' नामक अखबार में उनका एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 'स्वतंत्रता का प्रस्ताव से किसी का डरन की जरूरत नहीं है' (भाव में चापसराय की लिखे पत्र में भी उन्होंने यही बात दुहराई थी)। 30 जनवरी को अपने अखबार में इंडिया में उन्होंने ग्यारह सूत्री प्रस्ताव रखा जिसमें विभिन्न सुधारों का जिक्र करते हुए कहा गया था कि यदि इन सुधारों को मान लिया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा (इन सुधारों में मांग की गई थी कि रुपये की कीमत 1 शिलिंग 4 पस हो, देश में पूर्ण शराबबंदी हो, मालगुजारी और नैतिक धर्म में कमी की जाए विदेशी वपडा पर

चुगी लगाई जाए आदि)। सभ्यता की पूर्वप्रेता में इन ग्यारह शर्तों को प्रकाशित करके साम्राज्यवादियों के सामने यह स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वाधीनता की मांग केवल मोलभाव करने के लिए है, जिस तरह खरीद फरोक्त की बातचीत शुरू हान पर काफी मोलभाव की गुंजाइश रखकर दाम बताया जाता है पर सौदा तय हो जान पर दाम में कमी की जा सकती है उमी प्रकार यहां भी देश की मांग को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और यदि कोई समझौता होता है तो मांगें कम की जा सकती हैं।

आंदोलन की रणनीति भी उतनी ही अस्पष्ट थी। फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस समेटी की बैठक हुई जिसमें एक बार फिर आंदोलन का नेतृत्व करने और उसको चलाने के बारे में अधिकार 'महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों के हाथों में (न कि कांग्रेस के किसी चुने गए समूह के हाथों में) सौंप दिए गए। ऐसा करने के पीछे यह दलील पेश की गई कि 'जिन लोगों का अहिंसा के सिद्धांत में एक धार्मिक विश्वास है, उन्हें ही आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए और उनके ही द्वारा आंदोलन का संचालन होना चाहिए।' लेकिन कांग्रेस के चुने हुए नेताओं द्वारा बिना किसी निर्देश के समूचा आंदोलन उनके हाथों में सौंप दान से सभ्यता की रूप लेने वाला था 'लाहौर अधिवेशन की चर्चा करते हुए सुभाष बोस ने लिखा

वामपंथी खेमे की ओर से मैंने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में एक समानांतर सरकार की स्थापना करना होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मजदूरों, किसानों और युवकों का संगठन बनाना चाहिए। यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय तो मान लिया लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई और न तो आगामी वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम ही तैयार किया गया। अब और किस हान्यास्पद स्थिति की कल्पना की जा सकती है। (सुभाषचंद्र बोस 'दि इंडियन स्ट्रगल', पृष्ठ 200)

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है

भविष्य के बारे में हमारे सामने अब भी कुछ स्पष्ट नहीं था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई यह नहीं जानता था कि सभ्यता के कार्यक्रम में देश के लोग कहां तक साथ चल सकेंगे। हम जिस स्थिति तक पहुंच गए थे वहां से अब लौट नहीं सकते थे पर आगे का रास्ता हमारे लिए एकदम अज्ञात था। (जवाहरलाल नेहरू, 'आत्मकथा', पृष्ठ 202)

जो लोग आंदोलन की योजना की जानकारी चाहते थे उनको फटवार बताते हुए कांग्रेस



सावरमती में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने गांधी जी के योजना के बारे में उनसे जानकारी चाही। उनका यह पूछना ठीक ही था हालांकि विश्वयुद्ध शुरू होने से पहले किसी ने लाठ बियनर या माशल फौक अथवा बान हिंडेनबग से यह कभी नहीं पूछा कि उनकी योजना क्या है। उनके पास योजनाएँ थी पर उन्होंने कभी उन योजनाओं के बारे में बताया नहीं। सत्याग्रह के साथ ऐसी बात नहीं थी। हमारी योजनाएँ किसी भी रूप में गोपनीय नहीं थी लेकिन वे बहुत साफ भी रही थी। हम जानते थे कि वे अपने आप अपना रास्ता उसी तरह तैयार करती जाएंगी जिस तरह कोहरे से भरी सुबह में एक तेज चलती मोटर को आगे का रास्ता धीरे धीरे एक एक गज करके अपने आप दिखाई पड़ता जाता है। सत्याग्रही अपने मस्तिष्क पर मशाल बांध कर चलता है। उसकी रोशनी में उसे अगले कदम के लिए रास्ता मिलता जाता है। (हिस्ट्री आफ दि नेशनल कांग्रेस, पृष्ठ 628)

इस प्रकार गान्धी बाबू इस पर निश्चय थे कि आंदोलन के बारे में गांधी की धारणा क्या है? देश का भाग्य उनके हाथों में सौंप दिया गया था।

यह स्पष्ट है कि आंदोलन के उद्देश्य के विषय में दो विरोधी धारणाएँ संभव हैं। या तो इसका उद्देश्य यह होगा कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति और पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना के लिए भारतीय जनता की सभी शक्तियाँ एक निर्णायक संघर्ष में बूँद पड़ें ('कांग्रेस का इतिहास' में इस संघर्ष में संबंधित अध्याय का शीर्षक 'अंतिम दम तक संघर्ष' रखा गया है) या सरकार पर जनता का बोझ और सीमित दबाव डाला जाए ताकि उसमें कुछ बदलाव हों और रिमाफ्टें प्राप्त कर ली जाएं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निश्चय ही पहली तरह के आंदोलन की बात मोची गई थी और भारत की जाना भी यही आता कर रही थी। लेकिन यहाँ यही उद्देश्य था तो इतने विनाश काय का मतलब करने के लिए और देश की शक्तियों को दुर्गम का मान देने के लिए यह जरूरी था कि दुर्गम द्वारा जवाबी हमला शुरू किए जानें। पहले ही भरपूर ताकत बतोरकर उस पर घावा बोल दिया जाए। कांग्रेस और मजदूर आन्दोलन की पूरी शक्ति के साथ एक ही आह्वान का गारा दिया जाता कर और संगठन का अभिप्राय शुरू करने के लिए समूह विभाजन का आवाहन, तथा देश भर में अपनी विभागों, अरबों अंगणवाड़ी और भव्य स्वयंसेवक आदि का संग संगठनात्मक सरकार कायम किया जाता आदि जरूरी था। उन दिनों देश में जैसा मातावनी था और जैसा मजदूरों का संग संगठन हुआ वह कहा जा सकता था कि यदि एक तरह का आन्दोलन प्रत्यक्ष मजदूरों और मजदूरों के साथ चलाना होता तो देश की वर्तमान समस्याओं की दिशा में एक नया रास्ता उभरती गता किन्तु एकमात्र यह रास्ता (एकमात्र विचारधारा के विचार और दृष्टिकोण तथा एक संयुक्त संगठन का संग संगठन की कानूनन स्थापना के लिए) और आखिरी हाथों का संग संगठन।

तबिन गांधी की यह धारणा नहीं थी। उस समय के और बाद के प्रमाणों से यही पता चलता है कि गांधी की मुख्य समस्या इस तरह के विवास को आगे बढ़ने से रोकने की थी। मई 1931 में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने कहा है कि यदि अहिंसा के सिद्धांत से 'रत्ती भर भी हटने से' मुझे विजय मिल जाती है तो मैं इस विजय से अपनी पराजय ज्यादा पसंद करूंगा 'अहिंसा से रत्ती भर भी हटने से सदेहपूर्ण सफलता के बदले में मैं यह ज्यादा पसंद करूंगा कि अहिंसा पर आच न आए भले ही मैं हार क्यों न जाऊ।' (8 मई 1931 के 'दि टाइम्स' ने गांधी के मई 1931 के लेख को उद्धृत किया था।) मार्च 1930 में गांधी ने वायसराय के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने वायसराय को बताया था कि सघप के पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं और यह (गांधी) उनका नेतृत्व क्यों कर रहे हैं ?

हिंसा का पक्ष मजबूत हो रहा है और इसका अनुभव भी किया जाने लगा है मेरा मकसद यह है कि ब्रिटिश शासन की संगठित हिंसा के साथ साथ हिंसा के बढ़ते हुए पक्ष की असंगठित हिंसा के खिलाफ मैं उस शक्ति का (अहिंसा का) प्रयोग शुरू करूँ। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का अर्थ दोनों शक्तियों को बेलगाम छोड़ देना होगा। (गांधी का पत्र वायसराय के नाम, 2 मार्च 1930)

इस प्रकार आतंकवादी लहर की उठान से ठीक पहले गांधी ने दो मोर्चों पर लड़ाई चलाने की घोषणा कर दी। उन्होंने केवल अंगरेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश के अदरुनी दुश्मनों के खिलाफ भी सघप चलाने की घोषणा की। दो मोर्चों पर लड़ने की यह धारणा भारतीय पूँजीपतिवर्ग की भूमिका के अनुरूप है। भारत के पूँजीपतिवर्ग ने इस खतरे को महसूस किया, उसने देखा कि साम्राज्यवाद और जनआंदोलन के बीच बढ़ते सघप से उसके परो तले से जमीन खिसकने लगी है। उसे मजबूरी में सघप का नेतृत्व करना पड़ा हालाँकि इस काम में उसे 'भयंकर खतरा' (वायसराय के पत्र में गांधी ने इसी शब्द का प्रयोग किया था) दिखाई पड़ा और उसके लिए आंदोलन को सीमाओं में बांधकर रखना जरूरी हो गया ('खामोश बैठने का अर्थ था दोनों शक्तियों को मनमानी करने की छूट देना')। उसके लिए यह जरूरी हो गया कि वह 'अहिंसा' की जादुई छड़ी से दोनों शक्तियों को मनाने की कोशिश करे। फिर भी यह 'अहिंसा' ठीक उसी तरह 'एकतरफा अहिंसा' थी जिस तरह बाद के वर्षों में जनतांत्रिक शक्तियों ने स्पेन के सदाभ में 'हस्तक्षेप न करने' की शरारतपूर्ण नीति का पालन किया। यह 'अहिंसा' भारतीय जनता के लिए थी न कि साम्राज्यवादियों के लिए। उन्होंने जमकर हिंसा का सहारा लिया और विजय भी उन्हें ही मिली।<sup>3</sup>

गांधी ने सघप के बारे में अपनी धारणा के अनुरूप ही अपनी रणनीति भी तैयार की। यदि यह मानकर चला जाए कि इस रणनीति का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं बल्कि दुर्जेय आतंकवादी लहर के बीच जनआंदोलन पर अपना नेतृत्व बनाए रखना आर



करें, विदेशी कपडों की दूकानों पर और शराब की सरकारी दूकानों पर पिकेटींग करें। 9 अप्रैल को गांधी ने जो निर्देश जारी किए थे उनसे पता चलता है कि आंदोलन के बारे में उनकी क्या धारणा थी

हमारा रास्ता पहले से ही हमारे लिए निश्चित किया जा चुका है। हर गांव को चाहिए कि वह गैरकानूनी नमक तैयार करे। वहनों को चाहिए कि वे शराब की दूकानों, अफीम के ठेकों और विदेशी कपड़े की दूकानों के सामने पिकेटींग करें। हर घर में बूढ़ों और जवानों को चाहिए कि वे तकली और चरखा काँते और रोज का बुना सूत इकट्ठा करें। विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत से दूर रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई, सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के बाद जो कुछ बचे उसी से बहुसंख्यकों को संतुष्ट रहना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि वे सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करें और सरकारी कमचारियों को चाहिए कि वे अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर जनता की सेवा में लग जाए। तब हम देखेंगे कि पूर्ण स्वराज हमारे दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है।

जनआंदोलन, जो अप्रैल में ही काफी विकसित हो चुका था, इन सरल सीधी सीमाओं को काफी दूर तक पार कर गया। देश भर में हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा, जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे, बंगाल में चटगांव के हथियारखाने पर छापा मारा गया, पेशावर में विद्रोह की घटनाएं हुईं जिसके फलस्वरूप पेशावर पर दस दिनों तक जनता का कब्जा रहा। जगह जगह किसानों द्वारा लगान न देने का स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन खास तौर से संयुक्त प्रांत में काफी तेज रहा जहां कांग्रेस ने कोशिश की कि 50 प्रतिशत लगान का भुगतान करा कर समझौता करा दिया जाए पर इस कोशिश में उसे सफलता नहीं मिली।

समूचे भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों द्वारा की गई बग़ावत थी जहां स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता के रोपपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए बख्तरबद गाड़ियां भेजी गईं। जनता ने एक बख्तरबद गाड़ी को जला दिया। गाड़ी के भीतर जो लोग थे वे भाग खड़े हुए। इसके बाद जनता पर घुआधार गोलियां चलाई गईं जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। स्थिति की गंभीरता को देखकर 18वीं रामल गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन की तीन टुकड़ियां भेजी गईं। मुसलमानों की भीड़ से निबटन के लिए हिंदू सैनिकों को भेजा गया पर उन्होंने भीड़ पर गोली चनाने के आदेश को मानने से इकार किया, अपनी कतारें ताड़ दी भीड़ के साथ भाईचारा कायम कर लिया और अनेक सिपाहियों ने तो अपने हथियार भी जनता को सौंप दिए। इसने फौरन बाद पेशावर से सारी फौज और पुलिस हटा ली गई। 25 अप्रैल

इस पर अधिक से अधिक रोक लगाना था तो इसमें कोई शक नहीं कि गांधी की रणनीति बहुत ही कुशल और योग्य रणनीति थी। इसका पता उसी समय लग गया था जब गांधी ने अपने आंदोलन का पहला लक्ष्य तैयार किया था और उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता निर्धारित किया था। अपने लक्ष्य और तरीके के निर्धारण में उन्होंने बहुत कुशलता का परिचय दिया था। उन्होंने सरकार के नमक बनाने के एकाधिकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ना तय किया। इस आंदोलन से यह संभावना उत्पन्न हो गई कि मजदूर वगैरह सघन भाग लेंगे। गांधी ने अपने लगभग सभी वक्तव्यों में यह कहा था कि भारत में उन्हें मजदूरवर्ग से ही काफी डर लगता था। इस आंदोलन में किसानों का समयन प्राप्त करने की योग्यता थी और इस बात का कोई भय नहीं था कि किसान वगैरह जमींदारों के खिलाफ सघन करेंगे। इसकी ओर भी ज्यादा गारंटी के लिए गांधी ने घोषणा की कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत वह स्वयं अपने शिष्यों के एक दल के साथ करेंगे 'जहां तक मेरा संबंध है, मैं चाहता हूँ कि यह आंदोलन में आश्रमवासियों और उन लोगों के जरिए शुरू करूँ जिन्होंने आश्रम का अनुशासन स्वीकार कर लिया है और कायपद्धति मान ली है।' (यंग इंडिया में गांधी का लेख, 27 फरवरी 1930)

इसके बाद गांधी ने अपने 78 चुन हुए शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे किनारे डांडी यात्रा शुरू की और इसमें उन्होंने तीन वेशकीमती हफ्ते निकाल दिए। दुनिया भर के समाचारपत्रों और यूजरीलों के फोटोग्राफर इस यात्रा की तस्वीरें खींचते रहे, जनता से कहा गया कि वह चुपचाप इंतजार करे कि आगे क्या होता है। समाचारपत्रों, सिनेमा तथा अन्य प्रचार साधनों द्वारा डांडी यात्रा को जो धूमधारा प्रचार किया गया, उसे देख कर कांग्रेस नेताओं ने समझा कि जनता में जागृति पैदा करने और उसे जादोलित करने के रूप में इस रणनीति की जबरदस्त सफलता मिली है। यह भी सच है कि इससे जनता के पिछड़े तबकों को जगाने में मदद मिली लेकिन साथ ही साम्राज्यवादियों ने अपने बाद के रुख के विपरीत (जब प्रमुख वामपंथी राष्ट्रवादी नेता सुभाष बोस को सघन शुरू होने के पहले, स्वतंत्रता दिवस के पहले ही पकड़ लिया गया) डांडी यात्रा को प्रचारित करने की जो खुली छूट दे रखी थी वह किसी नासमझी या अज्ञानता के कारण नहीं थी। इसके विपरीत सरकार इस आंदोलन के महत्व को खूब अच्छी तरह समझती थी। सरकार ने उसका प्रचार महज इसीलिए किया ताकि जनआंदोलन उस दलदल में जाकर फंस जाए जो गांधी ने तैयार कर दिया था।

तो भी, तीन सप्ताह समाप्त होते ही 6 अप्रैल को जब गांधी न समुद्र तट पर काफी समाराहपूर्वक नमस्कार कराया (और वह गिरफ्तार नहीं किए गए) तो देश भर में जन आंदोलन की ऐसी जबरदस्त लहर चल पड़ी कि दोनों तरफ के नेता आश्चर्यचकित रह गए। आंदोलन के मिलमिले में गांधी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उनमें बहुत ही सीमित और अपेक्षाकृत अहानिवरक से सविनियम अवज्ञा आंदोलन छेड़ना की बात थी। इसमें कहा गया था कि लोग रमन नानून का उल्लंघन करें, विदेशी वस्तु का बहिष्कार

करें, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर और शराब की सरकारी दुकानों पर पिकेटींग करें। 9 अप्रैल को गांधी ने जो निर्देश जारी किए थे उनसे पता चलता है कि आंदोलन के बारे में उनकी क्या धारणा थी

हमारा रास्ता पहले से ही हमारे लिए निश्चित किया जा चुका है। हर गांव को चाहिए कि वह गैरकानूनी नमक तैयार करे। वहनों को चाहिए कि वे शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने पिकेटींग करें। हर घर में बूढ़ों और जवानों को चाहिए कि वे तकली और चरखा कातें और रोज का बुना सूत इकट्ठा करें। विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए। हिंदुओं को छुआछूत से दूर रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई, सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के बाद जो कुछ बचे उसी से बहुसंख्यकों को संतुष्ट रहना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि वे सरकारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करें और सरकारी कमचारियों को चाहिए कि वे अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर जनता की सेवा में लग जाएं। तब हम देखेंगे कि पूरा स्वराज हमारे दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है।

जनआंदोलन, जो अप्रैल में ही काफी विकसित हो चुका था, इन सरल सीधी सीमाओं को काफी दूर तक पार कर गया। देश भर में हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा, जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे, बंगाल में चटगांव के हथियारखाने पर छापा मारा गया, पेशावर में विद्रोह की घटनाएं हुई जिसके फलस्वरूप पेशावर पर दस दिनों तक जनता का कब्जा रहा। जगह जगह किसानों द्वारा लगान न देने का स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन खास तौर से संयुक्त प्रांत में काफी तेज रहा जहां कांग्रेस ने कोशिश की कि 50 प्रतिशत लगान का भुगतान करा कर समझौता करा दिया जाए पर इस कोशिश में उसे सफलता नहीं मिली।

समूचे भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना पेशावर में गढ़वाली सिपाहियों द्वारा की गई बग़ावत थी जहां स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता के रोषपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए बख्तरबद गाड़ियां भेजी गईं। जनता ने एक बख्तरबद गाड़ी को जला दिया। गाड़ी के भीतर जो लोग थे वे भाग खड़े हुए। इसके बाद जनता पर घुआधार गोलीया चलाई गईं जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। स्थिति की गंभीरता का देखकर 18वीं रायल गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन की तीन टुकड़ियां भेजी गईं। मुगलमानों की भीड़ से निपटने के लिए हिंदू सैनिकों का भेजा गया पर उन्होंने भीड़ पर गोनी चलाने के आदेश को मानने से इंकार किया, अपनी मत्तारें ताड़ दी, भीड़ के साथ भाईचारा कायम कर लिया और अनेक सिपाहियों ने तो अपने हथियार भी जनता को गौरे लिए। दंगने पीछे बाद पेशावर से सारी फौज और पुलिस हटा ली गई। 25 अप्रैल

स 4 मई तक शहर पर जनता का कब्जा रहा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने हवाई टुकड़ियों के साथ एक शक्तिशाली फौज पेशावर पर 'फिर से कब्जा' करने के लिए भेजी। बिना किसी प्रतिरोध के सेना ने फिर से पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। गढ़ वाली राइफल्स के 17 आदमियों का कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें गभीर सजाए दी गई, एक को बाले पानी की सजा, एक को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 15 लोगों को 3 से 10 वर्ष तक की कैद की सजा दी गई।

अपने देशवासियों पर गोली न चलाने की जो मिसाल गढ़वाली सिपाहिया ने कायम की उसके विषय में कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह गांधी के सबसे प्रिय सिद्धांत 'अहिंसा' का एक सफल प्रदर्शन था। लेकिन गांधी का मत यह नहीं था। यह एक ऐसी अहिंसा थी जिसने सचमुच अंगरेजी राज्य की नींव हिला दी। गांधी इव्हिंग समझोते में उल्लिखित राजबंदियों की रिहाई की धारा में गढ़वाली सिपाहियों को खास तौर से अलग रखा गया। 'कांग्रेस का इतिहास' में अनेक छोटी मोटी आतंकवादों कायवाहिया का जिक्र है और इनके जरिए यह बताया गया है कि इनसे राष्ट्रीय भावना के बढ़ने में मदद मिली। लेकिन इस पूरे इतिहास में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के इस काम को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। गढ़वाली वीर इस दौरान जेलों में पड़े रहें और 1937 के उत्तराखण्ड में वे तब रिहा किए गए जब कांग्रेसी मंत्रियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। गढ़वाली सिपाहियों की वीरता की कहानी को जनता ने अपने हृदय में स्थान दिया और जब आजाद भारत में लोग अनेक राजनीतिज्ञों को भूल चुके होंगे, गढ़वाली बहादुर का नाम गढ़ और सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी लंदन गए थे, एक फ्रांसीसी पत्रकार के साथ अपनी भेंटवार्ता में उन्होंने बताया कि उन्होंने गढ़वाली सिपाहियों के काम को क्यों नहीं पसंद किया

एक निपाही जो गोली चलाने का आदेश मानने से इंकार करता है वह आज्ञाकारिता की शपथ का उल्लंघन करता है और आज्ञा भंग करने के अपराध का दोषी है। मैं अफसरों और सिपाहियों से आज्ञा का उल्लंघन करने को नहीं कह सकता। क्योंकि जब मेरा शासन होगा तब संभव है कि मैं भी इन्हीं अफसरों और सिपाहियों से काम लूँ। यदि मैं इन्हीं आज्ञा उल्लंघन करना सिखाऊंगा तो बल के मेरे राज्य में भी ऐसा ही कर सकते हैं। (गढ़वाली सैनिकों के प्रश्न पर फ्रांसीसी पत्रकार चार्ल्स पेंनास के सवाल का गांधी द्वारा दिया गया जवाब, 'मोद', 20 फरवरी 1932)

बारदोली के पंचसत की ही तरह यह वाक्य (जिस पर गांधी के प्रत्येक शांतिवादी प्रशंसक को विचार करना चाहिए) भी 'अहिंसा' के अर्थ को बहुत स्पष्ट कर देता है।

जब यह स्पष्ट हो गया कि जनआंदोलन का तूफान अपने ऊपर थोपा गई सीमाओं को

ताड़ता जा रहा है और गांधी की बात लोग अब कम मानने लगे हैं तो सरकार ने, जिसने अभी तक गांधी को स्वतंत्र छोड़ रखा था, 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकारी 'कम्प्यूनिके' (विज्ञप्ति) में गिरफ्तारी का कारण बताया हुआ कहा गया

हालांकि मिस्टर गांधी इन हिंसात्मक उपद्रवों की लगातार निंदा करते आए हैं लेकिन अपने उच्छृंखल अनुयायियों के खिलाफ उनकी आवाज दिनोदिन कमजोर पड़ती जा रही है और यह बात स्पष्ट है कि अब वह इन तत्वों का काबू में रखने में असमर्थ है। गिरफ्तारी के दौरान उनके स्वास्थ्य और आराम का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

इस गिरफ्तारी के बाद देश भर में हड़तालों की लहर चल पड़ी। बंबई प्रेसीडेंसी के औद्योगिक नगर शोलापुर में आबादी के कुल 140,000 लोगों में से 50,000 कपड़ा मिल मजदूर थे। इन मजदूरों ने पुलिस को हटाकर अपना प्रशासन कायम कर लिया और शहर पर एक सप्ताह तक उनका कब्जा बना रहा। 13 मई को माशुल ला लागू करके ही मजदूरों का प्रशासन समाप्त किया जा सका। 'दि टाइम्स' के सवाददाता ने 14 मई 1930 को लिखा कि 'यहां तक कि कांग्रेस नेताओं का भी भीड़ पर कोई काबू नहीं रह गया था। भीड़ स्वयं अपना शासन कायम करना चाहती थी।' पूना के समाचारपत्र 'स्टार' ने लिखा 'जनता ने प्रशासन अपने हाथों में संभाल लिया था और वे अपने कामदे कानून चलाने की कोशिश कर रहे थे।' समाजवादी प्रमाणों से पता चलता है कि पूरी व्यवस्था कायम हो गई थी।

साम्राज्यवादी दमन की कोई सीमा नहीं थी। एक के बाद एक अध्यादेश जारी किए जा रहे थे जिससे स्थिति माशुल ला जैसी ही हो गई थी। जून में कांग्रेस और इसके तमाम संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1931 में गांधी-श्वेन समझौता हान तक के एक साल से भी कम समय में 60,000 सत्याग्रहियों का सजा दी गई थी। यह सख्या निश्चित रूप से कम करके बताई गई है क्योंकि जिन लोगों को दगा आदि करने के आराप लगाकर पकड़ा गया था, उन्हें इस सख्या में शामिल नहीं किया गया था। इसमें केवल उन्हीं लोगों की गिनती की गई थी जिन्हें सरकार राजनीतिक बंदी मानती थी। राष्ट्रवादियों ने उन दिनों का जो विस्तृत विवरण तैयार किया है उसके अनुसार 90,000 लोगों को सजा दे दी गई। '1930-31 में, 10 महीने के अल्प अंतराल के अंदर ही 90,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सजाए दी गई' ('हिस्ट्री ऑफ़ दि नेशनल कांग्रेस', पृष्ठ 876)। यसार काम 'लेबर' सरकार के शासन काल में हुआ। 27 अप्रैल 1930 को प्रतिश्रियावादी पत्र 'आब्जर्वर' ने लिखा कि यह एक 'सुखद संयोग' है कि इस समय लेबर सरकार सत्ता में है और यह कि भारत को ध्यान में रखते हुए अब यह एक सावजनिय आवश्यकता है कि लेबर मंत्रिमंडल सत्ता में बने रहने दिया जाए।'

सांगों को गिरफ्तार कर लेना दमन का सबसे हल्का रूप था। जेलों में लागू ठसठस भर





कलकत्ता के 'स्टट्समैन' के स्तम्भों को छोड़कर हर जगह पस्तहिम्मती छाई हुई है। इस आशय की भी अफवाह काफी फैल रही थी कि कलकत्ता और बंबई के अंगरेज व्यापारियों तथा कांग्रेसी तत्वों के बीच इस तरह की बातचीत चल रही है कि बहिष्कार तथा दूसरी अस्थायी बुराइयों को यदि थोड़ा कम कर दिया जाए तो स्याई तीर पर राजनीतिक आत्मसमर्पण हो सकता है। यूरोपीय लोग का मनोबल टूट रहा है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर जगह यूरोपीय लोगों का मनोबल टूट रहा है। कलकत्ता में इसके खिलाफ जबरदस्त जनमत है। ('आब्जर्वर', 6 जुलाई 1930)

अगस्त आने आने 'आब्जर्वर' का कलकत्ता स्थित सवाददाता वीकनेस इन बावे ('बंबई में कमजोरी') शीपक से यह लिखने लगा था

बंबई के इस समाचार से यहां के जनमत को बड़ा धक्का लगा है कि अंगरेजों की देखरेख में चलने वाली कुछ मिलों को कांग्रेस की शर्तें मान लेनी पड़ी हैं और इसलिए एक प्रमुख नागरिक बंबई की लाइट होस से इस्तीफा दे रहा है। योरोपियन एमोमिएशन की बंबई शाखा के ध्वम्न होने की खबर का भी यही असर हुआ है। इसने उल्लेखनीय बहुमत से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर इसलिए राय देने से इकार कर दिया था कि क्योंकि यह भारतीय जनमत का मान्य नहीं था। गोलमेज सम्मेलन के लिए बंबई शाखा ने अपन उम्मीदवार का नाम भी वापस ले लिया है। ('आब्जर्वर', 24 अगस्त 1930)

इस प्रकार मारी धमकिया और दमन के बावजूद साम्राज्यवादी खेमे में 'पराजय बाध' और 'पस्तहिम्मती' की हालत पैदा होने लगी थी। साम्राज्यवादियों के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वे किसी भी कीमत पर कोई समझौता कर लें। भारतीय जनता के गणप और बलिदानों के आधार पर कांग्रेस के नेताओं का पलड़ा भारी था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने अपने कल्याण का एकमात्र रास्ता यह रह गया था कि वे नरम-दली राष्ट्रीय नेताओं से कुछ आशा कर। सरकार को यह पता था कि नरमदली नेता जनसमर्थ के व्यापक स्वरूप का देखकर बहुत घबरा गए हैं। मितवर में मैली ओव कालेज, बरमिधम में अंतर्राष्ट्रीय संघों के प्रोफेसर एच० जी० एलेजेंडर ने गांधी से भेंट की और उन्होंने गांधी के विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा

जेल के एवान में भी उनका इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि इस तरह की कटुता फैल रही है और इस कारण जितनी जल्दी ईमानदारी के साथ शांति और सहयोग की भावना फिर से स्थापित हो जाए वह उतना ही उसका स्वागत करेंगे उनका प्रभाव अब भी बहुत ज्यादा है लेकिन हर दिन जो शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं वे अपवादोक्त काफी घटिरनाय हैं और उन पर बाध पाना

दिए गए थे और यह बात स्पष्ट थी कि गिरफ्तारियों से आंदोलन को रोकना असंभव था। इसलिए सरकार शारीरिक यातना के हथियार को अपना मुख्य हथियार बना रही थी। जितना बड़े पैमाने पर अधाधुंध लाठीचार्ज हुए, लोगों को जिस बबरता से पीटा गया, निहत्थी जनता पर जिस तरह गोली चलाई गई पुरुषों और महिलाओं की जितनी व्यापक ढंग से हत्याएं की गई (कई मामलों में तो लोगों को गोलीबारी से भून दिया गया और फासी दे दी गई टैंक और बस्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और विमानों से बम बरसाए गए) उसकी तुलना किसी भी देश में हुए दमनचक्र से नहीं की जा सकती। जिन अत्यंत अनुभवी पत्रकारों ने इन घटनाओं की एक झलक भी पा ली उनका दिल दहल उठा।<sup>1</sup> इन कायवाहियों पर परदा डालने के लिए खबरों पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सावधानीपूर्वक इन तमाम घटनाओं का व्योरा तैयार किया। इसके लिए उसने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे किए जिनसे पता चलता है कि कितनी बबरतापूर्वक दमन किया गया था।

फिर भी 1930 के दौरान आंदोलन जितना शक्तिशाली हो गया था उसका अगरेजों ने अनुमान भी नहीं लगाया था। दमन के बावजूद आंदोलन दिनोदिन बढ़ता जा रहा था जिससे साम्राज्यवादी खेमे में आतंक फैल गया था। 1930 की गर्मियां तक यह बात अब काफी खुलकर सामने आने लगी थी। खास तौर से ब्रिटेन का व्यापारीवर्ग बेहद घबरा गया था क्योंकि विदेशी सामानों के त्रहिप्पार में सबसे बुरी तरह वही प्रभावित हुआ था। बंबई के सदर्भ में यह बात खास तौर से देखी जा सकती थी। वहां औद्योगिक मजदूरों का केंद्र था और दमन भी यहां काफी जबरदस्त था। यहां आंदोलन सबसे जबरदस्त था और पुलिस द्वारा बार बार लाठीचार्ज के बावजूद लोग सड़कों पर कब्जा कर लेते थे। बड़े बड़े जुलूस निकलते थे जो कांग्रेसियों के बहुत निवेदन करने पर भी पीछे नहीं हटते थे। इन जुलूसों में कांग्रेसी झंडा के साथ साथ लाल झंडे लहराते हुए देखे जाते थे, कहीं कहीं तो लाल झंडा की ही भरमार रहती थी। 29 जून को 'आब्जर्वर' के संपादक ने लिखा कि कलकत्ता तथा अन्य बड़े शहरों से आए लोग बंबई की हातहत देखकर दंग रह जाते थे। 5 जुलाई के 'स्पेक्ट्र' में 'बंबई का एक पक्ष प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि यदि यहां सेना और सशस्त्र पुलिस तैनात न की गई होती तो बंबई की सरकार का एक दिन में तख्ता पलट जाता, प्रशासन पर कांग्रेस का कब्जा हो जाता और इस काम में उसे सबका समर्थन मिलता। 'बंबई में रहने वाले अगरेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों के साथ साथ 'मिल आनस एसोसिएशन' (जिसमें एक तिहाई यूरोपीय थे) और चेंबर आफ कामर्स के जगिए यह मांग शुरू की कि भारत को डोमिनियन राज्य के आधार पर फौरन स्वराज दे दिया जाए। बंबई के 'टाइम्स आफ इंडिया' का यह चमत्कार भी सामने आया जिसमें उसने केंद्र में जिम्मेदार संसदीय सरकार की हिमायत की थी। 6 जुलाई आते आते 'आब्जर्वर' ने यह चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी थी कि भारत में रहने वाले यूरोपीयों का मनोबल टूट रहा है।

कलकत्ता के 'स्टूड्समैन' के स्तम्भों को छोड़कर हर जगह पस्तहिम्मतों छाई हुई है। इस आशय की भी अफवाह काफी फैल रही थी कि कलकत्ता और बर्बई के अगरेज व्यापारियों तथा कांग्रेसी तत्वों के बीच इस तरह की बातचीत चल रही है कि वहिष्कार तथा दूसरी अस्थायी बुराइयों को यदि थोड़ा कम कर दिया जाए तो स्थाई तौर पर राजनीतिक आत्मसमर्पण हो सकता है। यूरोपीय लोगों का मनोबल टूट रहा है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर जगह यूरोपीय लोगों का मनोबल टूट रहा है। कलकत्ता में इसके खिलाफ जबरदस्त जनमत है। ('आब्जर्वर', 6 जुलाई 1930)

अगस्त आते आते 'आब्जर्वर' का कलकत्ता स्थित सवाददाता 'वीक्नेस इन बाबे' ('बर्बई में कमजोरी') शीपक से यह लिखने लगा था

बर्बई के इस समाचार से यहां के जनमत को बड़ा धक्का लगा है कि अगरेजों की देखरेख में चलने वाली कुछ मिलों को कांग्रेस की शर्तें मान लेनी पड़ी हैं और इसलिए एक प्रमुख नागरिक बर्बई की लाइट होस से इस्तीफा दे रहा है। योरोपियन एसोसिएशन की बर्बई शाखा के ध्वस्त होने की खबर का भी यही असर हुआ है। इसने उल्लेखनीय बहुमत से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर इसलिए राय देने से इकार कर दिया था कि क्योंकि यह भारतीय जनमत को माय नहीं था। गोलमेज सम्मेलन के लिए बर्बई शाखा ने अपने उम्मीदवार का नाम भी वापस ले लिया है। ('आब्जर्वर', 24 अगस्त 1930)

इस प्रकार सारी धमकियों और दमन के बावजूद साम्राज्यवादी खेमे में 'पराजय बोध' और 'पस्तहिम्मती' की हालत पैदा होने लगी थी। साम्राज्यवादियों के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वे किसी भी कीमत पर कोई समझौता कर लें। भारतीय जनता के संघर्ष और बलिदानों के आधार पर कांग्रेस के नेताओं का पलड़ा भारी था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने अपने कल्याण का एकमात्र रास्ता यह रह गया था कि वे नरम-दली राष्ट्रीय नेताओं से कुछ आशा करें। सरकार को यह पता था कि नरमदली नेता जनसंघर्ष के व्यापक स्वरूप को देखकर बहुत घबरा गए हैं। सितंबर में सैली ओक कालेज, बरमिंघम में अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के प्रोफेसर एच० जी० एलेजैंडर ने गांधी से भेंट की और उन्होंने गांधी के विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा

जेल के एकांत में भी उनको इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि इस तरह की बटुता फैल रही है और इस कारण जितनी जल्दी ईमानदारी के साथ शांति और सहयोग की भावना फिर से स्थापित हो जाए वह उतना ही उसका स्वागत करेंगे उनका प्रभाव अब भी बहुत ज्यादा है लेकिन हर दिन जो शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं वे अप्रत्याशित काफी खतरनाक हैं और उन पर बाध पाना

मुश्किल है। (प्रोफेसर एच० जी० एनेग्जेडर 'मिस्टर गांधीज प्रजेंट आउटलुक', 'इस्पैक्टटर', 3 जनवरी 1931)

इस प्रकार दोनों तरफ चिंता बढ़ रही थी और इस दोनों ओर की चिंता तथा घबराहट के कारण समझौते की संभावना पैदा हो गई थी, लेकिन यह समझौता भारतीय जनता के खिलाफ ही होना था।

1930 के शरद में समझौते की बातचीत शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 20 जनवरी 1931 को प्रधानमंत्री की हैसियत से मैकडोनेल्ड ने गोलमेज सम्मेलन में घोषणा की

मैं इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि हमारी मेहनत से भारत उस एकमात्र वस्तु को पा जाए जिसके अभाव के कारण ही उसे अभी तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर डोमिनियन का दर्जा नहीं मिल सका है भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण स्वशासी शासन की जिम्मेदारी और भार तथा गव और सम्मान प्राप्त हो सके।

जैसा कि वाद की घटनाओं से पता चला, भारत के सामने बड़े गोलमोल शब्दों में यह एक चारा डाला गया था और इस घोषणा के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कोई वायदा नहीं किया था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन आगे के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि कांग्रेस इसमें हिस्सा ले सके।

26 जनवरी को गांधी और कांग्रेस कायसमिति को बिना शर्त रिहा कर दिया गया और उन्हें बैठक बनने की स्वतंत्रता दी गई। गांधी ने एलान किया कि वह 'पूरी तरह खुला हुआ दिमाग' लेकर जेल से बाहर निकले हैं (यह किसी क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के लिए जिसे एक घूत और बेईमान दुश्मन का मुकाबला करना हो, बड़ी खतरनाक स्थिति है)। इसके बाद समझौते की लंबी बातचीत चली। 4 मार्च को गांधी-इर्विन समझौते पर हस्ताक्षर हो गए और आंदोलन को अस्थाई तौर पर स्थगित करने की घोषणा की गई।

इर्विन-गांधी समझौते ने कांग्रेस के सघन के एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की (यहां तक कि नमक कर भी रद्द नहीं हुआ)। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेना पड़ा। कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ा जिसमें भाग न लेने की उसने बसम खाई थी। स्वराज की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गोलमेज सम्मेलन में बातचीत के लिए यह आधार निश्चित किया गया कि 'भारतीयों के हाथों में जिम्मेदारी' सहित सचीव सविधान के आधार पर विचारविमर्श किया जाए लेकिन 'भारत के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकार अंगरेजों के हाथ में सुरक्षित रहें।' यह तय हुआ कि अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे और राजनीतिक बदियों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन

जिन बंदियों पर 'हिंसा' या 'हिंसा के लिए भड़कान' की कायवाहियों का आरोप लगाया गया है अथवा आज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में जो सैनिक बंद हूँ उनको नहीं छोड़ा जाएगा। विदेशी सामानों के बहिष्कार की आज्ञा दी दे दी गई लेकिन इनके साथ कुछ शर्तें भी लगाई गईं। इन शर्तों के अधीन बहिष्कार 'केवल ब्रिटिश सामानों' का न किया जाए, किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए 'इस आंदोलन का इस्तेमाल न हो, इस आंदोलन में पिकेटिंग का सहारा न लिया जाए जिसमें लोगों को जबरदस्ती रोका जाता हो, विरोधी प्रदर्शन होत हों या जनता के कामकाज में रुकावट पैदा होती हो।' समझौते की अथ धाराएं भी इसी तरह की थीं जिनमें अगर एक हाथ से कुछ दिया जाता था तो दूसरे हाथ से उसे छीन भी लिया जाता था। इस समझौते का अधिक से अधिक केवल यह लाभ हुआ कि जनता को विदेशी वपड़ों के शांतिपूर्ण बहिष्कार का अधिकार मिल गया। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि इस समझौते की आड़ में भारत के लोगों के हित के नाम पर किन लोगों का स्वायत्त काम कर रहा था।

निस्संदेह इस तथ्य से राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति का पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के साथ सावजनिक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े जबकि उसने शुरू में कांग्रेस को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था और इसे ध्वस्त करने की भरपूर कोशिश की थी। शुरू शुरू में इस बात से जनता में खुशी और विजय की भावना काफी फैली। केवल वे लोग इन चीजों से प्रभावित नहीं हों सके जो राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक थे और जिनका ख्याल था कि इस समझौते से अब तक के सारे सघप और अब तक की सारी कुर्बानियों को व्यर्थ कर दिया गया है। समझौते की शर्तों का अर्थ बहुत धीरे धीरे लोग समझ सके और उन्होंने महसूस किया कि देश को कुछ भी नहीं मिला है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में काफी जोर शोर से घोषणा की गई थी कि कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण-स्वराज की प्राप्ति है और इस सिलसिले में साम्राज्यवाद के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा लेकिन ये सारी बातें भुला दी गईं। यहाँ तक कि गांधी ने कांग्रेस की पीछे पीछे समझौते की जो 11 शर्तें रखी थी उन सबका भी अब कहीं नामो-निशान नहीं था, उनमें से एक भी शर्त नहीं मानी गई थी। कांग्रेस की हालत अब यह हो गई थी कि जिस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का उसने फैसला किया था, अब वह उसी में भाग लेने जा रही थी जबकि यह काम बिना सघप चलाए भी वह कर सकती थी (बेशक यदि शुरू में वह चाहती तो उसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजन का अधिकार मिल सकता था)।

इस प्रकार इतिहास गांधी समझौते के जरिए बारदोली के अनुभव का ही और बड़े पैमाने पर दोहराया गया। एक बार फिर आंदोलन का बड़े रहस्यमय ढंग से अचानक ठीक उस समय रोक दिया गया जब वह अपने शिखर पर पहुँच रहा था ('यह कहना सरासर झूठ है कि हमारा आंदोलन ध्वस्त होने वाला था, आंदोलन धीमा पड़ने का कोई भी संकेत दिखाई नहीं देता था'—समझौते के अवसर पर भारत की स्थिति के बारे में मोद की



जनता के व्यापक आंदोलन के बीच जो घातक दरार पैदा हो गई थी उसकी अभिव्यक्ति कराची अधिवेशन में ही हो चुकी थी। सुभाषचंद्र बोस ने लिखा है कि समझौते के विराधियों को चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समयन प्राप्त होता और कांग्रेस के अधिवेशन में केवल चुने हुए प्रतिनिधि मतदान में हिस्सा ले सकते थे लेकिन आम जनता में और घासकर नौजवानों में काफी बड़ी संख्या में लागू उनके साथ थे' ('दि इंडियन स्ट्रगल', पृष्ठ 233)। कांग्रेस के भीतर इन 'समयको' की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था। कराची अधिवेशन में वामपंथी राष्ट्रवादिता के ध्वस्त होने की घटना से गांधी की मजबूत स्थिति का पता चलता है।

बढ़ने में एक प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार करके वामपंथी राष्ट्रवादियों को रियायत दी गई। यह कार्यक्रम मूल अधिकार' वाले प्रस्ताव के रूप में था। उसमें काफी आधुनिक किस्म की मूल जनवादी मांगों की सूची थी जिसमें प्रमुख उद्योगों और यातायात का राष्ट्रीयकरण, मजदूरों के अधिकार और कृषिव्यवस्था में सुधार की मांगें शामिल थी। यह कार्यक्रम, जिसे कांग्रेस आज भी मानती है, स्वीकार करके कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। फिर भी इंदिरा-गांधी समझौते के फलस्वरूप आत्मसमर्पण से देश को जो नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति इस कार्यक्रम से नहीं हो सकती थी।

कांग्रेस के बाहर युवक और मजदूरवर्ग के आंदोलन ने समझौते की तीखी आलोचना की। इसकी अभिव्यक्ति युवक संगठनों और सम्मेलनों के अनेक प्रस्तावों में हुई है और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के अवसर पर गांधी के खिलाफ बर्बाद में मजदूरों ने जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे उनसे भी पता चलता है कि समझौते के बारे में इन लोगों की क्या राय थी। 'दि टाइम्स' समाचारपत्र ने लिखा कि 10 वर्ष पहले इस तरह के प्रदर्शनों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।

बड़ी तेजी से और लोगों के भ्रम भी टूटने लगे। 1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में (और उच्च आध्यात्मिक विचारों वाले भक्ता की उन अनेक सभाओं में जो गोलमेज सम्मेलन की बैठकों से फुरसत पाने पर जगद्गुरु गांधी का सदेश सुनने के लिए हुआ करती थी) गांधी की क्या भूमिका रही यह यदि उदघाटित न किया जाए तभी अच्छा है। पुराने जमाने में जिस तरह रोम के सम्राट अपने देश की जनता को दिखाने के लिए विदेशों के केंद्रों को पकड़कर मगवाया करते थे उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के मन्त्रियों के मातृजन के लिए भारत से तरह तरह की सरकारी वस्तुतः मगवाकर लंदन में झंझट पैदा की गई थी और वे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी मूछना और फूट का प्रदर्शन कर रही थी। गांधी राम्ने में मुमोलिनी में मिलते हुए भारत लौट आए। गोलमेज सम्मेलन का उ- कोई लाभ नहीं मिला। वापस लौटने में मग गांधी ने राम्ने में यह आगा प्त गी कि जय मगप फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। पाट गई ने



गांधी से भेंटवार्ता, 20 फरवरी 1932)। 5 मार्च को 'दि टाइम्स' ने लिखा कि 'इस तरह की जीत शायद ही किसी वायसरॉय को पहले कभी मिली हो।' 5 मार्च को विस्मय से भरे पत्रकारों के बीच गांधी ने समझौते का औचित्य साबित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विजय के लिए कभी कोशिश ही नहीं की थी' (गांधी स्पेचिज ऐंड राइटिंग', पृष्ठ 778)। इस प्रकार गांधी ने निश्चय ही अपनी रणनीति की अस्तित्व को जाहिर कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने विचारों की ओर भी व्याख्या की। जून 1931 में उन्होंने अपने पत्र 'यंग इंडिया' में लिखा कि 'फिलहाल हमें स्वराज का विधान प्राप्त करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हम राजनीतिक सत्ता पाए बिना भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।' 6 मार्च को उन्होंने सवाददाताओं के साथ एक बातचीत में कहा था कि पूर्ण स्वराज का असली अर्थ 'आंतरिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण' है और किसी भी रूप में इसका अर्थ यह नहीं है कि 'इंग्लैंड के साथ संबंध न रखा जाए' ('संबंध रखना' की बात भी कितनी दिलचस्प है—खास तौर से जब इसका अर्थ तेज नौकवाली सगीन के साथ 'संबंध रखना' है)। इस प्रकार एक तरफ मकडोनल्ड ने और दूसरी तरफ गांधी ने शब्दों का आडंबर फैलाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें आजादी जैसे सरल शब्द का अर्थ भी गड़बड़ा गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आजादी के उद्देश्य का बड़े साफ शब्दों में परिभाषित किया गया था ('ब्रिटिश प्रभुत्व और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वाधीनता') लेकिन इन दोनों सतों ने इस सीधी सी बात को कानूनी व्याख्याओं और धार्मिक सूत्रों के शब्दाडंबर से इस तरह ढक दिया कि यह कहना भी मुश्किल हो गया कि बाजी किसने हाथ रखी, मकडोनल्ड के या गांधी के। ये दोनों व्यक्ति गुलामी और आत्म समर्पण की कठोर वास्तविकता पर आध्यात्मिक और चौकाने वाले शब्दाडंबरों का पर्दा डालने की कला में बहुत माहिर थे।

उसी महीने जल्दी जल्दी कांग्रेस का कराची अधिवेशन कर इस समझौते को सबसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। अधिवेशन के सामने समझौते को पेश करने का काम जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था और उन्हें यह काम करने में 'क्या भी मानसिक सघर्ष और शारीरिक कष्ट का अनुभव करना पड़ा था।' वह बार बार यह सोच रहे थे कि क्या इसी के लिए हमारे देश के लोग ने इतनी बहादुरी के साथ सघर्ष किया था? क्या हमारी तमाम वीरतापूर्ण बातें और कामों का यही नतीजा होना था? फिर भी उन्होंने यह महसूस किया कि समझौते से अपनी असहमति प्रकट करना व्यक्तिगत दम' का परिचय देना होगा। सुभाषचंद्र बोस ने समझौते की बड़ी आलोचना की थी लेकिन उन्हें लगा कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध करना संभव नहीं है क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता भंग होने का खतरा हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह समझौता 'लोकप्रिय' नहीं था। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में बहुत कम आवाजें उसने धिलाफ उठीं। एक प्रतिनिधि ने कहा कि यदि गांधी जी के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का समझौता हमारे सामने पेश करता तो हम लोग उस उठाकर समुद्र में फेंक देते। लेकिन चुन अधि- यचना में इस तरह का विचार अपवादात्मक ही आते हैं। कांग्रेस के अनन्य तत्व और

जनता के व्यापक आंदोलन के बीच जो घातक दरार पैदा हो गई थी उसकी अभिव्यक्ति कराची अधिवेशन में ही हो चुकी थी। सुभाषचंद्र बोस ने लिखा है कि समझौते के विरोधियों को 'चुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समयन प्राप्त होता और कांग्रेस के अधिवेशन में केवल चुने हुए प्रतिनिधि मतदान में हिस्सा ले सकते थे लेकिन आम जनता में और खामखोर नौजवानों में काफी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ थे' ('दि इंडियन स्ट्रगल', पृष्ठ 233)। कांग्रेस के भीतर इन 'समयकों' की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था। कराची अधिवेशन में वामपंथी राष्ट्रवादिता के ध्वस्त होने की घटना से गांधी की मजबूत स्थिति का पता चलता है।

बदले में एक प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार करके वामपंथी राष्ट्रवादियों को रियायत दी गई। यह कार्यक्रम 'मूल अधिकार' वाले प्रस्ताव के रूप में था। उसमें काफी आधुनिक किस्म की मूल जनवादी मांगों की सूची थी जिसमें प्रमुख उद्योग और यातायात का राष्ट्रीयकरण, मजदूरों के अधिकार और कृषिव्यवस्था में सुधार की मांगें शामिल थी। यह कार्यक्रम, जिसे कांग्रेस आज भी मानती है, स्वीकार करके कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। फिर भी इंदिरा-गांधी समझौते के फलस्वरूप आत्मसमर्पण से देश को जो नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति इस कार्यक्रम से नहीं हो सकती थी।

कांग्रेस के बाहर युवका और मजदूरवर्ग के आंदोलन ने समझौते की तीखी आलोचना की। इसकी अभिव्यक्ति युवक संगठनों और सम्मेलनों के अनेक प्रस्तावों में हुई है और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के अवसर पर गांधी के खिलाफ बर्बाद मजदूरों ने जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे उनसे भी पता चलता है कि समझौते के बारे में इन लोगों की क्या राय थी। 'दि टाइम्स' समाचारपत्र ने लिखा कि 10 वष पहले इस तरह के प्रदर्शनों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था।

बड़ी तेजी से और लोगों के भ्रम भी टूटने लगे। 1931 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में (और उच्च आध्यात्मिक विचारों वाले भक्तों की उन अनेक सभाओं में जो गोलमेज सम्मेलन की बैठकों से फुरसत पाने पर जगद्गुरु गांधी का सदेश सुनने के लिए हुआ करती थी) गांधी की क्या भूमिका रही यह यदि उद्घाटित न किया जाए तभी अच्छा है। पुराने जमाने में जिस तरह रोम के सम्राट अपने देश की जनता को दिखाने के लिए विश्व से कैदियों को पकड़कर मगवाया करते थे उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों के मनोरंजन के लिए भारत से तरह-तरह की सरकारी कठपुतलियां मगवाकर लंदन में झुंटा की गई थी और वे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी मूर्खता और फूट का प्रदर्शन कर रही थी। गांधी रास्ते में मुसोलिनी से मिलते हुए भारत लौट आए। गोलमेज सम्मेलन का उह कोई लाभ नहीं मिला। वापस लौटते समय गांधी ने रास्ते में यह आशा व्यक्त की कि अब सघर्ष फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोट्सडैम में

उन्होंने इंडिया आफि<sup>र</sup> को तार भेजा कि जहाँ तक संभव हो सकेगा वह शांति वायम रखने का प्रयत्न करेंगे। भारत पहुँचते ही उन्होंने फौरन ही इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार कर डाला। वे<sup>कन</sup> उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ब्रिटिश सरकार कुछ और ही सोच रही थी।

कोडे का हत्या अव<sup>र</sup> ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथ में था और उसने इस परिस्थिति का अधिकतम लाभ उठा<sup>ने का फैसला किया। जो</sup> समझौता' हुआ था वह गुरु से ही एक-तरफा था, दमन बर<sup>विर जारी रहा। 1931 के अंतिम दिना</sup> म जब गांधी स्वदेश वापस आए तो अपने सहयो<sup>गिया से उन्होंने एक ददभरी कहानी सुनी। उन्होंने फौरन ही वाय</sup> सराय को तार भेजकर यह निवेदन किया कि उन्हें मिला का मौका दिया जाए। वायसराय ने उनसे मिलने से इश्वा<sup>र कर दिया। समझौते के बाद के 9 महीने के प्रत्येक दिन का साम्राज्य</sup> तमाल किया था (और इस बीच लंदन में एक प्रहसन का भी आयोजन कर डाला था)। इ<sup>म 9 महीने की तैयारी में अंगरेजों ने एक निष्पक्षिक युद्ध की योजना</sup> बनाई थी। इसके फ<sup>ए सर जान एडरसन को जिन्होंने आयरलैंड में क्रूर दमन करने में</sup> ल की थी खास तौर पर बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। इस काफी शौहरत हासि<sup>रह तैयार बैठी थी। उसने कांग्रेस का सबक सिखाने की मोच ली थी।</sup> वार सरकार पूरी त<sup>कि इस बार की लड़ाई में फैसला हा जाना है और जब तक कांग्रेस</sup> उसने तय किया था<sup>वना शत आत्मसमर्पण नहीं कर दगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी।</sup> सरकार के सामने

4 जनवरी 1932 को अंगरेजों ने अचानक बहुत जबरदस्त आक्रमण किया। उसी दिन समझौते की बातें<sup>नग कर दी गई। वायसराय ने अपना एक घोषणापत्र जारी किया और</sup> गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक साथ ही कई अध्यादेश जारी कर दिए गए (1930 की तरह<sup>इस बार एक एक करके अध्यादेश नहीं जारी किए गए बल्कि पहले ही</sup> पटार से निकालकर ढेर सारे अध्यादेश लागू कर दिए गए)। दश भर दिन मानो किसी<sup>इसी नेताओं और संगठनकर्तारों का गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस</sup> में सभी प्रमुख कार्यकर्ता भी संगठन का गैरबानूनी घोषित कर दिया गया उनके अध्यक्ष बद<sup>पाटी और उसके</sup> पार्टी और उसके अध्यक्षों पर बर्बाद कर लिया गया और उनका स्पर्धा पैसा तथा हर<sup>कर दिए गए। उ</sup> कर दी गई। यह संगठन की विजय थी।

सरकार ने यह वा<sup>न स्पष्ट कर दी कि इस बार का हमला का उद्देश्य कांग्रेस को पूरी तरह</sup> ध्वस्त करना है। सरसम्मूजल हार न हाउस आफ कामंस में बताया कि अध्यादेश 'बहुत<sup>स्त है' और दस बार लड़ाई</sup> बठोर और जबर<sup>तारक गृहमंत्री सर हरी जंग ने कहा हम नया नियम त जापान पर</sup> होगी। भारत में<sup>ही उतरे हैं।' और जहाँ तक सरकार का मंत्र है</sup> खेल के मैदान में<sup>मा नहीं। बरफ सरकार का प्रस्ताव न प्रांतीय विधायकता में यह बड़ा</sup> समय की कोई स<sup>कर लड़ाई नहीं लगे जाना।</sup> नि 'मस्तान पटन

कांग्रेसी नेता इस आक्रमण से हतप्रभ रह गए। वे यह समझ ही नहीं सके कि गोल्डमेज सम्मेलन का माहौल वहाँ गायब हो गया। उन्होंने इस लड़ाई की कोई तैयारी नहीं की थी। 1930 में कांग्रेस आक्रामक की स्थिति में थी। लेकिन इस बार उसे सुरक्षात्मक स्थिति की ओर धकेल दिया गया था। कांग्रेसी नेताओं ने नहीं समझा था कि इविन गांधी समझौते की उह क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य डा० संयद महमूद ने इंडिया लीग के प्रतिनिधिमंडल को बताया

दुनिया को उस प्रस्ताव के बारे में कुछ भी नहीं पता है जो महात्मा गांधी ने तैयार किया था और कार्यसमिति के मामले पेश किया था। महात्मा गांधी सहयोग करने पर आमादा थे सरकार सहयोग नहीं चाहती थी। जदरुनी बातों की अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि कांग्रेस संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी। हमें यह आशा थी कि लंदन से लौटने पर महात्मा जी किसी तरह शांति कायम कर लेंगे। (इंडिया लीग डेलीगेशन की रिपोर्ट, 'कडीशन आफ इंडिया', 1933, पृष्ठ 27)

उन्होंने आगे यह भी कहा कि 'उन्हें और उनके सहयोगियों को निश्चित रूप से यह जानकारी है कि सरकार ने दमन की तैयारी नवंबर में ही कर ली थी जब गांधी जी लंदन में थे। सरकार के इस अचानक हमले ने कांग्रेस को लड़खड़ा दिया।'

इस बार 1932-33 में जो दमन हुआ, वह 1930-31 के दमन से कहीं ज्यादा जबरदस्त था। 2 मई 1932 को पंडित मालवीय ने एक सावजनिक रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार पहले चार महीनों में 80,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1933 में कांग्रेस के गैर-कानूनी ढंग से आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में पेश की गई इस रिपोर्ट के अनुसार पंद्रह महीनों बाद अर्थात् मार्च 1933 के अंत तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 1,20,000 तक पहुंच गई थी। 1933 में प्रकाशित 'कडीशन आफ इंडिया' शीपक से इंडिया लीग के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन गिरफ्तारियों के साथ साथ सरकार की ओर से कितने बड़े पैमाने पर हिंसा की गई, लोगों को कितनी शारीरिक यातनाएं दी गईं, किस तरह उनपर गोलीया चलाई गईं, गांधी और शहरा पर पुलिस ने किस तरह हमले किए, सामूहिक जुमले किए और गांव वालों की जमीन जबरदस्ती जब्त कर ली।

सरकार ने अनुमान लगाया था कि छह हफ्ते में लड़ाई का निपटारा हो जाएगा लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन इतना शक्तिशाली निकला कि प्रतिबल परिस्थितियों के बावजूद 29 महीनों तक लड़ाई चलती रही और इसके बाद ही कांग्रेस ने अंतिम रूप से आत्मसमर्पण किया। फिर भी यह लड़ाई केवल सैनिकों ने लड़ी थी जिनको सेनापतियों का नेतृत्व नहीं प्राप्त था। स्थितियां ऐसी थी जिनमें मारा नाम गैरकानूनी ढंग से करना पड़ता था और जबरदस्ती दमनचक्र चल रहा था। ऐसी अवस्था में आंदोलन का नेतृत्व करना काफी

कठिन काम था। लेकिन गांधी और कांग्रेस हाई कमान ने इस काम को और आसान नहीं किया। उनके सारे काम ऐसे थे जिनसे पता चलता था कि गांधी और हाई कमान नेतृत्व की जिम्मेदारी से न केवल बच रहे थे बल्कि उसे अस्वीकार भी कर रहे थे। उनकी ओर से गोपनीयता के विरुद्ध आदेश जारी कर दिए गए (जबकि कांग्रेस गैरकानूनी घोषित की जा चुकी थी) क्योंकि यह कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ था। जमींदारों को एक प्रस्ताव द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके हितों के खिलाफ किसी आंदोलन को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। 1932 को गरमियों तक गांधी ने राष्ट्रीय संघ में दिलचस्पी लेना बिल्कुल बंद कर दिया और सारा समय हरिजनता के हितों के लिए काम करने लगे। सितंबर में उन्होंने नाटकीय 'आमरण अनशन' किया था। यह दमन के विरुद्ध न था और न ही यह अनशन जिदगी और मौत की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह लगा हुआ था। इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि विधानसभाओं में 'दलित वर्गों' के प्रतिनिधियों को अलग से निर्वाचित करने की योजना को रोका जाए। अनशन समाप्त हो गया, वह न तो आमरण हुआ और न ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ, बल्कि पूना का समझौता हो जाने पर अनशन समाप्त किया गया। इस समझौते के द्वारा 'दलित जातियों' के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या दुगुनी कर दी गई। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन से हट गया जिसके नेता अब भी गांधी ही समझे जाते थे।

मई 1933 में गांधी ने एक नया अनशन शुरू किया। यह अनशन भी सरकार के खिलाफ नहीं था बल्कि इसका उद्देश्य देशवासियों का हृदय परिवर्तन करना था। गांधी ने अपने इस अनशन के बारे में बताया कि 'इस व्रत का उद्देश्य मेरी अपनी और मेरे सहयोगियों की आत्मशुद्धि करना है ताकि हम लोग हरजिन उद्धार के लिए और अधिक सतक हो जाए।' इस वक्तव्य पर सरकार काफी प्रसन्न हुई और उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया ताकि यह सत पुरुष अपना शुभ कार्य कर सकें। इसके फौरन बाद ही गांधी की सहमति से कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने छह हफ्तों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी के शब्दों में वह तो आंदोलन इसलिए नहीं बंद किया गया था कि सरकार ने कांग्रेस की कोई शर्त मान ली थी या इसकी कोई आशा पैदा हो गई थी बल्कि इसलिए बंद किया गया था कि जब तक उनका अनशन जारी रहेगा तब तक देश 'भयंकर रूप से बेचैनी की स्थिति' में रहेगा और इसलिए इस अवधि में आंदोलन रोक देना ही बेहतर होगा (भले ही सरकार अपना दमनचक्र न रोके)।<sup>15</sup>

जुलाई 1932 में गांधी ने वायसराय से मिलने का अनुरोध किया पर उनका यह अनुरोध नामजूर कर दिया गया। वायसराय ने कहा कि जब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम तौर पर समाप्त नहीं कर लिया जाता, वह नहीं मिल सकते। कांग्रेस के नेताओं ने फंसना किया कि सामूहिक आंदोलन समाप्त करके व्यक्तिगत तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। इसने साथ ही कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्षों के सभी सगठन

को भग कर दिया। सरकार ने इस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वह यही थी कि व्यक्तिगत सत्याग्रहियों पर दमन और तेज कर दिया गया। अगस्त में गांधी फिर गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और एक महीने के अंदर ही उन्हें रिहा कर दिया गया। शरद में उन्होंने घोषणा की कि अब वह राजनीति में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उनकी अंतरात्मा को अब यह गवारा नहीं है। उन्होंने हरिजनो के उद्धार के लिए यात्रा शुरू की। इस बीच आंदोलन घिसटता रहा, न तो वह समाप्त हो हुआ और न उसका नतुत्व ही मिल सका।

यह आंदोलन मई 1934 में जाकर समाप्त हुआ जो 1930 में बड़ी शान के साथ शुरू हुआ था। अप्रैल के महीने में गांधी ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने आंदोलन की विफलता के कारणों के बारे में अपनी राय जाहिर की थी। उनके विचार से आंदोलन की विफलता का सारा दोष जनता पर था। 'मेरे विचार से जनता अभी तक सत्याग्रह का संदेश ग्रहण नहीं कर पाई है क्योंकि यह जनता तक पहुंचने पहुंचत अशुद्ध हो जाता है। मेरे लिए अब यह बात साफ हो गई है कि आध्यात्मिक अन्तों के इस्तेमाल का तरीका जब गरबाध्यात्मिक माध्यमों से बताया जाता है जो वे अपनी ताकत खो बैठते हैं तमाम लोगों के निष्क्रिय सत्याग्रह से शासकों का हृदय नहीं पसीजा है।' जन सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का तरीका अपना लेने के बावजूद जनआंदोलन को नियंत्रण में रखने की समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसलिए अकाद्यों तकपद्धति के आधार पर यह नतीजा निवाला गया कि 'एक समय में केवल एक ही योग्य व्यक्ति को सत्याग्रह करना चाहिए।' 'वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल मुझे ही सत्याग्रह की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।' गांधीवादी सिद्धांत ने भारतीय जनता की मुक्ति के लिए 'अहिंसक असहयोग' का जो रास्ता निर्धारित किया था, उसका अंत में जाकर यही असंगत प्रदर्शन रहा।

मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पटना में अपना अधिवेशन करने दिया गया ताकि वह बिना शर्त सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दे (गांधी द्वारा सुझाए गए एकमात्र अपवाद को छोड़कर)। सरकार ने न तो कोई शर्त रखी थी और न कोई रियायत दी थी। इसके साथ साथ कमेटी ने आने वाले चुनावों को सीधे कांग्रेस के नाम पर लड़ने के लिए कुछ फैसले भी ले लिए थे। इसके लिए पहले से ही जमीन तैयार कर ली गई थी।

जून 1934 में सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया पर कांग्रेस की सहयोगी नस्लियों युवक संगठना, किसान सभाओं और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत (मरहूदी सूबा) के ताल बुर्तीधारियों के संगठनों (खुदाई खिदमतगारों) पर प्रतिबंध बना रहा। जुलाई 1934 में सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गैरकानूनी करार दिया। अब सचप का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था।



## पाद टिप्पणियाँ

- 1 ब्रिटिश सत्ताशा के प्रति इन पुराने कांग्रेसी नेताओं की प्रचुर प्रशंसा भरे दृष्टि की बिड़बना पर भी गौर किया जाना चाहिए। सुरप्रताप बनर्जी ने ही 1892 के कांग्रेस अधिवेशन में एलान किया था हम एक विशाल और स्वतंत्र साम्राज्य के नागरिक हैं और हम एक ऐसे उदात्त संविधान की छत्रछाया में पल रहे हैं जसा विश्व में पहले कभी न था। अंगरेजों के अधिकार हमारे अधिकार हैं उनके विशेषाधिकार हमारे विशेषाधिकार हैं उनका संविधान हमारा संविधान है। लेकिन हमें उनसे बहिष्कृत किया गया है।
- 2 बाद में बंबई के तत्कालीन गवर्नर लार्ड लायट ने एक भेंट वार्ता में 1922 के सफ़र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बताया। उन्होंने सरकार के इस दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति की कि गांधी द्वारा आंदोलन वापस ले लिए जाने से ही सरकार बच सके। उन्होंने हमारे प्रदर दहशत फैला दी। उनके कार्यक्रम ने हमारी जेलें भर दी। आप लगातार लोगों को गिरफ्तार करते हो जाए यह नहीं हो सकता और घास तौर से तब जब लोगों की तादात 31 करोड़ 90 लाख हो। अगर लोग उनके अगले कार्यक्रम पर अमल करना शुरू कर देते और टक्स देना बंद कर देते तो भगवान ही जानता है कि हमारी क्या हालत होती। विश्व इतिहास में गांधी का प्रयोग अत्यंत विराट था और इसे सफलता पाने में इस भर की देर थी। लेकिन वह लागा के उत्साह पर बाबू नहीं पा सका। लाग उग्र हो उठे और उन्होंने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया। बाद का किस्सा आपको पता ही है, हमने उन्हें जेल में डाल दिया। (डिप्टी कमिशनर के साथ लार्ड लायट की भेंटवार्ता जिस सी० एफ० एड्जुज ने 3 अप्रैल 1939 के 'यू रिपब्लिक' में उद्धृत किया है।)
- 3 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का गांधी का उद्देश्य यह था कि हिंसक भाँति की पहले से ही रोकथाम कर दी जाए और अपने इस उद्देश्य को उन्होंने अपने वक्तव्यों और पत्रों में स्पष्ट कर दिया था। उनके लिप्य सी० एफ० एड्जुज ने ही लिखा है उनके पत्र मुझे मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण बताए हैं, और उन्होंने समाचारपत्रों में उन बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला है जिनके कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े जो ऊपर से देखने पर हताशा में उठाए गए कदम लगते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुझे लिखा कि भारत सरकार अपनी दमनकारी नीति के जरिए निर्दोष हिंसा बढ़ाती जा रही है और इसकी सीधी प्रतिक्रिया—घासतौर से 'मग इंडिया' में व्यक्त हुई। इस तरह की स्थिति से निबटने का एकमात्र तरीका यह था कि अहिंसामय आंदोलन बलावर इसकी रोकथाम की जाए और इस काम की अनुवार्दी यह स्वर्ण करते हैं, चाहे इसमें कितना भी खर्च क्यों न हो। (स्पेक्टर में सी० एफ० एड्जुज का लेख, 27 सितंबर 1930)
- 4 14 जुलाई 1930 की विधानसभा में सरकारी तौर पर लिए गए एक प्रश्नोत्तर में बताया गया कि 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक गोलीबारी की 24 घटनाएँ हुई। इनमें 103 लोग मारे गए और 420 घायल हुए।
- 5 इस संज्ञके से जनरल प्रहार के कारण ही मुभाषचंद्र बाल और सी० एम्स न जा उस समय भारत से बाहर थे एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि 'गांधी न सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का जो ताजा कथन उठाया है कि वे असफल हो चुके हैं—हमारी यह स्पष्ट राय है कि गान्धेजी के रूप में गांधी असफल हो चुके हैं। अब वह समय आ गया है जब एक नए सिद्धांत और नई कामगारों के आधार पर कार्यक्रम का आमूल पुनर्गठन किया जाए और इसके लिए एक नए नेतृत्व का होना आवश्यक है।



1934 के शरद में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उनका काम फिलहाल पूरा हो चुका था। कांग्रेस से अलग होते हुए उन्होंने एक दस्तावेज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि, 'मुझमें और अनेक कांग्रेसियों में मतभेद है और वह बढ़ता ही जा रहा है।' यह स्पष्ट था कि 'कांग्रेसियों के बहुमत' के लिए 'अहिंसा' कोई 'बुनियादी धर्म' नहीं था बल्कि यह एक 'नीति' थी। कांग्रेस में समाजवादी लोगों की संख्या बढ़ रही थी और उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। 'यदि कांग्रेस में उनका प्रभुत्व कायम हो गया जिसकी काफी संभावना है तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता।' यह नया चरण महसूस किया जा रहा था और पुराने विचारों के लोगों को यह पसंद नहीं था। गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी लेकिन वह उससे तब तक अलग नहीं हुए जब तक उन्होंने कांग्रेस के संविधान एवं समूह में कुछ प्रतिक्रियावादी संशोधन नहीं करा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रगतिशील दिशा में कांग्रेस के बढ़ने में काफी दिक्कतें आईं। अब वे पर्व के पीछे रहकर कांग्रेस के अत्यंत शक्तिशाली पथप्रदर्शक बन गए और इस बात के लिए तैयार बैठे रहे कि जरूरत पड़ने पर फिर से कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लें। 1939-40 के संकट में और फिर 1942 में उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व सीधे अपने हाथ में ले लिया।

1930-34 में संघर्ष की जो महान लहर उठी थी, उसके दुःखद अंत में हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इस आंदोलन की महान उपलब्धियां रही, इसने अत्यंत गंभीर और स्थाई महत्व के सबक दिए तथा इसके महान लाभ प्राप्त हुए। इस आंदोलन के पीछे जनता की असीम श्रद्धा, निष्ठा, त्याग और समर्थन था और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आंदोलन सफलता के काफी करीब तक पहुंच गया था लेकिन इसे अस्थायी तौर पर विफलता मिली। हम यह खोज करनी चाहिए कि नेताओं के किन तरीकों और उनकी किन कायपद्धतियों के कारण यह असफल हो गया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है जिसका हमें बार-बार अध्ययन करना चाहिए ताकि भविष्य में हम उन खामियों को दूर कर सकें। असफलता के कारणों का हम इस अध्याय में वर्णन कर चुके हैं। लेकिन उन वर्षों में जो घटनाएं घटित हुईं, उनपर राष्ट्रीय आंदोलन गति कर सकता है। साम्राज्यवादियों ने इन वर्षों में दमन के अपने आधुनिक शस्त्रागार के प्रत्येक शस्त्र का इस्तेमाल किया ताकि भारत की जनता को वह अपनी मर्जी के आगे झुका ले, उनकी कुचलकर रख दें और आजादी की उनकी लड़ाई को मटियापेट कर दें लेकिन वह इस काम में विफल रहा। साम्राज्यवादियों के जबरदस्त दमन के बावजूद दो वर्षों के अंदर ही राष्ट्रीय आंदोलन पहले से भी ज्यादा तीव्र वेग से आगे बढ़ चला। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। संघर्ष की भट्टी में तपकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव और सकल्प को जन्म दिया। आज के ही संघर्ष फल दे रहे हैं। अंतिम संघर्ष आज भी सामने है। लेकिन आज इस संघर्ष के लिए पहले से नहीं अधिक जबरदस्त तयारी है।

## पाद टिप्पणियां

- 1 ब्रिटिश सत्त्वावा के प्रति इन पुराने मायसा नताओं का प्रचुर प्रशंसा भरे दृष्टि का बिड़बना पर भी गौर किया जाना चाहिए। मुस्लिम बजरों ने ही 1892 के कांग्रेस अधिवेशन में एतान किया था हम एक विशाल और स्वतंत्र साम्राज्य के नागरिक हैं और हम एक ऐसे उदात्त संविधान की छत्रछाया में चल रहे हैं जसा विश्व में पहले कभी न था। मगरेजा के अधिकार हमारे अधिकार हैं उनके विशेषाधिकार हमारे विशेषाधिकार हैं, उनका संविधान हमारा संविधान है। लेकिन हम उनसे बहिष्कृत किया गया है।
- 2 बाद में बंबई के तत्कालीन गवर्नर लार्ड सायड ने एक भेंट वार्ता में 1922 के संकट के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बताया। उन्होंने सरकार के इस दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति की कि गांधी द्वारा आंदोलन वापस ले लिए जाने से ही सरकार बच सगी। उन्होंने हमारे भ्रम दूर कर फेंका दी। उनके कार्यक्रम ने हमारी जेलें भर दी। आप लगातार लोगों को गिरफ्तार करते जा आए यह नहीं हो सकता और घास तीर से तब जब लोगों की तादात 31 करोड़ 90 लाख हो। अगर लोग उनका अगले कार्यक्रम पर अमल करना शुरू कर देते और टक्का देना बंद कर देते तो भगवान ही जानता है कि हमारी क्या हासत होती। विश्व इतिहास में गांधी का प्रयोग अत्यंत विराट या और इसे सफलता पान में इंच भर की देर थी। लेकिन वह लोग का उत्साह पर काम नहीं पा सके। साथ उग्र हो उठे और उन्होंने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया। बाद का निस्सा आपकी पता ही है हमने उन्हें जल में डाल दिया। (डिप्टी कमिशनर के साथ साईं सायड की भेंटवार्ता जिसे सी० एफ० एड्जुज ने 3 अप्रैल 1939 के 'न्यू रिपब्लिक' में उद्धृत किया है।)
- 3 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का गांधी का उद्देश्य यह था कि हिंसक नीति की पहले से ही रोकथाम कर दी जाए और अपने इस उद्देश्य को उन्होंने अपने वक्तव्यों और पत्रों में स्पष्ट कर दिया था। उनके लिख्य सी० एफ० एड्जुज ने ही लिखा है उनके पत्र मुझे मिले हैं जिनमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण बताए हैं, और उन्होंने समाचारपत्रों में उन बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला है जिनका कारण उन्हें एक बंदम उठाने पडे जो ऊपर से देखने पर हताशा में उठाए गए लगने हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुझे लिखा कि भारत सरकार अपनी दमनकारी नीति के जटिल निर्यादिन हिंसा बढ़ाता जा रहा है और इसकी तीव्र प्रतिक्रिया—घासतीर से 'थग इंडिया' में व्यक्त हुई। इन तरह की स्थिति से निबटने का एकमात्र तरीका यह था कि अहिंसक आंदोलन चलाने इतनी रोकथाम की जाए और इस काम की भगुवाई वह स्वयं करते हैं, चाहे इसमें कितना भी खतरा क्यों न हो। ('एक्स्ट्र' में सी० एफ० एड्जुज का पृष्ठ 27 सितंबर 1930)
- 4 14 जुलाई 1930 को विधानसभा में सरकारों तौर पर लिए गए एक प्रस्ताव में बताया गया कि 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक गोलीबारी की 24 घटनाएं हुईं। इनमें 103 लोग मारे गए और 420 घायल हुए।
- 5 इस संकेत के अवरणन प्रहार के कारण ही गुमावजन बोम और बी० पटन ने जो उस समय भारत में बाहर थे, एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि 'गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का जो ठाका बंदम उठाया है कि वे असफल हो चुके हैं—हमारी यह स्पष्ट राय है कि आंदोलन के रूप में गांधी असफल हो चुके हैं। अब यह समय आ गया है जब एक नए विद्रोह और नई वादवर्द्धि के आधार पर बाइबल का आख्यान पुनर्पुन किया जाए और इसके लिए एक नए मनुष्य का होना आवश्यक है।

## मजदूरवर्ग का उदय और समाजवाद

भारतीय मजदूरवर्ग अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वह वर्ग चेतना से पूर्ण और राजनीतिक जनसंघ बन सकता है, और ऐसी स्थिति होने के कारण भारत में आगल रूसी पद्धतियाँ पुरानी पड़ चुकी हैं। (1908 में लेनिन का कथन)

37 वर्ष पूर्व यह सम्भव था कि ब्रिटेन के मजदूरवर्ग को संगठित करके और उनमें राजनीतिक चेतना का संचार करने में समाजवाद के पक्षधर जिन ब्रिटिश नेताओं ने अग्रगामी का कार्य किया और जिन्होंने भारतीय जनता के मित्र तथा ब्रिटिश शासन के आलोचक के रूप में भारत की यात्रा की, वे भारत से लौटने पर भारत के बारे में ऐसी पुस्तक लिखें जिसमें भारतीय मजदूरवर्ग का न तो वही उल्लेख हो और न इस बात की ही किसी संभावना का अंदाजा लगाया गया हो कि भविष्य में यहाँ किसी मजदूर आंदोलन का अस्तित्व हो सकता है (कैर हार्डी इंडिया इंप्रेशंस एंड सजेशंस, 1909 में प्रकाशित)। इसी प्रकार 1910 में प्रकाशित मैकडोनाल्ड की पुस्तक 'दि अवैकैनिंग आफ इंडिया' में हम केवल एक स्थल ऐसा मिलता है जहाँ यह अटकल लगाई गई है कि भविष्य में कभी भारत का मजदूरवर्ग किसी तरह का मजदूर संगठन बना सकता है 'यें संगठन संभवतः भारत की जातिघो और ग्रेट ब्रिटेन के मजदूर संघों के बीच होंगे।' (पृष्ठ 179)

भारतीय घटनाओं के विकासक्रम की अध्यापन जानबूझकर नहीं था। उस समय केवल यही देख सकते उनके महत्व को समझ सकते थे

भावी निर्णायक  
जो वास्तविक  
एक मार्गदर्शक  
सही।

प्रति यह संकीर्ण  
पड़ी थी उन्हें  
के लिए  
'के उदय

का स्वागत किया था और कहा था कि यह वग अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वह वगचेतना से पूर्ण और राजनीतिक जनसंघप छेड़ सकता है। लेनिन के इस कथन का आधार बर्बई के मिल मजदूरों की वह राजनीतिक हड़ताल थी जो उन्होंने उस वप तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में की थी। इस हड़ताल के ही आधार पर लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दिन अब लड़ चुके हैं।

आज घटनाओं के वेग ने लेनिन की इस अतद्दृष्टि को सही साबित कर दिया है। इन घटनाओं के प्रति अब पहले की तरह आखें बंद रखना संभव नहीं है। भारत के राष्ट्रीय संघप के इतिहास में अपनी एक के बाद एक नई मजिल से यह प्रदर्शित कर दिया है कि मजदूरवर्ग की भूमिका और उसका महत्व तेजी से बढ़ रहा है और समाजवाद या साम्यवाद के प्रश्न भारत में चलने वाली राजनीतिक बहस के मुख्य प्रश्न बन गए हैं।

1914 से पहले के वर्षों में मजदूर वग की यह भूमिका पृष्ठभूमि में पड़ी हुई थी। उस समय तक मजदूर वग राष्ट्रीय आंदोलन के आगे चलने के बजाय उसके पीछे पीछे चलता था। उन वर्षों में मजदूर वग ने जो एकमात्र असाधारण राजनीतिक काम किया वह था तिलक का 6 वप की सजा दिए जाने के विरोध में बर्बई में आम हड़ताल। प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर भारत में चेतना के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह शुरूआत 1918-21 की जबरदस्त हड़ताल से हुई। इस हड़ताल ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी लहर के लिए अग्रदूत का काम किया और इसने ही अतत कांग्रेस को भी आंदोलन के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप 1920-22 का असहयोग आंदोलन छिड़ा।

इसके दस वप बाद स्थिति यह थी कि मजदूर वग ने एक संगठित और स्वतंत्र शक्ति का रूप ले लिया, उसकी अपनी विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करने लगी हालांकि उसने अभी तक नेतृत्व की भूमिका नहीं प्राप्त की। 1928 में जबरदस्त हड़तालें हुईं जिनका नेतृत्व जुमार वगचेतना से लैस सवहाराबग ने किया। इसके साथ साथ युवकों और निम्न पूँजीपतिवर्ग के बीच भी एक नई चेतना आई और उन्होंने राष्ट्रीय संघप की नई लहर का नेतृत्व किया। 1930-34 के संघप की इस नई लहर के दौरान भारत के बुजुर्ग नेताओं ने साफ साफ कहा कि उन्हें दो मोर्चों पर एक साथ संघप चलाना पड़ रहा है वे एक तरफ साम्राज्यवाद के खिलाफ और दूसरी तरफ नीचे से उठने वाले क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ संघप कर रहे हैं। दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद से यह बात अब पहले की तुलना में और स्पष्ट हो गई है कि भारत की भावी राजनीति में मजदूर-वर्ग ही निर्णायक शक्ति का काम करेगा।

## 1 औद्योगिक मजदूरवर्ग का विकास

प्रचलित अर्थों में वह तो भारतीय मजदूरवर्ग समस्या की दृष्टि से भारत की आबादी की तुलना में अधिक नहीं है। लेकिन चूंकि निर्णायक केंद्रों पर इसका जमाव है इसलिए यह

सबसे ज्यादा सुसंगत, सबसे ज्यादा विकसित, सर्वाधिक कृतसंकल्प और बुनियादी तौर पर आबादी का सबसे अधिक क्रांतिकारी हिस्सा है।

अक्टूबर 1922 में लीग आफ नेशंस की कौंसिल में ब्रिटिश सरकार की ओर से बोलते हुए लार्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था कि भारत में 2 करोड़ 'औद्योगिक मजदूर' हैं

भारत के इस खास दावे का औचित्य सिद्ध करना अभी शेष है कि उसे आठ प्रमुख औद्योगिक देशों में शामिल कर लिया जाए। उसके इस दावे के व्यापक सामान्य आधार हैं और इन दावों का औचित्य ठहराने के लिए आकड़ों की जरूरत नहीं है। भारत में औद्योगिक मजदूरी पर जीवनयापन करने वालों की संख्या काफी है जो अनुमानतः 2 करोड़ है। इसके अलावा खेतिहर मजदूरों की एक बड़ी तादाद है।

विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों की श्रेणी में भारत को स्थान दिलाने के लिए बड़ाबड़ाकर इस तरह के दावे किए गए थे जो कूटनीतिक धोखाधड़ी का ही एक हिस्सा था। यह जिनेवा में ब्रिटिश सरकार के हाथों में अतिरिक्त मत दिवाने की चाल थी। मजदूरों की संख्या जो दो करोड़ बताई गई थी, उसमें प्रचुर संख्या दस्तकारों और धरेलू उद्योगों में लग मजदूरों की थी जिनका आधुनिक उद्योग से कोई संबंध न था।

इसी प्रकार 1927-28 में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की थी उसने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि भारत में 'संगठनीय मजदूरों' की संख्या ढाई करोड़ से अधिक है। लेकिन इस ढाई करोड़ में से कम से कम 2 करोड़ 15 लाख लोग खेतिहर सबहारा थे जो किसी पूँजीवादी खेती में नहीं लगे थे (इनमें से 10 लाख लोग बागानों में काम करते थे), इन्हें कभी रोजगार मिलता था कभी नहीं मिलता था, ये अत्यंत गरीबी की हालत में थे और प्रचलित अर्थों में किसी मजदूर संगठन की इनकी क्षमता नहीं थी (हालांकि किसान आंदोलन में इनकी बड़ी संक्षम भूमिका हो सकती थी)। उनके विश्लेषण के अनुसार, औद्योगिक संगठनीय मजदूरों की संख्या मात्र 35 लाख थी।

भारतीय मजदूरवर्ग की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए यह भेद समझ लेना जरूरी है कि भारत में संपत्तिहीन सबहारा की संख्या काफी अधिक है और आधुनिक उद्योग में लगे मजदूरों की संख्या कम है। लेकिन यही वह वर्ग है जो भारतीय मजदूरवर्ग का सबसे संगठित, निर्णायक, सचेतन और अग्रणी हिस्सा है।

भारतीय मजदूरवर्ग की संख्या की कोई आकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1931 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार

भारत जैसे विशाल अवादीवाले देश के सद्भूम में देखें तो सगठित श्रम में लगे मजदूरों की संख्या असाधारण रूप से कम है और ब्रिटिश भारत के संस्थानों में काम करने वालों की औसत दैनिक संख्या, जिनपर फ़ैक्टरीज ऐक्ट लागू होता है, केवल 1,553,169 है

1921 में संपूर्ण भारत में बागानों, खानों, उद्योग और परिवहन में काम कर रहे लोगों की संख्या 24,239,555 थी जिनमें से केवल 22,685,909 लोग ऐसे सगठित संस्थानों में थे जिनमें 10 या 10 से अधिक कमचारों काम करते हो।

1931 में इसी घाते में लोगों की कुल संख्या 26,187,689 थी और यदि इस तरह के संस्थानों में काम कर रहे श्रमिकों का अनुपात वही हो तो यह संख्या अब 2,901,776 हो जाएगी। औसतन रोजाना काम करने वालों की संख्या से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इस संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इस हिसाब से यह संख्या इस समय 3,500 000 होनी चाहिए। 1931 में भारत में सगठित मजदूरों की संख्या यदि 5,000 000 मान लें तो संभवतः यह उचित संख्या होगी। (सेंसस आफ इंडिया, 1931, खंड 1, भाग 1, पृष्ठ 285)

व्यापक अर्थों में ले, तो भारत में मजदूरों पर अपनी जीविका चलाने वालों की संख्या अनुमानित लगभग 6 करोड़ थी। भारतीय मताधिकार समिति (इंडियन फ्रैंचाइज कमिटी) के अनुसार 1931 में यह संख्या 5 करोड़ 65 लाख थी

1921 में खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या 2 करोड़ 15 लाख बताई गई थी जबकि 1931 की जनगणना से पता चला कि यह संख्या 3 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई है। इसमें से, भारतीय मताधिकार समिति के अनुसार 2 करोड़ 30 लाख लोग भूमिहीन थे और समिति के अनुसार गैरखेतिहर मजदूरों की कुल संख्या 2 करोड़ 50 लाख थी। इस प्रकार संपूर्ण भारत में विभिन्न घटो में लगे लोगों की 15 करोड़ 40 लाख की संख्या में से मजदूरों पर जीने वाला की संख्या 5 करोड़ 65 लाख आती है। बहने का तात्पर्य यह है कि सभी तरह के घटा में लगे पूरी कुल आबादी का 36 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा मजदूरी करके अपनी रोटी चलाता है। (आई० एल० ओ० रिपोर्ट 1938, 'इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया', पृष्ठ 30)

यदि औद्योगिक सवहारा शब्द का बहुत सखीण अर्थों में लिया जाए और इस श्रेणी में केवल उही लोगो को रखा जाए जो आधुनिक उद्योगों में लगे हैं और छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को छोड़ दिया जाए तो 1921 की जनगणना से हम पता चलता



फैक्टरीज ऐक्ट के आवेग में औद्योगिक सवहारा की वृद्धि का व्यौरा दिया हुआ है (इससे इस ऐक्ट के तहत निर्धारित क्षेत्र के विस्तार का भी पता चलता है)

| सन   | कारखानों की संख्या | रोजाना काम करने वालों की औसत संख्या |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| 1894 | 815                | 349,810                             |
| 1902 | 1,533              | 541,634                             |
| 1914 | 2,936              | 950,973                             |
| 1918 | 3,436              | 1,122,922                           |
| 1922 | 5,144              | 1,361,002                           |
| 1926 | 7,251              | 1,518,391                           |
| 1930 | 8,148              | 1,528,302                           |
| 1935 | 8,831              | 1,610,932                           |
| 1936 | 9,323              | 1,652,147                           |
| 1938 | 9,743              | 1,737,755                           |
| 1939 | 10,466             | 1,751,137                           |
| 1943 | 13,209             | 2,436,310                           |
| 1944 | 14,071             | 2,522,753                           |

## 2 मजदूरवर्ग की हालत

भारत में मजदूरवर्ग की स्थिति के बारे में हमने इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में एक सामान्य तस्वीर पेश की है। 1928 में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा के बाद जो रिपोर्ट पेश की थी, उसके निष्कर्षों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा

सारी जाच पड़ताल से पता चलता है कि भारत के मजदूरों की एक विशाल संख्या को लगभग 1 शिलिंग प्रतिदिन से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। बंगाल प्रांत में औद्योगिक मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस सूचे में जाच से यही पता लगाया जा सका है कि यहां के 60 प्रतिशत मजदूरों की अधिकतम मजदूरी 1 शिलिंग 2 पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं है। यह राशि पुरुषों के लिए वही नहीं है ता 7 पैसे प्रतिदिन और महिलाओं तथा बच्चों के लिए 3 से 7 पैसे प्रतिदिन तक है। हमारी अपनी जांचों से भी पता चलता है कि इन्हें इतनी ही मजदूरी मिलती है और वस्तुतः दैनिक मजदूरी के बारे में हमें जो आंकड़े मिल हैं वे महिलाओं के लिए सवा तीन पैसे प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 7 पैसे या इससे भी कम हैं। (ए० ए० परमेन और जे० हाल्लवर्थ, 'रिपोर्ट ऑन सेक्टर कंडीशन इन इंडिया', ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1928, पृष्ठ 10)

इसी प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के बारे में लिखा



है कि दस या इससे ज्यादा मजदूरों से काम लगाने वाले कारखानों के मजदूरों की कुल संख्या 26 लाख थी। इसके बाद कोई औद्योगिक जनगणना नहीं हुई लेकिन ऊपर 1931 की जिस जनगणना का उल्लेख है, उससे अनुसार ऐम मजदूरों की संख्या 35 लाख तक हो गई है। फैक्टरीज ऐक्ट प्रशासन ही सही आंकड़े दे सकता है। 1934 के ताजा फैक्टरीज ऐक्ट के अंतर्गत वही कारखाने आते हैं जिनमें विद्युतशक्ति से मशीनें चलती हैं और जिनमें बीस या उससे ज्यादा मजदूर और कहीं कहीं 10 या 10 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इस तरह के कारखानों में 1938 में कुल 1,737,755 मजदूर काम करते थे। इस संख्या में उन 299,003 मजदूरों को जोड़ना पड़ेगा जो भारतीय रियासतों के 'बड़े औद्योगिक संस्थानों' में काम करते थे। इस प्रकार भारत के बड़े और आधुनिक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या 2,036,758 थी।

इसको आधार मानकर हम निम्नाविक्त निष्कर्ष पर पहुंचते हैं

#### मशीनें और बड़े कारखानों में मजदूरों की संख्या

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| (उपयुक्त आधार पर)    | 2,036,758 |
| खान मजदूर            | 413,458   |
| रेल मजदूर            | 701,307   |
| जल परिवहन            |           |
| (गोदी मजदूर नाविक)*  | 361,000   |
| इन सब वर्गों का जोड़ | 3,512,523 |

\*यह 1935 की संख्या है।

यह 35 लाख मजदूर आज के भारत के विशाल आधुनिक उद्योगों में कार्यरत औद्योगिक सवहारा के मूल तत्व हैं। इसमें वे मजदूर नहीं शामिल हैं जो छोटे उद्योगों में (अर्थात् दस से कम मजदूरों वाले उद्योगों में) काम करते हैं या ऐसे बड़े कारखानों में काम करते हैं जिनमें विद्युत शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है (जैसे सिगरेट बनाने के कुछ कारखानों में जिनमें बिना पावर के मशीनें चलती हैं 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं)। संगठित मजदूर आंदोलन की ताकत का सही सही अंदाजा लगाने की दृष्टि से हम इस संख्या में उन दस लाख से ज्यादा मजदूरों का भी जोड़ना पड़ेगा जो बागानों में काम करते हैं। बागानों में काम करने वाले मजदूर ऐसे मजदूर हैं जिन्हें काफी बड़े उद्योगों में लगाकर अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से दासता की बंडिया में जकड़ दिया जाता है। इन मजदूरों ने अशक्ति के दिनों में अपनी जबरदस्त जुझारू गतिविधियों का परिचय दिया है हालांकि ये अभी तक हर तरह के संगठनों से कटे हुए हैं और इन्हें गुलाम बनाकर बिल्कुल अलग रख रखा गया है। इसके अलावा छोटे मोटे उद्योगों और फैक्टरीज ऐक्ट के दायरे में न आने वाले बड़े उद्योगों के मजदूरों के एक हिस्से को भी जोड़ना चाहिए। इस प्रकार भारत में संगठित किए जाने योग्य कुल मजदूरों की संख्या 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए।

फैक्टरीज ऐक्ट के आकड़ा में औद्योगिक सवहारा की वृद्धि का ब्योरा दिया हुआ है (इससे इस ऐक्ट के तहत निर्धारित क्षेत्र के विस्तार का भी पता चलता है)

| सन   | कारखानों की संख्या | रोजाना काम करने वालों की औसत संख्या |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| 1894 | 815                | 349,810                             |
| 1902 | 1,533              | 541,634                             |
| 1914 | 2,936              | 950,973                             |
| 1918 | 3,436              | 1,122,922                           |
| 1922 | 5 144              | 1,361,002                           |
| 1926 | 7,251              | 1,518,391                           |
| 1930 | 8 148              | 1,528,302                           |
| 1935 | 8,831              | 1,610 932                           |
| 1936 | 9,323              | 1,652,147                           |
| 1938 | 9,743              | 1,737,755                           |
| 1939 | 10 466             | 1,751,137                           |
| 1943 | 13,209             | 2,436,310                           |
| 1944 | 14 071             | 2 522,753                           |

## 2 मजदूरवर्ग की हालत

भारत में मजदूरवर्ग की स्थिति के बारे में हमने इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में एक सामान्य तस्वीर पेश की है। 1928 में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा के बाद जो रिपोर्ट पेश की थी, उसके निष्कर्षों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा

सारी जाच पड़ताल से पता चलता है कि भारत के मजदूरों की एक विशाल संख्या को लगभग 1 शिलिंग प्रतिदिन से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। बंगाल प्रांत में औद्योगिक मजदूरों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस सूचे में जाच से यही पता लगाया जा सका है कि यहां के 60 प्रतिशत मजदूरों की अधिकतम मजदूरी 1 शिलिंग 2 पेंस प्रतिदिन से अधिक नहीं है। यह राशि पुरुषों के लिए कहीं कहीं तो 7 पेंस प्रतिदिन और महिलाओं तथा बच्चों के लिए 3 से 7 पेंस प्रतिदिन तक है हमारी अपनी जाचा से भी पता चला है कि इहे इतनी ही मजदूरी मिलती है और वस्तुतः दैनिक मजदूरी के बारे में हम जो आंकड़े मिले हैं वे महिलाओं के लिए सवा तीन पेंस प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 7 पेंस या इससे भी कम है। (ए० ए० परसेल और जे० हात्सवथ, 'रिपोर्ट आन लेबर कंडीशंस इन इंडिया', ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1928, पृष्ठ 10) -

इसी प्रतिनिधिमंडल ने मजदूरों के आवास के बारे में लिखा

हम जहा वही भी ठहरे वहा हमने मजदूरो के क्वाटरों को देखा और यदि हमने स्वयं यह सब नहीं देखा होता तो हम यह यकीन नहीं होता कि ऐसी गंदी जगह भी है। यहा 'लाइनों' में मकानों के समूह हैं जिनके मानिक इन मकानों के किरायेदारों से किराए के रूप में प्रतिमाह 4 शिलिंग 6 पेंस लेते हैं। मकान के नाम पर यह 9 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी एक अंधेरी कोठरी है जिसकी दीवारें मिटटी की हैं और टूटी-फूटी छत है। इसी कमरे में लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं और सोते भी हैं। इन कमरों के सामने एक छोटा सा आंगन है जिसके एक कोने में पाखाना बना है। रहने के मकान में कोई खिड़की नहीं है, केवल दरवाजे के ऊपर छत को तोड़कर एक सुराख बनाया गया है जिससे रोशनी और हवा आ सकती है। इन कोठरियों के बाहर एक लंबी सड़की नाली है जिसमें हर तरह का कूड़ा कचरा डाला जाता है और जिसपर ढेर सारी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। सभी कोठरियों के बाहर दोनों सिरों पर, लाइनों के बीच छोटी सी जगह है जहा खुली गलियां हैं। ये गलियां बूड़ों के मलबों से बंद हैं और इनसे भयंकर बदबू आती है। जाहिर है कि इन गलियों को लोग, खास तौर से बच्चे शौचालय के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

हर जगह लोगों की भीड़ भरी है और गंदगी का साम्राज्य है। इससे पता चलता है कि सबंध अधिकारी अपने कर्तव्य की कितनी जबरदस्त उपेक्षा करते हैं।  
(वही, पृष्ठ 89)

यह रिपोर्ट 11 वर्ष पूर्व जारी की गई थी। तब से आज तक ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भारत नहीं भेजा।

1938 में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि एस० बी० परलेकर ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन के समान जा रिपोर्ट पेश की थी उससे इधर हाल के वर्षों की तस्वीर मिलती है। इससे पता चलता है कि मजदूरों की हालत में कितनी तब्दीली आई है, या यों कहें कि मजदूरों की हालत और कितनी बदतर हुई है।

भारत में मजदूरों के अधिकांश को जितनी मजदूरी मिलती है उससे वे अपनी मामूली से मामूली जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। 1921 में श्री फिडले शिराज ने बंबई मजदूरों के मासिक आय व्यय की जांच के बाद बताया था कि औद्योगिक मजदूर उतना ही अनाज खाता है जितना अनाज सहिता के अंतर्गत सरकार अनाजपीडितों को देती है लेकिन बंबई की जेल सहिता के अंतर्गत बंदियों को जितना भोजन दिया जाता है मजदूरों को उससे कम ही अनाज मिल पाता है। उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद स स्थिति बदतर हो गई है क्योंकि 1921 की आय की तुलना में आज आय में और गिरावट आई है।

1935 में बंबई सरकार ने मजदूरी के मदद में जो जाच की थी उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि संगठित और प्रमुख उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग में मजदूरों की हालत कितनी दयनीय है। रिपोर्ट के अनुसार गोवाक में 18 प्रतिशत मजदूरों की मासिक आय 3 शिलिंग से 9 शिलिंग के बीच है। शोलापुर में 32 प्रतिशत मजदूरों की मासिक आय 7 शिलिंग 6 पेंस से 15 शिलिंग के बीच है और 20 प्रतिशत मजदूरों की मासिक आय 22 शिलिंग 6 पेंस से कम है। इसी प्रकार बंबई शहर में 32 प्रतिशत मजदूर 22 शिलिंग 6 पेंस से 30 शिलिंग के बीच मजदूरी पाते हैं।

असंगठित उद्योगों में, जिनकी सख्या भारत में काफी है मजदूरों की क्या हालत होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। जमीन से किसानों को बेदखल किए जाने का काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है और मिलमालिकों ने इस वर्ग के होने का लाभ उठाकर मजदूरों इतनी कम कर दी है जिससे किसी का गुजारा भी नहीं चल सकता। और वे मजदूरों की दर को उसी सीमा तक भी बढ़ाना नहीं चाहते जहां तक उद्योग की स्थिति को देखते हुए वे बढ़ा सकते हैं।

भारत के मजदूरों की बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के समय मदद मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार ने, बेरोजगारों को कोई भत्ता देने की कोई योजना तैयार करने से लगतार इन्कार किया है। ऐसी कई घटनाएं देखने में आई हैं जब बेरोजगारी से अपनी रक्षा के लिए मजदूरों ने आत्महत्या कर ली हो। बंबई शहर की नगरपालिका की रिपोर्ट में भूख से हुई मौतें भी दर्ज हैं।

1931 की जनगणना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बंबई में लोग जिस तरह से घरा में रहते हैं वह किसी भी मध्य समाज के लिए शर्म की बात है। यहां 95 प्रतिशत मजदूर परिवार औसतन 110 वर्ग फीट की छोटी में अपना जीवन बिताते हैं। बंबई में हजारों की सख्या में ऐसे मजदूर हैं जो फुटपाथ पर ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।

|  | प्रति हजार पर मरने वाले बच्चों की सख्या |
|--|---|
| एक काठरी या इससे कम में रहने वाले परिवार | 524 0                                   |
| दो कमरों में रहने वाले लोग               | 394 5                                   |
| तीन कमरों में रहने वाले लोग              | 255 4                                   |
| चार कमरों या इससे अधिक में रहने वाले लोग | 246 5                                   |

पृष्ठ 397 पर दिए गए आकड़ों से पता चलता है कि बंबई में 1933-34 में बच्चे की शैशवावस्था में मृत्यु दर क्या थी। बाकी आबादी के मुकाबले मजदूरों के कितने बच्चे मरते हैं यह देखकर हैरानी होती है

तब से आज तक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे मजदूरों को उतने किराए पर स्वास्थ्यप्रद मकान दिया जा सके जितना वे भुगतान कर सकते हों और इस प्रकार मृत्यु दर को या यह कहना ज्यादा सही होगा कि मजदूरों के बच्चों के नरसंहार को रोका जा सके।

(जुलाई 1938 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि एस० बी० पट्टेकर का भाषण)

भारतीय उद्योग में घटती स्तर तथा मजदूरों के बारे में सामान्य तौर पर किया गया व्यापक सर्वेक्षण 1831 की ब्रिटिश कमिशन रिपोर्ट में बाहर डी० एच० बुकानन की पुस्तक 'दि डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया' (1934) के पंद्रहवें अध्याय में पृष्ठ 317-60 पर मिलेगा। इस पुस्तक में लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 1860 से 1890 के बीच भारतीय कारखाना उद्योग की वास्तविक आय में बहुत मामूली बढ़ती का आभास मिलता है, 1890 से 1914 के बीच 'कीमती मजदूरी से वृद्धि हुई और मजदूरों में भी इसके अनुरूप वृद्धि हुई हालांकि यह वृद्धि कीमती मजदूरी से कम ही रही।' इसके साथ ही विश्वयुद्ध की विभीषिका के कारण अनेक वर्षों तक मजदूरों की दर में काफी कमी रही और फिर यह तेजी से बढ़ी। लेकिन यह वृद्धि बहुत अगमनी थी और कहीं कहीं तो ऊंची कीमतों के बिल्कुल अनुरूप थी। इस प्रकार 1914-18 के युद्ध की समाप्ति तक वास्तविक मजदूरों के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई उल्टे मजदूरों के स्तर में जो परिवर्तन आया उसे गिरावट ही कहा जाना ठीक होगा। बाद के वर्षों में वृद्धि जाकर इसमें कोई परिवर्तन हुआ। युद्ध के बाद से मजदूरों के प्रश्न को लेकर अनेक विवाद हुए और जबकि वृद्धि वही हल्की सी मंदी की स्थिति दर्शन में आई वही वृद्धि उल्लेखनीय प्रगति के भी मुकदमों में। 'युद्ध उद्योगों में घातक से बंबई के कपड़ा उद्योग में मजदूरों की दर में जो वृद्धि हुई वह जीवनयापन के घब की तुलना में काफी अधिक थी। हाल के वर्षों में जबकि कीमती मजदूरी से गिरावट आई है मजदूरों की पुरानी दर बनी रहने दी गई है। मजदूर इतना जागरूक हो गया है कि यदि उसके वेतन में कटौती की जाए तो भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है।' युद्ध के कारण जो आर्थिक मंदी आई थी उमंग मजदूरों में कटौती के जरिए और बेरोजगारी आने की खबर से काफी सुखाना का सामना करना पड़ा तो भी वास्तविक मजदूरों के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी और युद्ध पूर्व के समय में जो प्रगति की गई थी वह उजागर नहीं हुई। हमने जिन 19०९ में बांगुर में कपड़ा मिल मजदूरों की गणना हुआ था का पता लगाया है। उस प्रकार यह दया जाता है कि भारत में औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि अभी हुई है जब उनका दैनिक जीवन गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। यह

भी देखा जाता है कि जहाँ जहाँ जिस सीमा तक मजदूर संगठनों की शक्ति थी वहाँ उसी के अनुसार मजदूरी भी बढ़ी। लेकिन अत्यंत पिछड़े मजदूरों के वर्ग को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है।

भारत में कहा कितनी मजदूरी मिलती है इसके बारे में सामान्यतौर पर कोई आकड़े नहीं मिलते। इसका भी कोई व्योरा नहीं मिलता कि एक औद्योगिक केंद्र में एक ही तरह के काम के लिए एक जैसी मजदूरी मिलती है। ब्रिटिश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1925 से 1929 तक पांच वर्ष की अवधि में मजदूरों के मुआवजा कानून के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमों के आकड़ा का अध्ययन किया था जिससे इस बात का पता चलता है कि अधकुशल औद्योगिक मजदूरों को किस दर से मजदूरी मिलती है। यहाँ तक कि अकुशल मजदूर या कम वेतन पाने वाले मजदूरों के बारे में इन मुकदमों से कुछ नहीं मालूम हो सकता था क्योंकि ऐसे मजदूर बहुत असहाय होते हैं और उनमें से बहुतों को तो मुआवजा कानून की कोई जानकारी नहीं होती। इन मुकदमों के वागजा से प्राप्त होने वाले आकड़ों को सरकारी अधिकारियाँ ने यह कहकर पेश किया था कि 'उनसे संगठित उद्योगों के अधकुशल मजदूरों की मजदूरी की दरों का मोटेतौर पर अनुमान लग सकता है' (इसमें वच्चा, अकुशल मजदूर और असंगठित उद्योगों के बहुत कम मजदूरों पाने वाले मजदूरों को छोड़ दिया गया है) इन आकड़ों से बहुत ही चौंका देने वाली तस्वीर सामने आती है। गैरभारतीय पाठकों के सामने इन आकड़ों को पेश करने के लिए हमने रुपये की मुद्रा को अंगरेजी मुद्रा में तब्दील ही नहीं किया है बल्कि रुपये की कीमत एक शिलिंग 6 पेंस मान कर और इसीके आधार पर महीने की कुल राशि को साप्ताहिक राशि में बांट दिया है। इस तरह के आकड़ों से निम्नावृत्त तस्वीर सामने आती है

#### संगठित उद्योग में लगे अधकुशल बालिग मजदूरों की औसत आय

|                 | 4 शि० 6 पें० से कम | 4 शि० 6 पें० से 6 शि० | 6 शि० से 7 शि० 9 पें० | 7 शि० 9 पें० से 9 शि० 6 पें० | 9 शि० 9 पें० से 11 शि० 3 पें० | 11 शि० 3 पें० तथा इससे अधिक |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| संयुक्त प्रांत  | 26                 | 27                    | 15                    | 9                            | 7                             | 16                          |
| मद्रास          | 22                 | 25                    | 19                    | 15                           | 4                             | 15                          |
| मध्य प्रांत     | 18                 | 38                    | 17                    | 8                            | 4                             | 15                          |
| बिहार और उड़ीसा | 21                 | 24                    | 21                    | 12                           | 8                             | 14                          |
| बंगाल           | 13                 | 18                    | 18                    | 15                           | 10                            | 26                          |
| बम्बई           | 3                  | 10                    | 19                    | 23                           | 13                            | 23                          |

(भारत में श्रम स्थिति के बारे में ब्रिटिश कमीशन की रिपोर्ट से ली गई तालिका, पृष्ठ 204। इसे उपर्युक्त आधार पर ब्रिटिश मुद्रा में समतुल्य रखकर पेश किया गया है।)

इस प्रकार संयुक्त प्रांत में एक चौथाई से ज्यादा अधकुशल बालिग मजदूरों की प्रति सप्ताह 4 शिलिंग 6 पेंस से कम और आधे से ज्यादा की 6 शिलिंग से भी कम मजदूरी मिलती थी। मध्य प्रांत में आधे से ज्यादा अधकुशल मजदूरों को और मद्रास, बिहार तथा उड़ीसा में लगभग आधे मजदूरों को 6 शिलिंग से कम मजदूरी मिलती थी। बंगाल में आधे मजदूर 7 शिलिंग 9 पेंस से कम मजदूरी प्रति सप्ताह पाते थे और यहाँ तक कि बंबई में जहाँ जीवनयापन का खर्च अपेक्षाकृत अधिक है आधे से ज्यादा मजदूर प्रति सप्ताह 9 शिलिंग 6 पेंस से कम ही मजदूरी पाते थे।

ये आंकड़े अपेक्षाकृत बेहतर परिस्थितियों में रहने वाले मजदूरों के हैं। इनसे सभी मजदूरों के बारे में कोई आम जानकारी नहीं पाई जा सकती। इधर हाल के वर्षों में प्रांतीय श्रम विभागों की ओर से मजदूर परिवारों के आय व्यय के बारे में अनेक जाँचें की गई हैं और उनके निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं। इन विभागों द्वारा 1935 में बंबई में ( जाच में 1932-33 की अवधि को लिया गया ) 1937 में अहमदाबाद में और 1938 में मद्रास में की गई जाच के नतीजे प्रकाशित किए गए। इससे पहले 1928 में शोलापुर के बारे में इसी तरह की जाच की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें वर्ष 1925 की अवधि को जाच के लिए चुना गया था।

इन निष्कर्षों से पता चला कि औसतन एक परिवार की आय ( किसी व्यक्ति की आय नहीं ) बंबई में 50 रुपये मासिक या 17 शिलिंग 4 पेंस प्रति सप्ताह थी, अहमदाबाद में 46 रुपये मासिक या 15 शिलिंग 11 पेंस प्रति सप्ताह शोलापुर में 40 रुपये मासिक या 13 शिलिंग 10 पेंस प्रति सप्ताह, मद्रास में संगठित उद्योगों के मजदूरों के लिए 37 रुपये मासिक या 12 शिलिंग 10 पेंस प्रति सप्ताह और असंगठित उद्योगों तथा व्यवसायों में लगे मजदूरों के लिए 20 से 27 रुपये मासिक या 7 शिलिंग से 9 शिलिंग 3 पेंस प्रति सप्ताह मजदूरी थी। बंबई, शोलापुर और अहमदाबाद की जाचों से पता चला कि औसतन एक परिवार में कुल सदस्यों की संख्या चार होती है जिनमें से डेढ़ या दो आदमी काम करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त आंकड़ों को एक तिहाई से लेकर आधे तक कम कर दिया जाना चाहिए। इससे जो परिणाम प्राप्त होगा वह इस प्रकार होगा बंबई के लिए औसत मजदूरी 9 शिलिंग 10 पेंस प्रति सप्ताह, अहमदाबाद के लिए 9 शिलिंग 1 पेंस प्रति सप्ताह शोलापुर के लिए 7 शिलिंग 11 पेंस प्रति सप्ताह मद्रास के लिए संगठित उद्योगों के लिए 7 शिलिंग 4 पेंस और असंगठित उद्योगों के लिए 4 शिलिंग से लेकर 5 शिलिंग 3 पेंस प्रति सप्ताह।

यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि निर्धारित मजदूरी में से अनेक तरह की कटौती हो जाती है। कमीशन जुर्माना, फोरमैन को दी जाने वाली रिश्वत और मजदूरों पर लगे हुए वज्रों को भयकर सूद का कारण बटौती होते होते वागमर पर निखी ताम्बाह कुछ की कुछ ही

जाती है (मजदूरों के लिए कर्जा लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि अधिकांश मजदूरों को मामूली वेतन मिलता है और प्रायः महीना खत्म हो जाने के भी दस पंद्रह दिन बाद पैसे दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मजदूर को लगभग 6 सप्ताह उधार लेकर घबराव में चलना पड़ता है)। ब्रिटिश कमिशन ने अनुमान लगाया था कि 'अधिकांश औद्योगिक केंद्रों में कम से कम दो तिहाई मजदूर या उनके परिवार ऐम हूजो कज में लदे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर मजदूरों का कज उनकी तीन महीने की तनखाह से ज्यादा है और कभी कभी तो कज की राशि इन तीन महीनों की तनखाह की राशि से बहुत ज्यादा हो जाती है।' बाद की जांच पड़ताल से पता चला कि ब्रिटिश कमिशन ने अपने अनुमान से कर्ज में लदे मजदूरों की दो तिहाई की जो संख्या बताई थी वह वास्तविक संख्या से काफी कम है। ऊपर बर्बई की जिस जांच का हमने उद्धरण दिया है उसके अनुसार 75 प्रतिशत परिवार कज से लदे पाए गए। मद्रास की रिपोर्ट से पता चला कि संगठित उद्योगों के 90 प्रतिशत मजदूरों पर कज का बोझ था और औसतन प्रत्येक का कज छ महीने की तनखाह से ज्यादा था।

गोरे कमचारियों की तनखाह भी काफी कम है। रगे कमेटी (1946) द्वारा की गई जांच पड़ताल के अनुसार कांचीन गांधी में काम करने वाले कुल कमचारियों में से 30.5 प्रतिशत कमचारी प्रतिदिन एक रुपये से कम मजदूरी पाते हैं और 68 प्रतिशत कमचारी प्रतिदिन एक रुपये से लेकर दो रुपये तक की मजदूरी पाते हैं। सिंधिया शिपयार्ड में 82 प्रतिशत कमचारियों की मजदूरी प्रतिदिन एक रुपये से भी कम है।

खानों में काम करने वालों की मजदूरी घासतौर से बहुत कम है और हाल के वर्षों में उनकी मजदूरी में से जबरदस्त कटौती भी हुई है। भारत की कोयला खानों में काम करने वाले कुल मजदूरों का 4/5 हिस्सा रानीगंज और झरिया की कोयला खानों में काम करता है। रानीगंज की कोयला खान में 1914 से पहले घनिका की मजदूरी 6 आना या 6 पैसे प्रतिदिन थी। मुद्र के बाद इस राशि में वृद्धि हुई और 1929 तक यह राशि बढ़कर 13 आना या एक शिलिंग दो पैसे प्रतिदिन हो गई थी। 1936 तक यह राशि घटकर सवा सात आना या आठ पैसे प्रति दिन हो गई थी। कोयला खान मैनजरों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष ने फरवरी 1937 में 'मजदूरों की अत्यंत दयनीय मजदूरी' के बारे में ठीक ही कहा था। भारत में एक घनिक औद्योगिक 131 टन कोयला प्रति वर्ष निर्यात करता है जबकि जापान में एक घनिक प्रति वर्ष 260 टन, ब्रिटेन में 298 टन और अमेरिका में 671 टन कोयला निर्यात करता है।

चायखानों की मजदूरी की हालत तो सबसे खराब है। असम पार्टी के चायबानानों में (भारत की ज्यादातर चाय असम और बंगाल में पैदा होती है) वैसे मजदूरों में पुरुषों की औसत मासिक आय 7 रुपये 13 आने, औरतों की 5 रुपये 14 आने और बच्चों की 4 आने होती है। (शिवराव 'दि इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया, 1939, पृष्ठ 128)



राशि पुर्णों के लिए प्रति सप्ताह 2 शिलिंग 8 पेंस, महिलाओं के लिए 2 शिलिंग और बच्चों के लिए 1 शिलिंग 5 5 पेंस के बराबर है। इसके अलावा इन मजदूरों को नि गुल्क 'घर' की सुविधा और चिकित्सा की सुविधा तथा जो अन्य रियायतें मिली हुई हैं उनसे इनकी गुलामी जैसी हालत का ही सबूत मिलता है। सूरमा घाटी में मजदूरों की दर और भी कम है। रंगे कमेटी ने बताया था कि सूरमा घाटी में मासिक वेतन की जो दर है वह असम घाटी की तुलना में लगभग 2 रुपये कम है। दक्षिण भारत के बागानों में मजदूरों की दर पुर्णों के लिए 4 से 5 आना (4 5 पेंस से 5 5 पेंस) प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 3 आना (3 5 पेंस) से भी कम है।

इतने बड़े पैमाने पर शोषण करके कितना जबरदस्त मुनाफा कमाया जाता है इसके बारे में बागानों के मालिक काफी बुद्धिमान हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद व्यवसाय में आई तेजी के कारण इन मालिकों का मुनाफा आसमान पर पहुँच गया। 1925 में डडी की जूट मिल मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल ने जूट उद्योग के सदस्यों में यह रिपोर्ट दी थी

रिजर्व कोपी और मुनाफे का जोड़ने पर पता चलेगा कि 10 साल के दौरान (1915 से 1924 तक) 30 करोड़ पौंड का मुनाफा हिस्सेदारों को मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जूट उद्योग में लगी हुई पूँजी पर 90 प्रतिशत सान्ना का लाभ है। जूट उद्योग में 3 लाख से लेकर 3 लाख 27 हजार मजदूर काम करते हैं और उन्हें औसतन प्रति वर्ष 12 पौंड 10 शिलिंग मजदूरी के रूप में प्राप्त होते हैं। 3 लाख मजदूरों में 10 वर्षों के दौरान 30 करोड़ पौंड का मुनाफा वसूलने का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक मजदूर से साल भर में 100 पौंड वसूले गए। मजदूरों की औसत मजदूरी चूँकि 12 पौंड 10 शिलिंग प्रति व्यक्ति है इससे यह पता चलता है कि मालिकों का सालाना मुनाफा मजदूरों की वार्षिक मजदूरी का 8 गुना होता है। (टी० जानसन और जे० एफ० सीमे 'एक्सप्लायटेशन इन इंडिया', पृष्ठ 56)

सूती कपड़ा उद्योग के बारे में सीमा शुल्क बोर्ड ने 1927 में जांच करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो इस प्रकार की

बवाई की मिलों की आमदनी और खर्च के हिसाब को देखकर पता चलता है कि 1920 में 35 कंपनियाँ ने, जिनके अंतर्गत 42 मिलें आती थीं, अपने हिस्सेदारों को 40 प्रतिशत या उससे भी अधिक लाभांश बाँटा था। इनमें से 14 मिलों का स्वामित्ववाली 10 कंपनियाँ 100 प्रतिशत या उससे भी अधिक मुनाफा बाँटा था और 2 मिलों ने 200 प्रतिशत से ज्यादा लाभांश अपने शेयर होल्डरों को दिया था। 1921 में 41 कंपनियाँ ऐसी थीं जिनके अधीन 47 मिलें आती थीं।

इनमें से 9 कंपनियों ने, जिनका 11 मिलों पर स्वामित्व था, 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा लाभांश बांटा था।

ऐसी कंपनी भी देखने में आई है जिन्होंने लाभांश के रूप में 365 प्रतिशत बांटा है। 1927 में नागपुर की इप्रेस मिल ने अपनी स्वयंजयती के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका में बड़े गव के साथ लिखा था

शुरू के 20 वर्षों के लाभांश को देखने से पता चलता है कि यह औसतन 16 प्रतिशत था और विश्वयुद्ध से पहले के वर्षों में व्यवसाय में जिस समय तजी आई थी, हिस्सेदारों को औसतन 23 प्रतिशत का लाभांश दिया गया। युद्ध के कारण आई तेजी के वर्षों में 90 प्रतिशत में अधिक लाभांश दिया गया लेकिन उन दिनों जिन पैमानों पर मुनाफा हुआ उससे इस राशि के दिए जाने का औचित्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। यह इच्छा श्री टाटा ने ही प्रकट की थी कि इप्रेस मिल को 100 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान करना चाहिए। हालांकि टाटा की मृत्यु के बाद तक लाभांश का यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। लेकिन इस कंपनी ने अपने सस्यापकों की परंपराओं का कितनी सफलतापूर्वक निर्वाह किया इसका पता हम आसानी से चला जाता है। 1919 में 500 रुपये के प्रत्येक साधारण शेयरों पर लाभांश 350 रुपये था लेकिन 1922 में यह राशि बढ़कर 525 रुपये हो गई हालांकि कंपनी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 1923 में सूती कंपनी व्यापार के क्षेत्र में मंदी और हड़तालों के कारण हुई गड़बड़ी के बावजूद प्रत्येक साधारण शेयर पर 380 रुपये के लाभांश का भुगतान किया गया।

व शेयरहोल्डर जिन्हें थोनास शेयर मिला था और जिस पर उन्हें वही लाभांश प्राप्त हुआ था, 1920 में यह जोड़ सकते थे कि वास्तविक लाभांश उन्हें 458 प्रतिशत मिला है

सामान्यतः यह काफी दिलचस्प बात है कि 30 जून 1926 तक इप्रेस मिल ने कुल 92,214,527 रुपये का मुनाफा कमाया जो मामूली शेयरहोल्डरों की कुल पूँजी का करीब 61.47 गुना होता है। इस अवधि तक कंपनी मामूली हिस्सेदारों को 59,431,267 रुपये का मुनाफा बांट चुकी है। इस प्रकार मूल पूँजी पर हिस्सेदारों को बांटे गए मुनाफे की दर 80.86 प्रतिशत सालाना बैठती है। इस प्रकार असली हिस्सेदार का फायदा हुआ है क्योंकि वह कंपनी की 500 रुपये की प्रदत्त पूँजी का शेयर लेने का सीमांत पाता है। उसको जो 2.05 का शेयर मिला है उसमें वर्तमान बाजार दर के आधार पर 7838 रुपये के बराबर की राशि मिलती है और इस प्रकार लाभांश के रूप में उसे 19,810 रुपये प्राप्त

होते हैं। ('दि इंप्रेस मिल्स, नागपुर, स्वर्णजयंती, 1877-1927', पृष्ठ 90-93)

मुनाफाखोरी का यह सिलसिला अनिश्चित काल तक नहीं चल सका हालांकि विश्वव्यापी आर्थिक संकट पैदा होने के समय तक असाधारण रूप से ऊँची दरें बनाई रखी गईं। इस प्रकार 1928, 1929 और 1930 में भी इंप्रेस मिल 28, 26 और 24 प्रतिशत का लाभान्न घोषित कर रही थी। पटसन के मामले में गौरपुर का प्रमुख कारखाना (जिसने 1918 में 250 प्रतिशत का मुनाफा अपने हिस्सेदारों में बाँटा था) 1927 में 100 प्रतिशत, 1928 में 60 प्रतिशत और 1929 में 50 प्रतिशत मुनाफा बाँट रहा था। कोयले के क्षेत्र में 1929 में चार प्रमुख कंपनियाँ 70,55,36 और 30 प्रतिशत मुनाफा बाँट रही थी। चाय के मामले में भारत में काम कर रही 98 कंपनियों ने 1928 में औसतन 23 प्रतिशत का लाभान्न घोषित किया और 1929 में 74 कंपनियों ने औसतन 20 प्रतिशत मुनाफा बाँटा।

आर्थिक संकट और आर्थिक मदों ने भारतीय उद्योग पर बहुत बुरा असर डाला। मुनाफा खोरी बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर और बबरतापूर्वक विभिन्न उद्योगों में तथा खासतौर पर वस्त्र उद्योग में छूटनी की गई और वेतन में कटौती की गई। कपास के क्षेत्र में 1922-23 में कुल खपत 47 लाख हज़ेड वेट थी जो 1934 में बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल खपत में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि रोजगार में लगे लोगों की संख्या 3 लाख 56 हजार से बढ़कर 4 लाख 14 हजार अर्थात् 16 प्रतिशत ही हुई। 1922-23 में कारखानों में पटसन की खपत 47 लाख गाँठ थी जो 1935-36 में बढ़कर 60 लाख गाँठ हो गई अर्थात् कुल खपत में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि रोजगार में लगे लोगों की संख्या 3 लाख 21 हजार से घटकर 2 लाख 78 हजार हो गई अर्थात् इसमें 13 प्रतिशत की कमी हुई। 1929-30 में रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 8 लाख 17 हजार थी जो 1936-37 में घटकर 7 लाख 10 हजार हो गई। 1921 में 1 करोड़ 91 लाख टन कायले का उत्पादन हुआ जो 1935 में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख टन हो गया जबकि कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 79 हजार हो गई।

युद्ध में पहले के वर्षों में मुनाफा कमाने के स्तर, हालांकि यह 1914-18 के बाद आई अतिशय वृद्धि के बराबर नहीं था, संतोषजनक चलता है कि असाधारण शोषण किया जाता था। इस प्रकार पटसन के क्षेत्र में रिलायंस जूट मिल्स कंपनी ने 1935 में अपने हिस्सेदारों को बीच 35 प्रतिशत 1936 में 42.5 प्रतिशत और 1937 में 30 प्रतिशत लाभान्न बाँटा। सूती उद्योग में म्यार मिल्स कंपनी ने 1935 में 35 प्रतिशत 1936 में 27.5 प्रतिशत तथा 1937 में 22.5 प्रतिशत लाभान्न दिया। चाय के क्षेत्र में यू.डब्ल्यू.टी. कंपनी ने 1935 और 1936 में 50 प्रतिशत लाभान्न बाँटा, नगाईमूव टी. कंपनी ने 1935 में 60 प्रतिशत और 1936 में 50 प्रतिशत लाभान्न बाँटा तथा ईस्ट इंडोपेस्टम कंपनी ने 1935 में 23 प्रतिशत 1936 में 33 प्रतिशत और 1937 में 40 प्रतिशत लाभान्न बाँटा। युद्ध के दौरान इन सभी

राशि व चावजूद मुनाफे में कई गुना वृद्धि हुई (देखें छाटा अध्याय, पृष्ठ 173-74)।

1914-18 के बाद व तीस वर्षों में वृद्धिशील मुनाफे से बर्माई गई राशि करोड़ों पौंड में थी। इस राशि में मजदूरों की आवास व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता था और सामाजिक संरक्षण तथा जन स्वास्थ्य की दिशा में ठोस मदद उठाए जा सकते थे। इस संबंध में कोई कदम उठाने की आवश्यकता भारत की तत्कालीन सरकार ने कभी महसूस नहीं की। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां धनिकवर्ग को इतनी आसानी से कर देने में छुट्टी दे दी जाती हो जबकि सबसे निधनवर्ग के कंधों पर कर का बोझा सबसे ज्यादा लाद दिया जाता हो। किसानों को मालगुजारी देनी पड़ती है जबकि जमींदारों की आमदनी को आयकर से छूट दे दी गई है। मजदूरों का अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्त कर देने पड़ते हैं जबकि ऊंची आमदनी वाले लोगों पर आयकर का भार बहुत हल्का रखा गया है। अप्रैल 1938 में भारत सरकार के वित्तीय सदस्य सर जेम्स प्रिंस ने कहा था कि अप्रत्यक्ष करारोपण का कुल वार्षिक भार प्रत्यक्ष करारोपण से आठ गुना अधिक है। 1936-37 में आयकर से हुई कुल आमदनी 1 करोड़ 15 लाख पौंड थी जो कुल राजस्व का 14वां भाग है और राष्ट्रीय आय का यह 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। इसकी तुलना में ब्रिटेन में आयकर, मृत्युकर तथा अधिभार से जो आय होती है वह कुल राष्ट्रीय आय के 10 प्रतिशत से भी अधिक है।

भारत में श्रमिक और सामाजिक कानून भी कम पिछड़े हुए नहीं हैं और बावजूद इन कानूनों का जो रूप है वह व्यवहार में नहीं है। इसी तरह का एक कानून फेक्टोरियों के बारे में है जो सबसे पहले 1881 में बना था। उस समय लकाशायर के मिलमालिक भारतीय मिल उद्योग के विप्लव को देखकर चिंतित हो उठे थे। कई दशकों तक यह कानून सरकारी फाइला में बंद पड़ा रहा हालांकि मजदूरों के हित के संदर्भ में इस कानून की बहुत सीमित भूमिका थी। इसकी असली रूप इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि इसको कार्यान्वित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

1905 के प्रारंभिक दिनों में भारत में कारखानों की जांच प्रणाली आशियन तौर पर छिन्न-भिन्न हो गई थी। उस समय एक कारखाना कानून भी था लेकिन कई मामलों में यह बिल्कुल बेकार था। कई शहरों में 79 कपड़ा मिलें थी जिनमें औसतन 1 लाख 14 हजार लोग रोजाना काम करते थे फिर भी बगई के कारखानों की जांच से संबंधित प्रत्येक अधिकारी का इन कारखानों को देखने की फुरसत नहीं थी। असिस्टेंट क्लर्क ही कारखानों का प्रधान निरीक्षक था। 1905 में इस कदम पर 6 जलम अलग-अलग व्यक्तियों ने काम किया। इन सारे व्यक्तियों को इस काम का कोई अनुभव नहीं था और सामान्य तौर पर अपने-अपने कामों में वे कारखानों की जांच की कोई गंभीर काम नहीं समझते थे। केवल एक इंस्पेक्टर ऐसा था जो वाटन एक्साइज ऐक्ट के अंतर्गत तैयार सामान की निगरानी के लिए

पूरा समय देता था। इसकी वजह यह थी कि सरकार इन सामानों के बकाया पर काफी ध्यान देती थी। स्वाभाविक है कि इस तरह की व्यवस्था में कारखाना कानून के प्रावधानों की उपेक्षा होनी ही थी। कतकता में कारखाने की जाच का काम असफल रहा और इसकी वजह से लगातार जो बुराईया पैदा हुईं उनके बारे में भी सभी लोग जानते हैं। द्वितीय फ़ैक्टरी लेबर कमीशन के सामने कलकत्ता के एक मिल मैनेजर ने बड़े साफ़ शब्दों में यह स्वीकार किया कि उसने कारखाना कानून पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक और मैनेजर ने, जिसके कारखाने में लगभग चार सौ बच्चे काम कर रहे थे, बताया कि उसने कभी यह मुना ही नहीं था कि कारखाना कानून के अंतर्गत बच्चा से मजदूरी कराने पर किसी तरह का प्रतिबंध है। (लोवाट फ़ैजर 'इंडिया अंडर वजन ऐंड आफ्टर', पृष्ठ 330-31)

यहां तक कि 1924 में भी बंबई के कलक्टर ने, जिसकी देखरेख में उस वर्ष के लिए कारखानों की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। (संयोगवश जिसमें यह बताया गया था कि व्यवहार रूप में प्रत्येक कारखाने में अनियमितताएं हैं), अपनी भूमिका में सरकार के दृष्टिकोण का इस प्रकार परिचय दिया

फ़ैक्टरीज ऐक्ट और इससे संबंधित नियमों के पालन पर बहुत जोर देने से, मेरे विचार में, उद्योग धंधों का नुकसान पहुंचेगा। इस कानून की वजह से किसी विशेष काम के आने पर मालिक और कर्मचारी दोनों के लिए छुट्टी के दिनों में या ओवरटाइम घंटों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जो कर्मचारी समय से ज्यादा काम करना चाहते हैं उनसे काम लेने में कोई नुकसान नहीं है। उन्हें ओवरटाइम का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इस विभाग की यह नीति रही है कि वह उचित छूटों की सिफारिश करे। (बंबई प्रेसीडेंसी की वार्षिक कारखाना रिपोर्ट, 1924—बंबई के कलक्टर की भूमिका)

वर्तमान 1934 का कारखाना कानून (फ़ैक्टरीज ऐक्ट आफ 1934) स्थाई कारखानों के लिए अर्थात् बारह महीने चलने वाले कारखानों के लिए दस घंटे का दिन और 54 घंटे का सप्ताह तथा सीजनल कारखानों (जो छ महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं) के लिए 11 घंटे का दिन (महिलाओं के लिए दस घंटे) और 64 घंटे का सप्ताह निर्धारित करता है। इस 11 घंटे को अधिक से अधिक 13 घंटा किया जा सकता है लेकिन इसके साथ ओवर टाइम की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं से रात में काम लेने पर रोक है। बारह साल से कम उम्र के बच्चों का नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता और 12 से 15 साल के बच्चों से दिन में पांच घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। इस समय का बड़ाकर अधिक से अधिक साढ़े सात घंटे किया जा सकता है। इस कानून से केवल 25 लाख मजदूर प्रभावित होते हैं (1944)।

1935 के माइस ऐक्ट में जमीन के ऊपर काम करने की सीमा 10 घंटे और जमीन से नीचे काम करने की सीमा 9 घंटे निर्धारित की गई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों से नौकरी कराने पर पाबंदी है। इस कानून से 25 लाख मजदूर प्रभावित होते हैं। 1937 में जमीन के नीचे खानों में महिलाओं में काम कराने पर पाबंदी थी लेकिन 1943 में एक अध्यादेश के जरिए इस पाबंदी को तब तक के लिए हटा दिया गया जब तक युद्ध जारी है। रेल कमचारियों के लिए काम की निर्धारित अवधि 60 घंटे प्रति सप्ताह है।

1931 के इंडियन पाट्स ऐक्ट के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। इस कानून के द्वारा गोदी कमचारियों की सुरक्षा के भी सीमित उपाय प्रदान किए गए। 1934 का कंक्मस कंसेशन ऐक्ट के ताले में लगभग 60 लाख मजदूर आते हैं लेकिन दडित हान के भय से इन प्रावधानों का बहुत सीमित अंश में लाभ उठाया गया। 1936 के पमेट आफ वंजेज ऐक्ट के अनुसार वेतन देने की अधिकतम अवधि एक महीना निर्धारित की गई (साप्ताहिक या पाक्षिक वेतन की बात नामजूर कर दी गई) और कहा गया कि महीना खतम हान के एक सप्ताह के अंदर वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। इसमें जुर्माना करने और मनमाने ढंग से कटौती करने की भी सीमा निर्धारित की गई। इन तथ्यों में यह देखा जा सकता है कि भारत में मजदूरों से संबंधित कानून किस हद तक सीमित है।

मजदूरों से संबंधित सारे उन कानूनों को ध्यान में रखें जो कारखानों, खानों, बागानों, गोदियों, रेलों, बंदरगाहों आदि को प्रभावित करते हैं, तो हम बात में सदेह है कि इन कानूनों से बाहर के 70 या 80 लाख मजदूरों को भी कोई लाभ मिलता होगा। शेष मजदूर, जो औद्योगिक मजदूरों की एक और विशाल संख्या है, छोटे उद्योगों में या अनियमित उद्योगों में लगे हैं। (शिवराव 'दि इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया', 1939, पृष्ठ 210)

कारखानों से संबंधित प्रमुख कानून को 1944 में व्यापक बनाया गया जिसके दायरे में केवल 2,522,753 मजदूर आते हैं जो भारतीय मजदूरवर्ग का एक मामूली हिस्सा है। यहाँ भी इन कानूनों का लागू करने की अक्षम व्यवस्था से इसकी प्रभावकारिता कम ही होती है। 1944 में फक्टरीज ऐक्ट के तहत 14,071 कारखाने रजिस्टर्ड थे। इनमें से केवल 11,713 कारखानों का अर्थात् 83.2 प्रतिशत कारखानों का निरीक्षण किया गया। 2358 कारखाने ऐसे थे जिनका साल में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया और ऐसे कारखानों की भी संख्या काफी अधिक थी जिनका साल में केवल एक बार निरीक्षण किया गया। फलस्वरूप इन कानूनों की प्रभावकारिता की कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि इन कानूनों का उल्लंघन करने के जो 1,775 मामले सामने आए उनपर बहुत कम जुर्माना किया गया जिससे प्रत्यक्ष रूप में कानूनों का उल्लंघन करने की प्रेरणा ही मिली थी। संयुक्त प्रांत की एक रिपोर्ट में यह धारणा व्यक्त की गई (इस धारणा से



भाग से ज्यादा आमदनी होती है पर सिविल लाइस पर जितना धन खर्च किया जाता है वह शहर की तुलना में काफी अधिक होता है। इसकी वजह यह है कि सिविल लाइस के काफी बड़े इलाके के लिए अपेक्षाकृत अधिक सड़क की जरूरत होती है और उनकी मरम्मत तथा सफाई करनी पड़ती है, उनपर रोशनी का इंतजाम करना पड़ता है तथा पानी का छिड़काव किया जाता है। यहां की जल निकासी, जल सप्लाई और सफाई की व्यवस्था ज्यादा भ्रष्ट होती है। शहर के हिस्से की हमेशा ही काफी उपेक्षा की जाती है और शहर का वह इलाका जो काफी निधन है बिल्कुल ही उपेक्षित रहता है। इस इलाके में अच्छी सड़कें गिनी चुनी होती हैं और यहां की अधिकांश सड़कें गलियों में न तो बिजली की उचित व्यवस्था होती है और न जलनिकासी या सफाई का ही कोई इंतजाम किया जाता है। (जवाहरलाल नेहरू, 'आत्मकथा' पृष्ठ 143)

नेहरू ने जमीन के मूल्य पर टैक्स लगाने की प्रणाली शुरू करना चाही ताकि सम्भावित सुधार किए जा सकें लेकिन उनके इस काम में फौरन ही जिलाधीश ने टांग बड़ा दी और कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव जमीन की काश्त से संबंधित विभिन्न शर्तों या अधिनियमों के विरोध में हो जाएगा, इस तरह के टैक्स से सबसे ज्यादा बड़ी लोग प्रभावित होते जिनके बड़े बड़े बगले सिविल लाइस में बने हैं। इस प्रकार 'सुमस्कृत' ब्रिटिश राज के प्रबुद्ध संरक्षण में भारतीय मजदूरों की गंदगी भरी स्थितियां, असौम्य शोषण और दासता की स्थितियों का बहुत उत्साह के साथ बरकरार रखा गया। अपने साफ सुथरे और पूर्ण रूप से सुरक्षित महलों में अगरज शासकों ने गंदगी और यातना के साम्राज्य पर शासन किया।

हावड़ा और उत्तरी कलकत्ता की मजदूर वस्तियों में गंदगी, दुर्गंध और सड़ाघ का जो वातावरण है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जूट मिला में काम करने वाले अधिकांश मजदूर इन प्राइवेट वस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। बंगाल म्यूनिसिपलिटिज ऐक्ट के तहत इन गंदी वस्तियों के विकास का दायित्व इन वस्तियों के मालिकों पर है जो इनमें रहने वाले गरीबों से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। लेकिन निहित स्वार्थी तत्व हमेशा इस घात में रहते हैं कि इन कानूनों को कभी अमल में न आने दिया जाए। इन वस्तियों की दुदशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 'दुर्गंध और बीमारियों से भरी शोषणियां हैं जिनमें न तो कोई खिडकी है और न कमरे से घुआ निकलने के लिए कोई चिमनी है। इनके दरवाजे इतने नीचे हैं कि अंदर घुसने के लिए लगभग घुटने के बल रेंगना पड़ता है। इनमें बिजली पानी का और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। इन वस्तियों में पहुंचने के लिए आमतौर से बदबू भरी एक सुरंग से गुजरना पड़ता है जिसमें साल भर और खासतौर से बरसात के दिनों में मच्छरों और मक्खियों के झुंड के झुंड पतत और भिनभिनाते रहते हैं।



बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नगरपालिका हावड़ा नगरपालिका है जहाँ की हालत कनकता के उत्तरी उपनगरी से भी बदतर है। यहाँ की जमीन बहुत मृगी है और उसमें उपलब्ध हर फुट भर जमीन पर भी निमाण किया जा चुका है। जिन गलियों के दोनों तरफ ये बस्तिया बसाई गई हैं, वे अधिक से अधिक 3 फीट चौड़ी हैं लेकिन इन गलियों के साथ साथ खुले गंगे नाले भी हैं और यही स्थिति कारखाने वाले प्रत्येक इलाक़ की है। (शिवराव दि 'इंडस्ट्रियल वकर इन इंडिया', पृष्ठ 113-14)

जूट मिल के मजदूरों के जीवनयापन की यही स्थिति है। इन मजदूरों की महन्त से हुए शत प्रतिशत मुनाफ़े का फायदा अगरेजों द्वारा संचालित कपनिया उठाती हैं। यह मुनाफ़ा मूल पूँजी से कई गुना अधिक होता है।

यह रही भारतीय मजदूर आंदोलन की पृष्ठभूमि। समाजवाद और ट्रेड यूनियन की भावना से दुदशाग्रस्त स्थिति में जीवन बिताने वाले मजदूरों के बीच पहली बार आशा और विश्वास की किरणें फूटीं, मजदूरों ने पहली बार एकजुटता की ताकत का एहसास किया और उन्हें पहली बार अपने सामने एक ऐसा लक्ष्य दिखाई दिया जिसकी प्राप्ति से उनके सारे दुःख दूर हो सकते हैं।

### 3 मजदूर आंदोलन की स्थापना

भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी लेकिन एक संगठित आंदोलन के रूप में उसका निरंतर इतिहास प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही शुरू होता है। 19वीं सदी के आठवें दशक में जब देश में कारखानों की स्थापना हो गई तब हड़ताल होना भी अवश्यभावी हो गया हालांकि शुरू में इसका रूप बहुत प्रारंभिक और असंगठित था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि मजदूरों की दर का प्रश्न का लेकर 1877 में नागपुर की इप्रेस मिल में हड़ताल हुई थी। 1882 से लेकर 1890 के बीच बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी में हुई 25 हड़तालों का उल्लेख भी मिलता है।

भारत में मजदूर आंदोलन के प्रचलित इतिहास के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसकी शुरुआत 1884 में बंबई के मिल मजदूरों की बैठक से होती है जिसका आयोजन एन० एम० लोखंडे नामक एक स्थानीय संपादक ने किया था। श्री लोखंडे ने मजदूरों की मांगों का एक पापन तैयार किया था जिसमें काम के घंटों को सीमित करने, साप्ताहिक अवकाश देने, दीपहर में छाने की छुट्टी देने और घायल होने की अवस्था में मुआवजा देने की मांगें शामिल थीं। यह पापन इन मिल मजदूरों की तरफ से कारखानों के कमिश्नर को दिया जाना था। लोखंडे ने अपने को बंबई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहा था। आमतौर पर इस संगठन को भारत का पहला मजदूर संगठन कहा जाता है। लोखंडे साहब ने बाद में 'दीनचधु' नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया।

श्री लोखंडे की गतिविधियों की जा जानकारी हम उपलब्ध है उसका भारतीय मजदूर आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन यह मान लेना बहुत भ्रामक बात है कि भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत लोखंडे ने की। हम आगे चलकर बार बार यह देखेंगे कि इस आंदोलन का चरित्र भी काफी भ्रामक था। 'बंबई मिल मजदूर एसोसिएशन' (बांबे मिल हैंड्स एसोसिएशन) किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं था। इसके न तो सदस्य थे, न कोई नियम थे और न इसका कोई कोष था। 'बंबई मिलमजदूरों का कोई संगठित मजदूर आंदोलन नहीं था। यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि हालांकि श्री एन० एम० लोखंडे, जिन्होंने पिछले फैक्टरी आयोग में काम किया था खुद को बंबई मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते थे लेकिन इस एसोसिएशन का कोई संगठित अस्तित्व न था। इसका एक भी सदस्य नहीं था। नहीं कोई इसका अपना कोष था और न कोई कायदा कानून था। मेरा खयाल है कि श्री लोखंडे ने स्वेच्छा से ऐसे सलाहकार का काम किया था जिससे कोई भी मिलमजदूर उनसे आकर सलाह ले सके।' (रिपोर्ट ऑन दि बकिंग आफ दि फैक्टरी एक्ट इन बांबे फार 1892, पृष्ठ 15) लोखंडे साहब एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति थे जो मजदूरों की भलाई चाहते थे और इस कोशिश में रहते थे कि मजदूरों के हित में कानून बनवाए जाए। वह मजदूरों के संगठन या मजदूरों के संघ के अग्रदूत नहीं थे।

भारत में मजदूर आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए 19वीं सदी के नवें दशक और उसके बाद के वर्षों में हुई हड़तालों से संबंधित दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालांकि उस समय तक मजदूरों के किसी संगठन का अस्तित्व नहीं था फिर भी 1914 के युद्ध पूर्व के दशकों के दौरान भारतीय औद्योगिक मजदूरों की प्रारंभिक वगैरह बातों के विकास और उनकी संगठित शक्ति के विकास को कम करके आफना गलत होगा। 1895 में बम्बई जूट मिल के डायरेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'उह इस बात का खेद है कि इन छ महीना के दौरान मजदूरों ने एक बार हड़ताल की जिसकी वजह से छ हफ्ते तक मिल की बंद रचना पड़ा।' इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि 1895 में अहमदाबाद में 8 हजार बुनकरों ने अहमदाबाद के मिलमालिक संघ (अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन) के खिलाफ हड़ताल की थी। (बांबे फैक्टरी रिपोर्ट, 1895)

1880 से 1908 के बीच विभिन्न आयोगों के सामने प्रस्तुत की गई सभी गवाहियां में यह बात कही गई कि मजदूरों की अभी तक कोई वास्तविक यूनियन नहीं है। अनेक गवाहियों में लोगों ने यह भी बताया कि बहुधा अलग अलग मिलों के मजदूर आपस में एक साथ मिल जाते हैं और एक गुट के रूप में वे काफी स्वतंत्र हैं। 1892 में वायलर के इन्स्पेक्टर ने बताया था कि 'मजदूरों में एक अजीब विस्म की एकता दिखाई देती है जिसको न तो कोई खास नाम दिया जा सकता और न जिसके बारे में किसी तरह की लिखा पड़ी है। बंबई के कलक्टर ने लिखा था कि 'हालांकि यह एकता केवल वायवीय' है फिर भी यह काफी शक्तिशाली' है।

बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नगरपालिका हावड़ा नगरपालिका है जहाँ की हालत कलकत्ता व उत्तरी उपनगरों से भी बदतर है। यहाँ की जमीन बहुत महंगी है और उसमें उपलब्ध हर फुट भर जमीन पर भी निर्माण किया जा चुका है। जिन गलियों के दानों तक यहाँ बस्तियाँ बनाई गई हैं, वे अधिक से अधिक 3 फीट चौड़ी हैं लेकिन इन गलियों के साथ साथ घुले गंदे नाले भी हैं और यही स्थिति कारखाने वाले प्रत्यक्ष इलाक़ों की है। (शिवराव दि 'इंडस्ट्रियल वरकर इन इंडिया', पृष्ठ 113-14)

जूट मिल के मजदूरों के जीवनयापन की यही स्थिति है। इन मजदूरों की मेहनत से हुए शत प्रतिशत मुनाफ़े का फायदा अंगरेजों द्वारा संचालित कंपनियाँ उठाती हैं। यह मुनाफ़ा मूल पूँजी से कई गुना अधिक हाता है।

यह रही भारतीय मजदूर आंदोलन की पृष्ठभूमि। समाजवाद और ट्रेड यूनियन की भावना से दुर्दशाग्रस्त स्थिति में जीवन बिताने वाले मजदूरों के बीच पहली बार आशा और विश्वास की किरणें फूटी, मजदूरों ने पहली बार एकजुटता की ताकत का एहसास किया और उन्हें पहली बार अपने सामने एक ऐसा लक्ष्य दिखाई दिया जिसकी प्राप्ति से उनके सारे दुःख दूर हो सकते हैं।

### 3 मजदूर आंदोलन की स्थापना

भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी लेकिन एक संगठित आंदोलन के रूप में उसका निरंतर इतिहास प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही शुरू होता है। 19वीं सदी के आठवें दशक में जब दश में कारखानों की स्थापना हो गई तब हड़ताल होना भी अवश्यभावी हो गया हालाँकि शुरू में इसका रूप बहुत प्रारम्भिक और असंगठित था। इस बात का उल्लेख मिलता है कि मजदूरों की दर के प्रश्न को लेकर 1877 में नागपुर की इंग्रेस मिल में हड़ताल हुई थी। 1882 से लेकर 1890 के बीच बंबई और मद्रास प्रेसीडेन्सी में हुई 25 हड़तालों का उल्लेख भी मिलता है।

भारत में मजदूर आंदोलन के प्रचलित इतिहास के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसकी शुरुआत 1884 में बंबई के मिल मजदूरों की बैठक से होती है जिसका आयोजन एन० एम० लोखंडे नामक एक स्थानीय संपादक ने किया था। श्री लोखंडे ने मजदूरों की माँगों का एक ज्ञापन तैयार किया था जिसमें काम के घंटों को सीमित करने, साप्ताहिक अवकाश देने, दोपहर में खान की छुट्टी देने और घायल होने की अवस्था में मुआवज़ा देने की माँगें शामिल थीं। यह ज्ञापन इन मिल मजदूरों की तरफ से कारखानों के कमिश्नर को दिया जाना था। लोखंडे ने अपने को 'बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष' कहा था। आमतौर से इस संगठन को भारत का पहला मजदूर संगठन कहा जाता है। लोखंडे साहब ने बाद में 'दीनबन्धु' नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया।

श्री लोखंडे की गतिविधियों की जो जानकारी हम उपलब्ध है उसका भारतीय मजदूर आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन यह मान लेना बहुत भ्रामक बात है कि भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत लोखंडे ने की। हम आगे चलकर बार बार यह देखेंगे कि इस आंदोलन का चरित्र भी काफी भ्रामक था। बंबई मिल मजदूर एसोसिएशन' (बांबे मिल हेड्स एसोसिएशन) किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं था। इसके न तो सदस्य थे, न कोई नियम थे और न इसका कोई कोष था। बंबई मिलमजदूरों का कोई संगठित मजदूर आंदोलन नहीं था। यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि हालांकि श्री एन० एम० लोखंडे, जिन्होंने पिछले फैक्टरी आयोग में काम किया था, खुद को बंबई मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते थे लेकिन इस एसोसिएशन का कोई संगठित अस्तित्व नहीं था। इसका एक भी सदस्य नहीं था। नहीं कोई इसका अपना कोष था और न कोई कायदा कानून था। मेरा खयाल है कि श्री लोखंडे ने स्वेच्छा से ऐसे सलाहकार का काम किया था जिससे कोई भी मिलमजदूर उनसे आकर सलाह ले सके।' (रिपोर्ट ऑन दि वर्किंग आफ दि फैक्टरी ऐक्ट इन बांबे फार 1892, पृष्ठ 15) लोखंडे साहब एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति थे जो मजदूरों की भलाई चाहते थे और इस कोशिश में रहते थे कि मजदूरों के हित में कानून बनवाए जाए। वह मजदूरों के संगठन या मजदूरों के मध्य के अग्रदूत नहीं थे।

भारत में मजदूर आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए 19वीं सदी के नवें दशक और उसके बाद के वर्षों में हुई हड़तालों में संबंधित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालांकि उस समय तक मजदूरों के किसी संगठन का अस्तित्व नहीं था फिर भी 1914 के युद्ध पूर्व के दशकों के दौरान भारतीय औद्योगिक मजदूरों की प्रारंभिक वर्ग चेतना के विकास और उनकी संगठित शक्ति के विकास को कम करके आकना गलन होगा। 1895 में वनब्रज जूट मिल के डायरेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'उह इस बात का खेद है कि इन छ महीनों के दौरान मजदूरों ने एक बार हड़ताल की जिसकी वजह से छ हफ्ते तक मिल की बंद रखना पड़ा।' इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि 1895 में अहमदाबाद में 8 हजार बुनकरों ने अहमदाबाद के मिलमालिकों से (अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन) के खिलाफ हड़ताल की थी। (बांबे फैक्टरी रिपोर्ट, 1895)

1880 से 1908 के बीच विभिन्न आयोगों के सामने प्रस्तुत की गई सभी गवाहियों में यह बात बही गई कि मजदूरों की अभी तक कोई वास्तविक यूनियन नहीं है। अनेक गवाहियों में लोगोंने यह भी बताया कि बहुधा अलग अलग मिलों के मजदूर आपस में एक साथ मिल जाते हैं और एक गुट के रूप में वे काफी स्वतंत्र हैं। 1892 में वायलरा के इन्स्पेक्टर ने बताया था कि 'मजदूरों में एक अजीब विस्म की एकता दिखाई देती है जिसको न तो कोई खास नाम दिया जा सकता और न जिसके बारे में किसी तरह की लिखा पड़ी है। बंबई के क्लर्क ने लिखा था कि हालांकि यह एकता केवल बायबीय' है फिर भी यह काफी शक्तिशाली है।

उन्होंने सरकार को लिखा कि मेरा खयाल है कि काफी अरमे से इनकी मजदूरी का एक ही स्तर पर बने रहना या मजदूरी के मामले में इनके एकाधिकार का बना रहना इसी कारण संभव हो सका है क्योंकि इनके बीच काफी एकजुटता है।' 1908 में सर सेमून डेविड ने कहा कि 'यदि मजदूरों का कोई उचित संगठन नहीं है तो भी उनकी एक आपसी समझदारी है।' बंबई प्रेसीडेंसी में उद्योगों के डायरेक्टर श्री वरदा ने कहा कि 'मालिकों की तुलना में मजदूरों की ताकत काफी अधिक है और हालांकि उनकी कोई यूनिफा नहीं है लेकिन वे आपस में एकजुट हो सकते हैं'। इन वक्तव्यों में यदि किसी सीमा तक अतिशयोक्ति है तो वर्धा स्थित ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने तो अपने इस कथन से बमाल ही कर दिया कि 'चारों तरफ मजदूर हावी हो गए हैं और अब मजदूरों की वजह से मिलमालिकों की हिफाजत का इतना काम करने की जरूरत है।' (डी० एच० बुकानन, दि डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, पृष्ठ 425)।

इन शब्दों से पता चलता है कि भारतीय मजदूरों की उभरती हुई वगचेतना को देखकर मालिकों में दहशत फैल गई थी।

1905-1909 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की जुझारू लहर के समानांतर मजदूर आंदोलन ने भी उल्लेखनीय प्रगति की। इन वर्षों के स्वरूप का पता इससे ही चल जाता है कि काम के घटे बढ़ने व विरोध में बंबई के मिलमजदूरों ने हड़ताल की, रेल कमचारियों ने खासतौर से ईस्टन बंगाल स्टेट रेलवे कमचारियों ने कई बार गंभीर हड़तालों की रेल के कारखानों में हड़तालें हुई और कलकत्ता के गवर्नमेंट प्रेस में वहां के कमचारियों ने हड़ताल की। हड़तालों की यह लहर अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुंच गई जब 1908 में तिलक को छ वर्षों की सजा दिए जाने के विरोध में बंबई के मजदूरों ने छ दिनों की सांख्यिक राजनीतिक हड़ताल कर दी।

फिर भी अभी तक मजदूरों का कोई ठोस संगठन बनना संभव नहीं हो सका था। इसका कारण यह नहीं था कि मजदूरों की चेतना पिछड़ी हुई थी या उनमें जुझारूपन की कमी थी बल्कि इसकी वजह केवल यही थी कि भारत के मजदूर बेहद गरीब और निरक्षर थे तथा उनके पास साधनों का अभाव था। संगठन की संभावनाएं अब भी अम तत्वा के हाथ में थी। 1910 में बंबई में कुछ परोपकारियों ने मजदूरों के हित के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम 'कामगार हितवधक सभा' था। इस संस्था का उद्देश्य मजदूरों और मालिकों के बीच उत्पन्न विवाद हल करने के लिए सरकार के समक्ष याचिकाएं पेश करना था। सामान्य अर्थों में 1914 से पहले मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल यूरोपीय और आंग्ल भारतीय रेल कमचारियों तथा सरकारी कमचारियों के ऊपरी तबके तक सीमित था। इस प्रकार 1897 में 'अमलगामेंटड सोसाइटी आफ रेलवे सर्वेंट्स' नामक संस्था की स्थापना हुई जिसे कंपनोज ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। मूलतः इसका

काम आपसी लाभ तक सीमित था और हालांकि आज भी इसका अस्तित्व है (1928 में इसने अपना नाम बदलकर नेशनल यूनियन ऑफ रेलवेमैन रख लिया) लेकिन भारत के मजदूर आंदोलन में इसने कोई भी भूमिका नहीं अदा की।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी और रूसी क्रांति तथा इसके फलस्वरूप समूचे विश्व में जो क्रांतिकारी लहर आई थी उसने भारत के मजदूरवर्ग को भी पूरी तरह सक्रिय बना दिया और भारत में आधुनिक मजदूर आंदोलन का सूत्रपात किया। इन बातों के साथ-साथ इस नई जागृति में आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने भी भरपूर योगदान किया। युद्ध के दिना में चीजाँ की कीमतें दुगुनी हो गई थी, इस मूल्यवृद्धि के अनुरूप वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई और मिलमालिकों ने वेतनहारा मुताफा कमाया। राजनीतिक क्षेत्र में नई मार्गों सामने आने लगी थी। देश को तुरंत स्वराज्य दिए जाने के कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित हो गई थी। क्रांतिकारी चेतना की पहली लहरें भारत में पहुंचने लगी थी।

1918 में हड़तालों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1919 और 1920 में पूरी तेजी के साथ समूचे देश में फैल गया। 1918 के अंतिम दिनों में बंबई में सूती कपड़ामिलों में जबरदस्त हड़ताल हुई जिसके कारण औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर में समूचा उद्योग ठप हो गया। 1919 की जनवरी तक 1 लाख 25 हजार मजदूर, जो सभी मिलों का प्रतिनिधित्व करते थे, एक तरह से बिल्कुल बाहर निकल आए। 1919 के वसंत में रौलट ऐक्ट के खिलाफ मजदूरों ने एक शानदार हड़ताल करके यह दिखा दिया कि देश का मजदूरवर्ग राष्ट्रीय संघर्ष में भी आगे के मोर्चे पर है। 1919 में देश भर में हड़तालों का ताता लग गया। 1919 की समाप्ति तक और 1920 के शुरू के छ महीनों में हड़तालों की लहर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई।

इस अवधि में जितनी हड़तालें हुई और ये हड़तालें जितनी तीव्रता के साथ हुई उसका अंदाजा नीचे दिए गए आंकड़े में लग सकता है।

4 नवंबर से 2 दिसंबर 1919 तक कानपुर की ऊनी मिला के 17 हजार मजदूर हड़ताल में शामिल हुए, 7 दिसंबर 1919 से 9 जनवरी 1920 तक जमालपुर के 16 हजार रेल मजदूरों ने हड़ताल की, 1920 में 9 जनवरी से 18 जनवरी तक पल्लवता के 35 हजार जूट मिलमजदूरों ने हड़ताल की, 2 जनवरी से 3 फरवरी तक बंबई में मजदूरों की आम हड़ताल रही जिसमें 2 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। 20 जनवरी से 31 जनवरी तक रंगून के 20 हजार मिलमजदूरों ने काम बंद रखा। 31 जनवरी को बंबई में ब्रिटिश इंडिया नेवीगेशन कंपनी के 10 हजार मजदूरों ने हड़ताल की 26 जनवरी से 16 फरवरी तक झोलापुर के 16 हजार मिनमजदूरों ने हड़ताल की, 2 फरवरी से 16 फरवरी तक इंडियन मेरी टाइम वर्क

के 20 हजार कमचारियों ने काम बंद रखा, 24 फरवरी से 29 मार्च तक टाटा आयरन एंड स्टील के 40 हजार मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया, 9 मार्च को बजई के 60 हजार मिलमजदूरों ने काम बंद रखा, 20 मार्च से 26 मार्च तक मद्रास के 17 हजार मिलमजदूरों ने हड़ताल की, मई 1920 में अहमदाबाद के 25 हजार मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। (आर०के० दास 'दि लेबर मूवमेंट इन इंडिया', 1923, पृष्ठ 36-37)

1920 के शुरू के छ महीने में 200 हड़तालों हुईं जिनमें 15 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया।

यही वह परिस्थितियाँ थीं जिनमें भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्म हुआ। प्रमुख उद्योगों और औद्योगिक केंद्रों की अधिकांश ट्रेड यूनियनों इसी दौरान बनीं हालांकि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण ये संगठन स्थायी रूप से नहीं चल पाए। जुम्हारूपन के इस महान दौर में ही आधुनिक भारत के मजदूर आंदोलन का उदय हुआ।

इन वर्षों के दौरान काफी बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ तो बुनियादी तौर पर महज हड़ताल समितियाँ थीं। इनका उद्देश्य फौरी तौर पर संघों को चलाना होता था और ये बनी रहना नहीं चाहती थीं। मजदूरवर्ग तो संघों के लिए तैयार रहता था लेकिन यूनियन के कार्यालय संबंधी काम लाजिमी तौर पर दूसरों को ही करने थे। इसलिए शुरू के दिनों में मजदूर आंदोलन में एक अंतर्विरोध पैदा हो गया। इस समय तक देश में समाजवाद के आधार पर, मजदूरवर्ग के विचारों तथा वर्गसंघर्ष की भावना पर आधारित कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं तैयार हो सका था। नतीजा यह हुआ कि दूसरे वर्ग से बाहरी तत्व या मददगार लोग विभिन्न कारणों ने प्रेरित होकर मजदूरों के संगठनों की सहायता के लिए आए और इन प्रारंभिक दिनों में वस्तुतः इनकी सहायता अपरिहार्य भी थी लेकिन इनमें मजदूर आंदोलन के उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की कोई समझ नहीं थी। अपने साथ ये लोग मध्यवर्गीय राजनीति के विचार लेकर आए थे। उनमें से कुछ भले ही परांपकार की भावना से आए रहे हों या कुछ महज अपना राजनीतिक जीवन बनाने की लालसा लेकर आए रहे हों अथवा कुछ ऐसे लोग भी रहे हों जो मजदूर आंदोलन में शामिल होकर देश के राजनीतिक संघर्ष का आग बढाना चाहते रहे हों लेकिन इन सबका दृष्टिकोण एक दूसरे वर्ग का दृष्टिकोण था और इसीलिए वे वर्ग संघर्ष की लड़ाई में जुट मजदूरों का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। भारत का मजदूर आंदोलन काफी दिनों तक इस दुर्भाग्य का शिकार रहा और इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ने मजदूरों की शानदार जुझारू भावना और बहादुरी की वृद्धि में काफी बाधा डाली और उसका असर आज भी बरकरार है।

आमतौर पर यह समझा जाता है कि यहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत मद्रास लेबर

यूनियन से हुई जिसका गठन 1918 में वी० पी० वाडिया ने किया था। श्री वाडिया, थियोसाफिस्ट श्रीमती वेसेंट के सहयोगी थे। भारतीय मजदूर आंदोलन के वर्तमान इतिहास को देखते हुए यह बात कुछ भ्रामक लगती है। इस अवधि में देश भर में ट्रेड यूनियन बनाने की पहली कोशिशें जारी थी। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि 1917 में अहमदाबाद की सूती कपड़ा मिलों में ताना बाना बुनने वाले लोगों ने (वापस ने) अपनी एक यूनियन बना ली थी। लेकिन इस समय तक मगठन का आधार बहुत कमजोर था और जहां तक मजदूरवर्ग के जुझारूपन का और उसकी क्रियाशीलता का संबंध है, यह मगठन काफी कमजोर था। इसमें कोई शक नहीं कि मद्रास लेबर यूनियन ही ऐसा पहला मजदूर संगठन था जो काफी सुव्यवस्थित था। उसके पास काफी सदस्य थे और उनसे चंदा लिया जाता था। इस पहल के लिए इसके संगठनकर्ताओं का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन अपेक्षाकृत कमजोर औद्योगिक क्षेत्र में (1921 से 1933 के दौरान यहां केवल 28 लाख दिन हड़ताल हुई थी जबकि बंगाल और बंबई में हड़ताल क्रमशः 2 करोड़ दिन और 6 करोड़ दिन तक ही थी। इस पहल से पता चलता है कि यहां मजदूरों की यूनियन संयोगवश और बिना ही व्यक्तिगत कारणों से बन गई थी और भारत के मजदूर आंदोलन के विकास में उसके महत्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना ठीक नहीं होगा। इस यूनियन के संस्थापक वी० पी० वाडिया का दृष्टिकोण कितना सीमित था, इसका पता एक घटना से चल जाता है। अप्रैल 1918 में श्री वाडिया की अध्यक्षता में यूनियन की स्थापना के बाद मद्रास के मजदूरों ने अपनी कुछ मांगों को मालिकों के सामने रखी और मांगें नामजूर हो जाने के बाद उन्होंने हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा लेकिन वाडिया साहब ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसके लिए यह तर्क दिया कि मजदूरवर्ग को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए (राष्ट्रीय आंदोलन में श्रीमती वेसेंट का भी यही रुख था)। श्री वाडिया ने 3 जुलाई 1918 को दिए गए अपने भाषण में कहा

यदि हड़ताल करके आप लोग सिर्फ मेसर्स बिल्ली एंड कंपनी का नुकसान करते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि यह कंपनी काफी पैसों कमा रही है लेकिन हड़ताल से आप मित्र राष्ट्रों को नुकसान पहुंचाएंगे। हम अपने सैनिकों के लिए कपड़े तैयार करने हैं और आपकी हड़ताल से उन सैनिकों के लिए असुविधा होगी। महज इसलिए कि इस मिल से संबंधित कुछ यूरोपीय और सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, हमें उन लोगों को तकलीफ में डालने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे राजा की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम हड़ताल नहीं करनी चाहिए।

वाडिया साहब हड़ताल को रोकने में सफल रहे पर मेसर्स बिल्ली एंड कंपनी पर वाडिया के 'देशभक्तिपूर्ण' तर्कों का कोई असर नहीं पड़ा और उसने तालाबंदी की घोषणा कर दी। मजदूरों ने हमले के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने वाडिया साहब की सलाह पर हड़ताल का अपना हथियार छांट ही दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें मजदूरों



अपनी मांगों को फिलहाल छोड़ देना पड़ा। मद्रास में असली लड़ाई 1921 में हुई जब मिलो में तालाबदी के बाद हड़ताल हुई। कंपनी मामले को अदालत में ले गई और हाई कोर्ट ने यूनियन पर 7000 पौंड का जुर्माना किया। कंपनी ने शत रखी कि यदि वाडिया अपने का मजदूर आंदोलन से अलग कर ले तो यूनियन से यह जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। वाडिया को मजदूर हाकर मजदूर आंदोलन से खुद को अलग कर लेना पड़ा। प्रारंभिक दिनों में भारत के मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया, इसका यह बहुत सटीक उदाहरण है।

अब केंद्रों में मजदूर संगठन की जिम्मेदारी उठान के लिए अनेक तरह के मददगार सामने आए। इनमें से कुछ का मालिकों के साथ घनिष्ठ संबंध था। अहमदाबाद में गांधी ने मित्रमालिका की मदद से एक भिन्न मतावलंबी यूनियन बनाई जिसका उद्देश्य वग शांति कायम करना था और आज तक अहमदाबाद लेकर एशोसिएशन भारतीय मजदूर आंदोलन से बंटा हुआ है।

इसी दिनों 1920 में इटियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन 1920 के अक्टूबर में बंबई में हुआ जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय नेता लाजपतराय न और उपाध्यक्षता जोसेफ बेप्टिस्टा ने की। अपने शुरू के वर्षों में यह संस्था केवल 'उच्च वर्ग' के नेताओं का संगठन थी और उसके बहुत में नेताओं का मजदूर आंदोलन से बड़ा सीमित संबंध था। उसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य प्रेरणा काम कर रही थी, वह यह थी कि इस संगठन के आधार पर कुछ सदस्यों का नामजद करके जियोवा के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भेजा जा सकेगा। इस आंदोलन के एक पुराना नेता श्री एन० एम० जोशी ने अपनी एक पुस्तिका 'ट्रेड यूनियन इन इंडिया' (पृष्ठ 10) में यह धारणा व्यक्त की है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वाणिज्य के मजदूर सम्मेलन के प्रभाव से हुई थी। इससे यह बात काफी साफ हो गई कि मजदूरों का न केवल संगठन बनना जरूरी है बल्कि उनके बीच किसी न किसी तरह का सहयोग भी स्थापित करना जरूरी है ताकि वे एक स्वर से अपनी बातें कह सकें।' 1924 में इसका चौथा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास ने की। अधिवेशन में दिए गए भाषणा में प्रायः वग शांति के सिद्धांतों तथा मजदूरों की सामाजिक एवं नैतिक उन्नति की बातें होती थी और सरकार से यह मांग की जाती थी कि वह मजदूरों के हित में कानून बनाए तथा उनकी खुशहाली के उपाय करे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के शुरू के दिनों में मध्यवर्गीय नेताओं का जो दृष्टिकोण था, उसका एक उदाहरण 1926 में छठे अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्ष पद में दिया गया निम्न भाषण है

बंबई के राष्ट्रीय मजदूर बोर्ड के विशुद्धता अभियान द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की मैं हार्दिक सराहना करता हूँ। यह अभियान इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि वह मजदूरों का पुरी आदर्श धार्मिक में मदद दे और उन्हें ईमानदार, शांतिपूर्ण

और सतुष्ट जीवन विताने की प्रेरणा दे सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर वस्तियों में जाते हैं और उन्हें शराब, जुआ तथा अन्य बुराइयों के बारे में बताते हैं। मजदूरों को इसी तरह की शिक्षा की जरूरत है और इसी के जरिए वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। (मद्रास में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के छठे अधिवेशन (1926) में अध्यक्ष पद से वी० वी० गिरि का भाषण)

1927 में कानपुर में मगठन के आठवें अधिवेशन में महामंत्री ने जो रिपोर्ट पढ़ी, उससे भी पता चलता है कि हड़ताल के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था

जिस अवधि की यह रिपोर्ट है उसमें कार्यकारिणी ने हड़ताल की बिल्कुल इजाजत नहीं दी लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में और यहां के विभिन्न व्यापारों में मजदूरों की स्थिति अत्यंत गंभीर होने के कारण कुछ हड़तालों और तालाबंदी की घटनाएं हुईं। इनमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी दिलचस्पी लेनी पड़ी। (कानपुर में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आठवें अधिवेशन (1927) में महासचिव एन० एम० जोशी की रिपोर्ट)

1927 तक ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मजदूरों के संघ से व्यावहारिक रूप में बहुत सीमित संबंध था। फिर भी इस समस्या ने एक ऐसा आधार तैयार किया जिसके कारण नवगठित ट्रेड यूनियनों के नेता पास आ सके और इसीलिए अब इसको मजदूरों के संघ की हवा लगने में कुछ ही देर थी। 1927 तक ट्रेड यूनियन कांग्रेस से 57 यूनियनों संबंध हो चुकी थी जिनके सदस्यों की कुल संख्या 150,555 थी।

#### 4 राजनीतिक जागरण

शुरू के दिनों में भारतीय मजदूर आंदोलन के नेताओं का जो चरित्र था उसके बावजूद सरकार को आने वाले दिनों में मजदूर आंदोलन के महत्व को समझने में देर नहीं लगी। उससे पिछले 20 वर्षों में भारतीय मजदूरवर्ग के आंदोलन के उदय का महत्व महसूस किया था। सरकार की चिंता का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि उसने 1921 में बंगाल में औद्योगिक अशांति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। 1922 में बंबई में औद्योगिक विवाद समिति बनाई गई, 1919-20 में मद्रास में सरकार को एक श्रमिक विभाग खोलना पड़ा और उसके बाद बंबई में भी इसी तरह का एक विभाग खोला गया। 1921 में एक ट्रेड यूनियन बिल तैयार किया गया हालांकि वह 1926 में जाकर पारित हो सका। 1921 से औद्योगिक विवादों के नियमित रूप से आंकड़े रक्षे जाने लगे। ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे आंदोलन की प्रगति की तत्वीर मिलती है। (कृपया पृष्ठ 418 तालिका देखें)। औद्योगिक संघों में काम के कुल जितने दिनों का अनुमान हुआ उनमें से आधे में अधिकांश दिनों अर्ध-वर्क मित्रों से संबंधित हैं और आधे से ज्यादा दिन अर्ध-वर्क बंबई में हुए विवादों में संबंधित हैं।

आगे चलकर यह देखा जाएगा कि सघष की तीन प्रमुख अवस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं। पहला चरण युद्ध के बाद आई विश्वव्यापी सहर थी जिसकी परिणति 1925 में बर्बई कपडामिलों की सफल हड़ताल में हुई। यह हड़ताल वेतन में कटौती की धमकी के खिलाफ की गई थी और तीन महीनों के सघष के बाद मिनमालिकों को यह धमकी वापस लेनी पड़ी। सघष का दूसरा दौर 1928-29 का है जब मजदूरों में संयुक्त रूप से राजनीतिक और औद्योगिक जागृनि आई। तीसरा दौर 1937 में कांग्रेस मन्त्रिमंडल के गठन के बाद शुरू हुआ और प्रगति की यह नई शुरुआत आज भी विकासोन्मुख है।

### औद्योगिक विवाद

| वर्ष | हड़तालों और सालावदियों की संख्या | इनमें शामिल मजदूरों की संख्या | काम के नुकसान हुए दिनों की संख्या |
|------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1921 | 396                              | 600,351                       | 6,984,426                         |
| 1922 | 278                              | 433,434                       | 3,972,727                         |
| 1923 | 213                              | 301,044                       | 5,051,704                         |
| 1924 | 133                              | 312,462                       | 8,730,918                         |
| 1925 | 134                              | 270,423                       | 12,578,129                        |
| 1926 | 128                              | 186,811                       | 1,097,478                         |
| 1927 | 129                              | 131,655                       | 2,019,970                         |
| 1928 | 203                              | 506,851                       | 31,647,401                        |
| 1929 | 141                              | 532,016                       | 12,165,691                        |
| 1930 | 148                              | 196,301                       | 2,261,731                         |
| 1931 | 166                              | 203,008                       | 2,408,123                         |
| 1932 | 118                              | 128,099                       | 1,922,437                         |
| 1933 | 146                              | 164,938                       | 2,168,961                         |
| 1934 | 159                              | 220,808                       | 4,775,550                         |
| 1935 | 145                              | 114,217                       | 973,457                           |
| 1936 | 157                              | 169,029                       | 2,358,062                         |
| 1937 | 379                              | 647,801                       | 8,982,000                         |
| 1938 | 399                              | 401,075                       | 9,198,708                         |
| 1939 | 406                              | 409,189                       | 4,992,795                         |
| 1940 | 322                              | 452,539                       | 7,577,281                         |
| 1941 | 359                              | 291,054                       | 3,330,503                         |
| 1942 | 694                              | 772,653                       | 5,779,281                         |
| 1943 | 716                              | 525,088                       | 2,342,287                         |
| 1944 | 658                              | 550,015                       | 3,447,306                         |
| 1945 | 848                              | 782,192                       | 3,340,892                         |
| 1946 | 1,593                            | 1,951,756                     | 12,678,121                        |
| 1947 | 1,811                            | 1,840,781                     | 16,567,666                        |
| 1948 | 1,639                            | 1,332,956                     | 7,214,456                         |

सरकार को और सरकार द्वारा नियुक्त उन समितियों और आयोगों को जिनके जिम्मे जाच का काम दिया गया था, यह अच्छी तरह पता था कि यदि इस उभरते हुए मजदूर आंदोलन ने एक बार राजनीतिक चेतना प्राप्त कर ली और यदि उसे ठोस संगठन तथा वगचेतना से लैस नेतृत्व मिल गया तो यह साम्राज्यवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सरकार को मजदूरवर्ग की सघन शक्ति का प्रमाण युद्ध के बाद के वर्षों में मिल चुका था। सरकार के सामने यह सवाल था कि मजदूर आंदोलन को किस तरह किसी ऐसे रास्ते पर लगाया जाए जिससे साम्राज्यवाद के लिए कोई खतरा न रहे अथवा जैसा कि सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था, सरकार की समस्या यह थी कि 'सही ढंग' का ट्रेड यूनियन आंदोलन कैसे स्थापित किया जाए। यह काम साम्राज्यवादी देश के मुबाले औपनिवेशिक देश में ज्यादा कठिन है। 1926 के ट्रेड यूनियन ऐक्ट का यही उद्देश्य था। इसके जरिए यूनियनों की राजनीतिक गतिविधियों पर खास तौर से रोक लगा दी गई थी। सरकार हमेशा इस बात के प्रति सतर्क रहती थी कि मजदूरवर्ग में कहीं राजनीतिक जागरण के चिह्न तो प्रकट नहीं हो रहे हैं।

फिर भी इन सारे अवरोधों और शुरु के दिनों की उलझना के बावजूद मजदूरवर्ग में समाजवादी और साम्यवादी विचारों की राजनीतिक चेतना की शुरुआत हो चुकी थी जो युद्ध के बाद के वर्षों में धीरे-धीरे भारत पहुँचने लगी थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अभी काफी कमजोर थी लेकिन उसका साहित्य 1920 से ही लोगों के बीच पहुँचने लगा था। 1924 से बंबई से 'सोशलिस्ट' नामक एक पत्र का प्रकाशन शुरू हो गया था जिसके संपादक श्री एस० ए० डांगे थे। श्री डांगे बाद में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहायक मंत्री चुने गए। सरकार ने इसपर प्रहार करने में तनिक भी देर नहीं की। 1924 में (जिस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी) चार कम्युनिस्ट नेताओं—डांगे, शीमल उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और दास गुप्त पर बानपुर पड़्यत्र कैसे के सिलसिले में मुकदमा चलाया गया। इन चारों नेताओं को चार-चार वर्ष की सजा सुना दी गई। यही भारत के राजनीतिक मजदूर आंदोलन की अग्निदीक्षा थी।

जनता के बीच जो जागृति पैदा हुई थी उसे दमन से रोक नहीं जा सका। 1926-27 तक समाजवादी विचारधारा का व्यापक प्रचार हो गया था। देश में स्थान-स्थान पर मजदूर और किसान पार्टियों के रूप में मजदूरवर्ग के राजनीतिक और समाजवादी संगठन का एक नया रूप दिखाई देने लगा था जिनमें ट्रेड यूनियन आंदोलन के जुआरू तत्व और कांग्रेस के वामपंथी कार्यकर्ता एक मंच पर इकट्ठे होना लग गये। फरवरी 1926 में बंगाल में पहली मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद बंबई, संयुक्त प्रांत और पंजाब में भी इस तरह की पार्टियाँ बनीं। 1926 में ये मारी पार्टियाँ एक साथ मिल गई और अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का जन्म हुआ जिसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1928 में हुआ। मजदूरों के बीच जिस नई राजनीतिक चेतना के पहलू रिक्त 1927 में प्रकट हुए थे उसका राजनीतिक रूप इस संगठन के रूप में सामने आया। हालाँकि शुरू-शुरू में

अनेक उलझनों का शिकार रहा। इन तथ्यों में उन नई शक्तियों का पता चलता है जो बिकासो-मुख हुईं।

1927 के वसंत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन (इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य शापुरजी शक्लतवाला भी शामिल हुए थे) और आगे चलकर इसी वर्ष कानपुर में आयोजित अधिवेशन में और भी स्पष्ट रूप से यह बात प्रकट हो गई कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में जुझारू नेतृत्व की चुनौती भरी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यह बात बड़ी तेजी से स्पष्ट होने लगी कि भारत की अधिकांश ट्रेड यूनियनें मजदूरवर्ग के इस नये नेतृत्व के साथ हैं हालांकि ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण कराने में देर होने के कारण 1929 तक इस तथ्य को सरकारी तौर पर नहीं माना गया। 1927 में पहली बार बवई में 1 मई, मई दिवस के रूप में मनाया गया और इसे मजदूर दिवस का नाम दिया गया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत के मजदूर आंदोलन के इतिहास में उस नए युग का सूत्र पात हो चुका है जब वह अंतराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के एक सजग अंग के रूप में काम करेगा।

1928 में मजदूर आंदोलन जिस तेजी से आगे बढ़ा और उसने जिस सक्रियता का परिचय दिया, वह लड़ाई के बाद के वर्षों में पहले कभी देखने में नहीं आई थी। इस प्रगति का केंद्र बवई था। पहली बार मजदूरवर्ग के बीच से ऐसा नेतृत्व उभरकर सामने आया जिसका कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से घनिष्ठ संपर्क था और जिसने वर्गसंघर्ष के सिद्धांत का अपना निदेशक सिद्धांत माना था और जो आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक शक्ति की तरह काम करता था। मजदूरों ने इस नेतृत्व का जारदार स्वागत किया। फरवरी में साइमन कमीशन के भारत आने पर राजनीतिक हड़ताल और प्रदर्शनों का जा सिलसिला शुरू हुआ उससे कुछ समय के लिए मजदूरवर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन के हिराबल दस्ते का स्थान मिल गया। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस के और ट्रेड यूनियन आंदोलन के सुधारवादी नेता इस बात में सहमत नहीं थे कि साइमन कमीशन के खिलाफ हानि वाली हड़तालें और प्रदर्शनों में मजदूरवर्ग भी भाग ले। लेकिन मजदूरवर्ग की सफलता से वे हैरान रह गए। बवई के अनकं म्यूनिसिपल मजदूरों को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था। दुबारा हड़ताल करने पर ही उन्हें फिर नौकरी पर वापस लिया गया।

ट्रेड यूनियनों के संगठन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ा। सरकारी जाकड़ों के अनुसार बवई में 1923-26 के तीन वर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या 48,669 से बढ़कर महज 59,544 हो गई थी लेकिन 1927 तक यह संख्या 75,602, मार्च 1928 तक 95,321 और मार्च 1929 तक यह संख्या घटकर 200,325 हो गई। इन सब यूनियनों में पहले स्थान पर प्रसिद्ध गिरनी कामगार (लाल गंडा) यूनियन थी। यह यूनियन बवई में मिलमजदूरों का संगठन था और इसका सदस्यों की संख्या 1928 में शुरू में केवल 324

थी लेकिन सरकार के 'लेबर गजट' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 1928 में यह सख्या 54,000 और मार्च 1929 तक 65,000 हो गई थी। इस बीच 1926 में वनी और ट्रेड यूनियन के सुधारवादी नेता एन० एम० जोशी के नेतृत्व में काम बंद रहने, बर्बई की पुरानी, सूती कपड़ा मजदूर यूनियन (वायं टेक्सटाइल लेबर यूनियन) के सदस्यों की सख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इस यूनियन को सरकार तथा मिलमालिका दोनों की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा था। लेबर गजट के ही आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 1928 में इस यूनियन के सदस्यों की सख्या 8,436 थी जब दिसंबर 1928 में केवल 6,749 रह गई। इससे साफ पता चलता है कि मजदूरों को कौन सी यूनियन पसंद थी। गिरनी कामगार यूनियन की शक्ति इस बात में निहित थी कि उसने मिला में समितियाँ बनाई थी जिनका मजदूरों के साथ घनिष्ठ संबंध था।

1928 में हुई हड़तालों में कुल 3 करोड़ 15 लाख काम के दिनों का नुकसान हुआ। पिछले पांच वर्षों में कुल मिलाकर भी इतनी बड़ी सख्या में काम के दिनों का नुकसान नहीं हुआ था। यद्यपि हड़तालों का केंद्र बर्बई था जहाँ कपड़ा मिल के मजदूरों ने सक्रियता दिखाई थी लेकिन यह आंदोलन समूचे देश में फैल गया था। 1928 में औद्योगिक विवादों के 203 मामले सामने आए जिनमें से 111 मामले बर्बई के, 60 बंगाल के, 8 बिहार तथा उड़ीसा के, 7 मद्रास के और 2 पंजाब के थे। इनमें 110 विवाद सूती और ऊनी कपड़ा मिलों में हुए थे 19 जूटमिलों में, 11 इंजीनियरिंग कारखानों में, 9 रेलवे तथा रेलवे कारखानों में, और 1 कोयले की खान में हुआ था। इन वर्षों में सबसे ज्यादा शानदार बर्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल थी और भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी हड़ताल थी। इस हड़ताल में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अर्थात् छ महीने तक इन मिलों के सभी डेढ़ लाख मजदूरों ने सरकारी हिंसा और दमन के हर रूप का जमकर सामना किया। यह हड़ताल मूलतः अभिनवीकरण के लिए उठाए गए कदमों और साठे सात प्रतिशत वेतन कटौती के विरुद्ध आरंभ हुई थी लेकिन बाद में इसमें और भी तमाम मार्ग जुड़ गईं। शुरू में सुधारवादी नेताओं ने इस हड़ताल का विरोध किया और एन० एम० जोशी ने कहा कि हम लोगों की स्थिति 'दशकों' की है लेकिन बाद में ये नेता भी आंदोलन में खिंच आए। सरकार ने आंदोलन को विफल करने की तमाम कोशिशें की लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम-याब हो गईं। अंत में उसने फासेट बमेट्री की नियुक्ति की घोषणा की जिसने साठे सात प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया और मजदूरों को कुछ अच्छे मार्ग भी मान ली।

इस प्रकार 1929 का वर्ष शुरू होते होते एक नाजुक स्थिति पैदा हो गई थी। मजदूर आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक रणमंच पर सबसे आगे पहुंच गया था। पुराने सुधारवादी नेतृत्व को मजदूरवर्ग अपने रास्ते से हटा रहा था। 1927-28 में ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। इस प्रतिनिधिमंडल से साम्राज्यवादियों का बड़ी आशाएँ थी ( ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इधर भारतीय मजदूरों की स्थितियों में जो दिलचस्पी लेनी शुरू की है वह काफी लाभदायक मिश्र हो सकती है बशर्ते उससे भारत

की मजदूर यूनियनो का संगठन सुधर जाए और इन यूनियनों से साम्यवादी तत्वों का निष्काशन बाहर किया जाए।' तदन (टाइम्स 14 जून 1928) ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यूरोप की सुधारवादी ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल से संबंध स्थापित करना था। लेकिन उसे इस काम में सफलता नहीं मिली। इस असफलता से सरकार काफी चिंतित हुई और उसकी यह चिंता छिपी न रह सकी। जनवरी 1929 में विधानमंडल में वायसरॉय लार्ड ईविन ने अपने भाषण में कहा कि 'कम्युनिस्ट विचारधारा के ध्रुव प्रचार से चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है।' उन्होंने ऐलान किया कि सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाएगी। सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 'इंडिया इन 1928-29' शीर्षक के अंतर्गत कहा गया है कि 'कम्युनिस्टों के प्रचार और प्रभाव से, विशेष रूप से कुछ बड़े शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में उनके प्रचार और प्रभाव से अधिकारियों को काफी चिंता हो गई है।' इंग्लैंड के उदारवादियों ने भी यही चिंता दोहराई। अगस्त 1929 में 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने लिखा कि 'पिछले दश वर्षों के अनुभव ने यह बता दिया है कि कम्युनिस्टों ने चक्कर में बड़े बड़े क्षेत्रों के औद्योगिक मजदूर बहुत जल्दी आ जाते हैं।' भारत के राष्ट्रवादी अखबारों ने भी इसी तरह की चीख पुकार मचाई। मई 1929 में 'वाय क्वॉन्टल' ने लिखा कि 'पिछले कई महीनों में भारत में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों में और खासतौर से किसानों तथा मजदूरों के सम्मेलनों में समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है।' सुधारवादी नेताओं ने अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस की और मांग की कि कम्युनिस्टों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मई 1928 में ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री शिवराव ने कहा था कि 'अब समय आ गया है जब भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपने संगठन से उन तत्वों को चुन चुन कर निकाल देना चाहिए जो शरारतपूर्ण कार्रवाहियाँ करते हैं। इस तरह की चेतावनी इसलिए भी आज बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग मजदूरों को हड़ताल का उपदेश देने में लगे हुए हैं।

1929 में सरकार ने कदम उठाए और मजदूरों के बढ़ते आंदोलन पर जबरदस्त प्रहार किया। सितंबर 1928 में सावजनिक सुरक्षा बिल (पब्लिक सेफ्टी बिल) असेंबली में पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य सरकारी तौर पर यह बताया गया था कि इससे 'भारत में कम्युनिस्टों की गतिविधियों को रोका जाएगा।' लेकिन असेंबली ने इस बिल को नामजूर कर दिया। 1929 के वसंत में वायसरॉय ने एक विशेष अध्यादेश के जरिए इस बिल को लागू कर दिया। इसके बाद मजदूरों की स्थिति की जांच के लिए क्लिफ्टन कमीशन नियुक्त किया गया। बाद में ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट बनाया गया जिसका उद्देश्य मजदूरों और मालिकों के विवादों को वास्तविकता के जरिए सुलझाने की व्यवस्था करना, दूसरा के समयन में की जाने वाली हड़तालों पर रोक लगाना और सावजनिक सेवा में उद्योगों में हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाना था। इसी समय बंबई में हुए दंगों की जांच के लिए एक रायट इन्क्वायरी कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने सिफारिश की कि 'बंबई में कम्युनिस्टों की कार्रवाहियों को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।' इस समिति ने यह सवाल भी उठाया कि क्या न ट्रेड यूनियन ऐक्ट में इस तरह

की मजदूर यूनियनों का संगठन सुधर जाए और इन निकाल बाहर किया जाए।' लंदन टाइम्स, 14 जून। उद्देश्य भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यूरोप की सुध सवध स्थापित करना था। लेकिन उस इस काम में स से सरकार काफ़ी चिंतित हुई और उसकी यह बिता में विधानसभा में वायसराय लॉर्ड इविन ने अपन भा धारा के खुले प्रचार से चिंताजनक स्थिति पैदा हो ग इसे रोकने के लिए कदम उठाएगी। सरकार की र शीपक के अंतर्गत कहा गया है कि कम्युनिस्टों के कुछ बड़े शहरों के औद्योगिक केंद्रों में उनके प्रचार चिंता हो गई है।' इंग्लैंड के उदारवादियों ने भी 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने लिखा कि पिछले दो कम्युनिस्टों में चक्कर में बड़े बड़े केंद्रों के और भारत के राष्ट्रवादी अखबारों ने भी इसी त 'वावे नानिकल' ने लिखा कि 'पिछले कई मही में और खासतौर से किसानों तथा मजदूरों के हो रहा है।' सुधारवादी नेताओं ने अपने पत्रों की कि कम्युनिस्टों के खिलाफ कड़ों कायदा कांग्रेस की वापकारिणी के अध्यक्ष श्री शि जब भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन को अप देना चाहिए जो शराबखोर कायवाहिया आज बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग मज



भारतीय कांग्रेस कमेटी के तीन सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया, इनमें कांग्रेस के, वबई के प्रांतीय सचिव भी शामिल थे। बानपुर पटवर्धन केस में जिन चार लोगों को सजा दी गई थी उनमें से तीन फिर इस मुकदमे की चपेट में आ गए थे। इनमें तीन अंगरेज भी थे। इंग्लैंड के मजदूर आंदोलन के ये तीन प्रतिनिधि जब भारतीय मजदूरों के साथ कटघरे में खड़े हुए और बाद में उनके साथ सजा काटने जेल में गए तो विश्व के सामने मेहनतकश वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता का उदाहरण उपस्थित हो गया जिसने पुरानी दीवारें तोड़ दी और जिसने ब्रिटेन तथा भारत की जनता के भावी मैत्री संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना का काम किया।

भारत के मजदूर आंदोलन के गिरफ्तार नेताओं के व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि संगठन के अभी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद मजदूर आंदोलन को अपनी भूमिका का पूरा पूरा एहसास है और उसे पता है कि इस देश में उसे एक गौरवपूर्ण भूमिका निभानी है। अभियुक्तों ने अपने बचाव में जो बयान दिए वे भारतीय मजदूर आंदोलन के अत्यंत मूल्यवान दस्तावेज बने रहेंगे। इस तरह के वक्तव्यों से एक नए भारत की तत्त्वीय सामन आई

यह ऐसा मामला है जिसका राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह कोई ऐसा साधारण मामला नहीं जिसमें पुलिस ने 31 अपराधियों के खिलाफ महज अपने कृतव्यय का पालन किया हो। यह वर्गसंघर्ष के इतिहास की एक घटना है। इसे अमल में लाने के पीछे एक निश्चित राजनीतिक नीति है। यह भारत में स्थापित ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार द्वारा उस ताकत पर प्रहार करने की कोशिश है जो असली दुश्मन को पहचानती है, जो अंततोगत्वा अपने इन दुश्मनों का तख्ता पलट देगी, जिसने इनके खिलाफ असमर्थतापूर्ण बरत का रुख अपना लिया है और जिसने देश की अपार गरीब और शोषित जनता की प्रत्यक्ष शक्ति का प्रदर्शन किया है। (राधारमण मित्रा का बयान)

मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ पडयत्न किया। मैं पूरा जोर देकर कहना चाहूंगा कि मैंने ऐसा किया है। कम्युनिस्ट लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ पडयत्न नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट चूंकि मेहनतकश वर्ग की पार्टियों के सबसे प्रगतिशील हिस्से हैं और सिद्धांत वे सामान्य सवहारा जनता के हवावल दस्ते का काम करते हैं तथा इस बात का दावा करते हैं कि वे सवहारा आंदोलन के सवभाय कार्यक्रमों को समझ सकते हैं और उनके संचालन की प्रक्रिया तथा परिणामों का पूर्वज्ञान रखते हैं इसलिए वे महज समाज के ढांचे के जबर मौजूद वर्गसंघर्ष की ठोस परिस्थितियों को सामान्य भाषा में अभिव्यक्ति देते हैं।

यदि कोई ऐसा अपराध है जिसपर अदालत मुझे दंड देना चाह तो वह यही है

पी० सी० जोशी सयुक्त प्रांत की किसान मजदूर पार्टी के सचिव ।

ए० ए० आल्वे गिरनी कामगर यूनियन के अध्यक्ष ।

जी० आर० कासले गिरनी कामगर यूनियन के अधिकारी ।

गोपाल बसाक साशलिस्ट यूथ काफ़ेस के 1928 में अध्यक्ष ।

जी० एम० अधिकारी पी० एच० डी०, बंबई के समाजवादी अखबार 'स्पाक' के लेखक ।

एम० ए० मजोब 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ उन्होंने भारत छोड़ दिया, रूस की यात्रा की और वापस आने पर गिरफ्तार कर लिए गए । कीर्ति किसान पार्टी, पंजाब के सचिव और पंजाब यूथ लीग के संस्थापक ।

आर० एस० निंबकर बाव ट्रेड्स कौंसिल और बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी के महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य ।

विश्वनाथ मुखर्जी सयुक्त प्रांत की मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष ।

केदारनाथ सहगल पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के वित्तीय सचिव, आल इंडिया यूथ लीग के सदस्य ।

राधारमण मित्रा बंगाल जूट वर्कर्स यूनियन के सचिव ।

धरनी के० गोस्वामी बंगाल की मजदूर किसान पार्टी के सहायक मंत्री, प्रमुख मजदूर नेता ।

गौरीशंकर सयुक्त प्रांत की मजदूर किसान पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य ।

शमसुल हूदा बंगाल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के सचिव ।

शिवनाथ बनर्जी बंगाल जूट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, इससे पहले खडगपुर रेल हड़ताल के सिलसिले में एक वर्ष की सजा काट चुके हैं ।

गोपेंद्र चक्रवर्ती ईस्ट इंडिया रेलवे यूनियन के अधिकारी, इससे पहले खडगपुर रेल हड़ताल के सिलसिले में डेढ़ वर्ष की सजा काट चुके हैं ।

सोहनसिंह जोशी अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी के पहले सम्मेलन के अध्यक्ष ।

एम० जी० देसाई बंबई के समाजवादी पत्र 'स्पाक' के संपादक ।

अयोध्याप्रसाद बंगाल की मजदूर किसान पार्टी के सक्रिय सदस्य ।

लक्ष्मण राव कदम म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन, झांसी के संगठनकर्ता ।

एच० एल० हर्चिसन 'यू स्पाक' के संपादक ।

वाद में गिरफ्तार किए गए बत्तीमवे व्यक्ति लेस्टर हर्चिसन एक अंगरेज पत्रकार थे जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद 'यू स्पाक' का संपादन संभाला । इनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष, एक भूतपूर्व अध्यक्ष, और दो सहायक मंत्री, बंबई के और बंगाल के प्रांतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मंत्रीगण, गिरनी कामगर यूनियन के सभी अधिकारी, जी० आई० पी० रेल वमचारिया की यूनियन के अधिकांश पदाधिकारी तथा अनेक दूसरी यूनियनों के पदाधिकारी और बंगाल, बंबई तथा सयुक्त प्रांत की मजदूर किसान यूनियन के अन्य अधिकारी थे । अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के तीन सदस्या को भी गिरफ्तार किया गया, इनमें कांग्रेस के, बंबई के प्रांतीय सचिव भी शामिल थे। कानपुर पडयत्न केस में जिन चार लोगों को सजा दी गई थी उनमें से तीन फिर इस मुकदमे की चपट में आ गए थे। इनमें तीन अंगरेज भी थे। इंग्लैंड के मजदूर आंदोलन के ये तीन प्रतिनिधि जब भारतीय मजदूरों के साथ कटघरे में खड़े हुए और वाद में उनके साथ सजा काटने जेल में गए तो विश्व के सामने मेहनतकशवर्ग की अंतराष्ट्रीय एकता का उदाहरण उपस्थित हो गया जिसने पुरानी दीवारें तोड़ दी और जिसने ब्रिटेन तथा भारत की जनता के भावी मैत्री संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना का काम किया।

भारत के मजदूर आंदोलन के गिरफ्तार नेताओं के व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि संगठन के अभी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद मजदूर आंदोलन का अपनी भूमिका का पूरा पूरा एहसास है और उसे पता है कि इस देश में उसे एक गौरवपूर्ण भूमिका निभानी है। अभियुक्तों ने अपने बचाव में जो बयान दिए वे भारतीय मजदूर आंदोलन के अत्यंत मूल्यवान् दस्तावेज बने रहेंगे। इस तरह के वक्तव्यों से एक नए भारत की तस्वीर सामने आई

यह ऐसा मामला है जिसका राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह कोई ऐसा साधारण मामला नहीं जिसमें पुलिस नं 31 अपराधियों के खिलाफ महज अपने कृतव्यय का पालन किया हो। यह वर्गसंघर्ष के इतिहास की एक घटना है। इसे अमल में लाने के पीछे एक निश्चित राजनीतिक नीति है। यह भारत में स्थापित ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार द्वारा उस ताकत पर प्रहार करने की कोशिश है जो असली दुश्मन को पहचानती है, जो अंततोगत्वा अपने इन दुश्मनों का तख्ता पलट देगी जिसने इनके खिलाफ असमझौतापूर्ण बैर का रख अपना लिया है और जिसने देश की अपार गरीब और शोषित जनता की प्रलयकर शक्ति का प्रदर्शन किया है। (राधारमण मित्रा का बयान)

मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ पडयत्न किया। मैं पूरा जोर देकर कहना चाहूंगा कि मैंने ऐसा किया है। कम्युनिस्ट लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ पडयत्न नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट चूक मेहनतकशवर्ग की पार्टियों के सबसे प्रगतिशील हिस्से हैं और सिद्धांत वे सामान्य सवहारा जनता के हरावल दस्ते का काम करते हैं तथा इस बात का दावा करते हैं कि वे सवहारा आंदोलन के सवामान्य कार्यक्रमों को समझ सकते हैं और उनके सवालन की प्रक्रिया तथा परिणामों का पूर्वज्ञान रखते हैं इसलिए वे महज समाज के ढांचे के अंदर मौजूद वर्गसंघर्ष की ठोस परिस्थितियों को सामान्य भाषा में अभिव्यक्ति देते हैं।

यदि कोई ऐसा अपराध है जिसपर अदालत मुझे दंड देना चाह तो वह यही है

कि मैं भारत को पूँजीवाद के शापण से वंचित करना चाहूँ और लाखों करोड़ों उत्पीड़ितों को मुक्त करना चाहूँ। यदि आप मेरे ऊपर य आरोप लगात हं ता म स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपराध किया है। (धरणी गोस्वामी का बयान)

चूँकि मेरा यह लक्ष्य था कि मेहनतकशवर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जाए इसलिए मेरे लिए यह एक बुनियादी काम था कि मैं खुद को कमजोर और असंगठित मजदूर संगठनों का मजबूत बनाने के काम में पूरी निष्ठा के साथ लगा हूँ।

ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि वह किसी उद्योग के प्रत्येक बेतनभोगी कमचारी को एक मंच पर इकट्ठा कर देता है और उन्हें वग आधार पर संगठित करता है। यदि कोई ट्रेड यूनियन सही अर्थों में मजदूरों का संगठन होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह मालिका और पूँजीपतियों के वर्ग के विरुद्ध मजदूरों के आर्थिक वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करे। यदि कोई ट्रेड यूनियन मजदूरों को वर्ग चेतना और वर्ग एकता के बुनियादी सिद्धांत समर्थान में असफल रहता है तो वह निश्चय ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। (गोपेन चक्रवर्ती का बयान)

मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं युवकों के बीच काम किया और युवकों के संगठन बनाए। यह सच है, मैंने युवकों के बीच कुछ काम करने की कोशिश की। मैं भी भारत के हर युवक की तरह यह चाहता हूँ कि भारत आजाद हो। मैं भी चाहता हूँ कि देश को पूर्ण आजादी मिले, भारत का पूर्ण उद्योगीकरण हो तथा देश को राजनीतिक और आर्थिक आजादी मिले। आजादी की इच्छा करना और उसके लिए काम करना कभी अपराध नहीं हो सकता।

भारत का नौजवान यदि पुश्तहाली चाहता है तो उसके सामने दो ही आदर्श हो सकते हैं, आजादी की प्राप्ति और समाजवादी समाज की स्थापना। (गोपाल बसाक का बयान)

हम लोगों के खिलाफ दज किया गया मामला कुछ ऐसा है कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में दलीलें देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस बात के पक्ष में दलील देने का प्रश्न पैदा होता है वह है पार्टी का प्रश्न, पार्टी की विचारधारा का प्रश्न, पार्टी के बने रहने के अधिकार का प्रश्न और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबद्ध होने या सहयोग लेने का प्रश्न। अभियोग पक्ष में कम्युनिज्म, कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल (अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन) पर अत्यंत घिनौने आरोप लगाए हैं। उसमें कहा गया है कि हमारा अपराध न केवल राजतन्त्र

के खिलाफ है वल्कि समूचे समाज के खिलाफ है। मैं इन गालियों को वेहद अपमानजनक मानता हूँ और कहता हूँ कि सही जर्वा में समूचे मानव समाज के दुश्मन वही लोग हैं, वे साम्राज्यवादियों के हमियार हैं और उनके दलाल हैं। मैं पूछता हूँ कि सामाजिक अपराधी कौन हैं? खून के प्यास साम्राज्यवादी—जिन्होंने समूचे महाद्वीप में सगीन और गोलियाँ का आतक स्थापित किया है, जिन्होंने रक्तपात और यातना का उपनिवेशवादी शासन स्थापित किया है, जिन्होंने इस महाद्वीप की करोड़ों जनता को दाने दाने का मोहताज किया और गुलाम बना रखा है और जो जनता के विनाश का खतरा बन हुए हैं या सामाजिक अपराधी वे कम्युनिस्ट हैं जो समूची दुनिया की शोषित और उत्पीड़ित जनता की क्रांतिकारी शक्ति को संगठित करने के लिए और इस शक्ति से दमन और शोषण पर आधारित सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील हैं जो इस व्यवस्था को समूल नष्ट करके एक नई समाज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, और सवनाश की तरफ बढ़ रहे मानव समाज और सभ्यता को बचाना चाहते हैं? इस मुकदमे में सामाजिक अपराधियों के आधिकारिक प्रतिनिधि अभियाग पक्ष की बेंच पर बैठे हुए हैं।

जैसा कि मैंने कहा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, (अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन) पिछले सौ वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के सहज विकास का नतीजा है। यह अपने से पहले के दो 'इंटरनेशनल' की क्रांतिकारी परंपरा का विकास है। अपने कई दशकों के सहारा संघर्ष के अनुभवों पर निर्भर होकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आज पूँजीवादी देशों में समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्षरत क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित कर रहा है और अंततः विश्व के छठे हिस्से में समाजवाद की स्थापना का वास्तविक काम कर रहा है और इस काम में निश्चा निदेशन कर रहा है। इस अंतिम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की उपलब्धियों से ही पूँजीवादी देशों की सहारा जनता के बीच इसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ रहा है और उपनिवेशों की शोषित जनता के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रसार बढ़ता जा रहा है।

सोवियत संघ का अस्तित्व आज कोमिनतर्न के नेतृत्व में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस आधार से ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, विकसित देशों की सहारा जनता और उपनिवेशों की मेहनतकश जनता के सहयोग से पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अभियान जारी रखेगा और अंत में उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आज विश्व इतिहास में एक ऐसा विशाल कारखाना है जो

मानव समुदाय और मानव सभ्यता की नियति को एक नया स्वरूप प्रदान करना और वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद सबनाशकारी घतरा से उसकी रक्षा करेगा

लेकिन बुजुर्गवय (पूज्यपतिवय) के इन घृणित दलाला की समय में यह बात नहीं आएगी। उनके लिए कम्युनिस्ट इंटरनशनल एक ऐसा गुप्त पडयंत्र है जिस दंड संहिता की किसी धारा की मदद से समाप्त करना होगा।

(डा० जी० एम० अधिकारी का बयान)

इस मुकदमे में भारत के मजदूर आंदोलन को जो भूमिका रही वह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के उच्चतम मानदंडों के अनुरूप रही और यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा और मिसाल बनो जिनके ऊपर आज भारत में समाजवाद और मजदूरवर्गों के झंडे को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी है।

सरकार ने इस मुकदमे को साढ़े तीन साल तक घसीटा, भारत के इतिहास में चार वर्ष की यह अवधि बहुत ही नाजुक थी और इस अवधि में मजदूरवर्ग का सबसे अच्छा नेतृत्व जेलों में पड़ा रहा। दंड संहिता की धारा 121A के तहत जो आरोप लगाए गए थे उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण पेश करने की कोई कोशिश नहीं की गई।

ब्रिटिश भारत के भीतर या बाहर जो भी व्यक्ति ऐसे किसी अपराध का पडयंत्र करता है जो धारा 121 के तहत दंडनीय हो या सम्राट को ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी हिस्से से अपदस्थ करता है या अनुचित शक्ति के जरिए भारत सरकार का, या स्थानीय सत्ता का तख्ता पलटने का पडयंत्र करता है उसे आजन्म या कुछ समय के लिए कालापानी की सजा दी जाएगी या उसे ऐसी कोई भी सजा दी जाएगी जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो।

यह स्वीकार किया गया कि आरोपों को सही साबित करने के लिए अभियुक्तों की किसी कोषवाही का हवाला नहीं दिया जा सका। हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा यह मान लिया गया है कि अभियुक्तों पर यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्होंने तथा कथित पडयंत्र में कोई गैरकानूनी तरीका अपनाया।

सरकारी वकील ने कहा

अभियुक्तों पर यह आरोप नहीं लगाया गया है कि वे कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं बल्कि यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने—भारत में सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त करने के लिए पडयंत्र रचा था। मुकदमे के मकसद के लिए

यह साबित करना जरूरी नहीं है कि अभियुक्तों ने वास्तव में कुछ किया है। यदि केवल यही साबित हो जाता है कि उन्होंने पड़यत्न किया था तो काफी है।

पड़यत्न' जैसी कोई चीज नहीं थी। अभियुक्तों के समाजवादी सिद्धांतों को सभी लोग जानते थे और उन्होंने खुलेतौर पर अपने इन सिद्धांतों की घोषणा भी की थी। इसी तरह मजदूर संगठन के काम भी सबके सामने थे। कहीं कोई 'अनुचित शक्ति' नहीं थी। केवल मजदूर आंदोलन का संगठन और नेतृत्व था।

जसली आरोप का पता अभियोगपत्र से चला। इसमें अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था कि वे 'पूँजी और श्रम के बीच शत्रुता बढ़ाते हैं' मजदूर किसान पार्टियाँ, यूव लीग, यूनियन आदि बनाते हैं' और हड़तालों को बढ़ावा देते हैं।' गवाहियों में भी इन्हीं गति-विधियों पर खासतौर से ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर सारा जोर दिया गया था। इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त, बगाल जूट बकस यूनियन के मंत्री पर सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि वह पड़यत्न में उसी समय शामिल हो गया था जब उसने कलकत्ता के भगियों की हड़ताल में हिस्सा लिया था।' इस मुकदमे के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसकी घोषणा जज ने अपने फैसले में कर दी।

संभवतः इसमें ज्यादा गंभीर बात यह है कि बंबई के कपड़ा मिलमजदूरों पर इनका काफी प्रभाव है। इसका उदाहरण 1928 की हड़ताल और गिरनी कामगार यूनियन की क्रांतिकारी नीति में मिल गया था।

फिर भी यह मुकदमा उभरते हुए मजदूर आंदोलन को रोकने में ऐतिहासिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण था जितना महत्वपूर्ण ब्रिटिश मजदूर आंदोलन के इतिहास में सौ वर्ष पुराना डोरचेस्टर के मजदूरों का मुकदमा था। यह मुकदमा लेबर सरकार के शासनकाल में चलाया गया था और लेबर सरकार ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी (हम इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं—भारतीय मामलों के मंत्री पूर जोरशोर से भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं,—1929 में ब्राइटन में लेबर पार्टी के सम्मेलन में डा० ड्रमंड शील्स का भाषण)। 25 जून 1929 को डेली हेराल्ड ने कहा 'कानून की मशीन को अपना काम करते रहना चाहिए।' ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के नाम भारत की ट्रेड यूनियन की अपील के जवाब में सर वाल्टर सिटीन ने 1 अक्टूबर 1929 को लिखा कि मुकदमे की कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए हैं वे राजनीतिक आरोप हैं और जनरल कौंसिल की राय में भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का इससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वाद में जब मुकदमा समाप्त हो गया और लेबर पार्टी की सरकार भी नहीं रही तब 1933 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस और लेबर पार्टी की गठना राष्ट्रीय समिति ने एक पुस्तिका प्रकाशित की और यह कहा कि

‘मुकदमे की पूरी कायवाही शुरू से अंत तक ऐसी थी जिसके एक भी शब्द का पक्ष नहीं लिया जा सकता और जो याचिक धाधलेवाजी का उदाहरण है।’

जनवरी 1933 में अदालत ने अत्यंत क्रूरतापूर्ण सजाए सुनाईं मुजफ्फर अहमद को आजीवन कालापानी, डागे घाटे, जोगलेकर निबकर और स्ट्रैंट को बारह साल का कालापानी ब्रडले, मिरजकर और उस्मानी को दस साल का कालापानी तथा इसी तरह की जय सजाए थीं जिनमें सबसे कम सजा तीन वर्ष का कठोर कारावास था। इन सजाओं की घोषणा के बाद विश्व भर में विरोध प्रदर्शन हुए, परिणामतः अपील करने पर इन सजाओं में काफी कमी कर दी गई।<sup>1</sup>

## 6 मेरठ के बाद मजदूर आंदोलन का पुनर्गठन

मेरठ में हुई गिरफ्तारियों के बाद के कुछ वर्ष भारत के मजदूर आंदोलन के लिए काफी कठिन वर्ष थे। हालांकि मेरठ के मुकदमे में ऐसी हर घटना की तरह ही आंदोलन की भावी शक्ति और विजय के बीज काफी मजबूती से बोए फिर भी इन गिरफ्तारियों से आंदोलन पर एक तात्कालिक प्रहार तो हुआ ही।

भारत के मजदूर आंदोलन के विकास का यह प्रारंभिक चरण था और ऐसी स्थिति में वह अपने गिरफ्तार नेताओं की कमी को जल्दी पूरा नहीं कर सका। जायिक संकट का दौर चल रहा था और इन दिनों जो भी हड़तालें हुई, उनमें मजदूरों की जबरदस्त हार हुई। जायिक संकट के दौर के बाद राष्ट्रीय संघ के नाजुक वर्ष शुरू हुए और इन वर्षों में मेहनतकश वर्ग की राजनीतिक भूमिका काफी कमजोर कर दी गई। साम्राज्यवादियों का इरादा भी यही था।

ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने भी जनक तरह की कठिनाईयां आईं। पिछले दो वर्षों में संगठन के व्यावहारिक काम और अपनी अपेक्षाकृत बढ़ी शक्ति के आधार पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वामपंथी बहुमत को अंततः 1929 के जल में नागपुर अधिवेशन में सफलता मिल गई। पुराने सुधारवादी नेताओं ने अपने को अल्पमत में पाया। उन्होंने बहुमत के जनतांत्रिक फल से इकार किया और उन्होंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फूट डालकर अपनी अनुयायी यूनियनों को लेकर ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर ली। एन० एम० जोशी, शिवराव गिरि दीवान चमनलाल तथा जय लोणा की जार से जो वर्मान जारी किया गया उसमें कहा गया कि ‘अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी की कायवाही से यह बात अब साफ हो गई है कि उसमें सदस्यों या बहुमत ऐसी नीति के पालन के पक्ष में है जिससे हम पूरी तरह असहमत हैं। इस वक्तव्य में आज कहा गया कि हम कोई सदह नहीं कि कांग्रेस का एक निर्णायक बहुमत उनमें साथ है। इन परिस्थितियों में हम बहना चाहते हैं कि कार्यकारिणी के प्रस्तावों से हमारा कोई



नवध नहीं है और हम यह भी महसूस करते हैं कि कांग्रेस की कायवाहियों में शिरस्त करत रहन से अब कोई मकसद पूरा नहीं होगा ।'

लेकिन ट्रेड यूनियन आदोलन पर अब जिन वामपथी नेताओं का नेतृत्व हुआ उनमें एकता या सहयोग नहीं था । इसकी वजह यह थी कि इस नेतृत्व में तरह तरह के लोग थे । फल-स्वरूप कुछ समय बाद मुख्यतया मजदूरवाग की स्वतन्त्र राजनीतिक भूमिका के प्रश्न पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर फूट पड़ गई । मजदूरवाग की स्वतन्त्र राजनीतिक भूमिका की बात कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग करते थे और उन्होंने अपनी अलग अलग लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ली ।

इन फूटों से ट्रेड यूनियन आदोलन कमजोर हो गया लेकिन मजदूरों ने अलग अलग हड़तालों के जरिए अपना सधप जारी रखा । उन्होंने न केवल आर्थिक मांगों के लिए बल्कि ट्रेड यूनियन कायकताओं को नौकरी से निकाले जाने और दडित किए जाने के खिलाफ जर्थात संगठन के जनवादी अधिकार के लिए सधप किया । इसका प्रमाण हड़तालों की बढ़ती हुई सख्या से मिल सकता है । 1929 में 141 हड़तालें हुईं और 1930 तथा 1931 में क्रमशः 148 तथा 166 हड़तालें हुईं । इन हड़तालों में प्रति वर्ष 1 लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया । इन सधपों का नेतृत्व लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कम्युनिस्टों ने किया और 1933 तक सरकार को भी बड़ी खीज के साथ यह कहना पड़ा कि हालांकि मेरठ बाड के नेता अब भी जेलों में पड़े हैं पर कम्युनिस्टों का खतरा बना हुआ है और यह पहल से तज हुआ है' (इंडिया, 1932-33) ।

इन अलग अलग हड़तालों से 1934 की हड़तालों के बड़े सिलसिले का माग प्रशस्त हुआ जिसका उद्देश्य मिलमालिका की अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन) योजना का विरोध करना था । यह योजना काम बढ़ाने और शोषण तेज करने के लिए तैयार की गई थी । सधप की इस लहर की तीव्रता और विस्तार का सबूत इस बात से ही मिल सकता है कि 1933 में जहां 146 हड़तालों में 164,938 मजदूरों ने भाग लिया और 2,168,961 काम के दिनों का नुकसान हुआ, वहीं 1934 में 159 हड़तालों में 220,808 मजदूरों ने भाग लिया और 4,775,559 काम के दिनों का नुकसान हुआ । कहन का तात्पर्य यह है कि 1934 में 1933 के मुकाबले दुगने काम के दिनों का नुकसान हुआ । सरकार के जवरदस्त दमन के बावजूद सूती कपडा मिलमजदूरों की हड़ताल बर्दई में अप्रैल से जून तक जोर शोलापुर में फरवरी से मई तक चली । यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि मजदूरवाग ने अपनी विखरी शक्ति का फिर से बटोर लिया था अपनी एगजुटता फिर कायम कर ली थी और जुआरू नेताओं की एक नई पीढ़ी को सामन ला दिया था ।

सरकार ने फिर हमला किया । जापात अधिवारों से नरधित एक अध्यादश जारी किया गया और कम्युनिस्टों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार व

लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। कानूनी तौर से पजीकृत एक दर्जन से अधिक ट्रेड यूनियनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, यंग वकस लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मेहनतकश वर्ग के जुझारू और भ्रांतिकारी संगठनों को कुचलने के लिए गोतिया चलाई गईं।

इस जबरदस्त सघप का ही यह नतीजा था कि मेहनतकश वर्ग के संगठनात्मक फिर से एकता स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए। 1935 में लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मिलकर एक हो गए और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्वागत समिति के अध्यक्ष एस० एच० ज्ञानवाला ने अपने भाषण में कहा

अपने व्यक्तिगत अनुभव से बिना किसी अतिशयोक्ति के, मैं यह कह सकता हूँ कि कम्युनिस्टों के साथ काम करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कम्युनिस्टों में ही मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो मजदूरों के राजमर्ग के हिता के लिए और उनकी एकता के लिए निरंतर सघप कर सकते हैं। (अल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बंबई के 15वें अधिवेशन की रिपोर्ट, मई 1936)

इस अधिवेशन के मंच से ही नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने सुधारवादी नेताओं के नाम एक अपील की गई थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें मजदूरों के केंद्रीय नेतृत्व में एकता पायाम करने के लिए सहमत हो जाना चाहिए क्योंकि मालिकों और सरकार की ओर से मजदूरों पर हो रहे हमले को मजदूरों के दशव्यापी हमले के जरिए ही रोक जा सकता है। फेडरेशन के नेताओं का विश्वास दिलाया गया था कि एकता के लिए उनकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी बशर्ते वे दो बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत हो जाएं—पहला यह कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का आधार वर्गसघप है और दूसरा यह कि ट्रेड यूनियनों के अंदर जनवादी होना चाहिए। लेकिन फेडरेशन के नेताओं ने तुरंत संगठनात्मक एकता को जाने का विरोध किया। इसलिए 1936 में एक संयुक्त बाढ़ उनाया गया और 1938 में कहीं जाकर नागपुर अधिवेशन के समय नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ सबद्ध हुई और कांग्रेस की प्रवर्ध समिति में दोनों संगठनों के बराबर बराबर प्रतिनिधि शामिल किए गए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एक बार फिर ऐसे संगठन का श्रेय मिला जो भारत के समूचे मजदूर आंदोलन को एकजुट कर सके। केवल एक संगठन इसके बाहर रहा और वह था अहमदाबाद के लेबर एसोसिएशन जो गांधीवादी विचारधारा के तहत था।

राजनीतिक क्षेत्र में भी नई घटनाएं हुईं। मजदूर और किसान पार्टियां अपने दो वर्ग चरित्रों की वजह से राजनीतिक मजदूर संगठन के लिए कोई स्थायी आधार न देकर महज विचारों की सक्रमणकारी न्यस्वा तयार कर मजदूरों की ओर भ्रम के बाण से पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर से गायब हो गईं। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर

दिया गया था पर इस तरह के उपायो से समाजवादी और साम्यवादी प्रभाव तथा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार को नहीं रोका जा सका। 1930-34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाने के बाद शक्ति में और भी वृद्धि हुई क्योंकि बहुत से राष्ट्रवादी युवकों ने इस आंदोलन से सबक लेना गुरु कर दिया था।

1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का गठन युवा वामपंथी राष्ट्रवादी तत्वा के एक ग्रुप ने किया था जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में जाशिक रूप से आ गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की खास विशेषता यह थी कि उसके सदस्य वही लोग हो सकते थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। इस प्रकार यह पार्टी कांग्रेस का एक अंग बन गई जिसमें आम जनता को सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। पार्टी का कार्यक्रम और मविधान कुछ ऐसा था (पार्टी के संस्थापकों में जो प्रगतिशील तत्व थे, उनका इरादा भले ही कुछ भी रहा हो) जिसमें मजदूर आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व व अनुशासन और नियंत्रण के अधीन हो जाता था। व्यवहार में इसका अर्थ यह हो जाता था कि मजदूर आंदोलन पूँजीपतिवर्ग के अधीन हो जाता था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद में ही यह अंतर्विरोध था जिसकी अभिव्यक्ति मजदूर आंदोलन के हर नाजुक दौर में उसकी भूमिका में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का समूचा इतिहास इसका प्रमाण है। यह अंतर्विरोध जागे चलकर पार्टी के भीतर के वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के पक्षों के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ, वामपंथी विचारधारा वाले चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी और मेहनतकशवर्ग के संगठनों के साथ सहयोग किया जाए जबकि प्रतिनिध्यावादी दक्षिणपंथी तत्व, जिनका पलड़ा भारी था, कम्युनिस्ट पार्टी तथा मजदूरवर्ग की हर प्रकार की स्वतंत्र गतिविधियों का विरोध था।

## 7 विश्वयुद्ध से पहले की लहर

चुनावों में राष्ट्रीय कांग्रेस की विजय तथा प्राता में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के साथ साथ ट्रेड यूनियन गतिविधियों की एक नई लहर उमड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि 1937-38 में हड़तालों का जवरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। हथियारों की हड़त से पूँजीवाद को अस्थाई तौर पर पुनर्जीवन मिल गया था और इसके फलस्वरूप समूचे विश्व में हड़तालों की जो लहर आई थी, भारत की ये हड़ताले भी उसका एक अंग थी।

ट्रेड यूनियन आंदोलन इतनी तेजी से फला कि अनेक नई यूनियनों का गठन हुआ और साल में कुछ महीने चलने वाली (सीजनल) फ़ैक्टरियों तथा असंगठित उद्योगों तक के मजदूर इस आंदोलन में शामिल हो गए। पंजीकृत यूनियनों की संख्या बढ़ती गई। 1928 में पंजीकृत यूनियनों की संख्या केवल 29 थी जो 1929 में बढ़कर 75 और 1934 में 191 हो गई थी, 1938 में बढ़कर 296 हो गई। यूनियनों के सदस्यों की संख्या 261,000 हो गई। दरअसल ये मजदूर संगठन ही ऐसे केंद्र थे जो मजदूरों की कई गुना अधिक संख्या का आंदोलन के लिए प्रेरित कर सकते थे।

1937 में हड़तालों की संख्या 379 तक हो गई। 1921 के बाद इतनी बड़ी हड़ताल पहली बार हुई थी। 1921 में भी जो हड़तालें हुई थी वह इस वर्ष की हड़तालों में 17 ही अधिक थीं। 1937 की हड़तालों में 676 000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। पहले कभी मजदूरों ने इतनी बड़ी संख्या में हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया था। यह संख्या ट्रेड यूनियन के सदस्यों की निगुनी संख्या थी। इन हड़तालों में कुल 8,983 000 काम के दिनों का नुकसान हुआ। 1929 के बाद से कभी इतने दिन काम का नुकसान नहीं हुआ था। 45 प्रतिशत मामलों में मजदूरों को अपनी मांगें पूरी कराने में सफलता मिली थी।

हड़तालों का जो सिलसिला चला था उनमें सबसे जबरदस्त हड़ताल बंगाल की जूट हड़ताल थी जो सरकारी दमन के बावजूद समूचे जूट उद्योग में फल गई। इसने आम हड़ताल का रूप ले लिया जिसमें कुल मिलाकर 225,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। मजदूरों के बीच 1929 की उस आर्थिक मंदी के दिनों से ही असंतोष इकट्ठा हो रहा था जब 130,000 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया था, वेतन में कटौती की गई थी और 'अभिनवी' फरण (रेशनलाइजेशन) के नाम पर काम के घंटे बेहद बढ़ा दिए गए थे और मजदूरों का जमकर शोषण किया जाने लगा था। 1931 से 1936 तक बीच हालांकि जूट के मूल्यों में कमी की संख्या केवल 13 प्रतिशत बढ़ी पर जूट के उत्पादन में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बंगाल के प्रसिद्ध जूट उद्योगपति सर जलेक्जेडर मरे ने कहा कि 'जब समूची दुनिया में मंदी आई थी तब भी वे मुनाफा कमाने में सफल हुए।' 1936 से जूट उद्योग पुनर्जीवन प्राप्त करने के युग में प्रवेश कर रहा था और फरवरी में जूट मजदूरों ने अपनी बतन कटौती रद्द करने तथा पर्याप्त मजदूरी पाने के लिए हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल मई तक चली हालांकि फजलुल हक के प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडल ने इसको कुचलने के लिए तरह-तरह के उपाय किए और इसके लिए यह दलील दी कि हड़ताल का कोई जायज आधार नहीं है और 'भारत में शांति का मांग प्रशस्त करने के लिए कम्युनिस्ट लोग इस हड़ताल का इस्तेमाल कर रहे हैं।' मजदूरों ने अपनी एकता कायम रखी और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की हमदर्दी पाने में सफल हो गए। कांग्रेस कमेटी ने जनता से अपील की कि वे जूट मजदूरों की हड़ताल के लिए तैयार कोप में धन दें। अंततः मजदूरों की यूनियन का मान्यता मिल गई और मालिकों को वेतन कटौती रद्द करने का सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा।

हड़ताल की यह जो लहर आई थी उसकी खास बात यह थी कि इस बार बंगाल के गांधीवादी सिद्धांतों पर काम करने वाली यूनियनों के गढ़ अहमदाबाद तक हड़ताल की लपट पहुंच गई। यहाँ बड़े प्रांत की कांग्रेस सरकार ने दंड महिमा की घृणित धारा 144 लागू कर दी जिसके अंतर्गत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों ने एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी थी। यही वह धारा थी जिसका कांग्रेस सभा से विरोध करती आई थी।

इन हड़तालों की चरम स्थिति उम्र समय आई जब कानपुर की बगडा मिला में हड़ताल

का सिलसिला शुरू हुआ। यह हड़ताल भी शीघ्र ही आम हड़ताल में तब्दील हो गई और उसमें 40 000 कपड़ा मजदूर शामिल हो गए। माचिस फैक्टरी, आयरन फाउंड्री और वर्मा शैल डिपो जैसे कुछ अन्य उद्योगों के लोग भी हमदर्दी में हड़तालें कीं। कांग्रेस जाच समिति के फैसले को मजदूरों ने तो मान लिया पर मिलमालिका ने इस फैसले को अमल में लाने से इंकार किया। नतीजा यह हुआ कि 1938 में एक आम हड़ताल शुरू हुई ताकि मालिकों का यह फैसला लागू करने के लिए मजबूर किया जा सके। इस हड़ताल में कांग्रेस और मजदूरवर्ग की आदर्श एकता स्थापित हुई। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि 'कानपुर का मजदूरवर्ग केवल अपने लिए नहीं बल्कि भारत के समूचे मेहनतकशवर्ग के लिए लड़ रहा है (और) मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।' कांग्रेस कमेटी ने जनता से अनुरोध किया था कि 'इस महान् कार्य में, जिसे मजदूरों ने शुरू किया है, जनता को हर तरह की सहायता देनी चाहिए।' मिलमालिका के दलालों ने सांप्रदायिक दंग कराने की कोशिश की पर हिंदू और मुसलमान मजदूरों की एकता ने उनके पड़ोस विफल कर दिए। अंत में 55 दिनों के संघर्ष के बाद मजदूरों की शानदार जीत हुई जिसमें अन्य मांगें पूरी होने के साथ-साथ उनकी यूनियन का भी मान्यता मिली।

नवंबर 1938 में बंबई के 90,000 से ज्यादा मजदूरों ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पूर्ण समर्थन से खतरनाक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल के विरोध में हड़ताल की (इस बिल के जरिए मजदूरों के विवादों को हल करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था दी गई थी जिससे हर मामले में चार महीने के लिए हड़ताल का अधिकार छिन जाता था, साथ ही मजदूर यूनियनों के पंजीकरण के ऐसे नियम बनाए गए थे जिससे कंपनी की समय-ब-समय यूनियनों को फायदा पहुंचता था)। मजदूरवर्ग की चेतना और जागरूकता का यह जबरदस्त प्रदर्शन था। इस हड़ताल द्वारा बंबई प्रांत की कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी गई थी ताकि वह मजदूर संगठनों के द्वारों में किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा करे।

रेल मजदूरों के संगठन का नेतृत्व सुधारवादी नेताओं के हाथ में होने के बावजूद वहां भी मजदूर आंदोलन में पुनर्जीवन के संकेत मिलने लगे। बंगाल नागपुर रेल हड़ताल, जिसमें 40 000 मजदूर शामिल हुए, एक महीने तक चली और उसे कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन का समर्थन मिला। सुधारवादी नेताओं के प्रभुत्ववाली अखिल भारतीय रेलवेमैन फेडरेशन मजदूरों पर होने वाले दमन को चुपचाप देखती रही। 17 प्रतिशत मजदूरों की छटनी हुई, वेतन में कटौती की गई मजदूरों से जमकर काम लिया जाने लगा जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रेलवे कंपनियों के मुनाफे बढ़ते रहे लेकिन फेडरेशन के नेता इन सारी स्थितियों से जाबे-बाद किए रहे। फिर ट्रेड यूनियन गतिविधियों की जो लहर चली थी उसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के सुधारवादी तथा लाल झंडा यूनियनों को मिलाकर एक कर दिया और इसकी सदस्य संख्या 20 000 से भी अधिक हो गई। यही बात बाघ बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे, मद्रास एंड सदन मराठा रेलवे और साउथ इंडियन रेलवे की यूनियनों में भी देखने में आई। ट्रेड यूनियन

आंदोलन की इस जुगारू चेतना से उत्पन्न घतरे का सामना करने के लिए रेल प्रबंधकों ने क्या क्या दावपेच अपनाए इसका एक उदाहरण यह है कि प्रबंधकों ने दाव बड़ीदा एंड सेंट्रल रेलवे की सुधारवादी यूनियन के सामने प्रस्ताव रखा कि 'जब तक श्री जमनादास मेहता का यूनियन से संबंध रहेगा और कम्युनिस्टों को इससे बाहर रखा जाएगा', तब तक उसे मायता मिली रहेगी। लेकिन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के एकीकरण ने और प्रतिद्वंद्वी यूनियनों को मिलाकर एक करने की मजदूरों की जबरदस्त इच्छा ने फूट डालने की इस तरह की साजिशों को नाकाम कर दिया।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना दिवस 30 अक्टूबर 1938 तक इसकी सदस्य संख्या 125 000 हो गई। भारत के मजदूरवर्ग ने साम्राज्यवादी अपराधों के खिलाफ शक्तिशाली राजनीतिक विरोध करके और साम्राज्यवादी दमन के खिलाफ राष्ट्रीय मांगों के समर्थन में हर रोज सघन छेड़कर अपने को साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक संगठित और मजबूत हिस्सा बना लिया था।

इन घटनाओं के साथ साथ और इनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर भी मजदूर आंदोलन की राजनीतिक भूमिका और उसके प्रभाव को महसूस किया जाना लगा। कम्युनिस्ट पार्टियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कांग्रेस के प्रगतिशील तत्वों ने व्यापक अभियान शुरू किया जिसका अनेक ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के वन जाने से नागरिक स्वतंत्रता का क्षेत्र व्यापक हो जाने के कारण प्रतिबंधों के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए अंगरेजी और मराठी में अपना मुखपत्र निकालना संभव हो सका। कम्युनिस्ट पार्टियों ने अंगरेजी में 'नेशनल फ्रंट' नाम से और मराठी में 'क्रांति' नाम से अपने मुखपत्र निकाले। बंबई के मजदूरों के अधिकांश हिस्से की भाषा मराठी थी। इन अखबारों से साम्राज्यवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के विचार का तथा फासिज्म के बढ़ते हुए खतरों का प्रचार किया जा सका। ये अखबार मजदूरों, किसानों तथा रियासतों में बसने वाली जनता के सघर्षों का व्यापक प्रचार करते थे। विभिन्न कांग्रेस समितियों के महत्वपूर्ण पदां पर कम्युनिस्टों का चुनाव किया गया और कांग्रेस की सर्वोच्च निर्वाचित समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कम से कम 20 कम्युनिस्टों को स्थान दिया गया। कम्युनिस्टों तथा कांग्रेस समाजवादी तत्वों के बीच वामपंथी एगेंडा स्थापित करने की बार बार कांशिश की गई ताकि कांग्रेस के असरदार दमिणपंथी नेतृत्व की घटनाटक नीति के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जा सके किंतु कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रति नियावादी नेतृत्व ने जबरदस्त विरोध के कारण इस वाम में सीमित सफलता मिली।

## 8 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में मजदूरवर्ग

सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ने पर भारत में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तथा भारत के मजदूर वर्ग के लिए एक निर्णायक दौर का मुखपात हुआ। राष्ट्रीय नेता अभी टालमटोल में ही

लगे थे कि मजदूर आंदोलन 2 अक्टूबर 1939 को साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ एक दिन की राजनीतिक हड़ताल करके अपने जाग्रमण की शुरुआत कर दी। इस हड़ताल में ववई के 90,000 मजदूरों ने भाग लिया और विश्व के मजदूर आंदोलन में यह युद्धविरोधी पहली हड़ताल थी। शक्तिशाली और संगठित वर्ग के बीच से मजदूरवर्ग भारत में साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों का हरावल दस्ता बनकर सामने आ रहा था।

युद्ध के कारण जीवनयापन के खर्च में तेजी से वृद्धि आई लेकिन इसके अनुरूप वेतन में वृद्धि नहीं हुई और इस बात को भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डा० टी० ई० ग्रेगरी ने भी स्वीकार किया। डा० ग्रेगरी के अनुसार यदि सितंबर की कीमती को 100 मान लिया जाए तो 'प्राथमिक चीजों के दामों का सूचक जून 137 तक पहुँच गया था।' इस सङ्ख्या में फुटकर विप्रेताओं का मुनाफा भी जोड़ा जाना चाहिए। 'वावे ट्रान्जिक्ल' के विशेष सवाददाता ने लिखा कि 'इन सामानों में मुनाफाखोरी (अर्थात् बाजरा, ज्वार, चावल और गेहूँ जैसे अनाजों में) को यदि सितंबर की कीमती पर देखें तो औसतन 28 प्रतिशत थी। यदि इसमें फुटकर विप्रेताओं का मुनाफा जोड़ें जो कि अनुमानतः 8 से 14 प्रतिशत है तो यह पता लगाया जा सकता है कि गरीब आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है।' ('वावे ट्रान्जिक्ल', 6 दिसंबर 1939)

मजदूरवर्ग ने युद्ध के कारण पड़े इन आर्थिक बोझों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत 5 मार्च 1940 को उस समय कर दी जब ववई के 175 000 कपड़ा मिलमजदूरों ने महगाई भत्ता पान के लिए हड़ताल की। यह पूरा हड़ताल थी और 40 दिनों तक चली हालाँकि हड़ताल के दौरान नेताओं की व्यापक तौर पर गिरफ्तारियाँ की गईं। मजदूरों के मकान में घुसकर पुलिस ने परिवार के सदस्यों को पीटा और आतंकित करने की हर कोशिश की पर हड़ताली मजदूरों का मनोबल बना रहा। 10 मार्च को ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आवाहन पर एक दिन की हड़ताल रही जिसमें सभी वर्गों के साढ़े तीन लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया।

ववई की इस हड़ताल से संपूर्ण देश में हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। महगाई भत्ते की माँग को लेकर बानपुर के बीस हजार कपड़ा मजदूरों, कलकत्ता के बीस हजार म्युनिसिपल मजदूरों, बंगाल और बिहार के जूट मजदूरों, असम में डिगबोई के तेल मजदूरों, धनबाद और झरिया के कोयला मजदूरों, जमशेदपुर के लोहा और इस्पात उद्योग के मजदूरों तथा अन्य विभिन्न उद्योगों के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। अब यह बात स्पष्ट हो गई थी। समूचा मेहनतकशवर्ग लड़ाई में शामिल हो गया था।

सरकार ने एक बार फिर हमला किया। 'नेशनल फ्रंट' और 'प्राति' जखबारा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत रक्षा अधिनियम बानून जारी कर दिया गया। देश भर में कम्युनिस्टों तथा अन्य प्रगतिशील तत्वों की गिरफ्तारियाँ की गईं और जनवरी 1941 में

सरकार के गृहमन्त्री रेजिनेल्ड मैक्सवेल ने कहा कि जेलों में जो 700 व्यक्ति बिना मुकदमे के बंद हैं उनमें से लगभग 480 व्यक्ति बिना किसी अपवाद के या तो घोषित रूप से कम्युनिस्ट हैं या हिंसात्मक आति के कम्युनिस्ट कार्यक्रम के सक्रिय समर्थक हैं' (लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स, 12 फरवरी 1941)। इसके अलावा 6,466 व्यक्तियों का सजा हो चुकी थी और 1,664 व्यक्तियों का नजरबंद कर दिया गया था, उनपर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे या उन्हें निर्वासित कर दिया गया था।

कम्युनिस्ट पार्टी पर सरकार की तरफ से तो हमला ही हो रहा था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी इसी समय कम्युनिस्टों के खिलाफ आक्रमण शुरू किया और अपनी पार्टी से उन लोगों को बाहर निकाल दिया था जिनपर कम्युनिस्ट होने का संदेह था या जो कम्युनिज्म के प्रति हमदर्दी रखते थे। अपनी इन कार्रवाहियों के पक्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने यह दलील दी कि वे (कम्युनिस्ट) अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकें। पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण ने सदस्यों के नाम एक गंभीर चिट्ठी में लिखा कि कुछ गैरजिम्मेदार लोग हैं—जो बिना सोच-समझे और दुस्साहसपूर्ण ढंग से हिंसा की भावना को बढ़ावा देते हैं—गांधी जो यह समझ सकें कि हम (कांग्रेस सोशलिस्ट) हमेशा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित जनसंघर्ष पर जोर देते हैं।' इस अवधि के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जुझारू सदस्यों का एक बहुमत अपनी पार्टी छोड़कर गैरकानूनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। वह इस तरह के सोशलिस्ट नेतृत्व से बहुत असंतुष्ट था जिसने अहिंसा से गांधीवादी सिद्धांत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और वग-संघर्ष के आधार को तिलाजलि दे दी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे नेताओं का महज एक गुट बनकर रह गई जिनका न तो कोई जनसंगठन था और न तो मजदूरवर्ग में कोई वास्तविक आधार ही था।

अधिकारियों के आक्रमण के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी का न तो संगठन टूट सका और न उसके सदस्यों की सक्रिय भूमिका में ही कोई कमी आई। हालांकि सरकार ने इसके लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया पर पार्टी बाकायदा काम करती रही, कुछ नेता पुलिस को चमका देकर काम करते रहे और कानूनी जनआंदोलन के साथ गैरकानूनी आतिकारी प्रचार का काम भी होता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य संख्या में कम थे और उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इसलिए वे घटनाओं को कोई निर्णायक मोड़ तो नहीं दे सके पर इसमें किसी को संदेह नहीं रहा कि यही पार्टी मजदूरवर्ग की असली पार्टी है और भारतीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति है।

इसके साथ ही देश भर में मजदूरवर्ग ने मिलकर जो आंदोलन किया उसका नतीजा यह हुआ कि केंद्रीय ट्रेड संगठनों में पूर्ण एकात्मता कायम हो गई। नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस पूरी तरह आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ मिल गई, पर मिलने से पहले उसने जोर देकर विधान में यह संशुद्धि करा ली कि सभी राजनीतिक संघात, हड़तालों



से संबंधित मसले तथा किसी विदेशी संगठन से संबद्ध होने के सवाल तीन चौथाई बहुमत से तय किए जाएंगे।' ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के जुझारू वग न एकता के हित में इस धारा का मान लिया हालांकि बाद के वर्षों में इसने संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को गंभीर नुकसान पहुंचाया और इसके कारण मजदूरों को स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिना जा सका।

इस सीमा निर्धारण से जो नुकसान हुए उन्हें युद्ध तेज हाने पर उत्पन्न कुछ नई समस्याओं के सदर्भ में तब देखा गया जब सोवियत संघ पर नाज़ियों ने हमला कर दिया, युद्ध के मैदान में जापान कूद पड़ा और उसने दक्षिण पूर्व एशिया को रोद डाला, संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना हुई और भारत के लिए जापान का खतरा बढ़ने लगा।

फरवरी 1942 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। इस बीच मजदूरों की हालत काफी खराब हो गई थी। जापानी सेना मलया और बर्मा को रौंदने के बाद भारत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन का केंद्रीय नेतृत्व मजदूरों को स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व देने में असफल रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के उस प्रस्ताव का बहुमत ने समर्थन दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में युद्ध का बिना शर्त समर्थन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के काम को कारगर बनाने के लिए भारत के मजदूरों को राष्ट्रीय मागपत्र (चाटर ऑफ नेशनल डिमांड्स) के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन प्राप्त था फिर भी उसे आवश्यक तीन चौथाई वोट नहीं मिले। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल प्रत्येक राजनीतिक दल को इस बात की छूट मिल गई कि वह अपनी निजी नीतियों का प्रचार करे।

1942-45 का दौर मजदूरवर्ग के लिए तथा संपूर्ण देश के लिए जग्नपरीक्षा का दौर था। इस दौर में तमाम घटनाएं हुई, सरकार युद्ध का खर्च चलाने के लिए अधाधु ऐसे काम कर रही थी जिनसे भ्रष्टास्फीति बढ़ती है, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की जखीरेबाजी और चोरबाजारी हो रही थी, रहन सहन का खर्च 200 प्रतिशत बढ़ गया था, देश भर में राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारियां की गईं और इसके बाद काफी बड़े पैमाने पर सरकार का दमनचक्र चला, सरकारी नीति से संपूर्ण देश में रोप की लहर दौड़ गई ये और ऐसी बातें थी जिनमें से कोई एक अकेले भी होती तो मजदूरवर्ग हड़ताल पर चला जाता लेकिन यह मजदूरवर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी की विवेकपूर्ण वगभावना और विकसित राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण है कि उन्होंने बदली हुई परिस्थिति को समझा, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को महसूस किया और हड़तालों से अपने को बचाए रखा हालांकि इस बात के भी प्रमाण है कि अनेक अवसरों पर मजदूरों को भड़काया गया और मजदूरों के एक वग को घूस देने की काशिश की गई ताकि वे हड़ताल करें। यह बात काफी महत्वपूर्ण है कि इस दौरान केवल दो जगह महत्वपूर्ण हड़तालें हुईं, एक तो गांधीवादी ट्रेड यूनियन

आंदोलन के गढ़ अहमदाबाद में जो तीन महीने तक चली और दूसरी हड़ताल जमशेदपुर के लोहा और इस्पात कारखाना में। इन हड़तालों में मजदूरों का जितना श्रेय था, कम से कम उतना ही मानिकों का भी था।

इस अवधि में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूरवर्ग ने साम्राज्यवादी दमन का डटकर मुकाबला किया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 25 सितंबर 1942 को दमन विरोधी दिवस मनाने का आह्वान किया। पार्टी ने देशरक्षा के विचारों का प्रचार किया, जनता की दैनिक जरूरतों में सतत मूल्य नियंत्रण और राशनिंग के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ा। काला बाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त शुरू किया तथा जनता को इस बात के लिए आगाह किया कि वे साम्राज्यवादी उकसावे या जापानी प्रलोभना में न पड़े।

इन कार्यक्रमों से ट्रेड यूनियन आंदोलन विकसित हुआ और आंदोलन पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ा। 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी को 8 वर्ष तक गैरकानूनी रहने के बाद कानूनी करार दिया गया जो कि मजदूरवर्ग के आंदोलन की सफलता थी। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों के निम्नांकित आंकड़ों से ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास देखा जा सकता है

| वर्ष         | ट्रेड यूनियनों की संख्या | पंजीकृत सदस्यों की संख्या |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 1938         | 188                      | 363 450                   |
| 1940         | 195                      | 374,256                   |
| 1941         | 182                      | 337 695                   |
| 1942 (फरवरी) | 191                      | 369,803                   |
| 1943         | 259                      | 332,079                   |
| 1944         | 515                      | 509 084                   |

1942-45 की संकट की घड़ी में अत्यंत विपन्न परिस्थितियों के बावजूद कम्युनिस्टों ने जो बहुमुखी कार्य किए, उससे पार्टी की सदस्यता काफी बढ़ गई। जुलाई 1942 में सदस्यों की संख्या महज 4,000 थी जो मई 1943 तक 15 000 की भारी संख्या तक पहुंच गई। जनवरी 1944 में यह संख्या 30 000 और 1946 की गरमियां तक 53,000 से भी अधिक हो गई।

युद्ध के दौरान एम० एन० राय ने समझकों ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूट डालने का असफल प्रयास किया। एम० एन० राय के समर्थकों ने पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी हिंसा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया था। इन समर्थकों ने 1941 में तत्कालीन इंडियन फेडरेशन ऑफ नवर् की स्थापना की जिस सरकार से 13 000 रुपये मासिक का अनुदान मिलता था। इन्होंने काफी जमकर प्रचार किया फिर भी मजदूरवर्ग के बीच

इनकी प्रभावकारी पैठ नहीं हो सकी। सितंबर 1946 में एक सरकारी जांच ने जतन नियम दिया कि सात लाख सदस्या वाली आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की निर्णायक रूप से प्रतिनिधि संस्था है।

1940 के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मुख्यता नेताओं का एक जुट बनकर रह गई थी। उसने कांग्रेस के 1942 के प्रस्तावों तथा कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी (अध्याय 16 देखें) के बाद अपना गुप्त संगठन बनाने की कोशिश की और कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हो गया था उसे संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें अपने इन प्रयासों में मजदूरवर्ग का सहयोग नहीं मिल सका। विद्रोह के शांत होने पर तथा अपने प्रयासों के व्यर्थ प्रमाणित होने पर उन्होंने तेजी से अपना रवैया बदला, 'अब वे फासीवाद के प्रति तटस्थ न रहकर ऐसे रव्य अख्तियार करने लगे जो सुभाषचंद्र बोस के समर्थकों के काफी समतुल्य था (सुभाषचंद्र बोस ने जर्मन और जापानी फासीवाद के साथ समझौता कर लिया था। उन्हें यह आशा थी कि फासिस्टों की मदद से वे भारत को आजादी दिला लेंगे)। इन सबके बावजूद सचार्इ यह थी कि उन्होंने (कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने) जनता की स्वतः स्फूर्त वीरता की प्रशंसा में बशुमार गैरखानूनी साहित्य प्रकाशित किया था और कुछ हद तक तोडफोड की कायबाही का संगठन किया था इसलिए देश के युवा राष्ट्रवादियों पर और खासतौर से छात्रों पर उनका प्रभाव बढ़ गया लेकिन मजदूरों में वे अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सके। युद्ध के बाद उन्होंने कम्युनिस्टविरोधी और सोवियतविरोधी प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया।

युद्ध के दौरान मजदूरवर्ग के आंदोलन में जो सफलता प्राप्त की और जो प्रगति की वह घटनाक्रम के विकास की एक अविस्मरणीय अवस्था है। युद्ध समाप्त होने और फासीवाद पर विजय प्राप्त करने तक मजदूर आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघन करनेवाला सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा अनुशासित शक्ति बन गया था। इसका प्रमाण युद्ध बाद के महान जनमण्डलों में देखने को मिला। आम राजनीतिक आंदोलन के नेताओं में जबरदस्त मतभेद के बावजूद मजदूर आंदोलन में हिंदू, मुसलमान और अछूत सब एक-मंच पर एकजुट रहे। राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक मुक्ति के लिए होने वाले जागे के सघनों में मजदूरवर्ग को हरावल दस्ता का स्थान प्राप्त हुआ।

भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया हालांकि जनता पर प्रभाव के मामले में इसकी तुलना राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग से नहीं की जा सकती। कम्युनिस्ट पार्टी का इस स्थिति तक पहुंचना ही मजदूरवर्ग की प्रगति का चोख है। युद्ध के बाद जो तूफानी दौर शुरू हुआ जो महान राष्ट्रीय विद्रोह शुरू हुआ और हड़-ताड़ों का जो जबरदस्त सिलसिला चल पड़ा वह मजदूरवर्ग के आंदोलन का एक विकास था। जनमण्डलों में मजदूरवर्ग ने हरावल की भूमिका निभाई और यह प्रथम अवधि जारी है।



## भारतीय जनतंत्र की समस्याएँ

-

प्राचीन रोमन सम्राटों का यह आदर्श वाक्य था कि 'फूट डालो और राज करो', और यही हमारा भी आदर्श वाक्य होना चाहिए।—थॉमस के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन का कथन, 14 मई 1859 का कायवृत्त।

भारतीय राष्ट्रवाद, किसान विद्रोह और मजदूरवर्ग के आंदोलन की उभरती शक्तियाँ ही भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वे किसी भी अर्थ में भारतीय समाज की समूची तस्वीर नहीं हैं। हालाँकि वे भारतीय जनता के एक विशाल हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं फिर भी उन्हें सारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता। यदि वे ही शक्तियाँ समूची जनता का प्रतिनिधित्व करती, यदि यह सघर्ष एवं खेमे में स्थित संयुक्त भारतीय जनता तथा दूसरे खेमे में स्थित मुट्ठीभर ब्रिटिश शासकों के बीच का साधारण सघर्ष होता तो यह पहले ही समाप्त हो चुका होता या यों कहें कि अंगरेजों का प्रभुत्व कभी नहीं कायम हो पाता।

साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत भारत जैसे किसी समाज के लिए जहाँ विकास का अवकाश हो जाना ही घास विशिष्टता हो, लाजिमी तौर पर समाज की रूढ़िवादी शक्तियाँ अपनी अदृष्टनी ताकत के कारण महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन्हीं पतनो-मुख शक्तियों के कारण साम्राज्यवादियों की विजय संभव हो सकी। राष्ट्रीय जागरण की लहर तेजी से ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है ऐसा लगता है कि इन पुराने अवशेषों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसका असली कारण यह है कि साम्राज्यवादी शासन के ये ही एरनास जीवित अवलंब हैं।

सार्वजनिक बर्मीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले पुनः ब्रिटिश नागरिकों की संख्या 156,000 है (यद्यपि यूरोपीय पंजीकृत लेकिन मुख्यतया ब्रिटिश)। 1931 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 168,000 है। इनमें से 60,000 सेना में, 21,000 व्यापार या निजी व्यवसाय में और 12,000 सरकारी अंतर्निहित सेवा में थे। इसका अर्थ यह है कि देश पर साम्राज्यवादी शासन का प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की कुल वास्तविक संख्या 100,000 से कम है या प्रति 4000 भारतीय पर 1 के अनुपात में है। हालांकि इस बात का पूरा एहतिपात बरता गया है कि भारतीय जनता को निरस्त रखा जाए और खासतौर से गार गारी हथियार, तापखान और वायुसेना ब्रिटिश हाथों में बंद रहने दिए जाएं फिर भी यह स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति केवल ताकत के बल 40 करोड़ भारतीयों पर निरंतर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की आशा नहीं कर सकती। इसलिए अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उसे भारतीय जनता के बीच से ही अपने लिए एक सामाजिक आधार तैयार करना अनिवार्य है।

साम्राज्यवादी शासन बने रहने की यह अनिवार्य शक्ति है कि भारतीय जावादी के बीच ही एक ऐसा सामाजिक आधार बरकरार रखा जाए जो साम्राज्यवाद के साथ संबद्ध हो। प्रत्येक प्रतिक्रियावादी शासन और खासतौर से विदेशी शासन के राज्यतंत्र के लिए यह जरूरी है कि वह जनता में फूट डाले। लेकिन इस तरह का सामाजिक आधार प्रगतिशील तत्वों में नहीं मिल सकता क्योंकि ये साम्राज्यवाद के विरुद्ध तन रहे हैं। यह आधार केवल प्रतिक्रियावादी तत्वों के बीच ही तैयार किया जा सकता है क्योंकि इस बात के हित हमेशा जाता है कि हितों के विपरीत होत है। हमने पहले ही यह देख लिया है कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार अपने को बड़े सचेतन वर्ग में जमींदारवर्ग के आधार पर खड़ा किया है—भाटे तौर पर इस वर्ग को अंगरेजों ने ही राज्य की नीति के रूप में अपना सरकारी आदेशों के जर्गिए पैदा किया है। इन तत्वों के साथ-साथ अनेक ऐसे व्यापारिक एवं महाजनी हित भी हैं जो आपण की साम्राज्यवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और जो साम्राज्यवाद की ओर इस हसरत से देख रहे हैं कि वह उन्हें सुरक्षण प्रदान करेगा तथा सरकारी स्तर पर अपना भातहत बनाकर रखेगा। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार साम्राज्यवाद ने सामाजिक सुधार की अपनी भूमिका को एक सौ वर्ष पहले ही छोड़ दिया है और आज जहां तक उसमें संभव हो पाता है वह सुधार की राष्ट्रीय भाषा के विरुद्ध हर उस चीज का पोषण करता है जो उसे सुरक्षण देता है जो जनता के जीवन में सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ापन लाती है (साथ ही वह हमेशा यह भी कहता रहता है कि जनता की सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों में वह हस्तक्षेप नहीं करता है और निष्पक्ष भूमिका निभाता है), साथ ही वह जनता के बीच नदभाव पैदा करने की चिन्माल से चली आ रही प्रतिक्रियावादी नीति का जहां तक हो सकता है दस्तकाल करता है, उदाहरण के लिए जातपात का भेदभाव (दलित वर्गों का अलग से प्रतिनिधित्व तथा इस आधार पर कनी पार्टियों की प्रोत्साहन देने की नीति)। लेकिन यह नीति जितनी धूर्वी के साथ इस दो क्षेत्त्रों में अपनाई गई है उतनी और कही देखने का

मिनती एक तो भारतीय राजाओं या तत्कालीन 'भारतीय रियासतों' के मामले में दूसरे सांप्रदायिक भेदभावों को, खासतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बैर-वद्वाने के क्षेत्र में।

3 की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ के सदृश में राष्ट्रीय आंदोलन के सामने जो आम या है, वस्तुतः ये दोनों समस्याएँ उस आम समस्या का ही रूप हैं। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हो रहा है इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इस्तेमाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान युग के चरित्र में ही यह बात निहित है। साम्राज्य-शासन के समाप्त होने के ये लक्षण हैं। इनसे यह पता चलता है कि साम्राज्यवादी या इस जुए में अपनी अंतिम बाजी लगा रही है। भारत में जनतन्त्र की विजय के इन समस्याओं का समाधान किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

## 1 राजा महाराजा

राज्यवाद ने भारत को असमान खंडों में बांट रखा है एक खंड है ब्रिटिश भारत और 21 खंड हैं तत्कालीन 'भारतीय रियासतें'। इस वद्वारे को किसी भी जय में प्रशासन दृष्टि से किया गया वद्वारे नहीं कहा जा सकता और इसका विस्तार देश की राजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में काफी गहराई तक है। इस वद्वारे के अंदर असंगत स्वरूप को सभी समझा जा सकता है जब यहाँ के मानचित्र का ध्यान से अध्ययन किया जाए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के मानचित्र पर जो छोटी-छोटी 'रियासतें' हैं और अस्तव्यस्तता का जो अराजक बोलाहल है उसकी तुलना 9वीं सदी से पूर्व के जमानों की भी राजनीतिक प्रणाली कहीं ज्यादा व्यवस्थित थी।

उत्तर में पंजाब, उत्तर से दक्षिण तक, काठियावाड़ की 200 रियासतों या पश्चिम में गुजरात से लेकर मणिपुर की अनेक रियासतों और ध्रुव पर्वत में वेणुमार यामी सरदारों, उत्तर में कश्मीर और शिमला की छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों से लेकर दक्षिण में तमिल तथा मद्रास की रियासतों तक हर जाति प्रजाति की अनेक रियासतों की जनक होती है। इनका विस्तार भारत के पाँचवें हिस्से से लेकर आधे हिस्से तक है (वर्मा के मानचित्रों से जब यह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा तक फैला हुआ है)। जो चौहद्दियाँ ऐसी हैं जो किसी भी नवजातवादी के लिए चुनौती हैं। भारत में कुल 31 रियासतें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 712,000 वर्गमील और आबादी 8 करोड़ 10 लाख (1931 की जनगणना के अनुसार) है जो भारत की कुल आबादी का लगभग एक पाँचवाँ (24 प्रतिशत) है। इनमें हैन्दववाद जैसी रियासतें भी हैं जो आचार में दृढ़ता के साथ हैं और जिनमें आबादी 1 करोड़ 40 लाख है ताकि जहाँ बहुत छोटी रियासतें हैं जिनका क्षेत्रफल महज 19 वर्गमील है और जिनमें जहाँ छोटी पहाड़ी रियासतें भी हैं छोटी-छोटी जातों में बाँटा ही बँटकर रहती हैं। इन रियासतों के अंदर तब-तब अंतर 1931 में 5 विभिन्न सामान्य जातें नहीं किया जा सकता। इनमें 103 वर्ग

रियासते हैं जिनके शासकों को चैवर आफ प्रिंसेज में शामिल किया गया है। 127 ऐसी छोटी रियासते हैं जिनके शासक अप्रत्यक्ष रूप से अपने 12 प्रतिनिधि चुनकर चैवर आफ प्रिंसेज में भेजते हैं। शेष 328 रियासते दरअस्त एक तरह की जमींदारिया हैं जिनको कुछ सामंती अधिकार भी मिले हुए हैं पर जिनका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। जो रियासते अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं उनमें निर्णायक शक्ति एक अगरेज रेजीडेंट के हाथ में होती है। छोटी रियासतों के लिए सरकार के कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि (पोलिटिकल एजेंट) हैं जो जलम अलग इलाकों की देखरेख करते हैं।

इन्हें 'स्टेट' कहना सचमुच इनको एक गलत नाम देना है क्योंकि ये पुरानी रियासतों के प्रेत या सरक्षित अवशेष हैं जिन्हें कृत्रिम ढंग से बनाए रखा गया है। इन रियासतों के राजा महाराजा बिलकुल ही भ्रम, सत्तालुब्ध शक्ति के हावों की कठपुतली हैं जो सत्ता के राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं। इन राजाओं को छोटे छोटे मामलों में जनता पर मनमाना अत्याचार करने की और कानून की अवहेलना करने की पूरी छूट थी लेकिन वास्तविक और निर्णायक शक्ति अगरेजों के ही हाथ में होती थी। 1853 में माक्स ने इस सद्भ में जो लिखा था वह आज भी काफी सही है

जहाँ तक देशी रियासतों का संबंध है, जिस क्षण से वे कंपनी के नियंत्रण में आईं या कंपनी द्वारा उन्हें संरक्षण मिलने लगा, उसी क्षण से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया जिन परिस्थितियों में उन्हें ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली अपनी आजादी को बनाए रखने की इजाजत दी जाती है, वे परिस्थितियाँ स्याई पतन की परिस्थितियाँ हैं—उनमें किसी भी हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता। मौन अनुमति पर टिके सभी अस्तित्वों की ही तरह मूलभूत कमजोरी ही उनके अस्तित्व का सहज नियम है। इसलिए देशी रियासतों के नहीं बल्कि देशी राजाओं महाराजाओं और उनके दरबारों के बने रहने से मसला हल होता है। देशी राजा महाराजा वर्तमान घृणित अगरेजी शासनव्यवस्था के गढ़ हैं और भारत की प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हैं। (माक्स दि नेटिव स्टेट्स', न्यूयाक डेली ट्रिब्यून, 25 जुलाई 1853)

माक्स ने यह बात 86 साल पहले कही थी। भारतीय 'रियासते' या दूसरे शब्दों में कह तो भारतीय राजा आज भी अपनी 'स्याई पतन' की स्थिति में पड़े हुए हैं, और इस बात की अत्यंत धिनीनी कोशिश की गई है कि इन लाशों का विप्रवसनीय रूप में सहज सच्ची बनाकर पण किया जा सके। ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की समय अन्यवस्था से भर रहा था कि भारत की पीड़ा कि समान राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के जरिए वह इस बात का पूरा कर रहा है। फिर क्या बजह है कि वही ब्रिटिश शासन विनाश के बगार पर अभी इन रियासतों के मायाजाल का इतना जागरण के



साथ बनाए रखने पर तुला है जबकि इन रियासतों के अस्तित्व से सभी प्रशासनिक और वैधानिक एकरूपता को या जत्यत बुनियादी न्यूनतम मनदंडा को बनाए रखने के काम को और यहाँ तक कि आकड़ों से सवधित एकरूपता को क्षति पहुँच रही है ? यदि बुजुर्ग शासन की दृष्टि से या व्यापारी के खाते को ध्यान में रखकर अथवा पूँजी लगान वाले पूँजीपति की दृष्टि से देखे तो अमृत ढग स विचार करने पर यह प्रणाली वेहद असंगत लग सकती है क्योंकि किसी बुजुर्ग, व्यापारी या पूँजी निवेशक के लिए जत्यत समान आर्थिक प्रशासनिक प्रणाली का होना आवश्यक है ताकि देश के अंदर आसानी से घुसपैठ की जा सके । लेकिन सचार्ई यह है कि बुजुर्ग इंग्लंड में राजतंत्र और कुलीनतंत्र (इसी तरह के प्रेततुल्य और नपुंसक रूप में) को बनाए रखने की तुलना में यह कतई असंगत नहीं है । इसके जो कारण हैं वे 'राज्य के कारण' हैं । भारत में विदेशी बुजुर्ग शासन के बने रहने के लिए इसे सामंती आधार का समर्थन मिलना जरूरी है ।

अंगरेजों ने देशी राजाओं को अपनी कठपुतलियाँ बनाकर रखने की नीति का पालन हमेशा किया और यह नीति आधुनिक काल तक जारी है । 19वीं सदी के पूर्वाध में जब अंगरेज बड़े उत्साह के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग गये और उन्हें अपनी ताकत में विश्वास था, वे सहो गलत कोई न कोई बहाना ढूँढकर इन पतनोन्मुख रियासतों को एक एक कर अपने राज्य में मिला लेने की नीति का पालन कर रहे थे । लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति बदल गई । 1857 का विद्रोह सामंतवाद की नष्ट हा रही शक्तियों का, देश के पुराने शासकों का विदेशी प्रभुत्व की बढ़ती हुई धारा को वापस मोड़ने के लिए किया गया आखिरी प्रयत्न था । जैसा पहले ही बताया जा चुका है नवजात युजुआवग का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षित वर्ग ने, जो इस समय की प्रगतिशील शक्ति या विद्रोह का खिलाफ ब्रिटिश शासन का समर्थन किया । विद्रोह तो कुचल दिया गया पर अंगरेजों को इससे एक अच्छा सबक मिला गया । इसके बाद में ही सामंती शासक ब्रिटिश राज के न ता मुख्य प्रतिद्वंद्वी रह गए और न उनके लिए कोई ठोस खतरा बन सका, इसके विपरीत वे जागृत जनता की प्रगति के भाग के प्रमुख अवरोध बन गए । प्रगतिशील तत्वा का प्रति पहले अच्छा व्यवहार किया जाता था पर अब उन्हें सदेह से देखा जाना लगा और सरार का लगा कि जनता की आत्मा ही शक्ति का कुशल नेतृत्व यही शक्तियाँ अब करेंगी । इस अवधि में सामंती तत्वा का अधिक से अधिक सहारा लेने और देशी राजा महाराजा तथा उनकी रियासतों को ब्रिटिश शासन का स्तंभ का रूप में बनाए रखने की नीति अपनाई गई ।

विद्रोह से एकदम पहले के वर्षों में सर विनियम स्टीमन ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी का चतावनी दी थी कि अवधि का अपने साम्राज्य में मित्रान से जितनी बड़ी कीमत ब्रिटिश सरकार का अपन करने की होगी वह अवधि जैसे उस राज्या के बराबर होगी और इसकी वजह से सिपाहियों में विद्रोह हाना अवश्यभावी है । उन्होंने यह भी धारणा व्यक्त की कि भारतीय रियासतों का तरंग राध' जनतंत्रता साक्षि बनाने के अर्थ में भी 'गमाए' जाएंगे तो फिर हम अपनी गनी गनी की गनी पर निर्भर रहना पड़ेगा जो

जरूरी नहीं कि हमेशा पर्याप्त रूप से हमारे नियंत्रण में रहे।' लेकिन डलहौजी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह विस्तार की नीति का जब प्रबल समर्थक और प्रवक्ता था और अपनी इस नीति का वह पूरे जोश खराश के साथ पालन करता था। 1857 के विद्रोह के अनुभवों से इस नीति में निर्णायक तब्दीली आई।

1858 में महारानी की घोषणा में इस नई नीति का एलान किया गया 'हम देशी राजाओं के अधिकार, प्रतिष्ठा और सम्मान को अपना अधिकार, प्रतिष्ठा और सम्मान की तरह समझेंगे।' 1860 में, डलहौजी के उत्तराधिकारी गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने इस नीति के उद्देश्य को बहुत साफ शब्दों में बतला दिया

सर जान मैलकोन ने बहुत पहले ही यह कहा था कि यदि हमें समूचे भारत को जिलों में बांट दिया तो कुदरती तौर पर हमारा साम्राज्य पचास वर्ष भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन यदि हमें देशी रियासतों को राजनीतिक ताकत दिए बिना अपना हथियार के रूप में बनाए रखा तो जब तक हमारी नीसना की श्रेष्ठता बनी रहेगी तब तक भारत में हम भी बने रहेंगे। इस बयान में काफी सच्चाई है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं और हाल की वास्तवता ने तो उनके बयान का और भी गौरवशालक बना दिया है। (लार्ड कैनिंग, 30 अप्रैल 1860)

इस प्रकार सारा जाटतोड़ इस तरह किया गया था कि ब्रिटिश राज्य को बनाए रखने के लिए भारतीय राजाओं को बिना राजनीतिक ताकत दिए शाही हथियार के रूप में सुरक्षित रखा जाए। पंद्रह वर्षों बाद वायसराय लार्ड लिटन ने 1876 के रायल टाइटिल्स बिल के महत्व का इसी तरह बयान दिया। इस बिल के जरिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। लार्ड लिटन ने इस बिल के बारे में कहा कि यह एक नई नीति की शुरूआत है जिसके जरिए आज से इंग्लैंड के सम्राट को शक्तिशाली देशों कुलीनतंत्र के हितों आशाओं, आकांक्षाओं और उसकी हमदस्तियों का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए।'

इस प्रकार देशी रियासतों का समाप्त होना से बचा लेना—जो अंगरेजी राज ने हाल पर देर सत्र जल्द समाप्त हो जाती, अंगरेजों की आधुनिक नीति का परिणाम था और यह पहना एकदम गलत है कि इन रियासतों के बने रहने से भारत की प्राचीन परंपराओं एवं संस्थाओं के अवशेष जीवित थे। देशी राजाओं के प्रमुख सरकारी प्रचारक प्राफेसर रणजित विलियम्स ने 1930 में एलान किया था। (प्राफेसर विलियम्स 'द इंडियन प्रिंसज एंड द आगनाइजेशन' के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे चुके हैं। गोलमज मम्मेलन में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार रहे चुके हैं और 1925 तक भारत सरकार के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर रहे चुके हैं)

देशी रियासतों का समाप्त अंगरेजी राज के साथ अपने संबंधों का प्रति काफी बफादार

है। उनमें से अनेक का अस्तित्व तो ब्रिटिश सरकार के 'चाय और हथियारों' पर टिका हुआ है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए संघर्षों के समय यदि ब्रिटिश सरकार ने इन शासकों को मदद न दी होती तो आज उनमें से अनेक का कहीं नाम निशान भी न होता। मौजूदा गडबडिया और आने वाले दिनों में होने वाले उलटफेर के समय भी इन राजाओं के प्यार और निष्ठा से ब्रिटन सरकार को काफी मदद मिलेगी।

भारत भर में फैली इन सामंती राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो हमारे लिए रक्षा उपाय का काम करती है। इन राज्यों की स्थिति ऐसी ही है जैसे किसी विवादग्रस्त इलाके में हमारे दोस्तों ने जवरदस्त किलाबंदी कर रखी हो। इन शक्तिशाली और निष्ठावान देशी रियासतों के इस जाल के कारण अंगरेजों के खिलाफ किसी आम विद्रोह का समूचे देश में फैलना बहुत कठिन होगा।

(एल० एफ० रशब्रुक विलियम्स का 'इर्वनिंग स्टैंडर्ड' में बयान, 28 मई 1930)

लेकिन यह 'किलेबंदी' उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूती का दावा इन प्रतिक्रियावादी गुलाम रियासतों के भद्र सरकारी प्रचारक किया करते हैं। यह सभी लोग जानते हैं कि अधिकांश राजा महाराजा अंगरेजों की ताकत के बल पर अपनी प्रजा की इच्छा के विरुद्ध शासन कायम किए हुए हैं।

यदि इनकी प्रजा के बीच आज जनमत संग्रह कराया जाए तो पता चलेगा कि लोग बड़ी खुशी के साथ रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिलाने के पक्ष में मत देंगे। इन रियासतों का अस्तित्व अंगरेजों की कृपा से ही बना हुआ है। (एस० सी० 'रंगा अय्यर इंडिया, पीस आर वार')

आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता होती है वे विशेषताएँ इन रियासतों में से किसी के पास शायद ही हों। ज़ामतौर पर इनकी सीमाएँ कृत्रिम होती हैं और वे जाति धर्म या संस्कृति के भेदों के अनुरूप नहीं होती। इसके अलावा राज्य के साथ राजवंश को जोड़ने वाले तत्व आकस्मिक और कृत्रिम हैं और बहुधा 200 वर्ष से कम पुराने हैं। दूसरी तरफ़ इन रियासतों की प्रजा को ब्रिटिश भारत के उनके भाइयों के साथ जोड़ने के जो सांस्कृतिक और सामाजिक सबंध हैं वे काफी शक्तिशाली और पुराने हैं। ऐसा लगता है कि राजा के प्रति प्रजा का जो प्रेम है वह इस सबंध में किए गए प्रचार की तुलना में काफी कम है। (जे० टी० ग्वेइन कांग्रेस ऐंड दि स्टेट्स, मनचेस्टर 'गार्जियन', 12 मई 1939)

1929 की बटलर कमिटी की रिपोर्ट में औपचारिक तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी गई थी

कि 'विद्रोह अथवा बगावत' की स्थिति में देशी राजाओं की रक्षा करना अंगरेज सरकार का कर्तव्य है।

सधियों और सनदों की धाराओं को तथा राजाओं के अधिकारों, सम्मान और गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के सम्राट के वायदों को और दस्तूर को देखते हुए कहा जा सकता है कि सर्वोपरि सत्ता (सम्राट) का यह कर्तव्य है कि वह विद्रोह या बगावत की स्थिति में रियासतों की रक्षा करे देशी राजाओं के अधिकारों, सम्मान और गौरव को सदा अक्षुण्ण रखने के सम्राट के वायदे में यह बात भी शामिल है कि यदि किसी देशी राजा को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे ढंग की शासनव्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाए तो ब्रिटिश सरकार का फज होगा कि उसकी रक्षा करे। (रिपोर्ट आफ दि इंडियन स्टेट्स कमेटी, 1929, अनुच्छेद 49 और 50)

इस तरह अंगरेजों की देखरेख में किस प्रकार की शासनव्यवस्था को मरक्षण मिल रहा था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल नेहरू ने एक भारतीय रियासत के सामान्य वातावरण का चित्र खींचा है

यहां जुल्म का एहसास होता है ऐसा माहौल है जिसमें दम घुटता है और सास लेना मुश्किल लगता है। इस ठहरे हुए या धीरे धीरे बह रहे पानी के नीचे सड़न और गतिहीनता है। इसे देखकर कोई भी आदमी खुद को दिमागी और शारीरिक तौर पर कंद और घिरा हुआ महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि एक तरफ तो जनता बेहद पिछड़ेपन और बगाली की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ शाही महलों की तड़क भड़क की कोई सीमा नहीं है। रियासत की गणति का कितना बड़ा हिस्सा इन राजाओं की निजी जल्दरता और उनके ऐशो-आराम पर खर्च होता है और इसका कितना कम हिस्सा किसी सेवा के रूप में जनता तक वापस पहुंचता है

इन रियासतों पर रहस्य का परदा पड़ा रहता है। जखवार निकालने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता—अगर बहुत हुआ तो कोई साहित्यिक या अथ सरकारी साप्ताहिक प्रकाशित हो जाता है। बाहर के अखबारों पर प्रायः रोक लगी रहती है। त्रावणकोर, कोचीन आदि कुछ दक्षिणी रियासतों का छोड़कर बाकी सभी जगह साक्षरता बहुत कम है। इन दक्षिणी रियासतों में साक्षरता ब्रिटिश भारत से भी कहीं ज्यादा है। रियासतों में जो प्रमुख खर्चें आती हैं उनमें या तो बायसराय की याता का बणन हाता है या जाहिर है पूरे तड़क भड़क के साथ हुई रहती है और उन भाषणों के समाचार हाते हैं जो एक दूसरे की प्रशंसा में किए गए होते हैं या राजा के जन्मदिन अथवा विवाह की वषगाठ पर फिजूलखर्चों के मान्य मनाए

गए समारोहों का जिक्र होता है या किसानों के विद्रोह की खबर हाती है। विशेष कानूनों के कारण राजाओं की आलोचना नहीं की जा सकती और मामूली से मामूली आलोचना पर भी कड़ा रुख अख्तियार किया जाता है। सावजनिक सभाएँ नहीं के बराबर होती हैं और सामाजिक उद्देश्यों से आयोजित सभाओं पर भी प्रतिवध लगा दिया जाता है। (जवाहरलाल नेहरू 'आत्मकथा' पृष्ठ 531)

भारत सरकार की 25 जून 1891 की विनयित के जरिए भारतीय रियासतों के समाचार पत्रों पर बड़े साफ शब्दों में प्रतिवध लगा दिया गया है '1 अगस्त 1891 के बाद किसी भी स्थानीय इलाके में जहाँ गवर्नर जनरल का प्रशासन है पर जो ब्रिटिश भारत में नहीं है किसी भी समाचारपत्र या किसी भी प्रकाशित रूप में, चाहे कोई पत्रिका हो या पुस्तक, सावजनिक समाचार या सावजनिक समाचारों पर टिप्पणी को संपादित, प्रकाशित या मुद्रित करने के लिए राजनीतिक एजेंट की अनुमति आवश्यक है।' ब्रिटिश भारत में रियासतों की स्थिति के बारे में किसी भी तरह की आलोचना को प्रकाशित होने से रोकने के लिए 1934 के स्टेट्स प्रोटक्शन ऐक्ट के जरिए और भी कानून बनाए गए।

भारत के यह कठपुतली राजा महाराजा जगरेजों की छलछाया में जिस प्रकार अपना शासन चलाते थे उसकी इतिहास में शायद ही कोई और मिसाल मिले। कुछ देशी रियासतें ऐसी हैं जिनकी शासन व्यवस्था का स्तर ब्रिटिश भारत से कुछ ऊँचा है और जिनके यहाँ अनिवार्य शिक्षा की योजनाओं पर कुछ हद तक जमल हुआ है या जिनके यहाँ ऐसी सलाहकार परिषदें बना दी गई हैं जिनके पास बहुत सीमित अधिकार हैं और जिनका ढाँचा बहुत प्राथमिक ढंग का है। लेकिन ये रियासतें अपवाद रूप में हैं। अधिकांश रियासतों में जिस पैमाने पर गुलामी, तानाशाही और दमन देखने को मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एशिया के निरंकुश राजाओं के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि इनके लिए भ्रष्टाचार और जुल्म कोई चीज नहीं है लेकिन उन पुराने राजाओं को कम से कम बाहरी जाक्रमण या जदरूनी विद्रोह का डर तो लगा ही रहता था जिनसे इनका निरंकुश शासन पर कुछ अंकुश रहता था। इन नए राजाओं का अंगरेजों के संरक्षण के कारण इन बातों का भी कोई डर नहीं है। अंगरेज सरकार के पास यह अधिकार है कि यदि वह किसी रियासत में बहुत ज्यादा अत्याचार देखें तो राजा को गद्दी से हटा दे या उसके अधिकारों पर नियंत्रण लगा दें लेकिन व्यवहार में अंगरेजों ने इस अधिकार का उपयोग अत्यंत रोकने के लिए नहीं बल्कि राजाओं को अपने प्रति निष्ठावान बनाए रखने के लिए किया है। इस प्रकार यहाँ के राजाओं ने पूरी तरह अपने को अंगरेजों के हाथ की कठपुतली बना दिया है। इस प्रकार अत्यंत पिछड़ेपन की स्थितियों में रहने वाली भारतीय रियासतों की जनता अपमान और यातना की जिंदगी बिता रही है।

1939 में रियासतों की जनता के सम्मेलन स्टेट्स पीपुल्स काफ़स (रियासतों में चल रहे

लोकप्रिय जनवादी आंदोलन की एक सस्या) ने अपने घोषणापत्र में इन राजाओं के शासन के स्वरूप के बारे में अपनी धारणा इन शब्दों में व्यक्त की थी

इन छोटी बड़ी रियासतों में अत्यंत व्यक्तिगत और निरकुश शासन का बोलबाला है। बहुत कम रियासतें ऐसी हैं जो इस मामले में अपवाद हैं। अधिकांश रियासतों में कोई कानून नहीं है और जनता से बहुत बड़े पैमाने पर कर वसूला जाता है। नागरिक स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया है। आमतौर से इन राजाओं के प्रिवीपस की राशि निर्धारित नहीं की गई है और जहां यह राशि निर्धारित की भी गई है वहां इसका पूरी तरह पालन नहीं होता। इन रियासतों में एक तरफ तो राजाओं की फिजूलखर्ची और जबरदस्त ठाट धाट देखने का मिलता है और दूसरी तरफ जनता भयंकर गरीबी की हालत में गुजर बसर कर रही है।

इस गरीब जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई से इन रियासतों के शासक विदेशों में और भारत में हर तरह के आनंद उठा रहे हैं और ऐयाश जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। कोई भी सभ्य समाज इस बरदाश्त नहीं कर सकता। इतिहास की समूची व्याख्या इसके विपरीत है। भारतीय जनता का तब तक इस तरह के अत्याचारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। (आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स काफ्रेस की स्थाई समिति का बयान, जून 1939)

इन रियासतों के प्रशासन का क्या स्वरूप था, इसका बहुत स्पष्ट संकेत उनके बजट देखने से मिल जाता है

इंग्लैंड के महाराजा मोटोर पर राष्ट्रीय आय के सोलह सौ में से एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। बेल्जियम के महाराजा एक हजार में से एक, इटली के महाराजा पांच सौ में से एक, डेनमार्क के महाराजा तीन सौ में से एक और जापान के सम्राट चार सौ में से एक हिस्सा प्राप्त करते हैं

त्रावणकोर (जिसे भारत की सबसे प्रगतिशील रियासत समझा जाता है) की महारानी राष्ट्रीय आय के 17 में से एक हिस्सा, हैदराबाद के निजाम और बड़ोदा के महाराजा तेरह में से एक हिस्सा तथा कश्मीर के महाराजा और बोकानर के महाराजा पांच में से एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह राशि जय दलों की तुलना में आश्चर्यजनक है। दुनिया के लोगों को यदि यह बताया जाए कि भारत में कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जहां के राजा राष्ट्रीय आय के तीन हिस्से में से एक हिस्सा या दो हिस्से में से एक हिस्सा प्राप्त करते हैं तो लोग का हैरान होना बहुत स्वाभाविक है। (ए० आर० दसाई इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दि नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल)

ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा घासतौर से सराह गये बीकानेर राज्य का 1929-30 का बजट यहाँ प्रस्तुत है

|                      | रुपये     |
|----------------------|-----------|
| राजकुल व्यय          | 1,255,000 |
| राजपुमार की घादी     | 82,500    |
| मकान और सड़क निर्माण | 618,384   |
| शाही महल का विस्तार  | 426,614   |
| शाही परिवार पर व्यय  | 222,864   |
| शिक्षा               | 222,979   |
| स्वास्थ्य सेवा       | 188,138   |
| जन सुविधा            | 30,761    |
| सफाई                 | 5,729     |

राजा, राज परिवार और महल पर जितना खर्च होता है उसके एक चौथाई से भी कम राशि शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, जन सुविधाओं और सफाई पर खर्च किया जाता है। जामनगर का उदाहरण लें तो पता चलेगा कि 1926-27 में कुल 10 लाख पौंड का जो राजस्व प्राप्त हुआ था उसमें से 7 लाख पौंड की राशि जामनगर के राजा के व्यक्तिगत कामों में खर्च हुई जबकि शिक्षा पर 1.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य-सेवा पर 0.9 प्रतिशत की राशि खर्च की गई।

इस तरह के प्रशासन के अंतर्गत रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है? भारतीय रियासतें सामंती ढंग की अत्यंत पिछड़ी कृषीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ ही रियासतें ऐसी हैं जहाँ औद्योगिक विकास हुआ है। अनेक रियासतों में गुलामी प्रथा तो आम बात है

राजपूताना की रियासतों के अनेक हिस्सों में गुलामी का समुदाय मौजूद है। यही स्थिति काठियावाड़ सहित पश्चिमी भारत की अनेक रियासतों की है। 1921 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अकेले राजपूताना और मध्यभारत में चाकर तथा दरोगा वर्गों के एक लाख 60 हजार 735 गुलाम मौजूद थे। (पी० एल० चूडगर 'इंडियन प्रिंसेज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन', 1929, पृष्ठ 33)

इन रियासतों का एक सामान्य नियम यह बन गया था कि यहाँ के शासक गरीबों से हर तरह की बेगार कराते थे और मजदूरी के रूप में भोजन के अलावा कुछ भी नहीं देते थे।

वेध और बंगार के नाम से प्रचलित प्रणाली लगभग सभी भारतीय रियासतों में कायम है। सभी वर्गों के मजदूर, कामगार और शिल्पी राजा और उनके

अधिवारिया व किए बिना पस लिए काम करना का मातूर है। जनक मामरा म दन्त जो मजदूरी ले जाती है वह जाती महज समय बुनियादी जरूरत व रूप म अर्थात् भोजन के रूप म मिलती है। यह प्रजा सिंगी भी समय और सिंगी भी जवधि के लिए काम करने की मजदूर है। यहां तक कि जवान और लूरी, विवाहिता या विधवा महिलाओं का भी नहीं छाड़ा जाता। यदि पुरुष या महिलाओं म स कोई भी व्यक्ति असक्त है और ठीक से काम नहीं कर पाता तो उसे छोड़े लगाए जाते हैं।

इस चक्र को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वास्तविकों से 60 साल की गरीब लूरी महिलाओं को कामे लगाए हैं। कामे लगाए का काम पुनः काम सड़ना पर बेंत की छड़ियां से किया गया है। इसका अर्थ यह महज यह था कि इन्होंने अपनी गारोहिक ज़ामभता बताई हुए बाजार में छूट की मांग की थी। (वही पृष्ठ 37)

इन स्थिति में तारिख अधिवारा अभी भी कोई चीज नहीं है



रियासत के हिस्से में 40 प्रतिशत भाग आ जाता है। यदि बहुत सतुलित अनुमान लगाए तो अन्य कर लगभग 10 प्रतिशत हैं। इस प्रकार किसान के पास केवल 50 प्रतिशत ही बचता है।

इसके अलावा उसे गांव के मुखिया या मुखिया के परिवार के सदस्यों की शादी का खर्च भी वहन करना पड़ता है और मुखिया के यहाँ यदि कोई लड़का पैदा हुआ तो पुत्रजन्म समारोह पर तथा मुखिया की पत्नी या माँ के मरने पर अंतिम संस्कार के समय उसे इन समारोहों का खर्च बरदाश्त करना होता है।

भारतीय रजवाड़ा की यह शासनव्यवस्था जितनी दमनकारी और अत्यायपूर्ण है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसकी खास वजह यह है कि इसमें अत्यंत आदिम, सामंती दमन सम्मिलित है, यहाँ नीचे के स्तर पर प्रत्यक्ष गुलामी के अवशेष हैं और ऊपर सर्वोच्च साम्राज्यवादी शक्ति और शोषण है।

इस शासनव्यवस्था को अंगरेजी राज ने न केवल सुरक्षित रखा है और भारत के 2/5 से भी अधिक हिस्से पर कृत्रिम ढंग से लागू किया है बल्कि आधुनिक युग में इसे और अधिक सामने रखा है और समूचे भारत के मामलों में इसे महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश की है। जैसे जैसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आगे बढ़ता गया है, वैसे वैसे साम्राज्यवाद इस नीति पर अधिक से अधिक जोर देने लगा कि दशों राजाओं के साथ गठबंधन किया जाए और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरोध में उसे खड़ा किया जाए। 1921 में चर्चर आफ प्रिंसेज की स्थापना हुई। 1935 के कानून के जरिए जिस संघीय विधान की योजना बनाई गई उसकी नींव देशों राजाओं की भूमिका पर रखी गई। उसमें ऊपरी सदन में 2/5 से अधिक स्थान इन राजाओं को दिया गया और निचले सदन में एक तिहाई सीटें इन्हें मिलीं। ससदीय बहुसंख्यकों में लाइ रीडिंग ने अपना मकसद बड़े स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया।

यदि भारतीय राजाओं का कोई अखिल भारतीय महासंघ बनता है तो इसका हमेशा ही एक स्थाई प्रभाव होगा। इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात क्या है? कुछ राजा ऐसे हैं जो भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह अलग होने के लिए आंदोलन करते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह की मांग करने वाले राजाओं का अल्पमत है लेकिन यह बहुत सुस्पष्ट अल्पमत है और इनके पीछे कांग्रेस का संगठन है। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस विचारधारा के विरुद्ध हम जो भी स्थाई प्रभाव पैदा कर सकते हैं, करें। तकरीबन 33 प्रतिशत राजा विधानसभा के सदस्य होंगे और ऊपरी सदन में इनका प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत होगा। वेशक एस भारतीयों की काफी संख्या है जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हैं। इस प्रकार यदि कांग्रेस में काफी अधिक वोट

अधिकारिया के लिए बिना पैसे लिए काम करने का मजबूर है। अनेक मामला में इन्हें जो मजदूरी दी जाती है वह उनकी महज सबसे बुनियादी जरूरत के रूप में अर्थात् भोजन के रूप में मिलती है। यह प्रजा किसी भी समय और किसी भी अवधि के लिए काम करने को मजबूर है यहा तक कि जवान और बूढ़ी, विवाहिता या विधवा महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। यदि पुरुष या महिलाओं में से कोई भी व्यक्ति अशक्त है और ठीक से काम नहीं कर पाता तो उसे कोड़े लगाए जाते हैं।

इस लेखक को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कास्टेबलों ने 60 साल की गरीब बूढ़ी महिलाओं तक को कोड़े लगाए हैं। कोड़े लगाने का काम खुलेआम सड़कों पर बैठ की छड़ियों से किया गया है। इनका अपराध महज यह था कि इन्होंने अपनी शारीरिक असमर्थता बताते हुए वेगार से छूट की मांग की थी। (वही, पृष्ठ 37)

इन रियासतों में नागरिक अधिकारों जैसी भी कोई चीज नहीं है

प्रजा को इस बात का अधिकार नहीं है कि राजा, प्रधानमंत्री या रियासत द्वारा अपने अधिकारों का हनन किए जाने पर वह हरजाने की मांग कर सके। राजा मनमाने ढंग से किसी की भी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे सकता है। वह किसी भी सीमा तक जुर्माना कर सकता है और वसूली का कोई भी तरीका अस्तिभार कर सकता है। वह बिना किसी आरोप के या बिना मुकदमा चलाए किसी का भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। (वही, पृष्ठ 72-73)

जनता पर अपनी मरजी के अनुसार करों का बोझ लाद दिया गया है ताकि राजमहल की अस्तित्वोभी मांगों की पूर्ति के लिए गरीब से गरीब आदमी का भी खून चूसा जा सके

नवानगर रियासत में जिस तरह करों की वसूली की जाती है उससे और सभी रियासतों में प्रचलित रीति का पता चल जाता है। पहली सूची में कुछ व्यावसायिक लोग हैं तथा मजदूरों, शिल्पियों का नाम है। इसके साथ ही मवेशियों, सगाई, विवाह, जन्म, मृत्यु और दाह संस्कार पर कर लिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि हाथ से चक्की चलाकर पिसाई का काम करने वाली विधवा महिलाओं तक से कर लिया जाता है जबकि यह उनके जीवन यापन का एक मात्र साधन है

जहां तक भूमि कर की बात है—जहां नफ़ाद भुगतान किया जाता है वह कर प्रति एकड़ 4 शिलिंग है लेकिन जहां नफ़ाद कर नहीं दिया जाता वहां फसल का एक चौथाई हिस्सा कर के रूप में चना जाता है। व्यवहार में यह दर बढ़ जाती है।

रियासत के हिस्से में 40 प्रतिशत भाग आ जाता है। यदि बहुत सन्तुलित अनुमान लगाए तो अथ कर लगभग 10 प्रतिशत है। इस प्रकार किसान के पास केवल 50 प्रतिशत ही वृत्त है।

इसके अलावा उसे गांव के मुखिया या मुखिया के परिवार के सदस्यों की शादी का खर्च भी वहन करना पड़ता है और मुखिया के यहाँ यदि कोई लड़का पैदा हुआ तो पुत्रजन्म समारोह पर तथा मुखिया की पत्नी या माँ के मरने पर अंतिम संस्कार के समय उसे इन समारोहों का खर्च बरदाश्त करना होता है।

भारतीय राजवाड़ों की यह शासनव्यवस्था जितनी दमनकारी और अत्याचारी है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसकी खास वजह यह है कि इसमें अत्यंत आदिम, सामंती दमन सम्मिलित है, यहाँ नीचे के स्तर पर प्रत्यक्ष गुलामी के अवशेष हैं और ऊपर सर्वोच्च साम्राज्यवादी शक्ति और शोषण है।

इस शासनव्यवस्था को अंगरेजी राज ने न केवल सुरक्षित रखा है और भारत के 2/5 से भी अधिक हिस्से पर कृत्रिम ढंग से लागू किया है बल्कि आधुनिक युग में इसे और अधिक सामने रखा है और समूचे भारत के मामलों में इसे महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश की है। जैसे जैसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आगे बढ़ता गया है, वैसे वैसे साम्राज्यवाद इस नीति पर अधिक से अधिक जोर देने लगा कि दशों राजाओं के साथ गठबंधन किया जाए और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरोध में उसे खड़ा किया जाए। 1921 में चैंबर आफ प्रिंसेज की स्थापना हुई। 1935 के कानून के जरिए जिस संघीय विधान की योजना बनाई गई उसकी नींव देशों राजाओं की भूमिका पर रखी गई। उसमें ऊपरी सदन में 2/5 से अधिक स्थान इन राजाओं को दिया गया और निचले सदन में एक तिहाई सीटें इन्हें मिलीं। मसदीय बहसों में लाइ रीडिंग में अपना मकसद बड़े स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया

यदि भारतीय राजाओं का कोई अखिल भारतीय महासंघ बनता है तो इसका हमेशा ही एक स्थाई प्रभाव होगा। इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात क्या है? कुछ राजा ऐसे हैं जो भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह अलग होने के लिए आंदोलन करते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह की मांग करने वाले राजाओं का अल्पमत है लेकिन यह बहुत सुस्पष्ट अल्पमत है और इनके पीछे कांग्रेस का समर्थन है। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस विचारधारा के विरुद्ध हम जो भी स्थाई प्रभाव पैदा कर सकते हैं करें। तकरीबन 33 प्रतिशत राजा विधानसभा के सदस्य होंगे और ऊपरी सदन में इनका प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत होगा। यशक ऐसे भारतीयों की काफी संख्या है जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हैं। इस प्रकार यदि कांग्रेस ने काफी अधिक वोट

पाने की व्यवस्था कर भी ली तो भी मुझे इस बात का तनिक भी भय नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकेगा जो हमारे लिए प्रतिकूल हो ।

इधर हाल के वर्षों में राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन इन कठपुतली रियासतों की मड़ी गन्ती सीमाओं को ताड़ता हुआ आगे बढ़ा है । स्टेट्स पीपुल्स काफ़ेंस रियासतों में जनआंदोलनों का संगठन किया करती है और इसकी तात्त काफी तजी स बढ़ी है । बुनियादी नागरिक अधिकारों के लिए एच के बाद दूसरी रियासत में सक्रिय सघष चलाए गए हैं ।

रियासतों में जनआंदोलन की इस प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में भी परिवर्तन की झलक मिली है । अतीत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीधे तौर पर भारतीय रियासतों में आंदोलन की इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से अपने को अलग रखा । 'हस्तक्षेप न करने' की नीति को जानबूझकर अपनाया गया और इसके साथ ही यह गूठी आशा की गई कि इन कठपुतली रियासतों के राजाओं के साथ किसी तरह की एकता कायम हो जाएगी । कांग्रेस ने कभी यह नहीं सोचा कि इन रियासतों की 8 करोड़ दलित जनता के साथ किसी तरह की एकता कायम की जाए । गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कहा था कि 'अब तक कांग्रेस ने राजाओं की इस तरह सेवा करने की काशिश की है कि वह उनके घरेलू तथा आंतरिक मामलों में किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करती ।' गांधी ने आगे कहा

मैं महसूस करता हूँ और यह जानता हूँ कि इन राजाओं के दिलों में अपनी प्रजा के हित की बातें हैं । उनके ओर भेद बीच कोई फाँव नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं और उन्हें ईश्वर ने नन्द राजकुमार बनाया है । मैं उनके लिए शुभचामना व्यक्त करता हूँ, मैं उनकी समृद्धि की कामना करता हूँ ।

बाद में घटनाचक्र ने खुद ही इस पातल नीति का असफल साबित कर दिया । कांग्रेस ने स्वेच्छापूर्वक अपनी गतिविधियाँ का ब्रिटिश भारत तक ही सीमित रखा और हालाँकि उसने खुद को अधिकृत भारतीय राष्ट्रीय संस्था का नाम दिया था लेकिन भारतीय रियासतों में अपने नतुख के तहत उसने कोई समानांतर गणटा कायम करने की कोशिश नहीं की । लेकिन हाल के वर्षों में सावणवार और मंगूर जैसे तत्पावधित अवसर 'प्रगतिशील' रियासतों सहित राजाओं द्वारा जनआंदोलनों की प्रारम्भिक सुरक्षाता व हियारमन दमा स जा स्थिति पैदा हुई उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इस बात व लिए प्रियत कर दिया कि यह उठे और गधष का पीडा खुद ही उठाए । 1938-39 का घटनाचक्र में दया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता व अधिकारों और भारतीय रियासतों में अपना अधिकृत कायम रखा व अधिकार के लिए गधष का गूजपात लिया । रियासतों में गधिनय जमा आंदोलन का सम्भन दन का प्रता राष्ट्रीय कांग्रेस व मन्सों व बीच एक गनत व गन वाकर साम व आ गया ।

1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ जिसमें रियासतों के संबंध में कांग्रेस के आम सिद्धांतों की घोषणा की गई

कांग्रेस रियासतों में भी उसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की हिमायती है जैसी वह देश भारत में चाहती है। इसके साथ ही कांग्रेस इन रियासतों को भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग मानती है। कांग्रेस ने पूरे स्वराज्य का जो लक्ष्य अपनाया है वह रियासतों सहित समूचे भारत के लिए है क्योंकि आजादी के दिनों में भी भारत की एकता और अभिन्नता वैसी ही बनी रहनी चाहिए जैसी गुलामी के दिनों में रही है।

कांग्रेस केवल उसी तरह के महामघ की बात स्वीकार करेगी जिसमें रियासतें भी स्वतंत्र इकाई के रूप में भाग ले सकें और उन्हें भी देश भारत की तरह ही जनतंत्र और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके।

इसलिए कांग्रेस की राय यह है कि रियासतों में पूरी तरह उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन कायम होना चाहिए और नागरिक अधिकारों की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस इस बात पर भी खेद प्रकट करती है कि इन रियासतों की मौजूदा हालत पिछड़ी हुई है और अनेक रियासतों में स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है तथा नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

इसके साथ ही हरिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव ने रियासतों के अंदर कांग्रेस की गतिविधियों पर खुद ही कुछ सीमाएँ भी लगा दी थीं

रियासतों में जनता का अदखली संघर्ष कांग्रेस के नाम पर नहीं चलाया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए स्वतंत्र संगठनों की शुरुआत की जानी चाहिए और जहाँ इस तरह के संगठन पहले से मौजूद हों, वहाँ उन्हें जारी रखना चाहिए।

1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसमें उसने अपनी स्थिति में आंशिक संशोधन किया

कांग्रेस की यह राय है कि रियासतों के संबंध में हरिपुरा अधिवेशन के प्रस्ताव में इसके द्वारा उत्पन्न की गई आशाओं को पूरा किया है और रियासतों की जनता को अपने आपको संगठित करने तथा आजादी के लिए अपने आंदोलनों को संचालित करने का बड़ा बड़ा देवर कांग्रेस ने अपना औचित्य साबित कर दिया है। हरिपुरा में जो नीति अपनाई गई वह जनता के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर अपनाई गई थी ताकि जनता के अंदर आत्मनिर्भरता तथा शक्ति पैदा हो। यह नीति मौजूदा



नूबो म लोकप्रिय मन्त्रिमंडलों के फिर से गठित होन तथा उभरत क्रांतिकारी विद्रोहों के कारण साविधानिक बहुसत्तों के शुरू होने के साथ ही भारतीय रियासतें भारत की राजनीतिक स्थिति का केंद्रबिंदु हो गईं हैं। रियासतों में सामंती निरंकुशता के विरुद्ध स्वतन्त्र-स्फूर्त संघर्ष प्रारंभ हो गए और उनका बहुत ही हिंसात्मक तरीके से राजाओं ने दमन किया है। राजाओं के इस काम में ब्रिटेन के राजनीतिक विभाग का समर्थन प्राप्त है। इन संघर्षों का सबसे जबरदस्त उभार 1946 में कश्मीर में देखा गया जब जनता ने डोगरा राजवंश के खिलाफ बहुत स्पष्ट और खुले शब्दों में 'कश्मीर छोड़ो' नारा दिया।

यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस की वर्तमान नीति आज भी रियासतों के पहले से बने बनाए ढांचों के अंदर तथा राजाओं के चले आ रहे शासन के अंतर्गत ही सुधारों की बात करती है। इस तरह की स्थिति महज एक अधूरी स्थिति हो सकती है, यह राष्ट्रीय जादोलन को बुनियादी मसले तक पहुंचाने की दिशा में एक अवस्था हो सकती है।

1946 के ब्रिटिश साविधानिक प्रस्तावों ने राजाओं की भावी भूमिका के प्रश्न को एक नए चरण में पहुंचा दिया। प्रस्तावित संविधान सभा में राजाओं को कुल 386 स्थानों में से 93 स्थान दिए जाने थे और जनतांत्रिक ढंग से चुनाव के किसी भी तरीके का इसमें प्रावधान नहीं था। जैसा कि 1935 के संघीय संविधान में कहा गया था, राजाओं को प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के दायरे में लाना था। लेकिन जिन शर्तों के अंतर्गत उन्हें इसमें शामिल होना था वे शर्तें पूरी तरह एच्छिक बातचीत पर छोड़ दी गईं। फिर भी यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अगर राजाओं द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के बाद सर्वोपरिता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा जिससे बातचीत के जरिए यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके तो राजा कानूनी और कूटनीतिक तौर पर 'स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न' बने रहेंगे।

भारत में जनतंत्र के भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि राजाओं की असामाय स्थिति और रियासतों के मनमाने ढांचे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्र भारत में इन देशी रियासतों का कोई स्थान नहीं हो सकता। ब्रिटिश भारत और राजाओं का भारत नाम से देश का विभाजन किसी भी अर्थ में प्राकृतिक विभाजन नहीं है, इसकी न तो कोई ऐतिहासिक आवश्यकता है और न यह जनता की भावात्मक जरूरतें पूरी करता है बल्कि यह साम्राज्यवादियों की एक ऐसी चाल है जिसके जरिए जनता में भेदभाव पैदा करके अपना प्रशासन बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय जादोलन का एकमात्र लक्ष्य यही हो सकता है कि संपूर्ण भारत में समान अधिकारों और समान नागरिकता सहित जनतंत्र की स्थापना की जाए। भारत की एकता, उसके प्रगतिशील विकास और भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि भारतीय रियासतों को पूरी तरह समाप्त किया जाए, सामंती दमन के इन अवशेषों का नामोनिशान मिटा दिया जाए तथा प्राकृतिक, भौगोलिक, जातिक और सांस्कृतिक समूहों के आधार पर भारतीय जनता का एक वास्तविक संघ में एकताबद्ध किया जाए (ऐसा तथाकथित 'संघ' नहीं

परिस्थितियाँ को देखकर तैयार की गई थी लेकिन यह नहीं सोचा गया था कि इस नीति का हमेशा पालन करने के लिए कांग्रेस मजबूर है। कांग्रेस का हमेशा यह अधिकार रहा है और उसका यह कर्तव्य भी रहा है कि वह रियासतों की जनता का नेतृत्व करे तथा उन्हें प्रभावित करे। जनता के बीच जा महान जागरण हो रहा है उससे कांग्रेस ने अपने ऊपर जो सीमाएँ थोप रखी थीं उनमें ढील दी जा सकती है या उन्हें एकदम समाप्त किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप रियासतों की जनता के साथ कांग्रेस का तादात्म्य अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा।

इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय नेताओं ने रियासतों की जनता के आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। फरवरी 1939 में आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस का लुधियाना अधिवेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष तथा पट्टाभि सीतारमैया उपाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन ने 'उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार' की स्थापना के संधर्ष में रियासतों की जनता के आंदोलन की प्रगति का स्वागत किया और कहा

अब समय आ गया है जब इस संधर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के उस अधिक व्यापक संधर्ष के साथ मिलाकर चलाया जाए जिसका वह एक अभिन्न अंग है। अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जाने वाला इस प्रकार का संयुक्त संधर्ष अनिवार्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में ही चलाया जाना चाहिए।

युद्ध के बाद अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस की बैठक दिसंबर 1945 में उदयपुर में हुई और उसमें सम्मेलन का यह लक्ष्य स्वीकार किया गया कि 'वह एक स्वतंत्र तथा संघबद्ध भारत के अभिन्न अंग के रूप में रियासतों में शांतिपूर्ण तथा वैधानिक तरीकों से उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना करेगा।' अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कहा

यह अनिवार्य है कि रियासतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो संभवतः आर्थिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सकता, पड़ोसी इलाकों में मिला दिया जाए इस तरह की छोटी रियासतों के शासकों का किसी तरह की पेंशन दी जा सकती है और यदि वे किसी काम के योग्य हों तो उन्हें इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

अन्य रियासतों, जिनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है और जो मध्य की स्वायत्त शासित इकाइयों के रूप में रह सकती हैं उनके शासक एक जनतान्त्रिक सरकार के अंतर्गत सांविधानिक अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इनमें से कुछ शासक और राजा महाराजा जयंत प्राचीन रजवाड़े हैं जिनका इतिहास और परंपरा से घनिष्ठ संबंध है।



सूबों में लोकप्रिय मन्त्रिमंडलों के फिर स गठित होना तथा उभरते नातिहारी विद्रोहों के कारण साविधानिक बहसों के शुरू होने के साथ ही भारतीय रियासतें भारत की राजनीतिक स्थिति का केंद्रबिंदु हो गई हैं। रियासतों में सामंती निरकुशता के विरुद्ध स्वतंत्र-स्फूर्त संघर्ष प्रारंभ हो गए और उनका बहुत ही हिंसात्मक तरीके से राजाओं ने दमन किया है। राजाओं के इस काम में ब्रिटेन के राजनीतिक विभाग का समर्थन प्राप्त है। इन संघर्षों का सबसे जबरदस्त उदाहरण 1946 में कश्मीर में देखा गया जब जनता ने डोगरा राजवंश के खिलाफ बहुत स्पष्ट और खुले शब्दों में 'कश्मीर छोड़ो' नारा दिया।

यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस की वर्तमान नीति आज भी रियासतों के पहले से बने बनाए ढांचों के अंदर तथा राजाओं के चले आ रहे शासन के अंतर्गत ही सुधारों की बात करती है। इस तरह की स्थिति महज एक अधूरी स्थिति हो सकती है, यह राष्ट्रीय आंदोलन का बुनियादी मसले तक पहुंचाने की दिशा में एक अवस्था हो सकती है।

1946 के ब्रिटिश साविधानिक प्रस्तावों ने राजाओं की भावी भूमिका के प्रश्न को एक नए चरण में पहुंचा दिया। प्रस्तावित संविधान सभा में राजाओं को कुल 386 स्थानों में से 93 स्थान दिए जाने थे और जनतांत्रिक ढंग से चुनाव के किसी भी तरीके का इसमें प्रावधान नहीं था। जसाकि 1935 के संघीय संविधान में कहा गया था, राजाओं को प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के दायरे में लाना था। लेकिन जिन शर्तों के अंतर्गत उन्हें इसमें शामिल होना था, वे शर्तें पूरी तरह ऐच्छिक बातचीत पर छोड़ दी गईं। फिर भी यह बात स्पष्ट कर दी गई कि जगरेजा द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के बाद सर्वोपरिता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा जिससे बातचीत के जरिए यदि कोई वैयक्तिक व्यवस्था हो सकती तो राजा कानूनी और कूटनीतिक तौर पर 'स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न' बने रहेंगे।

भारत में जनतंत्र के अविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है कि राजाओं की असामान्य स्थिति और रियासतों के मनमाने ढांचों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्र भारत में इन दशों रियासतों का कोई स्थान नहीं हो सकता। ब्रिटिश भारत और राजाओं का भारत' नाम से देश का विभाजन किसी भी अर्थ में प्राकृतिक विभाजन नहीं है, इसकी न तो कोई ऐतिहासिक आवश्यकता है और न यह जनता की भावात्मक जरूरतें पूरी करता है बल्कि यह साम्राज्यवादियों की एक ऐसी चाल है जिससे जरिए जनता में भेदभाव पैदा करने अपना प्रशासन बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य यही हो सकता है कि संपूर्ण भारत में समान अधिकारों और समान नागरिकता सहित जनतंत्र की स्थापना की जाए। भारत की एकता, उसके प्रगतिशील विमान और भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि भारतीय रियासतों को पूरी तरह समाप्त किया जाए, सामंती दमन के इन अवशेषों का नामानिर्माण मिटा दिया जाए तथा प्राकृतिक, भौगोलिक, जातिक और सांस्कृतिक समूहों का आधार पर भारतीय जनता को एक सार्वजनिक निकाय में एकताबद्ध किया जाए (ऐसा संभावित संघ नहीं

हाना चाहिए जो मौजूदा निरकुशता को बनाए रखने तथा जनता की आकांक्षाओं को दमन करने का एक व्यापक तंत्र है)।

## 2 सांप्रदायिक भेदभाव

अंगरेजों ने राजाओं के जरिए भारतीय जनता में फूट डालने की जो नीति अपनाई थी ठीक उसी तरह की नीति वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करने के लिए वरतते थे।

यह सांप्रदायिक भेदभाव की आम समस्या तथा इस समस्या के विभिन्न राजनीतिक रूपों के बीच फाट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हाल के वर्षों में मुस्लिम लीग का उदय और पाकिस्तान की मांग ने यह साबित कर दिया है कि यह समस्या राजनीतिक रूप ले चुकी है। इन खास तरह के राजनीतिक रूपों के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं जिनपर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे लेकिन उसके पहले सांप्रदायिक समस्या और खासतौर से हिंदू-मुस्लिम विरोध के आम प्रश्न पर विचार कर लेना जरूरी है।

भारत में करीब दो तिहाई आबादी हिंदुओं की है तथा एक चौथाई मुसलमानों की और इनके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे धार्मिक समुदाय हैं जो मिलकर आबादी का दसवां भाग होते हैं। इसलिए 'सांप्रदायिक' समस्या के नाम से या अलग-अलग धार्मिक 'समुदायों' के आपसी संबंधों के रूप में या सवाल सामने आता है, भारत में उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह एक गंभीर समस्या है लेकिन यह ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सिर्फ भारत में ही दखन में आ रहा हो।

कुछ विशेष परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों के एक ही देश में रहने से काफी गंभीर कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं, कभी-कभी तो दंगा-फसाद और खून खराबा हो सकता है। 20वीं सदी के विश्व में ही अगर उदाहरण लें तो हम इस तरह की समस्याएँ दखन में मिल सकती हैं। उत्तरी आयरलैंड में ओरेजमें और कैथोलिकों का झगडा, शासनान्देश (मंडेट) के दिनों में फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों का संघर्ष, जारशाही रूप में स्लाव लोग और यहूदियों का संघर्ष, नाजी जर्मनी में तथाकथित 'आर्यों' तथा यहूदियों का झगडा, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे पता चलता है कि साम्राज्यवादियों ने भेदभाव की नीति हर जगह अपनाई। यूरोप में आज यहूदी विरोध की जो भावना देखने को मिलती है उससे पता चलता है कि अलग-अलग नस्ल या धर्म पर आधारित भेदभाव तथा विरोध कितने तीव्र रूप में सामने आ सकता है।

ऐतिहासिक अनुभव का आधार पर बहुत स्पष्ट रूप में यह बताया जा सकता है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें इस तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं।

जब तक फिलिस्तीन ब्रिटेन के संरक्षण में नहीं आया या अरब और यहूदी लोग सदियों से शांतिपूर्ण जीवन बिताते रहे। ब्रिटेन का शासन कायम हान के बाद और साम्राज्यवादियों द्वारा अपनी ताकत के बल पर तथा पश्चिमी महाजनी पूँजी के संरक्षण में यहूदिया का आग्रजन शुरू होने के बाद से हिंसात्मक संघर्षों की भी शुरुआत हो गई। इन संघर्षों को कभी कभी नस्लवादी या धार्मिक संघर्ष का नाम दिया जाता है लेकिन सचाई यह है कि ये संघर्ष आक्रमण और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ आजादी के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रीय संघर्ष हैं।

जारशाही रूस में और खासतौर से जारशाही के पतन के दिनों में यहूदिया का जितना जबरदस्त कत्लेआम हुआ उसकी कहीं और मिसाल नहीं है। समूचा विश्व इस कत्लेआम को देखकर हैरान रह गया और इन घटनाओं से इतिहास के वेशुमार पृष्ठ भरे पड़े हैं। इस कत्लेआम के बारे में यह समचा जाता था कि रूस की जनता बहुत मूख और जगली है तथा उसके अनियंत्रित उपद्रवों के कारण हिंसा का सहारा लेना पड़ा लेकिन बाद के वर्षों में खुफिया पुलिस की रिपोर्टें प्रकाशित हुईं उनसे यह बात साबित हो गई कि कत्लेआम के लिए सरकार ने सीधे तौर पर पहल की थी और इसका संचालन भी किया था। इन रिपोर्टों के छपने से पहले तक लोग 'ब्लैक हंड्रेड्स' या 'पैटिआटिक' नामक गुंडा संगठनों के साथ सरकार के अनाखे सबधों की ओर संकेत करते थे। जिस दिन स रूस की जनता ने अपने देश का शासनभार स्वयं संभाला उस दिन से ही इस तरह के हत्याकांड भी बिल्कुल समाप्त हो गए। आज सोवियत गणराज्य में तमाम तरह की नस्लों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बहुत सुख चैन से एक साथ रह रहे हैं।

जर्मनी में, वाइमर प्रजातंत्र के दिनों में जर्मन और यहूदी लोग शांतिपूर्वक साथ साथ रहते थे। जब जर्मनी में नाजियों का शासन कायम हुआ तो हत्याकांड जारशाही रूस की वजाय मध्य यूरोप में होने लगा।

इस प्रकार भिन्न भिन्न नस्लों और धर्मों के लोग यदि एक साथ रह भी तो इस तरह की कठिनाइयाँ पैदा होना स्वाभाविक रूप से अनिवार्य बात नहीं है। ये कठिनाइयाँ सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से ये कठिनाइयाँ उन देशों में पैदा होती हैं जहाँ कोई प्रतिक्रियावादी सरकार जनता के आंदोलन के खिलाफ अपने को बनाए रखने की कोशिश करती है। इस तरह की स्थितियाँ यदि कहीं पैदा हो रही हों तो यह समझना चाहिए कि जब इस शासनव्यवस्था को समाप्त हों स कोई ताकत रोक नहीं सकती।

भारत में हमारे सामने आज इसी तरह की समस्या है। भारत में आज (1941 की जनगणना के अनुसार) 25 करोड़ 40 लाख में अधिक हिंदू रहते हैं जो कुल जावादी का 65.93 प्रतिशत है। इनमें से 19 करोड़ 'ब्रिटिश भारत' में रहते हैं जहाँ उनका अनुपात

कुल जनसंख्या का 64.5 प्रतिशत होता है और साढ़े छ करोड़ लोग देशी रियासतों में रहते हैं जहाँ उनका अनुपात रियासतों की कुल आबादी का 70.57 प्रतिशत होता है। यहाँ मुसलमानों की संख्या 9 करोड़ 20 लाख है जो कुल आबादी का 23.81 प्रतिशत होता है। इनमें से 7 करोड़ 90 लाख मुसलमान ब्रिटिश भारत में रहते हैं जहाँ उनका अनुपात कुल आबादी का 26.84 प्रतिशत होता है और 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक मुसलमान देशी रियासतों में रहते हैं जहाँ उनका अनुपात आबादी का 13.93 प्रतिशत होता है।

अंगरेजों का शासन कायम होने से पहले भारत में उस तरह के हिंदू मुस्लिम झगड़े कभी नहीं दिखाई दिए जैसे बगड़े अंगरेजी शासनकाल में और खासतौर से इसने अंतिम दिनों में देखने को मिले। किसी एक रियासत का किसी दूसरी रियासत के साथ सघर्ष भी हुआ और कभी कभी यह भी देखने में आया कि एक रियासत का राजा हिंदू है और दूसरी रियासत का मुसलमान लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन सघर्षों ने हिंदू मुस्लिम सघर्ष का रूप लिया हो। मुसलमान शासक हिंदुओं को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने यहाँ ऊँचे से ऊँचे पदा पर नियुक्त करते थे और हिंदू शासक भी मुसलमानों के प्रति इसी तरह का रवैया अपनाते थे।

देशी रियासतों में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 'मौजूदा देशी रियासतों में सांप्रदायिक सघर्ष का अपेक्षाकृत काफी अभाव है।' इसके बाद के वर्षों में जहाँ जहाँ सांप्रदायिक सघर्ष हान की प्पूर मिली, जैसे कि 1931-32 में कश्मीर में, वहाँ सघर्ष की बुनियाद में सांप्रदायिक प्रश्नों का रत्तीभर भी स्थान न था। सघर्ष के मुद्दे कुछ और थे और साम्राज्यवादियों ने इन सघर्षों का सांप्रदायिक सघर्ष कहकर प्रचारित किया। इन सघर्षों का सांप्रदायिक मसला सवाई भी संवध नहीं था। दरअसल कश्मीर में मुस्लिम जनता ने, जो कुल आबादी का 4/5 भाग थी, अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और यह इत्फाक की बात थी कि उनका राजा हिंदू था। इस प्रकार इस विद्रोह को सांप्रदायिक विद्रोह की संज्ञा दे दी गई हालांकि प्रिटन के अधिवारों को यह स्वीकार करना पड़ा कि 'यह एक अजीब स्थिति है कि सांप्रदायिक विद्रोह होने के बावजूद एक भी हिंदू नहीं मारा गया' (डेली टलीग्राफ 8 फरवरी 1932)। वस्तुतः जैसे जैसे भारतीय रियासतों में जनता का विद्रोह तेज होता गया और शक्ति ग्रहण करता गया वैसे वैसे इन रियासतों में जनता के बीच गंदभाव पैदा करने का प्रचलित प्रतिस्पर्धावादी तरीका भी अपनाया जाने लगा।

जसा हमने देखा है, हिंदू मुस्लिम विरोध के बारे में वणन वगैरह हुए साइमन कमीशन की रिपोर्ट में दो अजीब तथ्यों का संक्षेप मकत किया गया है। एक तो यह कि इस तथ्य का विरोध उन दरबारों में जाना है जहाँ अंगरेजों का प्रभुत्व था जहाँ देशी रियासतों में यह विरोध कम है हालांकि दरार दरारों से जाना जा रहा है और दूसरा

रियासतों तथा ब्रिटिश सूबों की सीमाएँ केवल प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत के इलाकों में भी यह विरोध अभी हाल के वर्षों में बढ़ा है और एक पीढ़ी पहले तक ब्रिटिश भारत में ऐसे साम्प्रदायिक संघर्ष बहुत कम थे जिनसे जनजीवन की शांति को कोई खतरा हो। अतः साम्प्रदायिक संघर्ष ब्रिटिश शासन की जार खासतौर पर उसके अंतिम दिनों की अर्थात् साम्राज्यवादी प्रभुत्व के पतन के दौर की विशेष देन है।

इस धारणा में सरकारी क्षेत्रों में काफी रोप पैदा किया कि भारत में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की मूल जिम्मेदारी अंगरेजों के शासन की है (हम आगे चलकर देखेंगे कि और भी कई चीजों के लिए ब्रिटिश शासन जिम्मेदार है)। फिर भी विभिन्न साक्ष्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से इन तथ्यों की अपरिहार्यता समान रूप से सिद्ध होती है। स्वतंत्रता और रोप प्रकट किया जाना कोई तक नहीं है। क्योंकि साम्राज्यवाद सीजर की पत्नी नहीं है। इसके साथ ही साम्राज्यवादियों के छल-कपट से भरे दस्तावेज इतने अधिक हैं कि अत्यंत जाहिर तथ्यों को पाखंडपूर्ण ढंग से नकार देने से विश्व जनमत धोखा नहीं खा सकता।

शुरू के वर्षों में अंगरेज शासकों ने 'फूट डालो और राज करो' सिद्धांत की खुलेआम घोषणा की लेकिन बाद के वर्षों में वे इस तरह की घोषणाओं के प्रति सतर्कता का रव्व अपनाते लगे। 1821 में ही एक अंगरेज अफसर ने मई 1821 के एशियाटिक रिव्यू के एक में 'कनाटिकस' नाम से लिखते हुए कहा था कि 'राजनीतिक, नागरिक अथवा सैनिक हर क्षेत्र में हमारे भारतीय प्रशासन का मूल वाक्य फूट डालो और राज करो होना चाहिए।' मुरादाबाद के बमार्डेंट लफ्टीनेंट कनल बोक ने 19वीं सदी के मध्य में इस सिद्धांत की नींव डाल दी।

हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम पूरी ताकत के साथ विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मौजूदा भेदभाव को बना रहने दें। हम यह भेदभाव समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फूट डालो और राज करो ही भारतीय सरकार का सिद्धांत होना चाहिए।<sup>1</sup>

1888 में भारतीय मामलों के आधिकारिक विद्वान सर जान स्ट्रेथी ने लिखा

सचार्ई यह है कि भारत में एक दूसरे की विरोधी जातियों का साथ साथ रहना ही हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। (सर जान स्ट्रेथी इंडिया, 1888, पृष्ठ 255)

गांधी ने बताया है कि किस प्रकार कांग्रेस ने 'मनुकुल सस्थापन' छद्म में उनसे साफ साफ

यह कहा था कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर दृढ़ है (जे० टी० सडरलैंड की पुस्तक इंडिया इन बाडेज के पृष्ठ 232 पर उद्धृत)। 1910 में जे० रेमजे मैकडोनल्ड ने मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय में लिखा था

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 का हुई। मुस्लिम लीग को अपनी कोशिश में इतनी अधिक राजनीतिक सफलताएं मिली हैं कि लोगों को यह संदेह होने लगा है कि इस संगठन के पीछे काफी घातक शक्तियां का हाथ हैं। यह भी मदद किया जाता है कि मुस्लिम नेताओं को कुछ अंगरेज अफसरों से प्रेरणा मिली है और ये लोग शिमला और लंदन में ही बैठे बैठे अपने इशारे पर मुस्लिम नेताओं को नचा रहे हैं तथा मुसलमानों के साथ विशेष पक्षपात करके हिंदू और मुसलमानों के बीच जानबूझकर मनमुटाव को बढ़ावा दे रहे हैं। (जे० आर० मैकडोनल्ड 'दि अवेकनिंग आफ इंडिया', 1910, पृष्ठ 283-84)

बाद के वर्षों में जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह संदेह और भी पुष्ट हो गया है। 1926 में लार्ड ओलीवियर ने कुछ समय तक भारतीय मामलों के मंत्री का पद संभालने के बाद, और सभी दस्तावेजों को देखने के बाद 'दि टाइम्स' अखबार को एक पत्र लिखा

जिस भी व्यक्ति को भारतीय मामलों की अच्छी जानकारी है वह इस बात से इकार करने को तैयार नहीं होगा कि ब्रिटिश अफसरशाही ज़ामतीर पर मुसलमानों का पक्ष लेती है। कुछ हद तक तो यह पक्षपात सहानुभूति के कारण होता है ज्यादातर इसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवादिता को खिलाफ मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। (10 जुलाई 1926 के दि टाइम्स में लार्ड ओलीवियर का पत्र)

हाल के दिनों में इसी तरह के बुनियादी दृष्टिकोण को बड़ी चालाकी के साथ व्यक्त किया गया है। 1941 में दि टाइम्स अखबार ने लिखा

हिंदू मुस्लिम समझौते के बुनियादी महत्व पर जोर देने का अर्थ यह नहीं है कि अंगरेज फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहा है। दोनों संप्रदायों के बीच फूट मौजूद है और जब तक यह फूट बनी रहती तब तक अंगरेजों का शासन भी निश्चित रूप से बना रहेगा। (दि टाइम्स 21 जनवरी 1941)

इस प्रकार सरकारी नीति प्रतिनिधियों के अधीन।

कहा जाता है।

जिम्मेदार सरकारें

फिर भी इस आम नीति ने प्रशामनिक व्यवस्था का रूप आधुनिककाल में ही ग्रहण किया है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ने तथा एक के बाद दूसरे वैधानिक सुधारों के साथ-साथ इस बात की कोशिशें भी बढ़ती गईं कि सांप्रदायिक फूट को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए एक ऐसी अजीब ढंग की चुनाव प्रणाली का आविष्कार किया गया जिसमें इन वैधानिक सुधारों के साथ जोड़ दिया गया था। यह नया कदम 1906 में अर्थात् ठीक उस समय जब राष्ट्रीय आंदोलन की पहली बड़ी लहर आई थी उठाया गया।

घटनाक्रम के इस विकास की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उस सामाजिक आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के बीच देखना आवश्यक है जिसका असर हिंदुओं और मुसलमानों पर नहीं बल्कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्ग पर पड़ता है। वयई, कलकत्ता और मद्रास में अर्थात् हिंदू बहुल क्षेत्रों के उत्तर में मुस्लिमबहुल क्षेत्रों की तुलना में व्यापार व्यवसाय तथा शिक्षा का विकास काफी पहले शुरू हो गया था। 1882 में हटर कमीशन की रिपोर्ट ने यह पता लगाया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के मामले में औसतन मुसलमानों का अनुपात केवल 3.65 प्रतिशत था। आज भी मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं में साक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए भारतीय बुजुर्गों का उदय होने के साथ-साथ ऐसे भेदभावों के लिए परिस्थितियाँ तैयार हो गईं जो बहुत आसानी से सांप्रदायिक रूप धारण कर सकती थीं। मुसलमानों का ऊपरी वर्ग, जिसका मुख्य आधार बड़े जमींदारों में था व्यापारिक एवं औद्योगिक पूँजीपतिवर्ग की उन्नति को देखकर खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यह उन्नति हिंदुओं की या 'हिंदू बनियाँ' की उन्नति है। इसे वे बड़ी खतरनाक स्थिति मानते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्ग में अलग-अलग व्यापारिक गुटों के बीच सांप्रदायिक विरोध का आधार मौजूद था क्योंकि मुसलमान लोग ज्यादा पिछड़े हुए थे। इसी प्रकार प्रशासनिक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं पर आधारित प्रति-योगिता में भी हिंदू मुसलमानों की तुलना में बाजी मार ले जाते थे। जब प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास होने लगा और चुनाव प्रणाली आरंभ हुई तो मुसलमानों को फिर बंठनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि मताधिकार केवल शिक्षा या संपत्ति के आधार पर मिलता था। और यहाँ भी मुसलमानवर्ग हिंदुओं की तुलना में पीछे छूट जाता था। यही वजह थी कि अलग निवाचन की माँग को मुसलमानों के बीच प्रेरणा मिली। इन स्थितियों से सरकार के लिए फूट के बीच बौना और दोनों संप्रदायों के बीच निहित विरोधों को सामने लाकर उनके सहारे समूची राजनीतिक प्रणाली का एक ढाँचा तैयार करना आसान हो गया।

1890 में ही सर सैयद अहमद खाँ ने, जिसका सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध था मुसलमानों के एक गुट का नतत्व किया और उन्होंने मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों और पदों की माँग की। लेकिन जिम्मेदार मुस्लिम जनमत ने इस माँग का विरोध किया। 'मुस्लिम हेराल्ड' नामक पत्र ने इस माँग की निंदा करते हुए कहा कि यह माँग ग़ावाँ और जिलों

के सामाजिक जीवन में जहर घोल दंगी और भारत को नरक बना दंगी।' उस समय इस सिलसिले में कुछ और सुनने की नहीं मिला।

लेकिन अगरज सरकार का 1906 में जब भारत के पहले व्यापक राष्ट्रीय जन आंदोलन का सामना करना पड़ा तो उसमें एक ऐसी नीति का सूत्रपात किया जिससे सचमुच ही गांवों और जिलों के सामाजिक जीवन में जहर फैल जाने वाला या और भारत नरक बन जाने वाला या।' मुसलमानों के एक शिष्टमंडल ने वायसरॉय में भेंट की और उनमें मांग की कि भारत में चुनाव की यदि कोई प्रणाली जारी की जा रही हो तो उसमें मुसलमानों के लिए ज्यादा सीटों का बंदोबस्त रहे। वायसरॉय लार्ड मिंटो ने फौरन ही इस मांग को स्वीकार कर लिया।

आपका यह दावा बहुत सही है कि आप नाया का महत्व आपकी संख्या में न आका जाए बल्कि आपके समुदाय का राजनीतिक महत्व देखा जाए और इस ध्यान में रखा जाए कि आप लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी सेवाएं की हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। (1906 में मुसलमानों के शिष्टमंडल के सामने लार्ड मिंटो का भाषण, 'लाइफ ऑफ लार्ड मिंटो', जान वुशन, 1925, पृष्ठ 244)

बाद में 1923 में राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए मुसलमानों के नेता मोहम्मद अली ने कहा कि यह मुस्लिम शिष्टमंडल सरकार के ही इशारे पर वायसरॉय से मिलने गया था। यह पूरी योजना सरकारी अधिकारियों के दिमाग की उपज थी और इसका संकेत 1906 के अंत में लार्ड मिंटो के नाम लिखे गए एक पत्र में लार्ड मोर्ले ने दे दिया था।

मैं आपको मुसलमानों के इस झगड़े में फिर नहीं डालूंगा। मैं आदर के साथ सिर्फ एक बार और आपका यह वाद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ही अपने एक भाषण में विशेषाधिकारों की बात करके (मुसलमान) खरगोशों को दौड़ने के लिए बढ़ावा दिया है। (लार्ड मिंटो के नाम लार्ड मोर्ले का पत्र, 6 दिसंबर 1909, मोर्ले, रिप्लेवशंस, खंड 2, पृष्ठ 325)

इस प्रकार सांप्रदायिक चुनावक्षेत्रों और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली की शुरुआत हो गई जिसने हर जनवादी चुनाव प्रणाली की जड़ पर हमला किया। इसकी तुलना के लिए हम उत्तरी आयरलैंड की स्थिति की कल्पना करनी होगी। यदि वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का अलग-अलग मतदाताओं की सूची में डाल दिया जाए और उन्हें अलग-अलग प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाए तो संसद में जो संस्य चुन कर आएंगे वे अपने क्षेत्रों की समूची जनता के प्रति दायित्व का अनुभव न करके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सदस्यों के प्रति ही अपने कृतव्या का निर्वाह करेंगे। सांप्रदायिक मण्डल



और बरभाव को बढ़ावा देने के लिए इससे भी अच्छा कोई तरीका हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और सचमुच मुस्लिम लीग का पथक संगठन का समय दिसंबर 1906 ही है।

बहुधा यह तक दिया जाता है कि हिंदुआ की भरमार से मुसलमानों को बचाने के लिए पृथक चुनाव प्रणाली और पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अनिवार्य थी। इस तक का खोखलापन उही दिन स्थानीय सरकारी चुनावों में दिखाई पड़ गया। यह चुनाव संयुक्त चुनाव प्रणाली के पुराने आधार पर ही संपन्न हुए थे। इस प्रकार 1910 में संयुक्त प्रांत में दानो संप्रदायों के संयुक्त मतदाताओं ने जिला बोर्डों व चुनावों में 189 मुसलमान तथा 445 हिंदू और नगरपालिकाओं व चुनावों में 310 मुसलमान और 62 हिंदू प्रतिनिधि भेजे जबकि कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/7 थी।

इन दोनों संप्रदायों के बीच वैरभाव पैदा करने के पीछे जाँचकर देखा जा सकता है कि वह सबसे ज्यादा स्पष्टता के साथ केवल अलग चुनाव क्षेत्रों और अलग प्रतिनिधित्व की प्रणाली से ही नहीं बल्कि इस बात से भी व्यक्त हुआ कि मुसलमानों को विशेष रूप से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। भारयोजन के लिए एक भारी अल्पमत व्यवस्था तैयार कर दी गई। इस प्रकार माले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मतदान का अधिकार पाने के लिए मुसलमानों के लिए यह जरूरी था कि वह कम से कम तीन हजार रुपये मालाना की आमदनी पर आयकर देता हो जबकि गैरमुसलमानों के लिए यह राशि कम से कम तीन लाख रुपये कर दी गई थी। इसके अलावा मतदान का अधिकार पाने के लिए मुसलमानों को तीन साल पुराना ग्रेजुएट होना चाहिए था जबकि गैरमुस्लिम लोगों के लिए तीन साल पुराना ग्रेजुएट होने की शर्त थी। कुल सीटों के मामले में भी मुसलमानों को इसी तरह की सुविधाएँ दी गई थी। यह तरीका अपनाकर सरकार विशेषाधिकार प्राप्त अल्पमत का समयन प्राप्त करने की आशा करती थी और यह प्रयत्न करती थी कि इससे बहुमत वाले लोग सरकार पर अपना गुस्सा उतारने की वजाय मुस्लिम अल्पमत पर ही अपना गुस्सा उतारते रहेंगे।

वाद के वर्षों में जो सांविधानिक याजनाएँ बनीं उनमें यह व्यवस्था और व्यापक बनाई गई जिसकी चरम परिणति 1935 के संविधान में देखने को मिली। इस समय भी (1946) जो संविधान है उसमें यह व्यवस्था है कि नए संविधान की रचना के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के चुनावों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया जाए। 1935 के कानून में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि सिखों, एंग्लोइंडियन्स और भारतीय ईसाइयों के लिए तथा दलित वर्गों और यूरोपीयों, जमींदारों और उद्योगपतियों आदि के लिए भी अलग अलग चुनावक्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई। संघीय धारासभा में कुल 250 सीटों में से 82 सीटें अर्थात् एक तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे हालाँकि मुसलमानों की आबादी देश की कुल आबादी की चौथाई से भी कम थी। दूसरी ओर जावाणी के अधिकांश के लिए केवल 105 अर्थात् 40 प्रतिशत 'जाम सीटें'

रखी गई थी और इनमें से भी 19 सीटें अनुसूचित जातियाँ (दलितवर्ग) के लिए सुरक्षित थीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने चुनाव के मामले में जा गोलमाल किया था उसका यही गुणगान है।<sup>4</sup>

चुनाव के सदर्भ में जा नीति बरती जा रही थी वसी ही नीति का समूचे प्रशासन प्रवृत्ति में भी पालन किया जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि सांप्रदायिक विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। सांप्रदायिक विरोधों को शापण और साम्राज्यवादी शासन की व्यवस्था की रक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाता था लेकिन उनके पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी थे। यह बात उस समय और भी ज्यादा स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है जब मध्यवर्गीय सांप्रदायिक तत्व सरकारी पद या नौकरी के लिए एक दूसरे से होड़ लगाए हात है। जहाँ सांप्रदायिक कठिनाइयाँ आम जनता तक पहुँच गई हैं वहाँ भी यह बात इतनी ही स्पष्ट है। बंगाल और पंजाब में जा हिंदू वर्ग रहता है उसमें ज्यादातर धनी जमींदार, व्यापारी और महाजन भी शामिल हैं जबकि मुसलमान लोग बहुधा गरीब किसानों के रूप में हैं और स्थानीय महाजनो के कजदार हैं। दूसरे मामला में हिंदू किसानों के बीच बड़े जमींदारों के रूप में मुसलमान पाए जाते हैं। बार बार जिस 'सांप्रदायिक झगड़ा' या 'सांप्रदायिक विद्रोह' कहा गया है उसके पीछे हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का संघर्ष रहा है अथवा हिंदू महाजनो के खिलाफ मुसलमान कजदारों का संघर्ष रहा है अथवा हड़ताल ताड़ने के लिए बाहर से बुलाए गए पठानों के खिलाफ हिंदू मजदूरों का कोई संघर्ष रहा है। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब कभी किसी औद्योगिक केंद्र में मजदूरवर्ग आगे बढ़ा है तो वहाँ सांप्रदायिक दंगे करा दिए गए हैं (जिसमें कुछ अज्ञात लोगों का हाथ रहता है) और पुलिस को मजदूरों की भीड़ पर गोलियाँ चलाने का मौका मिल जाता है। इन घटनाओं की मिसाल 1929 में बंबई में हुई महान हड़ताल के अवसर पर या 1938 में कानपुर में सफल हड़ताल के बाद 1939 की घटनाओं में देखी जा सकती है। प्रतिक्रियावादियों की तिकड़म और उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे, वे चाहते थे कि मजदूरवर्ग की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया जाए।<sup>5</sup>

भारत की हिंदू मुसलमान जनता के दो अलग अलग लक्ष्य नहीं हो सकते और न हैं। मुसलमानों की गरीबी और गुलामी तथा हिंदुओं की गरीबी और गुलामी अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि वे समूचे गरीबी और गुलामी के हजारों लाखों गांवों में हिंदुओं और आबादी का हिस्सा एक जसी जमींदारी प्रथा के बोझ के एक जसे सूत का शिकार रहा है, एक जसे साधन का शिकार इन दोनों वर्गों के बीच फूट डालने की काशिसे रचने की,

सांप्रदायिक समस्या का अंतिम समाधान सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चलकर ही होगा। मजदूर संगठन और किसान संगठनों में हिंदू और मुसलमान दोनों बिना किसी भेदभाव के शामिल हो रहे हैं (और पृथक निर्वाचन पद्धति की जरूरत महसूस किए बिना), वर्गीय एकता और एक जैसी सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताएँ सांप्रदायिक तथा जातिपात के भेदभाव की नकली सीमाओं को तोड़ डालती हैं। सांप्रदायिक समस्या को अंतिम तौर पर हल करने का रास्ता यही है शुरू होता है। आम जनता के हितों के आधार पर जब जनआंदोलन जागे बढ़ेगा और सामान्य जनवादी आंदोलन की प्रगति होगी तभी सांप्रदायिक वैरभाव भी अंतिम और पूर्ण रूप में समाप्त किया जा सकेगा।

धर्म के आधार पर भारत की जनता को कृत्रिम रूप से दो 'राष्ट्रों' में बांटने की कोशिश वस्तुतः एक प्रतिक्रियावादी और अव्यावहारिक कोशिश है तथा यह जनतांत्रिक स्वतंत्रता के हितों के विपरीत है। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंगिकारों के घोषणापत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जिस बुनियादी नीति की स्थापना की थी वह जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव बिना सभी लोगों को समान जनवादी नागरिकता देने के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित थी। इसके साथ ही इसमें सभी अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण देने तथा अपनी आत्मा की आवाज बहिष्कृत कहने की स्वतंत्रता देने की भी व्यवस्था थी।

लेकिन इसके साथ ही समस्या का पूरी तरह जनवादी समाधान ढूँढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों अथवा जातियों के स्वायत्त शासन या आत्मनिर्णय के अधिकार के दावों के नए उभरते सवाल पर विचार करना भी जरूरी है। हाल के दिनों में यह सवाल अस्थायी तौर पर हिंदू मुस्लिम सवाल के साथ उलझ गए हैं। इधर के कुछ वर्षों में मुस्लिम लीग का बढ़कर एक जनसंगठन का रूप ले लना और पाकिस्तान नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग करना, इस विश्लेषण की अभिव्यक्ति करता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों की समस्याएँ बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक रंगमंच पर सामने आई हैं। इन प्रश्नों का जल्दी से जल्दी समाधान हो जाना चाहिए क्योंकि जैसा हमने 1946 के कैबिनेट मिशन के समझौते में देखा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मौजूद मतभेदों का साम्राज्यवादियाँ ने अपनी नीति निर्धारित करने के लिए मुख्य उत्तोलक बना लिया है। इन प्रश्नों के समाधान के लिए इतना ही जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता का सामान्य लक्ष्य प्राप्त किया जाए और सांप्रदायिक वैरभाव समाप्त किया जाए बल्कि इसके साथ ही हाल में पैदा हुई विशेष नई राजनीतिक समस्याओं की जांच-पड़ताल करना और उनका समाधान ढूँढ़ना जरूरी है।

### 3 बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान

बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान तथा कांग्रेस लीग एकता के ताज़ा सवाल पर आगे में पहले

रखी गई थी और इनमें से भी 19 सीटें 'अनुसूचित जातियों' (दलितवर्ग) के लिए सुरक्षित थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने चुनाव के मामले में जो गोलमाल किया था उसका यही गुणगान है।<sup>4</sup>

चुनाव के सदृश में जो नीति बरती जा रही थी वसी ही नीति का समूचे प्रशासन प्रवर्धन में भी पालन किया जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि सांप्रदायिक विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। सांप्रदायिक विरोधी को शापण और साम्राज्यवादी शासन की व्यवस्था की रक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाता था लेकिन उनके पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी थे। यह बात उस समय और भी ज्यादा स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है जब मध्यवर्गीय सांप्रदायिक तत्व सरकारी पद या नौकरी के लिए एक दूसरे से हाड़ लगाए होते हैं। जहां सांप्रदायिक कठिनाइयां आम जनता तक पहुंच गई हैं वहां भी यह बात इतनी ही स्पष्ट है। बंगाल और पंजाब में जा हिंदू वर्ग रहता है उसमें ज्यादातर धनी जमींदार, व्यापारी और महाजन भी शामिल हैं जबकि मुसलमान लोग बहुधा गरीब किसानों के रूप में हैं और स्थानीय महाजनों के कब्जेदार हैं। दूसरे मामले में हिंदू किसानों के बीच बड़े जमींदारों के रूप में मुसलमान पाए जाते हैं। बार बार जिसे 'सांप्रदायिक झगड़ा या सांप्रदायिक विद्रोह' कहा गया है उसके पीछे हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का संघर्ष रहा है अथवा हिंदू महाजनों के खिलाफ मुसलमान कब्जेदारों का संघर्ष रहा है अथवा हड़ताल तोड़ने के लिए बाहर से बुलाए गए पठानों के खिलाफ हिंदू मजदूरों का कोई संघर्ष रहा है। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब कभी किसी औद्योगिक केंद्र में मजदूरवर्ग आगे बढ़ा है तो वहां सांप्रदायिक दंगे करा दिए गए हैं (जिसमें कुछ अज्ञात लोगों का हाथ रहता है) और पुलिस का मजदूरों की भीड़ पर गोलीया चलाने का मौका मिल जाता है। इन घटनाओं की मिसाल 1929 में बंबई में हुई महान हड़ताल के अवसर पर या 1938 में कानपुर में सफल हड़ताल के बाद 1939 की घटनाओं में देखी जा सकती है। प्रतिक्रियावादियों की तिकड़म और उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे, वे चाहते थे कि मजदूरवर्ग की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया जाए।<sup>5</sup>

भारत की हिंदू मुसलमान जनता के दो अलग अलग लक्ष्य नहीं हो सकते और न ही। मुसलमानों की गरीबी और गुलामी तथा हिंदुओं की गरीबी और गुलामी अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि वे समूचे भारत की गरीबी और गुलामी हैं। भारत के हजारों लाख गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक जमींदारी प्रथा के बांध के नीचे पिस रहा है एक जसमूंदघार महाजनों का लूट का शिकार हो रहा है, एक जस साम्राज्यवाद के दमन का शिकार हो रहा है और इन दोनों का और पूट डालने का नाजिम वस्तुतः शापण की नग व्यवस्था का बख्तरार रहने का वागिर्ज ?।

सांप्रदायिक समस्या का अंतिम समाधान सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चलकर ही होगा। मजदूर संगठनों और किसान संगठनों में हिंदू और मुसलमान दोनों बिना किसी भेदभाव के शामिल हो रहे हैं (और पृथक निर्वाचन पद्धति की जरूरत महसूस किए बिना), वर्गीय एकता और एक जैसी सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताएँ सांप्रदायिक तथा जातपात के भेदभाव की नकली सीमाओं को तोड़ डालती हैं। सांप्रदायिक समस्या को अंतिम तौर पर हल करने का रास्ता यही से शुरू होता है। आम जनता के हितों के आधार पर जब जनजादोलन आगे बढ़ेगा और सामान्य जनवादी जादोलन की प्रगति होगी तभी सांप्रदायिक वैरभाव भी अंतिम और पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकेगा।

धर्म के आधार पर भारत की जनता को कृत्रिम रूप से दो 'राष्ट्रों' में बांटने की कोशिश वस्तुतः एक प्रतिक्रियावादी और अव्यावहारिक कोशिश है तथा यह जनतांत्रिक स्वतंत्रता के हितों के विपरीत है। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकारों के घोषणापत्र में राष्ट्रीय जादोलन के लिए जिस बुनियादी नीति की स्थापना की थी वह जाति धर्म या लिंग के भेदभाव बिना सभी लोगों का समान जनवादी नागरिकता देने के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित थी। इसके साथ ही इसमें सभी अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण देने तथा अपनी आत्मा की आवाज बेहिचक कहने की स्वतंत्रता देने की भी व्यवस्था थी।

लेकिन इसके साथ ही समस्या का पूरी तरह जनवादी समाधान ढूँढ़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों अथवा जातियों के स्वायत्त शासन या आत्मनिर्णय के अधिकार के दावा के नए उभरते सवाल पर विचार करना भी जरूरी है। हाल के दिनों में यह सवाल अस्थायी तौर पर हिंदू मुस्लिम सवाल के साथ उलझ गए हैं। इधर के कुछ वर्षों में मुस्लिम लीग का बढ़कर एक जनसंगठन का रूप ले लेना और पाकिस्तान नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग करना, इस विश्लेषण की अभिव्यक्ति करता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संघर्षों की समस्याएँ बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक रणमंच पर सामने आई हैं। इन प्रश्नों का जल्दी से जल्दी समाधान हो जाना चाहिए क्योंकि जैसा हमने 1946 के कैबिनेट मिशन के समझौते में देखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मौजूद मतभेदों का साम्राज्यवादियों ने अपनी नीति निर्धारित करने के लिए मुख्य उत्तालक बना लिया है। इन प्रश्नों के समाधान के लिए इतना ही जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता का सामान्य लक्ष्य प्राप्त किया जाए और सांप्रदायिक वैरभाव समाप्त किया जाए बल्कि इसके साथ ही हाल में पैदा हुई विशेष नई राजनीतिक समस्याओं की जांच-पड़ताल करना और उनका समाधान ढूँढ़ना जरूरी है।

### 3 बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान

बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान तथा कांग्रेस लीग एकता के ताजा सवाल पर आगे से पहले

रखी गई थी और इनमें से भी 19 सीटें अनुसूचित जातियों' (दलितवर्ग) के लिए सुरक्षित थीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने चुनाव के मामले में जो गोलमाल किया था उसका यही गुणगान है।<sup>4</sup>

चुनाव के सदृश में जो नीति बरती जा रही थी वसी ही नीति का समूचे प्रशासन प्रबन्ध में भी पालन किया जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि सांप्रदायिक विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। सांप्रदायिक विरोधों का शोषण और साम्राज्यवादी शासन की व्यवस्था की रक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाता था लेकिन उनके पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी थे। यह बात उस समय और भी ज्यादा स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है जब मध्यवर्गीय सांप्रदायिक तत्व सरकारी पद या नौकरी के लिए एक दूसरे से होड़ लगाए होते हैं। जहां सांप्रदायिक कठिनाइयाँ आम जनता तक पहुंच गई हैं वहां भी यह बात इतनी ही स्पष्ट है। बंगाल और पंजाब में जो हिंदू वर्ग रहता है उसमें ज्यादातर धनी जमींदार, व्यापारी और महाजन भी शामिल हैं जबकि मुसलमान लोग बहुधा गरीब किसानों के रूप में हैं और स्थानीय महाजनों के कजदार हैं। दूसरे मामले में हिंदू किसानों के बीच बड़े जमींदारों के रूप में मुसलमान पाए जाते हैं। बार-बार जिस 'सांप्रदायिक झगड़ा' या 'सांप्रदायिक विद्रोह' कहा गया है उसके पीछे हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का संघर्ष रहा है अथवा हिंदू महाजनो के खिलाफ मुसलमान कजदारों का संघर्ष रहा है अथवा हड़ताल तोड़ने के लिए बाहर से बुलाए गए पठानों के खिलाफ हिंदू मजदूरों का कोई संघर्ष रहा है। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब कभी किसी औद्योगिक केंद्र में मजदूरवर्ग आगे बढ़ा है तो वहां सांप्रदायिक दंगे बरप दिए गए हैं (जिसमें कुछ अज्ञात लोगों का हाथ रहता है) और पुलिस को मजदूरों की भीड़ पर गोलीयाँ चलाने का मौका मिल जाता है। इन घटनाओं की मिसाल 1929 में बंबई में हुई महान हड़ताल के अवसर पर या 1938 में कानपुर में सफल हड़ताल के बाद 1939 की घटनाओं में देखी जा सकती है। प्रतिक्रियावादियों की तिकड़म और उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे, वे चाहते थे कि मजदूरवर्ग की एकता को छिन भिन कर दिया जाए।<sup>5</sup>

भारत की हिंदू मुसलमान जनता के दो अलग अलग लक्ष्य नहीं हो सकते और न हैं। मुसलमानों की गरीबी और गुलामी तथा हिंदुओं की गरीबी और गुलामी अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि वे समूचे भारत की गरीबी और गुलामी हैं। भारत के हजारों लाखों गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक जसी जमींदारी प्रथा के दास के नीचे पिस रहा है, एक जैसे सूदखोर महाजनों की लूट का शिकार हो रहा है, एक जैसे साम्राज्यवाद के दमन का शिकार हो रहा है और इन दोनों वर्गों के बीच फूट डालने की वांछिश वस्तुतः शोषण की इस व्यवस्था को बरकरार रखने की वांछिश है।

सांप्रदायिक समस्या का अंतिम समाधान सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चलकर ही होगा। मजदूर संगठना और किसान संगठनों में हिंदू और मुसलमान दोनों बिना किसी भेदभाव के शामिल हो रहे हैं (और पृथक निर्वाचन पद्धति की जरूरत महसूस किए बिना), वर्गीय एकता और एक जैसी सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताएँ सांप्रदायिक तथा जातपात के भेदभाव की नकली सीमाओं को तोड़ डालती हैं। सांप्रदायिक समस्या को अंतिम तौर पर हल करने का रास्ता यही संशुरू होता है। आम जनता के हितों के आधार पर जब जनआंदोलन आगे बढ़ेगा और सामान्य जनवादी आंदोलन की प्रगति होगी तभी सांप्रदायिक वैरभाव भी अंतिम और पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकेगा।

धर्म के आधार पर भारत की जनता को कृत्रिम रूप से दो 'राष्ट्रों' में बांटने की कोशिश वस्तुतः एक प्रतिक्रियावादी और अव्यावहारिक कोशिश है तथा यह जनतांत्रिक स्वतंत्रता के हितों के विपरीत है। 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकारों के घोषणापत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जिस बुनियादी नीति की स्थापना की थी वह जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव बिना सभी लोगों को समान जनवादी नागरिकता देने के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित थी। इसके साथ ही इसमें सभी अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक संरक्षण देने तथा अपनी आत्मा की आवाज बहिष्कृत करने की स्वतंत्रता देने की भी व्यवस्था थी।

लेकिन इसके साथ ही समस्या का पूरी तरह जनवादी समाधान ढूँढने के लिए अलग अलग क्षेत्रों अथवा जातियों के स्वायत्त शासन या आत्मनिर्णय के अधिकार के दावों के नए उभरते सवाल पर विचार करना भी जरूरी है। हाल के दिनों में यह सवाल अस्थायी तौर पर हिंदू मुस्लिम सवाल के साथ उलझ गए हैं। इधर के कुछ वर्षों में मुस्लिम लीग का बढ़ते-चले जनसंगठन का रूप ले लेना और पाकिस्तान नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग करना, इस विश्लेषण की अभिव्यक्ति करता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंधों की समस्याएँ बढ़ी तेजी के साथ राजनीतिक रंगमंच पर सामने आई हैं। इन प्रश्नों का जल्दी से जल्दी समाधान हो जाना चाहिए क्योंकि जैसा हमने 1946 के कैबिनेट मिशन के समझौते में देखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मौजूद मतभेदों को साम्राज्यवादियों ने अपनी नीति निर्धारित करने के लिए मुख्य उत्तोलक बना लिया है। इन प्रश्नों के समाधान के लिए इतना ही जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता का सामान्य लक्ष्य प्राप्त किया जाए और सांप्रदायिक वैरभाव समाप्त किया जाए बल्कि इसके साथ ही हाल में पड़ा हुई विशेष नई राजनीतिक समस्याओं की जाच-पड़ताल करना और उनका समाधान ढूँढना जरूरी है।

### 3 बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान

बहुराष्ट्रवाद और पाकिस्तान तथा कांग्रेस लीग एकता के ताजा सवाल पर आने से पहले

मुस्लिम लीग व विकास तथा कांग्रेस लागू मसाला के इतिहास पर मधेय म विचार कर लेना आवश्यक है।

मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हुई थी। जैसा शुरू में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मामले में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना में भी अंगरेजों की सरकारी नीति की उल्लेखनीय भूमिका रही। ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों ने यह आशा की कि सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का विभाजन करने के साथ साथ मुसलमानों का यदि अलग से राजनीतिक संगठन बना दिया जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन को छिन्न भिन्न किया जा सकता है और कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को कमजोर बनाया जा सकता है। उस समय एक अंगरेज अफसर ने वायसरॉय लॉर्ड मिंटो को लिखा था

महामहिम की सेवा में मुझे यह कहना है कि आज एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। राजनीतिक निपुणता का आज एक ऐसा कमाल हो गया है जो आने वाले कई वर्षों तक भारत को और भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। दरअसल, आज का काम हुआ है उससे 6 करोड़ 20 लाख लोगों को (मुसलमानों को) देशद्रोही विपक्ष (कांग्रेस) से भिन्न करने में मदद दिया गया है। (लेडी मिंटो 'इंडिया, मिंटो ऐंड माले', 1934, पृष्ठ 47)

लेडी मिंटो ने आगे लिखा है कि लंदन की सरकार का भी काफी हद तक यही विचार था।

अपने गुरु के दिनों में मुस्लिम लीग एक ऐसा सकीण सांप्रदायिक संगठन था जो मुख्यतया उच्चवर्ग के मुसलमान जमींदारों को आकर्षित करता था। लेकिन कांग्रेस की ही तरह जल्दी ही मुस्लिम लीग में भी साम्राज्यवादविरोधी राष्ट्रीय भावना अपना असर दिखाने लगी। 1913 के आठवां मुस्लिम लीग ने भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज्य प्राप्त करने का अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने 'दूसरे संप्रदायों के साथ सहयोग' करने का एलान कर दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गई थी और 1916 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों का व्यवस्थापन करने के साथ साथ यह भी घोषणा की गई थी कि दोनों संस्थाओं का समान लक्ष्य भारत को डोमिनियन का दर्जा दिलाना है और इसकी प्राप्ति के लिए दोनों संस्थाएं प्रयास करेंगी।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। कांग्रेस अधिवेशन में तत्काल ने कहा



उपस्थित सज्जनो, कुछ तांगा द्वारा यह कहा जाता है कि हम हिंदू लोग अपन मुसलमान भाइयों के सामने बहुत अधिक झुक गए हैं। मेरा विश्वास है कि मैं दशभर के हिंदूओं की ओर से यह कह सकता हूँ कि यह कहना गलत है कि हम जरूरत से ज्यादा मुक गए हैं जब हमें किसी तीसरे पक्ष से लड़ना हो तो यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि आज हम इस मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं, हम नस्ल, धर्म तथा राजनीतिक विचारों के सभी भेदभाव भूलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं।

इसी प्रकार लीग के नेता माहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने उस समय कांग्रेस लोग एकता के लिए काफी सक्रियता दिखाई थी, लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से कहा

मैं पूरी जिदगी कट्टर कांग्रेसी रहा हूँ और सांप्रदायिक नारों से मुझे कभी लगाव नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों पर कभी कभी अलगाव का जो आरोप लगाया जाता है वह बिल्कुल गलत है। खासतौर पर जब मैं यह देखता हूँ कि यह महान सांप्रदायिक संगठन एक संयुक्त भारत के जन्म के लिए बड़ी तेजी के साथ एक बड़ी ताकत बनती जा रही है तो ये आरोप मुझे और भी गलत लगते हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जो तूफानी उभार आया उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और जुझारू मुस्लिम नेताओं की खिलाफत समिति, जिसका नेतृत्व अली बहुधा न किया था, के बीच संयुक्त मोर्चा कायम हो गया। दोनों समस्याओं ने संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा कायम किया जो स्वराज्यप्राप्ति के लिए सघन दौड़ सके। सबको पर हिंदू मुस्लिम एकता के जोश भरे नार सुनाई देने लगे। 1919 की सरकार की रिपोर्ट को मजबूर हाकर यह स्वीकार करना पड़ा कि 'हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है दोनों संप्रदायों के बीच मैत्री के असाधारण दृश्य दिखाई देने लगे हैं।'

राष्ट्रीय उभार के इस महान युग में मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता ने भी कांग्रेस के साथ साथ अपना जुझारूपन का परिचय दिया। अनेक बहुओं और हुसैन मदानी जैसे मुस्लिम नेताओं ने सैनिकों का राजद्रोह करने की शिक्षा दी और इसके लिए उन्हें छ बप कद की सजा सुनाई गई। मालाबार के मोपला किसान अपने आप ही जमींदारों तथा साम्राज्यवादियों के दमन के खिलाफ उठ खड़े हुए, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और आश्चर्यजनक वीरता तथा सघन और बलिदान की क्षमता का परिचय दिया।

खिलाफत रुमेटों के नेताओं ने ही सबसे पहले यह मांग उठाई थी कि स्वराज की व्याख्या पूर्ण स्वाधीनता के रूप में की जाए। 1921 में अहमदाबाद में मौलाना हमरत मोहानी ने

यह मांग उठाई थी। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि गांधी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि 'इस मांग से मुझे यहद अप्रसन्न हुआ है क्योंकि इससे गैरजिम्मेदारी की भावना प्रकट होती है।' इसी प्रकार 1919 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया था कि भारत में मुसलमानों का फौज में भरती नहीं होना चाहिए।

जून 1922 में खिलाफत समिती और जमियत उल उलमा का एक मयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि 'भारत और मुसलमानों, दोनों के हित में यह है कि कांग्रेस के घोषित लक्ष्य में 'स्वराज्य' शब्द के स्थान पर 'पूर्ण स्वाधीनता' शब्द रख दिए जाएँ। दुर्भाग्यवश उन दिनों कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अपने विरोध के पक्ष में यह तर्क दिया कि इससे कांग्रेस के मविधान में 'यूनियादी परिवर्तन' हो जाएगा।

कांग्रेस और खिलाफत समिती के बीच जो एकता कायम हुई थी वह बनी नहीं रह सकी। गांधी के नतत्व में कांग्रेस द्वारा आंदोलन को अचानक बीच में ही रोक दिए जाने में दोनों गुटों में फूट पड़ गई। फरवरी 1922 में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन बढ़ा दिया तो खिलाफत समिती के सभी नेताओं ने इस तरह से संपर्क का रोक देने का विरोध किया।

इसके बाद के वर्ष निराशा के वर्ष थे जिसमें एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग-अलग तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच बरभाव का रास्ता खोल दिया। साम्राज्यवादियों का यह अवसर अपने लिए काफी अनुकूल लगा और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। बाद के वर्षों में यह देखा गया कि जहाँ आजादी के लिए मिलजुलकर संपर्क हो रहे थे वहाँ अब जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्धावाद पूरी तरह हावी हो गया। 1925 में मुस्लिम लीग के विरोध में अखिल भारतीय पैमाने पर हिंदू महासभा का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय चुने गए। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर साइमन कमिशन का बहिष्कार किया लेकिन 1928 के सचदलीय सम्मेलन में समझौता कराने की सारी कोशिशें विफल हो गईं।

इस प्रकार 1937 में जब प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के विरोध में मैदान में आ डटे। ये चुनाव 1935 के नए विधान के अंतर्गत पहली बार कुछ अधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर हुए थे। इन चुनावों में आम सीटों में से ज्यादातर और प्रांतीय विधानसभाओं की कुल सीटों में से लगभग आधी सीटें (1585 सीटों में से 711 सीटें) कांग्रेस को मिलीं लेकिन मुस्लिम सीटों में से उमे विशेष सफलता नहीं मिली। कांग्रेस ने 482 मुस्लिम सीटों में से केवल 58 के लिए चुनाव लड़ा और उनमें से महज 26 सीटों पर उस सफलता मिली (इसमें से 15 उसे सरहदों सूबों में और 11 सीटें देश के बाकी हिस्सों में मिलीं)। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को इस

कारण बहुत कम सफलता मिली क्योंकि मुसलमानों के अलग अलग गुट बन गए थे और उनमें गहरी फूट थी। मुस्लिम लीग को कुल मुस्लिम वोटों का केवल 46 प्रतिशत भाग ही मिल सका (चुनाव में मुसलमानों के कुल 7 319,445 वोट थे जिनमें से मुस्लिम लीग को केवल 321,772 वोट मिले)।

1937 के चुनावों के बाद मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं से अनौपचारिक तौर पर प्रांतीय मंत्रिमंडलों के मंत्रियों में तथा सीटों के निर्धारण के बारे में समझौता करने की कोशिश की। लेकिन इस समय कांग्रेस यह महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति काफी मजबूत है और इसलिए उसने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, राजनीतिक भूमिका निभाने के मुस्लिम लीग के हर दावे को ठुकरा दिया और खुद यह दावा किया कि कांग्रेस ही समूचे देश की प्रतिनिधि संस्था है। जनवरी 1937 में नहरू ने जिन्ना के नाम एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा

अंतिम विवरण में भारत में आज केवल दो ही शक्तियाँ हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस मुस्लिम लीग मुसलमानों के एक गुट का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें निःसंदेह काफी महत्वपूर्ण लोग हैं लेकिन मुस्लिम लीग का काम केवल उच्च मध्यवर्ग के लोगों तक ही सीमित है और उसका मुस्लिम जनता से कोई आम संपर्क नहीं है। मुसलमानों के निम्न मध्यवर्ग से तो उसका बहुत कम संपर्क है।

इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बहुत जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कुशल नेतृत्व में अपने संगठन को मजबूत बनाने का बीड़ा उठा लिया और इसने मुस्लिम जनता में अपनी गहरी पैठ बनानी शुरू कर दी। इसने इधर उधर फैले विभिन्न असंतुष्ट मुस्लिम दलों और संगठनों को अपने में मिलान की कोशिश का ताकिया मुस्लिम लीग भारत में रहने वाले मुसलमानों की प्रमुख संस्था बन जाए। यह नीति अमफल नहीं रही। 1937 से 1945 के बीच मुस्लिम लीग की स्थिति में और उसकी सांप्रदायिक शक्ति में निष्ठापूर्ण परिवर्तन हो गया। मुसलमानों ने अधिक से अधिक संख्या में इस संस्था का समर्थन करना शुरू किया। 1927 में मुस्लिम लीग के सदस्यों की कुल संख्या 1330 थी जो लीग द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार 1938 में लाखों तक पहुँच गई और 1944 में तो लीग ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया कि उसके सदस्यों की संख्या 20 लाख हो गई है। 1946 के चुनावों से इस बढ़ती हुई स्थिति का पता चला। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में कुल 533 मुस्लिम सीटों में से 460 पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन वर्षों में मुस्लिम लीग ने खुद को भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित कर लिया है।

व कौन से कारण व जिनमें दो वर्षों में मुस्लिम लीग का जनता पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा ? इसके कई कारण दूढ़े जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि पिछले दशक की राजनीतिक गतिविधियों का असर यह हुआ था कि जनता के नए हिस्से, जो अभी तक पिछड़े हुए थे, राजनीति में खिंच आए थे और उनके अंदर राजनीतिक चेतना का प्राथमिक रूप में संचार हो गया था। इसी वर्षों के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई। 1935-36 से 1938-39 के बीच कांग्रेस व सदस्यों की संख्या में 9 गुनी वृद्धि हुई और वह 44 लाख तक पहुंच गई लेकिन इनमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। जनवरी 1938 में नहरू द्वारा जारी किए गए एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस के 31 लाख सदस्यों में से केवल एक लाख अर्थात् 3.2 प्रतिशत सदस्य मुस्लिम भ्रूण थे। मुसलमानों के जिस विशाल बहुमत में नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था उसने राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग में शामिल होना प्रेरित किया था।

दूसरी बात यह है कि खुद मुस्लिम लीग के अंदर नौजवानों और प्रगतिशील तत्वों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जो एक जनतावादी कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहा था और जिसका विरोध संगठन के ऊपरी पदा पर बैठे पुराने प्रतिक्रियावादी नेता कर रहे थे। कुछ जिलों और प्रांतों, जैसे पंजाब और बंगाल, में ये नौजवान जनता के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में सक्रिय रूप से अभियान कर रहे थे और अपने इस अभियान के जरिए उन्हें गरीब मुसलमान वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा था। इस नीति की सफलता 1946 में पंजाब के चुनाव में साबित हुई जहां मुस्लिम लीग का हमला के सामने बहा की पुरानी प्रमुख पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी को जबरदस्त मात खानी पड़ी।

तीसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग का जनता के बीच जो प्रभाव बढ़ा और कांग्रेस संगठन में जो बहुत कम मुसलमान आए उससे निस्संदेह रूप से कांग्रेस की कुछ राजनीतिक, संगठनात्मक और कार्यक्रमी संबंधों में कमजोरियां भी सामने आईं। कांग्रेस का बुनियादी लक्ष्य यह रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को इस संगठन में शामिल किया जाए। लेकिन व्यवहार में देखें तो सदस्य संख्या के संदर्भ में यह लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया गया। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार 1922 में जब असहयोग आंदोलन अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गया था तब उम अचानक रोक दान से कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के संयुक्त मोर्चे में कार्ययोजना पर जबरदस्त आघात पहुंचा था। प्रांतों में कांग्रेस के मजिद बनने के काल में लीग द्वारा प्रस्तावित समझौते की योजना का कांग्रेस द्वारा ठुकराने से यह पता चलता है कि उस समय मुस्लिम लीग की शक्ति को कांग्रेस बहुत कम करके आकंती थी। बाद के वर्षों में यही बात मुस्लिम लीग के हाथ में एक जबरदस्त हथियार बन गई थी जिसके जरिए कांग्रेस विरोधी प्रचार आसानी से हो जाता था। युद्ध के दौरान और युद्ध शुरू होने से पहले की जटिल राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ज्यादा उलझनों, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों और दुर्लभता का परिचय दिया (मुभापचंद्र बोस

को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और फिर कांग्रेस में ही उन्हें निकाल दिया गया। युद्ध के साम्राज्यवादी दौर में निष्प्रियता दिखाई गई। ऐसी नीति का पालन किया गया जिसमें कहा गया कि युद्ध के प्रयासों की न तो हम मदद करेंगे और न उसका विरोध करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। जिस समय जापानी सैनिक आगे बढ़ते आ रहे थे तब दुर्भाग्यपूर्ण जगहों पर प्रस्ताव पास किया गया जिसके बावजूद समूचा नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया। कठिन गैरकानूनी परिस्थितियाँ पैदा हो गईं और छिटपुट उपद्रवों की घटनाएँ हुईं जिन्हें नेतृत्व ने उस समय अस्वीकार किया और बाद में उन्हें राष्ट्रीय संघ का नाम देकर सराहा गया। युद्ध के कारण देश की आर्थिक कठिनाइयाँ और अकाल का सामना करना पड़ा लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए जनता का नेतृत्व नहीं किया। इसके फलस्वरूप युद्ध के अंतिम चरण में राजनीतिक विघटन हुआ और जनता का मनोबल गिरा। इस प्रकार इस दौर में संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन की अपील पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया।

मुस्लिम लीग के विकास के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस ने गंभीरता के साथ मुस्लिम जनता तक पहुँचने और उससे अपील करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। इसका स्रोत यह था कि सरहद्दी सूबों में जहाँ पर अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने जनता के बीच गंभीरता के साथ काम किया वहाँ की स्थिति अन्य स्थानों की तुलना में बिल्कुल भिन्न थी और वहाँ के मुसलमान पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस में थे। यह भी सही है कि कांग्रेस का कार्यक्रम हालाँकि अमाप्रदायिक था और इस संगठन में अनेक प्रमुख दशमकत मुसलमान शामिल थे फिर भी कांग्रेस के काफी प्रचार में तथा खासतौर पर दक्षिणपंथी नेताओं और गांधी के प्रचार में हिंदू धर्म की एक गंध बनी रहती थी जो मुसलमान जनता को कांग्रेस की ओर आकर्षित होने से रोक देती थी।

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं पर इसकी बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। हमने पहले ही देखा है कि युद्ध के पूर्व भारत में राष्ट्रीय जागरण की जा पहली बड़ी लहर आई थी उसमें तिलक, अरविंद घोष तथा अन्य जुझारू नेताओं ने हिंदू धर्म को अपने प्रचार का आधार बनाया था और इस बात को कोशिश की थी कि राष्ट्रीय जागरण को हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ मिला दिया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में अलग पड़ गई और सरकार का इस बात का अवसर मिल गया कि वह 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होने दे।

यह पातक गलती पुरातनकाल के राष्ट्रवादियों या तथाकथित 'उग्रपंथियों' तक ही सीमित नहीं रही। आधुनिक काल में भी यह गलती जारी रही और गांधी के समूचे आंदोलन तथा प्रचार में इस गलती की गंभीर छाप देखी जा सकती है। गांधी के समूचे प्रचार में एक तरफ तो हिंदूवाद और उनकी धार्मिक धारणाओं का उपदेश दिया गया है तथा दूसरी तरफ आम राजनीतिज्ञ उद्देश्यों की बात नहीं गई है। इस प्रकार गांधी ने राजनीति और

धम की धारणाओं को बुरी तरह उनसा दिया। 1920-22 में अब राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन काफी जोर पर था और इस संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में जनता के सामने गांधी थे और जब उनपर यह जिम्मेदारी थी कि वह जा भी कहें यह एक संयुक्त आंदोलन के नेता का शोभा देन योग्य हो, उस समय उन्होंने सावजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि वह 'सनातनी हिंदू' हैं (यह एक तरह का उग्रवाद था)। उन्होंने खुलेआम यह कहा था

मैं अपने को सनातनी हिंदू कहता हूँ क्योंकि —

- 1 मैं वेदा, उपनिषदा पुराणों और समस्त हिंदू शास्त्रों में विश्वास करता हूँ और इसीलिए अवतारों तथा पुनर्जन्म में भी मेरा विश्वास है।
  - 2 मैं वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता हूँ। इसे मैं उन अर्थों में मानता हूँ जो पूरी तरह वेदसम्मत हैं लेकिन उसके वर्तमान प्रचलित और भोड़े रूप को मैं नहीं मानता।
  - 3 मैं प्रचलित अर्थों से कहीं अधिक व्यापक अर्थ में गाय की रक्षा में विश्वास करता हूँ।
  - 4 मूर्तिपूजा में मेरा अविश्वास नहीं है।
- (यंग इंडिया में गांधी का लेख, 12 अक्टूबर 1921)

'सनातनी' शब्द का अब साधारण जनता क्या समझती है यह जानने के लिए नेहरू के इस कथन को याद कर लेना पर्याप्त होगा

सनातनी लोग जिस रफ्तार से पीछे की तरफ चल रहे हैं उससे हिंदू महासभा मात खा गई है। सनातनियों में धार्मिक कट्टरता के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत तेज या कम से कम काफी जोरदार शब्दों में प्रकट की जाने वाली वफादारी भी होती है। (जवाहरलाल नेहरू आत्मकथा पृष्ठ 382)

यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपील करते समय भी गांधी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं बोलते जो दोनों संप्रदायों में एकता की भावना पैदा करता हो। वह हमेशा एक हिंदू नेता के रूप में बोलते थे, हिंदुओं को वह 'हम लोग' और मुसलमानों को 'वे लोग' कहते थे।

यदि हम मुसलमानों को जीतना है तो हम आत्मसुद्धि के लिए तपस्या करनी होगी। (यंग इंडिया में गांधी का लेख, सितंबर 1924)

आधुनिक राष्ट्रीय संघर्ष के किसी भी दौर में गांधी कांग्रेस की राजनीति को छोड़कर हिंदू

धर्म का सुधार आदोलन शुरू कर सकत थे (जैसा उन्होंने 1932-33 में संघ के संकट-पूर्ण दौर में किया था) और सुधार आदोलन को छोड़कर फिर कांग्रेस की राजनीति में आ सकते थे।

इस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि नता और जनता की निगाहों में इसका मुख्य प्रतिनिधि हमेशा हिंदू धर्म तथा हिंदू पुनर्जागरण के एक सक्रिय नेता के रूप में लोगों के सामने आता रहा। फिर इसमें आश्चर्य क्या यदि ऐसी परिस्थिति में (जो जहाँ इस संदर्भ में मुख्य अपराध गांधी का था वहाँ यह भी सच है कि कांग्रेस के बहुत से छोटे नेता और खासकर वे लोग जो गांधीवाद से प्रेरणा लेते थे, इसी तरीके का प्रयाग करते थे) जो कांग्रेस के ऐसे नेताओं तथा ऐसे प्रचार के अस्तित्व में होने के कारण केवल दुश्मन आलाचक्र ही नहीं बल्कि साधारण जनता का भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को 'हिंदू आंदोलन' समझता था? यदि इन सारी चीजों के बावजूद कुछ चुने हुए मुसलमान नेता हमेशा निष्ठापूर्वक कांग्रेस के साथ चलते रहें तो इसका श्रेय उनकी राष्ट्रभक्ति को है। लेकिन यही तरीके ऐसे नहीं थे जिनसे आम मुसलमान जनता कांग्रेस के साथ आ जाती।

ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक फूट से भरपूर फायदा उठाया और जनता के आंदोलन के विरुद्ध निस्संदेह एक घृणित अस्त्र के रूप में इस फूट का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार के हाथों में यह अस्त्र तिलकवाद और गांधीवाद ने दिया था।

फिर भी, इन सबके अलावा एक और विशेष कारण है जिससे जनता पर मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ा खासतौर पर 1940 में पाकिस्तान का कार्यक्रम स्वीकार कर लेने के बाद। पाकिस्तान के कार्यक्रम के जरिए शुरू शुरू में यह मांग की गई थी कि मुसलमान बहुल पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में जलजल से प्रभुसत्तासंपन्न राज्यों की स्थापना की जाए। पाकिस्तान का कार्यक्रम क्या था इसपर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। प्रभुसत्तासंपन्न राज्यों की जो मांग थी वह आगे चलकर छः प्रांतों के एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग में तब्दील हो गई। इस कार्यक्रम की आलोचना के लिए बड़े ठोस आधार हैं। लेकिन इधर हाल के वर्षों में जिस तरह यह कार्यक्रम राजनीतिक रंगमंच पर सामने आया और इन इलाकों की मुसलमान जनता ने उसका जिस तरह समर्थन किया उससे स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम एक हद तक जनता की उचित भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता था भले ही उसका स्वरूप काफी उलझा हुआ क्यों न हो। पाकिस्तान की मांग और जनता द्वारा इस मांग को मिले जबरदस्त समर्थन के पीछे यह देखा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक नया तत्व सक्रिय हो उठा था।

राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे जनता के बीच व्यापक रूप ले रहा था वैसे वैसे वह राष्ट्रीय चेतना के नए स्वरूपों का ऊपर ला रहा था और भारतीय जनता के विभिन्न राष्ट्रीय तत्व

इन स्वरूपों से अभिव्यक्ति पा रहे थे। जिन राष्ट्रीय समूहों में खासतौर पर उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भारत के राष्ट्रीय समूहों में जहाँ आवादी पर मुस्लिम धर्म का काफी प्रभाव था एक हद तक पाकिस्तान का नाग इस नई बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को एक विकृत रूप में व्यक्त कर रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ साथ भारतीय जनता का बहुजातीय स्वरूप तेजी के साथ स्पष्ट होता जा रहा था और स्तालिन ने 1912 में ही इस भावी स्थिति का अनुमान लगा लिया था 'संभवतः भारत में भी यह देखा जाएगा कि अमूल्य जातियाँ जो अभी तक सोती रही हैं, दुजुआ विकास के आगे बढ़ने पर जग उठेंगी।'।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वाधीनतासंघर्ष में भारतीय जनता की एकता और भविष्य के स्वतंत्र भारत को आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट बनाए रखने के प्रगतिशील लक्ष्य से यह नतीजा नहीं निगाल लेना चाहिए कि भारत की जनता कोई एकरूप इकाई है। इसके बदले आवश्यकता इस बात की है और इसके बहुत स्पष्ट तथा ठोस आधार हैं कि हम भारतीय जनता के बहुजातीय स्वरूप को स्वीकार करें। वस्तुतः कांग्रेस ने इन जातीय समूहों को उसी समय आंशिक रूप से मान्यता दे दी थी जिस समय उसने अंगरेजों द्वारा मनमाने ढंग से बनाए गए प्रांतों की जगह पर सांस्कृतिक और भाषायी प्रांतों को स्वीकार किया था और यह माना था कि भविष्य में स्वतंत्र भारत के संविधान में इन प्रांतों को पूरी पूरी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। लेकिन इस अवधि के दौरान कांग्रेस ने इन समूहों के जातीय स्वरूप को नहीं माना और उनका आत्मनिर्णय का पूर्ण अधिकार देने का विरोध किया। फिर भी भारतीय जनता के बहुजातीय स्वरूप के इस प्रश्न को और मुस्लिम लीग द्वारा की गई पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल अलग अलग चीजों के रूप में देखना चाहिए और उनके भेद को समझना बहुत जरूरी है।

पाकिस्तान की मांग को (हालांकि इसे अभी तक नाम नहीं दिया गया था) मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में अपनाया था। इससे पहले चौथे दशक में कुछ लोगों ने जब यह मांग की थी (1930 में उदू के शायर इकबाल ने और 1933 में ब्रिज में कुछ छात्रों ने यह मांग उठाई थी) तो मुस्लिम लीग के राजनीतिक नेताओं ने इस मांग को नामजूर कर दिया था। 1933 में सांविधानिक सुधारों की संयुक्त समिति के सामने बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि यह विद्यार्थियों का एक सपना तथा अव्यावहारिक है। 1937 में भी मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में संगठन का यह लक्ष्य स्वीकार किया गया था कि मुस्लिम लीग भारत में पूर्ण स्वतंत्र जनतांत्रिक राज्यों के एक सपने के रूप में पूर्ण स्वाधीनता की स्थापना के लिए काम करेगी। लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने यह प्रस्ताव पास किया

यह तय किया जाता है कि जाल इंडिया मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की राय में इस दशक में कोई भी सांविधानिक योजना उभरने तक असमर्थ नहीं लाई जा



सकती या ऐसी किसी योजना को मुसलमानों की स्वीकृति नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि वह इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाई जाती, भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के आसपास की इकाइयों को अलग करके और उनकी चौहद्दियों में आवश्यक परिवर्तन करके ऐसे प्रदेश बना दिए जाएं ताकि जिन इलाकों में सख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत हो जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाके, उन मुस्लिम बहुमत के इलाकों को मिलाकर ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाएं जिनमें सम्मिलित इकाइयों का स्वायत्त शासन का अधिकार हो तथा प्रभुसत्ता प्राप्त हो।

बाद में इस अस्पष्ट प्रस्ताव की जगहदस्त व्याख्या की गई। 10 दिसंबर 1945 को एक भेटवार्ता में जिन्ना ने लोग की भाग की इन शब्दों में व्याख्या की

भारत में गतिरोध, भारत और अंगरेज के बीच में उतना ज्यादा नहीं है। वह हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच है। जब तक पाकिस्तान की स्थापना नहीं होती तब तक कोई समस्या नहीं हल हो सकती है और नहीं होगी। संविधान निर्माण के लिए एक नहीं बल्कि दो संस्थाओं का गठन करना होगा, एक संस्था हिंदुस्तान का संविधान बनाएगी और दूसरी संस्था पाकिस्तान के संविधान के बारे में फसला करेगी और उसकी रचना करेगी।

भारत का मसला हम दस मिनट में हल कर सकते हैं बशर्ते मिस्टर गांधी कह दें कि मैं पाकिस्तान के निर्माण के लिए राजी हूँ, मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि एक चौथाई भारत जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद्दी सूबा, बंगाल और असम शामिल हैं, अपनी मौजूदा सीमाओं के साथ पाकिस्तान नामक नए राज्य का निर्माण करें।

यह भी संभव है कि आवादी की जदला बदली करनी पड़े लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि लोग स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हों। सीमाओं में निस्संदेह कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें संभव हैं लेकिन पहले यह मानना जरूरी है कि इन प्रांतों की वर्तमान सीमाएं भावी पाकिस्तान की सीमाएं होंगी। पाकिस्तान की हमारी सरकार संभवतः प्रांतों की स्वायत्तता पर आधारित एक संघीय सरकार होगी।

जहां तक मेरी बात है मुझे अंगरेज सरकार की ईमानदारी में कोई संदेह नहीं है लेकिन मुझे उन लोगों की ईमानदारी में पूरा शक है जो यह उम्मीद लगाए हैं कि भारत के मुगलमानों को पूरा पाकिस्तान दिए बिना ही कोई समझौता हो सकता है।

अतः म अग्रेल 1946 म मुस्लिम विधायकी के सम्मेलन मे निम्न शब्दो म पाकिस्तान की व्याख्या की गई

उत्तर पूव म बंगाल और असम का इलाका तथा उत्तर पश्चिम म पंजाब, सरहदी सूबा, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके मुसलमानो क बहुमत स भरे हैं जिन्हें हम 'पाकिस्तान जोन' कह सकत हैं। इन्हें मिलाकर एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न राज्य बना दिया जाए।

पाकिस्तान का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जातियाँ हैं। सारे भारत म और भारत के हर इलाके म हिंदू और मुसलमान भले ही मिलजुलकर रहत हों, भले ही हिंदू और मुसलमान एक ही परिवार क सदस्य हों लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार वे दो अलग अलग जातियाँ क लागू हैं। स्पष्ट है कि धर्म को जातीयता का आधार बनाने की यह कोशिश (और धर्म स संबंधित समान संस्कृति को भी आधार बनाने की कोशिश) जातीयता की प्रत्यक्ष ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या एवं अनुभव के विपरीत है। यह ठीक वैसे ही है जैसे यूरोप म रहने वाले कथालिकों को एक अलग जाति मान लिया जाए। और वंशक यदि इस तक का और बढ़ाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि केवल मुसलमान होंगे स यदि जातीयता की परिभाषा निधारित होती है तो उत्तरी अफ्रीका से लेकर भारत तक के सभी मुसलमानों की एक जाति है और पाकिस्तान के सिद्धांत की अंतिम पूर्णाहुति सब इस्लामवाद (पान इस्लामिज्म) में होगी।

माक्स ने जाति या राष्ट्र की व्याख्या किस प्रकार की है इसका सारांश स्टालिन ने अपनी पुस्तक 'माक्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक प्रश्न' में प्रस्तुत किया है। जाति हम उसे कहेंगे जिसका ऐतिहासिक विकास इस प्रकार हुआ हो कि उसमें भाषा प्रदेश, आर्थिक जीवन तथा मनोवैज्ञानिक गठन की एकता हो। इसमें स्टालिन ने यह महत्वपूर्ण बात और जोड़ दी थी कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ऊपर बताई गई विशिष्टताओं में से कोई भी विशिष्टता जाति की व्याख्या करने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है। बल्कि अगर इन विशिष्टताओं में से एक भी अनुपस्थित है तो जाति जाति नहीं रहगी।

इस जाच-पड़ताल से यह जाहिर है कि भारत के मुसलमानों को एक 'जाति' नहीं माना जा सकता। उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके इलाके अलग हैं और उनकी संस्कृतियाँ अलग हैं। नस्ल की दृष्टि से उनमें अनेक तरह की विभिन्नताएँ हैं। एक पठान और एक बंगाली मुसलमान के बीच जो एकमात्र समानता है वह धर्म की या पुरानी संस्कृति के कुछ अवशेषों की है। लेकिन जाति कहाना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। पुराने सभी साम्राज्य में रहने वाले यहूदियों के अलग अलग इलाके थे और उनकी अलग अलग

भापाएँ थी लेकिन स्टालिन ने उनको एक अलग जाति मानने से इकार किया और अपने पक्ष में उहोने यह दलील दी

उनके जीवन में यदि किसी तरह की समानता है तो वह यह है कि उनका धर्म एक है, उनकी जड़ एक है और उनमें जातीय स्वरूप के कुछ अवशेष पाए जाते हैं। इन सब बातों में कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या कोई गंभीरतापूर्वक यह कह सकता है कि जिस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में ये यूहूदी रहते हैं उससे ज्यादा ये मृत धार्मिक रीतियाँ और नष्ट हो रहे मनोवैज्ञानिक अवशेष उनके भाग्य का निणय करेंगे ?

यहाँ जो प्रश्न है वह केवल जाति की औपचारिक परिभाषा का प्रश्न नहीं है। यदि यह केवल शब्दावली देने का प्रश्न होता तो इसपर बहस करना बकार था लेकिन यदि जाति का आधार धर्म को एक बार मान लिया जाएगा तो उसके राजनीतिक परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। चूँकि ठोस वास्तविकता में जाति केवल एक निश्चित इलाके में ही रह सकती है और चूँकि यह सिद्धांत धरती से नहीं उपजा है बल्कि इसे राजनीतिज्ञों ने तैयार किया है इसलिए इस कल्पित 'जाति' के लिए एक इलाका नकली तौर पर तैयार कर लेने की भी जरूरत पड़ती जाती है। जैसे ही हम पाकिस्तान के भौगोलिक स्वरूप की जांच करते हैं, इस सिद्धांत की कमजोरी का पता चल जाता है।

जिन छः प्रांतों को 'उनकी वर्तमान सीमाओं के साथ' मिलाकर पाकिस्तान के निर्माण की बात कही गई थी उनकी कुल आबादी 10 करोड़ 70 लाख है। इनमें से मुसलमानों की संख्या 5 करोड़ 90 लाख अर्थात् 55 प्रतिशत और गैरमुसलमानों की संख्या 4 करोड़ 80 लाख अर्थात् 45 प्रतिशत है। इस प्रकार इस इस्लामी राज्य की लगभग आधी आबादी गैरमुसलमानों की होगी और लगभग 3 करोड़ 50 लाख अर्थात् भारत के कुल मुसलमानों का तकरीबन 40 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के बाहर रह जाता है। इससे यह पता चलता है कि भारत की मिलीजुली हिंदू मुस्लिम आबादी की सांप्रदायिक समस्या को जबरन इलाके बांटकर हल करने की कोई कोशिश सफल नहीं हो सकती। पूर्वी पंजाब मुख्यतया गैरमुस्लिम क्षेत्र है। सिक्खों ने एलान किया है कि यदि पंजाब को किसी भी मुस्लिम राज्य में मिलाया गया तो वे उसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल भी गैरमुस्लिम इलाका है। असम में गैरमुस्लिम लोगों का बहुमत है और सरहद्दी सूबों में मुसलमानों का काफी बड़ी संख्या में है जहाँ कांग्रेस का भी मजबूत गढ़ है।

इन इलाकों के राजनीतिक अलगाव के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उनका औचित्य अभी ठहराया जा सकता है जब यह साबित कर दिया जाए कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का निर्णायक बहुमत इस तरह के अलगाव को पसंद कर रहा है। यहाँ बुनियादी मसला यह नहीं है कि गुलाम जनता स्वीकृत और मान्य राष्ट्रीय दावों की मांग कर रही

है। यह दावा उम तरह का नहीं है जैसाकि भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन से अपन को मुक्त करने के लिए किया है। यहाँ जिस दावे पर विचार किया जा रहा है वह बहुत ही विवादास्पद है। पाकिस्तान बनाने की मांग पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने उठाई है और उसे अत्यंत सांप्रदायिक शत्रुतापूर्ण स्थिति के बीच राजनीति में प्रवेश करा दिया है। इस दावे के विवादास्पद स्वरूप को देखते हुए और इन इलाकों में आबादी के अत्यंत विभाजित स्वरूप के कारण यह उचित होगा कि सबद्व लोको की आकाक्षाओं को भलीभाँति जाँचा जाए और इसके लिए जनमत संग्रह कराकर या जनतांत्रिक सलाह-मशविरे के ऐसे ही किसी उपाय के जरिए उनकी आकाक्षाओं को साधित किया जाए। यह प्रस्ताव (मुस्लिम बहुमतवाले इलाकों में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव) सबसे पहले 1942 में सी० राजगोपालाचारी ने और 1944 में गांधी जिन्ना बातचीत में गांधी ने पेश किया था। लेकिन इस प्रस्ताव का मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने नामजूर कर दिया। उन्होंने यह कहा कि पूरी तरह मुस्लिम बहुमतवाले जिलों को मिलाकर यदि पाकिस्तान की रचना की जाती है तो इससे एक 'नकली' 'विकृत और बजर पाकिस्तान' की रचना होगी। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि समूची जनता के बीच जनमत संग्रह कराने का अर्थ यह होगा कि मुसलमानों के रूप में मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका अर्थ यह होगा कि इस तरह का कोई भी जनमत संग्रह मुसलमानों की 55 प्रतिशत आबादी के बीच ही सीमित रहेगा जिससे यह नतीजा निकलेगा कि आबादी का 28 प्रतिशत हिस्सा समूची जनता के लिए इस समस्या का समाधान कर देगा। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति, जिसका जनतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास है, इस तरह के प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता। जनता की आकाक्षाओं को उपेक्षा करके और जनतांत्रिक समाधानों का विरोध करके अल्टीमेटम के रूप में सरकारी तौर पर पाकिस्तान की स्थापना की मांग जिस प्रकार आई है उससे यह व्यवहार में प्रतिश्रियावादी जनतंत्रविरोधी और विध्वंसक मांग हो गई है जो साम्राज्यवादियों के हाथ का खिलौना है। लेकिन इन तमाम बातों से हम इस सच्चाई की ओर से जाग नहीं मूढ़ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की मांग के पीछे जातीयता का सच्चा सवाल भी छिपा हुआ था।

इस प्रश्न का अंतिम समाधान जनतांत्रिक सिद्धांतों पर चलकर ही हो सकता है। आत्मनिर्णय का जनतांत्रिक सिद्धांत यह मानता है कि जिस इलाके में स्पष्ट रूप से आत्मनिर्णय की जातीय मांग उठ रही हो अर्थात् जिस इलाके में अधिकांश लोग अपने विशिष्ट जातीय स्वरूप एवं संस्कृति के आधार पर यह मांग कर रहे हैं कि उनकी अलग राजनीतिक संस्थाएँ हानी चाहिए यदि भौगोलिक तथा जातीय दृष्टि में यह बात सम्भव हो तो उस इलाके में निवासियों को अपनी अलग राजनीतिक संस्थाएँ कायम करने का पूरा अधिकार है। यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनपर कोई राजनीतिक समस्या थपी जाएगी तो यह किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। भारत की बहुजातीय समस्या का समाधान का मात्र कारण उराना रही है कि आत्मनिर्णय व इस जनतांत्रिक सिद्धांत

का निरंतर इस्तेमाल किया जाए। इसी सिद्धांत पर चलकर सभी जातियों के स्वेच्छा-पूर्वक संगठित होने के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। इस तरह का समाधान हाल के दिनों में बहुजातीय सोवियत संघ में और चीनी जनता के जनतंत्र में किया गया है।

इस सिद्धांत को मायता देने का अर्थ यह होगा कि भारतीय जनता का प्रत्येक ऐसा वर्ग जिसके रहने का एक मिलाजुला प्रदेश है, जिसकी एक समान ऐतिहासिक परंपरा है, जिसकी एक समान भाषा, संस्कृति, मानसिक गठन और समान आर्थिक जीवन है, उसे इस बात का अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र भारत में एक स्पष्ट जाति के रूप में जीवन बिताए और यदि चाहे तो स्वतंत्र भारतीय संघ या राज्य संघ के अंदर एक स्वायत्त शासित राज्य के रूप में रहे (जिसे संघ से अलग होने का अधिकार भी होगा)।

इस प्रकार आगामी कल का स्वतंत्र भारत पठान, पंजाबी सिंधी हिंदुस्तानी, राजस्थानी गुजराती, बंगाली, असमी बिहारी, उडिया, आंध्र, तमिल, केरलवासी, मराठा आदि विभिन्न जातियों के स्वायत्तशासी राज्यों के संघ या फेडरेशन का रूप धारण कर सकता है। इस तरह जा नए राज्य बनेंगे उनमें जल्पसंख्यक जातियों के जो लोग इधर उधर बिखरे रह जाएंगे उनकी संस्कृति, भाषा तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों को कानून के जरिए संरक्षण मिलेगा, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। जाति, नस्ल या समुदाय पर आधारित हर तरह की अयोग्यताओं, विशेषाधिकारों और भेदभावों को कानून के जरिए समाप्त कर दिया जाएगा और इनका उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी।

वस्तुतः इस तरह के जनतांत्रिक समाधान से उन जनतांत्रिक सिद्धांतों की पूर्ति ही होगी जिसकी 1931 में कांग्रेस ने अधिकारों के घोषणापत्र में अभिव्यक्ति की थी और जिसे 1946 में कांग्रेस ने अपने चुनाव कार्यक्रम में दोहराया था

कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए चाहे वह पुरुष हो या महिला, समान अधिकारों और अवसरों के पक्ष में है। कांग्रेस ने हमेशा सभी समुदायों और धार्मिक संगठनों के बीच एकता के लिए तथा इनके बीच सहिष्णुता एवं सदभाव कायम करने का समर्थन किया है। कांग्रेस इस पक्ष में है कि देश की समूची आबादी को अपनी इच्छानुसार और अपनी योग्यता के अनुरूप उन्नति करने और विकसित होने के पूरा अवसर प्राप्त हो। वह इस पक्ष में भी है कि देश की सीमा के अंदर जितने भी समूह हैं और जितने भी इलाके हैं उन्हें इस बात की आजादी हासिल हो कि वे व्यापक ढाँचे के अंदर अपनी संस्कृति और जीवन का विकास कर सकें और इस उद्देश्य के लिए जहां तक संभव हो प्रादेशिक

इनाको या प्राता को भाषा और संस्कृति के आधार पर गठित किया जाए। कांग्रेस ने सदा इस बात का समर्थन किया है कि सामाजिक दमन और अत्याय के शिकार लोगों को उनके अधिकार मिले और समानता के मांग में उन्हें जिन अवरोधों का सामना करना पड़ता है वे दूर किए जाए।

कांग्रेस ने एक स्वतंत्र जनतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए मध्यम किया है। ऐसे राज्य में सभी नागरिकों को संविधान के तहत मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कांग्रेस का विचार है कि यहाँ का संविधान एक मधीय संविधान होना चाहिए जिसमें इसकी इकाइयों को स्वायत्तता प्राप्त हो तथा इसकी विधान संस्थाएँ बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संस्था हों। भारत का राज्यसंघ ऐसा होना चाहिए जिसमें इसके विभिन्न भाग स्वेच्छापूर्वक एकजुट हो सकें। राज्यसंघ में शामिल होने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की दृष्टि से ऐसी मधीय जनता की समान और बुनियादी न्यूनतम सूची होनी चाहिए जो सभी इकाइयों पर लागू हो सकें तथा इसके अलावा एक वैकल्पिक सूची होनी चाहिए जिन्हें यदि चाहें तो इस तरह की इकाइयाँ स्वीकार कर सकें।

लेकिन भविष्य के प्रगतिशील विकास के लिए जहाँ कांग्रेस ने भारत की एकता को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और इसके लिए अपनी चिंता जाहिर की है वही उसने आज तक राष्ट्रीय जात्मनिष्ठ के सिद्धांत को पूरी तरह लागू होने का विरोध किया है। सितंबर 1945 में कांग्रेस का पूना में अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस की स्थिति को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया गया

कांग्रेस इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सकती जो किसी संघटक राज्य या क्षेत्रीय इकाई को भारतीय संघ या राज्यसंघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्रदान करके भारत का विघटन करना चाहता है। जहाँ कांग्रेस काय समिति ने 1942 में घोषित किया था, कांग्रेस भारत की आजादी और एकता के लिए कृतसंकल्प है और आज के युग में जबकि लोग का विभाग अनिवाय रूप से और बड़े राज्यसंघों के अर्थों में सांचे का आदी हो गया है, इस एकता में किसी भी तरह की फूट सभी सबद लोग के लिए हानिकार और दुखदायी होगी। फिर भी समिति यह घोषणा भी करती है कि कांग्रेस किसी क्षेत्रीय इकाई की जनता का उसकी पापित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संघ में बने रहने पर उन्हें बाध्य करने की बात नहीं सोच सकती है।

हम देख सकते हैं कि इस प्रस्ताव में दो भागों में कुछ अंतर्विरोध है। प्रस्ताव में अलग होने के अधिकार का मान्यता देने से इनकार भी किया गया है और इस बात से भी इनकार किया

गया है कि सघ म बने रहने के लिए वह किसी इकाई पर दबाव डालेगी ।

अलग होने के अधिकार के साथ साथ आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने का यह अर्थ नहीं होता कि अलग हो जाना सही है । इसके विपरीत भारत के जनतांत्रिक विकास के हित में यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की एकता बनी रहे । भारत की एकता खासतौर से इसलिए भी जरूरी है ताकि उसके विभिन्न भाग परस्पर सहयोग के जरिए तेजी से प्रगति कर सकें तथा समूचे भारत की उन्नति के लिए पर्याप्त आर्थिक योजना बनाई जा सके, उसके अनुसार पूरे देश का विकास किया जा सके और जनता का सामाजिक स्तर ऊपर उठाया जा सक । लेकिन यह एकता स्वेच्छा से ही हा सकती है ।

यह नीति सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942 के एक प्रस्ताव में पेश की थी जिसमें भारतीय जनता के बहुजातीय स्वरूप से पैदा होने वाली नई नई समस्याओं पर पहली बार गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था । अभी हाल ही में 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें भी इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया था

सविधान सभा के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो जबरदस्त मतभेद है उसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ईमानदारी से लागू करके ही दूर किया जा सकता है ।

हमारा यह सुझाव है कि अस्थाई सरकार को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वह प्रत्येक जनता के प्राकृतिक प्राचीन निवास स्थान के आधार पर सीमाएं पुनर्निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन करे ताकि फिर से सीमांकित प्रांत जहां तक संभव हो सके भाषा और संस्कृति की दृष्टि से एकरूप राष्ट्रीय इकाई बन सकें । उदाहरण के लिए सिंध, पठानलैंड, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब आदि ।<sup>6</sup> इस तरह की प्रत्येक इकाई की जनता के पास आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए । अर्थात् उसे यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से यह तय कर सके कि वह भारतीय सघ में शामिल होना चाहता है या अलग प्रभुसत्तासंपन्न राज्य का गठन करना चाहता है ।

इसलिए सविधान सभा का चुनाव इस मौलिक अधिकार को मान्यता दिए जाने पर आधारित होना चाहिए और चुनावों के दौरान अलग होने का या साथ • रहने का प्रश्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता के सामने रखा जाना चाहिए । प्रत्येक जातीय इकाई से निर्वाचित प्रतिनिधियों को बहुमत के आधार पर यह निर्णय लेना होगा कि वे एक भारतीय सघ की रचना के लिए अखिल भारतीय सविधान सभा में शामिल होना पसंद करेंगे या इससे अलग रहेंगे और स्वयं

एक पृथक प्रभुसत्तासंपन्न राज्य की स्थापना करेगा या दूसरे भारतीय सघ में शामिल होगा।

कम्युनिस्ट पार्टी इस पक्ष में है कि प्रभुसत्तासंपन्न इकाइयों का एक स्वतंत्र स्वैच्छिक जनवादी भारतीय सघ कायम हो। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि भारत की जनता यदि एक सघ में और समान भाईचारे की नीयत से एक साथ रहे, मिलजुलकर स्वतंत्रता की रक्षा करे और सबके सहयोग से गरीबी की समस्याओं का हल ढूँढ़े तो यही उसके सर्वाधिक हित में होगा। जैसाकि ऊपर बताया गया है आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अमल में लाकर ही भारत की एकता बनाई रखी जा सकती है।

यदि इस दृष्टिकोण का पालन करे तो हम इन समस्याओं का सबसे ज्यादा उपयुक्त ढंग से समाधान ढूँढ़ सकते हैं।

## पाद टिप्पणियाँ

1. बी० डी० यमु की पुस्तक 'कत्तालिडेशन आफ दि क्रिश्चियन पावर इन इंडिया' में उद्धृत पृष्ठ 74
2. सर जान स्ट्रुथी ने अपनी पुस्तक के परवर्ती संस्करण में इस साधारण वक्तव्य को भी सन्तोषित करने का प्रयास किया लेकिन उसमें उन्हें मामूली सफलता मिली। वक्तव्य के नए रूप में कहा गया था  
यह पुराना सूत्र वाक्य 'फूट डालो और राज करो' भारत में हमारी सरकार की नीति और व्यवहार का जितना विरुद्ध है शायद ही कोई दूसरी चीज इतनी खिलाफ हो। हमारी मुद्रासारी सभ्यता का यह अत्यावश्यक कर्तव्य रहा है कि सभी वर्गों के बीच शांति बनाए रखने को मान्यता दी जाए लेकिन इसकी वजह से हम इस तथ्य से बांध नही मूढ़ लेनी चाहिए कि इन विरोधी तत्वों का एकसाथ अस्तित्व बना रहना ही भारत में हमारी राजनीतिक स्थिति का सबसे मजबूत भूदा है। मुसलमानों के बेहतर वर्गों को हम अपने लिए कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत मानते हैं। वे सभ्यता की दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़े हैं लेकिन उनमें काफी उत्साह है उनके राजनीतिक हित हमारे ही हितों जैसे हैं और वे किसी भी स्थिति में हिंदुओं के बजाय हमारे शासन को ज्यादा पसंद करेंगे। (सर जान स्ट्रुथी इंडिया 1894 पृष्ठ 241)  
इन दो विवरणों, वारे सत्य और कूटनीतिक भूल सुधार की यदि तुलना करें तो हमें साम्राज्यवादी तत्वों का विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी। यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अपने वक्तव्यों को थोड़ा अधिक कूटनीतिक रूप देकर तथा आह्वारपूर्ण बनाकर मूल नीति को जस का तसा रहने दिया जाता है।
3. यह ध्यान देने का बात है कि भारतीय ईशार्ड नेताओं ने पृथक निर्वाचनमंडल प्रणाली का जबरदस्त विरोध किया है। यह प्रणाली सरकार द्वारा अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिए, न कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन पर थोरी गई है। इसलिए 1938 में आल इंडिया क्रिश्चियन काँग्रेस के अधिवेशन में अपने भाषण में कहा  
पृथक निर्वाचनमंडल के प्रति हमारा सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इन प्रणाली के जरिए हमें अन्य मुसलमानों के साथ परिचित एक कायम करने से राका जाता है। अपने पुराने नेताओं के



जिनमें से कुछ हम छोड़कर जा चुके हैं बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एक समुदाय के रूप में हमने हमारा विशेष निर्वाचनमंडला का विरोध किया है क्योंकि य हमारे ऊपर हमारी इच्छा के विरुद्ध ताद दिए गए हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचनमंडला की मौजूदा प्रणाली ने भारत को एक ऐसे मकान के रूप में बदल दिया है जिसने अपने ही खिलाफ अपना बटवारा कर दिया हो। मेरे पूर्ववर्तियों ने बार बार बताया है कि पयक निर्वाचनमंडल की इस प्रणाली को स्वीकार करके हमारे समुदाय के लोगों ने कितना नुकसान उठाया है। मेरी राय है कि हम सभी समुदायों के नेताओं के पास जाकर उस बार बार यह अनुरोध करना चाहिए कि व उचित समय आते ही देश के साफ मुथरे नाम पर लग इस घाबे को मिटान के लिए मिलजुलकर अपनी पूरी तानत लगा दें। (आल इंडिया क्रिश्चियन वाफेंस मंत्रालय के अध्यक्ष डाक्टर एच० सी० मुखर्जी का बयान दिसंबर 1938)

- 4 यह दलील देना बिलकुल गलत है कि मुसलमानों के इस विशाल प्रतिनिधित्व के पीछे एक अल्पसंख्यक जाति को संरक्षण देने की चिंता निहित है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल विधानसभा की सीटों का जिस तरह बटवारा किया गया उससे इस दलील का खोखलापन पूरी तरह साबित हो जाता है। देश की मौजूदा सीमाओं के अंतर्गत बंगाल में मुसलमानों का बहुमत है। फिर भी इनको ही सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमानों की आबादी वहां 55 प्रतिशत है और उन्हीं सदन में 117 सीटें प्राप्त हैं जबकि हिंदुओं की आबादी 43 प्रतिशत है और जो सामान्य सीटें उनके लिए निर्धारित हैं उनकी संख्या 78 है। (इनमें से 30 सीटें अनुसूचित जातियों अर्थात् दलितों के लोगों के लिए सुरक्षित हैं और सामान्य सीटों के नाम पर केवल 48 सीटें बच रहती हैं।) उन्हीं द्वारा निर्धारित आधार पर किए गए बटवारे के अनुसार हिंदुओं को 78 और मुसलमानों को 99 सीटें मिलती हैं। इसलिए यह कहना कि ज्यादा प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए किया गया है बिलकुल बेकवास है।

यह उदाहरण उस दोगपन तक की भी घड़िया उठा देता है (जिसे विस्तार से साइमन कमिशन की रिपोर्ट में और माटेयू चम्सफोर्ड रिपोर्ट में बताया गया है) जो सांप्रदायिक निर्वाचनमंडल का औचित्य ठहराने के लिए यह बताने की कोशिश करता है कि इसकी प्रेरणा 1916 में लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग संधि की सिफारिशों से मिली थी। लखनऊ संधि ने साठ मिनटों और साठ मोर्चों द्वारा शुरू किए गए निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक भेदभाव को अवश्यभावी मानकर स्वीकार कर लिया और यह उसने गंभीर भूल की लेकिन किसी भी रूप में उसने यह प्रस्ताव सामने रखा कि निर्वाचनमंडल के बारे में फसला ऐसा होना चाहिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के अनुकूल हो ताकि जिन प्रांतों में मुसलमानों का अल्पमत में है वहां उन्हें थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व करने की गुंजाइश हो और बंगाल जैसे प्रांतों में जहां इसका बहुमत है इसे थोड़ा कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन साम्राज्यवादी अधिकारियों ने यह कहने में कोई चूक नहीं की कि वे लखनऊ संधि से ही प्रेरणा लेकर यह विभाजन कर रहे हैं हालांकि उन्होंने हर मामले में जहाँ मुसलमान अल्पमत में हैं या बहुमत में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर दिया और इस प्रकार यह बता दिया कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण से उनका कोई वास्ता नहीं है व विशुद्ध रूप से नस्लवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं। वे मान माने दंग से पक्षपात करके आबादी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और जनता में फूट डालना चाहते हैं।

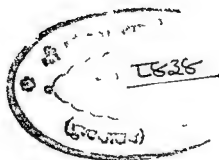
- 5 1931 में दया के बारे में नियुक्त कानपुर रायटम इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे छिपे तौर पर सरकारी अधिकारियों का कितना हाथ था हर वर्ग के गवाहों ने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि दंगों की विभिन्न धारणाओं से निबटने में पुलिस ने निष्प्रयत्ना और उदासीनता दिखाई। इन गवाहों में घग्गेज व्यापारी हर विचारधारा के हिंदू और मुसलमान सैनिक अधिकारी जयर दंडिया चेंबर आफ कामर्स के सचिव इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रतिनिधि और भारतीय अधिकारी भी शामिल हैं।

गवाहों व जयानों में जितनी सम्मति है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे दिमाग में अब यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि दंगे के शुरू के तीन दिनों के दौरान पुलिस ने अपने कर्तव्य का परिचय नहीं दिया जबकि उससे ऐसा आशा नहीं की जाती थी। जनक गवाहों ने ऐसी घटनाओं के उदाहरण दिए हैं जिनमें पुलिस की बाघों के सामने गंभीर अपराध हो रहे थे और वह चुपचाप खड़ी थी। हम कह गवाहों ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी अपनी गवाही में यह बताया कि पुलिस की निष्क्रियता और उदासीनता के बारे में उस समय शिकायतें दर्ज कराई गईं लेकिन ख़द की बात है कि इन शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

(कापुर रायट्स रिपोर्ट 1931 पृष्ठ 39)

- 6 राष्ट्रीय इकाइयों के निम्नांकित नामों का महा उल्लेख किया जा रहा है जो ज़ार दिए गए सभा के अनुसार भारतीय रिपब्लिक के समाप्त होने पर अस्तित्व में आ जाएंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सिंध, बंजिस्तान, पठानखंड, कश्मीर, पंजाब, हिंदुस्तान, बिहार, असम, बंगाल और उड़ीसा।

४०६  
इतिहास



खण्ड पाच  
साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय मुक्ति



## साविधानिक रणक्षेत्र

यह प्रस्तावित करना कि ग्रेट ब्रिटन का अपने उपनिवेशों पर से सभी अधिकार स्वच्छापूर्वक छोड़ देना चाहिए और उपनिवेशों पर ही यह काम छोड़ देना चाहिए कि वे अपना 'यायाधीश' चुनें, अपने कानून अमल में लाए और युद्ध का या शांति का, जो भी रास्ता उचित समझें अपनाएं, एक ऐसा उपाय प्रस्तावित करना है जैसा दुनिया के किसी भी देश में तो देखने में आया है और न देखने में आएगा। कभी भी किसी देश ने स्वच्छापूर्वक किसी उपनिवेश पर से अपना प्रभुत्व नहीं समाप्त किया है।—एडम स्मिथ 'वेल्थ ऑफ नेशंस', 1776, खंड 4, अध्याय 7।

एक ऐसे प्रकाशन में जिसकी दिलचस्पी वर्ष बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है यानी 'रिफॉर्मस इयर बुक 1906' में 1905 के रूस के बारे में एक पृष्ठ सामग्री प्रकाशित है। उस महत्वपूर्ण और घटनाओं से भर वर्ष के बारे में जो 30 पक्तियों की सामग्री प्रकाशित है उनमें से 23 पक्तियों में तो केवल दूमा (संसद), उसकी स्थापना, उसका गठन, निर्वाचक आधार, उसके अधिकार और सभापनाओं के बारे में ही लिखा गया है। फादर गोयन का एक छाटा सा प्रसंग है। शेष पक्तियां में हम बताया गया है कि राष्ट्रीय संकट और पुलिस की अत्यधिक बखर्ती के कारण इस वर्ष मजदूर संगठना का तजी से विकास नहीं हो सका। रूस के प्रत्येक हिस्से में दंगे और विद्रोह की घटनाएं हुईं। समकालीन प्रबुद्ध पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में 1905 की रूसी जाति का यही महत्व था।

इसी प्रकार ब्रिटिश विचारकों द्वारा भारतीय समस्याओं के बारे में जो माट माट ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें से 90 प्रतिशत ग्रंथों की यही राय है कि 1914-18 के विस्फोट के

बाद के 30 वर्षों में 'भारतीय समस्या' मुख्यतया ऐसे क्रमिक 'संविधानों' की समस्या रही है जो समय-समय पर साम्राज्यवाद ने भारत की जनता को दिए। पण्डितजी ने, सांविधानिक समस्या का वातावरण दिखलाने के लिए इस बात की धुंधली भी झलक दी गई है कि 'उग्रवादियों' के प्रभाव में आकर जनता में 'वेचनी' पैदा हो गई थी और इसकी जवाबदारी अभिव्यक्ति होने लगी थी। इसके साथ ही गांधी के रहस्यमय व्यक्तित्व के भेद-बोझ बहुत जिक्र है। तेजी से तैयार हो रही भारतीय क्रांति की सभी गूढ़तम राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ ऐसे सांविधानिक पांडित्य प्रदर्शनो के बजरे रेगिस्तान में दफना दी गई हैं जिनके अकथनीय उच्चारण ने ब्रिटेन के राजनीतिक लोगो के अंदर नफरत पैदा कर दी है और बड़े प्रभावकारी ढंग से भारतीय मामलों में उनकी दिलचस्पी को समाप्त कर दिया है। समूची मानव जाति के आंदोलनरत इस पांचवें हिस्से की ज्वलंत सचाइयों को ऊपरी तौर पर विश्वसनीय लगने वाले 'नए संविधान' के धुंधले शीशे से देखा जा रहा है और इस 'नए संविधान' को ही केंद्रबिंदु माना जा रहा है।

लेस्सले ने एक बार कहा था कि किसी समाज का सही संविधान उस समाज का वास्तविक सत्ता संचय है। भारतीय 'संविधान' के संदर्भ में यह बात जितनी स्पष्ट है उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। साम्राज्यवाद ने भारत के लिए जो विभिन्न 'संविधान' या सांविधानिक योजनाएँ पेश की हैं, वे भारतीय समस्या के न तो समाधान हैं और न समाधान के प्रयास। वे महज साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष, एक के बाद एक गई अवस्थाओं और संघर्ष स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि वे संघर्ष के मुख्य चरण भी नहीं हैं। यथार्थ तो संघर्ष है संविधान एक भ्रम है।

## 1 साम्राज्यवाद और स्वशासन

साम्राज्यवाद सम्यक सरकारी खेमों से कभी-कभी यह बात कही जाती है कि भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित करना है। भारत पर शासन करने वाले प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों की यह धारणा नहीं थी। राष्ट्रीय भुक्ति आंदोलन की शक्ति ने जब तक स्वशासन के मसले का राजनीतिक मंच पर ठेलकर सामन नहीं ला दिया तब तक इस तरह के बिकाम की किसी भी संभावना को ब्रिटन के शासकों ने बड़े अपमानजनक ढंग से नामजूर किया। कजरबेटिव नेताओं ने ही नहीं बल्कि ब्रिटिश प्रभुत्व के पुरातन काल से ही लिबरल नेताओं ने भी इसी दृष्टिकोण से अपनी सहमति प्रकट की। मैकाले ने 1833 में कहा था

भारत में आपके पास प्रतिनिधि संस्थाएँ नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय राजनीति के प्रश्न पर जिन अमध्य चिंतकों ने अपना सुझाव पेश किए उनमें से एक न भी फिक्कल भारत में इस तरह की संस्थाओं की संभावना नहीं व्यक्त की बल्कि वह विचारों में जितना भी जनतांत्रिक क्या न रहा हो।  
(टी०बी० मैकाले का हाउस आफ कॉमंस में भाषण, 10 जुलाई 1833)

दार्शनिक उदारतावाद के सवमाय पैगवर और प्रतिनिधि सस्याभा के घोर हिमायती जान स्टुअर्ट मिल ने भी इस तरह की मस्याओं का नकारन मे कम स्पष्टता का परिचय नहीं दिया। अपने उसी भाषण म मैकाले ने मिल के विचारा को उद्धृत किया

उन्होंने (मिल ने) जोरदार शब्दो म, मैं समझता हू कि काफी जोरदार शब्दो मे, विशुद्ध जनतन्त्र के पक्ष म लिखा है—लकिन जब पिछने वष की समिति के सामने उनसे पूछा गया कि क्या व भारत मे प्रतिनिधि सरकार की स्थापना व्यावहारिक मानत है तो उनका साफ जवाब था कि इसका सवान ही पैदा नहीं होता।  
(वही)

म्लैडस्टोन और ब्राइट के बीच की बातचीत से भारतीय समस्या के सदभ म 19वीं सदी के उदारतावाद के दिवालियेपन का पता चलता है

आज शाम भारत के प्रश्न पर ब्राइट के माथ मेरी काफी लंबी बातचीत हुई वह मानत है कि जनता को जनता द्वारा शासित करना अर्थात् भारत को विशुद्ध संसदीय सरकार द्वारा शासित करना कितना कठिन काम है।

(म्लैडस्टोन का पत्र सर जेम्स ग्राहम के नाम, 23 अप्रैल 1858 'लाइफ ऐंड लेटर्स आफ सर जेम्स ग्राहम', खंड 2, पृष्ठ 340)

लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं है कि 19वीं सदी के उदारतावाद के इन नताओं म से किसी ने भी (ब्राइट ने भारत म कुप्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करके महत्वपूर्ण काय किया) इस समाधान की संभावना नहीं व्यक्त की कि भारतीय जनता अपना शासन स्वयं कर सकती है।

लाड क्रोमर ने प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व बड़े साफ शब्दो म साम्राज्यवाद का पक्ष प्रस्तुत किया था

आज जो हालात है उनम भारत मे स्वशासी सरकार की बात करना वैसे ही है जैसे संयुक्त यूरोप मे स्वशासन के लिए दलील दी जाए ये बातें महज भोड़ी ही नहीं हैं, ये महज अव्यावहारिक ही नहीं हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की बातों को तरजीह देना संभ्यता के विरुद्ध अपराध है और खासतौर से यह भारत के उन करोड़ों मूलक लोगों के प्रति अपराध है जिनके हितों को देखना हमारी जिम्मेदारी है। (लाड क्रोमर, ऐंशेट ऐंड माइन इपीरियलिज्म, 1910 पृष्ठ 123)

उसी अवधि म उदारवादी नेता लाड मोले ने भी इस विषय पर अपनी बड़ी निश्चित राय

दी। लाड मोर्ले न मोर्ले मिटो सुधार के नाम में विख्यात साविधानिक सुधारों को पेश करते हुए कहा था कि इन्हें किसी भी अर्थ में वह नहीं समझना चाहिए कि इनमें समदीय संस्थाओं का भाग प्रशस्त किया जा रहा है।

यदि ऐसा कहा जाना हो कि इन सुधारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारत में समदीय प्रणाली का रास्ता खुला तो कम से कम मुझे इन सुधारों से कोई सरोकार नहीं है। (हाउस आफ लाड्स में लाड मोर्ले का भाषण 17 दिसंबर 1908)

भारत के संघ में 1917 तक निरंतर साम्राज्यवाद का यही दृष्टिकोण था। यदि 1917 के बाद साम्राज्यवादियों के कथन में अचानक कोई परिवर्तन आया है और मध्यता के विरुद्ध अपराध' को विधिवत रूप से घोषित लक्ष्य बना लिया गया है तो जाहिर है कि साम्राज्यवादी नीति में या घोषित नीति में जो अचानक रूपांतरण हुआ उसका कारण वतई यह नहीं था कि साम्राज्यवादियों के मूल इरादों में यह बात निहित थी बल्कि इनका कारण यह था कि बाह्य घटनाओं का जबरदस्त दबाव पड़ा था।

वास्तविक तब्दीली कहा तक हुई है? या 1917 के बाद साम्राज्यवादी नीति या दृष्टिकोण में ऊपरी तौर पर दिखाई पड़ने वाली तब्दीली किस सीमा तक परिस्थितियों के दबाव से अपनाई गई रणनीति है जिसका दुनियादी उद्देश्य और भी जबरदस्त तरीक़ों से ब्रिटिश प्रभुत्व का बनाए रखना है न कि उस समाप्त करना? आज इन बातों की जांच करना बहुत जरूरी है।

## 2 1917 से पूर्व की सुधारनीति

युद्ध शुरू होने तक साम्राज्यवाद का घोषित लक्ष्य यह था कि साम्राज्यवादी प्रशासनिक तंत्र के घेरे में निरंतर अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। किसी भी साम्राज्यवादी व्यवस्था के सफल संचालन के लिए इस तरह की नीति अनिवार्य है (भारत में सरकारी नौकरियों में लग लोंगों की संख्या 15 लाख है और व्यावहारिक रूप से यह असंभव है कि इन 15 लाख लोगों में अधिकांश अंगरेज हों)। इस लक्ष्य की निरंतर घोषणा की जाती रही है और पिछले 1 सौ वर्षों से भी अधिक समय से इसका पालन किया जाता रहा है। वेशक इस बात की सतकता बरती जाती थी कि सामरिक महत्व की जगहों पर अंगरेजों की ही रखा जाए। इस लक्ष्य से यह गलतफ़हमी नहीं पैदा होनी चाहिए कि यह स्वशासन स्थापित करने का लक्ष्य था। दरअसल दोनों एकदम विरोधी स्थितियाँ हैं। 1917 तक स्वशासन की बात का लगातार नकारा जाता रहा है। इन दो लक्ष्यों के बीच उल्लाप होना संतुष्टा दम्य तरह की गलत तस्वीर सामने आता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तथाकथित प्रगति हुई है।

1913 के घोषणापत्र में यह निर्धारित किया गया था कि नाई ती भारतीय मजदूर धर्म,



जन्म स्थान, वंश, रंग या इस तरह के किसी भी आधार पर उक्त सरकार के अधीन कोई पद या नौकरी पाने के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।' कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने इस धारा की अपनी ही व्यवस्था प्रस्तुत की 'कोर्ट इस धारा का यह अर्थ समझती है कि ब्रिटिश भारत में कोई अभिशासी जाति नहीं होगी कि योग्यता के लिए जो अर्थ जांचे की जानी चाहिए उनमें उस सीमा तक जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।'।

1858 में महारानी ने जो घोषणा की और जिसे आमतौर पर नई नीति की शुरुआत समझा जाता है उसमें भी वस्तुतः उपर्युक्त कथन को ही विस्तार दिया गया था

हमारी यह इच्छा है कि जहाँ तक संभव हो, हमारी प्रजा को जाति धर्म का भेदभाव करते बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में हमारी सेवा में लिया जाए उह उन कर्तव्यों का निर्वाह करने दिया जाए जिसके लिए शिक्षा, योग्यता और निष्ठा पर उनका चुनाव किया गया है।

शासक और शासित के बीच भेदभाव समाप्त करने और पूरी समानता बरतने की शपथ ली गई और वायदे किए गए पर इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर से ये वायदे जिन इरादों की अभिव्यक्ति करते थे उन्हें व्यापक अर्थों में पूरा करने की इच्छा नहीं थी। 1876-80 में भारत के वायसरॉय लार्ड लिटन ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की नीति के बारे में सेक्रेटरी आफ स्टेट लार्ड फ्रेन्ड्स को जो 'गोपनीय' पत्र लिखा था उसमें कही गई बहुचर्चित बातों से लगा कि ब्रिटिश नीति 'उन वादों के सारस्त्व को ध्वस्त करने की थी जो लोगों से किए गए थे'

हम सभी जानते हैं कि ये वादे और आशाएँ न तो कभी पूरे हो सकते हैं और न पूरे होंगे। हमें दो में से एक रास्ता चुनना था, या तो उन्हें इन चीजों से बचित्र रखा जाए या उन्हें धोखे में रखा जाए और हमने वह रास्ता अख्तियार किया जो कम से कम स्पष्टवादी था यह बात मैं केवल आपको गोपनीय ढंग से लिख रहा हूँ। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता से किए गए वादों के सारस्त्व को ध्वस्त करने के लिए हर तरीके अपनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे इंग्लैंड और भारत की दोनों सरकारें सतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर रही हैं।

लार्ड साल्सबरी ने भारत के संदर्भ में ब्रिटेन के वादों को 'राजनीतिक पाखंड' का नाम दिया। (यह एक दिलचस्प अटकलवाजी होगी कि लार्ड साल्सबरी आधुनिक युग के वाल्डविन, लायड जॉर्ज, मैकडोनाल्ड और चैम्बरलेन जैसे लोगों को क्या कहते हैं।)

बीते दिनों के (आज जबकि हम इसकी समानांतर प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़

गए है उन दिनों से शिक्षा ली जा सकती है) इन भ्रामक और भडकीले वादों तथा घोषणाओं का असली मकसद यह था कि साम्राज्यवादी प्रशामनिक प्रणाली में बड़ी सावधानी के साथ भारतीयों को धीरे धीरे भातहत सेवाओं में लेने का काम बढ़ाया जाए ताकि जनता को गुलाम बनाए रखने में उच्च तथा मध्यवर्ग के भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके।

सरकारी सेवा में बड़ी सतकतापूर्वक भारतीयों के लिए निर्धारित पदों (महत्वपूर्ण पदों को अलग रखकर) की संख्या बढ़ाने के साथ साथ इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1861 के बाद से एक के बाद एक सुधार सवधी उपाय किए। 1861 में इंडियन कौंसिल ऐक्ट ने वायसरॉय की विधानपरिषद में छः नामजद गैरसरकारी सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था की। इन नामजद सदस्यों में कुछ ऐसे भारतीय थे जिनका पदों सावधानी के साथ चयन किया गया था। ध्यान देने की बात है कि वाट के सभी सुधार उपायों की तरह ही इस बार भी 'सुधार' के साथ साथ एक नया दमनकारी कदम भी उठाया गया, वायसरॉय को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय छः महानों की अवधि तक के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है यह ऐसा अधिकार था जिसका आज खुलकर इस्तेमाल हो रहा है।

1883-84 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट ने नागर प्रशासन में निर्वाचक सिद्धांत की शुरुआत की और ग्रामीण परिषदों तथा जिला कौंसिल की स्थापना की। 1892 में इंडियन कौंसिल ऐक्ट ने प्रांतीय विधानपरिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कुछ सदस्यों को (दरअस्त स्वीकृति के लिए प्रस्तुत न कि स्थानीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा विधिवत निर्वाचित) शामिल कर लिया और इन कौंसिलों के जरिए फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर इन्हें वायसरॉय की विधानपरिषद में ले लिया गया। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से विख्यात इंडियन ऐक्ट ने प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित बहुमत की (कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से) और वायसरॉय की विधानपरिषद में निर्वाचित अल्पमत की (जमींदारों और मुसलमानों की सीटों को छोड़कर शेष मामलों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन) स्थापना की। इन परिषदों के कार्यों पर जबरदस्त प्रतिबंध बने रहे। इनका प्रशासन या वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था, इनके विधानों को अस्वीकृति की हालत में खीटा किया जा सकता था, मताधिकार का दायरा बेहद संकीर्ण था और निर्वाचन समस्याओं की वर्तमान बहुलता तो थी ही, साथ ही इसमें पृथक् मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।

मॉर्ले मिंटो सुधार इस तरह के पहले सुधार थे जिन्हें स्वाशासन की मांग के समर्थन में हो रहे आंदोलनों के बीच और इन आन्दोलनों के पक्षस्वरूप लागू किया जाना था। इन सुधारों का निश्चित उद्देश्य इन आंदोलनों को परास्त करना तथा मॉर्ले के शब्दों में 'नरमदली नेताओं का मान देना' था। इन सुधारों का पहली बार 1906 में मामने लाया गया।

इससे पहले 1905 में विदेशी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी के अपनाने का आंदोलन शुरू हुआ था, और 1905 की रूसी क्रांति हुई थी जिसने पूर्वी देशों के एक और बड़े तानाशाह जार को हिलाकर रख दिया था। इस परिस्थिति में इन मामूली सुधारों को धुआधार प्रचार के बीच पश किया गया और इस बात का डिबोरा पीटा गया कि इससे एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इसके बाद तैयार की गई माटेगु चेम्सफोड रिपोर्ट में (जिसे खुद भी और बड़े पैमाने पर उसी प्रक्रिया को दोहराना था) जतयत नीरस शब्दों में बहा गया 'उस क्षण के उत्साह में उनके लिए बहुत अधिक दावे किए गए इन आशावादी आकाक्षाओं की अवधि बहुत थोड़ी थी।'।

लाड मोर्ले ने स्वराज-आंदोलन को अपने सुधारों के जरिए विफल करने का जो जोड़-तोड़ बँटाया था उसे खुले तौर पर जाहिर कर दिया गया। उन्होंने निम्नलिखित विवरणात्मक शब्दों में स्थिति का विश्लेषण किया

इस तरह की योजना पर काम करते समय हम जिन लागा पर विचार करना है उनके तीन बग हैं। एक बग तो उग्रपथियों का है जो यह सपना देख रहे हैं कि वे एक दिन हमें भारत से खदेड़ देंगे दूसरा बग इस तरह की कोई आशा नहीं पाल रहा है लेकिन यह आशा है कि उपनिवेशवादी तौर-तरीके पर आधारित स्वायत्त सरकार या स्वराज की स्थापना होगी। इन दोनों के बाद जो तीसरा बग बचता है उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए कि हमारे प्रशासन में उसका सहयोग लिया जाए।

मेरा ख्याल है कि इन सुधारों का प्रभाव दूसरे बग के लोगों को, जो औपनिवेशिक स्वायत्तता की आशा करते हैं तीसरे बग के लोगों की ओर जो उचित और पूर्ण सहयोग से ही सतुष्ट रहेंगे, खींचना रहा है, और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। (हाउस आफ लाड्स में वाइकाउट मोर्ले का भाषण, 23 फरवरी 1909)

इस प्रकार साविधानिक सुधारों के साथ साथ 'अपने प्रशासन में सहयोग' ही साम्राज्यवादीयों का तयशुदा तरीका था जिसके जरिए वे स्वराज्य के राष्ट्रीय लक्ष्य को विफल बनाने की आशा करते थे।

सुधारों को 'स्वराज्य की दिशा में एक कदम' कहकर पश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जना हमने देखा है, लाड मोर्ले ने यह बात एकदम साफ तौर पर कह दी थी कि इन सुधारों से यह नहीं समझना चाहिए कि वे 'भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मसदीय व्यवस्था कायम करने' की दिशा में हैं। इसी प्रकार लाड मोर्ले ने लाड मिंटो के दावे का स्वीकार करते हुए और उसपर बल देते हुए लाड मिंटो का लिख भेजा कि भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना या न ता तब और न भविष्य में कोई प्रश्न पैदा होता है

महामहिम का अपनी सरकार के द्वार में यह जस्वीकरण कि वह 'भारत के लिए उही अर्थों में प्रतिनिधि सरकार की हिमायती है जिन अर्थों में पश्चिमी देश इस शब्दावली को ग्रहण करते हैं' आशा के अनुरूप है। यूरोप में प्रतिनिधि सरकार प्रणाली की अत्यंत जोरदार शब्दों में हिमायत करने वाला मैं से कुछ लोगों ने स्वयं भारत के अनुभव से जा सरक लिया है उम्मे यदि महामहिम के ही शब्दों में कहें तो ऐसी सरकार 'विभिन्न नस्ल और जातियां से गठित भारतीय साम्राज्य की जनता के मनोभावों के सदृश कभी नहीं हो सकती' प्रतिनिधि सरकार ने किसी भी यूरोपीय रूप को भारत में प्रतिरोपित करने के प्रयास की इच्छा को या ऐसे किसी इरादे को जस्वीकार करने के साथ ही परिपक्व में महामहिम ने यह इच्छा जाहिर की है कि वर्तमान शासनतंत्र में सुधार किया जाए अथवा अपने देश की सरकार में हिस्सा लेने की भारतीय शिक्षित वर्ग की सहज आकांक्षाओं को मान्यता देने के लिए 'कभी नए स्वरूप की तलाश की जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस याजना में आपको ब्रिटेन की शाही सरकार का हार्दिक सहयोग प्राप्त है।

चाहे कलकत्ता हो या व्हाइट हाल, जो लोग भारत संबंधी नीति निर्देशन में हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी जांच का मुख्य मानदंड यही होना चाहिए कि सर्वाच्च सत्ता की शक्ति और दृढ़ता के आधार पर किसी भी समय जो भी नए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं उनका क्या असर होता है। (लाड मिंटो के नाम लाड मोर्ले का पत्र। माटगु वेन्सफोर्ड रिपोर्ट, पृष्ठ 64)

इस स्थल तक साम्राज्यवाद की नीति बहुत ही स्पष्ट है और इस समझन में कोई भूल नहीं हो सकती। स्वराज्य की दिशा में किसी तरह की प्रगति का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वोच्च सत्ता के हित में बहुत निश्चित हैं। सांविधानिक सुधार का मकसद यही है कि साम्राज्यवाद के हितों को दखत हुए उच्चवर्ग के अल्पमत का समयन प्राप्त किया जाए।

### 3 डोमीनियन का दर्जा देने का प्रश्न

1914-18 का युद्ध हुआ जिसने साम्राज्यवाद की नींव को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध ने सभी उपनिवेशों की तरह भारत की जनता को भी जगा दिया। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता बढ़ी और 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वराज्य की याजना बनाई। मार्च 1917 में रूसी नाति हुई। इस घटनाओं ने सभी देशों में जा-आंदोलनों को तज किया और विश्वभर में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का नारा गूज उठा।

20 अगस्त 1917 का ब्रिटिश सरकार ने अपनी नई नीति की घोषणा में इस स्थिति का मुकाबला किया। तब से ही इस नाति का आधुनिक साम्राज्यवाद की सांविधानिक नाति

की कुजी समना जाने लगा । इस घोषणा के खास अर्थ इस प्रकार हैं

महामहिम की सरकार की नीति, जिसके हाथ भारत सरकार पूरी तरह महमत है, यह है कि प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की साझेदारी बढ़ाई जाए और स्वशासी सत्ताओं का प्रमत्त विकास किया जाए । ये उपाय इसलिए किए जान चाहिए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना का प्रगतिशील लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । उन्होंने फैसला किया है कि इस दिशा में जितनी जल्दी हो सके ठोस कदम उठाए जाए । इस नीति में प्रगति प्रमत्त चरणा में ही की जा सकती है । भारतीय जनता की जनता और खुशहाली की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार पर है और इनकी जाच हर विकास के परिणाम और समय से की जानी चाहिए । उन्हें अपनी दिशा का निर्धारण उन लोगों से प्राप्त सहयोग के जरिए करना चाहिए जिन्हें सेवा के नए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे और इस तथ्य से करना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी की भावना में किस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है ।

यह घोषणा सैक्रेटरी आफ स्टेट ई० एस० माटेगु ने जारी की थी इसलिए इसे आमतौर से माटेगु घोषणा नाम से जाना जाता है । मोटे तौर पर इसका प्रारूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कट्टर महारविया—कजन और आस्टिन चवरेलेन ने तैयार किया था । इस दस्तावेज में लार्ड कजन ने 'जिम्मेदार सरकार' का जिक्र शामिल किया था (रोनाल्ड डो लाइफ आफ कजन, खंड 3, पृष्ठ 167) । स्मरणीय है कि 1905 में लार्ड कजन ने भारत छोड़त समय अपने विदाभाषण में कहा था मैं हृदय से आशा करता हूँ कि आप भारत के वायसराय, भारत के राज्याध्यक्ष के पद पर इस शब्द के पूरे सही सही अर्थों में सदा बने रहेंगे ।

यह घोषणा जारी करने में कितनी जल्दबाजी का गई इसका पता इस तथ्य से ही लग जाता है कि इसके जारी करने के बाद ही सरकारी जाच का एक लड़ा और व्यापक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें यह पता लगाना था कि इस घोषणा का मकसद क्या है ? अंत में इस जाच के परिणामस्वरूप 1919 का भारत सरकार अधिनियम बना ।

घोषणा का क्या अर्थ है यह एक विवाद का विषय बना हुआ है । क्या इसका इगदा स्वशासित डोमीनियन का अर्थ में ही डोमीनियन का दर्जा (घोषणा में इस शब्दावली का इस्तमाल नहीं किया गया है) देना है ? और यदि ऐसा है तो क्या इसमें यह बात भी निहित है कि अमुक तिथि तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा ?

इस नीति को उन विभिन्न 'चरणा' से समझा जा सकता है जिसके लिए ब्रिटिश सत्ता के

अधिकारिया को हर विनास के परिणाम और समय से जाच करनी थी। पहला चरण पूरा होने में दो वर्ष का समय लगा। दूसरे चरण की तुलना में यह अवधि बहुत कम थी। माटंगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था कि एक चरण से दूसरे चरण में पहुँचने के लिए हर 10 वर्ष बाद समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए। फिर भी दूसरे चरण को पूरा होने में 16 वर्ष का समय लग गया और 7 वर्षों की भरपूर जाच के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट ऑफ 1935) सामने आया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि दस वर्षों का अंतराल बहुत कम समय है इसलिए यह अवधि बढ़ा दी जाए। 'नई प्रणाली' के प्रशासन का वास्तविक प्रभाव देखन के लिए दस वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है' (साइमन रिपोर्ट, खंड 2, पृष्ठ 7)।

जून 1924 में याक में भारत ने नाम अपोत्र करत हुए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपने सापण में भारत में नई साम्राज्यवादी नीति का चौकस रुढ़म र कदम प्रगति और विकास-मूलक जाच के अभिप्राय को बड़ी कुशलतापूर्वक ग्रहण किया (यह नीति कम विकासमूलक और प्रिन्सकारी साबित हुई जब उसमें व्यावहारिक उपायों का महारा लिया। मसलन उ होने वगान आपानकालीन जघरादेश थोप दिए और बिना मुकदमा गिरफ्तारी की प्रणाली कायम की)

आप ब्रिटिश जनतंत्र में अपना विश्वास बनाए रख, लेबर सरकार में भी आप अपना विश्वास बनाए रखें। भारत सरकार और लेबर सरकार द्वारा एक जाच की जा रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान, उनकी कार्यप्रणाली और उसका सभावनाओं का आधार नैयार करने के लिए इस जाच में जा परिणाम होगा, उनसे भारतीयों का एक ऐसी व्यवस्था का जन्म दन में सहयोग मिलेगा जो स्वराज्य होगा।

इस कार्यक्रम और वचन की जाशापूर्ण सुस्पष्टता ने भारत में प्रति साम्राज्यवादी नीति का उन्नी पुरातन शली में मूल रूप दिया है जिसमें मैकडोनाल्ड अद्भुत रूप से प्रयोग है।

नई नीति को अमल में लाने के लिए अतः दो वैधानिक उपाय शुरू किए गए थे। पहला उपाय 1919 का भारत सरकार अधिनियम है जिसमें जरिए द्वितंत्र (डाइरेक्टोरी) की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के हाथ में राई परितंत्र नहीं किया गया लेकिन प्रताप सरकार के मामले में स्वाम्म्य मित्रा तथा दूसरी तरह के रचनात्मक विषयों को, जिनके लिए दन नहीं था उन भारतीय मंत्रियों के पास स्थानांतरित कर दिया गया जो प्रताप विधान मंडल के लिए जाना-हुं थे जबकि पुत्तित तथा तूराजस्य जस सामरिक महत्त्व के मामले उन मंत्रियों के हाथ में सुरक्षित रहने लिए गए जो गवर्नर के प्रति जवाबदार थे। प्रताप विधानमंडल की स्थापना विचारित मस्य्या के अमल में ही गई। इस विधानमंडल का आधार पर सीमित मनाधिकार का गहरा किया गया जो तुन जाया (यमा

को छोड़कर) के 28 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता था। प्रांतीय गवर्नर का इस बात का अधिकार था कि विधानमंडल द्वारा यदि कोई कानून स्वीकार नहीं बल्कि पारित कर दिया गया है तो चाह तो व उसे वापस कर सकत है या उसकी पुष्टि कर सकते हैं। केंद्र में दो सदनों की स्थापना की गई—एक कॉमिल आफ स्टेट और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉमिल आफ स्टेट में लगभग आधे सदस्य नामजद होते थे और शेष आधे सदस्यों को उच्चवर्ग की एक वेहद मामूली तादाद में से (संपूर्ण देश के 18 000 से भी कम मतदाताओं में से) चुना जाता था। लेजिस्लेटिव असेंबली में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था और इस निर्वाचन के लिए प्रांत में हुए चुनाव से भी ज्यादा सीमित मतधिकार (कुल आवादी के 1 प्रतिशत के आधे से भी कम हिस्से को) को आधार बनाया जाता था। इन सब अधिकारों से बढ़कर गवर्नर जनरल के पास अधिकार थे वह चाहे तो कानून विशेष की पुष्टि करे या वापस करे।

द्वितंत्र की सभी न मंजूरियाँ थीं। भारतीय जनमत ने ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ साम्राज्यवादियों ने भी कुछ वर्षों के अनुभव के बाद इसकी निंदा की। यहाँ फिनहल उन सीमाओं का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है जो बड़ी स्पष्ट दिखाई देती थीं। भारतीय मामलों में मंत्री ने 1925 में इसका इस प्रकार वर्णन किया—यह एक तरह का पड़ताऊ दकियानुम संविधान था जिसके प्रति ऐंग्लो संवर्ग समुदायों ने आमतौर पर कोई प्रतिनित्य नहीं व्यक्त की और इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि एक ऐसे समुदाय से सफलतापूर्वक कोई अपील की जा सके जिसके राजनीतिक विचार इतने बड़े पैमाने पर ऐंग्लो संवर्ग प्रनिमानों से उद्भूत हैं' (हाऊस आफ लाड्स में लाड बर्कनहड का भाषण 7 जुलाई 1925)। भारतीय मंत्रियों को 'जिम्मेदारी' एक डाय था, यह सभी मालते थे। साइमन, कमिशन की रिपोर्ट ने इस व्यवस्था के दावा का काफी भंडाफोड़ किया जिसके जरिए व्यवहार में भारतीय मंत्री माटे तौर पर सरकारी खेमे पर निर्भर करते थे और 'सरकारी आदमी' समझे जाते थे, 'सरकार के एकीकरण की अत्यंत सम्मोहक भावना' ने जिम्मेदारियों को अलग अलग वाटन की कागजी योजनाओं को विफल कर दिया। देशक उस निष्पक्ष थाय से ज्यादा प्रभावशाली और कोई बात नहीं होगी जिसके जरिए साम्राज्यवादी संविधान निर्माण के हर अगले चरण ने अपने पूर्ववर्तियों के आडवरो का पर्दाफाश किया। माटेंगु चैम्सफोर्ड रिपोर्ट ने मालें मिटो सुधारों के हवाई बायरो के प्रति काफी निमग रख अपनाया। माटेंगु चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की असफलताओं और कमियों को बनाने में साइमन कमिशन रिपोर्ट ने भी कोई उदारता नहीं बरती। फिर भी, हर बार की ही तरह वर्तमान संविधान को आदेश कहा गया और कहा गया कि इसकी मंजूरियों के पीछे भारतीयों की अद्वैतशिता ही है।

1935 का भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद किए गए दूसरे साविधानिक अधिनियमों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि यही संविधान 1937 से लागू है (हालांकि मुख्य संघीय अनुच्छेदों को युद्ध के बाद से अमल में नहीं लाया गया और अनिश्चित काल के





कई वयान सामन आए लेकिन व समय बाध्यकारी अधिकारो से रहित थे। इन भाषणा में कोई भाषण कम महत्वपूर्ण था ता कोई ज्यादा, कोई कम निश्चित था ता कोई ज्यादा। 1928 में अपने पद से अवकाश पान के बाद मैकडोनाल्ड ने कहा था

मैं आशा करता हूँ कि कुछ वर्षों नहीं बल्कि कुछ महीनों के अंदर ही हमारे राष्ट्रमंडल में एक नया डोमिनियन शामिल हो जाएगा, एक दूसरी नस्ल के लोगो का डोमिनियन जिसे राष्ट्रमंडल के अंदर उतना ही आत्मसम्मान मिलेगा जितना अन्य देशों को प्राप्त है। मेरा आग्रह भारत से है। (जे० आर० मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश कामनवेलथ लेबर पार्टी में भाषण, 2 जुलाई 1928)

लेकिन 'कुछ वर्षों नहीं बल्कि कुछ महीनों के अंदर' जो कुछ हुआ वह भारत में आतंक का साम्राज्य था और लगभग 100,000 भारतीयों की गिरफ्तारी थी जिसका संचालन मैकडोनाल्ड ने ही किया और यह सारी कायबाही इसलिए की गई क्योंकि जनता स्वराज्य की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रही थी।

1929 में वायसराय लाड इविन ने एक वयान जारी किया जिसका उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन के लिए आधार तैयार करना था। उन्होंने कहा

मुझे महामहिम की सरकार की ओर से यह कहने का अधिकार दिया गया है कि उनकी राय में 1917 की घोषणा में यह अतिनिहित है कि भारत की साविधानिक प्रगति का स्वाभाविक मुद्दा डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना है। (लाड इविन का 31 जनवरी 1929 का वयान)

दस वक्तव्य पर ब्रिटिश संसद के सभी अंगरेज राजनेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रकट किया और इसका औचित्य महज इस आधार पर ठहराया गया कि भारत में एक कठिन राजनयिक स्थिति में इसके 'बड़े अच्छे प्रभाव' हुए। लेकिन सेक्रेटरी आफ स्टेट ने उन सारी कोशिशों का जोरदार विरोध किया जो उनसे जिरह के लिए की जा रही थी। उन्होंने कहा 'वायसराय की घोषणा का अर्थ वही है जो उसमें कहा गया है और मैं आदरणीय महानुभावों से कहना चाहूंगा कि वे मुझसे जिरह न करें वरना कठिनाइया पैदा हो जाएगी।'।

'डोमिनियन का दर्जा' का अर्थ क्या होता है? इसका भी जवाब तरह-तरह का है। जैसा-कि हमने देखा है, भारतीय मामलों के मंत्री ने दिसंबर 1929 में ही यह विचक्षण तक पेश किया था कि भारत को दस वर्ष पहले ही उसी समय से डोमिनियन का दर्जा मिल गया है जबसे 'भारत' ने बर्साई सवि पर हस्ताक्षर किए और उसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिली। एक तरफ तो इस तरह का अपना प्रिय तरु पेश किया जाता था और दूसरी तरफ इसी के

साथ भारत की सांविधानिक प्रगति के भावी लक्ष्य के रूप में डोमोनियन दर्जे का वादा दिया जाता था जैसाकि वायसराय की घोषणा में किया गया था। लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि इन दोनों बातों में समझ क्या है ?

दूसरी ओर, इस दलील की हिमायत की जाती है कि अतः 'डोमोनियन का दर्जा' शब्द की परिभाषा देना असंभव है (हालांकि ऐसा लगता है कि वेस्टमिन्सटर के विधान ने इसकी परिभाषा दे दी है)। इस प्रकार भारत सरकार विधेयक के आमुख में डोमोनियन स्टेट्स लक्ष्य को शामिल करने की मांग के सदन में 'दि टाइम्स' समाचारपत्र ने 1935 में लिखा

किसी विशुद्ध सांविधानिक दस्तावेज में 'डोमोनियन स्टेट्स' की परिभाषा नहीं दी जा सकती 'डोमोनियन स्टेट्स' का अलग अलग समय में इतना अलग अलग अर्थ रहा है और यह आज इतनी तरह की सरकारों पर लागू है कि यदि इसे यहाँ तक कि संसदीय विधेयक के आमुख में भी ऐसी कोई परिभाषा देने की कोशिश की गई जिसपर सभी समान रूप से सहमत हो, तो निराशा ही हाथ लगनी।  
(दि टाइम्स का संपादकीय, 25 जनवरी 1935)

इस प्रकार चमक दमक से भरा यह लक्ष्य एक जनता और अबूझ क्षेत्र में लुप्त हो जाता है। ये पकितया तब लिखी गई थी जब वेस्टमिन्सटर की संविधि में बड़ी स्पष्टता के साथ 'सांविधानिक दस्तावेज' और 'संसदीय विधेयक' के अर्थों में डोमोनियन स्टेट्स की परिभाषा दी जा चुकी थी। लेकिन यह परिभाषा तो कनाडा, आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के लिए थी, भारत के लिए नहीं।

इस अपरिभाषित और अपरिभाष्य डोमोनियन स्टेट्स का लक्ष्य कितनी दूर है ? यह कोई नहीं जानता। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन साम्राज्यवाद के प्रमुख जिम्मेदार राजनेताओं ने स्पष्ट तौर पर यह बताने में कोई चूक नहीं की कि यह लक्ष्य काफी दूर है। भारतीय मामलों के भूतपूर्व मंत्री लार्ड बर्केंहेड ने 1929 में एतान किया

कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी कोई अनुमानित अवधि नहीं निर्धारित कर सकता जिसमें हम कह सकें कि भारत को डोमोनियन का दर्जा मिल जाएगा। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत की जनता को यह बताए कि निकट भविष्य में उन्हें डोमोनियन का दर्जा हासिल हो जाएगा। (हाउस आफ लार्ड्स में लार्ड बर्केंहेड का भाषण, 5 नवंबर 1929)

इसी प्रकार की धारणा वाट्सडविन ने भी व्यक्त की

कोई यह नहीं बता सकता कि उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना बच हा जाएगी, कोई यह नहीं बता सकता कि इसका रूप क्या होगा। कोई यह नहीं जानता कि निकट भविष्य में या काफी समय बाद जब भारत में एक जिम्मेदार सरकार बन जाएगी तो डोमोनियन का दर्जा क्या होगा। (हाउस ऑफ कॉमंस में स्टैनले वाल्डविन का वक्तव्य, 7 नवंबर 1929)

इस प्रकार अज्ञात लक्ष्य एक अज्ञात भविष्य की अभेद्य दूरी में गुम हो जाता है।

1939 में युद्ध छिड़ने के बाद डोमोनियन का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य का मसला एक बार फिर नवम आगे ला दिया गया क्योंकि सरकारी प्रवक्ता ने एक बार फिर इसे स्वाधीनता की मांग के विकल्प में पेश करना चाहा। 17 अक्टूबर 1939 को वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा

जिसका गवर्नर जनरल के नाम निर्देश के प्रपत्र में कहा गया है महामहिम की सरकार का यह इरादा है और इसके लिए वह उत्सुक है कि साम्राज्य के दायरे के अंदर ही भारत और ब्रिटेन के बीच सार्वभौमिकता बढ़ाई जाए ताकि भारत को बड़े डोमोनियन के बीच उचित स्थान दिलाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

लेकिन यह बताने की कृपा नहीं की गई कि वह 'उचित स्थान' क्या होगा। वायसरॉय की घोषणा के बाद जो सप्तदश बहस हुई उसमें सर मैम्बुअल होर ने सरकार की ओर से यह निश्चयपूर्वक कहा कि सरकार का लक्ष्य '1926 का डोमोनियन स्टेट्स' दिलाना है

जो लोग यह सोचते हैं कि डोमोनियन स्टेट्स दो तरह का है वे गलत सोचते हैं। जिस डोमोनियन स्टेट्स की हमने अपेक्षा की है वह 1926 का डोमोनियन स्टेट्स है। (हाउस ऑफ कॉमंस में सर मैम्बुअल होर का वक्तव्य, 26 अक्टूबर 1939)

लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस पर रहस्य का एक नया आवरण डाल दिया

डोमोनियन का दर्जा कोई पुरस्कार नहीं है जो किसी योग्य समुदाय को दिया जाता है बल्कि यह उन तथ्यों का मापदंड है जो वास्तव में मौजूद हैं। जब ही ये तथ्य भारत में अस्तित्व में आएंगे, और मेरे विचार से जितनी जल्दी ये अस्तित्व में आए उतना ही बेहतर है, हमारी नीति का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

इस देववाणी सदृश उक्ति के पीछे जो बात थी वह वस्तुतः रहस्यपूर्ण नहीं थी। मैम्बुअल होर का एक और वक्तव्य आया जिसने एक बार फिर हम वादा के अवसर के बीच बड़ी चिरपरिचित बिंदुपक चेहरा देखने को मिला



सके ये समूचे ढांचे का इस्पाती चौखट है। (हाउम आफ कामस म लायड जाज का भाषण, 2 अगस्त 1922)

इसी प्रकार चर्चिल ने 1930 में एलान किया

भारतीया के जीवन और उनकी प्रगति पर से अपना अच्छूक नियंत्रण समाप्त करने का ब्रिटन का कोई इरादा नहीं है।

हमारा यह कतई इरादा नहीं है कि हम ब्रिटिश सम्राट के ताज में से उस शानदार चमकील और बहुमूल्य रत्न का निकाल दें जो हमारे अंग सभी डोमोनियनों और उपनिवेशों की तुलना में ब्रिटिश साम्राज्य को सर्वाधिक गौरव और शक्ति प्रदान करता है। (इंडियन इंपायर सोसायटी में 11 दिसंबर 1930 को विंस्टन चर्चिल का भाषण)

1934 में प्रधानमंत्री की हैसियत से बाल्डविन ने भी ऐसी ही भाषा इस्तमाल की थी

आज की इस दुनिया के संयोगों और बदलावों के बीच मेरी यह निश्चित धारणा है कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमेशा के लिए बनाए रखने के आपके पास अच्छे अवसर हैं। (नेशनल यूनियन आफ कंजरवेटिव ऐंड यूनियनिस्ट एसोसिएशन की केंद्रीय कौंसिल में स्टेनले बाल्डविन का भाषण, 4 दिसंबर 1934)

इसी प्रकार 1931 में एक भाषण के दौरान उन्होंने साविधानिक सुधारों के मकसद की व्याख्या की

भारत और ग्रेट ब्रिटेन की एकता के सूत्र में पिरोने वाले बंधनों में किसी तरह की कमजोरी लाए बिना हम ऐसी घनिष्ठता कायम करना चाहते हैं जैसे पहले कभी नहीं थी। इस समय हम इसी घनिष्ठ एकता के काम में लगे हुए हैं। (स्टेनले बाल्डविन का यूटन एक्ट में भाषण 6 मार्च 1931)

इस सर्वेक्षण के नतीज अपरिहार्य हैं। इन और इस तरह के समान वक्तव्यों के संचित प्रभावों का सर्वेक्षण असंभव है जैसे कि भारत में जिम्मेदार सरकार कायम होने की संभावना पर दृढ़ अविश्वास और दुर्ग्राह्यता तथा भारत में अगरजी राज्य का बने रहने के बारे में आरोपित निश्चितता एवं कठमुल्लेखन से परिपूर्ण ऐसे और इस तरह के तमाम वक्तव्यों से संचित प्रभाव का सर्वेक्षण असंभव है। इन सबने विभिन्न साविधानिक वाक्यश्रमों और योजनाओं के जरिए आधुनिक युग में भारत में ब्रिटिश नीति के बारे में

यदि इसके माग म कठिनाइया है तो वे हमारी वजह से नहीं ह। वे किसी ऐसे विशाल उपमहाद्वीप म जो विभिन्न जातियों और समुदायों में बंटा हो, सहज रूप से निहित ह। यहां के राजा-महाराजा ब्रिटिश भारत का प्रभुत्व कायम होने की आशका से डरे है, मुसलमान लोग इस बात के पक्के विरोधी है कि केंद्र म हिंदुओं का बहुमत स्थापित हो, दलितवर्ग के लोगो या अल्पमत जातियों के अल्प लोगो का यह सोचना ठीक ही है कि कोई जिम्मेदार सरकार जिसका अर्थ हिंदुओं के बहुमत पर टिकी सरकार है, उनके हितों की बलि चढ़ा देगी। ये चिंताएं आज भी बनी हुई है। काश। ये चिंताएं न होती। लेकिन जब तक इनका अस्तित्व है सरकार के लिए यह असंभव है कि वह किसी निश्चित तिथि पर केंद्र को तत्काल और पूरी जिम्मेदारी देने की माग स्वीकार करे।

इस प्रकार एक बार फिर वे हथकड़े अपनाए गए जिनसे हम अच्छी तरह परिचित है। एक तरफ तो बिना किसी ठोस प्रस्ताव या निश्चित तिथि के डोमोनियन का दर्जा देने का वादा किया गया और दूसरी तरफ भारतीय जनता की 'फूट' का बहाना लेकर इसकी प्राप्ति के हर प्रयास को विफल किया गया। डोमोनियन स्टेट्स के वादे का इस्तेमाल गंभीर स्थितियों का सामना करने तथा आजादी की माग का प्रतिकार करने के लिए एक कूटनीतिक चाल के रूप में किया गया लेकिन इस वादे को ऐसी शर्तों से घेर दिया गया है जो बड़े आराम के साथ इसकी उपलब्धि को एक अज्ञात तिथि के लिए गुप्तनाम मसला बनाकर रख देगी।

लेकिन असौम्य अनिश्चितता के इन चालपूण बुझासों के विपरीत जब यह वायदा 1917 के सकल्प को पूरा करने का या भारत में जिम्मेदार सरकार' की स्थापना की संभावना या मसला बन जाता है तो समूचा दृश्य ही बदल जाता है और जब यह तथ्य लगता है कि निवृत्त नविव्य म भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जबरदस्त प्रभुत्व बना रहगा तो इस अनिश्चय के कुहासे का स्थान निश्चय की ठोस चट्टान ले लेती है। यहां हम ठोस आधार पर हात है, यहां पर स्वर गुंजायमान और आत्मविश्वासपूर्ण हो जाता है।

इस प्रकार लायड जाज न 1922 में प्रधानमंत्री की हैसियत से अपने मंत्रालय इस्पाती (स्टील प्रेम) भाषण में एलान किया

ब्रिटिश किसी भी हालत में भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा—यह भूतभूत मित्रता मौजूद रखकर या ही नहीं बल्कि इसका कोई भी ऐसी सरकार पालना करेगी जिसका इस देश की जनता का पूरा पूर्ण विश्वास प्राप्त है

मैं किंगी एनी अवधि का अनुमान नहीं लगा सकता जब भारत ब्रिटिश निवृत्त नविव्य में इस छोट-छोटे विद्रोहों में मिलन बात बिना निंदों और सहयोग का छाड़

सके य ममुचे दांचे के इस्पाती चौघट है। (हाउस आफ कामंस म लायड  
जाज का भाषण, 2 जगस्त 1922)

इसी प्रकार चर्चिल ने 1930 म एलान किया

भारतीयो के जीवन और उनकी प्रगति पर से अपना अचूक नियंत्रण समाप्त  
करन का ब्रिटन का कोई इरादा नहीं है।

हमारा यह कतई इरादा नहीं है कि हम ब्रिटिश सम्राट के ताज म से उस शानदार  
चमकीले और बहुमूल्य रत्न का निकाल दें जो हमारे अंग सभी डोमीनियनो  
और उपनिवेशो की तुलना म ब्रिटिश साम्राज्य को सर्वाधिक गौरव और शक्ति  
प्रदान करता है। (इंडियन इंपायर सोसायटी म 11 दिसबर 1930 को  
विस्टन चर्चिल का भाषण)

1934 म प्रधानमन्त्री की हैसियत से वाल्डविन ने भी ऐसी ही भाषा इस्तेमाल की थी

आज की इस दुनिया के संयोगो और बदलावो के बीच मेरी यह निश्चित धारणा  
है कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हमेशा के  
लिए बनाए रखने के आपके पास अच्छे अवसर है। (नेशनल यूनियन आफ  
कजरवेटिव ऐंड यूनियनिस्ट एसोसिएशंस की केंद्रीय कौंसिल मे स्टेनले वाल्डविन  
का भाषण, 4 दिसबर 1934)

इसी प्रकार 1931 म एक भाषण के दौरान उन्होंने साविधानिक सुधारो के मकसद की  
व्याख्या की

भारत और ग्रेट ब्रिटेन को एकता के सूत्र म पिराने वाले बंधनो म किसी तरह  
की कमजोरी लाए बिना हम ऐसी घनिष्ठता कायम करना चाहते है जसी  
पहले कभी नहीं थी। इस समय हम इसी घनिष्ठ एकता के काम मे लगे हुए  
है। (स्टेनले वाल्डविन का यूटन एक्ट म भाषण, 6 मार्च 1931)

इस सर्वेक्षण के नतीज अपरिहाय है। इन और इस तरह के समान वक्तव्यो के संचित  
प्रभावो का सर्वेक्षण असंभव है जैसे कि भारत मे जिम्मेदार सरकार कायम होने की  
संभावना पर दृढ़ अविश्वास और दुर्ग्राह्यता तथा भारत म अंगरेजी राज्य के बने रहने के  
बारे म आरोपित निश्चितता एवं कठमुल्लेपन से परिपूर्ण ऐसे और इस तरह के तमाम  
वक्तव्यो स संचित प्रभाव का सर्वेक्षण असंभव है। इन सबने विभिन्न साविधानिक  
कायक्रमो और योजनाओ के जरिए आधुनिक युग म भारत म ब्रिटिश नीति के बारे म

स निष्पन्न तब पहुँचे बिना अंगरेजों के हाथ में तिहरे सुरक्षा उपायों सहित सभी सामरिक स्थल सौंप दिए हैं। इस विषय में अधेपन या अनिश्चितता या भोल भाले भ्रमों को पालना कोई सफाई नहीं है। साम्राज्यवादियों की बुनियादी नीति में कोई परिबर्तन नहीं हुआ है केवल उनकी रणनीति बदल गई है।

डोमीनियन का दरजा' देने की परिकल्पना, अपरिभाषित, अनात और अनिश्चित मृग मरीचिका एक ऐसा सुनहरा जाल थी जिसमें भारतीय राजनीतिज्ञों को फसाकर उनका सहयोग लिया जा सकता था। लेकिन साविधानिक सुधारों की जो सच्चाई थी उनका चरित्र एकदम भिन्न था।

साम्राज्यवादी प्रभुत्व को बनाए रखने का बुनियादी लक्ष्य आज भी वैसे ही जारी है जैसे पहले था। वर्तमान सुधारों का रास्ता वही है जो 1917 से पूर्व के वर्षों में किए गए सुधारों का रास्ता था। इनका विकास और भी कठिन स्थितियों में तथा साम्राज्यवादी पतन के और भी विकसित चरण में हो रहा है। आज जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वह भारत में साम्राज्यवाद के प्रगतिशील ढंग से समापन का और भारत की जनता के हाथ में सरकार की बागडोर सौंपने का लक्ष्य नहीं है बल्कि आज कोशिश यह की जा रही है कि पूरी एह्तियात के साथ भारतीय जनता के अल्पमत उच्चवर्ग को अपना सहयोगी बनाकर जनता को गुलामी की जंजीर में जकड़े रखा जाए ताकि साम्राज्यवादी शासन और शोषण बरकरार रहे। जिन साविधानिक सुधारों और नई दृष्टि' का काफी ढिंढोरा पीटा गया था उनका बुनियादी रणनीतिक मवसद यही था। 1935 के संविधान के निर्माता वाल्टडविन के शब्दों में

भारत में हमारे वायसरॉय और गवर्नरों तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा भरती किए और संसद द्वारा सुरक्षा प्रदान किए गए सैनिकों का कतब्य यह होगा, और जल्द ही पड़े तो उन्हें इस बात की गारंटी देनी होगी, कि भारतीय मजिगण और विधानमंडल उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। (गवर्नमेंट आफ इंडिया बिल पर स्टैंले वाल्टडविन का रेडियो प्रसारण, 5 फरवरी 1935)

#### 4 1935 का संविधान

यदि हम मोल्ले मिटा सुधारों को पहला संविधान मानें तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तुत संविधान, जिसे माटगु घोषणा के बीस वर्षों बाद 1937 में अमल में लाया गया, आधुनिक युग में भारत के लिए तैयार किया गया तीसरा साम्राज्यवादी संविधान है। सात वर्षों में भी अधिक समय तक निमाणाधीन रहने के बाद इसे संविस्तार प्रतिपादित किया गया। यह काम पहली बार साइमन कमिशन की नियुक्ति के समय से



शुरू हुआ और इसपर ब्रिटन में काफी विवाद हुआ और भारत में इसे लेकर काफी सघर्ष हुए।

इस सविधान को आमतौर पर अगरजी ने कुछ परवर्तों रक्षा उपायों के अंतर्गत स्वराज्य की परोक्ष उपलब्धि या किसी भी रूप में स्वराज्य की विस्तृत और उदार स्थापना कहा। परिणामतः भारतीय जनता ने इसे एक स्वर से अस्वीकार किया और जब इसे नामजूर करने में न केवल राष्ट्रीय कांग्रेस बल्कि भारतीय उदारवादियों या नरमदली लोगों ने भी भाग लिया तो इसपर लोगों को आश्चर्य हुआ और इस कायवाही का अनुचित बताया गया। उन लोगों ने भी इसे अनुचित बताया जो औपनिवेशिक जनता के अतिरिक्त अन्य लोगों से अपने व्यवहार में सामान्यतः उदार जनतात्मिक रवैया अतिथार करत थे।

इसके वास्तविक प्रावधानों की यदि मावधानी से जांच करे तो इस विरोध के कारण का पता चल जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन कारणों से भारतीय राजनीतिक नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और प्रसार के लिए इस व्यवस्था द्वारा खास तौर से प्रांतीय अनुच्छेदों में दी गई सुविधाओं को भरपूर इस्तेमाल करने और उन्हें मायता देने के बावजूद सविधान का विरोध किया और उसे नामजूर किया। उन्होंने किन कारणों से विशेष रूप से सविधान के सघीय अनुच्छेदों का विरोध किया और महसूस किया कि यह योजना स्वराज्य की स्थापना के लिए नहीं बल्कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व को और मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई है।

सविधान में दो मुख्य अनुच्छेद हैं पहला सघीय अनुच्छेद है जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रायोजित अखिल भारतीय फेडरेशन की केंद्रीय सरकार के लिए है और दूसरा है प्रांतीय अनुच्छेद जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए है। प्रांतीय अनुच्छेद 1937 में अमल में आया जबकि सघीय अनुच्छेद को कभी अमल में नहीं लाया गया (हालांकि वर्तमान सरकार आधिकारिक तौर पर इससे प्रावधानों के अंतर्गत ही काम करती है)। प्रांतीय अनुच्छेद के तहत अधिकांश सूबा में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कायभार संभाला और राष्ट्रीय कांग्रेस ने सघीय अनुच्छेद को अमल में लाए जाने का विरोध किया। सविधान का मूल भाव सघ की अवधारणा था। इसी से पता चलता है कि वह कौन सी नई दिशा ले रहा था और इसी में उसका जबरदस्त प्रतिक्रियावादी चरित्र छिपा था।

भारत की राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक प्रगति के लिए भारत का राजनीतिक एकीकरण अनिवार्य है। इस बात को हर विचारधारा और हर प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। मुख्य रूप से छोटी छोटी रियासतों के रूप में भारत का मुखतापूर्ण विभाजन किया गया है, भारत की एकता को एकदम दो तरह की प्रशासनिक प्रणालियों में बांट दिया गया है देश का 45 प्रतिशत हिस्सा एक तरह की और 55 प्रतिशत हिस्सा दूसरी तरह की प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत है और इसके साथ अविषयसंगीय ढंग से जाड़ी तिरछी चौहद्दिया चीजें

दी गई है जो एक दूसरे को काटती है और जिनका भौगोलिक, आर्थिक, जातीय, भाषाई या सांस्कृतिक किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। ये सारी बातें एक ऐसे पुरावशेष हैं जिन्हें काफी पहले दूर किया जाना चाहिए था और जिनका बना रहना भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हर तरह का प्रतिक्रियावादी सुधार बनाए रखने का उपाय है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने पहले देखा है 'भारतीय रियासतों' का कृत्रिम तौर पर अस्तित्व कायम रखा गया है। अंगरेजों के मजबूत हथियारखानों ने इन रियासतों को ध्वस्त होने से बचा रखा है। इनके अस्तित्व से भारतीय जनता की कोई जरूरत पूरी नहीं होती, ये भारत में ब्रिटिश शासन को एक मजबूत सहारा देते हैं। सरकारी प्रवक्ता के शब्दों में कई रियासतें तो 'विवादग्रस्त क्षेत्रों में मित्र पक्ष के गढ़ हैं।'

लेकिन सध सध्यों जो प्रस्ताव आए उनके मकसद किसी भी रूप में इस विभाजन को समाप्त करना नहीं था, उनका मकसद उन पुरातन तानाशाही हुकूमतों को नष्ट करना नहीं था और न उनका मकसद ममान प्रशासनिक प्रणाली कायम करना ही था। इन प्रस्तावों का केवल एक मकसद था जो बहुत स्पष्ट था, इनके जरिए प्रतिक्रियावादी पुरावशेषों को और मजबूत बनाना था और उन्हें भारत की केंद्रीय सरकार के समक्ष तक लाना था ताकि ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादियों के कमजोर पड़ रहे प्रभुत्व को मजबूत बनाया जा सके और राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात् राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का मुकाबला किया जा सके।

राज्यसंघ क्या है ? किसी वास्तविक राज्यसंघ के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विस गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य जैसे राज्यसंघों के महान ऐतिहासिक मिसालों की जांच करनी होगी।

एक राज्यसंघ ऐसी स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न इकाइयों का वैच्छिक संघ है जो इन इकाइयों पर आधारित और इन इकाइयों या इनकी जनता के प्रति उत्तरदायी प्रभुसत्तासंपन्न केंद्रीय संगठन की स्थापना के लिए समान राजनीतिक लक्ष्यों, आदर्शों या बाह्य आवश्यकताओं से प्रेरित हो और जो सीमित मात्रा में समान संगठन की स्थापना करे जिनमें पूर्ण केंद्रीकरण न हान पर भी स्वेच्छापूर्वक सहमत सीमाओं के अंतर्गत सध के सभी नागरिकों के लिए एक संघीय कानून बनाया जा सके।

इस सारी जांच पड़ताल से पता चलता है कि भारत के लिए प्रस्तावित राज्यसंघ एक अयथाय नाम है यह भाषा का एक छल है जो वर्तमान ढांचे में कुछ और विशेष किस्म के प्रतिक्रियावादी तत्वों को शामिल करके मनमानी निरंकुश तानाशाही का बयां करने के लिए है।

पहली बात तो यह है कि राज्यसंघ में प्रभुसत्ता नहीं स्थित थी। प्रभुसत्ता स्पष्ट तौर पर

कानून के जरिए राज्यसभ से बाहर ब्रिटिश शासकवर्ग के लिए, लंदन से नियुक्त किए गए ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लिए, जो केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह हो और जो निरकुश अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हो, ब्रिटिश संसद के लिए जवाबदेह सेक्रेटरी आफ स्टेट के लिए और अतः सर्वोच्च सत्ता के रूप में ब्रिटिश संसद के लिए निर्धारित की गई थी। राज्यसभ के अंदर या राज्यसभ की संरचना करने वाले सदस्य देशों को प्रभुसत्ता नहीं मिली थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह राज्यसभ नहीं था बल्कि निरकुश शासन एक खास प्रशासनिक तरीका था।

दूसरी बात यह है कि यह सभ प्रभुसत्तासंपन्न घटकों का स्वेच्छिक सभ नहीं था। यहां तक कि रियासतों के खुशामदी राजाओं के शामिल होने को जो व्यवहार में ब्रिटन के सरकारी फरमानों को मानने के लिए मजबूर है और जो ब्रिटन सरकार की इच्छा के जबरदस्त प्रवक्ता हैं हम राजनयिक दृष्टि से 'स्वेच्छापूर्वक' शामिल होना, भले ही मान ले पर राज्यसभ के तीन चौथाई भाग की रचना करने वाले प्रांतों (ब्रिटिश भारत के) का शामिल होना एक अनिवार्य निया था जो उनपर बाहर से थोपी गई थी, यह उनकी स्वेच्छिक क्रिया नहीं थी।

तीसरी बात जो 'राज्यसभ' की अवधारणाओं में सर्वाधिक असाधारण थी, वह यह थी कि कुल मिलाकर राज्यसभ के लिए निर्धारित संघीय कानून, कानून रचना या प्रशासन की कोई प्रणाली नहीं थी। राज्यसभ के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की कोई घोषणा नहीं थी। रियासतों की प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं थे, राज्यसभ से वे पूरी तरह अप्रभावित थे। लेकिन तानाशाह राजाओं को ब्रिटिश भारत के आंशिक मत-अधिकार प्राप्त नागरिकों के लिए कानून बनाने हेतु संघीय सदनों में भाग लेने की व्यवस्था थी। संघीय विधानमंडल को राज्यसभ के लिए नहीं बल्कि एक वर्ग के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए कानून का निर्माण करना था। क्या राज्यसभ की बुनियादी अवधारणा में आज तक कभी इस तरह का अंतर्विरोध दखन को मिला है? एक बार फिर यह स्पष्ट है कि इस तथ्यांकित 'राज्यसभ' ने समूचे भारत के लिए किसी परिवर्तन का या अपेक्षातया घनिष्ठ सम्मिलन का प्रतिनिधित्व न करके ब्रिटिश भारत में नए प्रतिक्रियावादी तत्व पैदा करने का ही काम किया।

इसलिए शुरू में ही यह समझ लेना जरूरी है कि राज्यसभ का प्रश्न भारत के उस राजनीतिक एकीकरण का प्रश्न नहीं है जो आवश्यक है, जिसे सभी ने आवश्यक माना है, और जो होना अवश्यभावी है और काफी संभावना है कि जिस दिन यह एकीकरण होगा यह एक नही राजनीतिक राज्यसभ का रूप ले लेगा। इस मविधान के तथ्यांकित 'राज्यसभ' का मसला एक जनतंत्रविरोधी पद्धति का मसला था जिसने देश के राजनीतिक विभाजन और रियासतों की निरकुश व्यवस्था की बुरादों की ओर से तो जाख मूद ली पर भारत के उस हिस्से को एक नई प्रतिक्रियावाणी शक्ति से परिचित कराया जिसमें कुछ सीमित

अधजनतात्मिक संस्थाओं की स्थापना हो गई थी और जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ था।

इसलिए तथाकथित 'राज्यसभ' की योजना को ऐसी योजना का नाम देना बिल्कुल ठीक होगा जो रियासतों के निरंकुश राजाओं को जो अपने अंगरेज स्वामियों के अलावा और किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, ब्रिटिश भारत की 27 करोड़ जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दे। संविधान के मसले पर विचार करने के लिए और राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में भविष्य में जब कभी 'राज्यसभ' का उल्लेख किया गया है तो यह ध्यान रखा जाएगा कि इस शब्दावली का अर्थ वही है जो ऊपर बताया गया है।

राज्यसभ का वास्तविक उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधावादी शक्तियों का पतड़ा भाँगे किया जाए। प्रस्तावित संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों में राजाओं को दिए गए विशेष प्रतिनिधित्व तथा महत्व से यह बात स्पष्ट हो गई।

संघीय विधानमंडल में दो सदन होंगे, ऊपरी सदन या कौंसिल ऑफ स्टेट और निचला सदन या संघीय विधानसभा। इन राजाओं का दोनों सदनों में महज प्रतिनिधित्व ही नहीं करना था बल्कि जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व करना था और इस काम में यह नहीं देखा जाना था कि अमुक राजा अपनी रियासत के आकार और जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व करे। कौंसिल ऑफ स्टेट के 260 स्थानों में से 104 स्थान अर्थात् कुल का 2/5 हिस्सा, राजाओं के लिए निर्धारित था। संघीय विधानसभा में 375 स्थानों में से 125 स्थान अर्थात् एक तिहाई स्थान राजाओं के लिए निर्धारित थे। समूचे भारत की आबादी का 24 प्रतिशत या एक चौथाई से भी कम भाग इन देशी रियासतों में रहता है। यदि वित्तीय आधार को ध्यान में रखा जाए तो यह असंगति और भी स्पष्ट है। अनुमान यह लगाया गया था कि संघीय राजस्व का 90 प्रतिशत हिस्सा ब्रिटिश भारत से और केवल 10 प्रतिशत रियासतों से बसूला जाएगा। इनके बावजूद राजाओं को ऊपरी सदन में 2/5 और निचले सदन में 1/3 के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था।

इस प्रकार प्रत्येक सदन में 'सरकारी गुट' के स्थान पर एक अनिर्वाचित और अप्रतिनिधिक ठास प्रतिक्रियावादी गुट का प्रविष्ट करके इस तथाकथित 'प्रतिनिधि' प्रणाली का शुरू में ही विफल कर दिया गया। यह नया गुट पहले के गुट से भी ज्यादा प्रतिक्रियावादी था और इसकी संख्या पुराने मोटागू चेम्सफोर्ड संविधान के तहत गठित सदस्यों की संख्या से ज्यादा थी (पुरानी विधानसभा में अनिर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या 40 या कुल संख्या की एक चौथाई थी। सदन में कुल सदस्यों की संख्या 145 थी)।

हमें इन नमाल विधानसभाओं के अधिकारों पर भी अभी विचार करना है। संविधान द्वारा सद्रूप में वर्णित रूप से स्वीकृत जिम्मेदार सरकार की प्रतिम अवधि के अंत में भी

सुप्तप्राय हो जाती है। गवर्नर जनरल द्वारा चुने गए तथा गवर्नर जनरल के लिए जवाबदेह एक मन्त्रिपरिषद् का गठन किया जाना था पर उनकी सामर्थ्य बेहद सीमित थी। मिसान के तौर पर रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, घमसवधी विभाग तथा वर्जित क्षेत्रों से संबंधित मामले पूरी तरह गवर्नर जनरल के नियंत्रण में थे। अतः अनेक विभागों का काम देखने के लिए विशेष अधिकारियों की अलग से नियुक्ति की जाती थी, वित्तीय स्थिरता और साख की देखरेख के लिए वित्तीय सलाहकार, कानूनी मामलों के लिए एक एडवाकेट जनरल और सघीय बैंक तथा रेलवे के लिए अतः अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासकीय सेवा और पुलिस सेवा पर केवल सेक्रेटरी आफ स्टेट ही नियुक्ति कर सकता था। कुछ अतः विशेष प्रावधानों के जरिए ब्रिटिश सरकार के बुनियादी कानूनों का उल्लंघन अथवा ब्रिटिश आर्थिक हिता या अल्पसंख्यकों के अधिकारों या रियासतों के अधिकारों के विपरीत की जान वाली किसी भी कार्यवाही को रोका जा सकता था। गवर्नर जनरल के पास जो सामान्य अधिकार थे वे इन सबसे ऊपर थे। यह बताना कठिन है कि मंत्रियों के हाथों में कौन से अधिकार बच रहे थे। लेकिन काफी मुमकिन है कि उन्हें इस बात की देखभाल करने की स्वतंत्रता रही हो कि डाकखाने का कामकाज ठीक से चल रहा है या नहीं ?

कानून में ऐसी कोई बात नहीं थी जो मंत्रियों को विधानाग के प्रति जवाबदेह बनाए। उनके वेतना को विधानाग की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी और यदि उनके विरुद्ध बहुमत से भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो जरूरी नहीं था कि वे इस्तीफा दे दें। केवल गवर्नर जनरल के नाम निर्देशों के प्रपत्र में यह सिफारिश की गई थी कि मंत्रियों का चुनाव ऐसा हो जो विधानमंडल में एक ठोस बहुमत पर नियंत्रण रख सकें। लेकिन इसमें यह भी बात बड़ी गई थी कि मन्त्रिपरिषद् में रियासतों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

विधानमंडल के अधिकारों की स्थिति क्या है ? प्रतिनिधि संस्था द्वारा शासन कायम करने की पहली कुंजी है वित्तव्यवस्था पर नियंत्रण। वित्त के संबंध में स्थिति क्या थी ?

बजट को दो भागों में बांट दिया गया था 'राज्यसंघ से प्राप्त राजस्व से किया जाना वाला व्यय' तथा 'अतः व्यय'। पहले भाग के अंदर सभी भारी और मुख्य खर्च, जिनके लिए विधानाग की स्वीकृति नहीं ली जाती, शामिल है, उदाहरण के लिए रक्षा व्यय, ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, अधिकारियों की बड़ी बड़ी तनखाह और पेंशने आदि। इस तरह के मदों में बजट का तीन चौथाई से 4/5 भाग तक खर्च हो जाता था। प्रोफेसर जी०एन० जोशी के अनुसार ('इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन', पृष्ठ 69) कुल व्यय का अनुमानित 75 प्रतिशत भाग इन मदों में खर्च होता था। राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान है कि इन मदों पर बजट का 80 प्रतिशत अंश खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार था कि वह जिस मद का चाहें इस भाग के अंतर्गत ला सकते हैं।

केवल 20 या 25 प्रतिशत छोटे मोटे पच्चे ऐसे थे जिनके बारे में विधानमंडल अपनी राय व्यक्त कर सकता था। लेकिन इस मामले में भी वह राय ही व्यक्त कर सकता था। इन छोटे मोटे पच्चे में भी विधानमंडल का कोई वश नहीं था। कोई भी वित्तीय विधायक या प्रस्ताव स्वीकृति के लिए तब तक पेश नहीं किया जा सकता था जब तक उसे पहले गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं प्राप्त हो। विधानसभा द्वारा किसी अनुदान को नामजूर करने या अनुदान की राशि को कम कर देने की अवस्था में गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह अपने विशेष दायित्वों के निर्वाह के लिए अनुदान को आवश्यक घोषित कर दे और विधानमंडल की अस्वीकृति के बावजूद उक्त पंच को प्राधिकृत कर दे। इस प्रकार वित्तव्यवस्था की किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि संस्था के लिए जो पहली बुनियादी शर्त है उसका यहाँ पूरी तरह अभाव था।

प्रतिनिधि संस्था द्वारा शासन कायम करने की दूसरी कुंजी है सना और नौकरशाही के राजतंत्र पर नियंत्रण। रक्षा विभाग को विधानमंडल के क्षेत्र से बाहर सुरक्षित रखा गया था। पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में सेनेटरी आफ स्टेट को नियुक्ति करनी थी। उनके अधिकारों और सेवा शर्तों को विशेष धाराओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। पुलिस के लिए नियमों का निर्धारण गवर्नर जनरल को करना था, खुफिया पुलिस या राजनीतिक पुलिस पूरी तरह गवर्नर जनरल के ही अधीन थी। शासन कायम करने की तीसरी कुंजी है कानून बनाने का अधिकार, कानूनों को पारित करने का अधिकार या प्रस्तावित कानूनों को मंजूर न देने का अधिकार।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानमंडल उन सीमित विषयों के बारे में कानून पारित कर सकता था जिन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त थी। इन विषयों के क्षेत्र को अनेक धाराओं द्वारा सीमित रखा गया था। विधानमंडल तब तक वित्त संबंधी उपायों पर हाथ नहीं लगा सकता था यहाँ तक कि उनपर बहुत भी नहीं कर सकता था जब तक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति उसे न मिल गई हो। यह उन कानूनों पर हाथ नहीं लगा सकता था जो ब्रिटिश सत्ता के बुनियादी को यथा सेना संबंधी मसला, एंव प्रशासनिक सेवाओं, रियासतों अल्पसंख्यकों ब्रिटिश आर्थिक हितों आदि के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। विशेष तौर से संधीय विधानमंडल को यह अधिकार नहीं था कि वह ऐसे किसी उपाय को स्वीकृति दे जो

- 1 ब्रिटेन में रहने वाली ब्रिटिश जनता पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जायें जिनका संबंध उनके ब्रिटिश भारत में प्रवेश करने या घूमने, रहने, संपत्ति कमाने, रखने या बेचने से हो या सार्वजनिक सेवा में कोई पद ग्रहण करने कोई पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने से हो।
- 2 भारत में करारापण के मद में ब्रिटेन में रहने वाली ब्रिटिश जनता या ब्रिटेन में स्थापित किसी कंपनी के प्रति भेदभाव बरतें।

- 3 ब्रिटेन में पजीकृत जहाजा, उनके नाविको, यात्रिया, उनपर लदे मालो आदि के प्रति भेदभाव वरते ।
- 4 ब्रिटेन के वानूनो के तहत सस्थापित कपनियो को राज्यसघ से प्राप्त राजस्व में से अनुदान, आनुतोपिक या आर्थिक सहायता देने के सदभ में भेदभाव वरत ।

इन शतनामा' से पता चलता है भारत में ब्रिटिश महाजनी पूजी को मजबूत सुरक्षा देने के बारे में अंगरेज कितने चिंतित थे । इन शतनामा की वजह से भारतीय उद्योग, व्यापार या नौपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए या विशेष रियायत एवं आर्थिक सहायता देने के लिए (ठीक उसी तरह जिस तरह ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में वहां के उद्योग व्यापार या नौपरिवहन के साथ करती है) तब तब अनुमति नहीं मिलती थी जब तक भारत में ब्रिटेन के औद्योगिक तथा व्यापारिक हितों को भी वैसे ही सुविधाएं न दी जाए ।

शेप जिन क्षेत्रों में कानून बनाने की छूट थी भी, वहां विधानमंडल के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था । यदि विधानमंडल न किसी ऐसे विधेयक को पारित कर दिया जिसे सरकार नहीं पसंद करती थी और मान लें कि घोर प्रतिक्रियावादी मंत्रिपरिषद ने भी उस विधेयक को पारित कर दिया तो गवर्नर जनरल अपनी सहमति को एकदम 'रोक' रखता था । दूसरी ओर, गवर्नर जनरल अपनी सहमति को यह कहकर 'रोक' सकता था कि विधेयक पर अभी और विचार करने की जरूरत है और यदि 12 महीनों तक उसने अपनी सहमति 'रोक' रखी तो विधेयक रद्द कर दिया जाता था । यदि उसने अपनी सहमति दे दी तो और बाद में उसने सोचा कि यह गलत हुआ है तो वह उसे बाद में 'अस्वीकार' कर सकता था ताकि वह रद्द हो जाए ।

दूसरी तरफ यदि विधानमंडल किसी ऐसी कायवाही को स्वीकृति देने में विफल रहता है जिसे सरकार आवश्यक समझती हो तो गवर्नर जनरल उसे 'गवर्नर जनरल का कानून' कहकर पारित कर सकता था और यह कायवाही उतनी ही शक्तिशाली होती जितना कोई भी साधारण कानून । विक्ल्प के रूप में गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, इन अध्यादेशों को छ महीने तक कानून के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता था । इसी तरह के 'अधिकार' इस 'विधानमंडल' के पास थे । इसके चयन में की गई मेहनत बेकार ही प्रतीत हुई होगी ।

लेकिन इन सारी बातों से साम्राज्यवादी शासकों के एहतिषात में एकदम कमी नहीं आई । वे स्पष्टतः इस बात से पूरी तरह निश्चित होना चाहते थे कि व्यवस्था के बद दरवाजों से स्वराज्य की किसी फुसफुसाहट के भी अदर जाने की गुंजाइश न रहे । हम अभी और भी विस्तार से इन सुरक्षित अधिकारों और 'सुरक्षा उपायों' के मोहक रूप की जांच करनी होगी ।

जब हम विधानमंडल के 'अधिकार' से होकर गवर्नर जनरल के अधिकार तक पहुँचते हैं तो हम अघेरे से एकदम उजाल में पहुँच जाते हैं। कानून की कम से कम 94 धाराएँ ऐसी थीं जिन्होंने गवर्नर जनरल को खद ही नियम लेने के विशेष अधिकार दे दिए थे। इस प्रकार कोई भी गवर्नर जनरल अपने आप लिए गए नियम के आधार पर (अर्थात् मंत्रियों या निर्वाचित सभाओं को किसी सलाह के बिना) निम्न कार्य कर सकता था

- 1 मंत्रियों की नियुक्ति या बरखास्तगी,
- 2 विधानमंडल द्वारा पारित कानून पर वीटो,
- 3 विधानमंडल द्वारा नामजूर कानून का पारित करना,
- 4 कानून के बारे में बहस पर प्रतिबन्ध,
- 5 अध्यादेश जारी करना,
- 6 प्रांतीय गवर्नरों का अध्यादेश जारी करने का निर्देश,
- 7 प्रांतीय कानूनों पर वीटो का इस्तेमाल,
- 8 पुलिस के लिए कायदे कानून जारी करना,
- 9 सेना के इस्तेमाल को अपने अधीन रखना,
- 10 विधानमंडल भंग करना,
- 11 संविधान को स्थगित करना।

यह उसके कुछ चुने हुए मनमाने अधिकारों की सूची है। इसी के साथ साथ उसके पास कुछ सुरक्षित अधिकार भी थे। सुरक्षित विभागों के रूप में उसके एकदम अपने नियंत्रण में रक्षा, विदेश, वार्षिक बजट तथा वज्रित क्षेत्र से संबंधित विभाग थे। और अतः कुछ ऐसे विशेष अधिकार हैं जिनका मकसद यह है कि यदि इन सबके बाद भी बचाव के किसी रास्ते के बन्द रहने की आशंका हो तो उस रोक जा सके। गवर्नर जनरल के पास आठ 'विशेष जिम्मेदारियाँ' थीं जिनके पालन के लिए वह व्यक्तिगत तौर पर जिस भी तरह की कार्यवाही आवश्यक समझे कर सकता था। इन 'विशेष जिम्मेदारियों' (आमतौर से इन्हें 'सुरक्षा उपाय' कहा जाता था हालांकि यह कानून, जादि से अत तक दरअस्त सुरक्षा उपाय ही था) के अंतर्गत निम्न बातें आती थीं

- 1 भारत या उसके किसी भी भाग में शांति या चैन के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे को रोकना,
- 2 संघीय सरकार की वित्तीय स्थिरता और साथ ही रक्षा करना,
- 3 जलमयस्कता व 'वायव्यचित हितों' की रक्षा करना,
- 4 सांख्यिकीय मेवा व सदस्या, भूतपूर्व सदस्या या उनके आधिता व 'वायव्यचित हितों' का सुरक्षा देना,
- 5 ब्रिटिश नागरिकों या भारत में काम करने वाली कम्पनियाँ व प्रति चाह व भारत



म सस्थापित हा या ब्रिटिश, वित्त एवं व्यापार संधी मामला म भेदभाव बरत जान स रोकता,

6 भारत म ब्रिटन से आयातित सामाना क प्रति भेदभाव का रचना,

7 रियासतो और राजाजा के अधिकारो की रक्षा करना,

8 और अंत म एक शानदार एवं बहुप्रयोजनपूर्ण रक्षा उपाय यह सुनिश्चित करके कि अपन कार्यों का उचित निष्पादन उन मामलो के सबध म करके, जिनक सबध म उसे इस कानून के द्वारा या अनगत अपन निणय से काय करना है, वह किसी अन्य मामले के सबध म की गई काय प्रक्रिया द्वारा समुपस्थित नहीं होता है या प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता ह ।'

संविधान का व्यापक सर्वेक्षण करने क उद्देश्य से अधिनियम की उन विशेष (और अति-विस्तृत) धाराओ को खोज करना एक लंबी प्रक्रिया होगी जिनम ब्रिटिश महाजनों पूजो के प्रत्यक्ष हिता, व्यापार और पूजो निवेश, भारत मे काम करने वाली ब्रिटिश कंपनियो, ऋण, रेलवे, बैंका जादि के हिता का विशेष तौर पर सुरक्षा दी गई है या स्वतंत्र प्राधिकरणो के अंतगत रखा गया है। लेकिन यह निश्चय ही कहा जाना चाहिए कि अधिनियम की इन्ही धाराओ से हम समूचे संविधान के असली कार्यों का पता चलता है कि वह किस तरह भारत म ब्रिटिश महाजनों पूजो के शोषण की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया एक सुव्यवस्थित तंत्र है।

संविधान की जो प्रांतीय धाराएं हैं वे केंद्र के निरक्षुज और प्रतिक्रियावादी रचनातंत्र के मातहत ह। सामान्यतः प्रांता की राज्यव्यवस्था केंद्रीय राजतंत्र के मनोनूकूल अशा का ही जरा नरम रूप प्रस्तुत करती है। प्रांतीय गवर्नर के पास भी इन मारी धाराओ से बढ़कर अधिकार है, वह किसी कानून को वीटो कर सकता है या स्वतंत्र कानून पास कर सकता है। पुलिस, कानून और व्यवस्था तथा वित्तप्रबंध पर उसका कारगर नियंत्रण रहता है और उसके पास भी सात विधेय जिम्मेदारिया होती ह। इसी प्रकार विधान-मंडला का गठन भी सांप्रदायिक आधार पर हुआ होता है और ऊपरी सदनों को जिनका पहले किसी प्रांत म अस्तित्व न था बंगाल, बर्मा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बिहार जैसे सभी प्रमुख प्रांता पर थाप दिया गया ह।

तो भी, यह तंत्र केंद्र की तुलना म प्रांतो म ज्यादा लचीला है और केंद्र की तुलना म यहा जनआदालता की ज्यादा गुंजाइश रहती है। इसके निम्न कारण है

पहली बात ता यह है कि प्रांता म राजाजो का अस्तित्व नहीं होता। विधानमंडला का पूरी तरह और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है हालांकि ऊपरी सदन का स्वरूप प्रति-प्रियावादी है और उनका गठन अत्यंत सामित मतधिकार के आधार पर किया गया ह। दूसरी बात यह है कि प्रांती म केंद्र की तरह आरक्षित विभाग नहीं हैं हालांकि पुलिस के

मामले में विशेष व्यवस्थाएँ हैं। पुलिस के लिए निर्धारित नियम खुद गवर्नर के अधीन होते हैं, खुफिया पुलिस या राजनीतिक पुलिस को विशेष अधिनियमों के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती है और यहाँ तक कि उनके कार्यों से संबंधित कामजात भारतीय मतियों को भी देखने को नहीं उपलब्ध हो सकते, पुलिस का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आंदोलन का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है जिसका उद्देश्य यह समझा जाए कि 'कानून द्वारा स्थापित सरकार का तख्ता पलटना' है। गवर्नर यदि यह महसूस करता है कि 'प्रात की शांति और सुख चैन के लिए खतरा है।' तो यह किसी भी तरह का कदम, जो वह उचित समझे, उठा सकता है। सत्ता के वान्तविक तंत्र के सदस्य में इन अत्यंत जबरदस्त नियंत्रणों के अधीन, प्रांतीय सरकार कुल मिलाकर प्रशासन के लिए कार्य संचालन करती है और वह एक सीमा तक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकती है। तीसरी बात यह है कि विधि निर्माण के मामले में यहाँ केंद्र जैसे व्यापक नियंत्रण नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि विधि निर्माण के अधिकार यहाँ अपक्षतया व्यापक है बल्कि इसलिए क्योंकि वे और भी ज्यादा सकीण हैं, ऐसे मामले जिनका स्वरूप अखिल भारतीय होता है और जो ब्रिटन के विशेष हिता को या आर्थिक वृत्तीय सत्ता को प्रभावित करते हैं, प्रांतों में पैदा ही नहीं हो सकते। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि प्रांतों में लोकप्रिय मजिस्ट्रेट काय संचालन कर सकें और यहाँ वे शासक की नहीं बल्कि एकदम उपयोगी तत्व की भूमिका निभाएँ।

ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 10 हजार थी जो कुल आबादी का 11 प्रतिशत ही थी (जबकि माटेगु चेम्सफोर्ड के संविधान में इसे 28 प्रतिशत बताया गया था)। ब्रिटन की निसाल लें तो पता चलता कि वहाँ 67 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार प्राप्त करने की योग्यता मुख्यतया वयस्कता पर, कर देने की क्षमता पर और एक निश्चित मूल्य की काशत पर निर्भर थी, इसके अलावा साक्षर होना जरूरी था। महिला मतदाताओं की संख्या 43 लाख थी। 1937 के चुनावों में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुए वहाँ मतदान में 1 करोड़ 55 लाख अर्थात् उन निर्वाचन क्षेत्रों के कुल मतदाताओं के 50 प्रतिशत हिस्से ने भाग लिया।

ग्यारह प्रांतीय विधानसभाओं में 1,585 सीटों की निम्नावित्त तरीके से बांट दिया गया है

|                   |     |
|-------------------|-----|
| सामान्य सीटें     | 657 |
| मुस्लिम           | 482 |
| अनुसूचित जाति     | 151 |
| वाणिज्य और उद्योग | 56  |
| महिलाएँ           | 41  |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| भजद्वर                    | 38 |
| भूस्वामी                  | 37 |
| सिख                       | 34 |
| यूरोपीय                   | 26 |
| पिछडे क्षेत्र और जनजातिया | 24 |
| भारतीय ईसाई               | 20 |
| आग्ल भारतीय               | 11 |
| विश्वविद्यालय             | 8  |

यह देखा जा सकता है कि इतने जबरदस्त और प्रतिक्रियावादी उपविभाजन के बावजूद सघीय विधानसभा की तुलना में यहाँ काफी अनुकूल सभावनाएँ हैं। यही वे स्थितियाँ थी जिन्होंने अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन को संभव बनाया। फिर भी यह सोच लेना गलत होगा कि इन प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों के पास अत्यंत सीमित अधिकारों से कुछ ज्यादा अधिकार थे या ये मंत्रिमंडल उन महत्वपूर्ण समस्याओं पर हाथ लगा सकते थे जिन्हें स्वराज्य प्राप्ति के बाद ही हल किया जा सकता है।

इन प्रांतीय मंत्रिमंडलों की पृष्ठभूमि में क्या चीजें हैं, यदि इसपर गौर करें तो पता चलेगा कि इनका दायरा अत्यंत सीमित है। दरअसल इनकी पृष्ठभूमि में एक ऐसी तानाशाह केंद्रीय सरकार है जिसपर अंगरेजों का नियंत्रण है, विधान के जरिए हर उस काम को या ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप को नियंत्रित कर दिया गया है जो ब्रिटिश हितों को या शासन के मूल संगठन को प्रभावित करे और साथ ही प्रांतीय गवर्नरों के पास सर्वोपरि अधिकार है। वित्त व्यवस्था के सदर्भ में ये बातें खासतौर से प्रकट हैं। आयकर और सीमा शुल्क जैसे राजस्व के बढ़ते हुए स्रोतों को केंद्र के अधीन कर दिया है (वर्शर्त-नैमेयर फॉर्मूले का अंतर्गत आर्थिक पुनर्निर्धारण का कुछ प्रबंध हो) और केंद्र का 30 प्रतिशत बजट ऐसा होता है जिसपर भारतीय प्रतिनिधियों का मत नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे व्यय के सभी रचनात्मक स्वरूप प्रांतों को सौंप दिए गए हैं जबकि राजस्व के अपने मुख्य स्रोतों के लिए उन्हें अत्यंत बोझिल, अनम्य और अलोकप्रिय माल-गुजारी का बोझ दे दिया गया है जिसे कम करने की जबरदस्त जरूरत है। इस तरह के विभाजन का मकसद बहुत स्पष्ट है, साम्राज्यवादियों ने इस विभाजन द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडलों के काम में बाधा डालने की कोशिश तो की ही है साथ ही यह भी चाहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सभी आवश्यक सामाजिक सेवाओं और रचनात्मक विकास के मामले में वे जो उपक्षा वरतते हैं उसके लिए प्रांतीय मंत्रिमंडलों को जिम्मेदार ठहराया जाए और उनकी बदनामी हो।

परिणामतः प्रांतीय मंत्रिमंडलों को किसी भी अर्थ में स्वराज्य की प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अत्यंत सीमित क्षेत्रों में उनके अधिकारों पर भारी

प्रतिबन्ध लगा दिया गया है वरिन् सबसे बढकर इसलिए कि वे भारतीय जनता के अत्यन्त आवश्यक और बुनियादी मसलो पर हाथ ही नहीं लगा सकत ह । प्रमुख प्रातो म कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के गठन से पता चलता है कि स्वराज्य के लिए सघष म राष्ट्रीय आदालन ने एव विकसित रणनीतिक स्थिति की दिशा म महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है लकिन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय आदालन की सफलता के लिए अभी सघष चलाया जाना शेष ही है ।

जितनी ही वारीकी स छानवीन की जाएगी उतनी ही अधिक, कुल मिलाकर सविधान के बारे म और खासतौर से निर्णायक सघीय कदम के सद्भ म, जानकारी प्राप्त हो जाएगी । छानवीन से पता चलता है कि इसके जरिए न केवल जनतन्त्र को नकारा गया है बल्कि भारत म साम्राज्यवादिया का शिकजा और मजबूत बनाने के लिए तथा साम्राज्य वादी शासन के ढाँचे के अंदर प्रतिनियावादी शक्तिया का पलड़ा और भारी करने के लिए एक तन्त्र की स्थापना की गई है । 'जिम्मेदारी' की बात एक मखौल थी । साम्राज्य वाद की शक्ति को मजबूत और दढ बनाया गया था । स्वराज्य प्राप्ति का सही सघष इस सविधान की सीमाओं के अतंगत नहीं चलाया जा सका । हालांकि इस तन्त्र के जरिए कुछ गौण और प्रारम्भिक काय पूरे कर लिए गए लेकिन निर्णायक युद्ध इस सविधान के दायरे से बाहर और सविधान के विरुद्ध ही लडा जा सकता है ।

इस सविधान के बारे म किसी भी जनतान्त्रिक व्यक्ति की अंतिम राय वही हो सकती है जो ब्रिटेन के प्रमुख साविधानिक विशेषज्ञ प्रोफेसर ए० बी० कीय ने बडे कठोर और दो टूक शब्दों म व्यक्त की थी

इस धारणा से इकार करना मुश्किल है कि या तो जिम्मेदार सरकार की बात को खुलेआम असंभव घोषित किया जाए या सचाई को स्वीकार कर लिया जाए । इसमें कोई आश्चय नहीं कि विशेष जिम्मेदारियों वाली यह प्रणाली जैसी है वैसी दोगली रचना क लिए न तो स्वेच्छापूर्वक लोगो की कृतज्ञता सुलभ है और न सहयोग और सारे काय व्यक्तिगत फैसेले के अनुसार किए जाने हे ।

सघीय योजना के लिए किसी तरह के मतौप का अनुभव किया जाना कठिन है । जिन इकाइयों से इसकी रचना की गई है वे इतनी विषम है कि उन्हें ठीक से एक साथ नहीं रखा जा सकता और यह बात काफी स्पष्ट है कि अंगरेजा की तरफ से इस योजना का समर्थन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे विशुद्ध कट्टरवादिता का तत्त्व दिया जा सके जिससे ब्रिटिश भारत द्वारा प्रदान किए गए जनतन्त्र के हर खतरनाक तत्त्व का मुकाबला किया जा सके । भारत म इस दावे स इकार करना कठिन है कि मोटे तौर पर राज्यसघष की उत्पत्ति के पीछे यह इच्छा काम कर रही थी कि जिम्मेदार सरकार का ब्रिटिश भारत

म केंद्र सरकार तक विस्तार देने के मामले को टाल दिया जाए। इसके अलावा, रक्षा विभाग और विदेश विभाग को सधीय नियन्त्रण म देने से रोके रखना, जो इस प्रक्रिया मे अवश्यभावी है, जिम्मेदारी का कथित अनुमोदन प्रस्तुत करता है लेकिन यह सब व्यथ है। (प्रोफेसर ए० बी० कीथ, ए कास्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1600-1935, 1936, पृष्ठ 473-74')

प्रतिपक्ष लगा दिया गया है बल्कि सबसे बढ़कर इसलिए कि वे भारतीय जनता के अत्यंत आवश्यक और बुनियादी मसलों पर हानि ही नहीं लगा सकते हैं। प्रमुख प्राप्ति में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन से पता चलता है कि स्वराज्य के लिए संघ में राष्ट्रीय आंदोलन न एक विकसित रणनीतिक स्थिति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 'राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए अभी संघ चलाना जाना शेष ही है।

जितनी ही बारीकी से छानबीन की जाएगी उतनी ही अधिक, कुल मिलाकर संविधान के ताने में और खासतौर से निर्णायक संघीय कदम के संदर्भ में, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। छानबीन से पता चलता है कि इसके जरिए न केवल जनतंत्र को नकारा गया है बल्कि भारत में साम्राज्यवादियों का शिक्षा और मजबूत बनाने के लिए तथा साम्राज्यवादी शासन के ढांचे के अंदर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ का पलड़ा और भारी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। 'जिम्मेदारी' की बात एक मखौल थी। साम्राज्यवाद की शक्ति को मजबूत और दृढ़ बनाया गया था। स्वराज्य प्राप्ति का मही संघ इस संविधान की सीमाओं के अंतर्गत नहीं चलाया जा सका। हालांकि इस तंत्र के जरिए कुछ शौण और प्रारंभिक काम पूरे कर लिए गए लेकिन निर्णायक मुद्दे इस संविधान के दायरे से बाहर और संविधान के विरुद्ध ही लड़ा जा सकता है।

इस संविधान के बारे में किसी भी जनतांत्रिक व्यक्ति की अतिशय बड़ी हो सकती है जो ब्रिटन के प्रमुख सांविधानिक विशेषज्ञ प्रोफेसर ए० बी० कीथ ने बड़े बठोर और दो ठूक शब्दों में व्यक्त की थी

इस धारणा से इकार करना मुश्किल है कि या तो जिम्मेदार सरकार की बात को छुलेआम असंभव घोषित किया जाए या मचाई को स्वीकार कर लिया जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विरोध जिम्मेदारियों वाली यह प्रणाली जैसी है वसी दोगली रचना के लिए न तो स्वच्छापूर्वक लागू की कृतज्ञता मुलभ है और न सहयोग और सारे कार्य व्यक्तिगत फँसले के अनुसार किए जाने हैं।

संघीय योजना के लिए किसी तरह के मतभेद का अनुभव किया जाना कठिन है। जिन इकाइयों से इसकी रचना की गई है वे इतनी विपरीत हैं कि उन्हें ठीक से एक साथ नहीं रखा जा सकता और यह बात काफी स्पष्ट है कि अंगरेजों की तरफ से इस योजना का समर्थन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे विभिन्न कट्टरवादिता का तत्त्व दिया जा सके जिससे ब्रिटिश भारत द्वारा प्रदान किए गए जनतंत्र के हर घटकनाम तत्त्व का मुकाबला किया जा सके भारत में इस दावे से इकार करना कठिन है कि माट तौर पर राज्यमण को उत्पत्ति के पीछे यह इच्छा काम कर रही है कि जिम्मेदार सरकार का ब्रिटिश भारत

भ केंद्र सरकार तक विस्तार देने के मामले को टाल दिया जाए। इसके अलावा, रक्षा विभाग और विदेश विभाग को सघीय नियंत्रण में देने से रोके रखना, जो इस प्रक्रिया में अवश्यभावी है, जिम्मेदारी का कथित अनुमोदन प्रस्तुत करता है लेकिन यह सब व्यर्थ है। (प्रोफेसर ए० बी० कीथ, 'ए कास्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1600-1935, 1936, पृष्ठ 473 74')

प्रतिपक्ष लगा दिया गया है वल्कि सपस उड़कर इसलिए विष भारतीय जनता के अल्पत आवश्यक और चुनियादी मसला पर हान ही नहीं लगा सकत ह । प्रमुख प्राता में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के गठन से पता चलता है कि स्वराज्य क लिए सघष म राष्ट्रीय आंदोलन ने एक विकसित रणनीतिक स्थिति की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है त्विन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की सफनता के लिए अभी सघष चलाया जाना सेष ही है ।

जितनी ही बारीकी से छानबीन की जाएगी उतनी ही अधिक, कुल मिलाकर सविधान के बारे म और खासतौर से निर्णायक सघीय कद्र क सदम म, जानकारी प्राप्त हो जाएगी । छानबीन से पता चलता है कि इसके जरिए न केवल जनतत्व की नकारा गया है वल्कि भारत म साम्राज्यवादिया का शिकजा और मजबूत बनाने के लिए तथा साम्राज्य वादी शासन के ढांचे के अंदर प्रतिक्रियावादी शक्तिया का पलड़ा और भारी करने के लिए एक तत्व की स्थापना की गई है । जिम्मेदारी की बात एक मखौल थी । साम्राज्य वाद की शक्ति को मजबूत और दृढ़ बनाया गया या । स्वराज्य प्राप्ति का सही सघष इस सविधान की सीमाओं के अतगत नहीं चलाया जा सका । हालांकि इस तत्व के जरिए कुछ गौण और प्रारम्भिक काय पूरे कर लिए गए लेकिन निर्णायक युद्ध इस सविधान के दायरे से बाहर और सविधान के विरुद्ध ही बढ़ा जा सकता है ।

इस सविधान के बारे मे किसी भी जनतांत्रिक व्यक्ति की अंतिम राय वही हो सकती है जो ब्रिटेन के प्रमुख साविधानिक विशेषज्ञ प्रोफेसर ए० बी० कीथ ने बड़े कठोर और दो टूक शब्दा म व्यक्त की थी

इस कारण से इकार करना मुश्किल है कि या ना जिम्मेदार सरकार की बात को खुलेआम असभव घोषित किया जाए या सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए । इसम कोई आश्चर्य नहीं कि विशेष जिम्मेदारियों वाली यह प्रणाली जैसी ह वसी दागली रचना के लिए न तो म्वेच्छापूर्वक लोगा की कृतज्ञता मुलभ है और न सहयोग और सार काय व्यक्तिगत फंसले के अनुसार किए जान है ।

सघीय योजना के लिए किसी तरह क सताप का अनुभव किया जाना कठिन है । जिन इकाइयों से इसकी रचना की गई है वे इतनी विषम है कि उन्हें ठीक से एक नाथ नहीं रखा जा सकता और यह बात काफी स्पष्ट है कि अगरजा की तरफ से इस योजना का समर्थन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे विशुद्ध बट्टरवादिता का तत्व दिया जा सक जिसम ब्रिटिश भारत द्वारा प्रदान किए गए जनतत्व के हर छतरनाक तत्व का मुकाबला किया जा सक । भारत म इस दाब से इकार करना कठिन है कि मादे तौर पर राज्यसभ की उत्पत्ति के पीछे यह इच्छा काम कर रही थी कि जिम्मेदार सरकार का ब्रिटिश भारत





## युद्ध की पूर्वसंध्या में राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति

दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 'स्वाधीनता' शब्द को अधिग्रहण का रूप दे दिया है। भारतीय मामलों के मंत्री, दि. मारकस आफ जेटलैंड का एक सवाददाता सम्मेलन में कथन 11 फरवरी 1940।

1930-34 के महान जनसंघर्षों के बाद से भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उस हम बहुत साफ तौर पर दो अवस्थाओं से गुजरता देख सकते हैं। पहले चरण में हम देखते हैं कि जबरदस्त दमन शेलन के बाद संगठन के पुनर्निर्माण का काम हुआ और नई नीतियाँ तैयार की गईं जिसके बाद चुनावों तथा प्रांतों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के गठन के जरिए संगठन ने इतनी प्रगति की कि उसका एक तरह से दबदबा कायम हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 1934 से 1939 तक के वर्षों की यह उपलब्धि है। दूसरे चरण में हम देखते हैं कि संकट गहरा होता गया। इसकी प्रारम्भिक झलक 1938-39 में ही मिल गई थी। युद्ध के बाद से ही गंभीर संकट पैदा हो गया था जिसने नए संघर्षों को जन्म दिया।

### 1 नवजागरण

1934 में जनसंघर्ष और सरकारी दमन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था इसीलिए 1936 के वसंत में जब राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ उस समय तक कांग्रेस जबरदस्त संघर्षों और सरकारी दमन से प्रभावित अपनी ताकत सभालन में लगी थी। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 457,000 तक पहुँच गई थी। 1934-36 के दौर में कांग्रेस की पराजय का जो तात्कालिक असर पड़े था वे बरकरार थे और कोई नई

प्रगति अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। 1934 में कांग्रेस के बर्बई अधिवेशन में पारित प्रतिक्रियावादी मविधान का, जो गांधी की विदा विरासत था, निस्संदेह एक प्रतिवधकारी प्रभाव था (लखनऊ अधिवेशन में इसमें आंशिक रूप से संशोधन करना पड़ा था)। सारी गतिविधियाँ संसदीय क्षेत्र में आकर केंद्रित हो गई थी, 1934 के अंत में कांग्रेस ने विधान सभा के चुनावों में हिस्सा लिया। लेकिन इस संसदीय गतिविधि का बहुत साधारण स्वरूप था और इन गतिविधियों के प्रति आम जनता में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा हो सकी। लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बिना किसी लाग लपेट के वर्तमान स्थिति की कमजोरियों की आलोचना की और कहा 'हम मोटे तौर पर जनता के साथ अपना संपर्क खो चुके हैं।'

लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष पद से जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ कहा वह अविस्मरणीय है। इसका कारण यह है कि इस अधिवेशन में उन्होंने समाजवादी लक्ष्यों की घोषणा की, फासीवाद और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध दुनिया की जनता के बढ़ते संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता के संघर्ष को सामने रखा और साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक ऐसा व्यापक जनमोर्चा या 'संयुक्त जन मोर्चा' बनाने की मांग की जिसमें मजदूरों और किसानों का मध्यवर्गीय तत्वों के साथ, जिनका कांग्रेस में प्रतिनिधित्व है, एकताबद्ध किया जा सके। सभी दिशाओं में एक नई हलचल दिखाई पड़ने लगी थी। कांग्रेस के अंदर समाजवादी खेमा मजबूत होता जा रहा था। लखनऊ अधिवेशन में यह समाजवादी गुट संख्या की दृष्टि से तो छोटा था पर जैसे काफी महत्वपूर्ण था लेकिन 1936 में जब फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय कांग्रेस कमेटी के एक तिहाई सदस्य समाजवादी धर्म के ही थे। लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने प्रस्ताव रखा था कि मजदूरों और किसानों के संगठनों को सामूहिक तौर पर कांग्रेस के साथ संघर्ष कर दिया जाए पर यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को 35 के विरुद्ध 16 मतों से नामजूर कर दिया और इस विषय पर विस्तार से विचार करने के लिए एक 'जन संपर्क समिति' के गठन की बात कही। जनता और जनता के सामाजिक आर्थिक हितों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाने की जरूरत सभी लोग महसूस कर रहे थे। अभी तक सारा ध्यान चरखे पर और जनता का जीवनस्तर सुधारने पर केंद्रित था लेकिन अब किसानों की वास्तविक मांगों को लेकर एक ठोस कृषीय कार्यक्रम को व्यापक रूप देने की कोशिशों की जान लगी। फैजपुर अधिवेशन में एक 13 सूत्री अस्थायी कृषीय कार्यक्रम मंजूर किया गया। इसमें शामिल मांगों में लगान और मालगुजारी कम करने, कृषि की राशि घटाने या समाप्त करने, बंधुआ मजदूरी और जमींदारों के पावने की प्रथा समाप्त करने, खेतिहर मजदूरों के लिए एक उचित मजदूरी निर्धारित करने तथा बहुत सामान्य रूप में ही सही किसानों को यूनियन बनाने का अधिकार देने की मांगें शामिल थीं।

अप्रैल 1936 में संपन्न लखनऊ अधिवेशन से ही 'राष्ट्रीय कांग्रेस का आधुनिक' इतिहास प्रारंभ होता है। इस काल में कांग्रेस के बामा में जबरदस्त तेजी आई। दिसंबर 1936 में

फैजपुर रजिस्ट्रेशन होने के समय तब कांग्रेस की सदस्यता की संख्या बढ़कर 636 000 हो गई। 1937 की समाप्ति तक चुनावों और प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन के बाद यह संख्या 50 लाख से भी अधिक हो गई। फरवरी 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन हुआ तो सदस्यता की संख्या 3,102 000 तक पहुँच गई थी। 1938 खत्म होते होते 40 लाख से भी अधिक लोग कांग्रेस के सदस्य हो चुके थे। इनमें से अकेले संयुक्त प्रांत में साढ़े बारह लाख सदस्य थे। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के समय सदस्यों की संख्या करीब करीब 50 लाख हो चुकी थी।

## 2 1937 के चुनावों में विजय

नए संविधान के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रुझान था इसकी सिद्धांत रूप में घोषणा 1934 में ही उस समय हो गई थी जब संविधान सभा की मांग को मंजूर किया गया था। आने वाले वष में नए अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के फैसले को तखनऊ अधिवेशन ने अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1936 में चुनाव घोषणापत्र जारी किया गया जिसका अनुमोदन फैजपुर अधिवेशन ने कर दिया। दिसंबर 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव ने, चुनाव लड़ने के सदस्य में कांग्रेस के निश्चित दृष्टिकोण की घोषणा कर दी

देश की जनता की स्थापित आकांक्षा के विरुद्ध भारत पर थोपे गए संविधान और 1935 के भारत रक्षा अधिनियम को यह अधिवेशन एक बार फिर पूरी तरह अस्वीकार करने की घोषणा करता है। अधिवेशन की यह धारणा है कि इस संविधान के माध्यम से किसी भी तरह का सहयोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात होगा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ को मजबूत बनाना होगा तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्व के जुए तले बेहद गरीबी की चक्की में पहल से ही पिस रही जनता का शोषण और भी अधिक बढ़ाना होगा। इसलिए अधिवेशन एक बार फिर अपने इस सबूत को दोहराता है कि कांग्रेस ने तो इस संविधान के सामने आत्मसमर्पण करेगी और न इससे साथ सहयोग करेगी बल्कि वह विधानमंडल के बाहर और भीतर हर जगह इसके खिलाफ संघर्ष करेगी ताकि इसका अंत कर सके। कांग्रेस किसी विदेशी शक्ति या सत्ता द्वारा भारत के राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे को संचालित करने की बात को कभी मान्यता नहीं देती है और न देगी और इस तरह के हर प्रयास का भारतीय जनता के संगठित और दृढ़ प्रतिनिधि विरोध द्वारा मुकाबला किया जाएगा। भारतीय जनता जबल उस संविधानिक ढाँचे का अपनी मंजूरी देगी जिसका निमाण स्वयं उसने किया हो और जो एक राष्ट्र के रूप में भारत की आजादी पर आधारित हो तथा जो उनकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विकास का उद्देश्य पूरा करे।

कांग्रेस भारत में एक ऐसे वास्तविक जनवादी राज्य की स्थापना के पक्ष में है

जिसमें राजसत्ता का हस्तांतरण कुल मिलाकर जनता को कर दिया गया हो और सरकार जनता के प्रभावकारी नियंत्रण में रहे। ऐसे राज्य की स्थापना संविधान सभा के जरिए ही हो सकती है जो बालिग मताधिकार पर आधारित हो तथा जिसके पास इतना अधिकार हो कि वह देश के संविधान के बारे में अंतिम और निष्पक्ष फैसले करे। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस देश में काम कर रही है और जनता को संगठित कर रही है। विधानमंडल में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी हमेशा यही बात ध्यान में रखनी होगी।

नए संविधान के अंतर्गत विधानमंडलों के लिए निर्वाचित कांग्रेस सदस्य कोई पद स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इसका फैसला प्रांतीय चुनावों के समाप्त होते ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी।

पद स्वीकार करने के मामले पर फैजपुर अधिवेशन में मतभेद था। बहुमत की राय यह थी कि इस विषय में किसी तरह के फैसले को अभी स्थगित रखा जाए। डा. जे. बी. साहू (मेरठ पड़ोस के अभियुक्त और कम्युनिस्ट नेता) ने एक संशोधन पेश किया जिसमें संविधान सभा का गठन संभव बनाने के लिए जनसंघ की तैयारी करने की बात थी लेकिन कांग्रेस कमेटी ने 45 के विरुद्ध 83 मतों से और कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन ने 62 के विरुद्ध 451 मतों से इस प्रस्ताव को नामजूर कर दिया। कोई पद निश्चित रूप से स्वीकार न करने के बारे में प्रस्तुत संशोधन को कांग्रेस कमेटी ने 48 के विरुद्ध 87 मतों से नामजूर कर दिया।

चुनावों में कांग्रेस ने एक ऐसे संगठन के रूप में भाग लिया जो अखिल भारतीय था। विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव के मद्दान में उतरने के लिए सांप्रदायिक और मौलसी पार्टियों का एक जुट तैयार हो गया। ये पार्टियां जल्दी जल्दी बनाई गई थीं और इनकी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय कांग्रेस संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में डटती रही। इस राष्ट्रीय एकता, पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता के लक्ष्य की दृढ़ घोषणा, सामूहिक गिरफ्तारियों और गैरसांविधानिक तरीकों से चलाए गए जनआंदोलनों से भरे संघर्षों का इतिहास ही वह पहला कारण था जिसने चुनावों में कांग्रेस की विजय को संभव बनाया।

कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र एक ऐसा दस्तावेज था जिसने पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता और संविधान सभा की उपलब्धि के लक्ष्य को प्रमुख स्थान दिया। साम्राज्यवादी संविधान की बिना शर्त भत्सना की ओर विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि भेजने का मकसद स्पष्ट किया कि 'वह वहां किसी भी प्रकार का सहयोग करने नहीं बल्कि अधिनियम के खिलाफ जमकर संघर्ष करने और उसे समाप्त करने जा रहे हैं।' इसमें जलावा चुनाव घोषणापत्र सामान्य सिद्धांतों पर नहीं टिका था। इसमें एक ठोस और तात्कालिक कार्यक्रम भी तैयार किया जिसमें नागरिक स्वातंत्र्य और समान अधिकारों की जनवादी मांगें थीं तथा एक ऐसा

सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम था जो जनता के व्यापक हिस्से को अनुकूल लगे। चुनावों में कांग्रेस की जीत का यह दूसरा कारण था।

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जो सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वह वाद में गठित कांग्रेस मन्त्रिमंडल की नीतिनिर्धारण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। उसके प्रमुख अंशों में कहा गया था

कांग्रेस महसूस करती है कि इन विधानमंडलों से न तो आजादी प्राप्त की जा सकती है और न गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याओं का कारगर हल ढूँढ़ा जा सकता है। फिर भी कांग्रेस भारत की जनता के सामने अपना आम कार्यक्रम रख रही है ताकि उन्हें पता चल सके कि कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है और कांग्रेस के हाथों में जब शासन की बागडोर होगी तो वह किस लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगी।

1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के आम लक्ष्य को मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव में परिभाषित किया गया था। वह आम परिभाषा आज भी बनी हुई है। फिर भी पिछले पाँच वर्षों में निरंतर बढ़ते सकट के कारण यह जरूरी हो गया कि गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य आर्थिक समस्याओं पर विस्तार से विचार किया जाए।

देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक समस्या है जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी और किसानों पर लदा कज का बोझ। इनका बुनियादी कारण पुरातन और दमनात्मक भूमि व्यवस्था और लगान प्रणाली है। इसके साथ ही हाल के वर्षों में खेतिहर उत्पादनों की कीमतों में आई जबरदस्त गती ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

कराची अधिवेशन में की गई अपनी घोषणा को कांग्रेस फिर दोहराती है। कांग्रेस जमान की काश्त, मालगुजारी प्रणाली में सुधार चाहती है और खेतिहर भूमि पर पाँच प्रतिशत अधिक व्यय के पक्ष में है। इसके लिए वह किसानों को जल बाला, के " है मालगुजारी की राशि में ७५ के " है कि अलाभकार जोता का मुक्त

किसानों को चाहिए, घोषणा

वि

किया जाए तथा राज्य द्वारा आसान व्याज पर ऋण देने की सुविधा की व्यवस्था की जाए। यह राहत खेतिहर कृषकरो, किसान भूस्वामियो, छोटी जोत वाला और छोट व्यापारियो तक पहुंचाई जानी चाहिए।

जहां तक औद्योगिक मजदूरों का संबंध है कांग्रेस की नीति यह है कि उनका जीवनस्तर उन्नत किया जाए, जहां तक देश की आर्थिक स्थितिया अनुमति दें उनके काम के घंटे और श्रम की स्थितिया अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाए, कमचारियों और मालिकों के झगड़े निबटाने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, वृद्धावस्था, बीमारी और बेरोजगारी के दिनों की आर्थिक तंगी के लिए उपाय किए जाए तथा मजदूरों को यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन बना सकें और हड़ताल कर सकें।

कांग्रेस ने पहले ही घोषित कर दिया है कि वह लिंग के आधार पर किसी का आयोग्य ठहराए जान के पक्ष में नहीं है, चाहे यह कानूनी क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में अथवा सांस्कृतिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में। इसने मातृत्व संबंधी सुविधाओं और महिला श्रमिका की सुरक्षा के पक्ष में अपनी धारणा व्यक्त की है। भारत की महिलाओं ने स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है और कांग्रेस की दृष्टि में स्वतंत्र भारत में महिलाओं को भी पुरुषों जैसे ही विशेषाधिकार तथा दायित्व मिलने चाहिए।

कांग्रेस ने छुआछूत मिटाने तथा हरिजनों और पिछड़ी जाति के सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास करने पर जोर दिया है उसे सभी जानते हैं। कांग्रेस की धारणा है कि इन्हें सभी नागरिक मामलों में अन्या की तरह समाज-अधिकार मिलने चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना भी कांग्रेस के कार्यक्रम की एक मुख्य योजना रही है। जहां तक बड़े उद्योगों का संबंध है, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए पर मजदूरों और कच्चे माल के उत्पादकों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और ग्रामीण उद्योगों के हितों को उचित सम्मान मिलना चाहिए।

इस व्यापक जनतांत्रिक कार्यक्रम ने, जिसमें किसानों और औद्योगिक मजदूरों की तात्कालिक मांगें प्रत्यक्ष तौर पर मुखर हो रही थीं, चुनाव प्रचार में कांग्रेस द्वारा प्राप्त अजरदस्त जनसमर्थन (जो वास्तविक मतदाताओं से कहीं अधिक था) को सक्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

चुनाव के नतीजा ने पता चला कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अनूतपूर्व सफलता मिली उससे

सरकारी और आधिकारिक खेमे का लोग दग रह गए और इससे बहुत प्रभावशाली दग से यह पता चला कि जनता का अंदर आजादी की भावना कितनी जोर पकड़ चुकी है। सरकार ने कांग्रेस का विरुद्ध हर तरह का ताकत लगाने में कोई कसर न छोड़ी थी। चुनाव अभियान के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की हारने का प्रयास में सरकार ने सक्रिय रूप से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।

सरकार के कान खड़े हो गए थे। उसे पता था कि कांग्रेस की सफलता नए संविधान के लिए असुब है। विरोधों के बावजूद वह चुनाव के दौरान परोक्ष और अपरोक्ष रूप से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती रही। उसने कई पार्टियों के गठन में मदद की। संयुक्त प्रांत की नेशनल ऐग्रिकल्चरलिस्ट पार्टी, पंजाब की यूनिवर्निस्ट पार्टी तथा अन्य कई स्थानों पर इस तरह की पार्टियों को प्रांतीय सरकारों का समर्थन प्राप्त था (कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में महासचिव की रिपोर्ट 1938)

संयुक्त प्रांत में कोट आफ वाइस के सचिव द्वारा एक पत्रक जारी किया गया

सामान्य तौर पर खेतीवारी से सबद्ध वर्ग और खासतौर से उस वर्ग के हित के लिए जिसका हम प्रतिनिधित्व करने हैं कांग्रेस को जहां तक संभव हो सक करारी भाव देना बहुत जरूरी है। इसलिए कोट ने उस उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है जो कांग्रेस का सक्रिय रूप से विरोध करेगा जिन्हें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रांत के एक-एक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण करें और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उस उम्मीदवार की मदद के लिए खुद को तैयार रखें जो सरकार के प्रति निष्ठावान हो।

इस पत्रक को जारी करने के तदर्थ में सरकारी तौर पर खेद व्यक्त किया गया लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हर संभव प्रभाव का इस्तेमाल किया गया मले ही हर बार ऐसा इतना खुलकर न किया गया हो।

कांग्रेस का कितने बड़े पैमाने पर सफलता मिली इसकी जानकारी हम चुनाव परिणामों से पा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा विजित कुल 715 सीटों का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब हम यह याद करते हैं कि कुल 1585 सीटों में से, दरअसल, 657 सीटें ही ऐसी थीं, जो खुली प्रतियोगिता के लिए थी और किसी विशेष वर्ग के लिए जलग नहीं की गई थी।

कांग्रेस को मद्रास (ऊपरी सदन में भी) ववाई संयुक्त प्रांत, बिहार (ऊपरी सदन में भी), मध्यप्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल और असम में इस जगह की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला। तिवरत पार्टी का लोगा रो (अर्थात् नरमदलिया को) हर जगह भात पानी पड़ी। जस्टिस पार्टी (पुरानी गरम्राहण पार्टी) का पूर्ण तरह सफाया



हा गया जबकि एक समय मद्रास में उसकी धाक जमी हुई थी। उसे कुल सीटों के बारहवें भाग से भी कम सीटें मिलीं। इस पार्टी पर सरकार की कृपा भी थी। इसी प्रकार सरकार की कृपाप्राप्त 'नेशनल ऐग्रिकल्चरलिस्ट पार्टी' को संयुक्त प्रांत में और भी बुरे दिन देखने पड़े। कांग्रेस की हालत फल पंजाब और सिंध में बुरी रही।

### प्रांतीय चुनावों के परिणाम, 1937

| प्रांत         | कुल सीटें | सबके लिए सामान्य सीटें | कांग्रेस | मुस्लिम लीग | मुस्लिम सीटें निवर्तनीय | शेष              |
|----------------|-----------|------------------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|
| मद्रास         | 215       | 116                    | 159      | 11          | —                       | 45 <sup>1</sup>  |
| बंबई           | 175       | 99                     | 88       | 20          | 10                      | 57               |
| बंगाल          | 250       | 48                     | 50       | 10          | 43                      | 117 <sup>2</sup> |
| संयुक्त प्रांत | 228       | 120                    | 134      | 27          | 30                      | 37 <sup>3</sup>  |
| पंजाब          | 175       | 34                     | 18       | 1           | —                       | 156 <sup>4</sup> |
| बिहार          | 152       | 71                     | 98       | —           | 15                      | 39               |
| मध्य प्रांत    | 112       | 64                     | 71       | —           | 14                      | 27               |
| अजमेर          | 108       | 40                     | 35       | 9           | 14                      | 50               |
| सरहदी सूबा     | 50        | 9                      | 19       | —           | 2                       | 29               |
| उड़ीसा         | 60        | 38                     | 36       | —           | —                       | 24               |
| सिंध           | 60        | 18                     | 7        | —           | —                       | 53               |
| कुल योग        | 1,585     | 657                    | 715      | 108         | 128                     | 634              |

- 1 जस्टिस पार्टी सहित, 17। 2 प्रजा पार्टी सहित, 38।  
3 नेशनल ऐग्रिकल्चरलिस्ट पार्टी सहित, 16। 4 ज्यादातर यूनियनिस्ट पार्टी।

कांग्रेस का जिन सीटों पर सफलता मिली, वे लगभग सारी सीटें 'सामान्य' वर्ग की थीं। जिन 58 मुस्लिम सीटों के लिए चुनाव हुआ उनमें से 26 पर कांग्रेस का सफलता मिली (15 सीटें सरहदी सूबा में)। मजदूर, सिपाही और ईसाइयों के लिए निर्धारित कुछ सीटों पर भी सफलता मिली। नूस्वामियों के लिए निर्धारित 4 सीटों और वाणिज्य तथा उद्योग के लिए निर्धारित 3 सीटें भी कांग्रेस को मिलीं।

चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता का साम्राज्यवादियों के सोच पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस का अभी तक एक 'सामूली अल्पमत' का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानकर चलने वाले समाचारपत्र 'लंदन टाइम्स' को मजबूर होकर अपनी इस धारणा को पूरी तरह तिलाजलि देनी पड़ी और लिखना पड़ा

एक बार फिर भारत के चुनावों में दिखा दिया कि केवल कांग्रेस पार्टी ही ॥

पार्टी है जिसका महज प्रांतीय आधार पर संगठन नहीं है। इसकी सफलताओं का नेखा जोखा अत्यंत प्रभावशाली है कांग्रेस का काम कुन मिलाकर बहुत अच्छा रहा और हालांकि इसका श्रेय काफी हद तक कांग्रेस के उत्तम संगठन की और अपेक्षाकृत दबियानूस तर्कों की फूट तथा उनके संगठन की कमी का है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की इन तमाम सफलताओं का कारण महज यही बातें थीं। इस पार्टी के तमाम प्रस्ताव, अधिकांश विपक्षी पार्टियों के प्रस्तावों की तुलना में ज्यादा मनोवांछनीय और रचनात्मक रहे हैं। ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में जहाँ इसे आवश्यक जनक सफलता मिली है, इसने ग्रामीण सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम सामने रखा। पार्टी को ऐसे मतदाताओं के कारण विजय मिली जिनमें उन लाखों करोड़ों लोगों की दिलचस्पी है जो गांधी में रहते हैं और मतदाता हैं और जो मतदाता नहीं हैं ऐसे लाखों लोगों की भी दिलचस्पी है। ( 'दि टाइम्स', 9 मार्च 1937 )

अंतिम मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि साम्राज्यवादियों ने समूची चुनाव प्रणाली को खारों में बांटकर उसे अत्यंत सीमित कर रखा था फिर भी मतदान में भाग लेने वाले 1 करोड़ 55 लाख लोगों तथा उनके द्वारा कांग्रेस को मिले अपार बहुमत से पता चलता है कि आजादी और सामाजिक प्रगति की दशवासिमा को कितनी प्रबल आकांक्षा है। यह बताने की जरूरत नहीं कि यदि व्यापक जनता को, जिसके द्वार में 'दि टाइम्स' भी स्वीकार करता है कि कांग्रेस के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित थी, यदि वोट देने का अधिकार होता तो कांग्रेस को कितना विशाल बहुमत प्राप्त होता।

### 3 कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडल

चुनावों के बाद उन प्रांतों में, जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन का प्रश्न अंतिम रूप से हल किया जाता था। मार्च 1937 में, विस्तार से एक नियम तैयार किया गया और वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को कुछ शर्तों के तहत पद स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उन प्रांतों में जहाँ के विधानमंडल में कांग्रेस का बहुमत है अपने सदस्यों को यह अधिकार और अनुमति देती है कि वे पद स्वीकार करें लेकिन इसके साथ एक शर्त है। मंत्रिपद तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक विधानमंडल में कांग्रेस दल का नेता इस बात से आश्वस्त न हो जाए और सांविधानिक रूप से यह घोषित करने योग्य न हो जाए कि मंत्रियों के सांविधानिक कार्यों के मामलों में गवर्नर ने तो हस्तक्षेप करने के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेगा और न मंत्रियों की सलाह को दरकिनार करेगा।

यह नियम गांधी ने तैयार किया था और 70 के मुकाबले 127 मतों से इसे मंजूर किया गया था। समाजवादियों और वामपन्थियों के बहुमत ने आमगौर से इस बात का विरोध किया था कि कांग्रेसजन किसी पद का स्वीकार करें। उन्होंने इस साम्राज्यवादियों की तरफ से दी गई रियायत माना था और उन्हें इस बात का खतरा लगा था कि इससे जन-सभ्यों को छाड़कर लोग यही रास्ता अख्तियार करने लगेंगे। पद स्वीकार करने के विरोध में उन्होंने जा सशोधन पेश किया था वह 79 के मुकाबले 135 मतों से नामंजूर कर दिया गया। मोटोरी पर इस विरोध का कारण यह था कि वामपन्थियों और समाजवादियों का नरमपन्थी सविधानपरस्त नेताओं में विश्वास नहीं था और उन्हें डर था कि इस तरह के नेताओं का वग कांग्रेस की नीति का साम्राज्यवादियों के साथ अधिक से अधिक समझौता करने की नीति में बदल देगा।

कुछ शर्तों के तहत पद स्वीकार करने के पक्ष में लिए गए फैसले के तीन महीने बाद कांग्रेस मतिमंडलों का गठन हुआ। कांग्रेस अपनी इस मांग पर डटी रही कि सरकार पहले इस बात की घोषणा करे कि गवर्नरों के विशेष अधिकारों का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे मंत्रियों के साविधानिक क्रियाकलाप प्रभावित हो। इस बीच 1 अगस्त को अर्थात् 'सूय दिवस' को (साम्राज्यवादी कार्यालयों के दिन मसखरे लोगों ने यह तिथि निर्धारित की थी इसका कोई इतिहास नहीं है) नए सविधान का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर देशभर में पूरा हड़ताल रही। चूंकि कांग्रेस तथा सरकार के बीच बातचीत में गतिविरोध अभी बना हुआ था इसलिए बिना बहुमतवाले अंतरिम मतिमंडलों का गठन कर दिया गया। यह गतिविरोध 22 जून को अंतिम तौर पर तब समाप्त हुआ जब वायसरॉय ने एलान किया कि सभी गवर्नरों की कोशिश यह होगी कि वे अपने मंत्रियों के साथ, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों किसी तरह का सभ्य तो पैदा होने ही नहीं देंगे, हाँ यदि इस तरह का कोई सभ्य हो तो वे उसका समायोजन करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। इस तरह की समझदारी के बाद कांग्रेस ने पद स्वीकार किए हालांकि कार्यक्रममिति के अंतिम प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि वायसरॉय तथा अन्य अधिकारियों की घोषणाओं में यद्यपि कांग्रेस की मांग के साथ तालमेल बैठाने की इच्छा प्रदर्शित की गई है फिर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिन शब्दों में आश्वासन की मांग की थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है।

जुलाई 1937 में छ प्रान्त, बंबई मद्रास, मयुक्त प्रान्त बिहार, मध्य प्रान्त और उड़ीसा में कांग्रेस मतिमंडलों का गठन हो गया। इन प्रान्तों में निचले स्तर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। सरहदों भूय में 8 गैरकांग्रेसी सदस्यों का एक गुट कांग्रेस में शामिल हो गया और इस गुट ने कांग्रेस का अनुशासन स्वीकार किया (एक हस्ताक्षरित घोषणा के द्वारा) जिससे कांग्रेस को इस प्रान्त में भी पूर्ण बहुमत मिल गया और वहाँ भी कांग्रेस का मतिमंडल बन गया। इन प्रकार ब्रिटिश भारत का 11 जिलों में से सात जिलों में जिनकी कुल आबादी लगभग 36 करोड़ (ब्रिटिश भारत की कुल आबादी का 3 भाग और भारत की

कुल जावादी का लगभग  $\frac{2}{3}$  भाग) थी, कांग्रेस मन्त्रिमंडली की स्थापना हो गई। वाद में असम और सिंध में भी कांग्रेस की मिलजुल कर सरकारें बन गई।

कांग्रेस के प्रांतीय मन्त्रिमंडलों का दो वर्ष से भी अधिक समय तक अस्तित्व बना रहा। युद्ध के कारण उत्पन्न सकट एवं केंद्र सरकार के माध्यम से अनवरत के कारण इन मन्त्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। इन दो वर्षों के जबरन कांग्रेस मन्त्रिमंडलों ने जो कुछ किया उससे राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर जबरदस्त विवाद पैदा हो गया।

प्रांतीयों में जो कांग्रेस मन्त्रिमंडल थे उन्हें किसी भी आधुनिक संसदीय अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता। अगस्त 1938 में गांधी ने 'हरिजन' अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इन मन्त्रिमंडलों के वेहद सीमित अधिकारों की बात साफ साफ कही और कहा कि इन्हीं कारणों से देश के वास्तविक मुक्तिग्राम में एक साधन के रूप में इन मन्त्रिमंडलों की विशेष भूमिका है

जनतांत्रिक ब्रिटेन में भारत में एक उम्दा विस्म की प्रणाली स्थापित की है जिसमें यदि आप उसके नान रूप में देखें तो पता चलेगा कि यह और कुछ नहीं बल्कि अत्यंत संगठित सैनिक नियंत्रण है। वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के तहत यह किसी भी अर्थ में कम नहीं है। जहां तक वास्तविक नियंत्रण की बात है ये मन्त्रिमंडल महज साम्राज्यवादियों के हाथ की कठपुतलियां हैं। गवर्नर के आदेश मात्र से कोई कलक्टर या पुलिस अधिकारी मंत्रियों का उनके पद से हटा सकता है उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और जेल में डाल सकता है। इसीलिए मैंने कांग्रेस को यह सुझाव दिया है कि उसके सदस्यों ने पदों को स्वीकार किया है इसलिए नहीं कि उन्हें साम्राज्यवादियों के बनाए ढांचे के अनुरूप काम करना है बल्कि इसलिए ताकि वे जल्दी वह दिन ला सकें जब इस अधिनियम के स्थान पर भारत द्वारा सहो अर्थों में निर्मित अधिनियम पेश किया जा सके।

लेकिन इस तरह की नीति का पालन कोई नातिकारी नेतृत्व ही कर सकता था। मन्त्रिमंडलों में नरमदली नेताओं का प्रभुत्व था और यही वजह थी कि उन्होंने एक अलग नीति का ही पालन किया। व्यवहार में इन मन्त्रिमंडलों ने 'अधिनियम' पर उसी तरह अमल करना शुरू किया जिस तरह की आशा अधिनियम के निर्माताओं ने की थी और साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि भी अपने इस प्रयाग की 'मफ्तता' पर हुई घुशी को छिपा नहीं सके। नागरिक स्वातंत्र्य कृषि के क्षेत्र से संबंधित कानून के निर्माण तथा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों के मामले में घातक और शुरू के वर्षों में कुछ सफलता मिली। इन सुधारों में साम्राज्यवादी प्रभुत्व और भ्रष्टाचार के प्रमुख आधारों तथा आम जनता की गरीबी पर कोई ज़रूर नहीं पड़ा। इन सुधारों की सीमा के रूप में कांग्रेस मन्त्रिमंडलों का अस्तित्व बना रहा और आम जनता के पिता

साम्राज्यवादी प्रशासन के एक अंग के रूप में उन्होंने दिन व दिन पुनरुत्थान किया।

कांग्रेस मन्त्रिमंडलों का नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। इस क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त हुई वह खामती से शुरू के वर्षों की सफलता थी। एक एक करके नगरभंग नहीं राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए। 1921 और 1922 में क्रमशः चोरीचोरा कांड और मापता विद्रोह में शामिल लोग इस समय तक जेलों में सजाए काट रहे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया। गढ़वाली सैनिकों को भी रिहा कर दिया गया। अनेक राजनीतिक संगठनों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया (लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहा)। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एक स्थान में दूसरे स्थान जाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। समाचारपत्रों से ली गई जमानत राशियां वापस कर दी गईं और उस सूची को रद्द कर दिया गया जिनमें ऐसे समाचारपत्रों के नाम थे जिन्हें उनकी राजनीतिक विचारधारा के कारण सरकारी विनाशना आदि से बर्चित कर दिया गया था। समाचारपत्रों तथा अन्य प्रकाशनों को आंशिक तौर पर स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसका पता इस तथ्य से चलता है कि उन दिनों राजनीतिक विचारधारावाले साहित्य के प्रकाशन में जबरदस्त वृद्धि हुई।

तो भी, शुरू के दिनों से ही यह पता चलने लगा था कि कांग्रेस मन्त्रिमंडलों ने साम्राज्यवाद के पुलिस प्रशासन के अंग के रूप में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। शुरू के ही कुछ महीनों के दौरान तब उस समय सकते में आ गए जब मद्रास सरकार ने एक प्रमुख कांग्रेस समाजवादी को राजद्रोह के जुर्म में छ महीने की सजा दी। कई मामलों में धारा 124 ए (राजद्रोहात्मक प्रचार के विरुद्ध) और धारा 144 (सभाओं आदि पर पाबंदी के लिए) का प्रयोग किया गया। इन दोनों धूणित धाराओं के खिलाफ पहले कांग्रेस जोरदार शब्दों में आवाज उठाया करती थी और दमन के इन तरीकों की कटिना किया करती थी। इन घटनाओं से कांग्रेस संगठन के अंदर ही जबरदस्त विवाद पैदा हो गया। 'अहिंसा' के सिद्धांत में स्वभावतया अद्भुत लचीलापन था 'हिंसा का प्रचार' करने वाला के विरुद्ध की जाने वाली पुलिस कार्रवाहियों और सजाओं को भी इस सिद्धांत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। दरअसल 'हिंसा का प्रचार' एक ऐसी शब्दावली थी जिसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल उस मत के विरुद्ध किया जाता था जो मौजूदा प्रशासन के विरुद्ध होता था और जो जनसंघर्षों की हिमायत करता था। इस विवाद की जड़ में कांग्रेस के अंदर के उच्च और मध्यवर्गीय तत्वों की चिंताएँ थी जो मजदूरों और किसानों के तेजी से बढ़ते आंदोलन के कारण उत्पन्न हुई थी।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए मन्त्रिमंडलों ने बहुत सीमित कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया। इन्होंने उन जबरदस्त अवरोधों से निबटने का प्रयास नहीं किया जिनका प्रतिनिधित्व साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अंतर्गत वर्तमान भूमिब्यवस्था और आर्थिक

प्रणाली करती थी। इन्होंने जमींदारों और धावनों के प्रति काफी लिहाज बरती क्योंकि कांग्रेसी नस्ल व नरमदली सेमे पर इनका काफी असर था।

कानून की दृष्टि से खासतौर से किसानों के सवम में कुछ तात्कालिक उपाय लागू किए गए। किसानों पर लद वज की समस्या ऐसी थी जिसका तत्काल समाधान जरूरी था। मद्रास ऐग्रिकल्चरिस्ट डेट रिलीफ ऐक्ट व जरिए कज की बढ़ाया राशि का एक जस रद्द कर दिया गया। संयुक्त प्रांत और बंबई में तत्काल ऋण स्वयंसेवक की व्यवस्था की गई। ऋण की राशि कम करने और व्याज की दर सामित करने (सामान्यतः 69 प्रतिशत तक) के उपाय किए गए। काश्तकारी कानून लागू किया गया जिसका उद्देश्य वेन्चलरी के खिलाफ एंव निश्चित सीमा तक सुरक्षा देना, लगान की राशि में वृद्धि को रोकना, अनियमित पावन और जूमन को दूर करना और लगान की बढ़ाया राशि पर व्याज को सीमित करना था। कुछ मामलों में जमीन को मालगुजारी माफ कर दी गई। बंबई में 40 000 'दुबलो' या बंधुआ सेतिहर गुलामों को मुक्त कर दिया गया।

कृषि के क्षेत्र में जो कानून बने व काफी अपर्याप्त थे और उनका क्षेत्र भी काफी सीमित था। इन्हें लागू करने के लिए किसानों का जबरदस्त आंदोलन और प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ा। किसानों के इन प्रयासों का जमींदारों ने जमकर विरोध किया और इन्हें विफल बनाने के लिए अपने असर का इस्तेमाल किया। कज की राशि में जो सचमुच कटौतिमा हुआ वह कज की राशि समूची राशि की तुलना में बहुत कम थी। काश्तकारी से संबंधित कानून व काश्तकारों के एक अल्पमत को लाभ पहुंचाया (इस प्रकार बाबे टेनेंसी बिल के साथ मतदान विवरण के अनुसार इस बिल से केवल 4 प्रतिशत काश्तकारों को लाभ होने की आशा थी)। खेतिहर मजदूर अप्रभाविन रहे। हालांकि, मद्रास में वेकुल आवादी का 42 प्रतिशत व पर उ'हू ऐग्रिकल्चरिस्ट डेटरिलीफ ऐक्ट से अलग रखा गया। किसानों के लिए जितने भी कानून बने वे उन सबमें इस तरह की सीमाएं स्पष्ट दिखाई देती थी। इसमें यह पता चलता था कि इस तरीके से छोटी मोटी तात्कालिक रियायतें तो हासिल हो सकती हैं पर किसानों को कोई गंभीर राहत देने के लिए इन उपायों से कहीं अधिक बुनियादी और प्रगतिशील उपाय अमल में लाने जरूरी हैं। बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत में किसानों का आंदोलन जबरदस्त होता गया क्योंकि जमींदारों व विरोध को रोकने में कांग्रेस के मंत्री असफल साबित हुए थे और इस स्थिति से किसान बेहद असंतुष्ट थे। बिहार में तत्कालीन कांग्रेस जमींदार गठबंधन की भत्तवा की गई। कुछ मिलावर काश्तकारी कानून अत्यंत कम प्रभावकारी था और उसका चर्च शिकमी काश्तकारों या वेदघन किए गए किसानों की बजाय बड़े किसानों के हितों की रक्षा करता था।

कांग्रेस मजिस्ट्रेटों के गठन से औद्योगिक मजदूरों की सन्निधता में काफी तब्दी आई उन्होंने अपने वेतन बढ़ाने की मांगें रखी और ट्रेड यूनियन गठन का मजबूत बनाने का

काम शुरू किया। 1937 में हुई हड़ताल में कुल 90 लाख काम करने वालों का नुकसान हुआ जो पिछले तीन वर्षों में हुए नुकसान से कुल योग से भी अधिक था और 1929 के बाद के आकड़ा में सर्वोच्च था। इन हड़तालों में कुल 647,000 मजदूरों ने भाग लिया जो एक रिकार्ड है। कांग्रेस मतिमंडला ने जहाँ मालिक और मजदूर के झगड़े को समझौते से निपटाने की नीति को बढ़ावा दिया और इसके लिए श्रम विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट) का इस्तेमाल किया वहीं उन्होंने मजदूरों की हालत सुधारे तथा वेतनवृद्धि कराने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। बंबई कपड़ा मिनमजदूर जांच समिति ने मिलमजदूरों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की और मिलमालिकों के कुछ विरोध के बावजूद समिति के निपटारों को लागू किया गया। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने बानपुर में मजदूरों की हड़ताल समाप्त करने के लिए संपन्न समझौते में सहयोग किया लेकिन समझौते के लिए यह शर्त रखी कि मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाएं और यूनियन को मान्यता दी जाए, और 1938 में जब मालिकों ने फंसले का विरोध करना चाहा तो कांग्रेस और मजदूरों की एकता के कारण ही मालिकों के खिलाफ उन्हें सफलता मिल सकी।

आंदोलन के रूप में हड़ताल का महाराज ने के प्रश्न, हड़ताल के अधिकार से संबंधित प्रश्न और ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के सवाल का लेकर उठे तीखे मामले पैदा हो गए। मद्रास में मजदूरों और मालिकों के विवाद में सरकार ने जितनी बार भी हस्तक्षेप किया वह हमेशा मजदूरों के खिलाफ ही रहा। शालापुर में धारा 144 लगाने (जिसमें जुलूस निकालने या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होना पर प्रतिबंध लगाया गया था) हड़तालों के विरुद्ध अथवा प्रशासनिक उपायों के अमल में लाने तथा मजदूरवर्गों की गतिविधियों की स्वतंत्रता के सदर्भ में बंबई सरकार के सामने गंभीर बंठनाइयां पैदा हो गईं, जो 1938 के उत्तरार्ध में बांबे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल का लेकर काफी गंभीर हो गईं। इस बिल में कहा गया था कि विवाद हल करने के लिए जांच समिति गठित की जाएगी उसे काम करने के लिए चार महीने की अंतरिम अवधि मिलनी चाहिए और इन अवधि के दौरान हड़ताल करना गैरकानूनी समझा जाएगा। इस प्रकार इस बिल ने हड़ताल के अधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया। इसने यूनियनों के पंजीकरण के लिए ऐसे जटिल कार्य-कानून जोष दिए जो कंपनी की यूनियनों या मालिकों की समझौतेप्राप्त यूनियनों के ही अनुकूल थे। ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका विरोध करने पर इसमें कुछ संशोधन कर तो दिए गए पर इसका मुख्य मित्राता में कोई तब्दीली नहीं आई और 7 नवंबर को बंबई प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। इन हड़तालों का लोग ने काफी समर्थन दिया। हड़तालियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और कई मजदूर घायल हुए तथा एक मारा गया।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कांग्रेस मतिमंडला ने स्थानीय स्तर पर शराबबंदी और नशीली दवाओं की रोक पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया था (साम्राज्य

सरकार अपनी अधीनस्थ एजेन्सियों के जरिए शराब और नशीली दवाओं की बिक्री को प्रोत्साहन देती थी ताकि इससे उसे राजस्व मिले। इसलिए शराबबंदी का जब भारी आर्थिक नुकसान था)। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने के कार्यक्रमों की योजना तयार करने के प्रयास किए गए पर शिक्षा सबकी कितनी गंभीर कार्यक्रम के लिए धन की जरूरत थी और सरकार के पास पैसे का अभाव था। सामाजिक कानून बनाने के कुछ प्रयास किए गए जैसे संयुक्त प्रांत में कारखाना में काम करने वाली महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा की व्यवस्था की गई। अपनी आर्थिक सीमा के अंदर सावजनिक स्वास्थ्य के उपाय शुरू किए। यह काम खासतौर से गांवों में शुरू किया गया ताकि गांवों में पानी की उचित सप्लाई हो तथा गांवों का स्वच्छ रखा जा सके।

हर बंदम पर कांग्रेस मतिमंडलों को जिस सबव्यापी समस्या और अवरोध का सामना करना पड़ता था वह थी वित्त की समस्या। दरअसल यही वह समस्या थी जिससे पता चलता था कि साम्राज्यवाद के नियंत्रण में ये मतिमंडल कितने असमर्थ थे। वित्त की बर्बादी के कारण उनपर कितनी सीमाएं थोपी दी गई थी इस हम प्रांतीय सरकारों के बजट की छानबीन करके जान सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि वास्तव में कितना काम पूरा किया जा सका।

### शिक्षा पर व्यय

(हजार रुपये में)

|                | 1937-38 | 1938-39 | 1939-40 |
|----------------|---------|---------|---------|
| संयुक्त प्रांत | 20,615  | 20,852  | 21,242  |
| बंबई           | 16,805  | 19,064  | 20,017  |
| मद्रास         | 25,796  | 26,198  | 26,357  |

### सावजनिक स्वास्थ्य पर व्यय

(हजार रुपये में)

|                | 1937-38 | 1938-39 | 1939-40 |
|----------------|---------|---------|---------|
| संयुक्त प्रांत | 2,252   | 2,458   | 2,365   |
| बंबई           | 2,406   | 2,754   | 2,810   |
| मद्रास         | 4,407   | 2,657   | 2,730   |

राज्य के प्रांतीय मतिमंडलों के गठन और इसके प्रारंभिक दिनों में अनुभव से इसमें मतिविषयों के काम का इतना हाथ न था जितना कि इसके द्वारा उत्पन्न आशा और उत्साह के कारण, राष्ट्रीय आंदोलन में काफी तजवी आई। लेकिन दवा नकारात्मक पहलु भी कम उत्प्रेरणीय नहीं है। कांग्रेस मतिमंडलों के दो वर्षों में अनुभव ने अत्यंत गंभीरता के साथ



वे सतरे उजागर कर दिए थे जो पहले से ही समथीतावादी सम्मान वाले नतृत्व म अतर्निहित थे । कांग्रेस सगठन और मन्त्रिमडला पर नरमदलों नेताओं का दबदबा या और वे व्यवहार मे साम्राज्यवाद के साथ सहयोग को तेजी मे विकसित करने म लगे थे, उच्चवर्ग के जमींदारों और उद्योगपतियों के हित म खुलकर काम कर रहे थे तथा सभी तरह के जुगारू जनसपर्य और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध बहुत साफ तौर पर अधिकाधिक शत्रुतापूर्ण रवैया अक्षित्यार कर रहे थे । नैसे जसे लोगों को इन मन्त्रिमडलों का व्यावहारिक अनुभव होने लगा, लोग म असताप बढ़ता गया । यह बात अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगी कि राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य सघष का निर्णायक कार्य सामने आ चुका है और यह कांग्रेस मन्त्रिमडल तब से पूरा नहीं किया जा सकता । इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया सकट विकसित होने लगा ।

#### 4 सधीय सविधान और बढ़ता हुआ सकट

फरवरी 1938 म राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन ने सविधान के सधीय अनुच्छेद और इनको अमल म लाने की कोशिशों के मदम म कांग्रेस की नीति की व्याख्या की । सबसम्मति से पारित इस प्रस्ताव म कहा गया था

कांग्रेस ने नए सविधान को नामजूर कर दिया है और एतान किया है कि देश की जनता को वही सविधान मान्य होगा जो स्वाधीनता पर आधारित हो और ऐमे सविधान की रचना स्वयं जनता करेगी । इस तरह के सविधान का निर्माण एक ऐसी सविधान सभा के जरिए होगा जिसमे किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप न हो । सविधान की अस्वीकार करने की इस नीति पर दुढ़ रहने हुए कांग्रेस न फिलहाल प्रातों म कांग्रेस मन्त्रिमडनों के गठन की अनुमति, यह बात ध्यान म रखकर दी है कि इससे दश अपना स्वतन्त्रता सघष चलाने मे मजबूत होगा । प्रस्तावित राज्यसघ के मदम म अस्थाई तौर पर या किसी खास अवधि के लिए भी इस तरह का लिहाज नहीं किया जा सकता और राज्य सघ के थोमे जान से भारत को गभीर क्षति उठानी पड़ेगी तथा इससे वे बघन और मजबूत हान जिन्होंने भारत को साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अतर्गत गुलाम बना रखा है । राज्य सघ की यह योजना सरकार के महत्वपूर्ण जिम्मेदार कार्यों के दायरे से अलग है

इसलिए कांग्रेस एक बार फिर प्रस्तावित राज्य सघ योजना की मत्सना करती है तथा प्रातीय और स्थानीय कांग्रेस कमेडियों व साथ साथ सामाय तौर पर जनता मे और प्रातीय सरकारों तथा मन्त्रिमडलों से आग्रह करती है कि व इसका उद्घाटन न होन दें । जनता की धापित आका ना व बावजूद यदि इस धोषन की कोशिश की जाती है तो इस तरह के प्रयास का हर तरीके स मुखाबला लिया जाग चाहिए और प्रातीय सरकारों तथा मन्त्रिमडलों को चाहिए कि वे

इसके साथ सहयोग करने से इकार करे। यदि ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति पैदा होती है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार और निर्देश दिया जाता है कि वह यह तय कर ले कि इस दिशा में कौन सी कार्यवाही करनी है।

यह देखा जा सकता है कि इस प्रस्ताव में संविधान के सघीय अनुच्छेद को पूरी तरह नामजूर कर दिया गया है और ममचीते के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। यह पूरा अस्वीकार इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि सघीय व्यवस्था से स्वराज्य के मांग पर कतई नहीं बढ़ा जा सकता, उल्टे इससे साम्राज्यवाद की पकड़ और भी मजबूत होगी।

साम्राज्यवादियों द्वारा सघीय संविधान खोपने की स्थिति में कांग्रेस की रचनात्मक नीति और कार्य की दिशा क्या होनी चाहिए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिससे संघर्ष की नई अवस्था और आंदोलन के रूपा का समूचा भसला जुड़ा हुआ है, अभी तक हरिपुरा कांग्रेस ने भी, सिद्धांतवाक्या के अलावा कुछ भी नहीं कहा है।

सरकारी क्षेत्रों की यह राय थी कि पूरा अस्वीकार की यह प्रारंभिक भूमिका है और आगे चलकर किसी न किसी रूप में कांग्रेस इसे स्वीकार कर लेगी जैसा कि प्राता में मंत्रिमंडल बनाने के सिलसिले में हुआ था। हालांकि यह अनुमान करत समय सरकार ने देश के विपक्ष की ताकत को कम करके आका था फिर भी यदि नए और जबरदस्त संघर्ष के विकल्प के रूप में की गई तैयारियां वा न होना हम देखें और कांग्रेस के नेतृत्व में असरदार प्रवृत्ति को देखें तो पता चलगा कि उनमें कथन आधारहीन नहीं थे। ये नरमदली तत्व अधिनियम की शर्तों में वा उसने व्यावहारिक कार्यों में संशोधन करा मोलभाव की गुंजाइश निवाल संपत थे।

1938 के दौरान साम्राज्यवादियों के प्रमुख प्रतिनिधियों और कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच कई बार बातचीत हुई और इस आशय की अपवाह फलाई जान लगी कि जल्दी ही कोई समझौता हा जाएगा। सरकार की किसी भी घोषणा में इस तरह की अपवाह वा कोई आधार नहा था। फिर भी यह सही है कि दांणपथी ताताओं में अलग अलग वस्तुएं जारी लिए जिनमें संशोधित सघीय संविधान में आधार पर संभावित समझौते की बात लिहित थी। उनमें वामपथी तत्वा में पहले ही संशोधनकार की तरफ मुकाब' में घतर को समझ लिया था और यह जानत पूरे कि 'हार्ड कमन' में दांणपथी तत्वा वा बात जाता है उहो जागता व्यता की भी कि यहादुरी से भरे वस्तुओं में बायजू' में ताग आमसमगण कर दगे।

दरअसल कांग्रेस वा वा-आधार नवा है तथा मजदूरों और किसानों के सहा जागपव के साथ उमरा नवा रिता है यह प्रता ही दा बिता। वा जह में वा। कांग्रेस अरु आधार

का जितना ही मजबूत करती और जनता के साथ उसका जितना ही ज्यादा सहज सम्बन्ध होता, उस ही अनुपात में उसके अंदर वह क्षमता आ पाती जिससे वह राज्यसभ की याचना को विफल बना सकती और साम्राज्यवादियों पर अपनी शर्तें थाम सकती। नेतृत्ववर्ग के प्रमुख लोगो न किसानों और मजदूरों के आंदोलन तब होने पर जो चिंता व्यक्त की थी, वगमवग का 'अहिंसा' का उल्लंघन घोषित करके जिस प्रकार उसकी निंदा की थी और हड़तालों तथा अमताप के खिलाफ की गई पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही के पक्ष में दलील देने के लिए जिस प्रकार अपने को हमेशा तैयार रखा था उससे यह निश्चित हो गया था कि कांग्रेस ने ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया है जिसकी अंतिम परिणति साम्राज्यवादियों के साथ समझौता होगी।

ऐसी ही परिस्थिति में सुभाषचंद्र बोस ने, जिन्हें इसमें पहले के वष में कांग्रेस ने बिना चुनाव कराए अध्यक्ष पद के लिए नामजद किया था 1939 में फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने इस पद के लिए चुनाव लड़ने का यह आधार बताया कि राज्यसभ के प्रस्ताव का तथा कांग्रेस के मौजूदा दक्षिणीपथी नेतृत्व की समझौतापरस्त नीति का विरोध करने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए और यही आज का राजनीतिक मसला है। यह पहला अवसर था जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव का मर्म ज्यादा महत्व यह है कि अब तक कांग्रेस की कार्यसमिति या दल ने शासक वर्ग के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था—अध्यक्ष द्वारा उन्हें नामजद कर दिया जाता था। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना, सदस्यों का ऐसा सांविधानिक अवसर दिया जाना था जिससे जरिए वे कांग्रेस नेतृत्व के चरित्र के बारे में खुद को अभिव्यक्ति दे सकें। अध्यक्ष पद के लिए सुभाषचंद्र बोस ने विरुद्ध जो सदस्य चुनाव लड़ रहा था उसे गांधी तथा पुरानी कार्यसमिति के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। बातें को वामपंथी राष्ट्रवादियों, सोशलिस्टों तथा कम्युनिस्टों का समर्थन प्राप्त था। चुनाव में बोस को 1,376 मतों के मुकाबले 1,575 मतों से सफलता मिली।

कांग्रेस की आधिकारिक व्यवस्था के विरोध के बावजूद सुभाषचंद्र बोस ने चुन लिए जाने से भीतरी तौर पर जबरदस्ती सबूत पैदा हुआ। दरअसल अध्यक्ष पद पर किसी का व्यक्तिगत रूप से चुन लिया जाना मंगठन के सदस्यों की भावनाओं को नापने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन इस किन्हीं भी अर्थों में एक निश्चित राजनीतिक फैसला नहीं समझा जा सकता और न ही यह माना जा सकता है कि संस्था का बहुमत वामपंथी दिशा की तरफ मुड़ रहा है। त्रिपुरी अधिवेशन की कार्यवाहियां न इस सिद्ध कर दिखाया। फिर भी चुनाव का परिणामों में यह महत्त्व तो मिलता ही है कि वामतोर से जागो की विचार-धारा वामपंथी दिशा ले रही थी। स्वयं गांधी ने सुभाष बोस के चुनाव को अपनी व्यक्तिगत पराजय माना और कहा 'अब मुझे इसमें तनिक भी मदद नहीं कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व उन गिड़गता और नीतियों को नहीं मानते हैं जिनका मैं समर्थन करता हूँ।' दाइम्स आरु इंडिया। लिखा श्री बोस का चुनाव एक ऐसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है

जो वामपंथी निशा ले रहो है।' वाय नातिकल न टिणणी की 'इस चुनाव मे कांग्रेस का उग्रवाद की ओर चुनाव और जनता की दृढ़ता का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह बात ध्यान देने की है कि बंबई प्रांतीय कांग्रेस समिति के चुनावो मे कम्युनिस्टा का मुख्य रूप से सफलता मिली। मेरठ पञ्चवक्त्र के अभियुक्त अधिकारी को शहर के किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले और बंबई नगरपालिका के चुनावो मे जिन चार कम्युनिस्ट उम्मीदवारो ने भाग लिया उन्हें सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए।

अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे ने गांधी तथा मगठन के प्रमुख नरमदली नेताओं को काफी निराश किया और वे लोग अपना क्षोभ छिपा नहीं सके। गांधी ने तुरंत एक वयान जारी किया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह एक 'भ्रष्ट संगठन' हो गया है और उसने 'फर्जी सदस्यो' को इकट्ठा कर लिया है। साथ ही गांधी ने यह भी धमकी दी कि बहुमत की नीति को यदि इन सदस्या ने अस्वीकार किया तो मगठन के दक्षिणपंथी लोग संभवतः कांग्रेस से अलग हो जाएँ। कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले जो लोग कांग्रेस के पडयत्रो के कारण संगठन से बाहर हूँ वे कांग्रेस का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो लोग कांग्रेस में बने रहने में असुविधा महसूस करते हैं वे बाहर आ सकते हैं।'

नतीजा यह हुआ कि कायसमिति के 15 सदस्या मे से 12 सदस्यो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र देने के साथ अपने वक्तव्यो मे यह बताया कि वे सुभाषचंद्र बोस के लिए मैदान छोड़ दे रहे हैं ताकि बोस मनमाने ढंग से काम कर सके। इन सदस्या ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान बोस ने उनकी सदाशयता पर कीचड़ उछाला। जवाहरलाल नेहरू ने भी कायसमिति से इस्तीफा दे दिया लेकिन उन्होंने अलग से एक वक्तव्य जारी करके अपना खास दृष्टिकोण प्रकट किया (इस संकट के सद्भव में उनके द्वारा जारी की गई पुस्तिका 'व्हेयर आर वी?' में इसपर विस्तार से बताया गया है)।

मार्च 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को संगठन की एकता बनाए रखने में सफलता मिली लेकिन वह इस विवाद का हल नहीं कर सका। 'राष्ट्रीय मांगो' से संबंधित मुख्य प्रस्ताव में इस बात की फिर घोषणा की गई कि कांग्रेस, भारत सरकार अधिनियम की मधीय मांग का दृढ़ता के साथ विरोध करती है और इस ओपे जाने के विरुद्ध वह संघर्ष का संकल्प दोहराती है।

गांधी के समयका ने नेतृत्व में पैदा फूट के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे काफी वादविवाद के बाद अंतिम तौर पर स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में गांधी की नीतियाँ और उनके नेतृत्व में फिर से आस्था प्रकट की गई थी और अध्यक्ष से कहा गया था कि वह गांधी की इच्छा के अनुरूप अपनी कायसमिति के सदस्यो का नामजद करें। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से गांधी की, जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे व्यक्तिगत तानाशाही

ही स्थापित किया गया। यह प्रस्ताव 135 के मुकाबले 218 मतों से विषय समिति में पारित कर लिया गया और कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

त्रिपुरी अधिवेशन के बाद के अनुभवों से पता चलता है कि इस विवाद का कोई हल नहीं ढूँढा जा सका था। कर समिति के गठन के बारे में गांधी और बोस के बीच बातचीत चलती रही लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और वह बीच में ही टूट गई। अप्रैल 1939 में सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक नए अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद का चुनाव किया। इसके बाद बोस ने कांग्रेस के अंदर उन विपक्षी लोगों को संगठित करना शुरू किया जो उनका समर्थन करते थे और एक नए संगठन को जन्म दिया जिम्का नाम 'फारवर्ड ब्लाक' रखा गया। इन नए संगठन का लक्ष्य घोषित करते हुए कहा गया कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर के प्रगतिशील और साम्राज्यवादविरोधी तत्वों को संगठित करना है।

फारवर्ड ब्लाक ने संविधान, नीति और कार्यक्रम की कोई बुनियादी आलोचना नहीं की बल्कि उसने कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के प्रति असंतोष जाहिर किया और स्वतंत्रता के लिए तथा भारत को राज्यसंघ का दर्जा दिए जाने के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष की तैयारियाँ करने का आह्वान किया। 1939 की गर्मियाँ में इस विवाद ने और भी तीव्र रूप ले लिया। अप्रैल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें कहा गया कि कांग्रेस के संविधान को और कठोर किया जाए, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा किए गए कार्यों के सदर्भ में कांग्रेस की प्रांतीय समितियों के अधिकारों को सीमित किया जाए और कांग्रेस समितियों की उचित स्वीकृति के बिना अहिंसात्मक प्रतिरोध से संचालित आंदोलनों का नेतृत्व करने से कांग्रेसजनों को रोका जाए। अंतिम तीनों प्रस्तावों का उद्देश्य कांग्रेस के कब्जे से किसानों और मजदूरों के दिनादिन बढ़ रहे स्वतंत्रता आंदोलन को छीनना था और इन प्रस्तावों की सदन यही व्याख्या की कि इसका ज़रिए किसानों और मजदूरों के संघर्षों को सीमित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के विरोध में सुभाषचंद्र बोस तथा लैफ्ट कमोनिडेशन कमेटी ने, जो विरोधी तत्वों के मिलजुल संगठन का प्रतिनिधित्व करती थी 9 जुलाई को प्रदर्शनों का आह्वान किया। बोस की इस कार्यवाही को कांग्रेस के अनुशासन का उल्लंघन माना गया और बोस को बंगाल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता के अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन में उन्हें तीन वर्षों तक कोई भी पद न देने का फैसला किया गया।

कांग्रेस के संगठन के भीतर की यह जबरदस्त फूट दश में बढ़ने लगी थी और यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की जो संभावनाएँ सोची गई थी वे तबतब समाप्त हो चुकी हैं और साम्राज्यवाद तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बीच एक बहुत बड़ी मुठभेड़ है। कांग्रेस ने नेतृत्व के उच्चतम में पड़ी फूट से अभी तक किसी राजनीतिक तानसेन

तस्वीर नहीं साफ हो पा रही थी क्योंकि इस फूट के पीछे अनेक व्यक्तिगत मसले ली थे। लेकिन कांग्रेस के आम सदस्यों के बीच तथा आम जनता के बीच वैचनी बढ़ती जा रही थी। सगठन में मजबूत गांधीवादी नेतृत्व और कांग्रेस के अंदर बने गुट 'फारवर्ड ब्लाक' के बीच कार्यक्रम या नीति को लेकर कोई दुनियादी विभाजन नहीं था। सुभाषचंद्र बोस के शब्दा में 'फारवर्ड ब्लाक' श्री गांधी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के उनके सिद्धांत को पूरा सम्मान देता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस के मौजूदा हाई कमान में भी वह अपनी निष्ठा बनाए रखे।' जनआंदोलन के लिए अभी दुनियादी कार्यक्रम और नेतृत्व का विकास होना बाकी है लेकिन तथ्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए चरण में प्रवेश के लिए स्थितियाँ तैयार हो गई थी।

यही वह स्थिति थी जब युद्ध के छिड़ जाने से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच एकल हुए संघर्ष अचानक चरम बिंदु पर पहुंच गए और उन्होंने नई समस्याएं सामने ला दी।

## 16 द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत

भारत की भौगोलिक स्थिति उसे दिन ब दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगली पक्ति में लाती जाएगी।—23 मार्च 1905 इंडिया कौंसिल में लाड कजन का भाषण।

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रवाह ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धारा में पूरी तरह पहुँचा दिया। 1914 के विश्वयुद्ध में भारतीय सैनिकों और साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था फिर भी यह युद्ध भारत से अपेक्षित काफी दूर चल रहा था। लेकिन 1942-44 के युद्ध और आज़मण ने भारत के निकटतम पड़ोसियों को रोद दिया और भारत की सीमाओं तक इसके घमाके सुनाई पड़ने लगे। 1914 के युद्ध ने भारत पर गंभीर आर्थिक दबाव डाला था लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध ने न केवल भारत की नयकर आर्थिक लूट की बल्कि उसने भारत में जबरदस्त मुद्रास्फीति को जन्म दिया, आर्थिक संरचना को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और इस युद्ध के कारण भारत को अकाल का सामना करना पड़ा। 1914 के युद्ध ने भारत के लिए राजनीतिक प्रश्नों को काफी तीव्र बना दिया। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध ने भारत की आजादी के बुनियादी प्रश्न को भारतीय राजनीति की अगली पंक्ति में ला खड़ा किया। इसने नए मसल, नई समस्याएँ और नए संघर्षों को भारतीय राजनीति के ममस्यल तक पहुँचा दिया और हर तरह के राजनीतिक जोड़ तोड़ को प्रभावित किया।

1914 से पहले तक विश्व राजनीति में भारत की भूमिका के प्रश्न को यह समझा जा सकता था कि मूलतः यह प्रश्न ब्रिटिश की रणनीति और ब्रिटिश नीति से संबद्ध है। राष्ट्रीय

आंदोलन का पूरा ध्यान भारत में चलने वाले सघर्ष पर केंद्रित था और यह काफी स्वाभाविक भी था। यह बात काफी अंतर्कण लगती थी कि जब तक भारत आजादी नहीं हासिल कर ले तब तक भारतीय जनता से इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह विश्व की राजनीति में कोई स्वतंत्र भूमिका निभाए। तब 1931 में विश्वव्यापी फासिस्ट आन्दोलन के बाद से यह स्थिति बदल गई है। जब विदेश नीति का मसला राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख मसला बन चुका है।

द्वितीय विश्वयुद्ध से सबद्ध विशेष मसलों पर विचार करने से पूर्व यदि हम पहले की घटनाओं का संक्षेप में जायजा लेने और विश्व राजनीति के सदर्भ में ब्रिटिश रणनीति में भारत की भूमिका तथा विदेश नीति से सबद्ध मसलों के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन के रुख के बारे में थोड़ा विचार कर लें तो यह काफी उपयोगी होगा।

## 1 ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और भारत

व्यापक अर्थों में देखें तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का मसला विश्वव्यापी राजनीति का मसला रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है।

पिछले दो सौ वर्षों का इतिहास देखें तो यह बात स्पष्ट से स्पष्टतर होती गई है कि जंगरेजों ने भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की धुरी बना रखा था। ऊपरी तौर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि 18वीं सदी में यूरोप की बदलती हुई परिस्थितियाँ और नए गुट ही ब्रिटन और फ्रांस के बीच युद्ध का कारण थे लेकिन वास्तविकता यह है कि इन युद्धों का मुख्य कारण नई दुनिया के लिए सघर्ष तथा भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का सघर्ष था। ब्रिटन के हाथ में जब अमरीका निकल गया तो उसके लिए भारत का महत्व और अधिक बढ़ गया। नेपोलियन ने जब मिस्र और सुदूरपूर्व की तरफ अपनी सनाओ को बढ़ाने का आदेश दिया तो उसके दिमाग में भारत की ओर बढ़ने की बात थी। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटन को हमेशा रूस

रूस कहाँ एशिया में बढ़ता न च  
पहुँच जाए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध  
की अपनी नीति छोड़ी तो उसने  
संशोधित जापानी संधि  
किया गु से ब्रिटन का  
जमनी 1947  
रहना क रघन

रहा अ आशका थी कि  
प्रकार भारत तक न  
इन विषय उदासीनता  
के साँ जब दस  
ता शामिल  
म 1947

भारत 1947  
लिए नहीं था  
अमल में लाने



सदा हुआ है उसका एक बहुत बड़ा भाग इन युद्धों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। ब्रिटेन अपनी नीति के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए दूसरे एशियाई देशों और एशिया की सीमाओं से दूर लड़ाई लड़ता था और इन सारे युद्धों का ध्येय भारत को चुकाना पड़ता था। 1859 में ब्रिटेन के एक सैनिक अधिकारी ने लिखा

एशियाई देशों में हमने जितने युद्ध लड़े हैं उन सबका सैनिक और आर्थिक खर्च भारत सरकार ने दिया है हालांकि इन युद्धों का उद्देश्य, कुछ मामलों में शुद्ध रूप से ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना था और कई अन्य मामलों में इनका भारत के हितों से कोई संबंध न था। (मजर बिनगट, 'अवर फार्मर शिफ्ट रिनवास विद इंडिया', 1859, पृष्ठ 17)

दूसी आधार पर अफगानिस्तान, बर्मा, थायलैंड, चीन, फारम, मेसोपोटामिया, अरब, मिस्र और अबोसीनिया में युद्धों का संचालन किया गया।

19वीं सदी में जब ब्रिटेन अपने प्रभुत्व का विस्तार कर रहा था तब भारत के आधार पर विचार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की ब्रिटिश ने सैनिक अधिकारियों की कितनी जरूरत महसूस की थी और उन्होंने कितनी बर्बाद गणनाएँ कर रखी थी इसका दृष्टांत हम चार्ल्स गेपियर के कथन में मिलता है। चार्ल्स गेपियर 1857 के विद्रोह से पूर्व नाइल डलहौजी के अधीन सेना के कमांडर इन चीफ थे

अगर मैं भारत का सम्राट होता तो मैं न जान क्या क्या करता। मैं मास्को और पीकिंग को हिलाकर रख देता। भारत से इंग्लैंड तक नदियाँ और मैदानों का जाल बिछा दूँ। पंजाब की पाँचों नदियाँ, इंडस और सिंध, 'गलसगिर और माल्टा इन सबको जोड़कर इंग्लैंड तक का रास्ता तैयार किया जा सकता है। अगर मैं इंग्लैंड का राजा होता तो दिल्ली के महल से मैं अपने घूँसे तानकर निकलता और रूस तथा फ्रांस के दरबार पर दे मारता। पश्चिम में इंग्लैंड के जंगी जहाजों के घेरे और पूर्व में भारतीय सेना का एकछत्र राज्य होता चाहिए।

भारतीय सेना का जितना बड़ा बनाया गया था और उसपर जितना पैसा खर्च किया जाता था वह महज इसलिए नहीं कि भारत की जनता को गुलाम रखने के लिए यह जरूरी था बल्कि इसलिए कि भारत की सीमाओं में परे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो युद्ध लड़े जाएँ उनमें इस सेना का इस्तेमाल किया जा सके। 1885 में वायसराय की कोसिल के सर कार्टर इलवट ने वर्तमान नीति के प्रति अपनी विरोधात्मक टिप्पणी में कहा था

अपने देश की जरूरतों के लिए जितनी बड़ी सेना की आवश्यकता है उससे बड़ी सेना

रखने से हम अपनी सीमाओं से परे आक्रमण करने का लोभ सवरण नहीं कर पाएंगे।  
(सर फोर्टेन इलवट विरोध टिप्पणी, 14 अगस्त 1885)

इसके तत्काल बाद बर्मा पर विजय प्राप्त करके और उसे भारत में मिलाकर यह भविष्य वाणी पूरी कर दी गई। इसके बाद 1895 का छिन्नाल अभियान हुआ, तिराह का कुख्यात अभियान हुआ, 1900 में वजन के अधीन उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेशों को हथिया लिया गया और 1904 में तिब्बत पर हमला किया गया।

1904-5 में वजट पर हुई वहस के दौरान सर ई० एलिस न भारत के राष्ट्रीय नेता गोखले की आलोचनाओं के विस्तारवाद की नीति की बकालत की

क्या सीमाओं पर छोड़े पहाड़ों के पीछे अपने को छिपा लेने से ही हम यह भ्रम पाल लेना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं जबकि एशियाई राज्यों का तेजी से पतन होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भविष्य में निम्नलिखित भारतीय सेना की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। भारतीय सेना को अब महज स्थानीय सैनिक दस्ता समझना, जो केवल स्थानीय रक्षा और कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए बनी हो असंभव है।

इसी वहस के सदर्भ में लाड कर्जन ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने अपनी बातें और भी स्पष्टता के साथ कही

भारत एक बहुत बड़े किले के समान है जिसके दोनों तरफ विशाल सागर हैं और शेष दिशाओं में पर्वतमालाएँ हैं। लेकिन इन दीवारों के पार, जो निश्चित रूप से इतनी ऊँची हैं कि हूँ पार नहीं किया जा सकता और इतनी मजबूत हैं जिनका भेदन नहीं किया जा सकता विभिन्न लंबाई चौड़ाई के ढाल हैं। हम उनपर कब्जा करना नहीं चाहते लेकिन हम यह भी नहीं देख सकते कि हमारे दुश्मन उसपर कब्जा कर लें। हम इस बात से पूरा सतर्क रहेंगे अगर ये इलाके हमारे सहायिगियों या मित्रों के अधिकार में बने रहें। लेकिन हमारे प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों का प्रभाव इन इलाकों पर बढ़ता गया और उन्होंने बिल्कुल हमारी नाक के नीचे अपने को जमा लिया तो हम दखल देना पर मजबूर होंगे क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इतना भयावह खतरा पैदा हो जाएगा जो एक दिन हमारी सुरक्षा को चौपट कर देगा। जर्क, फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और पूरब में स्याम तक हमारी मौजूदा स्थिति का यही राज है।

लाड कर्जन की यह धारणा उनकी पुस्तक 'प्रावलम्स आफ दि फार ईस्ट' में विस्तार से देखी जा सकती है। लाड कर्जन के बाद जितने भी शासक भारत आए उन्होंने इसी

नीतियों का आज तक पालन किया है और इसके सकेत हम बूढ़ सकते हैं

भारतीय साम्राज्य इस भूमंडल के तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से में सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र पर स्थित है लेकिन उसकी केंद्रीय और संचालनकारी स्थिति को जितनी पूर्णता के साथ उन राजनीतिक प्रभावों में देखा जा सकता है जो वह निकट और दूर के अपने पड़ोसियों का भाग्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल करती है और जिन सीमा तक उनकी किस्मत भारतीय धुरी की परिक्रमा करती रहती है, वह और कहीं संभव नहीं है। (माननीय जी०एन० कज्जल 'प्रावलन्स आफ दि फार ईस्ट', 1894, पृष्ठ 9-10)

1913 में आर्मी इन इंडिया कमिटी ने कहा था 'भारत को इसलिए अपनी सेना नहीं तैयार करनी है कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब भारत से बाहर लड़ रहे युद्धों में इस सेना का इस्तेमाल करे, हालांकि, जैसा कि अतीत में हुआ है वह अपने सैनिकों को इन युद्धों के लिए उस स्थिति में भेज सकता है जब वे अन्याय उपनद्य हो।'।

1914-18 के युद्ध ने पूरी तरह दिखा दिया कि भारत का यही इस्तेमाल है। लगभग 10 लाख सैनिकों, जिनमें से आधे से अधिक लष्कर सैनिक थे, फ्रांस, को पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि में लड़े जा रहे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया गया और भारत में हजारों लाखों पाउंड की राशि बसूली गई। नए मध्य पूर्वी साम्राज्य की विजय के लिए भारत का आधार बनाया गया हालांकि बाद के वर्षों में टर्की के पुनरुत्थान और सऊदी अरब के मजबूत होने से यह विजय अधूरी हो रही गई।

1920 की ईशर कमिटी रिपोर्ट ने 1913 की आर्मी इन इंडिया कमिटी की तुलना में कहीं ज्यादा स्पष्टता के साथ भारतीय सेना के द्वार में सरकारी धारणा को व्यक्त किया और इसे ऐसा अस्तवताया जिसे ब्रिटिश शासक भारत से बाहर इस्तेमाल करते हैं

हम भारत में स्थित सेना के प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य की समूची नई शक्ति से अलग नहीं मान सकते।

जैसा लार्ड रातिसन ने, जो पिछले विश्वयुद्ध के बाद 1921 में सेना के कमांडर इन चीफ थे बताया था और बाद में दि आर्मी इन इंडिया ऐंड इट्स इवाल्याूशन' नामक सरकारी पुस्तिका (1924 में प्रकाशित) में जिसका विस्तार से उल्लेख किया गया है, आज भारत में सेना का तीन श्रेणियों में संगठित किया गया है

1. रजिसेना (फोर्म्ड आर्मी) जो भारत से बाहर लड़े बड़े युद्धों में भाग ले।

- 2 रक्षात्मक सेना (क्वॉरिंग ट्रूप्स) जो सीमाओं पर युद्ध का संचालन करे और बड़े युद्धों के समय एक ऐसे आवरण का काम करे जिसके पीछे समूची सैनिक गति विधियाँ बेरोकटोक होती रहे।
- 3 आंतरिक सुरक्षा सेना (इंटरनल सिनियारिटी ट्रूप्स) जो भारत के अंदर रक्षक दस्ते का काम करे।

यनसेना में चार डिवीजन और चार घुड़सवार ब्रिगेड (जब मशीन सज्जित) होते हैं और बताया जाता है कि किसी बड़े युद्ध की अवस्था में इन्हीं में दुश्मन पर भरपूर प्रहार किया जाता है।

1918 के युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने सैनिक व्यय का बोझ बिनने बड़े पैमाने पर भारत पर डाल दिया, इसका उदाहरण हम सैनिक खर्च के आनुपातिक आकड़ा से देख सकते हैं। निम्न तालिका से पता चलता है कि 1913 से 1928 के बीच ब्रिटेन, भारत और डोमोनियन राज्यों के सैनिक व्यय में कितनी आनुपातिक वृद्धि हुई

#### सैनिक व्यय, 1913-28

(लाख पाउंड में)

|               | 1913 | 1928 | प्रतिशत वृद्धि |
|---------------|------|------|----------------|
| ग्रेट ब्रिटेन | 770  | 1150 | 49             |
| भारत          | 220  | 440  | 100            |
| अन्य डोमोनियन | 90   | 120  | 33             |
| कुल योग       | 1080 | 1710 | 57             |

(ईस्टन आर्मामेंट्स सप्लिमेंट, 19 अक्टूबर 1929)

भारत पर (जिसे इस मामले में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था) यह बोझ दुगुना कर दिया गया जबकि ब्रिटेन पर इस बोझ में बाधा से भी कम और डोमोनियन पर तो एक तिहाई से भी कम वृद्धि हुई। 1914 के युद्ध से पहले कुल वज्र का 2/5 हिस्सा सैनिक कार्यों पर खर्च होता था। 1891-92 में यह व्यय 41 प्रतिशत और 1913-14 में 42.6 प्रतिशत था। 1914 के युद्ध से पहले कुल सैनिक व्यय औसतन 30 करोड़ रुपया था जो 1920-21 में बढ़े हुए कीमतों के समय 87 करोड़ 40 लाख रुपया या कुल वज्र का 51 प्रतिशत हो गया। 1925-26 तक कीमतों में बढ़ी आन के साथ इस राशि में भी बढ़ी आई और यह घटकर 56 करोड़ या 39 प्रतिशत हो गई। 1928-29 तक इस राशि में फिर वृद्धि हुई और यह बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई। सरकारी अनुमान व अनुमान

1936-37 में यह राशि कुल केंद्रीय बजट का 54 प्रतिशत और कद्र तथा प्राप्ति के मिल-जुल बजट का 29 प्रतिशत थी।

ब्रिटेन के लिए भारत का सामरिक महत्व दो विश्वयुद्धों के बीच के वर्षों में काफी बढ़ गया। मध्यपूर्व में अंगरेजों का नया साम्राज्य और प्रभावक्षेत्र भारत के आधार पर ही बनाया गया था। भूमध्य सागर पर नियंत्रण छोड़ने की महावित स्थिति का मुकाबला करने के लिए अंगरेजों ने साइमनटाउन में नया नौसैनिक अड्डा बनाया और कर्प माग पर जोर दिया तथा प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करने के माग पर कब्जा बनाए रखने के लिए सिंगापुर के तत्कालीन अपराजय नौसैनिक अड्डे पर जोर दिया। इन बातों से पता चलता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी भारत पर और भारत जाने वाले मार्गों पर अपने अधिकार को अपन साम्राज्य की धुरी मानते थे। जैसे जैसे भूमध्यसागर और स्वेज नहर का रास्ता दिनादिन महत्वपूर्ण होता गया वैसे वैसे ब्रिटेन को बगदाद कराची कलकत्ता और सिंगापुर तथा भारत और स्याम के जरिए सुदूर पूर्व होकर आस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले ब्रिटिश हवाई मार्गों का रास्ता ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। जैसे जैसे प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर और चीन के समुद्रतट तथा जलमार्गों पर जापान का कब्जा बढ़ता गया वैसे वैसे बर्मा होकर जाने वाले रास्ते का महत्व ब्रिटेन के लिए बढ़ता गया।

इन सारी नैयारियां में दोष का पता द्वितीय विश्वयुद्ध में चल गया। एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताकत ने नहीं बल्कि अमरीका, सोवियत मध्य और ब्रिटेन की मिलीजुली मदद से बुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय ने (जिसने अंतिम तौर पर जापान के खिलाफ शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया) एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा झेले गए घाटे और विनाश का अंतिम तौर पर निराकरण कर दिया। लेकिन इस समय तक एशिया के उपनिवेशों में मुक्तिआंदोलनों में काफी तजी आ गई थी और युद्ध के बाद पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का फिर से स्थापित करने के प्रयत्नों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

फिर भी यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय रणनीति में भारत का महत्वपूर्ण निर्णायक स्थान बना रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुत्व और प्रभावक्षेत्र के दो महत्वपूर्ण निरा, मध्यपूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया के बीच भारत एक बुरी का काम करता है और ब्रिटिश नीति के अनुसार यह एक ऐसा अड्डा है जो अपरिहाय है। जलाई 1944 में लेबर पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता लाड पैथिक सार्वजनिक हाउस आफ कामंस की उस के दौरान बड़े साफ शब्दों में कहा

तमाम गंभी घटनाएँ सामने आई हैं जिनसे माला समुद्रों में शांति कायम करने की ब्रिटेन की शक्ति पर सदेह पैदा होता है। और यह बात दुनिया के और किसी हिस्से में इतने साफ तौर पर नहीं देखी गई जितनी भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोस

म दखन म आई। जहा तक मरी धारणा ह, ब्रिटेन के लिए सैनिक दृष्टि स भारत एक महान बुज है। (इंडियन एनुअल रजिस्टर, 1914, पृष्ठ-2, पृ० 298)

एशिया म उपनिवेशवादविराधी राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ ब्रिटेन को बहुत गभीर लड़ाई लड़नी पड़ी और इसके लिए अंगरेजों ने अपने प्रमुख फौजी बड़ों के रूप म हमेशा भारत का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन न बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया जस एशियाई देशा म मुक्तिआंदोलनो का दमन करने के लिए और इन देशा पर औपनिवेशिक शासन फिर ने कायम करने के लिए न केवल भारत के साधना का इस्तेमाल किया बल्कि अपनी फौजा के लिए वहा लोगा की भरती भी की (यह काम वह तब तक करता रहा जब तक इंडोनेशिया के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने के लिए सैनिका की भरती के काम में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिरोध के कारण बाधा नहीं पड़ी)। अमरीका और ब्रिटेन की नीति म सोवियत सघ विरोधी जो खतरनाक प्रवृत्तिया थी उनका भारत पर अप्रत्यक्ष रूप स जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन द्वारा भारत भेज गए कैंब्रिज मिशन और 1946 म किए गए समझौता प्रस्तावों के पीछे सामरिक दृष्टि से की गई सोच की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तथाकथित जाजादी की बात के साथ साथ अंगरेजों ने भारत पर अपने सैनिक रणनीति नियंत्रण को और कारगर ढंग से मजबूत करने के व्यावहारिक उपायों को ही बढ़ावा दिया।

## 2 ब्रिटेन की अदरुनी राजनीति में भारत का महत्व

ब्रिटेन के लिए भारत के सामरिक महत्व के साथ साथ जो बात घनिष्ठ रूप स जुड़ी है वह है ब्रिटेन के अदरुनी सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के समूचे ढांचे और स्वरूप के लिए भारत के शोषण और नियंत्रण का सामाजिक राजनीतिक महत्व। हमने यह दख ही लिया है कि किस सीमा तक भारत का विशेष शोषण करके ब्रिटेन की पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का क्रमशः निर्माण हुआ है। यह काम 17वीं और 18वीं सदी में भारत की लूट के प्रारंभिक दौर के जरिए हुआ जिसने औद्योगिक क्रांति के लिए शुरू के दिना में पूँजी के संचयन को संभव बनाया। फिर 19वीं सदी में मशीन निर्माण के प्रमुख बाजार के रूप में और कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत का विकास किया गया और बाद के वर्षों में पूँजी का निर्यात करने वाले क्षेत्र के रूप में भारत को विकसित किया गया। इस घनिष्ठ आर्थिक संघर्ष की प्रतिनिधिता ब्रिटेन की जायिक-संरचना पर ही नहीं बल्कि इससे मेल खाते सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर तथा ब्रिटेन की समूची राजनीतिक धारा पर भी अनिवार्य रूप से हुई।

सीले ने एक्सपेंशन आफ इंग्लैंड' में खुद ही बड़े उद्धृत क्षणों में कहा था कि इतिहास का प्रत्येक छात्र यह मानता है कि रोमन साम्राज्य के दुस्स्वप्न के कारण ही रोम की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। सीले की यह टिप्पणी काफी गहरी चाट करती है और इसने

निष्पन्न जितने गंभीर है उतह वह शायद स्वयं स्वीकार करने को तैयार न हो। इंग्लैंड का आधुनिक इतिहास साम्राज्य और जनतन्त्र के निरन्तर संघर्ष से भरा पड़ा है।

18वीं सदी के मध्य में भारत की विजय काल से ब्रिटिश की घरेलू राजनीति पर साम्राज्य के प्रत्यक्ष प्रभाव के इस तत्त्व को निरन्तर देखा जा सकता है। 18वीं सदी की राजनीति पर और सुधार आंदोलन के पूर्व वाले समय के भ्रष्टाचार पर 'नवाबों' का कितना प्रभाव था, यह सभी नाग जानते हैं।

1783 में फ्रांस के सुधारवादी मतिमंडल का भारत के प्रश्न पर पराजय का सामना करना पड़ा और उसका स्थान पर प्रतिक्रियावाद का दीर्घकालीन शासन आरंभ हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के प्रति दुराग्रहपूर्ण प्रतिनातिकारी शत्रुता पैदा हुई और इंग्लैंड में जनतात्मिक सुधार का काम स्थगित हो गया। जब 1832 के सुधार विधेयक (रिफॉर्म बिल, न पुरातन आधिपत्य को समाप्त कर 19वीं सदी के लकाशायर के प्रभुत्व का स्थापित किया तो भारत के शोषण में लकाशायर ने ही एक अहम भूमिका निभाई। इसने 19वीं सदी के उदारतावाद की आकांक्षाओं को निष्फल करने के साथ उसे ऐसी दिशा दिखाई जिसमें प्रतिक्रियात्मक रूप में हमारे सामने उदार साम्राज्यवाद आया। तानाशाही शासन में प्रशिक्षित आंग्ल भारतीय शासकों के सेमे से ब्रिटिश की आंतरिक राजनीति में प्रतिक्रियावाद की शक्ति का निरन्तर भारती का काम जारी है और यह सिलसिला वेल्सिंगटन के शासनकाल से लेकर रजिन और लायड के शासनकाल तक जारी है। कजरवेटिव विचारधारा की अदहली धाराजी और दरारों के बीच आंग्ल भारतीयों और कट्टरपंथियों के घनिष्ठ संघर्ष को निरन्तर तलाशा जा सकता है।

ब्रिटिश के तत्पर आंदोलन में जो विकृति और पतनशीलता आई उसकी मुख्य जिम्मेदारी ब्रिटिश साम्राज्य के उस प्रभाव का है जिसका असर सत्ताधारी वर्ग के ही नहीं बल्कि मजदूरवर्ग के सदस्यों पर भी पड़ा था। इसलिए अधिकारपक्षवाद (ऑटिज्म) की नई और शक्तिशाली धारा ने दुनिया के मजदूरवर्ग को वर्गों की मुक्ति के लिए खुलेआम वर्ग-संघर्ष के रास्ते पर लाकर तथा औपनिवेशिक जनता के हित को अपनाकर 19वीं सदी में मजदूरों ने उच्चवर्ग के भ्रूणित समझौते को स्थान दिया और उन्हें मालिका का विनीत पिछलग्गू बना दिया। मार्क्स और एंगेल्स ने बार बार यह बताया है कि इस भ्रष्टाचार और पतन का मूल कारण यह है कि उपनिवेशों के शोषण से जा लूट का साल इकट्ठा होता है उनमें इन्हें भी हिस्सा मिलता है। इन उपनिवेशों में भारत का प्रमुख स्थान है। यही वजह है कि जब समाजवाद की जीवनदायी शक्ति ने नए सिर से ब्रिटिश के मजदूरवर्ग में जागृति का संचार किया तो यह प्रगति उदार साम्राज्यवाद (तत्पर इंपीरियलिज्म) के क्षयकारी प्रभाव से काफी हद तक कमजोर, विभाजित और विकृत हो गई। इसकी कीमत 1914 के युद्ध में और वर्तमान युद्ध में चुकानी पड़ी। भारत के मामलों में लेबर पार्टी के कार्यों का समनाक इतिहास देखने से पता चलता है कि ब्रिटिश मजदूरवर्ग की

आजादी से वंचित रखने वाला यह कैंगरू नेबर आंदोलन के प्रमुख वर्गों की नेता म कितनी गहराई तक धसा हुआ है। यह बात उन दोनों लेबर सरकारों के सदस्यों में भी सही है जिन्होंने एक जनतांत्रिक आंदोलन के दमन के लिए जारशाही के सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। नेबर पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी उसने भारतीय जनता के खिलाफ बार-बार कंजरवेटिव पार्टी की सरकार के साथ तालमेल बढ़ाया। 1937 में वून्माउथ में लेबर पार्टी के अधिवेशन की विषयसूची में एक प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि भारतीयों को एक मविधान सभा के जरिए आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। यह एक ऐसी जनतांत्रिक मांग थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था पर लेबर पार्टी के नेताओं ने इस बात की पूरी एहतिहास बरती कि यह प्रस्ताव अधिवेशन में न लाया जा सके और इसपर मतदान न कराया जा सके।

यहां तक कि आज जब इस प्रभुत्व का आधार लड़खड़ा रहा है और फलस्वरूप मजदूरों में एक वर्ष की परोक्ष उपलब्धियां समाप्त हो रही हैं साम्राज्यवाद के राजनेता अब भी ब्रिटिश साम्राज्य के मुनाफों का ब्रिटन के मजदूरवर्ग तथा ब्रिटिश जनता के हितों के लिए अपरिहाय बताने बढाए रखना चाहते हैं। इस सदस्य में चर्चिल ने कहा है

विदेशों के साथ हमारे व्यापक संबंध, हमारे निर्यात व्यापार का अब आधार हो गया है हमारी जहाजरानी जो इतने बड़े पैमाने पर ठप पड़ गई, और विदेशों में पूंजी लगाने से हुई आय जिनपर हमारी सामाजिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए भार डाला जा रहा है इन सबके बिना जितने लोग रह सकते हैं उनमें डेढ़ करोड़ ज्यादा लोग यहां हैं। मेरा ध्यान है कि इन द्वीपों में 20 या 30 लाख लोग उन परांपरिकी सेवाओं से अपना जीवन बसर कर रहे हैं जो हमारे और भारत के बीच परस्पर चलती हैं। (हाउस ऑफ कॉमन्स में विस्टेन चर्चिल का भाषण, 29 मार्च 1931)

भारत को अभी ब्रिटन के बेतनभोगियों के विषय में बहुत कुछ करता है। लकाशायर के कपासकर्मियों ने अब उसे समाप्त पाया है। उनमें से 1 लाख व्यक्ति पहले से ही खैरात पर काम चला रहे हैं, और यदि भारत को हमने छो दिया, यदि हमारे साथ ब्रिटिशशासित भारत ने भी वही व्यवहार किया जैसा ब्रिटिशशासित जायरलैंड ने किया था तो ज्यादा आश्चर्य इस बात की है कि इस दश में रोजीरोटी कमाने वाले 20 लाख लोग सबको की याक छानने नंगे और लेबर एक्मचेंजों के बाहर लाइन लगाने लगें। (भारत में वारे में विस्टेन चर्चिल का रेडियो प्रसारण, 29 जनवरी 1935)

- यह तब व्यवहार में भी उतना ही गलत है जितना मिट्टा में डूबपूण। एक दुर्भाग्यग्रस्त और नष्ट हो रही इज्जतदारी के दुकड़ा की रक्षा के लिए ब्रिटिश मजदूरों की स्वतंत्रता का



गुलाम ज़मसिद्ध अधिकार और अपने धर्म का भरपूर फल छाड़ देना पड़ेगा तथा गुलाम देश की जनता के विरुद्ध अपने मालिका की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इस नीति का नतीजा समृद्धि नहीं बल्कि बरबादी है। मौजूदा समय में यह बात व्यवहार में साबित हो चुकी है। भारत की आजादी नहीं दी गई है पर आजादी न देकर भी नौकरों के इच्छुक ब्रिटन के 20 लाख लोगो को लेकर एक्सचेंजों के सामने लाइन लगाने से नहीं रोका जा सका। 19वीं सदी की पुरानी इजारेदारी अब दुर्भाग्य का शिकार हो चुकी है और उसे देखाया नहीं जा सकता। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शोषकों के साथ कंधा मिलाना और ब्रिटिश सरकार के ही नहीं बल्कि ब्रिटिश जनता के प्रति भी गुलाम देशों की जनता के बीच शत्रुता की भावना को तज करना एक ऐसी हरकत है जिसका नतीजा यह होगा कि ब्रिटन एकदम अलग यत्न पड़ जाएगा और ब्रिटिश जनता बरबाद हो जाएगी। इसके विकल्प की तलाश विरादराना उत्पादन संबंधों पर ही की जा सकती है, इसके ही जरिए ब्रिटिश मजदूरों के सम्मानजनक और समृद्ध अस्तित्व का प्रयोजन पूरी तरह सिद्ध हो सकता है। वह आधार भी पाया जा सकता है लेकिन इसे पाने का आधार भी उन लोगो की समान मैत्री पर निर्भर होगा जो साम्राज्यवादी शोषण के पुराने संबंधों का समाप्त करने नए संबंध कायम करने में लगे हैं।

साम्राज्यवादियों की आपसी होड़ का परिणाम हमने एक बार फिर एक नए घातक विश्व-युद्ध के रूप में देख लिया है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश मजदूरवर्ग और ब्रिटिश जनता के सामने विकल्प के रूप में एक नया मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। यह मार्ग समान जनतावादी अधिकारों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, विश्वशांति और फिर समाजवाद के लिए समान रूप से संघर्ष में जुटो भारतीय जनता और सभी गुलाम देशों की जनता के साथ एकता कायम करने का मार्ग है। इन मामलों पर ब्रिटिश जनता का सजग होना भारतीय जनता के सजग होना की तुलना में किसी भी मान में कम महत्वपूर्ण नहीं है।

### 3 राष्ट्रवाद और विदेशनीति

ब्रिटन की अंतर्राष्ट्रीय नीति और ब्रिटन की फरेलू राजनीति के लिए भारत का सामरिक महत्व बना रहा है, इसपर विचार करें तो पता चलता है कि भारत की भूमिका हमेशा एक कठपुतली की रही है, उसने विश्वमक्तियों और संघर्षों के संतुलन में एक भूमिका बतली यह कह कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन इस भूमिका का चुनाव उसकी संसद ने नहीं हुआ और न इसपर उसका कोई बल ही रहा। आज वह स्थिति समाप्त हो रही है। भारत की जनता आज भारतीय मामलों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी अपने अधिकारों की दृढ़ता के साथ खड़ी रही है।

1914 में युद्ध से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मसला के उदय में कोई सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश नहीं की। उसकी यह कोशिश केवल इन तीन मामलों में ही रही जसे विदेश में रहने वाले भारतीयों का विशेष मसला और

ब्रिटिश साम्राज्य के जय दगा की असमर्थताएँ जिनका उन्हें शिकार होना पड़ता था।

इस युग में विश्व के प्रमुख राजनीतिक मनलों के सदस्य में महत्व के इस बोध से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि यह तटस्थता के अथवा सुविचारित अलगवा के कारण है। राजनीतिक आंदोलन में शामिल लोग और यहाँ तक कि इन आंदोलनों से काफी अलग पड़ लोगों के भी कुछ कम विदेशों में घटित हो रही राजनीतिक घटनाओं में बहद दिलचस्पी ले रहे थे और वे सोच रहे थे कि इन घटनाओं का भारत की मुक्ति पर क्या असर पड़ सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के कमजोर होने के हर संकेत को वे बड़ी उत्सुकता के साथ देखते थे और इनके अंदर आशा का संचार होता था। दक्षिण अफ्रीकी युद्ध इसका प्रमाण है। 1905 में जब जापान की जीत हुई तो उन लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ और उन्होंने इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद की अब तक अजेय समझी जाने वाली शक्ति पर किसी एशियाई दश की पहली सफलता के रूप में लिया। ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ मिस्र और थाइलैंड के संघर्ष, बड़ी शक्तिशाली लूट-मार की योजना के खिलाफ सेंट-पिटर्सबर्ग की योजना के संघर्ष या विभाजन की ब्रिटिश रूसी योजना के विरुद्ध कार्रवाई के संघर्ष के प्रति इन लोगों ने गहरी सहानुभूति दिखाई। 1905 की रूसी क्रांति, टर्की की क्रांति और चीनी क्रांति ने इनमें एक नए जीवन का संचार किया। इन सारी घटनाओं से इस बात का संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चेतना की गुरुजात हो चुकी है।

1914 के युद्ध ने और 1917 की रूसी क्रांति ने एक नई स्थिति को जन्म दिया। 1914 के युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्हें यह उम्मीद थी कि इस समर्थन के पुरस्कारस्वरूप उन्हें भारत की जनतांत्रिक दिशा में आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जिस समय युद्ध की घोषणा हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लन्दन में था जिसमें लाजपत राय, जिन्ना, तिलक तथा कुछ अन्य लोग थे। इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की शान्ति विजय के लिए अपने सहयोग की घोषणा करने में तैयारी नहीं की। गांधी की भूमिका का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। युद्ध के प्रारम्भ वर्षों में जहाँ तहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवक्ताओं में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों की जयजयकार की गई।

हरदयान बरसतुलना का जूगारू राष्ट्रवात्तिया के एक छाटन गुट ने जमनी के गाँव गवध स्थापित किया और उन्होंने उन भारतीय गमिनी का गठन किया जिनके इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। भारत के अंदर राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थकों के बीच संचालन कर रहे थे।

युद्ध समाप्त होने के समय तक भी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ यह आभारित्व के व्यापक चरणों का साथ -

1. भी मि

2. यह कि  
गाँव

सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए तिलक को चुना गया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पामपाट दन से इकार कर दिया और वह इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। इससे बाद तिलक ने शांति सम्मेलन के अध्यक्ष जेम्स के नाम एक पत्र लिखा ताकि भारत के दावा पर बल दिया जाए। अपने पत्र में उन्होंने लिखा

इस बात को विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि विश्व की भावी शांति और भारत की जनता की प्रगति के लिए भारतीय समस्या का हल किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत स्वतः पूर्ण है, दूसरे देशों की अछड़ता के खिलाफ उसकी कोई योजना नहीं है और दश से बाहर उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अपने व्यापक क्षेत्रफल, असीमित साधनों और अतिविशाल आबादी के कारण वह बड़े आराम से एशिया की प्रमुख ताकत बन सकता है। इसलिए वह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए और एशिया या और कहीं के शांति विरोधियों के हूर तरह के आक्रमणों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रसंघ का एक शक्तिशाली कारिदा हो सकता है।

1919 का यह दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला दस्तावेज है और इसमें पता चलता है कि उस समय किम तरह की विचारधारा हावी थी।

इन आशाओं का धूल में मिलना ही था। 'भारत' को राष्ट्रसंघ का मौलिक सदस्य बना लिया गया। एन समय में जबकि भारत पर ब्रिटेन का पूरी तरह कब्जा हो और ब्रिटन ही भारत की समूची नीतिमा का निर्धारण करता हो तथा उसका प्रतिनिधित्व करता हो, इस तरह की 'सदस्यता' देना कितना अमंगल है। प्रोफेसर ए० बी० कोथ ने इसपर बड़ी तीखी टिप्पणी की है

1919 की बुनियादी गलती यह थी कि भारत को राष्ट्रसंघ में ऐसे समय स्थान दिया गया जब उसकी घरेलू और विदेशी नीति पर पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। लीग की सदस्यता का औचित्य तभी ठहराया जा सकता था जब भारत को स्वायत्तता दी जाती। ग्रेट डोमोनियनो की बात में सदेम में इसकी वाप्यायदा भविष्यवाणी की जा सकती थी पर भारत के बारे में फिलहाल यह सच नहीं था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में यह स्वीकार करना ज्यादा युद्धिमत्तापूर्ण है कि भारत को फिलहाल राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हा, जब उस स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी तब उसे उसका विनिष्ट सदस्य बना लिया जाएगा अनी राष्ट्रसंघ में भारत की स्थिति स्पष्ट असमयियों से भरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नीतियां अभी

ब्रिटिश साम्राज्य के जय दशा की जममयताएँ जिनका उच्छेद शिकार होना पड़ता था।

इस युग में विश्व के प्रमुख राजनीतिक मसलों के सदभ में महत्व के इस बोध से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि यह तदस्थता के अथवा सुविचारित अलगाव के कारण है। राजनीतिक आंदोलन में शामिल लोग और यहाँ तक कि इन आंदोलनों से काफी अलग पड़े लोगों के भी कुछ वग विदेशों में घटित हो गयी राजनीतिक घटनाओं में बहद दिलचस्पी ले रहे थे और वे सोच रहे थे कि इन घटनाओं का भारत की मुक्ति पर क्या असर पड़ सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के कमजोर होने के हर संकेत को वे बड़ी उत्सुकता के साथ देखते थे और उनके अंदर आशा का संचार होता था। दक्षिण अफ्रीकी युद्ध इसका प्रमाण है। 1905 में जब जापान की जीत हुई तो उन लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ और उन्होंने इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद की अवतक अजेय समझी जाने वाली शक्ति पर किसी एशियाई देश की पहली सफलता के रूप में लिया। ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ मिन्न और आयरलैंड के संघर्ष, बड़ी शक्तियाँ की लूट मार की याजना के खिलाफ सकटग्रस्त टर्की साम्राज्य के संघर्ष या विभाजन की ब्रिटिश रूसी योजना के विरुद्ध फारस के संघर्ष के प्रति इन लोगों ने गहरी सहानुभूति दिखाई। 1905 की रूसी क्रांति, टर्की की क्रांति और चीनी क्रांति ने इनमें एक नए जीवन का संचार किया। इन सारी घटनाओं से इस बात का संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चेतना की गुरुवात हो चुकी है।

1914 के युद्ध ने और 1917 की रूसी क्रांति ने एक नई स्थिति को जन्म दिया। 1914 के युद्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के बड़े नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्हें यह उम्मीद थी कि इस समय के पुरस्कारस्वरूप उन्हें भारत को जनतांत्रिक दिशा में आगे ले जाने में मदद मिलेगी। जिस समय युद्ध की घोषणा हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लंदन में था जिसमें लाजपत राय, जिन्ना, सिन्हा तथा कुछ अन्य लोग थे। इन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य की शीघ्र विजय के लिए अपने सहयोग की घोषणा करने में तनिक भी देर नहीं की। गांधी की भूमिका का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में जहाँ तहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों की जयजयकार की गई।

हरदयाल, वरकतुल्ला जैसे जुझारू राष्ट्रवादियों के एक छोटे से गुट ने जर्मनी के साथ संबंध स्थापित किया और उन्होंने बर्लिन में एक भारतीय समिति का गठन किया लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के वामपंथी तत्व उग्र संघर्षों का संचालन कर रहे थे।

युद्ध समाप्त होने के समय तक भी राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग यह आशा किए बैठे थे कि आत्मनिर्णय के व्यापक वायदों का लाभ शायद भारत का भी मिल जाए। बर्साई शांति

सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए तिलक को चुना गया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया और वह इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। इसके बाद तिलक ने शांति सम्मेलन के अध्यक्ष क्लेमेंसो के नाम एक पत्र लिखा ताकि भारत के दावों पर ध्यान दिया जाए। अपने पत्र में उन्होंने लिखा

इस बात को विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि विश्व की भावी शांति और भारत की जनता की प्रगति के लिए भारतीय समस्या का हल किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। भारत स्वतंत्र पूर्ण है, दूसरे देशों की अखंडता के खिलाफ उसकी कोई योजना नहीं है और देश से बाहर उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अपने व्यापक क्षेत्रफल, असंमित साधनों और अतिविशाल आबादी के कारण वह बड़े आराम से एशिया की प्रमुख ताकत बन सकता है। इसलिए वह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए और एशिया या और कहीं के शांति विरोधियों के हर तरह के आक्रमणों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रसंघ का एक शक्तिशाली कारिदा हो सकता है।

1919 का यह दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला दस्तावेज है और इससे पता चलता है कि उस समय किस तरह की विचारधारा हावी थी।

इन आशाओं को धूल में मिलना ही था। भारत को राष्ट्रसंघ का मौलिक सदस्य बना लिया गया। ऐसे समय में जबकि भारत पर ब्रिटेन का पूरी तरह कब्जा हो और ब्रिटेन ही भारत की समूची नीतियों का निर्धारण करता हो तथा उसका प्रतिनिधित्व करता हो, इस तरह की सदस्यता देना कितना असंगत है। प्रोफेसर ए० बी० कीय ने इसपर बड़ी तीखी टिप्पणी की है

1919 की बुनियादी गलती यह थी कि भारत को राष्ट्रसंघ में ऐसे समय स्थान दिया गया जब उसकी घरेलू और विदेशी नीति पर पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। लोग की सदस्यता का औचित्य तभी ठहराया जा सकता था जब भारत को स्वायत्तता दी जाती। ग्रेट ब्रीटेनियों की बात के सद्व्यवहार में इसकी बाकायदा भविष्यवाणी की जा सकती थी पर भारत के बारे में फिलहाल यह सच नहीं था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में यह स्वीकार करना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण है कि भारत को फिलहाल राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जब उस स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी तब उस उसका विशिष्ट सदस्य बना लिया जाएगा अभी राष्ट्रसंघ में भारत की स्थिति स्पष्टतः असंगतियों से भरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नीतियाँ अभी

ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह नम अभी अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। (सर ए० बी० कीथ कास्टाट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया पृष्ठ 472-73)

एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन के बुजुर्ग नेतागण जब भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपना स्वाभाविक नतीजा मान रहे थे और सामाजिक रूप से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता देने के एक शक्तिशाली कार्रवाई के रूप में पेश कर रहे थे (जैसा कि 1919 में लिखे तिलक के पत्र से स्पष्ट है) और दूसरी तरफ प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से ही नई धाराएं विकसित हो रही थीं। 1917 की रूसी क्रांति, युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व भर में चली क्रांतिकारी लहर और सभी गुलाम देशों में उपनिवेशवादविरोधी मुक्ति आंदोलनों ने दुनिया के सामने एक ऐसे नए युग का सूत्रपात किया जिससे भारत का बहुत घनिष्ठ संबंध था। पश्चिमी साम्राज्यवाद के पुरातन प्रतिक्रियावादी चेहरे के विरुद्ध, सोवियत संघ के व्यापक समान हितों से, अंतराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन से तथा उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से विश्व की शक्तियां नए सिरे से पक्षितबद्ध हुईं। विश्व के इस नए मोर्चे के प्रति भारतीय राष्ट्रवाद की सभी प्रगतिशील धाराएं ने बड़े उत्साह के साथ अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की।

1925-27 के दौरान चीन की राष्ट्रीय क्रांति के विकास पर भारत की जनता ने काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें चीनी क्रांति के विरुद्ध लंडन के लिए भारतीय सैनिकों के शिपवाई भेज जाना का विरोध किया गया था। उसी वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्पीड़ित जनता की साम्राज्यवाद विरोधी अंतराष्ट्रीय लीग (इंटरनेशनल लीग ऑफ दि अप्रेसस्ड पीपुल्स अगस्ट इंपीरियलिज्म) की स्थापना में भाग लिया और स्वयं को इस लीग के साथ संबद्ध किया। इस सिलसिले में ब्रसेल्स में हुई कांग्रेस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नेहरू ने किया। उपनिवेशों की जनता और अंतराष्ट्रीय मजदूरवर्ग को जोड़ने वाली साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों के सामूहिक मोर्चे के विकास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी।

फासिस्ट युद्ध अभियान के तत्पश्चात् होने के साथ-साथ फासिस्ट हमले को सहयोग पहुंचाने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहायराधिता को देखते हुए, जिसकी परिणति एक विश्वयुद्ध में हुई, यह चेतना और भी अग्रेसर हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने जर्मनी-रूसीयों की जनता का और स्पेन के जनतंत्र का पक्ष लिया और उन्हें व्यावहारिक मदद दी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सितंबर 1936 में ब्रसेल्स में आयोजित वर्ल्ड पीस कांग्रेस में हुआ और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय दृष्टिकोण के तहत अपने को अंतराष्ट्रीय शांति अभियान से संबद्ध किया। भारतीय दृष्टिकोण यह था कि साम्राज्यवादी शोषण के आधार पर स्थाई शांति नहीं कायम हो सकती किसी भी ऐसी संधि का पवित्र नहीं माना जाएगा जो साम्राज्यवादी

प्रभुत्व को बनाए रखने के पक्ष में ही और भारत राष्ट्रमध्य में एक स्वतंत्र सदस्य की हैसियत से काम करने के लिए आजादी चाहता है।

1936 में जब स्पानी जनतंत्र के विरुद्ध जर्मनी और इटली की आक्रामक फायवाहिया के सदन में ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारें 'हस्तक्षेप न करने' की नीति का समर्थन कर रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1936 में अपने फजावाद अधिवेशन में एलान किया

फासिस्ट आक्रमण बढ़ गया है। फासिस्ट शक्तियाँ यूरोप और समूचे विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम करने तथा राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का दमन करने के इरादे में आपस में गठबन्दी और गुटबध्द कर रही हैं। कांग्रेस इस खतरे के प्रति पूरी तरह सजग है और इस विश्वव्यापी खतरे को वह दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों तथा प्रगतिशील जनता के सहयोग से इस विश्वव्यापी खतरे का मुकाबला करने की आवश्यकता को पूरी तरह महसूस करती है।

फरवरी 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन ने, 'सामूहिक सुरक्षा' के समर्थन की घोषणा की और फासिस्ट आक्रमण के साथ सहापराधिता की उस नीति की भर्त्सना की जो युद्ध के खतरे को दिनोदिन नजदीक लाती जा रही थी। 1938 में जापानी माल का बहिष्कार करने की घोषणा की गई। 1938 के वसंत में राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन ने स्पष्ट शब्दों में म्यूनिखनीति से भारत को अलग कर लिया

कांग्रेस ब्रिटेन की उस विदेशनीति को पूरी तरह नामजूर करती है जिसकी चरम परिणति है म्यूनिख संधि, जर्मन इतालवी समन्वयता, और विद्रोही स्पेन को मायता। इस नीति ने जानबूझकर जनतंत्र के साथ विश्वासघात किया है बार बार अपने वादा को भंग किया है, सामूहिक सुरक्षा को समाप्त किया है, और उन सरकारों के साथ सहयोग किया है जो जनतंत्र और स्वतंत्रता की घोर दुश्मन हैं। कांग्रेस अपने को पूरी तरह उस ब्रिटिश विदेशनीति से अलग करती है जिसने निरंतर फासिस्ट शक्तियों की मदद की है और जनतांत्रिक देशों के विनाश में सहायता पहुँचाई है।

इस प्रकार काफी पहले 1939 में ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध की गई युद्ध घोषणा ने पूरे के नाजुक वर्षों में ही जब ब्रिटिश सरकार फासिस्ट हमलावरों का व्यावहारिक और कूटनीतिक मदद दे रही थी, भारतीय जनता ने अपने राष्ट्रीय नेताओं के जरिए फासीवाद के प्रति अपने विरोध का और विश्व की जनतांत्रिक तथा प्रगतिशील शक्तियों के प्रति समर्थन का एलान कर दिया था।

#### 4 भारत और विश्वयुद्ध (1939-1942)

1939 में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो ब्रिटिश सरकार ने उसी नीति का पालन करना चाहा जो 1914 के युद्ध के समय अपनाई गई थी। भारत को ब्रिटिश नीति के हावा की कठपुतली बना दिया गया जो अपने देश की जनता से सलाह-मशविरा किए बिना अपने आप ही ब्रिटेन के पीछे पीछे युद्ध में घिसटता चला गया।

युद्ध की घोषणा के कुछ ही घंटा के अंदर वायसराय ने भारतीय जनता के प्रतिनिधियों से किसी तरह का सलाह-मशविरा किए बिना भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ब्रिटिश मजद ने चटपट 11 मिनट के अंदर 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमंडिंग ऐक्ट' पारित कर दिया जिसमें वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि वह प्रांतों की स्वायत्तता के प्रश्न पर भी संविधान के कार्यों को रद्द कर सकता है। 3 सितंबर 1939 के भारतरक्षा अध्यादेश ने केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वह राजाज्ञा (डिक्री) के जरिए शासन कर सकती है। ऐसे कानूनों की घोषणा कर सकती है जो 'ब्रिटिश भारत की रक्षा जनजीवन की सुरक्षा, सांख्यिक व्यवस्था, युद्ध के कुशल संचालन या समाज के लिए आवश्यक सामानों और सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी मामले जाएं', सभाओं तथा प्रचार के अर्थ तरीकों पर पाबंदी लगा सकती है, बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और वायद-कानूनों को तोड़ने के अपराध में जुमाने कर सकती है। इनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है।

11 सितंबर को वायसराय ने राज्यसभ की तैयारियां का स्वयं कर्त्तव्य की घोषणा की। भारत में निरंकुश शासनव्यवस्था को अब संविधान का कोई दाग रचे बिना जारी रखने की योजना बनाई गई और इस अत्यंत व्यापक असाधारण अधिकारों के जरिए मजबूत बनाया गया। 25 वर्ष पहले की ही तरह एक बार फिर भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के पीछे घिसटते हुए एक ऐसे युद्ध में शरीक हो जाना पड़ा जिसमें वचन का उसके पास कोई रस्ता नहीं था और जिसके बारे में उसने लगातार उस नीति का विरोध किया था जिसके कारण युद्ध अनिवार्य बना।

घटनाक्रमों ने जल्दी ही दिखला दिया कि 1914 के मुकाबले भारत की स्थिति कितनी भिन्न थी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति ने युद्ध के सदर्भ में अपना बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया था

यह समिति एक ऐसे युद्ध से न तो स्वयं का संबंध कर सकती है और न इस युद्ध के साथ सहयोग कर सकती है जो साम्राज्यवादिया नीति पर चल रहा



हो और जिसका मकसद भारत तथा अन्य देशों में साम्राज्यवाद को मजबूत बनाना हो।

प्रस्ताव में यह मांग की गई

भारत की जनता को किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना एक संविधान सभा के जरिए अपने संविधान का गठन करके आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उसे अपनी नीति स्वयं निर्धारित करने का अधिकार मिलना चाहिए।

इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के लिए प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत कर दी

इसलिए कांग्रेसमिति ब्रिटिश सरकार का उस बात के लिए निमन्त्रित करती है कि वह स्पष्ट शब्दों में बताए कि इस लड़ाई में जनतंत्र और साम्राज्यवाद के विषय में उसके क्या उद्देश्य हैं और खासतौर से जिस नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, उस सदन में ये उद्देश्य कहा तक भारत पर लागू होने जा रहे हैं और मौजूदा स्थिति में उन्हें किस प्रकार कारगर बनाया जा रहा है। क्या इन उद्देश्यों में साम्राज्यवाद को समाप्त करना और भारत के एक ऐसे स्वतंत्र देश जैसा व्यवहार करना शामिल है जिसकी नीति देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्देशित हो?

राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सीधे सवाल के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने जो जवाब दिया वह वस्तुतः नकारात्मक था। ब्रिटिश सरकार ने अपना वही पुराना वादा दुहराया जिसमें भविष्य में कभी 'डोमोनियन का दर्जा' देकर किसी तरह की रियायत देने की बात कही गई थी (पिछले विश्वयुद्ध के समय भी ऐसी ही परिस्थितियों में इसी तरह के उसने किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हो सके) और इस तरह के वादों की आड़ लेकर वादे अपना तात्कालिक कार्यक्रम एक 'परामश समिति' का गठन करना घोषित किया। परामश समिति, भारत को गुलाम बनाए रखने और युद्ध के संचालन को बढ़ावा देने के लिए वायसरॉय को मदद पहुंचाने के वास्ते भारतीयों के लिए बनाई गई थी।

राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के नेताओं के बीच की यह प्रारंभिक कूटनीतिक मुठभेड़ उस गहरे संघर्ष का पहला संकेत था जो जबर ही जबर पनप रहा था। कांग्रेस के नेतागण वायसरॉय के साथ इन कूटनीतिक घाताओं में लगे हुए थे जबकि जनता न आंदोलन छेड़ दिया था। 2 अक्टूबर को बंबई के 90 000 मजदूरों ने युद्ध और साम्राज्यवाद के दमनकारी उपायों के खिलाफ एक दिन की राजनीतिक हड़ताल की। बंबई की सड़कें 'साम्राज्यवादी युद्ध का नाश हो', 'भारतीय आजादी अमर रहे', 'ताल चड़ा की जीत हो' के नारा से गूँज उठी। युद्ध में सलग्न किसी भी देश में हुई यह पहली युद्धविरोधी

जन हड़ताल थी। हड़ताल के अंत में कामगार मैदान में आयोजित आमसभा में सचसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया

यह सभा दुनिया के मजदूरों और दुनिया की जनता के साथ अपनी एकता व्यक्त करती है जिन्हें साम्राज्यवादी शक्तियाँ द्वारा अत्यंत विनाशकारी युद्ध में घसीटा जा रहा है। यह सभा वर्तमान युद्ध को मजदूरवर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती मानती है और घोषित करती है कि विभिन्न देशों के मजदूरों और लोगों का यह कतव्य है कि वे मानवता के विरुद्ध की गई इस साजिश को नाकाम करें।

बंबई के मिलमजदूरों के इस प्रस्ताव में भारतीय मजदूरवर्ग के संघों का साम्राज्यवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मजदूरवर्ग द्वारा चलाए जा रहे संघों का एक हिस्सा समझा गया।

वायसराय के नकारात्मक जवाब के कारण अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 के वसंत में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया

भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की ओर से की गई हाल की घोषणाओं से पता चलना है कि ग्रेट ब्रिटेन मूलतः साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही यह लड़ाई लड़ रहा है—इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कांग्रेस परोक्ष या अपरोक्ष किसी भी रूप में युद्ध में शरीक नहीं होगी।

1940 की गर्मियों में यूरोप में नाज़ियों के बढ़ने के साथ और फ्रांस के पतन तथा युद्ध का सकट गहराने के साथ कांग्रेस ने ब्रिटेन के साथ सहयोग का प्रस्ताव किया, बशर्ते भारत को आजादी दे दी जाए और केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए जो भले ही अस्थायी स्तर पर हो लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में सभी निर्वाचित सदस्यों का उसे विश्वास प्राप्त हो—यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए तो देश की रक्षा के लिए कारगर संगठन बनाने के प्रयत्नों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी। यह प्रस्ताव जिसे स्पष्ट रूप में गांधी की अहिंसा की नीति से अलग होना ही था, जुलाई 1940 में पूना में दा तिरुहाइ बहुमत से स्वीकार किया गया। मतदान का परिणाम यह देखा गया कि 91 लोग अहिंसा की नीति को छोड़ने के पक्ष में थे जबकि 63 लोग इसके विपक्ष में थे, और 95 लोग ब्रिटेन के साथ सशत सहयोग करने के तथा 47 लोग सहयोग न करने के पक्ष में थे।

लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर इस प्रस्ताव पर नकारात्मक रवैया अपनाया। 8 अगस्त 1940 को वायसराय के दयान में (इस अवसर पर 'अगस्त प्रस्ताव' कहा जाता

है और बाद के वर्षों में क्रिप्स की योजना तथा नीति सख्ती अन्य वक्तव्यों का यही आधार बनाया गया था) घोषणा की गई कि 'भारत की शांति और खुशहाली को देखते हुए ब्रिटिश सरकार अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को किसी ऐसी सरकार को हस्तांतरित करने के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसकी सत्ता को देश के राष्ट्रीय जीवन के बड़े और शक्तिशाली तत्व प्रत्यक्ष तौर पर न मानते हों', अर्थात् मुस्लिम लीग और राजाओं-महाराजाओं को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वे भारत की किसी भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में वोटों का इस्तेमाल कर सकें। विकल्प के रूप में यह प्रस्ताव रखा गया

- 1 नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्वों को प्रतिनिधि संस्था की युद्ध के बाद स्थापना की जाए।
- 2 वायसराय की इक्जीक्यूटिव कीमिल में कुछ और भारतीयों को नामजद करके इसे विस्तार दिया जाए।
- 3 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों तथा अन्य भारतीयों को लेकर एक 'युद्ध सलाहकार परिषद' का गठन किया जाए।

यह उत्तर इतना असंतोषजनक था कि कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में एक व्यक्तिगत संविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया और अक्टूबर 1940 में यह आंदोलन छेड़ दिया गया।

साम्राज्यवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए दबाव डालने वाली शक्तियों का विकास कितनी तीव्रता के साथ हो रहा था इसकी अभिव्यक्ति 1939-40 से मजदूरों, किसानों और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों के खिलाफ सरकार द्वारा किए गए बबर दमन में ही नहीं बल्कि गांधी द्वारा शुरू किए गए अत्यंत सीमित और चारों तरफ से घिरे संघर्ष के स्वरूप में भी होती है। यह किसी भी रूप में आजादी के लिए किया जाने वाला संघर्ष नहीं था। यह बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया एक सांकेतिक सत्याग्रह था। संविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों के नाम की सूची गांधी के पास भेजी जाती थी ताकि वह पूरी तरह जांच ले और अपनी स्वीकृति दे। गांधी जिन नामों को अपनी स्वीकृति देते थे उनके लिए यह जरूरी था कि वे पहले से ही पुलिस को बता दें कि कब और किस जगह वे युद्ध के खिलाफ अपना सांकेतिक विरोध प्रकट करने जा रहे हैं। इसके बावजूद बाद के महीना में लगातार बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती रही और लोग जेलों में डाले जाते रहे (एक सरकारी बयान के अनुसार 24 मई 1941 तक संयुक्त प्रांत के ही 12,000 लोग पकड़े जा चुके थे और अनुमानित इस समय दश भर में गिरफ्तार लोगों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई थी। गिरफ्तार लोगों में प्रांतीय विधानसभाओं के 398 सदस्य, 31 भूतपूर्व मंत्री और केंद्रीय विधानमंडल के 22 सदस्य थे)।

देश इसी प्रकार के गतिरोध की स्थिति में पड़ा था जब 1941 के उत्तरार्ध की घटनाओं से युद्ध के स्वरूप में जबरदस्त तब्दीली आई। ये घटनाएँ थी सोवियत संघ पर जर्मनी का हमला, ब्रिटिश सोवियत संघ और सुदूर पूर्व में जापान का आक्रमण और ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ तथा चीन के नेतृत्व में ब्रिटिश सोवियत मध्य का मित्र राष्ट्रों के मिलेजुले मोर्चे का रूप लेना।

इन तमाम कारणों से युद्ध के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन आ गया और भारत के लिए इसका महत्व बढ़ गया जिसपर भारत के राष्ट्रवादी जनमत ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिसंबर 1941 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की 'दुनिया की प्रगतिशील ताकतें अब उस गुट के साथ पवित्रबद्ध हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूस, ब्रिटेन, अमरीका और चीन कर रहा है।'

युद्ध के बदले हुए स्वरूप पर राष्ट्रीय आंदोलन के सभी हिस्सों ने तत्काल इतनी निश्चित प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। अब भी कुछ हिस्से ऐसे थे जा गांधी की 'अहिंसक' शांतिवादी विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे। अन्य लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ किसी प्रकार के सहयोग के प्रति सशक्त थे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जिम्मेदार नेताओं ने, जिनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस अध्यक्ष, मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू बहुमत के समर्थन से कर रहे थे, बराबरी के स्तर पर संयुक्त राष्ट्रों के मित्र राष्ट्र की हैसियत से सहयोग का आधार ढूँढने की कोशिश की। स्पष्टतः यह ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों के हित में था कि वे इन शक्तियों के साथ समझौते का कोई आधार तलाशने की कोशिश करते। इस प्रकार 1941 के उत्तरार्ध से ब्रिटिश सरकार के सामने एक अनुकूल स्थिति पैदा हो गई यद्यपि वे एक नई भावना के साथ इस नई स्थिति का सामना करने को तैयार होत।

इन प्रस्तावों पर ब्रिटिश सरकार की पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। अगस्त 1941 में अंतर्लातिका चाटर्ने ब्रिटिश और अमरीकी सरकार की प्रतिभूत नीति का निर्धारण किया जिसका बाद में सभी संयुक्त राष्ट्रों ने पालन किया।

वे सभी दशा की जनता के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि जिस सरकार में अधीन उस (जनता का) रहता है उस सरकार का चुनाव वह अपनी इच्छानुसार कर, और वे चाहते हैं कि उन सभी लोगों को प्रभुसत्ता के अधिकार मिलें और स्वराज्य मिले जिन्हें इन चीजों से जबरन वंचित कर दिया गया है।

लेकिन 9 दिसंबर 1941 का प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल ने अपने भाषण में सरकार की ओर से वाक्य 'हमारी सैन्य शक्ति धीमा हो रही है' कहा कि भारत, रूस तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर अन्तराष्ट्रिय चाटर्न लागू नहीं होगा। उठा। कहा

अतलातिक चाटर के सिलसिले में हुई बैठक में हमारे दिमाग में मूलतः यूरोप के उन देशों को फिर से प्रभुसत्ता, स्वराज्य और राष्ट्रीय जीवन प्रदान करना था जो नाज़ियों के जुए तले पड़े हुए थे।

इस संशोधन से भारत के राष्ट्रीय जनमत को बहुत क्रोध आया और संयुक्त राष्ट्रा की विरोधी प्रवृत्तियों को बल मिला।

फिर भी दिसंबर 1941 में सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा कर देना नए सिरे से बातचीत शुरू करने की दिशा में पहला कदम था। इससे सहयोग का आधार ढूँढ़ने की दिशा में नई प्रगति हुई। दिसंबर 1941 की समाप्ति तक राष्ट्रीय कांग्रेस के वारदोली अधिवेशन ने (जनवरी 1942 में अभिपुष्ट) इस सिद्धांत की घोषणा की कि भारत संयुक्त राष्ट्रों के मित्र की हैसियत से फासिस्ट धुरी राष्ट्रों के खिलाफ हथियार लेकर लड़ेगा वरन् उसे यह अवसर मिले कि वह एक राष्ट्रीय सरकार के तहत जनता को गोलबंद कर सके। प्रस्ताव में कहा गया

यद्यपि भारत के प्रति ब्रिटेन की नीति में कोई तब्दीली नहीं आई है फिर भी समिति युद्ध के कारण घटित घटनाक्रमों पर तथा भारत के प्रति इसके रुख पर विचार करती है। कांग्रेस की महानुभूति निश्चित रूप से उही लोगों के साथ होगी जो आक्रमण के शिकार हैं और गुलाम बनाए गए हैं तथा अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक स्वतंत्र और स्वाधीन भारत ही ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर देश की रक्षा का दायित्व संभाल सके।

इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से गांधी की छुट्टी हो गई क्योंकि वह अहिंसा की नीति छोड़ने पर सहमत नहीं थे।

इस प्रस्ताव पर 'टाइम्स आफ इंडिया' ने यह टिप्पणी की

इस प्रस्ताव ने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते का दरवाजा फिर से खोल दिया है। इस प्रस्ताव के साथ एक महत्वपूर्ण पहल की गई है और हम आशा करते हैं कि बदले में हम भी ऐसा ही फल प्राप्त होगा।

रास्ता खुला था, केवल ब्रिटेन की ओर से कुछ राजनीतिज्ञता तथा अनुकूल प्रतिनिध्या की दरकार थी।

फरवरी 1942 में जनरल लिस्सिमो ज्योग काई शेक की भारत यात्रा से इस अनुकूल शुरुआत को और मदद मिली। उन्होंने साथ-साथ ही ब्रिटेन और भारत से मावजनिक् अपील की।

उन्होंने भारतीय जनमत के समक्ष यह जोर देकर कहा कि आक्रमणकारी और आक्रमण-विगोधी, इन दो घेमों के बीच का कोई मध्य मार्ग नहीं है।' अपने भाषण में उन्होंने ब्रिटन से अनुरोध किया कि वह भारत की जनता का जितनी जल्दी संभव हो वास्तविक राजनीतिक सत्ता प्रदान करे ताकि इस देश की जनता अपनी समूची शक्ति के साथ युद्ध में हिस्सा ले सके। यह ध्यान देने की बात है कि जनरलिस्सिमो व्याग काई शेक ने भारत की जनता का 'वास्तविक राजनीतिक सत्ता' देने की बात इसलिए बही है ताकि युद्ध में उसकी (भारत की) सहभागिता बड़े अर्थात् यह एक युद्ध संबंधी उपाय है न कि युद्ध के बाद का वादा। यह दृष्टिकोण भारतीय आंदोलन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री ने फरवरी 1942 में यही विचार व्यक्त किया और अनुरोध किया कि युद्ध के दौरान भारत को स्वराज्य प्रदान किया जाए ताकि युद्ध में उसकी सहभागिता बड़े

भारतीय जनता की स्वराज्यसपन्न राष्ट्र होने की आकांक्षाओं के प्रति हमारी सहानुभूति है। स्वराज्यसपन्न होने पर भारत एशिया में मित राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने में भाग ले सकेगा। (आस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के विदेशमंत्री डा० एच० बी० एवट का आस्ट्रेलिया की संसद में भाषण, 27 फरवरी 1942)

22 फरवरी 1942 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बड़े साफ शब्दों में एलान किया कि अंतर्जातिक चाटर 'समूची दुनिया' पर लागू होता है (इस प्रकार उन्होंने मौन भाव से चर्चित क उस वयान को ठीक कर दिया जो उन्होंने सितंबर 1941 में दिया था)

अंतर्जातिक चाटर केवल दुनिया के उन हिस्सों पर ही नहीं लागू होता जो अंतर्जातिक भाग्य के तट पर हैं बल्कि यह समूची दुनिया पर लागू होता है। (राष्ट्रपति रूजवेल्ट का रेडियो भाषण, 22 फरवरी 1942)

इस रेडियो भाषण के साथ ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भारत को आजागी दिए जाने का समर्थन करते हुए ब्रिटिश सरकार के पास सीधे अपना संदेश भेजा। 1946 में अमेरिका के भूतपूर्व विदेशमंत्री समनर वेल्लेस ने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया

1942 में जब जापान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और भारत में असंतोष काफी तीव्र हो उठा था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने श्री चर्चिन से अनुरोध किया कि वे इस बात को मान लें कि भारत को आजादी दिए जाने में अब और अधिक देर करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अनुरोध किया कि भारतीय नेताओं को महात्म्य की जमरी की धाराओं (अमेरिकन आर्टिक्ल ऑफ फ्रीडम) के आधार पर अपने राष्ट्रीय संविधान की रचना का अवसर

मिलना चाहिए। राष्ट्रपति की यह धारणा थी कि इस तरह की उत्तरिम सरकार की स्थापना से भारतीय नेताओं को मिलकर काम करने का प्रोत्साहन मिलता और उन्हें अपने व्यावहारिक अनुभव से यह जानने का अवसर मिलता कि भारत की जनता की खास जरूरतों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थाई संविधान का स्वरूप क्या होगा। इस तरह के समाधान को तब शायद भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया होता। वर्तमान ब्रिटिश सरकार आज इस तरह के प्रस्ताव पेश कर रही है और उसे सचमुच इस बात का खेद होगा कि क्या श्री चर्चिल ने इस तरह के प्रस्ताव को चार वर्ष पूर्व मानने से क्रोधवश इकार कर दिया था। (त्रिनिदियन साइंस मॉनिटर में समनर वेलेस का वक्तव्य, जून 1946)

भारत की राष्ट्रीय मांगों के सदृश में अमरीका, आस्ट्रेलिया और चीन द्वारा डाले गए दबाव को समझना तथा समुक्त राष्ट्र के अंदर ब्रिटेन के अपेक्षाकृत अलग धलंग पड़े सरकारी दृष्टिकोण को जानना, जिसमें युद्ध के दौरान भी भारत में जिम्मेदार राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को नामजूर किया जा रहा था, काफी आवश्यक है।

1942 का वसंत आत आत एक अनुकूल स्थिति तैयार हो गई थी। अब ब्रिटेन की बारी थी कि वह पहल करे। यदि ब्रिटेन के सरकारी खेमों में अब भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी और कुछ लागू इसका विरोध कर रहे थे तो मार्च में जापानियों के रगून तक पहुंच जाने से इस बाधा को दूर करने की आवश्यक प्रेरणा मिल गई। 8 मार्च को रगून का पतन हो गया। 11 मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा हो गई।

1942 के मार्च और अप्रैल महीनों में क्रिप्स मिशन की भारत यात्रा युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय संघों के संकट में एक सक्रान्तिविधु साबित हुआ। क्रिप्स योजना या भारत के लिए सांविधानिक प्रस्तावों को ब्रिटेन के युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने तैयार किया था और इन प्रस्तावों को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत लेकर आए थे ताकि वे इसे समझौते का आधार बनाकर भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श कर सकें। क्रिप्स योजना के दो मुख्य भाग थे

## 1 युद्ध के बाद के प्रस्ताव

- (क) एक नए भारतीय संघ के लिए डोमोनियन का दर्जा जिसे यह अधिकार प्राप्त हो कि यदि वह चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से खुद को अलग कर ले,
- (ख) युद्ध के तत्काल बाद एक 'संविधान का निर्माण करने वाले निकाय' का गठन किया जाए जिसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कुछ सदस्य हों जिन्हें युद्ध के पश्चात् समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाए तथा कुछ सदस्य ऐसे हों जिन्हें देशी रियासतों के राजा

अपनी रियासत की जावादी के अनुपात में नामजद करे। ये लोग मिलकर देश का एक नया संविधान बनाए।

- (ग) ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को या रियासत को अलग रहने का अधिकार हो और या तो वे वर्तमान आधार पर बने रहें या समान अधिकारों वाले एक पृथक् डोमिनियन के रूप में एक नए संविधान की रचना करें।
- (घ) ब्रिटेन तथा 'संविधान का निर्माण करने वाले निकाय' के बीच एक संधि हो ताकि जातिगत और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटेन की शाही सरकार द्वारा किए गए वादा के अनुरूप व्यवस्था की जा सके।

## 2 युद्ध के दौरान के तत्कालिक प्रस्ताव

भारतीय प्रतिनिधियों के परामर्शक सहयोग के जरिए ब्रिटेन द्वारा अपने हाथ में सत्ता रखना।

लेकिन कांग्रेस युद्ध के दौरान ऐसी राष्ट्रीय सरकार चाहती थी जिसके पास काफी अधिकार हों और यह अंतिम मुद्दा ही वह नाजुक मुद्दा साबित हुआ जिसपर क्रिप्स वार्ता टूट गई।

यह देखा जा सकता है कि समाचारपत्रों द्वारा एक नए और युगांतरकारी प्रस्ताव के रूप में बहुप्रचारित क्रिप्स योजना ने ब्रिटिश नीति में किसी बुनियादी तब्दीली का नमूना नहीं पेश किया। इसने 1940 में वायसराय द्वारा पेश किए गए 'अगस्त प्रस्ताव' की पुरानी चिरपरिचित बातों को ही दुहराया जिसे भारतीय जनमत के प्रत्येक वर्ग ने पहले ही ठुकरा दिया था। क्रिप्स मिशन के अधिसूचक इतिहास ने इस सच्चाई को स्वीकार किया

घोषणा के मसौदे में सरकारी नीति में कोई जबरदस्त परिवर्तन की बात नहीं थी सिद्धांत के रूप में घोषणा का मसौदा वस्तुतः 'अगस्त प्रस्ताव' से भी एक कदम आगे था। (प्रोफेसर आर० कूपलैंड 'दि क्रिप्स मिशन, जॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1942 पृष्ठ 30)

उन्होंने आगे लिखा

घोषणा के मसौदे में युद्ध के दौरान संविधान के स्वरूप में किसी बड़े परिवर्तन की बात को निकाल दिया गया था। (वही, पृष्ठ 31)

चातचीत के दौरान कांग्रेस ने किसी मनमुटाविक समझौते की आशा में बहद रियायतें दान की बात नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि यदि उन्हें सचमुच जिम्मेदारी और अधिकार दिए जाएं तो यह ब्रिटिश वायसराय के अधीन काम करने को तैयार है और वह एक ब्रिटिश ब्रमांडर



इस चीफ़ का भी स्वीकार कर लेना तैयार हो जा। उनसे सलाह लेना मानना ही नहीं होगा बल्कि उन प्रतिमंडल का सदस्य भी होगा।

लेकिन इन गारों बाता का कोई नतीजा नहीं निकला। उनसे कहा गया कि ब्रिटन का प्रभुत्व और ब्रिटन की तानाशाही पूरी तरह बनी रहती, उनसे कहा गया कि भारत के रक्षा-मन्त्री का अधिकार अधिकार कटौत और स्थगित की दृष्टिगत का काम दिया जा सकता है। जब उन्होंने (कांग्रेस सरकार ने) अपनी असहमति के क्षेत्र का काम करने की घोषणा की तो उनसे एक सन्देश में कहा गया कि जो दिया जा रहा है उसे 'लेना हाता तो नहीं तो जाओ'। 'लेना हाता तो लेना हाता जाओ' की इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि अगर जा का इरादा समझौता करने का नहीं बल्कि भविष्य के संघर्ष के लिए आधार तैयार करने का था।

7 अप्रैल का लाड हलौफ़ानस ने जा दुर्भाग्यपूर्ण भाषण दिया उसने यह धारणा और दृढ़ हो जाती है। लाड हलौफ़ानस का यह भाषण सभी मान्य जाया जब समझौते की बातचीत अभी जारी थी। उन्होंने अपने भाषण में पहले ही से यह अनुमान लगा लिया कि यह बातचीत विफल हो जायगी और कहा कि उस हालत में ब्रिटन सरकार शासन की राइडोर अपन हाथ में बचाए रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स मिशन ने भारत में ब्रिटिश शासन के भावी आलोचना को एक अवांछ्य मामला बनकर अपना मजसद हल कर लिया होगा।

भारतीय जनमत में हर वक़्त के लागा न, यहाँ तक कि अत्यंत नरमदली विचारधारा के लोगो ने भी क्रिप्स योजना का जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख संगठनों ने क्रिप्स व प्रस्तावों को ठुकरा दिया। बातचीत में हाने पर कलकत्ता के स्टैंडसमैन ने लिखा

जब तक प्रस्तावों का मसौदा ब्रिटन का भारतीय विभाग (इंडिया आफिस) और भारत सरकार द्वारा तैयार होता रहेगा तब तक किसी भी दूत की सफलता नहीं मिल सकती और तब तक इस देश के लिए हर घट बढ़ते खतरों से निवृत्ति का तरीका नहीं ढूँढा जाएगा

सारा दोष इंडिया आफिस का और भारत सरकार के अधिकारीवर्ग का है।

## 5 अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद (1942-45)

क्रिप्स मिशन का साथ बातचीत में हाने के बाद देश की राजनीतिक स्थिति में तज़ी से गिरावट आई।

ब्रिटिश सरकार ने एलान किया कि इससे ज्यादा न दिया जा सकता था और उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का बदनाम करने के लिए अत्यंत पक्षपातपूर्ण ढंग का दुष्प्रचार शुरू

किया और दुनिया ने सामने वही घिसा पिटा तर्क देना शुरू किया कि कांग्रेस जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, भारतीय जनता निराशाजनक रूप से राजनीतिक फूट का शिकार है और वह स्वराज्य पाने लायक नहीं।

कांग्रेस जब फासिस्टविरोधी युद्ध में अपनी इच्छा के बावजूद सहयोग करने में असफल हो गई तो कुछ समय तक हिचकिचाते और काइ निश्चित फैसला न करने के बाद उसने देश की मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से असहयोग का रास्ता अख्तियार कर लिया।

कांग्रेस के एक वरग ने जिसका प्रतिनिधित्व मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी० राजगोपालाचारी कर रहे थे, यह तक पेश किया कि ब्रिटेन द्वारा भारत की राष्ट्रीय मांगों का नामजूर कर दिए जाने के बावजूद मुस्लिमबहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के आधार पर मुस्लिम लीग तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए और रचनात्मक नीति अपनाई जाए ताकि जापान का खतरा हान पर संयुक्त रूप से मिनाजुला प्रतिरोध संगठित किया जा सके। इस प्रस्ताव को अखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मई में 15 वें विरुद्ध 120 मतों में नामजूर कर दिया हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मोलाना आजाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों पक्षों को माय आधार तब पहुंचने के लिए कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल को नामजद करने के लिए तैयार है जो मुस्लिम लीग के साथ समझौते की बातचीत कर सके। श्री राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया ताकि वह अपनी नीति के पक्ष में प्रचार कर सकें।

दिसंबर 1941 में ही गांधी ने हाथ से कांग्रेस का नेतृत्व निकल चुका था लेकिन अब वह फिर गांधी के हाथ में आ गया। गांधी अपने शांतिवादी सिद्धांत के प्रचार में लग गये जिसमें ये बातें शामिल थीं - 1 जापान का अहिंसात्मक प्रतिरोध, 2 ब्रिटिश अधिकारियों के साथ असहयोग 3 फासिज्म व विरुद्ध संगठित देशों के मोर्चों के प्रति हमदर्दी, 4 भारत को संधि में जलज रक्षक का प्रयास और नेहरू द्वारा प्रस्तुत हथियारबंद संधि, छापामारों का गठन तथा परफूरा नीति की दलील का विरोध। कांग्रेस गांधी के शांतिवाद से सहमत नहीं थी पर भारत को आजादी दिलाने और इस प्रकार भारत की रक्षा की कारण वे संधि बनाने के लिए उमने गांधी के असहयोग संबंधी प्रस्तावों को एकमात्र हथियार मान कर अपना लिया। जून में गांधी, नेहरू और आजाद के बीच बातचीत के फलस्वरूप समझौते का आधार पालिया गया जो 14 जुलाई को कांग्रेसमिति द्वारा पारित असहयोग संबंधी प्रस्ताव में प्रतिफलित हुआ। इस प्रकार फासिस्टविरोधी महत्वपूर्ण नेता, संयुक्त राष्ट्र के मान्य सहयोग के हितायनी लोग गांधी के पीछे और असहयोग आन्दोलन छेड़ने के उनके पतनवादी प्रस्तावों के पीछे उस समय चल पड़े जब जापानी हमले का खतरा बना हुआ था।

दसस घुसे राष्ट्रों की माफो मुशी हुद और उहान कांग्रेस की बाह्वाही की। मुनायददनास

के अनुयायियों को, जो धुरी राष्ट्रों के तत्वावधान में अपना प्रचार चला रह थे, अपनी घुसपैठ बढ़ान के लिए अनुकूल अवसर मिल गया जिसपर कांग्रेस ने काफी चिंता के साथ गौर किया ('इम निराशा का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के विरुद्ध बड़ी तीव्र और व्यापक दुर्भावना बढ़ी तथा जापानी सैनिकों की सफलता पर लोगों ने सतुष्टि महसूस की, कांग्रेसमिति इन घटनाओं को गंभीर आशंका के साथ देखती है।' कांग्रेस कांग्रेसमिति का प्रस्ताव, 14 जुलाई)

ब्रिटेन के सरकारी क्षेत्रों के जनताधिकार प्रतिक्रियावादी दुष्प्रचार ने भी कांग्रेस का बदनाम करने के इस नए अवसर का लाभ उठाया। जिस नीति ने नेहरू और आज़ाद जैसे प्रमुख फ़ासिस्टविरोधी तथा समुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग के हिमायती नेताओं को गांधी और असहयोग आंदोलन के पीछे चलने पर मजबूर किया उस नीति के दिवालियापन को स्वीकार करने की वजह से इस नतीजे को सरकारी नीति का उत्साहपूर्ण समर्थन समझा गया। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी द्वारा शांतिवादी और तुष्टीकरण की नीति के समर्थन में कही गई अजीबोगरीब बातों को देश और विदेश में व्यापक प्रचार दिया गया। इससे पीछे उद्देश्य यह था कि समूचे राष्ट्रीय आंदोलन को आत्मसमर्पणवादी और जापान के साथ संधि करने का झुठका घोषित कर दिया जाए। भावी संधि की तैयारियों के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था इसका पता उन दस्तावेजों के धुआधार प्रकाशन से चलता है जो पुलिस द्वारा मारे गए छात्रों के दौरान जब्त किए गए थे। इनके जरिए उन तथ्यों का भंडाफोड़ किया जा रहा था जो पहले ही गांधी ने सावजनिक रूप से लिखे अपने लेखों में द दिए थे।

इसमें कोई शक नहीं कि गांधी द्वारा कांग्रेस का 'जनरलिस्मिओ, पद (यह उपाधि उन्हें दी गई थी) ग्रहण करना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा भार था और उसमें विश्व जनमत की निगाह में काफी नुकसान पहुंचाया। विश्व जनमत ने गांधी की शांतिवादी और तुष्टीकरण की नीति तथा राष्ट्रीय आंदोलन की नीति को एक दूसरे के साथ मिला दिया। लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि अहिंसा और तुष्टीकरण नीति के सदम में गांधी के जितने भी व्यक्तिगत बयान आए उन्हें कांग्रेस के आधिकारिक वक्तव्यों और प्रस्तावों द्वारा साफ तौर पर अस्वीकार किया गया।

असहयोग संधि कांग्रेस प्रस्ताव जुलाई में लाया गया और 8 अगस्त को अंतिम रूप से संशोधित रूप में पारित कर दिया गया (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के विरोध में 13 वोट पड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 22 जुलाई को उसके कानूनी अधिकार पुन प्राप्त हो गए थे जिससे इस पार्टी के वन्ते प्रभाव और ताकत का पता चलता है)।

इस प्रस्ताव में एक बार फिर समुक्त राष्ट्र के साथ सहानुभूति प्रदर्शित की गई थी और यह भाग दोहराई गई थी कि भारत में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए ताकि वह

एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ कंधा मिलाकर फासिज्म के विरुद्ध संश्लेष संघर्ष में भाग ले सके

भारत के हित और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की सफलता—इन दोनों बातों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया जाए।

भारत की आजादी की घोषणा के बाद एक अस्थाई सरकार का गठन किया जाएगा और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र के मित्र की हैसियत से फासिस्ट विरोधी महान संघर्ष में उसकी हर तकलीफ और मुसीबतों तथा स्वाधीनता संघर्ष में हिस्सा लेगा।

अस्थाई सरकार का गठन देश की प्रमुख पार्टियों और प्रमुख ग्रुपों के सहयोग के जरिए ही हो सकता है इस सरकार का धुनियादी कार्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर अपने सभी हथियारों और जहिसात्मक साधनों द्वारा भारत की रक्षा करना तथा हर तरह के आक्रमण का प्रतिरोध करना होगा

भारत और मित्र राष्ट्रों के आपसी संबंधों का निर्धारण इन सभी स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधि आक्रमण का मुकाबला करने के सामूहिक कार्य में आपसी हितों और सहयोग के आधार पर विचार विमर्श के द्वारा करेंगे

कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी रूप में चीन या रूस का सुरक्षा में जिनकी आजादी बहुत अनमोल है और जिसे सुरक्षित रखने की जरूरत है—बाधा न पड़े या संयुक्त राष्ट्रों की रक्षात्मक क्षमता मजबूत न पड़े।

यहां तक तो यह प्रस्ताव ऐसा था जो भारत तथा दुनिया के सभी जनतांत्रिक और फासिस्ट विरोधी लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकता था। लेकिन प्रस्ताव के अंतिम अंश में कहा गया था कि यदि राष्ट्रीय मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो असहयोग का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक बार फिर विश्व स्वाधीनता के हितों के इस अंतिम क्षण में ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी अपील दुहराती है।

लेकिन कमेटी यह महसूस करती है कि अब इस बात का एकदम औचित्य नहीं है कि किसी राष्ट्र को साम्राज्यवादी और सत्तावादी सरकार के विरुद्ध, जो उस पर शासन कर रही हो और उस अपने तथा मानव समुदाय के हितों में बाधा डालने से रोक रही हो अपनी आकांक्षा की विलंबक कहने से रोक जा सके।

इसलिए कमेटी यह निश्चय करती है कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता के भारत के अभिन्न अधिकार की रक्षा के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर जनसंघर्ष शुरू कर दिया जाए ताकि दश पिछले 22 वर्षों के दौरान चलाए गए शांतिपूर्ण संघर्ष के फलस्वरूप इकट्ठी की गई अहिंसक शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल कर सके।

इस तरह का संघर्ष अनिवार्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाना चाहिए और कमेटी उसे अनुरोध करती है कि वे इस संघर्ष का नेतृत्व अपने हाथ में लें तथा आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा प्रदान करें।

क्रिप्स मिशन की बातचीत असफल हान के बाद जो निराशा छाई थी उसका ही नतीजा था अगस्त प्रस्ताव। इस निराशा की अभिव्यक्ति नेहरू की 19 अप्रैल की घोषणा में हुई

मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या किया जाए लेकिन मैं एक बेचैनी की भावना से प्रेरित होकर तेज चल रहा हूँ। यह सोचकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि — भारत पर किसी दुश्मन द्वारा हमला किया जा रहा हो और इसमें अमरीका, ब्रिटन तथा अन्य दश भाग ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करता हूँ।

अगस्त प्रस्ताव को लेकर बड़ी तीखी बहस चली है। इसकी कोई भी आलोचना करने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि भारत के राष्ट्रीय नेता, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीयतावादी और फासिस्टविरोधी रवैया अख्तियार करते रहे हैं, किस निम्न धमसकट में फँस गए थे और किन स्थितियों में उन्होंने निराशा और विवश होकर यह रास्ता अख्तियार किया। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध इस रास्ते पर खिंच आए थे क्योंकि वे स्वतंत्रता के आधार पर सहयोग करने की हर कोशिश हार गए थे और उनके मामले अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बच रहा जिसके जरिए वे भारत की जनता को गोल-बंद कर पाते और युद्ध से उत्पन्न तात्कालिक संकट की हालत में कारगर ढंग से भारत की सुरक्षा कर पाते।

फिर भी यदि यह देखा जाए कि अगस्त प्रस्ताव का भारत पर और विश्व जनतांत्रिक लोकमत पर क्या प्रभाव पड़ा तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक भयंकर भूल था। राजनीतिक दृष्टि से इस प्रस्ताव में एक ऐसी घातक विसंगति थी जिससे पता चलता था कि प्रस्ताव पारित करने वाला वे मन में उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। प्रस्ताव के आमुख और उपमहार में बहुत स्पष्ट विसंगति थी और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता था। प्रस्ताव में एक तरफ तो यह माना गया था कि 1941 के बाद से युद्ध का स्वरूप साम्राज्यवादी नहीं रह गया है अब यह दो साम्राज्यवादी सेना की हाड से उत्पन्न युद्ध नहीं है और इसके परिणामों के प्रति तटस्थ नहीं रहना जा सकता, अब यह ऐसा युद्ध बन

गया हे जिगम कांग्रेस संयुक्त राष्ट्रों की विजय चाहती है जिससे प्रस्ताव में यह लक्ष्य शामिल करने की घोषणा की जा सके कि 'संयुक्त राष्ट्रों की जीत है' तथा भारत को 'संयुक्त राष्ट्रों का सहयोगी बनना चाहिए।' प्रस्ताव में विशेष रूप से यह बात कही गई कि कांग्रेस को इस बात की बहुत चिंता है कि किसी भी रूप में चीन या रूस की सुरक्षा में बाधा न पड़े या 'संयुक्त राष्ट्रों की रक्षात्मक क्षमता सकट में न पड़े।' प्रस्ताव के अंत में जो कार्यक्रम पेश किया गया था उसे यदि अमल में लाया जाता तो मित्र राष्ट्रों के एक प्रमुख और बड़े देश में भयंकर अदरुनी सघर्ष और अव्यवस्था शुरू हो जाती जो व्यवहार में संयुक्त राष्ट्रों की रक्षात्मक क्षमता को कमजोर करती और फासिस्ट शक्तियों की जीत में मदद मिलती।

युद्ध के शुरू के दिनों में जिस समय यह युद्ध अभी महज आगल फ्रांसीसी साम्राज्यवाद और नाज़ी जर्मनी के बीच का युद्ध था, जब भारत अंगरेजों ने पीछे चलने के सिवा युद्ध से और किसी भी तरह संबद्ध नहीं था और उसपर आक्रमण का कोई खतरा नहीं था उस समय भी इस बात की पूरी कोशिश की गई कि कांग्रेस की किसी भी नीति से युद्ध के लिए आवश्यक तैयारियों में बाधा न पहुंचने पाए। 5 सितंबर 1939 को गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटेन एक 'उचित कारण के लिए युद्ध' लड़ रहा है और भारत को इस युद्ध में 'बिना शर्त सहयोग' देना चाहिए

इसलिए मैं अभी, इस समय, भारत के उद्धार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ।  
लेकिन यदि इंग्लैंड और फ्रांस का पतन हो गया तो भारत का उद्धार किस तरह का होगा? ('हरिजन', 9 सितंबर 1939)

नतीजा यह हुआ कि ऐसे समय जब स्वयं कांग्रेस के ही शब्दों में युद्ध 'साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति' के लिए लड़ा जा रहा था और भारत का अपना सघर्ष तर्ज करने का बहुत अनुकूल अवसर मिला था, जनआंदोलन या सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के हर प्रस्ताव को इस आधार पर नामजूर कर दिया कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की युद्ध संबंधी तैयारियों में अड़चन पैदा होगी। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का विशुद्ध सांकेतिक तरीका अपनाया गया ताकि ब्रिटिश सरकार को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। जघनकारी इतिहासकार सर रगिनाल्ड कूपलैंड ने ठीक ही स्वीकार किया है कि 'इस आंदोलन से सरकार को कुछ खास कठिनाई पैदा नहीं हुई।' ('इंडिया एग्जिस्टेंट-मंट', 1945, पृष्ठ 206)

फिर भी जब युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और कांग्रेस ने इस बदलाव का मान लिया, जब भारत के आवश्यक हित रूस और चीन तथा संयुक्त राष्ट्रों की विजय के साथ जुड़ गए और जब भारत पर सीधे आक्रमण का खतरा पैदा हो गया तो इस अवसर को

जन प्रतिरोध आंदोलन छेड़ने का सबसे उचित अवसर माना गया जबकि 1939-40 में इसे छेड़ना संभव नहीं माना गया था।

यह सही है कि इस तरह का संघर्ष छेड़ने का कोई गंभीर इरादा नहीं था। नेताजी ने इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ समन्वित की बातचीत शुरू करने के लिए संघर्ष की घमकी दी थी। अपनी नीति के समर्थन में कांग्रेसी नेताओं ने इस तथ्य का बार-बार उल्लेख किया है जिसमें यही पता चलता है कि उन्होंने कितनी बुद्धिहीनता का काम किया। एक भयंकर युद्ध के नाजुक दौर में ऐसी नीति पर चलने का अर्थ यह था कि स्थिति को समझने में और साम्राज्यवादियों के दाव-पेच से परिचित होने में वे धोखा खा गए।

जहां तक वायनीति का संबंध है यह प्रस्ताव बहुत अविवेकपूर्ण था। इस प्रस्ताव के जरिए साम्राज्यवादों प्रतिक्रियावादियों को एक बहाना मिला गया था जिससे वे अपना हमला कर सकते थे। यह काफी स्पष्ट है कि निम्न मिशन के साथ बातचीत भग हो जाने के बाद के वर्षों में साम्राज्यवादों प्रतिक्रियावादियों ने जो तरीके अपनाए उनका उद्देश्य कांग्रेस को दुविधा की स्थिति में डाल देना था और उससे ऐंम गलत कदम उठवाना था जिनसे उन्हें अपना दमनचक्र चलाने का एक बहाना मिल जाए। जहां तक कांग्रेस की पुरानी फासिस्ट विरोधी नीति की बात है साम्राज्यवादी अपने दाव-पेच में लाभप्रद स्थिति में नहीं थे। कांग्रेस ने शुरू से ही फासिस्टविरोधी नीति का पालन किया था और अपनी इसी नीति को एक ऐसी निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया था जो फासीवाद, साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद के फासिस्ट समर्थक सदहास्पद कार्यों के खिलाफ दुनिया की जनता के सामूहिक संघर्ष में भारत की जनता को भी गालबंद कर सके। ज्योंही यह प्रस्ताव पारित हुआ साम्राज्यवादियों को यह अवसर मिल गया कि वे अपने को भारत के रक्षक कहने का दावा कर सकें। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने कहा कि रक्षा व्यवस्था को भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन फासिस्ट समर्थक और जापान समर्थक हो गया है और वह संयुक्त राष्ट्रों की युद्ध तैयारियाँ को बरबाद करना चाहता है। अंगरेजों ने इसी बात को राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए तैयार की गई प्रति-  
पक्षीय नीति का राजनीतिक आधार बनाया।

इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रस्ताव से भारत की स्वतंत्रता का रास्ता आसान नहीं हुआ बल्कि इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रीय नेताओं ने साम्राज्यवादियों की मड़बाने वाली कायवाही के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रस्ताव को पारित करने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाए गए जाल में सीधे जा फंसा। दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय नेता वास्तविक स्थिति से इतने घेयबर थे कि प्रस्ताव पारित करने के बाद वे वायसरॉय के साथ शांतिपूर्ण बातों की तैयारियाँ कर रहे थे। उन्होंने न तो इस बात की कल्पना की कि उनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं और न ऐसी

स्थिति से निबटने की कोई तैयारी ही की। उन्होंने इस तरह के कोई निर्देश भी नहीं दिए कि अगला कदम क्या हो।

कांग्रेस के एक अल्पमत में इस प्रस्ताव का विरोध किया था और लगातार इसके दुष्प्रणामों की ओर ध्यान दिलाया था। 26 जुलाई 1942 को कम्युनिस्ट पार्टी ने एक खुला पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि

आप अगर सघन शुरू करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? वे आपको और हजारों सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुपचाप जेल में डाल देंगे और बहुत मोनेपन के साथ इस बात का एलान कर देंगे कि भारत को फासिस्ट हमलावरों से बचाने के लिए उन्हें मजबूर होकर अपना फज निभाना पड़ा है।

दुर्भाग्यवश इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेसी नेताओं के स्मरणों और वक्तव्यों को देखने से पता चलता है कि जब गिरफ्तारियां हुईं तो वे आश्चर्यचकित रह गए। 14 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी के तुरंत बाद गांधी ने वायसरॉय के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कहा

भारत सरकार को कम से कम तब तक इतजार करना चाहिए था जब तक मैं जनआंदोलन न शुरू कर दता। मैं सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले मैं आपको एक पत्र भेजना।

राष्ट्रीय आंदोलन के जिन फासिस्टविरोधी मजदूरवर्गीय हिस्सों का प्रतिनिधित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करती थी वे शुरू से ही देश के मुक्तिसंग्राम के सदर्भ में एक स्पष्ट और सुसंगत नीति का प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि इस युद्ध से जो नए कार्य और दायित्व सामने आए उनको आगे बढ़कर सभाला जाए। उन्होंने ठोस ढंग से यह दिखाया भी कि भारतीय जनता को लोकप्रिय या राष्ट्रीय मांगों का ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिरोध के बावजूद किस प्रकार एक रचनात्मक प्रतिक्रिया संभव और आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने वर्तमान नाजुक स्थिति में असहयोग के विकल्प के रूप में अपना रचनात्मक कार्यक्रम पेश किया

- 1 कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक मजबूत राष्ट्रीय मोर्चा बनाया जाए जो मिलकर एक ही मंच से फासिज्म का मुकाबला करें।
- 2 इस तरह के राष्ट्रीय मोर्चे के आधार पर सभी पार्टियों के समर्थन से ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह समर्थन की मांग को मंजूर करे और भारतीय सरकार की स्थापना हान न दे।



- 3 इस न्यायपूर्ण राजनीतिक मांग पर जोर देने के साथ-साथ पूरी ताकत के साथ युद्ध सबधी प्रयत्न में भाग लिया जाए, जनता को गोलबंद किया जाए और जनता के युद्ध प्रयासों को मजबूत करने के लिए तथा फासिज्म के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध की क्षमता का बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में गैरसरकारी तौर पर जनता को एकजुट किया जाए।
- 4 असहयोग की सभी नीतियों को दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया जाए क्योंकि ये नीतियाँ भारतीय जनता के हितों के लिए घातक हैं।

लेकिन उस समय लोग बहुत गुस्से में थे और ब्रिटन का शासक बग बड़े प्रतिक्रियावादी ढंग से राष्ट्रीय सरकार की मांग को पूरा करने से इकार कर रहा था इसलिए यह नीति राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी।

भारत के राष्ट्रीय नेताओं में से अधिकांश ने यह आशा की कि बहुत बड़े समय तक अत्यंत तीव्र सघर्ष चलाकर राष्ट्रीय आजादी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए मजबूत स्थिति बना ली जाएगी तथा संयुक्त राष्ट्रों के कारगर मित्र के रूप में कार्य किया जा सकेगा (गांधी के प्रमुख सहयोगी बल्लभभाई पटेल ने कहा कि एक हफ्ते में आजादी हासिल कर ली जाएगी हालांकि गांधी ने इसके जवाब में कहा 'यदि एक हफ्ते में आजादी मिल जाती है तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा')। उह यह विश्वास था कि इस तरह की सफलता से वे अपनी कानूनीति का औचित्य यह कहकर साबित कर लेंगे कि भारत की रक्षा इसी ढंग से हो सकती थी और फासिज्म के विरुद्ध विश्वव्यापी विजय में यही उनका सर्वोत्तम योगदान है। यह नीति कितनी आत्मघाती थी इसका पता चल गया। अहिंसा के इन पैगंबरों ने, जो अपने तरीके से पिछले 22 वर्षों से ब्रिटिश राज्य सत्ता के गढ़ को हिलाने में सफल नहीं हो सके थे, अब यह आशा की थी कि दरवाजे पर दस्तक दे रहे जापानी हमलावरों का मुकाबला करने के लिए वे अपने इसी तरह के आंदोलन के जरिए कुछ ही सप्ताहों के अंदर पूरी राजसत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। विवल्स के रूप में यदि उन्होंने यह आशा की हो कि उनका आंदोलन बढ़ते-बढ़ते एक हिंसात्मक जनविद्रोह का रूप ले लगे तो इससे यही पता चलता है कि अहिंसा का प्रशिक्षण प्राप्त कोई आंदोलन कितने मूखतापूर्ण ढंग से अपनी योजनाएं तैयार कर सकता है। यह सोचना सचमुच आश्चर्य की बात है कि जिस समय सीमाओं पर हमलावर सनाए खड़ी हो और युद्ध चल रहा हो, किसी देश की निहत्थी जनता राजसत्ता के लिए क्रांतिकारी मध्य बिना हिंसा का पाठ पढ़े, गुरु कर सकती है। वे इतनी जासान बात को नहीं समझ सके कि उनके आंदोलन से भारत को आजादी मिलना तो दूर देश के अंदर सघर्ष, अव्यवस्था और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे भारत में फासिज्म की विजय का मांग प्रशस्त हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिना किसी लागतपट के कहा कि उनकी नीति खुद ही अपना गला

काटने वाली नीति है। इससे हमलावरा के विरुद्ध देश की रक्षा का काम कमजोर होता है और फासिस्टों का काम आसान हो जाता है।

असहयोग की नीति एक हताशाभरी नीति थी लेकिन इस नीति का पालन करने वाले नेतागण दरअसल सहयोग का कोई आधार ढूँढने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि वे पहले समझौते की कोशिश करेंगे और यदि समझौता संभव नहीं हुआ तभी आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसी नीति की आलोचना करने के पर्याप्त आधार हमारे पास हैं। इतनी नाजुक स्थिति में असहयोग आंदोलन छेड़ने की बात कर रही हैं। सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति इस बात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि उसने भारत की न्यायाचित मांगों को ठुकराकर और समान शर्तों पर सहयोग की उनकी आकांक्षा का गला घोटकर इस निराशाजनक परिणति को जन्म दिया।

जहाँ तक कांग्रेस की बात है उसने जतन तक अपनी यह इच्छा जाहिर की कि कोई समझौता हाँ जाए। व्यावहारिक सहयोग और समझौते की इच्छा पर ज़रूरत के लिए (ताकि फासिज्म के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष में भाग लिया जा सके) प्रस्ताव में मशौदन किया गया। वहस के अंत में गांधी और नेहरू ने जो भाषण दिए वे उनमें समझौते की इच्छा पर ही जोर दिया गया था। नेहरू ने अपने भाषण में कहा था 'यह प्रस्ताव कोई धमकी नहीं है, यह एक आमन्त्रण है और अपनी नीति की व्याख्या है, यह एक सहयोग का प्रस्ताव है।' जुलाई में जनरल लिस्सिमो च्याग काइ शेक के नाम लिख गए गांधी के प्रकाशित पत्र में साफ़तौर पर कहा गया था

हम लोग जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे और जो भी कदम उठाया जाएगा, यह ध्यान में रखकर उठाया जाएगा कि इससे चीन का कोई नुकसान न हो या भारत अथवा चीन पर जापानी आक्रमण के लिए बढ़ावा न मिले। मैं हर तरह से यह कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी तरह का संघर्ष न पड़ा हो।

यह बताया गया कि पहले कदम के रूप में कोई कायवाही शुरू करने से पहले वायमारय के नाम एक पत्र लिखा जाए जिसमें समझौते की बातचीत का प्रस्ताव हो।

कांग्रेस कमिटी की बैठक के तुरंत बाद पत्र लिखने का काम शुरू हुआ लेकिन इस पूरा नहीं हो पाया। कुछ ही घंटों के अंदर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं और इन गिरफ्तारियों ने एक व्यापक संघर्ष की शुरुआत कर दी।

कांग्रेस ने 8 अगस्त को अपना प्रस्ताव पारित किया था। 9 अगस्त की सुबह नाना प्रमोद नागेशी नेताजी का गिरफ्तार कर लिया गया (148 साल बर्बर में पकड़े गए) जिनमें

गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, कृपालानी, राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य लोग शामिल थे। इसके साथ ही कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया।

कायसमिति के सदस्यों को अहमदनगर किले में कैद रखा गया। लेकिन गांधी को अलग से आगा खान के महल में नज़रबंद रखा गया। वेशव इस महल में आराम की सारी सुविधाएँ थी (आपने मुझे एक ऐसे महल में रखा है जहाँ सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मैंने इन सुख सुविधाओं का उपभोग किया है लेकिन ऐसा करते समय हमेशा मुझे अपने कर्तव्य का बोध रहा है न कि आराम का'—वायसराय के नाम गांधी का पत्र, 31 दिसंबर 1942)। जेल में बंद नेताओं को बाफ़ी आराम से रखा गया और इसकी वजह यह थी कि वे इन नाज़ुक वर्षों में अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका या नेतृत्व न कर सकें। और ऐसा ही हुआ भी। डा० सीतारमैया के मस्मरणों को देखने से पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों ने राजनीतिक मसला पर बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने अपना सारा ध्यान धर्म, दर्शन और मनोरंजन में लगाया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्वविहीन होकर रह गया। इसकी वजह यह थी कि कभी इस बात की कोशिश नहीं की गई कि नेतृत्व की दूसरी पक्ति तैयार की जाए अथवा नेताओं के गिरफ्तार हो जाने की अवस्था में आंदोलन का आगे चलाने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित किया जाए।

राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से देश भर में प्रदर्शनों और अमंगुलित सभों का तथा अव्यवस्था का साम्राज्य कायम हो गया। इन प्रदर्शनों और सभों का पुलिस ने बड़े हिंसात्मक और क्रूर ढंग से दमन किया। इस काम में सेना की भी मदद ली गई। अनेक लोग हताहत हुए। केंद्रीय विधानसभा के गृह सदस्य के सरकारी बयान के अनुसार 9 अगस्त 1942 से लेकर 31 दिसंबर 1942 तक 60229 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 18000 लोगों का भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंद किया गया, सेना और पुलिस की गोली से 940 लोग मारे गए और 1630 लोग घायल हुए। (माच आफ इवेंट्स 1942 45', बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित, 1945)

राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश भर में रोष का जो वातावरण बना और जनता ने जो व्यापक प्रदर्शन किए वे स्वतः स्फूर्त थे। लेकिन इस तरह की जो छिटपुट मुठभेड़ें हुईं, असंतोष फैला या अलग अलग गुटों और दलों की तरफ से जो परस्पर विरोधी और उत्पन्न पैदा करने वाली हिंसाएँ जारी हुईं, वे कांग्रेस के किसी संगठित आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। जैसा कि चर्चिल ने बाद में मसद में कहा, ये छिटपुट आंदोलन बड़े आराम से दबा दिए गए। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के लिए कभी अनुमति नहीं दी थी और गांधी ने सावजनिक रूप से यह कहा कि इन आंदोलनों से उनका कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ने का अधिकार केवल गांधी को दिया था। 23 नवंबर 1942 को गांधी ने वायसराय के नाम अपने पत्र में लिखा

ऐसा लगता है कि कांग्रेसी मताआ की जबरदस्त धर पकड़ स जनता इतने गुस्से में जा गई है कि यह नियंत्रण छो बैठी है। मैं महमूस करता हू कि यह जो विध्वंस हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है।

गृह विभाग के नाम लिखे गए 15 जुलाई 1943 के पत्र में गांधी ने लिखा

सरकार का दशव्यापी गिरफ्तारी का कदम इतना उग्र था कि जनता ने आत्मनियंत्रण छो दिया क्याकि कांग्रेस के साथ उसकी सहानुभूति थी। आत्मनियंत्रण खोने का जब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका पीछे कांग्रेस का हाथ था।

एक अनौपचारिक सत्र में कहा गया था (अपने 15 जुलाई 1943 के पत्र में उद्धृत इन पक्तिया में गांधी ने उनमें निहित नीति को हिचक के साथ किंतु पूरी तरह स्वीकार किया है)

कोई भी आंदोलन तब तक नहीं किया जाना चाहिए या कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक महात्मा गांधी इस विषय में कोई फैसला नहीं करते हैं। यदि आपने कोई आंदोलन छेड़ दिया और मान लीजिए कि उन्होंने कोई दूसरा फैसला लिया तो इस अकारण भूल के जिम्मेदार आप होंगे। हमेशा तैयार रहिए, तुरंत संगठित हो जाइए, हमेशा सतक रहिए लेकिन कभी कोई कदम न उठाइए।

21 सितंबर 1945 को कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और गोविंदवल्लभ पंत के हस्ताक्षरों से एक आधिकारिक वयान जारी किया गया जिसमें कहा गया था

काई भी आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा या गांधी जी द्वारा आधिकारिक तौर पर कभी नहीं शुरू किया गया।

यह वाद की बात है कि एक अरुवाई और गुटबाजी से भरे राजनीतिक उद्देश्य के लिए अगस्त 1942 और उसके बाद के महीनों की नेतृत्वविहीन लड़ाई को 'अगस्त संधप' का नाम देने की कोशिश की गई। इस संधप को कांग्रेस द्वारा प्रेरित संधप कहा गया जबकि कांग्रेस का एकमात्र अधिकृत नेता इस आंदोलन को अपना मानन से इकार कर चुका था और इसकी भत्सना कर रहा था। हिंसा की निरकुश घटनाओं को कांग्रेस की कार्यवाही कहा गया जबकि कांग्रेस की नीति सदा से अहिंसक थी, अगस्त प्रस्ताव में कही गई बातों का बिल्कुल उलटा प्रचार किया गया था, इसमें वास को और जापानी श्रेमे का समर्थन

दिया गया था तथा संयुक्त राष्ट्रों के मोर्चों की निंदा की गई थी फिर भी इसे कांग्रेस का प्रचार घोषित किया गया। और अतः इस विरोधाभास की चरम उपलब्धि हम तब देखते हैं जब बुनियादी तौर पर इस कांग्रेस विरोधी आंदोलन में शामिल न होने को कांग्रेस का अनुशासन भंग करना माना गया जबकि कांग्रेस के अनुशासन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी आंदोलन तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक गांधी को सहमति न हो। गांधी ने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस संधि के लिए उन्होंने कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

अगस्त की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जो विघटन की स्थिति पैदा हुई, संगठित नेतृत्व का अभाव हुआ और कोई स्पष्ट नीति नहीं रही उससे बाद के वर्षों में राजनीतिक गतिरोध के साथ-साथ एक निराशा और उत्थान का दौर शुरू हो गया। यही वे दिन थे जब मुस्लिम लीग ने तेजी से अपनी ताकत बढ़ा ली।

अस्वस्थ होने के कारण 6 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने बाहर आते ही एलान किया कि 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव का सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला अंश अपने आप ही रद्द हो गया है क्योंकि 1944 में वह 1942 की तरफ लौटकर नहीं जा सकते। फिर भी राजनीतिक गतिरोध जारी रहा क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि जब तक अगस्त प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता तब तक सरकार किसी तरह के समझौता प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी। इसके साथ ही सरकार ने जून 1945 तक कार्यसमिति के सदस्यों को रिहा करने से इकार कर दिया और कार्यसमिति के सदस्य ही अगस्त प्रस्ताव की समीक्षा करने तथा नीति संबंधी कोई नया वक्तव्य तैयार करने की स्थिति में हो सकते थे।

1945 की गरमियों में इस गतिरोध को दूर करने की एक बार फिर कोशिश की गई। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेता भूलाभाई देसाई (जो गांधी के परामर्श पर और उनकी स्वीकृति से यह पदभार सभाल रहे थे) और मुस्लिम लीग के संसदीय नेता लियाकत अली खा के बीच मई में एक अस्थायी समझौता हो गया जिसका आधार यह था कि जो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाएगी उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बराबर बराबर सदस्य रहेंगे (40 प्रतिशत कांग्रेस, 40 प्रतिशत मुस्लिम लीग और 20 प्रतिशत अयदल)। इस प्रस्ताव को वायसराय लाड वेविल के सामने रखा गया और वह सलाह लेने लंदन खाना हो गए। लंबी बातचीत के बाद लाड वेविल जब लंदन से लौटे तो उनके साथ नीति संबंधी एक नया प्रस्ताव था जिसे ब्रिटिश सरकार ने 14 जून 1945 को घोषित किया था। इसमें अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की योजना तो थी लेकिन इसमें बहुत चालाकी के साथ एक परिवर्तन कर दिया गया था और इस सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शामिल होने की बात को बदल दिया गया था। कांग्रेस और लीग की बराबरी के स्थान पर सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की बराबरी

शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार इस सारे प्रश्न को एक सांप्रदायिक बरातल पर लाकर रख दिया गया था। ऊपर से देखने पर यह सशोधन बहुत मामूली सशोधन लगता था लेकिन इसन बातचीत भग हान म मदद की। इस परिवर्तन का अय यह था कि या तो कांग्रेस खुद को एक हिंदू संगठन के दरजे तक पहुंचा दे अथवा किसी मुसलमान कांग्रेसी के लिए एक मुस्लिम सीट की माग करके लीग के साथ बराबरी क आधार का उल्लघन करे। दूसरी तरफ लीग या तो उस मुसलमान कांग्रेसी को अपनी कोई मुस्लिम सीट दे दे और इस प्रकार बराबरी वाली बात छोड़कर कांग्रेस की तुलना म घाटे की स्थिति को स्वीकार करे। ऐसा न होने पर उसके सामने विरोध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहता और विरोध करने स सम्मेलन को भग करने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है।

जून 1945 म कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अ य पार्टियों के प्रतिनिधिया का एक सम्मेलन शिमला म आयोजित किया गया लेकिन जल्दी ही इस सम्मेलन की कायवाही म गतिरोध पैदा हो गया। बुनियादी योजना के लिए कोई सयुक्त मोर्चा बनाने के स्थान पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नता एक दूसरे के खिलाफ कुप्रचार मे लग गए। शिमला सम्मेलन असफल सावित हुआ। इस तरह युद्ध के समाप्त होने पर जब समूची दुनिया के लोग आजादी और मुक्ति की दिशा म बट रह थे, भारत उसी प्रकार गुलाम बना रहा जसा वह युद्ध से पहले था।

हमारी हडताल हमारे देश के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना रही है। यह पहला अवसर है जब सैनिकों का खून आम आदमियों के खून के साथ समान हित के लिए बहा है। हम सेना के लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम यह भी जानते हैं कि आप, हमारे सभी बहन और भाई भी इस नहीं भूलेंगे। हमारी महान जनता जिंदावाद ! जयहिंद ! —नौसैनिक केंद्रीय हडताल समिति का अंतिम संदेश, 23 फरवरी 1946।

वहता की यह राय है कि ब्रिटिश केबिनेट मिशन के भारत आने से पहले, भारत क्रांति के कगार पर खड़ा था। केबिनेट मिशन ने इस खतरे को दूर भल ही न किया हो लेकिन स्थगित तो कर ही दिया है। (भारतीय केंद्रीय विधानसभा में यूरोपीय ग्रुप के नेता पी० जे० ग्रिफिथ्स का लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में भाषण, 24 जून 1946)

जून 1946 में लेबर दल के नेता, प्रधानमंत्री सी० आर० एटली ने अपनी पार्टी के अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा था

हम दूसरा के लिए उसी आजादी की बात करते हैं जसी हम अपने लिए चाहते हैं। हम इस आजादी की घोषणा करते हैं लेकिन हम केवल घोषणा तक ही इस सीमित नहीं रखते हैं। हम इसका जमल में लाने की कोशिश करते हैं। इसका सबूत भारत है।

इसी प्रकार लबर पार्टी के अध्यक्ष प्राफेसर लास्की ने 23 मई 1946 को भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित एक भेटवार्ता में कहा था

आधुनिक इतिहास में किसी साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा किसी देश की जनता को इतने बड़े पैमाने पर अहिंसक तरीके से पद त्याग करते हुए नहीं देखा गया। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता साने की तश्तरी में दिए गए इस उपहार की प्रशंसा करेंगे।

दुनिया के अखबारों ने और खासतौर से ब्रिटेन और अमरीका के समाचारपत्रों ने 1946 के इन नए ब्रिटिश साविधानिक प्रस्तावों को जोरदार प्रचार दिया। अभी तक आग्ल अमरीकी समाचारपत्र ब्रिटेन द्वारा किए गए स्वायत्त्याग की प्रशंसा करने में डूबे हुए थे।

दूसरी तरफ इस विचारधारा को भारतीय जनमत ने किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। 1 जून 1946 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक समाचारपत्रक ने अपना विचार प्रकाशित किया

वही हुआ जिसका हमें डर था। कैबिनेट मिशन ने सांप्रदायिक और सामंती हिता का तरजीह देने की कोशिश में देश के व्यापक हितों को भुला दिया। ब्रिटेन के मंत्रियों ने, अपनी अच्छी नीयत के साथ अपनी तरफ से जितना कर सकते थे, उतना किया लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च 1942 में सर्वश्री चर्चिल और ऐमरी ने जो कुछ दम की इच्छा जाहिर की थी उससे बेहतर चीज हम नहीं पा सके जिस आजादी का वादा किया गया है उसके चारों तरफ पावदियों का ऐसा घेरा डालकर रखा गया है कि इसे आजादी नाम देना ही गलत है।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की आत्मप्रशंसा और भारतीयों के असंतोष को अभिव्यक्ति देने वाली विचारधारा के बीच पूरी तरह से विरोध का कारण क्या है? क्या 1946 के ब्रिटिश साविधानिक प्रस्तावों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम तौर से पद त्याग और भारतीय आजादी की मांग का प्रतिनिधित्व किया है? अथवा वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की बहुत दिना से चली आ रही इन कोशिशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनमें भविष्य के आधार पर समझौते का कोई तरीका ढूँढ लिया जाए ताकि ब्रिटेन अपने आपका भारत की राष्ट्रीय मांग के अनुरूप बदलती स्थितियों में ढाल ले और साथ ही इसका प्रभुत्व और शासन भी मूलतः भारत पर बना रहे? क्या ये नये प्रस्ताव भारतीय आजादी की अभिव्यक्ति करते हैं? अथवा वे भारत की आजादी दम का महज दिखावा करते हैं जिस शर्त, प्रतिबंध और सीमाओं के अन्तर्गत जंगल में व्यवहार में असमर्थ कर रखा हो?



## 1 बदलते हुए विश्व में भारत

1946 में क्विंट मिशन का भारत क्या भेजा गया ?

ब्रिटेन की नीति ने जो नई धारा ली थी उसके चार प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह है कि विश्वयुद्ध की समाप्ति ने समूचे विश्व में जनविद्रोहों की लहर तैयार कर दी थी। आधुनिक युग के प्रतिन्यावाद के मुख्य अंगुष्ठा, जनतन्त्र के खिलाफ हमलावरा के प्रमुख नेता और नस्त्ववादी प्रभुत्व का धुले तौर पर अत्यंत निर्मम तरीके से प्रचार करने वाले तत्व अर्थात् फासिज्म को जनतांत्रिक लोगों के संयुक्त संघ ने करारी हार दी थी। जर्मन, इतालवी और जापानी साम्राज्यवाद का नामोनिशान मिटा दिया गया था। शेष बच रहे थे ब्रिटिश अमरीकी साम्राज्यवाद लेकिन उन्हें भी विश्व नेतृत्व में समाजवादी सोवियत संघ के साथ हिस्सा बंटाना पड़ा था और इस प्रकार विश्व की तीन शक्तियों की एक असुविधाजनक हिस्सेदारी कायम हो गई थी। सोवियत संघ को युद्ध में अपार क्षति उठानी पड़ी थी और इसका मुख्य भार लाल सेना तथा सोवियत जनता पर पड़ा था। इन सबके बावजूद उसकी विश्व में अपनी स्थिति और अपनी ताकत बड़ी तजी से उभरी और यूरोप के जिन देशों को मुक्ति मिल गई थी वे पुरानी सामंती और सैन्यवादी तथा बड़ी व्यापारी शक्तियों के विरुद्ध प्रगतिशील जनतांत्रिक सत्ता के भाग पर बढ़त रहे। इन घिनोनी शक्तियों ने राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात किया था और हिटलर की जी हुजूरों की थी। चीन पर से जापान का शिकजा हटा दिया गया और अमरीकी प्रतिन्यावादियों द्वारा प्रगति के भाग में डाली गई तमाम बाधाओं के बावजूद चीन का राष्ट्रीय और जनतांत्रिक आंदोलन फिर से आगे बढ़ाया गया। सभी उपनिवेशों की जनता आंदोलन में जुट गई थी और वह उस आजादी की मांग करने लगी थी जिसके लिए उनके मुक्ति-आंदोलनों ने संघर्ष किया था। विश्व की इस नई और बदनी हुई परिस्थिति में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि भारत में पुरानी निरंकुश और नोकरशाही शासनव्यवस्था को बिना बदले बनाए रखा जा सके। भारत ही ऐसा उपनिवेश था जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था और जहाँ का राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था।

दूसरी बात यह है कि जीत में बराबर की हिस्सेदारी के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य बुनियादी तौर पर कमजोर हो गया था। ब्रिटेन की अदरुनी अव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था में ब्रिटिश पूंजीवाद का अपेक्षाकृत पतन हो गया था और औपनिवेशिक साम्राज्या पर से इसका दबदबा कम हो गया था। दो विश्वयुद्धों के बीच के दौर की यह एक उल्लेखनीय बात है। ब्रिटेन की विश्व में जो पुरानी महत्वपूर्ण स्थिति थी वह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से और खराब हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्मट्स और चर्चिल जैसे पुराने राजनीतिज्ञों ने बड़ी चिंता के साथ इस बात पर गौर किया था कि नए विश्व की दो विशालकाय शक्तियाँ—अमरीका और सोवियत संघ—अत्यंत प्रबल ढंग से बढ़ती जा रही हैं और मजबूत होती जा रही हैं और इस बात की आशंका पैदा हो गई है कि ब्रिटन

जब दूसर या तीसर स्थान पर पहुँच जाएगा। मिस्र और फिलिस्तीन स लकर वर्मा और मलाया तथा इंडोनेशिया तक ब्रिटेन के प्रभुत्व वाल क्षेत्र म हर तरफ स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाए गए लोगो की चुनौतिया ब्रिटिश साम्राज्य पर टूट पड़ी थी।

ब्रिटेन की जनता ने इन नई परिस्थितियों को सतक होकर महसूस किया था और वह टोरीवाद से दूर हटती जा रही थी ताकि अपनी प्रगति और समृद्धि के लिए कोई नया रास्ता ढूँढ सके लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के पुराने शासकों ने प्रभुत्व की इस टूटती आधारशिला का हर तरह स बनाए रखने की सारी सभव काशिशें की। जसाकि वर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इन फिर से विजित इलाकों में औपनिवेशिक दमन को पुन स्थापित करने की कोशिश की। उ होने विश्व के बदल हुए सतुलन का मुकाबला करने के लिए नए साम्राज्यवादी गठबंधन किए। इस दिशा में उ होने सबसे पहले पश्चिम यूरोपीय गुट बनाने की काशिश की लेकिन यूरोप की जनता के विरोध के कारण उन्हें इसमें असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ एक आरल अमरीकी गुट के निर्माण की कोशिश की। इन सभी नई रणनीतिक जोड़तोड़ों में भारत का दुनियादी महत्व था। जजर हो रहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए और उसकी आर्थिक जरूरतों तथा सैनिक योजनाओं के लिए भी यह बहुत जरूरी हो गया था कि वह भारत में बने रहने के लिए समझौते का कोई आधार ढूँढ ले। इसके जरिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्चवर्ग का सतुष्ट करके और यदि सभव हो तो उनपर विजय हासिल करके वह भारत को ब्रिटेन के आर्थिक और सामरिक दायरे में कद रख सकता था।

तीसरी बात यह है कि विश्व के रगमच पर ब्रिटेन की स्थिति में आए परिवर्तन की झलक ब्रिटेन की घरेलू स्थिति में भी दिखाई पड़ रही थी। 1945 की गरमिया में टोरी पार्टी को चुनाव से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा हालांकि इन लोगों ने विजय के अवसर और चर्चिल की प्रतिष्ठा को खूब भुलाने की काशिश की। पहली बार लेबर पार्टी बहुमत में आई और सत्तारूढ़ हुई। हालांकि नई सरकार का गठन करनेवाले लेबर पार्टी के नरम-दली दक्षिणपंथी नेताओं का व्यवहार में टोरी दल के ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के साथ घनिष्ठ संबंध था (और यह वाद के अनुभवों से जल्दी ही साबित हो गया), लेकिन चुनाव में जनता द्वारा टोरीवाद को नामजूर करना इस बात का संकेत था कि ब्रिटेन की जनता पुराने साम्राज्यवादी आधार के स्थान पर किसी नए रास्ते की तलाश शुरू कर चुकी थी। लेबर पार्टी के अधिवेशन ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन के बाद काय समिति के प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद आंदोलन की ओर स पेश प्रस्ताव को पहल ही स्वीकार कर लिया था जिसमें भारत को आजादी देने की बात कही गई थी। इस प्रकार लेबर आंदोलन आधिकारिक तौर पर भारत को आजादी देने के लिए प्रतिबद्ध था और नई लेबर सरकार के लिए यह जरूरी हो गया कि वह भारत के संबंध में अब तक चली आ रही नीति से कोई अलग नीति अपनाए।

चौथी और निर्णायक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने अंदर तथा विश्व भर में भारत को तत्काल आजादी देने की मांग बहुत जोर पकड़ती जा रही थी। साम्राज्यवाद के लिए अब यह संभव नहीं रह गया था कि वह पुराने तरीके से भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखे।

## 2 1945-46 का राष्ट्रीय उभार

फासीवाद की पराजय के बाद विश्व भर में लोकप्रिय आंदोलनों की जो जबरदस्त लहर आई थी उससे भारत भी प्रभावित हुए बिना न रहा। हालांकि भारत में संयुक्त राष्ट्रों के साथ मिलकर उन महान मुक्ति आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया था जिन्होंने फासिस्ट अधिभूत देशों में सफलता हासिल करने के काम में और युद्ध के बाद राजनीतिक रूपांतरण के लिए मांग प्रशस्त करने के काम में शक्तिशाली भूमिका अदा की थी फिर भी भारत के अंदर भी राष्ट्रीय मुक्ति और जनतांत्रिक प्रगति की वही भावना काम कर रही थी। यहां तक कि घुरी राष्ट्रों के खेमे में सुभाषचंद्र बोस द्वारा तैयार की गई 'इंडियन नेशनल आर्मी' का उदाहरण और खासतौर से युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इस सेना के प्रमुख अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों को देखें तो पता चलेगा कि भारत में जुझारू राष्ट्रभक्ति की दीपशिखा जल चुकी थी और यहां के सैनिकों में इसका विशेष प्रभाव था।

1945 की गरमिया में शिमला सम्मेलन का भंग होना इस बात का द्योतक है कि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति किस तरह के दलदल में फंसी गई थी। इसके साथ ही इस घटना से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक इतनी गहरी खाई हो गई थी जिसका पाटा जाना असंभव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों दलों के नेताओं के लिए ब्रिटेन के खिलाफ कोई सामूहिक मोर्चा बनाने से ज्यादा आसान काम यह हो गया था कि वे एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करके ब्रिटेन के साथ समझौते की बातचीत करें। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय मोर्चे की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। साथ ही प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कांग्रेस लीग खिलाफत का जो संयुक्त मार्चा बना था, मौजूदा नीतियां उसकी नीति के एकदम विपरीत थीं। अंगरेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया।

इसलिए युद्ध के दौरान बाद भारत में जनविद्रोह हुए, उन्हें किसी आधिकारिक राष्ट्रीय आंदोलन या संयुक्त और कारगर नेतृत्व नहीं मिल सका। जहां तक जनता की बात है, उसके अंदर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकता की इच्छा काफी प्रबल थी। इसका प्रमाण कलकत्ता, बंबई तथा अन्य प्रमुख शहरों में हुए विशाल प्रदर्शन हैं जहां जनता की भीड़ ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे तथा कई स्थानों पर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहराए। दुर्भाग्य की बात है कि निचले तबके में जितनी एकता थी उतनी एकता नेतृत्ववर्ग में नहीं पाई गई।

फिर भी जादोलन जाम नागरिकों के बीच ही नहीं बल्कि सेना के जवानों के बीच भी तेजी से स्थान बनाता गया और तब होता गया। भारत के लिए यह एक नई बात थी। उसके क्रांतिकारी महत्व को समर्थन में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों जैसा राष्ट्रीय आंदोलन के उच्चवर्गीय नेताओं में किसी ने भूल नहीं की। इससे पहले 1930 में गडवाली सिपाहियों ने गोली चलाने से इकार कर ही दिया था। लेकिन अब फौजा में और खासकर वायुसेना तथा नौसेना में बड़े पैमाने पर हड़तालें हो रही थी जिनसे यह पता चलता था कि अंगरेजों की ताकत का आधार और उनका शासनतंत्र पूरी तरह छिन्नभिन्न हो चुका है। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो माना बिजली की तरह चमककर भारतीय क्रांति की परिपक्व शक्तियों का परिचय दे दिया। महान क्रांतियों में नौसेना ने किस तरह हरावल दस्त का काम किया है इसे हम 1905 में रूस में 'पोतेमकिन' 1917 में रूस के कासतात या 1918 में जर्मनी में 'कोल' विद्रोह में महसूस कर चुके हैं। 1946 में भारतीय नौसेना में जो विद्रोह हुआ और उसके समर्थन में देश में जनआन्दोलन की जो लहर आई तथा बर्बई के मजदूरों ने जितनी वीरता के साथ हड़ताली नाविका का समर्थन किया उससे जाहिर हो गया कि भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है और ये घटनाएँ भारतीय इतिहास में मोल का पत्थर हैं। फरवरी 1946 के उन ऐतिहासिक दिनों में यह बात सामने आ गई कि भारतीय जनता के प्रगतिशील आंदोलनों के कौन लोग दुश्मन हैं और कौन लोग दोस्त हैं।

शाही भारतीय नौसेना के नाविकों के विद्रोह का केंद्रबिंदु बर्बई था लेकिन इसका विस्तार कराची और मद्रास तक था। इन शहरों में लोगों ने इन नाविका का काफी समर्थन किया था। विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी की सुबह 'तलवार' प्रशिक्षण स्कूल से हुई थी जहाँ बहुत दिनों से लोगों की कुछ शिकायतें थी जिन्हें अधिकारीगण दूर नहीं कर रहे थे। 19 फरवरी की सुबह तक यह विद्रोह बर्बई में 12 तटवर्ती प्रतिष्ठानों तथा बदरगाह पर बड़े 20 जहाजों तक फैल गया और इसमें सभी 20 हजार नाविकों ने भाग लिया। जहाज के मस्तूल पर से अंगरेजों का झंडा यूनियन जक हटा दिया गया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के झंडे फहराए गए। शहर में नाविकों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लेकर जुल्स निकाले तथा नारे लगाए। उनके नारे थे, 'जय हिंद', 'इकलाव जिदावाद', 'हिंदू मुस्लिम एक हो', 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो', 'हमारी मांगें पूरी करो', आई० एन० ए० के लोगों को और राजनीतिक बदिया को रिहा करो, इंडोनेशिया से भारतीय सत्ता हटाओ'। यह हड़ताल भारतीय नौसेना के अर्थ जहाजों तक भी फैल गई। इनमें कराची का 'हिंदुस्तान' जहाज भी शामिल था जिसने बाद में सशस्त्र संघर्ष में भी हिस्सा लिया।

विद्रोही नाविका न शुरु से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ संपर्क बनाकर किया था लेकिन इन नेताओं का न तो उन्हें कोई समर्थन मिला और न कोई व्यावहारिक मदद दी। इन विद्रोहियों ने एक केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया और

पूरा अनुशासन वायम रखा। बंबई की जनता ने इन हड़तालियों का जोरदार समर्थन किया और अपने घर से खाना बनवाकर जहाजां तक पहुंचाया। ब्रिटिश अधिकारियों का उस समय बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि आंदोलन का तेजी से विस्तार होता जा रहा है और फिर उन्होंने जबरदस्त दमन का सहारा लिया। जल्दी जल्दी भारी सैनिक और नौसैनिक टुकड़ियां बंबई तथा कराची भेजी गईं। इन टुकड़ियों के भारतीय जवानों ने जब अपने साथी हड़ताली नाविका पर गोली चलाने से इकार कर दिया तब इस काम के लिए अंगरेज सैनिकों को बुलाया गया और 21 फरवरी को कंसिल बैरक के बाहर सात घंटे तक घमासान लड़ाई चलती रही। 21 फरवरी के तीसरे पहर एडमिरल गाडफ्रे ने रडिया पर विद्रोहियों का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 'सरकार तुम लोगों के खिलाफ अपनी जबरदस्त ताकत का पूरा पूरा इस्तेमाल करेगी भले ही ऐसा करने में हमारी नौसेना पूरी तरह बरबाद हो क्यों न हो जाए। केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति ने इस धमकी के जवाब में शहर की जनता से शांतिपूर्ण हड़ताल करने की अपील की। हालांकि उस समय जरूरत इस बात की थी कि हड़ताल का समर्थन करके अंगरेज अधिकारियों की इस धमकी को विफल किया जाए और नौसेना के नाविकों का जीवन बचाया जाए लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से बल्लभभाई पटेल ने हड़ताल का समर्थन करने से इकार कर दिया और उसके खिलाफ हिदायतें जारी कर दी। फिर भी केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति की अपील का बंबई की ट्रेड यूनियनों और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया और 22 फरवरी को बंबई की मजदूर जनता ने इसके समर्थन में व्यापक हड़ताल की। अंगरेज अधिकारियों ने इस जनआंदोलन को विफल करने की कोशिश में सेना और पुलिस का सहारा लिया तथा जनता पर अधाधुंध गोलीयां चलाई गईं। 21 फरवरी से 23 फरवरी, तीन दिनों के अंदर सरकारी आकड़ों के अनुसार 250 लोग मारे गए। घटना का विवरण एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अधिकारी ने प्रस्तुत किया है

शाम के चार बजे थे। मैं बंबई की मजदूर बस्ती परेल में एल्फिंस्टन रोड के कान के पास सुपारीवाग रोड के बराबर में टहल रहा था।

सड़क पर काफी लोग थे लेकिन उन्हें भीड़ नहीं कहा जा सकता था। कम्युनिस्ट पार्टी की सलाह पर इन लोगों ने अपने साथ कोई हथियार नहीं रखा था यहाँ तक कि इनके पास डंडे या पत्थर भी नहीं थे।

अचानक बिना किसी चेतावनी के ब्रिटिश सैनिकों से लड़ी एक लारी गर्नाफ़मैन रोड से गुजरी। इन सिपाहियों के पास राइफलें थीं और एक ब्रैनगन थी।

साथ इधर उधर भागने लगें और मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया लेकिन तभी गारे सिपाहियों ने भागते हुए लोगों की तरफ गोली चलाना शुरू कर दी। चौंसठ लोग घायल हुए और चार मारे गए।

इसक पीछे वजह क्या थी ?

ट्रड यूनियनो ने नौसैनिक विद्रोह के समर्थन में आम हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल सूती कपड़ा मिलों, कारखानों और रेलवे वकशापा में शतप्रतिशत सफल हुई थी।

किसी बड़े अधिकारी ने फैसला किया कि 'इन कलूटों को सबक सिखाया जाए', और उसके आदेश पर युद्ध के लिए तैयार हथियारबंद दस्ते लारियो में लादकर खाना कर दिए गए और उन्हें आदेश दिया गया कि जहाँ भीड़ दिखाई दे फौरन गोलियाँ चला दो और किसी को पत्थर उठाने तक का मौका मत दो।

सड़का पर कोई एवुलेस नहीं थी और लोगों को अपने ही आप अस्पताल जाना पड़ा।

बाद में डेलिजली रोड पर मने देखा कि गोरे सैनिक मजदूरों की चाल में घुस रहे हैं और घरों में बैठे लोगों पर गोलीयाँ चला रहे हैं। इन चालों में चार लोग मारे गए और 16 घायल हुए।

परल जिले में स्थापित किंग एडवर्ड मेमोरियल हास्पिटल में ही 50 व्यक्तियों की मौत हुई। परल के अस्पतालों ने छ सौ घायलों में से दो सौ की चिकित्सा की।

तमाम अखबारों ने आपको 'गैरजिम्मेदाराना विद्रोह' की खबरे दी होंगी लेकिन इन अखबारों ने यह नहीं बताया होगा कि कैसिल घेरकों में अधिकारियों ने हड़तालियों को कैद कर दिया, उन्हें बिना खाना पानी दिए चारों तरफ से घेर लिया और अगर कोई पानी पीने बाहर निकला तो उसे गोलीयाँ से भून दिया गया।

उन्होंने आपको भीड़ की हिंसा और उपद्रवी हरकतों के बारे में बताया होगा। उन्होंने यह नहीं बताया होगा कि जिस ट्रक पर सबसे पहले पथराव हुआ था उस ट्रक ने एक अनुशासनबद्ध जुलूस को अपनी तब रफ्तार से रौंद दिया था।

अधाधुंध आतङ्ग से अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए जनता द्वारा किया गया यह एक संयुक्त संघर्ष था।

वातावरण में एक ही गन्ध गूँज रहा था और वह था, हम एक हैं। टोपधारी

सैनिकों को जिस दृश्य से सबसे ज्यादा घबराहट हो रही थी वह था कांग्रेस के तिरंगे पड़े, मुस्लिम लोग के आगे चाद वाले पड़े और कम्युनिस्ट पार्टी के लाल पड़े का जुलूस में एक साथ फहराया जाना। मुस्लिम लोग और कांग्रेस के पड़े नवदा' नामक जगो जहाज के मस्तूल पर फहरा रहे थे।

जैसे ही हम अंदर घुसे और पीछे से सनसनाती हुई गोलियां निकल गई, एक भारतीय ने मुझसे कहा—'यह है ब्रिटेन का ममाजवाद जो इस समय जमल में है।' मेरी चिंता लेकर सरकार की प्रतिष्ठा को लेकर हम जिसने 24 घंटों के अंदर वह समय भी गवा दिया जो इंडोनेशिया के वाद उसमें पास बचा हुआ था।

सबसे बड़कर मैं ब्रिटेन की जनता के सम्मान का लेकर चिंतित हूँ। लगभग सारी गोलियां ब्रिटिश सैनिकों द्वारा चलाई गईं।

पुलिस को सबसे पीछे रखा गया था। मैंने एक भी भारतीय सैनिक नहीं देखा और मुझे बताया गया कि चूक सेना में भी असंतोष फैल गया है इसलिए सरकार ने डर के कारण दमन के इस कार्य में भारतीय सैनिकों को नहीं लगने दिया।

ब्रिटिश सैनिक किसी विशेष सैनिक दस्ते या सुरक्षा यूनिट के नहीं थे। वे साधारण रंगरूट थे और युद्ध के समय स्वयंसेवी सैनिकों के रूप में काम कर चुके थे। अर्थात् वे वर्दी पहने ब्रिटिश मजदूर थे, लिसेस्टर रेजिमेंट, ऐसेक्स रेजिमेंट, दि रायल आर्टिलरी और दि रायल मरींस के सैनिक थे।

अतः 23 फरवरी को वल्लभभाई पटेल के दबाव से केंद्रीय हडताल कमेटी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। पटेल ने नाविका को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी और आश्वासन दिया था कि 'कांग्रेस इस बात की हर संभव काशिश करेगी कि हड़ताली नाविका से बदला न लिया जाए।' मुस्लिम लोग ने भी इसी तरह का आश्वासन दिया था। लेकिन दो दिनों के अंदर ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हड़ताल समिति के अध्यक्ष ने अपने अंतिम वक्तव्य में कहा 'हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ब्रिटेन के सामने नहीं।'।

फरवरी में नौमना के नाविकों के विद्रोह और बंबई की जनता के संघर्षों से यह बात काफी स्पष्ट हो गई थी कि 1946 में भारत में जो विस्फोटक स्थिति थी उसमें कौन सी शक्तियाँ किनके साथ थीं। एक तरफ तो इस आंदोलन से यह पता चला कि आंदोलन कितना विवक्षित हो चुका है, जनता में कितना जबरदस्त साहस और संकल्प है, और हिंदू मुस्लिम

एकता तथा कांग्रेस लीग एकता के लिए जनता कितनी व्यग्र है। यह भी पता चला कि आंदोलन का विस्तार सेना तक में हो गया है और अब ब्रिटिश शासन का आधार सुरक्षित नहीं रह गया है। दूसरी तरफ इस आंदोलन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश का वर्तमान नेतृत्व इन स्थितियों के लिए एकदम तैयार नहीं है और उसमें एकता का अभाव है और इसीलिए राष्ट्रीय सघष का नेतृत्व करना उनके वश की बात नहीं है।

पहले मंच पर भाषण देने के लिए बराबर पहले जापानिया और फिर ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सुभाषचंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी को, तथा कथित क्रांतिकारी राष्ट्रीय सघष के प्रतीक के रूप में गौरवाचित किया गया था। 1942 की घटनाओं को भी, जिन्होंने कभी जनसघष का रूप नहीं लिया, गौरवाचित करने को काफी कोशिशें की गईं।

लेकिन अब, जबकि जनता का सही आंदोलन सचमुच शुभ हो चुका था, जब हिंदू मुस्लिम एकाता कायम हो रही थी और उसपर अमल हो रहा था, जब सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन में सेना के जवानों में आम नागरिकों के कंधे से कंधा मिलाकर सघष शुरू कर दिया था और जब आजादी की सही लड़ाई में ब्रिटिश शासन की जड़े हिला दी थी राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं के रुख में जबरदस्त तब्दीली दिखाई पड़ी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उच्चवर्गीय नेता जनआंदोलनों के खिलाफ हो गए और जनता के विरुद्ध कानून और व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पक्ष लिया। इन नेताओं की तरफ से एक के बाद एक बयान निकाले गए जिनमें 'हिंसा' की निंदा की गई थी, लेकिन यह निंदा उन साम्राज्यवादियों की हिंसा की नहीं थी जिन्होंने तीन दिनों के भीतर सैकड़ों लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था वल्कि इनमें उन निहत्थे हड़तालियों की भरसना की गई थी जिन्हें निममतापूर्वक गोलियां स भून दिया गया था। वल्लभभाई पटेल ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि नौसना व नावियों का हथियार नहीं उठाना चाहिए था और पटेल ने यह भी कहा कि 'मैं कमांडर इन चीफ की इस बात से सहमत हूँ कि नौसना में अनुशासन जरूरी है।' कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने कहा

हड़ताल या दश की अम्पाई सरकार के आदमा का उल्लंघन कराना का अब समय नहीं है। इस समय विदेशी शासक से किसी बात पर लड़ने का यत्न नहीं है क्योंकि ये दंगल करने वाली सरकार के रूप में फिन्हाल काम कर रहे हैं।

गांधी ने अपना एक महत्वपूर्ण बयान में हिंदुओं और मुसलमानों का नापसंद एकाता की भरसना की क्योंकि यह अहिंसा व मित्रता का दुस्तरा कर स्थापित हुई थी

यदि मैं ऊपर में नाच तब एकतायुद्ध होता तो बात मंग मंग में आ गता था।



तब निम्नलिखित इसका अर्थ यह होता कि भारत का निरुद्ध पाटि के अव्यवस्थित लागा क हाथों में सौंप दिया गया । मैं इस काम का अजाम दखने के लिए 125 साल तक जीना नहीं चाहता । इसके बजाय मैं चित्ता की लपटा को समर्पित हो जाना चाहूंगा । ( हरिजन, 7 अप्रैल 1946 )

इस प्रकार देश के सुधारवादी नेताओं और जनजादोलन के बीच की खाई जो पहले भी 1922 में चोरीचोरा कांड के बाद और 1931 में गांधी इरिन समझौते के बाद प्रकट हो चुकी थी, अब और भी ऊंचे धरातल पर सामन आ गई । कांग्रेस शासक के खिलाफ मिला-जुला संघर्ष चलाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का देश की राष्ट्रीय आजादी का रास्ता न समझकर एक ऐसा खतरा समझा गया जिसका रोकने की जरूरत महसूस की गई क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत में आम जाति की विजय होती ( भारत की निरुद्ध पाटि के अव्यवस्थित लागा के हाथ में सौंपना, एक ऐसा उद्घाटक वाक्य है जो आम जनता के प्रति उच्चवर्गीय नस्ल की शत्रुता को प्रकट करता है ) । भारतीय उच्चवर्ग ने अगरजों के दमनकारी शासक न समझ दखलाल करने वाला शासक माना । उस संकट की घड़ी में भारत की स्थिति में छिपी प्रांतिकारी शक्तियों के मन में उच्चवर्ग का इतना पतन हो गया था कि वह साम्राज्यवादियों की ओर ही झुकता चला गया । पहले भी जब जब भारत में जनसंघर्ष अपने उत्कर्ष पर पहुंचता था वहीं स्थिति दिखाई पड़ती थी । और आज जब भारत का स्वाधीनता संघर्ष अपने अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है, यह बात एक बार फिर सही साबित हो रही है ।

अगरज शासक ने राष्ट्रीय मोर्चे की इस कमजोरी को भांपने में तनिक भी देर न की और उन्होंने इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाया । जसा बाद की कैबिनेट मिशन की कार्यवाहियों से पता चला, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की मपूर्ण कार्यनीति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं का दस्तमाल करने की हो गई । ब्रिटिश साम्राज्यवादी इन नेताओं में एक तरफ तो उनके अंदर यह आश्वासन पैदा करते थे कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ वे उन्हें जनता का डर दिखाते थे तथा उनके आपसी मतभेदों और विद्वेषों का फायदा उठाते थे ।

18 फरवरी को बंबई में नौसाला के नाविका की हड़ताल शुरू हुई । 19 फरवरी को प्रधान-मंत्री एटली ने हाउस आफ कामंस में एलान किया कि एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा ।

### 3 कैबिनेट मिशन

मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा । इसकी हिदायत में उसी नीति पर अमल किया गया जिसका सितंबर 1945 में बायसराय ने अपने रेडियो प्रसारण में एलान किया था । सितंबर 1945 में बायसराय ने अपने रेडियो प्रसारण में कहा था

सरकार का यह इरादा है कि जितनी जल्दी संभव हो संविधान का निर्माण करने वाले एक निकाय का गठन किया जाए। और इसके प्रारंभिक कदम के रूप में उसने मुझे यह अधिकार दिया है कि चुनावों के फौरन बाद में विभिन्न सुवा में विधानसभाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करके यह पता लगाऊँ कि 1942 की घोषणा में शामिल प्रस्ताव स्वीकार्य हैं या कोई संशोधित अथवा वैकल्पिक योजना पसंद की जाएगी।

भारतीय रियायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि संविधान का निर्माण करने वाले निकाय में वे किस तरह अधिक से अधिक सक्रिय रह सकते हैं।

सरकार उस संधि की मुख्य बातों पर विचार करने को सोच रही है जो ग्रेट ब्रिटन और भारत के बीच सपने हानी है।

जब तक ये तयारियाँ पूरी नहीं हो जाती भारत सरकार को अपना काम जारी रखना चाहिए। इसलिए ब्रिटन सरकार ने मुझे इस बात का अधिकार दिया है कि प्रांतीय चुनावों के परिणाम प्रकाशित होने के फौरन बाद में एक ऐसी मायकासी परिषद का गठन करूँ जिसकी भारत की सभी प्रमुख पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो

यह देखा जा सकता है कि इस वक्त में संशोधन की संभावना के साथ सामान्य तौर पर उसी नीति का पालन किया गया है जो 1942 में ब्रिटिश प्रस्तावों में पेश की गई थी। वायसरॉय के रेडियो प्रसारण के साथ ही प्रधानमंत्री ने एलान किया

भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को जो व्यापक परिभाषा 1942 की घोषणा में दी गई है और जिसे इस देश की सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है वह आज भी अपनी समप्रता और उद्देश्य में उभरी की रहीं हैं।

1946 के शुरू के महीने में चुनाव कराए गए। परिणामों को देखते ही पता चला कि देश का जनमत दो बड़े राजनीतिक संगठनों के साथ है जो स्वाधीनता का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, सामान्य सीढ़ी पर लागू न कांग्रेस का और मुस्लिम लीग पर मुस्लिम लीग को पसंद किया है। इससे साफ हो यह भी पता चला कि जनगणना के बाद छोट-छोट राजनीतिक गुटों का अस्तित्व अब अपेक्षाकृत समाप्त हो गया है। इन छोट-छोट गुटों में हिंदू महासभा या पंजाब में यूनिवर्निस्ट पार्टी और मद्रास में जस्टिस पार्टी जैसे राजनीतिक गुट हैं। केंद्रीय विधानसभा में (जिसका निर्वाचन अत्यंत सीमित मतानुसार पर हुआ था। इसमें ब्रिटिश भारत की जावाली के एन. प्रतियोग के आधे से भी कम लोग ही भाग लेने का अधिकार था) कांग्रेस का 56 स्थान मिले (जो पहले 36 थे) और अन्य सभी सामान्य

सीटा पर 91 प्रतिशत त स कुल वोट का 59 प्रतिशत भाग मिला। मुस्लिम लीग को सभी 30 मुस्लिम सीटा पर गफलता मिली (पहले उस 25 सीटें मिली थी) और उसे 86 प्रतिशत मुस्लिम वोट तथा कुल वोट का 27.6 प्रतिशत भाग मिला। प्रांतीय विधानसभा चुनावों में आवाजों के 11 प्रतिशत लागू न और बालिग आवाजों ने 1/5 से 1/4 हिस्से का भाग लिया। इनमें कांग्रेस का 930 सीटें मिली जबकि 1937 में उस महज 715 सीटें मिली थी और उस कुल 55.5 प्रतिशत वोट मिले जबकि मुस्लिम लीग का 507 मुस्लिम सीटा में 427 सीटें प्राप्त हुईं जबकि 1930 में उस महज 108 सीटें मिली थी और कुल मुस्लिम वोट का 74.3 प्रतिशत उनमें प्राप्त किया। यह पहला मोड़ा स जय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में हिस्सा ले सकी और उसे 8 स्थान तथा 6,84,925 वोट प्राप्त हुए।

19 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एनान किया कि तीन कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय मामलों के मंत्री पैथिक लॉरेन, वाइसराय और अध्यक्ष स्टैंफोर्ड क्रिप्प और नोपरिवहण मंत्री लार्ड एडमिरल्टी एलबर्ट डेविस को भारत भेजा जा रहा है। इस घोषणा के साथ ही एक दूसरे बयान के जरिए कैबिनेट मिशन के विस्तार में घोषणा का एलाप किया गया था जिसमें कहा गया कि मिशन का उद्देश्य भारतीय जनता के नेताओं के सहयोग से भारत में पूर्ण स्वराज्य शीघ्र स्थापित करने का काम का बड़ावा देना है। इस दिशा में कैबिनेट मिशन का जो कदम उठाने थे उनमें ये बातें शामिल थीं

1. ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देशों की स्वायत्तता के साथ प्रारम्भिक बातचीत करना ताकि संविधान की निर्माण विधि पर सहमति की अधिक से अधिक गुंजाइश पैदा की जा सके।
2. संविधान बनाने वाले निकाय का गठन करना।
3. एक ऐसी कार्यकारी कौंसिल की स्थापना करना जिसका भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां का समर्थन प्राप्त हो।

15 मार्च को कैबिनेट मिशन की खानगी के अवसर पर संसद के अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने एब और नीति संबंधी वक्तव्य जारी किया (देख पहला अध्याय) जिसकी दो बातों ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहली बात ता यह थी कि इस वक्तव्य में 'स्वतंत्रता' शब्द का इस्तमाल पहली बार किया गया था जिस भारत के डोमिनियन राज्य चुन जाने के संभावित विकल्प के रूप में कहा गया था

भारत को खुद यह तय करना चाहिए कि उसकी भावी स्थिति क्या होगी और विश्व में उसका क्या स्थान होगा। मुझे आशा है कि भारत शायद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत रहना पसंद करे, लेकिन इसके बजाय यदि वह स्वतंत्रता चाहता है, और हमारे विचार से उस यह चाहना का पूरा हक है, तो हम चाहिए कि हम इस हस्तांतरण को जहां तक संभव हो आसानी और बाधा रहित बनाएं।

दूसरी बात अल्पसंख्यकों के प्रश्न से संबद्ध थी

हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में काफी सचेत हैं और अल्पसंख्यकों को भय से मुक्त वातावरण में रहने की सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग को इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि वह बहुसंख्यक वर्ग के विकास के खिलाफ अपने निपेधाधिकार का इस्तेमाल कर सके।

भारत के सांविधानिक विकास के एक सभावित लक्ष्य के रूप में 'स्वतंत्रता' के जिक्र का काफी स्वागत किया गया। इसे यह माना गया कि ब्रिटिश सरकार अब तक चली जा रही अपनी नीति से अलग हट रही है, साथ ही इसे भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नए रुझान का प्रमाण माना गया। वहम में टोरी प्रवक्ताओं ने मतभेदों का परिचय दिया जो बात काफी सदिग्ध थी। भारत में ब्रिटिश शासन के अत्यंत सक्रिय और घोर समर्थक व्यक्ति सर स्टैनले रीन जैसे लोगों ने भी कहा कि 'स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करने में किस तरह की हिचकिचाहट पैदा हो रही है?' फिर भी अत्यंत चौकस और परिकल्पित यह प्रस्ताव कि ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्धारित की जाने वाली कार्यपद्धति और स्थिति से संपन्न राजनीतिक संविधाननिर्माता निकाय को डोमिनियन और स्वतंत्रता में से चुनाव करना होगा, दरअसल नीति की कोई नई व्याख्या नहीं पेश करता था। 1942 में क्रिप्स द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में यह बात पहले ही कही जा चुकी थी जिसे टोरी बहुमतवाला मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी थी

ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव है कि भारत में जल्दी से जल्दी स्वराज्य कायम करने के उद्देश्य से एक ऐसे नए भारतीय संघ की स्थापना की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए जिसको पूरा पूरा डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो और जो चाहे तो, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपने को अलग कर सके।

राजनीतिक विकास रोकने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को वोटों की अनुमति देने से इन्कार करने का वादा शिमला सम्मेलन की स्थिति से आगे बढ़ने का दावा है और इससे वर्तमान राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के नकल्प का पता चलता है। लेकिन बाद में सरकारी स्तर पर भारत में दी गई व्याख्याओं में बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग का अर्थ यहाँ मुसलमानों से नहीं है और इस व्याख्या ने सरकारी नीति में तथाकथित परिवर्तन के महत्व को समाप्त कर दिया।

कैबिनेट मिशन ने शुरू के कुछ सप्ताहों की अपनी कार्यवाहियों के दौरान गवर्नर, राजाओं, प्रांतों के प्रधानमंत्रियों तथा विपक्षी नेताओं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग बैठकें कीं और बातचीत की। इन लोगों से अलग अलग बातचीत करके दुनिया को यह दिखाया गया कि भारत में विभिन्न राजनीतिक गुटों और

खासतौर से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच काफी मतभेद है और ये अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं। ईस्टर की छुट्टियों के बाद मिशन की कायवाही का दूसरा चरण शुरू हुआ और मिशन ने कांग्रेस तथा लीग के बीच कोई समान आधार ढूँढने की दृष्टि से विचार विमर्श शुरू किया। मिशन ने इस तरह के आधार के लिए प्रस्ताव पेश किए और मिशन कांग्रेस तथा लीग के बीच त्रिपक्षीय बातचीत के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन का 5 मई से स्थगित करते 12 मई कर दिया गया। यह दूसरा शिमला सम्मेलन भी एक वर्ष पूर्व आयोजित शिमला सम्मेलन की ही तरह बिना किसी फल पर पहुँचे समाप्त हो गया। इस प्रकार कैबिनेट मिशन की कायवाहियों के प्रथम सात सप्ताहों ने ब्रिटेन के फैसले के लिए जमीन तैयार कर दी।

16 मई का कैबिनेट मिशन के वायसराय तथा ब्रिटिश कैबिनेट के साथ अपनी नीति से संबंधित एक वक्तव्य जारी किया। नीति संबंधी इस वक्तव्य में फसले और सिफारिशें दोनों बातें थीं। संविधानसभा की स्थापना और इसके मध्यम तथा इसकी कार्यपद्धति के सदस्यों में उठाए जाने वाले तात्कालिक बदलों के बारे में फैसले लिए गए थे तथा भावी संविधान के प्रथम सिद्धांतों के सदस्यों में कुछ सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों में संविधानसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता था जबकि ये फैसले मंजूर या नामंजूर करने के लिए रंगे गए थे। चूंकि तथ्य रूप में ये फैसले उन सभी महत्वपूर्ण बदलों का संचालित करते थे जिन्हें अनिवार्य रूप से संविधान के चरित्र का आगे चलकर निर्धारित करना था इसलिए नीति संबंधी यह वक्तव्य, दरअसल, ब्रिटेन द्वारा लिए गए एकतरफा फैसले द्वारा घोषित किया गया था (हालांकि शत से बचा गया था)।

कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत में भारतीय प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग खेमों में बंटे हुए थे। चुनावों के परिणामों ने दोनों पार्टियों की ताकत को पुष्टि कर दी थी और इससे इस फूट को और बल मिला था। अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलजुलकर एक मंच से काम करने की कोशिश की होती तो कैबिनेट मिशन इतनी आसानी से आजादी की घोषणा करने और सत्ता का हस्तांतरण करने की व्यापक मांग से कतरा नहीं सकता था। दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, भावी संविधान पर तत्काल सहमत न होने पर भी, यदि मिशन के सामने कोई संयुक्त मोर्चा बना पाते और मिशन द्वारा अलग अलग चलाई जा रही बातचीत को नामंजूर करते तथा इस बात की मांग करते कि तत्काल आजादी की घोषणा की जाए और सत्ता का हस्तांतरण किया जाए (साथ ही संविधान के स्वरूप के बारे में अन्य तमाम प्रश्नों को यह मानकर छोड़ दिया जाता कि ये घरेलू राजनीति के मामले हैं और इन्हें बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के देश के राजनीतिक संगठन स्वयं हल कर लेंगे) तो अंगरेज शासकों को पहल करने से रोका जा सकता था और ब्रिटेन के लिए एकतरफा फैसला लेना असंभव हो जाता। दुर्भाग्यवश कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के नेतागण एक दूसरे की बजाय मिशन के साथ गोपनीय और घनिष्ठ बातचीत

के लिए ज्यादा उत्सुक थे और वे एक दूसरे के विरुद्ध अपने दावों की पूर्ति के लिए मिशन का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें अंगरेजी शासकों को दुनिया के सामने यह ढिंढोरा पीटने का मौका मिल गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जबरदस्त फूट है और यह फूट ही भारत को आजादी मिलने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अपने इसी दुष्प्रचार के आधार पर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को भारत की भावी राजनीति के बारे में अपना फैसला घोषित करने का मौका मिल गया जिसे उन्होंने अनिवार्य और एकमात्र फैसला घोषित किया।

## 4 1946 के नए साविधानिक प्रस्ताव

कैबिनेट मिशन ने 16 मई की अपनी घोषणा में निम्न प्रस्ताव पेश किए

### 1 भावी संविधान के लिए सुझाव

- (क) ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत का एक सघ बनाया जाना चाहिए जो विदेश, रक्षा और संचार संबंधी मामलों की देखरेख करे तथा जिसके पास जनता के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार हो।
- (ख) सघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों।  
विधानमंडल में किसी महत्वपूर्ण आप्रदायिक मामले से संबंधित प्रश्न पर फैसला लेने के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत तथा दो प्रमुख समुदायों (कांग्रेस और मुस्लिम लीग) का मतदान जरूरी है—साथ ही सभी उपस्थित सदस्यों का बहुमत और मतदान जरूरी है।
- (ग) सघ विषयों से अलग सभी विषयों तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों में निहित होने चाहिए।
- (घ) सघ को सत्तातरित विषयों और अधिकारों के अलावा सभी विषयों और अधिकारों राज्य के हान चाहिए।
- (ङ) प्रांतों की कार्यपालिकाओं और विधानांगों सहित समूहों के गठन की छूट होनी चाहिए और प्रत्येक समूह को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रांतों के लिए समान विषय निर्धारित कर सके।
- (च) सघ और समूहों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोई प्रांत अपना विधानसभा के बहुमत से कम से कम दस वर्षों के बाद और बाद में दस दस वर्ष के अंतराल से संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार का काम कर सके।

## 2 सविधान बनाने वाले तब के लिए प्रस्ताव

(क) 389 सदस्यों की सविधानसभा बनाई जाए, इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लिए जाएं जिनका सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदाय के लिए आबादी के अनुसार निर्धारित पथक सीटों से सांप्रदायिक आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए और यह काम प्रांतों की मौजूदा विधानसभाएं करें, रियासतों से 93 लोगों का चुनाव किया जाए और चुनाव का तरीका आपसी सलाह मशविरों से तय हो।

(ख) प्रांतों का तीन भागों में विभाजन

(अ) जो हिंदू बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें (मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्यप्रांत और उड़ीसा)।

(ब) जो उत्तरपश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का (पंजाब, उत्तरपश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान) और उत्तरपूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का (बंगाल और असम) प्रतिनिधित्व करें। इन समूहों के प्रतिनिधि प्रत्येक समूह में सबसे प्रांतों के लिए सविधान निर्धारित करने के लिए अलग अलग मिला करेंगे। प्रांतों को नए सविधान के बनने तथा इस आधार पर प्रथम चुनावों के होने के बाद ही अपनी पसंद तय करने का अधिकार होगा।

(स) अपेक्षाकृत छोटे अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति बनाई जाए।

(द) सभ का सविधान निर्धारित करने के लिए संघीय सविधानसभा बनाई जाए। महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मतलों से संबंधित प्रस्तावों के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत की और दोनों बड़े समुदायों में से प्रत्येक के मतदान की आवश्यकता होगी।

## 3 राज्य

नए भारतीय सभ में राज्यों के सहयोग का आधार बातचीत द्वारा तय किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में एक प्रबंधसमिति नियमित होगी।

स्वाधीनताप्राप्ति के बाद ब्रिटेन की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी।

## 4 ब्रिटिश भारतीय संधि

संघीय सविधानसभा और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक ब्रिटिश भारतीय संधि संपन्न की जाएगी।

## 5 अंतरिम सरकार

‘प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से एन अंतरिम सरकार’ के गठन की सिफारिश का काम वायसराय अपनी कायकारी कौंसिल के पुनर्गठन के आधार पर करेगा

कैबिनेट मिशन की योजना पर तात्कालिक प्रतिक्रिया मिश्रित थी। सामान्य तौर पर अंगरेजी न इसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि ये प्रस्ताव भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने तथा भारतीय जनता को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार देने के वादे को पूरा करते हैं। टोरी पार्टी के दक्षिणपंथी खेमे के एक बग ने जिसका प्रतिनिधित्व चर्चिल करते थे, अपनी आलोचना में इस आम दृष्टिकोण पर ही जोर दिया क्योंकि यह आलोचना भी उसी धारणा पर आधारित थी कि इस योजना में भारत का आजादी देने की बात निहित है।

इस मिशन के प्रति भारत में जो टिप्पणियाँ हुईं उनका दृष्टिकोण और भी विविधता लिए हुए था। गांधी ने शुरू से अंत तक बातचीत के दौरान इस कैबिनेट मिशन के और अंगरेज सरकार के सद्भाव और ईमानदारी की प्रशंसा करने में बेहद चुस्ती दिखाई दी (‘वे हमें छोड़ा नहीं देंगे’—ये ये गांधी के शब्द जिनसे पता चलता है कि विद्रोह के लिए उठ खड़े देश के नेता का दमनकारियों के प्रति क्या रवैया था) उन्होंने इस योजना का स्वागत किया और कहा ‘इसमें ऐसे बीज हैं जो इस दुखददहरी धरती को एक ऐसी धरती में बदल देंगे जहाँ न दुख होगा और न यातना होगी।’ कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेताओं की टिप्पणियाँ समर्थन और आलोचना का मिलाजुला रूप थी। मुस्लिम लीग ने तब तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बहुत संतुष्टता बरती और एक अनिश्चित रख दिखलाया जब तक जिन्ना ने एलान नहीं कर दिया कि इस योजना में ‘पाकिस्तान के लिए बुनियाद और आधार प्रदान किया है।’ वामपंथी कांग्रेस के लागा की राय खुलेआम विरोधप्रत्मक थी। फ्री प्रेस जनरल ने इस योजना की भत्तना करते हुए इसे ‘भारत के भविष्य को बिगाड़ने के लिए ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत योजना’ बताया है। कम्युनिस्ट नेता पी० सी० जोशी ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा ‘भारत को अपने उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा आधार बनाए रखने के लिए ब्रिटेन की यह एक साम्राज्यवादी चाल है।’ और इसके जरिए ब्रिटेन स्वाधीनता का कानून पारित होने से रोक रहा है ताकि भारत की जनता हमेशा आपस में लड़ती रहे।’

योजना की घोषणा के बाद लंबी बातचीत का दौर चला। 27 मई को कांग्रेस कायसमिति ने अपना रुख के बारे में एक अंतिम बयान जारी किया। कांग्रेस के प्रस्ताव में अंतिम फ़ैसले को रोक लिया लेकिन कांग्रेस की नीति और योजना में अनेक विरोधी बातें दिखाई दीं जो व्यासतौर से अंतरिम सरकार की अवधि में सैनिक कब्जा बनाए रखने (आजादी न देने की स्थिति में विदेशी आधिपत्य सत्ता की मौजूदगी बराबर बनी रहेगी) संविधान सभा में यूरोपीयों का प्रतिनिधित्व होना, प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण करने प्रांतीय



स्वयत्तता वा उल्लघन करने, रियासतों में जनतन्त्र की कोई गुजाइश न हान तथा प्रस्तावित अन्तरिम सरकार के अधिकारों के सीमित हान के सद्व्यवहार में थी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आधिकारिक समाचारपत्रक ने 1 जून को अपनी आलोचना विस्तार से प्रकाशित की और कहा कि इस योजना के जरिए

माघ 1942 में ही सर्वश्री चर्चिल और एमेरी ने जो कुछ देने की इच्छा जाहिर की थी उससे बेहतर चीज हम नहीं पा सके।

जिस आजादी का वादा किया गया है, उसके चारों तरफ पाबंदियों का ऐसा घेरा डाल रखा गया है कि इसे आजादी नाम देना ही गलत है। तथाकथित संविधानसभा यथाथ में कोई प्रभुसत्तासम्पन्न संस्था नहीं होगी बल्कि वह इसका दिखावा भर होगी। संध और प्रांत दोनों, प्रांतों के कुछ मनमाने वर्गीकरण की दया पर निर्भर रहेंगे। माप्रदायिक आधार पर विभाजित भारत में संभव लगभग सभी दोष इस योजना में हैं। पाकिस्तान के निर्माण की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रांतीय इकाइयों को जो एकरूपता और संप्रभुता प्राप्त हो सकती थी उसकी भी कोई संभावना इसमें नहीं है।

मुद्रा, बैंकिंग चुगी और योजना पर नियंत्रण न होने की वजह से केंद्र सरकार इतनी कमजोर होगी कि वह आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों में देश की आर्थिक प्रगति का दिशा निर्देश नहीं कर सकेगी।

राष्ट्रीय हित माप्रदायिक ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सामंती हितों के मातहत हो गए हैं। केंद्र के साथ भविष्य में रियासतों के क्या संबंध होंगे इसका फैसला राजा साहब करेंगे न कि उनकी जनता

यह योजना न तो आसान है और न जासानी से कार्यान्वित करने योग्य है।

प्रभुसत्ता में इतने बढ़िया ढंग से संघीय केंद्र उपसंघीय समूहों, प्रांतीय यूनिटों और राज्यों के बीच बांट रखा गया है (शाही सरकार की तो बात ही दूर जिसके आदेश संविधान बनने के बाद भी सर्वोपरि होंगे) कि इसकी तलाश हमेशा एक समस्या बनी रहेगी

प्रतिबंध, शर्तों, सुरक्षा उपायों और एक के विरुद्ध दूसरे हितों के संतुलन के इस जंगल में एक मुक्त और स्वाधीन भारत की तस्वीर साफ साफ देख पाना बहुत कठिन है।

जमी तब राष्ट्रपति और सामंती हित, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्त का मुख्य सहारा रहे हैं। उन्हें तथाकथित स्वतंत्र भारत में एक स्थाई और प्रभावकारी विधिप्रताप का रूप में बनाए रखने की कोशिशें यह सदैव पैदा होता है कि ब्रिटिश सरकार अपने पूर्ववर्ती शासकों की परंपरागत नीति त्यागन में असमर्थ है।

24 मई के कांग्रेस प्रस्ताव के अनुसार मंत्रिमंडल मिशन ने 25 मई का एक और वक्तव्य जारी किया तथा सफाई पत्र की। इस वक्तव्य में जय मुद्रा के अलावा यह स्पष्ट किया गया था

- 1 यह योजना अपनी समग्रता के साथ प्रस्तुत है' अर्थात् इस पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार किया जाए।
- 2 प्रांतों को तब तक अपनी पसंद के अनुसार समूहों के चुनाव का अधिकार नहीं हो सकता जब तक एक संविधान की स्थापना न कर दी गई हो, उसे अमल में न लाया गया हो तथा चुनाव न हो गए हों।
- 3 मंत्रिमंडल भारत की प्रमुखता दो शक्तों के अधीन की जाएगी
  - (क) 'अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था'
  - (ख) 'ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि करने पर सहमति जिसके अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न सभी मसले जा जाए।'
- 4 संविधानसभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व के मसले को उनकी सलाह के जरिए ही हल किया जा सकता है और 'यह ऐसा मामला नहीं है जिसपर शिष्टमंडल कोई फैसला ले।'
- 5 अंतरिम सरकार की अवधि में वर्तमान संविधान जारी रहना चाहिए और इसलिए अंतरिम सरकार कानूनी तौर पर केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।
- 6 अंतरिम सरकार की अवधि में सैनिक बर्खास्त जारी रहना चाहिए। इस अवधि में ब्रिटिश संसद पर वर्तमान संविधान के अंतर्गत, भारत की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है और इसलिए यह जरूरी है कि ब्रिटिश सैनिक यहां बने रहें।

संविधानसभा के चुनावों के लिए बाद में जो तैयारियां की गईं उनसे पता चला कि संविधानसभा के सदस्यों को पहले से ही सांविधानिक योजना को स्वीकार और कार्यान्वित करने का संकल्प करना जरूरी था।

योजना के निहितार्थों से इसका वास्तविक चरित्र का और भी स्पष्टता से पता चला कि यह एक थोपा हुआ फैसला है और कांग्रेस तथा वामपंथी राष्ट्रीय विचारधारा के उल्लेखनीय हिस्सा में इस योजना के प्रति जबरदस्त विरोध की भावना पैदा हुई।

6 जून को मुस्लिम लीग ने अपना यह वचन दुहरात हुए कि 'पूर्ण प्रभुसत्तामयन पाकिस्तान की स्थापना ही अब भी भारत के मुसलमानों का अटल उद्देश्य है', यह एलान किया कि जब तक इस योजना में पाकिस्तान की बुनियाद और इसका आधार निहित है, मुस्लिम लीग दीर्घकालिक और अंतरिम दोनों प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार करती है।

अंतरिम सरकार के संविधान के लिए बातचीत शुरू हो गई और इसके लिए अल्पसंख्यकों के मुख्य प्रतिनिधियों के रूप में कांग्रेस और लीग के मिलेजुले प्रतिनिधित्व को आधार बनाया गया। इन समझौता वार्ताओं से वे संघर्ष और मतभेद तत्क्षण सामने आ गए जो व्यवहार में योजना के कार्यान्वयन के लिए हर कदम पर निरंतर थे। अंतरिम सरकार के संघटन के बारे में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। समझौता होने की स्थिति में ब्रिटिश शासक ने एक बार फिर वचन भंग किया और 16 जून के निर्णय की घोषणा की। अंतरिम सरकार के प्रस्तावित संघटन की घोषणा कांग्रेस के 5 प्रतिनिधियों (सभी हिंदू और कोई भी मुसलमान कांग्रेसी नहीं), मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों तथा अल्पसंख्यकों के 4 प्रतिनिधियों (सिख, इसाई, हरिजन और पारसी) साथ में कांग्रेस का एक अतिरिक्त घूस कि हरिजन एक कांग्रेसी हरिजन है इस प्रकार कांग्रेस को 6 सीटें देकर) के आधार पर की गई थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार में शामिल होने का 'आधार यह होगा कि संविधान बनाने का काम 15 मई के वचन के अनुसार होगा।'

अंतरिम सरकार ने इस प्रस्तावित संघटन का काफी विरोध हुआ, खासतौर से मुसलमान कांग्रेसी को अलग रखने के सद्भ में जिसके कारण कांग्रेस एक हिंदू संस्था बनकर रह जाती थी। 24 जून को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार की योजना को नामजूर करने की घोषणा की लेकिन इसका अनुसरण उसने संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार करके किया। कांग्रेस कायसमिति के 26 जून के प्रस्ताव में कैबिनेट मिशन की 'खामियों' पर जोर दिया गया था 'फौरन आजादी' और सामाजिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की कांग्रेस की नीति को दुहराया गया तथा एलान किया गया कि इस योजना में इन लक्ष्यों का अभाव है। कांग्रेस के प्रस्ताव में योजना को स्वीकार करने की घोषणा नहीं की गई बल्कि एक 'स्वतंत्र संयुक्त और जनतांत्रिक भारत का संविधान बनाने के उद्देश्य से' प्रस्तावित संविधानसभा में शामिल होने का फैसला लिया गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे इसमें अपनी व्याख्या और कानूनी सलाह के साथ शामिल होंगे तथा वे प्राप्ति का अनिवार्य वर्गीकरण नहीं स्वीकार करेंगे।

इस घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन और वायसरॉय ने एलान किया कि अस्थाई राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सिलसिले में जब तक आगे बातचीत नहीं होती है, अधिकारियों की एक अंतरिम प्रभारी सरकार बना ली जाए।

29 जून का कैबिनेट मिशन भारत से खाना हो गया।

दुनिया के सामने 1946 की नई साविधानिक योजना को भारत की आजादी की योजना के रूप में पेश किया गया था। तो भी इसकी धाराओं की जाच-पड़ताल करें ता यही निष्कर्ष निकलेगा कि वस्तुतः 1942 की त्रिप्स योजना को ही दुहराया गया था और भारत को आजादी देने से या जनतांत्रिक ढंग से चुने गए जनप्रतिनिधियों को अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने के अधिकार से उसका कोई संबंध न था।

यह योजना निस्संदेह ब्रिटिश नीति को भारत की नई स्थिति के अनुरूप ढालने की निपुण कोशिश थी। मुख्य प्रस्तावों का उद्देश्य उस गतिरोध को तोड़ना था जिसने पूर्ववर्ती वर्षों में भारत में किसी तरह के साविधानिक विकास को रोक रखा था हालांकि इस व्यवस्था का स्वरूप भी वैसा ही था जिसमें आने वाले दिनों में अनक नए गतिरोधों की संभावना शामिल थी। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मिलने वाले सभावित समयन और सहयोग के लिए आधार प्रस्तुत किया। इसने भावी स्वतंत्रता का एक काल्पनिक प्रस्ताव सामने रखा। इसने मुख्य पार्टियों पर आधारित अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया। ये प्रस्ताव 1942 के त्रिप्स प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1935 के संघीय संविधान से संबंधित प्रस्ताव की नीतियों की तुलना में बहुत थोड़ा आगे थे। लेकिन इस योजना की सीमाएँ काफी स्पष्ट थीं।

पहली बात तो यह है कि डोमोनियन का दर्जा और आजादी के प्रस्तावों में से कोई एक चुनने की बात थी जो भारत की आजादी की तात्कालिक घोषणा से काफी अलग थी। देश के सभी राजनीतिक संगठन बिना किसी अपवाद के यह मांग कर रहे थे कि आजादी की फौरन घोषणा की जाए। दरअसल आजादी से संबंधित मामले को एक ऐसी अतिनिधि सभा के ऊपर फैसले के लिए छोड़ दिया गया था जिसका गठन और जिसकी कार्यपद्धति का निर्धारण ब्रिटेन के नियंत्रण द्वारा हुआ था और जिसका हस्तान हमेशा प्रतिक्रियावादी दिशा की ओर रहता था।

दूसरी बात यह है कि संविधान के जनतांत्रिक चयन के लिए किसी अनिवार्य आधार की बात नामजूर की गई थी अर्थात् व्यापक मतदान पर आधारित जनतांत्रिक संविधान सभा के चुनाव को महज इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह काम जल्दी होना है। संविधानसभा का गठन अजनतांत्रिक था क्योंकि इसमें सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ा था इसका गठन विधानसभाओं व अल्पसंख्यक निर्वाचन से हुआ था और यह निर्वाचन जिस निर्वाचनमंडल पर आधारित था वह आजादी के महज 11 प्रतिशत लोगों को तय करता था। इन सारी बातों के अलावा इस संविधानसभा में राजाओं के 93 नामजद सदस्य थे जो कुल सदस्यों का एक चौथाई हिस्सा था।

तीसरी बात यह है कि राजाओं के क्षेत्र में जनतंत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और भारत का एक तिहाई हिस्सा इन राजाओं के अधिकार में था। राजाओं के साथ प्रबंध की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वच्छिक बातचीत पर छोड़ दी गई थी। इनमें वे मामले भी शामिल थे जिनका संबंध संविधानसभा में उनसे प्रतिनिधित्व से था। इन रियासतों पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया था। इतना ही नहीं ब्रिटेन की सर्वोच्चता समाप्त होने तक यदि बीच के समय में राजाओं की सहमति से कोई समझौता नहीं हो पाता तो वे वैधानिक और राजनयिक रूप से स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न प्रदेश बन जाते।

चौथी बात यह है कि इस योजना ने भारत को चार क्षेत्रों में बांट दिया, एक हिंदूबहुल क्षेत्र दो मुस्लिमबहुल क्षेत्र और चौथा राजाओं की रियासतोंवाला क्षेत्र। इस बंटवारे के बारे में एकदम एकतरफा निर्णय लिया गया और इन इलाकों में रहने वाले लोगों से सलाह-मशविरा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बंटवारे का आत्मनिर्णय के किसी सिद्धांत से कोई संबंध नहीं था।

पांचवीं बात यह है कि इस बंटवारे के आधार पर केंद्र की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती थी और उसके अधिकार बहुत सीमित हो जाते थे। विशेष रूप से इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे भारत के आधार पर आर्थिक योजना तैयार करने या सामाजिक कानून निर्धारित करने के लिए कोई अधिकार नहीं बच रहता था। किसी समाज के प्रगतिशील जनतांत्रिक विकास के लिए तथा व्यापक आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक स्तर के उत्थान के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं।

छठी बात यह है कि इस अंतरिम अवधि के दौरान सत्ता के हस्तांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं था, पुराने संविधान को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी और अंतरिम सरकार वायसराय की परिपद का महज एक पुनर्गठित स्वरूप थी जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर वीटो का अधिकार था और सर्वोच्च सत्ता थी।

सातवीं बात यह है कि इस अनिश्चित अंतरिम अवधि के दौरान ब्रिटिश सेना का अधिकार बनाए रखने की बात कही गई थी ताकि नए संविधान के निर्माण का काम सेना की देखरेख में हो सके।

आठवीं बात यह है कि संविधानसभा को प्रभुसत्ता संपन्न नहीं माना गया था। इसके द्वारा तैयार किया गया नया संविधान तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उसे ब्रिटेन की स्वीकृति न मिल जाए और ब्रिटेन की यह स्वीकृति दो शर्तों के पूरी होने पर निभर करती थी, अंगरेज शासक का इस बात के प्रति सतुष्ट हो जाना कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तथा भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली संधि को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त

व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की प्रभुसत्ता प्रदान करने से पूर्व इन बातों का पूरा होना जरूरी है।

यह योजना निश्चित रूप से एक ऐसे प्रयास की जानकारी देती है जो भारत में उच्चवर्ग के नतुत्व व साथ तालमेल बैठाना का आधार बूझ रहा हो। सांविधानिक समझौता के साथ साथ इस बात के लिए पूरा प्रयास किए जा रहे थे कि ब्रिटन और भारत के बड़े पूंजीपतियों के बीच घनिष्ठ संबंध कायम कराया जा सके (विडला यूफील्ड और टाटा-आई० सी० आइ० समझौता आदि) जिसकी समीक्षा पहले ही छठे अध्याय में की जा चुकी है।

इन बड़े पूंजीपतियों के बीच गठबंधन कायम करने की कामिनी भारत की आंतरिक स्थिति के सदम में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के सदम में भी काफी महत्वपूर्ण है। उच्चवर्ग के नतुत्व और जबरदस्त प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक राजाओं की महत्व देकर तथा इनके साथ गठबंधन के आधार पर भारत में किसी समझौते को बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता की उभरती हुई ताकत को रोका जा सके और ब्रिटिश हिता की रक्षा की जा सके तथा इस प्रकार भारत की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ उस एक ऐसे सैनिक अड्डे के रूप में बनाए रखा जा सके जो ब्रिटन की अंतर्राष्ट्रीय नीति के सदम में भारत का ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोगी बना दे। भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपनी बातचीत चलाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नीति में भी रणनीति विचार करें तो ब्रिटिश नीति का यह पहलू और भी गंभीर प्रतीत होगा। जिन दिनों बातचीत चल रही थी, भारत में सोवियतविरोधी दुष्प्रचार बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा था। आजादी की बातचीत के साथ साथ सैनिक और सामरिक तैयारियां भी काफी जबरदस्त ढंग से की जा रही थी।

केंद्रीय विधानसभा में एक प्रश्न के दौरान जब यह मांग की गई कि दस वर्षों के अंदर भारतीय सेना का भारतीयकरण हो जाना चाहिए तो इसके जवाब में सेना के कमांडर इन चीफ ने कहा कि इस काम के लिए काई समय नहीं निर्धारित किया जा सकता और भारतीयकरण के काम में वीस या इससे भी अधिक वर्ष लग सकते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा नीति संबंधी वक्तव्य जारी करने के फौरन बाद फील्ड मार्शल माटोमरी रणनीति से संबंधित विशेष मसलो पर विचार विमर्श के लिए भारत खाना हुए। जाहिर है कि कैबिनेट मिशन की योजना के साथ साथ नीति से संबंधित यह पहलू भावी भारत के लिए बहुत गंभीर परिणामों को अपने अंदर समेटे हुए था हालांकि उन दिनों इन बातों पर जनता ने कम ध्यान दिया था।

इन बातों के सामान्य निष्कर्ष अपरिहार्य है। 1946 की सांविधानिक योजना में भारतीय राजनीतिक जीवन के विभिन्न तत्वों को व्यापक रूप से संतुलित रखने का वही पुराना

तरीका अख्तियार किया गया था। इसमें खासतौर से एक ऐसी राजनीतिक स्थिति के निर्माण की कोशिश थी जो सांप्रदायिक द्वेष पर आधारित हो। इसमें मुस्लिम लीग के भुलावले कांग्रेस को संतुलित रचने की कोशिश की गई थी और राजाओं को एक ऐसी प्रतिक्रियावादी धुरी के रूप में स्थापित किया गया था जो व्यवहार में भारत को आजादी देने के तत्पाकयित प्रस्ताव को व्यर्थ कर दे और अंतिम तथा कारगर नियंत्रण उनके हाथों में बना रहने दें। नाज़ुक और अनिश्चित अंतरिम अवधि में ब्रिटन का नियंत्रण बने रहने की व्यवस्था थी और इस बात की भी व्यवस्था थी कि वह भावी संविधान के समूचे स्वरूप को अपने अनुसार ढाल सके। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अभी तक भारतीय जनता के हक में सत्तात्याग नहीं किया था और भारत की जनता को सत्ता नहीं सौंपी थी। इसका बजाय उसने अपनी सारी चतुराई और सदिया पुराने राजनीतिक अनुभव का पूरा पूरा इस्तेमाल इस काम के लिए किया कि वह एक ऐसे व्यापक ब्रिटन और दुम्ह शासनक्षेत्र की स्थापना कर सके जिसके जरिए भारत को विधिवत 'आजादी' देने का नाटक रचने के साथ-साथ वहाँ के आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखा जा सके। कैप्टिनट मिशन की घोषणा के बाद समझौता वार्ताओं का लंबा सिलसिला 1946 की गरमियों तक चला और इस समय तक भारतीय जनमत बड़ी तजी से यह समझ चुका था कि अंतिम तौर पर भारत की आजादी के लिए अभी आने वाले दिनों में संघर्ष चलाने होंगे।





खण्ड छ  
निष्कर्ष



किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्र की प्रगति की कोई सीमा निर्धारित करे। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने देश से कहें हम इस सीमा तक बढ़ा, इससे आगे नहीं—पारनेल

एक शताब्दी पूर्व मकाले ने भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में कहा था कि वह एक 'महान और अति विशाल काम' में लगा है और यह काम है 'एक सड़े-गले समाज के पुनर्निर्माण का काम'। मकाले ने बीस दिनों के भारत का महज एक ऐसे 'अरक्षित' साम्राज्य के रूप में देखा था जिनपर तभी से एक के बाद एक अलार्क्स और अट्टिलास का राज्यारोहण होता गया था लेकिन अपने जमान के आत्मतुष्ट आशावाद के कारण वह यह जान ही नहीं पाए कि उन दिनों भारत में ब्रिटिश शासन अलार्क्स और अट्टिलास की तुलना में कहीं अधिक तभी से प्राचीन भारतीय समाज को सड़ाने में लगा था, वह कहीं अधिक ताकत से सदियों से चली आ रही भारतीय जीवन-पद्धति का और भारतीयों के समूचे पुराने आधार को नष्ट करने में लगा था।<sup>1</sup>

आज यह तस्वीर उलटी हो गई है। आज खुद साम्राज्यवाद ही सड़ान की स्थिति में आ चुका है और फासिज्म के हाल के अनुभव ने एक ऐसे सड़े गले समाज के चमत्कारिक दृश्य को बहुत साफ साफ दिखा दिया है जो यूरोपीय संस्कृति को पैरों तले रौंदत हुए 'अलार्क्स' और 'अट्टिलास' के तीव्र राज्यारोहण के दुःस्वप्न से मत्तस्त है।<sup>2</sup> साम्राज्यवाद, फासीवाद और प्रतिनिधायवाद के विरुद्ध मुक्ति की दिशा में विश्व की जनता काफी प्रगति कर चुकी

है और इस विकास यात्रा में शामिल होकर अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता तेजी से आगे आ रही है।

## 1 ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन

भारत पर स्याई तौर पर तानाशाही हुकूमत बनाए रखने के पुराने मसूवे अब धूल में मिल चुके हैं। मौजूदा हालात में साम्राज्यवाद अधिक से अधिक यही उम्मीद कर सकता है कि वह नए राजनीतिक ढांचों की आड़ में अपने को इस तरह ढाल ले कि साम्राज्यवादी विशेषाधिकारों और शोषण का जारी रखा जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले पचास वर्षों में सांविधानिक सुधारों की भरमार के साथ साथ लगातार और कभी कभी बहुत तीव्र दमनचक्र चलाया गया। यहां तक कि 1946 में 'आजादी' के विधिवत प्रस्ताव के जरिए जब इस नाटक की चरम परिणति हुई तब भी साम्राज्यवादी शासन भारत में समाप्त नहीं हुआ। यह नए राजनीतिक ढांचे के अनुरूप सांविधानिक तौर पर अपना रूपांतर करने की तमाम कोशिशों की अंतिम कड़ी साबित हुआ। वे दिन अब बीत गए जब कट्टर दक्षिणपंथी तत्व भारतीय समस्या के सहज समाधान के लिए सख्त कर्म उठाने की दुहाई देते थे। वे आज उन बीत हुए सुखद दिनों की याद में आह भर रहे हैं और उन दिनों के लौट आने के लिए तरस रहे हैं जब इन काले कलूटों को (लाट साल्सबरी ने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य को यही कहा था) बतला दिया गया था कि उनकी जीकात क्या है, और अब वे अपने छोए हुए अधिराज्य की याद में भावुकतापूर्ण शाकगीत लिखने में लगे हुए हैं। व आज भी यही सोचते होंगे कि पश्चिम की अमंगल मस्थाओं को शाश्वत रूप की कृतघ्न धरती में स्थानांतरित करने के लिए सर्वोत्तम समुचित राजनीतिज्ञों को सुधारने के जोश के कारण ही हम 'भारतीय प्रदेश' से हाथ धो बैठे (मेरा ख्याल है कि ड्यूक ऑफ वेल्सिंगटन ने एक बार कहा था 'यदि भारत कभी हमारे हाथ से गया तो इसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर होगी जिसकी वजह से भारत का खोएगा' लाड कोमर, एंशेट ऐंड माइन इपीरियलिज्म पृष्ठ 126)। लेकिन 19वीं सदी के प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए एक सरलीकृत समाधान के रूप में जिस जबरदस्त दमन का सहारा लिया गया वह ब्रिटिश फासीवाद के शौश्रवकाल वाले इस आधुनिक युग में एक कार्यक्रम के रूप में खुलकर सामने आ सका।<sup>3</sup>

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यवहारकुशल राजनीतिज्ञों ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि महज दमन का तरीका इस्तेमाल करना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ साथ राजनीतिक दावपेच के अधिकाधिक नए तरीकों की भी जरूरत है।

राष्ट्रीय विद्रोह के खिलाफ एक परकोटा तैयार करने की चूठी आशा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रेरणा उग्र सुधारवादी लाड रिपन ने नहीं बल्कि लिबरल यूनिवर्सिटी और अनुभवों परेश्वर बूटनीतिज्ञ लाड डफरिन ने दी थी। उग्र सुधारवादी लाड मॉर्ले ने नहीं बल्कि टोरी पार्टी के लाड मिंटो ने राष्ट्रीय आंदोलन की सचाई का

मौके पर सामना किया था और 1900 के सुआरा के साथ मोर्चे की तुलना में वामपंथ से और भी दूर जाने की कोशिश की और ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने इसे स्वीकार करने की तत्परता दिखाई। लिबरल नेता माटेगु ने नहीं बल्कि उग्र कजरवेटिव नेता कजन तथा जास्टिन चवरलन ने 1917 में जिम्मेदार सरकार की स्थापना के वादे वाली सरकारी घोषणा तैयार की ताकि रूसी क्रांति के बाद आई क्रांतिकारी लहर की चुनौतियाँ का मुकाबला किया जा सके। यह ठीक वैसे ही था जैसे मिलनर किडरगार्टन के 'गोलमेज ग्रुप' के शिष्यों ने जमल में लाने के लिए बड़ी खूबी के साथ 'द्विशासन' की अव्यवहार्य योजना तैयार की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को और संघीय संविधान को वाल्डविन की कजरवेटिव सरकार ने सविस्तार प्रतिपादित किया था न कि दोनों में से किसी एक लेबर सरकार ने।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में पुरुष में जितना कजरवेटिव पार्टों की प्रेरणा और दिशा-निर्देशन में भारत में सांविधानिक सुधारों के जितने भी कदम उठाए गए उनके पीछे का यह मोह नहीं था कि सचमुच ही सुधार किया जाए बल्कि इन सारकदमों के पीछे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बाढ़ को रोकने के लिए एक बाध तैयार करने की हताशापूर्ण कोशिश थी। और यह भी कहा जा सकता है कि लेबर सरकार के 1946 के सांविधानिक प्रस्तावों के जरिए भी 1942 की उस योजना में निहित आम नीतियों को ही आगे बढ़ाया गया जिसे विदेशमंत्री एमेरी और टोरी बहुमतवाले मंत्रिमंडल के तहत तैयार किया गया था।

राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की बाढ़ को रोकने के लिए एक के बाद एक बाध बनाकर और अस्थाई समझौतेवाले समाधानों तथा सत्रमणकालीन अवस्थाओं के लंबे सिलसिले के जरिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नेताओं ने अपना गृष्ठीरक्षक युद्ध जीतने की जाशा की है। उन्होंने नए राजनीतिक ढांचे के अनुरूप अपने को ढालने की प्रक्रिया पर अमल करने की जी जान से कोशिश की है। इसके ही जरिए वे भारत का शोषण करके अपना आर्थिक और वित्तीय हितों को और भारत पर अपने सैनिक प्रभुत्व को सभी अवधि तक बनाए रखने को आज भी कोशिश कर रहे हैं। वे जनता को व्यवस्था के तहत रखने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग का आधार बनाए रखने का काम धीरे-धीरे भारतीयों के हाथों में सौंपते जा रहे हैं।

लेकिन क्या वे इसमें सफल हो सकते हैं ?

यदि यह मान लिया जाए कि समस्या का जड़ वस्तुतः समाधान हो गया है और भारत में साम्राज्यवादी शासन की शर्तें निर्धारित हो चुकी हैं तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अतिपुष्टन कूटनीतिज्ञों ने आजकल इस तरह के वक्तव्य देने शुरू कर दिए हैं कि भारत से अगर जड़ जड़ जा रहा है तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद न बिना मरपट के

अपना प्रभुत्व समाप्त कर दिया और वह भारत में हाराकिरी करने को तत्पर है। लेकिन इन वक्तव्यों के फलस्वरूप जो भ्रम पैदा होगा उससे बड़ा भ्रम कोई नहीं हो सकता।

ब्रिटिश बुर्जुआ हिता के लिए भारत पर ब्रिटन का प्रभुत्व बना रहना कितना आवश्यक है इसे काफी पहले ही माना जा चुका है। साम्राज्यवाद के पतन के युग में जब विश्व बाजार में ब्रिटन का एकाधिकार लड़खड़ा रहा था और ब्रिटिश उद्योगधंधा की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, जब जगरेजा के डोमिनियन की आर्थिक और राजनीतिक स्वाधीनता बढ़ रही थी, ब्रिटन के सत्ताधारी वर्ग के लिए भारत पर एकाधिकारी प्रभुत्व को और उपनिवेशवादी शासन को न केवल बनाए रखना ही बल्कि इसका और अधिक विस्तार करना ज्यादा जरूरी हो गया। चर्चिल ने 1933 में इस बात को बड़े ज़ारदार शब्दों में कहा था। इन सारे वर्षों में चर्चिल भारत में ब्रिटन के साम्राज्यवादी हितों के सबसे उग्र और हठधर्मी प्रवक्ता थे।

ब्रिटन के लोगों की खुशहाली के लिए भारत का बहुत महत्व है और जब मैं यह देखता हूँ कि वे शक्तिशाली जिनपर हमारे देश की जनता काफी हद तक निर्भर करती है धीरे धीरे समाप्त हो रही है तो मुझे बहुत चिंता होती है। विदेशी पूँजी-निवेश में धीरे धीरे कमी आती जा रही है और नौपरिवहन की स्थिति में भी काफी गिरावट आ गई है। इन नुकसानों के साथ यदि हम किसी न किसी रूप में भारत का खो देते हैं तो यहाँ ऐसी समस्याएँ पैदा हो जाएंगी जैसी पहले कभी देखने में नहीं आई। फिर यहाँ अतिरिक्त जावादी का ऐसा बोझ बढ़ सकता है जिसका भरण-पोषण करना सरकार के लिए काफी कठिन हो सकता है।

(विस्टन चर्चिल का एपिंग में भाषण, 8 जुलाई 1933)

भारत में साम्राज्यवादी हितों का निमग्नतापूर्वक दावा करने वाली यह पुनर्जनन विचारधारा सुधारों और रियायतों के दौर में निरंतर जारी रही। उन बलों और सुपरिचित घापणाओं का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है जैसी अमृतसर कांड के समय पंजाब के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर माइकेल जो डायर ने की थी, उन्होंने उस कृतव्य की दुहाई दी थी जो ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में रहने वाले जगरेजा भाई बंधुओं और भारत में लगी हजारों लाइनों की ब्रिटिश पूँजी के प्रति है (सोसायटी आफ आर्यम में भाषण जिसे लॉर्ड ओलिवर ने 12 मार्च 1925 के 'मैनचेस्टर गार्जियन' में उद्धृत किया था) या जो लॉर्ड रोथेरीमीयर ने 16 मई 1930 के 'डेली मेल' में की थी कि 'जनेक अधिकारियों का अनुमान है कि ब्रिटन का महत्वपूर्ण व्यापार, बैंकिंग और नौपरिवहन व्यवस्था का जो अंश प्रत्यक्षतः भारत के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर है वह 20 प्रतिशत है भारत ब्रिटिश साम्राज्य का ठोस आधार है। यदि हम भारत का खो देते हैं तो यह निश्चित है कि ब्रिटिश साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा पहले आर्थिक रूप से फिर राजनीतिक रूप से।

तमाम नूट गैतिक मापना अनिशचित और अस्पष्ट था तथा अनिच्छापूर्णक दी गई रियायत व जरिए हम आज भी यह पता लगा सके हैं कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व को बनाए रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और इस हम हर निर्णायक वक्तव्य में देख सकते हैं। अगस्त 1922 में लायड जूज की 'स्टील फ्रेम स्पीच' का महत्व यही था कि ब्रिटेन किसी भी हालत में भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं त्यागेगा और वह ऐसा कोई दौर देख पाए जब भारत अपने को ब्रिटेन के दिशा-निर्देशन से अलग कर सके। 1929 में बर्केंहड की चेतावनी का यही महत्व था कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी ऐसी तथ्य का अनुमान नहीं लगा सकता जब हम भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करते देखें। 1930 में चर्चिल ने जा चेतावनी दी थी उसका भी यही महत्व था कि 'ब्रिटेन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह भारतीय जनता के जीवन और प्रगति पर में अपना प्रभावकारी नियंत्रण समाप्त कर दे।' 1935 के संविधान का उद्देश्य बताते हुए चाल्डविन ने जो व्याख्या प्रस्तुत की थी उसका भी यही महत्व था कि ग्रेट ब्रिटेन और भारत की एकता को मजबूत करने वाले बंधन को कमजोर बनाने पर विचार करना तो दूर की बात है, हम चाहते हैं कि अब यह एकता इतनी प्रगाढ़ हो जाए जितनी पहल कभी नहीं थी।

इधर हाल के वर्षों में अब भाषा बदल गई है। सरकारी बयानों में अब भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की लंबी सूची का जिक्र नहीं किया जाता। उल्टे सरकारी बयानों में अब यह कहा जाता है कि ब्रिटेन अब पूरी तरह भारत पर से अपना शासन समाप्त कर लेगा और भारत को 'पूरी आजादी' दे देगा। लेकिन पिछले अध्याय में हमने 1946 के सांविधानिक प्रस्तावों की जो जांच पड़ताल की है उससे यही पता चलता है कि इन प्रस्तावों को आजादी मान लेना असंभव है।

हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवादी शासन की वास्तविकताएँ वरकरार हैं लेकिन अंगरेजों ने 'आजादी' और साम्राज्यवाद की समाप्ति की बातें खूब बढ़चढ़कर शुरू कर दी हैं। साम्राज्यवादी नीति और प्रचार ने इधर हाल में जो पैतरा बदला है उससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम आधुनिक साम्राज्यवाद के विकास पर विस्तार से विचार करना होगा तथा भारत पर नजर डालनी होगी। साम्राज्यवादियों ने इधर एकदम हाल के वर्षों में एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है और इसका दिनोदिन खूब प्रचार तथा इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को 'जोष-चारित्र्य आजादी' देने की तकनीक कहा जा सकता है। सिद्धांत रूप में यह अपने आप में कोई नई चीज नहीं है। दरअसल यह प्रच्छन्न शासन के उस पुराने सिद्धांत की ही जारी रखना है जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रारंभिक दिनों की छायी बात थी, लेकिन आधुनिक युग में इसका और विस्तार किया गया है तथा इसे और परिष्कृत ढंग से प्रतिपादित किया गया है ताकि राष्ट्रीय भुक्ति आंदोलन को बढती हुई ताकत का मुकाबला किया जा सके।

इस तकनीक का बड़ी खूबी के साथ 1922 में मित्र के मामलों में देखा गया। स्मरणीय है कि 28 फरवरी 1922 को प्रकाशित ब्रिटिश का एक नीति संबंधी दस्तावेज के तहत मित्र को आजादी दी गई थी। लेकिन इस घोषणा में कहा गया था कि कुछ विषयों पर तब तक ब्रिटेन की महामहिम सरकार को फैसला लेने का पूरा पूरा अधिकार होगा जब तक उन विषयों के विनियमन के लिए ब्रिटेन और मित्र की सरकारों के बीच कोई मधि नहीं हो जाती। इन खास खास विषयों में निम्न बातें शामिल थीं

- 1 मित्र में ब्रिटिश साम्राज्य की संचार व्यवस्था की सुरक्षा,
- 2 मित्र की प्रतिरक्षा,
- 3 मित्र में विदेशी हितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षण,
- 4 सूडान,
- 5 अन्य देशों के साथ मित्र के संबंध।

इन शर्तों को मित्र के राष्ट्रीय आंदोलन ने मान्यता देकर दिया। फिर भी मित्र को आजादी देने की घोषणा की गई, फुआद को राजा बनाया गया और एक उपयुक्त प्रधानमंत्री का चयन किया गया। 1923 के अगस्त तक मित्र में ब्रिटिश मासल ला लागू रहा। इस तरह मित्र एक 'आजाद' देश बन गया।

मित्र से ब्रिटिश सैनिकों को हटाने का मुसला 24 वर्ष बाद तक भी तय नहीं हो सका था और 1946 में भी ब्रिटेन और मित्र की सरकारों के बीच इस विषय पर बातचीत चल रही थी। तब से आज तक 'आजादी' देने की साम्राज्यवादियों की इस नई तकनीक को और भी विस्तार दिया गया है और लागू किया गया है। इसे हम ईराक तथा अन्य देशों के मामले में देख सकते हैं।

इस प्रकार भारत में इस तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले इस काफी अच्छी तरह आजमा लिया गया था। जाहिर है कि औपचारिक 'आजादी' देने की इस तकनीक का उस मांग से कोई साम्य नहीं है जो भारतीय जनता आजादी के लिए कर रही है। साम्राज्यवाद ने अभी तक अपनी जकड़ ढीली नहीं की है। संघर्ष अब भी जारी है।

लेकिन क्या साम्राज्यवादी शासक अपना प्रभुत्व बनाए रख सकते हैं? यह अलग बात है। क्या वे उन उदीयमान युगांतरकारी शक्तियों पर काबू पा सकते हैं जो भारत में तेजी से विकसित हो रही हैं? क्या वे भारत के जबरदस्त मुक्ति आंदोलन को रोकने के लिए नए स्वरूपों और सामाजिक आधार का सहारा प्राप्त कर सकते हैं ताकि साम्राज्यवादी घोषणा को बनाए रखने के लिए वे परिवर्तन की इस प्रक्रिया को बाधकर रख सकें? इस सवाल के जवाब पर ही भारत में साम्राज्यवाद के भविष्य का सवाल टिका हुआ है न कि



चमचमान साविधानिक सुधारों पर जो कि अत्यंत जटिलतापूर्वक राजनीतिक अभियानों की एक सावजनिक सूची मात ह ।

दरअसल बात यह है कि पुराना भारत अब नष्ट हो चुका है और वह अब कभी अस्तित्व में नहीं जाएगा । पिछले डेढ़ सौ वर्षों में पूँजीवाद की निमम घुसपैठ के कारण पुरानी समाजव्यवस्था की बुनियाद ध्वस्त हो चुकी है जिसकी वजह से परिवर्तन की सक्रिय शक्तिया गतिशील हो चुकी है और उन्होंने ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है जिस अब रोकना नहीं जा सकता । पुरानी बुनियादों के ध्वस्त होने के साथ ही अपसाकृत धीरे धीरे, पर पूरी अनिवायता के साथ पुराने दृष्टिकोण और सामाजिक रूढ़िवादिता के विश्वास, पुराने संप्रदाय और पुराने अवरोध नष्ट होते जा रहे हैं ।

जमशेदपुर के इस्पात कारखानों में या बंबई के शेयर बाजार में जाति की क्या भूमिका है ? अपनी जमीन से वेदखल किए गए ग्रामीण सवहारा की बढ़ती हुई तादाद में (जो गांव की कुल आबादी के 1/3 से 1/2 भाग तक है) संयुक्त परिवार प्रणाली कौन सी भूमिका अदा कर सकती है ? बुजुर्ग संपत्ति सबंध का क्षयकारी तेजाब रीति रिवाजों और पद पर निर्मित सामाजिक संस्थाओं के तानेबाने का उत्तनी ही कठोरता से खाता जा रहा है जितनी कठोरता से ब्रिटेन या जापान में बन ससत मशीनी सामान लाखों हस्त-कर्मियों की मुसीबत में डालते जा रहे हैं और उन्हें दान दान का मोहताज बना रहे हैं ।

भारत आज भी कालदोष की धरती है । यहां आज भी सामंती और अधमामती अवशेष मौजूद हैं दुराचारी रजवाड़ों का अस्तित्व है, बेगार प्रथा कायम है, मादरकारा, तारघरा और वायरलस के साथ साथ कृपिदास प्रथा भी जारी है । पुरातन मंदिर हैं जिनमें अति-प्राचीन यथीय अनुष्ठा हो रहे हैं और पास में ही आधुनिक गंदी बस्तिया हैं । आधार तो गायब हो चुका है पर इस आधार पर वन ऊपरी ढांचे का भूत अब भी छाया हुआ है । साम्राज्यवाद के मृत हाथ समूच तानबाने को एक म्यगित प्राणसंचारण और जबरदस्त विकास की स्थिति में पकड़े हुए हैं और उनकी कोशिश महज यह है कि समाज की शक्तियों को भीतर से पुनर्जीवित किए बिना वे अपना शोषण प्रणाली को ऊपर से थोप दें ।

लेकिन 20वीं सदी के रूस के पुराने जारशाही दिनों की ही तरह यह केवल एक खोल है जो स्पष्ट मात्र से टुकड़े टुकड़े हो सकता है । साम्राज्यवादी पतन के दिनों के पश्चिमी दशा के रोमानी बुद्धिजीवी, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता के विकास से पैदा अपने दुखा से छुटकारा और शांति पान की कोशिश में पुण्यदेश रूस के घिनौने सुअरवाड़े का बिरतन आध्यात्मिक मूल्या का तीर्थस्थल माना और जनतंत्र तथा समाज की आधुनिक धाराओं से अछूते कल्पित विनीत तथा श्रद्धालु किसानों की भूमि माना, एक साश की आराधना में तन थ और जीवन की प्रचुर शक्ति तथा उस वास्तविक जनता की चेतना के प्रति अंधे थे ।

जा उसकी मृगमरीचिका ता धूल में मिला देन के लिए तैयार बैठी थी। इसी प्रकार आज पश्चिम दक्ष का कोई डोंगी यात्री, जो भारत में स्मरणानीत पूव क दशन करने जाता है, वह चाह पूवदशीय उच्च आध्यात्मिक विचारों के कीचड़ में से अपनी प्यास बुझा रहा हो या एक सरक्षक की तिरस्कार नरी मुद्रा में 'भारत माता' के पिछड़ेपन का भडाफाड कर रहा हो वह महज मध्ययुगीन कवाले के संग्रहालय के दशन कर रहा है और भारतीय जनता की जीवन शक्तियाँ की ओर से आगे मूढ हुए हैं।

भारतीय जनता की प्रगामी शक्तियाँ आज जिस संघर्ष का नेतृत्व कर रही हैं वह जात पात, निरक्षरता, जड़ों के अपमान सांप्रदायिक भेदभाव, महिलाओं के गुलामी की जजोर में जकट रहने तथा उन सभी चीजों का खिलाफ हैं जो जनता को पिछड़ेपन का शिकार बनाती हैं। जहाँ एक ओर पुराकालीन हिंदू सभ्यता और इसकी अपरिवर्तनशील विशिष्टताओं पर विद्वत्तापूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं वहीं निर्विवाद रूप से भारतीय जनता के जहुमत का समर्थन प्राप्त यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी ध्वजा पर सावभौम समान नागरिकता का पूर्ण जनतात्मिक कार्यक्रम चकित कर दिया है। इस कार्यक्रम में जाति, धर्म या लिंग का कोई भेद नहीं करता गया है सभी विशेषाधिकारों और पद्धतियों को समाप्त करने की बात है, व्यापक वालिग मताधिकार और निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की योजना है, धर्म के मामले में राज्य के तटस्थ रहने की घोषणा है तथा भाषण करने, समाचारपत्रों के प्रकाशन विचारों की अभिव्यक्ति, सभा करने तथा संगठन बनाने पर छूट है जो ब्रिटिश के अधजनतंत्र से काफी आगे है।

1936 के उत्तराध में उदारवादी पत्र मैनेचेस्टर गार्जियन ने 'दि फर्मेट इन इंडिया' नामक लेख में मजबूरन यह स्वीकार किया कि भारत में नाति की शलक भिन्ननी शुरू हो गई है जो राजनीतिक राष्ट्रवाद की पुरातन विचारधारा के अनुयायियों द्वारा कल्पना की गई किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है

युद्धविराम के अठारह वर्षों बाद हम महसूस करते हैं कि भारत अब फिर विश्व की शक्तिमती से अप्रभावित अपनी उस पुरानी स्थिर संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है ब्रिटिश राज के वृद्धिवाद ने अतिप्राचीन बुराईयाँ का अनुमोदन किया। प्रजातंत्र की नवपरिवर्तनशील चेतना, जो जनमत के लिए प्रतिद्वंद्विता करने वाले, मत शक्ति प्राप्त करने के लिए बलप्रयोग का सहारा देने वाले राजनीतिक दलों का माध्यम से कार्य करती है, उन सभी प्राचीन विशेषाधिकारों (सुविधाओं) को समाप्त करने में सक्षम होती है जिनके पीछे तक शक्ति और साहस का अभाव होता है जाति का आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पीछे हटाना ही पड़ा है और यह पीछे हटाना और पराजय जसा दिखता है यदि छुआछूत को समाप्त कर दिया जाए तो क्या जाति के आधार पर भेदभाव बना रह सकता है? हममें कोई गंदेह नहीं कि हिंदुओं की

शक्ति न ता विद्याया म हे जीर न मदिरा म यह घर न अदर है। फिर भी महिलाओं का शिक्षा दूर आधुनिकता की भावना घर में पैदा करने की दिशा में सन्नियता बनी हुई है। जात पात का प्रमुख परकोटा है हिंदुओं का समुक्त परिवार और महिलाओं का शिक्षा दूर तथा उन्हें यात्रा की ओर बाहरी दुनिया में संपर्क की सुविधा देकर इस परकोट की जड़ छोदी जा रही है। ('मैनचेस्टर गार्जियन वीकली', 4 दिसंबर 1936)

इस प्रकार जातान्त्रिक लहर की प्रगति राजनैतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में किसी भी अर्थ में कम नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त लेख में ही स्वीकार किया गया है यह लहर निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण सामाजिक आर्थिक क्रांति की जबरदस्त शक्तियाँ को इकट्ठा कर रही है ताकि उस बुनियादी समस्या का समाधान हो सके जिसे 'भारत की गरीबी' कहते हैं।

भारत की गरीबी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो लोग भारत की आवादी को तुलना उसकी धन-संपत्ति पदा करने की क्षमता से करते हैं वे यह कहने से बाज नहीं आएंगे कि यह रोग लाइलाज है। लेकिन साम्यवाद के प्रचारक इस दिशा में प्रयत्न की निराशावादी पक्ष को कभी नहीं स्वीकारते। उनमें अरबों का समर्थन बनाने की कोशिश करने का साहस है और भारत की पीड़ित जनता उतावलेपन के लिए उन्हें दावी नहीं ठहराएंगी। इसलिए हम यह देखने की आशा कर सकते हैं कि भारत में नए अधिकारीगण इस पक्की सामाजिक आर्थिक क्रांति का विरोध करने या उसे दिशा देने जायेंगे या सफल होंगे।

क्या साम्राज्यवाद यह आशा कर सकता है कि वह इन शक्तियों को अपने जुए तने रख सकेगा और उनका इस तरह से पथ प्रदर्शन कर सकेगा जिससे शोषण की उसकी व्यवस्था मुकम्मल तौर पर बनी रहे जो कि भारतीय जनता के शोषण की समूची व्यवस्था का गढ़ है? इस प्रश्न का उत्तर न तो उदारवादी साम्राज्यवादियों की त्रिशुद्ध अटकलवाजी से भरी बहसों में मिलेगा और न बकीलों की सामंतिधानिक सुधारों की जटिलताओं से प्राप्त होगा इसका जवाब साम्राज्यवाद की आर्थिक बुनियादों के ठोस तथ्यों में और भारतीय जनता की जनत आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के साथ उनके अंतर्विरोधों में ही मिलेगा।

भारत की जनता को अत्यंत महान् काय करने हैं। भारत एक रोगग्रस्त देश है, एक पिछड़ा देश है। यह ऐसा देश है जहाँ विज्ञान की गति अवरुद्ध हो गई है। यह बीमारी, गरीबी, परोपजायिता और प्रवादी से ग्रस्त देश है। इस क्षेत्र में दुनिया के किसी भी भाग में इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो यहाँ असीमित प्राकृतिक संपदा का भंडार है और दूसरी तरफ जनता की भयंकर गरीबी और दुखद है। यह विरोधाभास

हर प्रश्नक की निगाह में कौंध जाता है चाहे वह किसी भी सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा का क्या न हो। दूसरा कोई दश ऐसा नहीं है जहाँ जनता की हालत खुद बताती हो कि सरकार ने अपनी कौन सी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं और वह भी ऐसी सरकार जिस विकास के एक सौ वर्षों से भी अधिक समय तक निरंतर जिम्मेदारी सभालने का मौका मिला हो। भारत की बुनियादी समस्या आर्थिक और राजनीतिक है। राजनीतिक समस्या राष्ट्रीय मुक्ति और जनतंत्र के लिए सघन महज इस समस्या की तात्कालिक ऊपरी अभिव्यक्ति है। यह वास्तविक लड़ाई का पहला चरण है। कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष एकड़ गहरा होता जा रहा है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का चाहें वे किसी भी विचारधारा के क्या न हो यही कहना है कि व्यापक कृषि क्रांति के अलावा इसका समाधान का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन कृषि समस्या को औद्योगिक विकास से अलग रखकर नहीं हल किया जा सकता है। यह सभी लोग मानते हैं कि यहाँ जरूरत इस बात की है कि औद्योगिक विकास का वृहत कार्यक्रम हो दश व वरवाद हो रहे साधना का इस्तेमाल किया जाए, शक्ति का नए स्रोतों को काम में लाया जाए दश के लावा करोड़ बेरोजगारों को काम पर लगाया जाए और गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहे धन का सही इस्तेमाल किया जाए राष्ट्र की समृद्धि के लिए बुनियादी उद्योगधंधों की शुरुआत की जाए और उत्पादन स्तर को इस सीमा तक ऊँचा उठाया जाए जिसकी तुलना किसी भी विकसित तंत्रनीयवादी दश से की जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई तथा जनता की बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक पैमाने पर उद्दाम काम करना है। भारत की जनता के सामने आज यह प्रश्न है कि पुनर्निर्माण के इस महानतम कार्य का नतत्व कौन करेगा ? इस पूरा करने की शर्तें क्या हैं ? किन स्वरूपा और तरीकों के जरिए यह काम निष्पन्नित किया जा सकता है ?

निस्संदेह साम्राज्यवाद अब भी इस आशा में है और यह साचे बँठा है कि वह भारत में अवश्यमावी परिवर्तन की लहरों को नियंत्रित रख सकता है, वह यह सोच रहा है कि रियायत और संचालन शक्तियाँ व सुविचारित उपयोग से इस तरह रखा जा सके और माध्यमों में हों वही भी रूपांतरण को दिशा दे सकता है, उस पीछे ल जा सकता है या अपने अनुरूप ढाल सकता है जिससे सही अर्थों में स्वतंत्र भारत का उदय का रोका जा सके और ब्रिटिश पूँजी द्वारा निरंतर गोपण किए जाने के लिए भारत पर एकाधिकारी प्रभुत्व को बनाए रखा जा सके।

इंग्लिश आधुनिक युग में बहुप्रचारित साविधानिक गुंथारा के साथ साथ समूह मात्रों पर राजनीति और कूटनीति संबंधी जरूरत तयारियाँ तथा रक्षा व सुरक्षित भावों पर अच्छा तरह प्रतिपन्नित नीतियाँ रची गई हैं। यह काम सिंग आवाज और अनुरोधों वानूना व अन्य तरह प्रितितिक के जरिए किया गया है। 1916-13 में भारतीय जोधामित जाया का गठन हुआ, 1921-22 में भारतीय राजरोधोय जायाग (इंडियन विन्सत यमीता) 1926-28 में भारतीय वित्त और मुद्रा संबंधी गारो जायाग 1926-28 में भारतीय दृष्टि

सबधी शाही जायाग और 1929/31 में भारतीय धर्म सत्रही शाही जायाग का गठन किया गया। 1935 तक वह आफ इंग्लैंड के साथ निजी सान्नेदारी के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गई और इसे महाजनी पूजी के नियंत्रण का निर्णायक गढ़ बनाया। इसे पूरी तरह ब्रिटेन के वायसराय के अधीन रखा गया ताकि 'राजनीतिक दबाव' (अर्थात् भारतीय राजनीतिक दबाव) से अलग रखा जा सके। वायसराय का बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के पद के लिए नामांकन करने का अधिकार है और उस इस बात का भी अधिकार है कि वह बोर्ड के फैसलों को नामजूर कर दे। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का भारत सरकार अधिनियम की धारा 152 के तहत सांविधानिक सुधारों के मुख्याश से खासतौर से अलग रखा गया और वायसराय को अनियंत्रित 'स्वनिर्णय' तथा 'व्यक्तिगत फैसल' का अधिकार देकर इसे सुरक्षा प्रदान की गई। इस प्रकार आधुनिक पूजीवादी आर्थिक कार्य प्रणाली में शक्ति का मुख्य केंद्र ब्रिटिश महाजनी पूजी के विश्व रूप से सुरक्षित क्षेत्र में बना रहने दिया गया।

ब्रिटिश वर्गिक व्यवस्था की दमपोटू पकड़ का भारत में क्या भविष्य है? इसमें कोई संदेह नहीं कि साम्राज्यवादी आर्थिक एकाधिकारिक हितों के अर्थ महत्वपूर्ण मसलों की तरह यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सत्ता हस्तांतरण के तुरंत बाद पैदा होने वाले कुछ मामलों में से होगा और ब्रिटेन तथा भारत के बीच आने वाले दिनों में होने वाली संधि में इसे हल कर लेना जरूरी होगा। स्मरणीय है कि इस प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने की घोषणा कैबिनेट मिशन ने 25 मई 1946 के अपने वयान में कर दी थी। उसने कहा था कि भारत की जनता को प्रभुसत्ता देने की दो अपरिहार्य शक्तों में से एक शक्त यह संधि भी होगी।

इसके साथ ही हाल के वर्षों में ब्रिटिश महाजनी पूजी की सक्रिय गतिविधियां को भी देखा जा सकता है। यह बात खासतौर से इंपीरियल कैमिकल इंडस्ट्री, 'यू फील्डस' जैसे बड़े न्यासा और एकाधिकारी कंपनियों के मामले में देखा जा सकता है जो नए युग की तैयारियों के लिए भारत में अपना आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

इस प्रक्रिया में किसी सफलता को कम करके आकरना गलत होगा। आधुनिक युग में ब्रिटिश महाजनी पूजी कुछ मामलों में जितनी मजबूती के साथ भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपेक्षाकृत निपुण तरीकों का जो इस्तेमाल कर रही है उसे देखने में यदि कोई चूक हुई तो यह बहुत बड़ा राजनीतिक भोलापन होगा। यह राजनीतिक भोलापन सांविधानिक सुधारों की चकाचौंध में से आखें बंद कर लेने या सत्ता द्वारा बड़े जोरशोर से प्रचारित की गई रियायतों को अथवा लकाशायर के व्यापारियों द्वारा भारत में अपने एकाधिकार के खो जाने की चीख-पुकार को सही मान लेने से भी ज्यादा घातक होगा। इस प्रक्रिया का विश्लेषण हमने छठे अध्याय में किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ब्रिटिश न्यासा द्वारा नियंत्रित कंपनियों के जरिए भारत का जो नया साम्राज्यवादी अतिभ्रमण हुआ है (ये कंपनियां अपने आपको भारतीय औद्योगिक कंपनियां कहकर

पण करती थी) उस हम गुद्ध की पूव सध्या म महसूस कर चुक है। इसका प्रमाण हम 1939 म सीनियर ट्रेड कमिश्नर फार इंडिया की रिपोर्ट म मिलता ह। उहाने लिखा है

कुछ महत्वपूर्ण मामला म खासतौर स सिगरट, दियासलाई रबड टायर, मायुन, रंग रागन और कुछ दवाइयो क उत्पादन के मामले मे, य औद्योगिक संस्थान ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य देशा की महत्वपूर्ण फर्मो की शाखाण है। इन फर्मो न यह फैसला किया है कि सीमा शुल्क के दायर क भीतर रहते हुए और सरकारी खरीद-फरास्त विभागो की जरूरतो के लिए टेंडर देत समय खुद का भारतीय मूल का बताकर यदि भारत क लोगो की माग पूरी की जाए तो इसमें उह (फर्मो को) काफी फायदा है। (भारत म ब्रिटेन के व्यापार की स्थितिया और मभावनाओ पर रिपोर्ट के लिए सर यामम एमकफ की प्रारंभिक रिपोर्ट 1939)

भारत के राष्ट्रवादी तत्वा की ये कटु शिकायतें ह कि भारतीय उद्योग को संरक्षण देने का उद्देश्य इस प्रकार विफल होता जा रहा है और आराम लगाया है कि सरकार और बैंक ब्रिटिश पूजा का पक्ष ले रहे हैं जो अपने का भारतीय उद्योग क छद्म रूप म सामने प्रस्तुत कर रही हैं। भारतीय उद्योग के नाम पर बहुविनाशित के सीमा शुल्क रियायतें उह मिल रही हैं जिनके बारे म यह प्रचार किया जाता रहा है कि ये रियायतें भारतीय पूजा-पतिया का दी जाएगी। इस प्रकार भारत म ब्रिटिश पूजावाद का और भी मजबूती स संस्थापन हा रहा है

इस संरक्षण का उद्देश्य भारतीय उद्योगो को विकसित करना है। भारतीय उद्योगो म वे उद्योग शामिल ह जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन भारतीयो के द्वारा होता है लेकिन भारत म गरभारतीय उद्योगो क काम करने स संरक्षण का यह उद्देश्य विफल हो जाता है। विदेशी पूजा जिस तरीके स भारत पर घावा बोल रही है वह बहुत गूढ़ और जटिल तरीका है। बहुधा इस भारतीय रूप र्ण की कोशिश की जाती है जो महज एक प्रदर्शन कला है। बहुधा दया जाता है कि इन उद्योगो पर वास्तविक निश्चयण और इन उद्योगो का वास्तविक संचालन गैर भारतीयो के हाथ म है जो प्रायः दिबाव के लिए कुछ भारतीय डायरेक्टरो को अपनी सहायता क लिए नियुक्त किए रहत हैं

यह बुराई महज आर्थिक नहीं है क्योंकि इस तरह के प्रत्येक निहित स्वार्थ सांविधानिक उपायो क जरिए अपनी घुसपठ की निश्चित बनाने का तरीका निकाल लेंग इनके जरिए वे भारतीय विद्याभ्युदयो क अधिकार और शक्तियों का अत्यंत सीमित कर देंगे तथा महत्वपूर्ण उद्योगो के राष्ट्रीयकरण का काम कठिन बना देंगे।

उद्योग के क्षेत्र में इस तरह के तत्प्राकृतिक भारत ब्रिटिश सहयोग का पलड़ा अतत्तोगत्वा राजनीतिक प्रतिक्रियावाद के पक्ष में भारी पड़ेगा और इस प्रकार वह वास्तविक आर्थिक स्वराज के लक्ष्य को एक स्वप्न बना देगा। (अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता में प्रकाशित लेख 'ए 'न्यू मिनेस' 11 नवंबर 1937)

1946 के सांविधानिक प्रस्तावों के साथ इधर हाल के वर्षों में ब्रिटिश पूँजी की आर्थिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति 'फाइनेशियल टाइम्स' में प्रकाशित इन अशांति में देखी जा सकती है

आर्थिक दृष्टि से भारत अंगरेजों की मदद के बिना नहीं रह सकता और ब्रिटेन भारतीय बाजार का हाथ से निबटना नहीं बरदाश्त कर सकता। भारत के विकास में और भारत की समृद्धि में ब्रिटेन की आज भी उत्प्रेक्षणीय आर्थिक साझेदारी है। भारत को ब्रिटिश बाजारों और अनुभवों की जरूरत है और स्टर्लिंग का व्यापक मतुलन होने के साथ ब्रिटेन के वित्तीय भविष्य में उसकी काफी दिलचस्पी है। यदि ब्रिटेन भारत को छोड़ता है तो उस सभी संभव सद्भावना से जलग होना पड़ेगा। फिर ब्रिटिश हितों के प्रति अनुकूल रवैया अपनाने के लिए कौन से प्रमुख रणनीति उपाय बच रहेंगे? क्या यह जुगा खेलना है? समूची योजना अनेक चीजों का दाव पर लगाना है लेकिन निणय ले लिया गया है। मुमकिन है कि इससे साम्राज्यवादी हितों को नुकसान पहुंचे लेकिन यह भी हो सकता है कि इससे इन हितों को मजबूती मिले। फिलहाल इस सदन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। (फाइनेशियल टाइम्स, 18 मई 1940)

इस प्रकार साम्राज्यवाद ने अपनी वर्तमान रणनीति को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों की दिशा में मोड़ दिया है ताकि जानें नए युग में वह अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बनाए रखने में सफल हो सके। इससे उसे यह लाभ मिलेगा कि उस नए युग में ब्रिटिश पंडों के स्थान पर भले ही भारतीय पंडों फहरा दिया जाए लेकिन अंतिम शक्ति और शापण का मुख्य लाभ जहां तक संभव होगा ब्रिटिश पूँजीवाद के हाथ में बना रहेगा।

यही वह असली खतरा है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लक्ष्य तक सघर्ष को जारी रखना आवश्यक बना दिया है। इस तरह की आजादी को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी आजादी प्राप्त करनी होगी, विदेशी पूँजी को दो जान वाली सभी रिमायंटें रद्द करनी होंगी और उन सभी विदेशी उद्योगों, चाय बागानों, कारखानों, रेलवे, नौपरिवहन व्यवस्था आदि पर बज्जा करना होगा।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आधुनिक युग में निम्नानुसृत वृद्धि की कुशल और श्रमसाध्य रणनीति

अपनाई है लेकिन इसके बावजूद इस बात का कोई सम्भावना नहीं है कि आने वाले नए युग में भारत पर अपना प्रभुत्व और एकाधिकार बनाए रखने के ब्रिटेन के ये सपने कभी पूरे हो सकेंगे। भारत की उदीयमान शक्तियाँ का इतनी आसानी से उन रास्तों की ओर नहीं ले जाया जा सकता जिन्हें ब्रिटेन के गिमम शासकवर्ग ने तैयार किया है। आज के भारत में प्रति वर्ष आर्थिक समस्याएँ तभी में बढ़ती जा रही हैं लेकिन साम्राज्यवाद की स्थितियों में इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जादुनिका काल में साम्राज्यवादी नियंत्रण के तहत अथवा इस नियंत्रण द्वारा रोप गए प्रतिवधा के बावजूद होने वाला आर्थिक विकास जटिल, बाधित तथा विकृत विकास है और उसमें राष्ट्रीय पुनर्गठना का कोई लक्षण नहीं है। ट्रेड कमिश्नर की रिपोर्ट में ब्रिटिश पूँजी के नियंत्रण और इसकी पहल के अंतर्गत जिन नए उद्योग धंधों के विकसित होने का उल्लेख किया गया है वे मूलतः अप्रधान हल्के उद्योग धंधे हैं ( सिगरेट, दियासलाई, खड्ड टायर, साबुन, रंग रोगन और कुछ दवाइयाँ ) और उद्योगीकरण के लिए ये कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते। भारत के अब तक छिपे हुए रासायनिक साधना का पता लगाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए कई योजनाओं की घोषणाएँ की गईं और यह भी मानने के पर्याप्त कारण हैं कि सरकार ने 'आई० सी० आई० (इंडिया) लिमिटेड' को उल्लेखनीय रियायतें दीं। त्रेपिन भारी उद्योगों के विकास के लिए इस तरह का कोई उपाय नहीं किया गया। सम्भावनाओं और आवश्यकताओं के मन्त्र में देखें तो लोहा और इस्पात उद्योग का विकास बहुत दयनीय है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ जा निर्णायक पथप्रदर्शक कार्य किया गया है वह ब्रिटिश पूँजी ने नहीं बल्कि टाटा की भारतीय फर्म ने किया। बाद में इसमें ब्रिटिश पूँजी इसलिए लगी ताकि इसपर वित्तीय दबाव बना रहे ( इंडियन जायरन एंड स्टील कंपनी के अधिकांश शेयर ब्रिटिश स्वामित्व वाली बगाल आयरन कंपनी ने खरीदे )। 1935 में लोहा और इस्पात उद्योग में लगे मजदूरों की कुल संख्या 32,000 थी। 1924 से 1939-40 के बीच इस्पात की सिलिलियों का उत्पादन 341,000 टन से बढ़कर 10,70,355 टन हो गया। इसी अवधि में सोवियत संघ में यह उत्पादन 1924 में 14,08,000 टन से बढ़कर 1936 में 16,300,000 टन हो गया।

पिछले युद्ध के दौरान यह पता चला था कि सबूट के दिना में भारत एक मोटर इंजन या हवाई जहाज भी नहीं बना सका था। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयर प्रापर्टी फैक्टरी, बंगलूर ( जिसे थोड़ी अवधि के लिए अमरीकी सेना को सौंप दिया गया था ) ने एक भी हवाई जहाज नहीं बनाया। युद्ध के बाद के दिनों में भी विकास की जो योजनाएँ तैयार की गईं उनमें इसी प्रवृत्ति की झलक मिलती है। यह घोषणा की गई कि नई 'भारतीय' कार हिंदुस्तान 10' के निर्माण के लिए विन्ला और यूफील्ड के बीच समझौते की बातचीत चल रही है लेकिन इस घोषणा के बाद पता चला कि इस कार के आवश्यक पुर्जों का निर्माण यूफील्डस करेगा और इन्हें भारत में महज जाड़ा जाएगा। इसी प्रकार टाटा और आई० सी० आई० के बीच सपने में ममथता की शर्तों में पता चलता है कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता (आत्मनिर्भर ह्रा की अवधि कम से कम बीस



वष बताई गई) तब तक आवश्यक दवाएँ इंग्लैंड से आयात की जाएंगी और उन्हें 'भारतीय' कहकर भारत में बेचा जाएगा। इस तथ्य को भी काफी प्रचारित किया गया है कि सिंहभूम का रेलवे वकशाप टाटा उद्योग समूह का सोप दिया गया है ताकि वे भारतीय लान्गमोटिव इंजनों का उत्पादन कर सकें लेकिन अनुमान है कि पहला लोकोमोटिव इंजन बनाने में अभी कई वर्ष लग जाएंगे। इस घोषणा को भी दुनिया भर में खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एयर ट्राफ्ट फैक्टरी अब भारत सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व में तथा ब्रिटिश इंजिनियरों के माग निर्देशन में हवाई जहाजों का निर्माण शुरू करेगी। लेकिन जसाकि इस घोषणा में स्वयं बताया गया है हवाई जहाजों के निर्माण के मामले में भारत कम से कम बीस वर्षों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकेगा।'

समचित्त आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योग के आधार को विकसित करना एक बुनियादी शर्त है लेकिन इस काम में जो असफलता मिली है वह मयोगवश नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व के तहत किसी देश की क्या स्थिति होती है। भारत मशीनों के लिए आज भी पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। जसाकि पहले ही कहा जा चुका है धातुकर्मीय उद्योगधंधों के विकास का अर्थ है वास्तविक औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका इन सभी देशों ने अपने यहां बपड़ा बनाने वाले कारखानों की शुरुआत से पहले आधुनिक पैमाने पर लाहा और इस्पात उद्योग की नींव डाली।' (एल० सी० ए० नावेल्स, 'इयनामिक डेवलपमेंट आफ दि ओवरसीज इंपायर', पृष्ठ 443। विस्तार से अध्ययन के लिए पृष्ठ 160 देखें) यह प्रक्रिया सोवियत संघ में और भी तेजी से देखी जा सकती है। भारत में एकदम उल्टी ही प्रक्रिया है और इसमें उसकी औपनिवेशिक स्थिति प्रतिबिंबित होती है। भारत में भारी उद्योग के सही अर्थों में विकास के लिए सभी प्राकृतिक और तकनीकी संभावनाएं मौजूद हैं और इस विकास के लिए देश की स्थितियां फरियाद करती हैं लेकिन चूंकि यह एक उपनिवेश है इसलिए विकास की प्रक्रिया का औपनिवेशिक स्थिति में परस्पर विरोध है। यदि भारत में भारी उद्योग का विकास हो जाए तो दुनिया के पैमाने पर एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत के उभरने का आधार तैयार हो सकता है।

यही कारण है कि भारत में आर्थिक विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्व के जबरदस्त बंधनों के बीच संघर्ष दिन व दिन तेजी से बढ़ता जाएगा और संभाव्य तथा सहयोग कायम करने के हर प्रयास को बेकार कर देगा।

एक शताब्दी पूर्व भारत में ब्रिटिश बुरजुआ के शासन का उसके तमाम विध्वंसों और बबरताओं के बावजूद यह कहा जा सकता था कि वह पुरानी समाजव्यवस्था की बुनियादों को नष्ट करने में और नई समाजव्यवस्था के लिए स्थितियां तैयार करने में 'इतिहास के हाथों में एक अचेतन हथियार' की भूमिका अदा कर रहा था। आधुनिक साम्राज्यवाद

वर्तमान युग की घटनाओं के क्रम में, जब पुनर्निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, अब यह भूमिका अदा नहीं कर सकता।

भारत में साम्राज्यवाद के दिवालियेपन की कहानी भारत की वर्तमान स्थिति और यहाँ की जनता की हालत के रूप में लिखी हुई है। पिछले 25 वर्षों में सोवियत संघ ने जो उपलब्धियाँ की हैं और इसी अवधि के दौरान भारत की जो उपलब्धियाँ रही हैं उनके बीच कितनी विषमता है इसे देखे बिना नहीं रहा जा सकता। हम जब उन आँकड़ों पर विचार करते हैं जो लाहौर और इस्पात उद्योग के बारे में ऊपर पेश किए गए हैं तब भारत और सोवियत संघ की प्रगति की विषमता का स्पष्ट पता चलता है। यही स्थिति अन्य मामलों में भी है। मसलन, सोवियत संघ में निरक्षरता का समाप्त हो जाना और भारत में बीस वर्षों में निरक्षरता में महज दस प्रतिशत की कमी होना, कृषि के विकास में और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में दोनों देशों के बीच का अंतर अथवा सोवियत संघ में स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं का निरंतर जाल बिछते जाना तथा भारत में अत्यंत बुनियादी सेवाओं का लगभग पूरी तरह अभाव का होना। इन तथ्यों से भारतीय जनता का महत्वपूर्ण सबक मिलता है और इस सबक को पूरी तरह हृदयंगम कर लेना चाहिए।

यह दिवालियापन किसी एक प्रशासक की योग्यता या यहाँ तक कि उसकी ईमानदारी अथवा सद्भाव का मामला नहीं है जिसने यदि वह बहुत सजग प्रतिनिधि हुआ तो, इन निराशाजनक स्थितियों के खतरे को महसूस किया और यह समझ सका कि ये स्थितियाँ किसकी दिशा में ले रही हैं। यदि इन प्रतिनिधियों के भीतर कुछ अच्छा कर दिखाने की इच्छा भी रही तो साम्राज्यवादी शासन ने उन्हें ऐसी शक्ति नहीं दी थी कि वे कोई असामान्य नतीजे निकाल सकें। इसका कारण यह है कि साम्राज्यवादी शासन के बन रहने का सामाजिक आधार वही शक्तियाँ हैं जो भारत को पिछड़ेपन का शिकार बनाए हुए हैं। कृषि आयोग के समक्ष भारत में निरंतर बढ़ रहे कृषि संकट के बुनियादी प्रश्न पर विचार विमर्श करने के द्वार में सरकारी तौर पर जो निपेधात्मक खयाल अपनाया गया वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिवालियेपन का एक प्रतीक है। जब तक जमींदारी प्रथा से संबंधित समस्याएँ हल नहीं कर लिये जायें, जब तक भूमि समस्या का कोई बुनियादी समाधान नहीं ढूँढ़ लिया जाता तब तक भारत की प्रगति की समस्या नहीं हल हो सकती, बुनियादी आर्थिक या सामाजिक पुनर्निर्माण की संभावनाएँ नहीं ढूँढ़ी जा सकती। लेकिन जमींदारी प्रथा पर जाँच-पड़ताल करने का अर्थ यह है कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व की बुनियाद पर जाँच-पड़ताल किया जाए और उन सामाजिक शक्तियों को लिए माँग प्रशस्त कर दिया जाए जिनकी प्रगति का अर्थ है साम्राज्यवाद का विनाश। साम्राज्यवाद ने अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए एक सामाजिक आधार पान की काशिश की है और इसके लिए उसने जावादी के उस हिस्से के विशेषाधिकारों और सुविधाओं का बनावट दिया है जिनसे दलित जाति जनता को हिताय प्रतिकूल है। इसी से पता चलता है कि अंगरेजों का सामाजिक तौर पर कितना दक्षिणानुसृत है और अत्यंत बुनियादी मुद्दों पर

मांग में वह किंग तरह मोघाए डालता है।<sup>14</sup> ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत में अपनी किस्मत को जमींदारवग, राजाजा महाराजाजा सांप्रदायिक भेदभाव बनाए रखने वाले निहित स्वार्थी तत्वा तथा पिछड़ेपन और पतनशीलता की हिमायती प्रतिक्रियावादी शक्तियों की किस्मत के साथ बाध रखा है।

इधर हाल के वर्षों में भारत के औद्योगिक बुजुर्गवग के साथ सहयोग कायम करने के लिए अंतिम बार किसी आधार का प्राप्त करने की कागिश की गई है लेकिन जनता की सामाजिक प्रगति का विरोध करने वाल कुछ समान हिता के बावजूद यह आधार कभी स्थिर नहीं हो सकता। जाने वाले दिना में इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पतन से कोई नहीं बचा सकता और उन्ही के साथ साम्राज्यवाद का भी विनाश निश्चित है।

इसलिए इस बात की पूरी सभावना है कि जाने वाले दिना में भारत का स्वाधीनता मिल जाएगी हालांकि अंतिम लड़ाई जब भी लडनी बाकी है। यह आजादी जल्द या देर से प्राप्त होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनता में कितनी एकता है। राष्ट्रीय आंदोलन का जन आधार कितना मजबूत है तथा आंदोलन की अपने लक्ष्य के प्रति कितनी साफ दृष्टि है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो भारत में पुनर्निर्माण के अत्यंत आवश्यक काय होने बाकी हैं और इसे स्वयं भारत की जनता ही चला सकती है और उसी को यह काय पूरा करना होगा।

## 2 किस तरह का आजाद भारत ?

इस प्रकार भारत के भविष्य से संबंधित अंय प्रश्न भारतीय जनता की आंतरिक शक्तियों पर आकर टिक जाते हैं। भारत की जनता समग्र रूप से सजातीय नहीं है। हमने देखा है कि कुछ ऐसी ताकतवर प्रतिन्यावाणी शक्तियां हैं जो अपने विशेषाधिकार बनाए रखने की आशा में साम्राज्यवादियों के साथ पूरी तरह साठ गाठ किए हुए हैं (हालांकि साम्राज्यवाद के कमजोर होने के साथ ही इनमें से भी कुछ के अंदर अब अनिश्चय की भावना घर करने लगी है)। हमने भारतीय बुजुर्गों की दुलमुल भूमिका को देखा है जिसका ब्रिटिश बुजुर्गों से जवरदस्त विरोध है वह भविष्य के भारत को एक आजाद देश के रूप में देख रहा है और उसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक शक्तिशाली ही नहीं बल्कि प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर भी हर बार जब जनसघर्ष तेज होने लगा है उसने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अवरोध का काम किया है और साम्राज्यवाद के साथ अस्वाइं मोलभाव करने के बाद फिर सघर्ष में कूद पड़ा है। हमने औद्योगिक मेहनतकशों का उदय और किसानों का विद्रोह देखा है जिसके फलस्वरूप भारत के राजनीतिक रगमच पर नए सामाजिक मसल बड़ी तजी से उभरकर सामने आए हैं। छात्र, बुद्धिजीवी युवक, शहरी निम्न पूजीपतिवग कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा सकते लेकिन वे एक सचेतन राजनीतिक आंदोलन को अत्यंत सन्नित्य आंदोलनकारी और सगठनकारी अवयव प्रदान

कर सकते हैं। हमने देखा है कि प्रगत हुए राष्ट्रीय और सामाजिक मंच के दौर में इन वर्गों में सभी परस्पर विरोधी धाराएँ उद्घाटित हुई हैं।

क्या स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में साम्राज्यवाद का अंतिम रूप से पराजित करने तक राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को सफलतापूर्वक बनाया रखा जा सकेगा? या बढ़ते हुए जनआंदोलन के मध्य से पुर्जुआनवादी का राष्ट्रीय रुढ़िवादी तत्व आंदोलन से अपने को अलग करके साम्राज्यवाद के साथ माठ गाठ कर लेगा और इस प्रकार साम्राज्यवाद को जस्थाई जीवनशक्ति दे देगा जिससे राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष की अंतिम विजय सामाजिक मुक्ति के लिए जारी जनसंघर्ष से जुड़ जाएगी? यदि आजादी हासिल होती है तो पुराने ब्रिटिशशासित भारत के स्थान पर किस तरह के नए भारत की स्थापना होनी चाहिए? क्या नवीकृत ग्रामीण अव्यवस्था तथा उद्योगवाद की सीमाओं पर आधारित आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप रूपांतरित पुनर्निर्मित हिंदू या प्राचीन भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थानवादी समर्थक संघर्ष का आग बक्शा करेगा और अपने सपना के भारत का निर्माण कर सकेगा? या औद्योगिक पुर्जुआनवादी तथा शिक्षित वर्ग में उनका प्रतिनिधि यह घोषणा उठाएंगे और पश्चिम के पूँजीवादी दशों के नमूने पर आधुनिक पूँजीवादी भारत का निर्माण करेंगे? या टीकों की तरह ही नियंत्रित पूँजीवाद की पद्धति पर एकलौती राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अस्साई दौर आ टपक जाएगा? या जनता का कठिन परिश्रम तथा जबरदस्त संघर्ष निकट भविष्य में ही समाजवाद के रास्ते पर बढ़ने वाले एक जनवादी भारत को जन्म देगा?

भारत से संबंधित विचारणीय विषयों में ऐसे और इस तरह के कई प्रश्न बढ़ी तेजी से पैदा हो रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो भविष्य के बारे में पूरी तरह अटकला पर आधारित हैं क्योंकि भावी लक्ष्यों की अवधारणा और वर्तमान संघर्ष में समाज के अलग अलग वर्गों और शक्तियों की भूमिका का आकलन मौजूदा संघर्ष को और राष्ट्रीय आजादी की प्राप्ति की संभावनाओं को अत्यधिक प्रभावित करता है। भारत में वर्गसंघर्ष और राष्ट्रीय संघर्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और भारतीय राजनीति को समझने के लिए तथा भारतीय जनता के सामने मौजूद लूफ्तानी सागर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए इस अंतरसंघर्ष को समझना अत्यावश्यक है।

इन समस्याओं पर विचार करते समय उन वास्तविक सामाजिक या वर्ग शक्तियों के बीच (जिनकी सापेक्षिक शक्ति और जिनका पारस्परिक प्रभाव एक के बाद एक आने वाली अवस्थाओं तथा अंतिम निष्पत्ति का दरअसल संचालित करता है) तथा एकदम ताजा दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के बीच फर्क करना जरूरी है जिनके जरिए फिलहाल ये शक्तियाँ स्वयं जाणिक रूप से अभिव्यक्त होती हैं और जो अनेक स्तरों पर विचार धाराओं के संघर्ष का मूलतः आधार प्रतीत होती हैं।

राष्ट्रीय आंदोलन में आज तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ या मुख्यतः तीन तरह के सामाजिक सामाजिक दृष्टिकोण मौजूद हैं। इनमें पहली प्रवृत्ति को रूढ़िवादी (सामाजिक अर्थों में इसे रूढ़िवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि राजनीतिक अर्थों में या साम्राज्यवाद के सदस्य में भी यह प्रवृत्ति रूढ़िवादी हो) या पीछे की ओर देखने वाली प्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति अपना पायथर एक ऐसे आदर्श पुरातन भारतीय सभ्यता के आधार पर तैयार करती है जिसकी बुराईयों का मोटा तौर पर तो निकाल लिया जाता है पर जिसमें हिंदूवाद की बुनियादी मर्यादाएँ और इसमें सिद्धांत बने रहते हैं। यह आधुनिक उद्योगवाद को बहुत घटकरनाक समझती है (इसे बिना किसी भेदभाव के पूँजीवाद या साम्यवाद जितना घटकरनाक मानती है) और चरखा लेकर तथा आदिम कृषीय जीवन को ही एक आदर्श स्थिति मानकर समझती है कि किसानों की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व कर रही है।

दूसरी शक्तिशाली प्रवृत्ति औद्योगिक बर्जुआ की प्रवृत्ति है। औद्योगिक बर्जुआ पश्चिम के नमून पर आधुनिक पूँजीवादी भारत के निर्माण की कोशिश करता है लेकिन साथ ही वह औद्योगिक मजदूरों की अनिवाय रूप से बढ़ती शक्ति तथा उनकी मांगों और किसानों के बीच बढ़ते असंतोष से भयभीत रहता है। नतीजा यह होता है कि वह अपने लक्ष्यों को कभी कभी एक अल्पसमाजवादी नारा देकर आदर्श साबित करने की कोशिश करता है। वह सामाजिक तौर पर प्रचलित 'बिना वगसंधर्ष या समाजवाद' या 'भारतीय समाजवाद' नारा देता है जो एक बहुत अस्पष्ट मानवतावाद और वग सम्योतावाद को अभिव्यक्त करता है।

तीसरी प्रवृत्ति है समाजवाद की उभरती प्रवृत्ति जो अत्यंत स्पष्ट रूप में औद्योगिक मेहनतकशवर्ग के लक्ष्य की सचेतन अभिव्यक्ति का और भारतीय समाज के बुनियादी रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रवृत्ति को दिनादिन काफी तेजी से घासतौर से युवावर्ग का समर्थन मिलता जा रहा है।

इन तीनों प्रवृत्तियों में से पहली प्रवृत्ति का महत्व आज भी बना हुआ है और हालांकि इसका न तो कोई ठोस सामाजिक आधार है और न अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इससे पास कोई व्यावहारिक संभावना है फिर भी इसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए। इसका यह विश्वास एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वह किसानों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है और इसलिए 'वास्तविक जनता' तथा 'भारतीय समाज की संरचना' के काफी निकट है। यह भ्रम ठीक वैसा ही है जसा एक जमाने में रूस में पार्लियामेंट ने तथा अन्य देशों में आंदोलनों के दौरान विभिन्न प्रवृत्तियों ने पाल रखा था। लेकिन जैसाकि रूस में या अन्य देशों में हुआ, औद्योगिक मजदूरवर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करके जल्द ही प्राप्ति विवास करेगी तो यह भ्रम अपने आप ही चूर चूर हो जाएगा। दरअसल जब किन्हीं पूँजीपतिवर्ग का एक उल्लेखनीय हिस्सा आर्थिक स्थिति में होने वाले



राष्ट्रीय आंदोलन में आज तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ या मुख्यतः तीन तरह के सामाजिक दृष्टिकोण मौजूद हैं। इनमें पहली प्रवृत्ति को रूढ़िवादी (सामाजिक अर्थों में इसे रूढ़िवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि राजनीतिक अर्थों में या साम्राज्यवाद के संदर्भ में भी यह प्रवृत्ति रूढ़िवादी हो) या पीछे की ओर देखने वाली प्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति अपना कार्यक्रम एक ऐसे आदर्श पुरातन भारतीय सभ्यता के आधार पर तैयार करती है जिसकी बुराइयों को मोटा-तौर पर तो निकाल दिया जाता है पर जिनमें हिंदूवाद की बुनियादी संस्थाएँ और इससे सिद्धांत बने रहते हैं। यह आधुनिक उद्योगवाद को बहुत खतरनाक समझती है (इस बिना किसी भेदभाव के पूँजीवाद या साम्यवाद जितना खतरनाक मानती है) और चरखा लेकर तथा आदिम ग्रामीण जीवन को ही एक आदर्श स्थिति मानकर समझती है कि किसानों की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व कर रही है।

दूसरी शक्तिशाली प्रवृत्ति औद्योगिक बर्जुआ की प्रवृत्ति है। औद्योगिक बर्जुआ पश्चिम के नमूने पर आधुनिक पूँजीवादी भारत के निर्माण की कोशिश करता है लेकिन साथ ही यह औद्योगिक मजदूरों की अनिवाय रूप से बढ़ती शक्ति तथा उनकी माँगों और किसानों के बीच बढ़ते असंतोष से भयभीत रहता है। नतीजा यह होता है कि वह अपने लक्ष्यों का बर्फी-बर्फी एक अर्धसमाजवादी नारा देकर आदर्श साबित करने की कोशिश करता है। वह सामाजिक तौर पर प्रचलित 'बिना बगसमय का समाजवाद' या 'भारतीय समाजवाद' नारा देता है जो एक बहुत अस्पष्ट मानवतावाद और बग समझौतावाद को अभिव्यक्त करता है।

तीसरी प्रवृत्ति है समाजवाद की उभरती प्रवृत्ति जो अत्यंत स्पष्ट रूप में औद्योगिक मेहनतकश वर्ग के लक्ष्यों की सचेतन अभिव्यक्ति का और भारतीय समाज के बुनियादी रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रवृत्ति को दिनोदिन काफी तेजी से खागतौर से युवावर्ग का समर्थन मिलता जा रहा है।

इन तीनों प्रवृत्तियों में से पहली प्रवृत्ति का महत्व आज भी बना हुआ है और हालांकि इसका न तो कोई ठोस सामाजिक आधार है और न अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इससे पास कोई व्यावहारिक संभावना है फिर भी इसे कम करके नहीं आका जाना चाहिए। इसका यह विश्वास एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वह किसानों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती है और इसलिए 'वास्तविक जनता' तथा 'भारतीय समाज की संरचना' के काफी निकट है। यह भ्रम ठीक वैसा ही है जैसा एक जमाने में रूस में पापुलिस्टों ने तथा अंश दशा में आंदोलनों के दौरान विभिन्न प्रवृत्तियों ने पाल रखा था। लेकिन जसाकि रूस में या अंश देशों में हुआ, औद्योगिक मजदूरवर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाम बुरा जंग कृषि प्राप्ति बिनाग करेगी तो ये भ्रम अपने आप ही चूर चूर हो जाएंगे। दरअसल जब निम्न पूँजीपतिवर्ग का एक उत्प्रेक्षणीय हिस्सा आर्थिक स्थिति में होने वाले

परिवर्तनों का वरदाशत नहीं कर पाता, उससे परेशान हो जाता है तथा खतरा महसूस करने लगता है, उसके परिचित तटवधा में जब दरार पड़ जाती है सक्रमण और सघप के तूफान में वह बिना किसी पथप्रदशक के फँक दिया जाता है और सहार के लिए किमी पुरातन अनिश्चितता की चट्टान तलाशने की असफल कोशिश कर रहा होता है तब प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में इसी तरह के भ्रम सामने आते हैं। अपने गूढ़तम अर्थों में वह उन सभी सामाजिक शक्तियों की वरदादी की अभिव्यक्ति है (उजड़े हुए हस्तकर्मों, जमीन से वेदखल किए गए किसान दिवालियापन के शिकार छोटे व्यापारी) जिन्हें साम्राज्यवाद विनष्ट कर रहा है और जो पैशाचिक पश्चिमी सम्पत्ता तथा मशीनों को ही अपना दुश्मन समझ रही हैं। यह अत्यंत दुःखद दृष्टिकोण है जो भूलतः निराशावादी है। यह पृथ्वी व जीवन का दुःख और भ्रमों से भरा मानकर किमी दूसरे लोक के काल्पनिक आध्यात्मिक जगत में राहत तलाश करना है। यह चुकी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के भीतर भी एक हार रही लड़ाई लड़ रही हैं जबकि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का स्वरूप ही उदीयमान होता है और वह आशावादी आंदोलन होता है। लेकिन इसका वर्तमान महत्व है। महज इसलिए नहीं कि यह भारत में साम्राज्यवाद द्वारा की गई विनाश प्रक्रिया का एक सामाजिक लक्षण है बल्कि इसलिए भी कि यह आज भी उस पुरातनपथी 'कट्टरवादिता' का आधार है जो कांग्रेस के अंदर मौजूद है और जो गांधी का मसीहा मानकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हुई।

इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधियों ने रचनात्मक कार्यक्रम के नाम पर गांधी में पुनर्निर्माण का काम शुरू किया और उद्योगीकरण का विरोध किया।

सही समाजवाद ग्रामोद्योगों के विकास में है। हम यह नहीं चाहते कि हम अपने देश में भी पश्चिमी देशों की तरह वैसी ही अव्यवस्थापूर्ण परिस्थिति पैदा कर दें जो बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से हुई है। (वल्लभभाई पटेल का अहमदाबाद में भाषण, 3 जनवरी 1935)

अपनी सत्कृति के पुनर्विकास के लिए भारत, चीन और मिस्र को अपनी कृषि-सम्पत्तावाले अतीत के दिनों की देखना चाहिए। (अखिल भारतीय ग्रामोद्योग एसोसिएशन के सचिव जे०भी० कुमारप्पा व्हाई दि विलज भूवमट, 1936, पृष्ठ 55)

आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों पर आधारित पुरानी 'भारतीय सम्पत्ता' (मावम ने इसी के घिसे पिटे रूप के बारे में बताया था कि इसने पूर्वी देशों में तानाशाही, गुलामी और विश्वास और जड़ता पैदा की) को एक ऐसा आदर्श माना गया जिसके पुनर्जीवन की जरूरत पर जोर दिया गया।



मेरा विश्वास है कि भारत में जिम सम्यता का विकास किया या उसका मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। (गांधी 'इंडियन होम रूल', 1908, नई भूमिका के साथ पुनमुद्रित 1919, पृष्ठ 66)

जैसाकि गांधी के शुरु के लेखा में दखा गया, बाद के वक्तव्या में और भी जोरदार शब्दा में मशीन और आधुनिक विज्ञान की एक साथ मत्सना की गई

यह मानना बहुत जरूरी है कि मशीन अपने आप में बुरी चीज है। पहले हम यह मान ले फिर धीरे धीरे इस योग्य हो जाएंगे कि उसके बिना भी काम चला लें। (गांधी 'इंडियन होम रूल', पृष्ठ 124)

अस्पताल पाप का प्रचार करने वाली संस्था है। (वही, पृष्ठ 64)

1909 में अपने एक मित्र को लिखे 'कंफेशन आफ फेथ' में गांधी की यह विचारधारा और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है

भारत पर अंगरेजों का शासन नहीं है बल्कि यह आधुनिक सम्यता है जो अपनी रेलव्यवस्था, तार, टेलीफोन तथा सभी नए आविष्कारों के जरिए भारत पर शासन कर रही है। इन आविष्कारों को सम्यता की विजय माना गया है

यदि बल अंगरेजों के शासन के स्थान पर भारतीयों का शासन स्थापित हो जाए और यह शासन भी उन्हीं आधुनिक साधनों पर आधारित हो तो भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। हा, वह अपना कुछ पैसा जरूर बचा सकेगा जो अभी इंग्लैंड चला जाता है लेकिन तब भारत यूरोप या अमरीका के देशों में महज दूसरे या पाचवे राष्ट्र का स्थापना सकेगा

चिकित्साविज्ञान काले जादू का साराश है। उच्च चिकित्साविज्ञान की कुशलता से जो नान हासिल होता है उससे नीम हकीमी कई गुना बेहतर है

भारत का उद्धार इसी में है कि उसने पिछले पचास वर्षों के अंदर जो कुछ भी सीखा है, भुला दे। रेलव्यवस्था, तार अस्पताल, वकील, डाक्टर और इस तरह के सभी साधनों को समाप्त होना होगा और तथाकथित उच्चवर्ग के लोगों का यह सीखना होगा कि वे किस तरह सचेतन ढंग से और धार्मिक रूप से साधारण किसानों का जीवन व्यतीत करें। (गांधी 'ए कंफेशन आफ फेथ', 1909, स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स', पृष्ठ 1041-43)

जाहिर है कि यह कार्यक्रम भारत की गरीबी का कोई समाधान नहीं प्रस्तुत करता है वल्कि गरीबी को वह मानव जाति के बहुमत के लिए दैवी दृष्टि मानकर आदर्श रूप प्रदान करता है।

भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि किसी भी रूप में नैतिक विकास में सहायक नहीं होती है। (गांधी 'ए कनफेशन आफ फेथ', स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स', पृष्ठ 1042)

भौतिक सुख-साधन हमारे पास जितना ही अधिक रहेगे उतना ही अधिक हम दुनिया की मोहमाया से बंधते जाएंगे। (कुमारप्पा 'व्हाई दि विलेज मूवमेंट', पृष्ठ 39)

सुख की प्राप्ति हमें भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता से नहीं होती है। (वही, पृष्ठ 65)

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भूखी और असंतुष्ट जनता को दिए जाने वाले इस तरह के उपदेशों को भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का भरपूर समर्थन और सरक्षण मिलता है। ये उद्योगपति स्वयं भी एक तरफ तो अपन फुरसत के समय में थोड़ा-बहुत चरखा कात कर आम जनता के सादा जीवन के प्रति अपनी संतुष्टि का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ मशीनों और औद्योगिक शोषण के जरिए अपार संपत्ति इकट्ठा करते हैं। संपत्ति व अधिकार के सद्भ में गांधी ने अपन सामाजिक सिद्धांत में जो कहा था उससे भी हम अपरिचित नहीं हैं।

मेरा सामाजिक सिद्धांत यह है कि हालांकि हम जन्म से एक समान हैं अर्थात् हम समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है तो भी हम सबकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं है। कुदरती तौर पर यह असंभव है कि हम सब डीलडौल में एक जैसे हों, हमारी चमड़ी का रंग एक हो और हम सबके पास एक जैसी बुद्धि हो और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर हममें से कुछ ऐसे होंगे ही जो दूसरों की तुलना में ज्यादा भौतिक समृद्धि जुटा सकेंगे। जिनके पास क्षमता है, वे अपनी क्षमता का इस्तेमाल इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। यदि वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल अच्छी भावना के साथ करेंगे तो उनका काम जनता के कल्याण के लिए होगा। ये लोग 'पासधारी' (ट्रस्टीज) होंगे और कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे अधिक से अधिक सम्मान का मौका देना चाहिए और उसे अपनी योग्यता का इस्तेमाल करने में कोई बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। (चार्ल्स पेलाश का दिया गया गांधी का इंटरव्यू, माद', 20 फरवरी 1932)

यहाँ आदर्शवाद की जाड़ में उही ज्ञान-पहचाने बुजुर्ग सिद्धांतों को पक्ष किया गया है।

इस कार्यक्रम की तत्काल व्यावहारिक रूप से जो अभिव्यक्ति हुई वह चरखा और तकली

के प्रचार में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में खादी व इस्तेमाल का बढ़ावा देने में तथा ग्रामोद्योग के विकास में दिखाई पड़ी। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग मंच का राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सहायक संस्था के रूप में संगठित किया गया। इस आंदोलन के लिए आधार कितना व्यावहारिक या यह देखना जरूरी है। विकसित बुजुर्ग अथर्वव्यवस्था के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्री अपनी व्यवस्था की ज्ञानोद्दीप्त ऊँचाइयों से इस अत्यंत पिछड़ी धारणा का बड़े बेलोंस ढंग से मजाक उड़ाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशाल समस्याओं को और उत्पादन की कमी को चरखा कातकर और आदिम तरीके अपनाकर हल कर लिया जाएगा। फिर भी इस आंदोलन को जो सीमित और आंशिक समर्थन मिला उसके कारण विद्युत् सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक समझ है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि के क्षेत्र में निराशाजनक रूप से विघटन की स्थिति मौजूद है जिसकी वजह से काफी बड़ी आबादी का इस तरह के श्रम में जुटना पड़ता है जिसमें तकरीबन वष का आधा हिस्सा वह बेरोजगारी में काटती है और यहां औद्योगिक विकास न होने के कारण चरखा, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग किसी भी रूप में एक उल्लेखनीय आबादी के लिए अस्थाई तौर पर राहत पहुंचा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम उपकरणों या साधनों का इस्तेमाल होता है।

फिर भी यह एक ऐसी दिलासा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा विकृति और अवरोधता की निरूपितता को स्वीकार करने पर आधारित है और इसका मकसद इन बुराइयों को समाप्त करने के बजाय अपने का इनके अनुसार ढालना है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पूँजीवादी जगत में हस्तउद्योग को फिर से स्थापित करने के कृत्रिम प्रयास का कोई भविष्य नहीं है। कीमत के मामले में खादी का कपड़ा मिल में बने कपड़े का मुकाबला नहीं कर सक्ता और इसलिए यह अत्यंत निधनवर्ग की पहुंच के बाहर है। गांधी ने अपने पत्र 'हरिजन' के 19 जनवरी 1938 के एक में शिकायत की थी कि कांग्रेस संविधान में खादी से संबंधित धारा का पालन से ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है और उन्होंने अपने देशवासियों से अपील की कि 'विदेशी कपड़ा जला मुलायम, आकषक तथा सस्ता न होने के बावजूद व खादी का ही इस्तेमाल करें।' पहली दिक्कत (अर्थात् मुलायम और आकषक न होना) को देशभक्तिपूर्ण अपील से दूर किया जा सकता है लेकिन दूसरी दिक्कत (सस्ता न होना) काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आम भारतीय की मौजूदा आय बहुत कम है। यहां एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत जैसे अत्यंत गरीब देश में उत्पादन के ऐसे श्रमसाध्य और आदिम साधनों की जरूरत नहीं है जिससे अधिक से अधिक महानत से कम से कम उत्पादन हो बल्कि अत्यंत आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जरूरत है जिससे काफी तेजी से अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके ताकि गरीबी पर काबू पाने के साधन उपलब्ध हों। वंशक यह ध्यान देने का बात है कि अपनी वाद की घोषणाओं में गांधी ने आधुनिक मशीनों के बारे में अपने विचारों में तनाव नहीं दिया और यह तब पत्र किया जाता कि उन्होंने ग्रामोद्योग के बारे में 'हरिजन' में अपने वाद के एक लेख में कहा कि 'मशीनीकरण उस स्थिति में अच्छा है जब निर्धारित काम

का पूरा करन के लिए बहुत कम हाथ हो। जब काम की जरूरत से ज्यादा हाथ हो तो मशीनीकरण एक बुराई है और भारत में यही स्थिति है।' इस तक मछिपी प्रतिक्रियावादी भ्रांति स्पष्ट है।

भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए एक आदिम अव्यवस्था का प्रचार करना महज इसलिए प्रतिक्रियावादी काम नहीं है क्योंकि यह सारी कोशिशों को मूल समाधान की विपरीत दिशा में ले जाता है (क्योंकि गरीबी और दुखदद को वर्तमान बुराईया की जड़ आदिम तकनीक ही है और यह अपने आप में उस समाजव्यवस्था की जड़ में मौजूद है जो साम्राज्यवाद के तहत शोषण की शिकार है) बल्कि यह किसानों और आम जनता का ध्यान उन बुनियादी सामाजिक समस्याओं से हटाता है जो उनके सामने अपने भीषणतम रूप में खड़ी हैं। जब तक जमीन, जमींदारी प्रथा और जमीन के पुनर्वितरण की समस्या से नहीं निबटा जाता, तब तक कृषि में क्षेत्र में विवास असंभव है। लेकिन इस स्थल पर खेतिहर आदशवादियों और लुप्त ग्रामीण समुदाय के पुजारियों की आवाज धीमी पड़ जाती है जबान लड़खड़ान लगती है और जमींदारी प्रथा के पक्ष में अस्पष्ट सकोचपूर्ण दलील में डूब जाती है। गांधी ने संयुक्त प्रांत के जमींदारों से 1934 में कानपुर में जो बातचीत की थी वह काफी मशहूर है। जमींदारों द्वारा समाजवाद के खतरा का भय प्रदर्शित करने पर गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 'जमींदारों और काश्तकारों के बीच अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं और इसके लिए दोनों का हृदय परिवर्तन करना होगा। मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूँ कि तालुकेदारी या जमींदारी प्रथा का समाप्त किया जाए।' उन्होंने आगे कहा

मैं संपत्तिवान वर्गों को बिना किसी उचित कारण के उनकी निजी संपत्ति से वंचित कराने का काम में कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। मेरा लक्ष्य आपके हृदय तक पहुंचकर उसका इस तरह से परिवर्तन करना है ताकि आप अपनी सारी निजी संपत्ति को अपने काश्तकारों के लिए 'यास' का रूप दे दें और इसका इस्तेमाल जब मुख्यतया उनकी खुशहाली के लिए करें। मेरी कल्पना में जो रामराज्य है उसमें राजा और रक दोनों के अधिकारों की गारंटी शामिल है। आप निश्चित रह सकते हैं कि किसी तरह का वगसंधप रोकने में मैं अपने प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए कि आपको आपकी संपत्ति से वंचित करने का कोई अन्यायपूर्ण प्रयास होता है तो वैसी हालत में आप मुझे अपनी ओर से लड़ना पाएंगे। हमारा समाजवाद या साम्यवाद अहिंसा पर तथा श्रम और पूँजी एवं जमींदार और काश्तकार के बीच सद्भावपूर्ण सहयोग पर आधारित होना चाहिए। (गांधी की संयुक्त प्रांत के जमींदारों के शिष्टमंडल से भेंटवार्ता, जुलाई 1934, 'महरट्ठा', 12 अगस्त 1934)

हमने पहले भी कई बार देखा है कि किस प्रकार गांधी ने इसी तरह से औद्योगिक पूँजीपति

का पक्ष लिया है और वगनगण पर आधारित मजदूर गगणा का विराध लिया ।

यदि बडे बुजुआ के दृष्टिकोण म दय जो एक मुस्मान के साथ अपनी आदशवादी उत्कठाओं और भोलीभाली अद्भुत कल्पनाओं का खेलना या कभी कभी प्रोत्साहित भी करता होता है तो इस उपदेश का व्यावहारिक महत्व समझ म आ जाएगा । वे जानत है कि अपन वग-हिता की रक्षा के लिए और जनता का काठू म रखकर शांति बनाए रखन के लिए इनका व्यापारिक महत्व कितना है । आधुनिक युग की नाजुक सक्रमणशील स्थितियों म बुजुआ राष्ट्रवाद के अभीष्ट प्रतिनिधि और याग्यतम नता के रूप म गांधी की ऐतिहासिक भूमिका का जा सामाजिक महत्व है, यह उनके सामाजिक दशन और बुजुआ दृष्टिकोण के बीच के सतही अंतर्विरोध का बावजूद व्यवहार म उनकी राजनीतिक भूमिका से मल पाता है । उनके भाषणा और प्रवचना म जो अंतर्विराध और दाप दिखाई देत है, जिसे कोई भी सामान्य आलाचक्र भाप सकता है वही दरअस्त उनकी अद्भुत सफलता और उपलब्धि का रहस्य है । दम सक्रमणकाल म दूसरा ऐसा नता न था जो राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविक बुजुआ दिशा और सजग होती हुई (किंतु जो उस समय तक पूरी तरह जागरूक न थी) जनता के बीच की खाई को पाट सपता । शुभ और अशुभ दोनों के लिए गांधी ऐसा कर सके थे । उन्होंने आंदोलन को नतृत्व दिया यहां तक कि ऐसा लगता था मानो आंदोलन को उद्धान ही जम दिया था । उनकी यह भूमिका तभी समाप्त हुई जब जनता धीरे धीरे अपने वगहिता को स्पष्ट रूप से पहचानने लगी और भारतीय दृश्यपटल पर वास्तविक वगशक्तियों तथा वगसबधों न कल्पनिक तथा धार्मिक आवरण का सहारा लिए बिना डटना शुरू किया ।

फिर भी औद्योगिक बुजुआ ने गांधीवाद को यद्यपि बहुत खुलकर नाम के लिए अपना और जनता का नता माना पर राष्ट्रीय आंदोलन के आवश्यक कार्यक्रम के रूप म प्रगतिशील औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के माग म इसे कभी नहीं आने दिया । यहां सामाजिक रुढ़िवाद को सिद्धांत म चाह यह कुछ भी उपदेश क्यों न दे व्यवहार म बदलना पडा । भारतीय मिलों म बने कपडे के समान अधिकार को स्वीकार किया गया और 1930 के गांधी के 11 सूत्री प्रस्ताव को माना गया जो सामान्यतया बुजुआ व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय कार्यक्रम था । जैसाकि 1938 के औद्योगिक नियोजन कार्यक्रम के बाद कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना आयोग से पता चलता है राष्ट्रिय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ अत्यंत तीव्र औद्योगिक विकास की योजना म जुट गए ।

औद्योगिक विकास के बारे म कांग्रेस के आधुनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष ने 1938 म इंडियन साइंस एसोसिएशन की वार्षिक बैठक म की । इस बैठक म प्रोफेसर साहा ने सवाल किया था

क्या मैं जान सकता हूँ कि जान वाले कल का भारत ग्राम्य जीवन के दर्शन को या बलगाड़ी दशन को फिर से जीवित करने जा रहा है जिससे गुलामी का शाश्वत बनाया जा सके अथवा यह एक ऐसे आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र का रूप लेने जा रहा है जो अपने सभी प्राकृतिक साधनों का विकास करके गरीबी, अज्ञानता और मरुता की समस्याओं को हल कर सके और राष्ट्रों के सौजन्य में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सभ्यता का एक नया चक्र शुरू कर सक ?

राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस ने जवाब दिया

राष्ट्रीय विकास का काम विज्ञान की मदद से ही संभव है भारत आज भी विकास की पूँव औद्योगिक अवस्था में है। कोई भी पुनरुज्जीवन या पुनरुत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक भारत एक औद्योगिक क्रांति की यातना से न गुजरे। हम चाहे इसे पसंद करें या नहीं लेकिन हम यह तथ्य मानना होगा कि आधुनिक इतिहास का वर्तमान युग औद्योगिक युग है। औद्योगिक क्रांति से बचने का कोई उपाय नहीं है। अधिक से अधिक हम यही तय कर सकते हैं कि यह क्रांति अर्थात् उद्योगीकरण का काम ग्रेट ब्रिटेन की तरह अपेक्षित धीरे धीरे हो या सोवियत रूस की तरह तेजी के साथ जिसमें अधिक प्रयत्न की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ कि इस देश में भी यह काम तेजी से होना है।

इस प्रकार व्यावहारिक अनुभव और विकास ने पुरानी आधिभौतिक अटकलवाजियों का जवाब दे दिया। सत्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र से सामाजिक रुढ़िवादिता अब जा रही है सिवाय कुछ पुराने त्रमा के जो अब भी घिसट घिसट कर अपना अस्तित्व बनाए हुए है, पर वे अब नीतिनिर्देशन का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार यह बात सामने आई कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में व्यावहारिक रूप में तीन नहीं बल्कि दो मुख्य प्रवृत्तियाँ, वर्गीकरण, कार्यक्रम और नीति हैं। एक तो प्रमुख औद्योगिक उर्जुजा प्रवृत्ति जिसकी निम्न पूँजीपतिवर्ग के समूहों पर अलग अलग छाप है और दूसरी औद्योगिक मजदूरवर्ग की समाजवाद की प्रवृत्ति जो मजदूरों, गरीब किसानों और शहरी निम्न पूँजीपतिवर्ग के निचले तबके के हितों को अभिव्यक्त करती है। नीति विषयक इन दो प्रमुख धाराओं के बीच विभिन्न कार्यक्रम, नेतृत्व और वर्ग एक समूह बनाते हैं हालाँकि इनकी नीति अक्सर बहुत साफ नहीं होती। इन वर्गों के आपसी संबंधों और शक्ति संबंधों पर, जो अपने भिन्न सामाजिक लक्ष्यों के बावजूद राष्ट्रीय मंच और कुछ सीमा तक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्यों की दिशा में फिलहाल एक साथ चढ़ सकते हैं भारतीय राजनीति में विकास का भावी मार्ग निर्धार है।

### 3 पुनर्निर्माण, उद्योगीकरण और समाजवाद

आधुनिक युग में राष्ट्रीय आंदोलन में उद्योगीकरण का केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण

के दूरगामी कार्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया है। अक्टूबर 1938 में दिल्ली में प्रांतीय सरकारों के उद्योगमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें पक्ष प्रस्ताव में कहा गया था

उद्योगमंत्रियों के इस सम्मेलन की धारणा है कि गरीबी और बेरोजगारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक तौर पर आर्थिक पुनरुत्थान की समस्याएँ उद्योगीकरण के बिना हल नहीं की जा सकती। उद्योगीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में राष्ट्रीय नियोजन की एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए

विभिन्न प्रांतीय सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद सम्मेलन की यह राय है कि जब तक व्यापक औद्योगिक योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के निम्नांकित बड़े उद्योगों को शुरू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहाँ तक संभव हो सभी प्रांतों तथा रियासतों को मिलकर प्रयास करना चाहिए

- (क) सभी तरह की मशीनों, यंत्रों और औजारों का निर्माण,
- (ख) मोटरगाड़ियाँ, मोटरचालित नौकाओं, आदि तथा इनके सहायक उपकरणों और परिवहन तथा संचार व्यवस्था से संबंधित अन्य उद्योग,
- (ग) विद्युत यंत्रों और इनके सहायक उपकरणों का निर्माण,
- (घ) भारी रसायन और उर्वरकों का उत्पादन,
- (च) धातु उत्पादन,
- (छ) बिजली पैदा करने और बिजली सप्लाई करने से संबंधित उद्योग।

इस प्रस्ताव के अनुरूप कांग्रेस कार्य समिति की निर्देशन में एम. अखिल भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों का सारांश पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

पुनर्निर्माण और नियोजित विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ भारत में तैयार की जा रही हैं या इनपर विचार किया जा रहा है। भारतीय उद्योगपतियों की सबसे बड़ी योजना, 'ए. प्लान आफ इकनामिज डेवलपमेंट फॉर इंडिया' (जिसे आमतौर से 'बर्ड योजना' कहते हैं) का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 1944 और 1945 में इसे दो भागों में प्रकाशित किया गया था। 100 अरब रुपये की वृद्धि पूँजी व्यय करने के कार्यक्रमवाली इस योजना के तहत के अनुसार 15 वर्षों के अंदर कुल राष्ट्रीय आय में तीन गुणो वृद्धि हो जाएगी जिससे इस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से उद्योग पर निर्भर रखा गया है। उपर्युक्त योजना के निर्माताओं ने प्रस्तावित किया था कि उद्योगों

हान वाली आय में ५०० प्रतिशत वृद्धि में होनी वाली आय में १३० प्रतिशत और सेना में होनी वाली आय में २०० प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ताकि कुल राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान मौजूदा १७ प्रतिशत की बजाय ३५ प्रतिशत, कृषि का योगदान मौजूदा ५३ प्रतिशत की बजाय ४० प्रतिशत और सेना का योगदान मौजूदा २२ प्रतिशत की बजाय २० प्रतिशत हो जाए। उद्धान बुनियादी उद्योगों का वरीयता देने की मांग की है, इन उद्योगों में विजली, धान, इंजीनियरिंग, रसायन, जहाजनिर्माण, आटोमोबाइल्स और विमान निर्माण आदि शामिल हैं। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जान की योजना है।

इस योजना में वैसे तो बड़े प्रशासनीय उद्देश्य शामिल किए गए हैं लेकिन इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तों की उपेक्षा कर दी गई है। इस योजना में भारत में उद्योग धंधों के विकास पर लग बुनियादी ढरणा को जमींदारी प्रथा के जानलेवा नियंत्रण को तथा ब्रिटेन के निहित स्वार्थों के प्रभुत्व का समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। न तो राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण की समस्या को किसी प्रभावकारी ढंग से हल किया गया है। यहाँ तक कि काफी हद तक वित्त की आपूर्ति मुद्रास्फीति और विदेशी पूँजी के जरिए करने की व्यवस्था है। सचार्ई यह है कि राष्ट्रीय हितों का बढ़ाने के लिए कोई स्वतंत्र औद्योगिक विकास का खाका सामने रखने की बजाय इस योजना में यह गंध मिलती है कि भारतीय युजुआवग जब ब्रिटिश महाजनी पूँजी के साथ मिलकर शापण करने का प्रयास करेगा। जीवनस्तर उठाने के सिलसिले में जो बड़ चढ़कर बातें की जाती थी उनके पीछे असली इरादा क्या था यह उस समय बहुत स्पष्ट हो गया जब इस योजना के तीन प्रमुख प्रवक्ता जे० आर० डी० टाटा, धनश्यामदास विडला और सर श्रीराम ने ब्रिटिश पूँजीपतियों के साथ समझौते कर लिए।

भारत के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उद्योगीकरण की आवश्यकता को एक मुख्य व्यापक कार्यक्रम के रूप में सामान्य रूप से और अधिकाधिक सुस्पष्टता के साथ स्वीकार कर लेना ही राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन साथ ही यह भी जाहिर है कि इस तरह के कार्यक्रम के प्रश्न के साथ कुछ नए तरह के दूरगामी मसले पैदा हो जाते हैं जिनका सबंध आवश्यक स्थितियों तथा इस कार्यक्रम की पूर्ति के तरीकों से तथा इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली सामाजिक शक्तियों की क्षमता से है। जैसाकि जनक विकसित पूँजीवादी देशों में देखा गया है, आर्थिक संकट के सद्मे के कारण तथा सोवियत संघ में समाजवादी योजना की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक देशों में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया है लेकिन यह काम बहुत अमूर्त तकनीक के साथ हुआ है और इस अवधारणा को स्वीकार करते समय न तो उन विभिन्न नियमों की ध्यान में रखा गया जो पूँजीवादी और समाजवादी अव्यवस्था को संचालित करते हैं और न वास्तविक सामाजिक तथा वंशशक्तियों को ही ध्यान में रखा गया। पूँजीवादी देशों के अनुभव ने इस तरह के दृष्टिकोण की कमजोरी को पूरी तरह साबित कर दिया है।



इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना तो भारत जैसे देश में मध्य भी नहीं क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ वस्तुतः क्रांतिकारी सामाजिक स्थापत्य की प्रक्रिया में गुजर रहा है और जहाँ भूमे मजदूरों तथा किसानों की मांगों को अनिवार्य रूप से परिवर्तन की निर्णायक प्रेरक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान लेना होगा। आर्थिक पुनर्गठन के प्रश्न को बुनियादी सामाजिक और वर्गीय मसलों से अलग नहीं किया जा सकता।

भारत के उद्योगीकरण का काम और मौजदा निधनताग्रस्त निम्न तकनीक के स्तर से उठाकर इसे विकसित तकनीकवाले देशों के स्तर तक पहुँचाने का काम एक ऐसा विशाल कार्य है जिसके लिए अत्यंत विराट शक्तियाँ की जरूरत हैं। इसने लिए समूची जागदी के सक्रिय सहयोग को जरूरत है। इसके लिए देश की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था के निर्णायक स्थला पर राजसत्ता का अपने हाथ में होना जरूरी है।

क्या भारतीय बुर्जुआ यह काम पूरा कर सकता है? क्या भारत की जनता एक तब मध्य के द्वारा आजादी हासिल करने के बाद देश का मुट्ठी भर शापकवर्ग का सौपना और पुद को गुलामी की बेडिया में जकड़ना पसंद करगी? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है ताकि यह बताया जा सके कि भारत में आर्थिक और सामाजिक प्रगति का काम उद्योगीकरण का काम तथा नए समाज की स्थापना का काम पश्चिमी दशा के प्रारम्भिक पूँजीवाद के दिना की औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया से बुनियादी तौर पर भिन्न होना चाहिए। पूँजीवाद के ह्रास तथा अंतराष्ट्रीय सवहारा क्रांति के विकास के दौर में भारत में हो रहे उद्योगीकरण और आर्थिक पुनर्गठन का काम निश्चित रूप से अपने अनुकूल स्वरूपों और तरीकों के जरिए पूरा होगा।

उद्योगीकरण का काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह पुनर्गठन नहीं है। यह आज भी भारतीय अव्यवस्था की मुख्य समस्या है। यदानी प्रक्रियाएँ दरजस्त एक दूसरे की पूरक हैं। यहाँ तक कि पूँजीवादी अव्यवस्था की स्थितियों में भी जब तक खेती में लगी जनता गरीबी की निम्नतम सीमा पर रहती है और औद्योगिक उत्पादना के लिए देश में बाजार तैयार नहीं होता है तब तक औद्योगिक विकास बाधित और पगु बना रहता है। इसकी उलटी स्थिति यह है कि कृषि के क्षेत्र में पुनर्गठन के लिए औद्योगिक विकास जरूरी होता है क्योंकि औद्योगिक विकास के जरिए ही सत्ती के लिए मशीनें मिलती हैं और मशीनें ही उत्पादन का स्तर ऊँचा उठाती हैं तथा बड़े बड़े बाजार पड़े सत्ती को जोतती जाती हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास से उन लाघा लोगों को काम मिलना है जो खेती पर जरूरत से ज्यादा बान होने के कारण गरीबी और अध धराजगारी का जीवन बिता रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में पुनर्गठन से खेती पर तब अत्यधिक बोध से छुटकारा मिलता है।

लेकिन जसाकि इस समस्या से संबंधित स्थितियों की तीसर अध्याय में की गई जान

पडताल से पता चलता है, कृषि के क्षेत्र में पुनर्गठन के लिए जरूरी है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, खेतिहर जातों का बुनियादी तौर पर पुनर्वितरण हो, अलाभकर जीतों की दिवालिया प्रणाली को समाप्त किया जाए और खेती की आदिम छोटे पैमाने वाली तकनीक से धीरे धीरे बड़े पैमाने पर की जाने वाली सामूहिक खेती की दिशा में बढ़ा जाए। इसका कोई अधूरा समाधान यहाँ संभव नहीं है। कृषि के क्षेत्र में 'सुधार' की बात करना और जमींदारी प्रथा को ज्यों का त्यों बना रहने देना, 'विकसित' खेती का प्रवचन देना और वर्तमान भूमि वितरण व्यवस्था पर आच न आन देना, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। भारत की जो वर्तमान निराशाजनक स्थिति है उसमें मौजूदा जमींदारी प्रथा और उपजमींदारी प्रथा की बेतहाशा परजीविता को, किसानों पर असौम्य बोझों की जयवा भूमि की वर्तमान जोत व्यवस्था तथा खेती की भयंकर दरवादी को न तो कोई गुजाइश है और न इन घामियाँ को चेलने के लिए साधन ही उपलब्ध हैं। भारत के प्रमुख कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी ने जो अपने दृष्टिकोण में किसी भी अर्थ में समाजवादी नहीं हैं, तो 1945 में अपने जागरण एक्सपोज़िशन लेक्चर में यहाँ तक कहा है कि भारतीय कृषिव्यवस्था में तभी तक कोई सुधार संभव नहीं है जब तक 'भारत के गाँवों में बिखरी छोटी छोटी जीतों को मिलाकर एक सहकारी फार्म न बना दिया जाए और कृषि को एक सामूहिक सेवा न माना जाए।' यह काम महज एक छलांग में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस दिशा में पहला कदम यह हो सकता है कि जमींदारी प्रथा समाप्त की जाए, और खेतिहर जीतों का पुनर्वितरण हो तथा इसके बाद सरकारी सहायता, सहकारी संस्था से ऋण सुविधाओं तथा कृषि तकनीक को उन्नत बनाने के लिए डिपो केंद्रों से खेती के काम करने वाली मशीनों को उधार के रूप में देने की व्यवस्था की जाए। कृषि क्रांति से कतराकर नहीं निकला जा सकता। यह परिवर्तन की मुख्य प्रेरक शक्ति है और नए भारत की आधारशिला है।

फिर भी यही वह स्थल है जहाँ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के भावी नतीजे के रूप में भारतीय बुर्जुआवर्ग की कमजोरी बहुत खुलकर सामने आती है। अपनी उन्नति और विकास की स्थितियों की वजह से भारत का औद्योगिक और व्यापारिक बुर्जुआवर्ग जमींदारवर्ग के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, संपत्ति के हितों और स्वरूपों में एक अतिसंबंध है। इसलिए प्रगतिशील बुर्जुआ ने भूमिव्यवस्था में बुनियादी सुधार की समस्या को हल करने में तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में हमेशा हिचकिचाहट दिखाई है भले ही ये चीजें भारतीय अव्यवस्था या भारत के औद्योगिक विकास के लिए कितनी भी जरूरी क्यों न हों? 1946 के कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रम में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के सिद्धांत को मान लिया गया था लेकिन इसके लिए यह आधार तय किया गया था कि जमींदारों को बदले में 'उचित मुआवजा' दिया जाए जिसका अर्थ वस्तुतः किसानों पर बोझ का बना रहना ही है। इसी प्रकार 1946 में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति के तत्वावधान में प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम का जो मसौदा प्रकाशित हुआ था उसमें बड़े शक्त भाव से यह प्रस्ताव रखा गया था कि किसानों का दिया

जान वाला भ्रष्ट सरकार द्वारा निधिवद्ध होना चाहिए जिसका 10 प्रतिशत किमानो से लिया जाना चाहिए, जिसमें ने 5 प्रतिशत भाग सूदखोरो को चला जाएगा और 5 प्रतिशत से प्राथमिक शिक्षा का खर्च चलेगा ।

भूमिस्वयंस्वयं की दुनियादी समस्या हल करने में भारतीय वर्जुआवग की हिचकिचाहट का मुख्य कारण महज यही नहीं है कि जमींदारवग के हितों के साथ उसके हित में खात है या जमींदारवग के साथ उसका घनिष्ठ अंतर्मर्बध है बल्कि इस हिचकिचाहट के पीछे यह भय भी काम करता है कि कृषि शक्ति से व सामाजिक शक्तिया छूट निकलेगी जो इस वर्जुआवग के विशेषाधिकारों संपत्ति के पूँजीवादी स्वामित्व के समूचे आधार और शोषण को समूल नष्ट कर दगी । भारतीय वर्जुआ का साम्राज्यवादविराधी सघष को पशु प्रान के लिए और इस प्रकार राष्ट्रीय सघष को भीतर में कमजोर करने के लिए साम्राज्यवादियों ने बड़ी चालाकी से और लगातार इस मय को खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया है । साड हली (तत्कालीन सर मैलबोम हली) ने 1924 में ही स्वराज पार्टी को चेतावनी देने के लिए विधानसभा में यह तक पेश किया था

भारत में यदि सही अर्थों में शांति जैसी कोई घटना हुई तो इसका उस वग पर बहुत घातक जमर पड़ेगा जिसका इस समय विधानसभा और प्रांतीय कौंसिला में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि ज्ञानता में डूबी भारतीय जनता के बीच कोई भी राजनीतिक शांति बहुत कम समय में सामाजिक शांति का रूप लेगी ।

इस वक्तव्य के साथ गांधी के इस स्पष्ट कथन की तुलना की जा सकती है जो जनवरी 1940 में उनके पत्र 'हरिजन' में छपा था

कांग्रेस व एक काफी प्रभावशाली मदस्व ने मुझसे कहा है कि इस बार जस ही मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा मुझे बहुत आश्चर्यजनक प्रतिनिध्या देखने को मिलेगी । उन्होंने मुझे अप्पवामन दिया कि देश के अनेक हिस्सा के मजदूर किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही हड़ताल छेड़ देंगे । मैंने उनसे बताया कि यदि ऐसा हुआ तो मैं बहुत उत्सहन में पड़ जाऊंगा और मेरी सारी योजना ही अस्त-व्यस्त हो जाएगी मैं जाशा करता हू कि मुझसे यह अपक्षा नहीं की जाती है कि मैं जानबूझकर कोई ऐसा मघप छेड़ूंगा जिसकी परिणति अराजकता और खनरजिन तनावही हो ।

सभी देशों के दकिमानूस प्रतिक्रियावादी दसी उहुप्रचलित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि मजदूरों और किसानों की कायनाही से 'खनरजिन तनावही' हा जाएगी और वे साम्राज्यवाद तथा राष्ट्रीय वर्जुआ के लिए एक ही मय प्रदान करत ह ।

इस प्रकार भारतीय स्थिति के प्रत्यक्ष अनुभव न और इसकी पहले के किसी भी दौर की तुलना में तीव्र आवश्यकताओं ने, राष्ट्रीय सघन में वृद्धि के नतीजों की विफलता और कमजोरी के बार-बार के अनुभव ने तथा इन सबसे बढ़कर मजदूरवर्ग की उदीयमान शक्ति, सन्नित्यता और चेतना ने तथा किसान क्रांति को सपना करने वाली शक्तियों की एकजुटता ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक दौर में समाजवाद के प्रश्नों को अपरिहार्य रूप से अगली पक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में समाजवाद की अवधारणा भविष्य की कोई अमूर्त अटकलवाजी नहीं है जो विदेश से आयात की गई हो बल्कि यह भारतीय स्थितियों और भारतीय अनुभव का सीधा उत्पाद तथा परिणाम है जिसने हर देश की ही तरह विश्व आंदोलन के अनुभव, सिद्धांत और व्यवहार का इस्तमाल किया है। भारत में मजदूरवर्ग का आंदोलन आज भी विकास की प्रक्रिया में है, यह आज भी अपने संगठन, अपने कार्यक्रम की स्पष्टता, अनुभव और जन जागरूकता को मजबूत कर रहा है लेकिन सभी लोग यह मानने लगे हैं कि यह भविष्य की एक उभरती शक्ति है।

राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर समाजवादी विचारधारा के प्रभाव का और राष्ट्रवाद के साथ समाजवाद के संबंध को प्रचारित करने के काम को पिछले दशक में 1929 और 1936-38 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की साप्ताहिक स्थिति में विशिष्ट अभिव्यक्ति मिली। जवाहरलाल नेहरू हमेशा संगठित समाजवादी आंदोलन से बाहर रहें लेकिन उन्होंने उभरती हुई समाजवादी विचारधारा और अपेक्षाकृत पुराने नतीजों के बीच एक पुल का काम किया। नेहरू ने राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक मुक्ति के बीच के घनिष्ठ संबंध को एकदम सामने ला दिया।

विदेशी सरकार के स्थान पर यदि कोई देशी सरकार स्थापित होती है और उस समय भी निहित स्वार्थ ज्यों के स्थापित रहते हैं तो यह आजादी की छाया भी नहीं होगी।

इसलिए भारत का तात्कालिक लक्ष्य महज यही होना चाहिए कि उसकी जनता का शोषण समाप्त हो। राजनीतिक रूप से इसका अर्थ स्वाधीनता तथा ब्रिटेन के साथ संबंधों की समाप्ति अर्थात् साम्राज्यवादी प्रभुत्व की समाप्ति होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इसका अर्थ सभी जाति वर्गों के विशेषाधिकारों और निहित स्वार्थों की समाप्ति होना चाहिए। (जवाहरलाल नेहरू 'विदर इंडिया' ? 1933)

यह मानते हुए कि राष्ट्रीय सघन में कांग्रेस समाजवादी और गैरसमाजवादी तत्वों के सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है और गैरसमाजवादी तत्वों का फलहाल बहुमत है, उन्होंने यह उताया कि बिना प्रचार यह यह आशा करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ेगा।

मैं भारत की आजादी के लिए सघष कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भीतर जो राष्ट्रीय तत्व है वह कभी विदेशी प्रभुत्व का वरदास्त नहीं कर सकता, मैं आजादी के लिए इसलिए भी सघषरत हूँ क्योंकि मेरे विचार से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए यह एक अनिवार्य कदम है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस एक समाजवादी संगठन का रूप ले और नई सम्यता के लिए दुनिया की जो अन्य शक्तियाँ काम कर रही हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का आज जो स्वरूप है, उसमें अधिकांश कांग्रेसी शायद इसके लिए तैयार न हों।

इस देश में समाजवाद के विकास की जबरदस्त इच्छा के बावजूद मैं दस प्रश्न को कांग्रेस पर धोपना नहीं चाहता और अपने स्वाधीनता सघष में कोई कठिनाई नहीं पैदा करना चाहता। मैं खुशी खुशी और अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों के साथ सहयोग करूँगा जो आजादी के लिए काम कर रहे हैं भले ही वे समाजवादी समाधान से असहमत क्या न हों। लेकिन मैं अपनी स्थिति बड़े साफ शब्दों में स्पष्ट करके ही ऐसा करूँगा और यह आशा करूँगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और देश को समाजवादी विचारधारा में ढाल लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करके ही आजादी मिलेगी। (जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण, 1936)

यह कांग्रेस के धीरे धीरे समाजवाद में रूपांतरित होने की एक तत्त्ववीर पेश की गई है। समाजवाद में रूपांतरण के बीच की अवधि में एक अस्थायी सतुलन भी बनाए रखा गया। फिर भी इस अवधारणा में उन बग शक्तियों के वर्तमान सघष को परे रखा गया है जो अनिवार्य रूप से कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस तथा आम जनता के बीच के सघष के मसले में अभिव्यक्त होती है। परिणामतः यह अवधारणा राष्ट्रीय एकता के नाम पर वर्गों के बीच समझौते का मिश्रित बन जाती है और इस तरह का बग समझौता व्यवहार में उस राष्ट्रीय वुजुआ नेतृत्व के इशारे पर चलता है जो सक्रिय राष्ट्रीय सघष के विकास को पीछे खींचता है।

इसमें कोई सघष नहीं है, और यह प्रगतिशील भारतीय जनमत के दिमाग में अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की समस्याओं को समाजवादी रास्ते पर चलकर ही हल किया जा सकता है। समाजवादी उद्योग और सामूहिक कृषि के जरिए ही अंतिम तौर पर वे साधन प्राप्त हो सकते हैं जो भारत को दुनिया भर के कूड़े-कचरे में उठाकर समृद्धि और उत्थास की धरती बना दें। अपन पूँण स्वरूप में विकसित और नेतृत्व की भूमिका प्राप्त मजदूरवर्ग तथा तमाम बघना से मुक्त मेहनतकश किसानवर्ग की जबरदस्त सामाजिक शक्तियाँ ही अंत्यतः कुशाग्र बुद्धिवाले प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और निम्न पूँजीवादी तत्वों के

के लोगो को अपने साथ लेकर गंदगी से भरे अस्तवल को अंतिम तौर पर साफ कर सकेंगी और भारत में नए समाज का निर्माण कर सकेंगी।

दूर बैठे किसी प्रेक्षक को भले ही भारत की भविष्य के बारे में यह दृष्टि काफी दूर की बात लगे लेकिन बात ऐसी है नहीं। भारत के समाजवादी भविष्य की गतिशील शक्तियाँ, औद्योगिक मजदूरवर्ग और जागृत किसानवर्ग की शक्तियाँ पहले से ही एकजुट हो रही हैं और राजनीतिक रंगमंच पर दिन ब दिन बड़ी स्पष्टता के साथ अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना रही हैं। एक बार जैसे ही मजदूरवर्ग ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त कर और वर्गसंघर्ष के दृढ़ आधार पर अपनी राजनीतिक पार्टी और टेड यूनियन संगठन के जरिए संगठन और राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता को प्राप्त कर लिया और जैसे ही उसने एक बार गरीब किसान जनता तथा अपने किसान संगठन बना रहे खेतिहर सर्वहारा के साथ संपर्क और सहयोग कायम कर लिया तब ही मेहनतकशवर्ग के भारतीय गणराज्य की प्राप्ति के लिए स्थितियाँ तैयार हो जाएंगी। यह गणराज्य मजदूरों और किसानों की जनतांत्रिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। इस गणराज्य में मजदूरों और किसानों के साथ होंगे प्रगतिशील बुद्धिजीवी तथा शहरी निम्न पूँजीपतिवर्ग के अल्पतम जो अपने सामूहिक प्रयास से उस रास्ते पर सामाजिक पुनर्निर्माण की नींव डाल सकते हैं जो समाजवाद की ओर जाता है।

इस सदर्भ में सोवियत संघ और वहाँ विकसित नए तरह के जनतंत्र के अनुभव का भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्व है और इस अनुभव से लाभप्रद सबक लिया जा सकता है। क्रांति से पूर्व के पुराने जारशाही रूस और वर्तमान भारत की स्थिति के बीच बुनियादी मतभेद है और दोनों की स्थितियाँ या यांत्रिक ढंग से कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह अंतर खासतौर से एक साम्राज्यवादी देश और एक उपनिवेश की स्थितियों के बीच का अंतर है फिर भी सामाजिक शक्तियों और रूस में पैदा हुई विशेष तरह की समस्याओं के सदर्भ में जिनका समाधान किया गया, दोनों देशों में महत्वपूर्ण साम्य है जिनका आज भारत के लिए बहुत महत्व है। भारत में हम एक ऐसे विदेशी तानाशाह शासन की तस्वीर देखते हैं जो दिनोदिन कमजोर होता जा रहा है और जो प्रतिस्पर्धावाद सामंती शक्तियों को अपने टिके रहने का आधार बना रहा है। यहाँ हम एक कमजोर औद्योगिक बुर्जुआवर्ग को देखते हैं जो तानाशाही शासन का बड़े ढुलमुल ढंग से विरोध करके आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा तो रखता है पर साथ ही वह जनशक्ति से भी भयभीत है। यहाँ हम एक उभरते हुए मेहनतकशवर्ग को देखते हैं जो संख्या में तो कम है लेकिन बड़े पैमाने पर फैले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में (अपेक्षाकृत अत्यंत सीमित महत्वपूर्ण केंद्रों में) जमा है और अत्यंत जुझारू चमकेतना तथा सक्रियता का परिचय दे रहा है। यहाँ हम आवादी के एक विशाल भाग के रूप में किसानों को देखते हैं जो पुरातन भूमिब्यवस्था की अत्यंत पिछड़ी स्थितियों में रह रहे हैं जिन्हें अज्ञान और अशिक्षा की बड़ियाँ में बंद रखा गया है, जिन्हें

राजा के गहन अधिकार में डेल दिया गया है पर जो कृषि के क्षेत्र में बुनियादी रूपांतरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

भारत जैसी सामाजिक स्थितियों वाले देश में यह स्पष्ट है कि जनतंत्र का सर्वाधिक उचित स्वरूप समदीय जनतंत्र न हो बल्कि ऐसा स्वरूप हो जो जनता की स्थितियों और जीवन की काफी अनुरूप हो और मेहनतकश किसानों की ग्रामीण परिपदों को कारखाना मजदूरों की परिपदों तथा अन्य ऐसे संगठनों से जोड़ता हो। जनतंत्र का यह स्वरूप ही सोवियत जनतंत्र है। सोवियत जनतंत्र आम जनता, कारखाना मजदूरों और ग्रामीण किसानों के काफी निकट है। किसी भी अर्थ रूप की अपेक्षा सोवियत जनतंत्र ही मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और शहरी निम्न पूँजीपतिवर्ग की रचनात्मक शक्ति का उद्धार कर सकता है। समाज के इन वर्गों को अभी तक वर्तमान व्यवस्था में सबके कल्याण के लिए तथा नए भारत के निर्माण के सामूहिक काम में सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने से रोका गया है।<sup>4</sup>

भारत के लिए और खास तौर से देश के पिछड़े इलाकों तथा देश के मूल निवासियों की श्रेष्ठ वृद्धि जातियों के लिए, सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों का अनुभव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें जारशाही के दिनों में पूरी तरह राष्ट्रीय तथा सामाजिक अधीनता की स्थिति में रखा गया था। इन इलाकों में विकसित औद्योगिक मजदूरवर्ग के सहयोग से संस्कृति की अत्यंत आदिम अवस्था में भी जनता को सभायताएँ दिखाई गई हैं ताकि वह तेजी से विकास कर सके और बीच की पूँजीवादी व्यवस्था के बिना वह तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति के जरिए समाजवाद तक पहुँच सके।

#### 4 भारत राष्ट्र के समक्ष महत्वपूर्ण कार्य

समाजवाद की दिशा में बढ़ रहे जनवादी भारत या मजदूरों और किसानों के भारत का यह परिप्रेक्ष्य ही आधुनिक विश्व में भावी भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस परिप्रेक्ष्य के सहारे हम भारत में समाजवाद के निर्माण और अंततः ऐसे भावी वगैरहित समाज के निर्माण की तस्वीर देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव (अनिवार्य स्वाधीनता और अलगवा की साम्राज्यिक स्थिति में एक देश द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाने की रीति खत्म करने के लिए) अंतिम तौर पर समाप्त हो जाएँ और भारत संयुक्त विश्वव्यापी वगैरहित समाज का एक हिस्सा बन जाएगा।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस लक्ष्य की एक ही कदम में प्राप्त किया जा सकता है या भारत में तत्काल उठाया जाने वाला अगला ही कदम समाजवाद है। पहला महत्वपूर्ण काम है राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति। भारत की जनता के सामने तत्काल पूरा किया जाना वाला दूसरा काम है राष्ट्रीय स्वाधीनता पर विजय प्राप्त करना जो साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करके और आवादी के अंदर इस शासन के सामंती प्रतिक्रिया-

मादियो का तख्ता पलटकर अर्थात् जनतन्त्र के लिए सघप चलाकर पूरा किया जा सकता है।

लेकिन भारत में राष्ट्रीय मुक्ति और जनवादी क्रांति का काम ब्रिटिश शासन से भारतीयों के हाथ में सत्ता का महज हस्तांतरण करके और प्रभुसत्ता सोपकर नहीं पूरा किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि जैसा हमने देखा है, पूरा स्वाधीनता की कारगर ढंग से प्राप्ति और भारत में साम्राज्यवादी प्रभुत्व की समाप्ति का काम भारत में साम्राज्यवाद के राजनीतिक शासन के विधिवत समापन से ही नहीं पूरा होता। इसके लिए भारतीय जनता के जीवन, श्रम, साधन और विकास की स्वतन्त्रता पर ब्रिटिश महाजनी पूँजी की दमघोट पकड़ को छिन्नभिन्न करना होगा अर्थात् विदेशी पूँजी को फिलहाल दी जा रही रियायते समाप्त करनी होंगी और सभी विदेशी उद्योगों, चाय बागानों, कारखानों रेलों, जहाजों सिंचाई कार्यों आदि का इस तरह राष्ट्रीयकरण करना होगा जो शक्तिसंवधों के अनुसार राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से संभव हो ताकि कृषि का बोझ उतारा जा सके।

दूसरी बात यह है कि जैसा हमने देखा है जनतांत्रिक रूपांतरण का काम कृषि क्रांति से जुड़ा हुआ है। उसमें जमींदारी प्रथा की समाप्ति होगी, भूमि का पुनर्वितरण होगा, किसानों पर से कृषि का बोझ उतरेगा और खेती का आधुनिकीकरण होगा। तीसरी बात यह है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के तात्कालिक कार्यों के लिए, उद्योगीकरण और आवश्यक सांस्कृतिक प्रगति को स्वतन्त्र भारत के एकमात्र आधार के रूप में संभव बनाने के लिए यह जरूरी है कि स्वाधीन भारतीय राज्य के अधिकार में अथर्वव्यवस्था के मुख्य केंद्र हों (जिसकी कांग्रेस के अधिकारों के घोषणापत्र में कहा गया था) अर्थात् प्रमुख उद्योगों, सेना, खनिज साधनों, रेल व्यवस्था, जल माग, जहाजरानी तथा सार्वजनिक परिवहन और बैंकिंग तथा साख के अन्य साधनों पर स्वाधीन भारतीय राज्य का नियंत्रण हो।

फिर भी इन कामों से समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती है हालांकि इनसे इसकी नींव जरूर पड़ जाती है। जाहिर है कि भारत में जिस जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होगी जो राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का वर्तमान लक्ष्य है, वह अनिवार्य एक नए तरह का जनतांत्रिक गणराज्य होगा जो पश्चिम के धनिकतन्त्र साम्राज्यवादी अधिजनतन्त्रों से एकदम भिन्न होगा। यह एक ऐसा जनतांत्रिक गणराज्य होगा जो सामंतवाद और जमींदारी प्रथा की बुनियादों को समाप्त कर चुका होगा, जो राष्ट्रीय विकास के लिए अथर्वव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर अपना अधिकार कायम कर चुका होगा और जो मजदूर तथा किसानों के संगठन और विकास के लिए खुला रास्ता प्रदान करेगा।

भारत में स्वतन्त्रता के लिए निर्णायक संग्राम निकट भविष्य में हान वाले हैं। स्वतन्त्रता



म यह सत्रमण तूफानी होगा और भारी कुरवानियों के बाद प्राप्त होगा अथवा शीघ्र गति से और सहजता से होगा, यह केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति पर निर्भर नहीं करता यह ब्रिटिश मजदूरवर्ग और जनतांत्रिक आंदोलन के सदभाव तथा सन्ध्या सहयोग पर निर्भर करता है। संध्या की चाहे जैसी भी स्थिति हो लेकिन हर हालत में यह सत्रमण ऐतिहासिक दृष्टि में निश्चित है और ब्रिटेन के मजदूरों तथा जनतांत्रिक शक्तियों के लिए यही अच्छा होगा कि वे इस सच्चाई को समझ रहे हों मान लें। युद्ध ने उन मसलों को महज ओर तज कर दिया है जो भारत में पहले से ही चरम बिंदु पर पहुंच रहे थे, ये मसले राष्ट्रीय मुक्ति के लिए और परिणामतः सामाजिक मुक्ति के लिए चल रहे निर्णायक संध्या से संबद्ध मसले हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जनवादी शक्तियाँ जागे स वृद्ध रही हों। मजदूरों और किसानों की शक्तियाँ संध्या के जरिए शक्ति की चेतना की, महान रचनात्मक कार्य की, और एक सुखद भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। समूची दुनिया की प्रगतिशील शक्तियों और विश्व के मजदूरवर्ग की सहानुभूति और सदभाव भारतीय जनता के साथ है जो अपनी पूर्ण मुक्ति के लिए ऐसे संध्या में जुटी है जिसका विश्व के भविष्य के लिए वृद्ध महत्व है और जिसपर तमाम जाशाएँ टिकी हुई हैं। भारत की स्वतंत्रता का जय मानव जाति की मुक्ति, समानता और एकता की दिशा में एक महान कदम है, साथ ही यह विश्व-शांति और विश्वसमाजवाद की दिशा में अंतिम विजय के लिए उठाया गया कदम है।

## पादटिप्पणियाँ

- 1 10 जुलाई 1833 को मकाले ने भारत में ब्रिटिश शासन के बरदानों के पक्ष में और इस्ट इंडिया कंपनी के गुणों की प्रशंसा में हाउस आफ कॉमंस में अपने भव्य शब्दावली से भरे विख्यात भाषण में जो कुछ कहा था उसका पूरा पूरा रसास्वादन करने के लिए उस समय विद्यमान परिस्थितियों से अवगत हो लेना जरूरी है। 17 अगस्त 1833 को मकाले ने अपनी बहाना को लिखा मुझे अवश्य जाना है मैं केवल अपना कलम के बल पर जी सकता हूँ और किसी भी व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह इतना अधिक लिखे जिससे वह प्रतिष्ठित जीवन बिताने के लिए पर्याप्त पैसे पा सके और साथ ही राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग ले सके। मैंने कभी अपने लेखन से प्रति वर्ष दो सौ से ज्यादा नहीं कमाया। मैं खुद पाँच सौ से कम में आराम से नहीं रह सकता और तमाम सभावनाएँ इस बात की हैं कि मुझे जय कई लोगों का भी खर्च चलाना होगा। हमारे परिवार का भविष्य, यदि इसकी सभावना है तो, पहले के किसी भी समय से ज्यादा भयानक है।

अपने इसी पत्र में उन्होंने बताया है कि उनके भारत में विधि सदस्य के पद पर नियुक्त किए जाने की सभावना है और यदि ऐसा संभव हो गया तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। इस पद पर 1834 में उनकी नियुक्ति की गई

इसमें मुझे प्रति वर्ष 10 हजार पौंड वेतन मिलेगा। मुझे तमाम ऐसे लोगों ने जो कलकत्ता के बारे में खूब अच्छी तरह जानते हैं और कलकत्ता के श्रेष्ठतम तबके में तथा प्रसीडेंटों के उच्चतम पदों पर रह चुके हैं, बताया है कि मैं वहाँ प्रति वर्ष 5 हजार पौंड में बड़े ठाठबाट के साथ रह सकता हूँ और वेतन के शेष हिस्से को गृह के साथ बचा सकता हूँ। मैं महज 39 वर्ष की उम्र में

जीवन की भरपूर उमर में साथ झलक वापस आ जाऊंगा और मेरे साथ 30 हजार पौंड की धनराशि होगी। इससे ज्यादा समृद्धि की मैंने कभी इच्छा भी नहीं की।

यह छोटा ग्रन्थ जिससे साम्राज्यवाद और समूह दुर्जुआ जीवन दशन के रहस्यों का पता चलता है इस महत्वपूर्ण भाषण के प्रत्येक पुनर्मुद्रण में (यासतौर से स्कूलों के लिए तयार किए गए संस्करण में) परस्पर समझौता सबधी बातचीत के प्रवर्धन के रूप में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इस भाषण को आज भी भारत में ब्रिटिश उद्देश्य की भव्यता की दाद अतिव्यक्ति माना जाता है। यदि उपयुक्त ग्रन्थों को इस भाषण के साथ प्रकाशित कर दिया जाए तो यासतौर से इस तरह के ग्रन्थों के व्यक्त शब्दों का पूरा पूरा जायका मिल जाएगा।

मैं अंधा और उल्लास के साथ उस सम्माननीय गरीबी को देखता हूँ जो अबरदस्त प्रलोभन के बीच बनाकर रखी गई ईमानदारी का सबूत है। मैं यह देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि मेरे देशवासी, बराबरी नामों पर शासन करने के बाद पर्याप्त संपन्नता व धाय स्वयं लौटते हैं।

- 2 मकाले ने ब्रिटिश शासन के बरताना के भारत में आने से पूर्व, 18वीं सदी के भारत में व्याप्त अराजकता और आतंक की जो अतिरिक्त तस्वीर प्रस्तुत की है उसके समक्ष चर्चित का यह उद्धरण पता किया जाता है जो उनके द्वारा 1914-18 के यूरोप के वणन से लिया गया है जब सब कुछ समाप्त हो गया था तब उत्पीड़न और मानवभक्षण ही दो प्रकृतियाँ थीं जिनसे सम्पन्न वस्तुनिष्ठ ईसाई राज्य बच सकते थे और इनकी उपयोगिता सिद्ध थी। (विस्टर चर्चिल दि बल्ड प्राइसिस। पृष्ठ 20)

दोस वर्षों बाद उत्पीड़न का लोप कर देने से कोई कल्याण नहीं हुआ।

- 3 ब्रिटिश फासिज्म ने फासिज्म ऐंड इंडिया शीपक से प्रकाशित कार्यक्रम की घोषणा में, जिसकी राजनीतिक निरक्षरता से बुनियादी तथ्या तक के बारे में भी उसकी अज्ञानता का पता चलता है भारत में ब्रिटिश शासन के तेजी से विनाश के लिए अपना अच्छा नुस्खा पेश किया है। फासिस्ट सूत्रों इस तरह की दृढ़ घोषणाओं से शुरुआत करते हैं जो पूर्वी मानस की समझ में आए कि तत्काल या अतः ब्रिटिश प्रभुत्व का ह्रास होने की कोई संभावना नहीं है, वे सांविधानिक सुधारों को भिदा दग, कल्याणकारी शक्ति के रूप में बड़ जमींदारों का समर्थन करण, औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करण (क्याकि भारत का भविष्य मुख्यतया ग्राम पर निर्भर है) और आधुनिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देंगे (सामान्य तौर पर भारतीयों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए)। इस प्रकार भारत के हमन की भरपूर शक्ति की मदद से 19वीं सदी का पुराना स्वम फिर स्थापित किया जाएगा हम दोनों देशों के बीच सहज व्यापार सतुलन का विकास करण ग्रेट ब्रिटेन से तयार माल जाएगा और भारत से कच्चा माल तथा खाद्य सामग्री जाएगी (मोस्ले 'फासिज्म ऐंड काटन 1934) जबकि फासिस्ट सरकार के तहत भारत पर्याप्त पूँजीनिवेश के लिए उपयुक्त स्थितियाँ प्रस्तुत करेंगी। साम्राज्यवाद की सहज मूल्य की बिना किसी जिम्मेदारी के अभिव्यक्ति की गई है।

- 4 वर्ष 1912 के लिए इंग्लैंड के लेजिस्लेटिव कौंसिल के कार्यक्रमों की दृष्टि से मेरी विवाह एक विधायक पर गई जिसमें विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सिविल विवाह की छूट के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस विधायक को श्री भूपद्रनाथ बनू ने पेश किया था। ऐसा लगता है कि इस विन में इससे ज्यादा कुछ कहा गया था कि लोगों को बिना यह घोषित किए कि वे भारत के किसी जात धर्म के अनुयायी नहीं हैं 1872 के विनाय विवाह अधिनियम (जो संभवतः सिविल विवाह की छूट देता है) का साथ उठाने की छूट मिलनी चाहिए। इस बिल पर बहस में एक उपवाद छोड़ केवल भारतीय सदस्यों ने ही भाग लिया। यह उपवाद यहूद सदस्य जिन्होंने ठाकुर से एतान किया कि जब तक विधायक के प्रस्तावक यह न साबित कर दें कि इस परिवर्तन के पक्ष में विज्ञान जनमत है तब तक सरकार इसका विरोध करेगी। श्री गोपबने न दलील दी कि

इस विधायक को चयन समिति में भेज दिया जाए जिसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत है लेकिन उनकी दलील अनमानी कर दी गई। जवाब देने के बाद प्रस्तावक का दस अन्य सदस्यों ने समर्थन किया। उसके खिलाफ बहुमत को देखकर गवर्नर जनरल धीरे-धीरे उनकी कौंसिल ने ब्रिटिश अधिकारियों के समूह जल्द ही आदेश दिया कि वे सदन में जाएं और विधायक को पारित न होने दें।

इन विषयों पर सरकार का दस समाजसुधारकों के सामने बाधाएं उपस्थित करना है जो यही दुष्ट स्थिति है। (सायनेल कटिस सटस ट दि पीपुल्स आफ इंडिया आन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1918 पृष्ठ 140-42)

इसके बाद एक समर्थनकारी कानून पारित हुआ है लेकिन आज भी कोई सामान्य सिविल मरिज एक्ट नहीं है (देखें नेहरू की आटोबायोग्राफी) पृष्ठ 451 जिसमें उन कठिनाइयों का जिक्र किया गया है जो आज भी आबादों के विभिन्न भागों के बीच कृत्रिम अवरोधों का काम करती हैं। एक भगरेज साम्राज्यवादी की इस टिप्पणी के साथ नेहरू के अपने वक्तव्य की तुलना की जा सकती है।

समाजसुधारकों की दृष्टि से दशों तो आधुनिककाल में स्थिति बदतर हुई है क्योंकि भगरेज लोग अब दिनादिन इन बुराइयों की मोन प्राचीर का काम कर रहे हैं। ऐसा अत्यंत प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के कारण है। (नेहरू आटोबायोग्राफी पृष्ठ 382)

- 5 जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सोवियत जनतंत्र के प्रति जो सम्मान प्रकट किया वह ध्यान देने योग्य है।

रूस के बारे में वेन्स की नई पुस्तक में प्रस्तुत ऐतिहासिक और प्रभावकारी विवरण काफी दिलचस्प हैं कि किस प्रकार सोवियत संघ का समूचा ढांचा एक विशाल और जीवन जनतांत्रिक बुनियाद पर आधारित है। रूस को पश्चिमी देशों के नमूने पर तयार जनतांत्रिक देश नहीं माना जाता है फिर भी हम देखते हैं कि उस देश में जनता में जनतंत्र के बुनियादी तत्व जितनी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। वहां 6 लाख गांवों और नगरों का विशाल जनतांत्रिक संगठन है प्रत्येक की अपनी सोवियत है जो निरंतर नीतिशास्त्र तयार करने के लिए आपस में बहस विचार विमर्श, आलोचना और एक दूसरे की सहायता करते हैं और उच्च समितियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस संगठन में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक हैं। इसने अलावा जनता का एक और विशाल संगठन है जो उत्पादन में लगा है और तीव्रता इतना ही बड़ा संगठन उपभोक्ताओं का है। लाखों पुरुष और महिलाएं सांख्यिकीय मामलों से संबंधित बहुतेक में वस्तुतः देश के प्रशासन में निरंतर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक इतिहास में जनतांत्रिक प्रक्रिया का इतना व्यावहारिक उपयोग नहीं देखने में आया।



## अनुक्रमणी

- अकबर, 240  
 अकाल, 68, 69, 131, 219, 276, 278,  
 279, 280, 281, 282, 294,  
 320, 475  
 अकाल आयोग, 223, 229, 320  
 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 386, 530,  
 531, 541, 568, 570, 578,  
 582, 599  
 अखिल भारतीय किसान सङ्गठन, 291  
 अखिल भारतीय किसान सभा 291, 292,  
 293, 294, 295  
 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ, 631  
 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 258,  
 430, 439  
 अखिल भारतीय रेलवेमंस फेडरेशन, 435  
 अगस्त प्रस्ताव, 566, 570  
 अछूत, 299, 441  
 अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट जादोलन, 426,  
 427  
 अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर जादोलन 556  
 अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन, 396, 398  
 अन्तर्राष्ट्रीय सबहारा, 637  
 अन्तलाटिक चाट्टर, 564  
 अधिकारी, जी० एम०, 424, 428  
 अफगानिस्तान, 156, 545  
 जवेडकर, 306, 510  
 जमरोकी तकनीकी मिशन, 47, 48, 194,  
 196  
 जमरोकी स्वाधीनता की घोषणा, 23  
 अमलगमेड सोसाइटी आफ रेलवे सर्वेड्स,  
 412  
 अमृतवाजार पत्रिका, 621  
 अमृतसर, 293 339  
 अमृतसर कांड, 612  
 अय्यर, एस० सी० रंगा, 449  
 अयोध्याप्रसाद, 424  
 अधिसामती सस्थाए, 285  
 अल्पसङ्ख्यको क अधिकार, 594  
 अनीबधु, 350, 471  
 अस्थाई जमींदारी बंदीवस्त, 252  
 असहयोग जादोलन, 344 346 391,  
 472, 474, 476, 568, 569,

- अहमद मकबूल, 210  
 अहमदावाद 59 356, 357, 400, 434  
 अहमदावाद लेवर एसोसिएशन, 416  
 अहिंसक असहयोग, 367 386  
 अहिंसात्मक आंदोलन, 347  
 आगल अमरीकी गुट, 584  
 आगल अमरीकी वित्तीय समझौते 199  
 आगल-डच साम्राज्यवाद 27  
 आग्यर 134  
 आजाद मौलाना, 562, 568, 569, 577  
 आतंकवादी आंदोलन 337  
 आत्मसहायता आंदोलन 294  
 आधुनिक पूजावाद 124  
 आधुनिक मजदूर आंदोलन, 413  
 आधुनिक साम्राज्यवाद, 30  
 आदिम साम्यवाद 109, 110  
 आब्जवर, 377, 378, 379  
 आयरलैंड, 384, 460  
 आयरलैंड की समस्या, 104  
 आक्राइट, 133, 134  
 आर्थिक मंदी, 434  
 आम्स ऐक्ट, 322  
 आर्मी इन इंडिया कमेटी, 547  
 आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 436, 440, 441  
 आल इंडिया मुस्लिम लीग 478  
 आल इंडिया लैंड होल्डर्स कांग्रेस 249  
 आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस 458  
 आल्वे ए० ए०, 424  
 आशिक दास, 256  
 इकवाल, 478  
 इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा, 246  
 इंग्लैंड व कुलीन तत्त्व, 67, 113  
 इजारेदारी, 113 114, 136  
 इजवा, 257  
 इंडियन जनरल, 305  
 इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, 44, 45, 49, 169  
 इंडियन एसोसिएशन, 322  
 इंडियन कौन्सिल ऐक्ट, 341, 496  
 इंडियन टरिफ बोर्ड की रिपोर्ट, 49  
 इंडियन नेशनल आर्मी, 25, 585, 590  
 इंडियन फेडरेशन आफ लेबर 440  
 इंडियन फेमिन कमीशन रिपोर्ट, 149  
 इंडियन लिबरल फेडरेशन, 346  
 इंडियन लेबर गजट, 203 408  
 इंडिया ऐक्ट, 139, 204  
 इंडिया लीग 385  
 इंडस्ट्रियल एक्सचेंज ट्रेड, 85  
 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, 435  
 इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया, 62  
 इपीरियल कैमिकल्स 187  
 इपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, 103, 144, 308  
 इपीरियल बक आफ इंडिया, 159, 179, 189 190, 191, 192  
 इमरसन, जी०, 64, 232  
 इविन लाड 422, 503  
 इलवट, सर बोर्टने, 545, 546  
 इस्तमरारी बंदोबस्त, 131 140, 246  
 ईशर कमेटी रिपोर्ट, 347  
 ईस्ट इंडिया कंपनी, 67, 108 112, 113 122, 123, 124, 125 128, 129 136, 137, 138, 139, 140, 146, 156, 159, 230 231, 232, 242  
 ईस्टन इक्वोनोमिस्ट, 192, 193 200  
 उजबेकिस्तान, 92, 95  
 उपनिवेशवादविरोधी मुक्ति आंदोलन, 27  
 उस्मानी शोक्त 419, 423  
 एनायड डा० 57 73  
 एक्सचेंज कपिटल बमटी, 191

- एगल्स, 108, 109, 120, 551  
 एटली, सी० आर०, 27, 581, 591  
 एडरसन, सर जान, 384  
 एमरी, 582, 599, 611  
 एल्फिस्टन, लाड, 443  
 एनिस, सर ई०, 546  
 एलेक्जेंडर, एच० जी०, 379, 380  
 एलेक्जेंडर, एम०, 153  
 एवट, डा० एच० बी०, 564  
 एसकफ, सर थामस, 620  
 एस्टे, डा० बेरा, 34, 63, 68, 74, 248,  
 278, 288, 289, 305  
 ऐजूकेशन इन इंडिया, 87  
 ऐडम्स, सी०, 232  
 ऐड्डूज, 326  
 आटावा समझौता, 175, 176,  
 ओटिस, 302  
 ओलिवर, लाड, 464  
 औद्योगिक आयोग, 60  
 औद्योगिक नाति, 70, 114, 135, 136,  
 147, 550, 634, 637  
 औद्योगिक जनगणना, 85  
 औद्योगिक पूजा, 122 152  
 औद्योगिक पूजावाद, 133, 137, 139  
 औद्योगिक पूजावादी शोषण, 140, 150  
 औद्योगिक बुर्जुआवग, 625, 626, 633,  
 634, 642  
 औद्योगिक मजदूर, 170, 365, 378, 527,  
 534, 627, 641, 643  
 औद्योगिक सवहारा, 393, 394  
 औपनिवेशिक मजदूर, 93  
 औपनिवेशिक युद्ध, 120  
 कजरवटिव पार्टी, 552  
 कजाकिस्तान 92, 98  
 कट्टर राष्ट्रवादी, 334 337  
 कदम, लक्ष्मणराव, 424  
 कनिंघम डा०, 133, 134, 303,  
 कम्युनिस्ट घोषणापत्र, 108  
 कम्युनिस्ट पार्टी, 432, 433, 436, 438,  
 439, 440, 441, 486, 533,  
 574, 587, 589  
 कर्मिंग, सर जान, 305  
 कजन, लाड, 30, 31, 51, 150, 152,  
 169, 334, 340, 499, 543,  
 546 547, 611  
 कराची अधिवेशन, 383, 526  
 क्रामवेल, 113, 313  
 क्रिप्स मिशन, 66, 67, 70, 565  
 क्रिप्स समझौता, 26  
 क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड, 565  
 क्रेनब्रुक, लाड, 495  
 क्रोमर, लाड 493, 610  
 कलकत्ता अधिवेशन, 385  
 क्लबट, एच०, 242  
 क्लाइव, 44, 105, 128, 129, 143  
 क्लाउस्टन, डी०, 57  
 क्लाक, जी०, 77  
 क्लेमेंसु 555  
 कश्मीर, 445  
 काउत्सकी, 120  
 काग्रेस जमींदार गठबंधन, 534  
 काग्रेस जाच समिति, 435  
 काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 433, 436,  
 441, 438  
 काटन, ले० कनल, 230  
 काटन, हेनरी, 143  
 काठियावाड 445, 453  
 कानपुर अधिवेशन, 439  
 कानपुर पड्यत्र, 365  
 कानूनी छेतिहर गुलाम 257  
 कामिया, 257  
 काटराइट, 133, 135

- कानवालिस, लाड, 131, 132, 139, 140, 232, 246, 248, 249
- काल्टल क्लब, 305
- कार्लाइल, 272
- कारा काल्पक स्वायत्त गणराज्य, 92
- कालावाजार, 281
- कालीकट, 30
- काश्तकार संवधि कानून, 286
- कासले, जी० आर०, 424
- कावू, एफ० एफ०, 44
- किचनर, लाड, 372
- किर्पलिंग 105
- किरगीज स्वायत्त गणराज्य, 92
- किरोल, बेलेंटाइन, 168
- किसान आंदोलन, 290, 294, 392
- किसान आति, 290, 640
- किसान विद्रोह, 290, 291, 443, 451
- किसान संगठन, 293
- कीटिंग, 261
- कीथ, ए० वी०, 249, 520, 521, 555
- कुक्किंस्की डा०, 75
- कुनिज, जे०, 94
- कुमारप्पा, जे० सी०, 628, 630
- कुलक, 86
- कुलाच, मैक, 141
- कूपलैंड, आर, 566, 572
- केन, डब्ल्यू० एस०, 332
- केंद्रीय बैंकिंग आच समिति, 70, 71, 270, 276
- केड, जेम्स, 229
- कैनिंग, नाड, 448
- कैपिटल, 209, 246
- कैबिनेट मिशन, 27, 28, 213, 469, 550, 581, 582, 583 591, 593, 594 595 596, 598, 600, 601, 602, 604, 619
- कल्ट, 109
- कैसर लवर आदालत, 552
- कोन, कनल 463
- कोचीन गादी, 401
- कोप, 146
- कोमिनतन, 427
- कोमिल्ला अधिवेशन, 291
- खवाता, के० जे०, 54, 55
- खा, अब्दुल गफ्फार, 475
- खा, लियाकत अली, 579
- खा, सर सैयद अहमद, 465
- खिलाफत आदालत, 350, 354
- खिलाफत कमटी, 471, 472, 474
- खिलाफत पार्टी, 356
- खुदाई खिदमतगार, 386, 475
- खेतिहर मजदूर, 257, 282, 392, 393, 523, 534
- खेतिहरवग, 276
- खेतिहर सवहारा, 245, 275, 392
- गदर, 296
- गढ़वाली सिपाहियों का विद्रोह, 372, 375
- ग्रामीण गृहयस्तता, 267
- ग्राहम, कनल, 57
- ग्राहम, सर जेम्स, 493
- ग्रिग, सर जेम्स, 51, 55, 405
- ग्रिफिथ्स, पी० जे०, 581
- ग्रेगरी, डा० टी० ई०, 436
- ग्लैडस्टोन विलियम एबड, 314, 330, 493
- ग्वान्, जे० टी०, 449
- गांधी, 305, 310, 328, 343, 344, 346 347, 348, 349 351, 352, 353 354, 355, 356, 357, 358, 359 360 361, 362, 366, 367, 368, 369



- 370, 371, 372, 373, 375,  
376, 377, 380, 381,  
382, 385, 387, 388, 416,  
438, 456, 463, 471, 472,  
475, 476, 477, 479, 482,  
492, 531, 532, 539, 540,  
542, 544, 560, 561, 568,  
569, 570, 572, 575, 577,  
578, 579, 590, 628  
गांधी ईविन समझौता, 370, 376, 377,  
380, 381, 383, 591  
गांधीवाद, 337  
गांधीवादी ट्रेड यूनियन आंदोलन, 439  
गांधीवादी सिद्धांत, 387, 432, 434,  
438  
गांव की सामुदायिक व्यवस्था, 241  
गिरनी कामगर यूनियन 429  
गिरी, बी० वी०, 417, 430  
गुप्तर, 360  
गुप्त, प्रेमसागर, 202  
गुलामी प्रथा, 312, 453  
गैराट, जी० टी०, 106, 242, 289  
गोखले, 328, 334, 340  
गोदी कमचारी, 401  
गोपाल, एम० एच०, 201  
गोयनका, सर ब्रह्मदास, 193  
गोरक्षा समिति, 336  
गोलमेज सम्मेलन, 376 379, 380, 381,  
383, 385, 448, 456  
गोवा, 30  
गोस्वामी, घरनी के०, 424, 426  
गोस्वामी टी० वी०, 191  
गौरीशंकर, 424  
घाट, एस० वी०, 423  
घोष, अरविंद, 334, 475  
घोष, किशोरीलाल, 423  
चक्रवर्ती, गोपेंद्र, 424, 426  
चटगाव, 375  
चट्टोपाध्याय, के० पी०, 279  
चमनलाल, 430  
च्याग-काई-शेक, 26, 563, 564, 576  
चर्चिल, विंस्टन, 26, 302, 507, 552,  
562, 564, 565, 577, 582,  
583, 584, 599, 612, 613  
चाटड बैंक आफ इंडिया, 189  
चिरोल, विलेटाइन, 305, 348  
चीन, 29, 30, 68, 156, 184, 232,  
246, 545, 583  
चीनी क्रांति, 554  
चूडगर, पी० एल०, 453  
चेम्सफोर्ड, लाड, 392  
चेरुभा, 257 —  
चैटन, सर अल्फ्रेड, 31  
चवर आफ प्रिंसेज, 446 455  
चैवरलेन, 345, 495, 499  
चौरीचौरा कांड, 357 359, 360, 533,  
591  
छुआछूत, 305  
जन आंदोलन, 328, 373, 374, 375,  
376, 438, 456, 469, 542,  
572, 586, 587, 626  
जनतांत्रिक आंदोलन, 292, 313  
जनतांत्रिक क्रांति, 313  
जनतांत्रिक मुक्ति आंदोलन, 314  
जनवादी राष्ट्रीय आंदोलन, 308, 456  
जमियत उल उलमा, 472  
जमशेदपुर, 307, 440, 615  
जमींदारी प्रथा, 245, 252, 253, 275,  
282, 283, 284, 285, 291,  
294, 363, 632, 638, 644  
जस्टिस पार्टी, 528, 592  
जानसन, टी०, 482

- जापान, 184, 439  
 जापानी फासीवाद, 441  
 जापानी साम्राज्यवाद, 27  
 जाज लायड, 506 613  
 जारशाही, 66, 285 313, 340, 345,  
 जारशासित रूस, 86  
 जिन्ना मोहम्मद अली 343, 471, 473,  
 482 554  
 जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, 47  
 जूट उद्योग, 402  
 जूट मिल मजदूर, 410  
 जूट मिल मजदूर यूनियन, 402  
 जेम्स, एल० एच०, 158  
 जेनेवा, 167, 392 396, 398  
 जेबोस एच० स्टैनले 289  
 जन, पी० सी०, 193  
 जोगेलकर, के० एन० 423  
 जोन्स, सेसिल, 47  
 जोश, सोहनसिंह, 424  
 जोशी, एन० एम०, 258, 416 417,  
 421, 430  
 जोशी जी० एन०, 513  
 जोशी, पी० सी०, 424, 598  
 झाबवाला, एम० एच०, 423, 432  
 ड्रयूटन 109  
 ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 422, 535  
 ट्रेड यूनियन आंदोलन, 365, 414, 426,  
 430, 433 435, 439, 540,  
 541  
 ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 422  
 ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 416, 417, 420  
 436, 437, 440 535, 584  
 ट्रेवेलियन, सर चार्ल्स 143, 223  
 टाइम्स आफ इंडिया, 207, 210, 378,  
 539 563  
 टाटा-आई० सी० आई० समझौता, 604  
 टाटा आयरन एंड स्टील, 178  
 टाटा, जे० आर० डी०, 403, 636  
 टाउनशी, ए०, 133  
 टेंचुल, सर रिचाड, 248  
 टैंक्सटाइल लेबर इन्वायरी कमेटी रिपोर्ट,  
 59  
 टैगोर, रवीन्द्रनाथ, 82  
 टारी पार्टी, 584, 598  
 टारीवाद, 26, 27, 584  
 डगल, डोडा, 134  
 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 30  
 डनलप, 187  
 डफरिन, लाड, 324, 325, 326, 333,  
 610  
 डलहौजी, लाड, 155, 447, 448, 545  
 डाये एस० ए०, 419, 423, 525  
 डाडी यात्रा, 374  
 डायर, जनरल, 348, 612  
 डार्लिंग, एम० एल०, 43, 267, 268,  
 278, 287  
 डाल्टन ह्यू, 187  
 डिग्बी, डब्ल्यू० 51, 148  
 डिजरायली 104  
 डेली हुराल्ड, 429  
 डेविड सर सेसून, 412  
 डोमोनियन स्ट्रट्स 504, 506  
 ताजिकिस्तान, 92, 93, 94, 95, 98  
 तिब्बत, 546  
 तिलक, बालगंगाधर 334, 336, 341,  
 344, 391, 412, 470  
 तुर्कमेनिस्तान, 92, 98  
 तेवर्निमर, 44  
 ताक्वेल डी०, 30  
 वामस पी० ज०, 72, 73  
 वामसन, ई०, 106, 242, 289  
 वेंगडी डी० आर० 423

- दक्कन का किसान विद्रोह, 320, 322  
 दक्कन रायट्स कमीशन, 263  
 दक्कन विद्रोह, 291  
 दक्षिण अफ्रीका, 343, 347  
 दक्षिण अफ्रीकी युद्ध, 554  
 दक्षिण पूव एशिया, 439  
 दत्त रमेशचन्द्र, 331, 332  
 द्वित्व, 500, 501  
 द्वितीय अफगान युद्ध, 322  
 द्वितीय विश्वयुद्ध, 26, 31, 32, 182  
 दास, आर० के०, 48, 227  
 दासगुप्त, 419  
 दास, चित्तरजन, 363, 364, 416  
 दास, सी० आर०, 346, 350 354, 358  
 दि अवेकनिंग आफ इंडिया, 390  
 दि इकोनामिक डेवलपमेंट आफ इंडिया 34, 63, 68, 74  
 दि इंडस्ट्रियल एक्सिप्शी इन इंडिया, 48  
 दि इंडियन इंपायर, 230  
 दि ग्रेट फेमिन, 266  
 दि टाइम्स, 50, 64, 65, 73, 369, 373, 377, 382, 383, 464, 504, 530  
 दिल्ली का घोषणापत्र, 369  
 दीनबधु, 410  
 देसाई, एम० जी०, 424  
 देसाई, ए० आर०, 452  
 देसाई, भूलाभाई 579  
 नए औद्योगिक पूजीपति, 330  
 नजराना, 152, 153, 167, 241  
 नमक कानून, 374  
 नमक सत्याग्रह, 374  
 न्यूयाक डेली ट्रिब्यून, 108 112, 117, 230, 307  
 न्यूयाक वर्ल्ड, 370  
 नरमदनी नेता, 369, 496  
 नरमदली बुजुआ, 367  
 नवजात बुजआवग 447  
 नवोदित मजदूरवर्ग, 333  
 नस्लवाद, 191  
 नस्लवादी दगे, 301, 461  
 नाजी, 439  
 नायडू, बी० बी०, 281  
 नारायण, जयप्रकाश, 438  
 नाबेल्स, एल० सी० ए०, 68, 125, 126, 147, 181, 623  
 निबकर, आर० एम०, 424  
 निम्न पूजीपतिवर्ग, 391  
 नीबर, 104  
 नील आयोग, 147  
 नपियर चाल्स, 545  
 नेपोलियन 314, 544  
 नेविमन, एच० डब्ल्यू०, 299, 300  
 नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, 529  
 नेशनल फ्रंट, 436  
 नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन, 436, 438  
 नेहरू, जवाहरलाल, 239, 310, 399, 353, 358 366 368, 369, 371 382, 408 409, 450 451, 458, 473, 474, 476, 523, 540, 556, 562, 568, 569, 570, 576, 577, 578, 640, 641  
 नेहरू मोतीलाल, 338, 339, 350, 358, 366, 369, 370  
 नेहरू रिपाट, 370  
 नैश वागान, 266  
 नीरोजी, डी०, 51, 52, 333, 340  
 पंजाब का गदर, 344  
 पटसन उद्योग, 170

- पन्त, बल्लभदास, 575, 577 578 557,  
589, 628
- पत गाविंदबल्लभ, 578
- पब्लिक वर्क्स इन इंडिया, 230
- प्रगतिशील बुर्जुआवग, 163
- प्रगतिशील राष्ट्रीय आंदोलन, 305
- प्रतिप्रियावा, 60 121
- प्रथम विश्वयुद्ध, 24, 35, 84, 151, 342,  
391, 402, 471
- पल हाथर, 25
- परसेल, ए० ए०, 395
- प्रातीय स्वायत्तता, 292
- प्रावलम्भ आफ दि फारईस्ट, 31
- परलेकर, एस० बी०, 396, 398
- प्लासी का युद्ध, 30, 133, 135
- पश्चिमी महाजती पूजा, 461
- पश्चिमी पूजावाद, 23
- पाकिस्तान, 297, 460, 469, 477,  
478, 479, 480 481, 482  
598, 599, 601
- पाडियाल, 257
- पारनेल, 609
- पारीख, एच० टी०, 201
- पाल, विपिनचंद्र, 334
- पिट, 138, 139, 140
- पीपुल्स बैंक आफ इंडिया, 184
- पक्तावादी संगठन, 308
- पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 179
- पुलेया, 257
- पूजापतिवग, 120, 123, 124, 133,  
137, 155, 316
- पूजावाद, 32 67, 108, 113, 120,  
121, 145
- पूजावादी राष्ट्रीय उत्पादन प्रणाली, 246
- पूणदास 256
- पूना का समझौता, 386
- पटेल ता, 343
- परिा, सी० पी०, 49
- परीज, जी० एच०, 133
- पशावर, 372, 375, 376
- पलाश, चाला, 630
- पैट्रिआटिक, 461
- पैन, सर जान, 160
- पोट सद्द, 383
- फास की क्रांति, 67, 139, 272
- फासिम फिलिप, 140
- फ्रेजर, लावाट, 406
- फलेस्टाफ, सर जान, 298
- फलाउड यमीशन, 282
- फार्नेशियल टाइम्स, 164, 621
- फास, सी० एस०, 49, 139, 551
- फारस, 545
- फारवद ब्लाक, 541, 542
- फामिस्ट गठबंधन, 26
- फाभीवाद, 25, 26, 27, 441, 523,  
557, 573, 585, 609
- फासट कमेटी, 421
- फिनलाइजेन, 69
- फुल्लटन, विलियम, 132
- फूड ग्रेस पालिसी कमेटी की रिपोर्ट, 57
- फजपुर, 291
- फंजपुर अधिवेशन, 523, 524, 525
- फोड 197
- फोक, माशत, 372
- बगभग, 340
- बगाल, 400
- बगाल की जूट हड़ताल, 434
- बगाल मालगुजारी आयोग, 260
- बगाल लैंड होल्डिंग सोसायटी, 321
- बगाल सेसस रिपोर्ट, 71, 77, 226
- बटलर कमेटी, 449
- बटलर, सर हारकोट, 310

- बधुआ गुलाम मजदूर, 226  
 बनर्जी, शिवनाथ, 424  
 बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, 322, 325, 333  
 बबई मिल मजदूर एसोसिएशन, 410, 411  
 बबई योजना, 205  
 बक, 105, 132, 135, 139, 313, 314  
 बरबतुल्ला, 554  
 बर्क्रेनहेड, लाड, 501, 504, 613  
 बनबी, 302  
 बनम, डब्ल्यू०, 235  
 बर्नियर, 45  
 बथ कट्रोल आफ एशिया की रिपाट, 68  
 ब्रह्म समाज, 321  
 ब्राइट, जान, 230, 314, 493  
 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 321  
 ब्रिटिश इंडिया सासायटी, 321  
 ब्रिटिश कपडा उद्योग, 141  
 ब्रिटिश जापानी संध, 544  
 ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 392, 395, 396, 421  
 ब्रिटिश पूजीवाद, 31, 32, 77, 180  
 ब्रिटिश भारत के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, 87  
 ब्रिटिश महाजनी पूजी, 160, 165, 168, 178, 179, 185, 188, 192, 210, 300, 515, 619, 636, 644  
 ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, 36  
 ब्रुक एटम्स, 135  
 ब्रूचा, 412  
 ब्रेडले, बी० एफ०, 423  
 बसाक, गोपाल, 424, 426  
 बहिष्कार आंदोलन, 341  
 बहुराष्ट्रवाद, 469  
 बहोर, सर जोसेफ, 63  
 बाब्रे फ्रान्कल, 211, 362, 422, 437, 540  
 बाब्रे लेबर गजट, 61  
 बायर, जान, 45  
 बायरन, 315  
 बारदोली, 244, 357, 362  
 बारदोली अधिवेशन, २६३  
 बारदोली का फैसला, 358, 359, 360, 376  
 वाल्डविन स्टैनले, 495, 505, 507, 508, 613  
 बिचवई परोपजीविता, 37  
 बिडला यूफील्ड समझौता, 208, 210, 211, 604, 622  
 बिडला, जी० डी०, 210, 536  
 बिहार, 257, 400  
 बुकानन, डी० एच०, 183, 241, 398  
 बुकानन फ्रांसिस, 145, 174  
 बुर्जुआवग, 351  
 बुर्जुआ सभ्यता, 105  
 बुर्जुआ समाज, 108  
 बुर्जुआ सामाजिक क्रांति, 115  
 बुशनान, प्रो०, 33  
 बेगार, 453, 454  
 बेगार प्रथा, 615  
 बेचेर, 131  
 बेन, बेजहुड, 502  
 बेस, 135  
 बेप्टिस्टा, जासेफ, 416  
 बेरिंग, मेजर, 52  
 बेविल, नाड, 579  
 बेसैंट, श्रीमती एनी, 333, 344, 345, 346, 369, 415  
 बैक आफ इंग्लैंड, 134, 135, 188

- वैजय नामग 146  
 वैदिक ला. विनियम एंडिंग, 146,  
 249  
 वोल्स्ट विनियम 126 127  
 वोस, जानदमोहन, 322 333  
 वोस सुभाषचंद्र, 25 352, 353 358  
 366, 368 371, 374, 382  
 383, 441, 474 539, 555,  
 541, 542, 566, 578, 585,  
 589  
 भारत की कृषि समस्या, 217, 278, 289  
 भारत की गरीबी, 66  
 भारत की मेहनतमश जनता, 39  
 भारत में ओसते जातु, 62  
 भारत में यूरोपीय पूजी, 30  
 भारत रक्षा अधिनियम, 293  
 भारतीय औद्योगिक आयोग, 45, 173,  
 618  
 भारतीय औद्योगिक मजदूर, 411  
 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 356, 387,  
 419, 485, 569, 575  
 भारतीय नौसिना या विद्रोह, 586  
 भारतीय बाजार, 31  
 भारतीय मजदूर आंदोलन, 410 411,  
 413, 414 415 417, 425  
 भारतीय मजदूरवर्ग, 390, 391, 392  
 407, 417  
 भारतीय मताधिकार समिति, 393  
 भारतीय मिल उद्योग, 405  
 भारतीय रजवाडों की शासन व्यवस्था,  
 455  
 भारतीय राजकीय आयोग 618  
 भारतीय राष्ट्रवाद, 321, 330, 443  
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 291, 320, 322,  
 325  
 भारतीय रियासते, 445  
 भारतीय व्यापार एवं उद्योग महामण्डल,  
 193  
 भारतीय साम्यवाद, 109  
 भारतीय सवहारा घन, 300  
 भूमिहीन चेत मजदूर, 254, 255, 285  
 भूमिहीन मजदूर, 245, 253, 255, 258,  
 259, 261, 280  
 भूमिहीन सवहारा, 239, 269, 275, 276  
 मई दिवस, 420  
 मद्रास, 280  
 मजदूर आंदोलन, 307, 368, 372, 383,  
 433, 440, 441, 443  
 मजदूर किसान पार्टी, 365, 368, 419  
 मजदूरवर्ग, 205, 313, 365, 368, 374,  
 391, 435  
 मजदूर सप, 366  
 मजौद, एम० ए०, 424  
 मणिपुर, 445  
 मयली रिब्यू, 94  
 मद्रास, 400, 445  
 मध्यवर्गीय नेता, 323  
 मनु, 240  
 मनूची, 45  
 मरुटाइल बक आफ इंडिया, 159  
 मरे, सर अलेक्जेंडर, 434  
 मलिक, एच० एस०, 210  
 मलरिया, 231, 232  
 महमूद, डा० सैयद, 385  
 महलनबीस पी० सी०, 279  
 महाजन, 86  
 महाजनी प्रथा, 283  
 महाजनी पूजी, 24, 36, 122 123, 152,  
 154, 160, 161, 164, 167,  
 185, 243, 244, 261, 280,  
 619  
 महाभारत, 303

- माइरम्स, ए० ई०, 61  
 माइस एक्टर, 407  
 माटगोमरी, फील्ड माशाल, 604  
 माटगु, ई० एम० 499  
 माटगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 219, 497, 498,  
 500, 501  
 माइन इंडिया, 305, 310  
 मान, हेराल्ड एच०, 224 225, 242,  
 243, 260, 262  
 माक्स, बाल, 67, 107, 108, 109,  
 110, 111, 112, 113, 114,  
 115, 117, 118, 119, 122,  
 123, 134, 211, 212, 229,  
 230, 245, 246, 307, 315,  
 446, 480, 551  
 मार्टिन, माटगोमरी, 143, 145, 230  
 मार्ले, लाड, 169 ~ -  
 मार्लिन, जे० एल०, 317  
 मालगुजारी, 130, 131, 132, 140, 146,  
 218, 241, 242, 243, 244,  
 247, 250, 264, 265, 266  
 267, 269, 270, 271, 370,  
 523, 526, 534  
 मालथेस, 67, 68, 69, 72, 76  
 मालवीय, पंडित मदनमोहन, 354, 380,  
 मिखाइलोव 98, 99  
 मिटो, लाड, 466, 470, 497, 498, 610  
 मिरजकर, एस० एस०, 423  
 मिल बानस एसोसिएशन, 378  
 मिल, जान स्टुअर्ट, 127, 313, 314 493  
 मिल्टन, 315  
 मिता, राघारमण 424, 425  
 मोक, डी० बी०, 85  
 मुखर्जी, राधाकमल, 72 216, 222, 226,  
 227, 240, 243, 244 256,  
 257, 326, 638  
 मुखर्जी, विश्वनाथ, 424  
 मुज्जफर अहमद, 419, 423  
 मुनरो, वामन 250, 251, 255  
 मुर्शिदाबाद 44, 131, 143  
 मुसलमान, 175, 435 441, 462, 465,  
 467 471, 477, 506  
 मुस्लिम लीग, 344 345, 362, 413,  
 441, 464, 467, 469, 470,  
 472, 473, 474, 475, 477,  
 478, 479, 482, 485, 498,  
 561, 568, 574, 579, 580,  
 585, 586, 589, 590, 591,  
 592, 593 595, 596, 598  
 601, 602 605  
 मुस्लिम हेराल्ड, 465  
 मुत्सोलिनी 383  
 मेगा, सर जान, 57  
 मेटकाल्फ, लाड, 317  
 मेहता, जमनादास, 436  
 मेहता, फिरोजशाह, 332, 333  
 मेस्टन, सर जेम्स 343  
 मेसोपोटामिया, 545  
 मेसोपोटामिया का युद्ध, 343  
 मैकडोनल्ड, 234, 312, 367, 380, 382,  
 390, 464, 495, 500, 503  
 मैकलागन, सर एडवर्ड, 262  
 मैक्सफील्ड, 146  
 मैक्सवेल, रेजिनल्ड, 438  
 मैकाले, टी० बी०, 314, 315, 492, 493,  
 609  
 मैक्नेस्टर गार्जियन, 422, 449, 612,  
 616, 617  
 मेमोरेंडम, जान दि रिसोर्सेज आफ ब्रिटिश  
 इंडिया, 46  
 मैलकान, सर जान, 448  
 मसे, डब्ल्यू० एन०, 158

- माद, 76, 81  
 मापला विद्रोह, 353, 533  
 मार्ले मिटा सुधार, 151, 341, 345, 467, 494, 501, 508  
 मोर्ले, लाड, 341, 466, 493, 494, 497, 498, 610  
 मोरलड, 69  
 मोहानी, मोलाना हजरत, 356, 471  
 मग इंडिया, 370, 374, 382, 476  
 मूल्य, 429  
 यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 435  
 यूनियनिस्ट पार्टी, 474, 592  
 यूरोप के जनतांत्रिक मुक्ति आंदोलन, 26  
 रदरमोर, लाड, 312  
 रवर, 187  
 रसायन, 187  
 राजगोपालाचारी, सी० 482 568  
 राजनीतिक दासता, 66  
 राजेंद्रप्रसाद 541 577  
 रानाडे, 336  
 रामगढ़ अधिवेशन, 560  
 रायल इषायर सोसायटी, 50  
 राय, एम० एन०, 440  
 रायल टाइटिल्स एक्ट, 318, 443  
 राय, राममाहून, 314 317  
 रालिंसन, लाड, 547  
 राव, बी० के० जार० बी०, 51, 55  
 राष्ट्रीय आंदोलन, 24, 26, 35, 36, 37, 294, 296, 297, 298, 313, 321, 325, 331, 334, 335, 336, 337, 340, 341, 344, 349, 360, 361 362, 366, 331, 385, 386, 388, 391, 436, 445, 459, 460, 465, 470, 475, 476 477, 478, 509, 510, 512, 520, 532, 536, 543, 514, 550, 553, 556, 567, 569, 573, 577, 579, 583, 586, 616, 625, 626, 627, 634, 646  
 राष्ट्रीय कांग्रेस, 25, 173, 306, 321, 328, 331, 470, 512, 513, 522, 529, 537, 554, 557, 558, 563, 610 633  
 राष्ट्रीय जनआंदोलन, 466  
 राष्ट्रीय जागरण, 443, 475  
 राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, 25, 39, 296 302, 307, 316, 436, 455, 492, 611, 613, 628  
 राष्ट्रीय विद्रोह का आंदोलन, 27  
 राष्ट्रवादी चीन, 26  
 रिजव बन आफ इंडिया, 188, 198, 200 278  
 रिपन लाड, 341 610  
 रिपोर्ट आफ दि अमेरिकन टेक्निकल मिशन, 47  
 रिपोर्ट आफ दि हाउसिंग पैनल, 59  
 रिपोर्ट आफ दि हेल्थ सर्वे ऐंड डेवलपमेंट कमेटी, 64, 73  
 रिपोर्ट आन दि इप्रूवमेंट आफ इंडियन एग्रीकल्चर, 237  
 रीड, स्टैनले, 594  
 रीडिंग, लाड, 455  
 रूजवेल्ट, 26, 564  
 रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, 99  
 रूसी नाति, 98, 314, 340, 345, 413, 496, 554, 556, 611  
 रेगे कमेटी, 401, 402  
 रेल मजदूर, 435  
 रेल व्यवस्था, 155  
 रयतवारी बंदोबस्त 250 251, 252, 269



- रोजवेरी, लाड, 104  
 रोजीगर, लारेंस रे०, 166  
 रोथरमीयर, लाड, 612  
 रोनेल्डो, 334, 499  
 रोनेल्डस, सर आर्किगाल्ड, 206  
 रोसट ऐक्ट, 347, 413  
 रोसट क्रमीशन, 344  
 रकाशायर, 137, 405, 551, 552  
 सधनक अधिवेशन, 523, 524  
 सधनक सधि, 470  
 सगल, 244, 245, 247, 264, 272, 283, 361  
 सदन टाइम्स, 422, 529  
 लाकाफ, 196  
 लाजपतराय, लाला, 334, 343, 349, 358, 362, 416, 472, 554  
 लायल, सर अल्फ्रेड, 327  
 लारेंस, वैधिक, 593  
 लारेंस, सर हेनरी, 317  
 लाल शडा यूनियन, 365, 435  
 लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 431  
 लाहौर, 293, 370  
 लाहौर अधिवेशन, 371, 372, 381, 382, 478  
 लास्नी, हेराल्ड, 107, 582  
 लिटन, लाड, 318, 323, 324, 448, 495  
 लिनलिथगो, लाड, 505  
 लिली, डब्ल्यू० एच० 148  
 लीग आफ नेशन, 392  
 लीवर ब्रदर्स, 187  
 ली, विलियम, 134  
 लीघिस, सर जाज कानवल्, 127, 128  
 लवी, ई० ए०, 301  
 लेनिन 122, 341 390 391  
 लेबर पार्टी, 419, 552, 582, 584  
 लेबर सरकार, 429, 500  
 लेस्साले 492  
 लैंड ओवर एसोसिएशन, 249  
 लैंड प्रावलम्स आफ इंडिया, 216, 240, 244, 257  
 लैंड होल्डिंग फेडरेशन, 249  
 लोकनाथन, पी० एस०, 186  
 लाररडे, एन० एम०, 410, 411  
 व्यवसाई बग, 296  
 व्यापारिक पूजीवाद, 136  
 बग समाज 39  
 बगमधय की भावना, 414  
 बल्ड अलमनाक, 50  
 बल्ड पीस कांग्रेस, 556  
 बर्साई सधि, 502, 554  
 बर्लिगटन, 105  
 बाट, जेम्स, 133, 134, 135  
 बाटसन, सर अल्फ्रेड, 50  
 बाट, सर जार्ज, 46, 76  
 बाडिया, बी० पी०, 415  
 बामपथी कांग्रेस, 598  
 बामपथी राष्ट्रवादिता, 383  
 बायसलेस इंडिया, 64  
 बायसलेस मिलियंस, 232  
 बिक्टोरिया, 322, 327, 448  
 बिगनेट, सर जाज, 290  
 बिलसन, एच० एच०, 141  
 बिलबाक्स, सर विलियम, 45, 113, 231, 232  
 बिलिंगटन, लाड, 343  
 बिलियम, एल० एफ० रशमूक, 313, 448, 449  
 बिलियम, मो० आई० ई०, 232  
 बिद्वद्व्यापी आर्थिक चर्चा, 291, 331  
 विश्वसरया, एम०, 166, 174 192 195, 196

- विश्व समाजवाद, 39  
 द्विग क्रांति 113, 123  
 हितले कमीशन, 59, 60, 359, 401, 422  
 हितले कमीशन रिपोर्ट, 69, 91, 257, 398, 399  
 वेडरबन, विलियम, 323  
 वेथ, 453  
 वेरिंग, 51  
 वेरल्स्ट, गवनर, 129  
 वेलजली, लाड, 157  
 वेल्लस, समनर, 564  
 वेवल, लाड, 206  
 वेस्ट इंडीज, 29, 125  
 वेल्थ एंड टैक्सेवल कपिसिटी इन इंडिया, 31, 54, 56  
 वोल्कट, जे० ए० 236, 237  
 शकलतवाला, शापुरजी, 420  
 शाह, के० टी०, 31, 51, 53, 54, 55  
 शाही आयोग, 286  
 शिकमी किसान, 252, 258  
 शिकमी की प्रणाली, 286  
 शिमला, 445  
 शिमला सम्मेलन, 580, 585, 594, 595  
 शिराज, फिडल, 396  
 शिवाजी, 336  
 शील्स, डा० ड्रमड, 429  
 शेरीडान, 139  
 शेली, 315  
 शोलापुर, 372, 377, 400  
 स्क्रैपटन, एल०, 129, 130  
 स्टेटसमन, 50, 354, 379  
 स्टेटस पीपुल्स काफ़ेम, 451, 456  
 स्टेटस प्रादेवरान एक्ट, 451  
 स्ट्रेची, सरजान, 297, 298, 303, 463  
 सडरलड, जे० टी०, 464  
 स्तालिन, 99, 478, 480, 481  
 सती प्रग, 317  
 स्थाई अधिकार विहीन कृषक, 235  
 स्थाई जमींदारी बंदोबस्त, 248, 251  
 सयाल विद्रोह, 291  
 सनातनी हिंदू, 476  
 संपत्तिविहीन सवहारा, 392  
 सप्रू, सर तजबहादुर, 369  
 स्प्रेट, फिलिप, 423  
 स्मटस, 583  
 सवाटा, 31  
 समाजवादी क्रांति, 83  
 स्मिथ एडम, 49, 105, 137, 141, 168  
 स्मिथ, विनसेट, ए०, 303  
 सयुक्त राष्ट्र, 25, 26, 28  
 सयुक्त राष्ट्र संधि, 439  
 सरक्षित काश्तकार, 286  
 सवदलीय सम्मेलन, 472  
 सवहारा वग, 99, 133, 341, 391  
 स्लीमन, सर विलियम, 447  
 स्लेटर, डा०, 225  
 स्वराज पार्टी, 363, 364, 416, 639  
 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 299, 354, 357, 360 370, 374, 380, 386, 433, 561, 572, 579, 639  
 सहकारिता आंदोलन, 299, 370  
 सहगल, केदारनाथ, 424  
 साइक्स, कनल, 152  
 साइमन कमीशन, 52, 53, 54, 269, 300, 301, 304, 305, 364, 420, 472, 500, 508  
 साइमन कमीशन रिपोर्ट, 51, 219, 252, 258, 262, 298, 300, 309 310, 379, 444, 462, 501

- साइमन, सर जान 300  
 साबरमती, 371, 372  
 साबरमती समझौता, 364  
 सामतवाद, 109  
 सामती साम्राज्यवादी शोषण, 293  
 सामूहिक स्वामित्व, 109  
 साम्राज्यवादी सामती दबाव, 74  
 सायेर, 164  
 सावजनिक सुरक्षा बिल, 422  
 साल्सवरी, लाड, 105, 169, 170, 495,  
 610  
 साविधानिक रियासतें, 25  
 साहा, प्रोफेसर, 633  
 सिख, 375  
 सिंगापुर, 30  
 सिगरेटिस्ट, एच० ई०, 90  
 सिनहा, 554  
 सिराज, फिडले, 51, 52  
 सीतारमैया, पट्टाभि, 458, 477  
 सीमे, जे० एफ०, 402  
 सीले, जे० आर०, 140, 296, 298, 303  
 सुधारवादी नता, 435, 591  
 सुब्रह्मण्यम, एन० एस०, 270  
 सुदखोर महाजन, 86 252, 265, 268,  
 270, 275, 276, 291, 468  
 सूवेदार, 204  
 सेडीशश मीटिंग्स ऐक्ट, 341  
 सेन, भवानी, 279  
 सेसकफ, सर टी०, 208  
 सेंट्रल बैंकिंग इक्वायरी कमेटी, 51 220  
 सोवियत मघ, 285, 439, 483, 562,  
 583, 584, 622, 636, 642  
 सोवियत समाजवादी गणराज्य, 83  
 हक, फजलुल, 434  
 हर्चिसन, एच० एल०, 424  
 हटर कमीशन रिपोर्ट, 465  
 हटर सर विलियम 103  
 ह्यूम, ए० ओ०, 322, 323, 324, 325,  
 326 327, 463  
 हरदयाल, 554  
 हरिजन, 306, 532, 572, 591, 631  
 हरिपुरा अधिवेशन 457, 524, 528,  
 537, 557  
 हारग्रीव्स 135  
 हार्डिंग, लाड 170 171, 172  
 हार्डी, 390  
 हान, ई० ए०, 151  
 हाल्सवथ, जे०, 395  
 हालैंड, टी० एच०, 46, 171  
 हावड, एच० ई०, 160, 161  
 हिवस, जायसन, 312  
 हिटलर, 583  
 हिडेनवग, वान, 372  
 हिंदू 375, 435, 441, 461, 471  
 हिंदू आंदोलन, 477  
 हिंदू महाजन, 468  
 हिंदू महासभा, 362, 476, 592  
 हिंदू मुस्लिम एकता, 471, 476, 484,  
 490  
 हिंदू-मुस्लिम एकता सवधी जन प्रदर्शन,  
 27  
 हिंदू मुस्लिम मघप, 460, 462  
 हिंदूवाद, 475  
 हिंदुस्तान टाइम्स, 209, 210  
 हिल्टन यंग कमीशन, 178, 179  
 हिल, प्रो० ए० बी०, 76 205, 207  
 हीचेट, सर जान, 168, 169  
 हुदा, शमसुल, 424  
 हुसैन, मदानी, 471  
 हंग, सर हरी, 384  
 हवर, जिज्ञाप 242  
 हलीफावस, सर, 567

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| हेस्टिंग्स, 105, 114, 131, 139, 141 | होमरूल फार इंडिया लीग, 344           |
| हैजा, 63                            | होल्डरनेल, चार्ल्स, 224              |
| हैडो, सर रेनाविक, 207               | होलिया, 257                          |
| हैदराबाद, 445                       | होर, सर सैम्पुजल, 384, 505           |
| हैरिसन, आर० मैक, 58                 | त्रिपुरी अधिवेशन, 457 539, 540, 541, |
| जोग सर जी० १८८                      | <del>557</del>                       |





रजनी पाम दत्त परिचिता और मित्रा के बीच आर० पी० डी० नाम से लोकप्रिय । 1921 से लेकर मृत्युपयत लेबर मयलो' के संपादक और इसी पत्र के 'नोट्स आफ दि मय' स्तम्भ के लेखक ।

ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य और इसकी कार्यकारिणी के प्रथम कांग्रेस के समय से ही सदस्य । शीघ्रस्थ मार्क्सवादी चिंतक और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक । कुछ अत्यंत विख्यात पुस्तकें फासिज्म ऐंड सोशल रिवाल्यूशन, 'वर्ल्ड पालिटिक्स, 'ब्राइसिस आफ ब्रिटन ऐंड ब्रिटिश इंपायर, 'इंटरनशनल्स । ये सभी ग्रंथ पाम दत्त की मूर्धन्य मार्क्सवादी अवधारणा दृष्टि के परिचायक हैं । विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को आग बढ़ाने में इन पुस्तकों का बहुत बड़ा हाथ है ।